Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

113084

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

76308

सम्पदा

गुरुकुल कांगड़ी

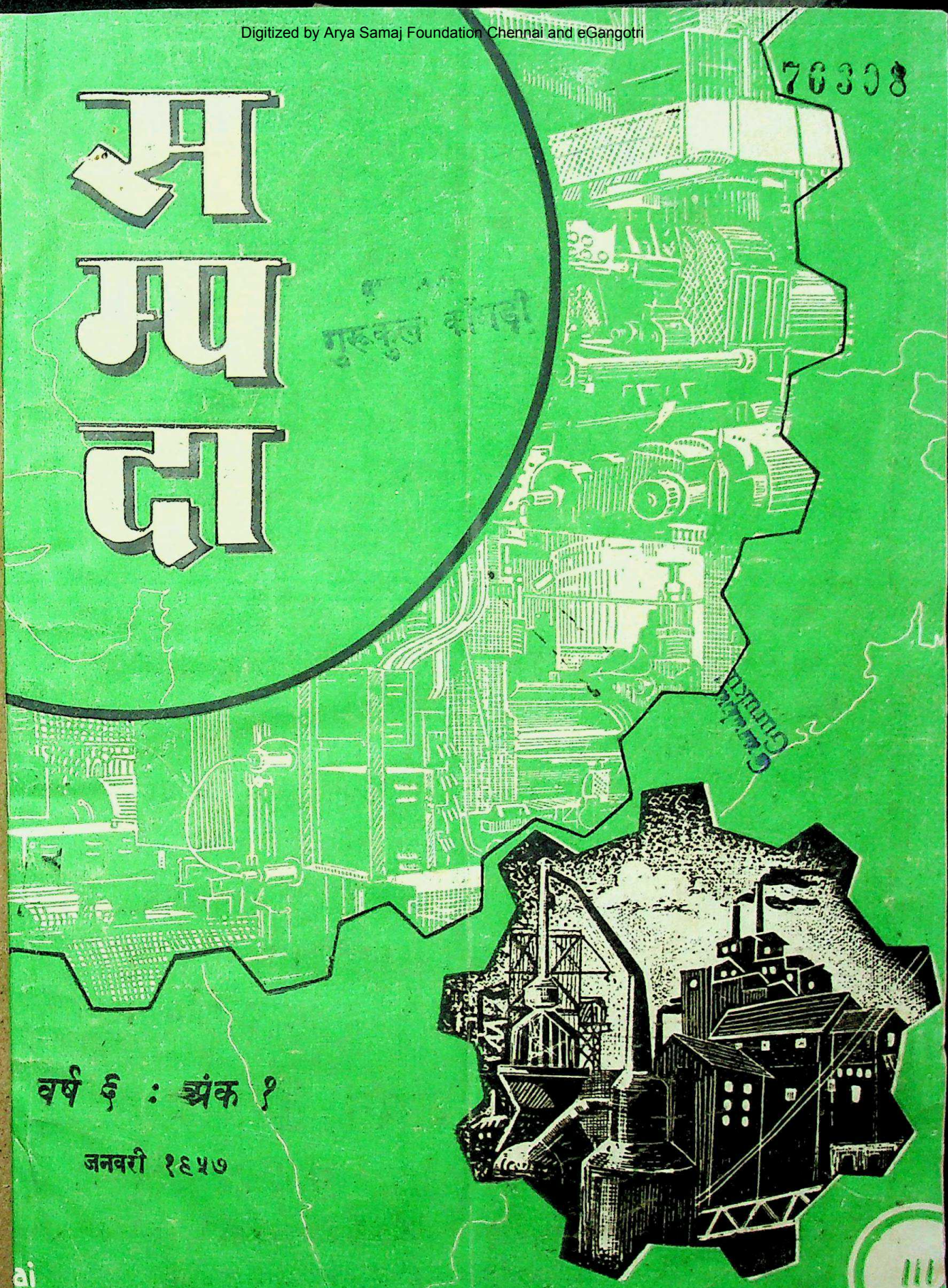

वर्ष ६ : अंक १

जनवरी १९५७

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

संतुलित और सुदृढ़

राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के लिये

दि पंजाब नैशनल बैंक लिमिटेड

बचत को एकत्रित करके
नियमित रूप से सहायता करता है। आज अनुसूचित बैंकों के
प्रति आठ ग्राहकों में एक पंजाब नेशनल बैंक का मूल्यवान
ग्राहक है।

चालू पूंजी

१२८ करोड़ रुपये से अधिक

चेयरमैन

श्री० एस० पी० जैन

दि पंजाब नैशनल बैंक लिमिटेड

प्रधान कार्यालय : दिल्ली

६१ वर्षों की विश्वसनीय सेवा का बृहत अनुभव

ए० वाकर—जनरल मैनेजर

पहली व दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के अनुसार—

भारतवर्ष आज अपने आर्थिक विकास व पुनर्निर्माण के लिए प्रयत्नशील है। देश के हर एक भाग में पक्की सड़कें, नदियों के बाँध, विशाल पुल, सुन्दर भवन, हस्पताल, स्कूल व कालिज तथा बड़े-बड़े कारखाने बनाये जा रहे हैं।

इनको टिकाऊ, सुन्दर, एवं सबल बनाने के लिए सर्वोत्तम डालमिया सीमेंट का प्रयोग कीजिए।

डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटिड

डालमियापुरम् (त्रिचनापल्ली)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

३ से १४ मार्च १९५७

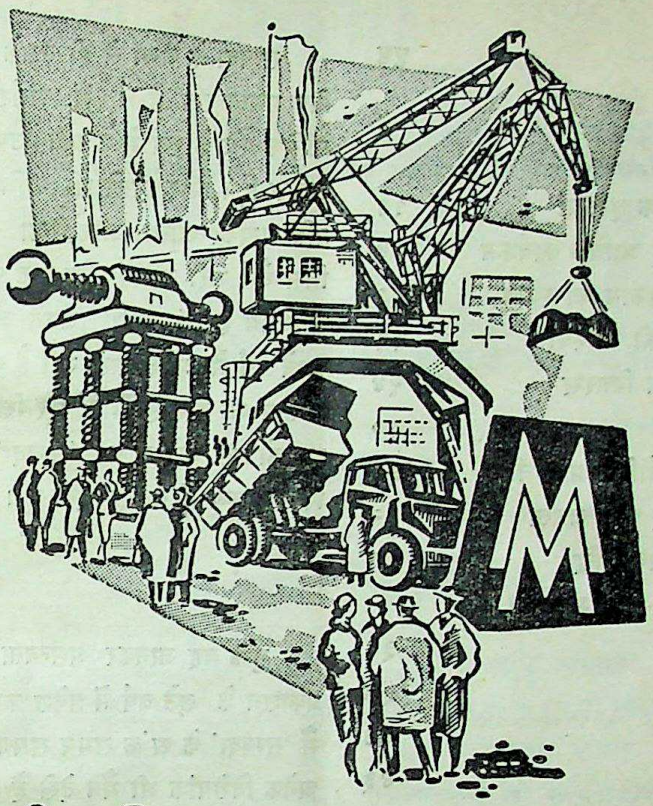

मुलाकात लीजिए....

लीपजिग व्यापारी मेला

टैक्निकल मेला और नमूनों का मेला

८ लाख वर्ग मीटर के विस्तृत क्षेत्र पर आप

४० देशों के १०००० निर्माताओं की वस्तुएं पावेंगे

विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क स्थापित कीजिये

लीपजिग फेअर एजेंसी इन इण्डिया

पो० बा० १९९३ बम्बई—१

या

लीपजिग फेअर एजेंसी इन इण्डिया

तीसरी मंजिल, मेहता मैंशन,

३ ए०, डी० ए० जी० स्कीम, आसफअली रोड, नई दिल्ली ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विषय सूची

संख्या	नाम	पृष्ठ
१.	कांग्रेस का महान् सन्देश	५
२.	सम्पादकीय टिप्पणियां	
३.	१९५६ में देश की आर्थिक वृत्तियां	११
४.	देश के राजनैतिक दलों के आर्थिक कार्यक्रम	१४
५.	निजी उद्योगों का राष्ट्र विकास का स्थान	१९
६.	वस्त्र उत्पादन व निर्यात की समस्या	२२
७.	विविध राज्यों में आय का वितरण	२४
८.	प्रान्तीय सहकारी बैंक	२७
९.	लीपजिग की प्रसिद्ध औद्योगिक प्रदर्शनी	३१
१०.	देश की विकास योजनाएं और जनता	३२
११.	सोवियत रूस में औद्योगिक वृद्धि	३५
१२.	अमेरिकी अर्थ व्यवस्था : बड़ी मंदी की सम्भावना नहीं	३६
१३.	अर्थवृत्त चयन	३८
१४.	नया सामयिक साहित्य	४१
१५.	सर्वोदय पृष्ठ	४३
१६.	उद्योग में दशमिक प्रणाली	४४

राज्यों में सम्पदा स्वीकृत

सम्पदा को निम्नलिखित राज्यों के शिक्षा विभागों ने अपने अपने राज्य के स्कूलों, कालेजों तथा सार्वजनिक वाचनालयों के लिए स्वीकृत किया है—

राज्य	परिपत्रक संख्या	दिनांक
(२) उत्तरप्रदेश	पुस्तक/५२५७	१२-१-५४
(२) बिहार	७३३/२पी/१/५३	२७-११-५३
(३) पंचाब	३२०६/५/२५/बी-५३-२६१४३	२३-३-५८
(४) मध्यप्रदेश (स्कूलों के लिए)	२/जी/वी	२-८-५२
(कालेजों के लिए)	३४२८/३XVIII	२४-८-५२
(५) राजस्थान	८६८०/EduII/५२	६-१२-५२
(६) मध्यभारत	३ : १५ : २ : ५२बी/२५६५	२४-३-५२

मंगल कामना व आशीर्वाद

सम्पदा के जन्म से ही उसके प्रति मेरा सहज स्वाभाविक ममत्व रहा है । मैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हिन्दी मासिक पत्र के रूप में उसकी उपयोगिता और महत्व का कायल हूँ । और इससे भी अधिक प्रशंसक रहा हूँ इसके प्रति आपकी आस्था और निष्ठा का । आपने 'सम्पदा' को जिस धैर्य भरी ममता और लाड प्यार से पाला पोसा है, वह अद्वितीय है । 'सम्पदा' अपने जीवन के ५ वर्ष पूर्ण कर छठवें वर्ष में प्रवेश कर रही है यह सबके लिये सुख और सन्तोष की बात है और मेरे लिये विशेष रूप से है । मैं आपको इस अवसर पर 'सम्पदा' के धर्म और ममतालू पिता के रूप में बधाई देता हूं ।

—मिश्रीलाल गंगवाल

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि 'सम्पदा' अपने प्रकाशन के छठे वर्ष में प्रवेश कर रहा है । प्रारम्भ से ही मैं 'सम्पदा' के अंक समय समय पर देखता रहा हूं । इसके अनेक विशेषांक भी मैंने देखे हैं । अर्थशास्त्र सम्बन्धी अनेक उपयोगी लेख तथा अन्य सामग्री इसमें प्रकाशित होती रहती है । जिस लग्न और परिश्रम से आपने इस पत्र को बढ़ाया है वह सराहनीय है । पत्रकी सफलताके लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं भेजता हूं ।

—श्री तख्तमल जैन

बैंक अंक वास्तव में बहुत उपयोगी है । राष्ट्र भाषा हिन्दी में एक स्थान पर इतनी सामग्री एकत्रित करने में कितना परिश्रम लगा होगा, यह अंक की विषय सूची देखने से सहज ही ज्ञात हो जाता है । इतने गहन विषय पर हिन्दी में प्रामाणिक लेखों की संकलन राज भाषा की भी बहुत बड़ी सेवा है । 'मेरी भी सुनोगे' हलका-फुलका लेख बड़ा उपयोगी जान पड़ा ।

—राजनारायण गुप्त

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

113084
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
113084

सम्पदा

वर्ष ६] जनवरी १९५७ [अंक १

कांग्रेस का महान् सन्देश

कांग्रेस ने विशालकाय चुनाव घोषणा-पत्र प्रकाशित किया है। इसमें अपनी नीति की व्यावहारिकता और सफलता दिखाते हुए, राजनैतिक, अन्तर्राष्ट्रीय तथा आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रमों की घोषणा की गई है। यह सब कार्यक्रम अत्यन्त महत्वपूर्ण हो सकते हैं, किन्तु हम उनकी चर्चा यहां नहीं करना चाहते। कांग्रेस के आर्थिक कार्यक्रम तथा कांग्रेसी सरकार की आर्थिक नीति का परिचय हम सम्पदा के पाठकों को सदा देते रहे हैं। हम जिस नीति की ओर पाठकों का ध्यान खींचना चाहते हैं, वह है जनता में कुछ नई मान्यता और भावना पैदा करने की प्रेरणा। राष्ट्र को आत्म विकास के लिये धन की अत्यन्त आवश्यकता है, इसमें सन्देह नहीं, किन्तु उससे भी अधिक आवश्यकता है धन के सदुपयोग की। योजना का अर्थ ही यह है कि उपयोग और आवश्यकता की दृष्टि से प्राप्त साधनों के प्रयोग का क्रम निर्धारित करना, अर्थात् जो चीज अधिक आवश्यक है, उस पर पहले और जो चीज कम आवश्यक है, उस पर पीछे व्यय करना। आज देश में जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं सर्वप्रथम पूरी करनी हैं और उनमें अन्न का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। यह दुर्भाग्य की बात है कि अन्न की दृष्टि से हम आज भी स्वावलम्बी नहीं हैं और विदेशों से भारी मात्रा में अन्न मंगवाने के लिये करोड़ों रुपया चाहिये। इस वर्ष के अन्त तक १८ लाख टन अनाज मंगवाया जायेगा। हमारी विदेशी मुद्रा निरन्तर कम हो रही है। ऐसी स्थिति में एक भी पैसा कम आवश्यक वस्तुओं पर व्यय करना अदूरदर्शिता होगी। योजना के अन्य अंगों की पूर्ति के लिए हमें एक-एक रुपए की बचत करनी है। देश में लगातार बढ़ती हुई मंहगाई को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन स्तर को कुछ निम्न करके भी रुपया बचाएं। योजना की पूर्ति के लिये जितना रुपया आवश्यक है, वह उपलब्ध नहीं हो रहा है। योजना आयोग ने ५-१० अरब रु० के नये करों के अतिरिक्त ५ अरब रुपया जनता से बचत के रूप में प्राप्त करने की आशा की है।

प्रश्न यह है कि क्या हम इन सब बातों पर विचार करके अपना कर्तव्य पूर्ण कर रहे हैं। कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में जनता के इसी कर्तव्य की ओर विशेष रूप से ध्यान खींचा गया है। यदि हम सब लोग देश के आर्थिक साधनों के सुविचार पूर्ण उपयोग का निश्चय कर लें, तो यह कठिनाई कुछ हद तक दूर हो सकती है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में देश के सामने करीब ४० करोड़ नागरिकों के जीवन को उन्नत करने के महत्वपूर्ण और विशाल कार्य के लिए देश की समस्त जनता का आह्वान करते हुए कहा गया है कि "एक अविकसित देश में जनता की दरिद्रता से मुक्ति तथा प्रगतिशील अर्थ व्यवस्था स्थापित करना

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बहुत कठिन काम है। इसके लिये पर्याप्त समय तक निरन्तर और सुसंगत प्रयत्नों की आवश्यकता है। हमें प्रत्येक प्रकार की तपस्या और संयम से काम लेना होगा। एक-एक पैसा फिजूलखर्ची से बचाना होगा, ताकि देश के साधनों का उत्पादक कार्यों के लिए अधिकतम प्रयोग हो सके। जीवन के उच्च स्तर तथा अपनी समृद्धि के प्रदर्शन की झूठी भावनाएं छोड़नी पड़ेंगी। आज जो लोग देश की जनता का नेतृत्व करते हैं, उन्हें उसके सामने अपना आदर्श पेश करना होगा। आज देश को खेती और उद्योगों की उन्नति के लिये करोड़ों, अरबों रुपयों की आवश्यकता है। इसके लिए भारी मात्रा में बचत तथा भावी उन्नति के लिए विनियोजन आवश्यक है। अपने भविष्य का निर्माण करने के लिये आज हमें कठिन परिश्रम करना होगा।"

वस्तुतः घोषणा पत्र के समस्त कार्यक्रमों में यही कार्यक्रम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व जिस तरह से राजनैतिक चैतन्य उत्पन्न किया गया था, उसी तरह आज देश की दरिद्रता से मुक्ति के लिये आर्थिक चैतन्य पैदा करने की आवश्यकता है।

किन्तु घोषणा पत्र के उक्त संदेश और शासन की कार्यनीति में तुलना बहुत सन्तोष प्रदान नहीं करती। समय-समय पर लेखा-आयोग के विवरण इस सत्य को प्रकट करते रहते हैं कि गरीब करदाता के रुपये का पूर्ण उपयोग नही होता। एक के बाद एक स्कैण्डल सामने आते हैं। अनियमित व्ययों को छोड़ भी दिया जाये तो बाकायदा किये जाने वाले व्यय भी लाखों रुपये के प्रत्येक विभाग में ऐसे ही हैं, जो बहुत आसानी से रोके जा सकते हैं। मंत्रियों और उपमंत्रियों की संख्या के लगातार बढ़ने की आलोचना बीसियों बार की जा चुकी है। मंत्रियों तथा अफ़सरों की बड़ी २ कोठियों तथा ऊपरी टीपटाप के खर्चों, बड़े २ भत्तों आदि में काफी कमी की जा सकती है। छपाई और स्टेशनरी के बिल अनावश्यक रूप से बढ़ गये हैं। हरेक विभाग अपनी-अपनी कारगुजारी दिखाने के लिए बढ़िया आर्ट पेपर पर पत्रिकाएं छापने लगा है। प्रकाशन विभाग मंत्रियों के चित्र लेने पर अनाप-शनाप खर्च करते हैं। जो काम निजी तौर पर १० रु० में होता है, सरकारी तौर पर कियाजायेगा, तो २० रु० का खर्च मामूली बात है। सामुदायिक योजनाओं में भी अपव्यय को रोका जा सकता है। तपस्वियों के साधु-समाज के नेता पहले दर्जे के डब्बे में सीटें रिजर्व कराते हैं। ऐसे सैंकड़ों खर्च हैं, जिन पर नजर डाली जाये, तो वे रोके जा सकते हैं। आवश्यकता यह है कि एक बार हम यह निश्चय कर लें कि जो खर्च बचाये जा सकते हैं, जरूर बचाने हैं।

कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में तपस्या और कष्ट सहन (आस्टैरिटी) का संदेश दिया है और शासकों से आदर्श स्थापित करने का अनुरोध किया है। वस्तुतः शासकों को, संसद के सदस्यों को, बड़े २ अधिकारियों को अपने बढ़ते हुए स्तर को नीचे लाना होगा। जीवन स्तर की उच्चता का आदर्श भूलना होगा। एक बार यह निश्चय करना होगा कि हमें सब काम मितव्यय से करने हैं। इस मितव्यय का तरीका छोटे कर्मचारियों की छटनी नहीं है, परन्तु बड़े अधिकारियों के व्ययों में कटौती है। समाजवाद के बार २ घोषित आदर्श की पूर्ति के लिए केवल राष्ट्रीयकरण अत्यन्त पर्याप्त है। इसके लिए बड़ों और छोटों के जीवन-स्तर में समानता लानी होगी और बड़ों को अपना जीवन-स्तर नीचा करना होगा।

हम सम्पदा के पाठकों का और उनके द्वारा नेताओं का ध्यान इसी अंक में प्रकाशित अन्यत्र सरदार पटेल की तपस्विनी पुत्री मणिबेन के सादगी और मितव्यय पूर्ण जीवन की ओर खींचना चाहते हैं। यही तपस्या है, यही सादगी है, यही मितव्यय है, जिसे हमें अपने सामने आदर्श के रूप में रखना होगा, तभी हम राष्ट्रीय विकास योजनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। यदि कांग्रेस का यह संदेश जनता को कुछ भी प्रेरणा दे सका, तो हम समझेंगे कि राष्ट्र का विकास बहुत निकट आगया है।

—

कृषि-उत्पादन के नये लक्ष्य

जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रकाशित हुई, तभी कुछ अर्थशास्त्रियों ने आयोग का ध्यान इस ओर खींचा था कि उद्योग की अपेक्षा कृषि की उपेक्षा की गई है। उस समय योजना आयोग का यह ख्याल था कि अन्न के उत्पादन में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हमने काफी सफलता पा ली है। किन्तु कुछ समय बाद ही यह प्रकट हो गया कि अभी देश अन्न संकट से बाहर नहीं निकला। इसलिये नेताओं का ध्यान फिर कृषि उत्पादन की ओर गया है। कुछ समय तक भारत सरकार के कृषि विभाग और योजना आयोग में कृषि सम्बन्धी व्यय को लेकर वाद-विवाद सा भी खड़ा हो गया था। अब महीनों तक विचार विनिमय के बाद कृषि उत्पादन के नये लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। पं० नेहरू ने ठीक कहा है कि—"वस्तुस्थिति हमारे सामने है। हमें दो में से एक का चुनाव करना है—कृषि उपज बढ़ा कर योजना को सफल बनायें या योजना छोड़ दें। कोई तीसरा मार्ग नहीं है। नीचे की तालिका से यह स्पष्ट हो जायेगा कि १९५५-५६ के उत्पादन को देखते हुए ५ वर्ष बाद योजना आयोग ने क्या लक्ष्य नियत किये थे और अब विचार विनिमय के बाद नये लक्ष्य क्या नियत किये गये हैं :—

अगर संशोधित लक्ष्यों की पूर्ति हो जाय, तो कुल मिला कर कृषि उपज में लगभग २८ प्रतिशत की वृद्धि होगी—अनाज की उपज में करीब २५ प्रतिशत और व्यापारिक फसलों की उपज में लगभग ३४ प्रतिशत।

यदि देश की आर्थिक व्यवस्था को मंहगाई के द्वारा विकृत नहीं होने देना है तो यह आवश्यक है कि कृषि का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में बढ़ाया जाये। बढ़ती हुई जन-संख्या की आवश्यकता पूर्ति के लिये भी कृषि उत्पादन के लक्ष्य बढ़ाने आवश्यक हैं। कृषि पदार्थों के मूल्य यदि कम होंगे तो अन्य पदार्थों के मूल्य पर भी नियंत्रण रखना कठिन नहीं होगा।

जिन्स	इकाई	१९५५-५६ की अनुमित उपज (योजना में वर्णित)—	योजना में उपज के अस्थायी लक्ष्य	उपज के संशोधित लक्ष्य	उपज के सूचक अंक में में वृद्धि का प्रतिशत	
					योजना के अनुसार	संशोधित
अनाज	लाख टन	६५०	७५०	८०४	१६	२४.६
तेलहन	लाख टन	५५	७०	७६	२७	३७.०
गन्ना (गुड़)	लाख टन	५८	७१	७८	२२	३३.९
कपास	लाख गांठें	४२	५५	६५	३१	५५.६
पटसन	लाख गाँठें	४०	५०	५५	४३	५८.१
अन्य फसलें					९	२२.४
सभी जिन्स					१७	२७.८

इस तालिका में तेलहन, गन्ना, जूट और अन्य फसलों के जो संशोधित लक्ष्य दिखाये गये हैं, वे मसूरी में राज्यों के परामर्श से ही निर्धारित किये गये थे। कपास का लक्ष्य भारतीय केन्द्रीय कपास समिति ने कपड़ा उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से सलाह करके सुझाया है। अनाज की उपज में १ करोड़ टन की वृद्धि के स्थान पर १ करोड़ ५४ लाख टन की वृद्धि का लक्ष्य सितम्बर में अलग-अलग राज्यों से बातचीत करने के बाद निर्धारित किया गया था।

आयात पर प्रतिबन्ध

भारत सरकार ने नई घोषणा द्वारा आयात व्यापार के सम्बन्ध में जो निश्चय किये हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। एक तरफ हमारा निर्यात व्यापार निरन्तर गिर रहा है, दूसरी तरफ आयात निरन्तर बढ़ रहे हैं। यह ठीक है कि अन्न संकट के समय बाहर से अन्न मंगवाना ही चाहिये। पंचवर्षीय की पूर्ति के लिये भारी मात्रा में मशीनरी भी विदेशों से मंगानी आवश्यक है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि निर्यात की अपेक्षा आयात निरन्तर बढ़ते रहें। यदि कुछ वस्तुयें अनिवार्य रूप से मंगानी है, तो कम आवश्यक वस्तुओं में तो कमी हो सकती है। इस दृष्टि से नई

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आयात नीति का हम स्वागत करते हैं। इस पर अमल से इन ६ महीनों में करीब ३० करोड़ रुपये की राशि बच सकती है। प्रस्तुत आयात नीति में ५०९ वस्तुओं का कोटा कम कर दिया गया है जिनमें फल, कुछ मसाले, सिगार, सिगरेट, शराब, साबुन, कागज, उनी सूती और रेशम के कपड़े, पैंसिल, साईकिल, कोलतार के रंग, कुछ दवायें तथा कुछ यंत्र आदि प्रमुख हैं। कुछ खेल के सामानों, कस्तूरी के तेल, राल आदि सामानों पर अगली छमाही में आयात की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जायेगी। इस प्रकार के सामानों को अनावश्यक मान लिया गया है।

जनवरी १९५६में हमारा स्टर्लिंग कोष ७४२ करोड़ रुपया था। नवम्बर १९५६ में यह घटकर ५३९ करोड़ रुपया रह गया और २१ दिसम्बर को तो वह और भी घट कर ५३६ करोड़ रु० की रह गया। इसका अर्थ यह है कि हमने इस वर्ष करीब २१० करोड़ रुपया अपनी जेब से खर्च किया। यह स्थिति हमारे लिये अत्यन्त शोचनीय है। इसका प्रतिकार बहुत पहले ही हो जाना चाहिये था। खैर, अब भी हो सकता है। किन्तु इसके साथ २ यह भी आवश्यक है कि जनता में यह भावना पैदा हो कि हम विदेशी वस्तुयें नहीं लेंगे। गर्म कपड़ा, टूथ पेस्ट व ब्रुश और शृंगार सामग्री आदि वस्तुयें निश्चित रूप से स्वदेशी ही ली जानी चाहियें। लेकिन आयात पर प्रतिबन्ध का अनुचित लाभ उठाकर भारतीय वस्तु निर्माता अपनी चीजों के दाम बढ़ा दें तो यह अत्यन्त निन्दनीय होगा। उन पर एक विशेष दायित्व आ जाता है कि वह और भी अधिक मात्रा में इन सब पदार्थों को सुलभ करें। साथ ही उनकी किस्म भी विदेशी माल जैसी हो।

—

निर्यात व्यापार बढ़ाओ

यों तो निर्यात व्यापार बढ़ाने की कोशिशें बहुत समय से हो रही हैं, परन्तु इन दिनों आयात व्यापार की एकाएक वृद्धि से इनकी आवश्यकता बहुत बढ़ गई है। सरकारी सहायता से जो निर्यात-प्रोत्साहन-परिषदें बनायी गयी हैं, वे भारत की निर्यात-योग्य वस्तुओं की खपत बढ़ाने के लिए, नये-नये खरीदार ढूंढने के लिए और निर्यात बढ़ाने के लिए अधिक प्रयत्नशील हो गई हैं।

परिषद् के विवरण के अनुसार इंजीनियरिंग की वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका में एक सर्वे किया गया है। मिस्र और सूडान में भी भारतीय इंजीनियरी की वस्तुओं की मांग बढ़ाने के बारे में सर्वे किये जा रहे हैं। यह परिषद भारतीय बाईसिकलों तथा उनके पुर्जों का आसपास के देशों को निर्यात करने की सम्भावना का भी अध्ययन कर रही है। ईरान में भारतीय इंजीनियरिंग की वस्तुओं की खपत बढ़ाने के बारे में भी परिषद् प्रयत्नशील है। काजू और काली मिर्च की निर्यात-वृद्धि-परिषद ने हाल में एक शिष्ट-मंडल मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों को भेजा था। जो दो पूर्वी यूरोपीय देशों से काली मिर्च के परीक्षणात्मक आर्डर भी लाया है। प्लास्टिक की वस्तुओं की निर्यात-वृद्धि के लिए तीन सदस्यों का एक शिष्टमंडल मिस्र, इराक, ईरान, अदन, पूर्वी अफ्रीका और इथोपिया जा रहा है।

तम्बाकू भारतीय आय का प्रमुख साधन है। इसे और बढ़ाने के लिए एक शिष्टमंडल मिस्र, सूडान, अदन, जंजी-बार, ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका, गोल्ड कोस्ट और नाईजीरिया के बाजारों का अध्ययन करने के लिए गया था। इस शिष्ट-मंडल ने बताया है कि मिस्र को तम्बाकू और सूडान, जंजी-बार तथा अदन को बीड़ियों का निर्यात किया जा सकता है। परिषद के पास रूस और चेकोस्लोवाकिया से तम्बाकू के नमूने की मांग आयी है। उसी के आधार पर बाद में रूस को २ हजार टन, और चेकोस्लोवाकिया को नमूने के तौर पर कुछ परिमाण में तम्बाकू भेजने का फैसला हुआ है। सूती कपड़ा निर्यात-प्रोत्साहन-परिषद ने बगदाद, सिंगापुर, अदन, रंगून, लागोस और मोम्बासा में अपने कार्यालय खोले हैं। निर्यातित माल की किस्म सुधारने के भी प्रयत्न किये जा रहे हैं। आवश्यकता यह है कि इन प्रयत्नों को और अधिक सक्रिय किया जाय।

—

विदेशी कम्पनियों में भारतीय

यह शिकायत बहुत समय से अनुभव की जा रही थी कि भारत में स्थित विदेशी कम्पनियों में ऊंचे पदों पर भारतीय कर्मचारियों को नहीं रखा जाता। सरकार ने उन पर यह दबाव डाला है कि वे भारतीय कर्मचारियों की

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अधिकाधिक उन्नति करें। इसका परिणाम यह हुआ कि ६०० रु०तक के सब पदों पर अब भारतीय काम करने लगे हैं। एक हजार रुपये या अधिक वेतन पाने वालों में भी अब भारतीय कर्मचारियों का अनुपात निरन्तर बढ़ रहा है। १९४८ में १,००० रु० से अधिक वेतन पाने वाले भारतीय और विदेशी कर्मचारियों की संख्या क्रमशः ७४२ और ६३६० थी। १९५६ में यह संख्या में क्रमशः ४६८५ तथा ६,५६६ हो गई। यह आशा की जानी चाहिये कि भारतीयों की उन्नति का अनुपात पहले से भी अधिक बढ़ जायेगा।

—

गन्ने की कीमत

चीनी उद्योग के साथ ही गन्ने की कीमत की समस्या अनेक वर्षों से सिर दर्द का कारण बनी हुई है। गन्ने का चीनी के उत्पादन व्यय पर बहुत प्रभाव पड़ता है। किसान चाहता है कि गन्ने की कीमत बढ़ा दी जाये। चीनी मिल का अधिकारी गन्ने की कीमत कम से कम करना चाहता है। उसकी यह शिकायत है कि भारतीय गन्ने में मिठास बहुत कम होती है और फिर अच्छे और नाकिस गन्ने पर एक सी ही कीमत देनी पड़ती है, इसलिये किसान को गन्ने की किस्म सुधारने के लिये कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। इसमें सन्देह नहीं कि यह आरोप बहुत कुछ सत्य है। चीनी उद्योग विकास परिषद् ने इस सम्बन्ध में विचार करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी। इसके सदस्यों ने विदेशों में जांच करने के बाद बताया है कि आस्ट्रेलिया में चीनी उद्योग के विकास का कारण यह है कि वहां गन्ने की कीमत उसकी किस्म के अनुसार दी जाती है। प्रतिनिधि मण्डल ने भारत में भी इसी पद्धति को अपनाने की सिफारिश की है। चीनी उद्योग विकास परिषद् और केन्द्रीय गन्ना समिति ने भी गन्ने की किस्म के अनुसार कीमत वसूल करने की सिफारिश की है। भारत सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। फ़िलहाल यह योजना १० चीनी मिलों में परीक्षण के लिये प्रारम्भ की जायेगी और अच्छी किस्म के गन्नों पर ज्यादा कीमत दी जायेगी। हमें आशा करनी चाहिये कि इससे किसानों को गन्ने की किस्म के सुधार के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

संविधान में संशोधन

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों मजदूरों के छटनी के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है कि जब कोई कारोबार बन्द किया जा रहा हो, तब निकाले गये मजदूरों को छटनी की क्षतिपूर्ति लेने का अधिकार नहीं है; क्योंकि छटनी का अर्थ काम के चालू रहने की हालत में ही मितव्यय अथवा काम की कमी के कारण मजदूर का निकालना है। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध मजदूर संघ भारत सरकार से यह अनुरोध कर रहा है कि संविधान में ही संशोधन करके छटनी की व्याख्या व्यापक कर दी जाये। भारत सरकार के मंत्रियों ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया है। हम मजदूरों की चिन्ता को समझ सकते हैं, किन्तु संविधान में संशोधन की मांग हमारी दृष्टि में अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न पर ही की जानी चाहिये। संविधान अत्यन्त पवित्र वस्तु है, जिसको हमें जब तब अपनी इच्छानुसार मोड़ने का अधिकार नहीं है। यह भी सम्भव है कि देश के महान् योग्य विचारपतियों का निर्णय न केवल कानूनी दृष्टि से ही उचित हो वरन् मानवीय न्याय और औचित्य दृष्टि से ठीक हो। संसद में बहुमत की सुविधा का प्रत्येक समय प्रयोग संविधान की पवित्रता और महत्ता को नष्ट कर देता है।

—

बिक्रीकर की नई व्यवस्था

बिक्री कर राज्यों के लिये और व्यापारियों के लिये बहुत समय से सिर दर्द का कारण बना हुआ है। छोटे दुकानदार तो इसके कारण बहुत ही परेशान हैं। अन्तर्राज्यीय बिक्री कर की पेचीदगियों के अतिरिक्त छोटे दुकानदारों को बिक्री कर का हिसाब रखना भी परेशान कर देता है। बहुत समय से यह मांग की जा रही थी कि बिक्री कर छोटे दुकानदारों से फुटकर न लेकर उत्पादक से ही एक साथ ले लिया जाये, ताकि उन्हें बहुत कठिनता का सामना न करना पड़े। अब सरकार इस दिशा में कुछ सोचने को तत्पर हुई है। राष्ट्रीय विकास समिति में यह प्रस्ताव उसने स्वीकार कर लिया दिखता है कि सूती कपड़े तमाखू, और चीनी पर राज्यों में जो बिक्री कर लगाये जाते हैं, उनके स्थान पर इन वस्तुओं पर लगने वाले केन्द्रीय उत्पादन शुल्क को

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बढ़ा दिया जाना चाहि । इस प्रकार से जो आय होगी, उसको विभिन्न राज्यों में खपत के अनुसार बांट दिया जाये । इसमें संदेह नहीं कि इस प्रकार के प्रस्ताव से छोटे दुकानदारों की बहुत सी कठिनता हल हो जायेगी और जो कर चोरी से छिपा लिया जाता है वह भी वसूल हो जाया करेगा ।

—

चुनाव के लिए भारी व्यय

भारत सरकार ने हाल ही में निकट भविष्य में होने वाले चुनावों के लिये प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा किये जाने वाले अधिकतम व्यय की सीमा निर्धारित कर दी है। विधान-सभाओं के लिये एक सदस्यीय क्षेत्र से ६ से ९ हजार तक तथा द्विसदस्यीय क्षेत्रों से ११ से १४ हजार रु० तक सीमा निथत की गई है। संसद के लिये यह संख्यायें क्रमशः२५ और ३५ हजार हैं। केन्द्र शासित प्रदेशों के लिये यह संख्यायें १० और १५ हजार हैं। पाठकों को यह मालूम होना चाहिए कि गत चुनाव में व्यय की सीमा बहुत कम थी। अब यह सीमा इतनी अधिक बढ़ा दी गई है कि अत्यन्त सम्पन्न व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकते हैं। समाजवादी समाज की रचना का उद्देश्य लिये हुए यह निश्चय कहां तक हमारी नीति के साथ संगत बैठता है, यह सोचने की चीज है। यह ठीक है कि चुनावों में वास्तविक व्यय इससे भी अधिक किये जा रहे हैं। किन्तु उनको कानूनी रूप देना समस्या का हल नहीं है। चुनावों को बहुत कम व्यय में करने की परिपाटी निकालनी चाहिये और विशेषकर जब हम समाजवादी समाज का नारा जोरों से लगा रहे हैं।

—

निर्यात के लिए वस्त्र उत्पादन

पाठक भारत के एक प्रमुख उद्योगपति लाला श्रीराम का लेख अन्यत्र पढ़ेंगे। इससे यह स्पष्ट है कि भारत में वस्त्र उत्पादन बढ़ने के बावजूद भी निर्यात कम हो रहा है। और विदेशी व्यापार की प्रतिकूलता देश के लिये बहुत खतरनाक है। इस दृष्टि से यह अत्यन्त आवश्यक है कि निर्यात व्यापार को बढ़ाया जाये। भारत सरकार ने स्वचलित करघों को लगाने की अनुमति इस शर्त पर दी है कि स्वचलित करघे केवल उन्हीं मिलों को दिए जायं, (१) जो इस बात की गारण्टी दें कि उनके लिए जितना कपड़ा निर्धारित किया जाएगा, उतना वे निर्यात करेंगी और (२) जो पहले से ही कपड़ा निर्यात कर रही है और जो इस बात की गारण्टी दें कि वे अपने पिछले निर्यात का कम से कम ८७॥ प्र० श० कपड़ा अब भी निर्यात करती रहेंगी और साथ ही इन नये स्वचलित करघों से जो कपड़ा तैयार होगा, उसे वे सबका सब निर्यात करेंगी। जो मिलें इन गारंटियों को पूरा नहीं करेंगी, उन्हें उस कपड़े के लिए दण्डस्वरूप उत्पादन शुल्क देना पड़ेगा जो निर्यात के लिए निर्धारित हो, परन्तु देश में ही खपत के लिए प्रयोग किया जाय। उक्त सिद्धान्तों के आधार पर १०,५१२ स्वचलित करघे लगाने की अनुमति दी जा चुकी है।

हमें आशा करनी चाहिए कि इस व्यवस्था से भारतीय वस्त्र उद्योग विदेशों के मुकाबले में सस्ता कपड़ा तैयार कर निर्यात व्यापार को बढ़ा सकेगा तथा विदेशी मुद्रा की कठिनता को हल करने में सहायक होगा।

—

मतदाताओं से

सम्पदा का यह अङ्क जब पाठकों के पास पहुँचेगा, तब देश में चुनावों की हलचल जोरों से होगी और विविध राजनैतिक दल अपने-अपने चुनाव घोषणा पत्र लेकर मतदाताओं के सामने आ रहे होंगे। इन चुनाव घोषणा पत्रों में राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रमों का वायदा करके अधिक वोट लेने की चेष्टा की जायेगी। हम अपने पाठकों से इतना ही अनुरोध करना चाहते हैं कि वे संस्था और उसके वचनों की शब्दावलि पर ही अपने मत का निर्णय न करें; वरन् कार्यक्रम की, विशेषकर आर्थिक कार्यक्रम की उपयुक्तता, सुसंगति, व्यावहारिकता आदि पर भी विचार करें। चुनाव के सम्बन्ध में इससे अधिक सम्पदा के विचारशील पाठकों को कहना अनावश्यक समझते हैं।

सफ़ेद कोढ़ के दाग

हजारों के नष्ट हुए और सैकड़ों के प्रशंसापत्र मिल चुके

दवा का मूल्य ५) रु० डाक व्यय १) रु०

अधिक विवरण मुफ्त मँगाकर देखिये।

वैद्य के० आर० बोरकर

मु० पो० मंगरूलपीर, जिला अकोला (मध्य प्रदेश)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

१९५६ में देश की आर्थिक वृत्तियां

संक्षिप्त सिंहावलोकन

[श्री कृष्णचन्द्र विद्यालंकार]

जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण

१९५६ का वर्ष जहां देश में राज्यों के पुनर्गठन की महत्वपूर्ण घटना के द्वारा राजनैतिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा है, वहां आर्थिक दृष्टि से भी कम महत्वपूर्ण नहीं रहा। यों तो इस वर्ष देश में आर्थिक दृष्टि से बहुमुखी विविध घटनाएँ हुई हैं, जिनमें से कुछ का इस लेख में उल्लेख हम करना चाहते हैं, तथापि यदि इस वर्ष की सब से महत्वपूर्ण कोई आर्थिक प्रवृत्ति रही है, तो वह देश की समाजवादी लक्ष्य की दिशा में प्रगति रही है। १६ जनवरी को भारत के वित्त मंत्री श्री चिन्तामणि देशमुख ने रेडियो पर अकस्मात् ही जीवन बीमा उद्योग के राष्ट्रीयकरण की घोषणा करके देश को विस्मित और स्तब्ध कर दिया था। इससे ६ मास पूर्व इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके समाजवादी आर्थिक रचना की ओर एक बड़ा कदम उठाया गया था। उसी समय निजी क्षेत्रों में यह आशंका उत्पन्न हो गई थी कि राष्ट्रीयकरण का यह सूत्रपात निकट भविष्य में अनेक बड़ी संभावनायें निहित किए हुए है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण की संभावना की जा रही थी, किन्तु बीमा कम्पनियों पर सरकार की दृष्टि गई और एक घोषणा द्वारा देश के बहुत बड़े उद्योग पर सरकार ने एकाधिकार कर लिया। यह क्रान्तिकारी कदम उचित था या नहीं, इस विवाद में आज पड़ना अनावश्यक है। किन्तु यह सफल हुआ या नहीं, यह एक वर्ष के कार्य विवरण को देखकर ही कहा जा सकेगा। यदि इसने कारोबार में उन्नति की, तो यह सफल माना जायेगा अन्यथा असफल।

नई उद्योग नीति

समाजवादी लक्ष्य की ओर देश ने प्रगति करनी है—यह उद्देश्य हमारे सामने वर्ष भर रहा है। जिस दूसरी पंचवर्षीय योजना का इसी वर्ष प्रारम्भ हुआ, उसमें उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की दिशा में प्रगति की नीति अपनाई गई। पं० जवाहरलाल नेहरू ने जिस नई औद्योगिक नीति की घोषणा की, उसमें भी सरकारी उद्योगों का क्षेत्र बहुत बढ़ा दिया गया। समस्त उद्योगों को ३ भागों में बांटा गया। १७ उद्योगों पर सरकार के एकाधिकार की घोषणा की गई, यद्यपि साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि इस क्षेत्र के वर्तमान निजी उद्योगों को लेने का कोई इरादा नहीं है। टाटा आदि लोह उद्योग अपना विस्तार भी कर सकेंगे। दूसरी श्रेणी के उद्योग सरकार और निजी क्षेत्र, इन दोनों के लिये खुले रखे गये। तीसरी श्रेणी में उन उद्योगों की गणना की गई, जिनके विकास का उत्तरदायित्व निजी क्षेत्र पर डाला गया। इस तरह यद्यपि १९४८ की मिश्रित अर्थनीति को कायम रखा गया, तथापि विशुद्ध सरकारी उद्योगों की सूची बढ़ाकर तथा अनेक ऐसे अधिकार अपने हाथ में रख कर निजी क्षेत्रों को चिंतित और भयभीत अवश्य कर दिया गया है। इसके अनुसार सरकार कोई भी (तीसरी श्रेणी के भी) उद्योग खोल सकेगी। इसके साथ ही निजी क्षेत्रों को भी यह अनुमति देने की गुंजाइश रखी गई कि वे अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिये अथवा सह उत्पादन के रूप में प्रथम श्रेणी के अंतर्गत उत्पादन प्रारम्भ कर सकें। यद्यपि परिवहन और बिजली सरकारी क्षेत्र में रखे गये, तथापि छोटी निजी फ़र्मों को अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिये हलकी नावें बनाने अथवा बिजली पैदा करने के अधिकार दिये गये। इस नई उद्योग नीति की दो विशेषताएँ और थीं। एक तो यह कि लघु और ग्राम उद्योगों पर अधिक बल दिया गया और दूसरी यह कि देश के विभिन्न भागों को औद्योगिक दृष्टि से विकसित करने की नीति अपनाई गई। अब उद्योगों का विकास नई नीति को सामने रखकर किया जा रहा है।

व्यापारी क्षेत्र में

समाजवादी समाज की दिशा में कुछ और भी प्रयत्न किये गये। स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन के हाथ में खनिज द्रव्यों के आयात निर्यात के काम सौंपने शुरू किये गये। यह भी सुझाव रखे गये कि विदेशी गेहूँ के वितरण का काम इस कार्पोरेशन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

को सौंप दिया जाये। इसका निजी क्षेत्रों में बहुत विरोध किया गया। फलतः सरकार को अपनी नीति शिथिल करनी पड़ी, फिर भी यह आशा की जा सकती है कि इस कार्पोरेशन द्वारा सरकार व्यापारिक क्षेत्र में भी अबाध प्रवेश करना चाहती है।

प्रभावकारी बैंक कानून

जो वर्ष जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण के द्वारा प्रारम्भ हुआ, उसकी समाप्ति नये बैंक कानून से हुई है। इस कानून के द्वारा सरकार ने बैंकों के कार्य संचालन में इतने अधिक अधिकार प्राप्त कर लिये हैं कि एक आलोचक के शब्दों में राष्ट्रीयकरण का नाम न लेते हुए भी बैंकों पर सरकार का पूर्ण अधिकार हो गया है। अब बैंकों के डाइरैक्टर कुछ भी करेंगे, सरकार को उसकी पूरी जानकारी रहेगी और कोई भी डायरेक्टर सरकारी अनुमति के बिना नहीं बन सकेगा। शेयर होल्डरों के वोट देने का अधिकार भी सीमित कर दिया गया है।

७७ अरब रु० की योजना

१९५६ दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ के लिए प्रसिद्ध रहेगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल मार्च १९५६ में समाप्त हुआ। अनेक कमियों के बावजूद वह योजना जिस तरह सफल रही उस पर देश गर्व कर सकता है। अप्रैल से दूसरी योजना का प्रारम्भ हुआ। प्रथम योजना का व्यय लक्ष्य २३ अरब रु० था, दूसरी योजना का लक्ष्य उससे बहुत अधिक रखा गया। पहले प्रारूप में ४३ अरब रु० व्यय नियत किया गया पर बाद में बढ़ाकर ४८ अरब रुपये कर दिया गया और इस वर्ष के अन्त में यह घोषणा की गई कि अनेक पदार्थों के विदेशों में मूल्य बढ़ जाने तथा योजनाओं के कुछ कार्य बढ़ा देने के कारण ४-५ अरब रु० अधिक अर्थात् ५३ अरब रु० व्यय होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रथम योजना की अपेक्षा २॥ गुना बड़ी दूसरी योजना बनाई गई। यह सब राशि सरकार को व्यय करनी है। इसके अतिरिक्त २४ अरब रु० निजी उद्योग से विकास कार्यों में विनियोग करने की आशा प्रकट की गई है। ७७ अरब रु० की विराट् योजना जिस समय पूर्ण हो जायगी, उस समय भारत की अनेक आर्थिक समस्याओं के हल हो जाने की आशा हम कर सकते हैं।

विराट् राशि के व्यय लक्ष्य के अतिरिक्त इस योजना की दूसरी विशेषता यह है कि यदि प्रथम योजना कृषि प्रधान थी, यह उद्योग प्रधान है। लोहा, इस्पात, रासायनिक पदार्थ, बिजली के भारी कारखाने, मशीन निर्माण आदि पर अधिक बल दिया गया है। इसका उद्देश्य देश को उद्योग और मशीनरी की दृष्टि से स्वावलम्बी बनाना है।

प्रतिकूल वित्तीय स्थिति

इन बड़े-बड़े लक्ष्यों को कागज पर लिखने से काम नहीं चलता। मुख्य प्रश्न तो यह है कि ५३ अरब रु० आयेगा कहां से? जब योजना बनाई गई थी, तब भी इसका अंतिम निर्णय नहीं हुआ था। १२०० करोड़ रु० घाटे से, अर्थात नासिक नोट छापने के प्रैस से, ८०० करोड़ रु० की विदेशी सहायता, ५००करोड़ रु० के नये कर आदि का अनुमान कर के भी ४०० करोड़ रु० की राशि बच गई थी, जिसका कोई साधन योजना आयोग निश्चित नहीं कर पाया था। अब योजना के व्यय लक्ष्य ५ अरब रु० बढ़ा दिये गये हैं। इसलिए यह एक कठिन समस्या बन गई है। भारत की समाजवादी नीति और अनेक राजनैतिक प्रश्नों पर अमेरिका व ब्रिटेन से मतभेद के कारण यही संदिग्ध हो गया कि विदेशों से ८ अरब रु० की राशि प्राप्त हो भी सकेगी या नहीं? पं० नेहरू की अमेरिका यात्रा से यह संभव है कि अमेरिका का सहयोग अधिक मात्रा में प्राप्त होने लगे। यदि ऐसा हो सका, तो वित्त समस्या के हल में यह सहायक होगा। सरकार ने नये-नये कर लगाकर इसे पूर्ण करने का भी प्रयत्न किया है। श्री देशमुख ने बजट में कुछ नये कर लगाये थे, श्री कृष्णमाचार्य ने वित्त मंत्री बनते ही दो बार अगस्त और नवम्बर में नये नये टैक्स लगाने की घोषणा की है। पहली घोषणा द्वारा वस्त्रों पर उत्पादन कर बढ़ाया गया। दूसरी घोषणा करके पूंजीगत लाभ पर कर लगाये गये। एक नये प्रस्ताव द्वारा सरकार ने उत्पादन कर को ५० प्रतिशत तक बढ़ाने का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। देखना यह है कि किस सीमा तक जनता कर देने की क्षमता रखती है। पूंजीगत लाभ पर कर लगाने से निजी उद्योग को यह आशंका हो गई है कि नये उद्योगों के लिए पूंजी निर्माण की प्रगति रुक जायगी। यदि सरकार ने इसकी कोई व्यवस्था न की, तो इसमें संदेह नहीं कि यह खतरा औद्यो-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गिक उन्नति में रुकावट जरूर पैदा करेगा।

कुछ विचारक तो यह कहने लगे हैं कि योजना का आधार देश की शक्ति से बाहर है, इसे या तो छोड़ दिया जाय अथवा ५ की बजाय ७ वर्षों तक इसकी अवधि बढ़ाई जाय। मुद्रा प्रसार के कारण देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। मूल्यों के सूचक अंक बहुत ऊंचे हो गये हैं। मौनसून के भी साथ न देने के कारण कृषि-उत्पादन भी कम हो गया और फिर विदेशों से अन्न का आयात इस वर्ष की एक शोचनीय घटना है। कृषि विभाग योजना आयोग से अतिरिक्त राशि मांग रहा है, पर आयोग रुपये की कमी परिश्रम से पूर्ण करने और ४० प्रतिशत उत्पादन बढ़ाने के लिए जोर दे रहा है। देखें, इस समस्या का समाधान कैसे होता है? अन्न के आयात से विदेशी मुद्रा बहुत कम होगी, यों भी विदेशी व्यापार, आयात-निर्यात का संतुलन हमारे प्रतिकूल जा रहा है। करीब २७ करोड़ रु० हम प्रति मास अपनी जेब से खो रहे हैं। हमारे रिजर्व फण्ड बहुत कम ही रहे हैं। योजना की पूर्ति के लिए मशीनरी का भारी आयात देश के मेरु दण्ड पर एक भार साबित हो रहा है। वस्त्रादि के निर्यात भी इस वर्ष कम हुए हैं। वर्ष के अन्तिम चरण में आयात पर कुछ प्रतिबन्ध अवश्य लगाये गये हैं, किन्तु वे कहाँ तक विदेशी व्यापार का सन्तुलन ठीक कर सकेंगे, यह सन्दिग्ध है। ठीक समय रूरकेला में स्थापित होने वाले इस्पात-उद्योग के लिए जर्मन कम्पनी ने रुपया देने से इन्कार कर दिया है। इस तरह नई योजना के लिए वित्तीय साधनों की दुर्लभता अधिकाबढ़ती जा रही है। ब्रिटिश आक्रमण द्वारा स्वेज नहर के रुक जाने के कारण जहाजी भाड़ा बहुत ज्यादा होने का प्रभाव भी विदेशी सामग्री के मूल्यों पर पड़ रहा है। केन्द्र व राज्यों की सरकारों ने इस वर्ष जनता से भारी राशि में ऋण लेकर मुद्रा प्रसार की समस्या को एक सीमा तक सरल करने का प्रयास किया है।

मजदूर आन्दोलन

इस वर्ष मजदूर आन्दोलन की दिशा पर भी दो चार पंक्तियां लिखना अप्रासांगिक न होगा। इस वर्ष हड़तालें बहुत नहीं हुईं, किन्तु खड़गपुर और कालका में रेलवे मजदूरों ने जो दृश्य दिखाये, वे चिन्ताजनक थे। वर्ष के अन्त में राष्ट्रीय मजदूर संघ ने वेतन वृद्धि का देश व्यापी आधार पर संगठित आन्दोलन प्रारंभ किया है। इसका उद्देश्य जूट, कपड़ा, सीमैण्ट, कोयला, इंजीनियरिंग आदि सात प्रधान उद्योगों में वेतनों का धरातल नियत करने के लिए वेतन मण्डल नियत कराना है। औद्योगिक विवाद कानून में भी संशोधन करके अपीलेट ट्रिब्यूनल समाप्त करने की योजना की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कारोबार बन्द करने पर निकाले जाने वाले मजदूरों को 'छटनी' न मानने और उसके अनुसार सुविधाएं न देने का जो निर्णय किया है, वह मजदूर संघों को परेशान कर रहा है और अब संविधान में भी परिवर्तन की मांग की जा रही है।

औद्योगिक विकास की दृष्टि से यह वर्ष सफल रहा है। लोहे के तीनों कारखानों का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है। इनके बन जाने पर देश प्रायः स्वावलम्बी हो जायगा। अन्य भी सरकारी या गैर सरकारी उद्योगों के विकास में कम प्रयत्न नहीं हुआ। वस्त्र उद्योग में अम्बर चरखे तथा आटोमैटिक लूमों को लेकर बहुत विवाद रहा, यद्यपि अम्बर चरखे के प्रसार के लिए एक बड़ी राशि नियत की गई है, तथापि विजय आटोमैटिक लूमों की हुई है। १६००० नये आटोमैटिक लूम लगाने की अनुमति मिल गई है। हैण्ड-लूमों को भी पावर लूमों में बदलने की योजना चल रही है। इन दोनों उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि हमारे शासक किस दिशा में सोच रहे हैं।

अन्य घटनाएं

इस वर्ष की अन्य प्रमुख आर्थिक घटनाओं में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विविध क्षेत्रों में प्रगति के अतिरिक्त साधु समाज की स्थापना है। परन्तु यह समाज कहां तक सफल होगा, यह तब तक नहीं कहा जा सकता, जब तक इसके कार्य न देख लिये जावें। हमें भय है कि सरकारी खजाने का करोड़ों रुपया साधुओं को त्याग व संयम से काम नहीं करने देगा। लड़कियों के लिए उत्तराधिकार सम्बन्धी नया कानून देश के सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह कुछ समय बाद स्पष्ट हो सकेगा। सेल्स टैक्स से व्यापारियों व जनता को जो असुविधाएं हो रही हैं, उनकी तरफ सरकार का ध्यान अवश्य गया है। अगस्त में रिजर्व बैंक

(शेष पृष्ठ ४९ पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

देश के राजनैतिक दलों के आर्थिक कार्यक्रम

सम्पदा का यह अंक जब पाठकों के पास पहुंचेगा, देश में विभिन्न राजनैतिक दल अपना-अपना घोषणापत्र लेकर मतदाताओं को अपना कार्यक्रम बताकर वोट लेने की तैयारी कर रहे होंगे। हम इन पंक्तियों में देश की चार बड़ी संस्थाओं के आर्थिक कार्यक्रम के मुख्य अंश दे रहे हैं। पाठकों से हमारा अनुरोध है कि वे सबको पढ़कर स्वयं तुलनात्मक दृष्टि से उन पर विचार करें।

अ० भा० राष्ट्रीय कांग्रेस

श्री उ० न० ढेबर

कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्रीय और शांतिपूर्ण उपायों से समाज में पूर्ण समाजवादी व्यवस्था करना है। राष्ट्र के विकास और नवनिर्माण के लिये कांग्रेस प्रतिज्ञा बद्ध है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसी ओर प्रगति की गई है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना देश के खनिज स्रोतों का पूर्ण प्रयोग करके राष्ट्र को स्वावलम्बी बनाने की दिशा में एक दूसरा बड़ा कदम है। छोटे और बड़े उद्योगों के विकास द्वारा कांग्रेस देश को समृद्ध बनाने के लिये कृत संकल्प है। प्रथम योजना की सफलता से यह स्पष्ट है कि कांग्रेस अपनी नीति में सफल हो रही है।

भारतवर्ष की नवीन क्रांति केवल तभी पूर्ण होगी जबकि राजनीतिक क्रांति के बाद आर्थिक और सामाजिक क्रान्ति भी हो। इसी दिशा में देश चल रहा है और हम तब तक प्रयत्न करते रहेंगे जब तक देश में पूर्ण सामाजिक व्यवस्था स्थापित न हो जाये, जिससे सब देश वासियों को स्वतन्त्रता, मंगलहित और अवसरों व सुविधाओं की समानता न मिलने लग जाये।

हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये शान्तिपूर्ण प्रयत्नों को केवल इसीलिये नहीं अपना रहे कि वे प्राचीन ऋषियों तथा अशोक से गांधीजी तक की भारतीय परम्परा के अनुकूल हैं, वरन् इसलिये भी अपना रहे हैं कि हम इन्हीं के द्वारा देश की एकता स्थापित रख सकते हैं।

आर्थिक सम्बन्धों में शोषण और एकाधिकार को समाप्त कर देना चाहिये। और आय की भारी विषमताओं को भी क्रमशः कम करना चाहिये। राष्ट्रीय जीवन का एक न्यूनतम स्तर जिसमें जीवन की सब आवश्यकतायें—जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन काम की सुविधायें सम्मिलित हैं—नियत करना चाहिये। जो प्रत्येक नागरिक को सुलभ हो। आज विभिन्न श्रेणियों की तरह देश के भिन्न भिन्न भागों में भी परस्पर असमानता है। इसे दूर करने के लिये अविकसित खण्डों को अधिक उन्नत करना चाहिये।

हमारे समाजवादी व्यवस्था का उद्देश्य समाजवादी सहकारी कामनवैल्थ बनाना है। सहकारिता मानव उन्नति के लिये आवश्यक है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में और विशेषकर उद्योग और कृषि में सहकारिता के तत्त्वों का समावेश करना चाहिये। मजदूरों के उद्योग में निरन्तर अधिकाधिक भाग लेने से हमें औद्योगिक लोकतंत्र स्थापित

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

करना चाहिये। और ग्रामों में सारी प्रवृत्तियां को सहकारिता के आधार पर होनी चाहिये। गरीबी को दूर करना और प्रगतिशील अर्थनीति की स्थापना अत्यन्त कठिन कार्य है। इसके लिये समस्त राष्ट्र को मितव्यता तथा संयम से काम लेना होगा। रहन-सहन का आडम्बर और झूठी शान छोड़नी होगी। नव भारत का निर्माण उद्योग व कृषि दोनों के विकास पर निर्भर है। इसके लिये अधिकाधिक बचत तथा योजना कार्यों में अधिकाधिक विनियोग आवश्यक है।

हमें एक ओर जहां भारी उद्योगों के विकास पर बल देना है वहां उसका कृषि से भी संतुलन नहीं खोना है। छोटे और ग्रामोद्योगों की उपेक्षा भी हम नहीं कर सकते। एक ओर आधुनिक जीवन में हमें केन्द्रीयकरण करना है, दूसरी ओर अर्थ-व्यवस्था के विकेन्द्रीकरण को भी बढ़ाना है। क्योंकि हमारी समस्या गरीबी और बेकारी को दूर करना है। हमें आधुनिक उत्पादन विधियों को प्रोत्साहित करते हुए यह नहीं भूलना है कि देश के विशाल जन-बल का भी प्रयोग करना है। तभी हम बेकारी की समस्या दूर कर सकेंगे।

विदेशों से मित्रतापूर्ण सहयोग का स्वागत करते हुए भी हमें अपने की साधनों पर निर्भर होना पड़ेगा। लेकिन यह भार इस तरह उठाना होगा कि समर्थ आदमियों पर अधिक जिम्मेदारी आये। इसी नीति के आधार पर नये कर लगाये जाने चाहियें।

कांग्रेस स्टेट बैंक, बीमा उद्योग के राष्ट्रीयकरण का स्वागत करती है। भारत सरकार द्वारा उद्योग नीति की घोषणा से सरकारी और गैर सरकारी निजी क्षेत्रों के लिये उद्योगों के क्षेत्र सुरक्षित कर दिये हैं। अत्यन्त आवश्यकता के बिना वर्तमान निजी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायेगा। नई उद्योग नीति को प्रोत्साहित किया जायेगा। वे योजना पूर्ति में सहायक होने चाहिये।

विकासशील उद्योग व्यवस्था में मंहगाई और मुद्रा प्रसार कुछ तो अनिवार्य है, परन्तु इन पर नियंत्रण किया जाएगा। जमीन के बोने वालों और सरकार के बीच सब प्रकार के मध्यस्थ हटा दिये जायेंगे। भूमि की अधिकतम सीमा नियत कर दी जायेगी। ताकि भूमि का अधिक वितरण हो सके। यांत्रिक कृषि कुछ क्षेत्रों में उपयोगी हो सकती है किन्तु देश में विशाल जन संख्या के उपलब्ध होते हुये सहकारिता के सिद्धान्त पर गहरी खेती को प्रोत्साहन देना अधिक उचित होगा। हमें यह नहीं भूलना कि हमारा मुख्य लक्ष्य उत्पादन बढ़ाना है। अतः छोटी और बड़ी सिंचाई योजनाओं को तथा अच्छे बीज, अच्छे हल खाद आदि की व्यवस्था को विकसित करना होगा।

सामुदायिक योजनाओं और राष्ट्रीय विकास खण्डों को कृषि के अधिक उत्पादन तथा ग्रामोद्योगों के विस्तार में विशेष सहायक होना चाहिये। तभी ग्रामों और नगरों की असमानता कुछ कम हो सकती है।

अशिक्षितों और शिक्षितों दोनों की बेकारी दूर करना कठिन सा विषय है। इसके लिये उद्योग सम्बन्धी शिक्षा, उद्योगों का विस्तार आदि की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।

शराब बन्दी कांग्रेस की बहुत समय से नीति रही है। इस ओर और भी अधिक कदम उठाना चाहिये।

औद्योगिक शान्ति आवश्यक है; इसलिये हड़तालों और ताला बन्दियों को निरुत्साहित करना चाहिये।

अखिल भारतीय जनसंघ

भारतीय जनसंघ का लक्ष्य केन्द्रीय शासन को सुदृढ़ बनाते हुए राजनीतिक एवं आर्थिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण करना है।

१. देश की अन्न, वस्त्र तथा निवास की समस्या सुलझाने तथा आर्थिक आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए जनसंघ किसी वाद-विशेष से बन्धा हुआ नहीं है। [उत्पादन में वृद्धि, वितरण में औचित्य तथा उपभोग में संयम के द्वारा ही आर्थिक समस्या का निराकरण हो सकता है। इस दृष्टि से जनसंघ का विश्वास है कि पूर्ण राष्ट्रीयकरण अथवा निजी उद्योग, दोनों में से किसी एक के द्वारा समस्या को सुलझाया नहीं जा सकता। राज्य के आर्थिक सामर्थ्य का कुछ हाथों में केन्द्रीयकरण जिस प्रकार व्यक्तिगत पूंजी-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वाद को जन्म देता है, उसी प्रकार पूर्ण राष्ट्रीयकरण का सिद्धान्त राजकीय पूंजीवाद की स्थापना करेगा। जिसकी परिणति अधिनायकवाद में होगी।] जनसंघ ऐसी अर्थ-व्यवस्था का विकास करेगा, जिसमें निजी उद्योग एवं राष्ट्रीयकरण, दोनों को मर्यादित करते हुए व्यक्तिगत प्रयत्न के लिए पूर्ण अवसर रहे।

श्री देवप्रसाद घोष

२. जनसंघ प्रत्येक नागरिक के जीवनोपार्जन के अधिकार को स्वीकार करता है। संविधान द्वारा स्वीकृत मौलिक अधिकारों में आजीविका के लिए कर्म के अधिकार का भी समावेश होना चाहिए।

३. जनसंघ समाज के विभिन्न वर्गों की आय के अन्तर में कमी करने के लिए धन का सम वितरण तथा सभी नागरिकों को जीवन-निर्वाह के न्यूनतम स्तर का आश्वासन देगा। वर्तमान परिस्थितियों में इस दृष्टि से अधिकतम आय २०००) रु० प्रतिमास तथा न्यूनतम १००) रु० प्रति मास निर्धारित कर यह प्रयत्न किया जाय कि न्यूनतम आय निरन्तर बढ़ती रहे, जिससे दृश्यमान भविष्य में अधिकतम और न्यूनतम आय के अन्तर का अनुपात १:१० का हो जाय।

४. जनसंघ राष्ट्रीय उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन और राष्ट्रीय उद्योगों को अनुचित विदेशी प्रतियोगिता से बचाने के लिए संरक्षण प्रदान करेगा। इसके लिए पूंजी, श्रम तथा उपभोक्ता तीनों का सहयोग प्राप्त करेगा।

जनसंघ विभिन्न प्रकार के उद्योगों की शीघ्र स्थापना चाहता है, जिससे देश सुरक्षा, उत्पादक तथा उपभोग्य वस्तुओं की दृष्टि से आत्म-निर्भर हो सके।

छोटे तथा ग्रामोद्योग

छोटे छोटे धन्धे तथा ग्रामोद्योग जनसंघ की अर्थनीति का आधार हैं। [सभी स्वस्थ व्यक्तियों के लिए काम की व्यवस्था करने तथा उपभोग्य वस्तुओं की दृष्टि से देश को आत्म-भरित बनाने के लिए सम्पूर्ण देश में छोटे कुटीर तथा ग्राम उद्योगों का जाल फैलाना होगा। राज्य का कर्तव्य है कि वह बड़े तथा छोटे उद्योग-धन्धों के कार्यक्षेत्र का स्पष्ट निर्धारण करे, जिससे सिद्धान्ततः उपभोग्य वस्तुएं केवल छोटे उद्योगों के आधार पर तथा उत्पादक वस्तुएं बड़े उद्योगों के द्वारा तैयार होनी चाहियें।

छोटे उद्योगों के विकास के लिए निम्न साधन उपयोग में लाये जायेंगे —

१—जल विद्युत-शक्ति का शीघ्रतर और अधिक उत्पादन।

२—ग्रामोपयोगी छोटी मशीनों और कलों द्वारा अर्वाचीन पद्धति से उद्योग चलाने की शिक्षा गांवों के श्रमिकों को देने के लिए औद्योगिक शिक्षालयों की स्थापना।

३—ग्रामोद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के लक्ष्य घटित सुविधायें पहुंचाना।

४—संयुक्त और सहकारी उद्योगों को प्रोत्साहन देना।

बड़े उद्योग

जनसंघ की नीति आधारभूत तथा सुरक्षा-उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने की है। अन्य उद्योगों को उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के हितों का ध्यान रखते हुए शासन के निरीक्षण और नियन्त्रण के आधीन विकसित होने का पूर्ण अवसर मिलना चाहिए। देश की आर्थिक शक्ति को कुछ हाथों में केन्द्रित होने से रोकने तथा अनुचित लाभ उठाने की वृत्ति को नियन्त्रित करने के लिए जनसंघ आवश्यक एवं प्रभावी कार्यवाही करेगा।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

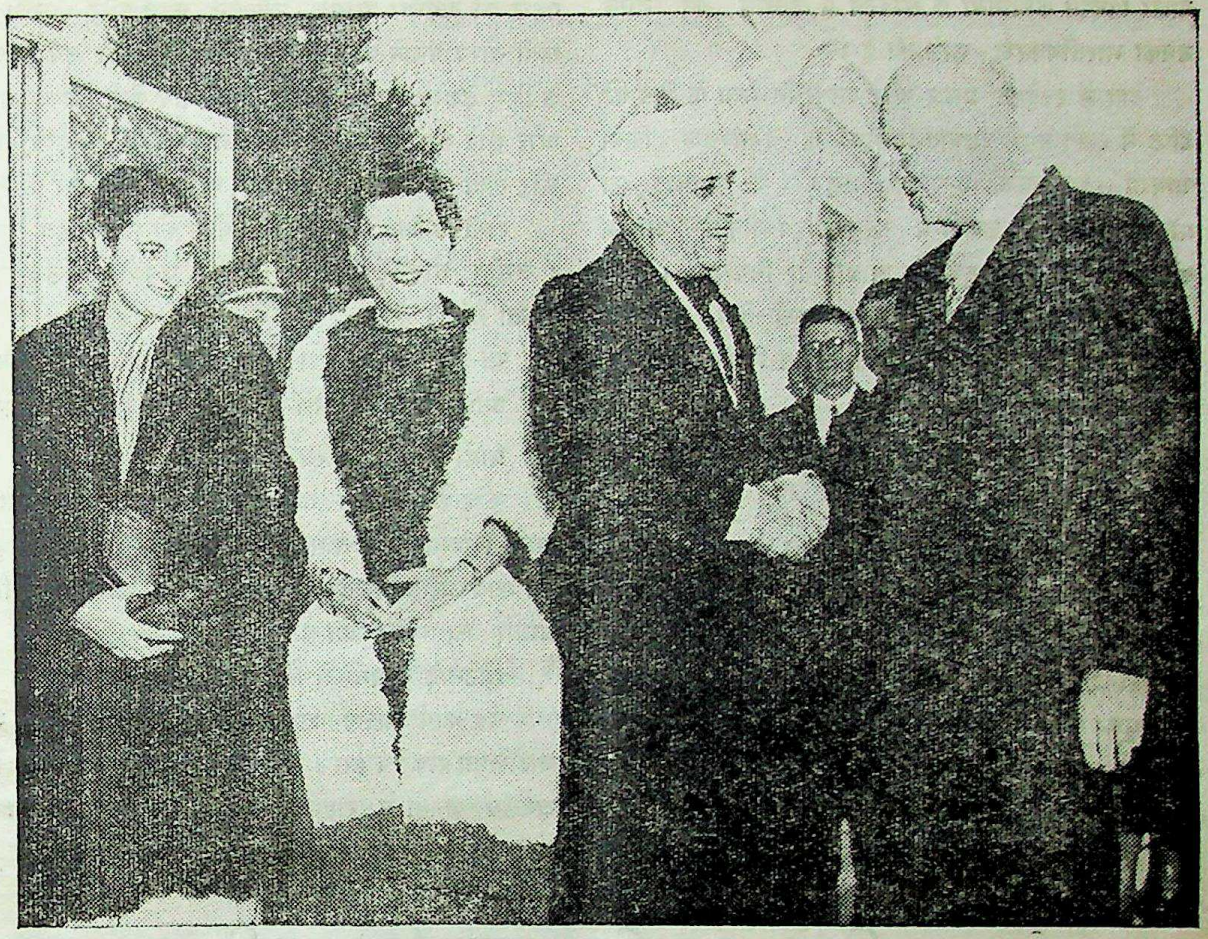

पं० जवाहरलाल नेहरू की अमरीका यात्रा और प्रेजिडैण्ट आइजन हावर की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक भेंट का प्रभाव विश्व शान्ति की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर क्या होगा, उसकी विविध कल्पनाएं की जा रही हैं किन्तु इस चर्चा से आर्थिक क्षेत्र में भारत को अमेरिकन सहयोग की अनेक सम्भावनाएं बहुत बढ़ गई हैं और इस दृष्टि से यह चर्चा बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। चित्र में पं० नेहरू और इन्दिरा गांधी राष्ट्रपति आइजन-हावर व उनकी पत्नी के साथ खड़े हैं।

पूंजी और श्रम का सम्बन्ध

जनसंघ वर्ग-विद्वेष एवं वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को अशुद्ध एवं अहितकर मानता है। पूंजी तथा श्रम एक दूसरे के विरोधक नहीं, पूरक हैं। जनसंघ श्रम को उद्योग के लाभ तथा प्रबन्ध में साझीदार बनाने का प्रयत्न करेगा।

वित्त-संचय तथा उत्पादक उद्योगों में उसके विनियोग के लिए देश में बेकार पड़े हुए धन को आकर्षित करने के लिए ग्रामों में बैंक खुलवाये जायेंगे और ग्राम-जनों तथा उनकी फसलों तथा पशुओं के बीमे की प्रथा चलाई जायगी।

विदेशी सहायता

देश के आर्थिक उत्थान के लिए जनसंघ स्वावलम्बन पर बल देगा। उत्पादक वस्तुओं के उद्योगों की स्थापना के निमित्त विदेशी सहायता को स्वीकार किया जायगा, किन्तु इस बात का ध्यान रखा जायगा कि विदेशी सहायता के साथ कोई राजनीतिक शर्त न बंधी हो। देश में चलने

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वाली विदेशी कम्पनियों के सम्बन्ध में जनसंघ की नीति उनका भारतीयकरण करने की है।

देश में स्वदेशी प्रसार और आत्म-निर्भरता के हित को दृष्टि में रखते हुए आयात-निर्यात का नियन्त्रण किया जायगा—आवश्यक उत्पादक वस्तुओं के आयात को प्रोत्साहन और उपभोग्य वस्तुओं विशेषकर आराम और प्रसाधन की वस्तुओं के आयात पर नियन्त्रण।

आन्तरिक व्यापार की दृष्टि से सम्पूर्ण देश को एक इकाई माना जायेगा। अन्तर्राज्यीय बिक्री-कर समाप्त किया जायेगा।

कृषि-नीति

भूमि-सुधार

उत्पादन की वृद्धि तथा ग्राम समाज की पुनर्रचना के लिए जनसंघ भूमि व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करेगा। जागीरदारी तथा जमींदारी-प्रथा का अन्त कर कृषकों और भूमिहीनों में भूमि का वितरण कर दिया जायेगा। वितरण का न्यूतमम एवं अधिकतम आधार सिंचाई के प्रबन्ध से युक्त अच्छी भूमि का क्रमशः ५ एकड़ एवं ३० एकड़ होगा।

उत्पादन-वृद्धि के लिए जनसंघ बोई हुई धरती पर पहले की अपेक्षा अधिक उत्पादन करने और धरती को खेती योग्य बनाने पर बल देगा तथा खेती की उपज बढ़ाने के लिए देशव्यापी आन्दोलन, बिखरे हुए खेतों की चकबन्दी और छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन पर रोक, बढ़िया बीज और खेती की अर्वाचीन पद्धतियों का गांव में प्रचार करेगा।

खेती के लिए ट्रैक्टरों के प्रयोग को निरुत्साहित करेगा (जमीन तोड़ने के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है।)

गो-वंश संवर्धन तथा गोचर भूमि का प्रबन्ध करना।

अधिकाधिक आत्म-निर्भर आदर्श गांवों की स्थापना

ग्रामों में डेयरियां स्थापित करना।

कृषि के सहायक तथा पूरक उद्योगों की स्थापना करना। अन्य कुटीर तथा छोटे उद्योगों में सुधार करके न्यूनतम व्यय में अधिकतम उत्पादन करना और उनके लिए बाजार का प्रबन्ध करना।

छोटे-बड़े साधनों से सिंचाई का प्रबन्ध करना।

यह कार्य केवल शासन द्वारा सफलतापूर्वक नहीं चलाये जा सकते। इसके लिए जन-सहयोग आवश्यक है। जनसंघ जनता के राष्ट्रसेवा भाव को जागृत कर इन कामों को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में चलायेगा।

——

अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी

उद्योग

(१) उद्योगों के विकास में बड़े और आधारभूत उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी। इनमें लोहे और इस्पात, मशीन बनाने सम्बन्धी उद्योग सम्मिलित हैं और ये राज्य के स्वामित्व में रहेंगे।

(२) विदेशी प्रतिस्पर्द्धा से स्वदेशी उद्योगों का संरक्षण किया जाएगा।

(३) उद्योगों की स्थापना किसी स्थान पर इस दृष्टि से की जाएगी कि उसके आस पास के क्षेत्रों के प्राकृतिक साधनों के पूर्ण उपयोग के साथ ही साथ उन क्षेत्रों का संतुलित विकास भी हो सके। पिछड़े राज्यों में जहां छोटे-छोटे उद्योगों तक के लिए पूंजी की प्राप्ति की संभावना नहीं है वहां शासन उद्योगों की स्थापना और संचालन करेगा।

(४) राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अस्त्र-शस्त्र, हवाई जहाजों और समुद्री जहाजों के निर्माण के लिए उद्योगों की स्थापना की जाएगी।

(५) देश की उपयोग की वस्तुओं की पूर्ति के लिए संगठित उद्योगों का पूर्ण उपयोग किया जाएगा और छोटे और ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में इस उद्योग-नीति के लिए साधन इस प्रकार जुटाए जाएंगे —

(क) बैंक–बीमा से आरंभ करके बाद में शीघ्र ही कोयलों की खानों तथा अल्यूमीनियम, मेंगनीज, तांबा, लोहे, सोने की खानों तथा अंग्रेजों की जूट मिलों और चाय-बागानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा।

(शेष पृष्ठ ४७ पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

निजी उद्योगों का राष्ट्रविकास में स्थान

श्री ए० डी० श्राफ़

निजी उद्योगों के विषय में पिछले कुछ समय से बहुत कुछ कहा गया है। इन आलोचनाओं में से तीन बातें उल्लेखनीय हैं। पहली बात यह कि निजी उद्योग देश में बड़े पैमाने पर तीव्र औद्योगिक उन्नति में असमर्थ हैं। कुछ लोगों के हाथ में सारी आर्थिक शक्ति केन्द्रित हो रही है। इनसे भी अधिक चिन्तनीय बात यह कही गई है कि निजी उद्योग और प्रजातन्त्र बेमेल हैं। याद रहे, अंतिम बात और किसी ने नहीं, वरन् स्वयं हमारे प्रधानमंत्री ने कही है।

अतीत पर एक दृष्टि

इन उक्तियों पर विचार करने के पूर्व निजी उद्योगों के इतिहास पर सरसरी निगाह डाल लेनी चाहिए। भारत की स्वतंत्रता के पूर्व के ६० वर्ष विदेशी शासन का वह काल है, जिसमें उद्योगों के विकास को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था। कर, यातायात की सुविधा और भाड़े के निर्धारण में बरती जाने वाली नीतियों का उद्देश्य ही देश में उद्योगों का विकास ही न होने देना था। पर फिर भी निजी उद्योग इन कठिन परिस्थितियों से जूझते रहे और अपने विकास का मार्ग साफ करते रहे। बाद में सरकार ने अवश्य अनिच्छा से संरक्षण की नीति अपनाई, पर इस नीति से भी उद्योगों को कोई प्रोत्साहन न मिला। उन्नति हुई अवश्य और उसका कारण थे निजी उद्योग। निजी उद्योगों ने उन्नति ही नहीं की, वरन् आज देश की गणना 'विश्व के प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रों में होने लगी है और उसका स्थान आठवां है।

एक दो उदाहरण देने से यह बात स्पष्ट हो जाएगी। ४० वर्ष पहले हम प्रतिवर्ष ६० करोड़ रुपए के कपड़े बाहरी देशों से मंगाया करते थे। लेकिन आज स्थिति यह है कि हमने अपने उद्योगों को सुदृढ़ ही नहीं किया, वरन् हम कपड़े का निर्यात भी करने लगे हैं। विश्व के ४०-५० बाजार हमारे हाथों में हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि लंकाशायर और जापान के साथ कैसी स्पर्द्धा रही होगी। इसी बात से इस उद्योग की कुशलता व उत्तमता का अनुमान लगाया जा सकता है।

लेखक

इस्पात के उद्योग में श्री ज० न० ताता की सेवाएं अवर्णनीय हैं। जब श्री ताता ने भारत में लौह उद्योग के स्थापना का निश्चय किया तो कलकत्ता में एक अङ्गेज व्यापारी ने इसे हास्यास्पद बताया था। उसने दंभ के साथ यह भी कहा कि भारत में बने समस्त लोहे को वह अकेला ही प्रयुक्त कर लेगा। सौभाग्य से वह सज्जन आज जीवित नहीं हैं। यदि जीवित होते तो अवश्य ही उन्हें अजीर्ण हो जाता। उन्हें समस्या का सामना करना पड़ता कि इतने उत्पादन का उपयोग वे कैसे करें? यह सब निजी उद्योगो के कारण ही सम्भव हुआ है कि आज भारत राष्ट्र मंडल में एक मात्र सर्वाधिक लौह-उत्पादक राष्ट्र है। हमें इस बात का गर्व है कि यह देश संसार में सर्वाधिक मितव्ययतापूर्ण और सस्ता इस्पात निर्माताओं में परिगणित होता है।

इसी प्रकार जल विद्युत के विकास का सारा श्रेय निजी उद्योगों को ही है और इसी जल विद्युत की शक्ति के कारण बम्बई आधुनिक औद्योगिक नगरी बन सकी है।

यह सब तब हुआ जब कि देश परतंत्र था – विदेशियों से हमें संघर्ष करना पड़ता था, हमारे साधन सीमित थे, हमें नाममात्र को भी कोई सुविधा प्राप्त न थी।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पहले भी निजी उद्योगों की देश के विकास में रुचि थी। १९४५ में ही भारत के ७ प्रमुख उद्योग-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पतियों ने मिलकर भारत के आर्थिक विकास की योजना प्रस्तुत की थी। इसके अनुसार १५ साल की कालावधि में १०,००० करोड़ रुपए खर्च होते थे, जिनमें से उद्योगों पर ४,४०० रुपए व्यय होते।

आज भी

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी जब सरकार स्वयं विकास कार्य में लीन हैं, तब भी निजी उद्योगों ने उत्पादन बढ़ा कर देश के विकास में महान योग दिया। नीचे १९४६ को आधार वर्ष १०० मान कर उत्पादन वृद्धि के आंकड़े दिए जा रहे हैं—

	१९५१	१९५५
वस्त्र उद्योग	१०१	१२७
जूट का माल	८०	९४
सीमेंट	२०७	२८६
इस्पात	११६	१३२
कागज गत्तां	१२४	१७४
दियासलाई	१४०	१४७
चीनी	१२१	१७३

ये तो जमे जमाए उद्योग रहे। पर जिन उद्योगों को स्थापित हुए कुछ ही वर्ष हुए, उनके उत्पादन में भी इसी प्रकार वृद्धि हुई

मशीन	५२	८२
डीजल इंजिन	१५३२	२१८४
साइकिल	२६६	११४३
सिलाई की मशीनें	७२६	१६५६
विद्युत गाड़ियां	३११	५४९
सोडा	३९६	६४४
कास्टिक सोडा	५०८	११८१
सुपर फासफेट	१३५६	१५९८

यह भी उल्लेखनीय है कि ४-५ सालों में हमारा देश रेयन यार्न में आत्म निर्भर हो जाएगा। स्टील पाइप, औटोमोबाइल के उद्योगों ने भी काफ़ी उन्नति की है।

मेरा विश्वास है कि यदि निजी उद्योगों को कुछ नियन्त्रण के कठोर प्रतिबन्ध के अनुसार काम न करना होता तो इससे भी अधिक अच्छे परिणाम मिलते। उद्योगों से सम्बन्धित एक समिति में रहने के नाते मुझे देश के प्रायः प्रत्येक भाग में जाने का अवसर मिला है। इसी दौरान में मुझे ज्ञात हुआ कि सरकार की वर्तमान अर्थनीति के कारण उद्योगों में काफी अनिश्चितता है और वे पूंजी लगाने में हिचक रहे हैं।

सरकार की १९४८ में घोषित आधारभूत उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की नीति से निजी उद्योग को धक्का लगा। वायु-यातायात के राष्ट्रीयकरण से जो अविश्वास फैला ही था कि इम्पीरियल बैंक और बीमा कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण से वह बिल्कुल पक्का हो गया और अब स्थिति यह हो गई है कि कोई भी उद्योगों में पूंजी लगाने का साहस नहीं कर पाता। इस वर्ष की घोषित सरकारी औद्योगिक नीति से उद्योगों और व्यापारियों दोनों में असन्तोष और भी बढ़ गया है।

अर्थ शक्ति केन्द्रित नहीं हुई

अब दूसरी आलोचना पर भी विचार कर लेना चाहिए कि निजी उद्योग में कुछ व्यक्तियों के हाथ में सारी अर्थशक्तियां केन्द्रित हो गई हैं। इस प्रकार कुछ व्यक्ति बड़े-बड़े फर्मों को अपने अधिकार और नियन्त्रण में लेने का विशेष उत्साह दिखाते हैं। सच तो यह है कि देश में इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं। हो सकता है कि यह आरोप ज्वाइंट स्टाक कम्पनियों की आधार भूमि के गलत अध्ययन का परिणाम हो। कोई भी फर्म कितनी ही प्रभावशाली और कितनी ही सम्पन्न क्यों न हो, वह अकेले ही आधुनिक उद्योगों की व्यवस्था का साहस नहीं कर सकती। आज के उद्योगों की परिस्थितियां हैं ही ऐसी। हमारी बड़ी सम्पन्न और प्रभावशाली टाटा कम्पनी के भी ४२००० शेयर होल्डर हैं। एक प्रकार से इन्हीं फर्मों के शानदार भूत के कारण लोगों में बचत को प्रोत्साहन मिलता है और वह बचत की पूंजी उद्योगों में लगाई जाती है। जहां तक कुछ लोगों के हाथ में सारी आर्थिक सत्ता के केन्द्रित हो जाने का प्रश्न है, वह भारत जैसे अविकसित देश में सम्भव हो ही नहीं सकता कि हजारों लोग उद्योगों में पूंजी लगाने के लिए सदैव प्रस्तुत रहें। जापान यहां तक कि जर्मनी में भी कुछ ही उद्योगों के कारण अन्य उद्योगों की वृद्धि हुई है।

उद्योगों पर प्रतिबन्ध

मेरा विश्वास है कि देश में वैसी आर्थिक उन्नति नहीं

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हो रही है जैसी होनी चाहिए थी। इसके लिए योजना बद्ध विकास (प्लांड डेवेलपमेंट) आवश्यक है कुछ कानूनों से यह काम किया जाता है। लेकिन उन कानूनों को उद्योगों के विकास में प्रतिरोधक नहीं होना चाहिए। दुख है कि भारत में यही हो रहा है। औद्योगिक विकास और नियंत्रण अधिनियम, तथा लाइसेंस देने की पद्धति आदि इसी प्रकार के हैं। साथ ही सरकार की 'लालफीता शाही' भी उद्योग विकास योजना में कम बाधक नहीं। जिस समिति का मैं सदस्य रहा हूं, उसके सुझाव अभी तक 'लाल फीते' में बंधे पड़े हैं। उन पर कोई विचार किया गया या नहीं, कहा नहीं जा सकता। देश की औद्योगिक उन्नति के लिए शासकीय प्रक्रिया को सरल करना ही होगा।

श्री ब्लैक की आलोचना

उद्योगों के संबंध में वर्ल्ड बैंक के गवर्नर श्री ब्लैक के पत्र का उल्लेख भी आवश्यक प्रतीत होता है। इस पत्र से देश में काफी व्यग्रता फैली। हमारे देश में उच्च अधिकारियों ने एक नहीं अनेक बार कहा कि कई प्रभावशाली राष्ट्रोंके व्यक्ति हमारी विकास योजनाओं की सराहना करते हैं। सम्भवतः यह पहला ही मौका था, जब एक प्रभावशाली विदेशी ने हमारी आलोचना भी की और खुल कर की। मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूं कि श्री ब्लैक भारत के सच्चे हितैषी मित्र हैं। वे चाहते हैं कि भारत तेजी से आर्थिक उन्नति करे, परन्तु उनकी आलोचना तथ्यहीन नहीं। उन्हें अपने अनुभव के आधार पर विश्व की आर्थिक उन्नति का गहरा ज्ञान है। उनका विश्वास है कि कुछ विशेष रीतियों द्वारा ही सर्वांगीण और ठोस आर्थिक उन्नति हो सकती है। अतः कोई कारण नहीं, उन रीतियों से एकाएक छुटकारा पाया जाए। उनके ये विचार वर्ल्ड बैंक द्वारा भेजे गये पर्यवेक्षकों के आधार पर ही व्यक्त हुए हैं। हमारे देश में कुछ प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जो इन समस्याओं का यथार्थवादी दृष्टिकोण से सामना करने के लिए मैदान में उतरने से संकोच करते हैं। हमें श्री ब्लैक का कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने हमें ऐसे संकट के समय 'भावुकतावादी' लक्ष्य को छोड़ कर यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने को कहा है।

श्री ब्लैक के पत्र का उत्तर देते हुए श्री कृष्णामाचार्य (वित्त मंत्री) ने यह स्वीकार किया था कि कुछ दशाओं में सरकारी उद्योग निजी उद्योगों से अधिक अवनत हैं। हमारा उनसे अनुरोध है कि वे इस समस्या का पक्षपात विहीन दृष्टि से मूल्यांकन करें।

प्रजातन्त्र के साथ संगत

कहा गया है कि 'प्रजातंत्र' और 'निजी उद्योग' बेमेल हैं। भारत में कितने ही लोग इस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन इसके विपरीत पूर्णतः इस बात पर विश्वास करते हैं कि यदि स्वतंत्र उद्योगों को खुली साँस न लेने दी जाय तो हमारा नियोजित अर्थ व्यवस्था का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। निजी उद्योगों को सीमित किया गया तो देश की प्रजातांत्रिक जीवन पद्धति ही विनष्ट हो जाएगी। सच तो यह है कि दोनों परस्पर सहयोगी हैं। इसी कारण हमारे संविधान में 'निजी उद्योगों' के अधिकार भी सुरक्षित रखे गए हैं।

नई दिल्ली व दिल्ली में सम्पदा

सम्पदा के फुटकर अंकों और विशेष कर विशेषांकों की मांग अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों में बनी रहती है। उनकी सुविधा के लिए आत्माराम एण्ड सन्स, काश्मीरी गेट, दिल्ली (हिन्दी विभाग) में सम्पदा की बिक्री की व्यवस्था कर दी गई है।

नई दिल्ली में सम्पदा के विक्रेता सेंट्रल न्यूज एजेंसी, कनाट सर्कस हैं।

इस प्रबन्ध से आशा है, दिल्ली के अर्थशास्त्र-प्रेमियों की असुविधा दूर हो जायगी।

— मैनेजर सम्पदा

अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिल्ली

11864

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वस्त्र-उत्पादन व निर्यात की समस्या

ला० श्रीराम

योजनानुसार अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के के लिए दृढ़ निश्चय वाले राष्ट्र के हिस्से के रूप में हममें से प्रत्येक को कुछ कर्तव्य पूर्ण करना है। और इस रचनात्मक सहयोग की भावना से ही मैं पाठकों का ध्यान कुछ बातों की ओर खींचूंगा और अपने उद्योगपति भाइयों से नम्रता-पूर्वक निवेदन करूंगा कि वे निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, मौसम और बिना मौसम के प्रश्न को उठाना छोड़ दें, क्योंकि इससे लाभ के स्थान पर शायद कुछ हानि होती है। मुझे विश्वास है कि दूसरी योजना में भी निजी क्षेत्र के लिए बहुत स्थान छोड़ा गया है।

दूसरे योजना काल में विदेशी मुद्रा के अर्जन में जिस कमी की आशंका पहले की जाती थी, वह सर्वविदित कारणों से और भी बढ़ गई है। ऐसी परिस्थितियों में सूती वस्त्र उद्योग पर, जो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति का एक प्रधान साधन है, और भी बड़ा दायित्व आ पड़ता है।

मेरा विश्वास है कि सूती वस्त्र का निर्यात एक अरब गज तक और कदाचित इसमें भी अधिक बढ़ाया जा सकता है। मेरा सुझाव है कि हमारे सूती वस्त्र के निर्यात व्यापार की वृद्धि में आने वाली अनेक कठिनाइयों के हल के लिए सब संबंधित पक्षों की—वाणिज्य, उद्योग, वित्त, रेल्वे और श्रम मंत्रालयों, उद्योगपतियों के प्रतिनिधियों और श्रमिकों के नेताओं की बैठक बुलाई जाए।

जब मिलों में बनने वाले वस्त्र का उत्पादन प्रतिवर्ष बढ़ता गया है, जैसा नीचे दिए आंकड़ों से प्रतीत होता है, यह शोक का विषय है कि निर्यात गिरता जाता है और प्रथम योजना के निर्धारित लक्ष्य एक अरब गज से निरन्तर से नीचे आ रहा है। यह स्थिति उद्योग और सरकार दोनों के लिए चिंता का विषय है।

	मिलों में बने वस्त्र का उत्पादन	मिलों में बने वस्त्र का निर्यात
	(मिलियन गज)	
१९५३-५४	४,९६४	७४०
१९५४-५५	५,०३४	७६१
१९५५-५६	५,१०१	६८०

ला० श्रीराम

दूसरे शब्दों में वर्तमान लक्षणों के आधार पर १९५६-५७ में भारत मिलों द्वारा उत्पादित १००० गज वस्त्र में से केवल १२७ गज का निर्यात करेगा, जबकि १९५४-५५ में १५१ गज का निर्यात किया था।

निर्यात में कमी क्यों ?

निर्यात क्यों घट रहा है, जबकि यह नितान्त आवश्यक है कि निकासी बड़ी मात्रा में बढ़ाई जाए ? उत्तर बिल्कुल सरल है। एक ओर तो देश के अन्दर ही मांग बहुत बढ़ गई, जिससे मिलों को यहां कपड़ा बेचने में मुनाफा अधिक होने लगा है। दूसरी ओर सरकारी नीति मिलों में कपड़े की बुनाई में बढ़ती न होने देने की है, जिससे मिलों में तैयार होने वाला कपड़ा देश के अन्दर बढ़ती हुई मांग के अनुसार नहीं बन पाता। इसका परिणाम यह हुआ है कि कीमतों में जबर्दस्त तेजी आ गई है। नीचे दिए आंकड़े बताते हैं कि देश के अन्दर मांग किस तरह ऊंची हुई है—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

	१९५४-५५	१९५६-५७	
१—मिल वस्त्र का उत्पादन	५,०३४ गज दस लाख में	५,३५० गज दस लाख में	३१६ गज दस लाख में
२—मिल वस्त्र की निकासी	७६१ गज दस लाख में	६७० गज दस लाख में	८९ गज दस लाख में
३—मिलों में जमा मिल वस्त्र	लगभग ४६० गज दस लाख में	२०० गज से कम दस लाख में	२६० गज दस लाख में
		(अनुमान)	

दूसरे शब्दों में, मिलों के अन्दर बुनाई की क्षमता पर प्रतिबन्ध होते हुए भी देश ने इन वर्षों में, जितना अधिक मिल वस्त्र तैयार किया, उससे प्रायः दुगुना खपाया और उत्पादन में बढ़ती से ऊपर के कपड़े को दो स्रोतों से प्राप्त किया—जमा माल और निर्यात से। अकेले १९५६-५७ के वर्ष में ही, १९५५-५६ की तुलना में मिल वस्त्र की मांग में वृद्धि ४७५०००००० गज के आर्डर की होगी जो उत्पादन से प्रायः दुगुनी है—२५,००,००,००० गज १९५५-५६ में गत वर्ष से अधिक थी। जमा माल में तीव्र कमी हो जाने के कारण देश की मांग में भविष्य में होने वाली बढ़ती का निःसंदेह और भी प्रभाव पड़ेगा।

इस परस्पर विरोधी स्थिति की ओर अवश्य ध्यान आकृष्ट किया जाना चाहिए कि एक ओर तो वस्त्र की ज्यादा से ज्यादा निकासी की अत्यन्त आवश्यकता है और दूसरी ओर निकासी से हटकर अधिक अधिक माल देसी मण्डियों की तरफ लगातार खिंचा जा रहा है।

इस स्थिति की गम्भीरता को अब सरकार ने अनुभव किया, जिसने पहले ही प्रति व्यक्ति वस्त्र की खपत का लक्ष्य ऊंचा करके १८.५ गज रखा है और इस आंकड़े पर फिर भी विचार का वचन दिया है। सरकार ने १४६०० स्वचालित करघों के लगाने का भी निर्णय किया है जिनका उत्पादन थोड़ा बहुत या पूर्णतः निकासी में जायेगा।

मैं इन कदमों का स्वागत करता हूँ। तो भी, बड़े विनय से मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि प्रति व्यक्ति वस्त्र की खपत के लक्ष्य में पहले के अनुमान से आधा गज अधिक करना पर्याप्त नहीं है। लक्ष्य १९६०-६१ में कम से कम २० गज तक रखना चाहिए, जिसके कारण पर्याप्त रूप से बताए जा सकते हैं और उस लक्ष्य की प्राप्ति की सब व्यवस्थाएं, जिनमें देश की मण्डी के लिए लगभग ३०,००० नये—दोनों प्रकार के सादे और स्वचलित करघों की स्वीकृति पहले से समय रहते हुए दे देनी चाहिए। देश की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह वस्त्र की कमी का संकट उठा सके, क्योंकि भोजन के बाद औसत उपभोक्ता के लिए वस्त्रका ही महत्व है। और साथ ही हम अपने निर्यात की मण्डियों के खो देने का संकट भी नहीं उठा सकते। मेरी समझ में मिलों की क्षमता की वृद्धि का हाथ करघा उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव होगा, इस भय के लिए विशेष कारण नहीं है। तो भी सरकार की दृष्टि में हाथ करघों के उत्पादन को जिस हद तक बढ़ाना आवश्यक हो, इसके लिए कुल वस्त्र का वार्षिक लक्ष्य निश्चित कर लिया जाए और हाथ करघा उद्योग के लिए प्रतिवर्ष पिछले वर्ष से ऊंचा लक्ष्य रखते हुए आगे बढ़ा जाए—परन्तु यह देख लिया जाए कि हाथ करघा उद्योग आवश्यक उत्पादन में कहां तक साथ देता है। मैं तो यहां तक सुझाव दूंगा कि मिलों का उत्पादन यदि किसी स्थिति में हाथ करघा उद्योग के लिए बाधक प्रतीत हो तो मिलों के करघों को थोड़ी मात्रा में बन्द करने की कार्यवाही का भी आश्रय लिया जा सकता है। परन्तु वस्त्र के उत्पादन के विषय में अपनी नीतियों को क्रियान्वित करते हुए हम घटते हुए निर्यात के विवश करने वाले परिणामों से तब तक नहीं बच सकते, जब तक मिल वस्त्र का उत्पादन कम से कम, बढ़ती हुई मांग के अनुपात में ऊंचा नहीं उठता, जिसका महत्व मैंने पहले दर्शाया है।

मुझे निश्चय है कि निर्यात के लिए विशेष रूप से निर्धारित स्वचालित करघों की सरकार की नीति से कुछ सहारा मिलेगा, परन्तु यह स्पष्ट है कि इसके पूर्ण होने में

(शेष पृष्ठ ५० पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दूसरे वित्त आयोग की सिफारिशें—

विविध राज्यों में आय का वितरण

जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन प्रारम्भ किया, केन्द्र का प्रान्तों पर कोई विशेष नियंत्रण न था। बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रैजिडैंसियां अपनी आय स्वयं व्यय करती थीं। ज्यों ज्यों शासन अधिक संगठित होता गया, केन्द्रीय शासन के धन-सम्बन्धी अधिकार भी बढ़ते गये और प्रान्तीय सरकारों की स्वतन्त्र सत्ता कम होती गई। किन्तु कुछ समय बाद प्रान्तीय सरकारें अपने बढ़ते हुए कार्यों के लिए अपनी मांग जोरों से रखने लगीं। केन्द्र व प्रान्तों में आय और व्यय के लिए संघर्ष बढ़ता रहा। सरकार ने अनेक पंच या कमीशन नियुक्त किये, ताकि केन्द्र और प्रान्तों में आय का उचित वितरण हो सके। ❀ अनेक निर्णय दिये गए और सिफारिशें की गईं, परन्तु राज्यों का असन्तोष बराबर बना रहा। देश के स्वतन्त्र होने के बाद यह समस्या अधिक उग्र रूप से आई। १९३५ के विधान से भी अधिक जिम्मेदारियां प्रान्तों और अब राज्यों को मिल गई थीं। नये सिरे से उनके भाग का निर्णय करना पड़ा। श्री चिन्तामणि देशमुख ने एक निर्णय दिया और वह कुछ समय लागू भी हुआ। फिर श्री के० सी० नियोगी की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त हुआ। इसकी सिफारिशें लागू हुईं, परन्तु संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को प्रति पांचवें वर्ष वित्त आयोग की नियुक्ति करनी पड़ती है। इसलिए १ जून १९५६ को एक वित्त आयोग की नियुक्ति दूसरे वित्त आयोग के रूप में की गई। इसके अध्यक्ष श्री० के० सन्तानम थे और सर्व श्री उज्जवलसिंह, एल० एस० मिश्र, एम० वी० रंगाचारी तथा बी० एन० गांगुली सदस्य थे।

जो सामग्री उपलब्ध हुई उसकी बहुत थोड़ीसी बातों का यह आयोग अध्ययन कर पाया है। बहुत से राज्यों ने और विशेषकर उन राज्यों ने जिनका अभी पुनर्गठन हुआ है, ज्ञापन और वह विवरण नहीं भेजा, जो उनसे मांगा गया था। असम, प० बंगाल और उड़ीसा की सरकारों से ही यह आयोग अभी तक विचार विनिमय कर पाया है। अन्य राज्य सरकारों से बातचीत पूरी कर लेने और उनके ज्ञापन तथा विवरण मिल जाने पर ही आयोग अपनी अन्तिम सिफारिशें तैयार करने के योग्य होगा। केन्द्र और राज्यों की सरकारों के बजट बनने के समय तक यह सामग्री नहीं मिल सकेगी। इसलिए आयोग ने ऐसी सिफारिशें करना उचित समझा, जिनके आधार पर बजट बनाये जा सकें और अस्थायी रूप से भुगतान भी हो सके।

आयोग ने भारत सरकार से सिफारिश की है कि अन्तिम प्रतिवेदन पर भारत सरकार जो निश्चय करे, उस पर एक अप्रैल १९५७ से अमल हो और इस प्रतिवेदन के आधार पर जो भुगतान हो, उसका अन्तिम भुगतान में हिसाब कर लिया जाय। इन अन्तरिम सिफारिशों को आयोग के विचारों का संकेत नहीं समझना चाहिए। केन्द्र और राज्यों की सरकारों की वित्तीय स्थिति का पुनर्निर्धारण किया जा रहा है और अन्तिम निर्णय इसी पुनर्निर्धारण के आधार पर किए जायंगे। अन्तरिम सिफारिशों का यह अभिप्राय सर्वथा नहीं है कि आयोग ने राजस्व या सहायक अनुदानों के किसी भी सिद्धान्त को स्वीकृत कर लिया है।

जब पहले वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशें की थीं, संविधान के अनुच्छेद २७०, २७२, २७५ (१) और २८० जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होते थे। १९५४ में ये उस राज्य पर भी लागू कर दिए गए। जम्मू काश्मीर राज्य में १४ जनवरी १९५६ को कुछ और भी धारायें लागू कर दी गई। १ अप्रैल १९५७ से सहायक अनुदानों और केन्द्रीय करों के बंटवारे के लिए समूचे देश की योजना की दृष्टि से जम्मू काश्मीर की स्थिति भी अन्य राज्यों जैसी ही हो जायगी।

अन्तरिम सिफारिशों के तैयार करने में जहां तक हो

❀ इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए अगस्त १९५६ का अङ्क मंगाइये।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सका है, आयोग ने भिन्न भिन्न राज्यों की वर्तमान स्थिति को बनाये रखने का प्रयत्न किया है। जिन राज्यों पर १९५६ के राज्य पुनर्गठन अधिनियम का असर नहीं पड़ा है, उनके लिए आयकर और उत्पादन कर शुल्क का उतना ही हिस्सा देना तय हुआ है, जितने की पहले वित्त आयोग ने सिफारिश की थी। हां जम्मू काश्मीर राज्य के भी शामिल हो जाने से बंटवारे की योजना में कुछ परिवर्तन किया गया है। १९५६ के राज्य पुनर्गठन अधिनियम और १९५६ के बिहार तथा प० बंगाल (क्षेत्र हस्तांतरण) अधिनियम का जिन राज्यों पर प्रभाव पड़ा है, उनके आयकर और उत्पादन-शुल्क में, उस प्रतिशत को स्वीकार कर लिया गया है, जो इन अधिनियमों में और दूसरे अधिनियम के साथ जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेश में निश्चित किया गया है।

अनुच्छेद २७५ (१) के अन्तर्गत उन राज्यों के लिए जिनमें कुछ पुराने 'ग' भाग के राज्यों का विलय हुआ है, सहायक अनुदानों की सिफारिश करने में किसी हद तक उस सहायता का भी ख्याल रखा गया है, जो इन्हें घाटा पूरा करने के लिए केन्द्र से मिला करती थी। फिलहाल प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए दिए जाने वाले अनुदानों को आम अनुदान मान लिया गया है। अन्यथा १९५६ के राज्य पुनर्गठन अधिनियम और १९५६ के बिहार और प० बंगाल (क्षेत्र हस्तांतरण) अधिनियम की धारा २१ के अन्तर्गत जारी किए गए आदेश के कारण जो हेर-फेर किया गया है, उसके अलावा वर्तमान अनुदानों को ही जारी रखने की सिफारिश वित्त आयोग ने की है। आयोग की सिफारिशों को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

आयोग ने जो अन्तरिम सिफारिशें की हैं वे उक्त पृष्ठभूमि और विचारों के अनुसार की गई हैं। वे सिफारिशें निम्नलिखित हैं—

आयकर का बंटवारा

(क) शुद्ध आयकर का ५५ प्रतिशत जिसमें निगम-कर (कारपोरेशन टैक्स) आदि शामिल नहीं, राज्यों को इस प्रकार बाँटा जाय :—

राज्य	प्रतिशत	राज्य	प्रतिशत
आन्ध्र प्रदेश	८.०१	असम	२.२३
बिहार	९.३१	बम्बई	१८.९१
केरल	३.६०	मध्यप्रदेश	५.०९

उद्योग, व्यापार और वित्त सम्बन्धी

उद्योग व्यापार शब्दावली

मंगाइये

भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय द्वारा प्रतिमास प्रकाशित होने वाली उद्योग व्यापार पत्रिका में प्रयुक्त हुए कई हजार शब्दों का यह सुन्दर संकलन है। शब्दावली के दो भाग हैं : (१) अंग्रेजी से हिन्दी और (२) हिन्दी से अंग्रेजी।

हिन्दी के माध्यम से उद्योग, व्यापार, वित्त और अन्य आर्थिक विषयों का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिये विशेषतः उपयोगी है।

मूल्य केवल आठ आने, साथ में उद्योग व्यापार पत्रिका सितम्बर १९५६ का एक अङ्क भी मुफ्त भेंट।

आठ आने का पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर भेज कर आज ही मंगाइये। वी० पी० भेजना सम्भव नहीं है।

सम्पादक, उद्योग व्यापार पत्रिका
वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मद्रास	७.९५	मैसूर	५.९३
उड़ीसा	३.४६	पंजाब	३.९६
राजस्थान	३.४७	उत्तरप्रदेश	१५.५९
प० बंगाल	११.४८	जम्मू और काश्मीर	१.०१

संविधान के अनुच्छेद २७० के उप-खण्ड (२) और उप-खंड (३) की दृष्टि से, केन्द्र शासित प्रदेशों को १ प्रतिशत आय दी जायगी।

(ख) खेती की जमीन को छोड़कर और सम्पत्ति पर लगने वाले सम्पदा शुल्क (एस्टेट ड्यूटी) का बटवारा

ऊपर के पैरा (क) में जो सिफारिशें की गई हैं, सम्पदा शुल्क की शुद्ध आय के बंटवारे के बारे में भी उन्हीं पर अमल किया जाय।

(ग) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क का बंटवारा

दियासलाइयों, तम्बाकू और वनस्पति की चीजों पर लगने वाले केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क के ४० प्रतिशत का बटवारा भिन्न भिन्न राज्यों में इस प्रकार हो—

राज्य	प्रतिशत	राज्य	प्रतिशत
आन्ध्र	८.९२	असम	२.५८
बिहार	११.०४	बम्बई	१३.५९
केरल	३.८६	मध्यप्रदेश	६.१७
मद्रास	८.५४	मैसूर	५.४५
उड़ीसा	४.१७	पंजाब	४.६०
राजस्थान	४.३४	उत्तरप्रदेश	१८.००
प० बंगाल	७.४९	जम्मू और काश्मीर	१.२५

(घ) पटसन और पटसन के माल के निर्यात-शुल्क के हिस्से के बदले सहायक-अनुदान

अनुच्छेद २७३ के अन्तर्गत निम्नलिखित राज्यों को यह धन राशि दी जाय।

राज्य	धन राशि (लाख रुपये में)	राज्य	धन-राशि (लाख रुपये में)
असम	७५.००	बिहार	७२.३१
उड़ीसा	१५.००	प० बंगाल	१५२.६९

(च) संविधान के अनुच्छेद २७५ के खण्ड (१) के मौलिक अंश के अन्तर्गत सहायक-अनुदान निम्नलिखित राज्यों को यह धन राशि दी जाय—

राज्य	धन राशि (लाख रु० में)	राज्य	धन-राशि (लाख रु० में)
आंध्र प्रदेश	२४	असम	१००
बिहार	८०	बम्बई	१३०
केरल	४१	मध्यप्रदेश	२५१
मद्रास	५	मैसूर	४६
उड़ीसा	१०७	पंजाब	१६३
राजस्थान	११५	प० बंगाल	८३
जम्मू और काश्मीर	१७५		

(छ) १५ अगस्त १९४७ और ३१ मार्च १९५६ के बीच भारत सरकार की ओर से राज्य सरकारों को दिए गए कर्जों की अदायगी की शर्तें और ब्याज को और ब्याज की दरें।

—

नयापथ

(प्रगतिशील मासिक पत्रिका)

सम्पादक—

यशपाल ❀ शिव वर्मा ❀ राजीव सक्सेना

स्तम्भ—

- चक्कर क्लब
- साहित्य समीक्षा
- संस्कृति प्रवाह
- सिनेमा
- लेख
- कहानियां
- कविताएं।

"नयापथ" का जनवरी अंक 'लोक साहित्य' विशेषांक है। इसका सम्पादन हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक श्री श्रीकृष्णदास कर रहे हैं। ग्राहकों को यह अङ्क साधारण मूल्य में ही दिया जाएगा।

वार्षिक ६) एक प्रति ।।)

पता :—

२२ कैसर बाग लखनऊ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रान्तीय सहकारी बैंक : एक आलोचनात्मक अध्ययन

—श्री विश्वनाथ हुक्कू

व्यवस्था के दृष्टिकोण से सहकारी साख संस्थाओं को तीन वर्गों में बांटा गया है। प्राथमिक सहकारी साख समितियाँ ग्रामों तथा नगरों में स्थापित की जाती हैं। इनकी स्थापना के लिए स्थानीय तथा अच्छे चरित्रवाले दस व्यक्तियों की सदस्यता का होना आवश्यक है। यह समितियां अपने सदस्यों से अंश पूंजी (शेयर कैपिटल) तथा जमा प्राप्त करती हैं। राशि की कमी पड़ने पर यह केन्द्रीय सहकारी बैंक से ऋण लेती हैं। प्राथमिक सहकारी साख समितियों का कार्य क्षेत्र एक गांव तथा नगर तक सीमित रहता है और यह केवल अपने सदस्यों को ऋण देती हैं। दूसरे वर्गमें केन्द्रीय सहकारी संघ तथा केन्द्रीय बैंक सम्मिलित हैं। संघमें केवल प्राथमिक सहकारी साख समितियां ही सदस्य हो सकती हैं, परन्तु बैंकमें इनके अतिरिक्त स्थानीय व्यक्ति भी अंश खरीदकर सदस्य बन सकते हैं। सहकारी केन्द्रीय बैंक साधारणतः जिले के मुख्य नगर में स्थापित किए जाते हैं और इनका कार्य-क्षेत्र साधारणतः एक जिला होता है। जिले के विस्तार तथा प्राथमिक सहकारी साख समितियों की संख्या के अनुसार इनका कार्य क्षेत्र बड़ा या छोटा भी हो सकता है। इन केन्द्रीय बैंकों का राशि प्राप्त करने का तरीका लगभग वही है, जो प्राथमिक सहकारी साख समितियों का है। अधिक राशि की आवश्यकता पड़ने पर यह प्रान्तीय सहकारी बैंकों से ऋण ले सकते हैं। कुछ केन्द्रीय सहकारी बैंकों को सीधे रिजर्व बैंक आफ इन्डिया से आर्थिक सुविधाएँ प्राप्त करने का अधिकार है। अर्थात् सहकारी केन्द्रीय बैंक साधारण रूप में इस प्रकार की संस्थाओंके काम करते हैं परन्तु उनका एक विशेष कार्य इनके क्षेत्र में स्थित प्राथमिक सहकारी साख समितियों में समन्वय स्थापित करना है। इनके द्वारा राशि के वितरण की विषमता को दूर करना सम्भव है, जैसे यदि किसी प्राथमिक समिति में राशि आवश्यकता से अधिक है तो इसका हस्तान्तरण ऐसी समिति में करना आवश्यक है, जहां पर राशि की कमी हो। इस कार्य में सहकारी केन्द्रीय बैंक सहायता देते हैं। इन सब सब संस्थाओं में चोटी की संस्था तीसरे वर्ग में आती हैं। इन्हें प्रान्तीय या उच्चतम या राज्य सहकारी बैंक कहते हैं। इनमें भी कुछ तो ऐसे हैं, जिनके सदस्य केवल केन्द्रीय सहकारी संघ या बैंक हो सकते हैं। कुछ की सदस्यता केन्द्रीय संस्थाओं के अतिरिक्त प्राथमिक सहकारी समितियोंके द्वारा भी ग्रहण की जा सकती है। कुछ प्रान्तीय सहकारी बैंकों में सहकारी समितियों के अतिरिक्त साधारण व्यक्ति तथा संस्थाएँ भी सदस्य बन सकते हैं। यह बैंक सरकारी साख संस्थाओं तथा भारतीय मुद्रा मंडी के अन्य खण्डों के बीच की कड़ी हैं। रिजर्व बैंक आफ इन्डिया द्वारा जो आर्थिक सहायता ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि तथा सम्बन्धित कार्यों के लिए दी जाती है वह सब इन्हीं प्रान्तीय सहकारी बैंकों द्वारा अन्य सहकारी साख-समितियों को तथा इनके द्वारा ग्रामीणों को प्राप्त होती है।

प्रान्तीय सहकारी बैंकों को अपनी पूंजी अंश बेंचकर,जमा प्राप्त करके तथा रिजर्व बैंक व अन्य संयुक्त पूंजी वाले बैंकों से ऋण लेकर प्राप्त होती है। यह बैंक पूंजी का विनियोग सरकारी प्रतिभूतियों तथा सहकारी संस्थाओं को ऋण देने में करते हैं। अन्यसदस्य भी इनसे ऋण प्राप्त कर सकते हैं। प्रान्त के प्रमुख नगर में इनका प्रमुख कार्यालय होता है। साधारणतः इनकी शाखाएँ नहीं होती हैं। प्रान्त की समस्त साख समितियों की देख-रेख तथा संतुलित विकास का दायित्व इन पर ही है। इन को रिजर्व बैंक की अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। अन्य अनुसूची-बद्ध बैंकों के अतिरिक्त इन बैंकों को अधिक सुविधाएँ दी जाती हैं। रिजर्व बैंक को इन संस्थाओं के निरीक्षण का तथा सहकारी साख से सम्बन्धित कोई भी सूचना इनके प्रान्त के सम्बन्ध में इनसे मांगने का अधिकार है। गतवर्ष १९५५ में रिजर्व बैंक ने १२ प्रान्तीय सहकारी बैंकों का निरीक्षण किया और जो दोष इनमें पाए गए उनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं —

(क) पूंजी सम्बन्धी दोष—

(१) इन बैंकों के व्यवसाय को देखते हुए इनकी पूंजी की मात्रा कम है। आवश्यक है कि अंश पूंजी का अधिक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

से अधिक प्रसार किया जाय।

(२) इन बैंकों को जो राशि संचिति (रिजर्व) के निमित्त रखी जाती है, उसका विनियोग अन्य प्रतिभूतियों आदि में करने के बजाय बैंक के साधारण व्यवसाय में किया जाता है।

(३) सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित सीमा का उल्लंघन करते हुए अधिक राशि अन्य बैंकों में जमा कराई गई है। इस प्रकार से ग्रामीण साख-सम्बन्धी कार्यों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग के लिए राशि की मात्रा कम रह जाती है।

(४) सहकारी केन्द्रीय तथा प्राथमिक साख संस्थाएँ प्रान्तीय सहकारी बैंकों की अंश-पूँजी में जिस अनुपात में भाग लेती हैं उससे अधिक अनुपात में उन्हें ऋण प्रदान किए जाते हैं और इस प्रकार उनके द्वारा दी गई अंश पूंजी तथा ऋण की राशि में सम्बन्ध का कोई उचित आधार नहीं है।

(ख) पूंजी-विनियोग संबंधी दोष—

(१) तरल पूंजी का हिसाब तथा रजिस्टर ठीक ढंग से नहीं रखे जाते हैं।

(२) सहकारी समितियों के अतिरिक्त जो अन्य व्यक्ति इन बैंकों के सदस्य हैं, उनको तथा अन्य ग्राहकों को ऋण दी गई राशि की मात्रा अधिक है।

(३) जो ऋण दिए गए हैं, उनकी वसूली उचित समय में न होने के कारण बहुत सी राशि बाकी पड़ी हुई है, जिसके कारण कार्यशील पूंजी में कमी पड़ती है।

(४) सहकारी संस्थाओं तथा अन्य व्यक्तियों को ऋण देते समय इस बात को ध्यान में नहीं रखा जाता है कि इससे पूर्व ऋण की राशि को उचित समय में लौटाने के सम्बन्ध में इनकी प्रवृत्ति किस प्रकार की रही है। सहकारी साख प्रदान करने में यह एक महत्वपूर्ण बात है।

(५) प्रान्तीय सहकारी बैंक जितनी राशि रिजर्व बैंक से कृषि, विपणन तथा अन्य सम्बन्धित कार्यों के लिए साख प्रदान करने को प्राप्त करते हैं, उससे कम राशि इन्हीं कार्यों के लिए केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा अन्य समितियों को ऋण के रूप में दी जाती है। इस प्रकार ग्रामीण-साख के हेतु प्राप्त राशि का प्रयोग अन्य कार्यों के लिए किया जाता है।

(ग) ब्याज की दर—

यद्यपि सहकारी समितियों की स्थापना से यह आशा की जाती थी कि कृषकों को सस्ती ब्याज-दर पर ऋण प्राप्त हो सकेंगे परन्तु अभी तक भी ब्याज की दर काफी अधिक है। रिजर्व बैंक सहकारी साख संस्थाओं को कम ब्याज की दर पर आर्थिक सुविधाएँ प्रदान करता है। जबकि भारत में रिजर्व बैंक की बैंक दर ३॥ प्रतिशत है, प्रान्तीय सहकारी बैंक रिजर्व बैंक से केवल १॥ प्रतिशत की दर राशि प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से प्राप्त राशि अन्य उपायों से प्राप्त राशि में सम्मिलित की जाती है और एक निश्चित दर पर केन्द्रीय सहकारी बैंकों को ऋण के रूप में दी जाती हैं। केन्द्रीय सहकारी बैंक भी इसी प्रकार एक निर्धारित दर पर प्राथमिक सहकारी साख समितियों को ऋण देते हैं। यह तो साधारण रीति है परन्तु बम्बई, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में दूसरी नीति है। रिजर्व बैंक से सस्ती दर पर प्राप्त राशि सस्ती ब्याज-दर पर ऋण के रूप में दी जाती है और अन्य साधनों से अधिक ब्याज-दर पर प्राप्त राशि ऊँची ब्याज-दर पर ऋण स्वरूप दी जाती है। दोनों राशियों को पृथक रखने से कृषक को ऊंची ब्याज की दर पर ऋण मिलता है।

ब्याज की दर की तालिका प्रतिशत

संस्था का नाम	रिजर्व बैंक से प्राप्त राशि में से दिए गए ऋण	अन्य राशि से दिए गए ऋण
बम्बई—राज्य सहकारी बैंक	२	४॥
केन्द्रीय सहकारी बैंक		४॥ समान द
प्राथमिक सहकारी समिति		७$\frac{12}{16}$,,
उत्तर प्रदेश—राज्य सहकारी बैंक	२॥	४॥
केन्द्रीय सहकारी बैंक	४॥	७
प्राथमिक सहकारी साख समिति	७॥	९

[सम्पद

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पंजाब—राज्य सहकारी

बैंक १॥। ६

१ जुलाई १९५६ से उत्तर प्रदेश में भी ब्याज की दर को समान रखने का निश्चय किया गया है। राज्य सहकारी बैंक केवल ३॥ प्रतिशत ब्याज की दर पर ऋण देंगे। सहकारी बैंक ६ प्रतिशत ब्याज लेंगे तथा कृषक को ७$\frac{13}{16}$ प्रतिशत की दर पर ऋण मिल सकेगा। पंजाब में भी राज्य सहकारी बैंक द्वारा दोनों प्रकार की राशि में से ऋण देने के लिए समान ब्याज की दर लिए जाने की बात विचाराधीन है।

(घ) अन्य दोष—

(१) कुछ स्थानों पर व्यापारिक तथा बैंकिंग क्रियाओं को साथ-साथ किया जाना पाया गया है, जो विशेष रूप से राज्य सहकारी बैंकों के लिए उचित नहीं है।

(२) बैंक के कर्मचारी बैंकिंग के कार्य तथा सहकारिता के उद्देश्य व प्रकृति से अनभिज्ञ हैं। इनके लिए इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण आवश्यक है।

(३) ऋण लेने वाली संस्थाओं पर देख-रेख कमजोर है। यद्यपि उनके कार्य में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है, परन्तु उन पर अधिक ध्यान देना आवश्यक है।

(४) बैंक में रखी जाने वाली तरल राशि अन्य बैंकों के पास जमा के रूप में रखी जाने वाली राशि की मात्रा के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की जाती है।

(५) डूबे तथा शंकित ऋण (Bad and doubtful debts) का अनुमान ठीक प्रकार से नहीं किया जाता है। अनेक अवसर ऐसे आते हैं कि बैंकों के निरीक्षकों तथा बैंक द्वारा किए गए अनुमान भिन्न होते हैं। इस प्रकार के ऋणों तथा अन्य विनियोगों पर छीजन (depreciation) उचित प्रकारसे नहीं लगाया जाता है।

इन सब दोषों को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक ने जो विस्तृत सुझाव दिए हैं, उनका इन संस्थाओं ने स्वागत किया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सहकारी संस्थाओं का प्रत्येक क्षेत्रमें बहुत महत्व है। आशा है कि शीघ्र ही यह दोष दूर किए जा सकेंगे जिससे कि देश में ग्रामीण साख को अधिक सस्ता, सुन्दर तथा दृढ़ बनाया जा सके।

——

आर्थिक समीक्षा

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आर्थिक राजनीति अनुसंधान विभाग का पाक्षिक पत्र

प्रधान सम्पादक : आचार्य श्री श्रीमन्नारायण

सम्पादक : श्री हर्षदेव मालवीय

★ हिन्दी में अनूठा प्रयास

★ आर्थिक विषयों पर विचारपूर्ण लेख

★ आर्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत

भारत के विकास में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यावश्यक, पुस्तकालयों के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक।

वार्षिक चन्दा : ५ रु० एक प्रति : ३॥ आना

व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी,

७, जन्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली।

वार्षिक मूल्य ८) रु० अर्धवार्षिक ४)

सरकारी विज्ञापनों के लिए स्वीकृत

राजस्थान शिक्षा विभाग से मंजूरशुदा

सेनानी साप्ताहिक

सम्पादक :—

सुप्रसिद्ध साहित्य सेवी श्री शंभुदयाल सक्सेना

कुछ विशेषताएं—

★ ठोस विचारों और विश्वस्त समाचारों से युक्त

★ प्रान्त का सजग प्रहरी

★ सर्वाधिक लोकप्रिय पत्र

ग्राहक बनिए, विज्ञापन दीजिए, रचनाएं भेजिए

नमूने की प्रति के लिए लिखिए—

व्यवस्थापक, साप्ताहिक सेनानी, बीकानेर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

फोन : ३३१११ तार : 'ग्लोबशिप'

न्यू ग्लोब शिपिंग सर्विस लिमिटेड

खताऊ बिल्डिंग्स

४४ ओल्ड कस्टम हाउस रोड, फोर्ट, बम्बई

सब प्रकार का क्लियरिंग, फारवर्डिंग, शिपिंग
का काम शीघ्र व सुविधापूर्वक
किया जाता है ।

सेक्रेटरी—
श्री बी० आर० अग्रवाल
बी. काम., एल. एल. बी.

मैनेजिंग डायरेक्टर—
श्री सी. डीडवानिया

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लीपजीग की प्रसिद्ध औद्योगिक प्रदर्शनी

पश्चिमी जर्मनी के प्रसिद्ध औद्योगिक नगर लिपजिग में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी व्यापारिक मेले का आयोजन किया गया है। यह मेला इस वर्ष ३ मार्च ४१ से मार्च तक लगेगा। लिपजिग में सर्वप्रथम मेला १५०७ ई० में शुरू हुआ था। इसमें पूर्वी योरप के देश विशेष रूप से भाग लेते थे और लाखों रुपए के माल की खरीद फरोख्त होती थी। यह मेला अब तक जारी ही नहीं है वरन् अन्तर्राष्ट्रीय रूप भी धारण कर गया है। इस मेले में योरप की ही नहीं वरन् संसार के सब भागों की बनी वस्तुओं का क्रय-विक्रय होता है।

इस वर्ष शरत् कालीन मेले में सरकारी आंकड़ों के अनुसार जर्मनी व विदेशी व्यापार संगठन का ६८,८० लाख मार्क का व्यापार हुआ। इसमें से ५१६० लाख मार्क का निर्यात व्यापार था। गत वर्ष जितना व्यापार हुआ, उसका ५० प्रतिशत विनिमयके रूप में हुआ।

गत वर्ष की प्रदर्शनी में भारतीय कक्ष

संसार में अन्यत्र किसी स्थान पर ग्राहक को रूस, चीन, पोलैंड, जेकोस्लावेकिया तथा अन्य साम्यवादी देशों के साथ साथ एशिया पश्चिमी यूरोप, तथा अमेरिका आदि देशों की निर्यात योग्य वस्तुओं की इतनी विविधता तथा इतनी मात्रा प्राप्त नहीं होती है।

प्रत्येक वर्ष में दो बार इस प्रकार के मेले लगते हैं। एक मेला वसंत में होता है, जिसमें प्राविधिक (टेक्नीकल) और नमूनों की वस्तुओं (सैम्पलों) का सम्मिलित रूप से प्रदर्शन किया जाता है। शरद में होने वाले दूसरे मेले में केवल नमूने की वस्तुओं और उपभोग की वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाता है।

३०लाख वर्गगज के विस्तृत क्षेत्र में प्रायः समस्त प्रकार के उद्योगों की बनी हुई वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाता है। इनमें इलेक्ट्रीकल, इंजिनियरिंग, कृषि-यंत्र, मोटर गाड़ियां, पुस्तकें, कपड़े आदि उल्लेखनीय हैं। इस वर्ष मार्च में लगने वाले मेले की कुछ नई विशेषताएँ भी हैं। इस वर्ष पहली बार यूगोस्लेविया इसमें भाग लेगा। डैनमार्क की कृषि कौंसिल भी अपने देश की ओर से पहली बार सामूहिक प्रदर्शनी के रूप में भाग लेगी। कोलम्बिया के पहली बार भाग लेने की आशा है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

देश की विकास योजनाएं और जनता

(श्री रामकिशोर व्यास, गृह व सूचना मंत्री, राजस्थान)

जब से हमने स्वतन्त्रता प्राप्त की है, तब से हम निरंन्तर यह सोच रहे हैं और प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारी यह स्वतन्त्रता केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता न बनकर रह जाए। हमें इसके साथ आर्थिक और सामाजिक स्वतन्त्रता भी प्राप्त करनी है, तभी हमारा देश मजबूत, सुखी और समृद्ध बन सकेगा और हमारी राजनीतिक स्वतन्त्रता सार्थक होगी। इसी विचार-धारा को लेकर हमारी सरकार ने पहली पंचवर्षीय योजना बनाई और उसमें प्राप्त सफलता से प्रेरणा और बल प्राप्त कर आज हम अपनी दूसरी पंचवर्षीय योजना को क्रियान्वित करने की दिशा में चल पड़े हैं। इस योजना द्वारा हम देशमें एक अद्वितीय साहसिक प्रयोग करने जा रहे हैं। हमारी कठिनाइयाँ हैं, हमारा मार्ग साफ नहीं है फिर भी हमारे हृदय में उत्साह है, उमंग है और हमारे सामने भविष्य का एक नकशा है।

पिछले कुछ सप्ताहोंमें पश्चिमी एशिया और योरोप में हुई कुछ घटनाओं ने हमारे भविष्य के चित्र को कुछ धुंधला बनाने का प्रयत्न किया है और हम अपनी दूसरी योजना के सम्बन्धमें और अधिक गम्भीरतापूर्वक विचार करनेके लिए बाध्य हुए हैं। कुछ दिन पूर्व राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक का नई दिल्ली में समारम्भ करते हुए प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने इस दिशा में संकेत किया था। अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा था कि हमारे लिए यही श्रेयस्कर है कि हम अपने ही पैरों पर खड़ा होने का प्रयत्न करें। यह नितान्त आवश्यक है कि हम अपनी अभिवृद्धि के लिए स्वयं ही पैसा जुटाएं— हम उनके लिए जो भी त्याग और तपस्या आवश्यक हो, करें और अधिक कर दें तथा और अधिक बचत करें, आज हमारे सामने दो ही मार्ग हैं या तो हम अनाज की पैदावार बढ़ाएं या अपनी योजना में असफल हों। पोलैंड और हंगरी में हुई हाल की घटनाओं से हमें सबक लेना है और देश के औद्योगिक विकास के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को इतना नहीं खींचना है, कि वह टूट जाए। कृषि-उत्पादन की दिशा में थोड़ी सी भी ढील डालना देश के लिए और सारे आयोजन के लिए घातक होगा। इससे स्पष्ट है कि हम अपने देश के विकास के लिए अपनी बुनियादी अर्थव्यवस्था को, जो खेती बाड़ी के साथ जुड़ी हुई है, मजबूत बनाना चाहते हैं, और इसका मतलब यह है कि हम उस व्यवस्था के पोषक, देश के उन ८५ प्रतिशत नागरिकों की ओर पहले ध्यान देना चाहते हैं जो गांवों में रहते हैं और जिन्हें हम किसान कहते हैं यही कारण है कि हम इस योजना

इस मेले में औद्योगिक दृष्टि से पूर्ण विकसित देश ही भाग नहीं लेते, वरन् जो इस दृष्टि से अल्प विकसित हैं या विकासोन्नमुख हैं, वे भी उत्सुकता पूर्वक मेले में भारी मात्रा में माल खरीदने के लिए आते हैं और अपनी आवश्यक वस्तुओं के आयात का भी प्रबन्ध यहीं कर लेते हैं। पूर्वीय देशों से बड़ी संख्या में व्यावसायिक प्रतिनिधि मंडल भाग लेते हैं। वही आयात के लिए भारी आर्डर देते हैं।

जर्मन डिमौक्रैटिक रिपब्लिक की सरकार इसी मेले में अपने विदेशी व्यापार के अधिकांश के लिए ठेके देती है। १९५५ की अपेक्षा १९५६ में तीन गुना व्यापार विदेशों से किया गया। भारत के साथ भी पहले की अपेक्षा अधिक व्यापार हुआ।

भारत ने भी पिछले वर्ष इस मेले में भाग लिया था साथ ही भारत सरकार की तरफ से औद्योगिक प्रतिनिधि मंडल को भी भेजा गया था। इस मंडल के नेता श्री पी के. पन्निकरने इस मेलेके संबंध में निम्नलिखित विचार प्रकट किया था:

"यह मेला अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास के लिए अत्युत्तम साधन है। इस मेले में न केवल जर्मनी से व्यापार की सुविधाएं मिलती हैं, किन्तु अन्य अनेक देशों के साथ भी व्यापार करने की सुविधाएं मिल जाती हैं।"

इस मेले के सम्बन्ध में अधिक जानकारी लीपजिग फेयर एजंसी आफिस बम्बई, दिल्ली कलकत्ता या मद्रास से प्राप्त हो सकती है।

—श्री त्रियुगी नारायण

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

को जनता की योजना कहते हैं और उसके लिए जनता के सहयोग की मांग करते हैं।

आयोजन-आयोग द्वारा स्थापित वैज्ञानिक मंडल की पहली बैठक में प्रधानमन्त्री ने इसीलिए जन-सहयोग पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हमें पंचवर्षीय योजना को क्रियान्वित करने के लिए लोकतन्त्रीय ढंग अपनाना है और उसे सफल बनाने के लिए किसानों, श्रमजीवियों, बुद्धिजीवियों और आम जनता का उत्साहपूर्ण समर्थन प्राप्त करना है। हमारी सरकार अपना प्रत्येक कार्य जनता के समर्थन के साथ करना चाहती है। वह अपनी कोई योजना या कार्यक्रम जनता पर लादना नहीं चाहती। वह जनता की भावनाओं की कद्र करती है और उनकी आवश्यकताओं और कठिनाइयों को समझना चाहती है। उसी प्रकार वह चाहती है कि जनता उस के बनाये कार्यक्रम को समझने का प्रयत्न करे और उसमें सक्रिय सहयोग दे। हमारी योजना का स्वरूप यद्यपि हमने एक प्रकार से निश्चित कर लिया है किन्तु उसे बदला नहीं जा सकता, यह बात नहीं है। मनुष्य का जीवन इतना पेचीदा होता है कि उसे किसी एक सांचे में नहीं ढाला जा सकता। हम अपने अनुभव से सीखना चाहते हैं और बदलती हुई प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुकूल चलना चाहते हैं। इसीलिए हमने अपनी योजना में समयानुसार रद्दोबदल की गुंजाइश रखी है और हम यह मानते हैं कि हर व्यक्ति भले ही वह कितना ही पिछड़ा हुआ या अनपढ़ क्यों न हो, इस योजना के लिए अमूल्य सुझाव दे सकता है।

राजस्थान में

जनता की योजना जनता तक पहुँचे इसी उद्देश्य से हाल में राजस्थान सरकार ने २४ नवम्बर से ३० नवम्बर तक सारे राज्यमें "विकास समारोह" का आयोजन किया था। सदियों से सामन्तवादी अर्थ-व्यवस्था में पले हुए राजस्थान में पिछले पांच वर्षों से देश के अन्य राज्यों की भांति विकास-कार्यक्रम चल रहे हैं। हमने सभी के साथ अपनी पहली पंचवर्षीय योजना समाप्त की है और पहली योजना से लगभग दुगुने परिमाण की दूसरी योजना लेकर हम मैदान में आये हैं। रेतीले और ऊबड़-खाबड़ प्रदेश को हरा-भरा बनाने के लिए हमने भगीरथ प्रयत्न किया है। प्राकृतिक-प्रकोप से पीड़ित न होने की अवस्था में हम अन्न के मामले में आत्म निर्भर रहेंगे—यह हमने साधना की है। इतना ही नहीं, आगामी पांच वर्षों में हम अपनी आवश्यकता से ४ लाख टन अन्न का अधिक उत्पादन करने लगेंगे। राजस्थान नहर के बनने से ३० लाख एकड़ से अधिक और भूमि में सिंचाई होने लगेगी। भाखरा और चम्बल योजनाओं से हमें सिंचाई के लिए जल मिलने लगा है। आगे उद्योगों के विकास के लिए बिजली भी मिलेगी। खनिज पदार्थों की अधिकाधिक मात्रा में निकाला जाएगा और वह राजस्थान जो अब तक एक पिछड़ा हुआ राज्य रहा है, देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आ जाएगा। वह सब हम अपने जीवन काल में ही देख सकेंगे। और आने वाली पीढ़ियों को केवल इतिहास से ही यह मालूम हो सकेगा कि राजस्थान कुछ ही वर्ष पूर्व दैन्य और दारिद्रय में सोता था या उसके नौनिहाल धरती पर लोटते थे। यह है हमारी योजना की रूपरेखा और इसी से जनता को परिचित करने के लिए और उसमें निर्धारित प्रत्येक व्यक्ति के योगदान के लिए उसे तैयार करने के लिए हमने राजस्थान भर में विकास समारोह मनाया। प्रभात फेरियां लगाई गईं, सभाएं हुईं, प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, प्रदर्शन किए गये, श्रमदान हुआ, और जनता ने अपने भविष्य को समझने का प्रयत्न किया जन जीवन में नव-जीवन फूंकने का वातावरण तैयार किया गया। राज्य के कोने कोने से इस समारोह के जो समाचार मिले वे काफी उत्साहवर्धक थे। झलावाड़ में छापेखाने के अभाव में साइक्लोस्टाइल्ड हैंडबिल बांटे गये और इस योजना का सन्देश घर घर तक पहुंचाने का प्रयत्न किया गया। अनेक प्रकार के मनोरंजक कार्यक्रमों, खेल-कूदों, छाया-चित्र प्रदर्शनों आदि ने इस समारोह को अत्यन्त सजीव बना दिया।

जयपुरमें इसी अवसर पर एक विशाल 'राजस्थान-प्रदर्शनी' का आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी में राजस्थान सरकारके विभागों की ओर से और भारत सरकार के सूचना व प्रसार मन्त्रालयकी ओर से स्टाल लगाये गए जिनसे हमें अपने देश और राज्यकी विकास गतिविधियों का एक चित्र मिल जाता है। आज के तेजी से बदलते हुए युग में आवश्यक है कि

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हम देश में हो रहे हर कार्य की प्रगति से परिचित रहें—नहीं तो बहुत पीछे रह जायेंगे और देश के नवनिर्माण में अपना पूरा सहयोग नहीं दे सकेंगे और हो सकता है कि अपना भी नुकसान करें।

आज हमारे देश पर—हमारी जनता पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें अपने ही लिए रास्ता नहीं बनाना वरन औरों के लिए भी बनाना है। आज विश्व के अनेक राष्ट्र हमारी ओर देख रहे हैं। वे देख रहे हैं कि हम किस प्रकार लोकतन्त्रीय भावनाओं का आदर करते हुए विशाल पथ पर बढ़ रहे हैं। वे देख रहे हैं कि हम राष्ट्रों की किसी गुटबन्दी में न पड़कर केवल मूलभूत सिद्धान्तों को लेकर विश्व में आगे बढ़ रहे हैं और राष्ट्रों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। कोरिया और हिन्दचीन में हमने मानवता पर बरसती हुई आग को रोका है। विश्वशाँति के प्रयत्नों को हमने बल दिया है। तीसरे विश्वयुद्ध की दिशा में जाते हुए राष्ट्रों को हमने रोकने का प्रयत्न किया है। आज संसार भारत का आदर करता है। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। हमने एशिया और अफ्रीका के देशों में जागरण का शंख फूंकने का प्रयत्न किया है। यह सब हो रहा है, किन्तु इसके लिए बल हमें अपने देश के भीतर से ही प्राप्त करना है। यदि हमारी आँतरिक स्थिति मजबूत न हुई, यदि हम नारों में भटक गये, यदि हमने केवल समस्याओं को ही सामने न रखा, वरन् दलबन्दी का शिकार हो गये या तुच्छ स्वार्थों में खो गए तो हम विश्वका मार्गदर्शन करने योग्य न रहेंगे। हमारी शक्ति सैन्य-शक्ति नहीं है—हमारी शक्ति नैतिक शक्ति है। किन्तु इस नैतिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें अपने देश को कल्याणकारी राज्य बनाना होगा। इसको समाजवादी ढांचे में ढालना होगा, एकता के सूत्र में पिरोना होगा। हमारी योजनाओं का यही उद्देश्य है—इनकी सफलता या विफलता के साथ हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है।

—

'पाञ्चजन्य'

ऐतिहासिक कहानी प्रतियोगिता

हिन्दी साहित्य में ऐतिहासिक कहानियों की परम्परा कुछ धीमी-सी पड़ गई है, अतः उसे पुनः प्रोत्साहित करने की दृष्टि से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता के अन्तर्गत ऐसी कोई भी मौलिक कहानी स्वीकार की जा सकेगी, जिसका आधार भारतीय इतिहास हो। कहानियों के सम्बन्ध में निर्णय करते समय भाषा, कहानी के तत्व तथा विषय पर विशेष ध्यान दिया जायगा। सर्वश्रेष्ठ कहानी पर १०१), द्वितीय पर ५१), तथा तृतीय पर ३१) के पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे।

प्रतियोगिता का निर्णय 'पाञ्चजन्य' के 'ऐतिहासिक कहानी विशेषांक' में घोषित किया जायगा, जिसके प्रकाशन की तिथि बाद में घोषित की जायगी। उक्त अङ्क में समस्त पुरस्कृत कहानियां तो प्रकाशित की ही जावेंगी, अन्य कुछ विशेष प्रशंसित कहानियों को भी उसमें स्थान प्रदान किया जायगा। किसी भी कहानी को लौटाया नहीं जा सकेगा। प्रत्येक पुरस्कृत कहानी पर 'पाञ्चजन्य' का पूर्ण अधिकार रहेगा।

विशेष—

१. प्रतियोगितार्थ प्रत्येक कहानी 'पाञ्चजन्य' कार्यालय में २० जनवरी १९५७ तक पहुँच जानी चाहिए।

२. कहानियां सम्पादक 'पाञ्चजन्य', गौतमबुद्ध मार्ग, लखनऊ के पते पर रजिस्टर्ड भेजी जानी चाहिए।

३. लिफाफे पर 'ऐतिहासिक कहानी प्रतियोगिता के लिए,' अंकित रहना चाहिए।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सोवियत रूस में औद्योगिक वृद्धि

रूस की सोवियत सरकारने पिछले दिनों औद्योगिक विकासके कुछ अंक प्रकाशित किये हैं। इनसे प्रकट होता है कि रूस किस गति से भारी उद्योगों का उत्पादन कर रहा है। साथ के चित्रों में इस्पात, लोह पिण्डों और तेल के उत्पादन के अंक दिये गये हैं। रूस ने उपभोग्य दप ार्थों की अपेक्षा भारी उद्योग की ओर अधिक ध्यान दिया है और उसके ही अनुभसव का परिणाम है रूस का भिलाई-लोह उद्योग में सहयोग। १९१३ में रूस बहुत पीछे था, पर १९५५ से भी १९५६ में १३ लाख टन ज्यादा इस्पात पैदा हुआ। लोह पिण्डका उत्पादन एक वर्ष में २० लाख टन और तेल का उत्पादन ६५ लाख टन बढ़ा है। ट्रैक्टर इस वर्ष में १९५५ की अपेक्षा १५९ हजार ज्यादा तैयार हुए हैं और धातु काटने के औजारों में गत वर्ष से ८३ हजार की वृद्धि हुई है। यही दशा अन्य प्रधान उद्योगों की है।

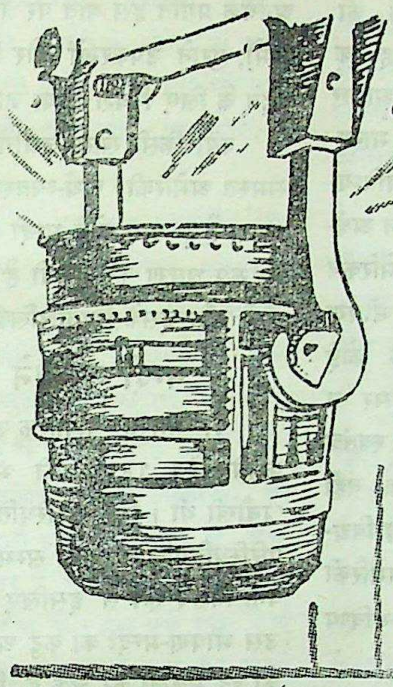

कुछ तुलनात्मक चित्र

लोह-पिंड का उत्पादन (लाख टनों में)

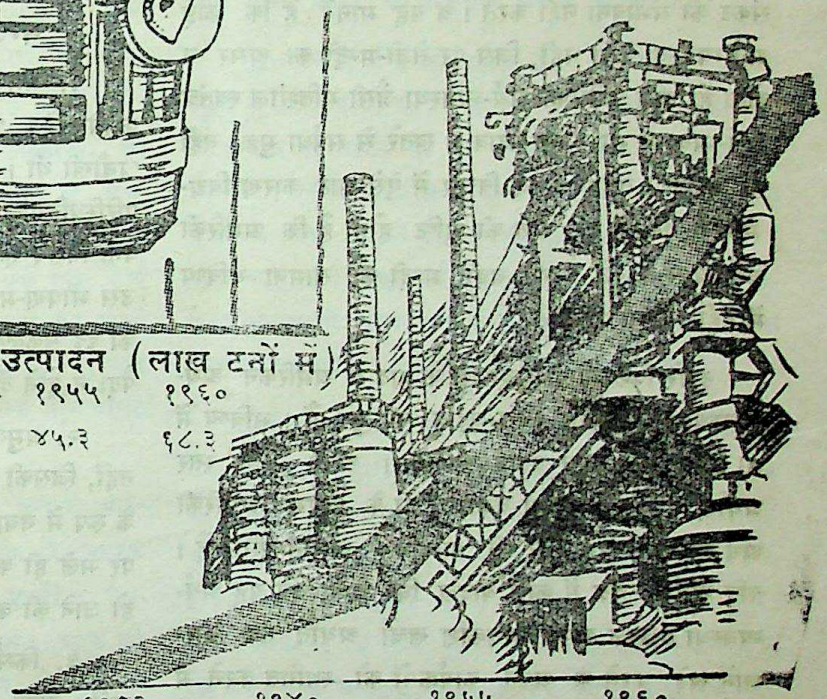

इस्पात का उत्पादन (लाख टनों में)

१९१३	१९५५	१९६०
४.३१	४५.३	६८.३

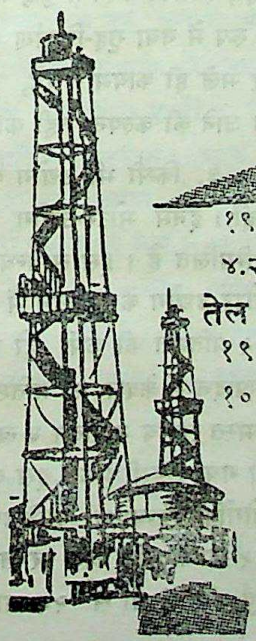

१९१३	१९४०	१९५५	१९६०
४.२	१४.१	३३.३	५३.०

तेल का उत्पादन (लाख टनों में)

१९१३	१९४०	१९५५	१९६०
१०.३	३१.१	७०.८	१३५.०

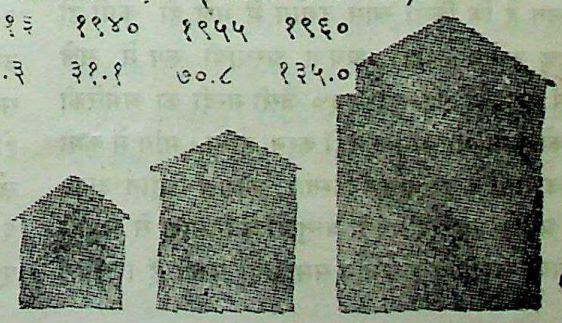

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था : बड़ी मन्दी की संभावना नहीं

अनेक अर्थशास्त्रियों का विश्वास है कि नक्षत्रों की गति की तरह आर्थिक मंदी के भी नियम हैं और वह एक नियत समय बाद आया करती है। इसी विश्वास के आधार पर अनेक अर्थशास्त्रियों ने और पूंजीवाद-विरोधी मान्यताओं के कारण समाजवादी अर्थशास्त्रियों ने यह भविष्यवाणी की थी कि युद्धकालीन समृद्धि के बाद अमेरिकन अर्थ-व्यवस्था में मंदी का चक्र चलने वाला है। लेकिन अमेरिकन अर्थशास्त्री श्री जोजेफ एच० स्पिजेलमैन ऐसे किसी भीषण संकट की संभावना नहीं करते। वे यह मानते हैं कि कोई अर्थ-व्यवस्था ऐसी नहीं, जिस पर तेजी-मन्दी का असर न होता हो और अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था जैसी गतिशील स्वतंत्र अर्थ-व्यवस्था भी उतार चढाव के खतरे से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकती। तथापि उनके विचार में ऐसे आठ कारण विद्यमान हैं, जिनसे इस बात की पुष्टि होती है कि अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था को किसी बड़ी मन्दी का सामना भविष्य में नहीं करना होगा।

दूसरे विश्वव्यापी युद्धकाल के बाद से अमेरिकन अर्थ-व्यवस्था में तीन बार उतार-चढ़ाव आ चुके हैं। भविष्य में भी इसी प्रकार उतार-चढ़ाव आएंगे। अपने उच्च स्तर अर्थात् बड़ी बचत तथा बड़ी पूंजी के कारण अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था स्वभाव से ही अत्यधिक परिवर्तनशील है। यदि आर्थिक क्षेत्र में काले बादल घिर आएं, तब यह अर्थ-व्यवस्था तत्काल अपने अधिकांश खर्चों अर्थात् नये कारखाने खड़े करने के अपने कार्यक्रमों को स्थगित करने में समर्थ है।

किन्तु इसके साथ ही उक्त लेखक की सम्मति में यह भी निश्चित है कि किसी खास उद्योग में भले ही कमी हो जाए, कुछ उद्योग स्थायी अथवा अस्थायी रूप में भले ही समाप्त हो जाएं, किन्तु १९३० जैसी मन्दी का अमेरिकी उद्योगों को कभी भी सामना नहीं करना होगा। मांग में कमी हो जाने, उद्योगों के अत्यधिक विस्तार, कौशल-विहीन उत्पादन तथा अनावश्यक एवं महंगी वस्तुओं के निर्माण से स्थायी या अस्थायी रूप में कुछ उद्योग समाप्त हो सकते हैं। स्वयं आर्थिक प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि अकुशल फर्मों, पुराने उपकरणों और विधियों को कारोबार से पृथक् रहने के लिए विवश किया जाता रहे।

क्या किसी खास उद्योग में भीषण मन्दी आने पर समस्त अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था के असंतुलित हो जाने का खतरा है? क्या कोई मन्दी १९३० जैसी भीषण मन्दी का रूप धारण कर सकती है? इस सम्बन्ध में उत्तर 'नहीं' में है और इसके निम्नलिखित आठ कारण हैं :—

मन्दी न आने के आठ कारण

१. समस्त व्यापारिक उतार-चढ़ाव भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं। १९३० की भीषण मन्दी अपने ढंग की अनौखी थी। जिन परिस्थितियों का वह परिणाम थी, वैसी परिस्थितियां पुनः होनी सम्भव नहीं। इस बात की सम्भावना विशेष रूप से इसलिए नहीं, क्योंकि जिन लोगों को उस भीषण-मन्दी का कटु अनुभव हो चुका है, वे इस बात का दृढ़ संकल्प कर चुके हैं कि वे पुनः वैसी परिस्थितियां पैदा न होने देंगे। इस सम्बन्ध में वे प्रयत्नशील भी हैं।

२. प्रमुख उद्योगों में वैसा उतार आने की सम्भावना नहीं, जिसकी कल्पना कुछ निराशावादी करते हैं। उदाहरण के रूप में नया गृह-निर्माण उद्योग १९५५ के उच्चतम स्तर पर भले ही कायम न रहे, किन्तु उसमें बहुत अधिक कमी हो जाने की कल्पना नहीं की जा सकती।

३. किसी भी उद्योग को आज पहले जैसा महत्व प्राप्त नहीं। इनमें मोटर-उद्योग जैसे विशालकाय उद्योग भी सम्मिलित हैं। इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बात यह है कि मोटर-उद्योग के उत्पादन में इस वर्ष के प्रारम्भिक दिनों में २५ प्रतिशत की कमी हो जाने पर भी कुल औद्योगिक उत्पादन में केवल २ प्रतिशत की ही कमी हो सकी। समस्त राष्ट्रीय उत्पादन ४ खरब डालर से भी अधिक इस वर्ष हो गया। इसी प्रकार इस वर्ष के जून मास में काम में लगे लोगोंकी संख्या भी अधिकतम रही। उस समय ६ करोड़ ६५ लाख व्यक्ति काम पर लगे हुए थे। यह संख्या ४ वर्ष पूर्व की संख्या से २५ लाख अधिक है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आशावादी दृष्टिकोण

४. किसी खास क्षेत्र में कमी या गिरावट हो जाने के बावजूद अपने आकार को कायम रखने की अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था का वास्तविक कारण अमेरिकी मण्डी की मजबूती है। युद्ध के बाद से भविष्य की मण्डी के स्वरूप में अनेक प्रकार की एक दूसरे से भिन्न अनेक कल्पनाएं की गई हैं। ये समस्त कल्पनाएं अपने आशावादी दृष्टिकोण के लिहाज से एक समान हैं।

इस आशावादी दृष्टिकोण का कारण आबादी में वृद्धि तथा नए मकानों, सामग्री तथा अन्य उपयोगी उपकरणों की आवश्यकता नहीं, अपितु जीवन-यापन का वह नया ढंग है, जो युद्ध के बाद से अमेरिका में विकसित हो चुका है। इस नए ढंग के कारण वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकताएँ पहले किसी तखमीने से कहीं अधिक हो गई हैं।

५. नए व्यापारिक कारखानों और उपकरणों की स्थापना और खरीद के लिए खर्च होने वाले धन के अनुमानों में भी यद्यपि बहुत अन्तर है, लेकिन इनमें भी सर्वत्र आशावादी दृष्टिकोण पाया जाता है। इस वर्ष इस कार्य के लिए अधिकतम राशि खर्च की गई। यह राशि ३६ अरब डालर वार्षिक की रही, जो गत वर्ष की अपेक्षा २६ प्रतिशत अधिक है। इस व्यय में कमी के कोई चिन्ह दृष्टिचोचर नहीं हो रहे।

अमेरिका इस समय आविष्कारों के नए युग के प्रारम्भिक दौर में से गुजर रहा है। आणविक शक्ति, जेट-चालक शक्ति, कृत्रिम वस्तुओं के निर्माण स्वचालित यन्त्रों के उपयोग तथा अन्य यान्त्रिक विकासों के फलस्वरूप आज की औद्योगिक प्रक्रियाएं पुरानी पड़ कर समाप्त हो जाएंगी तथा पूंजी लगाने के लिए मार्ग सुलभ हो जाएंगे।

इस विकास में अनुसंधान के फलस्वरूप और वृद्धि हो रही है। इस कार्य में अमेरिका अब प्रतिवर्ष ५ अरब डालर खर्च कर रहा है। अनुसंधान सम्बन्धी व्यय १० प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ रहा है।

अर्थव्यवस्था में सरकारी योग

६. अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सरकारी योग का भी कम महत्व नहीं है। रक्षा-सम्बन्धी व्यय इस समय ३५ अरब डालर प्रति वर्ष का है। इसमें बहुत बड़ी कमी होने की सम्भावना नहीं। इस व्यय में किसी प्रकार की कमी होने की दशा में उसकी पूर्ति सामाजिक सुरक्षा-कार्यों से हो जायगी। इसके अतिरिक्त नए स्कूलों, सड़कों और अन्य कार्य-क्रमों के कारण भी सरकारी व्यय काफी रहेगा। इन समस्त कार्यों के फलस्वरूप भीषण मन्दी सम्भव नहीं होगी।

७. यदि अर्थव्यवस्था में कोई अस्थायी उतार आया भी, तो उसकी भीषणता को कम करने के अन्य अनेक उपाय आज सुलभ हैं। इन उपायों से मन्दी के फलस्वरूप होने वाले कष्टों की रोकथाम की जा सकेगी।

गैर-सरकारी क्षेत्र में अनेक बड़े कार्पोरेशन पूंजीगत व्यय में जो देरी लगा रहे हैं, उससे अर्थव्यवस्था को उच्च स्तर पर काफी देर तक बनाये रखने में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त श्रम-संगठनों में भी यह शक्ति है कि वे बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं की क्रय-शक्ति को बनाए रहें। यह कार्य वेतन-दरों में कमी को रोककर, बेकारी-सम्बन्धी योजनाओं में अभिवृद्धि कर तथा वार्षिक वेतन-योजनाओं की गारंटी मांग कर वे कर सकते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र में यह कार्य १९३० के बैंकिंग तथा वित्तीय सुधारों द्वारा संघीय रिजर्व बैंक की उधार देने की प्रणाली द्वारा तथा सरकार की अर्थ व्यवस्था को मजबूत बनाने की विधियों द्वारा सम्पन्न किया जा सकता है। इन विधियों में बेकारी बीमा पद्धति, संघीय कृषि-कार्य-क्रम आय-कर इत्यादि सम्मिलित हैं। अनुमान यह है कि अन्य कोई कानूनी व्यवस्था किए बिना इन विधियों से राष्ट्रीय आय में एक तिहाई कमी होने पर उसकी पूर्ति होनी सम्भव है।

८. इस सबसे भी बड़ी बात यह है कि सरकार की ओर से यह आश्वासन प्राप्त हो गया है कि १९३० जैसी आर्थिक मन्दी को रोकने के लिए जो भी कार्य उचित होगा, उसे वह अवश्य सम्पन्न करेगी। इसके लिए प्राप्त उपायों के

(शेष पृष्ठ ४८ पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अर्थ वृत्त चयन

मितव्यय और सादगी इनसे सीखिये

मैंने कमरे में दाखिल होते ही देखा कि मणिबेन की साड़ी में एक बहुत बड़ी थेगली (पेबन्द) लगी है। मैंने जोर से कहा—"मणिबेन, तुम तो अपने को बहुत बड़ा आदमी मानती हो। तुम एक ऐसे बाप की बेटी हो, जिसने साल भर में इतना बड़ा चक्रवर्ती अखण्ड राज्य कर दिया है कि जितना न रामचन्द्रजी का था, न कृष्ण का, न अशोक का था, न अकबर का और न अंगरेज का था। ऐसे बड़े राजों-महाराजों के सरदार की बेटी होकर तुम्हें शर्म नहीं आती ?...."देहरे शहर में निकल जाओ तो लोग तुम्हारे हाथ में दो पैसे या इकन्नी रख देंगे यह समझकर कि भिखारिन जा रही है। तुम्हें शर्म नहीं आती कि थेगली लगी धोती पहिनती हो।" मैं तो हंसी कर रहा था। सरदार भी खूब हंसे और कहा, "बाजार में तो बहुत लोग फिरते हैं। एक-एक आना करके भी शाम तक बहुत रुपया इकट्ठा कर लेगी।"

पर मैं तो शर्म से डूब मरा, जब सुशीला नायर ने कहा—"त्यागीजी, किससे बात कर रहे हो ? मणि बहन दिन भर सरदार साहब की अथक सेवा करती है। फिर डायरी लिखती हैं और फिर नियम से चरखा कातती हैं। जो सूत बनता है, उसी से सरदार के कुर्ते-धोती बनते हैं। आपकी तरह सरदार साहब कपड़ा खद्दर भण्डार से थोड़े ही खरीदते हैं। जब सरदार साहब के धोती-कुर्ते फट जाते हैं तब उन्हीं को काट-सींकर मणि बहन अपनी साड़ी कुर्ता बनाती हैं।"

मैं राक्षस-रूप उस देवी के सामने अवाक् खड़ा रह गया। कितनी पवित्र आत्मा है मणिबेन। उनके पैर छूने से हम जैसे पापी पवित्र हो सकते हैं। फिर सरदार बोल उठे—"गरीब आदमी की लड़की है, अच्छे कपड़े कहां से लावे ? उसका बाप कुछ कमाता थोड़े ही है।" सरदार ने अपना चश्मे का केस दिखाया। शायद बीस वर्ष पुराना था। इसी तरह तीसियों वर्ष पुरानी घड़ी और एक कमानी का चश्मा देखा जिसके दूसरी ओर धागा बंधा था। कैसी पवित्र आत्मा थी ! कैसा नेता था ! उसी त्याग तपस्या की कमाई खा रहे हैं हम सब नई-नई घड़ियां बांधने वाले देशभक्त।

—महावीर त्यागी

वनों की रक्षा

'यह हमारा सौभाग्य है कि संसार की कुछ सबसे अच्छी किस्म की लकड़ी हमारे वनों में पैदा होती है। सागोन, चन्दन, पदांक, गुरजान और रोजवुड अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की व्यापारिक वस्तुएं हैं।'

इस समय देश की लगभग २० प्रतिशत भूमि पर ऐसे वन हैं, जो सरकार के हैं। यह क्षेत्र बहुत कम है। वनों से सम्बद्ध राष्ट्रीय नीति के अनुसार देश के ३३ प्र० श० क्षेत्र में जंगल होने चाहिएं। पहाड़ों का लगभग ६० प्रतिशत और मैदानों का लगभग २० प्रतिशत क्षेत्र वनों से ढका होना चाहिए। इसी दृष्टि से देश के विशाल क्षेत्र में वन लगाने की योजना बनाई गई है। भारत में लकड़ी की प्रति-व्यक्ति खपत संसार में सबसे कम है। लोगों का जीवन-स्तर ऊंचा उठाने के लिए हमें भांति-भांति के उद्योग बढ़ाने होंगे और उद्योगों तथा खेती-बाड़ी के कामों के लिए लकड़ी की भी बहुत जरूरत होगी। यूरोप के देशों की तुलना में हमारे वनों का उत्पादन बहुत कम है। कुछ वर्षों से साल, सागोन आदि के वनों को बहुत नुकसान पहुँच रहा है। इसको रोकने के लिए हमें जमीन को कटने से रोकना होगा और पानी को बांधने के उपाय करने होंगे।

— श्री पंजाबराव देशमुख

सड़क बनाने का खर्च आधा रह गया

दिल्ली के केन्द्रीय सड़क गवेषणा संस्थान की मिट्टी सम्बन्धी शाखा ने सड़कें बनाने की एक ऐसी विधि निकाली है, जिससे सड़कें बनाने का खर्च आधा रह जायगा। इस विधि के अनुसार मिट्टी को खूब कड़ा करके उससे सड़कें बनायी जाती हैं।

इस समय केवल एक सड़क के बनाने पर औसतन ३५,००० रु० मील खर्च बैठता है। उक्त नयी विधि से यह खर्च १८,००० रु० मील आयेगा और गांवोंकी सड़कों पर ऊपरसे पक्का करनेकी जरूरत नहीं होती। यह खर्च १०,००० रु० मील तक भी कम किया जा सकता है। कदि गांव

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वाले श्रमदान द्वारा सड़क बनाना चाहेंगे तो निर्माण का खर्च और भी कम, तीन हजार रु० मील ही बैठेगा। बहुत अधिक वर्षा वाले स्थानों को छोड़कर देश के बाकी सब भागों में इस तरह की सड़कें उपयोगी रहेंगी और इस प्रकार करोड़ों रु० की बचत हो सकेगी।

कई स्थानीय मिट्टियों को मिलाकर वैज्ञानिक रीति से ऐसा एक मिश्रण तैयार किया जाता है, जो हर मौसम और खुश्की और नमी में एक-सा कठोर रहे। इसके बाद इसमें ईंट, कंकड़ आदि मिलाकर इसका घनत्व बढ़ाया जाता है और फिर ऊपर से राल चढ़ादी जाती है।

लगभग ११ साल पहले पंजाब में इस तरह की २८० मील लम्बी सड़कें बनायी गयी थीं। काफी यातायात होने के बाद भी, ये अब तक अच्छी हालत में हैं। इसके अलावा इस दौरान में जो अनुभव मिला, उससे मिट्टी को सख्त करने के तरीके में और सुधार किया गया है।

इन्जनों की कीमतें

भारत सरकार ने अक्टूबर १९५५ में तट-कर कमीशन को यह काम सौंपा था, कि वह जांच करके यह निश्चय करे कि टाटा कम्पनीके कारखानेमें बनने वाले इंजनों की क्या कीमत होनी चाहिये। कम्पनीने जो कीमतें १ फरवरी १९५४ से मार्च १९५५ तक और १ मार्च १९५५ से ३१ मार्च ५६ तक के लिये बताई थीं, वे रेलवे बोर्ड को अधिक प्रतीत हुईं, इसलिए यह काम उक्त कमीशनको सौंपा गया था। कमीशनने जो सिफ़रिशें की हैं, वे सरकार ने स्वीकार करती हैं। कम्पनी और कमीशन द्वारा बताई गयी कीमतें निम्नलिखित हैं :—

	कम्पनी के अनुसार	कमीशन की अन्तर सिफारिशें	
	रुपये		रुपये
वाई. पी. इंजिन (एक)	७,२०,३९६	६,९०,१०५	३०२९१
एफ. सी. बायलर(एक)	३,६८,०९८	३,४०,९०८	२७१९०
वाई. डी. बायलर(एक)	२,०८,०७२	१,७५,५१२	३२५६०

इसी तरह १९५५,५६ के लिये दोनों की कीमतें निम्नलिखित हैं।

वाई० पी० इंजिन	६६३०२८	६३९८२९
वाई० पी० बायलर	२८०२७२	१६३२१६

इसी तरह दूसरे बायलरों की कीमतें भी कम की गई है। आगे के लिये कमशीनने यह राय दी है कि निर्माण व्यय के बदलने के साथ-साथ कीमतें भी बदलनी चाहिये।

सर्वसाधारण के लिये सस्ते कम्बल

भारतीय केन्द्रीय जूट समिति, कलकत्ता की औद्योगिक गवेषणा प्रयोगशाला में पश्चिम जर्मनी से मंगायी गयी ऐसी मशीन लगायी गयी है, जो ऊन मिश्रित जूट के कम्बल, रैपर आदि तैयार करती है। भारत में आयात की गयी यह अपने ढंग की पहली मशीन है।

इस मशीनके द्वारा जूट और ऊन समान मात्रामें मिलाकर जो कपड़ा तैयार किया जायगा, वह टिकाऊ और बढ़िया होने के साथ-साथ अपेक्षाकृत सस्ता पड़ेगा। प्रयोगशाला में की गयी गवेषणा से यह भी ज्ञात हुआ है कि इस तरह का कपड़ा कई खूबसूरत और पक्के रंगोंमें तैयार किया जा सकता है, जिससे कई तरह की कलात्मक वस्तुएं बनायी जा सकती हैं।

यह मशीन केन्द्रीय पुनस्संस्थापन विभागने मंगायी है। इसके दो लाभ होंगे—एक तो पूर्व पाकिस्तान के विस्थापितोंको काम मिल सकेगा और दूसरे सर्व-साधारण को सस्ते दामों पर टिकाऊ कम्बल, रैपर आदि मिल सकेंगे।

आप भी अपने खर्च कम कीजिए

छोटी बचत योजना में, पहली आयोजना की अवधि में लक्ष्य से भी ११ करोड़ रुपए अधिक एकत्र हुए। इसका लक्ष्य २२५ करोड़ रु० था।

पहली आयोजना की अवधि में बचत की रकम में साल दर साल वृद्धि होती रही। १९४८-४९ में २९ करोड़ ७१ रु०; १९४९-५० में २५ करोड़ ६२ लाख रु०; १९५०-५१ में ३३ करोड़ ७९ लाख रु०; १९५१-५२ में ३८ करोड़ ७९ लाख रु०; १९५२-५३ में ३९ करोड़ ७९ लाख रु०; १९५३-५४ में ३९ करोड़ ६६ लाख रु०; १९५४-५५ में ५५ करोड़ ५१ लाख रु०; १९५-५६ में ६७ करोड़ ९१ लाख रु० और अक्टूबर १९५६ तक, ७ महीनों में, ३८ करोड़ १० लाख रु० जमा हुए।

दूसरी आयोजना में ५०० करोड़ रु० अर्थात् १०० करोड़ रुपए प्रति वर्ष एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य तक, पहुंचने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दोनों ही क्षेत्रों में राष्ट्रीय बचत संगठन का विस्तार करने का प्रयत्न करना पड़ेगा ।

बचत के आन्दोलन को प्रोत्साहित करने के लिए दो नयी योजनाएं स्वीकार की गयी हैं और वे शीघ्र ही चालू हो जाएंगी । वे योजनाएं हैं—उपहार कूपन योजना और विशेष लक्ष्य के लिए धन जमा करने की योजना ।

क्या सम्पदा के हजारों पाठक-पाठिकाएं इस दृष्टि से कुछ सहयोग न देंगी ?

प्रति व्यक्ति कपड़े की खपत

इस समय प्रति व्यक्ति पीछे १६.८ गज कपड़े की खपत होती है । अनुमान है कि दूसरी पंचवर्षीय आयोजना में यह बढ़कर १८.५ गज हो जायगी । हमें कुल मिलाकर ८ अरब ४० करोड़ गज कपड़े का उत्पादन करने की आवश्यकता है । इसमें से १८.५ गज प्रति व्यक्ति के हिसाब से जनता के लिए और बाकी निर्यात के लिए चाहिए । १९५५ में कुल ६ अरब ७० करोड़ गज कपड़ा तैयार किया गया था । इसमें से ५ अरब गज मिलों से, १ अरब ५० करोड़ गज हथकर्घों से और २० करोड़ गज बिजली से चलने वाले कर्घों से तैयार किया गया ।

हमारा लक्ष्य, मौजूदा उत्पादन से १ अरब ७० करोड़ गज अधिक है । इस कमी को पूरा करने के लिए, मिलों को ३५ करोड़ गज, हथकर्घों को १ अरब गज और बिजली से चलने वाये कर्घों को २० करोड़ गज कपड़ा अधिक तैयार करना होगा । बाकी के १५ करोड़ गज की कमी किस प्रकार पूरी की जाय, यह बाद में तय किया जायगा ।

पूंजीगत लाभ पर कर क्या है ?

सम्पदा के पाठक गतांक में यह पढ़ चुके हैं कि सरकार ने पूंजीगत लाभ पर कर लगाये हैं । लेकिन यह कर क्या है, किस पर लगेगा, यह जानकारी नीचे दी जाती है ।

यह कर (१) जमीन जायदाद के बेचने पर चाहे अपनी इच्छा से बेची जाये, चाहे सरकार अपने काम के लिए खरीद लें, जो लाभ होगा उस पर ।

(२) यदि कोई साझेदारी का कारोबार बन्द हो जाये और उसका सामान वगैरह बेच-बाच कर जो लाभ साझेदारों में बांटा जाये, उस पर ।

(३) यदि कोई कम्पनी दीवाले में चली गई हो तो, उसका माल बेचकर जो लाभ शेयर होल्डरों को बांटा जायगा उस पर ।

(४) रहने के लिए जो मकान है, ६ वर्ष तक रहने के बाद उस पर ।

१९४६ में जब यह टैक्स बेकार समझकर रद्द कर दिया गया था, तब १५०००) रुपये के लाभ तक कोई कर नहीं लगता था । नये प्रस्ताव में वह रकम घटाकर ५०००) रुपये कर दी गई है । हां जो साधारण गृहस्थ पूंजीगत लाभ अपनी कुछ आमदनी मिलाकर १०,०००) रुपये से अधिक आमदनी नहीं कर सकेंगे, उनसे इनकमटैक्स ही लिया जायेगा पूंजीगत लाभकर नहीं लिया जायेगा । २५०००) तक का मकान बेचने वाले को यह टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बशर्ते बेचने वाले के पास और दूसरा मकान न हो ।

यह टैक्स आमदनी पर आय कर तथा और जो अधिक मुनाफा हुआ होगा, उस पर तृतीयांश अर्थात् १) में ।-)४ पाई के हिसाब से लिया जायेगा । और या तो पहले जो दाम लगे होंगे, उस पर या १ जनवरी १९५४ को उसके जो दाम हो सकते हैं, उसी हिसाब से लिया जायेगा ।

यह कर १ अप्रैल १९५६ से और उसके बाद से लगना शुरू हो जायेगा ।

नया बैंक कानून

दिसम्बर के दूसरे सप्ताह में वित्त मंत्री श्री कृष्णमाचार्य ने लोकसभा में बैंक कम्पनी (संशोधन) बिल पेश किया था, जो पास होगया है । इस कानून का उद्देश्य बैंकों पर और नियंत्रण करना है । बिल के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए बताया गया है—

१. बैंकों के कर्मचारियों को जो अत्यधिक पारिश्रमिक दिया जाता है, उस पर सब बातों पर बिचार कर रोक लगाना ।

२. शेयर होल्डरों को मताधिकार में जो रोक है उसका उपयोग उन बैंकों पर भी करना ,जो अभी तक इससे मुक्त हैं । इसमें वे बैंक आते हैं, जिनकी स्थापना १५जनवरी१९३७ के पहले हुई थी। रिजर्व बैंक को यह अधिकार मिल गया है कि वह बैंकों को नये मतदान पर रोक के अनुसार अपने

[शेष पृष्ठ ४२ पर]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नया सामयिक साहित्य

ज्ञानदेव चिन्तनिक ले०—आचार्य विनोबा। अनुवादक श्री दामोदरदास मूंदड़ा। प्रकाशक अखिल भारत सर्वसेवा, प्रकाशन, राजघाट काशी, पृष्ठ १५०। मूल्य १२ आने।

ज्ञानदेव महाराष्ट्र के महान संत हो चुके हैं। इन्हीं ज्ञानदेव के भजनों का 'चिन्तन' संत विनोबा मराठी में लिखाते रहते थे। दस वर्ष तक यह क्रम चलता रहा और बाद में यह पुस्तक मराठी में प्रकाशित हो गई। हिन्दी में इसका अनुवाद श्री दामोदर दास मूंदड़ा ने किया है, जिनको विनोबा के चिर सांनिध्य में रहने का अवसर मिला है। इन्होंने लिखा है कि विनोबा इन भजनों को (मराठी में) लिखाते-लिखाते ऐसी भाव-समाधि में लीन हो जाते कि इस दुनिया का उन्हें कुछ भान ही न रहता। कितनी ही देर तक अश्रु धाराएं बहती रहतीं। पुस्तक में इस अनुभाव सातत्य की झाँकी है।

सर्वोदय पद-यात्रा—श्री दामोदर मूंदड़ा। प्रकाशक उपर्युक्त। पृष्ठ २३८। मूल्य १ रुपया।

सर्वोदय विचारधारा के अनुसार पदयात्रा का विशेष महत्त्व है। इससे देश-दर्शन होता है, जनता के साथ सम्पर्क बढ़ता है और मुख्य कर सर्वोदय के संदेश का भी प्रचार प्रसार होता है। प्रस्तुत पुस्तक सर्वोदय के मार्ग पर चलने वाले एक पद यात्री की स्वानुभूति, वाणी का रूप धारण करके प्रकट हुई है। यह पद-यात्री और कोई नहीं, स्वयं लेखक श्री दामोदर मूंदड़ा हैं। इस पुस्तिका से देश दर्शन, जनता से सम्पर्क और सर्वोदय संदेश तीनों का परिचय हो जाता है और रोचक वाणी में।

हिंसा का मुकाबला—ले० श्री विनोबा। प्रकाशक वही। पृष्ठ ४० मूल्य ३ आने।

प्रस्तुत पुस्तिका में विनोबा के प्रवचनों का सार दिया गया है। ये प्रवचन भूदान यज्ञ के सिलसिले में धर्मपुरी और सर्वोदय पुरम् (कांचीपुरम्) में दिये गए थे। क्या हिंसा का मुकाबला हो सकेगा? 'हिंसा की चढ़ाई का मुकाबला कैसे, करें? और 'शस्त्र त्याग की शक्ति' के अतिरिक्त अन्य प्रवचन भी महत्वपूर्ण हैं। उन पर मनन करना चाहिए।

पूर्व बुनियादी—लेखिका—शाँता नारूलकर। प्रकाशक वही। पृष्ठ संख्या १०८। मूल्य ८ आने।

पूर्व बुनियादी (शिक्षा) का तात्पर्य छोटे बच्चों की शिक्षा से है, जिसका आरम्भ गर्भाधान से ही हो जाता है जिसमें पालकों (माता-माता) का विशेष दायित्व है। इसी दृष्टिको लेकर लेखिका ने प्रस्तुत पुस्तक में पूर्व बुनियादी शिक्षा पर अपने अनुभवों से प्राप्त विचार रखे हैं—सुझाव के रूप में, आग्रह विशेष से नहीं।

गांधी : एक राजनैतिक अध्ययन—लेखक—श्री जे० बी० कृपलानी। अनुवादक—मंगलनाथ। प्रकाशक उपर्युक्त। पृष्ठ संख्या १००। मूल्य ८ आने।

इस पुस्तक में अनुवादक ने आचार्य कृपलानी के गांधी विषयक लेखों को एकत्र कर दिया है, जो सबके सब 'विजिल' नामक अंग्रेजी पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। लेखक ने (अनुवादक नहीं) अपने इन लेखों के उद्देश्य में स्पष्ट लिखा है कि गांधीजी की रचनात्मक योजनाओं में सामाजिक राजनैतिक और आर्थिक समुत्थान का मूल निहित है, परन्तु लोग आज इनकी उपेक्षा करने लगे हैं और यदि उन्हें कार्यान्वित करने की कोशिश भी होती है, तो गांधी जी की नीति और शिक्षा के विपरीत ही।" वास्तव में ये लेख यही सोचने को विवश करते हैं कि क्या हमारी दशा ऐसी नहीं हो गई है?

युग प्रभात—(केरल का सचित्र हिन्दी पाक्षिक) सम्पादक—एन. वी. कृष्ण वारियर, प्रकाशक—मातृभूमि प्रिंटिंग एण्ड पबलिशिंग कम्पनी लिमिटेड कोषीकोड—केरल। पृष्ठ २८। मूल्य ४ आने प्रति।

दक्षिण में हिन्दी के प्रचार का ठोस प्रमाण ही यह प्रभात या युग प्रभात नामक पत्र है। इसका प्रकाशन केरल के प्रसिद्ध दैनिक साप्ताहिक मातृभूमि के प्रकाशकों द्वारा किया गया है। उसका उद्देश्य भी यही है कि उत्तर और दक्षिण के बीच राष्ट्रभाषा हिन्दी के माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान से भारत की एकता को अक्षुण्ण रखा जाय।

पत्रिका के प्रथम और द्वितीय अङ्क हमारे सामने हैं। केरल को ही नहीं, पूर्ण दक्षिण की साहित्य-संस्कृति, सभ्यता

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्बन्धी लेख-कविता कहानी आदि का चयन इनमें किया गया है। दक्षिण और उत्तर को परस्पर अनेक भ्रान्तियों का निराकरण पत्रिका के द्वारा होता रहेगा।

प्रकाशकों का उद्देश्य शीघ्र ही इस पाक्षिक पत्रिका को साप्ताहिक बना देने का है। पत्रिका के सम्पादक मजमालम के प्रमुख कवि और हिन्दी के अच्छे लेखक हैं। छपाई सफाई और सम्पादन आदि की दृष्टि से यह पत्रिका हमारे अधिकांश पत्रों से कई बातों में बढ़ कर हैं।

—म० मो० बि०

प्राप्ति स्वीकार

१—भारत और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था—लेखक श्रीनरेन्द्र नाथ कौल, राजकमल प्रकाशन मूल्य ३।)

२—भारतीय कृष्टि का क ख—लेखक जयचन्द्र विद्यालंकार। प्रकाशक हिन्दी भवन अलाहाबाद। मूल्य ६)

३—मनुष्य की कहानी—लेखक जयचन्द्र विद्यालंकार, प्रकाशक हिन्दी भवन मूल्य ॥=)

४—हमारा भारत—लेखक जयचन्द्र विद्यालंकार, हिन्दी भवन। मूल्य ।=)

५—छात्रों के बीच—ले० जयप्रकाश नारायण। प्रकाशक अ० भा० सर्व-सेवा-संघ प्रकाशन। मूल्य ।)

६—सामूहिक पद यात्रा—लेखक ठाकुरदास बंग, प्रकाशक—अ० भा० सर्व-सेवा-संघ प्रकाशन। मूल्य ।)

भूदान यज्ञ क्या और क्यों—लेखक चारुचन्द्र भण्डारी प्रकाशक अ० भा० सर्व सेवा-संघ प्रकाशन। मूल्य १)

८—मध्य भारत का इतिहास (प्रथम खण्ड) लेखक श्रीहरिहर निवास द्विवेदी। प्रकाशक-संचालक सूचना विभाग मध्यभारत, लश्कर ग्वालियर।

इन पुस्तकों की समालोचना आगामी अंकों में की जायेगी।

[पृष्ठ ४० का शेष]

डाइरेक्टरों को फिर से निर्वाचन करने की आज्ञा दे सके।

३. यदि कोई व्यक्ति ऐसी कम्पनियों का डाइरेक्टर होगा, जिसके पास मतदान के २० प्रतिशत से अधिक मतदान-अधिकार हैं, तो वह बैंक का डाइरेक्टर न रह सकेगा।

४. रिजर्व बैंक को यह अधिकार दिया है कि वह बैंक से और अधिक विषयों के सम्बन्ध में वक्तव्य और वस्तुस्थिति की मांग कर सके यह अधिकार रिजर्व बैंक को अब तक न था। बैंकिंग कम्पनी कानून के अन्तर्गत दिए हुए कामों को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है।

५. रिजर्व बैंक को यह अधिकार दिया गया है कि बैंकिंग कम्पनियों को उनकी नीति और कार्य-कलाप के सम्बन्ध में आज्ञा दे सके जिससे जनसाधारण का अहित होता है। यदि बैंक उस आज्ञा को अमान्य करे, तो रिजर्व बैंक उन पर कार्रवाई कर सकेगा।

६. बैंकिंग कम्पनी द्वारा अपने मैनेजिंग डाइरेक्टर, मैनेजर या चीफ एक्जिक्यूटिव आफिसर की नियुक्ति रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के बाद की जायगी।

७. रिजर्व बैंक को यह अधिकार मिल गया है कि वह अपने एक या अधिक निरीक्षक किसी भी बैंक में रख सके, जिससे बैंक के पूरे कार्य-कलाप की रिपोर्ट उससे मिल सके।

८. बैंकिंग कम्पनियोंके चेयरमैन, डाइरेक्टर आडिटर लिक्विडेटर तथा अन्य कर्मचारियों को पब्लिक सर्वैण्ट, की परिभाषा के अन्दर ले आया गया है जिनसे कि भारतीय दण्ड विधान और भ्रष्टाचार निरोधक नियम के अनुसार रिश्वत आदि अनियमित कार्यों पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

बाढ़ से नुकसान

अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले महीनों में ३३,८९० वर्ग मील क्षेत्र में बाढ़ों से नुकसान हुआ है। बाढ़ से सबसे अधिक नुकसान पश्चिम बंगाल (१० ००० वर्गमील से कुछ अधिक) में और फिर उत्तर प्रदेश (१०, ००० वर्ग मील से कुछ कम) में हुआ। इससे १ करोड़ ६० लाख जनसंख्या को नुकसान पहुँचा और लगभग ५१५ व्यक्ति मरे। बाढ़ों से ८ करोड़ ३७ लाख रुपए के मूल्य के लगभग ३ लाख ५० हजार मकान धराशायी हो गये। इसके अलावा, १ लाख ९७ हजार रुपए के मूल्य के लगभग १६,७२० पशु बह गए। ३० लाख ८७ हजार एकड़ रुपए से भी अधिक मूल्य की फसलों को नुकसान पहुँचा।

—सन् १९५५ में भारत में कुल ३,९३,१०० टन अमोनियम सल्फेट तैयार किया गया, जबकि १९४६ में सिर्फ २२,४५० टन का उत्पादन हुआ था।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

क्रान्ति की अनोखी प्रक्रिया

(दादा धर्माधिकारी)

लोकतन्त्र की स्थापना के बाद भी अमीर अमीर रह गया और गरीब गरीब रहा। एक वाक्य में कहें, तो गरीब तख्त का राजा तो बन गया, परन्तु मालिक नहीं बना। मान लें कि आज जो मालिक है, वह मजदूर बन जाय और मजदूर मालिक बन जाय, फिर भी मजदूर और मालिक तो बने ही रहे और मालिक-मजदूर का फर्क भी बना ही रहा। क्रांति तो तभी होगी, जब मालिक-मजदूर का भेद नहीं रहेगा।

इसके लिए हमें ऐसा समाज कायम करना होगा, जिसमें जरूरत की चीज उसे मिलेगी, जिसे उसकी जरूरत है। विनोबा इसलिए कहते हैं कि जो जमीन जोतता नहीं, उसे जमीन का मालिक नहीं रहना चाहिए, जमीन उसके हाथ में होनी चाहिए, जो जोतता है। इसी तरह काम करने के औजार उसके हाथ में रहें, जो वह काम करता है। जो स्त्री रोटी बनाती है, उसके पास चकला-बेलन होना चाहिए और जो लिखती है, उसके हाथ में कलम-कागज होना चाहिए।

हम आरम्भ भूमि से करते हैं। इसके कारण स्पष्ट ही हैं। सबसे पहला कारण यह है कि हमारा देश कृषि-प्रधान है। दूसरा यह है कि सबसे बड़ी समस्या भूख है। भूख का जवाब अन्न है। इसलिए इस देश में क्रांति की विभूति जमीन जोतने वाला किसान होगा। जमीन से आरम्भ करने का एक तीसरा कारण यह भी है कि उत्पादन के सारे साधनों का मूलभूत साधन, अखंड भण्डार यह धरती है। कोयला, लोहा, तेल, लकड़ी आदि उत्पादन की सारी सामग्री इसी में से निकलती है। इसलिए हम कहते हैं कि जमीन का मालिक वह होगा, जो उस पर मेहनत करेगा। जिसकी जमीन पर मालकियत है, उसे उस पर मेहनत करनी चाहिए। जो मेहनत करेंगे, वे मालिक होंगे, वे सब मेहनत करेंगे।

आज हमारा राजा पैसा बन गया है। आज आदमी की मेहनत और गुण पैसे से बिकती है। जहां ये सब चीज पैसे में बिकने लगीं, वहां वोट भी पैसे में ही बिकेगा। जिसकी मेहनत बिकती है, उसका हक भी बिकेगा। इतना ही नहीं, कानून भी पैसे में बिक जाता है। कानून बन जाय, पर जिसके पास पैसा है, वह जीतता है। जिसके पास लाठी है, वह छीनता है। विनोबा लोगों को बतला रहे हैं कि पैसे की कीमत घटाओ और मेहनत की कीमत बढ़ाओ।

विनोबा कहते हैं कि अमीरी और गरीबी, दोनों बढ़नी चाहिए। दुःख और सुख, दोनों बँटने चाहिए। दुःख बांटने से हल्का हो जाता है और सुख बांटने से दुगना हो जाता है। अमीरी और गरीबी दोनों बंट जायंगी, तो इंसान में इन्सानियत आयेगी, एक-दूसरे से बिछुड़ेंगे नहीं, आपस में मिलेंगे! यह राम और भरत की क्रांति होगी।

सुनहला खतरा

(प्रबोध चोकसी)

आणंद (जिला खेड़ा-गुजरात) में एक अद्यतन डेयरी ने डेरा डाला है। शायद एशिया में उसका कुछ नम्बर लगता है। ख्रुश्चेव को भी दिखाने के लिए लाया गया था और वह खेड़ा के किसानों की सहयोगी संस्था है। दूध से पाश्चराइज्ड मक्खन बना कर अब वह 'पाल्सन' की टक्कर में अपना 'सहयोगी' मक्खन शहरों के बाजारों में और अखबार के पन्नों पर गुरूर से पेश कर रही है और इधर एक खेड़ा की छोटी-सी जगह से एक संवाददाता अपने अखबार को खबर भेजता है 'देहातों से सब दूध आणंद की डेयरी में जा रहा है। पहले तो यहां घी बनता था, तो किसान के बच्चों को छाछ मिलती थी। अब न उनके लिए छाछ रही है, न मेहमदाबाद के छोटे व्यापारी के लिए घी का व्यापार!"

भारत में को-आपरेटिव कामनवेल्थ और सहयोग-प्रधान समाजवादी समाज रचना के सपने हम लोग देख रहे हैं। यहां सहयोग भी है और वह भी देहात के किसानों के नाम पर! सिर्फ बैलगाड़ी के नीचे रबड़ के पहिये ही क्यों,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उद्योग में दशमिक प्रणाली

पिछले विश्व-युद्ध के दिनों में ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा के विशेषज्ञों का एक सम्मेलन हुआ। यह सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य यह था कि मशीनों, मोटर गाड़ियों आदि में एक से पेच लगाने की व्यवस्था की जाए। कारण यह था कि उस समय हर मित्र-देश में बनने वाले यन्त्रों आदि में अलग-अलग नाप के पेच लगते थे और इस कारण एक देशके यन्त्रों में दूसरे देश में नये पुर्जे डालने या मरम्मत करने में कठिनाई होती थी। उदाहरण के लिए, ब्रिटिश मोटर गाड़ियों की मरम्मत अमेरिका के वर्कशापों में नहीं की जा सकती थी। इस सम्मेलन में विचार-विमर्श के बाद एक से नाप के पेच तैयार करने की प्रणाली बनायी गयी।

इसी प्रकार १९३९ में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मण्डल के एक सम्मेलन में विभिन्न देशों के लगभग १ हजार प्रतिनिधि एकत्र हुए, जिन्होंने तोल और नाप के सम्बन्ध में एक सी प्रणाली अपनाने का एक प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि "सभी देशों में एक सी प्रणाली लागू हो जाने से व्यर्थ के और जटिल हिसाब-किताब की परेशानी से बचा सकता है। बहुत से देश नाप और तोल की दशमिक प्रणाली अपने यहाँ अपना चुके हैं, इसलिए अन्य सभी देशों को भी अपने यहां यही प्रणाली लागू कर देनी चाहिए।"

दशमिक प्रणाली का सब से बड़ा लाभ यह है कि इस के कारण डिजाइन बनाने और विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करने का काम तेजी से और ठीक-ठीक हो सकता है। भारत में सरकारी क्षेत्र के कुछ नये उद्योगों में दशमिक प्रणाली के महत्व को समझा गया है। भारत इलैक्ट्रोनिक्स, हिन्दुस्तान मशीन टूल फैक्ट्री और हिन्दुस्तान जहाज कारखाना ऐसे ही उद्योगों में से है।

सभी उद्योगों में बाल-बेयरिंग और रोलर इस्तेमाल में आते हैं। दशमिक प्रणाली के आधार पर ही इनका अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिमान बना है। इस प्रकार इनके नाप का जो यूनिट बना है, वह अन्तर्राष्ट्रीय रूप से मान्य है और यह अनुमान लगाया गया है कि किसी कारखाने की ड्राइंग और विस्तृत विवरण तैयार करने में ही दशमिक प्रणाली के द्वारा ३० प्रतिशत समय की बचत होगी। सिलाई की मशीनों, टाइपराइटरों, मोटरों आदि के निर्माण में इस प्रणाली का विशेष महत्व है।

परिवर्तन का प्रभाव

उद्योग में दशमिक प्रणाली अपनाने का क्या प्रभाव होगा, इस सम्बन्ध में किये गये एक सर्वे से ज्ञात हुआ है कि इसके कारण बहुत अधिक यन्त्रों को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कारण यह है कि एक मशीन

'हार्स-पावर' ही लग गया है। गाड़ी को बैल खींचता है या उससे ढकेला जा रहा है, यह मत पूछिये! इतनी 'प्रगति' के बाद अब देहात की शानोशौकत में भला क्या कमी रह सकती है? आणंद से रेलगाड़ी में उतरने वाले असंख्य यात्री गवाही देंगे कि उस शानदार डेयरी की हवालात को देख कर आंखें चौंधिया जाती हैं। शान तो बेशक बढ़ गयी है, लेकिन जान भी बढ़ रही है क्या?

समाजवाद, सहयोग और ग्रामोद्योग को भी पूंजीवादी रचना--अपने यंत्र के पहिये बना सकता है, बना रहा है। यूरोप-अमेरिका में 'लिमिटेड' और 'इन्कार्पोरेटेड' के उपनयन संस्कार द्वारा पूंजीवाद सामूहिकता से सम्पन्न हुआ, यन्त्र और बाजार के विशाल आकार पर काबू पाने के लिए। रूस में राज्यसंस्था से विवाह करके वह सत्तासम्पन्न भी हुआ है, अपनी संतानों से वर्गों के संघर्ष पर काबू रखने के निमित्त पूंजीवाद और राज्यवाद, दोनों ने विश्व इतिहास में अभूतपूर्व, अश्रुतपूर्व सामर्थ्य प्राप्त कर ली है। अब भारत में 'समाजवाद' के वानप्रस्थाश्रम का नाटक उस दम्पति ने रचा है, समाजदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए। इस 'नाटक' का इतमीनान से स्वागत करके उसे वस्तुगत सत्य में परिणत कर देने का और पूंजीवाद एवं राज्यवाद के शोषण-शासनस्वरूप पापों को निर्मूल करने का आवाहन सर्वोदय को जमाना दे रहा है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

खुद चाहे किसी भी प्रणाली से बनी हो, किंतु उसके द्वारा दशमिक प्रणाली या इंच प्रणाली के अनुसार उत्पादन किया जा सकता है। हो सकता है कि उसके कुछ छोटे-मोटे पुर्जे बदलने पड़ें, लेकिन वे तो वैसे भी आम तौर पर घिसने के बाद बदलने ही पड़ते हैं। इसलिए अब आगे जब उन्हें बदलने का मौका आये तो उन्हें दशमिक प्रणाली के अनुसार बदला जा सकता है।

पिछले तीन वर्षों में किये गये सर्वे के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत के उद्योग दशमिक प्रणाली अपनाने के लिए तैयार हैं। वर्तमान प्रणाली को १९५८ से शुरू करके आगे के दस वर्षों में क्रमिक रूप से बदला जा सकेगा। कुछ समय तक दशमिक प्रणाली और इञ्च प्रणाली साथ-साथ चलेगी।

दोनों प्रणालियों के अनुसार साथ-साथ काम होने से धीरे-धीरे कर्मचारी भी नयी प्रणाली से परिचित हो जायेंगे। उत्पादकों का कहना है कि इञ्च प्रणाली की अपेक्षा दशमिक प्रणाली के अनुसार काम सीखना ज्यादा आसान है।

कपड़ा उद्योग

कपड़ा उद्योग में रेशम और बनावटी रेशम के विभागों में पहले से ही डेनियर प्रणाली के अनुसार काम हो रहा है, जो दशमिक प्रणाली पर आधारित है। सूती कपड़ा विभाग में भी दशमिक प्रणाली अपनाने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि उसमें ज्यादातर मशीनें यूरोप या जापान की बनी हुई है, जहां दशमिक प्रणाली के अनुसार कार्य होता है।

कपड़ा उद्योग में दशमिक प्रणाली अपनाये जाने से बहुत लाभ होने की आशा है। अभी सूत की किस्म बताने के लिए अलग-अलग यूनिटों का उपयोग किया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि तरह तरह के सूत में मुकाबला करना बहुत कठिन हो जाता है। दशमिक प्रणाली लागू होने से यह कठिनाई दूर हो जायगी। इसके कारण उद्योग में स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना आयेगी और उसका अपेक्षाकृत अच्छे ढंग से विकास होगा।

समन्वय की आवश्यकता

उद्योग की विभिन्न शाखाओं में समन्वय और सम्बन्ध स्थापित करना भी बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, दशमिक प्रणाली से टायर और ट्यूब बनाना तब तक व्यर्थ है, जब कि मोटरगाड़ी या साइकिल उद्योग इंच प्रणाली के अनुसार पहिये बनाता रहेगा।

दशमिक प्रणाली अपनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उद्योगों के मालिक इसके महत्व को समझें और परिवर्तन के लिए तैयार हों। अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि इस परिवर्तन में अधिक कठिनाई नहीं होगी।

उद्यम

खिलौना विशेषांक

१५ नवम्बर १९५६ को प्रकाशित होगया

खिलौनों की बिक्री अपने देश में हर साल बढ़ रही है। खिलौने विशेषांक में भारतीय तथा परदेशीय विविध प्रकार के खिलौने की जानकारी दी गयी है। कारखानेदार, व्यापारी वर्ग, पालक तथा बालकों के लिये उपयोगी जानकारी इस अङ्क में पढ़िये।

—उद्यम मासिक, धर्मपेठ, नागपुर १

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विज्ञापनदाताओं के लिए शुभ समाचार

पश्चिमोत्तर भारत की प्रमुख हिन्दी मासिक पत्रिका

विश्व-ज्योति

का वार्षिक अङ्क २८ फरवरी १९५७ को प्रकाशित होगा।

विश्वज्योति सारे देश में विशेषतः पश्चिमोत्तर प्रदेशों में, सहस्रों हाथों में पहुँचती है। प्रायः सभी प्रादेशिक सरकारों द्वारा प्रमाणित होने के कारण यह सर्वत्र कालेजों, स्कूलों और पुस्तकालयों में जाती है। विशेष रूप से वार्षिक अङ्क बहुत संख्या में छपा जा रहा है।

विज्ञापन-दाताओं को चाहिए कि नीचे लिखी दरों के अनुसार रुपया भेजकर विज्ञापन के लिए अभी से स्थान सुरक्षित करा लें।

(१) साधारण पृष्ठ	सम्पूर्ण	५० रुपए	टाइटल पेज २ या ३	चौथाई	३० ,,
,,	आधा	३० ,,	(३) टाइटल पेज ४	सम्पूर्ण	१०० ,,
,,	चौथाई	१५ ,,	,, ,, ,,	आधा	६० ,,
(२) टाइटल पेज २ या ३	सम्पूर्ण	८० ,,	(४) टाइटल पेज ४(दो रंगों में)	सम्पूर्ण	१२० ,,
,, ,, ,,	आधा	५० ,,	,, ,, ,, ,, ,,	आधा	७० ,,

पत्र व्यवहार के लिए पता :—

व्यवस्थापक विश्वज्योति, पो० साधु आश्रम, होश्यारपुर (पंजाब)

आपका स्वास्थ्य

(हिन्दी की एक मात्र स्वास्थ्य सम्बन्धी मासिक पत्रिका)

"आपका स्वास्थ्य" आपके परिवार का साथी है।

"आपका स्वास्थ्य" अपने क्षेत्र के कुशल डाक्टरों द्वारा सम्पादित होता है।

"आपका स्वास्थ्य" में अध्यापकों, अभिभावकों, माताओं और देहातों के लिए विशेष लेख प्रकाशित होता है।

आज ही ६) रु० वार्षिक मूल्य भेजकर ग्राहक बनिए।

व्यवस्थापक,

आपका स्वास्थ्य—बनारस-१

उद्योग विभाग, उत्तरप्रदेशीय सरकार

द्वारा प्रकाशित

सचित्र मासिक पत्र

उद्योग

पढ़िये, जिसमें भारत के आर्थिक विकास, विशेषतया उत्तरप्रदेश की औद्योगिक प्रगति के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण लेखों के साथ साथ अन्यान्य मनोरंजक साहित्यिक सामग्री—कविताएं, कहानियां और लेख भी उपलब्ध होंगी।

विवरणार्थ लिखें :

प्रकाशनाधिकारी
उद्योग विभाग
उत्तरप्रदेश—कानपुर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राजनीतिक दलों के आर्थिक कार्यक्रम

(पृष्ठ १८ का शेष)

(ख) निर्यात-लाभ की सीमा बांध दी जाएगी और ऐसे बड़े लाभ को अनिवार्य रूप में ऋणों के रुपये सरकार को देना होगा। यही बात बड़े उद्योग-व्यापारों के लाभों पर भी लागू होगी।

(३) इस प्रकार सरकार द्वारा ऋण के रूप में ली गई राशि और कम्पनियों की सुरक्षित राशि को मिलाकर राष्ट्रीय विकास निधि की संयोजना की जाएगी जिससे राज्य और निजी दोनों प्रकार के उद्योगों को सहायता दी जाएगी।

(४) विदेशी व्यापार में मुख्य वस्तुओं पर सरकार का एकाधिकार होगा और पारस्परिक समझौते से विदेशी व्यापार को बढ़ाया जाएगा। राज्य को अंतर्देशीय-व्यापार क्षेत्र में भी बढ़ावा दिया जाएगा।

(५) निगम-लाभ, वैयक्तिक संपत्ति और पूंजीगत लाभ पर भारी कर लगाए जाएंगे। बड़े बड़े जमींदारों को मुआवजा देना बन्द कर दिया जाएगा। प्रिवी पर्स भी समाप्त कर दिए जाएंगे, और राजाओं की संचित राशियों को सरकारी ऋण के रूप में ले लिया जाएगा। आयकर और निगमकर से कोई किसी प्रकार से छूट न जाए इसका पूरा प्रयत्न किया जाएगा।

(६) मोटी तनख्वाह पाने वाले अधिकारियों के वेतन और भत्ते कम कर दिए जाएंगे और ध्यान रखा जाएगा कि प्रयोजनाओं और सरकारी उद्योगों में पैसे का अपव्यय न हो।

किसान

(१) तुरन्त ही किसानों की दशा में सुधार किया जाएगा तथा लगान कम किए जाएंगे।

(२) कृषि भूमि को सीमा बांधकर अतिरिक्त खेतिहर मजदूरों और किसानों को बिना मूल्य दे दी जाएगी। भूमि सुधारों के लिए समितियों का निर्माण किया जाएगा। साथ ही कृषि योग्य बंजर भूमि को तीन साल के भीतर ही किसानों और कृषि मजदूरों में मुफ्त वितरित कर दिया जाएगा और उनको इससे कृषि योग्य बनाने में आर्थिक सहायता भी दी जाएगी।

(३) किसानों को बड़े बड़े ग्रामीण ऋणों से मुक्त कर दिया जाएगा। शेष छोटे छोटे ऋणों का इसी उद्देश्य के निमित्त संगठित समिति द्वारा निपटारा किया जाएगा।

(४) सहकारी समितियों का संगठन इस उद्देश्य से किया जाएगा कि वे ग्राम्य ऋण और फसलों के बेचने, कृषि यंत्रों, खाद आदि के खरीदने का प्रबन्ध करें। वर्तमान सहकारिता कानून में संशोधन किया जाएगा जिससे नौकरशाही की सत्ता सहकारी समितियों को प्राप्त हो जाए।

(५) कृषि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर दी जाएगी और कृषि-उपज का मूल्य निर्धारित कर दिया जाएगा।

(६) सिंचाई के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं के साथ साथ छोटी छोटी योजनाओं को भी चालू किया जाएगा। सिंचाई की दर इतनी कर दी जाएगी कि वह किसानों को भार न मालूम हो।

श्रमिक

(१) बड़े बड़े उद्योगों में चल रहे वैज्ञानिकीकरण (रैशनालाईजेशन) को रोका जाएगा।

(२) न्यूनतम राष्ट्रीय मजदूरी निश्चित की जाएगी और मजदूरों को अच्छी मात्रा में मजदूरी दी जाएगी जो न्यूनतम मजदूरी से अधिक होगी। मंहगाई को मूलभूत वेतन में सम्मिलित कर दिया जाएगा।

(३) सामाजिक बीमा योजना का शीघ्रता से विस्तार किया जाएगा और समस्त उद्योगों को इसके क्षेत्र में ले लिया जाएगा। वर्तमान स्वास्थ्य बीमा योजना से मजदूरों के पूरे परिवार लाभ उठा सकेंगे। बेकार अवस्था में उचित संरक्षण दिया जाएगा।

(४) गृह समस्या को प्रभावशाली ढंग से हल करने के लिए समितियों का गठन किया जाएगा जिसमें मजदूरों का खासा भाग होगा।

(५) मजदूरों को बोनस का अधिकार होगा।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अखिल भारतीय प्रजासमाजवादी दल

प्रजा समाजवादी दल के आर्थिक और राजनैतिक कार्यक्रम का केन्द्र बिन्दु किसान और ग्राम पंचायत हैं।

प्रजा समाजवादी दल जन सामान्य के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाएगा और सबको काम दिलाने का प्रयत्न करेगा तथा सबको अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करेगा।

प्रजा समाजवादी दल आज की स्थिति में इस बात पर विश्वास नहीं करता कि देश की प्रगति विकास की दिशा में हो रही है, जब कि मूल्य दिन प्रति दिन बढ़ रहे हैं, बेकारी फैली हुई है और आर्थिक असुविधाएं मुंह बाए खड़ी हैं। श्रमजीवियों का अपना गुजारा कठिन ही नहीं, असम्भव सा हो गया है। अति अल्प आय और लगातार बढ़ते हुए मूल्य, इन दो पाटों के बीच निम्न और मध्यम वर्ग बुरी तरह से पिस रहे हैं।

कर नीति के सम्बन्ध में दल का विश्वास है कि समाजवाद की प्राप्ति आर्थिक समता से ही होगी। अतः करों का निर्धारण इसी दृष्टि से किया जाएगा कि वे सामाजिक समता के साथ साथ आर्थिक समता को भी उत्पन्न करें। कीमतों के बढ़ने पर बड़े बड़े व्यापारियों के विपुल लाभों पर रोक लगाई जानी चाहिए। मुद्रा प्रसार के नियंत्रण को विचार में रखते हुए कर लगाए जाने चाहिए।

पूंजीगत लाभ और विपुल लाभ के अतिरिक्त सम्पत्ति पर भी कर लगाया जाएगा। राजाओं को दिये जाने वाले प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया जाएगा तथा राजाओं की शेष पूरी सम्पत्ति और आय पर देश के सामान्य कानून के अनुसार कर लगाया जाएगा।

उत्तराधिकार कर के साथ साथ उपहार की वस्तुओं पर भी कर लगाया जाएगा।

कर द्वारा प्राप्त समस्त आय का उपयोग लोगों की आय बढ़ाने में किया जाएगा, जिससे उन्हें अधिकाधिक आर्थिक सुविधाएं प्राप्त हों।

कर देने से छूटने का प्रयत्न घोरतम अपराध माना जाएगा और इसके लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था होगी।

दल का विश्वास है कि इस क्षेत्र में उपभोक्ताओं और श्रमिकों के संगठन काफी सहायता प्रदान करेंगे।

समाजवाद की स्थापना के सम्बन्ध में दल का विश्वास है कि जब तक एक वर्ग विशेष सुविधाओं से लाभ उठाता रहेगा, तब तक समाजवाद की स्थापना नहीं की जा सकती। अतः इस वर्ग का उन्मूलन किया जाएगा।

इस समय शासन के आन्तरिक और बाह्य, दोनों पक्षों में जो अपव्यय हो रहा है, उसको रोका जाएगा।

मजदूरों को व्यापक रूप में व्यवस्था कार्य में सम्मिलत किया जाएगा।

मजदूर संघों और कारखानों की समितियों को विकास, उत्पादन और आयोजना में सहयोग देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

गांवों में मूलभूत क्रांति का साधन, ग्राम पंचायतों को बनाया जाएगा, पंचायतों के सहयोग से ही ग्राम अर्थ व्यवस्था के साथ साथ ग्राम्य शासन का भी प्रबन्ध किया जाएगा, जिससे महात्मा गांधी का 'स्वराज्य' साकार हो जाए।

(पृष्ठ ३७ का शेष)

अतिरिक्त सुझाए गए उपायों को भी वह कार्य में लाएगी। १९४६ के 'एम्पलायमेन्ट एक्ट' में संघीय सरकार ने इस उत्तरदायित्व को स्वीकार कर लिया है। अमेरिका में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं, जो गम्भीरतापूर्वक यह सोचता हो कि मन्दी को रोकने के लिए सरकार अपने इस उत्तरदायित्व की पूर्ति नहीं करेगी।

वस्तुतः अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था में १९३० सा भीषण संकट उत्पन्न न होने देने के जो कारण ऊपर गिनाये गए हैं, उनमें से अधिकांश भारत में भी, चाहे थोड़ी मात्रा में ही हों,, विद्यमान हैं और इसलिए यहां भी १९३० की तरह भीषण आर्थिक संकट की कल्पना नहीं की जा सकती और न अनाज २-२॥ रु० मन होना ही सम्भव है।

—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बैंक अंक पर कुछ सम्मतियाँ

The editor of this very useful Hindi Journal of Economics is to be again congratulated upon an admirable special number. This 'Bank Issue' gives all round information of the banking business not only of this country and its various parts, but also in England, America, Germany and other foreign countries. It explains not only the working of Indian Banks and their place in nation's economy but also the International Monetry Fund and the World Bank and their importance in the world ecnomy. Almost all article give useful information on the topics of their choice and are supplemented by statistics where required. In fine here is one more 'Sampda' special worth treasuring as a source of ready reference.

—आर्गेनाइजर

आर्थिक पत्रिकाओं में 'सम्पदा' का महत्वपूर्ण स्थान है। उसने सदैव राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निष्पक्ष सामग्री प्रस्तुत करने का गुरुतर कार्य अत्यन्त सफलतापूर्वक किया है। प्रस्तुत 'बैंक अंक' में बैंक सम्बन्धी सभी पहलुओं का यथोचित विवेचन करते हुए महत्वपूर्ण विषयों पर गम्भीर प्रकाश डाला है। 'देश में बैंकों का महत्वपूर्ण स्थान' 'भारत में आधुनिक बैंकों का विकास' आदि लेख जहां बैंकिंग व्यवस्था के सम्बन्ध में पाठकों को ज्ञान प्रदान कर सकेंगे, वहां "बैंक आफ इंगलैंड", 'अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष' 'अमेरिका में बैंकिंग व्यवस्था' आदि लेख विदेशों की बैंकिंग व्यवस्था का।

आशा है कि अंक "भारत के ३६ करोड़ पुत्रों में "एक-एक पैसा बचाकर" राष्ट्रीय योजनाओंको पूर्ण करने की भावना निर्माण करनेमें सफल हो सकेगा। — पांचजन्य

हिन्दी की अर्थशास्त्र-विषयक पत्र-पत्रिकाओं में "सम्पदा" का अपना विशिष्ट स्थान है। यह पत्रिका अपने प्रथम वर्ष से ही अर्थशास्त्र सम्बन्धी विभिन्न विषयों पर अत्यन्त उपयोगी एव महत्वपूर्ण विशेषाङ्क प्रकाशित करती चली आ रही है। प्रस्तुत "बैंक अंक" पत्रिका का नया विशेषाङ्क है। इस में जिन विषयों की अधिकारी विद्वानों ने चर्चा की है, उन में से कुछ-एक ये हैं:—"बैंकों की समस्याएँ", "बैंक-दर", "केन्द्रीय बैंक का महत्त्व", 'ग्रामीण वित्त की समस्या", रूस, अमेरिका व जर्मनी में बैंक-व्यवस्था, "स्टेट बैंक आफ इंडिया", "रिजर्व बैंक", "बैंक क्या करते हैं", विश्व बैंक" आदि आदि।"

अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों एवं बैंक सम्बन्धी विशद प्रामाणिक जानकारी चाहने वाले पाठकों के लिए विशेषाङ्क पठनीय ही नहीं अपितु संग्रहणीय भी है। —विश्वज्योति

(पृष्ठ १३ का शेष)

एक्ट में भी संशोधन किया गया। दिल्ली में मद्य निषेध की दिशा में एक कदम उठाया गया। राज्यों के आय स्रोतों के निश्चय के लिए की श्री सन्थानम की अध्यक्षता में दूसरा वित्त कमीशन बनाया गया है। उसने अन्तरिम सिफारिशें भी कर दी हैं। श्री देशमुख की जगह वित्त मंत्री का पद श्री कृष्णमाचार्य ने ले लिया है। ४ अगस्त को प्रथम अणुशक्ति-रिएक्टर की स्थापना इस वर्ष की एक उल्लेखनीय घटना है।

भूदान यज्ञ

वर्ष की समाप्ति पर विभिन्न राजनैतिक दलों ने से वोट लेने के लिए चुनाव घोषणा पत्रों में बड़े-बड़े आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये हैं। पाठक इन्हें अन्यत्र पढ़ेंगे।

भूदान आन्दोलन की चर्चा किये बिना यह लेख अपूर्ण रहेगा। आचार्य विनोबा के प्रयत्न निरंतर जारी रहे, किन्तु इस वर्ष भूदान की एकड़ों में संख्या विशेष नहीं बढ़ी। इसका मुख्य कारण सिवाय इसके क्या है कि सार्वजनिक कार्य कर्त्ता राजनीति के चक्र में अधिक व्यस्त रहे और भूदान की उपेक्षा हो गई। आचार्य विनोबा ने भूदान समितियों को भंग करके तथा गांधी निधि से सहायता बन्द करके तंत्र और निधि से मुक्त करने की जो क्रान्तिकारी योजना बनाई है, उसकी सफलता के बारे में एक वर्ष बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। १९५७ अन्तिम वर्ष है, जिसमें ५ करोड़ एकड़ भूमिदान का लक्ष्य पूर्ण करना है। देखें, राजनीति और अर्थ प्रधान युग में भूदान यज्ञ का भविष्य क्या होगा?

—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वस्त्र आयात व निर्यात की समस्या

[पृष्ठ २३ का शेष]

लम्बा समय लगेगा। वास्तव में मुझे भय है कि इस समय से लेकर जब इन करघों का माल निर्यात के लिए पूरी तरह उपलब्ध होगा, तब तक १८ महीने निकल जाएंगे। मैं समझता हूं कि इन लाइसेंसों के देने में बहुत अधिक प्रतिबन्ध रखे गए हैं और स्वचलित करघों और दूसरी सामग्री पर बहुत ऊंची पूंजी की लागत को देखते हुए इसका बदला आकर्षक प्रतीत नहीं होता। जबकि हम यह देखते हैं कि निकासी के माल पर मिलने वाले मूल्यों का रुख निश्चित रूप से नीचे की ओर है, तो इसका आकर्षण और भी जाता रहता है। यह सम्भव है कि इच्छित समय के अन्दर इस सारी नीति को अमल में लाने पर इसका प्रतिकूल प्रभाव हो। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि बाहर से मशीनरी मंगवाने में विलंब के प्रमाण पहले ही मिल रहे हैं जो स्वचलित करघों के सम्बन्ध में एक विशेष महत्व की बात है।

इसके सिवाय, इस नीति के अधीन निर्यात के माल का पुराना दर्जा बनाए रखने का दायित्व उन मिलों पर ही आ पड़ता है जिन्हें इस नई योजना के अधीन करघे लगाने की स्वीकृति मिली है। अन्य मिलों पर इस प्रकार का कोई दायित्व नहीं है।

जबकि मिल वस्त्र का उत्पादन बढ़ाने की नीति निर्धारित की जा रही है, तब यह आवश्यक है कि निर्यात को स्थिर रखा जाए और बढ़ाया जाए। मेरी सम्मति में देश का हित अधिक अच्छी तरह सिद्ध होगा यदि वस्त्र के निर्यात का काम अधिक निष्पक्षता से इस काम में लगी हुई सभी मिलों में बांट दिया जाए और ऐसी शर्त लगा दी जाए कि कुल उत्पादन का कम से कम इतना प्रतिशत माल निर्यात करना होगा। आरम्भ में यह प्रतिशत कम रखकर उत्तरोत्तर बढ़ा दिया जाए क्योंकि देश के विशाल हित में विदेशी मुद्रा के लिए यह आवश्यक है। निःसंदेह सूती कपड़े के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव डालने वाली बड़ी बातों का ध्यान रखना होगा। देश के अन्दर बढ़ती हुई और अधिक लाभदायक मांग के होते हुए, निर्यात की अभीष्ट मात्रा पर प्रभाव डाले बिना, किसी भी उत्पादक के लिए एक मिल से दूसरी मिल पर कोटे के बदलने में प्रायः अधिक कठिनाई होगी। अब समय आ पहुँचा है जब हमारा नियत कार्य केवल कुछ एक मिलों के प्रयत्नों का फल ही नहीं होना चाहिए, बल्कि समस्त उद्योग में फैले हुए परिश्रम से किया जाना चाहिए जिससे राष्ट्र कार्य के लिए अपेक्षित विदेशी मुद्रा अर्जित हो सके।

लोगों का साधारणतया यह विचार बन गया पता लगता है कि पिछले साल—सवा साल में वस्त्र के दाम जो ऊंचे उठे हैं, उसका कारण मिलों के मुनाफे की मात्रा का बढ़ना है। मैं यह बताना चाहूंगा कि जहाँ लाभ की सीमा बढ़ी है, वहां उद्योग के सामने साधारणतया हर बड़ी मद में लागत बढ़ने की समस्या खड़ी हो गई है। इस प्रकार पिछले मौसम में विभिन्न प्रकार की रुई के मूल्य २० प्रतिशत से ४० प्रतिशत ऊंचे हो गए हैं। मजदूरी का खर्च बढ़ गया है और महंगाई भत्ते की दरों में मई १९५६ की तुलना में अक्टूबर १९५६ में १० से २५ प्रतिशत तक की बढ़ती हो गई। और यह वृद्धि इससे स्पष्ट हो जाती है कि हमारी दिल्ली की सूती कपड़े की मिलों में जहां मई १९५५ में एक कारीगर को महंगाई भत्ता ४८ रुपए १४ आने मिला था वहां दिसम्बर १९५६ में यह ६२ रुपए १२ आने तक पहुँच गया। इसी प्रकार कोयले के भाव में प्रायः २५ प्रतिशत की वृद्धि हो गई और रेलवे के ढुलाई खर्च पिछले बजट से ६। प्रतिशत बढ़ गए।

इस तरह के बाजार में तेजी का रुख जो १९५५-५६ में दिखाई देता है, वह अधिकांश लागत व्यय के बढ़ने से है, न कि उत्पादकों के अनुचित रूप में बढ़ाए गए लाभ से।

वित्त मंत्री द्वारा दिए गए इस आश्वासन का मैं स्वागत करता हूँ कि हाल में बनाए गए, चालू और संचित स्थिर कोष के विभिन्न हिस्सों के सरकार के पास अनिवार्य रूप से जमा करवाने के नियमों से कम्पनियों के चालू काम में कोई कठिनाई नहीं पैदा की जाएगी। किसी भी जमे हुए उद्योग में स्थिर पूंजीगत व्यय समयानुसार बहुत कुछ चालू व्यय हो जाता है। निक्षेप संबंधी नए नियमों को क्रियान्वित करते हुए इस बात का ध्यान रखना होगा कि देरी के कारण धन लगाने के एक इस प्रवाह में विघ्न न उत्पन्न हो।

★ दिल्ली क्लाथ मिल के वार्षिक सभा में दिये गये अध्यक्षीय भाषण से।

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्पदा

अर्थशास्त्र का एकमात्र हिन्दी मासिक
उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, मध्यभारत, पंजाब
राजस्थान व बिहार आदि राज्यों द्वारा स्वीकृत

विषयसूची (जनवरी-दिसम्बर १९५६)

आर्थिक

अर्थचक्र का राष्ट्रीयकरण तथा लोकतंत्र ५३९
आर्थिक विकास और खनिज तेल २२९
आर्थिक विकास व व्यक्ति स्वातंत्र्य ४२५
आय की विषमता ८
उत्पादन वृद्धि बनाम आय की सीमा ३४५
दुनिया में बढ़ती हुई जनसंख्या २९७
देश की आर्थिक गतिविधि—एक समीक्षा ४२७
देश की आर्थिक प्रगति—गत वर्ष का सिंहावलोकन ५९७
नौ वर्ष के बाद भी अस्थिर नीति ४०१
पूंजी पर नियंत्रण २५०
बेकारी की समस्या का अर्थशास्त्रीय उपचार ४०७
भारत और जनसंख्या समस्या ७७२
भारत में आबादी अधिक है ४४५
महंगाई की विषम समस्या ५१९
महंगाई लगातार बढ़ रही है : २९५
राष्ट्र का आर्थिक प्रवाह ५०१
राष्ट्र का आर्थिक प्रवाह ६०८
राष्ट्र की आर्थिक समस्या और उसका समाधान ७४२
रुपए की तंगी ७४५
विगत वर्ष की आर्थिक समस्याएं ६७
स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण ४६३
स्वेज जहर के राष्ट्रीयकरण का आर्थिक पहलू ५८१
शहरों में बेरोजगारी ४८३
सीमेंट की कमी २२८
हमारी अर्थ व्यवस्था पर भारी बोझ ७४८

वित्तीय

असह्य कर २३७
आय कर कौन कौन देते हैं ? ५४६
उत्पादन कर में वृद्धि ५२१
औद्योगिक वित्त निगम ७५३
अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ४६०
नया वित्त आयोग—पृष्ठ भूमि पर एक दृष्टि ४६५
भारत के विभिन्न राज्यों के बजट २६५
भारत में बिक्रीकर-व्यवस्था ४१५
विभिन्न राज्यों में वित्तीय व्यवस्था ४९७
सोलह करोड़ रुपए के नए प्रस्ताव ६५०

पंचवर्षीय योजना

एक हजार करोड़ रुपए की उत्पादन योजना ३२
गरीबी की दीवार में दरार ३४३
जनसहयोग और द्वितीय पंचवर्षीय योजना ४७७
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग बस्तियों का निर्माण ४३७
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के साधन ५
द्वितीय आयोजना और औद्योगिक विकास २५९
दूसरी योजना का डांवाडोल आधार ४९५
देश के सामने गंभीर खतरा ३४१

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

देश में बिजली की कमी २६
नई योजना का अंतिम लक्ष्य ३४४
नागार्जुन सागर योजना २९
प्रथम विकास योजना—अमेरिका का सहयोग ३२१
बड़ी या छोटी सिंचाई योजनाएं ५५७
मध्य रेलवे और द्वितीय पंचवर्षीय योजना ७६३
योजना के साधन २८६
लक्ष्यों की रूप रेखा : द्वितीय पंचवर्षीय योजना—
विकास-योजना और हिन्दी ५२२
साधु-समाज की स्थापना ५२२
सिंचाई योजना कैसे बनाई जाती है ? ३१९
हमारी नई योजना ४८६

राष्ट्रीय विकास अंक मूल्य १।)

(दूसरी पंचवर्षीय योजना पर विशेषांक)

हमें क्या करना है ? ११९
योजना के आधारभूत तत्त्व १२०
हमारी साहसिक योजना १२७
भू-स्वामित्त्व में सतर्कता १२९
हमारी नई नीति और नए लक्ष्य १३०
७१०० करोड़ रुपए की विराट योजना १३१
विभिन्न विचारधाराओं में आर्थिक योजना १३६
दूसरी योजना में उल्लेखनीय तथ्य १३९
द्वितीय योजना के वित्तीय साधन १४१
द्वितीय योजना में ८० लाख लोगों को रोजगार १४४
जन-जन को आमंत्रण १४७
विकास-योजना और विदेशी पूंजी १४८
नई योजना और कृषि-उपज के लक्ष्य १५१
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बिजली व सिंचाई १५५
विकास-योजना में औद्योगिक उन्नति १५९
रेल और जहाजों में उन्नति १६४
वायु-यातायात और संचार १६९

श्रम व योजना

मजदूरों की प्रतिष्ठा और उत्तरदायित्व में गौरव-मय वृद्धि १७१
पहले वेतन स्तर नियत हों १७३
पहली योजना से निराश मजदूर १७४
आवास की विकट समस्या १७५
जन सेवा व जन कल्याण १७७

आलोचनात्मक दृष्टि

योजना में निजी उद्योगों की उपेक्षा १७९
योजना पर एक दृष्टि १८१
योजना में श्रम की आवश्यकता १८३
निजी उद्योग से पक्षपात १८४
विभिन्न मत १८५
औद्योगिक नीति पर विहंगम दृष्टि १८०
आयोजित अर्थ व्यवस्था व बैंक १९०
योजना के लक्ष्य एक दृष्टि में १९४
नई योजना काल का पहला बजट १९५
भारत में कृषि-सुधार २०७

विविध राज्य

मध्यभारत की नई योजना २०३
राजस्थान ,, २०५
उत्तर प्रदेश ,, २०७
काश्मीर ,, २०९
हम कितना आगे बढ़ेंगे ? २११
आपकी आमदनी पर कितना कर लगेगा ? २१५
एक महत्त्वाकांक्षा : मद्य निषेध २१६

उद्योग

उद्योग-विकास के लिए अनेक ऋण-व्यवस्थाएं ७६०
औद्योगिक उन्नति—गणतंत्र के छठे वर्ष में ७१
कुटीर वस्त्र उद्योगों में नई क्रांति ६४
चाय उद्योग की समस्याएं ४०३
चाय उद्योग पर एक दृष्टि ४२
छोटे उद्योग और दूसरी योजना ३१२
नया दियासलाई उद्योग १०५
देश की सुन्दर दस्तकारियां ६१
निजी क्षेत्र के लिए पूंजी १७७
वस्त्र-उद्योग नीति में क्रान्तिकारी परिवर्तन ४२३
भारत का खनिज उद्योग ५११
भारत की औद्योगिक नीति २९१

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारतीय जूट उद्योग और उसकी समस्याएं ७३५
भारत में चीनी उद्योग का विकास ८७
भारत में हाथ कागज का उद्योग ८९
सूती मिलें बनाम अम्बर चर्खा १६
सीमेंट का सरकारी उद्योग ५२२
हमारी औद्योगिक नीति—१ ४११
हमारी औद्योगिक नीति—२ ४६१
हमारी औद्योगिक नीति—३ ५५२
हमारी नई उद्योग नीति २८५
हाथ कर्घों की मांगलिक संभावनाएं—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ६५
हाथ कर्घे भी बिजली से चलेंगे ४६०

हमारे उद्योग

जनवरी

टाटा के कारखाने का विस्तार—खादी उद्योग का विकास, इस वर्ष ५॥ लाख साइकिलें बनेंगी, प्लास्टिक उद्योगों का विकास ३९-४९

सितम्बर

हमारा मोटर उद्योग, सरकारा व निजी उद्योग, जूट उद्योग में शिथिलता, विदेशों से सहायता, दवाइयों का उद्योग, बिजली के बल्बों का उत्पादन, भारतीय पंखों का २३ देशों को निर्यात, मुनाफा भारत में ही ५५२-५५४

अक्तूबर

लोहे के ३ नये कारखाने, नये उद्योगों के निर्माण में, नये डिविडेंड और विनियोजन ६०५-६०७

दिसम्बर

चाय उत्पादन में भारत सबसे आगे, नाँगलमें खाद का कारखाना, डीजल इंजन, भारत रूस को जूते भेजेगा, कोयले की छोटी खानें, अखबारी कागज का एक और कारखाना, नये चर्खे पर एक लाख रुपए का इनाम ७७०-७७९

बैंक

वर्ल्ड बैंक मिशन के सुझाव ५२५
विश्व बैंक उद्देश्य संगठन और प्रगति १९
विश्व बैंक और विश्व कोष ६१८
बैंकों की प्रगति १९५५-५६ में ६१७
बैंक कर्मचारियों का संघर्ष २९
बैंकों का राष्ट्रीय करण—दोनों पहलू ३५९
बैंकों में जमा-राशि की वृद्धि ४४३
रिजर्व बैंक एक्ट में संशोधन ४९१
स्टेट बैंक आफ इंडिया

बैंक अंक

(बैंक और उनकी समस्याओं पर परिचयात्मक विशेषांक)

आइए, हम व्रत लें ६३१
बैंकों के सामने कुछ विचारणीय प्रश्न ६३२
देश में बैंकों का महत्त्वपूर्ण स्थान ६३३
भारत में आधुनिक बैंकों के विकास ६३८
व्यापारिक बैंकों के स्रोतों का नया विस्तार ६४२
बैंक संचालकों से ६४३
बैंक दर में घटा-बढ़ी क्यों ? ६४४
आधुनिक अर्थतंत्र में केन्द्रीय बैंक ६५३
ग्रामीण वित्त-व्यवस्था और महाजन ६५७
भारतीय महाजन और बैंक व्यवस्था ६६१
बैंक डिपाजिटों का बीमा ६६४
प्यार व तर्क से ६६९
सहकारी समितियां व सरकार ६६९
दूसरी विकास योजना में सहकारिता ६७१
भारत में बैंक सम्बन्धी कानून ६७३
बैंक आफ़ इंगलैण्ड ६७५
बैंक सम्बन्धी सांख्यिकी ६७७
बैंक अंकों का अध्ययन ६८४
रिजर्व बैंक आफ़ इण्डिया ६८५
बैंकों की विविध समस्या ६८७
राष्ट्रीयकरण, दोनों पहलू ६८९
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश ६९३
विश्व बैंक ६९७
मध्य प्रदेश में अधिकोषण ६९९
स्टेट बैंक आफ़ इण्डिया ७०१
पंजाब नेशनल बैंक ७०४
सेंट्रल बैंक आफ़ इण्डिया ७०५
बैंक आफ़ बड़ौदा ७०६
बैंक आफ़ इण्डिया ७०७

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

यूनाइटेड कमर्शियल बैंक ७०८
अमेरिका में बैंकिंग व्यवसाय ७०९
रूस में आर्थिक विकास और बैंक ७१२
जर्मनी का पुनर्निर्माण और बैंक ७१३
बैंकों का प्रबन्ध और संचालन ७१४
मध्यभारत में को-आपरेटिव बैंक ७१६
बैंक क्या काम करते हैं ? ७१८
विदेशों में भारतीय बैंक ७२१
रिजर्व बैंक : दूसरा पहलू ७२३
बैंक और हिन्दी शब्दावली ७२५
मेरी भी सुनोगे ? ७२७
सम्पादकीय २२९

बीमा

बीमा उद्योग की प्रगति (१९५६) २९
बीमा उद्योग का राष्ट्रीय करण ६१
बीमा उद्योग का राष्ट्रीय करण ७५
बीमा कम्पनियों का स्वामित्त्व और लाभ २९
बीमा कार्पोरेशन का संगठन ३०९
निर्यात व्यापारियों को गारण्टी का बीमा ५२३
भारतीय जीवन बीमा निगम ५५५
भारतीय बीमा निगम ६१२

कृषि और खाद्य

अधिक से अधिक जोत कितनी हो ३६२
अमेरिका भारत में समझौता ६३०
किसानों के लिए ऋण समस्या ३१४
किसानों को ऋण कौन देते हैं ? ७८३
कृषि उत्पादन : १५ सूत्री कार्यक्रम ७७४
कृषि सम्बन्धी १५ सिफारिशें ७४६
कृषि की वैज्ञानिक पद्धति ७४१
कृषि संसार का सबसे बड़ा उद्योग ६१४
खाद्य समस्या की नई उलझन ४२९
खेती का सबसे बड़ा शत्रु भमि क्षरण ७८२
दूसरा राष्ट्रीय किसान सम्मेलन ३२५
प्राचीन भारत में सहकारिता २३८
भारत में काश्तकारी सुधार ७३
भारत में कृषि उत्पादन ६१४
भारत में ५ किस्म की जमीनें ४४९
भूमि का कटाव रोकिए ३२७
भूमि का नया वटवारा जरूरी ५४२
भूमि सुधार—द्वितीय पंचवर्षीय योजना ५९०
रासायनिक खाद और मक्के की खेती ६१५
सहकारिता क्यों ? २६८
हमारी खेती व खाद ५६१
किसानों की नांगल यात्रा ३९१
गोबर की खाद ९५
जन कल्याण के लिए जन सहयोग ५७९
हमारे गांवों की समस्या २६७

व्यापार

आयात नीति में कठोरता ३४४
चाय, काफी और रबर ५२३
पाकिस्तान से अवैध व्यापार ३४५
विदेशी व्यापापार का नया क्षेत्र २३३
भारत के विदेशी व्यापार की कुछ नई दिशाएं ४७३
भारत सरकार की आयात-निर्यात नीति ११
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और वायदे का कारोबार ५८६
व्यापार का राज्यीयकरण ४५९
हमारी आयात नीति ७४७
हमारा गिरता हुआ विदेशी व्यापार ५७५
हमारा गिरता हुआ निर्यात व्यापार ७५१
हमारी नवीन वस्त्र नीति ५०९

श्रम समस्या

आज का मजदूर क्या चाहता है ? ३७९
उचित वेतन लागू किए जाएं ३७७
एक स्वस्थ दिशा की ओर ३९
औद्योगिक विवाद कानून नए संशोधन ४९३
औद्योगिक सम्बन्ध में नई दिशा ५९५
कुशल कर्मचारियों की कमी ३४५
खेतीहर मजदूरों की रहन-सहन की स्थिति ३५
धीरे काम करो और मजदूर ७४६
नेपा मिल में औद्योगिक सम्बन्ध ३७२

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पोलैण्ड में मजदूरों पर गोली ४०४
भारत में औद्योगिक स्त्री श्रमिक २३
भारत में बालक श्रमिक ४३५
मजदूर आन्दोलन की नई दिशा ९
मजदूरों को उचित वेतन २८०
राज्य कर्मचारी बीमा योजना
वर्ग संघर्ष का युग बीत गया ३७८
वेतनों का निश्चय कैसे हो ? ७४४
श्रमिकों के हित के लिए ५६७
सरकारी कारखानों में बोनस ४०४
सिन्द्री में कर्मचारियों की पुकार ५६८
सूरत में इंटक का अधिवेशन
हमारा अपना मजदूर दिवस ५६८

विविध राज्य

आन्ध्र
आन्ध्र राज्य की आर्थिक स्थिति २३६
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश के किसान प्रसन्न हों ! ३२६
उत्तर प्रदेश में नए उद्योगों की संभावनाएं ५२६
उत्तर प्रदेश में भारी उद्योग ४९७
उत्तर प्रदेश में विकास की प्रगति ९९
उत्तर प्रदेश में सहकारिता ७८०
बिहार
बिहार की वन सम्पदा ७६१
बिहार के उपवन में पंचवर्षीय योजना के खिलते पुष्प २५५
मध्य भारत
उन्नति के पथ पर मध्य भारत ३५१
काटन एक्सचेंज का समझौता ५०
मध्य भारत का किसान खुशहाल हो रहा है ३८४
मध्य भारत का चतुर्मुखी विकास ३४७
मध्य भारत की वरदायिनी चम्बल योजना ३५३
मध्य भारत में नए उद्योग ४९९
राजस्थान
राजस्थान की जवाई परियोजना ५९९
राजस्थान की दो योजनाएं ७८१
राजस्थान की नयी योजना २४३
राजस्थान की भाग्य लक्ष्मी ५०
राजस्थान के ग्रामों में क्रांति ३९०
राजस्थान में अभूतपूर्व श्रमदान ४४२
राजस्थान में मिट्टी का तेल ३४६
राजस्थान में सड़कों की विकास की समस्या २४
राजस्थान वित्त निगम १०१
बृहद् राजस्थान उन्नति के पथ पर २४०

अन्तर्राष्ट्रीय

अमेरिका में एक ही मजदूर संघ ३७
अमेरिका में समाज सुधार ३८२
चीन में कृषि-विकास ८०
चीन का विकास शील यंत्र निर्माण उद्योग ५५७
(रूस में) सामूहिक किसानों के लिए पेंशन ३२२
रूस की छठी पंचवर्षीय योजना ७८

राजनीति

कार्लमार्क्स और भारतीय कम्युनिस्ट २५
बगदाद संधि के देश ३३०
जरूरी चेतावनी ४०४

अर्थवृत चयन

फरवरी—उद्योग मेले की असाधारण सफलता, बेकार लकड़ीके चमत्कारी प्रयोग, गृह-निर्माण के लिए सामग्री, विज्ञान द्वारा पशु-प्रजनन, कृत्रिम गर्भाधान के अनेक लाभ : ९१-९३
मई—मेरी दृष्टि में समाजवाद, याकूनिया में हीरे की खान, गांव वालों की आय कम बढ़ी, मक्का अमेरिका की मुख्य फसल, भारत में सोने की खानें, बिना अशोक स्तंभ वाले नोट। ३१८-३१९
जून—नाई का अस्त्र छुरा, विश्व के विभिन्न सैनिक संगटन, ५ करोड़ गाएं। ३९४
जुलाई—सच्चा अर्थशास्त्र, चीन की पंचवर्षीय योजना, सोवियत संघ के किसानों की आय, राष्ट्रीय आय में असाधारण वृद्धि बिजली तार, भिखारियों का आकर्षण केन्द्र वाराणसी ४३२-४३४

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अगस्त—एक पीढ़ी के सुखों का बलिदान, नेहरू ख्रुश्चेव प्रतिद्वन्दी, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निजी पूंजी, सऊदी अरब या स्वर्ग, पाकिस्तान कृषि में पिछड़ रहा है, पश्चिमी योरप में मिट्टी के तेल की पाइप लाइन, गंगा में प्रति वर्ष ३ लाख मछलियोंका शिकार, भारत रूस व्यापार में वृद्धि ४८८

सितम्बर—अनाज की मंहगाई के कारण, कुम्हार मारे जा रहे हैं, भारत में खनिज तेल की खोज, रूस : कुछ ज्ञातव्य अंक लोग ज्यादा साफ रहने लगे हैं ५६५-५६६

अक्टूबर—रूस और चीन की अर्थनीति एक नहीं, जहाजों भाड़े में वृद्धि, पानी सुलभ,पर सिंचाई? भारत सरकार का ऋण, ग्रेट ब्रिटेन और स्टर्लिंग क्षेत्र, जनसंख्या की निरंतर वृद्धि, आसिफनगर का दियासलाई का कारखाना। ६०१-६०४

दिसम्बर—सामुदायिक विकास योजना, डाक-तार की प्रगति, तार एवं टेली-फोन, ज्ञातव्य बातें ७७६-७७७

सर्वोदय

भू-क्रांति होकर रहेगी ७४१
भारत कसौटी पर ६३
भूदान के ४ स्तम्भ ४३१
समाजवाद की सर्वोदय योजना
समाजी-करण का नवीन संदेश १५
सर्वोदय का साम्पत्तिक आधार ५३७
सर्वोदय की दृष्टि १०
सर्वोदय के संदेश-अर्थशास्त्र में पंचशील २६३
हृदय भावना आज भी विद्यमान है ३२९
यंत्र युग में भी रेलगाड़ी ७७२
शान्तिनिष्ट आर्थिक संयोजन ७७२
ग्रामीकरण में खेती और उद्योग ७७३

यातायात

डीजल या बिजली के इंजिन ४४१
भारत और विदेशी रेलें ३००
रेलवे निर्माण में नए उद्योग ३०५
रेलवे व द्वितीय विकास योजना २९९
सड़क और सड़क यातायात विकास २४६

विविध

अणुशक्ति भारत में ४६०
अराष्ट्रीयता से समझौता ३४६
आठ करोड़ बकरियां २६
आप भी नए मकान बना लीजिए ५९५
आंख खोलने वाले कुछ तथ्य ३८०
चीन और भारत तुलनात्मक दृष्टि ४२१
दक्षिणी पूर्वी एशिया में प्रशिक्षण सहायता ७६६
नयाहिन्दी टाइपराइटर २७
नए सिक्के चालू होंगे ३८९
नाप तोल की दशमिक प्रणाली २७०
पशु और दूध ५८८
पण्डित नेहरू की घोषणा के बाद २३६
पुनः सीमा विभाजन या ५ क्षेत्र ७
पुत्री को उत्तराधिकार २८२
बम्बई की समस्या सुलझी ४६२
भारत का नया मानचित्र ५२६
मद्यनिषेध २३६
मासिक पत्र और सरकारी प्रकाशन २३
राष्ट्र की सम्पत्ति ६४
वन सम्पदा व वन महोत्सव ३५५
वनों का शत्रु मानव ४३९
सम्पदा का अजस्र प्रवाह ३७५
हीरे मोती नहीं, उत्पादन ५०५

व्यक्ति परिचय

श्री एम० एन चक्रवर्ती और श्री एम० गणपति—पश्चिमी और मध्य रेलवे के योग्य मैनेजर ७७९
वित्त मंत्री श्री देशमुख—छः वर्षों पर एक दृष्टि ४६९
हमारे वित्त मंत्री श्री कृष्णमाचार्य ५८४

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कम्पनी परिचय

ईस्ट इंडिया काँटन एशोसिएसन ३१७
नए कम्पनी कानून २४८
नया कम्पनी कानून ३२६
भारत में कम्पनी कानून २४७
भारत में नई कम्पनियां ५३१

नया सामयिक साहित्य

जनवरी ३८
अप्रैल २६१-२६२
जून ३८२-३८३
अगस्त ४७९-४८०
अक्टूबर ६१२
दिसम्बर ७६७-७६९

सरल अर्थ चर्चा

४५, ९५, २११, २६७, ३३५, ३८९, ४४७, ५०५
५६१, ५९३, ७२१, ७९२

नक्शे-चार्ट आदि

पुनर्गाठित भारत १२४
विविध क्षेत्रों में आनुमानिक व्यय १३२
प्रथम योजना के अनुमानित लक्ष्य १४०
१९४१ से १९५१ जनसंख्या १४५
कृषि उत्पादन में वृद्धि १५२
विभिन्न कामों में दूध का प्रयोग १५४
बिजली उत्पादन में वृद्धि १५७
रासायनिक उद्योग १६२
जहाजी उद्योग व समुद्रतट १६५
राजस्थान की विकास योजना २०५
चम्बल बांध के स्थान ३२६
चम्बल योजना द्वारा सींचा जाने वाला क्षेत्र ३५३
द्वितीय पंचवर्षीय योजना चित्रों में २६५
नई योजना के व्यय का प्रतिशत १२७, २४४
प्रमुख उद्योगों के उत्पादन के नए लक्ष्य १५९, ५२
पंचवर्षीय योजना : तुलनात्मक आकार १३१, ९
भारत में कम्पनियों के विकास पर एक दृष्टि १६०, २५०
भिलाई—जहां रूस के सहयोग से कारखाना बन रहा है ६०५
मध्य भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना ३४८
योजना में कृषि उत्पादन के नए लक्ष्य १३३, ४२९
राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत के राज्य और क्षेत्र ५८६
विद्युत-प्रकाशित नगर २९३
विविध क्षेत्रों में अनुमानिक व्यय की तुलना ७
सिंचित कृषि भूमि २९३
स्वेज का चित्र ४६३
बैंकों की विविध कामों में सहायता ६३३
भारत में बैंक मानचित्र ६३५
डिपाजिटों का श्रेणी विभाजन ६३७
कुल लाभ व्यय बैंक ६३८
रिजर्व बैंक द्वारा ऋण ६३९
बैंकों की देयता ६४२
बैंकों की सम्पत्ति ६४३
बैंक कम्पनियों के दफ्तर ६७७

स्वतंत्र आंकड़

खाद्य तथा व्यापारिक फसलों का उत्पादन प्रति व्यक्ति ३२०
चीनी-उद्योग के कुछ अंक ८८
थोक मूल्यों के निदेश अंक २९६
भारतीय कम्पनियां कुछ अंक २५४
मध्यभारत की पंचवर्षीय योजना अंकों में ३५४
राष्ट्रीय आय ३२०
बैंक संबधी सांख्यिकी ६७७

यह विषय सूची पढ़कर आप एक ही परिणाम पर पहुंचेंगे कि सम्पदा अत्यन्त उपयोगी व ज्ञानवर्धक पत्रिका है।

मूल्य ८) रु० वार्षिक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्पदा पर विविध लोकमत

अर्थशास्त्र के विद्वान् और शिक्षणशास्त्री

अर्थशास्त्र के विभिन्न अंगों पर प्रकाश डालने तथा विद्वत्तापूर्ण और उच्च श्रेणी के साहित्य का निर्माण करने में सम्पदा बहुत उपयोगी सिद्ध होगी।

—डा. एल. सी. जैन, सागर विश्वविद्यालय मध्यभारत

Your journal is of high quality. I would certainly write for you. It is kind of journal which deserves every encouragement.

—पी. सी. जैन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी

It contains a wealth of good information.

—श्री गजराजसिंह संचालक शिक्षा विभाग राजस्थान

अर्थ शास्त्र के विशेषज्ञ विद्वानों और छात्रों के साथ-साथ साधरण व्यापारियों के लिए भी इसकी उपयोगिता स्पष्ट है। —मंगलदेव शास्त्री

एम० ए० डी० फिल (आक्सन)

From the subject dealt with in the various-articles, (in the Mazdoor-Ank) which are informative and cover wide range, I discern a catholicity of outlook which is essential for maintaining one objective angle.

—V.K.R. Menon, Director I.L.O. Indian Branch

व्यापारी और शासक क्या कहते हैं?

आपका पत्र हमारी आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में बड़ी भारी कमी को पूर्ण करेगा।

—त्रिलोकीनाथ जनरल मेनेजर, दिल्ली क्लाथ मिल्स

आप जैसे विद्वान और अनुभवी की चीज उपयोगी होनी चाहिए। वैसी ही सम्पदा है, इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं। —हरिभाऊ उपाध्याय, मुख्यमंत्री अजमेर

Sampada has given a new lead to our country. —Sri Padmapat Singhania

It will fill a want in Hindi commercial literature. —R. G. Sariya

Congratulationa to the Editor, great pains have been taken for Textile Industry Number.

—G. D. Birla

पत्र क्या कहते हैं?

हिन्दी में संभवतः अपने विषय की यह पहली पत्रिका है। लेख-चयन और सम्पादन में विशेष परिश्रम किया जाता है। —आज

यह बहुत बड़े पाठक वर्ग को पाठ्यसामग्री देती है।

—नवभारत टाइम्स

सम्पदा का प्रकाशन राष्ट्रभाषा के रत्नमणि भण्डारों की अभिवृद्धि की दिशा में एक महान प्रयत्न है।

—प्रदीप

प्रत्येक स्तम्भ में सुन्दर सूचनात्मक सामग्री है। गम्भीर आर्थिक समस्याओं को सरल भाषा में समझाना पत्र की मुख्य विशेषता है। —दैनिक वीर अर्जुन

देश जिस आर्थिक क्रान्ति के दौरान में से गुजर रहा है, उसमें यह प्रकाशन हमारे लिए वरदान है। —नया जीवन

Sampada is the best guide for digesting and understanding the economic situation of the country, —Commerce and Industry.

Hindi Readers will benefit immensely from this publication. —Organiser

The numbrr would help the reader in finding his place, and aspiration in the national economy. The magazine has been well brought out and is finely printed.

Thought

...All this makes this Bhoomi Sudhar number almost a reference number and deserves a place in all libraries and on every social worker's and patriot's table.

—Marahatha (Poona)

Welcome efforts. My congratulations in bringing out standard publication.

—Lala Bharat Ram (Delhi Cloth Mills)

The 'Sampada' is a journal devoted to the economic problems of the country.....It claims to make a new venture in the Hindi-world.

—Searchlight (Patna)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

१० के १५
२० के ३०

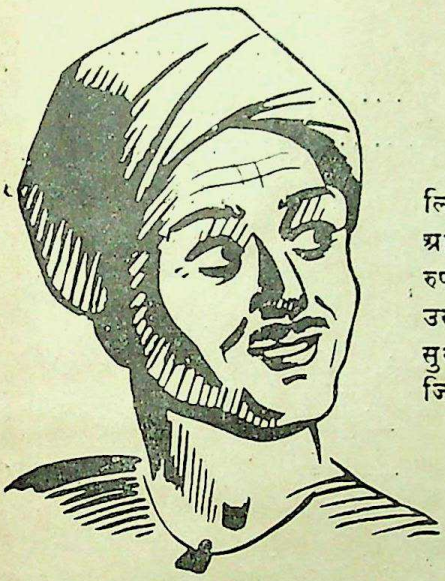

यह कोई कठिन नहीं और न तो इस के लिए किसी जादूगर की जरूरत है। यदि आप आज नैशनल सेविंग्ज सर्टिफिकेट में १० रुपये लगाएंगे तो १२ साल के बाद आप को उसके १५ रुपये मिलेंगे। आप का पैसा सुरक्षित रहेगा और आप को सूद देने की जिम्मेदारी सरकार की है।

दुगना लाभ

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सम्पन्न किए जाने वाली भिन्नभिन्न योजनाओं के लिए आप के पैसों का उपयोग किया जाएगा और उसी के जरिये देश की तमाम जनता के रहन-सहन का स्तर ऊंचा किया जाएगा। आपको सूद मिलने के अलावा आप देश की खुशहाली में हिस्सा लेते हे।

नव भारत के निर्माण में
आप सहायक होते हैं

अधिक विवरण और/या इस से सम्बन्धित नियमों की जानकारी के लिए नैशनल सेविंग्ज कमिश्नर, शिमला या अपने राज्य के रीजनल नैशनल सेविंग्ज आफिसर को लिखिए।

DA 56/151

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्पदा का बैंक अङ्क

पाठकों के हाथों में

सम्पदा का चिर प्रतीक्षित बैंक अङ्क पाठकों के हाथों में पहुँच गया और अङ्क पाते ही जिस प्रकार के पत्र आने लगे हैं, उनमें से एक पत्र निम्नलिखित है :—

"बैंक अङ्क आज मिला, जितना बाहर सुन्दर है, उतना ही भीतर भी।.....आपने अधिकोषण (बैंकिंग) पर एक सुन्दर साहित्य का निर्माण किया है.....सुन्दर और योग्य सम्पादन के लिए बधाई।.....दोनों ही लेख सुन्दर और मौलिक हैं।.....लेख बहुत ही सामग्रीपूर्ण एवं उपयोगी है।"

—प्रो० विश्वम्भरनाथ पाण्डेय, एम० ए०

एजण्टों के हाथों में

एजण्टों के हाथों में पहुँचते ही तीसरे दिन उनके आर्डर आने लगे हैं :—

२० कापी बैंक अङ्क तुरन्त भेजिये। —रांची

१० कापी और बैंक अङ्क भेजिये। —जोधपुर

उद्योगपतियों के हाथों में

बैंक अङ्क को देखते ही एक बड़ी फर्म के अधिकारी कहने लगे कि हमारा विज्ञापन तो इस अङ्क के लिए आपने लिया ही नहीं।

कुछ दिन बाद आप भी पछतावेंगे

यदि आपने अपने पुस्तकालय के लिए बैंक अङ्क १।=) डाक व्यय सहित [रजिस्टरी के लिए १।।।≡)] भेजकर नहीं मंगाया।

सम्पदा के पुराने विशेषांक भी १।) प्रत्येक अंक (डाक खर्च अलग) के हिसाब से मिल सकते हैं। सब अंक मंगाने पर डाक खर्च नहीं देना पड़ेगा। थोड़ी सी कापियां बची हैं।

—मैनेजर सम्पदा

अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिल्ली-६.

सम्पादक—कृष्णचन्द्र विद्यालंकार द्वारा अशोक प्रकाशन मन्दिर के लिए अर्जुन प्रेस देहली से मुद्रित व प्रकाशित

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्पदा

फरवरी १९५७

सम्पादक

कृष्णचन्द्र विद्यालंकार

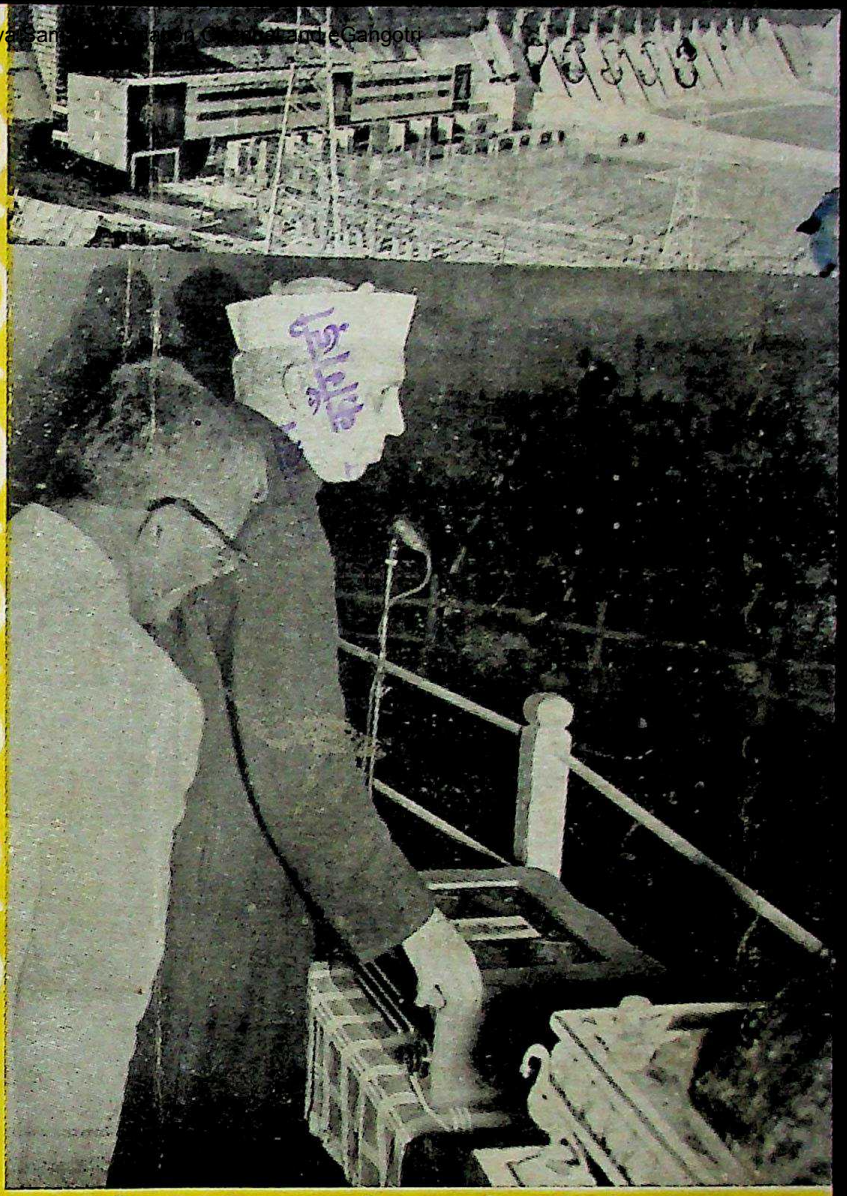

उड़ीसा का नया तीर्थ : हीराकुड बांध

पश्चिमी प्रान्त के भाकरा नांगल बांध की भांति देश के पूर्वीय प्रान्त उड़ीसा में एक नये तीर्थ हीराकुड पर एक विशाल मन्दिर का उद्घाटन करके पं० नेहरू ने राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। इस योजना की पूर्ति पर महानदी जल-प्रलय का भीषण अभिशाप न होकर उड़ीसा के लिए वरदान के रूप में परिणत हो जायगी।

मूल्य ।।।)

अशोक प्रकाशन मन्दिर : रोशनारा रोड, दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

देश के साथ फलिए फूलिए

अपनी बचत भारत सरकार की "अल्प बचत योजना" में लगाइए

और

भारत की निम्न योजनाओं की सफलता में मदद कीजिए

१. सामुदायिक उत्थान कार्य
२. नदी बांध योजनाएं
३. समाज सुधारक योजनाएं
४. रेल और सड़क योजनाएं

आप अपनी रकम निम्नलिखित सुरक्षित एवं आकर्षक मदों में लगाइए

१२ वर्षीय नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स—४$\frac{१}{६}$ प्रतिशत ब्याज (अवधि समाप्ति पर)। ५ रु० से लेकर ५००० रु० तक के अभिदानों के मिलते हैं। एक व्यक्ति २५,००० रु० तक के सर्टिफिकेट खरीद सकता है।

१० वर्षीय नेशनल प्लान सर्टिफिकेट्स—४॥ प्रतिशत ब्याज (अवधि समाप्ति पर)। ५), १०), २५), ५०), १००) और ५००) के मूल्य के मिलते हैं। एक व्यक्ति २५,००) तक के सर्टिफिकेट खरीद सकता है।

१० वर्षीय ट्रेज़री सेविंग्स सर्टिफिकेट्स—प्रति वर्ष ३॥ प्रतिशत ब्याज दिया जाता है। १००) एवं १००) के गुणकों में २५,०००) तक मिलते हैं। एक व्यक्ति २५०००) तक के सर्टिफिकेट खरीद सकता है।

पोस्ट आफिस सेविंग्स बैंक एकाउन्ट—१०,०००) रु० तक की जमा रकम पर २ प्रतिशत और बाकी की १५,०००) तक की रकम पर १॥ प्रतिशत ब्याज मिलता है।

१५ वर्षीय एन्यूइटि सर्टिफिकेट्स—३५००), ७०००), १४०००) और २८०००) के मूल्य के मिलते रहेंगे।

१५ वर्ष तक क्रमशः २५), ५०), १००), २००) मासिक मिलते रहेंगे।

एक व्यक्ति २८०००) तक के सर्टिफिकेट खरीद सकता है।

इन सब मदों पर कमाया ब्याज भारतीय आय-कर से मुक्त है।

विशेष विवरण के लिए, रीजनल नेशनल सेविंग्स आफिसर, राजस्थान, किशोर भवन, न्यू कालोनी, फोन नं० २२६६, जयपुर, अथवा अपने जिले के डिस्ट्रिक्ट आर्गेनाइजर से मिलिए या लिखिए।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारत की औद्योगिक नीति

लेखक—प्रो० श्री अश्विनीकुमार शाह और प्रो० श्री रामनरेश लाल

सम्पदा के पिछले अंकों में जिस अर्थशास्त्र माला के प्रकाशन की सूचना दी गई थी, उसमें प्रथम पुस्तिका प्रकाशित हो गई है। इसमें भारत की उद्योग नीति का अतीत, समय-समय पर होने वाले परिवर्तन और आज की नीति का संक्षेप से परिचय दिया गया है।

इसके लेखक काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के श्री अश्विनीकुमार शाह और सेण्ट जेवियर्स कालेज रांची अर्थशास्त्र के अनुभवी अध्यापक श्री रामनरेशलाल हैं। दोनों अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों की कठिनता और आवश्यकताएं जानते हैं। इसलिए यह पुस्तक हायर सैकेण्डरी, इन्टर व बी० ए० के परीक्षार्थी विद्यार्थियों के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी।

मूल्य ॥=)। ॥।) के टिकट भेजकर अण्डर पोस्टल सर्टिफ़िकेट मंगाइये।

—मैनेजर, अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिल्ली—६

पंचवर्षीय योजना अब एक राष्ट्रीय आन्दोलन है, जो आत्म-विकास के लिए जनता के संकल्प का द्योतक है। इसके द्वारा देश का रूप द्रुत गति से बदल रहा है।

—मध्यप्रदेश में गत पांच वर्षों में—

- ४ लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्नों की पैदावार हुई।
- ८७,००० एकड़ अतिरिक्त भूमि सिंचित हुई।
- ११,६००० अतिरिक्त किलोवाट बिजली का उत्पादन हुआ।
- २५०० मील नयी सड़कें बनीं।
- १३,००० नयी पाठशालाएं खुलीं।
- ५०० नये अस्पताल खुले।
- २३,३८८ ग्रामों के लगभग १ करोड़ निवासी विभिन्न विकास-योजनाओं द्वारा लाभान्वित हुए।
- १०० टन प्रतिदिन कागज बनाने वाला प्रथम अखबारी कागज का कारखाना चला।
- ११५ करोड़ लागत की भिलाई इस्पात योजना का आरम्भ हुआ।

अपनी यात्रा के दूसरे चरण में मध्यप्रदेश की दूसरी योजना का अर्थ है—

- ११५ करोड़ लागत के भिलाई इस्पात कारखाने का निर्माण।
- चंबल-योजना के दूसरे चरण की समाप्ति।
- २५ करोड़ लागत से भारी बिजली मशीनों का कारखाना।
- १२ करोड़ लागत की तवा-बहुद्देश्यीय योजना का आरम्भ।
- कोरबा की कोयला-खदानों का आरम्भ।
- ७०,००० ग्रामों में विकास-योजनाओं की क्रियान्विति।

समृद्ध, समाजवादी राज्य के लक्ष्य की ओर

म ध्य प्र दे श

धीरे-धीरे अग्रसर हो रहा है

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विषय-सूची

नाम	पृष्ठ
१ उड़ीसा का नया तीर्थ-हीराकुड बाँध	६९
२ केन्द्र व राज्यों में आय का वितरण	७०
३ सम्पादकीय टिप्पणियां	७२
४ नई योजना और वित्तीय साधन	७४
५ दूसरी योजना और नई समस्याएं	७७
६ राष्ट्र का आर्थिक प्रवाह	८१
७ विकासशील देशों की आर्थिक समस्याएँ	८३
८ उड़ीसा का समृद्धि-स्वप्न साकार हो गया	८५
९ समृद्धि के पथ पर कशमीर	८९
१० सड़कों का महत्त्व	९१
११ भारी मशीनों के उद्योग की प्रगति (हमारे उद्योग)	९४
१२ सामुदायिक विकास कार्यक्रम	९६
१३ सर्वोदय और समाजवाद	९९
१४ हमारा उत्तर प्रदेश : आर्थिक विकास में प्रगति	१०१
१६ समृद्धि की नई आशाओं से पूर्ण मध्य प्रदेश	१०४
१७ लीपज़िग की प्रसिद्ध औद्योगिक प्रदर्शनी	११०
१८ नया सामयिक साहित्य	११२
१९ अर्थवृत्त चयन	११५
२० बैंक और बीमा	
बैंकों की आर्थिक प्रवृत्ति	११८
रिजर्व बैंक और दरें	११९

★

सम्पदा और छात्र

हमारे रांची नगर में इस पत्रिका के ग्राहकों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। विशेषकर हम जैसे अर्थशास्त्र के विषय को लेने वालों के लिए 'सम्पदा' बहुत ही सहायक सिद्ध हुई है। भारतीय अर्थशास्त्र में अधिकतर सम्पदा पर ही निर्भर करना पड़ता है। कालेजों के विद्यार्थी ही क्या, अन्य लोग भी इस पत्रिका को पढ़कर लाभ उठाते हैं।

मैं एक वर्ष से सम्पदा का ग्राहक रही हूँ और सम्पदा के प्रत्येक अंक में नयी वस्तु पढ़ने को मिलती है। विशेषांक बहुत ही लाभप्रद है।

हमारे कालेज के सभी विद्यार्थी इस पत्रिका को चाव से पढ़ते हैं।

—कृष्णकुमारी शर्मा

३३६

शाखाएं समस्त भारत में विस्तृत

और

संसार के सभी महत्वपूर्ण

केन्द्रों में एजेंसियों द्वारा

दि पंजाब नेशनल बैंक लि.

आपकी सेवा करने में

सर्वप्रकार समर्थ है।

चालू पूंजी

१४० करोड़ रु० से अधिक

चेयरमैन

श्री एस. पी. जैन

दी पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड

प्रधान कार्यालय : दिल्ली

६१ वर्षों की विश्वसनीय सेवा का बृहत अनुभव

ए. एम. वाकर— जनरल मैनेजर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्पदा

वर्ष ६] फरवरी १९५७ [अंक २

उड़ीसा का नया तीर्थ : हीराकुड बांध

८ जुलाई १९५४ को भारत के प्रधान मंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू ने भारत के पश्चिमी सीमा प्रान्त पंजाब में भाखड़ा नंगल का उद्घाटन करके वह परियोजना भारतीय जनता के लिए समर्पित की थी।

करीब ढाई वर्ष बाद पं० नेहरू ने भारत के पूर्वी प्रान्त उड़ीसा के हीराकुड बांध का उद्घाटन कर उसे भी राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया है।

केन्द्रीय आयोजना एवं विद्युत तथा सिंचाई मंत्री श्री गुलजारीलाल नन्दा के शब्दों में हीराकुड का उन कामों में महत्वपूर्ण स्थान है, जो भारत ने स्वाधीन होने के बाद किये हैं। बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और विद्युत्-उत्पादन की दृष्टि से यह अब तक पूर्ण होने वाली सब से बड़ी योजना है।

१६ मील में फैला हुआ यह संसार का सब से बड़ा बांध है। २८८ वर्ग मील के क्षेत्र वाला जलाशय एशिया की सब से बड़ी कृत्रिम झील है। २७० हजार किलोवाट बिजली पैदा करने वाला यह भारत में सब से बड़ा जल विद्युत संयंत्र होगा।

इसने उड़ीसा के पिछड़े हुए प्रदेश की उन्नति और समृद्धि के लिये मार्ग प्रशस्त कर दिया है और इसलिए भारतीय अर्थ-व्यवस्था के इतिहास में इसका स्थान अमर हो गया है।

इसकी एक विशेषता यह है कि यह विशाल योजना भारतीय इंजीनियरों और मजदूरों की ही कुशलता से पूर्ण हुई है।

हम अपने समस्त पाठकों के साथ इस गौरवपूर्ण सफलता के लिए उड़ीसा की जनता, इस योजना के निर्माताओं और प्रशासकों का अभिनन्दन करना चाहते हैं।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

केन्द्र और राज्यों में आय-वितरण

भारत सरकार के एक निश्चय के अनुसार प्रति पांचवें वर्ष एक आर्थिक आयोग की नियुक्ति होती है। यह आयोग यह निश्चय करता है कि देश को होने वाली कुल आय का वितरण किस तरह किया जाय। संविधान ने कुछ विभाग राज्यों को सौंप रखे हैं। उन विभागों से होने वाली आमदनी तथा खर्च राज्यों के जिम्मे है। कुछ विभाग ऐसे हैं जो केवल केन्द्रीय शासन से सम्बन्ध रखते हैं। उन्हें चलाने के लिये केन्द्रीय सरकार ही जिम्मेदार होती है। सेना, रेलवे, डाक-तार, विदेशी नीति आदि ऐसे ही विभाग हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, स्वायत्त शासन, कृषि आदि राष्ट्र निर्माण के विभाग प्रायः राज्यों के सुपुर्द होते हैं। ब्रिटिश शासन के काल में बहुत समय तक यह विवाद बना रहा कि राज्यों को अपने उत्तरदायित्व निभाने के लिए आय के अधिक स्रोतों की आवश्यकता है। केन्द्र सदा अपनी आवश्यकतायें बताता रहा, परन्तु इस दीर्घकालीन विवाद में राज्यों के शनैः शनैः बल पकड़ने के कारण उन्हें क्रमशः अधिक भाग देना ही पड़ा। बम्बई अधिक सम्पन्न प्रान्त है। वहां आय कर की आमदनी अधिक होती है। बंगाल में जूट का निर्यात कर भारी मात्रा में एकत्र होता है। यह दोनों राज्य इन दोनों करों से एकत्र होने वाले धन का अधिकांश भाग चाहते रहे। किन्तु एक बयोवृद्ध पिता की भांति केन्द्रीय शासन को अपने सभी पुत्रों—सभी राज्योंकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना है, भले ही वे राज्य अपना खर्च भी न जुटा सकते हों। इस तरह केन्द्रीय शासन को होने वाली आय के वितरण पर भारी मतभेद और संघर्ष रहा है। समय-समय पर परिस्थितियां बदलती रहीं, राज्यों के उत्तरदायित्व बढ़ते गये। आय स्रोतों में भी परिवर्तन होता रहा इसलिये आप के वितरण पर भी बार बार विचार किया जाता रहा।

भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी श्री देशमुख और श्री के० सी० नियोगी ने इन प्रश्नों पर मत प्रकट किये हैं और अब श्री सन्तानम की अध्यक्षता में एक वित्त आयोग इस प्रश्न पर विचार कर रहा है। इस आयोग की विस्तृत चर्चा सम्पदा के पृष्ठों में पहले की जा चुकी है। इस आयोग ने अपनी सिफारिशें तय करने में विलम्ब देख कर अन्तरिम सिफारिशें कर भी दी हैं, जिससे राज्यों को अपने बजट बनाने में असुविधा न हो। इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल ने अपना एक आवेदन भारत सरकार के भेजा है। इसमें इस प्रश्न पर कुछ महत्वपूर्ण विचार किये गये हैं। आजकल आय कर की आय का ५५ प्रतिशत और दियासलाई, तम्बाकू तथा बनस्पति घी के उत्पादन कर का ४० प्रतिशत राज्यों को दे दिया जाता है। परन्तु राज्यों में भी इस राशि का वितरण जनसंख्या के आधार पर ८० प्रतिशत तथा आय कर के संग्रह के २० प्रतिशत के आधार पर होता है। उत्पादन करों के वितरण में जन संख्या का आधार माना जाता है।

प्रथम वित्त आयोग से पहले आयकर का ५० प्रतिशत राज्यों को दिया जाता था। उद्योग व्यापार मण्डल ने उस समय भी यह सम्मति प्रकट की थी कि राज्यों को ५० प्रतिशत से अधिक नहीं मिलना चाहिये, क्योंकि केन्द्रीय शासन पर विकास योजनाओं के साथ-साथ देश की रक्षा व्यवस्था को भी अधिक समर्थ बनाने की जिम्मेवारियां हैं। आज तो यह दोनों उत्तरदायित्व और भी अधिक बढ़ गये हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना पहली योजना की अपेक्षा दुगनी से भी अधिक बड़ी है। इस योजना के लिये पैसा जुटाना एक गम्भीर समस्या बन गई है। प्रतिदिन वित्त मंत्रालय नये से नये कर लगाने की चिन्ता में रहता है। दूसरी ओर पाकिस्तान की काश्मीर-सम्बन्धी संघर्ष को बढ़ाने की नीति के कारण रक्षा की व्यवस्था को अधिक समर्थ करने की आवश्यकता और भी अधिक बढ़ गई है। इसलिए केन्द्र को आर्थिक क्षमता को सुदृढ़ रखना ही होगा।

उद्योग व्यापार मण्डल ने राज्यों को केन्द्र की ओर से मिलने वाले अनुदानों की चर्चा करते हुए कहा है कि राज्य पहले की अपेक्षा केन्द्र से अधिक सहायता प्राप्त कर रहे हैं। १९५१-५२ में ३४ करोड़ रुपये की सहायता दी गई थी, और १९५५-५६ में ९८ करोड़ रुपया। १९५६-५७ के बजट में यह राशि ११२ करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। १९५१-५२ में राज्यों की आय में इस राशि का ९ प्रतिशत भाग होता था।

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

किन्तु १९५४-५५ में यह अनुमान १० प्र० श० से भी अधिक बढ़ गया। नये वर्ष के बजट में तो यह अनुपात २५ प्रतिशत तक जा पहुँचा है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि राज्यों को केन्द्रीय शासन की ओर से मिलने वाली सहायता निरंतर बढ़ती जा रही है, और राज्य भी इस पर निर्भर करने लगे हैं। ऐसी स्थिति में केन्द्र को आय-कर के ५० प्रतिशत से अधिक भाग राज्यों को नहीं देना चाहिये।

दियासलाई, तम्बाकू और वनस्पति घी के उत्पादन करों से प्राप्त होने वाली आय एक प्रकार का ऐसा तालाब है, जिसमें से राज्यों को पानी दिया जाता है। अब तक कपड़ा, चीनी व सीमेन्ट के उत्पादनकरों को इस विभाजनीय तालाब में सम्मिलित नहीं किया जाता था। राज्यों ने यह मांग की है कि इन उत्पादन करों को भी उसी विभाजनीय राशि में डालना चाहिये। इस सम्बन्ध में यह बात भी स्मरण रखनी चाहिये कि नेशनल डेवेलपमेंट कौन्सिल ने यह सलाह दी है कि मिल के कपड़े, तम्बाकू और चीनी पर बिक्री कर हटा देने चाहिये और उसके बदले में केन्द्र उत्पादन पर अतिरिक्त कर लगा दे। इससे बिक्रीकर से होने वाली परेशानी से न केवल दूकानदार बच जायेंगे, किन्तु यह कर वसूल करने के भारी खर्चों से भी सरकार बच जायेगी तथा बिक्री कर की चोरी भी नहीं हो सकेगी। किन्तु दूसरी ओर बिक्री कर से राज्यों की होने वाली विशाल आय भी बहुत घट जायेगी। इस लिये उत्पादन कर के वितरण प्रश्न पर और अधिक गम्भीर विचार करने की आवश्यकता है, ताकि राज्यों को उत्पादन कर और बिक्री कर से होने वाली आय में क्षति न होने पावे।

उद्योग व्यापार मण्डल ने अपने आवेदन में राज्यों के सम्बन्ध में भी कुछ विचार प्रकट किये हैं। आज कल राज्यों में केन्द्र पर अधिकाधिक आश्रित होने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। वे केन्द्र से मांग करते समय यह भूल जाते हैं कि केन्द्र के भी उत्तरदायित्व बहुत बढ़ रहे हैं और ऐसे भी राज्य हैं, जिनके आय के स्रोत बहुत कम हैं। इसलिये आवश्यकता यह है कि राज्य अपनी-अपनी आमदनी के नये स्रोत तलाश करें तथा केन्द्र पर अधिक आश्रित होने की प्रवृत्ति छोड़ दें। फिर भी केन्द्रीय शासन को यह तो ध्यान रखना ही होगा कि राज्यों की राष्ट्र निर्माण योजनाओं में कमी न आने पावे। किन्तु राज्य भी स्वावलम्बी होने का प्रयत्न करें, इसलिये मण्डल ने यह सम्मति दी है कि सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता के दो आधार होने चाहियें—

१. राज्यों द्वारा करों के रूप में आय प्राप्ति के प्रयत्न।

२. राज्यों की अनिवार्य विकास योजनायें।

उत्तराधिकार कर से यद्यपि अभी बहुत आमदनी प्राप्त नहीं हुई तथापि यह आशा करनी चाहिये कि यह कर भी आयका अच्छा स्रोत सिद्ध होगा। उद्योग व्यापार मण्डल ने यह सलाह दी है कि अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर उसी राज्य को मिलने चाहियें, जिस राज्य में वह सम्पत्ति है। चल सम्पत्ति पर प्राप्त होने वाले कर विविध राज्यों में अचल सम्पत्ति पर होने वाली आय के अनुपात में बांट देने चाहिये।

विविध राज्यों और केन्द्र में आय के स्रोतों के वितरण पर सदा मतभेद रहा है। अपने अपने हित देखने की प्रवृत्ति स्वाभातिक है किन्तु सम्पूर्ण देश की दृष्टि अत्यन्त महत्वपूर्ण है, जिसे हमें नहीं कभी भुलाना चाहिये।

विदेशों से मशीनरी

नीचे हम एक तालिका दे रहे हैं। इससे यह मालूम होगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के पहली छमाही में कितनी मशीनरी विदेशों से मंगाई गई है। पाठकों की जानकारी के लिए १९५४ और १९५५ के अङ्क भी दिये गये हैं।

(लाख रुपए में)

	१९५४ अप्रैल से सितम्बर	१९५५ अप्रैल से सितम्बर	१९५६ अप्रैल से सितम्बर
बिजली की मशीनें	८१३	८८४	१,२०९
सूती कपड़ों की मशीनें	३४६	३१२	६१६
जूट की मशीनें	१५५	१८२	३६०
चीनी की मशीनें	५१	१७५	५३१
कागज की मशीनें	४१	५८	१४१
मशीन टूल	११९	१७२	२८०

लेकिन सच्चाई यह है कि ये अङ्क केवल बड़ी मदों के हैं। कुल मशीनरी तो इस छमाही में ७६ करोड़ २०

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लाख रुपये की मंगाई गई है जब कि गत २ वर्षों में क्रमशः ४० और ५०.५ करोड़ रुपये की मंगाई गई थी, इसी छमाही में जो लायसेन्स नये उद्योगों को मिले हैं, यदि उन्हें ध्यान में रखें तो मालूम होगा कि देश का औद्योगिक विकास किस तेजी से होरहा है। इन छ महीनों में ६४ नये उद्योगों के लिए लायसेंस मिले हैं और १०१ वर्तमान उद्योगों को अपना कार्य विस्तार करने की अनुमति दी गई है। इसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि विदेशों से और भी भारी तायदाद में मशीनरी मंगाई जायेगी, और भारत को भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी। लेकिन 'सम्पदा' के पाठक जानते हैं कि भारत को विदेशी व्यापार में भारी मात्रा में क्षति होती है और विदेशी मुद्रा निरन्तर कम होती जा रही है इसलिए जहां भारत सरकार ने बहुत सी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है, वहां उसने उद्योग व्यापार मण्डल के द्वारा उद्योगपतियों से यह भी अनुरोध किया है कि वे कम से कम विदेशी मशीनरी मंगायें। हमें आशा करनी चाहिए कि देश के उद्योगपति जो स्वयं स्वदेशी आन्दोलन के सबसे बड़े प्रचारक हैं यह कोशिश करेंगे कि जहां भी कुछ बचाया जा सके, विदेशी मशीनरी के पुर्जे तथा अन्य सामग्री केवल देश की लें, भले ही वे कुछ मंहगी हों, अथवा कुछ हल्के किस्म की हों।

अलोह धातुओं का उत्पादन

१९५१ में देश में अलुमीनियम, तांबा, जस्त आदि अलोह धातुओं का उत्पादन कुल ३ करोड़ रुपये के मूल्य के बराबर हुआ था। ५ वर्ष बाद १९५६ में यह उत्पादन ६ करोड़ रुपये का हो गया। फिर भी प्रति वर्ष करीब २५ करोड़ रुपये की अलोह धातुएं मंगानी पड़ती हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो नये कार्य देश में होने जा रहे हैं, उनके अनुसार आगामी पांच वर्षों में अलोह धातुओं की खपत ४१ करोड़ रुपये तक बढ़ जायेगी। इसका अर्थ यह है कि प्रति वर्ष हमें ३५ करोड़ रुपये की अलोह धातुओं की कमी रहेगी। इसलिए यह आवश्यक है कि भारत इन धातुओं के उत्पादन में स्वयं स्वावलम्बी होने का प्रयत्न करे। भारत इस सम्बन्ध में उदासीन नहीं है और राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने मैसूर में एक अलूमीनियम कारखाना खोलने का निर्णय किया है। इसमें प्रति वर्ष १० हजार टन अलूमीनियम तैयार हो सकेगा। हीराकुड में भी इतना ही बड़ा कारखाना खोलने की स्वीकृति दी जा चुकी है। चालू कारखानों में भी काम को अधिक बढ़ा दिया जायेगा। इस तरह यह अनुमान है कि २० हजार टन अलूमीनियम हम भारत में अधिक तैयार कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश के रेहन्द बांध के क्षेत्र में भी अलूमीनियम का कारखाना खोलने का विचार है। देश को स्वावलम्बी बनाने की दिशा में यह प्रयत्न अति आवश्यक है।

राजस्थान की विशेष आवश्यकताएं

स्वातन्त्र्य प्राप्ति और उत्तरदायी शासन से पूर्व शायद राजस्थान से बढ़ कर, आर्थिक दृष्टि से अधिक अनुन्नत कोई और ख श्रेणी का राज्य नहीं था। पानी और यातायात की कमी के कारण तत्कालीन शासक और जनता औद्योगिक विकास की ओर बहुत कम ध्यान दे सकी थी। उनके पास आवश्यक धन का भी अभाव था। विभिन्न रियासतों के एकीकरण, लोकतन्त्रीय शासन तथा नई विकास योजनाओं के कारण राजस्थान आर्थिक विकास की दशा में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। उसके अपार खनिज स्रोत, जो अब तक अज्ञात रूप से वसुन्धरा के गर्भ में पड़े हुए थे, अब राजस्थान को समृद्ध बनाने की दिशा में प्रयुक्त किये जाने लगे हैं। किन्तु राजस्थान को विकसित होने के लिए बहुत अधिक वित्तीय साधनों की आवश्यकता है। राजस्थान का केन्द्र के साथ वित्तीय एकीकरण होने से उसे एक बड़ा नुकसान यह होने लगा है कि रियासतों को होने वाली रेलों की आय उसके हाथ से निकल गई। पहले की अनुन्नत स्थिति से अन्य राज्यों के समकक्ष बनने के लिए उसे बहुत अधिक धन-राशि की आवश्यकता है। भारी घाटे के राज्य अजमेर के विलय हो जाने के कारण करीब १॥ करोड़ का अतिरिक्त घाटा बर्दाश्त करना पड़ेगा। एकीकरण से पूर्व रियासतों को अन्तःराज्यीय चुंगी से करीब १॥ करोड़ रुपये की आमदनी होती थी, वह भी अब समाप्त हो चुकी है। राजस्थान की मरुभूमि को हरा-भरा बनाने के लिए किसी भी अन्य राज्य से अधिक धन की आवश्यकता है। राजस्थान भारत की पाकिस्तानी सीमा पर स्थित है। इस-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लिए उसे सीमावर्ती सशस्त्र पुलिस पर ६० लाख रुपया वार्षिक व्यय करना पड़ता है। इन सब बातों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने भारत सरकार द्वारा श्री सन्तानम् की अध्यक्षता में नियत वित्त आयोग से यह अनुरोध किया है कि वह भावी वित्त-व्यवस्था में भारत सरकार की तरफ से उसे १० करोड़ रुपये की विशेष सहायता दिलाये। राजस्थान शासन के विचार काफी तर्क संगत हैं। उसकी विशेष आवश्यकतायें कम नहीं हैं। यदि राजस्थान जैसे बड़े राज्य में कपड़ा, चीनी और सीमेण्ट आदि नये उद्योग जारी करने हैं, सिंचाई और यातायात को उन्नत करना है, जिससे प्रायः प्रति वर्ष आने वाला दुर्भिक्ष न हो, तो राजस्थान की विशेष आवश्यकताओं का ध्यान वित्त आयोग को करना ही चाहिये।

शक्ति और कोयला

देश के औद्योगिक विकास के लिए एक अत्यन्त प्रधान आवश्यकता शक्ति का उत्पादन है। शक्ति प्राप्ति के लिए आज मानव और पशु सेवा के अतिरिक्त तीन प्रमुख स्रोत हैं—कोयला, तेल और बिजली। जिस मात्रा में रेलवे तथा कल-कारखानों में कोयला खर्च हो रहा है, उसे देखते हुए यह भय पैदा हो गया था कि वसुन्धरा का कोयले का भण्डार जल्दी ही समाप्त हो जायेगा और हमें शक्ति के लिए अन्य साधनों की तलाश करनी पड़ेगी। तेल संशोधन के कारखाने इसी प्रयत्न के अच्छे परिणाम थे। बिजली के उत्पादन को पंचवर्षीय योजना में असाधारण महत्व भी इसीलिये दिया गया है। इस वर्ष का प्रारम्भ ट्राम्बे के द्वारा नियत कार्यक्रम से भी पहले १ लाख किलोवाट बिजली पैदा करने से हुआ है। हीराकुड के नये बांध के उद्घाटन से यह आशा की जाने लगी है कि १॥ मास तक वहां भी करीब १। लाख किलोवाट बिजली पैदा होने लगेगी। इसी तरह देश के भिन्न-भिन्न भागों में विविध योजनायें विद्युत उत्पादन में लगी हैं। इन्हें देखते हुए यह कल्पना की जा सकती है कि भारतवर्ष शक्ति की प्राप्ति में कितनी तेजी से प्रगति कर रहा है।

फिर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इतनी विशाल मात्रा में उत्पन्न होने वाली बिजली कोयले से प्राप्त होने वाली शक्ति का दसवां हिस्सा भी नहीं है। इसलिए कोयले का महत्त्व तेल और बिजली के उत्पादन से कम नहीं हो जाता। अणु शक्ति भी निकट भविष्य में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं कर सकती। उसके विकसित होने में समय लगेगा। इसलि हमें कोयला उद्योग के विकास की ओर आज विशेष दृष्टि रखनी होगी। यह सौभाग्य की बात है कि एक ओर जहां सरकार कोयला उद्योग को विकसित करने पर ध्यान दे रही है, वहां प्रकृति की उदारता भी प्रकट होने लगी है। दक्षिण में भूरे कोयले या लिगनाईट की अनन्त सम्पत्ति का पता लगा है। इसके निकालने और इसे प्रयुक्त करने की योजनायें प्रारम्भ हो चुकी हैं। अब भौगर्भिक अनुसन्धान से यह मालूम हुआ है कि रानीगंज की कोयले की खानों में कोयला समाप्त होने का कोई खतरा नहीं है। बताया गया है कि वहां १३०० करोड़ टन से भी अधिक कोयला खानों में जमा है। यह १९२८ में किये गये अनुमान से दुगुना है। यह भी अनुमान किया गया है कि यह कोयले के भण्डार अभी निरन्तर बढ़ते जायेंगे। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं होना चाहिये कि हम कोयले का दुरुपयोग प्रारम्भ कर दें।

भारत में अणु शक्ति का केन्द्र

भारत में गत २० जनवरी को पहली अणु-भट्टी और अणु शक्ति केन्द्र का उद्घाटन हो गया। इससे बिजली उत्पन्न की जायेगी। आजकल औद्योगिक विकास के लिए जिस तरह कोयला और तेल खर्च किए जा रहे हैं, उसे देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि हम शक्ति के दूसरे स्रोतों का प्रयोग करें। १४० मैगावाट के बिजली स्टेशन के लिए प्रति दिन २ हजार टन कोयला चाहिए और ३० इंजन तथा १७०० रेल वैगन इस काम के लिए सुरक्षित करने पड़ेंगे, जबकि इतनी बिजली निकालने के लिए केवल ५० या १०० टन यूरेनियम काफी है। इसका अर्थ यह है कि इससे न केवल कोयले की भारी बचत होगी, परन्तु यातायात पर भी बहुत कम बोझ पड़ेगा। प्रश्न सिर्फ यह है कि क्या हम पर्याप्त मात्रा में अणु शक्ति प्राप्त कर सकेंगे और उसके लिए विदेशों पर बहुत निर्भर हुए बिना काम चला सकेंगे? गत अगस्त मास में जो अणु शक्ति का रिएक्टर बना और १९५८ में जो स्वीमिंग पूल रिएक्टर बनने वाला है, उनमें क्रमशः ब्रिटेन और केनेडा की बहुत

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सहायता ली गई है। आवश्यकता यह है कि अणु-शक्ति के उत्पादन के साधनों के सम्बन्ध में हम अधिक से अधिक स्वावलम्बी हों। यह सन्तोष की बात है कि भारतीय वैज्ञानिक इस दृष्टि से अणु-शक्ति उत्पादन को स्वावलम्बी बनाने की दिशा में प्रयत्नशील हैं। सौभाग्य से भारत में यूरेनियम और थोरिया के भण्डार कोयले के खनिज भण्डार से १५ गुणा अधिक है। दक्षिणी त्रावणकोर में मैंग्नेजाइट सैण्ड प्रचुर मात्रा में है। हैवी वाटर भी अणु उद्योग के के लिये आवश्यक है। इसका उत्पादन नांगल में हो रहा है।

व्यवहार-शुद्धता

पाठक अन्यत्र स्वतन्त्र साहस सघ का एक वक्तव्य पढ़ेंगे। देश में अर्थव्यवस्था समाजवादी हो, निजी उद्योग वादी हो अथवा मिश्रित अर्थ-व्यवस्था हो, एक बात सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है और वह यह कि प्रत्येक उद्योग और व्यापार के कार्यकर्ताओं को अपने अपने कारोबार में व्यवहार को सर्वथा शुद्ध रखना चाहिए। जन-हित ही एक मात्र उनकी कसौटी होनी चाहिए। बेईमानी, अनुचित नफाखोरी, चोर बाजारी, चीजों में मिलावट आदि सामाजिक अपराध हैं। स्वतन्त्र साहस संघ ने विदेशी शासन की अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितियों में भी देश को औद्योगिक विकास के ऊंचे स्तर पर लाने तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना में सरकारी उद्योगों की अपेक्षा अधिक सफलता प्राप्त करने के निजी उद्योगों के प्रशंसनीय कामों का उल्लेख करते हुए भी उसे यह राय दी है कि वह अपने कारोबार में और भी अधिक सजग और भी अधिक चेतन रहे तथा देश की आर्थिक उन्नति में अपना पूरा भाग अदा करे। इसके लिए उन्हें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए, जिससे निजी उद्योग की कुछ भी बदनामी हो। हमारा विश्वास है कि जनता का अधिक विश्वास प्राप्त करने के लिए उद्योगपति और व्यापारियों को और भी अधिक ऊंचे स्तर पर काम करना चाहिए। यह परामर्श हमारी सम्मति में राजकीय उद्योग व्यापार के कर्मचारियों तथा सरकारी कर्मचारियों के लिए और भी अधिक अनुकरणीय है, क्योंकि दुर्भाग्य से आज सरकारी कर्मचारी निजी व्यापारियों से कम बदनाम नहीं हैं। संघ ने दुकानदारों, डाक्टरों, वकीलों तथा अन्य निजी धन्धा करने वालों को भी अधिक जनसेवी बनने का परामर्श दिया है। आवश्यकता यह है कि प्रत्येक नागरिक को आज अपनी दृष्टि बदल कर जनहित पर बनानी चाहिए।

पं० नेहरू की सतर्कता

पिछले दो तीन वर्षों से निजी उद्योग सरकार की अनेक नीतियों और विशेषकर राष्ट्रीयकरण की नीति से बहुत चिन्तित है। उसे यह भय हो गया है कि शायद सरकार कुछ समय बाद प्रायः सभी निजी उद्योगों को समाप्त कर देगी। अनेक सरकारी नेताओं के समय समय पर दिए गए भाषणों से यह भय और भी बढ़ जाता है। किन्तु प्रधान मंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू के इन्दौर में दिए गए महत्वपूर्ण भाषण का वे जरूर स्वागत करेंगे। उन्होंने पूर्वी यूरोप के देशों में असन्तुलित योजना के, जिसमें उपभोग्य पदार्थों की अपेक्षा आधारभूत उद्योगों पर विशेष बल दिया गया है, दुष्परिणामों की चर्चा करते हुए कहा कि हम निजी स्वतन्त्रता के महत्व को अनुभव करते हैं, क्योंकि हम मानव की उत्पादनशील और साहसपूर्ण भावना को बढ़ाना चाहते हैं। केवल बड़ी मशीनों को तैयार कर लेना ही काफी नहीं है। हमें हंगरी और पौलैंड की घटनाओं से शिक्षा लेनी चाहिए और अपनी पंचवर्षीय योजना को इतना लचकीला बनाना चाहिए, जिससे आवश्यकता के अनुसार उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किया जा सके। श्री नेहरू ने अपने वक्तव्य को और भी स्पष्ट करते हुए कहा कि हमें बड़ी मशीनरी पैदा करनी है तथा अपने जीवन का स्तर ऊंचा करना है, किन्तु मानव की स्वतन्त्रता, उसकी उत्पादन शक्ति, उसकी साहसपूर्ण भावना और जीवन के उन सब सुन्दर तत्वों का बलिदान करके नहीं, जिनके कारण वह अतीत में इतनी उन्नति कर सका है। श्री नेहरू के इस भाषण को हम निजी उद्योग को दिये गये आश्वासन के रूप में मान सकते हैं। परन्तु इसके साथ ही उस पर एक विशेष उत्तरदायित्व भी आ जाता है कि वह राष्ट्र के आर्थिक विकास में अधिक प्रयत्नशील हो।

—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दूसरी योजना व वित्तीय साधनों की कमी

श्री कृष्णचन्द्र विद्यालंकार

प्रथम योजना का लक्ष्य करीब दुगुना करके पहले ४३ अरब रुपए की दूसरी योजना बनाई गई। फिर इसे बढ़ाकर ४८ अरब का लक्ष्य रखा गया। योजना के अभी ८ महीने अमल में आये नहीं हुए कि योजना का लक्ष्य और बढ़ाकर ५३ अरब किया जा रहा है। यह भी प्रधान मंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू कह चुके हैं कि हमारी योजना आवश्यकताओं के अनुसार लचकीली होनी चाहिए और हमें एक साथ पंचवर्षीय योजना का पूर्ण रूप सामने न रख कर प्रति वर्ष के लक्ष्य अलग अलग नियत कर देने चाहिए।

चार प्रश्न

इतनी अनिश्चितता और इतने गम्भीर और लम्बे तर्क-वितर्क की आवश्यकता क्या है, इसे समझाने के लिए हमें विवादास्पद प्रश्नों और समस्याओं पर एक दृष्टि डालनी होगी। ये विवादास्पद प्रश्न निम्नलिखित हैं—

१—हमारी योजना उद्योग-प्रधान होनी चाहिए अथवा कृषि प्रधान? प्रथम योजना कृषि प्रधान थी। नई योजना में उद्योगों पर बहुत अधिक बल दिया गया है। उद्योग, खनिज, परिवहन आदि पर कुल योजना व्यय का ५० प्रतिशत व्यय रखा गया है, जबकि प्रथम योजना में ३३ प्रतिशत व्यय रखा गया था। प्रथम योजना में कृषि व तत्सम्बन्धी कार्यों पर कुल व्यय का एक तिहाई व्यय नियत किया गया था, पर दूसरी योजना में सिर्फ २० प्रतिशत।

२—औद्योगिक विकास का हमारा आदर्श क्या होना चाहिए? अमेरिका, रूस, की तरह बड़े बड़े विशालकाय उद्योग स्थापित किए जायें अथवा ग्रामोद्योगों का विकास किया जाये। योजना आयोग अणुशक्ति के युग में और उत्पादन वृद्धि की आवश्यकता को देखते हुए आधुनिकतम वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग आवश्यक समझता है। इसलिए प्रधान उद्योगों पर विशेष बल दिया गया है।

३--समाजवाद की दिशा में बढ़ने के लिए योजना आयोग ने अनेक उद्योगों का राष्ट्रीयकरण आवश्यक समझा है, जबकि बहुत से अर्थशास्त्री और उद्योगपति सरकार के उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में इतने अधिक हस्तक्षेप और प्रवेश के सिद्धान्ततः और व्यवहारतः विरुद्ध हैं।

४—एक बड़ा प्रश्न यह रहा है कि क्या हम इतनी विशाल योजना चलाने और पूर्ण करने की सामर्थ्य भी रखते हैं अथवा नहीं। क्या हमारे पास करीब ६० अरब रुपये प्राप्त करने के साधन भी हैं। योजना आयोग ने प्रथम योजना की पूर्ति के विश्वास और दूसरी योजना के लिए अत्यधिक उत्साह और आशा के साथ सब आशंकाओं की उपेक्षा कर एक विशाल कार्य योजना बना ली।

वित्तीय साधनों की समस्या

उपर्युक्त चारों प्रश्नों में से प्रथम तीन जहां व्यावहारिक के साथ सैद्धान्तिक आदर्शवादी भी हैं, वहाँ अन्तिम प्रश्न विशुद्ध व्यावहारिक है। इसलिए जब प्रथम तीन प्रश्नों पर आदर्श और भावुकता की दृष्टि से विचार किया जा सकता है। वहां अन्तिम प्रश्न पर केवल आंकड़ों की दृष्टि से ही विचार किया जाना चाहिए। योजना आयोग ने वित्तीय साधनों की चर्चा करते हुए यह अनुमान किया कि वर्तमान दरों पर सामान्य राजस्व से ३५० करोड़, अतिरिक्त करों से ४५० करोड़, रेलवे प्राविडेंट फण्ड आदि से ४०० करोड़, सार्वजनिक ऋण और बचत से १२०० करोड़ और विदेशी सहायता से ८०० करोड़ रु० प्राप्त होगा। घाटे की अर्थव्यवस्था का आश्रय लेकर नासिक के नोट छापने के प्रैस से १२०० करोड़ रुपए प्राप्त करने की भी योजना बनाई गई थी। फिर भी योजना आयोग ४८०० करोड़ रुपये का योग पूरा नहीं कर सका; अब तो योजना का यह लक्ष्य ५

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अरब रुपया और बढ़ा दिया गया है, अर्थात् करीब १० अरब रुपए की पूर्ति की भीषण समस्या हमारे सामने है।

यदि केवल १० अरब का ही प्रश्न होता तो भी गनीमत थी। आज तो स्थिति इतनी चिन्तनीय है कि आयके उपर्युक्त साधनों का अनुमान भी गलत हो रहा है। व्यापारिक संतुलन भी भारत के प्रतिकूल हो रहा है। अन्न-संकट फिर नये रूप में सिर उठा रहा है। इन सबके कारण वित्तीय साधनों की समस्या पर नये सिरे से विचार करना पड़ रहा है।

विदेशों में पदार्थों के मूल्य बढ़ जाने के कारण भी देश पर एक नया बोझ आ पड़ा है। इसी नवम्बर में भारत के वित्त मन्त्री श्री कृष्णमाचार्य ने १६ करोड़ रुपए के नये कर लगाते हुए बताया था कि देश की अर्थ-व्यवस्था पर बोझ निरन्तर बढ़ता जा रहा है। रिजर्व बैंक ने विदेशी विनिमय के लिए जो राशि सुरक्षित की थी, वह आठ महीने में ७४६ करोड़ से गिर कर ५४३ करोड़ रह गई। लड़ाई के कारण स्वेज नहर के रुक जाने से जहाजी भाड़ा बढ़ गया है। जहाजों की कठिनता भी कम नहीं हुई। इसलिए विदेशों से आने वाले सामान का मूल्य बढ़ता जा रहा है। देश में फिर अन्न संकट के भारी लक्षण दीखने लगे हैं। इस कारण १८ लाख टन अनाज इस वर्ष मंगाया जा रहा है। यदि देश में अन्न-संकट की पुनरावृत्ति नहीं करनी है तो यह अनाज मंगाना ही पड़ेगा। भारी उद्योगों के विकास की योजनाएं पूर्ण करने के लिए मशीनरी का मंगाना भी नहीं रोका जा सकता।

योजना में विदेशों से ८ अरब रुपए की प्राप्ति की आशा की गई है। लेकिन अब यह संदेह होने लगा है कि यह राशि मिल सकेगी या नहीं। रूरकेला में जर्मन फर्म जो करोड़ों रुपया लगाने वाली थी, वह उसने लगाने से इन्कार कर दिया है, क्योंकि अब जर्मनी में रुपए पर सूद दर बहुत बढ़ गई है। इस कारण यह रुपया भी भारत को लगना पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक के गवर्नर मि० ब्लैक ने भारत की आर्थिक नीति की जो आलोचना की है, उससे यह सन्देह और भी बढ़ जाता है कि विदेशों से आशा के अनुरूप सहायता मिलेगी, क्योंकि उसकी सम्मति में देश बहुत तेजी से राष्ट्रीयकरण और समाजवाद की ओर जा रहा है।

बचत की आशा भी ?

भारत सरकार ने अथवा योजना आयोग ने यह अनुमान किया था कि ज्यों-ज्यों देश समृद्ध होता जायेगा व राष्ट्रीय आय बढ़ती जायेगी त्यों-त्यों विनियोजन का प्रतिशत भी बढ़ता जायेगा। यदि प्रथम योजना के अन्त में यह प्रतिशत राष्ट्रीय आय का ७.३ था तो दूसरी योजना में यह १०.७ हो जाना चाहिये। परन्तु आज यह भी सन्देह किया जा रहा है कि चीजों की मंहगाई देखते हुए लोग कहां तक बचत कर सकेंगे। यदि मुद्रा प्रसार और मंहगाई को न रोका गया तो यह संदेह करने के कारण हैं कि जनता से ५ करोड़ रुपया बचत की आशा पूर्ण नहीं होगी। यह ठीक है कि प्रथम योजना के काल में बचत प्रतिवर्ष निरन्तर बढ़ती रही है। परन्तु इसका कारण यह था कि फसलें बहुत अच्छी हुई थीं। कृषि का देश की समस्त अर्थ व्यवस्था पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। सरकार जो नई अर्थ नीति लागू करना चाहती है, उसका भी प्रभाव बहुत सम्भवतः बचत की दृष्टि से अच्छा नहीं पड़ेगा, क्योंकि उससे सामान्य जनता की आय तो कुछ बढ़ सकती है, सम्पन्न वर्ग की नहीं। और सामान्य जनता कीमतें बढ़ जाने के कारण बचत बहुत नहीं कर सकेगी। नये उद्योगों में विनियोग की जो सम्भावना औद्योगिक क्षेत्रों से की जा रही थी, उसकी पूर्ति में समाजवादी नीति के कारण अब कुछ कठिनताएं अवश्य हो गई हैं।

प्रथम योजना में निजी उद्योग ने अपने लक्ष्य पूर्ण किये हैं, सरकारी पक्ष में ही कमी रही है। यदि इसकी पुनरावृत्ति दूसरी योजना में भी रही, तो योजना पर इसका प्रतिकूल प्रभाव और भी अधिक गंभीर रहेगा, क्योंकि इसमें सरकार के उत्तरदायित्व बहुत बढ़ गये हैं।

भारत के प्रधानमन्त्री पं० नेहरू तथा आयोग ने वित्तीय कठिनाइयों को न समझा हो, यह बात नहीं। पं० नेहरू ने देश का उत्पादन बढ़ाये बिना क्या स्थिति हो सकती है, इसकी चर्चा करते हुए कहा है—"वस्तुस्थिति हमारे सामने है। हमें इनमें से एक बात का फैसला करना है—कृषि उपज बढ़ाकर आयोजना को सफल बनायें या आयोजना छोड़ दें। उन्होंने फिर अपने वक्तव्य में कहा

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कि—"हमारे सामने जो सबसे महत्त्वपूर्ण समस्याएं हैं, वे हैं साधनों को कैसे बढ़ाया जाय और मुद्रा-बाहुल्य के खतरे का कैसे मुकाबला किया जाए, आदि। अब वह समय आ गया है, जब हमें इस बात पर बड़ी सावधानी से सोचना होगा कि कौनसी वस्तु, चाहे वह बड़ी हो या छोटी, हमारे लिए अत्यन्त आवश्यक है और कौनसी नहीं, क्या उससे धन की खराबी तो नहीं होगी, क्या फिलहाल हम उसके बिना भी काम चला सकते हैं या नहीं।" इन शब्दों से स्थिति की गम्भीरता प्रकट होती है।

योजना के बड़े बड़े लक्ष्यों में एक लक्ष्य है बेकारी का निवारण। इसमें १ करोड़ को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। प्रथम योजनाकाल में ५० लाख को काम मिला था, लेकिन ९० लाख नये व्यक्ति जनसंख्या वृद्धि के कारण मजदूर के रूप में बाजार में आ गये। दूसरी योजना में भी १ करोड़ नये आदमी बढ़ जावेंगे, जिनको रोजगार देना है। उद्योग की नयी टैकनीक को अपनाने की जो प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, उससे ग्रामोद्योगों का प्रसार बहुत संभव नहीं हैं। इसलिए बेकारी का यथेष्ट निवारण नहीं हो सकेगा। इस गम्भीर समस्या की उपेक्षा नहीं की जा सकती। किन्तु एक बात स्पष्ट है कि चाहे परिस्थितियां कितनी प्रतिकूल हों, समस्याएं कितनी गम्भीर हों, अपनी योजना को हमें अवश्य पूर्ण करना है। इस योजना की सफलता से देश का सम्मान जितना बढ़ जायगा, उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। यदि हम असफल हुए, तो यह लोकतंत्रात्मक योजना की पराजय होगी, और इसका दूसरा विकल्प है रूस का सा एक दलीय शासन, जिसमें व्यक्ति स्वातंत्र्य का अभाव होगा। परन्तु भारत को एक नया आदर्श चलाना है और इसके लिए जन-जन में उत्साह व आशा पैदा करनी है।

परन्तु निराशा नहीं

भिलाई व दुर्गापुर कारखानों के लिए रूस व ब्रिटेन से क्रमशः ४३ और ३३ करोड़ रु० मिलेंगे। अमेरिका ने १३० करोड़ रु० का अनाज देना मान लिया है। श्री के० सी० रेडी रूस द्वारा ६० करोड़ रु० उधार का प्रस्ताव लाये हैं। पं० नेहरू की अमेरिका यात्रा का प्रभाव भी अनुकूल हो सकता है। निजी उद्योग को भी विश्व बैंक से करोड़ों रुपया मिला है। यह राशि ५५३ करोड़ रु० तक सम्भवतः पहुँच सकती है। परन्तु इनसे भी काम नहीं बनेगा। भारतीयों को श्रमदान व धन दान के लिए उद्यत रहना चाहिए। सरकार अधिकाधिक कर लगा रही है, इसमें हमें सहयोग देना ही होगा। भारत कठिन परीक्षा काल से गुजर रहा है। यदि समस्त ३६ करोड़ भारतीय मिलकर राष्ट्र-विकास के लिए कटिबद्ध हो जावें, तो कोई शक्ति ऐसी नहीं, जो विकास की योजनाओं को पूर्ण होने से रोक सके।

—

हमारा मुख्य राष्ट्रीय कर्तव्य

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त

आज हम भारतीय इतिहास के परिवर्तनशील काल में से गुजर रहे हैं। सब तरफ बड़े-बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। पिछले एक हजार वर्ष से भारत पिछड़ता जा रहा था। हम अपने सम्पूर्ण साधनों से कई सदियों की इस कमी को दूर करने में जुट गये हैं। आशा, विश्वास, दृढ़ निश्चय और सतत प्रयत्न से ही हम इस कार्य में सफलता पा सकेंगे।

दूसरी पंचवर्षीय आयोजना कुछ महीने पहले ही शुरू की गयी थी। इससे ऐसी औद्योगिक क्रांति का श्रीगणेश हुआ है, जो देश की शकल बदल देगी। भावी औद्योगीकरण को ध्यान में रखते हुए इसमें भारी उद्योगों पर जोर दिया गया है। लेकिन छोटे उद्योगों की भी उपेक्षा नहीं की गयी है, क्योंकि उन्हीं से भारी संख्या में लोगों को रोजी मिलती है। आयोजना को चलाने के लिये आवश्यक धन एकत्रित करना होगा और हो सकता है कि इसके लिये कुछ लोगों को अस्थायी रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन प्रगति के सामान्य हित को ध्यान में रखते हुए इन कठिनाइयों को झेलना चाहिये। अब आयोजना को सफल बनाना हमारा मुख्य राष्ट्रीय कर्तव्य होना चाहिये।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

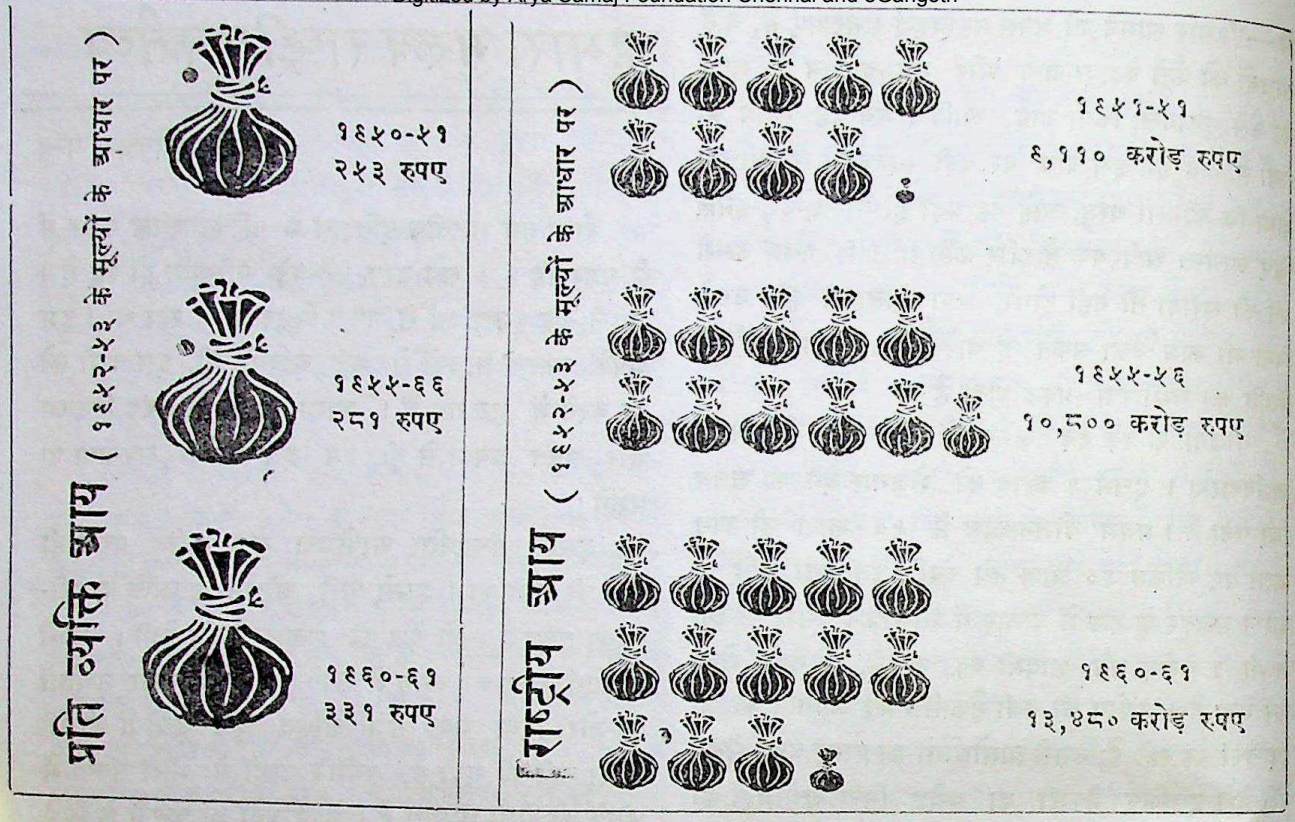

हमारी योजना और नई समस्याएं

श्री पी० सी० जैन

प्रथम पंचवर्षीय योजना के सफलता पूर्वक सम्पन्न होने से भारत की 'राष्ट्रीय आय' में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। १९४८-४९ के मूल्यों में १९५०-५१ की राष्ट्रीय आय ८,८५० करोड़ रुपये से बढ़कर १९५४-५५ में १०,१७० करोड़ रुपए होगई। १९५५-५६ के आंकड़े ठीक प्रकार से अभी उपलब्ध नहीं हैं, तथापि आयोजना आयोग के अनुसार, योजना की समाप्ति पर राष्ट्रीय आय में १०,४४३ करोड़ रुपये याने १८ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

इस अवधि में देश में उत्पादन की वृद्धि उत्साहजनक है। देश में खाद्य पदार्थों का उत्पादन १९५०-५१ में ५०० लाख टन था, वह १९५५-५६ में बढ़कर ६५० लाख टन हो गया। इसी प्रकार १९५१ को आधार वर्ष १०० मान करके औद्योगिक उत्पादन १९५५ में बढ़कर १२२.९ हो गया। यही १९५६ के पहले ८ महीनों में बढ़कर १३४.७ हो गया। इस प्रकार की उत्पादन-वृद्धि पर कोई भी राष्ट्र गर्व कर सकता है। भारत को तो इस श्रेय पर विशेष गर्व होना उचित ही है, क्योंकि जनता सरकार और उत्पादकों को इसकी सफलता लिए अगणित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

मुद्रा-स्फीति

प्रथम योजनावधि में कितनी ही कठिनाइयों के होते हुए भी मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखा गया। लेकिन १ अप्रैल ५६ से आरम्भ होने वाली द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता। दुर्भाग्य-वश द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ के कुछ महीनों में मुद्रास्फीति अपने भयंकर रूप में प्रकट हुई। थोक वस्तुओं के सामान्य सूचक अंक लगातार बढ़ते गए। सामान्य सूचक अंक १९५२-५३ में ३८०.६, १९५४-५५ में ३७७.५ और १९५५-५६ में ३६०.३ थे। जुलाई १९५६ से इनमें वृद्धि होने लगी। इस महीने में सूचक अंक ४०९.२ थे

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

और तब से इनमें इसी प्रकार की निरन्तर वृद्धि होती रही, १९५६ के नवम्बर २४ को समाप्त होने वाले सप्ताह में ये बढ़कर ४३३.२ हो गये। गत चार वर्षों का यह उच्चतम अंक है। हां, दिसम्बर १९५१ के अंक ४३३.१ से कुछ ही अधिक है। मूल्यों के इस प्रकार बढ़ते जाने से जनता को अत्यंत कष्ट झेलना पड़ रहा है।

सरकार ने निश्चय किया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजनामें घाटे की अर्थ-व्यवस्था का आश्रय लिया जाय। और योजना के इन ५ सालों में औसतन २४० करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से १,२०० करोड़ से भी अधिक रुपयों की अतिरिक्त व्यवस्था की जाए। अर्थात् सरकार समस्त करों, ऋणों और अन्यान्य समस्त साधनों से प्राप्त आय के अतिरिक्त औसतन २४० करोड़ रुपए प्रति वर्ष व्यय करेगी। कुछ विशेषज्ञों का, जिनका योजना आयोग या सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं, विचार है कि देश के लिए घाटे की अर्थ-व्यवस्था का यह स्तर काफी ऊंचा है या काफी भारी है। सामान्य स्थिति में औसतन २४० करोड़ रु० प्रतिवर्ष घाटे की अर्थ-व्यवस्था और इससे भी ऊंची राशि से संभवतः अधिक हानि न हो परन्तु आज तो स्थिति वैसी सामान्य नहीं है।

उत्पादन कम : मांग ज्यादा

भारत में मांग के अनुसार अपेक्षित रूप में वस्तुओं की पूर्ति नहीं बढ़ी, यद्यपि इसके लिए काफी विनियोजन किया गया है। इसके लिए यह बात ध्यान देने योग्य है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ऐसे उद्योगों को प्रमुखता दी गई है, जिनका फल काफी समय बाद मिलेगा। इस प्रकार जनता के पास खरीदने के लिए पैसा बढ़ रहा है। पर वस्तुओं की अपेक्षित पूर्ति न होने के कारण उनके दाम बढ़ना स्वाभाविक हो गया है। इन दोनों में एक सीमा तक समता लाने के लिए आवश्यक है कि मौजूदा बड़े उद्योग यथाशक्ति अपना उत्पादन बढ़ाएं। लेकिन सरकार इस विषय में एक भ्रामक नीति का अनुसरण कर रही है। जिसके अनुसार उसने बड़े-बड़े उत्पादनों पर इस दृष्टि से प्रतिबन्ध लगा दिया हैं कि उनसे छोटे उद्योगों और कुटीर-उद्योगों को हानि न हो। कोई भी छोटे और कुटीर उद्योगों की महत्ता को अस्वीकार नहीं कर सकता ताकि उनसे बेकारीको दूर करने में सहायता ली जाए। लेकिन सरकार ने जिस

वित्त मंत्री श्री टी० टी० कृष्णमाचार्य

नीति की अनुसरण किया है, उससे गहन मुद्रा-स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कुटीर उद्योगों के कपड़े जूते आदि वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा अवश्य है, पर उनसे मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित न हो सका। यह सर्व मान्य सत्य है कि ग्राहक अपनी रुचि के अनुसार ही वस्तुओं को खरीदते हैं और। उनकी रुचियों में अकस्मात परिवर्तन किया जा सकता है, भले ही कोई इसके लिए कितना ही कहता रहे। कुटीर उद्योगों के उत्पादन के प्रति लोगों की रुचि बनाने के लिए आवश्यक है कि पहले कुटीर उत्पादनों को आकर्षक बनाया जाए और उनका मूल्य भी कम हो। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निर्माताओं ने बड़े उद्योगों पर कुटीर उद्योगों के लाभ के विचार से अनेक प्रकार के नियंत्रण लगाये वहां उन्होंने कुटीर उद्योगों की वस्तुओं को अच्छी किस्म के और सस्ते बनाने पर बहुत ध्यान नहीं दिया, इसी कारण आज माँग और पूर्ति में इतना असन्तुलन हो गया है।

कृषि की उपेक्षा

कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हो जाने से, लोगों की बढ़ी आय का खाद्य पदार्थों के खरीद से सामंजस्य हो जाता, जिससे मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित करने में सहा-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

यता मिलती। लेकिन योजना के निर्माताओं ने अर्थशास्त्र के इस मूल सिद्धांत से अज्ञानता प्रकट करते हुए इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने वास्तव में खेती पर किये जाने वाले खर्च का प्रतिशत घटा दिया। मानो उन्होंने कृषि कार्य के लिए जो कुछ करना था, वह पूरा कर लिया हो और अब करने को कुछ न रहा हो। हमारा कृषि उत्पादन न भी बढ़े तो कोई बात नहीं, क्योंकि योजना आयोग का यह विश्वास था कि देश खाद्य में आत्मनिर्भर हो गया है। लेकिन बाद में स्वयं आयोग को अपनी गलती महसूस हुई और उसने योजना में संशोधन करके कृषि पर भी और जोर दिया लेकिन इसके लिए राशि में कोई वृद्धि नहीं की गई। अतः फिर भी स्थिति में कोई अन्तर नहीं हुआ। हमें यह बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि भारत में भूमि की उत्पादकता की एक सीमा है तथा जलवायु की अनिश्चितता का खाद्य तथा अन्य कृषि-उत्पादनों पर प्रभाव पड़ता है।

घाटे की व्यवस्था और मुद्राप्रसार

घाटे की अर्थ व्यवस्था में कर वृद्धिमान विनियोजन के कारण जो मूल्य-स्तर बढ़ गए हैं उनको उचित सीमा पर नियंत्रित किया जा सकता था यदि हमने पर्याप्त मात्रा में विदेशों से अन्न, कपड़ा और उपयोग की अन्य वस्तुओं का आयात कर लिया होता। पर हम ऐसा न कर सके, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त विदेशी विनिमय सम्बन्धी साधन न थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अपने औद्योगिक विस्तार के उद्देश्य की पूर्ति के लिए मशीन, इस्पात और अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए भारी आयात करने के कारण हमारा व्यापार-संतुलन घाटे में रहा, जो १९५४ में ४६ करोड़ रुपए, १९५५ में ४० करोड़ रुपए और १९५६ के पहले ११ महीनों में १८९ करोड़ रुपए था। इसी कारण जनवरी १९५६ में हमारा विदेशी विनिमय ७४२ करोड़ रुपए से घटकर नवम्बर १९५६ में ५३९ करोड़ रुपए रह गया। इसका तात्पर्य यह है कि हम देश की मुद्रा स्फीति का सामना आयात के द्वारा नहीं कर सकते। सच है, भारत सरकार की १९५७ के प्रथम छह महीनों की आयात नीति में उपभोग की वस्तुओं पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। लेकिन इससे भी अधिक मुद्रा-स्फीति का भय हो सकता है यदि विनियोजन की दर भविष्य में इसी प्रकार बढ़ती रहे।

ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए घाटे की अर्थ-व्यवस्था की राशि पर विचार करते समय इससे होने वाले परिणामों को भी ध्यान में रखा जाएगा। यद्यपि सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तथापि वित्तमंत्री श्री कृष्णमाचार्य द्वारा लोकसभा में दिये वक्तव्यों और हाल ही उनके मद्रास वाले भाषण से सरकार की नीति में परिवर्तन का संकेत मिलता है। ऐसा आभास मिलता है कि वित्तमंत्री घाटे की अर्थ व्यवस्था की राशि में कमी करना चाहते हैं और इसके स्थान पर अतिरिक्त करों से आय प्राप्त करना चाहते हैं। जनसाधारण में द्रव्य की बढ़ती होती जा रही है। १९५५ के अक्टूबर के महीने में लोगों में कुल मुद्रा १,९७८ करोड़ रुपए थी। इसी प्रकार जनवरी १९५६ में यह मुद्रा २,०९४ करोड़ रुपए से बढ़कर अक्टूबर १९५६ में २,१२१ करोड़ रुपए हो गई। वित्तमंत्री का विश्वास है कि अतिरिक्त करों के द्वारा लोगों में बढ़ी मुद्रा को खींचा जा सकता है। इसके साथ ही मांग और पूर्ति में सामंजस्य उत्पन्न हो जाएगा। श्री कृष्णमाचार्य के इस विश्वास के अनुसार मूल्य स्तर नीचे हो जाएंगे। लेकिन वे इस बात को भूल गये कि भारत में मूल्य इसीलिए ऊँचे नहीं कि मांग और पूर्ति में सामंजस्य नहीं, वरन् उत्पादनों की लागत ऊँची हो जाने से दाम बढ़े हुए हैं। हाल में ही तटकर और लाभांश पर कर में वृद्धि हो जाने से मूल्य और बढ़ गए हैं। भारत में स्थिति यह है कि अतिरिक्तों करों से मूल्य ही बढ़ेंगे। हां इतना अवश्य है कि लोगों की मांग में कुछ कमी अवश्य होगी। अतः मूल्य स्तर को कम करने और मुद्रा प्रसार को रोकने के साधन के रूप में अतिरिक्त कर की व्यवस्था इस दशा में कदापि नहीं की जानी चाहिए। इससे तो मूल्य लगातार बढ़ते ही जाएंगे और शीघ्र ही अर्थ-व्यवस्था चौपट हो जाएगी। इसके अलावा यह भी देखना चाहिए कि जनता अतिरिक्त कर देने का सामर्थ्य रखती है या नहीं? वैसे ही जनता असह्य कर भार से दबी है। इस स्थिति में वित्त मंत्री का यह कहना कि जनता को योजना की सफलता के लिए अधिक से अधिक त्याग करना चाहिए, गलत है। एक औसत व्यक्ति अन्न कपड़ा और आदि वस्तुओं का इतना उपभोग कर रहा है कि उनमें वह

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राष्ट्र का आर्थिक प्रवाह

श्री जी० एस० पथिक

भारत के विदेशी व्यापार की स्थिति पिछले तीन मास से सुधर रही है। उसके परिणाम स्वरूप विदेशी मुद्रा की कमी का बोझ हलका हो रहा है। अधिकृत अंकों के आधार पर सितम्बर १९५६ में विदेशी व्यापार में भुगतान की कमी २७ करोड़ के रेकार्ड तक पहुँच गयी थी। इसके उपरांत उत्तरोतर कमी हुयी। अक्टूबर में १८ करोड़ रुपए और नवम्बर में १४ करोड़ रुपए तथा उसके उपरांत डेढ़ मास में १२ करोड़ रुपए की कमी रह गयी। विदेशी व्यापार के आयात में सितम्बर मास के अंत से ओ० जी० एल० की आमद में कितनी ही मदें रद्द कर दी गयीं। स्वेज का मार्ग बंद होने से भी विदेशी व्यापार का प्रतिकूल पांसा हल्का हुआ है। नयी आयात नीति में और भी भारी कमी की गयी है। यंत्र सामग्री और स्पात का आयात घटा दिया गया है। जो निजी उद्योगों विदेशी सहायता से मशीनों का आयात करेंगे, उनके आयात में रुकावट न होगी। जिन मशीनों की आमद का पैसा लम्बी मुद्दत में कम से कम सात वर्षों में चुकेगा, और आरंभ में २० प्रतिशत की रकम चुकानी पड़े, तो उसकी आयात भी हो सकेगा। जिन जिन देशों में भारत की रकम जमा है या जहां की संस्थाएं रुपया लगाना चाहती हैं, वहां से आयात होने में कोई रुकावट खड़ी न होगी, उपभोक्ता पदार्थों के आयात में भी कमी की गयी है। यह भी कहा गया है कि स्थिति सुधरने पर आयात नीति में फिर ढील कर दी जायगी।

बम्बई मिल ओनर्स एसोसियेशन

पोद्दार ग्रूप के उद्योगों के संचालक श्री रामनाथ पोद्दार बम्बई मिल ओनर्स एसोसियेशन के १९५७ के लिए अध्यक्ष चुने गए हैं। पोद्दारजी टेक्सटाइल रिसर्च एसोसियेशन के सदस्य हैं और रेशम उद्योगकी विकास समितिके अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान वित्तीय कारपोरेशन तथा जयपुर बैंक के भी अध्यक्ष हैं। बम्बई तथा राजस्थान की यूनीवरसिटियों की सिनेट के भी सदस्य हैं। आप हिन्दी प्रेमी, व्यापारिक साहित्य के प्रणयन में अनुराग रखने वाले और समाज सुधारक हैं।

भारत-पाकिस्तान व्यापार

भारत और पाकिस्तान में अगले तीन वर्षों के लिए जो व्यापारिक समझौता हुआ है उसका अमल फरवरी १९५७ से होगा। इकरार नामेके अनुसार दोनों देश परस्पर पसंदगी के राष्ट्र के रूप में बर्ताव करेंगे। परस्पर व्यापार विकास का प्रयत्न करेंगे और वर्तमान में दोनों देशों के बीच में व्यापार का असंतुलन है, उसके मिटाने का प्रयत्न करेंगे। इसका अर्थ यह है कि भारत का निर्यात पाकिस्तान में बढ़ेगा। छह मास के उपरांत इकरार नामे की गतिविधि का परीक्षण किया जाएगा। प्रतिवर्ष के आरम्भ में इकरार नामे का पर्यवेक्षण होगा। कोई भी पक्ष एक वर्ष के अंत में इकरारनामा हटा सकेगा। इकरार नामे के अंत में पहले दो परिशिष्टों में आयात निर्यात के वस्तुओं की सूची दी गयी है। तीसरे परिशीष्ट में अनेक वस्तुओं के नाम, उनके लाट और मूल्य प्रकट किये गए हैं। चौथे परिशिष्ट में सीमावर्ती व्यापार की वस्तुओं का उल्लेख है। भारत पाकिस्तान को प्रतिमास १ लाख टन कोयले का निर्यात करेगा। इसमें से ३० हजार टन और ५५ हजार टन पश्चिम पाकिस्तान और पूर्व पाकिस्तान में रेल तथा नदी के मार्ग से जाएगा और १५ हजार टन समुद्र के मार्ग से जाएगा। भारत पूर्व पाकिस्तान को ५० हजार टन सीमेण्ट का निर्यात करेगा और वह बदले में पश्चिमी पाकिस्तान से ५० हजार टन सीमेण्ट का आयात करेगा। भारत पाकिस्तान से कच्चा पाट चमड़ा तथा अन्य कई पदार्थों का आयात करेगा तथा भारत पाकिस्तान को कोयले के अति-

---

कमी कर ही नहीं सकता, क्योंकि इनमें कमी करने का तात्पर्य उसके स्वास्थ्य और कार्य क्षमता में हानि होगी। सार्वजनिक सभा में त्याग की बात कहना ठीक है, भारत में इस प्रकार की गुंजाइश अब नहीं। सरकार इस बात को जितनी जल्दी समझ ले, उतना ही ठीक है, पर यदि वित्तमंत्री अपनी ही बात पर तुले रहें तो लोगों को किन असह्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, उन कठिनाइयों के स्वरूप की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रिक्त रासायनिक पदार्थ, मशीनरी, कलपुर्जे, विद्युत पदार्थ, फिल्म, चीनी, चाय, काफी, तम्बाकू, दवाइयां, स्ट्रा बोर्ड आदि पदार्थों का निर्यात करेगा। कपड़े के सम्बन्ध में पाकिस्तान की नीति यह है कि वह विदेशों के किसी भी कोने से कपड़े का आयात न करेगा। नए इकरार नामे में कपड़े को स्थान नहीं मिला है।

टाटा कम्पनी का राष्ट्रीयकरण नहीं

प्रधानमंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने अपने एक भाषण में यह प्रकट किया है कि सरकार टाटा आयरन एण्ड स्टील जैसी बड़ी कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहती है। विदेशी प्रभुत्व के उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के प्रति भारत सरकार उदासीन है। उन्होंने इस सिद्धान्त को प्रकट किया कि बिना मुआवजा चुकाए किसी उद्योग का राष्ट्रीयकरण न होगा; अन्यथा विदेशों में भारत की साख चली जाएगी। सोशालिस्टों का कहना है कि मुआवजा चुकाने की बात वे मान लेते हैं, किंतु मुआवजा सरकार अपने पास से न चुकाकर कम्पनियों के रिजर्व तथा पूंजीगत करों से चुका दे। नेहरूजी का कहना है कि कम्पनियों का रिजर्व धन नये विकास में लग रहा है। इस समय जितना धन हम उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के चुकाने में लगाएंगे, उतना नए उद्योगों में विनियोजित कर देश के औद्योगीकरण का विकास कर सकेंगे।

सेलिंग एजेंसी की स्थिति

नयी कम्पनी धारा के अंतर्गत सेलिंग एजेण्ट का क्या स्थान है। यह धारा १ एप्रिल १९५६ से अमल में आयी। इसके पूर्व मेनेजिंग एजेण्ट या उनके सहयोगियों ने सेलिंग एजेंसियों के लिए कोई इकरार किए हों, तो वे एप्रिल तक जारी रहेंगे। ऐसा अब तक समझा जाता था। पर भारत के एटर्नी जरनल श्री एम० सी० सीतलवाड़ का मत है कि जबसे नए कम्पनी कानून की धाराएं अमल में आयीं, तब से सेलिंग एजेंसी के चलतू इकरार नामे स्वतः रद्द हो जाते हैं। उनके मत से पुराने इकरारनामों का अब कोई अस्तित्व नहीं है। यह बात यों प्रकट हुयी कि चीनी उद्योग के एक शेयर होल्डर ने निजी तौर पर श्री सीतलवाड़ का मत प्राप्त किया। शेयर होल्डर के सालीसिटर ने श्री सीतलवाड का यह मत कम्पनी कानून एडमिनिस्ट्रेशन के पास भेज दिया। अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन का खयाल था कि यह व्यवस्था १९५८ तक जारी रहेगी, पर अब उसे भी चिंतित हो जाना पड़ा। किंतु यह प्रकट है कि केन्द्र के वित्तीय अधिकारी एटर्नी जरनल के मत पर ही चलेंगे। किंतु देश के विख्यात सालीसिटरों का मत है कि नये कम्पनी कानून के दायरे में सेलिंग एजेंसी के संबंध में सीतलवाड अर्थ ठीक नहीं है। सीतलवाड के मत पर सरकार चलेगी, तो सैकड़ों कम्पनियां संकट में पड़ जाएंगी, क्योंकि वे सोलिंग एजेण्टों का कमीशन चुका चुकीं और डिवीडेण्ड भी दे दिए गए। कम्पनी कानून एडमिनिस्ट्रेशन क्या आदेश देता है, इसकी प्रतीक्षा है अन्यथा अदालत में टेस्ट केस किया जाएगा।

सोने चांदी का वायदा व्यापार

गत वर्ष फरवरी मास में भारत सरकार के फारवर्ड मार्केट कमीशन ने यह प्रकट किया था कि वह सोने चांदी वायदा व्यापार की उपयोगिता के संबंध में जांच कर रहा है। इस प्रकार के व्यापार की उपयोगिता के संबंध में देश के कई क्षेत्रों में शंका प्रकट की गयी। इसका कारण यह है कि देश में सोने चांदी की पैदावार बहुत सीमित है और निजी आयात पर सरकारी प्रतिबंध लगा है। इधर केवल तिब्बत से चीनी डालर के रूप में चांदी के सिक्कों का आयात निजी साधन में बढ़ा है। ये सिक्के चांदी की आमद का स्थान लेते हैं। पर कमीशन ने देश की बुलियन संस्थाओं से मत लिये और उनसे काम काज की स्वीकृति लेने के संबंध में प्रार्थना पत्र भी प्राप्त किए। अब देश भर के सोने चांदी के व्यापारी निर्णय की प्रति कमीशन की प्रतीक्षा में हैं। कमीशन ने अपनी जांच रिपोर्ट तैयार कर केन्द्रीय सरकार के पास भेज दी है। कमीशन की जांच व्यापार के हित में प्रकट नहीं होती है।

विदेशी मुद्रा के व्यय में भारी कमी

जनवरी-जून १९५७ की अवधि के लिए विदेशी मुद्रा के व्यय में भारत सरकार ने भारी कमी करने का विचार किया है। सरकार की योजना के अनुसार इस काल में

[शेष पृष्ठ १२० पर]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विकासशील देशों की आर्थिक समस्याएं

(डा० आर्थर राबर्ट बर्न्स)

संसार के देश, विशेषतः अनुन्नत देश अपनी अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ व प्रगतिशील करने का प्रयत्न कर रहे हैं। बढ़ती हुई जन-संख्या का क्या हल हो, आयोजन की पद्धति क्या अपनाई जाय, सरकार का अर्थ-व्यवस्था में क्या भाग हो, आयोजन से बढ़ी हुई आय का उपयोग जीवन-स्तर को ऊंचा करने के लिए किया जाय अथवा भारी उद्योगों के विकास में, पूंजी का निर्माण कैसे हो, विदेशों की सहायता किस रूप में प्राप्त की जाय, आदि सामने आने वाले गम्भीर व विषम प्रश्नों की विद्वान् लेखक ने इस लेख में चर्चा की है।

ऐसा प्रतीत होता है जैसे द्वितीय विश्व-युद्ध धनी एवं निर्धन देशों में व्यापक आर्थिक आयोजन के युग के सूत्रपात का सूचक है। इन योजनाओं का उद्देश्य यह ध्यान रखना है कि निर्धारित लक्ष्यों को अत्यन्त मितव्ययता से पूरा किया जाए। अर्थशास्त्री इस विषय में तो पड़ताल कर सकते हैं कि विविध मार्गों का अवलम्बन करने के क्या परिणाम होंगे, किन्तु विविध सम्भावित नीतियों के खर्च को आँकने के बाद उनमें से किसी को चुनने का काम सरकारों का ही है। इस विषय में विशेष रूप से तीन जटिल समस्याएं सामने आएंगी : जनसंख्या : भावी उत्पादन को बढ़ाने के लिए पूंजी किस अनुपात से लगाई जाए, इस बात की व्यवस्था : और सरकार आर्थिक जीवन में कहां तक हस्तक्षेप करे, इसका निश्चय।

जनसंख्या की समस्या

अनेक गरीब देशों में, इस सदी में आबादी बड़ी तेजी से बढ़ी है। इनमें से अनेक (सब नहीं) की आबादी उनके साधनों के मुकाबले में इतनी अधिक है कि यदि आबादी का बढ़ना न रुका तो आय के स्तर गिर जाएंगे। जितना उत्पादन बढ़ेगा, यदि सबका अधिक लोगों के भरण-पोषण में ही खर्च कर दिया गया तो रहन-सहन के स्तर को ऊंचा उठाने की योजना निष्फल हो जाएगी। तथापि, परिवारों के आकार-प्रकार को कम करने का सवाल बहुत कठिन होगा, क्योंकि तत्सम्बन्धी नियंत्रण के वर्तमान उपायों में सुधार होने की आवश्यकता है और जनसंख्या में तेजी से होने वाली वृद्धि का प्रश्न अनेक देशों के रीति-रिवाजों में गुंथा हुआ है।

इस समस्या को हल करने के लिए पहला कदम यह उठाना होगा कि लोगों को यह निश्चय करा दिया जाए कि रहन-सहन का स्तर कुछ हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि राष्ट्रीय आय में हिस्सा बांटने वालों की संख्या कितनी है।

उत्पादन के लिए पूंजी

यह निश्चय करने का काम भी बड़ा गम्भीर है कि भविष्य में और अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्तमान आय का कितना भाग रखा जाए। इसमें सन्देह नहीं कि पूंजी लगने से मजदूर अधिक उत्पादन करने में समर्थ हो जाता है। गरीब देशों के सामने एक समस्या यह होगी कि वे बड़ी मात्रा में आवश्यक धन को कैसे जुटाएं। धनी देशों ने जब अपनी राष्ट्रीय आय को बढ़ाने का प्रयत्न आरम्भ किया था, तब उन्हें जितनी पूंजी दरकार थी, गरीब देशों को उससे भी अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। एक सदी या उससे भी पहले उत्पादन के जो तरीके थे, उनमें अब की अपेक्षा बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती थी। बिलकुल नये साधनों के बजाय अपेक्षाकृत कुछ पुराने तरीकों को अपना कर भी अर्थ-व्यवस्था को सुधारा जा सकता है, किन्तु इन तरीकों को अपनाने से उत्पादन में वृद्धि की रफ्तार मंद रहेगी। इन देशों के सामने दूसरी समस्या इस बात से पैदा होगी कि उन्हें विकास के प्रारम्भिक चरण में परिवहन-साधनों, बिजली तथा सिंचाई की व्यवस्था को सुधारने के लिए अधिकतर पूंजी दरकार होगी। इन चीजों में धन लगाने से अन्त में तो बड़ा लाभ है, किन्तु शुरू में यह लाभ बहुत धीरे-धीरे ही मिलता है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पूंजी की व्यवस्था

यद्यपि पूंजी तो बहुत अधिक चाहिए, किन्तु गरीब देश अपनी वर्तमान आय का बहुत थोड़ा भाग ही इस काम के लिए बचा सकते हैं। इस काम को पूरा करने का एक ही उपाय है और वह यह कि अन्य देशों से ऋण अथवा अनुदान प्राप्त किये जाएं। यदि विदेशों से प्राप्त धन का बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग किया जाए तो इस ऋण को चुकाने के लिए जितना उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता होगी, शायद उससे भी अधिक उत्पादन बढ़ जाएगा। किंतु किसी भी देश को सबसे पहले यह तय करना होगा कि वह विदेशी सहायता पर निर्भर होगा या धीरे-धीरे विकास करना ही पसन्द करेगा। कुछ देशों ने क्रूर आर्थिक साम्राज्य-वाद के पिछले अनुभवों की पुनरावृत्ति के भय से विदेशी पूंजी के विनियोग पर पाबन्दियां लगा दी हैं। किन्तु, सच बात तो यह है कि विदेशी ऋणदाता और उनकी सरकारें अपने गरीब पड़ोसी देशों के साथ व्यवहार में अब अधिक सभ्य हो गये दीखते हैं और बहुत से गरीब देशों की सरकारें विदेशी ऋणदाताओं के लिए अब अधिक आकर्षक शर्तें पेश कर रही हैं। लेकिन योजनाशील देशों को यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि जो देश आर्थिक प्रगति करना चाहते हैं, उन सबके शीघ्र विकास के लिए विश्व द्वारा पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था करना सम्भव नहीं है।

जिस किसी देश में विदेशी पूंजी लगने से या घरेलू साधनों का उपयोग करने से उत्पादन बढ़ता है, उसे यह निश्चय करना होगा कि वह बढ़ी हुई आय का उपयोग रहन-सहन के वर्तमान स्तर को ऊंचा उठाने के लिए करेगा या उस धन को भविष्य में उत्पादन को और बढ़ाने के लिए व्यय करेगा। यह निश्चय है कि गरीबी से पीड़ित लोग तत्काल राहत चाहेंगे। वे पहिले ही जमीन का लगान कम करने, अधिक वेतन देने तथा समाज सुरक्षा की व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं। इस प्रकार के कुछेक सुधारों से मजदूर की उत्पादन-क्षमता बढ़ जाती है, किन्तु साथ ही इनसे खपत भी बढ़ जाएगी और सम्भावित पूंजी-विनियोग में कमी आ जाएगी। तथापि, इन मांगों को अस्वीकार करने से सम्भव है, लोगों का सरकार और आयोजन में विश्वास कम हो जाए।

सरकारी हस्तक्षेप की सीमा

तीसरी समस्या यह निश्चय करने की होगी कि सरकार आर्थिक मामलों में कहां तक नियंत्रण रखे। यह समस्या सम्भवतः कई दशकों तक गम्भीर बनी रहेगी। किन्तु यदि समूची अर्थ-व्यवस्था की व्यापक योजना बनाई गई और उसे सख्ती से लागू किया गया तो लोकतंत्र की स्थापना और विकास में रुकावट पड़ सकती है। उस अवस्था में उत्पादन और वितरण पर सरकारका नियंत्रण होगा। इसका अर्थ यह होगा कि काम करने की परिस्थितियों, खपत और पूंजी-विनियोग पर भी सरकार का ही नियंत्रण हो जाएगा। तिस पर भी, वर्तमान आर्थिक दशा में सुधार के कार्य को स्थगित करने से इस प्रकार के आयोजन द्वारा ऐसी स्थिति आ सकती है, जिससे पूंजी का संचय बढ़ जाए।

किन्तु, आयोजन के कार्य को अर्थ-व्यवस्था के उन भागों तक सीमित रखना सम्भव हो सकता है, जिनके संबंध में उन्नति के लिए कार्रवाई करना अत्यन्त आवश्यक हो। सरकारें आयात-कर लगा सकती हैं, उद्योगों के लिए आर्थिक सहायता और पूंजी की व्यवस्था कर सकती हैं या सरकारी उद्योगों की स्थापना कर सकती हैं। वे आवश्यक धन जुटाने के लिए करों में वृद्धि कर सकती हैं, कर-प्रणाली में परिवर्तन कर कुछ लोगों पर करों का अधिक भार डाल सकती हैं या विदेशी साधन-स्रोतों अथवा अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से कर्ज ले लकती हैं।

जन सहयोग अपेक्षित

किन्तु इस प्रकार का आयोजन तभी सफल हो सकता है जबकि लोगों को यह प्रेरित किया जा सके कि परिवर्तन द्वारा ही आर्थिक परिस्थितियों को सुधारा जा सकता है और यह परिवर्तन बहुधा कष्टप्रद होता है। देश के धनिक वर्ग को अधिक कर देने होंगे और उत्पादन-कार्य में अधिक सक्रिय योग देना होगा। आबादी के बहुत बड़े भाग को अपने को नई परिस्थितियों के अनुरूप ढालना होगा। उन्हें अपनी जमीन छोड़नी होगी, ताकि समग्र रूप में भूमि का अधिक अच्छी तरह उपयोग किया जा सके, उन्हें नये स्थान और नई परिस्थितियों के अन्तर्गत नई नौकरियों पर जाने के लिए अपने वर्तमान स्थान और जीवन-पद्धति को त्यागना होगा।

(शेष पृष्ठ ११८ पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

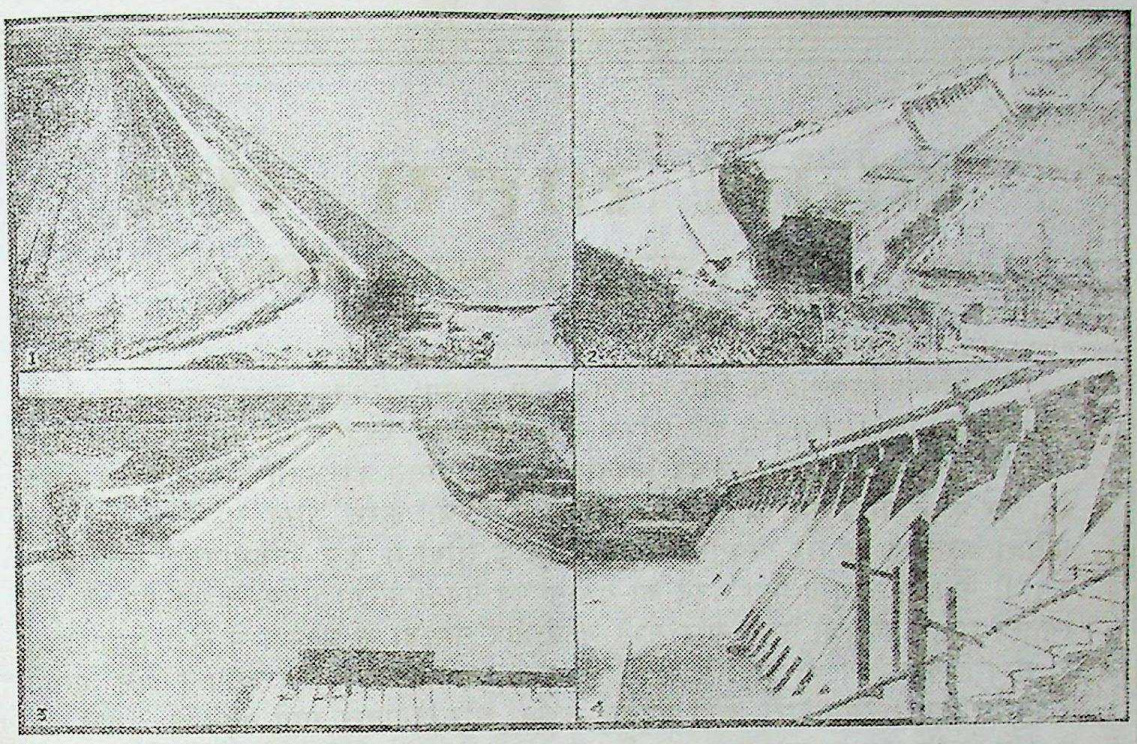

उड़ीसा के नये विशाल मन्दिर हीराकुड बांध के चार दृश्य—
(१) मिट्टी का बांध, (२) बिजली घर, (३) तेल-रेस नहर और (४) बांध।

उड़ीसा का समृद्धि-स्वप्न साकार हो गया : हीराकुड बांध

हीराकुड योजना के पूर्ण हो जाने पर सचमुच राष्ट्र को हीरों के कुण्ड की प्राप्ति हो जाएगी। इस योजना का प्रथम चरण अभी-अभी समाप्त हुआ है। १३ जनवरी ५७ को प्रधानमन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने बटन दबा कर हीराकुण्ड जलाशय से बरगढ़ नहर में पानी का मुक्त प्रवाह प्रारम्भ कर दिया।

उड़ीसा में महानदी के मुख्य प्रवाह पर बना हीराकुड संसार का सबसे लम्बा बांध है। इसकी पूरी लम्बाई १६ मील है। वैसे हीराकुड बांध की विशालता का अनुमान इससे भी लगाया जा सकता है कि इसमें जलाशय २८८ वर्गमील में फैला है, जिसमें ६६ लाख एकड़ फुट पानी का संचय हो सकेगा।

हीराकुड बाँध की मुख्य विशेषता है, उसकी नहर प्रणाली। इससे सम्बलपुर और बोलगिरि जिलों की ६,७१,००० एकड़ जमीन की सिंचाई होगी। बरगढ़, सेसन और सम्बलपुर नाम की ३ नहरें इस जलाशय से सम्बन्धित हैं। छोटी-छोटी नहरें तो अनेक हैं।

सम्पूर्ण नहर प्रणाली के बन जाने पर ५ लाख ६० हजार टन अधिक अन्न पैदा किया जा सकेगा तथा सिंचाई के लिए दोनों फसलों को पर्याप्त पानी मिलता रहेगा।

विगत २० वर्षों में दो बार यानि १९३५ और १९३६ में उड़ीसा को भयंकर बाढ़ का त्रास सहना पड़ा। महानदी के मध्यप्रदेश और उड़ीसा के विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र में बहने के कारण उसमें अत्यधिक पानी इकट्ठा रहता है। महानदी जब इस पानी को अपने विशाल तटों में सीमित नहीं रख सकती, तो भीषण समस्या विकराल रूप धारण कर सामने आ जाती है। यह समस्या वस्तुतः एक अभिशाप के रूप में सामने आती है। इसी अभिशाप को वरदान में परिणत

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

स्वतंत्र साहस संघ

स्वतन्त्र साहस की व्यवहार नीति

स्वतन्त्र व्यवसाय के लिए व्यवहार के ये नियम "स्वतन्त्र साहस संघ" ने तैयार किये हैं और यह नियमावली अब भारत के उद्योगपतियों, व्यवसायियों और विभिन्न पेशों व धंधों के लोगों के समक्ष इस दृढ़ विश्वास के साथ प्रस्तुत की जाती है कि वे इसे सहर्ष स्वीकार करने योग्य तथा अपने दैनिक जीवन में परिणत करने योग्य पायेंगे । यह संघ प्रतिज्ञा करता है कि वह "स्वतन्त्र साहस" क्षेत्र के लोगों में इस नियमावली के निहित कर्तव्यों के प्रति जागृति पैदा करने का यथासम्भव प्रयत्न करेगा । हमारा यह मत है कि स्वतन्त्र साहस को, जो समय और सभी जनतन्त्रीय समाजों के अनुभव में खरा सिद्ध हुआ है, सामाजिक उद्देश्य की दृष्टि से सचाई के उच्च स्तरों पर जोर देकर अपना यश बनाये रखना चाहिए । ईमानदारी, कड़ी मेहनत, नम्रता और लगातार आगे बढ़ने के प्रयत्न ही वे नींव हैं, जिनपर स्वतन्त्र साहस के विशाल भवन का आधार निर्धारित है ।

उत्पादकों और वितरकों का उनकी वस्तुओं का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के प्रति यह कर्तव्य है कि उनकी वस्तुएँ सदा उच्च स्तर की रहें और सुगमता से उचित मूल्य पर उपलब्ध हों । उत्पादकों और वितरकों को ठीक माप कायम रखना चाहिए और मिलावट से बचना चाहिए । ग्राहक नम्रता, तत्परता और अच्छी सेवा पाने के अधिकारी हैं और इस बात की कोशिश की जानी चाहिए कि उन्हें ये सब सुलभ हों ।

मालिकों का श्रमिकों के प्रति यह कर्तव्य है कि वे यह स्वीकार करें कि "श्रमिक कल्याण" का अर्थ दान करना नहीं है बल्कि यह एक सामाजिक उत्तरदायित्व है । उत्पादन कार्य में संलग्न पुरुष और स्त्रियों को यह काय आत्म सम्मान, प्रतिष्ठा, गौरव तथा सुरक्षा की भावना के साथ करना चाहिए । किये हुए कार्य के लिए उपयुक्त पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए । कार्य संबंधी परिस्थितियां भी जितनी सम्भव हों, उतनी आनन्ददायक होनी चाहिए । श्रमिक को यांत्रिक योग्यता प्राप्त करने व अपना आर्थिक भविष्य और सामाजिक स्थान उत्तम बनाने के लिए अवसर प्रदान किये जाने चाहिए । उचित शिकायतें दूर करने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि कर्मचारी को यह संतोष हो कि उसके साथ न्याय किया गया है । मालिकों को स्थायी व जनतंत्रीय कार्मिक संघ (ट्रेड युनियनों) के अस्तित्व का स्वागत करना चाहिए । उन्हें यह मानना चाहिए कि दूसरे क्षेत्रों के समान कर्मचारी मालिक के सम्बन्धों के क्षेत्र में भी विवेकपूर्ण व जनतंत्रीय उपाय खोजने के लिए नियंत्रण व संतुलन आवश्यक है । मालिकों को मानना चाहिए कि श्रम का कार्य रचनात्मक सहयोग देना है । उन्हें कर्मचारियों

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

की सलाह लेने के अधिकाधिक अवसर प्रदान करने की आवश्यकता को स्वीकार करना चाहिए और यह भी मानना चाहिए कि उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, जिससे सबका लाभ होगा कर्मचारियों का मालिकों के साथ सहयोग व सम्पर्क बढ़ते ही जाना चाहिए।

जो लोग व्यवसाय में अपनी पूंजी लगाते हैं, उनके प्रति **प्रबन्धक** का यह कर्तव्य है कि उन्हें अपनी लगाई हुई रकम पर खतरे के अनुपात में उचित लाभ मिले । साथ ही यन्त्र व मशीनों के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए कोष बनाया जाना चाहिए और इस कोष के लिए प्रबंधक पूंजी लगानेवाले के प्रति पूर्ण जिम्मेदार हैं। अन्वेषण (रीसर्च) के लिए भी धन-राशि की व्यवस्था की जानी चाहिए। अंशधारी (शेयर होल्डर्स) को उचित प्रतिफल की प्राप्ति या स्पर्धा की परिस्थितियों में व उचित वेतन देने के बाद उत्पादक को मुनाफा मिलने को पूंजी के साथखतरा उठाने के लिए न्यायपूर्ण इनाम और विकास व उन्नति का कार्य मानना चाहिए जिसकी जन समुदाय को अत्यधिक आवश्यकता है। कंपनी के प्रबंध की प्रणाली में कुछ अनु-चित तरीके आ गये हैं। इनकी घोर निंदा की जानी चाहिए और इन्हें तत्काल हटा देना चाहिए। माल को छुपा कर बहुत अधिक मात्रा में जमा करना, काला बाजार करना और अनुचित मुनाफा कमाना, ये सभी असामाजिक कार्य हैं व हानिकारक हैं। जनतंत्रीय राज्य में ईमानदार और कार्यकुशल शासन प्रबंध के द्वारा सत्यतापूर्ण व्यवसाय प्रणाली बढ़ायी जा सकती है और उसका काफी विकास किया जा सकता है और उसे सभी प्रकार के प्रोत्साहन प्राप्त हो सकते हैं।

जो लोग भिन्न भिन्न व्यवसाय करते हैं जैसे वकील, शिक्षक, डाक्टर, अंकेक्षक (आडिटर) अथवा लेखक, उनका जिन्हें वे अपनी सेवाएँ प्रदान करते हैं, उनके प्रति कर्तव्य है कि वे व्यवसाय के उच्चतम स्तर और परम्पराओं को कायम रखें। उन्हें अपना कार्य सचाई और निष्ठा की भावना से ही प्रेरित होकर करना चाहिए और व्यक्तिगत लाभ के विचार को उच्च सेवा के उद्देश्य से गौण मानना चाहिए।

हम सबको चाहिए कि हम अच्छे नागरिकों के समान जनसमुदाय के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करें। हमें अपने ऊपर लगाये गयें कर को ईमानदारी से वहन करना चाहिए। साथ ही साथ कर से बचने की कोशिश की हम स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं। हमें सामाजिक, सांस्कृतिक और नागरिक सुधारों को आगे बढ़ाने के कार्यों में सक्रिय भाग लेना चाहिए। धन अथवा अधिकार का अर्थ यह नहीं है कि उसका व्यर्थ घमंड अथवा प्रदर्शन किया जाये बल्कि उसे तो जन समुदाय की सेवा करने का ही एक अवसर मानना चाहिए ।

FORUM OF FREE ENTERPRISE

स्व तं त्र सा ह स सं घ

सोहराब हाउस, २३५, डा० दादाभाई नवरोजी रोड, बम्बई--१।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हीराकुड योजना : एक दृष्टि में

१. हीराकुड योजना बाढ़-नियंत्रण, सिंचाई और बिजली-उत्पादन की बहु-उद्देशीय योजना है ।

२. हीराकुड बांध ईंट, कंकरीट और मिट्टी का बना संसार का सबसे लम्बा बांध है। इसकी पूरी लम्बाई १५,७४८ फुट है, जिसमें से ३,७६८ फुट ईंट तथा कंकरीट और बाकी मिट्टी से बना है। इसकी अधिकतम ऊंचाई २०० फुट है। बांध के पीछे दोनों ओर १३ मील लम्बे मिट्टी के पुश्ते हैं।

३. जब योजना का काम पूरे जोर पर था, उस समय ३०,००० मजदूर लगाये गये थे, जो देश के प्रायः सभी भागों के रहने वाले थे।

४. हीराकुड जलाशय का क्षेत्रफल २८८ वर्ग मील है, जिस में से ४७ लाख २० हजार एकड़ फुट में निरन्तर पानी रहता है। इसके तट का दायरा ४०० मील है। इस जलाशय में तुङ्गभद्रा बांध से दूना और मैत्तूर बाँध से तिगुना पानी जमा रह सकता है।

५. १९५८-५९ तक हीराकुड की नहरों से ४ लाख ५४ हजार एकड़ भूमि में सिंचाई होने लगेगी। इस समय तक १ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होने लगी है।

६. हीराकुड योजना का पहला चरण पूरा हो जाने पर १,२३,००० किलोवाट बिजली तैयार करने की सामर्थ्य के कारखाने बन चुकेंगे।

७. उड़ीसा राज्य में लोहा, कोयला, मैंगनीज, बौक्साइट, चूना और क्रोमाइट बहुतायत से पाया जाता है। इन खनिजों का लाभ उठाने के लिए हीराकुड योजना पहला महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना से उड़ीसा के सीमेंट, अलुमीनियम, इस्पात, कागज, कपड़ा और लोहा-मैंगनीज आदि उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।

करने के लिए महानदी पर तीन स्थानों पर बांध की योजना की गई है। इससे बाढ़ और सूखे की समस्या का सामना तो किया ही जा सकेगा, इसके अलावा उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का भी नव-निर्माण के कार्य में उपयोग हो सकेगा।

उद्योग विकास

हीराकुड से केवल सिंचाई का सवाल हल नहीं होगा, इसके साथ साथ जो बिजली घर बन रहे हैं, उनसे १ लाख २५ हजार किलोवाट बिजली मिलेगी, जिससे उड़ीसा में कई नये उद्योग चलने लगेंगे। राज्य में एल्यूमीनियम, इस्पात, फेरोमेगनीज सीमेंट, कागज, कपड़ा, चीनी और भी अनेक कारखानों की स्थापना हो जाएंगी। इस प्रकार उड़ीसा के जीवन में कायापलट हो जाएगी, वहां समृद्धि चरणों को चूमने लगेगी।

पिछले आठ वर्षों से इस बांध पर निर्माण कार्य चल रहा है। शुरू-शुरू में यद्यपि इसके विषय में अनेक शंकाएँ उठाई गई थीं। किन्तु निर्माण की गति में किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी गई, दृढ़ता से काम चलता रहा। अब तो वे शंकाएं निर्मूल सिद्ध हो चुकी हैं। हीराकुड बांध के निर्माण में जो अनुभव हुए हैं, उनका लाभ अन्य स्थानों पर उठाया गया है। वस्तुतः हीराकुड एक सफल प्रयोगशाला रहा है।

पिछले वर्ष देश के पश्चिमी छोर नांगल पर इसी प्रकार की योजना का उद्घाटन हुआ था। अब देश के पूर्वी कोने पर भी इस योजना के उद्घाटन होने पर समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मंदिरों की प्रसिद्ध भूमि उड़ीसा में, हीराकुड़ बांध योजना के उद्घाटन पर तो, पं० नेहरू ने इस योजना को एक नया मंदिर बताया, तथा समस्त देश में इसकी 'पूजा' का आह्वान किया। बरुण देव की पूजा हमारे लिए नई नहीं है। अवश्य ही अब हमें बरुणदेव के साक्षात मंदिर की प्राप्ति हो गई है। इस अवसर पर उन लाखों श्रमिकों और कुशल इंजीनियरों का स्मरण करना आवश्यक हो जाता है, जिनके अथक परिश्रम से इस अद्भुत मंदिर की स्थापना सम्भव हो सकी। इस मंदिर से घंटे के रूप में निकलने वाली समृद्धि की ध्वनि को समस्त देश सुन सकेगा। उड़ीसा की गरीब जनता भी अपने उन असंख्य कष्टों को भूल जाएगी, जो कि योजना के निर्माण में या उससे पहले उसे सहने पड़े।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

समृद्धि के पथ पर कश्मीर

श्री बख्शीगुलाम मोहम्मद
(मुख्य मंत्री जम्मू, कश्मीर राज्य)

पाकिस्तान व उसके साथी राष्ट्रों द्वारा संकट पैदा करने के प्रयत्नों के बावजूद भारत के सहयोग से काश्मीर राज्य निरंतर प्रगति कर रहा है। इसका कुछ परिचय इस लेख में पाठक पढ़ेंगे।

छब्बीस जनवरी, १९५७ को जम्मू और कश्मीर के इतिहास का एक और सफल वर्ष पूरा हुआ है। राज्य के लोगों के लिये इस दिन का विशेष महत्व है, क्योंकि राज्य के चुने हुए प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से जो नया संविधान स्वीकार किया है, वह इस दिन पूर्णतः लागू हो गया।

इस वर्ष की दूसरी सबसे मुख्य घटना यह है कि जवाहर सुरंग आमदरफ्त के लिये खोल दी गयी। इस पर करोड़ों रुपये व्यय हुआ है। इसके द्वारा, कश्मीर घाटी को बाकी देश से अलग करने वाली प्राकृतिक रुकावट दूर हो गई है तथा कश्मीर और शेष भारत स्थायी रूप से परस्पर मिल गये हैं। व्यापार और यातायात की असाधारण सुविधा हो जाने से अब यह राज्य प्रगति और समृद्धि के मार्ग पर तेजी से अग्रसर हो रहा है।

इस वर्ष शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, ग्राम-सुधार आदि राष्ट्र-निर्माण के प्रायः सभी विभागों के कार्यों में काफी विस्तार हुआ है और लगभग ५०० नयी शिक्षाशालाएं खोली गयी हैं। इसका महत्व यह जानकर और भी स्पष्ट हो जायगा कि पिछली कई सदियों से राज्य में कुल मिला कर १,००० से अधिक शिक्षाशालाएं नहीं थीं। पंचायतों को फिर से सक्रिय बनाया गया है। राज्य में बिजली की सप्लाई बढ़ाने के लिये बहुत सी योजनाएं चलाई गई हैं। कम वेतन वाले कर्मचारियों, अध्यापकों के वेतन बढ़ा दिये गये हैं। क्लर्कों का न्यूनतम वेतन ३०) से ५०) तथा अध्यापकोंका २०) रु० से ५०) रु० कर दिया गया है। ३००) रु० मासिक वेतन वाले कर्मचारियों को १ अप्रैल ५६ से महंगाई भत्ता दिया जाने लगा है।

परिवहन

इस वर्ष परिवहन-संगठन को और भी मजबूत बनाया गया है। इसके कारण, न केवल जम्मू काश्मीर के भीतरी भागों में व्यापार बढ़ाना संभव हो सका है, बल्कि राज्य और बाकी भारत के बीच भी व्यापारिक माल की रफ्तगी बढ़ी है। रेलवे स्टेशन से जम्मू और कश्मीर से खाद्य-वस्तुएं तथा अन्य आवश्यक सामान तेजी से पहुंचने लगा है। इस संगठन के पास, कुल मिलाकर सब तरह की करीब ५०० मोटर-गाड़ियाँ हैं। १९४७ में, राज्य में इस तरह के किसी संगठन का नाम-निशान भी नहीं था।

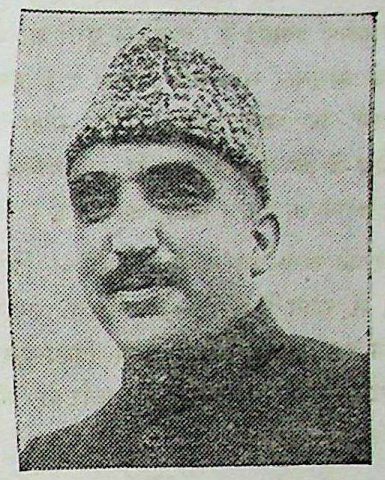

बख्शी गुलाम मोहम्मद

कृषि—खेती के लायक विशाल भू-क्षेत्र में अनाज उपजाया गया। जमीन को खेती के लायक बनाने के लिये सरकार ने उठाकर खेतों को पानी पहुंचाने की योजना चलायी। सिंचाई की जितनी सुविधाएं बढ़ी हैं, उनका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि सिर्फ १९५४-५५ में ही नहरें बनाने पर १४ लाख ८१ हजार रु० खर्च किया गया, जबकि १९४३-४४ में सिंचाई विभाग का पूरा

जवाहर सुरंग का निर्माण—नया संविधान लागू—सीमा शुल्क की समाप्ति—परिवहन का व्यापक संगठन—सिंचाई बजट में ४०० प्र. श. वृद्धि—किसानों से बलात् वसूली बंद।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बजट ३,२१,०५८ रु० था। इस प्रकार, सिंचाई के बजट में लगभग ४०० प्रतिशत वृद्धि हुई है।

किसानों को उपज बढ़ाने के लिये उर्वरक दिये जा रहे हैं। कृषि विभाग ने ग्राम वासियों के कल्याण के लिये बहुत सी नयी योजनाएं बनायी हैं। फलों के वृक्षों की बीमारियों को रोकने की योजनाएं भी इनमें शामिल हैं। इनके द्वारा बढ़िया किस्म का धान, गेहूँ और मक्का उपजाने, फलों की पौध के वियाड बनाने और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

कश्मीर की अर्थ-व्यवस्था में पर्यटकों का विशेष महत्व है। १९५६ में, राज्य में ६२,००० से भी ज्यादा पर्यटक आये, जबकि १९४३-४४ में, जो दूसरे विश्व-युद्ध के दिनों का इस दृष्टि से सबसे अच्छा वर्ष था, पर्यटकों की संख्या २७,२०७ से अधिक नहीं थी।

पाकिस्तान के अधिकृत इलाकों के लगभग एक लाख विस्थापितों को फिर से बसाया गया है। उनमें जो किसान थे, उन्हें खेती के लिये जमीनें दी गयी है। जम्मू, ऊधमपुर राजौरी और नौशेरा में शहरी विस्थापितों के लिये बस्तियां बनायी गयी हैं। वहां प्रारम्भिक तथा मिडिल स्कूल भी खोले गये हैं।

किसानों के लिए—राज्य के विभिन्न वर्गों की सामान्य सुविधा के लिये भी कई तरह की कार्रवाई की गयी है। किसानों से अनाज की जबरदस्ती वसूली की प्रणाली समाप्त कर दी गयी है। किसान अब स्वतन्त्रतापूर्वक अपनी उपज बेच सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वे सरकार को ही दें। सरकार ने किसानों से धान खरीदने का मूल्य ९) रु० से बढ़ाकर १० रु० खिरवाड (८३ सेर) कर दिया है। दूसरी तरफ, श्रीनगर शहर में बिक्री का भाव १० रु० ८ आने से घटाकर ८ रु० ८ वा० खिरवाड कर दिया गया है। जम्मू में चावल की बिक्री का भाव २५ रु० से घटाकर ८ रु० मन और आटे का भाव २८ रु० १० आ० से २० रु० मन कर दिया गया है। जम्मू में गेहूं (आटा) और चावल का बिक्री-भाव १९ रु० से घटाकर १२ रु० ८ आने और १० मन कर दिया गया गया है। श्रीनगर में, राशन की दर ४ ट्राक से बढ़ाकर ५ ट्राक प्रति मास कर दी गयी है (एक ट्राक करीब ६ सेर का होता है)।

१९४८-४९ से पहले बनी नहरों से सिंचाई का आबियाना लेना बंद कर दिया गया है। सहकार विभाग द्वारा दिया गया १७,००,००० रु० का ऋण माफ कर दिया गया है। गांववालों का कर्ज २ करोड़ रु० से घटकर सिर्फ ८६ लाख रु० रह गया है। चराई का कर भी कम कर दिया गया है।

सीमा-शुल्क समाप्त कर दिया गया है। इससे राज्य के व्यापारियों और उद्योगों को बहुत बढ़ावा मिला है।

लद्दाख में विकास-कार्य

लद्दाख के उपेक्षित क्षेत्रों के विकास पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। एक लद्दाख विषयक मंत्रालय खोला गया है और श्री कुशक बकुला उसके उप-मंत्री है। लद्दाख में कई विकास-योजनाएं शुरू की गयी हैं। वहां के कुछ व्यक्ति उच्च कृषि-शिक्षा के लिये भारत में भेजे गये हैं। किसानों को अच्छे बीज और खेती के आधुनिक औजार दिये गये हैं। पशु-पालन के विकास सम्बन्धी एक और योजना के अन्तर्गत लेह में एक पशु-चिकित्सालय और कडगिल तथा द्रासमें एक-एक दवाखाना खोला गया है। लद्दाख के छोटे उद्योगों और दस्तकारियों के विकास का भी प्रयत्न किया जा रहा है। श्रीनगर और लेह के बीच नागरिक-विमानों का आना-जाना शुरू हो गया है। लेह-कडगिल सड़क तेजी से बन रही है।

हमें विश्वास है कि
आप सम्पदा को पसन्द करते हैं
परन्तु
क्या आपने अपने कर्त्तव्य का पालन भी किया है?
सम्पदा के दो ग्राहक बनाकर
सिद्ध कर दीजिए कि राष्ट्र भाषा हिन्दी में गम्भीर साहित्य के पाठकों की कमी नहीं है!
मैनेजर सम्पदा
अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिल्ली-६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सड़कों का महत्त्व

ओमप्रकाश तोषनीवाल, एम. कामं

यातायात की समस्या किसी भी आधुनिक उद्योग-शील राष्ट्र के लिए जीवन मरण की समस्या है। अन्य शब्दों में यातायात राष्ट्र के जीवन की रेखाएं हैं। यदि एक मिनट के लिए यातायात के साधन पूर्ण रूप से रोक दिए जांय तो मनुष्य का जीवन कठिन हो जाय। मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता अनाज उदर-पूर्ति के लिए लाखों टन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तथा देश के खाद्य संकट को कम करने के लिए विदेशों से भी अनाज मंगाना पड़ता है। ये सब यातायात के साधनों द्वारा ही संभव है। यदि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से इन साधनों द्वारा नहीं जुड़ा होता तो शायद हम अपने अन्न-संकट का सामना न कर पाते और इस प्रकार लाखों लोगों को भूख की मौत मरना पड़ता। इसलिए यातायात के साधनों की व्यवस्था ही इन राज्यों के एकीकरण की जननी कही जा सकती है। इन साधनों के फलस्वरूप ही आज हम सैंकड़ों मील की दूरी कुछ ही घण्टों में तय कर लेते हैं। यातायात की सुविधाओं के कारण ही आज नागपुर के संतरे और बम्बई के केले उत्तरप्रदेश और राजस्थान के गांवों में भी खाने को उपलब्ध हो जाते हैं।

एक समय था, जब १०० मील की दूरी तय करने के लिए कई रोज चलना पड़ता था। धर्म और संस्कृति के एक सूत्र में बंधे हुए भी देश के एक भाग के निवासी दूसरे भाग वालों को परदेशी समझते थे। अशोक का साम्राज्य सारे देश में फैला, मुगलों की सेनाओं ने देश का कोना कोना छाना, लेकिन यातायात के साधन उनके समय में भी इतने प्रगतिशील नहीं थे। देश के एक प्रदेश में राज्य उलट पुलट हो जाते, क्रान्तियां मच जातीं और दूसरे भागों में इसका कोई आभास भी न होता। एक प्रान्त में अन्न की बहुतायत रहती लेकिन फिर भी अकालग्रस्त लोगों को सहायता न पहुंच पाती थी। उन दिनों यातायात के साधन ही इतने कम थे। लेकिन आवश्यकता ने मनुष्य को प्राकृतिक शक्तियों के विरुद्ध लड़ने के लिए विवश किया। आज देश में ये साधन बहुत उन्नति कर गए हैं।

स्वतन्त्र भारत में जहां राष्ट्रीय सरकारों को अनेक बड़ी और छोटी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, वहां देश की यातायात समस्या भी एक जटिल समस्या रही है। यातायात के साधन राष्ट्र के आर्थिक विकास में उसी प्रकार कार्य करते हैं, जैसे शरीर में रक्त नाड़ियां। जिस प्रकार शरीर रचना में रक्तवाहिनी नाड़ियों के बिना काम नहीं चल सकता, उसी प्रकार किसी भी राष्ट्र में यातायात के साधनों के अभाव में राजनैतिक स्वतन्त्रता तथा आर्थिक उन्नति करना अत्यन्त कठिन है। इसलिए यातायात के साधनों की ओर से विमुख होकर न तो कोई राष्ट्र अपनी सुरक्षा को बनाए रख सकता है और न व्यापार-वृद्धि कर आर्थिक स्वतन्त्रता को बनाए रख सकता है।

देश के वर्तमान यातायात के साधन मुख्य रूप से चार भागों में विभाजित किए जा सकते हैं:—

१. राज पथ अथवा सड़कें
२. रेलमार्ग
३. वायुमार्ग
४. जलमार्ग

महत्त्व के क्रम में सबसे प्रथम देश की रेलें और उसके पश्चात सड़कें हैं। लेकिन जहां तक प्राचीनता का सम्बन्ध है भारत के जलमार्ग तथा राजपथ यातायात व्यवस्था के इतिहास की दृष्टि से अत्यन्त पुराने हैं। इसका एक कारण था। पहले मुख्यतः व्यापार तथा प्रशासन के दृष्टिकोण से परिवहन व्यवस्था का विस्तार किया जाता था।

राजपथ

भारत जैसे विशाल देश में सड़कों की महत्ता को कोई कम नहीं कर सकता। देश में लगभग ५ लाख से अधिक गांव हैं। इन गांवों को एक दूसरे से सम्पर्क बनाए रखने के लिए यातायात के तमाम साधनों में सड़कें ही अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। इतना ही नहीं देश के आर्थिक विकास को देखते हुए भी सड़कें अधिक उपयुक्त जान पड़ती हैं। सड़कों की अन्य भी विशेषताएं हैं जो सड़कों के महत्त्व को बल प्रदान करती हैं। सड़कें यातायात के अनेक साधनों द्वारा उपयोग में ली जाती है। जैसे, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, घोड़ा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गाड़ी, लारी, बस, कार, ट्रक, साइकिल, मोटर साइकिल, रिक्शा, मोटर रिक्शा आदि । जबकि गमनागमन के अन्य मार्गों का उपयोग सीमित यातायात के द्वारा ही होता है। जैसे नदियां, समुद्र आदि केवल बड़े और छोटे जलपोतों द्वारा ही प्रयोग की जाती हैं। रेलों की पटरियों पर केवल माल और सवारी गाड़ियां ही चल सकती हैं। सड़कें गरीब और अमीर सभी प्रकार के लोगों द्वारा प्रयोग की जाती हैं। ऐसी बात अन्य मार्गों के साथ नहीं है। सड़क यातायात सुलभ और सस्ता भी पड़ता है। साथ ही अन्य मार्गों की तुलना में यह अधिक सुरक्षापूर्ण भी है।

इसलिए गांवों के विकास तथा देहातों की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए अच्छी और सुविधाजनक सड़कों के निर्माण की अत्यन्त आवश्यकता है। १९४३ को नागपुर योजना में यह व्यवस्था रखी गई थी कि २० वर्षों में विकसित कृषि क्षेत्र का कोई भी गांव ऐसा नहीं रह जाना चाहिए जो मुख्य सड़क से ५ मील की अधिक दूरी पर हो । वैसे तो प्राचीन काल में ही देश में हिन्दू नरेशों और मुसलमान शहंशाहों ने अच्छे से अच्छे राजपथों का निर्माण कराया था। हर्षवर्धन के समय में बौद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने सड़कों की प्रशंसा की है। पेशावर से कलकत्ता जाने वाली सुप्रसिद्ध ग्राण्ड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी की बनवाई हुई है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यातायात की महत्ता को प्राचीन काल के सम्राटों ने भी समझा था।

वर्तमान समय में देश में सड़कों का जाल बिछा हुआ है, लेकिन यह जाल केवल बड़े बड़े शहर और व्यापारिक केन्द्रों को मिलाता है। आवश्यकता इस बात की है कि एक एक गांव में सड़कों का निर्माण होना चाहिए। बम्बई जैसे उन्नतिशील राज्य में भी करीब आधे से ज्यादा भूमि पर यातायात के कोई साधन नहीं हैं। प्रथम योजना के प्रारंभ में भारत में कुल मिलाकर २ लाख ४४ हजार मील लम्बी सड़कें थीं, जिनमें से ९६,००० मील लम्बी पक्की सड़कें तथा १,४७,००० मील लम्बी कच्ची सड़कें थीं। दूसरे देशों की तुलना में भारत में कितनी कम सड़कें हैं यह निम्न तालिका से ज्ञात हो जाता है:—

	सड़कें एक वर्ग मीलमें (मील)	सड़कें एक लाख मनुष्यों के लिए (मील)	विशेषता
भारत	०.२०	४१	वर्ष में केवल ३५ प्रतिशत सड़कों पर मोटर चल सकती हैं
अमरीका	१.०१	२४ ९९	तमाम सड़कों पर मोटर चल सकतीं हैं।
ग्रेट ब्रिटेन	२.०२	३ ९२	,,
जापान	३.००	६ ९४	,,
फ्रांस	१.९४	९ ३४	,,

आशा है, प्रथम योजना को अवधि के अन्त तक लगभग १०,००० मील लम्बी पक्की नई सड़कें और २०,००० मील घटिया किस्म की सड़कें और निर्मित हो जाएंगी। केन्द्रीय सरकार के राष्ट्रीय राजपथ कार्यक्रम के अन्तर्गत ४० पुलों के अतिरिक्त ६४० मील लम्बी ऐसी सड़कें बनाई गई हैं, जो विभिन्न स्थानों को मिलाती हैं। इसके अतिरिक्त २,५०० मील लम्बी वर्तमान सड़कों का सुधार किया गया है। प्रथम योजना के अन्त तक नागपुर योजना का एक तिहाई लक्ष्य पूरा हो चुकेगा।

द्वितीय योजना के लक्ष्य

इस योजना में सड़क कार्यक्रम के लिए कहीं अधिक धन की व्यवस्था की गई है। प्रथम योजना में सड़क और सड़क यातायात योजनाओं के लिए यह धन राशि १४६ करोड़ रुपए थी, वहां द्वितीय योजना में यह राशि २६५ करोड़ रुपए कर दी गई है। पहली योजना में राष्ट्रीय राजपथ कार्यक्रम के अधीन जो कार्यक्रम शुरू किया जा चुका है, उसे पूरा किया जायगा और विभिन्न स्थानों को मिलाने वाली ६०० मील लम्बी सड़कों और ६० बड़े पुलों का काम हाथ में लिया जायगा। इसके अतिरिक्त १,७०० मील लम्बी वर्तमान सड़कों का सुधार किया जायगा और गाड़ी चलने लायक ३,७५० मील लम्बी सड़कों को चौड़ा किया जायगा। राष्ट्रीय राजपथों के अतिरिक्त अन्य प्रकार की सड़कों के कार्यक्रम में १,१५० मील लम्बी सड़कों का सुधार होगा। राज्यों के कार्यक्रमों में ८,००० से ९,००० मील तक अच्छी सड़कें बनाने की व्यवस्था है। राष्ट्रीय विस्तार तथा सामूहिक योजना क्षेत्रों में तथा लोगों की

[शेष पृष्ठ ११३ पर]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

महान प्रगति

द्वितीय योजना में मुख्य जोर औद्योगीकरण की रफ्तार तेज करने पर दिया गया है। जन साधारण को वस्तुएं और अन्य सेवाएं सरलता से प्राप्त करा देने के लिए परिवहन और संचार की सुविधाओं का पर्याप्त होना भी जरूरी है, अतः दूसरी योजना में इन को महत्त्व दिया गया है। उत्पादन और वितरण दूसरी योजना के मुख्य उद्देश्य हैं और योजना पर होने वाले व्यय में लगभग आधा व्यय इन दो मदों पर होगा।

हर एक वस्तु की विपुलता

भारी तथा मशीन बनाने वाले उद्योगों के विकास से उत्पादन की गति तेज होगी और हमारी समृद्ध खनिज संपत्ति का भी उपयोग किया जाएगा। उद्योग तथा खनिजों के विकास के लिए ८९० करोड़ रुपयों की राशि (कुल व्यय का १९ प्रतिशत) स्वीकृत की गई है। इस में ग्राम और लघु उद्योग भी शामिल हैं। दूसरी योजना का इन सब से अधिक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है—अधिक रोजगारों का निर्माण। अनुमान है कि लगभग ८० लाख लोगों को रोजगार मिलेगा जिस में कृषि क्षेत्र सम्मिलित नहीं है।

समृद्धि के मार्ग पर

जैसे जैसे उद्योगों का विकास होगा वैसे वैसे वस्तुओं और सेवाओं का वितरण भी शीघ्र होगा। द्वितीय योजना के कुल व्यय के २९ प्रतिशत यानी १,३८५ करोड़ रुपयों की राशि परिवहन और संचार सुविधाओं के विकास पर खर्च होगी। इस में रेलवे, नई सड़कें, अधिक स्थल परिवहन और पर्यटक-सुविधाएं, जहाजरानी, हवाई सेवा, प्रसार, डाक और तार विभाग आदि विषय सम्मिलित हैं।

राष्ट्र की समृद्धि के लिए

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारी मशीनों के उद्योग की प्रगति

भारतीय गणराज्य के ७ वें वर्ष में देश में उद्योग आगे ही नहीं बढ़ा, उसने एक नयी दिशा भी ग्रहण की है। औद्योगिक प्रगति की विशेषताएं ये हैं—

१. उत्पादन में वृद्धि।

२. नई-नई चीजों का निर्माण, और

३. इंजीनियरी उद्योगकी अधिक तेजी से उन्नति।

औद्योगिक उत्पादन का सूचक अंक, जो १९५५ में (आधार वर्ष १९५१) १२२.१ था, १९५६ के पहले ९ महीनों में बढ़कर १४४.७ हो गया।

बड़े उद्योगों ने, पिछले दो वर्षों की तरह इस वर्ष भी उत्पादन बढ़ाने का क्रम जारी रखा। बहुत से इंजीनियरी उद्योगों ने तो पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अधिक तीव्र गति से उन्नति की। उपभोग्य वस्तुओं के लिए बढ़ती हुई मांग के साथ-साथ इस वर्ष सूती कपड़े, ब्लेड, साबुन सिगरेट और जूतों आदि का उत्पादन भी काफी बढ़ा। इसके अलावा, आध इंची केपस्टन खराद यन्त्र, बिजली के उठाऊ बर्मे, शाक एब्जार्वर, क्लच डिस्क, ब्रेक लाइनिंग और अन्य महत्वपूर्ण रंग और दवाइयाँ इस वर्ष भारत में पहली बार तैयार की गईं।

नये कारखाने

इस वर्ष नये कारखाने खोलने या वर्तमान कारखानों का विस्तार करने तथा ४१ विभिन्न उद्योगों में नई वस्तुएं तैयार करने के लिए औद्योगिक अधिनियम के अन्तर्गत ८६० लायसेंस दिये गये। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि सीमेंट के १८ नये कारखाने खोलने के लिए लायसेन्स दिए गए और वर्तमान ८ कारखानों के विस्तार की अनुमति दी गई।

भारत में भारी उद्योगों के विकास पर अधिक जोर दिया जा रहा है और निम्नलिखित उद्योगों के लिए लायसेंस दिए जा चुके हैं—लोहे और इस्पात के ढांचे बनाना नये कारखाने ३४, कारखानों का विस्तार या नई चीजों का निर्माण, ५१, मोटर गाड़ियां और पुनः नये कारखा २७, विस्तार अथवा नयी चीजों का निर्माण २२, मशी और साज सामान नये कारखाने २५, विस्तार या न चीजों का निर्माण ४४, रेल के डिब्बे और इंजन बनान नये कारखाने ९, विस्तार और नयी चीजों का निर्मा ६, साइकिल बनाना— नये कारखाने १७, विस्तार या न चीजों का निर्माण ८, छोटे औजार बनाना—नये का खाने ९, विस्तार अथवा नई चीजों का निर्माण ८।

भारी मशीनों का निर्माण

१९५६ का वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इ वर्ष भारत में भारी मशीनें तैयार करने की योजना बना गई। कहा जा सकता है कि इस उद्योग क नींव इसी वर्ष रखी गई है।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा भारी मशी बनाने की योजना भी इसी वर्ष तैयार की गई। भार सरकार ने देशमें उद्योग के समन्वित विकास की दृष्टि से य निगम स्थापित किया था। भारी मशीनों की ढलाई क योजना तैयार हो चुकी है। प्राविधिक सलाहकारों का चुना पूरा हो जाने पर शीघ्र ही काम शुरू हो जायगा।

भारी इंजीनियरी उद्योग के विकास की योजनाएं तैया करने के लिए रूस और ब्रिटेन से विशेषज्ञों के दो द भारत आये थे। रूसी विशेषज्ञ-दल भारी मशीनों के का खाने की योजना तैयार करेगा और ब्रिटिश दल यह बताये कि देश में भारी मशीन-उद्योग का विस्तार किस प्रकार कि जा सकता है।

मशीन टूल उद्योग के विकास की दिशा निर्धारित क जा चुकी है। भारत सरकार ने मशीन टूल समिति क सिफारिशें मंजूर कर ली हैं। समिति की एक सिफारिश य भी थी कि निजी क्षेत्र में भारी मशीन टूल बनाने क क्षमता निर्धारित की जाय। यह भी सरकार ने मंजूर क ली है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इस्पात के कारखाने

इस वर्ष सार्वजनिक क्षेत्र में इस्पात के ३ विशाल कारखाने खोलने तथा टाटा इस्पात-कारखाने का काफी विस्तार करने की व्यवस्था को अन्तिम रूप दिया गया । रूड़केला (उड़ीसा), भिलाई (मध्यप्रदेश), और दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) में खोले जाने वाले इस्पात कारखानों के निर्माण तथा पूर्ति के लिए ठेके दे दिये गये हैं और सामान पहुँचना शुरू हो गया है । कुछ भारतीय विद्वानों को प्राविधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए विदेशों में भेजा गया है, ताकि वे लौटने पर इन कारखानों में ऊंचे-ऊंचे पद संभाल सकें । कारीगरों को यहीं काम सिखाया जा रहा है ।

उत्पादन के साथ-साथ कारखानों में रोजगार भी बढ़ा है । उदाहरणतः, शिल्पिक और सामान्य इंजीनियरी उद्योगों ने पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष लगभग ३,६०० अधिक लोगों को काम दिया । अन्य उद्योगों में रोजगार की वृद्धि इस प्रकार रही—मोटर-उद्योग-१९४०; बिजली इंजीनियरी उद्योग—४,५४१; रासायनिक उद्योग—५,९३०; चमड़ा और रबड़-उद्योग—१,३८०; सूती वस्त्र-उद्योग—५३,५० ; ऊनी वस्त्र उद्योग – २,२३० ।

इस वर्ष सूती कपड़े का उत्पादन ५ अरब २४ करोड़ २० लाख गज रहा । पिछले वर्ष उत्पादन ५ अरब ९ करोड़ ४० लाख गज था । इसी प्रकार इस वर्ष सूत का उत्पादन १ अरब ६४ करोड़ ५० लाख पौंड रहा । पिछले वर्ष यह १ अरब ६३ करोड़ पौंड था । ऊनी कपड़े का उत्पादन भी पिछले वर्ष १ करोड़ ३६ लाख ९० हजार गज से बढ़ कर इस वर्ष १ करोड़ ६३ लाख ९० हजार गज हो गया ।

इस वर्ष इस्पात का अनुमानित उत्पादन १: लाख ३० हजार टन है । पिछले वर्ष १२ लाख ६० हजार टन इस्पात तैयार हुआ था । टाटा इस्पात कारखाने की विस्तार योजना का एक अंश पूरा होने पर, नये वर्ष के आरम्भ में इस्पात-उत्पादन में थोड़ी वृद्धि हो जायगी ।

सीमेंट का उत्पादन भी पिछले वर्ष ४५ लाख टन से बढ़कर इस वर्ष ४९ लाख ५० हजार टन हो गया । दूसरी पंचवर्षीय आयोजना में निर्धारित नमक-उत्पादन का लक्ष्य प्रायः पूरा हो चुका है । यह लक्ष्य १० करोड़ मन का था, पर चालू वर्ष में ९ करोड़ ४० लाख मन नमक बनाया जाने लगा ।

मोटरों का उत्पादन दुगना

इस वर्ष अनुमानतः ३१,००० मोटर गाड़ियां तैयार हुईं । पिछले वर्ष २३,०८४ तैयार हुई थीं । दो ही वर्ष में उत्पादन दुगुना हो गया है । साइकिल उद्योग ने भी ऐसी ही उन्नति की है । इस वर्ष अनुमानतः ६,१५,१०० साइकिलें तैयार हुईं । पिछले वर्ष ४,९१,१७१ तैयार हुई थीं ।

१९५६ में अन्य उद्योगों के उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े नीचे दिये गये हैं । १९५५ के आंकड़े कोष्टक में हैं—

रेडियो १,३३,००० (८१,२००); बिजली की मोटरें ३,४७,००० अश्व-शक्ति (२५१,९१५ अश्वशक्ति); सिलाई की मशीनें १,२६,७८२ (१,०१,४७२); ब्लेड— २३ करोड़ ८० लाख (१७ करोड़ ४० लाख); डीजल-इंजन—१२,००० (१०,२२०); शक्ति-चालित पम्प—४६,००० (३४,४४१); पावर ट्रांस्फार्मर्स—९,०१,००० किलोवोल्ट एम्पीयर (५,६४,७१३ किलो वोल्ट एम्पीयर); बिजली के पंखे–३,३७,००० (२,६२,२३६); साबुन—१,१०,००० टन (९९,००० टन); रेयन—७,३७६ टन (५,७३२ टन); एसीटेट यार्न १,४०० टन (१,०३९); सिगरेट—२३ अरब ५८ करोड़ ८० लाख (२२ अरब ८२ करोड़ ८६ लाख); मोटर-गाड़ियों के टायर—९ लाख ३५ हजार (८ लाख ८२ हजार); रबड़ के जूते—३ करोड़ ५० लाख जोड़ों से अधिक (३ करोड़ ४९ लाख जोड़े) ।

आटोमैटिक लूम निर्माता

दिसम्बर के अंक में आयात नीति पर एक टिप्पणी प्रकाशित हुई है । इसमें लिखा है कि आटोमैटिक लूम बनाने के देश में दो तीन कारखाने हैं । किन्तु हमें मालूम हुआ है कि अभी तक केवल एक ही कारखाना टैक्समैको (ग्वालियर) है, जो आटोमैटिक लूम बनाता है । इस भूल के लिए हमें खेद है । इस कारखाने का इस उद्योग पर एकाधिकार है, यह गर्व की बात है । हमें आशा करनी

(शेष पृष्ठ ११४ पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दूसरा पहलू—

सामुदायिक विकास कार्यक्रम

श्री एल० एन० वर्मा

गांधी जयन्ती के अवसर पर २ अक्टूबर, १९५२ के दिन चुने हुए ५५ क्षेत्रों में सामुदायिक योजना का श्रीगणेश किया गया था। इसे अधिक प्रगति देने के लिए एक वर्ष बाद राष्ट्रीय विस्तार सेवा नामक एक और वैकल्पिक कार्यक्रम, जिसके अन्तर्गत केवल अत्यन्त आवश्यक कार्य ही हाथमें लिए जाते हैं, प्रारम्भ कर दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना की समाप्ति काल तक देश में कुल ११६० विकास खंडों पर कार्य चालू कर दिया गया था, जो देश के ८ करोड़ ८८ लाख जनसंख्या वाले लगभग १॥ लाख ग्राम अपनी परिधि में ले चुके हैं। २ अक्टूबर, १९५६ से कुछ अन्य नये विकास खंडों पर कार्य शुरू कर दिया गया है। गत पांच वर्षों में ग्रामीण जनता का एक चौथाई भाग इस योजना के अञ्चल में लाया जा चुका है। दूसरी पंचवर्षीय योजना इस सम्बन्ध में इससे भी कहीं अधिक महत्वाकांक्षी है। इसके अन्तर्गत अगले पांच वर्षों में राष्ट्रीय विस्तार सेवा के द्वारा ग्राम्य भारत के कोने-कोने को आलोकित करने का शुभ संकल्प किया गया है। इस अवधि में सम्पूर्ण देश में अतिरिक्त ३८०० राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड स्थापित किए जायेंगे, जिनमें से कम से कम ४० प्रतिशत कालान्तर में सामुदायिक विकास खंड बना दिये जायेंगे। इस कार्य के लिए योजना में २ अरब रुपयों की राशि की व्यवस्था की गई है।

कार्यक्रम की सफलताएँ

योजना आयोग के मतानुसार गत वर्षों में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न दिशाओं में उत्साहजनक सफलताएँ प्राप्त की गई हैं। कृषि को इसमें प्रारम्भ से ही प्राथमिकता दी गई थी। अतएव कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि की उन्नति के लिए किसानों को श्रेष्ठतर औजारों का प्रयोग करने, खेती की उन्नत विधियों को अपनाने, खेतों में अच्छी खादें एवं उर्वरक डालने तथा अच्छे किस्म के बीजों को बोने के लिए उत्साहित और तैयार किया गया। साथ ही में योजना-क्षेत्रों में सिंचाई के छोटे-छोटे साधनों तथा नवीन कृषि-भूमि का विस्तार किया गया। परिणाम यह हुआ कि सामुदायिक विकास के क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों के मुकाबले मुख्य-मुख्य उपजों में २० से २५ प्रतिशत तक वृद्धि हुई। कृषि के अतिरिक्त पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए ग्राम केन्द्रों की स्थापना की गई, जहां पर अच्छी नस्ल के पशु तैयार किये गए। यातायात की सुविधा बढ़ाने के लिए नई सड़कों के निर्माण तथा पुरानी सड़कों को सुधारने का काम हाथ में लिया गया। कल्याण-कार्य भी पीछे नहीं रहे। योजना-क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालाओं, स्वास्थ्य केन्द्रों, मातृत्व तथा शिशु कल्याण केन्द्रों की स्थापना की गई तथा पेय जल के कुओं, साधारण तथा आदर्श मकानों, शौचालयों, नालियों आदि का निर्माण किया गया। मार्च १९५६ तक विभिन्न दिशाओं में इस सम्बन्ध में जो सफलताएँ प्राप्त की गई हैं, उनके संक्षिप्त तथा निकटतम आंकड़े इस प्रकार हैं—

कृषि योग्य बनाई गई भूमि	११ लाख एकड़
अतिरिक्त सिंचाई की व्यवस्था	२० लाख एकड़
अच्छे बीजों का वितरण	४५ लाख मन
उर्वरकों का वितरण	९३ लाख मन
कृषि की उन्नत विधियों का प्रदर्शन	१२॥ लाख
पशु नस्ल सुधार ग्राम केन्द्र	२५५०
तैयार किये गए अच्छी नस्ल के पशु	१२८००
पक्की सड़कों का निर्माण	६०८० मील
कच्ची सड़कों का निर्माण	३८००० मील
सुधारी गई पुरानी सड़कें	२२००० मील
पेय जल के कुओं का निर्माण	१ लाख
नालियों का निर्माण	६४ लाख गज
नये मकानों का निर्माण	२९ हजार
आदर्श मकानों का निर्माण	३। हजार
प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	६७४
मातृत्व तथा शिशु कल्याण केन्द्रों की स्थापना	५७६
ग्राम शौचालयों का निर्माण	८० हजार

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्राथमिक स्कूलों की स्थापना	१५ हजार
प्राथ० स्कूलों का बुनियादी में परिवर्तन	७ हजार

परन्तु—

उक्त आंकड़ों के आधार पर सरकारी क्षेत्रों का दावा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रमों ने देश में आशातीत सफलताएँ प्राप्त की हैं। निरपेक्ष दृष्टिकोण से देखने से प्रथम दृष्टि में ऐसा ही लगता है। मेरे विचार से सही-सही मूल्यांकन के लिए हमें देश की आवश्यकताओं तथा सम्बन्धित जनसंख्या की पृष्ठभूमि में इन आंकड़ों का अध्ययन करना चाहिए और साथ में यह भी देखना चाहिए कि क्या इससे अधिक नहीं किया जा सकता था। जब हम इस दृष्टि से सामुदायिक कार्यक्रम की सफलताओं पर विचार करते हैं, तब वे उतनी बड़ी नहीं रह जातीं, जितनी बड़ी बहुधा उन्हें समझ लिया जाता है। उदाहरण के लिए ये समस्त कार्य, जिनसे उक्त आंकड़े सम्बन्धित हैं, लगभग ८ करोड़ ८८ लाख जनसंख्या के पीछे किए गये हैं। यदि इन आंकड़ों को प्रति व्यक्ति की दृष्टि से निकाला जाय, तो वे बहुत सन्तोषजनक नहीं दिखाई देंगे। इस हिसाब से प्रायः गत चार वर्षों में प्रति व्यक्ति लगभग ४ सेर से कुछ ही अधिक उर्वरक तथा लगभग दो सेर अच्छे बीजों का वितरण किया गया है और प्रति गांव पीछे केवल लगभग ३ मील लम्बी सड़कें बनाई गई हैं, जो बहुत उत्साहजनक नहीं हैं। अच्छी नस्ल के प्रायः १२८०० पशु तैयार किए गये; पर यह संख्या देश के पशुधन की करोड़ों की संख्या के सामने नगण्य है। कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित किए गये स्वास्थ्य केंद्रों तथा मातृत्व एवं शिशु कल्याण केन्द्रों की संख्या इतने बड़े देश में सागर में बूंद के समान है।

कार्यक्रम के आधारभूत उद्देश्य

सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन एक और विधि से भी किया जा सकता है। हमें यह देखना होगा कि जिन आधारभूत उद्देश्यों को लेकर यह योजना प्रारम्भ की गई थी, वे कहां तक प्राप्त किए जा सकते हैं? प्रारम्भ ही से कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित उद्देश्यों पर बल दिया गया है—

(१) ग्रामवासियों को अपनी सहायता स्वयं करने के सिद्धांत पर आत्मोन्नति के लिए प्रेरित करना तथा विकास कार्यों में उनका उत्तरोत्तर सहयोग प्राप्त करना।

(२) सम्बन्धित क्षेत्रों को गहन प्रयत्न के क्षेत्र बनाना तथा इसके अन्तर्गत सुनियोजित और सामंजस्यपूर्ण ढंग से ग्राम्य जीवन के प्रत्येक अंग का उत्थान करना।

(३) गांव के सभी परिवारों को, विशेषकर उस वर्ग को जो अभी तक अविकसित तथा पिछड़ा हुआ है, विकास कार्यक्रम की परिधि के अन्दर लाना।

जन-सहयोग

जहां तक विकास कार्यों में जनसहयोग प्राप्त करने की बात है, योजना आयोग का मत है कि सामुदायिक कार्यक्रम ने इस सम्बन्ध में आशाजनक सफलताएँ प्राप्त की हैं। मार्च, १९५६ तक इस योजना पर कुल ७२ करोड़ १५ लाख रुपया व्यय किया गया, जिसमें सरकार की ओर से जाने वाला व्यय केवल ४६ करोड़ २ लाख रुपये था। शेष २६ करोड़ १३ लाख रुपये की सहायता जनता ने नकद धन, वस्तुओं तथा श्रम के रूप में प्रदान की। इस प्रकार लगभग

दी बौम्बे स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि०

९ बेक हाउस लेन, फोर्ट, बौम्बे—१

(१९११ में स्थापित)

चेयरमैन : श्री रमणलाल जी, सरैया ओ० बी० ई०

इस बैंक में जमा किये हुए रुपये से भारत के किसानों तथा सहकारी संस्थानों को सहायता मिलती है।

हिस्सेदारों की परिदत्त पूंजी :—

हिस्सेदारों द्वारा खरीदी गई	३५,४५,६०० रु०
बम्बई सरकार द्वारा खरीदी गई	२६,००,००० रु०
	६१,४५,६०० रु०
रिजर्व तथा अन्य कोष	५६,०३,५०० रु०
कुल डिपाजिट	१२,८५,९७,२०० रु०
सक्रिय पूंजी	१५,३९,९१,२०० रु०

१३ जिलों में ६० शाखाएं !

भारत के सभी प्रमुख नगरों में रुपया एकत्र करने की व्यवस्था—सभी प्रकार के डिपाजिट स्वीकार किये जाते हैं।

प्रार्थना-पत्र भेज कर शर्तें मंगाइये।

वी० पी० वरदे

आनरेरी मैनेजिंग डायरेक्टर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गत चार वर्षों में जनता के योगदान का मूल्य सरकारी व्यय के ५० प्रतिशत से भी अधिक है। कम से कम आंकड़े तो यही प्रदर्शित करते हैं। परन्तु विकास कार्यों में अपेक्षित जन सहयोग प्राप्त हो रहा है—इस पर एकाएक विश्वास नहीं होता; क्योंकि विकास कार्यों के सम्पर्क में आने वाले सामान्य व्यक्तियों का अनुभव कुछ दूसरा ही है। एक जन सहयोग अधिकरण की स्थापना का निश्चय किया गया है। इस नये अधिकरण की आवश्यकता इस बात का प्रमाण है कि पर्याप्त जन सहयोग नहीं मिल रहा।

यदि जनता का वांछित सहयोग नहीं मिल रहा है तो इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा उसे कार्यान्वित करने की प्रणाली में से कोई एक या दोनों दोषपूर्ण हैं। सम्भवत यह कार्यक्रम जनता की असली तथा मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर रहा है। जब तक इसे दूर नहीं किया जाता, तब तक जनता का हार्दिक सहयोग नहीं प्राप्त हो सकता।

प्रशासन

अपेक्षित जन सहयोग प्राप्त न होने का उत्तरदायित्व उसे कार्यान्वित करने वाले दोषयुक्त प्रशासन और प्रणाली पर भी है। कर्मचारियों के कार्य करने का ढंग बड़ा ही औपचारिक, लालफीतेशाही तथा नौकरशाही है। सारा कार्य दिखावट तथा खानापूरी के लिए किया जाता है। योजना आयोग भी एक सीमा तक इससे सहमत है—जनता को स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरित व शिक्षित करने की बजाय बाहरी आडम्बर, भविष्य निर्माण प्रदर्शन आदि पर अधिक बल दिया गया है वस्तुतः हमारे अधिकारी जनता की उस बुनियादी शक्ति को प्राप्त करने में विफल रहते हैं, जो कार्यक्रम को मंजिल तक पहुँचाने के लिए अनिवार्य है। सामुदायिक योजनाओं को कार्यान्वित करने की प्रणाली में एक दोष और है, जिसके प्रति योजना आयोग ने सरकार को सावधान किया है। वह यह कि इनसे सम्बन्धित विभिन्न विभागों में बहुधा पारस्परिक सहयोग और सामंजस्य का अभाव देखा गया है। इसके अतिरिक्त जनता की दृष्टि में सामुदायिक प्रशासन प्रारम्भ से ही व्यय-साध्य है। इधर हाल में प्रशासन व्यय में कमी होने के स्थान पर विभागों की संख्या बढ़ते रहने के कारण खर्च बढ़ते जा रहे हैं। सामुदायिक विकास कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए पहिले ही एक पृथक संगठन स्थापित किया गया था। गत १८ दिसम्बर को सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना करके प्रशासन व्यय और भी बढ़ा दिया गया है।

बहुमुखी विकास

कार्यक्रम के अन्तर्गत जो सफलताएँ प्राप्त की गई हैं, उनके संक्षिप्त आंकड़े ऊपर दिये जा चुके हैं। परन्तु बहुत से लोगों का यह व्यक्तिगत अनुभव है कि सरकारी विभाग जिस ढंग से आंकड़े एकत्र करते हैं, वह विश्वसनीय नहीं है। हमारे अधिकारी अधिकतर विज्ञापन तथा प्रचार में विश्वास करते हैं। आंकड़े प्रगति की गाथा गाते हैं। पर इन आंकड़ों में वास्तविकता कहां तक होती है, इसे विकास कार्यों से सम्बन्धित व्यक्ति ही समझते हैं।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम गांवों के सर्वोन्मुखी विकास की योजना है। अभी बहुत काम पड़ा है, जिस ओर ध्यान नहीं दिया जा सका। कार्यक्रम ने कृषि-भूमि की हदबन्दी तथा पुनर्वितरण, आय के सम वितरण तथा बेकारी एवम् अर्ध-बेकारी की समस्या को जरा भी नहीं छुआ है। कुओं, नालियों, शौचगृहों, सड़कों तथा मकानों के निर्माण करने, स्कूलों, स्वास्थ्य केन्द्रों तथा मातृत्व एवम् शिशु कल्याण केन्द्रों की स्थापना करने तथा किसानों को अच्छे बीज, उन्नत औजार तथा विधियों, उर्वरकों आदि के प्रयोग की सुविधाएं प्रदान करने जो कार्य किये गये हैं, वे लाभदायक हैं। पर इतना ही काफी नहीं है। जब तक इनके साथ में बेकारी एवम् अर्ध-बेकारी को समाप्त तथा भूमि-व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं किया जाता और सबसे बढ़कर जब तक सब प्रकार के शोषण का नाश करके आय के समान वितरण की व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक अधिक लाभ होने की किसी भी प्रकार सम्भावना नहीं।

धनी किसान ही

कार्यक्रम का गांव के समस्त परिवारों को अपनी परिधि में लेने का तीसरा उद्देश्य भी प्राप्त होता नहीं ही दिखाई देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसा ९ अक्टूबर से जूनागढ़ में सामुदायिक विकास की अन्तर्राज्य प्रादेशिक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सर्वोदय और समाजवाद

—विनोबा

'सर्वोदय' शब्द को बहुत से लोग मान्य करते हैं फिर भी उसे यह कह कर टालने की भी कोशिश होती है कि यह उच्च शब्द है, शायद उतना हम न कर पायें, इसलिए "समाजवादी समाज-रचना" शब्द अच्छा रहेगा !

लेकिन यह "समाजवादी समाज-रचना" एक ऐसा गोलमटोल शब्द है कि उसके पचासों अर्थ होते हैं। उसका प्रयोग करना और न करना, दोनों बराबर हैं। हिन्दुस्तान के पूंजीवादी भी कह रहे हैं कि हमें "समाजवादी समाज-रचना" मान्य है। इसलिए अब उस शब्द से कोई बहुत ज्यादा हिन्दुस्तान का तारण होगा, ऐसा नहीं है। फिर, समाजवादी रचना में व्यक्ति और समाज के बीच एक झगड़ा भी माना जाता है। आजकल यूरोप में समाजवाद—"उत्पादन बढ़ाओ और लोगों को सुखी करो", इतने में ही समाप्त हो जाता है। केवल चन्द धन्धों को सरकारी बना लिया और सरकार की सत्ता उस पर लागू की, इतने से ही आम जनता की शक्ति निर्माण नहीं होती है और न उत्पादन बढ़ाने और लोगों में आज से अधिक समृद्धि लाने की कोशिश से ही जनता की शक्ति निर्माण होती है। पूंजीवादी समाज-रचना में भी उत्पादन बढ़ाने का और सबको सुखी करने का विचार मान्य किया जाता है। हां, पूंजीवादी साम्ययोग नहीं मानता है, परन्तु सब लोग सुखी हों, ऐसा तो वे भी मान्य करते ही हैं। सबके 'समान सुख' की बात वे कबूल नहीं करते हैं, परन्तु वे सुखी हों, इतनी बात वे भी मान्य करते हैं। इसलिए जिसे 'वेलफेअर-स्टेट'—कल्याणकारी राज्य कहा जाता है, वह कोई जन-शक्ति बढ़ाने वाली चीज नहीं है। मैं मानता हूं कि श्रीहर्ष का राज्य, राजराज सोलन और कृष्णदेव राय का राज्य 'वेलफेअर स्टेट' था। लेकिन इन लोगों के राज्य में जनता की कोई ताकत बढ़ी थी, ऐसा नहीं है। अकबर गया, जहांगीर आया, वह गया, औरंगजेब आया। लोगों की हालत बुरी होने लगी। अकबर के राज्य में अच्छी हालत थी, मगर जनता में शक्ति निर्माण हुई होती, तो फिर कायम के लिए लोगों की हालात अच्छी हो जाती। पुराने राजाओं से न वह हो सका था, न पूंजीवादी राज्य-व्यवस्था में वह होता है और न समाजवादी समाज-रचना की जो बात आजकल यूरोप में चल रही है, उससे ही होता है। आधुनिक लेखक इस बात को कबूल करते हैं। इसलिए वेलफेअर-स्टेट या समाजवादी समाज-रचना कहने से हम कोई बहुत ज्यादा प्रकाश डालते हैं, ऐसा नहीं। इसलिए "सर्वोदय" नाम से जो सुन्दर शब्द अपनी सभ्यता में से निर्माण हुआ है, उसे कबूल करना चाहिए। उस शब्द को एक सुन्दर शब्द के तौर पर मान्य तो कर लें, पर शायद वैसा हम न कर पायें, ऐसे डर से विनम्र भाव से उसे दूर रखना भी हम गलत समझते हैं।

हमें सर्वोदय का स्पष्ट भान होना चाहिए। इस शब्द को हमें छोड़ना ही नहीं चाहिए। जो इस शब्द को छोड़ते हैं, वे एक बड़ा भारी रत्न खोते हैं। उसका परिणाम यह हुआ है कि आज देश के सेवकों में दुविधा हो रही है। एक अजीब-सा दृश्य देश में दीख रहा है। एक बाजू कुल रचनात्मक कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, चाहे उनमें से कुछ कांग्रेस में, कुछ प्रजासमाजवादी दल में और कुछ अन्यत्र

गोष्ठी में भाग लेने वाले अधिकतर प्रतिनिधियों ने भी कहा है कि योजना का पूरा लाभ केवल उच्चस्तर के लोगों तथा धनी किसानों को ही मिल रहा है। अनार्थिक जोतों के छोटे-छोटे किसानों, भूमिहीन मजदूर तथा निम्न वर्ग के लोग इसके लाभों से वंचित हैं। उदाहरण के लिए ऋण लेने की सुविधाएं ग्राम्य जनता के एक छोटे वर्ग को ही मिल पाई है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार "केवल ३० प्रतिशत लोगों को ही ऋण दिया जा सकता है और वे ही इन योजनाओं के जरिये ऋण पाने की उम्मीद कर सकते हैं।" इस सम्बन्ध में हमें स्मरण रखना चाहिए कि जब तक विकास कार्यक्रमों का लाभ सबको समान रूप से नहीं प्राप्त होता, तब तक वे गांवों की अभीष्ट समय में काया-पलट करने में समर्थ नहीं हो सकते।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

एवं कुछ कहीं नहीं भी हैं; लेकिन उन सब लोगों का दिल "सर्वोदय" शब्द से जुड़ा हुआ है। दूसरे ऐसे लोग हैं, जो किसी न किसी कारणसे इस शब्द को टालते हैं। पर इससे देश की शक्ति नहीं बन रही है। 'शिव' और 'शक्ति' अलग ही रहे हैं।

इसलिए लोगों ने समाज-रचना करने की सत्ता जिन्हें सौंपी है, वे लोग और समाज-सेवा की तीव्र भावना रखने वाले, इन दोनों के बीच जहां भेद आ जाता है, वहां देश की ताकत नहीं बनती है। सर्वोदय "शिवम्" है और जिसे आप राज्यसत्ता कहते हैं, वह "शक्ति" है। जब शिवम् से वह शक्ति अलग पड़ जाती है; तब शक्ति क्षीण होती है। शक्ति से शिवम् अलग पड़ता है, तो वह तो वैराग्यमान है ही। उनका वह वैराग्य कोई छीन नहीं सकता।

——

१९५७—सत्-आवन

अगर राजनैतिक आजादी निश्चित दिन तथा समय पर घोषित हो सकती है, जिससे कि एक बलशाली राष्ट्र का सम्बन्ध था, तो क्या आर्थिक आजादी का यह पावन कार्य हम ठीक समय पर न करेंगे? संकल्प में शक्ति होती है। भगवान् अपने भक्तों की लाज रखते हैं। राजनैतिक गुलामी की तरह आर्थिक गुलामी का यह अभिशाप जितनी जल्द दूर हो, उससे हममें संतोष भी बढ़ेगा एवं तेज भी।

१९५७ आ रहा है। एक मित्र ने इसको 'सत्-आवन' के रूप में हमारे सामने रखा है, जो कई अर्थों में सत्य मालूम होता है। १९५७ में भमि-समस्या हल करने का संकल्प राष्ट्र ने किया है। इस आंदोलन को सभी विचारों की संस्थाओं का सहयोग एवं आशीर्वाद प्राप्त है, यह सत्-आवन का एक सबसे बड़ा प्रमाण है।

जरा करके तो देखें!

दो साल के लिए सरकार को भी छुट्टी देकर तो जरा हम देखें! अब पोस्ट वालों को हफ्ते में एक छुट्टी मिली है। स्कूल-कालेजों को भी लम्बी छुट्टियां दे देते हैं। तो कृपा कर सरकार को भी दो साल के लिए छुट्टी देकर देखा तो जाय कि क्या होता है! कुछ भी नहीं होगा। हमारा यह सिर्फ अहंकार है, जो हम समझते हैं कि सरकार से ही सब कुछ होता है। क्या सरकार न हो, तो होली-दिवाली नहीं होगी? अभी, चुनाव १५ मार्च के बदले १२ मार्च को ही पूर्ण हों, ऐसा तय हुआ, क्योंकि १५-१६ मार्च को होली आती है। कहा गया कि चुनाव के समय होली आ जाय, तो लोग होली ही खेलेंगे; वोट नहीं देंगे। स्पष्ट है कि जनता के लिए होली, चुनाव से ज्यादा जोरदार है। तो यह होली किसने तय की? लोगों ने ही। इसी का नाम तो लोकशक्ति है और लोकशक्ति का ही परिणाम हमें राज-सत्ता पर लाना है। अगर हिन्दुस्तान में हम यह कर सकें, तो दुनिया में भी यह हो सकेगा, भले ही कुछ समय लग जाय! लेकिन इस विज्ञान-युग में पहले के जमाने के पचास साल आज पाँच साल ही रह जाते हैं।

——

उद्योग विभाग, उत्तरप्रदेशीय सरकार

द्वारा प्रकाशित

सचित्र मासिक पत्र

उद्योग

पढ़िये, जिसमें भारत के आर्थिक विकास, विशेषतया उत्तरप्रदेश की औद्योगिक प्रगति के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण लेखों के साथ साथ अन्यान्य मनोरंजक साहित्यिक सामग्री – कविताएं, कहानियां और लेख भी उपलब्ध होंगी।

विवरणार्थ लिखें:

प्रकाशनाधिकारी
उद्योग विभाग
उत्तरप्रदेश—कानपुर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हमारा उत्तरप्रदेश : आर्थिक विकास में प्रगति

गंगा और यमुना का, राम और कृष्ण का उत्तरप्रदेश केवल धार्मिक व ऐतिहासिक दृष्टि से ही असाधारण महत्व नहीं रखता, उसका वर्तमान और भविष्य भी उज्ज्वल है। अन्य राज्यों की भांति वह भी राष्ट्र-निर्माण की विविध दिशाओं में उन्नति के पथ पर अग्रसर है। प्रस्तुत लेख में गत वर्षों में की गई उसकी कुछ आर्थिक सफलताओं का संक्षेप से परिचय दिया गया है।

सिंचाई के क्षेत्र में हुई प्रगति विशेषरूप से उल्लेखनीय है। सन् १९४६ में १७,८२४ मील लम्बी सिंचाई नहरें, ७,८१८ मील लम्बी नालियां और १,८४७ नलकूप थे, जिनसे लगभग ६८ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होती थी। निश्चय ही राज्य के ४ करोड़ १६ लाख ४२ हजार एकड़ कृषि क्षेत्र के लिए इन साधनों से सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। अतः सिंचाई सुविधाओं के अधिकाधिक बिस्तार की ओर विशेष ध्यान देना अनिवार्य था। शनैः शनैः सम्पूर्ण राज्य में सिंचाई-नहरों आदि का जाल बिछा देने के लिए अनेक योजनाएं बनाईं। इसका परिणाम यह हुआ कि मार्च १९५६ तक ५,२०९ मील लम्बी नहरों का निर्माण हुआ और ३,३१६ नलकूप लगाये गये जिनसे ३८,४१,००० एकड़ अतिरिक्त भूमि की सिंचाई संभव हुई।

अधिक नलकूपों की व्यवस्था

सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए अनेक कार्यों का सम्पादन सिंचाई की छोटी योजनाओं को सम्पूर्ण राज्य में कार्यान्वित किया गया। मेरठ, बुलन्दशहर, एटा, अलीगढ़, मथुरा, बिजनौर आदि ३६ जिलों में अतिरिक्त नलकूपों की व्यवस्था की गयी।

ललितपुर, सपरार, माताटीला, अर्जुन कर्मनासा, चन्द्रप्रभा, बानगंगा, आदि बीसियों सिंचाई की अनेक बड़ी योजनाओं में से कुछ पर जोर-शोर से कार्य चालू है।

शारदा नहर प्रणाली से २,००० से अधिक मील लम्बी नहरें तथा शाखाएं निकाली गयी हैं। अपर गंगा नहर की क्षमता २,५०० क्यूजेक्स और बढ़ाई गयी है। पूर्वी यमुना तथा आगरा नहरों और हाथरस तथा फतेहपुर सीकरी शाखाओं का पुनर्निर्माण किया गया।

विद्युत उत्पादन

सन् १९४६ तक राज्य में विद्युत उत्पादन के लिए कोई विशेष योजना नहीं थी। केवल कुछ ही नगरों में बिजली के प्रकाश की व्यवस्था थी। राज्य में बिजली की प्रतिष्ठापित क्षमता कुल ४३,२०० किलोवाट और विद्युत वाहक लाइनों की कुल लम्बाई ४,९०० मील थी। सरकार ने जिला मुहम्मदपुर, सहारनपुर वटीया (नैनीताल) पर विद्युत उत्पादन योजनाओं को कार्यान्वित किया है जिनकी प्रतिष्ठापित क्षमता क्रमशः ९,३०० किलोवाट और ४१,४०० किलोवाट है।

इस दिशा में अथक प्रयास का परिणाम यह हुआ कि मार्च १९५६ तक झांसी, जालौन, हमीरपुर और बांदा जिलों को छोड़कर राज्य के अन्य सभी जिलों में राजकीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों की व्यवस्था हो गयी। १९५६ तक ११ जल विद्युत, ६ थर्मल और १५ डीजिल केन्द्र राज्य सरकार द्वारा चालू कर दिये गये थे। कानपुर सप्लाई प्रशासन ने बिजली की ३०,००० किलोवाट की अधिकतम क्षमता को बढ़ाकर ४१,७६० किलोवाट की कार्यान्वित किया। राजकीय विद्युत केन्द्रों की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता १,८७,२८५ किलोवाट और विद्युत वाहक लाइनों की लम्बाई ६,३९४ मील और बढ़ी।

भूमि सुधार

राज्य में जमींदारी विनाश के फलस्वरूप किसानों में एक नई चेतना पैदा हुई और वे चकबंदी से होने वाले लाभों को समझने लगे। परिणाम यह हुआ कि अधिकाधिक संख्या में किसान अपनी जोतों की चकबंदी कराने के लिए आगे बढ़े। किसानों की इधर उधर बिखरी जोतों के कारण उन्हें जमींदारी विनाश और भूमि सुधार योजनाओं के फलस्वरूप सभी अपेक्षित लाभ नही हो रहे थे। अब चकबंदी योजना राज्य के २६ जिलों में चालू है।

सरकार ने खाद्योत्पादन में वृद्धि करने तथा भारी संख्या

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की भीषण समस्याओं को हल करने की दिशा में बहुत कदम उठाये हैं। सरकार ने ६ उपनिवेशन योजनाओं तथा गंगा खादर मेरठ, तराई तथा काशीपुर, नैनीताल, मनुनगर, रामपुर, अफजलगढ़, बिजनौर और दूनागिरी, अलमोड़ा को चालू किया जो प्रायः पूरी हो चुकी हैं। इन समस्त योजनाओं के फलस्वरूप कुल १,०१,२८४ एकड़ भूमि को तोड़ा गया है और लगभग ८,८७३ व्यक्तियों को, नयी आबाद की गयी भूमि पर बसाया गया है। इन उपनिवेशों में कुछ १९५ गांव बसाये गये हैं और लोगों में आत्म सहायता तथा सहयोग की भावना पैदा करने के लिए इतनी ही संख्या में सहकारी समितियों की स्थापना की गयी है।

खाद्योत्पादन में वृद्धि

कृषि ही राज्य की अर्थ व्यवस्था का मेरूदंड है और भी ८० प्रतिशत राजस्व की प्राप्ति कृषि से ही होती है। उत्तर प्रदेश में आत्म निर्भरता आन्दोलन को पर्याप्त सफलता मिली है। १९५०-५१ में राज्य में १ करोड़ ७ लाख ९० हजार टन खाद्योत्पादन हुआ जो १५५४-५५ के वर्ष में बढ़कर १ करोड़ २९ लाख टन हो गया अर्थात् लगभग २० प्रतिशत की वृद्धि हुई। द्वितीय पंचवर्षीय आयोजनावधि अर्थात् १९६०-६१ तक खाद्योत्पादन में २४ लाख टन की और वृद्धि होगी। इस प्रकार आयोजन काल के अन्त तक खाद्योत्पादन में कुल ५० प्रतिशत की वृद्धि होगी।

सरकार ने नकदी फसलों जैसे गन्ना, तिलहन, रूस और जूट की योजनाएं बनाई हैं। सन् १९४८ में ५,००० एकड़ भूमि में जूट की खेती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जो बढ़ाकर १९५५-५६ में ३४,००० एकड़ कर दिया गया। १९५७ में रूई के अधिकाधिक उत्पादन के लिए उसके कृषि क्षेत्र को बढ़ाया गया। प्रथम पंचवर्षीय आयोजना में रूई का उत्पादन ४० हजार अतिरिक्त गांठों के निर्धारित लक्ष्य से अधिक हुआ और १९६०-६१ तक इसका कुल उत्पादन बढ़ाकर एक लाख १० हजार गांठ कर देने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार आयोजन काल में तिलहन के उत्पादन को लगभग ९ लाख टन से बढ़ाकर ११ लाख ८० हजार टन कर देने की योजना है।

देश के कुल उत्पादन का ६० प्रतिशत गन्ना उत्तर प्रदेश में पैदा किया जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना में ३ करोड़ ९३ लाख टन गन्ना पैदा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जबकि अभी तक ३ करोड़ ३ लाख टन गन्ना पैदा होने लगा है। राज्य की चीनी मिलों की संख्या में वृद्धि करने की योजना है। इसका उद्देश्य है सहकारी समितियों द्वारा किसानों के गन्ने की पूरी खपत कराना।

सहकारी आन्दोलन

सन् १९४५-४६ में राज्य में सभी प्रकार की २१,७८० सहकारी समितियां थीं और इनकी सदस्य संख्या १७ लाख ५३ हजार थी। इन समितियों की कार्यकारी पूंजी ६ करोड़ ७२ लाख रुपये और निजी पूंजी २ करोड़ ९६ लाख रुपये थी। सन् १९५६ में समितियों की संख्या बढ़कर ४९,०३८ और सदस्यों की संख्या ३६ लाख हो गयी। साथ ही कार्यकारी पूंजी और निजी पूंजी भी बढ़कर क्रमशः ३५ लाख २६ हजार रुपये और १२ लाख ९२ हजार रुपये हो गयी।

द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना में राज्य के प्रत्येक गांव में एक सहकारी समिति स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और सहकारी समितियों के सदस्यों की संख्या १२ लाख से बढ़ाकर ४५ लाख की जायगी और फलस्वरूप ग्राम्य क्षेत्रों के ५० प्रतिशत परिवार सहकारी समितियों से लाभान्वित होंगे।

औद्योगिक विकास के लिए निर्धारित १७ करोड़ रुपये की धनराशि में से एक करोड़ रुपये की रकम औद्योगिक संस्थानों की स्थापना पर व्यय की जायगी। इस योजना के अधीन निर्मित कार्यशालाओं को छोटे उद्योगपतियों को किराये पर दिया जायगा। आस्थानों में बिजली, पानी और नाले नालियों की समुचित व्यवस्था की जायगी। राज्य में सहकारी आधार पर कतिपय चीनी मिलों को चलाने का निश्चय भी किया गया है और इस प्रयोजन के लिए द्वितीय पंचवर्षीय आयोजन में एक करोड़ रुपये की रकम निश्चित की गयी है जिसे इस प्रकार की चीनी मिलों की सहायता के लिए दिया जायगा।

छोटे पैमाने के उद्योगों तथा ग्रामोद्योग के विकास पर ९ करोड़ ७६ लाख रुपये व्यय किये जाएंगे और साढ़े पांच करोड़ रुपये की लागत से सरकारी क्षेत्र में भारी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उद्योगों की स्थापना की जायगी।

लालटेन, बटन, कार्बन कागज, नलकूपों के उपकरण, खेलकूद के सामान, रबड़ के समान, पेंट एवं वार्निश आदि के कुटीर उद्योग की स्थापना और पुराने कुटीर उद्योगों के विकास इन पांच वर्षों की सफलता है।

द्वितीय आयोजनावधि दो करोड़ रुपये व्यय करके चुर्क स्थित राजकीय सीमेंट कारखाने की उत्पादन क्षमता दुगुनी कर दी जायगी। साथ ही लखनऊ के सूक्ष्म यंत्र निर्माणशला में वर्तमान १,००० जलमापक यंत्रों की अपेक्षा आयोजन काल तक प्रति मास ३,००० जलमापक यंत्रों का निर्माण होने लगेगा। उद्योग की उन्नति के साथ साथ श्रम-कल्याण की दिशा में भी विशेष प्रयत्न किया जा रहा है।

राष्ट्रीकृत यातायात

सन् १९४७ में सरकारी रोडवेज में केवल ६ बसें थीं जबकि आज १,६६८ बसें, १४० ट्रकें और ५२ टैक्सियां हैं। ये बसें लगभग ६,००० मील लम्बे ३४२ मार्गों पर चलती हैं और प्रतिदिन औसतन डेढ़ लाख व्यक्ति इन बसों से सफर करते हैं। अनुमान है कि रोडवेज की सभी बसें प्रतिदिन कुल ९६,००० मील चलती हैं। रोडवेज की इस व्यवस्था पर ४ करोड़ ३० लाख रुपये की पूंजी लगी है और इससे १०,००० व्यक्तियों को रोजगार मिला है।

सड़कों एवं पुलों का विस्तार

आर्थिक विकास की दिशा में पहला चरण सड़कों एवं पुलों की सुरक्षा एवं विस्तार है। देश के स्वतन्त्र होने से पूर्व उत्तरप्रदेश में केवल ९,३०० मील पक्की तथा २५,५०० मील कच्ची सड़कें थीं किन्तु अब इस राज्य में ११,४३० मील पक्की तथा २३,५७७ मील कच्ची सड़कें हैं।

यातायात में पुलों के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए देश के स्वतन्त्र होने के समय से अब तक ९५ लाख रुपये की लागत से २६ प्रमुख पुलों का निर्माण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त २ करोड़ रुपये की लागत से २२ प्रमुख पुल और भी बनवाये जा रहे हैं जो कि अभी तक पूरे बनकर तैयार नहीं हुए हैं।

कचलाघाट में बरेली-मथुरा सड़क हर रेलवे पुल भी बनकर तैयार हो रहा जिसका निर्माण कार्य शीघ्र ही समाप्त होने वाला है। गढ़मुक्तेश्वर जिला मेरठ में भी गंगानदी पर एक सड़क का पुल बनवाया जा रहा है जो कि राज्य के सभी पुलों से अधिक बड़ा और लम्बा होगा। इन पुलों के अतिरिक्त अन्य १७ बड़े पुलों के नकशे बनकर तैयार हो गए हैं तथा व्यय का अनुमान भी किया जा चुका है और शीघ्र ही इनके निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायगा।

सामुदायिक योजनाएं

राज्य में विकास खंडों की वर्तमान संख्या १६१ है जिनमें तीन अग्रगामी विकास योजना की इकाइयां, ६ नवोद्घाटित राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड, २६ सामुदायिक योजना खंड तथा ५३ प्रगाढ़ विकास खंड हैं। इन विकास खंडों के अन्तर्गत २५,७९२ गांव हैं जिनका क्षेत्रफल २८९६२.७२ वर्गमील तथा जनसंख्या १,१३,६७,६०० है।

उन्नत बीजों के वितरण का कार्यक्रम अनुमानित लक्ष्य से भी आगे बढ़ चुका है और १६,६९,०२६ मन उन्नत बीजों का वितरण किया जा चुका है जिसमें से लगभग सात लाख मन बीज की खपत विकास खंडों में हुई है। उन्नत बीजों के प्रयोग के अतिरिक्त उर्वरकों के उचित प्रयोग तथा खेती के उन्नत ढंगों को प्रदर्शनों द्वारा किसानों में लोकप्रिय बनाया जा चुका है। अब तक ९,२१,६३१ मन उर्वरक बांटे जा चुके हैं तथा किसानों के लाभार्थ २,३४,०२६ प्रदर्शन किये गये हैं।

श्रमदान, पंचायत, हरिजन सेवा, शिक्षा, चिकित्सा आदि समाज निर्माण की विविध प्रवृत्तियों में भी उत्तर प्रदेश ने इन पांच वर्षों में जो उन्नति की है, वह कम सन्तोषजनक नहीं है, यद्यपि भावी योजनाएं उससे भी बड़ी और महत्वाकांक्षा पूर्ण हैं।

सफ़ेद कोढ़ के दाग

हजारों के नष्ट हुए और सैकड़ों के प्रशंसापत्र मिल चुके

दवा का मूल्य ५) रु० डाक व्यय १) रु०

अधिक विवरण मुफ्त मँगाकर देखिये।

वैद्य के० आर० बोरकर

मु० पो० मंगरूलपीर, जिला अकोला (मध्य प्रदेश)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मध्यप्रदेश समृद्धि की नई आशाओं से पूर्ण

नवीन मध्यप्रदेश का क्षेत्रफल १७१,२०० वर्ग मील है तथा इसकी जनसंख्या २६१ लाख से भी अधिक है। भारत के नवीन मानचित्र में यह बम्बई के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। कृषि तथा उद्योग में उचित संतुलन बनाये रखना, राज्य की अर्थ व्यवस्था की विशेषता है। यहां परती भूमि को कृषि योग्य बनाने का विस्तृत क्षेत्र है और भूगर्भ में अपार खनिज सम्पत्ति छिपी हुई है। राज्य में नर्मदा, चम्बल, बेतवा, ताप्ती और इन्द्रावती जैसी विशाल नदियों के कछार हैं और खाद्यान्न तथा अन्य अर्थकारी फसलों से भी खूब उत्पादन होता है। इन सबके कारण आर्थिक दृष्टि से यह राज्य एक आदर्श इकाई है।

कृषि—राज्य में अनेक प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मालवा क्षेत्र में कपास के लिये उर्वरा काली मिट्टी है तो नर्मदा घाटी में गेहूं और चना के लिये उपयुक्त मिट्टी के भंडार छत्तीसगढ़ के मैदानों में अधिक धान की फसल उपजाने वाली पीली रेतीली मिट्टी पाई जाती है। इन सभी फसलों के कारण राज्य खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्म-निर्भर हो गया है। कुल कृषि क्षेत्र का सिंचित क्षेत्र केवल लगभग ५ प्रतिशत होने के बावजूद (जबकि समस्त भारत में सिंचित क्षेत्र औसतन १७ प्रतिशत है) अन्न उत्पादन के क्षेत्र में इस राज्य का स्थान उत्तरप्रदेश के बाद दूसरा है। राज्य में कृषि के अन्तर्गत कुल ३ ५२,३०,००० एकड़ भूमि है जो कि सम्पूर्ण क्षेत्र का ५६.३ प्रतिशत है। भारत में, ज्वार उत्पादन में राज्य का स्थान प्रथम, गेहूं उत्पादन में द्वितीय, चना उत्पादन में तृतीय, तिलहन उत्पादन में चतुर्थ तथा चावल उत्पादन में पाँचवाँ है। सन् १९५५ में लगभग १५,००० एकड़ क्षेत्र में जापानी तरीके से धान की खेती की गई। यहां कपास, तिलहन, और गन्ने के समान अर्थकारी फसलों का भी बाहुल्य है। राज्य में कपास के अंतर्गत १८,८९,००० एकड़ क्षेत्र, तिलहन के अन्तर्गत ३५,५२,००० एकड़ क्षेत्र, तथा गन्ने के अन्तर्गत ८८,००० एकड़ क्षेत्र है। राज्य का लगभग एक तिहाई भाग वनों से आच्छादित है, जहां देश की सर्वोत्तम किस्म की लकड़ी पैदा होती है।

खनिज—समस्त राज्य भर में फैली हुई लग २९० खदानों से विभिन्न प्रकार के २० खनिज निकाले रहे हैं। बालाघाट, छिंदवाड़ा और इन्दौर के समीप खदानों से निकाले गये मैंगनीज से सन् १९५१ में ५ लाख रु० की धन राशि प्राप्त हुई। छत्तीसगढ़ क्षेत्र प्राप्त कोयला, लोहा और मैंगनीज के अक्षय भण्डार रा को देश का औद्योगिक केन्द्र बना देने में समर्थ हैं। के बस्तर के कच्चे लोहे के खनिज भंडार ही इतने विस्तृत व्यापक हैं कि वे कई शताब्दियों तक सम्पूर्ण देश तत्सम्बन्धी आवश्यकता पूरी कर सकते हैं। अमरकं बालाघाट, बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़ और सिवनी जि में बाक्साइट के भंडार हैं। सीधी, रीवा, पन्ना, छत्त और टीकमगढ़ में कोयला, ओकरी, सिलिमनाइट, कुरन और हीरा आदि खनिज निकाले जा रहे हैं। सीमेन्ट उद्य के लिए आवश्यक चूने का पत्थर उत्तरी क्षेत्रों में बहुता से पाया जाता है। हीरा उत्पादन में राज्य का एकाधि पूर्ण स्थान है। पन्ना की हीरा खदानें लगभग २४ वर्ग मी के क्षेत्र में फैली हुई है और इन्हें भारत के ९० प्रति हीरा उत्पादन का श्रेय प्राप्त है।

औद्योगिक विकास

औद्योगिक विकास के क्षेत्र में अभी हाल ही में रा ने कुछ उल्लेखनीय प्रगति की है। नेपा की अखबारी का मिल, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रमुख औद्योगिक यो नाओं में से थी। इस मिल ने निर्धारित अवधि में उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है। यह मिल भारत में अप किस्म की पहली ही है। इसमें अखबारी कागज का उ दन १०० टन प्रतिदिन अथवा लगभग ३०,००० टन प्र वर्ष है और आशा की जाती है कि यह देश की एक ति अखबारी कागज की जरूरत को पूरा करके बिदेश विनि में २२ करोड़ रु० वार्षिक की बचत करेगी। यह प्रतिदिन ९०।६५ टन अखबारी कागज पैदा कर रही है यह कागज विदेशी अखबारी कागज की समता का है।

कटनी के पास केमूर में देश की सबसे बड़ी सीमे

[सम्पू

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

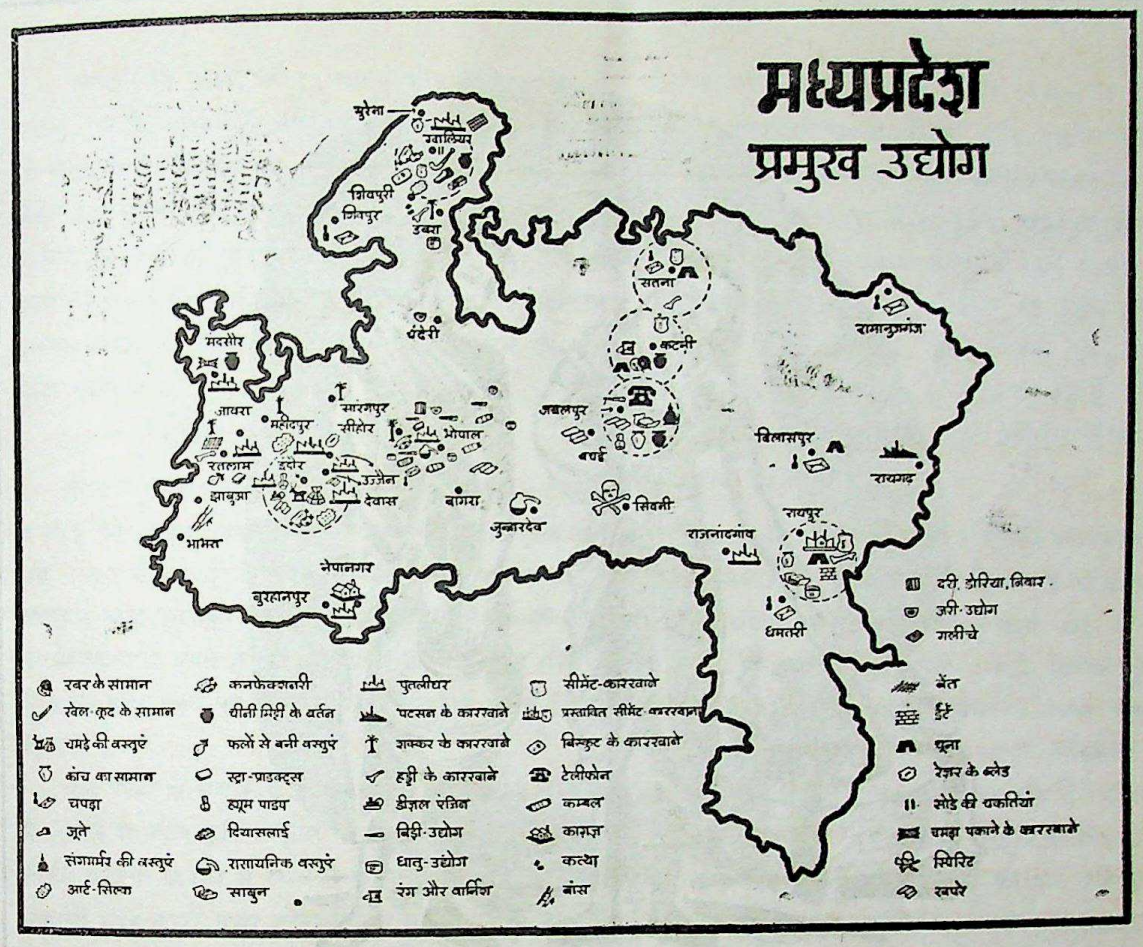

फैक्टरी स्थित है और सन् १९५४ में इसका उत्पादन ३,८३,००० टन था। बिलासपुर के निकट मोहतरा में एक अन्य सीमेन्ट फैक्टरी की स्थापना हेतु भी लायसेंस दिया गया है। प्रारम्भ में इस फैक्टरी में प्रति वर्ष २,१६,००० लाख टन पोर्टलेन्ड सीमेन्ट का उत्पादन होगा जो कि बाद को बढ़ कर ३३,००० लाख टन प्रति वर्ष हो जायगा। इसके पश्चात् दुर्ग के पास ११५ करोड़ की लागत से निर्मित भिलाई इस्पात कारखाना है, जिसमें १० लाख टन प्रति वर्ष पैदा करने की क्षमता है। सन् १९५९ से यहां उत्पादन प्रारम्भ हो जाने की आशा है। २४ मील लम्बी चापा कोरबा रेलवे लायन के खुलने से भिलाई और राउरकेला इस्पात कारखानों को कोरबा कोयला खदानों से लगभग ५०० वैगन कोयले की पूर्ति करने में सुविधा हो गई है। ये खदानें सरकार द्वारा खोली जा रही हैं। भोपाल के निकट २५ करोड़ रु० की लागत से खुलने वाली बिजली के भारी सामान की फैक्टरी देश में अपने किस्म की पहली ही होगी। सन् १९५८ में फैक्टरी के बन जाने पर यह बिजली के विभिन्न औजारों सम्बन्धी देश की अधिकांश आवश्यकता पूरी करेगी। फैक्टरी के पास ही एक विद्युत प्रशिक्षण केन्द्र भी खोला जायगा जो औद्योगिक और विद्युत कारखानों को तांत्रिक-टेक्निकल-शिक्षा प्राप्त कर्मचारियों की पूर्ति करेगा। कोरबा में एक सिन्थटिक पेट्रोल फैक्टरी, सुखेडा के पास एक सीमेन्ट फैक्टरी, शिवपुरी के पास एक कागज मिल, डबरा में एलकोहल फैक्टरी, तथा उज्जैन में एक वृहत तेल मिल खोलने के लिये प्रारम्भिक कार्यवाही की गई है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आओ बहन भरलो पानी!

पानी पर हमारा जीवन निर्भर है, पानी ही हमारे शरीर को स्वच्छ करता है, हमारी प्यास बुझाता है। भगवान की यह देन हम सभी के लिए है।

आइये, बंधुत्व की श्रेष्ठ भावना से हम हृदय ओतप्रोत करलें। हम अपने भाई-बहिनों की तरह हरिजनों को भी प्यार से गले लगाएं।

हिंदू शास्त्रों में अस्पृश्यता नाम की कोई चीज ही नहीं है:-
महात्मा गांधी।

"छूतछात को छोड़ो,
दिल को दिल से जोड़ो।"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चन्देरी की साड़ी, चमड़ा, कपड़ा और मिट्टी के खिलौने बर्तन, चटाई, लाख और नारियल की चूड़ियां, कांसा, धातु के बर्तन आदि परम्परागत गृहोद्योगों और हस्तशिल्प के लिए इस राज्य के बहुत से भाग प्रसिद्ध हैं। हाथ करघा उद्योग का इनमें महत्वपूर्ण स्थान है, जिससे कि राज्य में लगभग ७०,५०० व्यक्तियों को काम मिला है। केन्द्रीय सिल्क मंडल ने कोसा उद्योग के विकास के लिये सरगुजा और चांपा में एक योजना स्वीकृत की थी।

प्रथम पंचवर्षीय योजना

विलीन होने वाले चारों राज्यों में विगत ३१ मार्च १९५६ को प्रथम पंचवर्षीय योजनायें सफलतापूर्वक पूरी हुईं। इन योजनाओं ने जनता में अत्यधिक उत्साह जागृत किया है और अधिक प्रगतिशील और बहुमुखी अर्थ व्यवस्था का शिलान्यास हुआ है। चारों राज्यों की पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य और व्यय का अलग अलग विवरण नीचे दिया जा रहा है—

इन अंकों से यह स्पष्ट है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में अधिकांश व्यय कृषि विकास पर हुआ है और परिणाम-स्वरूप योजना अवधि में राज्य ने खाद्योत्पादन में वृद्धि की। तालाबों और कुओं द्वारा जो अतिरिक्त क्षेत्र कृषि के अंतर्गत लगाया गया है, वह लगभग ३,२४,२५६ एकड़ है।

सामुदायिक विकास योजना और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की कार्यान्विति से भी कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। वर्तमान मध्यप्रदेश के ५५९५२ वर्गमील क्षेत्रफल के अंतर्गत आने वाले २३३८८ गाँवों में रहने वाली ९९,२७,२७९ जनसंख्या को इस कार्यक्रम का लाभ पहुंचा है। फिलहाल १६२ विकास खंड, जिनमें ४९ सामुदायिक विकास खंड भी सम्मिलित है, कार्य कर रहे हैं और इनके अन्तर्गत राज्य का लगभग ३० प्रतिशत क्षेत्रफल और जनसंख्या आ जाती है।

१० बड़ी योजनाओं में से ३ भूतपूर्व मध्यभारत और ७ भूतपूर्व मध्यप्रदेश में थीं। इनमें से ६ पूरी भी हो चुकी हैं। योजना अवधि में २३ छोटे सिंचाई कार्य भी पूरे हो चुके हैं। नल कूप योजना में भी इसका विस्तार हुआ है। आगामी वर्षा ऋतु के बाद लगभग ९० हजार एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र सिंचाई के अन्तर्गत लाया जायगा। चम्बल घाटी योजना उल्लेखनीय प्रगति कर रही है यह राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई और विद्युत योजना है। इससे १४ लाख एकड़ भमि की सिंचाई की जा सकेगी, जिसके फलस्वरूप प्रति वर्ष ४,७५,००० टन खाद्यान्न अतिरिक्त

प्रथम पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य और व्यय (लाख रुपयों में)

क्रमाँक	विषय	मध्य प्रदेश		मध्य भारत		विन्ध्य प्रदेश		भोपाल	
		लक्ष्य	व्यय	लक्ष्य	व्यय	लक्ष्य	व्यय	लक्ष्य	व्यय
१.	कृषि	१४१५.०	१३५५.१	४८०.०९	४८९.०३	२०४.७०	१२४.४९	१७३.००	१६०,०४
२.	दुग्धशाला व पशु पालन	१३४.८	१२९.९	५७.२०	३५.५२	१४.४०	९.४१	७.००	८.८२
३.	वन	३९.७	३९.०	४८.१४	४६.०१	२२.५०	१३.६४	२०.००	१५.५५
४.	सहकारिता	२८.८	२०.४	२५.००	२५.४०	३.००	२.००	५.००	३.४३
५.	ग्राम विकास	१२४.३	१११.४	१७६.३८	१७०.६७	६.००	१.८६	.	.
६.	मत्स्य पालन	६.२	५.९	७.४७	७.००	१.२०	१.२३	२.००	२.०५
७.	सिंचाई	२३८.५	३२४.९	२८९.७०	१९१.१२	.	.	९.७०	३.२९
८.	विद्युत	७१९.२	६००.०	२८८.२८	२४०.७०	७२.५०	२६.८७	३०.८६	२०.५६
९.	उद्योग	२९४.४	३१५.२	७२.५५	४१.३६	.	.	२४.०	२०.१७
१०.	यातायात	२१७.८	२१८.०	२७८.०४	२१४.२२	१२५.९०	९१.९७	४९.००	५६.५९
११.	समाज सेवा	१६४१.५	१५६४.७	५९६.०९	५३२.७७	२४०.८०	१४९.३३	१८५.०४	१९९.३१
	कुल योग	४८६०.२	४६८४.५	२३१८.९४	१९९३.८४	६९१.००	४२०.८०	५०६.३०	४८९.८१

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उत्पन्न होने लगेगा। इस योजना से २,१०,००० किलोवाट विद्युत शक्ति पैदा की जायगी। गांधी सागर बांध का केन्द्रीय खंड, नींव से ५५ फीट ऊपर तक निर्मित किया जा चुका है। कोटा बांध और नहर का कार्य भी भलीभांति चल रहा है।

विद्युत शक्ति के क्षेत्र में प्रगति सन्तोषजनक है। भूतपूर्व मध्यप्रदेश, मध्यभारत, भोपाल और विन्ध्यप्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता को मिला कर कुल विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग १,३०,००० किलोवाट है, जो विद्युत योजनायें निर्माण की स्थिति में है उनमें २,१०,००० किलोवाट क्षमता वाली चम्बल विद्युत योजना, १४२ लाख रु० की लागत तथा ९० हजार किलोवाट बिजली पैदा करने वाला कोरबा थर्मल स्टेशन, २५ हजार किलोवाट की क्षमता वाला ग्वालियर थर्मल स्टेशन, सतना थर्मल स्टेशन, कटनी बिजली स्टेशन और भोपाल विद्युत योजना सम्मिलित है।

राज्य में १५,२१७ मील लम्बी सड़कें हैं। आज जो स्थिति दिख रही है वह पांच वर्ष पूर्व की स्थिति से बहुत सुधरी हुई है।

विगत वर्षों की हमारी गतिविधियों का पर्यवेक्षण इस बात का सूचक है कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत की गई प्रगति द्वारा संतुलित, योजनाबद्ध और सर्वतोमुख आर्थिक विकास हुआ है, जिसका उद्देश्य जनता के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना है। प्रथम योजना से कहीं अधिक महात्वाकांक्षी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसका अनुमानित व्यय १९०९०.२७ लाख रु० है, कार्यान्वित की जा रही है। विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत योजना अवधि में होने वाला व्यय निम्नानुसार है :—

द्वितीय योजना		लाख रुपयों में
१. कृषि और सामुदायिक विकास	...	५०४९.४
२. सिंचाई और विद्युत	...	६४९१.७
३. उद्योग और खनिकर्म	...	१०५२.५
४. यातायात और आवागमन ५. व्यापार और वाणिज्य	...	१२९९.६
६. शिक्षा	...	२०५२.७
७. स्वास्थ्य	...	१४३३.१
८. गृह निर्माण	...	४५०.२
९. अन्य सामाजिक सेवायें	...	९२६.३
१०. विविध	...	३३४.४
	कुल	१९०९०.२

———

भारत सरकार के व्यापार और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित

'उद्योग व्यापार पत्रिका'

★ उद्योग और व्यापार सम्बन्धी प्रामाणिक जानकारी युक्त विशेष लेख, भारत सरकार की आवश्यक सूचनाएं, उपयोगी आंकड़े आदि प्रति मास दिये जाते हैं।

★ डिमाई चौपेजी आकार के ६०-७० पृष्ठ : मूल्य केवल ६ रुपया वार्षिक। एजेण्टों को अच्छा कमीशन दिया जायगा। पत्रिका विज्ञापन का सुन्दर साधन है।

★ लघु-उद्योग विशेषांक मंगा कर छोटे उद्योगों के सम्बन्ध में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त कीजिये।

★ ग्राहक बनने, एजेन्सी लेने अथवा विज्ञापन छपाने के लिए नीचे लिखे पते पर पत्र भेजिये :—

सम्पादक

उद्योग व्यापार पत्रिका

व्यापार और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

SOVIET BOOKS

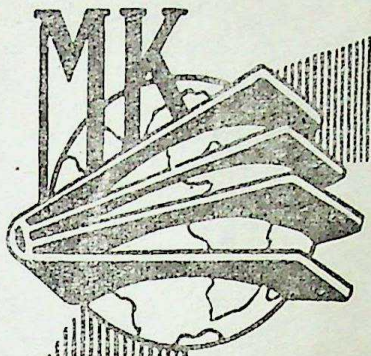

VSESOJUZNOJE OBJEDINENIJE
"MEZHDUNARODNAJA KNIGA"

Exports:

Social-political, belles lettres and children's literature, Books in all spheres of science, culture and technique, Soviet newspapers and magazines, Music, Post-cards, Reproduction of paintings, Portraits, Albums, Stamps for collections, Ordinary and long-time gramophone records, Recordings of musical works

SOVIET PUBLICATIONS AVAILABLE WITH

People's Publishing House, Private Ltd.
Asaf Ali Road, New Delhi.
People's Book House opp. B. N. College, Patna 4.
Peoples Book House, 7 Bishweswarnath Road, Lucknow.
P. P. H. Bookstall, 421 Vallabhbhai Patel Road, Bombay 4.

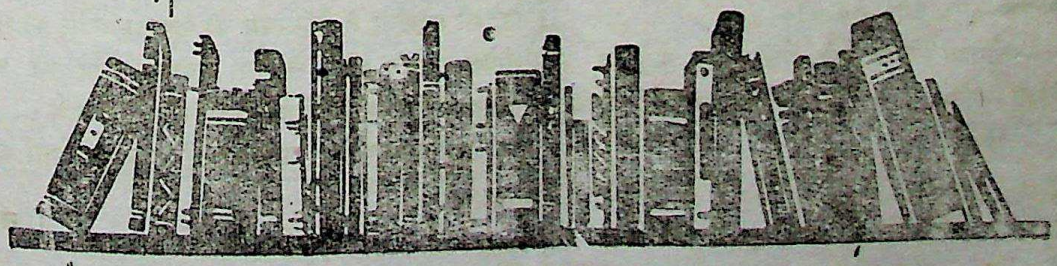

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लीपजीग की प्रसिद्ध औद्योगिक प्रदर्शनी

सम्पदा के पाठकों को यह मालूम ही है कि आगामी ३ मार्च से १४ मार्च तक लिपजिग का औद्योगिक मेला हो रहा है। इसके विशाल प्रांगण के छठे भाग में ४० भिन्न-भिन्न देश अपने उत्पादन पदार्थों का प्रदर्शन करेंगे। इस तरह यह मेला अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। विभिन्न उद्योगों का इस तरह वर्गीकरण किया जायेगा कि उनका सर्वेक्षण शीघ्र किया जा सके। विभिन्न देशों के वर्गीकरण के साथ-साथ पदार्थों का सामूहिक प्रदर्शन किया जायेगा ताकि थोक व्यापारी एक-साथ विविध देशों की वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कर सकें।

विविध १७ देशों की सरकारी ऐजेन्सियां या ट्रेड कार्पोरेशन इस मेले में अपने पदार्थों का प्रदर्शन करेंगे। रूस, चैकोस्लाविकिया, पोलैण्ड, हंगरी, बलगेरिया, ब्रिटेन, बैल्जियम, फ्रांस, आस्ट्रिया और भारत तो पहले की भांति इस मेले में सम्मिलित होंगे ही, लेकिन इस बार मेले की एक विशेषता यह है कि युगोस्लाविया, डेन्मार्क, आइसलैण्ड, ग्रीस टर्की, और ट्यूनिशिया भी पहली बार अपनी वस्तुओं का एक-साथ प्रदर्शन करने के लिये सम्मिलित हो रहे हैं।

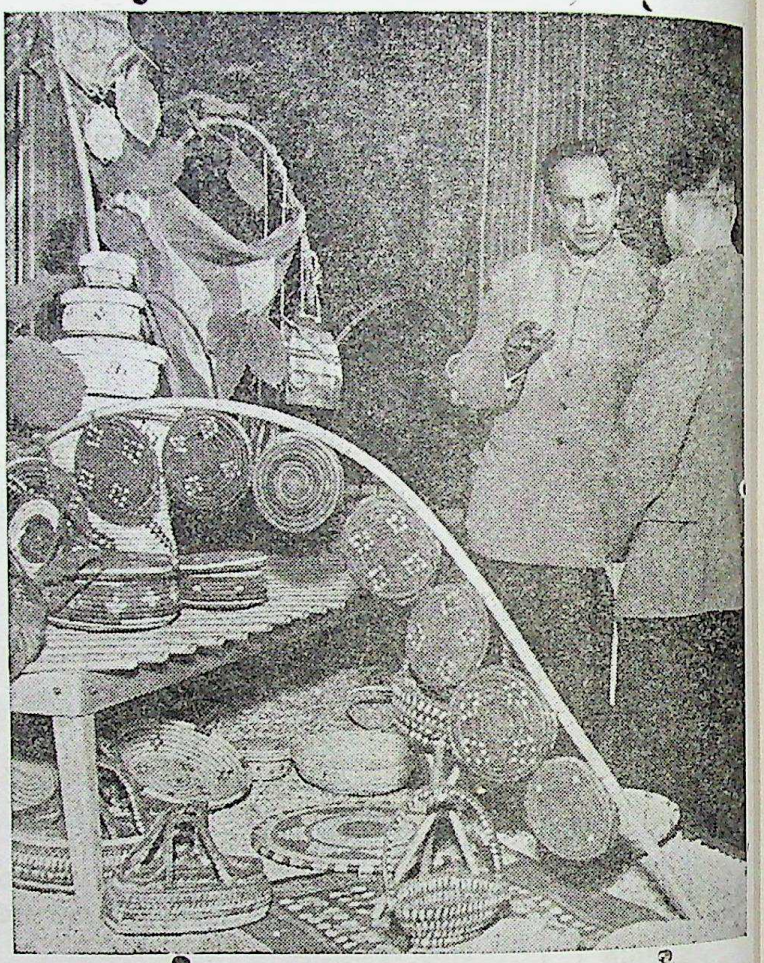

प्रदर्शनी में भारतीय मण्डप का एक दृश्य

इस मेले की कुछ अन्य विशेषतायें ये हैं कि विभिन्न विदेशी प्रदर्शक देशों के प्रमुख संस्थान इसमें अपनी प्रसिद्ध वस्तुओं का प्रदर्शन करेंगे, जिनमें से निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं—

बैलजियम—ए० ओ० ई० सी०

ब्रिटेन—स्टैण्डर्ड मोटर्स, पाई, मैसी हैरिस, फर्गुसन

आस्ट्रिया—शौलर ब्लैक मान और श्राक इलैक्ट्रिजिटेट ए० जी०

फ्रांस—रैनाल्ट, इकलेयर, सिमका

लक्समबर्ग—सिकाल्ट

स्विट्जरलैण्ड—सैण्डोज, गीगी तथा सूक्ष्म औजार आदि के निर्माता।

डैन्मार्क और स्वीडन के अनेक निर्माता भी इसमें अपनी वस्तुओं का प्रदर्शन करेंगे। उपभोक्ता वस्तुओं के विदेशी प्रदर्शनों में बैल्जियम की फेबल्टा, फ्रांस की मार्टिल, सोपेल, कोटि और लेलोंग, स्वीट्जरलैण्ड की ओमेगा जैनिथ आदि कम्पनियों की वस्तुएँ उल्लेखनीय हैं।

विशेष आकर्षण का यह केन्द्र विदेशी उद्योगों के सह

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

योग से पश्चिमी और उत्तरी यूरोप के देशों से आने वाली खाद्य और तत्सम्बन्धी वस्तुओं का प्रदर्शन करेगा। पुर्तगाल, इटली, ग्रीस, टर्की, पूर्वी एशिया और लैटिन अमेरिका के देश भी अपने उत्पादनों का प्रदर्शन करेंगे। ब्राजील, चिल्ली, कोलम्बिया, जमैका और बोलिविया आदि भी पहली बार इस वर्ष इस मेले में भाग ले रहे हैं। मुद्रण, रसायन, औषधि निर्माण तथा वस्त्र आदि के उद्योगों में विदेशी कम्पनियाँ अपने-अपने प्रदर्शन करेंगी।

जहां पश्चिमी यूरोप और अमेरिका के पूंजीवादी देश अपने उद्योगों का विशेष प्रदर्शन करेंगे, वहां रूस, चेकोस्लावेकिया और पोलैण्ड आदि साम्यवादी देश भी अपनी वस्तुओं का, जिनका निर्यात किया जा सकता है, विशेष प्रदर्शन करेंगे। इन देशों ने मेले में अपनी वस्तुओं के प्रदर्शन के लिये काफी स्थान सुरक्षित कर लिया है। हंसा हाऊस नामक खण्ड में साम्यवादी देशों के प्रकाशित साहित्य का प्रदर्शन किया जायेगा।

रूस ने प्रधान उद्योगों में जो चमत्कार पूर्ण उन्नति की है, उसका प्रदर्शन इस मेले की प्रधान विशेषता होगी। बड़ी मशीनें, औटोमेटिक मशीन टूल, कृषि के यंत्र, वाहन, मकान आदि बनाने की मशीनरी के साथ-साथ लोह उद्योग की अन्य वस्तुयें भी दिखाई जायेंगी। चेकोस्लावेकिया और पोलैण्ड भी आधारभूत उद्योग तथा खनिज यंत्रों व कोयले से निर्मित रासायनिक पदार्थों का प्रदर्शन करेंगे।

चीन भी अपनी नई औद्योगिक उन्नति का विविध प्रदर्शन करके यह बतायेगा कि उसने कुछ वर्षों में कितनी असाधारण उन्नति कर ली है।

हंगरी और बल्गेरिया भी मशीन टूल, गाड़ियां, मापन यंत्र, इंजीनियरिंग उद्योग, विद्युत उद्योग आदि के प्रदर्शन करेंगे। इस तरह यह मेला औद्योगिक दृष्टि से व्यापारियों व उद्योगपतियों के लिए बहुत लाभकारी होगा।

——

सम्पदा में विज्ञापन देकर लाभ उठाइये।

हिन्दी और मराठी भाषा में प्रकाशित होता है :

उद्यम

धर्मपेठ, नागपुर

सर्वोपयोगी हिन्दी उद्यम प्रतिमाह १५ तारीख को पढ़िये

उद्यम के स्थायी स्तम्भ

उद्यम में निम्न विषयों पर लेख प्रकाशित होते हैं

★ लाभदायक उद्योगधन्धों की व्यावहारोपयोगी जानकारी, अनाज की खेती, साग-सब्जी की बागवानी और रोगों का निवारण। पशुपालन, दुग्ध-व्यवसाय और ग्रामोद्योग-सम्बन्धी लेख। आरोग्य, घरेलू औषधियों सम्बन्धी जानकारी।

★ महिलाओं तथा विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त विभिन्न रुचिकर खाद्य पदार्थ बनाने की विधियां। घरेलू मितव्ययता। जिज्ञासु जगत्। कृषि व औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों की मुलाकात और परिचय। नित्योपगी वस्तुएं घर पर ही तैयार कीजिये।

आज ही उद्यम का वार्षिक चन्दा ७ रु० भेजकर उद्यम मासिक मंगवाइये।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नया सामयिक साहित्य

भूदान यज्ञ क्या और क्यों—ले० श्री चारुचन्द्र भण्डारी। प्रकाशक—अ० भा० सर्व सेवा संघ प्रकाशन, बनारस। मूल्य १) रु०।

प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने बहुत विस्तार के साथ सर्वोदय, भूदान, आचार्य बिनोवा के विचार आदि की विस्तार से चर्चा की है। भूदान यज्ञ के संबंध में उठने वाली शंकाएं, भूदान के कार्य में आने वाली व्यावहारिक समस्याएं, अधिकतम सीमा निर्धारण, ग्राम राज्य, ग्राम दान आदि के बीसियों प्रश्नों की चर्चा करके उनका उत्तर देने की चेष्टा की गई है। विविध प्रश्नों पर आचार्य बिनोवा के विचार उन्हीं के उद्धरण देते हुए बताये गए हैं। संक्षेप में भूदान, उसके दर्शन तथा व्यावहारिक प्रवृत्तियों और समस्याओं को समझने के लिए यह पुस्तक अच्छा काम देगी।

सर्वोदय भजनावलि—प्रकाशकः— अ० भा० सर्व-सेवा-संघ प्रकाशन काशी। मूल्य ।)

प्रस्तुत पुस्तिका में प्रायः उन भजनों का संग्रह किया गया है, जो आचार्य बिनोवा की प्रार्थना सभाओं में गाये जाते हैं। इसमें ११० हिन्दी भजन और २० मराठी भजन, २६ गुजराती भजन दिए गए हैं। कुछ बंगला, उड़िया, सिन्धी और अंग्रेजी के भजन भी दिए गए हैं। प्रारम्भ में ईशोपनिषद तथा गीता के स्थितप्रज्ञ-प्रकरण के हिन्दी पद्यानुवाद दिए गये हैं।

छात्रों के बीच—लेखक—श्री जयप्रकाश नारायण। प्रकाशक—अ० भा० सर्व-सेवा-संघ प्रकाशन, बनारस। मूल्य ।) आने।

प्रस्तुत पुस्तिका में विद्वान नेता के भाषणों का, जो उन्होंने सर्वोदय के सम्बन्ध में दिये थे, संग्रह है। अत्यन्त सरल भाषा में सर्वोदय और भूदान को समझने के लिए यह पुस्तक उपादेय होगी।

सामाजिक क्रान्ति और भूदान—लेखक—श्री जे० बी० कृपलानी। प्रकाशक—अ० भा० सर्वसेवा संघ प्रकाशन। मूल्य ।-) आना

आचार्य कृपलानी की इस पुस्तिका की विशेषता यह है कि इसमें उस शिक्षित वर्ग को भूदान की क्रान्ति समझाने का प्रयत्न किया गया है, जो केवल भावुकता और श्रद्धा में विश्वास नहीं रखता।

आलमे खयाल—लेखक—शौक किदवाई,

जहरे इश्क—लेखक—शौक लखनवी।

दोनों के प्रकाशक—अदबी पब्लिशर्स, ८ शैफर्ड रोड बम्बई—८। मूल्य क्रमशः १॥।=) और २।) रु० सजिल्द।

दोनों पुस्तकों में उर्दू के दो प्रसिद्ध कवियों की प्रेम सम्बन्धी कविता है। इनकी लिपि नागरी है, किन्तु भाषा उर्दू है। जहरे इश्क की भाषा में फारसी शब्द अधिक होने से केवल हिन्दी पढ़े लिखे शायद बहुत रस नहीं ले सकेंगे। दोनों में एक कथा का रूप देकर प्रेम काव्य लिखा गया है। दोनों की शैली सरल व मनोरंजक है। दोनों पुस्तकों की छपाई सफाई और गैट-अप बहुत आकर्षक है। उर्दू काव्य प्रेमियों का इनसे पर्याप्त मनोरंजन होगा।

—कृष्ण

बौद्ध धर्म के २५०० वर्ष—(आजकल का वार्षिक अंक)—सम्पादक—श्री पी० वी० बापट और श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार। पृष्ठ २५६। मूल्य ३) रुपए।

केन्द्रीय सरकार के पब्लिकेशन डिवीजन द्वारा प्रकाशित होने वाले मासिक पत्र 'आजकल' ने अपने दिसम्बर अंक को 'बौद्ध धर्म के २५०० वर्ष के नाम से पुस्तकाकार विशेषांक के रूप में निकाला है। बौद्ध धर्म के आज तक के २॥ हजार वर्षों को २॥ सौ के लगभग पृष्ठों में समेटने का सराहनीय प्रयत्न किया गया है। अंक बौद्ध धर्म सम्बन्धी समस्त जिज्ञासा को तृप्त करने में समर्थ है। बौद्ध धर्म का प्रारम्भ तथा कुछ चरित्र, चार बौद्ध परिषदें, अशोक और बौद्ध धर्म का विस्तार, बौद्ध साहित्य, बौद्ध शिक्षण, बौद्ध कला का संक्षिप्त पर्यवेक्षण, बौद्ध धर्म और आधुनिक संसार आदि अध्यायों में बौद्ध धर्म की 'व्यापकता' पर प्रकाश डाला गया है। भिक्षु जिनानन्द, राहुल सांकृत्यायन, अनागरिक गोविन्द जैसे बौद्ध दर्शन के विद्वान् लेखकों का सहयोग इस अंक को

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त कई चित्रों नक्शों और चार्टों के द्वारा अंक को सर्वांगपूर्ण बनाया गया है।

कुल मिलाकर अंक बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोष कहा जा सकता है। छपाई सफाई उत्तम है। अंक उपयोगी और संग्रहणीय है।

आर्थिक-समीक्षा—(इन्दौर कांग्रेस अधिवेशनांक) प्रधान सम्पादक—श्री श्रीमन्नारायण, सम्पादक श्री हर्षदेव मालवीय। पृष्ठ २१२। मूल्य १॥ रु०।

'आर्थिक समीक्षा' अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आर्थिक राजनैतिक अनुसन्धान विभाग का पाक्षिक पत्र है। इन्दौर कांग्रेस के अवसर पर इसने अपना सुन्दर विशेषांक निकाला है। । विशेषांक में अनेक महत्त्वपूर्ण आर्थिक लेख—मुद्रा-स्फीति, योजना, कर, उद्योग आदि अनेक क्षेत्रों को लेकर अधिकारी व्यक्तियों द्वारा लिखे गए हैं। समाजवादी व्यवस्था के अन्तर्गत पूंजी निर्माण, हमारा आयोजन व कठिनाइयां और करनीति की प्रवृत्तियाँ, लेख पठनीय हैं। भारत और विभिन्न राज्यों की आर्थिक गतिविधि का भी उल्लेख कुछ लेखों में हुआ है। इस अंक में आर्थिक ही नहीं, शिक्षा समाज, संस्कृति आदि पर भी लेख दिए गए हैं। अनेक कविताओं के चयन से अंक सरस भी हो गया है।

अंक उपयोगी व संग्रहणीय है।

साप्ताहिक मजदूर संदेश—कांग्रेस अधिवेशन अंक-प्रधान सम्पादक—श्री लाड़लीप्रसाद सेठी, पृष्ठ ८८। मूल्य १२ आने।

इन्दौर कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर मध्यप्रदेश राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के मुख पत्र मजदूर संदेश ने अपना कांग्रेस अधिवेशन अंक प्रकाशित किया है। कांग्रेस और मजदूर सम्बन्धी कई लेखों के अतिरिक्त इसमें कविता कहानी भी दी गई है। कार्टून और परिचयात्मक चित्रों से अंक की सजीवता बढ़ गई है।

अंक उपयोगी और संग्रहणीय है।

—म० मो० बि०

—

सड़कों का महत्व

[पृष्ठ ९२ का शेष]

सहायता से स्थानीय विकास कार्यों के कार्यक्रम द्वारा गांवों की सड़कों में बहुत वृद्धि की जाएगी। आशा है, दूसरी योजना के अन्त तक नागपुर योजना का लगभग दो तिहाई लक्ष्य पूरा हो चुकेगा।

अगर योजना में प्रस्तावित लक्ष्य पूरे हो जाते हैं तो भी सड़कों के अभाव में लाखों गांव ऐसे होंगे, जहां यातायात का एक मात्र साधन बैलगाड़ी ही रहेगी। बैलगाड़ी से हमारे देश में अभी भी यातायात के सभी दूसरे साधनों की अपेक्षा ज्यादा माल ढोया जाता है। एक अनुमान के अनुसार अन्तर्देशीय कुल ढोये जाने वाले माल का लगभग ७० प्रतिशत इन्हीं बैलगाड़ियों द्वारा ढोया जाता है। तो भी उनके सुधार के लिए कोई व्यवस्था योजना में प्रस्तावित नहीं की गई है। इसलिए जहां एक ओर ऐसी सड़कों के निर्माण की आवश्यकता है, जिन पर बैलगाड़ियां सुगमता और शीघ्रता से चल सकें, और जो गांव गांव को एक कड़ी में पिरो दें, वहां दूसरी ओर इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि बैलगाड़ी में सुधार होना चाहिए। आज देश में लगभग ९० लाख बैलगाड़ियां हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक ४० भारतीयों में से एक के पास बैलगाड़ी अवश्य है जबकि मोटर रखने वाले व्यक्ति प्रत्येक १४००० में से एक पाये जाते हैं। ये आंकड़े इस बात को स्पष्ट कर देते हैं कि गमनागमन के सभी साधनों में देश की आन्तरिक अर्थव्यवस्था को देखते हुए सड़कों का महत्व अधिक है और इन सड़कों में भी ऐसी सड़कों का, जिनका निर्माण प्रत्येक गांव में शीघ्रता से हो सके। सड़कों के निर्माण से न केवल ग्रामीणों का आर्थिक विकास ही होगा, बल्कि बौद्धिक और नैतिक विकास भी होगा।

—

रांची में सम्पदा मिलने का पता—
क्राउन बुक डिपो

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(पृष्ठ ९५ का शेष)

चाहिए कि वस्त्र उद्योग की नई नीति के कारण, जिसमें मिलों को आटोमैटिक लूम लगाने के लाइसैंस फिर से मिलने लगे हैं, मिलें इस उद्योग संस्थान की सेवाओं से लाभ आवेंगी।

—

साइकिल उद्योग

भारत में १९५९ में ६ लाख १५ हजार से अधिक साइकिलें बनीं। १९५५ में केवल ४ लाख ९१ हजार और १९५४ में ३ लाख ७२ हजार साइकिलें बनीं थीं। साइकिल उद्योग देश के नये उद्योगों में से है और पिछले ६ वर्षों में इसमें काफी प्रगति हुई है। १९५१ में देश में साइकिल बनाने के सिर्फ दो कारखाने थे जिनकी वार्षिक उत्पादन-क्षमता १ लाख २० हजार साइकिलें बनाने की थीं, लेकिन ये प्रतिवर्ष केवल १ लाख १ हजार साइकिलें बनाते थे।

इस समय भारत में साइकिल बनाने के कुल ६३ कारखाने हैं। इनमें से १६ पंजाब में, १३ दिल्ली में, ९ बम्बई में, ७ उत्तरप्रदेश में, ६ पश्चिमी बंगाल में, ५ मध्यप्रदेश में, ४ राजस्थान में, २ मद्रास में और १ बिहार में हैं। १९५६ में साइकिल के बड़े कारखानों में प्रतिदिन औसतन ८,१५८ आदमी काम करते थे। १९५५ में यह संख्या ६,४९३ और १९५४ में ५,०७७ थी। अनुमान है कि छोटे कारखानों में लगभग ६,५०० आदमी काम कर रहे हैं।

छोटे कारखानों में साइकिल के पुर्जे बनाने के काम को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने कई उपाय किये हैं। लुधियाना में साइकिलों के पुर्जों को अन्तिम रूप देने तथा उसका परीक्षण करने का एक केन्द्र खोला गया है। प्राविधिक परामर्श की व्यवस्था की गई है और कच्चा माल मंगवाने के लिए आर्थिक सहायता और सुविधा दी गई है।

देश में साइकिलों का उत्पादन बढ़ने से इनके आयात में कमी हुई है। साइकिल उद्योग को संरक्षण प्रदान किया गया है और आयात नियन्त्रित कर दिया गया है। देश में साइकिल के सभी हिस्से बनाये जाते हैं। इनके बनाने के लिए कुछ कच्चा सामान देश में ही मिल जाता है और कुछ बाहर से मंगाया जाता है। निर्यात की जाने वाली साइकिलों में लगे कच्चे सामान और पुर्जों के बाहर से मंगाने पर जो आयात शुल्क लिया जाता है, उसे वापस करने की एक योजना तैयार की गई है।

देश में बनी साइकिलें विदेशों में दूसरी साइकिलों के मुकाबले में कम मूल्य पर बिक सकें, इसके लिये भारत सरकार ने शीघ्र से शीघ्र देश में ट्यूब निर्माण उद्योग का विकास करने का निश्चय किया है। ट्यूब बनाने के लिए दो अतिरिक्त लाइसेंस दिए गए हैं।

इंजीनियरिंग निर्यात वृद्धि परिषद् ने बर्मा, श्रीलंका, थाईदेश मिस्र और पूर्व अफ्रीका में बड़े पैमाने पर मंडियों का सर्वेक्षण किया है। १९५४-५५ में जिन अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भारत ने भाग लिया है, उनमें साइकिलें भी प्रदर्शित की गई हैं। कोलम्बो, तेहरान, कराची और मनीला के भारतीय प्रदर्शन-कक्षों में भी साइकिलें रखी गई हैं।

सरकारी विज्ञापनों के लिए स्वीकृत
राजस्थान शिक्षा विभाग से मंजूरशुदा

सेनानी साप्ताहिक

सम्पादक :—

सुप्रसिद्ध साहित्य सेवी श्री शंभुदयाल सक्सेना

कुछ विशेषताएं—

★ ठोस विचारों और विश्वस्त समाचारों से युक्त
★ प्रान्त का सजग प्रहरी
★ सर्वाधिक लोकप्रिय पत्र

ग्राहक बनिए, विज्ञापन दीजिए, रचनाएं भेजिए
नमूने की प्रति के लिए लिखिए—

व्यवस्थापक, साप्ताहिक सेनानी, बीकानेर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अर्थ वृत्त चयन

जनता और नये कर

देश के शासन, राष्ट्र निर्माण और विकास कार्यों में जनता को निरन्तर अधिकाधिक भाग अदा करना पड़ रहा है। इसके लिए शासन किस तरह कर बढ़ाता जा रहा है, यह नीचे लिखे आंकड़ों से कुछ स्पष्ट हो जायगा—

साल	केन्द्रीय सरकार का बढ़ा टैक्स
१९४८-४९:	१४ करोड़ ४० लाख रु०

(तम्बाकू पर चुंगी लगा कर और आयात कर बढ़ाकर १४ करोड़ तथा लिफाफा पोस्टकार्ड के दाम और डाक महसूल बढ़ाकर ४० लाख रु०)

१९४९-५० :	१७ करोड़ रु०

(चुंगी की बाबत ११ करोड़, आयात कर ६ करोड़)

१९५१-५२ :	सवा २५ करोड़ रु०

(कार्पोरेशन टैक्स, आयकर सवा चार करोड़, जरूरत की चीजों पर टैक्स १७ करोड़)

१९५५-५६ :	१५ करोड़

(कार्पोरेशन टैक्स १५ लाख, आयकर ८ करोड़ ७ लाख। जरूरत की चीजों पर टैक्स ८ करोड़ ८ लाख)

१९५६-५७ :	३५ करोड़

(कार्पोरेशन टैक्स, आयकर १० करोड़; जरूरत की चीजों पर टैक्स २५ करोड़ रु०)

अगर सिर्फ १९५०-५१ से १९५६-५७ तक का ही हिसाब देखा जाय तो देखेंगे कि सिर्फ इन ६ सालों में केन्द्रीय सरकार के टैक्सों (राज्यों के टैक्स को छोड़कर) का जनता पर बोझ १०२ करोड़ ३९ लाख रुपया बढ़ गया है।

जरूरत की चीजों पर बेहद टैक्स

साल	जरूरी चीजों पर टैक्स बढ़ा
१९५१-५२	१७ करोड़ रु० लगभग
१९५३-५४	३॥ करोड़
१९५४-५५	१६ करोड़ से ज़्यादा
१९५५-५६	८ करोड़ ८ लाख
१९५६-५७	२५ करोड़

केरासिन तेल पर चुंगी से केन्द्रीय सरकार को १९४८-४९ में आमदनी २० लाख रु० थी। वह बढ़कर १९५६-५७ में हो गयी २॥ करोड़ रु०। यानी अवधि के ८ साल में केरासिन तेल पर चुंगी १२ गुना से ज्यादा हो गयी।

कपड़े पर चुंगी से केन्द्रीय सरकार को १९४८-४९ में आमदनी थी ८७ लाख रुपये। वह बढ़कर १९५६-५७ में २९॥ करोड़ रु० हो गयी। अर्थात् ८ सालों में कपड़े पर चुंगी बढ़ कर ३३ गुना हो गयी।

इसी तरह राज्यों में भी इन वर्षों में अमीरों पर टैक्स कम होते गये हैं और गरीबों पर बढ़ते गये हैं।

आम जनता की इस्तेमाली चीजों और किसानों की लगान वसूली से जबकि १९५१-५२ में १५०.०८ करोड़ रु० की आय हुई थी तो १९५६-५७ में यह बढ़कर २०५.०३ करोड़ हो गयी। १९५१-५२ में बिक्रीकर से ४७.९३ करोड़ रु० की आय हुई थी तो १९५६-५७ में यह आय ५५.८७ करोड़ रु० तक पहुँच गई।

दूसरी योजना में नये बोझ

दूसरी पंचवर्षीय योजना में (१९५६ से १९६१ तक) मौजूदा टैक्सों से २२५ करोड़ अधिक टैक्स वसूल करने की योजना बनाई गयी है। ये अतिरिक्त टैक्स नीचे लिखी मदों से वसूल किये जायंगे।

लगान-मालगुजारी	३७ करोड़
कृषि-आयकर	१२ ,,
विकास कर	१६ ,,
सिंचाई कर	११ ,,
बिक्री कर	११२ ,,
बिजली कर	६ ,,
मोटर गाड़ियों पर टैक्स और स्टाम्प से	१४ ,,
अन्य कर	१७ ,,
कुल	२२५ करोड़

ऊपर के आंकड़े देखने से पता चलता है कि अतिरिक्त टैक्सों को कुल रकम (२२५ करोड़ रु०) में से करीब आधी रकम (११२ करोड़ रु०) सिर्फ बिक्री टैक्स से वसूल

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

की जायगी। यानी मौजूदा बिक्री करों में और भी इजाफा होगा और ये सारे कर आम जनता को ही भरने पड़ेंगे।

अन्य स्थानीय टैक्सों का बोझ भी जनता पर निरन्तर बढ़ रहा है।

—जनयुग से

उद्योग-कम्पनी और राजनीति

टाटा स्टील आयरन कम्पनी ने जो भारत की प्रमुखतम कम्पनी है, हाई कोर्ट से अपने मेमोरेण्डम को बदलने की स्वीकृति लेकर एक अद्भुत प्रश्न उपस्थित कर दिया है। इस परिवर्तन का आशय यह है कि इस कम्पनी के अधिकारी ऐसे राजनैतिक दलों को कम्पनी के कोष में से सहायता दे सकेंगे, जो कम्पनी की सम्मति में देश के उद्योग और विशेषतः लोह उद्योग की उन्नति में सहायक हो सकें। एक शेयर होल्डर ने इस पर आपत्ति की थी, उसका कहना था कि राजनैतिक दलों को दी गई सहायता से शेयर होल्डरों को कोई लाभ नहीं होगा। और फिर इस प्रकार किसी विशेष राजनैतिक दल को दी गई सहायता से देश का राजनैतिक जीवन भी कलुषित और विकृत हो सकता है। किन्तु हाई कोर्ट ने इस आपत्ति को रद्द करते हुए कम्पनी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। सिर्फ संस्था के उद्देश्य, प्रयोजन के आगे उपयोगी विशेषण जोड़ने की आज्ञा दी है। कम्पनी की मुख्य युक्ति यह है कि आज जब कि देश समाजवाद की तरफ जा रहा है उद्योग का भविष्य शासक दल की नीति और सहानुभूति पर निर्भर है। कम्पनी ७५ करोड़ रुपये की नई विस्तार योजना बना रही है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि कम्पनी ऐसे राजनैतिक दल की सहायता करे जो उद्योग के विकास में सहायक हो। हाईकोर्ट ने यह मानते हुए भी कि इससे राजनैतिक जीवन में विकार आने की सम्भावना है, यह कहा है कि कम्पनी की नीति से पूर्णतः सहमत किसी राजनैतिक दल या उम्मीदवार को सहायता देना एक बात है और किसी व्यक्ति को रुपया देकर उसकी नीति के विपरीत अपना काम करा लेना दूसरी बात है। हाई कोर्ट ने उस शेयर होल्डर की इस बात को नहीं माना कि इससे शेयर होल्डरों को नुकसान होगा क्योंकि इससे उद्योग को जो विशेष लाभ होगा, उसमें शेयर होल्डर भी भागीदार होगा।

हाई कोर्ट के इस निर्णय से एक महत्वपूर्ण प्रश्न अवश्य पैदा हो गया है और वह यह कि क्या कोई उद्योग अपने निश्चित लाभ की आशा से किसी राजनैतिक दल को सहायता दे सकता है और यह सहायता किसी प्रकार की रिश्वत का रूप तो धारण नहीं कर लेती? क्या राजनैतिक दल भी बड़ी २ औद्योगिक कम्पनियों की अखुट धन राशि का प्रलोभन पाकर अपनी नीति तो नही बदल देंगे? आज कांग्रेस को एक कम्पनी सहायता देती है तो दूसरी कम्पनी जनसंघ या अन्य किसी दल को सहायता देकर अपने उद्योग के हितों के लिये विशेष आन्दोलन करने का प्रयत्न कर सकती है। दूसरी ओर कम्पनियों के डायरेक्टर जो शेयर होल्डरों के प्रतिनिधि हैं, किसी राजनैतिक दल को सहायता क्यों न दे सकें, जब कि व्यक्तिगत स्वातंत्र्य का अधिकार उन्हें भी है।

वस्तुतः इस प्रश्न के दोनों पहलू बहुत गम्भीर हैं और देश के विचारकों और विधान शास्त्रियों को इस प्रश्न पर गम्भीर विचार करना चाहिए।

योजना में असंतुलन

जब हम देखते हैं कि सोवियत रूस में या रूस द्वारा नियंत्रित पौलेंड, हंगरी, चैकोस्लोवाकिया आदि देशों में एक जोड़ी जूता खरीदने में मजदूर की सारी मासिक मजदूरी खत्म की जाती है, तो यह अच्छी तरह समझ सकते हैं कि साधारण जनता के लिये योजना का असली महत्व क्या है। अभी हाल में पूर्वी जर्मनी, पोलैंड और हंगरी में अशांतियां हुई हैं। पोजनान की अशांति का असली कारण शायद भारत की जनता को अभी भी मालूम नहीं है। पौलेण्ड की सरकार के उत्तरदायी सदस्यों ने भी अब इस बात को बहुत कुछ स्वीकार कर लिया है कि यह दंगा योजना की कुछ गम्भीर गलतियों के कारण उत्पन्न हुआ था। पौलेण्ड की सरकार के एक प्रमुख सदस्य का बयान है। "पोजनान के दंगे का आधारभूत कारण मजदूरों के प्रति हृदयहीन व्यवहार ही रहा है।" "उत्पादन की वृद्धि को ही एकमात्र लक्ष्य मानना और उसे अन्य लक्ष्य अर्थात् मानव कल्याण का साधन न मानना" कम्युनिस्ट

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आयोजन की प्रमुख विशेषता है। पौलैण्ड में ही नहीं, बल्कि सभी कम्युनिस्ट देशों में योजनाओं ने खेती और उद्योग के बीच, भारी उद्योग और हल्के उद्योग के बीच तथा उत्पादक वस्तु और उपभोक्ता वस्तु के बीच अनेक तरह का असन्तुलन पैदा कर दिया है। हालांकि उन्होंने कुल राष्ट्रीय आय के रूप में काफी उल्लेखनीय वृद्धि की है, फिर भी उन देशों के रहन-सहन के स्तर में उनके कारण अकसर ह्रास हुआ है।

जिस समय हमारी द्वितीय योजना तैयार हो रही थी, पोलैण्ड के एक कम्युनिस्ट अर्थशास्त्री डा० आस्कर लेंज भारत आये थे। वे कुछ समय तक यहां ठहरे। हमारी योजना की रूप-रेखा तैयार करने से उनका काफी सम्बन्ध था। उस समय कई दूसरे कम्युनिस्ट अर्थशास्त्री भी भारत में मौजूद थे। दरअसल, उस समय भारत के बहुत से लोगों को यह आशंका हो गई थी कि वे हम पर प्रभाव डाल कर हमारी योजना को कम्युनिस्ट योजना बना देंगे। किन्तु इसकी बजाय हमने देखा कि डा० लेंज इस विश्वास के साथ पौलैण्ड वापस लौटे कि भारतीय योजना काफी ठोस है। उन्होंने पौलैण्ड की सरकार से जोरदार अपील की कि वह रूसी योजना की बजाय भारतीय पंचवर्षीय योजना के आधार पर अपनी योजना संशोधित करे।

—आर्थिक समीक्षा

हम कितने पीछे हैं !

हमारे देश में लोगों के रहन-सहन का स्तर दुनियां भर में सबसे नीचा है। मनुष्य के लिए कम से कम २,२५० कैलौरी का खाद्य तत्व मिलना चाहिए। किन्तु हमारे देश के लोगों को केवल १,६९० कैलोरी ही मिल पाती है। देश के लोगों को प्रति व्यक्ति औसत रूप से १६ गज कपड़ा ही सालाना मिल पाता है और देश की लगभग आधी जनता को खाने और कपड़े पर खर्च करने के लिए १३ रु० ही मिल पाते हैं। देश में जितनी शक्ति का उपयोग होता है उसे कोयले की शक्ति में तब्दील करने पर हम देखते हैं कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति २२५ पौंड कोयले की शक्ति का उपयोग होता है, जबकि स्वेडन में ८४०० पौंड, बेल्जियम में ५,३०० पौंड, फ्रांस में १० हजार पौंड से अधिक और सं० रा० अमेरिका में १८ हजार पौंड खर्च होती है। जापान की तुलना में भारत के प्रति व्यक्ति शक्ति का उपयोग उस देश के औसत के १।९ के बराबर होता है। भारत में इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत जापान की तुलना में १।४ और फ्रांस तथा सं० रा० अमेरिका की तुलना में क्रमशः २ प्रतिशत और १ प्रतिशत होती है। हमारे देश के ६ से ११ वर्ष के बीच वाले बच्चों में से केवल ५० प्रतिशत और ११ से १४ वर्ष तक की अवस्था के बालकों में से केवल २० प्रतिशत ही स्कूल में पढ़ते हैं।

सामान्य रूप से १ हजार तक की जनसंख्या के लिए कम से कम १ अस्पताल का बिस्तर चाहिए किन्तु हमारे देश में १९५६ के अन्त में ८ हजार की जनसंख्या के लिए ही एक बिस्तर का प्रबन्ध किया जा सका। यही नहीं दाइयों की संख्या तो सामान्य आवश्यकता से २५ प्रतिशत कम है। हमारे ग्रामीण इलाकों में लगभग ५० से से ५५ प्रतिशत मकान कच्ची मिट्टी वाले हैं। इन मकानों में भी जगह बेहद कम है। इनमें से लगभग ४० प्रतिशत मकानों के प्रति व्यक्ति जगह १०० वर्ग गज से कम है।

—श्री मनुभाई शाह

नयापथ

(प्रगतिशील मासिक पत्रिका)

सम्पादक—

यशपाल ❀ शिव वर्मा ❀ राजीव सक्सेना

स्तम्भ—

- चक्कर क्लब
- साहित्य समीक्षा
- संस्कृति प्रवाह
- सिनेमा
- लेख
- कहानियां
- कविताएं।

"नयापथ" का जनवरी अंक 'लोक साहित्य' विशेषांक है। इसका सम्पादन हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक श्री श्रीकृष्णदास कर रहे हैं। ग्राहकों को यह अङ्क साधारण मूल्य में ही दिया जाएगा।

वार्षिक ६) एक प्रति ।।)

पता :—

२२ कैसर बाग लखनऊ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(पृष्ठ ८४ का शेष)

सरकार को भी अब की अपेक्षा अधिक योग्य और भ्रष्टाचार से मुक्त होना होगा, क्योंकि योजनाएं चतुराई से तैयार करनी होंगी और उन पर मितव्ययता से अमल करना होगा।

साधनों का सदुपयोग

अन्त में, इस सदी के अन्तिम दशकों पर दृष्टि डालते हुए कोई भी यह प्रश्न कर सकता है कि विश्व के पास पर्याप्त साधन न होने के कारण क्या अधिकांश मानव जाति के रहन-सहन के स्तर को उन्नत करने के प्रयत्न निष्फल रहेंगे। विश्व की वर्तमान आबादी को ही अधिक खाद्य-सामग्री की आवश्यकता है और बहुत से देशों की आबादी आहार और डाक्टरी सहायता-व्यवस्था में सुधार होने के साथ-साथ बढ़ जाएगी। विश्व की वर्तमान भूमि का यदि सर्वोत्तम रीति से उपयोग किया जाए तो उससे और काफी खाद्य सामग्री प्राप्त की जा सकती है तथा अपने ज्ञान में और अधिक सुधार करके अन्नोत्पादन की अधिकतम सम्भावित मात्रा में भी वृद्धि की जा सकती है। किन्तु इस बात की तो सीमा रहेगी ही कि कितने लोगों को भोजन मुहैया किया जा सकता है और सर्वोत्तम रीति से आयोजन करने पर भी यह सीमा भावी उन्नति पर ही निर्भर होगी।

तथापि, रहन-सहन को ऊंचा उठाने के लिए कुछ भिन्न प्रकार के साधनों की आवश्यकता है जैसे कि शक्ति, अधिक निर्माण-सामग्री और अधिक नौकरियां प्रदान करने वाले साधन। ऐसा प्रतीत होता है कि तेजी से बढ़ती हुई आबादी के लिए बहुत बढ़िया जीवन-स्तर तो कायम नहीं किया जा सकता, पर एक ऐसे विश्व का जीवन-स्तर काफी ऊंचा अवश्य उठाया जा सकता है जिसकी आबादी में बहुत अधिक वृद्धि न हो।

सही मार्ग जरूरी

अन्तिम बात यह है कि आयोजन भौतिक दृष्टि से जीवन को उन्नत करने का कोई मैकैनिक गुर नहीं है। अर्थ-शास्त्रियों को ऐसी योजनाएं तैयार करने के लिए जिन से बर्बादी और भूलें न हो सकें, अब से कहीं अधिक जानने समझने की आवश्यकता है। किन्तु किसी भी आयोजन के फलस्वरूप यह कठिन सवाल सामने आ जाता है कि कौन-सा मार्ग अपनाया जाय और योजना पर अमल करने से पूर्व इस सम्बन्ध में निश्चय कर लेना जरूरी है। जन-संख्या की वृद्धि के सम्बन्ध में किये जाने वाले निश्चय और उत्तम भविष्य की आशा में वर्तमान सुखों का त्याग करने की इच्छा से ही प्रत्येक देश की आशाओं और आकांक्षाओं का पता चल सकेगा। वास्तविक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने वाली योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए यह आवश्यक होगा कि लोग परिवर्तनों के लिए उद्यत हों और सरकार को अधिक कार्यकुशल बनाया जाए। यद्यपि आयोजन करना कोई आसान काम नहीं है, किन्तु विश्व भर में निर्धनता और असमानता को दूर करने के कार्य में इससे बड़ी-बड़ी उम्मीदें की जा सकती हैं। और साथ ही यह स्मरण रखना होगा कि इस सम्बन्ध में उठाये जाने वाले प्रारम्भिक कदम बहुत कठिन होंगे।

सम्पदा के बम्बई स्थित प्रतिनिधि
श्री टी० एन० वर्मा
चोगे बंगला, गोराई रोड,
बोरिवली, बम्बई।

आपका स्वास्थ्य

(हिन्दी की एक मात्र स्वास्थ्य सम्बन्धी मासिक पत्रिका)

"आपका स्वास्थ्य" आपके परिवार का साथी है।

"आपका स्वास्थ्य" अपने क्षेत्र के कुशल डाक्टरों द्वारा सम्पादित होता है।

"आपका स्वास्थ्य" में अध्यापकों, अभिभावकों, माताओं और देहातों के लिए विशेष लेख प्रकाशित होते हैं।

आज ही ६) रु० वार्षिक मूल्य भेजकर ग्राहक बनिए।

व्यवस्थापक,
आपका स्वास्थ्य—बनारस-१

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बैंक और बीमा

बैंकों की आर्थिक प्रवृत्तियां

१९५६ में प्रथम पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने के साथ ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आरम्भ किया गया है। इन आर्थिक आयोजनों के कारण औद्योगिक उत्पादन में सितम्बर के अंत तक १५ प्रतिशत की वृद्धि हुई यद्यपि कृषि उत्पादन में थोड़ी कमी हुई। विकास कार्यों के लिए भी काफी व्यय के कारण बैंक के उधार में २५ प्रतिशत की वृद्धि हुई। इन दो कारणों के साथ ही घाटे की अर्थ-व्यवस्था के कारण देश में द्रव्य का चलन बढ़ गया।

इसका प्रभाव देश के आर्थिक जीवन पर पड़ा है। वस्तुओं के मूल्य और रहन सहन के सूचक अंक बढ़ गये। सितम्बर के महीने में तो आर्थिक दबाव अधिक मालूम पड़ने लगा। १९३९ को आधार वर्ष १०० मानकर मूल्य स्तर १९५५ में ३७३·२ से बढ़ कर १९५६ के अंत में ४२१·९ हो गए। समस्त भारत में जीवन-स्तर का व्यय ९८ से बढ़कर सितम्बर में १०८ हो गया। भारी आयात और विभिन्न कारणों से बढ़े हुए उत्पादन व्यय के कारण व्यापरियों को भी रुपया उधार लेने के लिए बैंकों का आश्रय लेना पड़ा। बैंकों के निजी क्षेत्रों को उधार देने और रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को उधार देते रहने के कारण देश में मुद्रा का चलन ६ प्रतिशत बढ़ गया। प्रश्न यह है कि मूल्यों में जो बढ़ती होती रही है, उसका कारण क्या मुद्रा का चलन आधिक्य है। इसके साथ ही दूसरा प्रश्न यह उठता है कि मुद्रा का चलन अधिक्य क्या बैंकों के अधिक उधार बढ़ाने से हुआ? इस समय ठीक-ठीक आंकड़े उपलब्ध न होने से कुछ कहना कठिन है। पर विगत वर्षों में कीमतों और जीवन-स्तर के व्यय के बढ़ने का कारण इतना द्रव्य सम्बन्धी नहीं था, जितना वस्तुओं की पूर्ति में कमी। मांग के साथ उत्पादन का सामंजस्य न हो सका।

हम यहां केवल १९५६ में बैंक और द्रव्य सम्बन्धी स्थितियों का दिग्दर्शन कराना चाहते हैं। इस वर्ष में मुद्रा का चलन १३१·०३ करोड़ बढ़ कर २,१७८·१८ करोड़ हो गया। जनता के पास चलन में काफी मुद्रा आ गई। केवल कागजी मुद्रा और सिक्के कुल चलन का ७२ प्रतिशत लोगों के पास थे। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों की बैंकिंग आदत नहीं थी, उनकी आमदनी काफी बढ़ गई। पर अनुसूचित बैंकों की मांग जमा (डिमांड डिपोजिट) अधिक न बढ़ी। इसमें केवल ३५·४८ करोड़ रुपए याने ५·८ प्रतिशत की ही बढ़ती हुई।

कागजी मुद्रा का चलन उसके लिए सुरक्षित सोना-चांदी के अनुपात की अपेक्षा कई गुना अधिक बढ़ा। विदेशी विनिमय में भी कमी हो जाने के कारण रिजर्व बैंक को २०५·२७ करोड़ रुपए की हानि रही।

विगत ५ वर्षों (१९५२-५६) की द्रव्य सम्बन्धी स्थिति का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि द्रव्य का चलन ४०४.७९ करोड़ रुपए बढ़ा। यह बढ़ती लगभग २३ प्रतिशत है। लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस अवधि में चलन की प्रवृत्ति निरन्तर नहीं बढ़ रही थी। १९५२ में मुद्रा के चलन में ९०.५८ करोड़ रुपये की कमी हुई। कारण यह था कि विदेशी सौदों के कारण विदेशी विनिमय में ७५.६० करोड़ रुपए की कमी हो गई। इससे रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों ने अपने उधार में भी कमी कर दी। लेकिन बाद वाले ४ वर्षों में द्रव्य के चलन में ४९५.३७ करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। इसका कारण गत २ वर्षों की घाटे की अर्थ-व्यवस्था और पिछले २-३ वर्षों की बैंक के साख की वृद्धि है। १९५३-५४ और १९५५ में विदेशी व्यापार की दशा में सुधार हो जाने से विदेशी विनिमय में २९.६९ करोड़ रुपए की बढ़ती हुई। इसके कारण भी देश में मुद्रा के चलनाधिक्य कर विदेशी विनिमय में २०५.२७ करोड़ कमी हुई। अतः अब मुद्रा चलनाधिक्य पर विदेशी विनिमय का वह प्रभाव हट गया।

औद्योगिक विकास, कार्य अत्यधिक आयात और केन्द्रीय और राज्य सरकारों की मांग के कारण बैंकों को इस वर्ष में अपनी साख का विस्तार करना पड़ा। परिणामतः अनुसूचित बैंकों की जमा में (जिसमें खरीदे

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

व भुगताए बिल भी हैं) १९५६ में १५७.०१ करोड़ रुपए की वृद्धि हुई, जबकि विगत वर्ष याने १९५५ में केवल २३.०४ करोड़ रु० की वृद्धि हुई थी। ५ साल पहले यह वृद्धि २४५.९३ करोड़ रुपए याने ४५ प्रतिशत थी। लेकिन अनुसूचित बैंकों में जमा अत्यन्त अल्प मात्रा में हुई जिससे साख के विस्तार के साथ उनके साधनों का भी विस्तार न हो सका। १९५६ में अनुसूचित बैंकों की विशुद्ध जमा की वृद्धि केवल ७९.४३ करोड़ रुपए हुई जब कि १९५५ में ९०.०२ करोड़ रु० थी। पाँच साल पहले यह २५५.५४ करोड़ रुपए थी। फलस्वरूप १९५६ में बैंकों की अग्रिम राशि और जमा राशि का अनुपात ७१.६ प्रतिशत रहा। एक वर्ष पहले १९५५ में यह अनुपात ६१.८ प्रतिशत और १९५३ में केवल ५५.४ था।

बैंकों के पास उधार के लिए मांग पर माँग आते रहने के कारण और द्रव्य बाजार में कठोरता के कारण विगत वर्ष ब्याज की दर का प्रमुख स्थान रहा। इसके लिए यद्यपि मन्दी के अवसरों (Slack Season) में बैंकों को विशेष कठिनाई न हुई पर व्यस्त अवसरों (Busy Season) पर उन पर काफी जोर पड़ा। इस कारण बैंकों को रिजर्व बैंक से उधार लेना पड़ा। इसके लिए उनको अपनी तरल संचय में अत्यन्त कमी करनी पड़ी। इस वर्ष में अनुसूचित बैंकों ने रिजर्व बैंक से ९०३.७७ करोड़ रुपए उधार लिये जो १९५५ में लिये उधार के दुगने से भी अधिक है। इस विषय में एक बात उल्लेखनीय है कि सरकारी सिक्यूरिटियों के द्वारा लिये जाने वाले ऋणों की संख्या मियादी बिलों (Usance Bill) से लिए जाने वाले ऋणों से बहुत बड़ी थी। १९५५ से यह प्रवृत्ति बिल्कुल भिन्न है। कारण यह है कि १९५५ में सरकारी सिक्यूरिटियों की अपेक्षा ऋण पत्रों से उधार लेना सस्ता था पर १९५६ में बैंक दर ३ प्रतिशत से ३$\frac{1}{3}$ प्रतिशत हो जाने, तथा २१ मार्च से मुद्रा शुल्क की रियायतें समाप्त हो जाने के कारण सरकारी सिक्यूरिटियों से ऋण लेना बैंकों ने ठीक न समझा। इधर बैंकों पर मांग का काफी दबाव पड़ने के कारण उनके लिए इसी कारण मियादी बिलों का महत्व बढ़ गया।

जो कुछ भी हो, पर इस वर्ष में बैंकों ने अपने विनियोजन को घटाकर २०.३७ करोड़ रुपए कर दिया, जब कि पिछले वर्ष के विनियोजन की राशि ३७.०१ करोड़ रुपए थी, इस वर्ष उनकी नकद बचत ७.२३ करोड़ रु० है जब कि १९५५ में नकद बचत ५.२२ करोड़ रु० थी। निष्कर्ष यह कि १९५९ में बैंकों के नकद बचत और अनुमानतः कुल तरल अनुपात में काफी कमी हुई।

———

बैंक दर में वृद्धि

रिजर्व बैंक ने २५ जनवरी ५७ से अनुसूचित बैंकों को सरकारी तथा अन्य सिक्यूरिटियों के आधार पर ऋण देने के लिए ब्याज की दर में वृद्धि की जो घोषणा की है उससे किसी को आश्चर्य नहीं हुआ है। यूसेंस बिलों पर स्टाम्प ड्यूटी आधा प्रतिशत बढ़ाने पर इसकी आशा की जाने लगी थी। इस वृद्धि का यह असर होगा कि रिजर्व बैंक जो ऋण देगा, उसकी वास्तविक ब्याज दर ४ प्रतिशत बैठेगी। ब्याज वृद्धि के फलस्वरूप बाजार में मुलायमी आने की संभावना है।

इस बीच में बैंकों से ऋण की मांग बड़े पैमाने पर बनी हुई है। अनुसूचित बैंकों ने ८०० करोड़ से अधिक ऋण दे रखा है। रिजर्व बैंक ने अपने सदस्य बैंकों को जो ऋण दे रखा है उसकी रकम २५ जनवरी को बढ़कर १०२.१८ करोड़ रु० हो गई है। मियादी बिल के आधार पर ऋण की रकम ११ जनवरी को बढ़कर ६०.८६ करोड़ रु० हो गई। सक्रिय मौसम में रुपए की कमी को दृष्टि में रख कर यह कहा जा सकता है कि बैंकों से और अधिक ऋण की मांग होगी। यह भी स्वाभाविक है कि रिजर्व बैंक से ऋण लेने में बैंकों को जो अधिक खर्चना पड़ेगा, वह उसे अपने ग्राहकों में डाल देंगे। इसका यह भी प्रभाव पड़ सकता है कि बैंकों को जमा पर ब्याज की दर बढ़ानी पड़े।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम, १९३४ की धारा १७ (४) (ए) के अन्तर्गत रिजर्व बैंक सरकार तथा अन्य जमानतों पर अनुसूचित बैंकों को जो अग्रिम-धन देता है, पहली फरवरी १९५७ से उस पर ब्याज की दर बढ़ा कर ४ प्रतिशत प्रतिवर्ष कर दी गयी है।

———

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राष्ट्र का आर्थिक प्रवाह

[पृष्ठ ८२ का शेष]

विदेशी मुद्रा के व्यय में ५० प्रतिशत कमी की जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों के आयातों को सीमित किया जाएगा। गत वर्ष एप्रिल से सितम्बर तक आयात में जो व्यय हुआ, उसकी तुलना में यह नयी मर्यादा करीब आधी है। नयी योजना के अनुसार कई कदम उठाए गए हैं और अवशेष सरकार के विचराधीन हैं। अब सरकार का निश्चय है कि विदेशी मुद्रा का व्यय आमद से बाहर न हो। निर्यात से जितनी आमद हो उसके अंदर ही आयात में व्यय किया जाए। सम्प्रति निर्यात का मासिक औसत करीब ५० करोड़ रुपए का है। आगामी छः मास में ३ अरब रुपए के निर्यात की शक्यता है। इसलिए सरकार अगले छः मास में ३ अरब रुपए से अधिक व्यय नहीं करना चाहती है। इस दृष्टि से जनवरी-जून १९५७ में निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में २५० करोड़ रुपए व्यय करने का निश्चय है। यह दिलचस्प बात है कि एप्रिल से सितम्बर १९५६ तक छः मास में निजी क्षेत्र में करीब ३९२ करोड़ और सरकारी क्षेत्र में करीब ८५ करोड़ अर्थात कुल ४७७ करोड़ रुपए का आयात हुआ। इस आधार पर २५० करोड़ रुपए की मर्यादा निश्चित करने से व्यय में ५० प्रतिशत कमी होती है।

विनियोजन और नये कर

केन्द्रीय वित्त-मन्त्री श्री कृष्णमाचारी ने देखा कि उनके पिछले भाषणों का देश के आर्थिक क्षेत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। विनियोजन के केन्द्र स्थल शेयर बाजार ढीले पड़ गये हैं। मद्रास से औद्योगिक शेयरों के भाव गिर गए और विनियोजन में पूंजी लगाने की आस्था न रही। केन्द्रीय सरकार का शायद यह अभिमत था कि शेयर बाजारों के बिना भी उद्योगों के लिए पूंजी निर्माण हो सकता है। पर देश के वित्तीय क्षेत्र को उत्तरोत्तर गिरते हुए देख केन्द्रीय वित्त मन्त्रालय को चिन्ता हुई। शेयर बाजार पूंजी की कितनी शक्ति रखते हैं, इस सम्बन्ध में बिस्मार्क ने कहा था कि अंग्रेजों की नब्ज देखने के लिए पार्लियामेन्ट नहीं है, बल्कि लन्दन स्टाक एक्सचेंज है। ग्रेट ब्रिटेन की सच्ची स्थिति पार्लमेंट की अपेक्षा लन्दन स्टाक एक्सचेंज से प्रकट होगी। राष्ट्र के सुख-दुख की स्थिति का बेरामीटर शेयर बाजार है। वित्तमन्त्री को शेयर बाजार की स्थिति में चेतना हुई और उन्होंने घोषित किया है कि १९५८ के बजट के बाद भारी कर न लगेंगे। योजना के अन्तिम तीन वर्षों में सरकार अपनी आमद नए साधनों से पूरी करेगी। इससे प्रकट है कि चुनाव के उपरान्त मई १९५७ में १९५७-५८ के बजट में तथा फरवरी १९५८ में १९५८-५९ के बजट में नए भारी कर लगेंगे। ये भारी कर लगना अनिवार्य है, पर इसके बाद कर न लगेंगे। इससे विनियोजकों को संतोष हुआ है। विनियोजक यह देखते हैं कि तीन चार वर्षों के बाद देश की अर्थव्यवस्था में काफी अभिवृद्धि होगी। इसलिए सरकार इन दो वर्षों में चाहे जितने भारी कर लगाए, आगे चल कर उन्हें राहत मिलेगी, और वे अपना लाभ उठायेंगे, नए करों में सम्पत्ति पर वार्षिक कर और व्यय कर लगाने में सरकार बढ़ सकती है। इन नए करों से राजस्व की आय की वृद्धि होगी। ये कर सामाजिक कर के रूप भी हैं। मृत्यु कर और डिवीडेंड कर में भी वृद्धि हो सकती है। ये दो कर दुगुने किए जा सकते हैं।

राजस्व आय के तीन नये स्रोत

श्री कृष्णमाचारी सूझ का दिमाग है, इसलिए योजना के अन्तिम वर्षों में राजस्व में आमद की वृद्धि के तीन स्रोतों का उपयोग करेंगे। यह प्रकट है कि अभी जितने पुराने और नए कर हैं, उनसे पूरी आय नहीं होती है। लोग पूरे कर नहीं चुकाते हैं या अधिकांश लोग पूरे कर चुकाने से बच जाते हैं। उनसे कड़ाई से कर वसूल करने पर बिना नए कर लगाए, अधिक आमद हो सकती है; उतनी ही हो सकती है, जितनी नए करों से प्राप्त करने का अनुमान हो। इस समय देश के लिए विदेशी मुद्रा के संचय का विकट प्रश्न उपस्थित है। श्री कृष्णमाचारी एक नए साधन का उपयोग करना चाहते हैं। वे वित्तीय क्षेत्र में गोल्ड बियरर बांड जारी करने की कामना करते हैं। इन बांडों की बिक्री से सरकार का संकट टल सकेगा। निर्यात व्यापार से भी विदेशी मुद्रा की आमद बढ़ सकती है। पर वित्त मंत्री जानते हैं कि नए साधन से ही निर्यात बढ़ सकता है। इसलिए वे ३० लाख टन-कच्चे लोहे का निर्यात करना

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चाहते हैं। पर यह निर्यात १०० लाख टन तक पहुंच सकता है। श्री कृष्णमाचारी यह सोचते हैं कि नयी परिस्थितियों में नए स्रोतों के लिए स्थान है और उस सफलता में अर्थव्यवस्था की अभिवृद्धि और राष्ट्र का उत्थान है। राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की उन्नति का अर्थ है कि विनियोजकों को अपने काभकाज के लिए उन्नति क्षेत्र मिलना।

नये कर और कृष्णमाचारी

भारत के केन्द्रीय वित्तीय क्षितिज में देशमुख और कृष्णमाचारी, ये दो देदीप्यमान नक्षत्र प्रकट हुए। उनमें आज एक नक्षत्र क्षितिज से हट गया और दूसरे का उदय हुआ। इन दोनों की कार्यप्रणालियां भिन्न हैं। श्री देशमुख की नीति थी कि विकास योजना के पहले दो तीन वर्षों में हल्के कर लगाए जाएं और विकास व्यय की पूर्ति घाटे की अर्थ-व्यवस्था द्वारा हो। इसके उपरांत मुद्राप्रसार का धन भारी करों से खींच लिया जाये। इस योजना से विनियोजकों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता और रुपए की अधिक आमद होने पर उद्योगों को भारी कर चुकाने में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। इस कदम में श्री देशमुख का कौशल था। पर श्री कृष्णमाचारी ने दूसरी योजना के आरम्भ में भारी कर लगाये, जबकि पिछली योजना के भारी करों से विनियोजन क्षेत्र से रुपया खिंच गया था और रुपया बाजार में तंगी बढ़ती चली जाती थी। श्री कृष्णमाचारी योजना के अन्तिम तीन वर्षों में अतिरिक्त भारी कर नहीं लगाना चाहते हैं। पर क्या अन्तिम वर्षों में ऐसी परिस्थितियाँ न आयेंगी कि भारी कर न लगें?

———

विज्ञापनदाताओं के लिए शुभ समाचार

पश्चिमोत्तर भारत की प्रमुख हिन्दी मासिक पत्रिका

विश्व-ज्योति

का वार्षिक अङ्क २८ फरवरी १९५७ को प्रकाशित होगा।

विश्वज्योति सारे देश में विशेषतः पश्चिमोत्तर प्रदेशों में, सहस्रों हाथों में पहुँचती है। प्रायः सभी प्रादेशिक सरकारों द्वारा प्रमाणित होने के कारण यह सर्वत्र कालेजों, स्कूलों और पुस्तकालयों में जाती है। विशेष रूप से वार्षिक अङ्क बहुत संख्या में छापा जा रहा है।

विज्ञापन-दाताओं को चाहिए कि नीचे लिखी दरों के अनुसार रुपया भेजकर विज्ञापन के लिए अभी से स्थान सुरक्षित करा लें।

(१) साधारण पृष्ठ	सम्पूर्ण	५० रुपए	टाइटल पेज २ या ३	चौथाई	३० रुपए
,,	आधा	३० ,,	(३) टाइटल पेज ४	सम्पूर्ण	१०० ,,
,,	चौथाई	१५ ,,	,, ,, ,,	आधा	६० ,,
(२) टाइटल पेज २ या ३	सम्पूर्ण	८० ,,	(४) टाइटल पेज ४(दो रंगों में)	सम्पूर्ण	१२० ,,
,, ,, ,,	आधा	५० ,,	,, ,, ,, ,, ,,	आधा	७० ,,

पत्र व्यवहार के लिए पता :—

व्यवस्थापक विश्वज्योति, पो० साधु आश्रम, होश्यारपुर (पंजाब)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

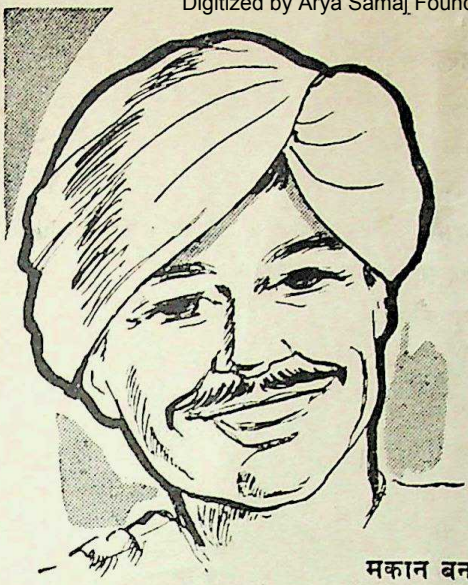

आप

मकान बना सकते हैं

ज़मीन खरीद सकते हैं

बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं

बीमारी का इलाज करा सकते हैं

वृद्धावस्था में सुख पा सकते हैं

आप का धन राष्ट्रीय बचतों में सुरक्षित है और इस से आप को उचित ब्याज मिलता है। विशेष कर यह धन राष्ट्रीय उन्नति के लिए पंच वर्षीय योजना में प्रयुक्त होगा।

अधिक विवरण और/या इस से सम्बन्धित नियमों की जानकारी के लिए नैशनल सेविंग्ज़ कमिश्नर, शिमला या अपने राज्य के रीजनल नैशनल सेविंग्ज़ आफिसर को लिखिए।

अपनी तथा राष्ट्रीय समृद्धि के लिए अपना संचित धन लगाइए

UA 56/160

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रथम पंच-वर्षीय योजना के अन्त में

द्वितीय पंच-वर्षीय योजना की बढ़ती हुई यातायात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अधिक विस्तार योजनायें बनाई जा रही हैं। मध्य और पश्चिम रेलें, गाड़ियों के डिब्बे इंजन इत्यादि के खर्च के अतिरिक्त, २२५ करोड़ रुपये से अधिक व्यय करके वर्तमान यात्री यातायात में १५ प्रतिशत और माल यातायात में ४० प्रतिशत इस योजना के अंत में वृद्धि करने की आशा करती हैं।

INDIAN RAILWAYS

मध्य और पश्चिम रेलवे

सम्पादक—कृष्णचन्द्र विद्यालंकार द्वारा अशोक प्रकाशन मन्दिर के लिए अर्जुन प्रेस देहली से मुद्रित व प्रकाशि

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

समय

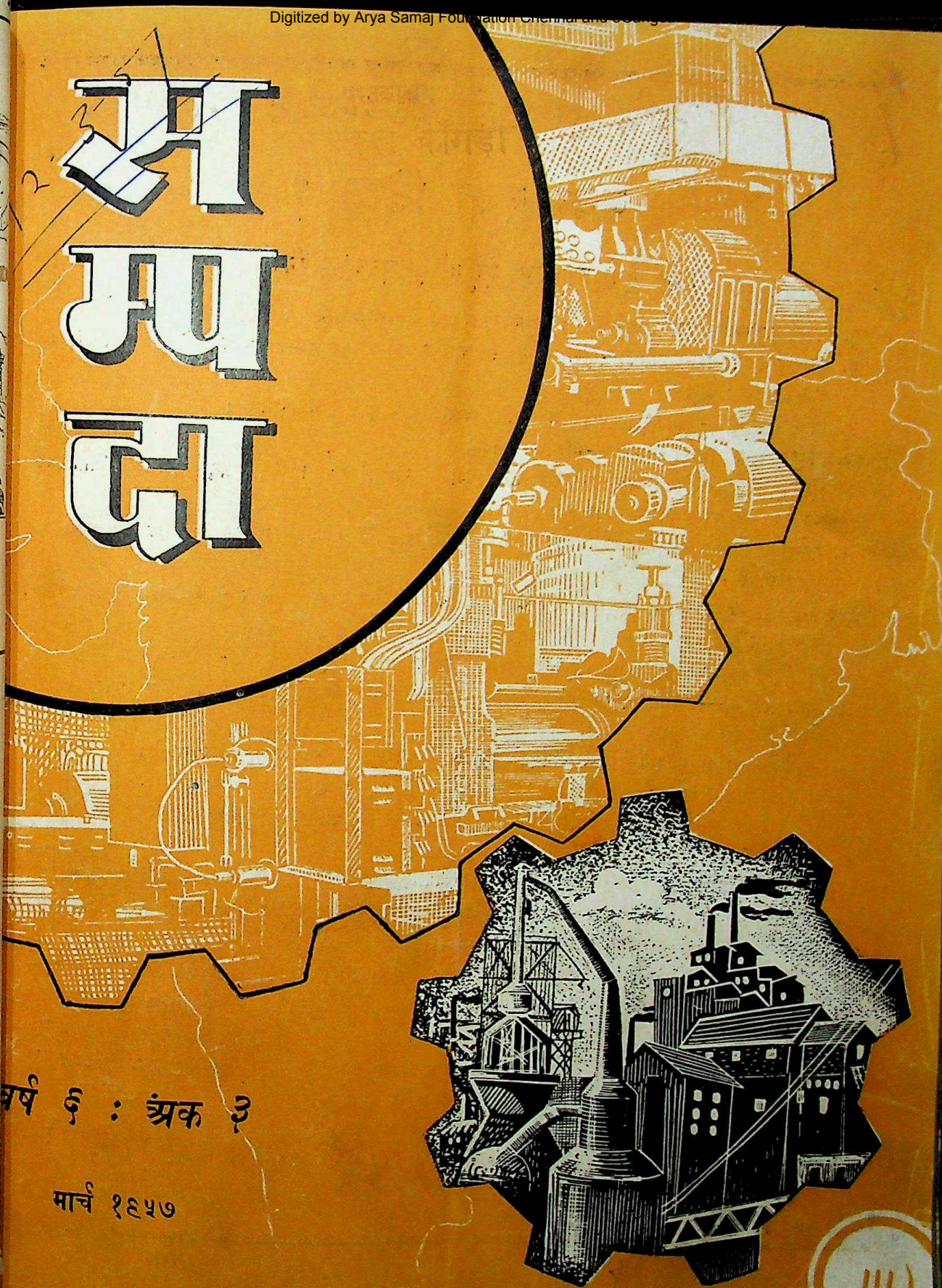

वर्ष ६ : अंक ३

मार्च १९५७

III)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पिछले ५ वर्षों में सम्पदा ने क्या क्या दिया ?

प्रति वर्ष दो महत्त्वपूर्ण ज्ञानवर्धक विशेषांक

१. भारत सरकार का बजट—प्रति वर्ष विवेचनात्मक तथा परिचयात्मक लेख।

२. पंचवर्षीय आर्थिक योजना—पहली व दूसरी दोनों योजनाओं पर अलग अलग विशेषांक तथा प्रति बीसियों लेख।

३. खाद्य समस्या—भूमि सुधार अङ्क तथा प्रायः प्रत्येक अंक में कृषि व खाद्य-स्तम्भ।

४. सामुदायिक विकास योजना—करीब २० लेख।

५. हमारे उद्योग—उद्योग अङ्क तथा वस्त्र उद्योग अङ्क लोहा, चाय, सीमेंट, वस्त्र, चीनी तथा इंजीनियरी आदि उद्योगों पर समय-समय पर लेख।

६. सरल अर्थ चर्चा—ग्रामवासी ग्राहकों के लिए सरल भाषा में आर्थिक समस्याओं व देश की प्रगति परिचयात्मक लेख।

७. बैंक और बीमा—बैंक अङ्क—भारत का रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, सहकारी बैंक तथा बैंक और बीमा सम्बन्ध चर्चा प्रायः प्रत्येक अंक में।

८. हमारा व्यापार—प्रायः प्रतिमास व्यापार-सम्बन्धी सूचनाएं।

९. श्रम समस्या—मजदूर अङ्क—कर्मचारी बीमा योजना, प्राविडेण्ट फण्ड आदि सामयिक श्रम सम्बन्धी प्रश्न प्रायः प्रत्येक अंक में।

१०. अर्थवृत्त चयन—देश-विदेश की आर्थिक प्रवृत्तियों की जानकारी से यह स्तम्भ पूर्ण रहता है।

११. विविध राज्यों की आर्थिक समस्याएं—उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, मध्यभारत, मध्यप्रदेश और राजस्थान आदि राज्यों की आर्थिक समस्याओं पर लेख और उनकी आर्थिक प्रगतियों का संक्षिप्त परिचय।

१२. विविध विषयों पर लेख—

स्टर्लिंग-समस्या	बेकारी की विकट समस्या	समाजवाद व साम्यवाद
केन्द्र व राज्यों में परस्पर सम्बन्ध	ग्रामोद्योग और मिलें	उद्योग वित्त आयोग
विश्व कोष व विश्व बैंक	वित्त आयोग	भारत की आयात नीति
निजी उद्योग और राष्ट्रीयकरण	सामूहिक कृषि की मृग मरीचिका	नये कम्पनी कानून
हमारी राष्ट्रीय आय	घाटे की अर्थ-व्यवस्था	जमींदारी उन्मूलन
भारत की कर-व्यवस्था	रुपये का अवमूल्यन	भूमि समस्या के कुछ पहलू
कण्ट्रोल व विनियन्त्रण	भूदान का सर्वोदय अर्थशास्त्र	सम्पत्ति पर उत्तराधिकार कर
रेलवे बजट	भारत सेवक समाज आदि-आदि	

अर्थशास्त्र की यह अमूल्य सामग्री लेने के लिये पिछले अङ्क भी मंगाइये

मैनेजर सम्पदा—अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिल्ली—६।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पहली व दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के अनुसार—

भारतवर्ष आज अपने आर्थिक विकास व पुनर्निर्माण के लिए प्रयत्नशील है। देश के हर एक भाग में पक्की सड़कें, नदियों के बाँध, विशाल पुल, सुन्दर भवन, हस्पताल, स्कूल व कालिज तथा बड़े-बड़े कारखाने बनाये जा रहे हैं।

इनको टिकाऊ, सुन्दर, एवं सबल बनाने के लिए सर्वोत्तम डालमिया सीमेंट का प्रयोग कीजिए।

डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटिड

डालमियापुरम् (त्रिचनापल्ली)

सम्पदा के सम्बंध में जानकारी

रजिस्ट्रार न्यूज पेपर्स एक्ट के नियम ८ के अन्तर्गत विज्ञप्ति

१. प्रकाशन का स्थान	१९ जैना बिल्डिंग्स रोशनारा रोड, दिल्ली
२. प्रकाशन की तिथि	प्रति मास ६-७ तारीख
३. मुद्रक का नाम	कृष्णचन्द्र विद्यालंकार
राष्ट्रीयता	भारतीय
पता	१९ जैना बिल्डिंग्स रोशनारा रोड, दिल्ली
४. प्रकाशक का नाम	कृष्णचन्द्र विद्यालंकार
राष्ट्रीयता	भारतीय
पता	१९ जैना बिल्डिंग्स रोशनारा रोड, दिल्ली
५. सम्पादक का नाम	कृष्णचन्द्र विद्यालंकार
राष्ट्रीयता	भारत
पता	१९ जैना बिल्डिंग्स रोशनारा रोड, दिल्ली
६. स्वामित्व	कृष्णचन्द्र विद्यालंकार

मैं कृष्णचन्द्र विद्यालंकार घोषित करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञानके अनुसार बिलकुल ठीक है।

प्रकाशक—कृष्णचन्द्र विद्यालंकार

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विषय-सूची

नाम	पृष्ठ
१ कर पद्धति के नये सुझाव	१२९
२ सम्पादकीय टिप्पणियां	१३१
३ ब्रिटेन व भारत के आर्थिक सम्बन्ध	१३४
४ जनसंख्या और भारतीय अर्थ व्यवस्था	१३७
५ आर्थिक प्रतिस्पर्धा के दो रूप	१४०
६ पश्चिमी योरोप में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र	१४३
७ भारतीय रेलवे : गत वर्ष पर एक दृष्टि	१४४
८ इंजिन किस तरह चलें ?	१४८
९ बैंकों को अधिक उपयोगी बनाइये	१४९
१० स्टेट बैंक आफ इण्डिया	१५०
११ चम्बल घाटी का विकास	१५१
१२ भारत भूमि में नये खनिज स्रोत	१५४
१३ नया सामयिक साहित्य	१५६
१४ पूर्वी जर्मनी का विदेशी व्यापार	१५८
१५ प्रगति के पथ पर कृषि	१५९
१६ मशीनी औजारों का उत्पादन	१६१
१७ मरुस्थल से शस्य श्यामल	१६५
१८ स्वेज़ नहर का आर्थिक महत्त्व	१६७
१९ अर्थवृत्त चयन	१६८
२० श्रम समस्या	१७३
२१ सरल अर्थ चर्चा	१७५
२२ सर्वोदय पृष्ठ	१७

★

सम्पदा के कुछ एजेण्ट

होशंगाबाद में

श्री अमीरचन्द जैन

रोकड़िया का मकान दूसरी मंजिल

मेन बोर्ड स्कूल के पास, मंगलवारा, होशंगाबाद (M. P.)

रांची में

क्राउन बुक डिपो।

जोधपुर में

मैसर्स द्वारकादास राठी, बुकसैलर्स।

DENA BANK

Services

CURRENT ACCOUNTS

SAVING BANK ACCOUNTS

SPECIAL SAVINGS SCHEMES

CASH CERTIFICATES

FIXED & CALL DEPOSITS

SAVINGS INSURANCE SCHEME

SAFE DEPOSIT VAULTS

SMALL SILVER BARS

INVESTMENT SERVICE

EXECUTOR & TRUSTEE SERVICE

FOREIGN EXCHANGE

A STRONG EDIFICE

Head Office:
Devkaran Nanjee Bldgs.
Hornlman Circle, Bombay 1.

Pravinchandra V. Gandhi
Managing Director.

DEVKARAN NANJEE BANKING CO., LTD.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्पदा

वर्ष ६] मार्च १९५७ [अङ्क ३

कर-पद्धति के नये सुझाव

कुछ समय तक भारत के व्यापारिक और आर्थिक क्षेत्रों में श्री निकोलस कैल्डर की रिपोर्ट की बहुत चर्चा रही है। श्री कैल्डर इंग्लैंड के प्रमुख अर्थ-शास्त्री हैं। उन्होंने भारत सरकार को देश की कर-व्यवस्था के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण रिपोर्ट दी थी। इसमें उन्होंने अनेक कर बढ़ाने के सुझाव पेश किये थे। सम्पदा के पाठक इनके बारे में पहले भी कुछ पढ़ चुके हैं। उन्होंने जो सुझाव दिये हैं, उन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है—व्यक्तिगत कर और दूसरा व्यापारिक कर। प्रथम भाग में पूंजीगत लाभ पर कर के अलावा सम्पत्ति पर वार्षिक कर, निजी व्यय पर कर तथा उपहार कर के सुझाव दिये गये हैं। लेकिन इसके साथ ही अतिरिक्त कर (सुपर टैक्स) में कमी का भी सुझाव दिया गया है, ताकि अतिरिक्त कर तथा आय कर की सम्मिलित दर १४ आने प्रति रुपया को घटा कर ७ आना प्रति रुपया कर दिया जाय। दूसरे भाग में इनकम टैक्स और सुपर टैक्स को एक में मिला कर ७ आना प्रति रुपया करने, पूंजी की छूट देने पर नियंत्रण करने, घाटे को आगे ले जाने तथा कुछ खर्चों में (जिन पर टैक्स नहीं लगता) अधिक सख्त नियम लागू करने के सुझाव दिये गये हैं। आय कर लगाने की व्यवस्था में भी कुछ परिवर्तनों का सुझाव दिया गया है। श्री कैल्डर का यह विचार है कि देश को अपनी पंच-वर्षीय योजना की पूर्ति के लिये बहुत अधिक धन राशि की आवश्यकता है और इसलिए यह जरूरी है कि इन्कम टैक्स की चोरी को रोकने के उपाय किये जायें। इसलिये यह भी सुझाव दिया है कि आयकर के दर में कुछ कमी की जाये, ताकि लोग आयकर छिपाने की बहुत कोशिश न करें।

श्री कैल्डर का मुख्य सुझाव वस्तुतः व्यय-राशि पर कर है। उनका सुझाव है कि इस समय देश में लोगों की आमदनी पर लगे हुए अनेक प्रकार के करों के स्थान पर केवल एक ही सशक्त कर के रूप में व्यय-कर लगाना चाहिए। श्री कैल्डर ने १९५५ में 'व्यय-कर' नाम की पुस्तक प्रकाशित की है। इस पुस्तक से भी उनके सुझावों को समझने में काफी सहायता मिलती है।

लेखक के अनुसार समाज में फैली हुई आर्थिक असमानता को आय या सम्पत्ति की असमानता की अपेक्षा उपभोग की असमानता के आधार पर माना जाना चाहिए। एक नागरिक छोटी सी झोंपड़ी में रूखा-सूखा खाकर फटे हुए कपड़े पहनता है, दूसरा शानदार कोठियों में नौकरों से सेवित मोटरों पर घूमता है, कीमती कपड़े पहनता है तथा ऐश-आराम की जिन्दगी बसर करता है।

उनका यह विचार है कि "एक व्यक्ति समाज में विषमता अपनी व्यय-राशि के (जो वह रहन-सहन का स्तर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ऊंचा करने के लिए करता है) द्वारा उत्पन्न करता है, आय या बचत के द्वारा नहीं। इसलिए व्यक्ति को ठीक समय पर ठीक स्थान पर पकड़ो।" फिर एक व्यक्ति के पास लाखों रुपये की सम्पत्ति है। उस पर कर क्यों न लगाया जाय? श्री कैल्डर के कथनानुसार सम्पत्ति पर क्रमशः वर्धनशील कर लगाना चाहिए। एक लाख या उससे अधिक की सम्पत्ति पर $\frac{1}{3}$ प्रतिशत से $1\frac{1}{2}$ तक सम्पत्ति-कर वार्षिक लगना चाहिए। व्यय-कर उनका सबसे अधिक प्रिय सुझाव है। बहुत आरामतलबी व ऐश-आराम से रहने वालों पर व्यय के २५ प्रतिशत से ३०० प्रतिशत तक कर लगाने की सम्मति उन्होंने दी है। इससे उनकी सम्मति में दो लाभ होंगे। एक तो यह कि लोग फजूल खर्च कम करेंगे और आयकर से बचने के लिए आय छिपाने की ओर कम ध्यान देंगे। उपहार-कर का उद्देश्य यह है कि सम्पत्ति कर बचाने के लिए दान के रूप में सम्पत्ति का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकेगा। पूंजीगत लाभ का प्रस्ताव भी दृढ़ता के साथ रखा गया है। करों की वसूली के लिए भी कुछ सख्त तरीके अपनाने की सलाह दी गई है।

भारतीय उद्योग-व्यापार-मंडल ने हाल ही में एक पुस्तक प्रकाशित करके इन सुझावों पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत किये हैं। मंडल की सम्मति में इन नये करों से समानता और कुशलता की प्राप्ति नहीं होगी। सम्पत्ति कर लगाने का सबसे बड़ा परिणाम यह होगा कि लोगों को रुपया बचाने की प्रेरणा नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई आदमी जितनी बचत करेगा, उस पर उतना ही सम्पत्ति कर लग जायगा। रहन-सहन के व्यय पर कर मुद्रा-प्रसार पर कुछ अंकुश लगाने वाला होगा, ऐसा कहा जाता है, लेकिन इसका परिणाम यह भी तो हो सकता है कि लोग मित-व्यय करें और उत्पादित माल की बिक्री कुछ कम हो, यद्यपि यह भय बहुत महत्व नहीं रखता। परन्तु एक मनोरंजक तर्क इस कर के विरुद्ध दिया जाता है, वह यह है कि एक व्यक्ति वस्तुओं या सेवाओं की खरीदने में अपनी प्राथमिकता से अंतर उपस्थित करने से झंझट पैदा कर सकता है। माना कि एक व्यक्ति ३०० रु० प्रतिमास व्यय करता है। यदि वह उनमें से ५० रु० सिगरेट पर खर्च करता है, उससे राज कोष को अच्छी आय मिल जाती है। पर जब वह इन ५० रु० से फल या मिठाई खरीदना ही पसंद करता है तो इस प्रकार राज्य कोष में उससे एक पैसा भी नहीं मिलता क्योंकि इनकी बिक्री कर से मुक्त है। यही बात सिनेमा के टिकटों पर लागू हो सकती है कि एक व्यक्ति के तीसरे श्रेणी के टिकट खरीदने की अपेक्षा प्रथम श्रेणी के टिकट खरीदने से रज्य कोष को अधिक आय होती है। दूसरे शब्दों में अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं या सेवाओं में परस्पर प्राथमिकता को प्रश्रय देते हैं। व्यय कर इस कार्य को नहीं कर सकते। यदि वस्तु-कर क्रमशः वर्धनशील रूप में लागू किया जाए तो भी परिमाण के अल्प अंश को ही प्रभावित कर सकेंगे। इस प्रकार भारत में वस्तु-कर को भी कैल्डर की कल्पना के अनुसार व्यय-कर का पूरक होना ही पड़ेगा। लेकिन व्यय-कर के लगाने पर वस्तुओं के श्रेणी और परिमाण में निश्चित रूप में परिवर्तन करना पड़ेगा। इसके बिना व्यय-कर सहज, न्याय-युक्त, निर्दोष और समता से पूर्ण नहीं हो सकता।

एक बड़ी कठिनाई यह है कि भारत में उपभोग का एक बड़ा अंश 'द्रव्य की माप' की सीमा से बाहर है। गाँव में कृषिकार्य से सम्बन्धित प्रत्येक व्यक्ति अनाजों की कमाई करता है और अनाजों में ही मजदूरी चुकाता है। जब तक वे इन मूल्यों को द्रव्य में न बदलें और खरीद-फरोख्त अपने खाते में न रखने लगें, तब तक व्यय-कर लगाने में कठिनाई होगी। यदि कर में छूट की सीमा बड़ी हो, तब यह कठिनाई नहीं रहेगी। लेकिन लम्बी छूट होने से कर का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है कि जनता का अधिक से अधिक भाग कर दे। जब तक द्रव्य को सर्वमान्य मापदण्ड नहीं मान लिया जाता, तब तक अस्पष्टता और दुबिधा बनी रहेगी।

उद्योग व्यापा मण्डल ने इस प्रकार का तर्क तो नहीं दिया परन्तु उसने एक बड़ी कठिनाई की ओर अवश्य ध्यान खींचा है। व्यय व सम्पत्ति के आंकड़े एकत्र करना, उसकी ठीक परीक्षा करना आदि बहुत पेचीदा और कष्ट प्रद होगा।

व्यापा रक क के सम्बन्ध में उद्योग व्यापार-मण्डल ने कुछ विचारणीय सुझाव दिये हैं। श्री कैल्डर ने अनिवार्य खर्चों को ही कर-मुक्त करने का सुझाव दिया है, उन्होंने उन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

खर्चों पर छूट देने की राय नहीं दी, जो व्यापर के उद्देश्य से किये जाते हैं। श्री कैल्डर ऐसा करके व्यापार व निजी पेशे की आय पर असमानता को दूर करना चाहते हैं। किन्तु इस प्रकार कर मुक्त व्ययों को कम कर देने से भारतीय उद्योगों को उन विदेशी उद्योगों से मुकाबला करना पड़ेगा जहां आयकर इतने अधिक कठोर नहीं हैं और इसका असर निर्यात व्यापार पर पड़ेगा।

उद्योग व्यापार मण्डल ने अपने विवेचन में सबसे अधिक महत्व इस बात को दिया है कि सामाजिक उन्नति के लिए साधन जुटाते समय हम यह न भूल जाएँ कि आज देश की मुख्य समस्या पूंजी निर्माण है, ताकि दूसरी पंचवर्षीय योजना पूर्ण हो सके। यदि नयी कर नीति बचत को प्रेरणा नहीं देती, तो वह देश के सामने पूंजी निर्णय की कठिन समस्या पैदा कर देगी।

वस्त्र-उद्योग की समस्या

भारत के वस्त्र उद्योग की समस्या भी अद्भुत और विषम है। एक तरफ हम इस बात पर हर्ष प्रकट कर सकते हैं कि वस्त्र उद्योग का उत्पादन गत वर्ष ५,०९,४० लाख गज से बढ़ कर इस वर्ष ५,३०,६० लाख गज हो गया और इस तरह उद्योग ने बहुत सन्तोषजनक उन्नति की। दूसरी तरफ एक नई समस्या यह पैदा हो गई है कि वस्त्र का यह अतिरिक्त उत्पादन खप नहीं पा रहा है और जनता को इससे मूल्य की कमी के रूप में कोई राहत नहीं मिल रही। यह उद्योग के लिये चिन्ता का प्रश्न बन गया है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि हमारे देश का निर्यात कम हो रहा है। जनवरी १९५६ में ६२० करोड़ गज का निर्यात हुआ था पर दिसंबर में गिरकर ५५६ लाख गज रह गया। विदेशों में इसकी मांग निरन्तर कम हो रही है, क्योंकि हम अन्य देशों के मुकाबले में सस्ता कपड़ा तैयार नहीं कर सकते। देश के अन्दर भी कपड़े की मांग कम हो रही है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। उनमें से एक कारण यह है कि सरकार ने उत्पादन कर बढ़ा दिया है। दूसरा सम्भवतः कारण यह है कि रिजर्व बैंक ने कपड़े के गोदामों को रुपया देने से इनकार कर दिया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि मिलों में कपड़े के गोदाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नीचे के अंक यह बतायेंगे कि मिलों में गांठों की गोदाम किस तरह से बढ़ते जा रहे हैं।

	बिका परन्तु उठाया नहीं	अनबिका	कुल मिलों के गोदामों में
३१ जनवरी	५८०००	३५०००	९३०००
२९ फरवरी	४२०००	३१०००	७३०००
३१ मार्च	६००००	३७०००	९७०००
३० अप्रैल	६४०००	३४०००	९८०००
३१ मई	६८०००	३३०००	१,०७०००
३० जून	७००००	३७०००	१,०७०००
३१ जुलाई	९००००	४२०००	१,३२०००
३१ अगस्त	९५०००	४६०००	१,४१०००
३० सितम्बर	१,०६०००	६२०००	१,६८०००
३१ अक्तूबर	१,०१०००	७६०००	१,७७०००
३० नवम्बर	९७०००	७७०००	१,७४०००
३१ दिसम्बर	१,०२०००	८४०००	१,८६०००
३१ जनवरी ५७	९९००००	८९०००	१,८८०००

इस तरह भारत सरकार की नीति के कारण तथा विदेशों में मांग कम हो जाने के कारण यह समस्या गम्भीर होती जा रही है और मिलों के लिए इतना अधिक माल गोदामों में रखना कठिन होता जा रहा है। मिलों की यह समस्या इसलिये और भी कठिन हो गई है कि नये कानून के अनुसार कम्पनियों को अपने रिजर्व फण्ड का अधिकांश भाग सरकार के यहां जमा कराना पड़ेगा। इसका अर्थ यह है कि मिलों के पास रुपया और भी कम हो गया है और वे अपने पास बहुत समय तक स्टाक जमा नहीं रख सकेंगी। यदि कपड़े की बिक्री देश और विदेश में नहीं बढ़ी तो वस्त्र उद्योग के सामने भारी संकट पैदा हो जायगा। सरकारी अधिकारियों को यह गम्भीरता से सोचना चाहिए कि इस समस्या का हल कैसे किया जाये।

वस्त्र उद्योग पर आने वाले संकट के परिणामस्वरूप सूती मिलों के शेयरों के मूल्य नीचे गिर रहे हैं। बम्बई डाइंग, सैंचरी और खताऊ के शेयरों के मूल्य इन ६ मासों में क्रमशः १३१, १२२ और १०७ रुपये तक पहुँच चुके हैं। इस गिरावट का कारण यह है कि सूती मिलों की

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आमदनी कम हो रही है। फरवरी के अन्तिम सप्ताह में मिलों के पास २ लाख गांठें माल जमा था, जब कि गत वर्ष इस मास में ७३ हजार से अधिक गांठें गोदामों में नहीं थीं। उत्पादन तथा बिक्री करों का भार कुछ किस्मों के कपड़ों पर बिक्री के मूल्य के २५ प्रतिशत पहुंच गया है। कपड़े का मूल्य कम करके भी मिलें अपना माल बेच नहीं पा रहीं। एडवर्ड मिल्स की मीडियम ग्रे धोती के, २१ अगस्त के बाद से जब उत्पादन कर बढ़ाया गया था, ५ आना मूल्य कम हो गये हैं। दूसरे कपड़ों के मूल्य में भी कुछ कमी की गई है, यद्यपि उत्पादन-कर बढ़ा दिया गया है।

पाकिस्तानी रुपया

पाकिस्तान के नेता अपना रुपया अपने देश के बैंक में न रख कर इङ्गलैंड, अमेरिका और स्विटजरलैंड के बैंकों में रखने लगे हैं। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि उन्हें अपने देश की अर्थ-व्यवस्था और मुद्रा की स्थिरिता पर विश्वास नहीं है। जब पाकिस्तान की नेशनल असेम्बली में यह सवाल पूछा गया, तब वित्त मन्त्री ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि पाकिस्तान के ऊंचे नेताओं में से कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसने यह अपराध न किया हो। जब देश के नेताओं को ही अपनी राष्ट्रीय मुद्रा में विश्वास न हो, तब दूसरे लोगों का क्या होगा। पाकिस्तान के रुपये की कीमत लगातार गिरती जा रही है। वहां के नागरिक अमृतसर या कलकत्ता में ३० से ४० प्रतिशत कटौती देकर भी भारत का रुपया खरीद रहे हैं। इस खरीद का एक यह भी कारण है कि पाकिस्तानी हज की यात्रा पर जाते हैं। वहां पाकिस्तानी रुपया नहीं स्वीकार किया जाता और न उसके बदले में अरब देश अपना सिक्का देते हैं। इसलिए पाकिस्तानी भारत से रुपया खरीद कर हज की यात्रा पूरी करते हैं, क्योंकि वहां भारतीय सिक्के की कदर है। पाकिस्तान ने अब कटौती देकर भारतीय रुपया लेने वालों को दण्ड देने की घोषणा की है, परन्तु समस्या इससे सुलझेगी नहीं। इसके सुलझाने के दो उपाय हैं, एक तो यह है कि पाकिस्तान और भारत में खुला व्यापार शुरू हो जाये और दूसरा यह है कि पाकिस्तान के रुपये की कीमत सरकारी तौर पर और भी गिरा दी जाय, ताकि लोगों को चोरी छिपे भारतीय रुपया खरीदने की जरूरत न पड़े।

रेलवे दरों में वृद्धि

भारत के वित्तमंत्री श्री कृष्णमाचारी ने मद्रास भाषण देते हुए कहा था कि "मुझे रेलवे मंत्रालय से लिए झगड़ना पड़ रहा है कि वह अपने उत्तरदायित्व पूरा नहीं कर रहा, क्यों कि वह बढ़ते हुए खर्च के अनु में किराये और भाड़े के दर नहीं बढ़ा रहा। यदि रेलवे मंत्रालय ही आवश्यक रूप में अपने दर बढ़ा विकास कार्य में धन की कमी की शिकायत न करनी वित्तमंत्री ने यह भी प्रकट किया था कि "इस में कुछ हो रहा है।" इससे व्यापारिक क्षेत्रों में चर्चा चलना स्वाभाविक ही है कि आगामी बजट रेलवे दर बढ़ेंगे। विश्व बैंक के भेजे हुए प्रति मण्डल ने भी अपने आवेदन में रेलवे पर बोझ डालने की सिफारिश की है। हाल ही में सरकार रेलवे कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने का जो फैसला है, उससे ५ करोड़ रुपया वार्षिक व्यय बढ़ने की संभ है। रेलवे के लिए अत्यन्त आवश्यक कोयले का खर्च अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसलों से बढ़ जायेगा, क्योंकि दूरी अधिक देनी पड़ेगी। इसलिए भी यह बहुत सम्भ कि आगामी बजट में किराया बढ़ा दिया जाये।

फिर मुक्त व्यापार की ओर

चीन में समाजवादी शासन की स्थापना के बा अर्थ पद्धति चल रही है, उसमें आवश्यकताओं के अनु परिवर्तन होते रहते हैं। कुछ वर्ष बाद स्थिर नी आशा की जा सकेगी। यह इस बात का प्रमाण है किसी एक नीति पर दृढ़ता पूर्वक आग्रह नहीं चाहिए। समस्त चीन की कृषि-उत्पादित वस्तुओं को अब मण्डी में लाया तथा बेचा जाता है। सामान्य भा बिक्री के लिए खुली मंडियों की ओर मुड़ने की योज नीति राष्ट्रीय स्तर पर सफल रही है।

खुली मण्डी के प्रथम ६ माह के कार्य का लेखा देते हुए अधिकारी ने बताया है कि मण्डी में उ सामग्री की मात्रा और किस्मों में अभिवृद्धि हुई है, में स्थिरता रही है और कुछ क्षेत्रों में कृषकों की पर्याप्त रूप में बढ़ गई है। उसने पूर्व की स्थिति

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चर्चा करते हुए बताया था कि १९५४ में पूंजीवाद का समाजवादी रूपान्तरण आवश्यक हो जाने के कारण राष्ट्र ने खानगी व्यापारियों द्वारा देहातों में उत्पादित माल के मुक्त व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। इसके फलस्वरूप मूल्य स्थिर हो गये और माल पर्याप्त परिमाण में उपलब्ध होने लगा। परन्तु मण्डी पर राज्य के अति कठोर अंकुश के फलस्वरूप कुछ दोष उत्पन्न हो गये। कई प्रकार के माल तथा किस्मों में ह्रास होने लगा, क्योंकि राष्ट्र की ओर से खरीद करने वाले अन्य सहकारी संघ या तो माल नहीं खरीद सके या उचित मूल्य नियत नहीं कर सके। पर अब यह पाबन्दी अनावश्यक हो गयी। कुछ चीजों को खुली मंडी में बेचने का कार्य गत वर्ष के उत्तरार्द्ध में शुरू हो गया था। बड़े शहरों में इस समय मौसम पर मिलने वाली सब्जियां मौसम के बाद भी बहुत ज्यादा परिमाण में उपलब्ध हो रही हैं। इसके अलावा खुली मंडी की ओर से आजीविकोपार्जन के साधनों की वृद्धि के लिए किसानों को विभिन्न बातों की ओर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया गया है। इसमें दुर्लभ जड़ी-बूटियों, कीमती जंगली फलों, ऊन दे सकने वाले और आखेट-योग्य जानवरों तथा तरह-तरह की अन्य वस्तुओं का संग्रह शामिल है। इन की ओर किसानों ने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। खुली मण्डियों

किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि सरकार व्यापार की गति-विधि का निरीक्षण व नियंत्रण भी न करें। "चीन में मण्डी पर राष्ट्र का नियंत्रण आर्थिक माध्यमों द्वारा किया जाता है। मूल्यों के बढ़ने पर सरकारी दुकानें और सहकारी संघ उचित मूल्य पर बाजारों में सामान उपलब्ध करा देते हैं। "व्यापार को इस तरह से मुक्त करने से कई वस्तुओं के बारे में उत्पादक तथा उपभोक्ता के सम्पर्क और घनिष्ठ हो गये हैं और बीच की प्रक्रियाएं, कम हो गयी हैं। इससे किसान की आमदनी बढ़ गई है। उक्त अधिकारी के कथनानुसार कियांगसू प्रान्त में किसानों की आय साधारणतः दस से पन्द्रह प्रतिशत तक बढ़ गई है।"

खर्च मत बढ़ाइए

कोयले की खानों के मजदूरों के वेतन सम्बन्धी निर्णय देते हुए अपीलेट लेबर ट्रिब्यूनल ने जो फैसले दिये हैं, उनसे कोयले का उत्पादन व्यय १॥।) प्रति टन बढ़ गया है। इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार कोयले के दाम १॥) रु० प्रति टन बढ़ाने का विचार कर रही है। १९५५ में ३,८२,०८,००० टन कोयले का उत्पादन हुआ था। इसका अर्थ यह है कि कोयले का व्यय करीब ६ करोड़ रुपया देश के उद्योगों—सरकारी या गैर सरकारी उद्योगों को भरना पड़ेगा। मद्रास के बागान में भी मजदूरों के वेतन बढ़ाये गये हैं। भारत सरकार ने रेलवे के भी कर्मचारियों के वेतन बढ़ाये हैं। अन्य उद्योगों में भी मजदूरी के दर बढ़ाने की चर्चा चल रही है। जहां तक मजदूरों का सम्बन्ध है, हम इसका स्वागत करते हैं। किन्तु प्रत्येक प्रश्न के दो पहलू होते हैं। मजदूरों की वेतन वृद्धि से उत्पादन व्यय बहुत बढ़ जायेगा, यह निश्चित है, और इसका भार देश की जनता और करदाताओं पर पड़ेगा। पंचवर्षीय योजना का व्यय भी कम नहीं बढ़ेगा। पहले ही योजना के लिये आवश्यक धन सुलभ नहीं हो रहा। इस पर और अधिक बोझ डालना कहां तक युक्तिसंगत होगा, यह प्रश्न उपेक्षा तथा मजदूरों के हित के भावावेश से कम गंभीर नहीं होजाता। हम यह मानते हैं कि लगातार बढ़ते हुए जीवन व्यय के कारण मजदूरों को अवश्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए पहली आवश्यकता यह है कि उनके जीवन व्यय को कम करने के लिए विशेष प्रयत्न किया जाये। वेतन वृद्धि की प्रक्रिया मुद्रा प्रसार को बढ़ावा देगी और जब चीजें ज्यादा मंहगी होंगी, फिर वेतन वृद्धि की आवश्यकता अनुभव होगी। इस तरह यह चक्र लगातार आगे बढ़ता रहेगा। जरूरत इस बात की है कि कृषि पदार्थों का उत्पादन अधिक से अधिक बढ़ाकर उन्हें सस्ता किया जाये ताकि जीवन व्यय कम हो और मजदूरों को सब सुविधायें सुलभ हों। वेतन वृद्धि अपने आप में उद्देश्य नहीं होना चाहिये। उद्देश्य है जीवन की सब सुविधायें प्राप्त करना और उसके लिये वेतन-वृद्धि का मार्ग नई समस्याएं उत्पन्न करेगा। इसलिये शासन को हम कृषि पदार्थों के मूल्य कम करने की दिशा में प्रयत्न करने की सम्मति देना चाहते हैं। हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि केवल मजदूरों के वेतन का प्रश्न नहीं है। अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों के वेतन में कमी की ओर भी ध्यान देना चाहिये।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ब्रिटेन व भारत के आर्थिक सम्बन्ध

कृष्णचन्द्र विद्यालंकार

अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, विशेषकर इधर काश्मीर के मामले में भारत ब्रिटेन के बिगड़ते हुए सम्बन्धों के बावजूद इस वर्ष १९५६ में दोनों देशों का व्यापार खूब बढ़ा। ब्रिटेन के माल को खरीदने में भारत का स्थान चौथा था।

ब्रिटेन से भारत को निर्यात

१९५६ में भारत-ब्रिटेन का व्यापार ३०९० लाख पौंड के मूल्य का हुआ, जो पिछले वर्ष १९५५ की अपेक्षा २०० लाख पौंड अधिक है। ब्रिटेन से भारतने आशा से बहुत अधिक आयात किया। भारत ने ब्रिटेन से १६८० लाख पौंड का आयात-व्यापार किया। ब्रिटेन ने ४५३ लाख पौंड के मूल्य की मशीनों का (बिजली की मशीनें छोड़र) निर्यात इस वर्ष किया। पिछले वर्ष केवल ३२३ लाख पौंड के मूल्य की मशीनों का निर्यात हुआ था। बिजली की मशीनों और सामान आदि का निर्यात इस वर्ष २१२ लाख पौंड का हुआ, जो पिछले वर्ष केवल १६३ लाख पौंड था। इसी प्रकार दवाइयों और लोह व इस्पात का भी ब्रिटेन ने भारत को इस वर्ष अधिक निर्यात किया। इस वर्ष इस्पात और लोह तथा रासायनिकों का निर्यात क्रमशः १५९ लाख पौंड, और १८३ लाख पौंड का हुआ, जब कि पिछले वर्ष इनका निर्यात क्रमशः १६५ लाख पौंड और ८८ लाख पौंड के मूल्य का ही हुआ था। इसी १९५६ के वर्ष में भारत ने १ करोड़ पौंड की लागत की सूती कपड़ों की मशीनें ब्रिटेन से मंगाईं। ५० लाख पौंड के केबल तार, ४० लाख पौंड की कन्वर्टिंग मशीनें व ट्रांसफार्मर आदि, ३० लाख पौंड के जेनरेटर तथा मोटर आदि और २० लाख पौंड के मूल्य की मशीनों के औजारों का आयात किया गया।

वस्तुतः स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भारत के नेताओं ने पुरानी सब कटुता भूलकर उससे अपने सम्बन्धों को बहुत अच्छा बना लिया था। यह स्वाभाविक ही था। इंगलैण्ड ने किन्हीं परिस्थितियों से विवश होकर किया हो, किन्तु अत्यन्त कुशलता के साथ उसने मित्रतापूर्ण वातावरण में भारत को छोड़ दिया। भारत ने सब विरोध और द्वेष भूलकर कामनवैल्थ में रहना स्वीकार कर लियां।

ब्रिटेन व भारत के आर्थिक सम्बन्ध स्वाधीनता के बाद और भी अच्छे हो गये थे, पर आज दोनों देशों में जो कटुता उत्पन्न हो रही है, उसके क्या आर्थिक परिणाम संभव हो सकते हैं, इसका संक्षिप्त परिचय इस लेख में देखिए।

आर्थिक संबन्ध

दोनों के आर्थिक हित इस बात का तकाजा करते कि दोनों एक दूसरे के मित्र बनकर अपनी आवश्यकता पूर्ण करें। दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता भी थी। दोनों देश एक दूसरे की व्यापारिक, औद्योगिक, आर्थिक आवश्यकताओं को जानते भी थे—भारत को अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के लिये ब्रिटिश मशीनरी के लिए और युद्ध में बुरी तरह क्षत-विक्षत ब्रिटेन को भारत जैसे बाजार के लिए। इन सम्बन्धों और आवश्यकताओं का परिणाम ऊपर लिखे अंकों से स्पष्ट हो जाता है।

भारत व ब्रिटेन के परस्पर आर्थिक सम्बन्धों को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ और अंक भी सहायक होंगे। १९५५-५६ में भारत सरकार के स्टोर्स डिपार्टमैण्ट ने यूरोप में जो आर्डर दिये, उनमें ब्रिटेन का बहुत अधिक भाग था। यह इन अंकों से स्पष्ट होगा।

भारत के स्टोर्स डिपार्टमैण्ट द्वारा यूरोप में आर्डर

ब्रिटेन	१,१५,००,००० पौण्ड
फ्रांस	४०,००,००० पौण्ड
जर्मनी	४०,००,००० पौण्ड
इटली	३५,००,००० पौण्ड
यूगोस्लाविया	२२,५०,००० पौण्ड
पौलेण्ड	२०,००,०००

भारत ब्रिटेन का बहुत बड़ा ग्राहक ही नहीं है, भारी मात्रा में माल बेचकर काफी रुपया भी कमाता है। गत वर्ष १९५६ में हमने ब्रिटेन को १४१० लाखों का माल बेचा, भारत से ब्रिटेन को सबसे अधिक

[सम्

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

की जाने वस्तु चाय थी। लगभग ६९० लाख पौंड मूल्य की चाय, इङ्गलैंड भेजी गई। यद्यपि यह मूल्य राशि १९५५ में निर्यात की गई राशि की अपेक्षा ८ प्रतिशत कम है, लेकिन परिमाण मे इस वर्ष २९९० लाख पौंड चाय भेजी गई, जब कि १९५५ में २८३० लाख पौंड चाय भेजी गई थी।

इस वर्ष चमड़ा तथा फर का बना सामान ११४.७५ लाख पौंड के मूल्य का इङ्गलैंड को निर्यात किया गया, जबकि १९५५ में यह राशि १२६.२ लाख पौंड थी। तम्बाकू तथा सिगरेट का निर्यात इस वर्ष ८२ लाख पौंड का हुआ, पिछले वर्ष ७१.६ लाख पौंड का ही निर्यात किया गया था।

फुटकर सूती कपड़ों के निर्यात में इस वर्ष कुछ कमती हुई। १९५६ में ११७ लाख पौंड का ही निर्यात हुआ, जब कि १९५५ में इनका निर्यात १४४ लाख पौंड था।

इसी प्रकार रुई का निर्यात ४० लाख पौंड से कम होकर ३० लाख पौंड का ही हुआ। इस वर्ष ७० लाख पौंड सूत इङ्गलैंड भेजा गया। साथ ही वनस्पति तेल ८० लाख पौंड तथा कच्चे खनिज २० लाख पौंड के मूल्य के निर्यात किये गये।

ऊन का निर्यात इस वर्ष अपेक्षाकृत कम हुआ, पर फिर भी यह ४० लाख पौंड का ही है।

इन अंकों से स्पष्ट है कि आयात व निर्यात दोनों तरह के व्यापारिक सम्बन्ध ब्रिटेन व भारत मे बहुत घनिष्ठ हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के विकास के लिए और भी अनेक योजनाएं ऐसी हैं, जिन पर दोनों देशों में सहयोग की चर्चायें चल रही हैं। उनके पूर्ण होने पर आयात की मात्रा बहुत बढ़ जायगी। आयातित माल की मात्रा ही नहीं, इसके कारण ब्रिटेन की जहाजी, बीमा व बैंक कम्पनियों का बढ़ता हुआ लाभ भी असाधारण होता है।

ऐसी अनुकूल परिस्थितियों में ब्रिटेन व भारत के राजनैतिक संबंध पिछले तीन मास से कटु से कटुतर होते जा रहे हैं। मिश्र पर आक्रमण के विरोध से क्षुब्ध होकर ब्रिटेन खुल्लम खुल्ला काश्मीर के प्रश्न पर पाकिस्तान का अविवेकपूर्ण समर्थन करने लगा है। इस नयी स्थिति का परिणाम क्या होगा, यह हमें सोचना है।

हम क्या कर सकते हैं?

ब्रिटेन के राजनीतिज्ञ मिश्र सम्बन्धी भारतीय रुख का विरोध करने के लिये आधार भूत बात भूल गये हैं। ब्रिटेन के भारत विरोधी रुख का परिणाम आर्थिक दृष्टि से ब्रिटेन के लिए कितना भीषण हो सकता है, इसकी कल्पना भारत-विरोधी आवेश में आकर नहीं की गई। भारत में ब्रिटेन के विरुद्ध जो तीव्र असन्तोष पैदा हो रहा है, वह उपर्युक्त गहरे आर्थिक संबंधों पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। राष्ट्रमण्डल से सम्बन्ध-विच्छेद की चर्चा आज केवल कम्युनिस्ट नेता ही नहीं करते, भारत के कांग्रेसी नेता भी करने लगे हैं। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के सबसे बड़े समर्थक पं० जवाहरलाल नेहरु भी ब्रिटेन के भारत विरोधी रुख पर

> "गलती मत करो। ब्रिटेन को आज कामनवैल्थ के अन्तर्गत भारत की आवश्ययकता है। यदि भारत कोमनवैल्थ से निकल जाता है, तो हम बहुत कुछ खो देंगे। भारत ब्रिटेन से विशाल स्टीलिंग निधि वापस लेकर हमें भंयकर आर्थिक संकट में डाल सकता है। यदि भारत को हमने खो दिया, तो वह रूस और चीन के हाथों में पड़ जायेगा।"
>
> —लन्दन के पीपल में प्रकाशित लेख से

अत्यन्त क्षुब्ध हो गये हैं। यदि ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने परस्पर बिगड़ते हुए सम्बन्धों को सुधारने का प्रयत्न नहीं किया, तो यह बहुत सम्भव है कि भारत निम्नलिखित कदम उठाने पर बहुत अनिच्छापूर्वक विवश हो—

१. भारतवर्ष की मुद्रा स्टर्लिंग के साथ जुड़ी हुई है, इससे ब्रिटेन को बहुत लाभ होता है। हम अनेक देशों के साथ स्टर्लिंग मुद्रा में ही व्यापार करते हैं और ब्रिटेन इस दृष्टि से हमारे बैंकर का काम करता है। भारत सरकार ब्रिटेन को यह सूचना दे सकती है कि अब वह अन्य देशों के साथ स्वयं अपनी मुद्रा में ही सम्बन्ध स्थापित करेगी। स्टर्लिंग का माध्यम और बन्धन वह स्वीकार नहीं करेंगे। अब तक इसी बन्धन के कारण हमें अपने विनिमय दर में परिवर्तन करने पड़े हैं। यह कदम उठाने से वह

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हमारा बैंकर नहीं रहेगा और निस्सन्देह इङ्गलैंड को काफी नुकसान होगा ।

२—अर्थ शास्त्र के विद्यार्थी जानते हैं कि ओटावा पैक्टके अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य के देशों को तरजीह देने की जो नीति प्रारम्भ की गई थी, आज भी जारी है। उस समय इसका बहुत विरोध हुआ था लेकिन हम पराधीन थे। कुछ कर नहीं सकते थे। १९३९ को सन्धि और साम्राज्य पक्षपात की नीतियों का अर्थ केवल यह है कि ब्रिटेन को उसके माल पर दूसरे देशों की अपेक्षा हम अधिक रियायत दें। ब्रिटेन ने भी पहले भारत के कच्चे माल को अधिक रियायत देने का वचन दिया था। किन्तु देशविभाजन के बाद यह लाभ उस मात्रा में भारत को नहीं रहा क्योंकि कच्चा माल अधिक पैदा करने वाले प्रदेश पाकिस्तान में चले गये हैं। फिर भी भारत को चाय, तम्बाकू, कपास, तिलहन आदि के ब्रिटेन को निर्यात से काफी विदेशी मुद्रा मिल जाती है।

३—विदेशी शासन के समय से ही अनेक ब्रिटिश कम्पनियों को विशेष सुविधायें भारत में प्राप्त हैं और वे व्यापार व उद्योग में अधिक लाभ उठा लेती हैं। अनेक देशों को इस पर आपत्ति है। इस सुविधा को समाप्त करने की माँग देश में की जाने लगी है।

४—ब्रिटेन से भारत पंचवर्षीय योजना की पूर्ति में विशेष सहायता ले रहा है - यदि वह सहायता दूसरे देशों से लेने लगे, तो ब्रिटेन के उद्योग को काफी नुकसान हो सकता है। आज रूस तथा पूर्वी यूरोप के देश यह सहायता देने में आगे बढ़ रहे हैं।

५—अब तक ब्रिटेन के बैंक, बीमा कम्पनियां, और जहाज भारतीय अर्थ व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यदि भारत अपने बैंकों, जहाजों और बीमा कम्पनियों को अधिक उन्नत और समर्थ करने का प्रयत्न करे तो ब्रिटेन को भारी चोट लग सकती है।

५—ब्रिटिश राष्ट्र मण्डल या कामनवैल्थ को भारत यदि छोड़ दे, तो इसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव इंगलैण्ड की आर्थिक परिस्थिति पर पड़ सकता है। इस कामनवैल्थ के कारण इंगलैण्ड आज भी अपने राजनैतिक वर्चस्व को थोड़ा बहुत कायम किये हुए हैं। आर्थिक व व्यापारिक सुविधाएं भी इसके कारण इंगलैण्ड को प्राप्त हो भारत जैसे विशाल देश के इसे छोड़ देने से उसका बहुत कम हो जायगा।

यह सब सम्भावनायें हैं, जिन पर ब्रिटेन के राज और विशेष कर उद्योगपति और व्यापारी अब सोच हैं। सुरक्षा परिषद में, जब इंगलैण्ड पाकिस्तान का र्थन कर रहा था, तब राजनीतिक प्रतिशोध की भा उसके समक्ष थी। इसलिये उस समय वह यह नहीं पाया कि इसके दूसरे भयंकर परिणाम भी सकते हैं। इंगलैंड के नेताओं और शासकों को यह गम्भीरता से सोचना पड़ रहा है कि व्यापार राजनीतिक प्रतिशोध में से उसे किस चीज को महत्त्व देना है।

हमारी असुविधाएं

हमने ऊपर इस प्रश्न पर विचार किया है कि और ब्रिटेन के पारस्परिक सम्बन्ध यदि खराब हो जा ब्रिटेन को कितनी क्षति पहुंच सकती है। किन्तु इसके इसका एक दूसरा पहलू भी है, जिसकी हम उपेक्षा कर सकते। और वह यह है कि ब्रिटेन के साथ स विच्छेद कर लेने पर भारत को भी आज अनेक अ धाओं का सामना करना पड़ सकता है। उसको इंगलैंड बड़ा ग्राहक आसानी से नहीं मिलेगा। आज पूं सामान की कमी सारे विश्व में है। स्टर्लिंग निधि हमारी ब्रिटेन में काफी जमा है। ब्रिटिश मशीनरी न से हमारे आयात व्यापार का क्षेत्र बहुत संकुचि जायगा। कामनवेल्थ छोड़ने से आस्ट्रिया व कैना व्यापार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऐ अन्य अनेक प्रश्न भी हो सकते हैं, जिन पर हमें वि करना होगा। फिर भी यह मानना चाहिये कि यदि आ संघर्ष प्रारम्भ हो गया तो ब्रिटेन को अधिक क्षति पहुंचे

हमारे व्यापार का नया क्षेत्र

रूस, पौलैंड, जैकोस्लोवाकिया, यूगोस्लेविया, जर्मनी और हंगरी आदि देशों से होने वाली व्या संधियां विदेशी व्यापार को बढ़ा रही हैं। अप्रैल से न (१९५६-५७) में पूर्वी जर्मनी से आयात व निर्यात १९०

[शेष पृष्ठ १७१ पर]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जनसंख्या और भारतीय अर्थ-व्यवस्था

श्री पद्मपत सिंहानिया

पंचवर्षीय योजना के द्वारा भारत में कल्याणकारी अर्थ-व्यवस्था के निर्माण का निश्चय किया गया है और छोटी बड़ी योजनाओं के द्वारा राष्ट्रीय आय की वृद्धि के लक्ष्य नियत किये गये हैं, किन्तु कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था के लिए सम्पूर्ण राष्ट्र की आय में वृद्धि के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि प्रति व्यक्ति आय में, लोगों के रोजगार में और रहन सहन के स्तर में भी वृद्धि हो, तभी कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य पूर्ण हो सकेगा। इतना ही पर्याप्त नहीं है कि पंचवर्षीय योजना से अधिक से अधिक लोगों को काम मिले और उत्पादन बढ़ाकर कुल देश को राष्ट्रीय सम्पत्ति व आय को बढ़ाया जाए; वरन् प्रति व्यक्ति-आय की वृद्धि भी करनी है। ऐसा विश्वास किया जा रहा है कि १९७५ तक भारत में कुल उत्पादन की मात्रा और रोजगार की सुविधाएं काफी हद तक बढ़ जाएंगी। आर्थिक उन्नति की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में दूसरा या तीसरा हो जाएगा। लेकिन एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या इस आर्थिक उन्नति का प्रति व्यक्ति की आय और उपभोग्य की वस्तुओं के उत्पादन पर भी कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं? यह प्रश्न इसलिए और भी महत्वपूर्ण बन जाता है कि हमारे देश की जन-संख्या निरन्तर तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। नई योज-नाएं राष्ट्रीय आय में वृद्धि करके भी प्रति व्यक्ति आय संभवतः बहुत कम बढ़ा सकेंगी। इसलिए यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य होगा कि हम बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण रखें, तभी हम आज के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े भारत को, आर्थिक रूप से समृद्ध बना सकते हैं। नीचे की तालिका से, १९५०-५१ से शुरू होने वाले आगामी २०-२५ वर्षों में होने वाली जनसंख्या और कुल राष्ट्रीय आय की वृद्धि का चित्र स्पष्ट हो जाता है—

लेखक

	१९५०-५१	१९५५-५६	१९६०-६१	१९६५-६६	१९७०-७१	१९७५-७६
कुल 'जनसंख्या करोड़ में'	३६.१	३८.४	४०.९	४३.४	४६.५	५०.०
काम करने वाली कुल जनसंख्या (करोड़ में)	१४.४	१५.३	१६.३	१७.३	१८.५	१९.९
कुल राष्ट्रीय आय (करोड़ रुपयों में)	९,१९०	१०,८००	१३,४८०	१७,२६०	२१,६८०	२७,२७०
प्रति व्यक्ति आय (रु० में)	२५५	२८१	३३०	३९८	४६६	५४५

इस तालिका से ज्ञात होता है कि २५ वर्ष बाद जब कुल राष्ट्रीय आय तिगुनी हो जाएगी, तब प्रति व्यक्ति आय दुगुनी से अधिक नहीं बढ़ सकेगी। १९७५ में भारत में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय ५४५ रु० होगी। पर आज भी विश्व के २६ देश ऐसे हैं, जिनकी राष्ट्रीय आय इससे भी ऊंची है। इन देशों में श्री लंका, जापान, फिलीपाइन तथा इटली जैसे छोटे देश भी हैं।

भारत तथा अन्य ८-९ देशों की राष्ट्रीय आय और और प्रति व्यक्ति की आय की वृद्धि का तुलनात्मक अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि भारत की राष्ट्रीय आय तेजी से बढ़ रही है। पर प्रति व्यक्ति आय में उसी तेजी से वृद्धि नहीं हुई है।

सभी यह मानते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि का कारण

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारत की जनसंख्या में वृद्धि

यही है कि मृत्यु संख्या से जनसंख्या का अनुपात बहुत ऊंचा रहता है। नीचे के तालिका से भारत और अन्य देशों की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि का अनुमान किया जा सकता है।

बढ़ती हुई जनसंख्या का अनुमान (करोड़ में)

	१९५५	१९६०	१९६५	१९७०	१९७५
विश्व	२६९.५	२८४.२	२९९.६	३१५.९	३४०.०
भारत	३८.८	४०.९	४३.४	४६.५	४९.३
अमेरिका	१६.६	१७.८	१९.२	२०.६	२२.५
रूस	२२.०	२३.५	२५.२	२७.१	२९.२
चीन	५५.०	६०.०	६६.०	७२.५	८०.०

इन अङ्कों से स्पष्ट है कि आगामी २० वर्षों में भारत की जनसंख्या १० करोड़ बढ़ जायगी। राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था के आयोजन में जनसंख्या के आकार की बढ़ती हुई विषमता पर विचार करना अत्यन्त आवश्यक है। अत्यधिक जन-संख्या की वृद्धि से हमारा जीवन स्तर बुरी तरह से नीचा ही नहीं होता, वरन् साथ ही शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, उन्नति आदि की उन योजनाओं को भी हानि पहुँचती है, जो प्रत्येक नागरिक के निजी विकास के लिए आवश्यक है। जितने भी स्कूल, अस्पताल आदि खोले जावेंगे, बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए वे पर्याप्त नहीं रहेंगे।

हमारे गांवों में जनसंख्या की वृद्धि का कारण २०० वर्ष के ब्रिटिश शासन द्वारा निर्मित दोषपूर्ण आर्थिक और सामाजिक पद्धतियां हैं। इन दो शताब्दियों में गांवों और उनकी समस्याओं पर कभी भी विचार नहीं किया गया और न ही ग्रामीण जनता को स्वस्थ वातावरण में रहने और काम करने की सुविधाओं पर कोई ध्यान दिया गया। स्वयं गांव वालों के संस्कार ऐसे न थे कि वे अपनी उन्नति में रुचि ले सकें। वे गरीबी में पिसते रहे, पर जीवन

१९५३ में विभिन्न देशों की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय

देश	राष्ट्रीय आय अमेरिकी डालर में (लाखों में)	प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डालर में
आस्ट्रेलिया	८३,१९०	९४४
आस्ट्रिया	२,४,३१०	३५०
ब्राजील	१,८१,८९०	३२६
श्रीलंका	९,२६०	११४
चिली	२४,२४०	३८३
डेनमार्क	३२,७७०	७५०
फ्रांस	३,१०,०३०	७२३
पश्चिमी जर्मनी	२,४६,९००	५०४
आइसलैंड	१,५९०	१,०५३
भारत	२,२२,६००	६०
इटली	१,४७,६२०	३११
जापान	१,६५,६९०	१९१
नेदरलैंड	५०,९२०	४८५
नार्वे	२४,०७०	७१७
फिलीपाइन्स	३६,१७०	१७२
दक्षिणी अफ्रीका	३८,५१०	२९३
ग्रेट ब्रिटेन	४,११,६८०	८०९
स. रा. अमेरिका	३,०५,०००	१,९११

१०० डालर = ४८० रुपए ९ आने।

के प्रति भाग्यवादी और दुलमुल मनोवृत्ति के कारण उनमें कोई चेतना न आ सकी।

भारत में पंचवर्षीय योजना के द्वारा जो आर्थिक उन्नति की जा रही है, उससे ग्रामों को इस परम्परागत व्यवस्था से कुछ छुटकारा मिल जायगा। फिर भी सच्ची आर्थिक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उन्नति प्राप्त करने के लिए जनसंख्या की वृद्धि पर अच्छी प्रकार से रोक लगाई जानी चाहिए, ताकि जनसंख्या और जीवन-स्तर की असमता को दूर किया जा सके। भारतमें जनसंख्या बढ़ रही है, पर जीवन-स्तर उसी प्रकार नहीं बढ़ रहा है। जनसंख्या की इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दृष्टि मे रखते हुए सहज ही में जाना जा सकता है कि जिस तेजी से श्रमिकों की पूर्ति हो रही है, काम उसी प्रकार नहीं मिल रहा है। निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि १९७५-७६ मे जनसंख्या और रोजगार का स्वरूप क्या होगा, क्योंकि इसके लिए उत्पादन, उपभोग और उच्च जीवन-स्तर सम्बन्धी उपयुक्त आंकड़ों के संग्रह की आवश्यकता है। फिर भी यह कल्पना की गई है कि १५ से ६० वर्ष तक की आयु वाले व्यक्ति लाभप्रद रोजगारों को प्राप्त करना चाहेंगे। इनके अतिरिक्त ६.३ करोड़ लोग पहले से ही रोजगार में लगे होंगे। संभवतः १९७५-७६ तक हमारी इतनी आर्थिक उन्नति न हो सके कि हम सब लोगों को तब काम दे सकें। भले ही आगामी पंचवर्षीय योजनाओं का स्वरूप जैसा भी रहे। यदि हम कृषि के अतिरिक्त अन्य पेशों में रोजगार की व्यवस्था करना चाहते हैं तो हमें बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा, क्योंकि १९७५ तक ऐसे पेशों में अधिक से अधिक २.५ करोड़ व्यक्तियों को ही काम दिया जा सकेगा, जबकि जनसंख्या १० करोड़ तक बढ़ जायेगी।

५ अरब रु० की योजना

सच तो यह है कि देशकी अर्थ व्यवस्थाके सुधार-सम्बन्धी समस्त प्रयत्न तब तक अधूरे रहेंगे, जब तक साथ ही साथ जनसंख्याकी समस्या पर विचार नहीं किया जाता। एक ओर जहां हम देश की अर्थ व्यवस्थाकी उन्नति के लिए साधन जुटाते हैं, वहां दूसरी ओर जनसंख्याके नियंत्रण के लिए प्रभावशाली कदम उठाने चाहिए। सामाजिक अर्थ-व्यवस्थाकी लिए, पारिवारिक सुख-शांतिकी स्थापनाके लिए तथा राष्ट्र के आयोजन कार्य और विकास के लिए बच्चों के जन्म पर नियंत्रण करके, परिवार का आकार कम करना अत्यन्त आवश्यक हो गया है। सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को परिवार-नियोजन की स्वतः प्रेरणा हो तथा सम्बन्धित साधनों के उपयोग के लिए सरकार की ओर से प्रोत्साहन मिले। साथ ही संतति-निरोध के उपायों का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए। जन्म-निरोध सम्बन्धी सस्ते और उपयोगी उपकरणों के प्रयोग के लिए डाक्टरी सहायता उपलब्ध होनी चाहिए। बहु-विवाह को समाप्त करने और विवाह की उम्र को बढ़ाने के लिए दृढ़ कानून बनाने चाहिए। देश की समस्त चिकित्सा सम्बन्धी संस्थाओं को सरकार को इस काय में योग देना चाहिए। आगामी २० वर्षों में इस क्षेत्र में ५ अरब रुपए खर्च करने से हमें इच्छित फल की प्राप्ति हो जाएगी, तथा देश के ५ लाख ६० हजार गांवों पर यानें ८३% जनता पर इसका सुन्दर प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार यदि जनसंख्या की वृद्धि को ठीक रूप से रोजगार के अनुरूप ही रोक लिया गया तो आगामी २० वर्षों में हमारा कुल राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ जाएगा, जिससे हमारा उपयोग भी बढ़ेगा तथा राष्ट्र का जीवन स्तर ऊंचा उठ जायगा। इस का तात्पर्य यह है कि जनसंख्याके नियंत्रण सम्बन्धी उपायों के लिए ५ अरब रुपए खर्च करने से हम ३१ अरब रुपए की बचत कर लेते हैं, जिसको हम अन्य विकास कार्यों में लगा सकेंगे।

इसमें सन्देह नहीं कि प्रति व्यक्ति की उत्पादकता या कार्यक्षमता में वृद्धि होने से ही राष्ट्र के उत्पादन और रोजगार में वृद्धि होगी। इसी के कारण देश की समृद्धि भी होगी। विभिन्न पेशों में लगे व्यक्तियों की कार्यक्षमता उनके जीवन स्तर और उपभोग पर निर्भर है। योजना के अनुसार १९७५ तक देशका उत्पादन प्रतिवर्ष ८ की दर से बढ़ाने का निश्चय किया गया है। इस दर को १० प्रतिशत किया जा सकता है। पर शर्त यह है कि जनसंख्या पर नियंत्रण रखा जावे। ऐसा करने से हमारी राष्ट्रीय आय १९७५ तक ३० हजार करोड़ से भी अधिक हो सकेगी। नहीं तो जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि हमारे उत्पादक साधनों को व्यर्थ करने का प्रयत्न ही नहीं करती रहेगी, वरन् हमारे जीवन स्तर और उपभोग पर भी बुरा प्रभाव डालेंगी। इस समस्या पर भली प्रकार विचार किया जाना चाहिए। मेरा विश्वास है कि सरकार और योजना आयोग ने इस समस्या की गंभीरता को समझ लिया है, लेकिन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आर्थिक प्रतिस्पर्धा के दो रूप : सहकारिता और सहयोगिता

[प्रो० विश्वम्भरनाथ पाण्डेय]

आधुनिक अर्थशास्त्र के सर्वप्रथम सुव्यवस्थित लेखक श्री आदम स्मिथ ने अपनी असीम आशावादिता की झोंक में जिस 'अदृश्य सत्ता' (इनविजिबल हैन्ड) की कल्पना की थी वह कल्पना नहीं, अपितु एक अस्तित्वमान सत्य का दर्शन था। आदमोस्मिथ ने कहा था कि मानवीय आचरण वस्तुतः आत्मप्रेम, सहानुभति, स्वातंत्र्येच्छा, आत्मगुण-परिज्ञान, परिश्रम के लिए अभ्यास और विनिमय प्रियता इन छः मानव स्वभाव को मूल प्रवृत्तियों द्वारा प्रेरित होते हैं; और ये प्रवृत्तियां परस्पर इतनी संतुलित हैं कि मनुष्य जब कोई आर्थिक क्रिया अपने हित की दृष्टि से करता है तो वह अनजाने और अनायास ही दूसरों का भी हित स्वतः सम्पादित कर डालता है। इसीलिये समष्टि के कल्याण के लिये किसी बाहरी शक्ति (राज्य अथवा ऐसे ही अन्य मानवीय संगठन) के हस्तक्षेप की न तो कोई आवश्यकता है और न वांछनीयता क्योंकि समाज के विभिन्न व्यक्तियों के हित परस्पर अविरोधी ही नहीं, अपितु एक दूसरे के स्वयमेव स्थापक भी हैं।

वास्तव में यह एक बड़ी विचित्र बात है कि हमारे समाज की व्याधियां स्वयं ही अपना उपचार भी हैं। आज का मानव जिस आर्थिक जगत में जी रहा है, वहां चारों ओर प्रतिद्वन्दिता और प्रतिस्पर्द्धा का राज्य है। हर मनुष्य हर मनुष्य का—फिर वह चाहे आज का चाहे कल का उत्पादक हो अथवा उपभोक्ता—प्रतिद्वन्द्वी है। छात्रों में योग्यता के क्रम में प्रथम आकर अच्छी नौकरी पाने की होड़ लगी है, शिक्षकों में इन छात्रों का शिक्षक बनकर इनके दिये हुए शुल्क पर अधिकार पाने की होड़ है, वस्तुओं के विक्रेताओं की अपने क्षेत्र के अन्य व्यवसायियों से होड़ है और हर क्रेता की बाजार के अन्य क्रेताओं से होड़ है क्योंकि हर विवेकी यह जानता है कि आर्थिक वस्तुओं की 'पूर्ति' समाज की 'कुल मांग' की तुलना में नितान्त अप्रचुर है। हम में से हर कार्यरत व्यक्ति सेवा (श्रम) अथवा वस्तु अथवा दोनों ही का क्रेता भी है और विक्रेता भी। अगर हमारे छात्रों के अभिभावक हमारी सेवाओं के क्रेता हैं तो उन नाना वस्तुओं के विक्रेता भी, जिन्हें हम उन्हीं के दिए पैसों से बाद में खरीदते हैं। हम जब किसी वस्तु को खरीदते हैं तो मूल्य के रूप में अपने पैसों को बेचते भी हैं। हमारे पैसे हमारी उन सेवाओं तथा वस्तुओं के प्रतीक हैं जिनके द्वारा हमने उन्हें अर्जित व उपार्जित किया है। इस प्रकार प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष रूप से हमारे आर्थिक समाज का हर व्यक्ति, क्रेता भी है और विक्रेता भी। यदि कोई श्रमिक अपने श्रम का विक्रेता है तो उसे नियुक्त करने वाले उद्योगपति के रुपये का क्रेता भी। इस प्रकार हमारे आर्थिक जगत का निर्माण इन असंख्य क्रेताओं और विक्रेताओं से ही हुआ है जिनमें निरन्तर होड़ मची है।

यहीं रुक कर यदि हम यह प्रश्न करें कि इस स्थिति का होना क्या 'भला' है तो शायद आप कहेंगे भला ऐसी सामाजिक स्थिति की भी क्या अपेक्षा, जिसकी कोख से संघर्ष और स्पर्द्धा का जन्म होता है; समाज में द्वेष और परस्पर ईर्ष्या बढ़ती है; एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता का अंश हड़पने की कोशिश करता है और उत्पादक गलाकट प्रतिस्पर्द्धा के विभिन्न दांव पेंचों द्वारा बाजार के दूसरे उत्पादकों का अस्तित्व मिटाने की दम भर कोशिश करते हैं। यही न? किन्तु नहीं, यह उत्तर ठीक नहीं। इस स्पर्द्धा का होना आवश्यक है, क्योंकि यह व्याधि के साथ

जनता अभी इस समस्या के प्रति उदासीन है। यदि दिन प्रतिदिन विकराल होती हुई जनसंख्या की इस समस्या पर और विकास कार्य के साधनों पर पर्याप्त विचार करके हल के उपाय ढूंढ लिए जाएं तो आगामी २० वर्षों में राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य सफलता से सम्पन्न कर लेंगे।

— —

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बचत देश की महान सेवा है

•

हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आगामी पांच वर्षों में ४,८०० करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था की गई है। इससे नये भारत के निर्माण में योग मिलेगा। इतनी बड़ी राशि में से ५०० करोड़ रुपये राष्ट्रीय बचतों से संग्रहीत किये जाएंगे। आपका योगदान चाहे कितना ही अल्पांश हो, राष्ट्र के निर्माण में सहायक होगा।

•

भारत के भविष्य में धन लगाइये

राष्ट्रीय बचतें

राष्ट्र की समृद्धि के लिए

विस्तृत जानकारी और/अथवा धन जमा करने की नियमावली के लिये नेशनल सेविंग्ज कमिश्नर शिमला अथवा अपने राज्य के रीजनल नेशनल सेविंग्ज आफिसर को लिखिए।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

साथ उसका एक मात्र उपचार भी है। स्पर्द्धा और अपने दूसरे प्रतियोगी के भय के ही कारण एक विक्रेता किसी वस्तु का जितना अधिक मूल्य क्रेताओं से लेना चाहता है, नहीं ले पाता। इसी प्रकार बाजार के अन्य क्रेताओं और उपभोक्ताओं की स्पर्द्धा के ही कारण एक उपभोक्ता वा क्रेता अनुचित दबाव डालकर किसी वस्तु का जितना कम मूल्य देना चाहता है, नहीं दे पाता। बाजार में समान वस्तुओं के मूल्य में हम जो समानता, व्यवस्था और एक रूपता पाते हैं, उसका प्रतिस्पर्द्धा ही कारण है। यदि अफगान और रेमी 'स्नों' का दाम बाजार में एक नहीं हैं तो इसका कारण या तो यह होगा कि उनमें से एक, दूसरे से गुण में अच्छा है, या मात्रा में अधिक है, या अच्छी शीशी और आकर्षक डिब्बे में बिकता है, या कुछ देर के लिये अधिक सुगन्ध देता है या और कुछ नहीं तो उसके उत्पादकों ने सुन्दर मुखाकृति के विज्ञापनों के माध्यम से आपके मन में उसके प्रति यह झूठी आस्था बैठा दी हैं कि संसार के सभी सुन्दर मुखड़े वाले इसे ही प्रयोग करते हैं। तात्पर्य यह कि वास्तविक या अवास्तविक असमानता के अभाव में समान वस्तुओं का मूल्य आर्थिक स्पर्द्धा के बीच असमान नहीं हो सकता। अर्थशास्त्र में 'बाजार' की कसौटी ही 'एक वस्तु एक मूल्य' माना गया है। अतः स्पर्द्धा वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में निराधार अव्यवस्था के ऊपर एक प्रभावशाली नियंत्रण का काम करती है और बाजार में न तो किसी विक्रेता का एकाधिकार उत्पन्न होने देती है न किसी क्रेता का सर्वाधिकार।

उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही

क्रेता और विक्रेता होने के कारण ही हम में से हर व्यक्ति सेवाओं अथवा वस्तुओं का उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही हैं और प्रतिस्पर्द्धा के कारण अपने समाज के हर अन्य सदस्य के समक्ष प्रतियोगी (विरोधी हितों वाला) और सहयोगी (समान हित वाला)—इन दो विरोधी रूपों में खड़ा है। प्रतियोगी के रूप में मनुष्य संघर्ष विरोध और स्पर्द्धा करता है और सहयोगी के रूप में साथ और सम्बन्ध। मजदूर रोजगार पाने के लिये अन्य मजदूरों के साथ संघर्ष भी करता है और मालिक के साथ शोषण के विरुद्ध लड़ने के लिये अथवा अधिक मजदूरी प्राप्त करने के लिए उन्हीं के साथ संघ भी बनाता है। दूसरे शब्दों में हम यह कहें कि अपने विरोधी हित वालों के साथ संघर्ष लेने के लिए मनुष्य अपने समान हित वालों के साथ संघबद्ध होता है और मेल करता है। इस प्रकार के संघों की हम दो श्रेणियां कर सकते हैं। एक वह जो वस्तु अथवा सेवाओं के विक्रय में प्रतिस्पर्द्धा कम करने के लिए और क्रेताओं को उनकी (विक्रेताओं की) प्रतिस्पर्द्धात्मक स्थिति के लाभ से वंचित करने के लिए विक्रेता करते हैं और दूसरी बार वह जो वस्तु अथवा सेवाओं के क्रय में प्रतिस्पर्द्धा घटाकर विक्रेताओं से सम्मिलित संघर्ष लेने के लिये क्रेता करते हैं। अर्थात् उत्पादकों (विक्रेताओं) का संघ तथा उपभोक्ताओं (क्रेताओं) का संघ। यहां यह स्मरणीय है कि आज के अतिशय 'श्रम-विभाजन' के युग में प्रचलित भाषा में उत्पादक हम मुख्यतः वस्तुओं के ही उत्पादकों को मानते हैं। सेवाओं के उत्पादकों जैसे डाक्टर, शिक्षक और मजदूर आदि को मुख्यतः हम उपभोक्ता या क्रेता मानते हैं।

प्रथम श्रेणी के संघों अर्थात उत्पादकों के संघों को अर्थशास्त्र में 'सहयोगिता' (Combination) कहते हैं और द्वितीय श्रेणी के संघों को 'सहकारिता' (Co-operation), किन्तु आजकल कतिपय सहकारी संघ छोटे छोटे उत्पादकों की सदस्यता से भी निर्मित हो रहे हैं जैसे 'कोआपरेटिव विवर्स सोसाइटी'। तो 'सहयोगिता' और 'सहकारिता' में अन्तर क्या है? अन्तर यह है कि पहला शोषण का प्रयास है, जबकि दूसरा आत्मरक्षा का उपाय। अर्थात् 'सहयोगिता' और 'सहकारिता' में प्रकार का नहीं अपितु उद्देश्य का अन्तर है। इस कसौटी से 'चैम्बर्स आफ कामर्स' सहयोगिता हैं और 'ट्रेड यूनियन्स' (मजदूर संघ) सहकारिता

उत्पादकों के संघ

आजकल औद्योगिक क्षेत्र के विभिन्न उत्पादक विभिन्न उद्देश्यों जैसे प्रतिस्पर्द्धा का अन्त, कच्चे पदार्थों के मूल्य पर दबाव, एकाधिकार मूल्य तथा औद्योगिक प्रभुत्व (industrial leadership) आदि के लिये विभिन्न प्रकार की औद्योगिक सहयोगिताओं की स्थापना

[शेष पृष्ठ १७० पर]

[सम्पादक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पश्चिमी योरप में स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र : नई योजना

पश्चिमी यूरोप के ६ देश मुख्यतः—फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नेदरलैंड और लक्जमबर्ग पश्चिमी यूरोप के लिए स्वतंत्र व्यापार-क्षेत्र की एक योजना बनाने में व्यस्त हैं। इस योजना के अनुसार सम्बन्धित देशों के कृषि और औद्योगिक उत्पादनों के इस क्षेत्र में व्यापार पर कोई रुकावट न होगी। साथ ही इन सब देशों में एक जैसी तट कर-नीति का पालन किया जाएगा। अभी तो यह योजना बन ही रही है। योजना के बन जाने और इसके ठीक-ठीक स्वरूप निश्चित हो जाने पर पश्चिमी यूरोप के १७ देशों को निश्चित करना होगा कि वे इसमें भाग लें या अलग रहें।

पश्चिमी यूरोप के देशों का विश्वास रहा है कि इस योजना में ब्रिटेन का सम्मिलित होना अति आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना पश्चिमी जर्मनी उन पर हावी हो सकता है। वैसे सम्मिलित व्यापार की योजना में समरूपता लाने के लिए जिस समिति का गठन किया गया है, उसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के वित्त विभाग के प्रधान श्री थोरेनी कौएट को प्रदान की गई। ब्रिटेन प्रारम्भ से इस 'स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र' का समर्थन करता रहा, लेकिन अब वही एक ऐसा देश है, जो कृषि-पदार्थों पर तट कर को कम करने का विरोध कर रहा है। किसी भी सम्बन्धित देश की अपेक्षा, ब्रिटेन पश्चिमी यूरोप से सर्वाधिक कृषिमाल का आयात करता है, इसलिए उसका तट कर कम न करने का उद्देश्य अनावश्यक रूप से आयात कम करना नहीं हो सकता। तब उसका उद्देश्य क्या है? वस्तुतः ब्रिटेन राष्ट्र मंडल और उपनिवेश के देशों के माल को प्राथमिकता देना आवश्यक समझता है; क्योंकि राष्ट्रमंडल की सुदृढ़ता के लिए उसका राष्ट्रमण्डलीय देशों से कच्चा माल मंगाना बहुत जरूरी हो जाता है।

फ्रांस का मत इससे भिन्न है—वह अपने विदेशी उपनिवेशों को स्वतंत्र व्यापार के क्षेत्र में लाना चाहता है। उसका विश्वास है कि इससे सम्बन्धित देश वहां पूंजी का विनियोग करेंगे। एक बात और भी है, फ्रांस के उपनिवेशों का कृषि उत्पादनों की पश्चिमी यूरोप से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, क्योंकि उनमें वे पदार्थ पैदा नहीं होते, जो यूरोप में होते हैं।

इन देशों के विदेशी मंत्रियों की जो मिनिस्ट्रियल कौंसिल बनी है, उसने औद्योगिक वस्तुओं पर तटकर की कमी की संभावना पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने का निश्चय किया है। इस कौंसिल ने इसी प्रकार की एक समिति को ग्रीस टर्की, जैसे अन्य कमजोर देशों की कठिनाइयों पर विचार करने को कहा है। ब्रिटेन ने कृषि पदार्थों के तटकर सम्बन्धी जो अपना विचार रखा है, उस पर भी एक समिति द्वारा विचार किया जाएगा। इन तीनों समितियों का कार्य ब्रिटेन के कोष विभाग के प्रधान श्री थौरेनी कौएट की संरक्षता में किया जाएगा।

अमेरिका और कनाडा दर्शक के रूप में इसी योजना को देख रहे हैं। अमेरिका यह तो चाहता है कि योरुप के देश तटकर नीति में मिल कर चलें, लेकिन साथ ही वह नहीं चाहता कि उसके अपने हित को इन देशों के व्यापारिक समझौतों से कोई हानि पहुँचे अथवा उसके माल का यूरोप में आयात कम होने लगे।

पश्चिमी यूरोप में स्वतंत्र व्यापार-क्षेत्र का निर्माण करने वाली इस योजना को स्पाक योजना कहा जाता है, क्योंकि पश्चिमी यूरोप के उपर्युक्त ६ देशों के विदेशी मंत्रियों की जिस कौंसिल ने इस योजना की रूपरेखा बनाई, उसके अध्यक्ष बेल्जियम के विदेश मंत्री श्री स्पाक थे।

स्पाक योजना के अनुसार पश्चिमी योरुप में तटकरों को समाप्त करके स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र की स्थापना की योजना ४-४ वर्ष की ३ अवधियों में पूरी की जाएगी। प्रथम वर्ष के अन्त में तटकर में १० प्रतिशत कमी कर दी जाएगी। फिर २ बार डेढ़-डेढ़ वर्ष के अंतर पर तटकर में १०-१० प्रतिशत की कमी की जाएगी। इस प्रकार प्रथम चार वर्ष की अवधि में तटकर ३० प्रतिशत कम कर दिए जाएंगे। दूसरी अवधि में भी इसी पद्धति के अनुसार तटकर में ३० प्रतिशत की और कमी हो जाएगी, यानि

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारतीय रेलवे : गत वर्ष पर एक दृष्टि

भारत का सर्व प्रधान सरकारी उद्योग रेलवे है, जिस में ३१ मार्च १९५६ को ९ अरब ७५ करोड़ ५० लाख रु० की पूंजी लगी हुई है। एक वर्ष पूर्व ३१ मार्च १९५५ को यह राशि ९१० करोड़ ९१ लाख रु० थी। रेलवे किसी देश के औद्योगिक आर्थिक विकास में जहां प्रधान साधन है, वहां रेलवे की उन्नति को देखकर यह भी अनुमान किया जा सकता है कि देश का आर्थिक विकास किस गति से हो रहा है। इस दृष्टि से १९५५-५६ की रेलवे-उन्नति को देखकर संतोष प्रकट किया जा सकता है।

१९५५-५६ के वर्ष भारतीय रेलों ने जितना माल ढोया, उतना उनके इतिहास में पहले कभी ढोया नही गया था। यह वर्ष पहली पंचवर्षीय आयोजना का अन्तिम वर्ष है और इससे ज्ञात होता है कि देश में आयोजना से जो आर्थिक उन्नति हुई, उसका रेलों पर असर पड़ा। आयोजना के पहले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष १७.७९ प्रति शत ज्यादा माल ढोया गया, जबकि यात्रियों की संख्या में ५.३० प्र० श० वृद्धि हुई।

माल-डिब्बों का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिये जो कारवाई की गयी, उसमें भी अपूर्व सफलता मिली।

इस वर्ष सरकारी रेलों को कुल ३ अरब १६ करोड़ २९ लाख रु० की आमदनी हुई। १ अरब ७ करोड़ ७५ लाख रु० सवारियों से, १ अरब ८० करोड़ २८ लाख रु० माल की ढुलाई से और बाकी २८ करोड़ ३० लाख रु० पार्सल, सामान आदि की ढुलाई से प्राप्त हुआ।

५०.३४ करोड़ रु० आय

१९५५-५६ में रेलों का कार्य-संचालन व्यय २ अरब १२ करोड़ ९५ लाख रु० हुआ। यह खर्च १९५४-५५ के खर्च से ७ करोड़ ८ लाख रु० अधिक था। इस वर्ष संचालन-अनुपात ८१.९५ प्र० श० रहा, जबकि पिछले वर्ष यह औसत ८१.७७ प्र० श० था। मूल्य ह्रास कोष में विनियोग को मिलाकर कुल खर्च हुआ, उसे घटाने के बाद इस वर्ष की शुद्ध आय ५० करोड़ ३४ लाख रु० रही। इसमें ३६ करोड़ १२ लाख रु० सामान्य राजस्व में दिया गया। इस वर्ष मूल्य ह्रास कोष की मद में ४५ करोड़ रु० रखा गया, जबकि पिछले वर्ष ३० करोड़ रु० जमा किया गया था। इस प्रकार १९५५-५६ में १४ करोड़ २२ लाख रु० की शुद्ध बचत हुई, जिसमें से ७ करोड़ ८ लाख रु० विकास कोष में और ७ करोड़ १४ लाख रु० राजस्व संरक्षित कोष में जमा किया गया।

इस वर्ष माल की ढुलाई से १ अरब ७७ करोड़ ९२

---

८ वर्ष बाद तटकर ६० प्रतिशत घटा दिए जाएंगे। शेष ४० प्रतिशत तटकर तीसरी अवधि तक हटा लिए जाएंगे।

इस प्रकार स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र में तटकर समाप्त तो किए ही जाएंगे लेकिन इस क्षेत्र के बाहर भी शेष विश्व के साथ भी तटकर नीति का पालन किया जायगा। समस्त सदस्य राष्ट्रों के तटकर के औसत के आधार पर इसका निश्चय होगा। प्रत्येक देश की औसतन कमी एक सदस्य देश के दूसरे सदस्य देश से आयात किए गए कुल माल की मात्रा पर लगाए गए कर की कमी के प्रतिशत के आधार पर निश्चित की जाएगी।

कोटा प्रणाली को प्रतिवर्ष २०प्रतिशत की बढ़ती करते हुए समाप्त कर दिया जाएगा। क्योंकि कोटा में वृद्धि का मतलब होगा राज्य अपनी इच्छा से भी अधिक खरीदें।

इसी १० मार्च को ये ६ देश इस उद्देश्य की एक संधि पर हस्ताक्षर कर लेंगे।

इसके अतिरिक्त पश्चिमी यूरोप के इन देशों ने अणुशक्तिके मामले पर भी परस्पर सहयोग का निश्चय किया है। अणुशक्ति के केन्द्रके निर्माणमें इन्होंने अमेरिका से सहायता भी मांगी है। फरवरी के आरम्भ में ही श्री लुई आर्मण्ड (फ्रांस) सिगनोर फ्रांसिको गिर्डानी (इटली) और हर फ्रांस इरजेल (पश्चिमी जर्मनी) इसी संबंध में अमेरिका की १० दिन की यात्रा पर गए थे। इस अणुशक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी यूरोप को मध्य एशिया के तेल पर भविष्य में कम से कम निर्भर करते जाना है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लाख रु० की आमदनी हुई, जबकि १९५४-५५ में १ अरब ५६ करोड़ ४५ लाख रु० प्राप्त हुआ था। औसतन प्रति टन-मील १०.८ पाई माल भाड़ा प्राप्त हुआ, जबकि १९५४-५५ में यह औसत ११.१ पाई था। प्रति यात्री मील की आमदनी का औसत ५.१५ पाई से बढ़कर ५.३४ पाई हो गया।

ज्यादा माल और सवारियों की ढुलाई

भारतीय रेलों ने इस वर्ष ११ करोड़ ५० लाख टन माल ढोया और ३६ अरब ४५ करोड़ ८० लाख टन-मील यात्रा की। भारतीय रेलों के इतिहास में इस वर्ष सबसे ज्यादा माल ढोया गया था और ३२ अरब १२ करोड़ ६० लाख टन-मील यात्रा की गयी थी।

इस वर्ष सवारियों की ढुलाई में भी वृद्धि हुई। यात्रियों की संख्या १ अरब २९ करोड़ ७७ लाख रही, जबकि १९५४-५५ में १ अरब २६ करोड़ १० लाख। थी रेलों ने १९५५-५६ में ३९ अरब ८ करोड़ ४० लाख यात्री-मील का सफर किया, जबकि १९५४-५५ में वे ३८ अरब ६४ करोड़ ४० लाख यात्री-मील चली थीं।

आलोच्य वर्ष में माल डिब्बों की लदाई (रेलों के अपने काम के लिए लादे गये माल-डिब्बों को छोड़कर) का औसत इस प्रकार रहा: बड़ी लाइन से ११,३७७ माल डिब्बे और छोटी लाइन के ७,२६४ माल डिब्बे प्रतिदिन। पिछले वर्ष का यह औसत क्रमशः १०,६७२ और ६,४८९ माल डिब्बे प्रतिदिन था। इसका अर्थ यह हुआ कि १९५५-५६ में बड़ी लाइन की लदाई में ७ प्रतिशत और छोटी लाइन में १२ प्रदिशत की वृद्धि हुई।

अगर रेलों की अपनी या बिना राजस्व वाली लदाई को भी शामिल कर लिया जाए, तो औसतन बड़ी लाइन के १३,४२० माल डिब्बे और छोटी लाइन के ८,०२८ माल डिब्बे प्रतिदिन लादे गये, जबकि पिछले वर्ष औसतम

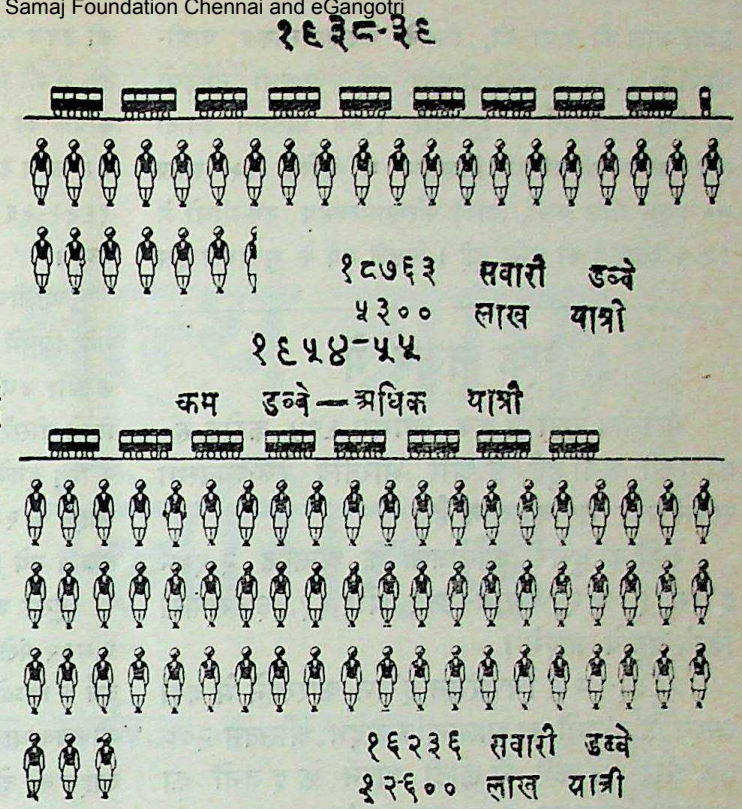

क्रमशः १२,५३२ और ७,२१५ माल-डिब्बे प्रतिदिन लादे गये थे। ये आंकड़े क्रमशः ७ और ११ प्रतिशत वृद्धि के के परिचायक हैं।

आर्थिक उन्नति और रेल

स्थिति-सुधार का एक और लक्षण यह है कि १९५५-५६ में बड़ी लाइन की माल गाड़ियों ने प्रति वैगन-दिन ५४१ टन-मील और छोटी लाईन की माल गाड़ियों ने २०३ टन-मील यात्रा की- जबकि पिछले वर्ष उन्होंने क्रमशः ४८२ टन-मील और १९४ टन-मील यात्रा की थी। ये आंकड़े बड़ी लाइन से माल की ढुलाई में १२,०८ प्रतिशत और छोटी लाइन में ४.६४ प्रतिशत वृद्धि के परिचायक हैं। माल-डिब्बों की लदाई तेजी से करने और उनका अधिक उपयोग करने के लिए जो विशेष प्रयत्न किये गये, उन्हीं के परिणामस्वरूप माल की ढुलाई में इतनी वृद्धि सम्भव हो सकी।

इस वर्ष सवारी गाड़ियों ने ११ करोड़ ५६ लाख ३०

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हजार मील की यात्रा की, जिसके परिणामस्वरूप यात्री-मीलों में १.२० प्रतिशत की वृद्धि हुई। सवारी गाड़ियों की दौड पिछले वर्ष के मुकाबले १.७४ प्रतिशत ज्यादा रही। माल गाड़ियां कुल मिलाकर ८ करोड़ २५ लाख ७० हजार मील चलीं, जिसके परिणामस्वरूप टन-मीलों में १३.६ प्रतिशत की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष माल गाड़ियां ७.०८ प्रतिशत अधिक चलीं।

१९५५-५६ में रेलों की आमदनी और कार्य में जो वृद्धि हुई, उससे देश की आर्थिक स्थिति में निरन्तर होने वाली उन्नति का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। बाढ़ों, तूफानों आदि से हानि पहुँचने के बावजूद भी, कृषि की उपज सामान्यतः सन्तोषजनक रही। औद्योगिक उत्पादन में भी पिछले वर्ष के मुकाबले ८ प्रतिशत वृद्धि हुई। कोयले का उत्पादन भी बढ़ा। पिछले साल ३ करोड़ ६९ लाख टन कोयला निकाला गया था। इसके मुकाबले १९५५-५६ में ३ करोड़ ७५ लाख टन कोयला निकाला गया।

आलोच्य वर्ष में १,२४१ नये सवारी डिब्बे चलाये गये, जिनमें से ४४९ बड़ी लाइन के, ७४४ छोटी लाइन के और ४८ संकरी लाइन के थे। इनमें से ८५२ सवारी डिब्बे तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिए थे और सुधरी किस्म के थे। इनके अलावा इस वर्ष बड़ी लाइन के ४३७, छोटी लाइन के २२१ और संकरी लाइन के १६ नये इंजन चलाये गये।

दूसरे और तीसरे दर्जे के डिब्बों में कुल मिलाकर ४,८९२ पंखे लगाये गये। इनमें से ४,४५१ पंखे तीसरे दर्जे के डिब्बों ने लगे। तीसरे दर्जे में सोने की जगह देने की व्यवस्था भी बड़ी लाइन की चार (दुतरफा) छोटी लाइन की दो (दुतरफा) गाड़ियों में की गयी।

पूंजीगत व्यय

६१ मार्च, १९५६ तक सभी भारतीय रेलों पर ९ अरब ७५ करोड़ ५० लाख रु० की पूंजी लगी थी (उन पटरियों को मिलाकर, जो उस समय बिछायी जा रही थीं), जबकि ३१ मार्च, १९५५ तक ९ अरब १० करोड़ ९१ लाख रु० की पूंजी लगी थी। इसमें ९ अरब ६८ करोड़ ६८ लाख रु० सरकारी रेलों की पूंजी थी और ७ करोड़ ५२ कम्पनियों, जिला बोर्डों आदि की थी।

आलोच्य वर्ष के अन्त में भारत के रेल-मार्ग की लम्बाई ३४,७३६ मील थी। इसमें से ३४,१८२ मील के रेल-मार्ग सरकारी रेलों के थे और बाकी ५५४ मील के रेल-मार्ग उन रेलों के थे, जिनका प्रबन्ध गैर सरकारी संस्थाओं के हाथ में है।

एक नजर में

भारतीय रेलों में कुल लगभग ९७४ करोड़ रु० की पूंजी लगी हुई है और भारतीय रेल-व्यवस्था सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्योग है।

रेलों की दूसरी आयोजना के अन्तर्गत २,२५८ इंजन, १,०७,२४७ माल-डिब्बे और ११,३६४ सवारी डिब्बे बढ़ाये जाएंगे।

१९५६-५७ में चित्तरंजन इंजन कारखाने में बड़ी लाइन के इंजनों का सालाना उत्पादन औसतन २०० तक और "टैस्को' में छोटी लाइन के इंजनों का उत्पादन औसतन १०० तक पहुंचाया जाएगा।

इस समय भारत में माल-डिब्बे बनाने वाले कारखानों की उत्पादन क्षमता २० हजार माल-डिब्बे बनाने की है, जिसे ३६ हजार माल-डिब्बे सालाना तक बढ़ाया जा रहा है।

विभाजन के बाद भारत के पास बड़ी लाइन के १,५४,२३२ और छोटी लाइन के ५१,६१२ माल डिब्बे बचे थे। तब से लेकर १५ दिसम्बर, १९५६ तक बड़ी लाइन के ४१,९५७ और छोटी लाइन के ३५,५१६ माल-डिब्बे बढ़ाये गये हैं, जिनमें विदेशों से मंगाये गये डिब्बे भी शामिल हैं। इनमें से बड़ी लाइनके ११ हजार माल डिब्बे देश में बने।

सम्पदा के आगामी विशेषांक की प्रतीक्षा कीजिए !

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

फोन नं० : ३३१११ तार : माइनहोल्डर

मिनरल वैल्थ आफ इंडिया लिमिटेड

सब प्रकार के खनिज व धातुओं

के

व्यापारी तथा एक्सपोर्टर्स

खताऊ बिल्डिंग्स

४४ ओल्ड कस्टम हाउस रोड, फोर्ट, बम्बई

मैनेजिंग डायरेक्टर:—

श्री सी० डीडवानिया

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भाप से, डीजल से या बिजली से ?

भारत में रेलें किससे चलाई जायें ?

श्री आर० वी० वाचीन

डीजल इंजन समान शक्ति के भापवाले इंजन की अपेक्षा अधिक बोझ खींच सकता है। इसलिए विशेषतया शंटिंग के लिए डीजल इंजन अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी समझा जाता है।

मुख्य मार्गों पर भी भाप के इंजन की अपेक्षा डीजल इंजन पर खर्च कम बैठता है। आंकड़ों से पता चलता है कि ३५ से ७० तक डीजल इंजन भाप के १०० इंजनों के बराबर काम कर सकते हैं।

अमेरिका में डीजल इंजनों के प्रतिमानीकरण और उत्पादन-वृद्धि से निर्माण-व्यय भाप के इंजन से अधिक से अधिक ड्यौढ़ा रह गया है; पहले तिगुना था।

डीजल इंजनों का दूसरा लाभ यह है कि इनमें पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए निर्जल क्षेत्रों में ये विशेष उपयोगी हैं। इनको चलाने के लिए बहुत आदमियों की जरूरत भी नहीं पड़ती।

डीजल इंजन वाली यात्री गाड़ियों में रोशनी के लिए इंजन से ही बिजली मिल सकती है। परन्तु भाप के इंजनों वाली यात्री गाड़ियों में दूसरा प्रबन्ध करना पड़ता है, जिसमें अधिक खर्च पड़ जाता है।

भाप से चलने वाले इंजनों की तुलना में डीजल इंजनों पर केवल मरम्मत आदि में ही अधिक खर्च पड़ता है। जहां डीजल इंजन साधारणतया १५ वर्ष चलते हैं, वहां भाप से चलने वाले इंजन ३० से ३५ साल तक चल सकते हैं।

परन्तु अमेरिका की रेलों को डीजल इंजनों से पूर्ण सन्तोष है। भाप के इंजनों के बदले डीजल इंजनों से काम लेने से जो अधिक खर्च हुआ, वह पहले ६-८ वर्षों में ही वसूल हो गया। शन्टिंग में डीजल इंजनों पर और भी कम खर्च बैठता है। लेकिन अमेरिका में इस बचत का मुख्य कारण यह है कि वहां कोयले की अपेक्षा तेल अधिक सस्ता होता है।

अमेरिका में १९४० से भाप वाले इंजनों के स्थान पर डीजल इंजन ही काम में लाये जा रहे हैं और वे पूर्णतया सन्तोषजनक सिद्ध हुए हैं। ये इंजन भारी बोझ को अधिक तेजी से खींच सकते हैं, इनके ब्रेक अधिक अच्छे होते हैं और इनमें ईंधन भी कम खर्च होता है।

भारत के लिये उपयोगिता

दो कारणों से भारत की स्थिति अमेरिका से भिन्न है—पहला तेल की कमी और दूसरा उसका मंहगापन। अच्छा तेल २० आना प्रति गैलन मिलता है जब कोयला प्रति टन २० रु० से ५० रु० तक मिल जाता और यह भारत में काफी मात्रा में मिलता है।

जब तक भारत में तेल सस्ता न मिलने लगे तब तक यहां भाप वाले इंजनों के स्थान पर डीजल इंजन चलना लाभदायक सिद्ध नहीं होगा। फिर भी कुछ कामों के लिए डीजल इंजन का प्रयोग अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

भारत में यातायात की वृद्धि होती जा रही है और भविष्य में बिजली से चलने वाली रेलों की आवश्यकता पड़ेगी। अतः हमें कम से कम खर्च पर बिजली प्राप्त करनी चाहिए और साथ ही खर्च को और कम करने के लिए आधुनिकतम तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए।

यहां एक बात ध्यान में रखना आवश्यक है। हमारा ध्येय केवल खर्च कम करना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें इस पर भी जोर देना चाहिए कि परिवहन सेवा अधिक अच्छी हो। हमें यात्रियों की सुरक्षा और आराम का विशेष ध्यान रखना चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि कर्मचारियों को अधिक सुविधाएं मिलें।

इन सुधारों का होना बहुत आवश्यक है, भले ही खर्च थोड़ा-बहुत बढ़ जाय।

[समाप्त

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बैंकों को अधिक उपयोगी बनाइये : स्टैंडिंग आर्डर सिस्टम चालू हो

बैंक और बीमा

भारत में व्यावसायिक बैंकों की कठिनाइयां यद्यपि कई हैं, परंतु इस समय मुख्य कठिनाई बैंक को उधार की बढ़ती हुई मांग को पूर्ण करने के लिए साधन जुटाना तथा तरल पूंजी का दृढ़ स्तर कायम करना है। बैंकों द्वारा सावधि जमा और सेविंग बैंक खाते की दर में वृद्धि किए जाने पर भी पर्याप्त मात्रा में जमा राशि की प्राप्ति नहीं हुई जिससे समस्या का सामना किया जा सके। देश में जितनी मुद्रा चलन में रही, उसमें केवल कागजी मुद्रा विगत ५ सालों की अपेक्षा ३२५ करोड़ रुपए बढ़ी, लेकिन अनुसूचित बैंकों की विशुद्ध जमा में केवल २५६ करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। इस विषय में एक बात उल्लेखनीय है कि कागजी मुद्रा की इस वृद्धि के कारण एक प्रकार से वे लोग हैं जिनको बैंक में रुपए जमा करने की आदत नहीं है और उनकी आमदनी का प्रायः पूरा भाग उन्हीं के पास जमा होता रहता है। बैंकों को सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह पड़ जाती है कि वे अपने साधनों का उपयोग इस प्रवृत्ति को रोकने में करें।

इसके लिए आवश्यक हैं कि बैंक इन लोगों में, जिनको बैंक में रुपए जमा करने की आदत नहीं है, इस आदत को बनाने का प्रयत्न करें। मुख्य कर ग्रामीण क्षेत्रों में तो बैंकों के कार्य का विस्तृत क्षेत्र हैं, जिसको अभी तक छुआ नहीं गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का कार्य केवल रुपया उधार लेना और ब्याज देना ही नहीं होना चाहिए, वरन् अन्यान्य समस्त द्रव्य सम्बन्धी सौदों जैसे अपने ग्राहकों की बीमा पालिसी की किश्त चुकाना, किराया चुकाना, संस्थाओं का चन्दा भरना आदि इसी प्रकार के कार्य भी करने होंगे। पश्चिमी देशों में बैंको का ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार का कार्य खूब प्रचलित है। इसको वहां 'स्टैंडिंग आर्डर सिस्टम' कहा जाता है। भारत में इसको प्रचलित करना बैंकों का मुख्य कर्तव्य होना चाहिए।

यह सत्य है कि देश में कई बड़े बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार को कुछ कार्य करते हैं, पर यह कार्य न तो व्यापक हो सका और न प्रभावशाली ही। इसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि स्वयं सामान्य जनता को यह मालूम नहीं कि उनको बैंक क्या-क्या सुविधाएं दे सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि यह बात बैंक इन लोगों को अपने प्रचार द्वारा ज्ञात कराएं। दूसरा कारण यह है कि बैंकों की अपेक्षाकृत सेवा का मूल्य इनके लिए काफी अधिक है। इसलिए इन लोगों में बैंकों के प्रति कोई रुचि उत्पन्न नहीं होती। इसके लिए भी उचित प्रकार से बैंकों को अपनी सेवा के मूल्य में कमी करनी होगी। ब्रिटेन के बैंकों ने इस सम्बन्ध में जो कार्य पद्धति अपनाई है, उसको सरलता से यहां भी अपना कर लाभ उठाया जा सकता है।

ब्रिटेन में 'स्टैंडिंग आर्डर सिस्टम' का काफी प्रचलन है। इस पद्धति के अनुसार बैंकों के ग्राहक अपने समस्त द्रव्य सम्बन्धी कार्य बैंकों को सौंप देते हैं। इसके लिए उनको एक फार्म भरना पड़ता है जिसमें इसका खुलासा रहता है कि किसको, कब और कितनी रकम चुकानी है। इस प्रकार का कार्य कुछ अन्तर पर होने वाली नियमित अदायगियों के लिए सुविधाजनक है। केवल बैंक ही नहीं, वरन् सेविंग बैंक और यहां तक कि डाक घर भी इस प्रकार का कार्य करते हैं।

इस पद्धति की मुख्य विशेषता यह है कि बैंक के ग्राहक उन सब तारीखों को याद रखने की झंझट से छूट जाते हैं जिनमें उन्हें अदायगी करनी होती है। न तो उन्हें समय-समय चेक ही काटने पड़ते हैं और मनिआर्डर भेजने की परेशानी ही मोल लेनी पड़ती है। इस पद्धति की दूसरी विशेषता उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के कार्य के लिए बैंक जो प्रतिफल लेते हैं, वह अपेक्षाकृत इसी प्रकार की अन्य सेवाओं से कम ही रहता है। इससे न तो प्रत्येक काटे गए चेक पर मुद्रा शुल्क लगाना पड़ता है। (यद्यपि भारत में काटे गए चेक पर इस प्रकार का कोई मुद्रा शुल्क नहीं लगता) यह भी कहा जाता है कि वहां व्यावसायिक बैंक स्टैंडिंग आर्डर सिस्टम के अनुसार होने वाले वार्षिक भुगतानों पर कोई विशेष शुल्क नहीं लेते-यह अवश्य है कि समय समय के

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अन्तर पर होने वाले नियमित भुगतानों पर कुछ अतिरिक्त शुल्क बैंक लेते हैं और उनमें राशियों के अन्तर के अनुसार ही फर्क भी होता है । उदाहरण के लिए उन लोगों से बैंक कम शुल्क लेते हैं, जिनकी बचतें जमा हो गई हैं और जो उनको साल में एक दो बार ही अन्य कार्यों में प्रयुक्त करते हैं। इसके विपरीत समय समय पर रुपया निकालने वालों से अधिक शुल्क लिया जाता है। सेविंग बैंक और डाकखाने की सेवाओं के प्रतिफल का बैंक के प्रतिफल में फर्क होता है।

स्टैंडिंग ऑर्डर सिस्टम केवल नियमित रूप से चुकाए जाने वाले राशियों में ही यथार्थ फलदायी होता है। इसलिए सेविंग बैंक ऐसी सुविधाएं वहां नहीं दे सकते, जहां अनियमित भुगतानों की मांग हो।

—

स्टेट बैंक आफ इंडिया

गत वर्ष की प्रगति

स्टेट बैंक आफ इन्डिया की १९५६ के लिए रिपोर्ट ऐसे समय में दिलचस्पी से पढ़ी जायगी, जबकि मुद्रा बाजार में रुपए की तंगी महसूस की जा रही है, बैंक द्वारा दिये गये ऋण की रकम जनवरी में १०२.९ करोड़ रु० से बढ़ कर मई में १३६.४ करोड़ रु० हो गई और इस प्रकार जमा के मुकाबले ऋण देने की प्रतिशत ५०.५ से बढ़कर ६५.३ हो गई। लेकिन अन्य अनुसूचित बैंकों का जमा के मुकाबले ऋण देने का अनुपात ६७.५ प्रतिशत से बढ़कर ७३.५ प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार कारोबार के मौसम में दिए गए ऋण की रकम १३६.३ करोड़ रु० से गिरकर गत अक्तूबर में १२५.९ करोड़ रु० रह गई थी तथा जमा की तुलना में ऋण देने का अनुपात ४ अंक गिर कर ६१.३ प्रतिशत रह गया था, जबकि अन्य अनुसूचित बैंकों में यह अनुपात १.६ प्रतिशत गिरा। अतः अन्य बैंकों की तुलना में स्टेट बैंक आफ इण्डिया का ऋण देना (एडवांस) तेजी के साथ बढ़ा, जबकि निष्क्रिय मौसम में वह अधिक तेजी से घटा। वर्तमान सक्रिय मौसम में जो कि गत नवम्बर में शुरू हुआ, एडवांसों की रकम दिसम्बर के अन्त में बढ़कर १३५ करोड़ रु० हो गई। जमा के सम्बन्ध में भी बैंक की स्थिति बेहतर थी और जमा की रकम वर्ष के प्रा[illegible] २०३.६ करोड़ रु० हो गई और इस प्रकार जमा में [illegible] ८.९ प्रतिशत हुई, जबकि अन्य अनुसूचित बैंकों में [illegible] वृद्धि ७.८ प्रतिशत रही और उनकी जमा की रकम [illegible] करोड़ रु० से बढ़कर ८८०.२ करोड़ रु० हो गई।

व्यापार को अधिक ऋण

बैंक ने विभिन्न समूहों को जो ऋण दिए हैं, [illegible] विश्लेषण करने से पता चलता है कि पूर्व वर्ष की [illegible] में अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल अंतर इतना [illegible] है कि व्यापारी को दिए गए ऋण की रकम बढ़कर [illegible] प्रतिशत से २५.८ प्रतिशत हो गई है और इसका प्रति[illegible] प्रभाव व्यक्तियों और पेशों को दिये गये ऋणों पर प[illegible] उद्योगों को दिया गया ऋण पहले के समान ५[illegible] प्रतिशत रहा। जिन जमानतों (सिक्यूरिटी) के आधा[illegible] ऋण दिया गया, उनमें व्यापारिक सामान के आधार [illegible] ५८-५९ प्रतिशत, सरकारी सिक्यूरिटियों के आधार [illegible] १७-१८ प्रतिशत और सोने-चांदी व कम्पनियों के [illegible] के आधार पर लगातार ४-५ प्रतिशत था। व्यापार [illegible] दिए गए ऋण में जो वृद्धि की गई है, वह स्वागत यो[illegible] वस्तुतः स्टेट बैंक को मुलतानी हुण्डी सकारने का जो [illegible] अनुभव है उसकी मदद से देश में एक नियमित [illegible] (बिल) बाजार के निर्माण में भारी सहायता मिल [illegible] है। हुण्डी बाजार योजना के विस्तार से बैंकिंग प्रणा[illegible] साधनों में तरलता आ जायगी, जिससे व्यापार और [illegible] की कार्य पूंजी की समस्या आसान हो जायगी। यह [illegible] है कि स्टेट बैंक आफ इन्डिया का कार्य ग्रामीण [illegible] बढ़ाने के बजाय, जिसका आजकल प्रयोग किया जा [illegible] व्यापारिक क्षेत्र में बढ़ाना अधिक बुद्धिमानी होगी।

नई शाखाएँ

स्टेट बैंक आफ इन्डिया ने १ जुलाई १९५५ से [illegible] यह अस्तित्व में आया, ३१ दिसम्बर १९५६ तक ६६ [illegible] शाखाएं खोली हैं। १९५६ में ४६ नई शाखाएं [illegible] गईं। बैंक को पांच वर्षों में कम से कम ४०० नई शा[illegible] खोलनी हैं। नई शाखाएं खोलने का काम अधिक [illegible] किया जा रहा है।

———

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

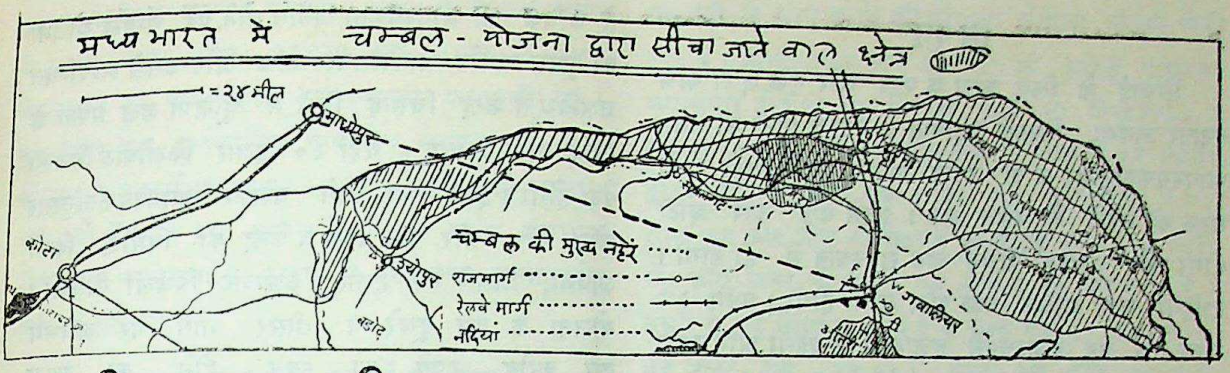

हमारी मुख्य नदी : चम्बल

पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित होने और इसका निर्माण कार्य की प्रगतिके कारण अब चम्बल नदी से, राजस्थान व मध्यभारत से बाहर के प्रायः सभी शिक्षित भारतीय परिचित हो गये हैं। यह महू के पास विन्ध्य की श्रेणी से निकलकर प्रथम उत्तर को और फिर मध्यभारत व राजस्थान की सीमा बनाती हुई पूर्वोत्तर बहती है और अन्त में उत्तरप्रदेश में इटावा के पास जमुना नदी में मिलती है। इसकी लम्बाई ६०० मील है और मध्यभारत व राजस्थान के लगभग ५५ हजार वर्गमील क्षेत्र की प्रति वर्ष औसतन ३५ इंच वर्षा का जल इस में पहुँचता है।

चम्बल विद्युत व सिंचाई योजना

इस योजना के फलस्वरूप २२७,००० किलोवाट विद्युत शक्ति जो मध्यभारत में फिलहाल पैदा होने वाली बिजली की कुल तादाद से दुगुनी है और १४ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की सुबिधा, जो आज मध्यभारत में केवला ५ लाख एकड़ में मिलती है, उपलब्ध होगी और इसका लाभ मध्यभारत व राजस्थान को समान रूप से मिलेगा। विशेष बात यह है कि मध्यभारत के हिस्से की नहर प्रणाली के अलावा इस योजना के बाकी निर्माण कार्य नैसर्गिक अनुकूलता के कारण बहुत ही सुगम, सफल और सस्ते होने जा रहे हैं। पूरी योजना में ऐसे तीन बांध होंगे। इनके लिए आदर्श स्थान उस संकरी, पथरीली घाटी में मिल गए हैं, जो मानपुरा के पास चौरासीगढ़ से प्रारम्भ होकर कोटा के करीब लगभग ५० मील तक नदी का मार्ग बनाती है। योजना का मुख्य जल प्रदाय प्रथम

लेखक—श्री० वी० वी० द्रविड़

अर्थात गांधी सागर बांध द्वारा इस घाटी के प्रवेश द्वार पर स्थित विशाल कटोरे जैसे प्राकृतिक क्षेत्र में निर्माण होगा। इसके लिए अलग कोई बांध बांधने की आवश्यकता नहीं होगी।

विद्युत शक्ति

प्रत्येक बांध स्थल पर बांध की ऊंचाई से गिरने वाले पानी की जिस शक्ति को विद्युत शक्ति में परिवर्तित करने वाले जल विद्युत केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। इन केन्द्रों से यह विद्युत शक्ति ६११ लंबी मुख्य लाइनें व पंद्रह उप केन्द्रों द्वारा मध्यभारत व राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में पहुँचाई जाएंगी।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सिंचाई

सिंचाई के लिए कोटा के पास और एक छोटा बांध बनाया जायगा, जिसकी सहायता से नदी के पानी की सतह आवश्यकतानुसार ऊंची उठाई जाएगी, ताकि पानी दोनों तरफ की नहरों में पहुँच सके। इनमें बाईं नहर छोटी होगी और उसका सिंचन क्षेत्र राजस्थान में ही होगा। दाहिनी नहर अधिक बड़ी और लम्बी होगी। प्रथम ३८ मील तक वह राजस्थानी इलाके में से बहेगी और उसके बाद पार्वती नदी को पार कर मुरेना जिले के श्योपुर तहसील के राधापुरा ग्राम के पास यह दाहिनी नहर मध्य-भारत में प्रवेश करेगी और अपनी शाखा प्रशाखाओं द्वारा मुरेना एवम् भिंड जिले की ६ तहसीलों के करीब १५५० गांवों में ७ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करेगी।

योजना पूर्ति का कार्यक्रम

यह सारी योजना तीन भागों में पूरी करने का संकल्प है। प्रथम भाग में मानपुरा के निकट का गाँधी सागर बांध, वहां का जल विद्युत केन्द्र, बिजली की अधिकांश लाईनें, कोटा का सिंचाई बांध व पूरी नहर-प्रणाली का निर्माण होना है। इस कारण लगभग ५० करोड़ रुपयों का व्यय होगा और ६६००० किलोवाट विद्युत शक्ति तथा पूरी याने १४ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। इसका लाभ मध्यभारत व राजस्थान दोनों को समान रूप से मिलेगा, किन्तु मध्यभारत को नहर प्रणाली पर अधिक व्यय उठाना पड़ेगा। इस भाग पर होने वाले लागत व्यय पर लगभग ४ प्रतिशत से अधिक शुद्ध लाभ अपेक्षित है। किन्तु इससे कई गुना अधिक महत्वपूर्ण और अमूल्य लाभ तो बिजली और सिंचाई की सुविधा के फलस्वरूप होने वाली इस पूरे क्षेत्र की सर्वांगीण उन्नति के रूप में होगा। योजना का यह पहला भाग द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लग-भग पूरा होने की आशा है। किन्तु गांधीसागर बांध की व उसके आनुषार्गिक कार्यों की प्रगति देखते हुए हम यह विश्वास कर सकते हैं कि बिजली व सिंचाई की सुविधा १६५६-६० से ही उपलब्ध होने लगेगी।

गांधी सागर जल विद्युत केन्द्र से उपलब्ध बिजली से अधिक की आवश्यकता प्रतीत होने पर चम्बल योजना का दूसरा अर्थात प्रतापसागर बांध और उससे सम्बन्धित जलविद्युत केन्द्र चित्तोड़ जिले में चूलिया जल प्रपात के निकट बांधा जायगा। यहां ६० हजार किलोवाट बिजली पैदा होगी। इसी प्रकार आगे चलकर आवश्यकतानुसार कोटा बांध और जल विद्युत केन्द्र का निर्माण किया जायगा, जिससे ४५ हजार किलोवाट बिजली मिलेगी। योजना के इस दूसरे व तीसरे भाग पर लगभग दस करोड़ रुपये का व्यय होने का स्थूल अनुमान है।

निर्माण कार्य का श्रीगणेश

योजना बन गई, काम शुरू हुआ, लेकिन वह नापसंद का दिया गया और योजना का निर्माण ठप्प हो गया। योजना आयोग ने भी पूर्ण चित्र तयार न होने तक इसे मान्यता देने से इन्कार कर दिया और योजना स्थगित करने के आदेश दे दिये गये। निराशा, व्यग्रता व अनिश्चितता के इस वातावरण में सन् १६५२ में जब इस योजना की जिम्मेदारी मुझ पर डाली गयी, मुझे यह प्रतीत हुआ कि इस गत्यवरोध को समाप्त करना कठिन है; क्योंकि काम स्थगित रखने का केन्द्रीय शासन का आदेश तब तक कायम रहने वाला था, जब तक कि योजना आयोग इस योजना पर अपनी स्वीकृति न दे और यह स्वीकृति कैसे मिल सकती थी, जब कि योजना के सारे ही महत्वपूर्ण अङ्ग तब तक अनिश्चित अवस्था में ही थे। गांधी सागर बांध की ऊंचाई व डिजाइन, कोटा बांध का स्थान व डिजाइन, नहरों का मार्ग व डिजाइन यह सभी अनिर्णीत थे।

अतः सर्वप्रथम कार्य, योजना आयोग व केन्द्रीय शासन को चम्बल योजना का मूलभूत रूप से सही व स्वीकार्य होने का विश्वास दिला कर उन से योजना का तात्कालिक कार्य प्रारम्भ करने की इजाजत लेने का था, जिससे योजना आगे अधिक खटाई व ढील में न पड़े और स्टाफ पर होने वाला व्यय निरर्थक न जाय। बहुत परिश्रम से यह इजाजत प्राप्त हुई और तब ता० २६ जनवरी १६५३ को गांधी सागर बांध की नींव की खुदाई आरम्भ की गई।

पंचवर्षीय योजना में चम्बल योजना भी समाविष्ट हुई। केन्द्रीय वित्त मंत्री से अल्प बचत की प्रादेशिक धनराशि पूरी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चम्बल के लिए उपलब्ध की गई। बादमें मध्यभारत शासन ने अपना प्रथम ऋण प्रमुखतः इस योजना के लिए निकाला। कुछ अन्तर्राष्ट्रीय सहायता भी प्राप्त की गई। इस प्रकार एक दीर्घकालीन गत्यवरोध समाप्त हुआ और योजना के तात्कालिक स्वरूप का कार्य प्रगति करने लगा। कई वर्षों में प्रथम बार चम्बल में नियुक्त व्यक्ति उलझन, निष्क्रियता व निराशा के कुचक्र से निकलकर उत्साहपूर्वक काम में जुट गए।

योजना के प्रमुख प्रश्नों का हल

लेकिन जब तक योजना के मुख्य पहलू, जो अब भी अनिर्जीत थे, निश्चित नहीं किए जाते, तब तक योजना का भविष्य सुस्थिर नहीं बन सकता था। इस संबंध में सबसे अधिक अस्पष्टता सिंचाई वाले हिस्से के विषय में थी। पानी के बंटवारे के संबंध में मध्यभारत व राजस्थान के बीच विवाद चल रहा था और उसका अन्त कब और कैसे होगा, यह नहीं कहा जा सकता था। इस विवाद को लेकर कोटा बेराज का स्थान व नहरों का मार्ग इत्यादि कुछ भी निश्चित नहीं हो सका था। यह सारी स्थिति समझाकर मैंने आपसी समझौते से इस विवाद को निबटाने का प्रयत्न करना उचित समझा और यह सचमुच प्रसन्नता की बात है कि राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री जयनारायण जी व्यास व विभागीय मंत्री श्री भोगीलाल जी पंड्या के सहयोग से इसमें सफलता मिली। पानी के लाभ का विभाजन, जो दोनों राज्यों में समानता के आधार पर हुआ है, विशेषज्ञों की सम्मति के अनुसार भी सर्वोचित है।

इस बुनियादी महत्व के निर्णय के फलस्वरूप, योजना का सिंचाई के पहलू का सारा चित्र फिर शीघ्रतापूर्वक तैयार किया जा सका। इसके अनुसार मध्यभारत में कमान्डेट एरिया का अधिकतम क्षेत्र सींचा जा सकेगा। गांधी सागर बांध का डिजाइन व अन्य विद्युत् सम्बन्धी प्रश्नों के भी अन्तिम निश्चय पीछे से हो गये और उन पर केन्द्रीय जल विद्युत् निगम, योजना आयोग व केन्द्रीय शासन की सम्मति भी प्राप्त कर ली गई।

निर्माण कार्य

इस सारी कार्रवाई के साथ ही निर्माण कार्य अधिकतम गति से आगे बढ़ाने की पूरी-पूरी कोशिश बराबर जारी रही है। गांधी सागर बांध की नींव की खुदाई आवश्यकतानुसार होते ही बांध निर्माण कार्य का शिलान्यास ७ मार्च १९५४ को पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के कर कमलों द्वारा सम्पन्न किया गया। इस बांध के निर्माण में ७५ लाख घन फीट नींव की चट्टान की खुदाई तथा २५६ लाख घन फीट, पत्थर की जुड़ाई एवं कांक्रीट का काम होना है। उसमें से यह सितम्बर १९५६ के अन्त तक ६२.३३८ लाख घन फीट तथा ७२.००३ लाख घन फीट का काम हुआ है।

मौजूदा मौसम में रातपाली में भी बांध का काम किया जायगा। प्रस्तावित बढ़े हुए प्रमाण में काम को पूरा करने के उद्देश्य से बांध स्थल पर पत्थर फोड़ने, रेत बनाने, चूना सीमेंट आदि मसाले का मिश्रण करने व यह सब सामग्री निर्माण स्थल पर पहुँचाने के लिए आवश्यक यांत्रिक व्यवस्था की जा चुकी है। बांध व जल विद्युत केन्द्र के निर्माण में आगे लगनेवाली सामग्री यथासमय उपलब्ध हो सके, इसका प्रबन्ध भी किया गया है। जल विद्युत गृह की नींव तैयार की जा रही है और बिजली के तारों का मार्ग निर्धारित किया जा रहा है। उज्जैन व इन्दौर तक की बिजली की लाइनों के मार्ग का सर्वेक्षण पूरा किया गया है।

नहर प्रणाली के मध्यभारत के हिस्से में १३,५०० लाख घन फीट मिट्टी की खुदाई ३०० लाख घन फीट पत्थर की खुदाई तथा २०० लाख घन फीट जुड़ाई का काम होना है। उसमें से माह सितम्बर १९५६ के अन्त तक ७८०.६७४ घन फीट मिट्टी की खुदाई और ४२.२१५ लाख घन फीट पत्थर की खुदाई हुई है। जुड़ाई के काम का प्रारम्भ हो चुका है।

बांध के क्षेत्र से विस्थापित कृषकों के लिए निर्धारित क्षेत्र में ३,४०० एकड़ जमीन साफ की गई है, उसमें से ५९५.९० एकड़ ट्रैक्टरों से जोती गई है और २७१ एकड़ जमीन में कंटूर बंडिंग भी किया गया है।

कुल मिलाकर यह विश्वास किया जा सकता है कि योजना की पूर्ति समय पर होगी और उसका कुछ लाभ तो निर्धारित समय के पूर्व से ही मिलने लगेगा। शासन ने

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारत-भूमि में नए खनिज स्रोत

अनेक नये खनिज

देश के भूगर्भ में अभी कितना धन छिपा पड़ा है, इसका पूरा अन्दाजा नहीं लग सका। अपने प्राकृतिक साधनों के पूर्ण उपयोग करते हुए हमने देश की सर्वांगीण उन्नति का निश्चय किया है। तब इस क्षेत्र में भी प्रयत्न होना चाहिए। हर्ष है कि सरकार ने इस बात को महज समझा ही नहीं वरन् इस क्षेत्र में कार्य भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने पंजाब के महेन्द्रगढ़ में लौह भी आरंभ कर दिया है। खनिज की २॥ मील लम्बी एक पट्टी का पता लगाया है अनुमान है कि इस पट्टी में २० लाख टन से अधिक लौह खनिज होगा।

भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग की प्रयोगशाला में इस पट्टी से निकाले गये लौह खनिज का रासायनिक विश्लेषण किया गया है। इससे पता चला है कि इससे अच्छी किस्म का लौहा तैयार किया जा सकता है।

लेकिन केवल यही पट्टी इस्पात का कारखाना चलाने के लिए काफी नहीं है। इसलिए यह सुझाव दिया गया है कि राजस्थान के धनौटा-धनचांली आदि समीपवर्ती क्षेत्र के लौह खनिज भंडार की जांच करके पता लगाना चाहिए कि वहां खनिज किस किस्म का है और कितनी मात्रा में मिल सकता है। विभिन्न भंडारों के लौह खनिज अगर एक ही किस्म का हो तो सम्भवतः उससे भाकड़ा-नंगल योजना से प्राप्त विद्युत-शक्ति की सहायता से इस्पात का एक कारखाना चलाया जा सकता है।

पट्टी से लौह खनिज निकालने का काम फिलहाल निजी तौर पर किया जा रहा है। फरवरी से अप्रैल १९५१ तक का उत्पादन ८० हजार मन था, जिसमें से ५ हजार मन स्थानान्तरित कर दिया गया। उत्पादन व्यय प्रति सौ मन ८० रु० हुआ। लौह खनिज नार्वे और चेकोस्लोवाकिया भेज दिया गया है।

आन्ध्र में भी

भारतीय भू-गर्भ सर्वे विभाग ने आंध्र में लौह खनिज के दो ऐसे भंडारों का पता लगाया है जिनमें अन्दाजन ३८ करोड़ ९० लाख टन लौह खनिज है। ये भंडार गुंटूर और नैल्लोर जिलों में हैं। कहा जाता है कि इन स्थानों से कई सदियों तक लौह खनिज निकाला जा सकेगा।

इन भंडारों में लगभग २९ करोड़ ६० लाख टन ऐसी चट्टानें हैं, जिनमें ३३ से ३७ प्रतिशत तक लोहा है। बाकी में लगभग २५ प्रतिशत लोहे का अंश है। और खोज करने से दूसरे भी भंडारों का पता चल सकता है।

चूने का पत्थर

आंन्ध्र राज्य ही गुंटुर जिले के मछेरला उपतालुका में अनुमानतः १२ करोड़ ४० लाख टन चूने के पत्थर के दो भण्डार मिले हैं। यह पत्थर सीमेंट बनाने के काम आ सकता है। भंडार मछेरला से दक्षिण-पश्चिम में हैं। मछेरला गुंटूर-मछेरला रेल-मार्ग पर अन्तिम स्टेशन है। चूने के पत्थर के ये भण्डार नंदीकोंडा बांध से केवल २५ मील दूर हैं और नागार्जुनसागर की बहूद्देशीय योजना के लिए मछेरला के पास जो सीमेंट कारखाना बनाया जा रहा है, उसके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।

इसी प्रकार भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने

यह नीति निश्चित कर ली है कि चम्बल विद्युत का पर्याप्त लाभ ग्रामीण क्षेत्रों को मिलना चाहिए। इसी प्रकार सिंचाई का भी पूरा लाभ उठाया जा सके, इस हेतु से विभिन्न नहरी क्षेत्रों में कृषि प्रयोग व प्रदर्शन फार्म प्रारम्भ किये गये हैं।

चम्बल योजना में नियुक्त श्रमिक, जिनकी संख्या अब तक १०,००० तक रही है, और जो दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली है, व कर्मचारियों की सुविधा पर भी यथोचित ध्यान दिया जा रहा है। इस हेतु से उन्हें मकान, वैद्यकीय सहायता आदि सहूलियतें यथा संभव दी जा रही हैं। एक उल्लेखनीय बात यह है कि नहरी क्षेत्र में स्थानीय आदिवासी श्रमिकों की सहकारी समिति को निर्माण कार्य दिया गया है और यह प्रयोग आशाजनक रूपमें सफल रहा है। उसे और फैलाने की नीति स्वीकार की गई है।

—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

देहरादून-मसूरी क्षेत्र में भी अच्छी किस्म का ४० करोड़ ६० लाख चूने के पत्थर का पता लगाया है।

उत्तर प्रदेश के भूतत्व एवं खनिकर्म संचालन कार्य की प्रारम्भिक जांच से भी पता चलता है कि ऋषिकेश के निकट गढ़वाल जिले में स्थित दो करोड़ ८४ लाख टन चूने के पत्थर की खानें हैं।

देहरादून जिले में स्थित बड़ाकोट के चूने की खान से नमूने लिए जा चुके हैं और अब इस सम्बन्ध में विश्लेषण कार्य हो रहा है। अनुमान है कि इस खान से सीमेंट बनाने के काम आने वाले तीन करोड़ ८२ लाख टन चूने के पत्थर प्राप्त हो सकते हैं।

मिर्जापुर जिले के बन्सी क्षेत्र में किये गये शोध कार्यों से पता चला है कि यहाँ अनुमानतः सात लाख टन चूने के पत्थर हैं।

भूरा कोयला

अभी अभी भारत सरकार ने मद्रास राज्य में नेवेली की खानों से प्रतिवर्ष ३५ लाख टन भूरा कोयला (लिग-नाइट) निकलने की बहुमुखी योजना स्वीकार की है। भूरे कोयले की खुदाई का काम सन् १९६० के प्रारम्भ में शुरू होगा और वर्ष के अन्त तक इन खानों में पूरी तरह काम होने लगेगा। ६८ करोड़ रुपए की इस बहुमुखी योजना में कोयले की खुदाई के अतिरिक्त बिजली और खाद तैयार करना भी शामिल है।

परीक्षण से मालूम हुआ है कि नेवेली की खानों के भूरे कोयले में ५० प्रतिशत नमी, ३ प्रतिशत राख और प्रति पौंड ५५०० ताप मात्रा है। करीब २॥ टन भूरा कोयला १ टन अच्छे कोयले के बराबर ताप देता है। एक वर्ष में ३५ लाख टन भूरा कोयला निकाला जायगा, जो १२॥ लाख टन अच्छे कोयले के बराबर होगा। भूरा कोयला कुछ भारी और अपने आप जल उठने वाला होता है। इसकी नमी में १५ प्रतिशत नमी लाने के लिए इसे सिझाया जायगा।

नेवेली के भूरे कोयले से मद्रास के औद्योगिक विकास में बहुत सहायता पहुँचेगी, क्योंकि इस राज्य में विद्युत-शक्ति की कमी है। कृषि के विकास के लिए भी यहां विद्युत-शक्ति जरूरी है। खानों के पास लगे वायलरों में भूरे कोयले का ईंधन के रूप में इस्पात सस्ता पड़ता है।

भारत सरकार के व्यापार और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित

'उद्योग व्यापार पत्रिका'

★ उद्योग और व्यापार सम्बन्धी प्रामाणिक जानकारी युक्त विशेष लेख, भारत सरकार की आवश्यक सूचनाएं, उपयोगी आंकड़े आदि प्रति मास दिये जाते है।

★ डिमाई चौपेजी आकार के ६० ७० पृष्ठ : मूल्य केवल ६ रुपया वार्षिक। एजेण्टों को अच्छा कमीशन दिया जायगा। पत्रिका विज्ञापन का सुन्दर साधन है।

★ लघु-उद्योग विशेषांक मंगा कर छोटे उद्योगों के सम्बन्ध में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त कीजिये।

★ ग्राहक बनने, एजेन्सी लेने अथवा विज्ञापन छपाने के लिए नीचे लिखे पते पर पत्र भेजिये :—

सम्पादक

उद्योग व्यापार पत्रिका

उद्योग और व्यापार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नया सामयिक साहित्य

वैज्ञानिक हिन्दी कोष—प्रकाशक—भारत सरकार का शिक्षा विभाग।

भारत में हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने में और देश भर में उसका प्रचार करने में जो सबसे बड़ी बाधा अनुभव की जा रही है वह यह है कि हिन्दी में पारिभाषिक शब्दों का अभाव है। इस सम्बन्ध में आचार्य डाक्टर रघुवीर के नेतृत्व में बहुत सुन्दर प्रयत्न किया गया है। अनेक राज्यों ने इस दिशा में कुछ कार्य अवश्य किया है। किन्तु सब राज्यों की ओर से एक सम्मिलित प्रयत्न की आवश्यकता थी और केन्द्रीय सरकार को इस दिशा में प्रयत्न करना चाहिए था। यह प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने इस दिशा में अब कुछ प्रयत्न किया है। हमारे पास डाक तार, रसायन शास्त्र, कृषि, वनस्पति शास्त्र, रक्षा, जहाजी यातायात, प्राकृतिक भूगोल आदि विषयों पर भारत सरकार के शिक्षा-विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकें पहुँची हैं। हम इस प्रयत्न का सहर्ष स्वागत करते हैं।

शब्द-निर्माण में दो बातों का ध्यान रखा गया है। अधिकांश शब्द संस्कृत से बनाये गए हैं। किन्तु बहुत से प्रचलित शब्द भी ले लिये गये हैं, और उनके ले लेने में हमें कोई आपत्ति नहीं दीखती। कुछ शब्द प्रांतीय भाषाओं से भी लिये गये हैं। इस तरह चुनाव का क्षेत्र असंदिग्ध रूप से व्यापक हो जाता है। किन्तु एक बात हमें समझ में नहीं आई और वह मूलभूत बात है। भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने यह स्वीकृत कर लिया है कि बहुत से अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक शब्द ज्यों के त्यों नागरी में लिखे जायेंगे। हमारी यह निश्चित सम्मति है कि बोल चाल में आये शब्दों के अतिरिक्त वैज्ञानिक शब्दों के लिए संस्कृत बहुत समर्थ भाषा है। शिक्षा विभाग को इस नीति पर पुनः विचार करना चाहिये।

यह सम्भव है कि शब्दों के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद हो, किन्तु उपर्युक्त त्रुटि के अतिरिक्त साधारणतया यह शब्द कोष हमें पसन्द आये।

Recent Developments in Indian Economy.—प्रकाशक—अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर कार्यालय भारतीय शाखा, नई दिल्ली। मूल्य १॥) रु०।

अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर कार्यालय समय समय पर भारत की आर्थिक नीति, प्रवृत्ति और परिवर्तन के सम्बन्ध में सुन्दर साहित्य प्रकाशित करता है। प्रस्तुत पुस्तक भी इसी विषय पर एक सुन्दर प्रकाशन है। प्रस्तुत पुस्तक में चार लेख हैं—भारत में उद्योग, भारत में औद्योगिक वेतन, भारत में सामूहिक समझौते तथा भारत में सहकारी बिक्री।

ये चारों लेख पर्याप्त अध्ययन और परिश्रम के बाद लिखे गये हैं। इन चारों लेखों में प्रत्येक विषय का परिचय तथा आज की प्रगति और उस पर विवेचनात्मक प्रणाली अपनाई गई है। अपने विषय की पुष्टि में नवीनतम अंक देकर इस पुस्तक को अर्थ-शास्त्र के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के लिए बहुत अधिक उपयोगी बना दिया गया है। सामग्री संग्रह की दृष्टि से यह पुस्तक बहुत उपयोगी हो गई है, क्योंकि मजदूर कार्यालय ने विभिन्न राज्यों की सरकारों से अधिकृत सूचनाएं मंगवाने के बाद उनका प्रयोग किया है। हमें आशा है कि अर्थशास्त्र के विद्वान और विशेषकर मजदूर समस्याओं में रुचि लेने वाले व्यक्ति इस प्रकाशन से लाभ उठायेंगे।

नक्षत्रों की छाया में—लेखक—श्री श्रीकृष्ण भट्ट प्रकाशक—अखिल भारतीय सर्व सेवा संघ राजघाट काशी पृष्ठ ३२०, मूल्य १॥ रु०।

प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने धरती के नक्षत्रों की बात कही है, जिनको कि भूदान यात्रा के सिलसिले में लेखक ने असंख्य रूप में हर रोज देखा है। मानव की उदारता मानवता की दयालुता और मानवता की पवित्रता को प्रकट कर द्रवीभूत कर देने वाले उज्जवल नक्षत्र हैं ये। इन नक्षत्रों की छाया में भूदान यज्ञ के अध्वर्यु संत विनोबा के अनुगमन में लेखक ने उड़ीसा, हैदराबाद और आंध्र में २॥ मास बिताए हैं। इन्हीं दिनों के ये प्रसंग हृदयस्पर्शी भाषा में दैनन्दिन स्मरण और सानिध्य के रूप में पुस्तकाकार व्यक्त हुए हैं।

[सम्पादक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भूदान गंगा—भाग १ २ । प्रकाशक—वही । पृष्ट क्रमशः २८० और ३१२ । मूल्य १॥) रुपया प्रति ।

भूदान की गंगा बहाने का श्रेय विनोबा के भागीरथ प्रयत्न को है। पिछले पांच वर्षों से विनोबा इस कार्य में संलग्न हैं। उन्हीं के पांच सालों के प्रवचनों के महत्वपूर्ण अंश चुनकर उनका संकलन सुश्री निर्मला देशपांडे ने किया है। भूदान आरोहण का इतिहास, सर्वोदय विचार के सभी पहलुओं का दर्शन तथा शंका समाधान आदि दृष्टिकोण ध्यान में रखकर यह संकलन किया गया है।

राजनीति से लोकनीति की ओर-प्रकाशक-वही। पृष्ठ १२८, मूल्य ॥)

इस पुस्तिका में वर्तमान लोकशाही, राजनीति, चुनाव तथा लोकनीति सम्बन्धी सर्व सेवा संघ के प्रस्तावों और सर्वोदयी विचारकों के लेखों और विचारों और प्रश्नोत्तरों का संकलन किया गया है। पुस्तक ३ भागों में विभाजित है। लोकनीति-सम्बन्धी जानकारी पुस्तक से प्राप्त होती है।

ब्याज-बट्टा—प्रकाशक वही, लेखक श्री अप्पा पटवर्धन, पृष्ठ ५२, मूल्य ।)

इस पुस्तिका में ब्याज या सूदखोरी पर विचार किया गया है तथा सूदखोरी को निकृष्ट माना गया है। लेखक के इन विचारों को प्रकट करने के दो मुख्य उद्देश्य हैं विचार शील लोगों द्वारा इसका परीक्षण और संशोधन होना और सहमत लोगों की ओर से ब्याज-निरसन कार्य में सहयोग प्राप्त करने हैं।

'योजना'—(हिन्दी पाक्षिक) प्रधान सम्पादक—श्री खुशवन्त सिंह। पृष्ठ १६, मूल्य २ आने।

गणतन्त्र दिवस के शुभावसर पर, भारत सरकार के पब्लिकेशन डिवीजन ने 'योजना' नाम को पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ किया है। पत्रिका का उद्देश्य देश के प्रत्येक भाग में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सन्देश इस दृष्टि से पहुँचाना है कि लोग इसके लक्ष्यों और मान्यताओं को समझ लें। अतः इसी उद्देश्य के अनुसार इस अंक में योजना सम्बन्धी लेखों, चित्रों और आंकड़ों का चयन किया गया है। कविता कहानी भी दे दी गई है।

एक बात भाषा के सम्बन्ध में कहना उचित प्रतीत होता है। प्रत्येक श्रेणी के पाठकों तक इसकी पहुँच के लिए (जो कि पत्रिका का उद्देश्य भी है) भाषा को अधिक सरल करना होगा। भाषा ही नहीं, भाव और अभिव्यक्ति में भी सरलता लानी होगी। —म० मो० वि०

उत्तरप्रदेश पंचायती राज्य—१५ अप्रैल १९५६ के प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रगति सम्बन्धी परिशिष्ट। प्रकाशक सूचना विभाग उत्तरप्रदेश, लखनऊ।

मार्च ५६ में प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं के पूर्ण हो जाने पर उत्तरप्रदेश में योजना के अनुसार जो भी विकास कार्य हुए, उनसे जनता को अवगत कराने के लिए उत्तरप्रदेश पंचायती राज्य पत्रिका (पाक्षिक) ने अपने अपने अप्रैल अंक के परिशिष्टांक निकाले हैं। प्रत्येक परिशिष्टांक में एक एक कमिश्नरी को लिया गया है, और सामान्य परिचय, बागबानी, पशुपालन, सहकारिता उद्योग, यातायात, जनस्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण और पंचायतें शीर्षकों के अन्तर्गत इन सब जिलों के विकास कार्य का दिग्दर्शन कराया गया है।

आपका स्वास्थ्य

(हिन्दी की एक मात्र स्वास्थ्य सम्बन्धी मासिक पत्रिका)

"आपका स्वास्थ्य" आपके परिवार का साथी है।

"आपका स्वास्थ्य" अपने क्षेत्र के कुशल डाक्टरों द्वारा सम्पादित होता है।

"आपका स्वास्थ्य" में अध्यापकों, अभिभावकों, माताओं और देहातों के लिए विशेष लेख प्रकाशित होते हैं।

आज ही ६) रु० वार्षिक मूल्य भेजकर ग्राहक बनिए।

व्यवस्थापक,

आपका स्वास्थ्य—बनारस-१

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पूर्वी जर्मनी का विदेशी व्यापार

औद्योगिक क्षेत्र में अत्यन्त विकसित होने के कारण पूर्वी जर्मनी, इंजीनियरी और कारखानों के निर्माण सम्बन्धी सामान, अच्छी किस्म की मशीनें और औजार, बिजली के सामान और रसायनों तथा अनेक प्रकार के औद्योगिक उत्पादनों का निर्यात करता है।

दूसरे देशों को इन सामानों के निर्यात करने का उद्देश्य बाजार में केवल प्रमुखता प्राप्त करना नहीं है। इसका उद्देश्य तो केवल कच्चा माल, औद्योगिक और कृषि उत्पादनों के आयात के साथ संतुलन स्थापित करना है। इसी माल के विनिमय के आधार पर पूर्वी जर्मनी ने कई देशों के साथ सुदृढ़ आर्थिक सम्बन्ध स्थापित किये हैं।

पूर्वी जर्मनी ने प्राविधिक उच्च-स्तर और वस्तुओं की अच्छी किस्म के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार तथा अनेक विदेशी व्यापारिक मेलों में सम्मान प्राप्त किया है। १९५४ में ९ और १९५५ में ११ अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेकर पूर्वी जर्मनी ने अपने औद्योगिक उत्पादनों का विशाल प्रदर्शन किया। इसके अतिरिक्त १९५५ में विभिन्न उद्योगों ने निजी रूप में भी ३७ औद्योगिक प्रदर्शनियों में भाग लिया। इसी प्रकार पूर्वी जर्मनी के उद्योगों ने १९५६ में सामूहिक रूप में १४, और निजी रूप में ५२ अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लिया। ब्रुसेल्स, पेरिस और पोनजान के मेलों में अच्छी सफलता मिली।

इस समय विश्व के लगभग १०० देशों के साथ जर्मनी के व्यापारिक सम्बन्ध हैं। ये देश पूंजीवादी और समाजवादी, दोनों प्रकार के हैं। जहां तक समाजवादी देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध का प्रश्न है, यह सम्बन्ध उन देशों के आयोजन के विकास के कारण बढ़ा है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय में कुल विदेशी व्यापार का ७० प्रतिशत इन्हीं देशों से होगा।

वर्ष	१९५०	१९५१	१९५२	१९५३	१९५४	१९५५
कुल विदेशी व्यापार	१००	१५०.८	१७२.६	२२२.७	२७१.३	२७९.९
समाजवादी देशों से	१००	१५८.९	१७९.२	२३८.९	२८६.०	२७९.२
पश्चिमी योरोपके देशोंसे	१००	२३०.३	२९१.३	२९८.३	३४८.४	४०५.८
पश्चिमी जर्मनी से	१००	५६.२	५६.३	९४.५	१४८.९	१९०.९

लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि पश्चिमी देशों के साथ व्यापार घट जाएगा। सचाई यह है कि १९६०-६१ दूसरी योजना के समय, विदेशी व्यापार को १९५५ की अपेक्षा ७० प्रतिशत बढ़ाने का संकल्प किया गया है।

मशीनों का निर्यात करना जर्मन प्रजातंत्र की अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। अपनी औद्योगिक सम्पन्नता के कारण यह देश अविकसित देशों को औद्योगिक विकास के लिए सहायता देने में समर्थ हैं। अविकसित देशों के विकास के लिए इंजीनियरी के सामान और कारखाने बनाने के लिए जो भी मशीनें दी जाएंगी, उस देश की उपज से ही इनका विनिमय करने का प्रयत्न किया जाएगा। इस नीति के कारण किसी भी देश के राष्ट्रीय उद्योग के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

जर्मनी के विभिन्न देशों के साथ इस प्रकार के समझौते हुए हैं, जिससे उन देशों के साथ अच्छे सम्बन्ध हो जाने पर व्यापारिक और अन्य किसी भी प्रकार की रही-सही कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। इस प्रकार घनिष्ठ सम्बन्ध के कारण जो चतुर्मुखी विकास होगा, उससे दोनों ही देशों को लाभ होगा।

नीचे जर्मनी के विदेशी व्यापार के सूचक अंकों की तालिका दी जा रही है—

पहले आयात ढाई गुना बढ़ा, लेकिन पहली पंचवर्षीय योजना के समय से इसमें सुधार होने लगा। चूंकि पूर्वी जर्मनी के निर्यात का अधिकांश व्यापार समाजवादी देशों से होता है, लेकिन १९५५ में इनके निर्यात में अस्थायी रूप से अपेक्षाकृत कमी हुई।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

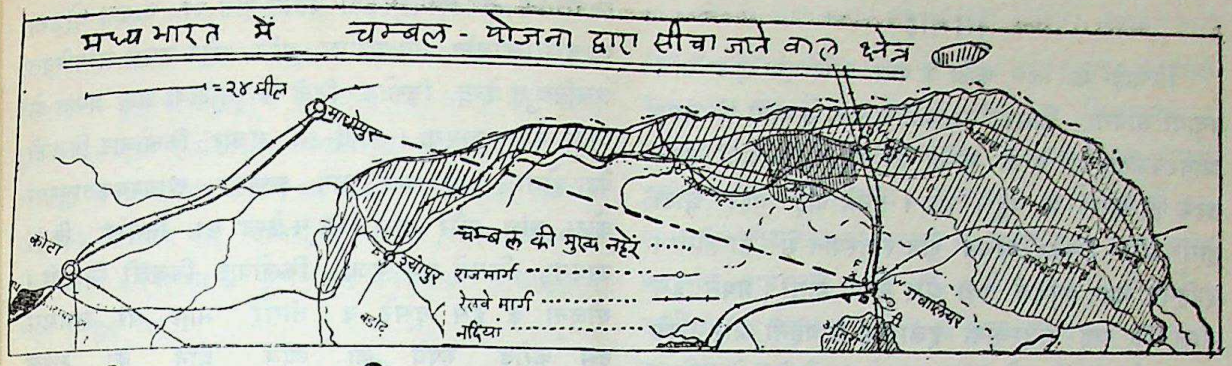

हमारी मुख्य नदी : चम्बल

पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित होने और इसका निर्माण कार्य की प्रगतिके कारण अब चम्बल नदी से, राजस्थान व मध्यभारत से बाहर के प्रायः सभी शिक्षित भारतीय परिचित हो गये हैं। यह महू के पास विन्ध्य की श्रेणी से निकलकर प्रथम उत्तर को और फिर मध्यभारत व राजस्थान की सीमा बनाती हुई पूर्वोत्तर बहती है और अन्त में उत्तरप्रदेश में इटावा के पास जमुना नदी में मिलती है। इसकी लम्बाई ६०० मील है और मध्यभारत व राजस्थान के लगभग ५५ हजार वर्गमील क्षेत्र की प्रति वर्ष औसतन ३५ इंच वर्षा का जल इस में पहुँचता है।

चम्बल विद्युत व सिंचाई योजना

इस योजना के फलस्वरूप २२७,००० किलोवाट विद्युत शक्ति जो मध्यभारत में फिलहाल पैदा होने वाली बिजली की कुल तादाद से दुगुनी है और १४ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की सुविधा, जो आज मध्यभारत में केवला ५ लाख एकड़ में मिलती है, उपलब्ध होगी और इसका लाभ मध्यभारत व राजस्थान को समान रूप से मिलेगा। विशेष बात यह है कि मध्यभारत के हिस्से की नहर प्रणाली के अलावा इस योजना के बाकी निर्माण कार्य नैसर्गिक अनुकूलता के कारण बहुत ही सुगम, सफल और सस्ते होने जा रहे हैं। पूरी योजना में ऐसे तीन बांध होंगे। इनके लिए आदर्श स्थान उस संकरी, पथरीली घाटी में मिल गए हैं, जो मानपुरा के पास चौरासीगढ़ से प्रारम्भ होकर कोटा के करीब लगभग ५० मील तक नदी का मार्ग बनाती है। योजना का मुख्य जल प्रदाय प्रथम

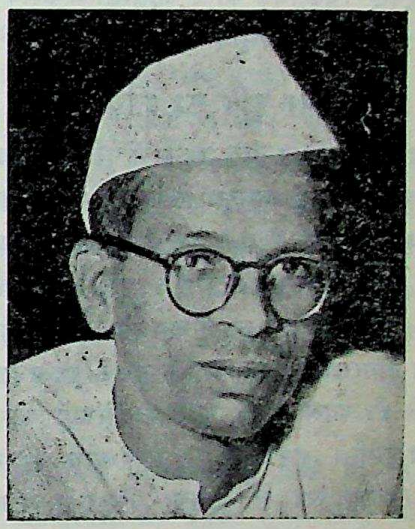

लेखक—श्री० वी० वी० द्रविड़

अर्थात गांधी सागर बांध द्वारा इस घाटी के प्रवेश द्वार पर स्थित विशाल कटोरे जैसे प्राकृतिक क्षेत्र में निर्माण होगा। इसके लिए अलग कोई बांध बांधने की आवश्यकता नहीं होगी।

विद्युत शक्ति

प्रत्येक बांध स्थल पर बांध की ऊंचाई से गिरने वाले पानी की जिस शक्ति को विद्युत शक्ति में परिवर्तित करने वाले जल विद्युत केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। इन केन्द्रों से यह विद्युत शक्ति ६११ लंबी मुख्य लाइनें व पंद्रह उप केन्द्रों द्वारा मध्यभारत व राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में पहुँचाई जाएंगी।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सिंचाई

सिंचाई के लिए कोटा के पास और एक छोटा बांध बनाया जायगा, जिसकी सहायता से नदी के पानी की सतह आवश्यकतानुसार ऊंची उठाई जाएगी, ताकि पानी दोनों तरफ की नहरों में पहुँच सके। इनमें बाईं नहर छोटी होगी और उसका सिंचन क्षेत्र राजस्थान में ही होगा। दाहिनी नहर अधिक बड़ी और लम्बी होगी। प्रथम ३८ मील तक वह राजस्थानी इलाके में से बहेगी और उसके बाद पार्वती नदी को पार कर मुरेना जिले के श्योपुर तहसील के राधापुरा ग्राम के पास यह दाहिनी नहर मध्य-भारत में प्रवेश करेगी और अपनी शाखा प्रशाखाओं द्वारा मुरेना एवम् भिंड जिले की ९ तहसीलों के करीब १५५० गांवों में ७ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करेगी।

योजना पूर्ति का कार्यक्रम

यह सारी योजना तीन भागों में पूरी करने का संकल्प है। प्रथम भाग में मानपुरा के निकट का गाँधी सागर बांध, वहां का जल विद्युत केन्द्र, बिजली की अधिकांश लाईनें, कोटा का सिंचाई बांध व पूरी नहर-प्रणाली का निर्माण होना है। इस कारण लगभग ५० करोड़ रुपयों का व्यय होगा और ६९००० किलोवाट विद्युत शक्ति तथा पूरी याने १४ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। इसका लाभ मध्यभारत व राजस्थान दोनों को समान रूप से मिलेगा, किन्तु मध्यभारत को नहर प्रणाली पर अधिक व्यय उठाना पड़ेगा। इस भाग पर होने वाले लागत व्यय पर लगभग ४ प्रतिशत से अधिक शुद्ध लाभ अपेक्षित है। किन्तु इससे कई गुना अधिक महत्वपूर्ण और अमूल्य लाभ तो बिजली और सिंचाई की सुविधा के फलस्वरूप होने वाली इस पूरे क्षेत्र की सर्वांगीण उन्नति के रूप में होगा। योजना का यह पहला भाग द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लग-भग पूरा होने की आशा है। किन्तु गांधीसागर बांध की व उसके आनुषांगिक कार्यों की प्रगति देखते हुए हम यह विश्वास कर सकते हैं कि बिजली व सिंचाई की सुविधा १९५९-६० से ही उपलब्ध होने लगेगी।

गांधी सागर जल विद्युत केन्द्र से उपलब्ध बिजली से अधिक की आवश्यकता प्रतीत होने पर चम्बल योज का दूसरा अर्थात प्रतापसागर बांध और उससे सम्बन्धि जलविद्युत केन्द्र चित्तोड़ जिले में चूलिया जल प्रपात निकट बांधा जायगा। यहां ९० हजार किलोवाट बिज पैदा होगी। इसी प्रकार आगे चलकर आवश्यकतानु कोटा बांध और जल विद्युत केन्द्र का निर्माण कि जायगा, जिससे ४५ हजार किलोवाट बिजली मिलेगी योजना के इस दूसरे व तीसरे भाग पर लगभ दस करोड़ रुपये का व्यय होने का स्थू अनुमान है।

निर्माण कार्य का श्रीगणेश

योजना बन गई, काम शुरू हुआ, लेकिन वह नापसंद दिया गया और योजना का निर्माण ठप्प हो गया। योज आयोग ने भी पूर्ण चित्र तयार न होने तक इसे मान्य देने से इन्कार कर दिया और योजना स्थगित करने आदेश दे दिये गये। निराशा, व्यग्रता व अनिश्चितता इस वातावरण में सन् १९५२ में जब इस योजना जिम्मेदारी मुझ पर डाली गयी, मुझे यह प्रतीत हुआ कि इस गत्यवरोध को समाप्त करना कठिन है; क्योंकि का स्थगित रखने का केन्द्रीय शासन का आदेश तब तक कायम रहने वाला था, जब तक कि योजना आयोग इस योज पर अपनी स्वीकृति न दे और यह स्वीकृति कैसे मि सकती थी, जब कि योजना के सारे ही महत्वपूर्ण अङ्ग त तक अनिश्चित अवस्था में ही थे। गांधी सागर बांध ऊंचाई व डिजाइन, कोटा बांध का स्थान व डिजाइ नहरों का मार्ग व डिजाइन यह सभी अनिर्णीत थे।

अतः सर्वप्रथम कार्य, योजना आयोग व केन्द्रीय शास को चम्बल योजना का मूलभूत रूप से सही व स्वीक होने का विश्वास दिला कर उन से योजना का तात्कालि कार्य प्रारम्भ करने की इजाजत लेने का था, जिससे योज आगे अधिक खटाई व ढील में न पड़े और स्टाफ पर हो वाला व्यय निरर्थक न जाय। बहुत परिश्रम से यह इज जत प्राप्त हुई और तब ता० २६ जनवरी १९५३ को गांधी सागर बांध की नींव की खुदाई आरम्भ की गई।

पंचवर्षीय योजना में चम्बल योजना भी समाविष्ट हुई केन्द्रीय वित्त मंत्री से अल्प बचत की प्रादेशिक धनराशि

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चम्बल के लिए उपलब्ध की गई। बादमें मध्यभारत शासन ने अपना प्रथम ऋण प्रमुखतः इस योजना के लिए निकाला। कुछ अन्तर्राष्ट्रीय सहायता भी प्राप्त की गई। इस प्रकार एक दीर्घकालीन गत्यवरोध समाप्त हुआ और योजना के तात्कालिक स्वरूप का कार्य प्रगति करने लगा। कई वर्षों में प्रथम बार चम्बल में नियुक्त व्यक्ति उलझन, निष्क्रियता व निराशा के कुचक्र से निकलकर उत्साहपूर्वक काम में जुट गए।

योजना के प्रमुख प्रश्नों का हल

लेकिन जब तक योजना के मुख्य पहलू, जो अब भी अनिर्जीत थे, निश्चित नहीं किए जाते, तब तक योजना का भविष्य सुस्थिर नहीं बन सकता था। इस संबंध में सबसे अधिक अस्पष्टता सिंचाई वाले हिस्से के विषय में थी। पानी के बंटवारे के संबंध में मध्यभारत व राजस्थान के बीच विवाद चल रहा था और उसका अन्त कब और कैसे होगा, यह नहीं कहा जा सकता था। इस विवाद को लेकर कोटा बेराज का स्थान व नहरों का मार्ग इत्यादि कुछ भी निश्चित नहीं हो सका था। यह सारी स्थिति समझाकर मैंने आपसी समझौते से इस विवाद को निबटाने का प्रयत्न करना उचित समझा और यह सचमुच प्रसन्नता की बात है कि राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री जयनारायण जी व्यास व विभागीय मंत्री श्री भोगीलाल जी पंड्या के सहयोग से इसमें सफलता मिली। पानी के लाभ का विभाजन, जो दोनों राज्यों में समानता के आधार पर हुआ है, विशेषज्ञों की सम्मति के अनुसार भी सर्वोचित है।

इस बुनियादी महत्व के निर्णय के फलस्वरूप, योजना का सिंचाई के पहलू का सारा चित्र फिर शीघ्रतापूर्वक तैयार किया जा सका। इसके अनुसार मध्यभारत में कमान्डेट एरिया का अधिकतम क्षेत्र सींचा जा सकेगा। गांधी सागर बांध का डिजाइन व अन्य विद्युत् सम्बन्धी प्रश्नों के भी अन्तिम निश्चय पीछे से हो गये और उन पर केन्द्रीय जल विद्युत् निगम, योजना आयोग व केन्द्रीय शासन की सम्मति भी प्राप्त कर ली गई।

निर्माण कार्य

इस सारी कार्रवाई के साथ ही निर्माण कार्य अधिकतम गति से आगे बढ़ाने की पूरी-पूरी कोशिश बराबर जारी रही है। गांधी सागर बांध की नींव की खुदाई आवश्यकतानुसार होते ही बांध निर्माण कार्य का शिलान्यास ७ मार्च १९५४ को पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के कर कमलों द्वारा सम्पन्न किया गया। इस बांध के निर्माण में ७५ लाख घन फीट नींव की चट्टान की खुदाई तथा २५६ लाख घन फीट, पत्थर की जुड़ाई एवं कांक्रीट का काम होना है। उसमें से यह सितम्बर १९५६ के अन्त तक ६२.३३८ लाख घन फीट तथा ७२.००३ लाख घन फीट का काम हुआ है।

मौजूदा मौसम में रातपाली में भी बांध का काम किया जायगा। प्रस्तावित बढ़े हुए प्रमाण में काम को पूरा करने के उद्देश्य से बांध स्थल पर पत्थर फोड़ने, रेत बनाने, चूना सीमेंट आदि मसाले का मिश्रण करने व यह सब सामग्री निर्माण स्थल पर पहुँचाने के लिए आवश्यक यांत्रिक व्यवस्था की जा चुकी है। बांध व जल विद्युत केन्द्र के निर्माण में आगे लगनेवाली सामग्री यथासमय उपलब्ध हो सके, इसका प्रबन्ध भी किया गया है। जल विद्युत गृह की नींव तैयार की जा रही है और बिजली के तारों का मार्ग निर्धारित किया जा रहा है। उज्जैन व इन्दौर तक की बिजली की लाइनों के मार्ग का सर्वेक्षण पूरा किया गया है।

नहर प्रणाली के मध्यभारत के हिस्से में १३,५०० लाख घन फीट मिट्टी की खुदाई ३०० लाख घन फीट पत्थर की खुदाई तथा २०० लाख घन फीट जुड़ाई का काम होना है। उसमें से माह सितम्बर १९५६ के अन्त तक ७८०.६७४ घन फीट मिट्टी की खुदाई और ४२.२१५ लाख घन फीट पत्थर की खुदाई हुई है। जुड़ाई के काम का प्रारम्भ हो चुका है।

बांध के क्षेत्र से विस्थापित कृषकों के लिए निर्धारित क्षेत्र में ३,४०० एकड़ जमीन साफ की गई है, उसमें से ५९५.९० एकड़ ट्रैक्टरों से जोती गई है और २७१ एकड़ जमीन में कंटूर बंडिंग भी किया गया है।

कुल मिलाकर यह विश्वास किया जा सकता है कि योजना की पूर्ति समय पर होगी और उसका कुछ लाभ तो निर्धारित समय के पूर्व से ही मिलने लगेगा। शासन ने

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारत-भूमि में नए खनिज स्रोत

अनेक नये खनिज

देश के भूगर्भ में अभी कितना धन छिपा पड़ा है, इसका पूरा अन्दाजा नहीं लग सका। अपने प्राकृतिक साधनों के पूर्ण उपयोग करते हुए हमने देश की सर्वांगीण उन्नति का निश्चय किया है। तब इस क्षेत्र में भी प्रयत्न होना चाहिए। हर्ष है कि सरकार ने इस बात को महज समझा ही नहीं वरन् इस क्षेत्र में कार्य भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने पंजाब के महेन्द्रगढ़ में लौह भी आरंभ कर दिया है। खनिज की २॥ मील लम्बी एक पट्टी का पता लगाया है अनुमान है कि इस पट्टी में २० लाख टन से अधिक लौह खनिज होगा।

भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग की प्रयोगशाला में इस पट्टी से निकाले गये लौह खनिज का रासायनिक विश्लेषण किया गया है। इससे पता चला है कि इससे अच्छी किस्म का लौहा तैयार किया जा सकता है।

लेकिन केवल यही पट्टी इस्पात का कारखाना चलाने के लिए काफी नहीं है। इसलिए यह सुझाव दिया गया है कि राजस्थान के धनौटा-धनचांली आदि समीपवर्ती क्षेत्र के लौह खनिज भंडार की जांच करके पता लगाना चाहिए कि वहां खनिज किस किस्म का है और कितनी मात्रा में मिल सकता है। विभिन्न भंडारों का लौह खनिज अगर एक ही किस्म का हो तो सम्भवतः उससे भाकड़ा-नंगल योजना से प्राप्त विद्युत-शक्ति की सहायता से इस्पात का एक कारखाना चलाया जा सकता है।

पट्टी से लौह खनिज निकालने का काम फिलहाल निजी तौर पर किया जा रहा है। फरवरी से अप्रैल १९५५ तक का उत्पादन ८० हजार मन था, जिसमें से ५ हजार मन स्थानान्तरित कर दिया गया। उत्पादन व्यय प्रति सौ मन ८० रु० हुआ। लौह खनिज नार्वे और चेकोस्लावाकिया भेज दिया गया है।

आन्ध्र में भी

भारतीय भू-गर्भ सर्वे विभाग ने आंध्र में लौह खनिज के दो ऐसे भंडारों का पता लगाया है जिनमें अन्दाजन ३८ करोड़ ९० लाख टन लौह खनिज है। ये भंडार गुंटूर और नैल्लोर जिलों में हैं। कहा जाता है कि इन स्थानों से कई सदियों तक लौह खनिज निकाला जा सकेगा।

इन भंडारों में लगभग २९ करोड़ ६० लाख टन ऐसी चट्टानें हैं, जिनमें ३३ से ३७ प्रतिशत तक लोहा है। बाकी में लगभग २५ प्रतिशत लोहे का अंश है। और खोज करने से दूसरे भी भंडारों का पता चल सकता है।

चूने का पत्थर

आंन्ध्र राज्य ही गुंटुर जिले के मछेरला उपतालुक में अनुमानतः १२ करोड़ ४० लाख टन चूने के पत्थर के दो भण्डार मिले हैं। यह पत्थर सीमेंट बनाने के काम आ सकता है। भंडार मछेरला से दक्षिण-पश्चिम में हैं। मछेरला गुंटूर-मछेरला रेल-मार्ग पर अन्तिम स्टेशन है। चूने के पत्थर के ये भण्डार नंदीकोंडा बांध से केवल २५ मील दूर हैं और नागार्जुनसागर की बहूद्देशीय योजना के लिए मछेरला के पास जो सीमेंट कारखाना बनाया जा रहा है, उसके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।

इसी प्रकार भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने

यह नीति निश्चित कर ली है कि चम्बल विद्युत का पर्याप्त लाभ ग्रामीण क्षेत्रों को मिलना चाहिए। इसी प्रकार सिंचाई का भी पूरा लाभ उठाया जा सके, इस हेतु से विभिन्न नहरी क्षेत्रों में कृषि प्रयोग व प्रदर्शन फार्म प्रारम्भ किये गये हैं।

चम्बल योजना में नियुक्त श्रमिक, जिनकी संख्या अब तक १०,००० तक रही है, और जो दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली है, व कर्मचारियों की सुविधा पर भी यथोचित ध्यान दिया जा रहा है। इस हेतु से उन्हें मकान, वैद्यकीय सहायता आदि सहूलियतें यथा संभव दी जा रही हैं। एक उल्लेखनीय बात यह है कि नहरी क्षेत्र में स्थानीय आदिवासी श्रमिकों की सहकारी समिति को निर्माण कार्य दिया गया है और यह प्रयोग आशाजनक रूपमें सफल रहा है। उसे और फैलाने की नीति स्वीकार की गई है।

—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

देहरादून-मसूरी क्षेत्र में भी अच्छी किस्म का ४० करोड़ ६० लाख चूने के पत्थर का पता लगाया है।

उत्तर प्रदेश के भूतत्व एवं खनिकर्म संचालन कार्य की प्रारम्भिक जांच से भी पता चलता है कि ऋषिकेश के निकट गढ़वाल जिले में स्थित दो करोड़ ८४ लाख टन चूने के पत्थर की खानें हैं।

देहरादून जिले में स्थित बड़ाकोट के चूने की खान से नमूने लिए जा चुके हैं और अब इस सम्बन्ध में विश्लेषण कार्य हो रहा है। अनुमान है कि इस खान से सीमेंट बनाने के काम आने वाले तीन करोड़ ८२ लाख टन चूने के पत्थर प्राप्त हो सकते हैं।

मिर्जापुर जिले के बन्सी क्षेत्र में किये गये शोध कार्यों से पता चला है कि यहाँ अनुमानतः सात लाख टन चूने के पत्थर हैं।

भूरा कोयला

अभी अभी भारत सरकार ने मद्रास राज्य में नेवेली की खानों से प्रतिवर्ष ३५ लाख टन भूरा कोयला (लिग-नाइट) निकलने की बहुमुखी योजना स्वीकार की है। भूरे कोयले की खुदाई का काम सन् १९६० के प्रारम्भ में शुरू होगा और वर्ष के अन्त तक इन खानों में पूरी तरह काम होने लगेगा। ६८ करोड़ रुपए की इस बहुमुखी योजना में कोयले की खुदाई के अतिरिक्त बिजली और खाद तैयार करना भी शामिल है।

परीक्षण से मालूम हुआ है कि नेवेली की खानों के भूरे कोयले में ५० प्रतिशत नमी, ३ प्रतिशत राख और प्रति पौंड ५५०० ताप मात्रा है। करीब २॥ टन भूरा कोयला १ टन अच्छे कोयले के बराबर ताप देता है। एक वर्ष में ३५ लाख टन भूरा कोयला निकाला जायगा, जो १२॥ लाख टन अच्छे कोयले के बराबर होगा। भूरा कोयला कुछ भारी और अपने आप जल उठने वाला होता है। इसकी नमी में १५ प्रतिशत नमी लाने के लिए इसे सिझाया जायगा।

नेवेली के भूरे कोयले से मद्रास के औद्योगिक विकास में बहुत सहायता पहुँचेगी, क्योंकि इस राज्य में विद्युत-शक्ति की कमी है। कृषि के विकास के लिए भी यहां विद्युत-शक्ति जरूरी है। खानों के पास लगे वायलरों में भूरे कोयले का ईंधन के रूप में इस्पात सस्ता पड़ता है।

भारत सरकार के व्यापार और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित

'उद्योग व्यापार पत्रिका'

★ उद्योग और व्यापार सम्बन्धी प्रामाणिक जानकारी युक्त विशेष लेख, भारत सरकार की आवश्यक सूचनाएं, उपयोगी आंकड़े आदि प्रति मास दिये जाते है।

★ डिमाई चौपेजी आकार के ६० ७० पृष्ठ : मूल्य केवल ६ रुपया वार्षिक। एजेण्टों को अच्छा कमीशन दिया जायगा। पत्रिका विज्ञापन का सुन्दर साधन है।

★ लघु-उद्योग विशेषांक मंगा कर छोटे उद्योगों के सम्बन्ध में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त कीजिये।

★ ग्राहक बनने, एजेन्सी लेने अथवा विज्ञापन छपाने के लिए नीचे लिखे पते पर पत्र भेजिये :—

सम्पादक

उद्योग व्यापार पत्रिका

उद्योग और व्यापार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नया सामयिक साहित्य

वैज्ञानिक हिन्दी कोष—प्रकाशक—भारत सरकार का शिक्षा विभाग।

भारत में हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने में और देश भर में उसका प्रचार करने में जो सबसे बड़ी बाधा अनुभव की जा रही है वह यह है कि हिन्दी में पारिभाषिक शब्दों का अभाव है। इस सम्बन्ध में आचार्य डाक्टर रघुवीर के नेतृत्व में बहुत सुन्दर प्रयत्न किया गया है। अनेक राज्यों ने इस दिशा में कुछ कार्य अवश्य किया है। किन्तु सब राज्यों की ओर से एक सम्मिलित प्रयत्न की आवश्यकता थी और केन्द्रीय सरकार को इस दिशा में प्रयत्न करना चाहिए था। यह प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने इस दिशा में अब कुछ प्रयत्न किया है। हमारे पास डाक तार, रसायन शास्त्र, कृषि, वनस्पति शास्त्र, रक्षा, जहाजी यातायात, प्राकृतिक भूगोल आदि विषयों पर भारत सरकार के शिक्षा-विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकें पहुँची हैं। हम इस प्रयत्न का सहर्ष स्वागत करते हैं।

शब्द-निर्माण में दो बातों का ध्यान रखा गया है। अधिकांश शब्द संस्कृत से बनाये गए हैं। किन्तु बहुत से प्रचलित शब्द भी ले लिये गये हैं, और उनके ले लेने में हमें कोई आपत्ति नहीं दीखती। कुछ शब्द प्रांतीय भाषाओं से भी लिये गये हैं। इस तरह चुनाव का क्षेत्र असंदिग्ध रूप से व्यापक हो जाता है। किन्तु एक बात हमें समझ में नहीं आई और वह मूलभूत बात है। भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने यह स्वीकृत कर लिया है कि बहुत से अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक शब्द ज्यों के त्यों नागरी में लिखे जायेंगे। हमारी यह निश्चित सम्मति है कि बोल चाल में आये शब्दों के अतिरिक्त वैज्ञानिक शब्दों के लिए संस्कृत बहुत समर्थ भाषा है। शिक्षा विभाग को इस नीति पर पुनः विचार करना चाहिये।

यह सम्भव है कि शब्दों के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद हो, किन्तु उपर्युक्त त्रुटि के अतिरिक्त साधारणतया यह शब्द कोष हमें पसन्द आये।

Recent Developments in Indian Economy. प्रकाशक—अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर कार्यालय भारतीय शाखा, नई दिल्ली। मूल्य १॥) रु०।

अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर कार्यालय समय समय पर भारत की आर्थिक नीति, प्रवृति और परिवर्तनों के सम्बन्ध में सुन्दर साहित्य प्रकाशित करता है। प्रस्तुत पुस्तक भी इसी विषय पर एक सुन्दर प्रकाशन है। प्रस्तुत पुस्तक में चार लेख हैं—भारत में उद्योग, भारत में औद्योगिक वेतन, भारत में सामूहिक समझौते तथा भारत में सहकारी बिक्री।

ये चारों लेख पर्याप्त अध्ययन और परिश्रम के बाद लिखे गये हैं। इन चारों लेखों में प्रत्येक विषय का परिचय तथा आज की प्रगति और उस पर विवेचनात्मक प्रणाली अपनाई गई है। अपने विषय की पुष्टि में नवीनतम अंक देकर इस पुस्तक को अर्थ-शास्त्र के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के लिए बहुत अधिक उपयोगी बना दिया गया है। सामग्री संग्रह की दृष्टि से यह पुस्तक बहुत उपयोगी हो गई है, क्योंकि मजदूर कार्यालय ने विभिन्न राज्यों की सरकारों से अधिकृत सूचनाएं मंगवाने के बाद उनका प्रयोग किया है। हमें आशा है कि अर्थशास्त्र के विद्वान और विशेषकर मजदूर समस्याओं में रुचि लेने वाले व्यक्ति इस प्रकाशन से लाभ उठायेंगे।

नक्षत्रों की छाया में—लेखक—श्री श्रीकृष्ण भट्ट, प्रकाशक—अखिल भारतीय सर्व सेवा संघ राजघाट काशी, पृष्ठ ३२०, मूल्य १॥ रु०।

प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने धरती के नक्षत्रों की बात कही है, जिनको कि भूदान यात्रा के सिलसिले में लेखक ने असंख्य रूप में हर रोज देखा है। मानव की उदारता मानवता की दयालुता और मानवता की पवित्रता को प्रकट कर द्रवीभूत कर देने वाले उज्जवल नक्षत्र हैं ये। इन्हीं नक्षत्रों की छाया में भूदान यज्ञ के अध्वर्यु संत विनोबा के अनुगमन में लेखक ने उड़ीसा, हैदराबाद और आंध्र में २॥ मास बिताए हैं। इन्हीं दिनों के ये प्रसंग हृदयस्पर्शी भाषा में दैनन्दिन स्मरण और सानिध्य के रूप में पुस्तकाकार व्यक्त हुए हैं।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भूदान गंगा—भाग १ २ । प्रकाशक—वही । पृष्ठ क्रमशः २८० और ३१२ । मूल्य १॥) रुपया प्रति ।

भूदान की गंगा बहाने का श्रेय विनोबा के भागीरथ प्रयत्न को है। पिछले पांच वर्षों से विनोबा इस कार्य में संलग्न हैं। उन्हीं के पांच सालों के प्रवचनों के महत्वपूर्ण अंश चुनकर उनका संकलन सुश्री निर्मला देशपांडे ने किया है। भूदान आरोहण का इतिहास, सर्वोदय विचार के सभी पहलुओं का दर्शन तथा शंका समाधान आदि दृष्टिकोण ध्यान में रखकर यह संकलन किया गया है।

राजनीति से लोकनीति की ओर-प्रकाशक-वही। पृष्ठ १२८, मूल्य ॥)

इस पुस्तिका में वर्तमान लोकशाही, राजनीति, चुनाव तथा लोकनीति सम्बन्धी सर्व सेवा संघ के प्रस्तावों और सर्वोदयी विचारकों के लेखों और विचारों और प्रश्नोत्तरों का संकलन किया गया है। पुस्तक ३ भागों में विभाजित है। लोकनीति-सम्बन्धी जानकारी पुस्तक से प्राप्त होती है।

ब्याज-बट्टा—प्रकाशक वही, लेखक श्री अप्पा पटवर्धन, पृष्ठ ५२, मूल्य ।)

इस पुस्तिका में ब्याज या सूदखोरी पर विचार किया गया है तथा सूदखोरी को निकृष्ट माना गया है। लेखक के इन विचारों को प्रकट करने के दो मुख्य उद्देश्य हैं विचार शील लोगों द्वारा इसका परीक्षण और संशोधन होना और सहमत लोगों की ओर से ब्याज-निरसन कार्य में सहयोग प्राप्त करने हैं।

'योजना'—(हिन्दी पाक्षिक) प्रधान सम्पादक—श्री खुशवन्त सिंह। पृष्ठ १६, मूल्य २ आने।

गणतन्त्र दिवस के शुभावसर पर, भारत सरकार के पब्लिकेशन डिवीजन ने 'योजना' नाम को पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ किया है। पत्रिका का उद्देश्य देश के प्रत्येक भाग में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सन्देश इस दृष्टि से पहुँचाना है कि लोग इसके लक्ष्यों और मान्यताओं को समझ लें। अतः इसी उद्देश्य के अनुसार इस अंक में योजना सम्बन्धी लेखों, चित्रों और आंकड़ों का चयन किया गया है। कविता कहानी भी दे दी गई है। एक बात भाषा के सम्बन्ध में कहना उचित प्रतीत होता है। प्रत्येक श्रेणी के पाठकों तक इसकी पहुँच के लिए (जो कि पत्रिका का उद्देश्य भी है) भाषा को अधिक सरल करना होगा। भाषा ही नहीं, भाव और अभिव्यक्ति में भी सरलता लानी होगी। —म० मो० वि०

उत्तरप्रदेश पंचायती राज्य—१५ अप्रैल १९५६ के प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रगति सम्बन्धी परिशिष्ट। प्रकाशक सूचना विभाग उत्तरप्रदेश, लखनऊ।

मार्च ५६ में प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं के पूर्ण हो जाने पर उत्तरप्रदेश में योजना के अनुसार जो भी विकास कार्य हुए, उनसे जनता को अवगत कराने के लिए उत्तरप्रदेश पंचायती राज्य पत्रिका (पाक्षिक) ने अपने अपने अप्रैल अंक के परिशिष्टांक निकाले हैं। प्रत्येक परिशिष्टांक में एक एक कमिश्नरी को लिया गया है, और सामान्य परिचय, बागवानी, पशुपालन, सहकारिता उद्योग, यातायात, जनस्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण और पंचायतें शीर्षकों के अन्तर्गत इन सब जिलों के विकास कार्य का दिग्दर्शन कराया गया है।

आपका स्वास्थ्य

(हिन्दी की एक मात्र स्वास्थ्य सम्बन्धी मासिक पत्रिका)

"आपका स्वास्थ्य" आपके परिवार का साथी है।

"आपका स्वास्थ्य" अपने क्षेत्र के कुशल डाक्टरों द्वारा सम्पादित होता है।

"आपका स्वास्थ्य" में अध्यापकों, अभिभावकों, माताओं और देहातों के लिए विशेष लेख प्रकाशित होते हैं।

आज ही ६) रु० वार्षिक मूल्य भेजकर ग्राहक बनिए।

व्यवस्थापक,

आपका स्वास्थ्य—बनारस-१

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पूर्वी जर्मनी का विदेशी व्यापार

औद्योगिक क्षेत्र में अत्यन्त विकसित होने के कारण पूर्वी जर्मनी, इंजीनियरी और कारखानों के निर्माण सम्बन्धी सामान, अच्छी किस्म की मशीनें और औजार, बिजली के सामान और रसायनों तथा अनेक प्रकार के औद्योगिक उत्पादनों का निर्यात करता है।

दूसरे देशों को इन सामानों के निर्यात करने का उद्देश्य बाजार में केवल प्रमुखता प्राप्त करना नहीं है। इसका उद्देश्य तो केवल कच्चा माल, औद्योगिक और कृषि उत्पादनों के आयात के साथ संतुलन स्थापित करना है। इसी माल के विनिमय के आधार पर पूर्वी जर्मनी ने कई देशों के साथ सुदृढ़ आर्थिक सम्बन्ध स्थापित किये हैं।

पूर्वी जर्मनी ने प्राविधिक उच्च-स्तर और वस्तुओं की अच्छी किस्म के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार तथा अनेक विदेशी व्यापारिक मेलों में सम्मान प्राप्त किया है। १९५४ में ९ और १९५५ में ११ अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेकर पूर्वी जर्मनी ने अपने औद्योगिक उत्पादनों का विशाल प्रदर्शन किया। इसके अतिरिक्त १९५५ में विभिन्न उद्योगों ने निजी रूप में भी ३७ औद्योगिक प्रदर्शनियों में भाग लिया। इसी प्रकार पूर्वी जर्मनी के उद्योगों ने १९५६ में सामूहिक रूप में १४, और निजी रूप में ५२ अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लिया। ब्रुसेल्स, पेरिस और पोनजान के मेलों में अच्छी सफलता मिली।

इस समय विश्व के लगभग १०० देशों के साथ जर्मनी के व्यापारिक सम्बन्ध हैं। ये देश पूंजीवादी और समाजवादी, दोनों प्रकार के हैं। जहां तक समाजवादी देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध का प्रश्न है, यह सम्बन्ध उन देशों के आयोजन के विकास के कारण बढ़ा है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय में कुल विदेशी व्यापार का ७० प्रतिशत इन्हीं देशों से होगा।

वर्ष	१९५०	१९५१	१९५२	१९५३	१९५४	१९५५
कुल विदेशी व्यापार	१००	१५०.८	१७२.६	२२२.७	२७१.३	२७९.९
समाजवादी देशों से	१००	१५८.९	१७९.२	२३८.९	२८६.०	२७९.२
पश्चिमी योरोपके देशोंसे	१००	२३०.३	२९१.३	२९८.३	३४८.४	४०५.८
पश्चिमी जर्मनी से	१००	५६.२	५६.३	९४.५	१४८.९	१९०९

लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि पश्चिमी देशों के साथ व्यापार घट जाएगा। सचाई यह है कि १९६० में दूसरी योजना के समय, विदेशी व्यापार को १९५५ की अपेक्षा ७० प्रतिशत बढ़ाने का संकल्प किया गया है।

मशीनों का निर्यात करना जर्मन प्रजातंत्र की अर्थ-व्यवस्था की एक विशेषता है। अपनी औद्योगिक सम्पन्नता के कारण यह देश अविकसित देशों को औद्योगिक विकास के लिए सहायता देने में समर्थ हैं। अविकसित देशों को विकास के लिए इंजीनियरी के सामान और कारखाने बनाने के लिए जो भी मशीनें दी जाएंगी, उस देश की उपज से ही इनका विनिमय करने का प्रयत्न किया जाएगा। इस नीति के कारण किसी भी देश के राष्ट्रीय उद्योग के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

जर्मनी के विभिन्न देशों के साथ इस प्रकार के समझौते हुए हैं, जिससे उन देशों के साथ अच्छे सम्बन्ध हो जाने पर व्यापारिक और अन्य किसी भी प्रकार की रही-सही कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। इस प्रकार घनिष्ठ सम्बन्ध के कारण जो चतुर्मुखी विकास होगा, उससे दोनों ही देशों को लाभ होगा।

नीचे जर्मनी के विदेशी व्यापार के सूचक अंक की तालिका दी जा रही है—

पहले आयात ढाई गुना बढ़ा, लेकिन पहली पंचवर्षीय योजना के समय से इसमें सुधार होने लगा। चूंकि पूर्वी जर्मनी के निर्यात का अधिकांश व्यापार समाजवादी देशों से होता है, लेकिन १९५५ में इनके निर्यात में अस्थायी रूप से अपेक्षाकृत कमी हुई।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रगति पथ पर कृषि

कृषि उत्पादन के दो तीन वर्ष अच्छे बीतने के बाद फिर कुछ संकट उत्पन्न हो गया था। और राष्ट्र का ध्यान पुनः कृषि की ओर खिंच गया है। इस वर्ष के प्राप्त समाचारों से मालूम होता है कि प्रकृति अनुकूल रहेगी और कृषिजन्य पदार्थों की उपज अपेक्षाकृत अच्छी रहेगी।

गेहूँ

१९५६ ५७ में देश में रबी की फसल (गेहूं और जौ) का रकबा प्रथम प्राक्कलन के अनुसार ३,८७,७१,००० एकड़ आंका गया है। पिछले वर्ष संशोधित प्राक्कलन के अनुसार ३,६०,१५,००० में रबी की फसल बोयी गयी थी। अर्थात् इस वर्ष रबी की फसल का रकबा २७,५७,००० एकड़ या ७.७ प्रतिशत अधिक है। यह सूचना कृषि मंत्रालय के आर्थिक एवं अंकसंकलन निदेशालय ने दी है। यह प्राक्कलन दिसम्बर, १९५६ तक का है। उस समय तक रबी की फसल अच्छी थी।

इस में रबी की फसल का सारा रकबा नहीं दिया गया। पहले अनुभव के अनुसार पहले प्राक्कलन में लगभग ९० प्रतिशत रकबा आता है। खरीब की फसलों का १९५६-५७ का प्राक्कलन पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है। पहले प्राक्कलन के तैयार होते होते रबी तथा खरीफ की फसलों की जो स्थिति है, उसका विवरण इस प्रकार है:—

इससे पता चलेगा कि चालू वर्ष के पहले प्राक्कलन के समय तक पिछले वर्ष से ३०,२५,००० एकड़ क्षेत्र बढ़ा, यानी १.७ प्रतिशत वृद्धि हुई;

गेहूं की खेती का क्षेत्र भी पिछले वर्ष की अपेक्षा बढ़कर ३,०५,०२,००० एकड़ हो गया है।

इस प्राक्कलन के अनुसार जौ की खेती का क्षेत्र भी इस साल बढ़कर ८२,७०,००० एकड़ हो गया। पिछले वर्ष यह रकबा कुल ८२,५९,००० एकड़ था।

धान का रकबा बढ़ा

केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के अर्थ तथा अंक-संकलन निदेशालय के अनुसार १९५६-५७ के दूसरे अखिल भारतीय प्राक्कलन में धान की खेती का क्षेत्रफल ७,२५,१२,००० एकड़ और उत्पादन २,३९,००,००० टन बताया गया है। १९५५-५६ के प्राक्कलन में क्षेत्रफल ७,१८,८६,००० एकड़ और उत्पादन २,३५,१५,००० टन था। इस प्रकार पिछले वर्ष की अपेक्षा धान की खेती का क्षेत्रफल ०.९ प्रतिशत अर्थात् ६,२६,००० एकड़ और उत्पादन १.६ प्रतिशत अर्थात् ३,८५,००० टन बढ़ा।

इस प्राक्कलन में १९५६-५७ की धान की खेती का समस्त क्षेत्रफल नहीं आता। पिछला अनुभव यह है कि पहले प्राक्कलन में कुल क्षेत्रफल का प्रायः ९५ प्रतिशत

कृषि का क्षेत्र (हजार एकड)

	१९५६-५७ प्र० प्राक्कलन	१९५५-५६ संशोधित प्र० प्राक्कलन	कालम (३) की अपेक्षा कालम (२) में वृद्धि (+) कुल	प्रतिशत
खरीफ की फसलें (चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, और अन्य छोटे अनाज)	१,४०,०७०	१,३९,८०२	(+) २६८	(+) ०.२
रबी की फसलें (गेहूं और जौ)	३८,७७२	३६,०१५	(+) २,७५७	(+) ७.७
कुल	१,७८,८४२	१,७५,८१७	(+) ३,०२५	(+) १.७

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

क्षेत्रफल आ जाता है।

कपास के उत्पादन में आत्म निर्भरता

भारत विश्व के किसी भी देश से सर्वाधिक वस्त्र निर्यात करता है। लेकिन अभी इस उद्योग की और उन्नति होनी है। इस क्षेत्र में अच्छी किस्म की रेशों वाली रुई की कमी मुख्य बाधा है, क्योंकि देश के विभाजन के बाद अच्छी कपास के क्षेत्र पाकिस्तान के पास चले गये।

उत्तम श्रेणी के कपड़ों के निर्माण के लिए आवश्यक विशेष बड़े रेशे की रुई के क्षेत्र में लगभग ६ लाख गांठ रुई बाहर से मंगायी जा रही है, क्योंकि इस आवश्यकता की पूर्ति अपने देश के उत्पादन से नहीं हो पाती है। ऐसी विशेष लम्बे रेशे की कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए देश के विभिन्न भागों में प्रयत्न किये जा रहे हैं। पंजाब, गुजरात, सूरत; मैसूर, मद्रास राज्य के दक्षिणी तथा पश्चिमी तट के क्षेत्र लम्बे रेशे की कपास की खेती के लिए विशेष उपयुक्त सिद्ध हुए हैं।

भारतीय केन्द्रीय कपास-समिति द्वारा प्रकाशित एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कपास उत्पादन सम्बन्धी शोध कार्य में उल्लेखनीय सफलता मिली है और आशा की जाती है कि अगले दो या तीन वर्षों में लम्बे रेशे की रुई के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो जायगा और इस प्रकार प्रति वर्ष लगभग २९ करोड़ रु० की बचत होगी। मध्यम श्रेणी तथा साधारण लम्बे रेशे की कपास के क्षेत्र में तो भारत आत्म निर्भर है ही।

भारत विश्व का प्रमुख वस्त्र नियांतक हैं, परन्तु देश के विभाजन के बाद से कपास की कमी मालूम होती रही है। लम्बे रेशों वाली अच्छी कपास के क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए इस कमी को दूर करने के लिए खेतिहरों की लगन और उत्साह के फलस्वरूप कपास के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो चुका है।

आगरा नहर की क्षमता में वृद्धि

उत्तर प्रदेश के आगरा तथा मथुरा जिलों और पंजाब के गुड़गांव जिले की कुल ५०,००० एकड़ अतिरिक्त कृषि में सिंचाई की व्यवस्था करने के सन् १८७४ में निर्मित आगरा नहर की क्षमता २,००० से बढ़ाकर ३,२५० क्यूजेक्स की जा रही है।

लगभग ५४ लाख रुपये की लागत की इस योजना के अधीन ओखला हेड वर्क्स में आधुनिक ढंग के फाटक लगाये जा रहे हैं और चिनाई के कार्य का पुनर्निर्माण हो रहा है। हिन्डन जल प्रणाली की, जो हिन्डन और गंगा के पानी को यमुना में पहुँचाती है और जहां से आगरा नहर निकलती है, क्षमता १,२०० [illegible] १,८०० क्यूजेक्स कर दी गयी है। इस योजना का कार्य प्रायः समाप्ति पर है।

सोने की खान-तम्बाकू

तम्बाकू का महत्व सारे देश के लिए और विशेषतया इसके उत्पादकों के लिए है। यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है और इससे हमें पर्याप्त विदेशी मुद्रा मिलती है।

"तम्बाकू सोने की खान है" सरकार को उत्पादन-शुल्क का अधिक भाग तम्बाकू से प्राप्त होता है। पिछले साल तम्बाकू के उत्पादन-शुल्क के रूप में ३५ करोड़ ६० लाख रुपए की प्राप्ति हुई थी। उत्पादकों को भी इससे औसतन प्रतिवर्ष ३२ करोड़ ४० लाख रुपये की प्राप्ति होती है। इस उद्योग के कारण हजारों लोग रोजगार से लगे हैं। इसलिए आयोजन आयोग ने दूसरी पंचवर्षीय आयोजना में तम्बाकू को उचित स्थान दिया है।

रूस २०००० टन तम्बाकू भारत से इस वर्ष लेगा, ऐसी आशा की जा रही है।

—१९५६ में अनुमानतः चाय ६५५०लाख पौण्ड पैदा होगी।

खाद्यान्न का स्थायी भंडार

भारत का लक्ष्य २० लाख टन खाद्यान्न का स्थायी भंडार बनाना है। इसलिए खाद्यान्न को संग्रह करने और सुरक्षित रूप से रखने के लिए देश भर में महत्वपूर्ण स्थानों पर गोदाम बनाने की योजना बनायी गयी है। इन गोदामों का निर्माण वैज्ञानिक ढंग से किया जायगा। २ लाख १० हजार टन खाद्यान्न संग्रह करने के लिए गोदाम बनाये जा चुके हैं और इस्तेमाल में आ रहे हैं। इनमें से अधिकतर बम्बई और कलकत्ते में हैं।

बम्बई, मद्रास, मध्य भारत, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

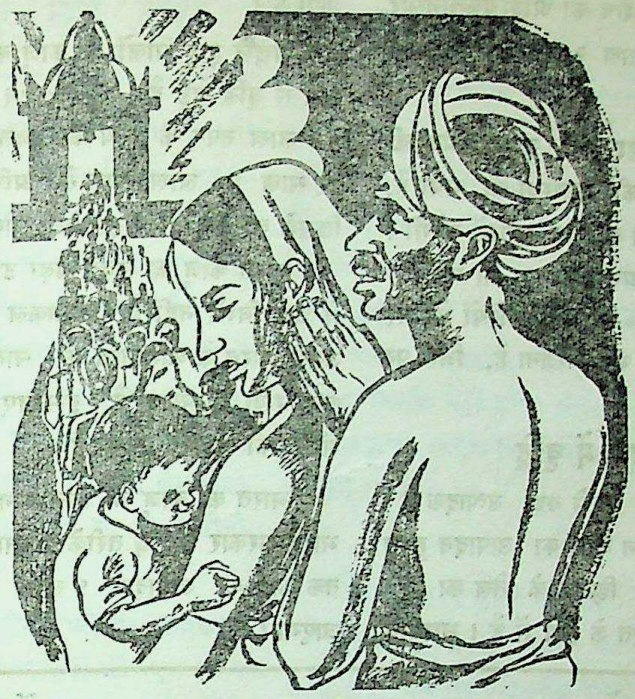

ईश्वर के सम्मुख सब बराबर . . .

"मंदिर में प्रवेश करना आध्यात्मिक क्रिया है जो अछूतों को स्वतंत्रता का सन्देश देगी और उन्हें विश्वास दिलाएगी कि वे परमात्मा के सम्मुख जातिभ्रष्ट नहीं हैं।"

महात्मा गांधी

भारतीय संविधान ने अस्पृश्यता का उन्मूलन कर सब व्यक्तियों को नागरिक और सामाजिक अधिकार समान दिए हैं।

कोई भी व्यक्ति किसी को सार्वजनिक पूजा के स्थान में जो कि उसी धर्म के अनुयायी अन्य व्यक्तियों के लिए खुले हैं, प्रवेश करने से मना नहीं कर सकता। अथवा वह सार्वजनिक पूजा के स्थान पर पूजा करने, प्रार्थना करने, या कोई अन्य धार्मिक सेवा के कार्य करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अधिकार एक ही धर्म के सब अनुयायियों के लिए समान हैं।

छूत छात को छोड़ो—दिल को दिल से जोड़ो

DA-56/208

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उत्तर प्रदेश, हैदराबाद और तिरुवांकुर-कोचीन राज्यों में १ लाख टन या इससे अधिक अनाज संग्रह किया जायगा। इन राज्यों के भंडारों में प्रदेश विशेष की आवश्यकतानुसार १५ हजार टन से लेकर १ लाख २५ हजार टन तक अनाज संग्रह किया जा सकेगा।

देश की सबसे बड़ी मंडी हापुड़ में उत्पादक-प्रणाली का एक आधुनिक भंडार बनाने की व्यवस्था की गयी है, जिसमें अनाज उठाने और तोलने का काम मशीनें करेंगी। इस भंडार में १० हजार टन अनाज रखा जा सकेगा। इसके अलावा, वहां पर १५,००० टन गेहूं बोरियों में भर कर रखने के गोदाम बनाने की भी योजना है, जिस पर शीघ्र ही काम शुरु हो जाएगा।

काजू के उत्पादन में वृद्धि

भारत संसार में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है। चालू साल में यहां ८०,४५० टन काजू का उत्पादन हुआ है। काजू की गिरी और इसके छिलके के तेल का ९० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार भारत के हाथ में है। भारतीय काजू के सबसे बड़े खरीदार अमेरिका और ब्रिटेन हैं। लगभग ७५ प्रतिशत भारतीय काजू इन्हीं देशों को जाता है।

पिछले कुछ सालों में काजू की गिरी के उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है। १९५५-५६ में भारत ने १२ करोड़ ९२ लाख रुपए के मूल्य की काजू की गिरी निर्यात की। हर साल ६० लाख रुपए से अधिक कीमत का काजू के छिलके का तेल भी बाहर भेजा जाता है।

भारत काजू का सबसे बड़ा उत्पादक होने पर भी इस में आत्मनिर्भर नहीं है। आजकल जो उत्पादन हो रहा है उससे भारत के कारखानों को साल में ८-१० महीने ही चालू रखा जा सकता है, इसलिए पूर्वी अफ्रीका से काजू मंगाने की जरूरत पड़ती है।

भारत को काजू का आयात न करना पड़े, इसके लिए भारत सरकार ने कुछ तरीके अपनाए हैं, जिनसे १९६०-६१ तक काजू का उत्पादन १ लाख ६ हजार टन तक पहुँच जाएगा।

हिन्दी और मराठी भाषा में प्रकाशित होता है

उद्यम

सर्वोपयोगी हिन्दी उद्यम प्रतिमाह १५ तारीख को पढ़िये

धर्मपेठ, नागपुर

उद्यम में निम्न विषयों पर लेख प्रकाशित होते हैं

★ लाभदायक उद्योगधन्धों की व्यावहारोपयोगी जानकारी, अनाज की खेती, साग-सब्जी की बागवानी और रोगों का निवारण। पशुपालन, दुग्ध-व्यवसाय और ग्रामोद्योग-सम्बन्धी लेख। आरोग्य, घरेलू औषधियों सम्बन्धी जानकारी।

उद्यम के स्थायी स्तम्भ

★ महिलाओं तथा विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त विभिन्न रुचिकर खाद्य पदार्थ बनाने की विधियां। घरेलू मितव्ययता। जिज्ञासु जगत्। कृषि व औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों की मुलाकात और परिचय। नित्योपगी वस्तुएं घर पर ही तैयार कीजिये।

आज ही उद्यम का वार्षिक चन्दा ७ रु० भेजकर उद्यम मासिक मंगवाइये।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मशीनी औजारों का दस गुना उत्पादन

मशीनी औजार उद्योग एक आधारभूत उद्योग है और देश की औद्योगिक प्रगति के लिए इसका विकास अत्यावश्यक है। यदि इसका विकास न किया गया तो हमें विदेशों से किये जाने वाले आयात पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो कि हमारे आर्थिक विकास के लिए हानिकारक है।

बम्बई में मशीनी औजार विकास परिषद् की पहली बैठक का उद्घाटन करते हुए, भारी उद्योग मंत्री श्री मनुभाई शाह ने कहा था कि दूसरी आयोजना के अन्त तक मशीनी औजारों का उत्पादन दस गुना बढ़ जाने की आशा है। इस समय देश में प्रतिवर्ष १ करोड़ रु० के मशीनी औजार बनते हैं।

बंगलौर का हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखाना काफी बढ़ाया जा रहा है और हैदराबाद में भी एक अन्य सरकारी कारखाने, प्राग टूल्स, को बढ़ाने का प्रस्ताव है। इन दोनों कारखानों और अम्बरनाथ के सरकारी कारखाने में १९६०-६१ तक ५ करोड़ रु० के मशीनी औजार बनने लगेंगे।

निजी क्षेत्र के वर्तमान ६ कारखानों का विकास किया जाएगा और भविष्य में कुछ और भी कारखाने खोले जाएंगे। इस प्रकार आशा है कि देश में १९६०-६१ तक कुल १० करोड़ रु० के मूल्य के मशीनी औजार बनने लगेंगे।

अगले पांच वर्षों में लगभग १,७०,००० मशीनी औजारों की आवश्यकता पड़ेगी। देश में इस्पात की खपत के अनुमान से ही मशीनी औजारों की आवश्यकता का अनुमान लगाया जा सकता है। इस्पात की खपत २० लाख टन से बढ़कर ४५ लाख टन प्रतिवर्ष होते ही मशीनी औजारों की खपत भी दूनी हो जाएगी।

यदि आयोजना के अन्त तक हम हर प्रकार के मशीनी औजार तैयार न कर सके, तो भी हमें अपनी वार्षिक आवश्यकता का ७५ प्रतिशत तो तैयार करना ही चाहिए। इसका अर्थ यह है कि देश में १९६०-६१ तक प्रतिवर्ष १० करोड़ रु० के मशीनी औजार बनने चाहिएं।

यों तो देश में पिछले ३० वर्षों से मशीनी औजार के निर्माण का काम हो रहा है, परन्तु देश की जरूरत को देखते हुए, इसमें कोई प्रगति नहीं हुई। हमारे देश में अभी अन्य प्रगतिशील देशों की तरह शिल्प-विज्ञान में अधिक उन्नति नहीं हुई। अतः मशीनी औजार के निर्माण में फिलहाल प्रगतिशील देशों की सहायता ली जानी चाहिए।

मैंगनीज उद्योग के सामने नयी समस्या

दुनिया में सबसे अधिक मैंगनीज भारत में पाया जाता है। भारतीय मैंगनीज अच्छी किस्म का होता है। विदेशों में इसकी मांग भी काफी रहती है। अमेरिका और कनाडा इसके मुख्य आयात करने वाले हैं इस कारण भारत को प्रतिवर्ष इससे अच्छी आय होती है। १९५४-५५ में ९ लाख ९० हजार टन मैंगनीज बाहर भेजा गया। इससे १२ करोड़ ९२ लाख रुपए की आय हुई। १९५५-५६ में भी १० करोड़ ७२ लाख रुपए का ९ लाख २१ हजार टन मेगनीज भेजा गया, परन्तु इस उद्योग को अब एक नयी समस्या का संभवतः बहुत शीघ्र सामना करना पड़ेगा।

इधर कनाडा और ब्राजिल में बिल्कुल ही नये प्रकार से मैंगनीज के उत्पादन का प्रयत्न किया जा रहा है। इसमें सफलता मिलने पर भारत के मैंगनीज व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है। घटिया प्रकार के मैंगनीज को ही नवीन रीति के अनुसार अच्छे मैंगनीज के रूप में परिणत किया जाएगा। यह रीति काफी कम खर्चीली होगी और इससे प्रतिदिन ५०००९६ टन कच्चा मैंगनीज लिया जाएगा और प्रतिवर्ष १॥ लाख टन अच्छा मैंगनीज तैयार किया जाएगा। इसमें ७५ हजार टन घटिया किस्म का इस्पात भी होगा।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अभी इसका परीक्षण जारी है। सफलता मिलने पर और इसका विस्तार करने पर समस्त उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप मैंगनीज में आत्मनिर्भर हो जाएगा। घटिया किस्म का मैंगनीज इस महाद्वीप मे पर्याप्त मिल जाता है जिसको अभी तक अनुपयुक्त समझा जाता रहा है।

इसी प्रकार के प्रयत्न ब्राजिल में भी हो रहे हैं। इसमें अमेरिका भी पूरा सहयोग दे रहा है। यहां ४५ प्रतिशत तक शुद्ध मैंगनीज मिलता है। और ११० लाख टन मैंगनीज यहां की खानों में सुरक्षित है। इसके विकास के लिए प्रयत्न हो रहे हैं। योजना के पूर्ण होने पर ७ लाख टन मैंगनीज का वार्षिक उत्पादन होने लगेगा।

निस्सन्देह यदि दोनों योजनाएं पूर्ण हो गईं, तो भारत के निर्यात को गहरा धक्का लगेगा। कनाडा और अमेरिका के इस्पात निर्माता इस समय तक बड़ी मात्रा में भारत से मैंगनीज का आयात कर रहे हैं। पर तब संभव है कि वे इतनी बड़ी मात्रा में हमारे मैंगनीज का आयात न करें। फलतः हमारे विदेशी विनिमय के लिए डालरों में कमी हो जाएगी। अकेले अमेरिका हमारे मैंगनीज का १३ प्रतिशत आयात करता है। १९५६ के वित्तीय वर्ष में अमेरिका ने ३,२१,४६८ टन मैंगनीज का आयात किया, जिसका मूल्य ४.०६ करोड़ रुपया था। इस वर्ष कुल निर्यात ९,२०,८४७ टन हुआ और इसका मूल्य १०.७२ करोड़ रुपए था।

★

अमोनियम सल्फेट का उत्पादन

१९५६ में सिंदरी उर्वरक और रसायन कारखाने में अमोनियम सल्फेट का उत्पादन अपने लक्ष्य से १,७२५ टन अधिक हुआ। प्रतिदिन का औसत उत्पादन ९०६ टन रहा; इतना उत्पादन पहले कभी नहीं हुआ। इस वर्ष ३,७४,००० टन अमोनियम सल्फेट की निकासी हुई। यह भी अब तक की निकासी में सबसे अधिक था।

★

हिन्दुस्तान जहाजी कारखाने के कार्य में प्रगति

हिन्दुस्तान शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड के कारखाने का सबसे बड़ा जहाज 'स्टेट आफ कच्छ' अप्रेल १९५६ में बनकर तैयार हुआ। इसके अलावा, तीन जहाजों का निर्माण इस वर्ष शुरू हुआ है।

पिछले साल जो तीन जहाज पानी में उतारे गये, उनमें एक यात्री और माल जहाज 'अंडमान' भी था। इसमें केबिन के ६६ और डेक के ५५० यात्रियों की जगह है। इसमें सुरक्षा का सब आधुनिक इन्तजाम हैं। यह जहाज गतमास खरीदार कम्पनी को सौंप दिया जाने वाला था।

★

रेशम के कीड़े पालने की शिक्षा

रेशम के कीड़े पालने के काम को बढ़ाने और उसे लोकप्रिय बनाने की एक योजना के लिए केन्द्रीय उत्पादन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को चालू वित्तीय वर्ष के लिए ३०,२४० रु० का अनुदान मंजूर किया है। यह उद्योग, देहरादून घाटी का एक महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है। इस योजना के अंतर्गत देहरादून जिले के प्राथमिक स्कूलों के विद्यार्थियों को शहतूत के पौधों पर रेशम के कीड़े पालने का काम सिखाया जाएगा। इस योजना पर कुल जो खर्च होगा, उसका आधा भारत सरकार ने इस अनुदान के रूप में दिया है। शुरू में प्रशिक्षण का यह कार्यक्रम दस केन्द्रों में चलाया जाएगा।

★

नये उद्योग-क़ानून

१ मार्च, १९५७ से १९५६ का उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम लागू हो गया है। यह अधिनियम पिछले साल नवम्बर में संसद ने पास किया था। इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप बहुत से नये उद्योग भी १९५१ के उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम की परिधि में आ जाते हैं। औद्योगिक संस्थाओं में बिजली से काम होता है और उनमें ५० या अधिक कर्मचारी काम करते हैं, या बिना बिजली से काम करने वाली जिन संस्थाओं में १०० या अधिक कर्मचारी काम करते हैं, वे सब उद्योग अधिनियम की परिधि में आ जाते हैं।

—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मरुस्थल से शस्यश्यामल

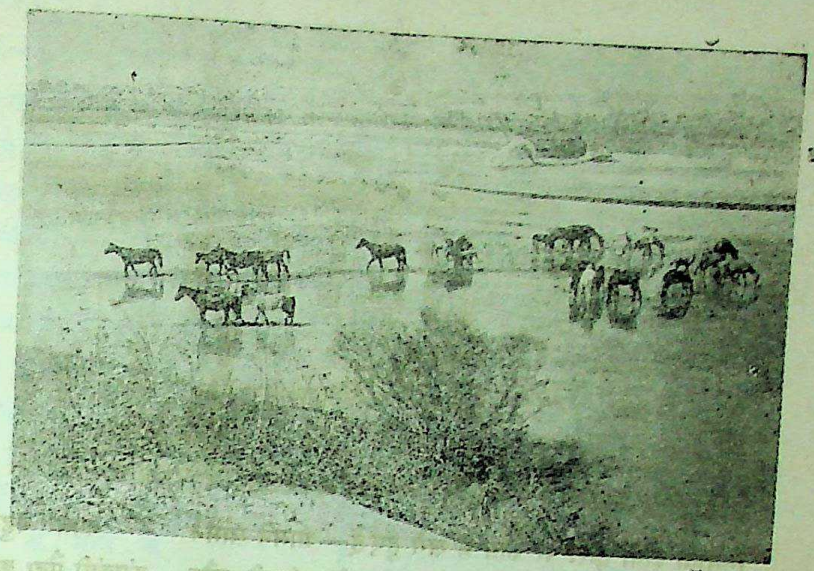

जल का उद्भव हुआ है और रेगिस्तान में जीवन आ गया

निश्चित योजना बनाकर किसी देश का कायापलट कैसे किया जा सकता है, रेगिस्तान को, जहां पानी की बूंद भी नहीं, शस्यशामला कैसे बनाया जा सकता है, इसका एक उदाहरण तुर्कमेनियामें योजनापूर्वक राष्ट्रव्यापी आर्थिक विकासमें नेतृत्व करने वाले रूस द्वारा किया गया कायाकल्प है।

ऊपर के चित्र में आप जो गहरी नदी देखते हैं, वह मानव-कृत है। यह उस जगह खोदी गयी है जहां अभी हाल तक पानी जैसी मामूली चीज या तो मशकों में लाई जाती थी या पीपों में। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां पानी "हीरे से भ अधिक कीमती" था।

सोवियत तुर्कमेनिया को धूप खूब मिलती है और इसकी जमीन उपजाऊ है। यहां की धरती को कपास के खेतों, बागीचों और अंगूर के उद्यानों में परिवर्तित करने में एक ही रुकावट थी और वह थी पानी की कमी।

सोवियत जनता ने इस विस्तृत ऊसर को काम में लाने का निश्चय किया। इस समय तुर्कमेनिया में कराकुम नहर बन रही है। मध्य एशिया की सबसे बड़ी नदी आमू दरिया से पानी लेकर यह नहर रेगिस्तान के आर-पार तक जायगी। कराकुम नहर की लम्बाई १,००० किलोमीटर होगी। यह दुनियां की अनेक बृहत्तम नहरों से बड़ी होगी। इससे ४,५०००० हेक्टर अछूती धरती की सिंचाई हो सकेगी। योजना यह है कि इससे १० लाख हेक्टर से अधिक भूमि की सिंचाई हो जाय और ५० लाख हेक्टर चरागाहों को पानी पहुँचाया जाय।

कपास उगाने वाला तथा फलों और अंगूरोंके उद्यानों से सम्बन्धित बड़ी बड़ी राज्य कृषिशालाएं और कपास ओटने वाले कारखाने नहर के इलाके में जन्म लेंगे।

नहर के प्रारम्भिक ४०० किलोमीटर भाग का निर्माण इस समय हो रहा है। यह भाग १९५८ तक बन चुकेगा।

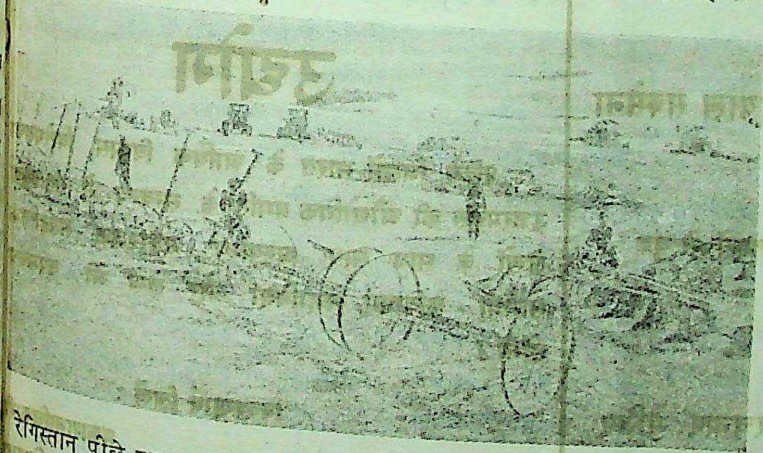

रेगिस्तान पीछे हट रहा है। और जहां सिर्फ एक या दो साल पहले ऊंटों का कारवां ही कभी-कभी देखने को मिलता था, वहां आज मशीन और ट्रैक्टर स्टेशन सिंची हुई धरती पर पहली बसन्त बुवाई की तैयारी कर रहे हैं।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

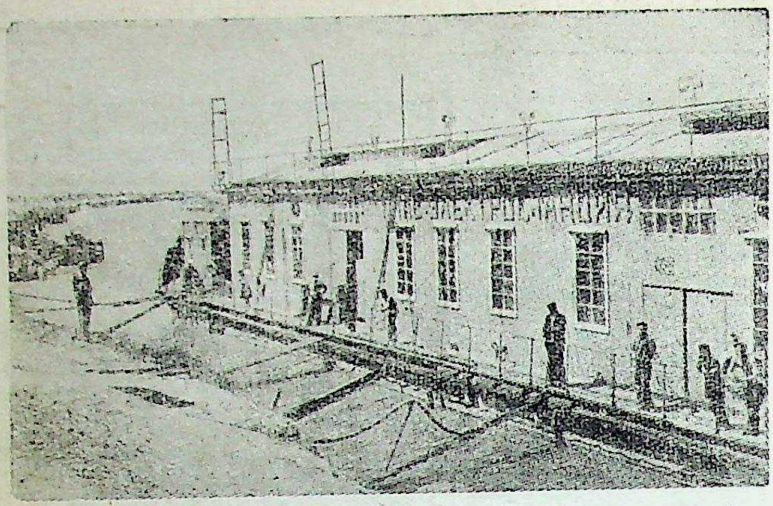

नहर के ऊपर, इस अप्राकृ
नदी के ऊपर तिरते हुए विद्यु
स्टेशन हो गये हैं जो घरों
को बिजली और मोटरों
को विद्युत् शक्ति पहुं-
चाते हैं।

निर्माता दोनों छोरों पर काम में लगे हुए हैं—आमने सामने से काम करते हुए बढ़ रहे हैं। सक्शन ड्रेज (पानी और कीचड़ खींचने वाले यंत्र) आमू दरिया में अपना जलीय मार्ग बना रहे है। उधर शक्तिशाली एक्सकैवेटर मुर्गाव मुर्गाव नखलिस्तान में कार्यरत हैं। यहां नहर का पहला भाग समाप्त होता है।

काम बहुत कठिन है। झुलसाने वाली गर्मी कंपकंपी पैदा करने वाले जाड़े का तो कहना ही क्या, के साथ आसानी से एक जगह जाने वाली बालू उनका रास्ता रोकते हैं। परन्तु आधुनिक साज-सामा लैस और अध्यवसायी निर्माता प्रकृति से सफल संग्राम कर रहे हैं।

सरकारी विज्ञापनों के लिए स्वीकृत
राजस्थान शिक्षा विभाग से मंजूरशुदा

सेनानी साप्ताहिक

सम्पादक :—

सुप्रसिद्ध साहित्य सेवी श्री शंभुदयाल सक्सेना

कुछ विशेषताएं—

★ ठोस विचारों और विश्वस्त समाचारों से युक्त
★ प्रान्त का सजग प्रहरी
★ सर्वाधिक लोकप्रिय पत्र

ग्राहक बनिए, विज्ञापन दीजिए, रचनाएं भेजिए
नमूने की प्रति के लिए लिखिए—

व्यवस्थापक, साप्ताहिक सेनानी, बीकानेर

उद्योग विभाग, उत्तरप्रदेशीय सर
द्वारा प्रकाशित
सचित्र मासिक पत्र

उद्योग

पढ़िये, जिसमें भारत के आर्थिक विकास, विशे
उत्तरप्रदेश की औद्योगिक प्रगति के सम्बन्ध में मह
लेखों के साथ साथ अन्यान्य मनोरंजक सा
सामग्री – कविताएं, कहानियां और लेख भी
होंगी।

विवरणार्थ लिखें :
प्रकाशन
उद्योग
उत्तरप्रदेश—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

स्वेज नहर का आर्थिक महत्त्व

यद्यपि स्वेज नहर की सफाई हो रही है, तथापि अभी तक राजनैतिक घटना चक्र जिस गति से चल रहा है, उसे देखते हुए यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कब तक स्वेज नहर सामान्य रूप में पहुँच जायेगी और यातायात के लिए सुलभ हो जायगी। स्वेज नहर का विश्व के व्यापार में कितना महत्वपूर्ण स्थान है, यह निम्नलिखित अंकों से स्पष्ट होगा। १९५५ में परिमाण और मूल्य की दृष्टि से स्वेज नहर के मार्ग से निम्नलिखित व्यापार हुआ था।

(लाख मैट्रिक टनों में)

	कुल जहाज	कुल	स्वेज के मार्ग से उत्तर को,	दक्षिण को
विविध पदार्थों के जहाज	४३००	३८७	२०५	१८२
तेल के टैंकर	३६००	६८८	६६९	१९
बड़ी झीलों के जहाज	२८०			
कुल योग	८१८०	१०७५	८७४	२०१

मूल्य की दृष्टि से यह व्यापार ११०० करोड़ डालर का हुआ, जबकि रूस, पूर्वी यूरोप और चीन को छोड़कर संसार का कुल व्यापार ८२५० करोड़ डालर का हुआ था। विभिन्न देशों की दृष्टि से स्वेज मार्ग कितना महत्वपूर्ण है यह निम्नलिखित अंकों से प्रकट होता है।

(लाख डालरों में)

	निर्यात		आयात	
	कुल मूल्य	स्वेज के मार्ग से प्रतिशत	कुल मूल्य	स्वेज के मार्ग से प्रतिशत
आस्ट्रेलिया	१८०००	६०	१९४००	६०
न्यूजीलैंड	७२००	८५	७०००	६५
भारत	१२८००	५०	१३६००	५५
इन्डोनेशिया	९३००	३५	६०००	४५
पाकिस्तान	४०००	५०	२९००	५५
सं० रा० अमेरिका	१५५०००	३	१.१४०००	५
फ्रांस	४८०००	१०	४७०००	२०
ग्रेट ब्रिटेन	८५०००	३०	१.१००००	३०

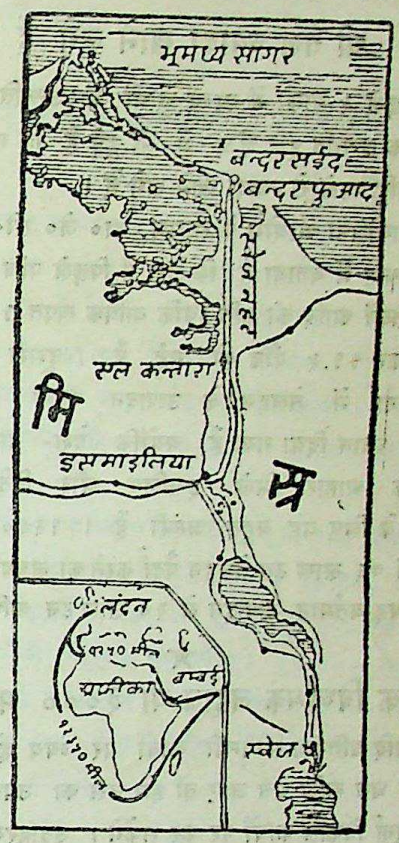

स्वेज नहर

स्वेज नहर के कारण सूखे माल के समुद्री मार्ग में १० प्रतिशत तथा टैंकरों के लिये ३० प्रतिशत मीलों की लम्बाई कम हो जाती है।

सफ़ेद कोढ़ के दाग

हजारों के नष्ट हुए और सैकड़ों के प्रशंसापत्र मिल चुके

दवा का मूल्य ५) रु० डाक व्यय १) रु०

अधिक विवरण मुफ्त मँगाकर देखिये।

वैद्य के० आर० बोरकर

मु० पो० मंगरूलपीर, जिला अकोला (मध्य प्रदेश)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अर्थ वृत्त चयन

घी तेल ज्यादा खाने लगे हैं

पिछले ५ सालों में अन्य क्षेत्रों में उन्नति के साथ साथ एक उन्नति इस क्षेत्र में भी हुई है कि हम घी व तेल आदि पहले से ज्यादा खाने लगे हैं।

आयोजना आयोग के सदस्य, डा० जे० सी० घोष ने एक भाषण में बताया है कि देश में पिछले पांच सालों में घी व तेलों आदि की प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत १०.५ पौंड से बढ़कर ११.५ पौंड हो गई है। दूसरी पंचवर्षीय आयोजना में तेलहन के उत्पादन बढ़ाने की ओर विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि देश- वासियों को पौष्टिक आहार मिले, इसलिए और विदेशी मुद्रा कमाने के लिए यह बहुत जरूरी है। १९६०-६१ तक देश में ७६ लाख टन तेलहन पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह वर्तमान उत्पादन से २० लाख टन अधिक है।

★

एक विध्वंसक जहाज या ३००० मकान

यदि प्रतिरक्षा सम्बन्धी कार्यों पर व्यय होने वाली विशाल धन राशि बच जाए तो हम उस का उपयोग अन्य शान्तिपूर्ण विकास-कार्यों पर कर सकेंगे। उदाहरणार्थ, एक विध्वंसक जहाज के निर्माण पर जितनी धनराशि व्यय होती है, उससे अमेरिका में ३ हजार परिवारों के रहने के लिए १० हजार डालर मूल्य वाले घरों का निर्माण किया जा सकता है। आजकल एक बम-वर्षक हवाई जहाज पर जो धनराशि व्यय होती है उस से १ लाख २५ हजार जन संख्या वाले नगर के लिए हर प्रकार की अस्पताली सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं। इसी प्रकार के और न जाने कितने उदाहरण दिए जा सकते हैं।

★

जहाज अणुशक्ति से चलेंगे

अमेरिकी अणुशक्ति-कमीशन ने अणुशक्ति-चालित बढ़िया किस्म के तेल वाहक जहाज को तैयार कराने का काम शुरू कर दिया है।

कमीशन ने फोर्ड इन्स्टमैण्ड कम्पनी को उक्त योजना सम्बन्धी "उचित अध्ययन" करने के लिए ठेका दे दिया है। इस योजना के फलस्वरूप १९६१ तक ३८ हजार टन का एक अणुशक्ति-चालित उत्कृष्ट तेल-वाहक जहाज तैयार कर तैयार हो जाएगा।

७०७ फुट लम्बा प्रस्तावित तेलवाहक जहाज अमेरिका का दूसरा अणुशक्ति चालित समुद्री जहाज होगा।

★

शहरों में आबादी बढ़ रही है

पिछले बीस वर्षों में शहरी क्षेत्र की आबादी गांवों के मुकाबले बहुत बहुत अधिक तेजी से बढ़ी है। १९४१ में शहरी इलाके की जनसंख्या देश की कुल आबादी का १३.८ प्रतिशत थी, परन्तु १९५१ में वह १७.४ प्रतिशत हो गई थी, इससे यह स्पष्ट है कि पहले की अपेक्षा देश की जनसंख्या का अधिकाधिक भाग शहरों में रहने लगा है। बड़े शहरों की आबादी तो इन दस वर्षों में और भी तेजी से बढ़ी है। वृहत्तर बम्बई की जनसंख्या में इन वर्षों में ६७ प्रतिशत, मद्रास में ८२ प्रतिशत तथा वृहत्तर दिल्ली में १०७ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। शहरी क्षेत्र में आबादी जन्मदर और मृत्युदर के अन्तर के मुकाबले बहुत अधिक बढ़ी है। वृहत्तर दिल्ली नगर में १९४१ से ५० तक आबादी १०० प्रतिशत बढ़ी। परन्तु इसी समय के भीतर जन्मदर और मृत्युदर-अन्तर केवल २४ प्रतिशत रहा। इससे स्पष्ट है कि जनसंख्या में वृद्धि प्राकृतिक रूप से बहुत ही कम हुई, अधिकतर वृद्धि दूसरे इलाकों से लोगों के दिल्ली शहर में आने के कारण ही हुई है। वृहत्तर दिल्ली शहर में इन दिनों बहुत से व्यक्ति गांवों या छोटे शहरों से आए हैं। ग्रामीण इलाकों व कस्बों से लोगों के शहरों में अधिक तादाद में आने के क्रम को शहरीकरण भी कहते हैं।

★

जूतों पर खर्च

अप्रैल-जून १९५१ में नमूने के तौर पर जो राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण दूसरी बार किया गया था उससे पता चलता है कि देश के विभिन्न भागों में देहातों में जूतों पर किये जाने

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वाले खर्च में बड़ा अन्तर होता है। यह तथ्य नीचे की सारणी से प्रकट होता है ;—

देहातों का उपभोग व्यय—अप्रैल-जून १९५१ में

	जूतों पर ९० दिनों में होने वाला उपभोग व्यय	प्रति घर के कुल उपभोग व्यय का प्र. श.	प्रति घर का कुल उपभोग व्यय
	प्रति परिवार	प्रति व्यक्ति	
	रु०	रु०	रु०	रु०
सारे भारत में	२.३९	०.४५	०.६१	३९०.८१
उत्तर भारत				
यू० पी०	२.३२	०.४३	०.५६	४१७.१२
उत्तरी पश्चिमी भारत में	९.४९	१.६३	१.५८	६६१.८३
पूर्वी भारत	०.८८	०.१७	०.२६	३५६.३१
दक्षिण भारत	०.५४	०.११	०.१७	३३३.३७
पश्चिमी भारत	२.७५	०.७०	०.९२	४०५.००
केन्द्रीय भारत	२.७२	०.५४	०.७४	३६७.२७

★

भारत में सड़कों का विकास

१. नागपुर सड़क योजना के अन्तर्गत भारत में कुल ३,३१,००० मील लम्बी सड़कें बनेंगी।

२. पहली पंचवर्षीय आयोजना से पहले देश में सड़कों की कुल लम्बाई २,४८,५०९ मील थी और आयोजना के अन्त में यह ३,१६,६६८ मील हो गयी।

३. पहली आयोजना में सामुदायिक विकास योजना और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के अन्तर्गत कुल ४४,२५९ मील लम्बी सड़कें बनायी गयीं।

४. पहली आयोजना में राष्ट्रीय सड़कों पर ३० और अन्य सड़कों पर ३ विशाल पुल बनाये गये। ४२ पुल पहली आयोजना में आरम्भ किये गये, जो दूसरी आयोजना में पूरे हो जाएंगे। और साथ ही ७२ विशाल पुलों का निर्माण आरम्भ किया जाएगा।

५. दूसरी आयोजना में राष्ट्रीय सड़कें बनाने के लिए २५ करोड़ रु० की व्यवस्था है। इससे दो सड़कों को जोड़ने वाली (२०० मील लम्बी) सड़कें बनायी जाएंगी, ११४ बड़े पुलों का निर्माण किया जाएगा और ४००० मील लम्बी सड़कों का सुधार किया जाएगा।

★

स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन द्वारा सीमेण्ट का आयात

पिछले कुछ समय से देश में सीमेण्ट की मांग उत्पादन से कहीं अधिक रही है। १ जुलाई १९५६ से सीमेण्ट का व्यापार सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और देसी सीमेण्ट के वितरण तथा विदेशों से सीमेण्ट मंगाने और उसके वितरण का काम स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया (प्राइवेट) लि० नामक सरकारी कम्पनी को सौंपा गया।

कारपोरेशन के प्रयत्न से जनवरी १९५७ के अन्त तक विदेशों से एक लाख टन से भी अधिक सीमेण्ट आयात किया गया। इसमें से ४६,००० टन बम्बई और ३४,००० टन कलकत्ते के बन्दरगाह पर पहुँचा। २४,००० टन वागा अतरी मार्ग से पाकिस्तान से मंगाया गया। अगस्त १९५७ तक १ लाख टन और सीमेण्ट विदेशों से आने की आशा है।

★

समाजवाद की ओर शनैः शनैः

भारतवर्ष के कम्युनिस्ट प्रायः यह मांग करते हैं कि सब उद्योगों को सरकार अपने हाथ में ले ले और उसके लिए कोई मुआवजा देने की जरूरत नहीं, किन्तु चीन की सरकार किस तरह शनैः शनैः समाजवाद की ओर चल रही है यह श्री चेन श्यू. तुंगी के वक्तव्य से प्रकट हो जाता है, श्री तुंग उस सम्मेलन के प्रधान थे जो पेकिंग में गत १० दिसम्बर को चीन सरकार ने पूंजीपतियों, उद्योगपतियों व व्यापारियों का बुलाया था और जिसमें १४०० प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे। उन्होंने बताया कि १९५३ में देश में निजी कारोबार को राज्य तथा उद्योगपतियों के कारोबार में परिणत करने का प्रयत्न किया गया था। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि—"निजी कारोबार को राष्ट्र तथा पूंजीपतियों का साझा

[शेष पृष्ठ १७६ पर]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सहकारिता और.....

[पृष्ठ १४२ का शेष]

करते हैं, उनमें १. पूल २. कार्टेल और ट्रस्ट मुख्य हैं। इन औद्योगिक सहयोगिताओं में उत्पादित वस्तुओं के मूल्य तथा मात्रा के निर्धारण से लेकर विभिन्न फर्मों के एकाकार हो जाने तक कई उद्देश्य मूलक भेद हैं।

(१) फूल—इस प्रकार की औद्योगिक सहयोगिता में मिलने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों (फर्मों) को अपने व्यवसाय की आन्तरिक व्यवस्था के क्षेत्र में पूर्ण स्वतन्त्रता रहती है। सिर्फ बाजार क्षेत्र के विभाजन, उत्पादन की सीमा और लाभ के वितरण आदि प्रश्नों पर समझौता होता है। इस प्रकार के संघों द्वारा मूल्य और उत्पादन की मात्रा पर प्रभावशाली नियंत्रण हो जाता है। किन्तु इनका सबसे बड़ा दोष यह है कि ये अस्थायी होते हैं और व्यवसाय की आन्तरिक स्वतंत्रता के कारण प्रतिष्ठानों में प्रायः ही विरोध होते रहते हैं।

(२) कार्टेल—'पूल' की भांति कार्टेल में भी औद्योगिक प्रतिष्ठानों को आन्तरिक स्वतंत्रता रहती है। इस प्रकार की सहयोगिता में उत्पादन की मात्रा, उत्पादित वस्तुओं के मूल्य तथा मूल्य-सूची सम्बन्धी समस्याओं पर समझौते होते हैं और विभिन्न प्रतिष्ठान (फार्म) अपनी वस्तुओं के विक्रय का भार एक संयुक्त 'विक्रय संघ' को सौंप देते हैं। इस प्रकार की सहयोगितायें जर्मनी में अधिक पायी जाती हैं, किन्तु वर्तमान काल में अन्य देशों में भी 'कार्टेल' बनने लगे हैं। भारत के 'इन्डियन सुगर सिन्डिकेट' तथा 'सिमेन्ट मार्केटिंग बोर्ड आफ इन्डिया' कार्टेल के भारतीय नमूने हैं।

(३) ट्रस्ट—जब विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठान परस्पर इस प्रकार मिल जाते हैं कि उनका वैयक्तिक अस्तित्व समाप्त हो जाता है और वे मिलकर एक नया प्रतिष्ठान सा बन जाते हैं, तो इस प्रकार की औद्योगिक सहयोगिता को हम अर्थ शास्त्र की शब्द वली में 'ट्रस्ट' कहते हैं। इस प्रकार की औद्योगिक सहयोगिता में मिलने वाले फर्मों की पूंजी एक कर दी जाती है और उन्हें 'ट्रस्ट सार्टिफिकेट' दे दिया जाता है और संयुक्त प्रबन्ध एक ट्रस्ट बोर्ड को सौंप दिया जाता है। जैसे भारतीय 'एसोसियेटेड सिमेन्ट कम्पनीज आफ इन्डिया'।

प्रकार भेद से ये औद्योगिक सहयोगितायें "क्षैतिज" (Horizontal) तथा लम्बमान (Vertical) दो प्रकार की हो सकती हैं।

क्षैतिज सहयोगिता—एक ही प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करने वाले प्रतिष्ठानों की सहयोगिता को हम 'क्षैतिज सहयोगिता' कहते हैं। जैसे १९३६ में भारतवर्ष की तत्कालीन सभी सिमेन्ट कम्पनियां आपस में मिलकर एक हो गईं।

लम्बमान सहयोगिता—एक ही वस्तु के विभिन्न अंगों का उत्पादन करने वाले प्रतिष्ठानों के संघ को 'लम्बमान सहयोगिता' कहा जाता है। इस प्रकार की सहयोगिता का उद्देश्य कच्चे पदार्थों की अवाधित सुलभता तथा

नयापथ

(प्रगतिशील मासिक पत्रिका)

सम्पादक—

यशपाल ❀ शिव वर्मा ❀ राजीव सक्सेना

स्तम्भ—

- चक्कर क्लब
- साहित्य समीक्षा
- संस्कृति प्रवाह
- सिनेमा
- लेख
- कहानियां
- कविताएं।

"नयापथ" का जनवरी अंक 'लोक साहित्य' विशेषांक है। इसका सम्पादन हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक श्री श्रीकृष्णदास कर रहे हैं। ग्राहकों को यह अङ्क साधारण मूल्य में ही दिया जाएगा।

वार्षिक ६) एक प्रति ।।)

पता :—

२२ कैसर बाग लखनऊ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विभिन्न अंगीय उत्पादनों का संगत और संगठित उत्पादन मुख्य है। जैसे टाटा आयरन एन्ड स्टील कम्पनी के स्वामित्व के अंतर्गत कच्चे लोहे और कोयले की खानें हैं, ब्लास्ट फरनेस है और वह स्वयं ही कच्चा लोहा तथा इस्पात का निर्माण करती है।

इन विभिन्न उद्देश्यों और प्रकार की औद्योगिक सहयोगिताओं में एक बात में समता है। इन सभी सहयोगिताओं का मूल उद्देश्य यह है कि पारस्परिक स्पर्द्धा को घटाकर प्रति-स्पर्द्धा जनित विज्ञापनों और अपनी-अपनी वस्तुओं के प्रचार पर किये गये खर्च से बचते हुए बाजार पर अधिक से अधिक शक्तिशाली नियंत्रण स्थापित किया जाय। अर्थतंत्र की यह कितनी विचित्र बात है कि प्रतिस्पर्द्धा की दवा प्रतिस्पर्द्धा से ही तैयार होती है और स्वतः ही।

किन्तु अर्थतंत्र की यह प्रतिस्पर्द्धा जिसकी सहयोगिता और सहकारिता दो रूप हैं। केवल पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था की ही विशेषता है। साम्यवादी अथवा समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में जहां 'सबसे क्षमता के अनुसार कार्य लिया जाता है और आवश्यकतानुसार वस्तुओं का वितरण होता है, 'जहां उत्पादन और वितरण पर राज्य का नियंत्रण तथा अधिकार होता है, वहां राज्य को छोड़कर व्यक्तिगत रूप से वस्तु और सेवाओं का न तो कोई क्रेता होता है न विक्रेता, क्योंकि इन अधिनायकतंत्री राज्यों में व्यक्ति का व्यक्तित्व हमेशा गौण माना जाता है। अस्तु साम्यवादी राज्यों में व्यक्ति को व्यक्ति से तथा व्यक्तिगत औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अन्य प्रतिष्ठानों से प्रतिस्पर्द्धा करने का क्षेत्र ही नहीं होता। वहां आर्थिक प्रतिस्पर्द्धा का मूलतः अभाव होता है। यही कारण है कि सोवियत रूस में पूंजीवादी अर्थतंत्रीय पद्धति के न तो 'चैम्बर्स आफ कामर्स' के लिए ही स्थान है, न मजदूर संघों (ट्रेड यूनियन्स) के लिए ही।

[पृष्ठ १३६ का शेष]

८० लाख के हुए हैं। पोलैंड, जैकोस्लोवेकिया और यूगोस्लेविया के १९५४-५५ और १९५५-५६ के प्रथम ९ मास में १२२, ४० तथा ११० और १९३,१५ और २५ लाख रुपये का माल क्रमशः आया है। रूस के साथ हमारा व्यापार निरन्तर बढ़ रहा है। नीचे के कुछ अंक इसे स्पष्ट करेंगे।

भारत रूस में व्यापार (लाख रु० में)

	आयत	निर्यात
१३५२-५३	२४	८४
१९५३-५४	६०	११५
१९५४-५५	१६१	२१२
अप्रैल १९५६ से जनवरी १९५६	३४६	२०८

भारत की औद्योगिक नीति

लेखक—प्रो० श्री अश्विनीकुमार शाह और प्रो० श्री रामनरेश लाल

सम्पदा के पिछले अंकों में जिस अर्थशास्त्र माला के प्रकाशन की सूचना दी गई थी, उसमें प्रथम पुस्तिका प्रकाशित हो गई है। इसमें भारत की उद्योग नीति का अतीत, समय-समय पर होने वाले परिवर्तन और आज की नीति का संक्षेप से परिचय दिया गया है।

इसके लेखक काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के श्री अश्विनीकुमार शाह और सेण्ट जेवियर्स कालेज रांची अर्थशास्त्र के अनुभवी अध्यापक श्री रामनरेशलाल हैं। दोनों अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों की कठिनता और आवश्यकताएं जानते हैं। इसलिए यह पुस्तक हायर सैकेण्डरी, इन्टर व बी० ए० के परीक्षार्थी विद्यार्थियों के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी।

मूल्य ॥=) । ॥।) के टिकट भेजकर अण्डर पोस्टल सर्टिफ़िकेट मंगाइये।

—मैनेजर, अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिल्ली—६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दशमिक सिक्कों का चलन : नए पैसे देने का प्रबन्ध

१ अप्रैल, १९५७ से वर्तमान सिक्कों को नये दशमिक सिक्कों से बदलने की देश के सब खजानों, रिजर्व बैंक आफ इंडिया के दफतरों, स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखाओं, स्टेट बैंक आफ हैदराबाद और बैंक आफ मैसूर की सब शाखाओं में सुविधा हो जाएगी।

इन स्थानों पर जनता को बदले में देने के लिए नये पैसों और दो, पांच और दस नये पैसों के सिक्कों का काफी स्टाक रखा जाएगा।

आजकल का पैसा, अधन्ना, इकन्नी और दुअन्नी भी ३ साल तक चलती रहेगी और जनता इनका लेन-देन कर सकती है। इसलिए खजानों या बैंकों से एकदम पुराने सिक्कों को बदलने की कोई जरूरत नहीं है और यदि इनके बदले किसी बैंक या खजाने से नये सिक्के न मिलें तो निराश भी नहीं होना चाहिए। एक बारमें केवल ४ आने या ८ और १२ आने के मूल्य के ही नये सिक्के दिये जाएंगे। इससे किसी को भी अपने सिक्के बदलवाने में नुकसान नहीं होगा।

रुपये का वर्तमान मूल्य रहेगा

रुपये का मूल्य उतना ही रहेगा, जितना आजकल है, लेकिन इसमें ६४ पैसों या १९२ पाइयों के बजाय १०० नये पैसे होंगे। अठन्नी और चवन्नी का भी यही मूल्य रहेगा और इन्हें क्रमशः ५० और नये पैसों के बराबर समझा जाएगा। इस मूल्य के नये सिक्के धीरे-धीरे शुरू किये जाएंगे।

सुभाषित रत्नमाला

(सम्पादक—श्री कृष्णचन्द्र विद्यालंकार)

प्रस्तुत पुस्तक में वैदिक एवं संस्कृत साहित्य के अगाध भण्डार में से कुछ सरल एवं सुन्दर मन्त्र और श्लोक संगृहीत किए गए हैं। अल्प आयु के बालक भी इन्हें सुगमता पूर्वक कण्ठस्थ कर सकते हैं। श्लोकों का अर्थ सरल हिन्दी में किया गया है। अन्त में कुछ संस्कृत सूक्तियां भी अर्थ सहित दी गई हैं, जिन्हें विद्यार्थी अपने निबन्धों में प्रयुक्त कर सकते हैं। उपहार तथा पुरस्कार के लिए पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है।

पुस्तक का मूल्य केवल चौदह आने

अशोक प्रकाशन मन्दिर रोशनारा रोड दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संस्था : उत्पादन क्षमता बढ़ाने में योग

पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से ही उत्पादन बढ़ाना और जनशक्ति को काम देना, ये दो मुख्य समस्याएं सामने आईं। इन समस्याओं के हल में अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संस्था से काफी सहायता मिली है। इस संस्था की सहायता के फलस्वरूप मजदूरों के जीवन और काम करने की दशाओंमें कुछ सुधार होने की आशा है।

श्रम समस्या

प्रथम योजना के लागू होने पर ही सरकार को प्राविधिक और कुशल श्रमिकों को पाने के लिए जो भी प्रयत्न हुए उनमें अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संस्था ने सहयोग दिया। इसके कारण बेरोजगार की समस्या कुछ हल हुई।

भारत सरकार ने रोजगार के सम्बन्ध में एक समिति स्थापित की व उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संस्था से २ विशेषज्ञ देने की प्रार्थना की। इन्हें विशेषज्ञों ने दिल्ली क्षेत्र में मिल सकने वाले कामों और कुल रोजगार चाहने वालों के आंकड़ों का संग्रह किया। इस योजना को देश व्यापी करने पर रोजगार सम्बन्धी समस्याओं के हल में बड़ी सहायता मिलेगी।

प्रथम योजना के साथ ही प्रशिक्षित श्रमिकों की आवश्यकता दिन प्रति दिन बढ़ती गई, लेकिन प्राशिक्षकों (इन्सट्रैक्टरों) की कमी के कारण यह समस्या हल न हो रही थी। इसलिए १९४८ में कोली विलासपुर में केन्द्रीय संस्थान की स्थापना की गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में इस संस्था के द्वारा इसकी क्षमता को तिगुना कर देने का निश्चय किया गया है। इसमें अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संस्था का पूरा सहयोग है। इसकी ओर से विविध शिक्षक मिल रहे हैं।

१९५६ तक अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन के विशेषज्ञों ने कपड़ा, लोहा इस्पात, इंजीनियरिंग औद्योगिक निर्माण सीमेंट, तेल और खनिज उद्योगों में सम्बन्धित कर्मचारियों दक्ष श्रमिकों व अधिकारियों का प्रशिक्षण किया। ५० और उद्योगों में भी इस योजना का अनुसरण हो रहा है। १९५६ में इन विशेषज्ञों के कार्य समाप्त होने तक १० हजार सुपरवाइजरों को ट्रेनिंग दी गई है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था द्वारा एशिया के लिए जो कार्य किए गए, उनसे भारत को भी बहुत लाभ पहुंचा है।

श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के क्षेत्र में भी संस्था ने कार्य किया। भारत सरकार को १९४८ के एम्प्लाईज स्टेट इन्शोरेंस एक्ट के प्रशासन वित्तीय और प्रशिक्षण को भी लागू करने की सँभावना में सलाह दी है।

आज देश ने उत्पादन और उत्पादन क्षमता बढ़ाना मुख्य समस्या है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था की भी यही सम्मति थी कि भारत जैसे देश में जहां अत्यधिक जनशक्ति है। लेकिन पूंजी की कमी है, अन्य विकसित देशों की अपेक्षा इस समस्या का समाधान भी भिन्न साधनों से होगा। संस्था के शब्दों मे ही उत्पादकता के बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जिसके लिए न तो नए विनियोग की आवश्यकता हो और न ही बेरोजगार के कम ज्यादा होने की चिन्ता ही करनी पड़े।"

—

चितरंजन में मजदूरी संबंधी योजना

मजदूरों के वेतन निर्धारण की जो कसौटियां हैं, उनमें काम के अनुसार दाम भी प्रमुख है। इस दिशामें चित्तरंजन इंजन कारखाना आजकल एक अनूठा ही प्रयोग कर रहा है। कारखाने में करीब एक वर्ष से एक योजना चलायी जा रही है, जिसका नाम है—कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने की योजना। इस योजना के अनुसार चित्तरंजन इंजन कारखाने में "जितना काम उतना दाम" प्रणाली चलायी गयी है। इससे कुशल कर्मचारी को और ज्यादा काम करने का प्रोत्साहन मिलता है और दूसरी तरफ ढीले कर्मचारी को इस बात की प्रेरणा मिलती है कि वह भी अपने कुशल साथी की तरह ही तेजी से और ज्यादा काम

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

करे। इस तरह कर्मचारियों का तो फायदा होता ही है, उत्पादन बढ़ने से प्रशासन को भी लाभ पहुँचता है।

चितरंजम कारखाने में इस बात का अध्ययन किया गया कि विभिन्न कार्यों में औसतन कितना समय लगता है। उस औसत समय के आधार पर काम के सम्बन्ध में हिसाब फैलाया जाता है।

कर्मचारियों के मन में यह विश्वास जमाने के लिए कि योजना सिर्फ उत्पादन बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि उनके लाभ के लिए भी चलायी जा रही है, यह निश्चय किया गया कि अपने काम में वे जितना समय बचायें, उसी के अनुपात में उन्हें बोनस दिया जाय, ताकि वे स्पष्ट रूप से यह जान सकें कि उन्होंने कितना समय बचाया है और उसके अनुपात में उन्हें कितना बोनस मिलेगा।

कोई भी कर्मचारी ज्यादा काम करके अपने मूल वेतन के ५० प्रतिशत से अधिक नहीं कमा सकता। इस नियम का उद्देश्य यह है कि कोई भी कर्मचारी अपनी सामर्थ्य से ज्यादा काम करने की कोशिश न करे और इस प्रकार उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ सके।

कर्मचारियों के काम और उत्पादन-वृद्धि में उनके अधीक्षकों का भी योग रहता है। इसलिए इस योजना में वे भी शामिल हैं। उन कर्मचारियों को जितना अधिक लाभ मिलता है, उसके ८० प्रतिशत के बराबर उनके अधीक्षकों को दिया जाता है।

कुल मिलाकर योजना से यह लाभ हुआ कि उत्पादन में ३० प्रतिशत वृद्धि हुई तथा कर्मचारियों की आमदनी भी बढ़ी।

★

रेल कर्मचारियों के वेतन

रेल मंत्री, श्री जगजीवन राम ने १० फरफरी, १९५७ को भारत की सभी सरकारी रेलों के नान-गजेटेड स्थानों के व्यापक पुनर्वितरण की योजना की घोषणा की है। इस योजना से निम्न वेतन-क्रमों से ऐसे लगभग १,७०,००० रेल-कर्मचारियों को लाभ पहुँचेगा, जिनका दायित्व और काम रेलों की विभिन्न जटिल समस्याओं के कारण बढ़ गया।

स्थानों के पुनर्वितरण के फलस्वरूप भारी संख्या में नान-गजेटेड कर्मचारियों के या तो वेतनों में वृद्धि होगी या आगे तरक्की के अवसर बढ़ेंगे।

इस योजना से जिन श्रेणियों के कर्मचारियों को लाभ पहुँचेगा, वे इस प्रकार हैं :—

स्टेशन-मास्टर—इस समय देश में लगभग ३ हजार स्टेशन-मास्टर १००-२०० रु० मासिक वेतन वाली श्रेणियों में हैं। अब इनकी संख्या ९,००० हो जाएगी। छोटे स्टेशनों के स्टेशन-मास्टरों का भी मूल वेतन ६४-१७० रु० से बढ़कर १००,१८५ रु० हो जायगा और यह वेतन पाने वालों की संख्या भी २ हजार से बढ़कर ७ हजार हो जायगी। असिस्टेंट स्टेशन-मास्टर, क्लर्क ट्रेन, एग्जामिनर, ड्राइवर, फायरमैन व गार्ड आदि के वेतनों, भत्तों आदि के भी स्तर ऊंचे किये गये हैं।

बागान-मजदूरों के लिए प्राविडेंट फंड

भारत सरकार ने ५० से ज्यादा मजदूरों वाले चाय, कहवा, रबड़, इलायची और काली मिर्च के क्षेत्र कर्मचारियों को भी १९५२ के कर्मचारी प्राविडेंट फंड अधिनियम के अंतर्गत, अनिवार्य अंशदायी प्राविडेंट फंड की सुविधा देने का निश्चय किया है। इसका क्षेत्र बढ़ाने से लगभग ३ लाख ६० हजार और कर्मचारियों को प्राविडेंट फंड का लाभ मिलने लगेगा।

इस अधिनियम के अंतर्गत, अब तक ४ हजार से भी ज्यादा कारखानों में प्राविडेंट फंड की व्यवस्था चालू हो चुकी है। १७ लाख से भी अधिक कर्मचारी प्राविडेंट फंड में आंशिक धन कटाते हैं। कुल मिलाकर लगभग १ करोड़ ६५ लाख रु० हर महीने इस प्रकार जमा होता है। नवम्बर १९५६ तक कर्मचारियों के वेतनों के अंशों से लगभग ७३ करोड़ रु० जमा हो चुका था।

कपड़े की मिलों के लिए वेतन मंडल

भारत सरकार ने सूती मिलों के मजदूरों के लिए एक केन्द्रीय वेतन मंडल बनाने का निश्चय किया है। दूसरी आयोजना में हर उद्योग के लिए अलग-अलग वेतन मंडल बनाने की बात कही गयी है। इसी के आधार पर यह वेतन मण्डल बनाने का निर्णय हुआ है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नई फसलें बोइये

अति हमेशा दुख देती है। पर वर्षा और घाम दोनों की अति से किसानों को जो कष्ट होते हैं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। अति घाम से सूखा पड़ जाता है फसल चौपट हो जाती है। ढोर-डंगर को चारा-पानी नहीं मिलता। अति वृष्टि से भी बाढ़ आ जाती हैं, फसल का नाश हो जाता है, ढोर-डंगर यहां तक मकान भी बह जाते हैं। दोनों तरह फसल चौपट होने से अन्न की कमी पड़ जाती है। यह किसान विचारे करे क्या? प्रकृति पर उनका वश ही क्या? पर क्या तब कुछ भी न किया जाय?

सरकार ने किसान के इस कष्ट और विवशता को समझा और सोचा है। ऐसा कुछ मालूम किया गया कि यदि फ़सलों के बोने-काटने में थोड़ा हेर-फेर कर दिया जाए तो किसानों को यह हानि न उठानी पड़े। यह हानि केवल किसानों की ही नहीं, सारे देश की है। अधिक वर्षा और बाढ़ के कारण खरीफ को काफी नुकसान पहुंचता रहा है। इसलिए अब ऐसी फसलें चलाने का इरादा किया जा रहा है जो बरसात के पहले ही पक कर कट जांय, या फिर वह वर्षा के धक्केको बरदाश्त कर सके। साथ ही जिसको बरसात के बाद बोने पर भी रबी के पूर्व उग आए। बरसात के पूर्व हीं उगने वाली ऐसीं फसलों के लिए सिंचाई का पूरा इंतजाम किया जाएगा।

बरसात के पूर्व उग सकने वाली फसलों में चीना, सावां, भदई, धान, मूंग को फाल्गुन चैत में बोकर जेष्ठ तक काटा जा सकता है।

बरसात के दिनों गहरे पानी में धान, अगहनी-धान, ढ़ंचा और पटसन गन्ना और सिंघाड़ा बोया उगाया जा सकता है।

बरसात के बाद की फसलों में बावनी, लाही, धुखा, मटर, आलू, आसानी से बोया, उगाया जा सकता है। गांव के समीप गाजर, मूली भी पैदा की जा सकती है।

गेहूं, चना, मटर, राई तथा जौ को बरसात के बाद बोकर जल्दी काटे जाने की तरकीबों पर भी सोचा जा रहा है।

यदि ये सब कोशिशें सफल हो गईं तो किसान लहलहाती फसलों को काट सकेंगे। इन्द्रदेव और सूर्य देव के प्रकोप से उनकी फसलें तो कम से कम बच ही जाएगी। फिर जब भरपूर फसल घर में आएगी तो क्यों न किसान खुशी से नाचने लगेंगे?

बुरादे का चारा बनेगा

आज विज्ञान के कारण असंभव भी संभव हो गया है। लकड़ी चीरने पर जो बुरादा निकलता है उससे गांवों में यों ही पड़े रहने देते हैं। हां शहरों में बुरादे को जलाने के काम में इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन बुरादा चारे के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा अब मालूम कर लिया गया है।

अमेरिका में, वहां के वैज्ञानिक इसी ढूंढ-खोज में लगे हैं कि बुरादे का चारा कैसे बनाया जाय। उन्होंने मालूम किया है कि बुरादे में कुछ चीजें होती हैं जिनके खाने से जानवर ताकतवर हो सकते हैं। गन्ने की मिठास और चावल की लप्सी के गुण वाले पदार्थ बुरादे भी पाए जाते हैं। ये पदार्थ अणु-शक्ति के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं, इससे पशु अपने पाचक रस से जो मनुष्यों की थूक की तरह ही जानवरों में भी होता है आसानी से हजम कर सकेंगे।

इस प्रकार बुरादे से तैयार किया चारा अनाज

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

की तरह ही पशुओं को दिया जा सकेगा।

पर आप क्या करेंगे ?

अमेरिका में कृषि-विशेषज्ञ एक नए किस्म की बीज बोने की मशीन तैयार कर रहे हैं। बीज बोने वाली इस नई बड़ी मशीन के तैयार हो जाने पर, सम्भवतः इस काम के लिए विमानों के इस्तेमाल की जरूरत न रहेगी।

इस समय इस मशीन की परीक्षा हो रही है। यह मशीन खाद डालने, भूमि में बीज डालने और फिर उसे मिट्टी से ढकने का सब काम एक ही बार में सम्पन्न कर देती है। विमानों की अपेक्षा यह नई मशीन कई दृष्टियों से अधिक लाभप्रद रहेगी। "हैवी ड्यूटी फीडर" नामी इस मशीन की एक विशेषता यह है कि हवाई जहाजों द्वारा बीज डालने से पूर्व भूमि को तैयार करना पड़ता है, लेकिन ये सब काम यह एक साथ कर देती है। साथ ही इस मशीन से बीज डालने पर हवाई जहाजों की अपेक्षा बीज आधी मात्रा में खर्च होते हैं।

इस नई मशीन का वजन एक टन है। आपका सब काम मशीन करने लगेगी, तब आप क्या करेंगे ?

हिसाब करने की नई मशीन

हिसाब करने के लिए भी अब आदमी बहुत नहीं चाहिए। यह काम मशीन ही किया करेगी।

अमेरिका की "वैस्टिंग हाऊस इलैक्ट्रिक कारपोरेशन" नामक कम्पनी ने हिसाब करने की एक नई मशीन तैयार की है। इस नई मशीन की विशेषता यह है कि किसी समस्या को हल करने के लिए प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह किसी समस्या पर सोच-विचार करने के बाद उसका सही हल निकाल लेती है।

"दि इलैक्ट्रोनिक माइण्ड" नामक हिसाब करने की इस नई मशीन को रासायनिक विधियों के पेचीदा हिसाब-किताब करने और उन पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। रासायनिक नाप-तौल करने वाले यन्त्रों द्वारा उक्त मशीन को सब सूचनाएं दे दी जाती हैं। बाद में यह मशीन बार बार जांच-पड़ताल करने के बाद सही हल पर पहुंच जाती है। यह मशीन विचाराधीन समस्या का एक हल सोचती है और यदि वह ठीक न हो तो फिर एक बार फिर कोशिश करती है। एक बार सही हल मिल जाने पर मशीन उसकी पुनः पड़ताल करती है।

(पृष्ठ १६६ का शेष)

कारोबार बना देने से वर्ग-संघर्ष का हल ज्यादा सुगम हो गया है। इस समय पूंजीपति तमाम देशवासियों के साथ मिल कर चीन को एक आधुनिक औद्योगिक देश बनाने और लोगों का आर्थिक तथा सांस्कृतिक स्तर ऊपर उठाने में संलग्न हैं।

"पूंजीवाद को शांतिपूर्ण ढंग से समाजवाद में परिणत करने के लिए राष्ट्र ने राष्ट्रीय पूंजीवाद की विधि अपना ली है और वह पूंजीपतियों से उत्पादन साधनों को खरीद रहा है। यह कार्य पहले तो पूंजीपतियों को मुनाफे में भागीदार बनाकर शुरू किया गया और निजी कारोबार को राष्ट्र व पूंजीपतियों से साझे का कारोबार बनाने का कार्य पूर्ण हो जाने के बाद, अब उन्हें क्षतिपूर्ति के रूप में नियत वार्षिक ब्याज दिया जा रहा है।"

क्या हम आशा करें कि भारत में राष्ट्रीयकरण और बिना मुआवजा दिए राष्ट्रीयकरण की मांग करने वाले समाजवादी और साम्यवादी इन पंक्तियों पर विचार करेंगे ?

बम्बई में सम्पदा के प्रतिनिधि

श्री टी० एन० वर्मा
c/o उदय ट्रेडर्स
नेशनल हाउस,
Tullock Road, Bombay—१

नागपुर में सम्पदा के प्रतिनिधि

श्री रामकुमार भारतीय
गंजी पेठ
नागपुर—२

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गांधी जी और समाजवाद

(श्री जयप्रकाश नारायण)

"अरे ! वह तो गांधीवादी समाजवादी है"—कुछ हलकों में किसी समाजवादी पर लानत पुकारने के लिए इतना कह देना काफी है। दूसरे कुछ हलकों में गांधी-जयंती मनाना धर्मद्रोह के बराबर माना जाता है, इस तरह की कोती नज़र से गांधीवाद या गांधीजी का कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि समाजवाद का ही नुकसान होता है। गांधी जी एक सामाजिक चमत्कार थे। समाजवाद को चाहिए कि उनको समझने की कोशिश करे। गांधी के बाद का संसार इस तरह अपना काम नहीं चला सकता कि मानों गांधी हुआ ही न हो ! हर मोड़ पर, हर मौके पर उनकी बुलन्द आवाज सहसा प्रतिध्वनित हो उठेगी।

गांधी जी एक सत्यान्वेषी पुरुष थे। उन्होंने कर्म में सत्य का शोध किया। जो लोग दीन, हीन और सर्वहारा हैं, उनकी सेवा में उन्होंने सत्य के दर्शन करने की साधना की। समाजवाद भी जीवन के भीतर कर्म में और साधारण मनुष्य की सेवा द्वारा सत्य की खोज का प्रयास है।

गांधीजी क्रांतिकारी इसलिए थे कि जनता में उनकी श्रद्धा थी और जनता के पुरुषार्थ में उनका विश्वास था। वे कोई विधानवादी नहीं थे, जो समाज को विप्लव में ढकेलने से डरते। समाजवाद भी जनता में श्रद्धा रखता है और जनता के पुरुषार्थ का भरोसा करता है।

गांधीजी इसलिए क्रांतिकारी थे कि उनमें अपनी निष्ठा पर दृढ रहने का साहस था। क्षुद्र पूंजीवाद के पूर्व-ग्रहों से उनका व्यक्तित्व सीमित नहीं होता था। समाजवाद की भी अपनी एक अबाधित तर्क-पद्धति है, जिससे वह मध्यमवर्ग के संशयवाद की इमारत को छिन्न-भिन्न कर देता है।

गांधी जी आग्रहवादी नहीं थे, वे व्यवहार निष्ठ प्रयोग-परायण और वैज्ञानिक थे। समाजवाद भी वैसा ही है। गांधी जी समाज को बदलने के लिए व्यक्ति को बदलने पर जोर देते थे। समाजवाद भी मानता है कि जब तक मनुष्य नहीं बदलेगा, तब तक समाज का परिवर्तन स्थायी नहीं हो सकता।

गांधी जी मार्क्सवादी नहीं थे। वे अपने आप थे। मार्क्स भी मार्क्सवादी नहीं था। वह अपने आप था। दोनों प्रधान रूप से कर्मयोगी थे, हालांकि विचार की गहराई दोनों में कम नहीं थी।

★

भूदान से ग्रामदान तक

··विनोबाजी को देश भर में १७०० ग्राम दान में प्राप्त हो चुके हैं। ग्राम भूमि में से बहुत कुछ का बँटवारा भूमि-हीनों में हो चुका है, जो इस बात का प्रमाण है कि इस आन्दोलन ने समानता और सामाजिक न्याय की स्थापना में पूर्ण योगदान किया है। प्राप्त भूमि को, खेती करने की इच्छा रखने वालों को देते समय, उसे खेती योग्य बनाने की समस्या संपत्तिदान के रूप में जो कुछ निधि संग्रहीत हुई, उसका उपयोग करके किसी अंश तक हल की गयी। परिणामस्वरूप सैंकड़ों ऐसे परिवारों को खेती करने योग्य और उसके माध्यम से जीविका चलाने योग्य बनाया जा चुका है, जिनके पास निर्वाह की कोई नियमित व्यवस्था नहीं थी। इतना होने पर भी आन्दोलन के अपने साधन इतने अपर्याप्त हैं कि चालीस-बयालीस लाख एकड़ भूमि का ठीक तरह से बँटवारा करना और उसे व्यवस्थित करना बहुत सरल काम नहीं, क्योंकि उसमें कुछ जमीन अच्छी और कुछ बुरी भी है।

★

बिहार में १८ अप्रैल, '५७ तक भू-वितरण

बिहार प्रदेश के भूदान-कार्यकर्त्ताओं ने भूक्रान्ति की जयन्ती के दिन, १८ अप्रैल १९५८ तक इस प्रान्त में भूदान में मिली सारी जमीन का बँटवारा समाप्त कर लेने का संकल्प किया है। भूदान के दानपत्रों में से बहुतों में दाता ने केवल, कितनी भूमि का वह दान देता है, यही लिख कर दानपत्र दे दिया है। कौनसी भूमि वे देंगे, इसका विवरण बाद में देने के लिए उस समय छोड़ा गया, वह

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अब तक प्राप्त नहीं हो रहा है। बड़े-बड़े राजा महाराजाओं के लाखों एकड़ के दानपत्र भी अधिकांश इस प्रकार के हैं। अभी तक कार्यकर्त्ता-गण इन दानपत्रों की भूमि का विवरण प्राप्त करके वितरण का प्रयत्न करते रहे हैं, पर केवल डेढ़ लाख एकड़ से कुछ अधिक भूमि ही बांटी जा सकी है।

१८ अप्रैल तक यदि सारे दानपत्रों की भूमि बांटने के लिए निश्चय ही प्रान्त भर के लोगों का सहयोग अपेक्षणीय है। जो भूमि बांटी जा चुकी है, उसे छोड़कर करीब १० लाख एकड़ भूमि के दानपत्र बिहार के लगभग ३७ हजार गांवों के दाताओं से प्राप्त हैं, जिनके वितरण का आयोजन करना है। सोचा यह गया है कि प्रत्येक गांव का उत्तरदायित्व लेने वाला एक व्यक्ति हो, जो पहले से अपने नाम पर लिये हुए गांव के लोगों के सहयोग से उस गांव के भूमिहीनों की सूची तैयार करे।

इस प्रकार १८ अप्रैल को बिहार राज्य के ७१ हजार गांवों में नहीं, तो जिन गांवों से भूदान मिला है, ऐसे बिहार प्रान्त के आधे गांवों में तो भी भूक्रान्ति-दिवस मना कर उन गांवों की भूमिहीनता मिटाने का प्रयत्न किया जायगा। जहां यह भी संभव नहीं हो सकेगा, वहां कम-से कम उस गांव में भूदान में मिली हुई और बांटने योग्य जमीन का बँटवारा ग्रामीणों की सभा करके, उनकी सम्मति से, उस दिन जरूर हो जाय, इसका आयोजन किया जायगा।

इस महान् संकल्प की पूर्ति में, अपनी शक्ति लगाने की सभी रचनात्मक संस्थाओं से अपील की गयी है। बिहार खादी-ग्रामोद्योग-संघ और बिहार प्रान्तीय ग्राम-पंचायत परिषद् से पूरा सहयोग मिलेगा। बिहार-सरकार के माल विभाग से भी इस कार्य को सम्पन्न करने में योग्य सहायता प्रदान करने की अपील की गयी है। आशा है, सबका सहयोग मिलेगा और १८ अप्रैल का यह महान् संकल्प पूरा होगा।

संचालक पंचायत राज विभाग उ० प्र०

की

विज्ञप्ति संख्या ४/५५८०/३३ : २७/५३, दिनांक १

द्वारा

पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत

सुन्दर पुस्तकें

	लेखक	मूल्य रु०	आ०
वेद सार	प्रो. विश्वबन्धु	१	[illegible]
प्रभु का प्यारा कौन ? (२ भाग)	,,		
सच्चा सन्त	,,		[illegible]
सिद्ध साधक कृष्ण	,,	०	[illegible]
जीते जी ही मोक्ष	,,	०	[illegible]
आदर्श कर्मयोग	,,	०	[illegible]
विश्व-शान्ति के पथ पर	,,	०	[illegible]
भारतीय संस्कृति	प्रो. चारुदेव	०	[illegible]
बच्चों की देखभाल	प्रिंसिपल बहादुरमल	१	[illegible]
हमारे बच्चे	श्री सन्तराम बी. ए.	३	[illegible]
हमारा समाज	,,	६	[illegible]
व्यावहारिक ज्ञान	,,	२	[illegible]
फलाहार	,,	१	[illegible]
रस-धारा	,,	०	[illegible]
देश-देशान्तर की कहानियां	,,	१	[illegible]
नये युग की कहानियां	,,	१	[illegible]
गल्प मंजुल	डा० रघुवरदयाल	१	[illegible]
विशाल भारत का इतिहास	प्रो. वेदव्यास	३	[illegible]

१० प्रतिशत कमीशन और ५० रु० से ऊपर के आदेशों पर १५ प्रतिशत कमीशन।

विश्वेश्वरानन्द पुस्तक भंडार

—साधु आश्रम, होशियारपुर, पंजाब

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उच्च जीवन स्तर

प्रथम योजना अवधि में खाद्य और कृषि उत्पादन में ठोस उन्नति हुई है। द्वितीय योजना अवधि में बड़ी और छोटी सिंचाई परियोजनाओं द्वारा और खाद, रासायनिक खाद और सुधरे हुए बीजों के अधिक प्रयोग करने से तथा प्रत्येक एकड़ भूमि पर भूमि संरक्षण की नई तकनीकों द्वारा उत्पादन का स्तर और भी ऊंचा होगा। द्वितीय योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति पर जनता जनार्दन की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी।

परिमाणतः प्रत्येक प्रौढ़ व्यक्ति की वर्त्तमान अनाज की मात्रा १७.२ आऊंस की तुलना में १८.३ आऊंस तक बढ़ेगी। इसी प्रकार चीनी की वर्त्तमान मात्रा १.४ आऊंस से १.७ आऊंस तक बढ़ जाएगी। इस के अतिरिक्त कपास की २३ लाख और पटसन की १५ लाख गांठों की वृद्धि होगी।

द्वितीय योजना के कुल व्यय में से ५६८ करोड़ रुपया यानी ११.८ प्रतिशत कृषि और सामुदायिक परियोजनाओं पर खर्च होगा। राष्ट्रीय विस्तार सेवा के साथ सामुदायिक परियोजनाओं के अन्तर्गत सम्पूर्ण ग्रामीण आबादी आ जाएगी। मीनक्षेत्रों, कृषिकरण, पशुपालन और जंगलात के क्षेत्रों में वृद्धि होगी। इस के अतिरिक्त बिजली और जल की सुविधाएं ग्रामीणों को स्वावलम्बी बनाने में सहायक होंगी।

द्वितीय योजना में २१० लाख एकड़ भूमि सिंचित होगी जिससे कुल मिला कर ८८० लाख एकड़ क्षेत्र सिंचाई के अंतर्गत आ जाएगा। उद्योग धंधो और गांवों की बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वर्त्तमान ३४ लाख किलोवाट क्षमता से ६९ लाख किलोवाट क्षमता तक बिजली बढ़ाई जाएगी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खर्च होने वाले प्रत्येक रुपये में से तीन आने सिंचाई और बिजली पर खर्च होंगे।

राष्ट्र की समृद्धि के लिये

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्पदा का :—

आगामी विशेषांक

१० वें स्वाधीनता दिवस १५ अगस्त '५७ को प्रकाशित होगा

परन्तु वह कैसा होगा,
किस विषय पर प्रकाशित होगा,
उसकी विशेषताएं क्या होंगी,
आदि जानकारी के लिए

आपको अभी प्रतीक्षा करनी चाहिए

इतना ही समझ लीजिए कि अपने विषय का एक अद्भुत विश्वकोश होगा—हिन्दी पत्र जगत् में एक दम अनुपम और संग्रहणीय। विविध विद्वत्तापूर्ण लेखों, ज्ञानवर्धक तालिकाओं, ग्राफों और चित्रों से परिपूर्ण।

अभी से सम्पदा का ग्राहक बन जाने वालों को साधारण वार्षिक मूल्य में ही मिलेगा।

मूल्य होगा १॥) रु०।

—मैनेजर सम्पदा
अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिल्ली-६

सम्पादक—कृष्णचन्द्र विद्यालंकार द्वारा, अशोक प्रकाशन मंदिर के लिए, अर्जुन प्रेस दिल्ली से मुद्रित व प्रकाशित

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्पदा

अप्रैल १९५७

सम्पादक :
कृष्णचन्द्र विद्यालङ्कार

एक किशोर कलाकार

मध्यप्रदेश का यह किशोर कलाकार सुन्दर कलापूर्ण रचनाओं के द्वारा न केवल देश में कलात्मक अभिरुचि का विकास करता है, बल्कि देश के आर्थिक विकास व विदेशी मुद्रा के अर्जन में भी परम सहायक हो रहा है, क्योंकि इस कलापूर्ण कृतियों की विदेशों में मांग बढ़ रही है। ऐसे हजारों कलाकार विविध राज्यों में कला की साधना के साथ साथ देश की समृद्धि में सहयोग दे रहे हैं।

मूल्य
७५ नये पैसे

अशोक प्रकाशन मन्दिर · रोशनारा रोड, दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कैसेल्स
आनन्द
लकी
आज़ाद

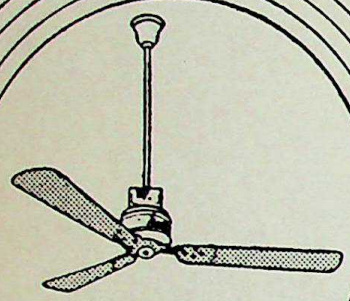

कैसेल्स ए. सी.
कैपैसिटर टाइप

कैसेल्स टिल्टिंग
केबिन फैन

एम.ई.आई. पंखे

मैचवैल इलैक्ट्रिकल्स इण्डिया लि०

आरामदेह होते हैं

सीलिंग, टेबुल,
केबिन व रेलवे
के पंखे

एअर सर्कुलेटर,
पेडेस्टल व सिनेमा
टाइप पंखे

कैसेल्स ओसिलेटिंग
व फिक्सड़ टेबुल फैन

मैचवैल इलैक्ट्रिकल
(इण्डिया) लि०
४/११ आसफअली रोड,
पोस्ट बाक्स नं० १५६
नई दिल्ली
टैलीफोन : २७८७१–२७८७२
तार : मैचवैल

कैसेल्स ए सी.
एअर
सर्कुलेटर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्पदा का :—

आगामी विशेषांक

१० वें स्वाधीनता दिवस १५ अगस्त '५७ को प्रकाशित होगा

परन्तु वह कैसा होगा,
किस विषय पर प्रकाशित होगा,
उसकी विशेषताएं क्या होंगी,
आदि जानकारी के लिए

आपको अभी प्रतीक्षा करनी चाहिए

इतना ही समझ लीजिए कि अपने विषय का एक अद्भुत विश्वकोश होगा—हिन्दी पत्र जगत् में एक दम अनुपम और संग्रहणीय। विविध विद्वत्तापूर्ण लेखों, ज्ञानवर्धक तालिकाओं, ग्राफों और चित्रों से परिपूर्ण।

अभी से सम्पदा का ग्राहक बन जाने वालों को साधारण वार्षिक मूल्य में ही मिलेगा।

मूल्य होगा १॥) रु०।

—मैनेजर सम्पदा

अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिल्ली-६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विषय-सूची

क्रम	विषय	पृष्ठ संख्या
१.	राष्ट्र को उद्बोधन	१८५
२.	हमारी अर्थ व्यवस्था पर भारी बोझ	१८६
३.	सम्पादकीय टिप्पणियां	१८७
४.	हमारी अर्थ-व्यवस्था और समस्याएं	१९१
५.	भारत में सहकारिता की प्रगति	१९५
६.	राष्ट्र का आर्थिक प्रवाह	१९९
७.	हमारा चाय उद्योग	२०४
८.	सर्वोदय पृष्ठ	२०५
९.	प्रतिदिन एक करोड़ रु० घाटे का बजट	२०७
१०.	१९५७-५८ का रेलवे बजट	२१०
११.	१९५६ में भारत की अर्थ-व्यवस्था	२१३
१२.	विदेशी अर्थ-चर्चा	२१५
१३.	नया सामयिक साहित्य	२१७
१४.	अर्थवृत्त चयन	२१९
१५.	द्वितीय आयोजना और बैंक	२२३
१६.	अ० भा० उद्योग व्यापार मंडल के महत्व-पूर्ण प्रस्ताव	२२६
१७.	हमारा विकासशील जूट उद्योग	
१८.	द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना में मध्यप्रदेश के खनिज एवं उद्योग	२३४
१९.	विभिन्न राज्यों के बजट	२३७

★

भारत की औद्योगिक नीति

सम्पदा अर्थशास्त्र मालाके अन्तर्गत भारतकी औद्योगिक नीति पुस्तक प्रकाशित की गई है। सम्पदा के ग्राहकों को ग्राहक नम्बर लिखने पर पौन मूल्य में मिलेगी। ९ आने अर्थात् ५६ नये पैसे के टिकिट भेज कर अन्दर पोस्टल सर्टिफिकेट मंगा सकते हैं। आशा है, इस सुविधा से सम्पदा के ग्राहक लाभ उठायेंगे।

मैनेजर—अशोक प्रकाशन मन्दिर,
रोशनारा रोड, दिल्ली।

★

अपूर्व

प्रगति

३१ दिसम्बर १९५६

डिपोजिट	१०६ करोड़ रुपये से अधिक
कार्यगत कोष	१४१ करोड़ रुपये से अधिक

१९५६ में देश के सभी अनुसूचित बैंकों के अधिक-जमा का लगभग २० प्रतिशत पंजाब नैशनल बैंक ने प्राप्त किया है।

चेयरमैन

श्री एस. पी. जैन

दी पंजाब नैशनल बैंक लिमिटेड

प्रधान कार्यालय : दिल्ली

६१ वर्षों की विश्वसनीय सेवा का बृहत अनुभव

ए. एम. वाकर— जनरल मैनेजर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्पदा

वर्ष ६] अप्रैल १९५७ [अङ्क ४

राष्ट्र को उद्बोधन

आज हम सबको देश की उन्नति करनी है। लेकिन जब मैं देश की उन्नति के सम्बन्ध में कुछ कहता हूं तब मेरे सामने केवल २००० मील लम्बा और १८०० मील चौड़ा विशाल देश नहीं रहता, अपितु उसमें रहने वाले ३७ करोड़ भारतीय आ जाते हैं। इन सबकी उन्नति ही देश की उन्नति है। प्रजातंत्र के अपनाने पर, कुछ बातों का होना स्वाभाविक ही है। जनता को, वयस्क मताधिकार तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के कारण यह अधिकार है कि वह अपनी राय प्रकट कर सके और यदि आवश्यकता हो तो सरकार को भी बदल दे। तब यह नहीं माना जा सकता कि कुछ बुद्धिमान् लोग कहीं भी, किसी स्थान पर बैठ कर, यह समझने लगें कि 'हम' ही देश के शासनकर्ता हैं। सच तो यह है कि भारत के लाखों, करोड़ों लोग ही हैं, जो सही या गलत जिस तरह से भी इसका निश्चय करते हैं, और आगे भी करते रहेंगे।

मैं और आप उनके विचार बदलने और उनको समझाने-बुझाने का प्रयत्न कर सकते हैं लेकिन बड़े-बड़े सामाजिक और आर्थिक नीतियां, केवल संसद के विधेयकों या सरकार के निर्णयों से पूरी नहीं की जा सकतीं। ये तो केवल खेतों, कारखानों और बाजारों में काम करने वाले लाखों आदमियों द्वारा ही पूर्ण होती हैं।

हम देश को अल्प विकसित अवस्था से निकाल कर आगे ले आये हैं। यह कठिन संक्रमण काल है। किसी न किसी को इसके लिये धन देना है। सारे देश को ही देना है। प्रश्न यह है कि यह भार कैसे बांटा जाय।

यह सच है कि भारत में कर-भार भारी हैं। लेकिन इस देश की उस ८० प्रतिशत जनता के भार के विषय में क्या कहा जाय? उन पर भार काफी भारी है और इन वर्षों में वह बढ़ता ही गया है। आज देश के भाग्य-निर्माण में, इस ८० प्रतिशत की आवाज का बड़ा महत्त्व है। इसलिए हमें यह भार बर्दाश्त करना ही है। हमें आज यह कह कर निराश नहीं होना है कि यह भार अत्यधिक है या हमारे हाथ पैर इतने मजबूत नहीं कि हम आगे बढ़ सकें। इस प्रकार की बात कोई जीवित व्यक्ति या राष्ट्र नहीं कहेगा। हमने जो भार उठा लिया है उसे मंजिल तक ले जायेंगे।

हमें दूसरे देशों से सीखने के लिए बहुत नम्रता ग्रहण करनी होगी। किन्तु यदि हमारे पैर अपनी भूमि में ही जमे न हों तो हम बहुत ज्यादा नहीं सीख सकते और न लाभ उठा सकते हैं। मैं अभी चारों ओर जितना देखता हूं, उतना ही मेरा विश्वास बढ़ता जाता है कि जिस जाति की जड़ जमी नहीं होती, वह समृद्ध नहीं होती। वह धीरे-धीरे मुर्झा जाती है। हमारे महान् गांधी जी ने हमें सिखाया कि डरो नहीं।

जवाहरलाल नेहरू

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आर्थिक स्थिति पर असह्य बोझ

मार्च मास में दो बहुत महत्वपूर्ण भाषण हुए हैं। एक भाषण है भारत सरकार के वित्तमंत्री श्री कृष्णमाचारी का, जो उन्होंने नये वर्ष का अन्तरिम बजट पेश करते हुए संसद में दिया। दूसरा भाषण है भारतीय उद्योगव्यापार मण्डल के अध्यक्ष श्री लक्ष्मी पत सिंहनियां का अध्यक्षपद से दिया गया भाषण दोनों। भाषण अलग-अलग दृष्टिकोण से दिये गये हैं। वित्तमंत्री सरकारी नीति के मुख्य प्रवक्ता हैं, जिसके मुख्य अंग अनेक उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, उद्योगों पर निरन्तर कर-वृद्धि, कम्पनियों पर अधिकाधिक नियंत्रण तथा दूसरी पंचवर्षीय योजना की पूर्ति है। दूसरी ओर श्री सिंहानिया का भाषण व्यक्तिगत उद्योग और उनकी सुविधाओं के समर्थन में दिया गया भाषण है। किन्तु दोनों देश की आर्थिक स्थिति के प्रश्न पर एकमत है। दोनों ने यह स्वीकार किया है कि देश भयंकर आर्थिक स्थिति में से गुजर रहा है। वित्त मंत्री कहते हैं—

"यह वर्ष द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष है और इसी वर्ष देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव के लक्षण दिखाई पड़े। इस वर्ष विकास-व्यय बढ़ जाने के बाद मूल्यों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। १९५६ में १९५५ की अपेक्षा थोक मूल्यों के स्तर में १३ % वृद्धि हुई। अर्थात् संकेतांक ३७३.४ से बढ़कर ४२१.९ हो गया। १९५५ के अन्त में ७३५ करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा रिजर्व बैंक के पास थी, पर इस वर्ष के प्रारम्भ में वह गिर कर ५३० करोड़ रु० रह गई है। कृषि का उपादन भी गत वर्ष की अपेक्षा २.४ % कम हुआ है। १९५३-५४ में ६८८ लाख टन अन्न पैदा हुआ था, परन्तु १९५५-५६ में ३१ लाख टन अन्न कम पैदा हुआ है। तिलहन और कपास की भी पैदावार गत वर्ष से ६ लाख टन और २ लाख गांठ कम हुई है। देश की जनता से छोटी बचत के रूप में भी आशाजनक वृद्धि नहीं हो रही। इस बचत से होने वाली रकम जो १९५१-५२ में ३९ करोड़ रु० से लगातार बढ़कर १९५५-५६ में ६७ करोड़ रु० हो गई थी, १९५६-५७ के पहले ११ महीनों में ४८ करोड़ रु० रह गई, जबकि गत वर्ष इसी अवधि में यह रकम ५६ करोड़ रु० थी। घाटे की अर्थव्यवस्था में भी काफी वृद्धि की सम्भावना है। आयात में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। गत वर्ष की अपेक्षा अप्रैल से नवम्बर तक इस वर्ष आयातित वस्तुओं का मूल्य ४१८ करोड़ रु० से बढ़कर ५३५ करोड़ रु० हो गया। द्वितीय आयोजना की रिपोर्ट में पहले वर्ष १४८ करोड़ रु० घाटे का अनुमान किया गया था। परन्तु इस वर्ष के पहले ६ महीनों में ही १४३ करोड़ रु० घाटा हो गया। यह स्पष्ट दीख रहा है कि विदेशी मुद्रा के साधनों में ११ अरब रु० की अनुमानित कमी से कहीं अधिक कमी रहेगी। इन सब प्रवृत्तियों का परिणाम यह हुआ कि बैंकों पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ गया और रिजर्व बैंक द्वारा काफी सहायता देने पर भी रुपये के बाजार में बहुत तंगी अनुभव की गई।" इन सब परिस्थितियों का परिचय देते हुए वित्त मंत्री इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आगामी वर्ष का सम्पूर्ण घाटा ३६५ करोड़ रु० अर्थात् प्रति दिन १ करोड़ रु० होगा।

अ० भा० उद्योग-व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री लक्ष्मीपत सिंहानिया भी वर्तमान स्थिति का सिंहावलोकन करते हुए इसी परिणाम पर पहुंचे हैं कि आन्तरिक और बाहरी स्थितियों के कारण हमारे देश की आर्थिक स्थिति पर बहुत बोझ पड़ रहा है। आयात बढ़ रहे हैं, निर्यात कम हो रहे हैं, अन्न का उत्पादन कम हो रहा है और मूल्य अधिक हो रहे हैं। पं० जवाहर लाल नेहरू ने भी फैडरेशन में दिये गये भाषण में यह स्वीकार किया कि हम कठिन संक्रांतिकाल में से गुजर रहे हैं।

जहां तक देश की वर्तमान आर्थिक कठिनाइयों का प्रश्न है, सभी इस पर एकमत हैं। किन्तु इसके उपायों पर ही प्रत्येक का अपना-अपना दृष्टिकोण है। पं० नेहरू जी के शब्दों में इसका बोझ समस्त देश को उठाना होगा किन्तु ८० प्रतिशत जनता तो पहले ही असह्य भार से दबी हुई है। इसलिए नया भार सम्पन्न वर्ग को ही उठाना होगा। वित्तमंत्री श्री कृष्णामाचारी ने भी अपने भाषण में कर-वृद्धि के पिछले निश्चयों का समर्थन करते हुए और अधिक त्याग के लिए—नये कर देने के लिये तैयार रहने की धमकी दी है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दूसरी ओर श्री सिंहानिया ने उत्पादन और निर्यात की वृद्धि के लिए नये औद्योगिक कानूनों और भारी करों को शिथिल करने की सम्मति दी है, ताकि उद्योग पनप सकें और उनके लिए पूंजी-निर्माण में कठिनता न हो।

कुछ अर्थशास्त्रियों ने यह सुझाव उपस्थित किया है कि पंचवर्षीय योजना को पांच के बजाय सात वर्षों में पूरा किया जाय अथवा उसके व्यय लक्ष्य कम कर दिये जायं, ताकि देश की अर्थव्यवस्था पर असह्य बोझ न पड़े। देश के नेता इसे देश की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते हैं। तब किया क्या जावे ?

यद्यपि हम यह समझते हैं कि राष्ट्र के विकास में उद्योग को अधिकाधिक त्याग करना चाहिये, तथापि हमारी नम्र सम्मति में रुपये के बाजार को इतना कठिन नहीं बना देना चाहिये कि नये उद्योग-विकास का रास्ता ही रुक जाये। यह भी नहीं भूलना चाहिये कि हमारा उत्पादन व्यय इतना अधिक न बढ़ जाय, जिससे हम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में विदेशी उत्पादकों का मुकाबला न कर सकें, भले ही हमें बढ़िया मशीनरी का उपयोग करना पड़े अथवा करों वा मजदूरी के रूप में कम देना पड़े। हम 'सम्पदा' के पाठकों से इन मौलिक प्रश्नों पर गम्भीर रूप से स्वयं विचार करने का अनुरोध करते हैं।

———

दिमागी दकियानूसीपन किसी क्षेत्र में नहीं

पं० जवाहरलाल नेहरू ने उद्योग व्यापार मण्डल में इस बात पर बहुत बल दिया था कि हमें दिमागी दकियानुसीपन से सतर्क रहना चाहिये। उन्होंने कहा था यदि हमने मजहब के कट्टरपन को छोड़ दिया है, तो हम दूसरी बातों में भी कट्टर या कठमुल्ला नहीं रह सकते। हमारी पंचवर्षीय योजना अपरिवर्तनीय लकीर नहीं है। परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन हो सकता है, कमी की जा सकती है और उसे बढ़ाया भी जा सकता है। प्रधानमंत्री का यह संदेश बहुत व्यापक और महत्वपूर्ण है। हमारे सामने अपने उद्देश्य का आग्रह होना चाहिये, मार्ग का नहीं। आज न पुराना पूंजीवाद चल सकता है और न कार्लमार्क्स की कल्पना का साम्यवाद। एक ओर जहां उद्योग पतियों को उन्नीसवीं सदी की मान्यतायें अपने हृदय से निकाल देनी चाहियें, दूसरी ओर साम्यवादी क्रिया-पद्धति में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। हमारा मुख्य लक्ष्य न पूंजीवाद है और न साम्यवाद की प्रक्रिया। हमारा मुख्य लक्ष्य तो राष्ट्र का और पं० नेहरू के शब्दों में २००० मील लम्बे और १८०० मील चौड़े देश का नहीं, ३७ करोड़ भारतीयों का हित होना चाहिये। इसके लिए हमको किसी विशेष 'इज्म' के चक्कर में पड़ कर अपने वास्तविक लक्ष्य को ओझल नहीं कर देना चाहिये। यह प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार की आर्थिक नीति में जहां पूंजीवाद का शोषक स्वरूप नष्ट किया जा रहा है, वहां साम्यवाद के भी रूसी स्वरूप को ग्रहण नहीं किया जा रहा। निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों को स्वीकार करके एक नई लोकतंत्रीय अर्थ-पद्धति का निर्माण किया जा रहा है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसी अर्थ-पद्धति के विस्तार का विधान है।

किन्तु, हमारी नम्र सम्मति में निजी स्वतन्त्रता की रक्षा करते हुए राष्ट्रीयकरण को भी उसके संकुचित रूप में नहीं लेना चाहिए। इसका अर्थ एकाधिकार नहीं हो जाना चाहिये। एकाधिकार के साथ पूंजीवाद के दोष आ जाते हैं। चाहे वह फिर व्यक्तियों का पूंजीवाद हो अथवा सरकार का हो। उत्पादकों की परस्पर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ता या जनता का हित ही होता है। इससे उत्पादकों में जनता को कम से कम मूल्य पर सुविधा देने प्रवृत्ति पैदा होती है। यह परस्पर प्रतिस्पर्धा ही लोकतंत्रीय अर्थशास्त्र को सुरक्षित रख सकती है। निजी स्वार्थ से प्रेरित उद्योगपतियों के दुश्चक्र को तोड़ने के लिए राज्य उसमें भी प्रवेश कर सकता है, किन्तु किसी ऐसे उद्योग पर, जो निजी रूप से भी चलाये जा सकें, एकाधिकार कर लेना जनता को प्रतिस्पर्धा से मिलने वाले लाभों से वंचित कर देना है।

स्वेज नहर खुल गई

स्वेज नहर संसार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उसके पिछले समय में बन्द हो जाने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कितना व्यापक प्रभाव पड़ा था यह सब जानते हैं। अब दीर्घकालीन संकट के बाद नहर खुल गई है और जहाजी भाड़े का खर्च पहले से बहुत कम हो गया है। इसका एक सुपरिणाम यह होगा कि भारत में आने वाला पूंजीगत सामान जो पंचवर्षीय योजना के लिये अनिवार्य है कुछ सस्ता पड़ेगा।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

किन्तु स्वेज़ का भविष्य कुछ अड़चनों से खाली नहीं है। छपते छपते मालूम हुआ है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, और इजराइल नहर शुल्क के सम्बन्धमें मिस्र से एकमत नहीं हो रहे। इसलिए तरह तरह की प्रतिकूल सम्भावनाएं की जा रही हैं। ब्रिटेन स्वेज नहर का बहिष्कार करने के विचार पर दृढ़ प्रतीत होता है और अमेरिका मिस्र को आर्थिक चोट पहुँचाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कपास का 'डम्पिंग' करने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है। देखें, इन सम्भावनाओं में कहां तक सचाई है और मिस्र अपने राजनैतिक प्रभुत्व की रक्षा के लिए इस आर्थिक युद्ध में किस तरह विजयी होता है ?

लघु उद्योगों की सहायता

स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने लघु उद्योगों के विकास के लिये रिजर्व बैंक से परामर्श के बाद सहायता की जो योजना चालू की है, उसका हम स्वागत करते हैं। फिलहाल यह योजना ६ चुने हुए केन्द्रों में प्रारम्भ की गई है—आगरा, दिल्ली, लुधियाना, बम्बई, कोल्हापुर, सूरत, कोयम्बटूर, मद्रास और विजयवाड़ा। जिन छोटे उद्योगों में बिजली या इंजन के साथ ५० कारीगर अथवा बिना शक्ति के १०० कारीगर काम करते हैं और जिनकी पूंजी ५ लाख रुपये से कम है, उन्हीं उद्योगों को इस योजना से मदद मिल सकेगी। बैंकों के अधिकारियों को यह परामर्श दे दिया गया है कि इन उद्योगों को सहायता देते समय कानूनी बारीकियों का सख्ती से पालन नहीं करें और सहयोग व सहानुभूति की भावना अपने सामने रखें। राज्यों के औद्योगिक विभाग लघु उद्योगों को जो सहायता देते हैं, वह बैंकों को सहायता के अतिरिक्त होगी। हमें आशा करनी चाहिये कि इस योजना से लघु उद्योगों के विकास में अवश्य कुछ सहायता मिलेगी।

नारियां व पंचवर्षीय योजना

अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष तथा प्रधान मंत्री की संसदीय सचिव श्रीमती लक्ष्मी मेनन ने भारत की शिक्षित और सम्पन्न महिलाओं से पंचवर्षीय योजना में सहयोग देने की अपील की हैं। उन्होंने कहा है कि कम से कम दो कार्य तो हम कर सकती हैं। एक तो यह कि अपने परिवारिक व्यय यथा संभव कम करके अधिक से अधिक रुपया बचायें। दूसरी बात यह कि प्रत्येक महिला निश्चय करले कि वह विदेशी श्रृंगार सामग्री और विदेशी वस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगी। यदि इस दिशा में हम दृढ़ संकल्प करलें तो हमारा बहुत सा रुपया बच जाये और उसका उपयोग पूंजीगत सामान मंगाने के लिये हो सके। परन्तु क्या यह संभव हो सकेगा? केवल नारियों के लिये यह व्यवस्था नहीं है, पुरुष भी खाद्य, पेय और तमाखू के रूप में कम रुपया विदेशों को नहीं भेजते विविध प्रकार के शराब और तमाखू तथा विदेशी कपड़ों का आयात आसानी से बन्द किया जा सकता है।

पूर्वी पाकिस्तान की मांग

पूर्वी पाकिस्तान की असेम्बली ने सर्व सम्मति से एक प्रस्ताव स्वीकार करके पाकिस्तान की सरकार से यह अनुरोध किया है कि पूर्वी पाकिस्तान को रक्षा, विदेशी नीति और मुद्रा के सिवाय बाकी सब दृष्टियों से स्वायत्त शासन दे दिया जाये। पाकिस्तान की आजकल जो आंतरिक दशा है, उसे देखते हुए यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इस प्रस्ताव की क्या गति होगी। यह संभव है कि वहां के राष्ट्रपति सर इसकन्दर मिर्जा इस प्रकार के प्रस्तावों पर कोई कार्यवाही न होने दें। किन्तु पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की जनता में आज केन्द्रीय शासन के विरुद्ध जो असन्तोष फैल रहा है उसे अधिक समय तक दबाया नहीं जा सकता। इसलिये किसी न किसी रूप में पश्चिमी पाकिस्तास में विभिन्न राज्यों की पुनः स्थापना तथा पूर्वी पाकिस्तान को स्वायत्त शासन का रूप देकर समस्या को हल करने की चेष्टा की जायेगी। यदि पूर्वी पाकिस्तान को व्यापारिक आर्थिक स्वायत्त शासन दिया तो उसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि पूर्वी पाकिस्तान और भारत का आन्तरिक व्यापार अधिक स्वच्छंदता के साथ होने लगेगा। राजनीतिक कारण व्यापार के वृद्धि में बाधक नहीं होंगे।

समाजवाद के लिए आवश्यक

राजस्थान के राज्यपाल श्री गुरुमुख निहालसिंह ने हाल ही में एक भाषण देते हुए पब्लिक स्कूलों में शिक्षण-पद्धति बदलने का परामर्श दिया है। इसमें उन्होंने विदेशी भाषा के बजाय शिक्षा का माध्यम हिन्दी तथा छात्रों के रहन सहन के खर्चे कम करने की राय देते हुए देश की जीवन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

धारा के साथ सम्पर्क कायम करने की सलाह दी है। इस परामर्श का हम विशेष रूप से स्वागत करते हैं। हमारी यह सम्मति है कि समाजवादी पद्धति के लिए वह आवश्यक है कि जनता की भिन्न भिन्न श्रेणियों में परस्पर सम्पर्क कायम करना चाहिए। जो विद्यार्थी अपने प्राथमिक जीवन में जन सामान्य से सम्पर्क कायम नहीं, करता उसके हृदय में समाजवादी समाज की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। वर्ग भेद को विद्यार्थी जीवन से ही समाप्त किया जा सकता है। उद्योगों का राष्ट्रीयकरण केवल निजी उद्योग पतियों से रुपया लेने या कमाई छीनने का साधन है। इससे वर्गभेद समाप्त नहीं होगा। बड़े बड़े शिक्षित और ऊंचे पदाधिकारी जनसामान्य से मिलने में संकोच करते हैं। यही समाजवाद के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। यह मानसिक बाधा दूर करने के लिए शिक्षा पद्धति को बदलना होगा। सम्पन्न वर्ग के बच्चे यदि ऊंचे जीवन स्तर के विद्यालयों में उच्च सम्पन्न श्रेणी के बच्चों के साथ पढ़ेंगे, रहेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे तो वे कभी समाजवादी भावना अपने को जनसामान्य का अंग समझने की भावना को हृदयंगम नहीं कर सकते। इसके लिए आवश्यक है कि पब्लिक स्कूलों में इतना बड़ा क्रान्तिकारी परिवर्तन किया जाये कि वह सर्वसाधारण के लिए सुलभ हो जावे। इसके लिए यदि वहां का जीवन स्तर कुछ निम्न भी करना पड़े, तो देश को कोई हानि होने वाली नहीं है। समाजवादी पद्धति के लिए यह अनिवार्य है कि 'एरिस्ट्रोक्रेटिक क्लास' बनाने वाले पब्लिक स्कूलों में क्रान्तिकारी परिवर्तन किया जाय। जो १०-१२ वर्ष का बालक प्रतिमास १०० १५० रु० सिर्फ अपने ऊपर व्यय करता है, वह किस तरह समाजवाद की भावना को अपना सकेगा? इस प्रश्न पर समाजवादी पद्धति के समर्थकों, शिक्षाशास्त्रियों व शासन अधिकारियों को विचार करना चाहिए।

विदेशी अर्थ-चर्चा

पिछले कुछ वर्षों से भारतवर्ष का विदेशी व्यापार बहुत तेजी से बदल रहा है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ब्रिटेन की अपेक्षा अब हम अन्य अनेक देशों से अपना व्यापार निरन्तर बढ़ाये जा रहे हैं। विशेषकर साम्यवादी

"मैं राज्य की बढ़ती हुई ताकत को बहुत भय के साथ देखता हूँ। यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से यह मालूम होता है कि वह शोषण को कम कर रही है, तथापि वस्तुतः इससे मानव जाति की बड़ी भारी हानि होती है, क्योंकि इससे मानव का वह व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है, जो सब प्रकार की उन्नति का मूल कारण है।"

—महात्मा गांधी

स्वतन्त्र साहस और उद्योग के सम्बन्ध में जनता को शिक्षित करने वाली एक अ-राजनैतिक संस्था।

Forum of Free Enterprise

स्वतन्त्र साहस संघ

२३५, डा० दादाभाई नौरोजी रोड, बम्बई-१

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

देशों से हमारा व्यापार पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ता जा रहा है। पंचवर्षीय योजना की पूर्ति में भी हम अनेक देशों में सहयोग अधिक से अधिक ले रहे हैं। हमारे विदेशी व्यापार में परिवर्तन का एक मुख्य कारण यह भी है कि अब हम बहुत सा नया सामान स्वयं तैयार करने लगे हैं। इसलिये हमारे आयात-निर्यात की वस्तुओं में पहले से बहुत अन्तर पड़ गया है।

इन नई परिस्थितियों और नये परिवर्तनों की जानकारी सम्पदा के पाठकों को देने के लिये यह विचार किया गया है कि समय-समय पर सम्पदा में विभिन्न देशों से आर्थिक सम्बन्ध और सहयोग का कुछ विस्तृत परिचय देने के लिये परिशिष्ट प्रकाशित किये जायें। इन परिशिष्टों में इन देशों से किये जाने वाले आयात-निर्यात व्यापार के साधन, उन देशों की आवश्यकतायें आदि के बारे में कुछ परिचय दिया जाये। साधारण अंकों में भी प्रायः विदेशों की आर्थिक चर्चा का स्तम्भ रखने का विचार है।

सूती मिलों के लिए वेतन मंडल

अनेक वर्षों से मजदूर समस्या का सबसे विवादास्पद प्रश्न वेतनों का रहा है। भारत सरकार ने दो वर्ष पूर्व यह मांग स्वीकार कर ली थी कि सरकार वेतनोंका दर निश्चित कर देगी, नये वर्षके प्रथम सप्ताह में भारत सरकार की विज्ञप्ति से मालूम होता है कि सूती वस्त्रोद्योग में वेतन निर्धारित करने के लिए एक बोर्ड नियत कर दिया गया है। लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष श्री एच० जीजी भाई की अध्यक्षता में यह बोर्ड तीन दृष्टियों से इस उद्योग के मजदूरों के लिए वेतन दर निर्धारित करेगा—

१—आर्थिक विकास की दृष्टि से उद्योग की आवश्यकताएं।

२—मानवीय न्याय की भावना।

३—अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए मजदूरों को प्रोत्साहन का ख्याल रखते हुए वेतनों के अन्तरों को संतुलित करना।

बोर्ड को यह भी कहा गया है कि वह उत्पादन के परिणाम के अनुसार वेतन की देयता को ध्यानमें रखे। किन्तु इस सिद्धान्त को सामने रखते हुए जहां न्यूनतम वेतन नियत किए जायें वहां यह भी ध्यान रखा जाय कि मजदूरों को अधिक समय तथा अधिक तेजी से काम न करना पड़े।

मजदूरों के वेतन निश्चित करने की समस्या बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। आजकल मजदूर और मिल-मालिक अपनी अपनी दृष्टि से इस प्रश्न पर विचार करते हैं और राष्ट्रीय हित की उपेक्षा की जाती है। इसलिए यह आवश्यक था कि एक दफा वास्तविक स्थिति, उद्योग की क्षमता, मजदूर की आवश्यकता और देश के हित आदि सब दृष्टियों से वेतनों के प्रश्न पर गम्भीर विचार किया जावे, और इस सम्बन्ध में एक बार निश्चित नीति निर्धारित कर ली जाये। इसके बाद वेतनों के प्रश्न पर औद्योगिक विवाद समाप्त हो जाने चाहिएं और औद्योगिक शांति के वातावरण में समस्त देश—को उद्योग के विविध अंगों को देश के औद्योगिक विकास में लग जाना चाहिए।

—

खेद-प्रकाशन

सम्पदा के सितम्बर अक्तूबर १९५६ के अंकों में एक हिन्दी साप्ताहिक 'हम लोग' का विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। सम्पदा के अनेक पाठकों ने उसे पढ़कर पत्र मंगाने के लिये रुपये भेजे। किन्तु वहां से कोई उत्तर न मिला और न अखबार मिलना शुरू हुआ। हमने उक्त पत्र को स्वयं भी पत्र लिखे लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। हमें खेद है कि सम्पदा में इस प्रकार का विज्ञापन छप गया और उससे हमारे पाठकों को बहुत परेशानी हुई। आगे से हम विज्ञापन छापने में अधिक सावधानी रखेंगे।

———

बम्बई में सम्पदा के प्रतिनिधि

श्री टी० एन० वर्मा
c/o उदय ट्रेडर्स
नेशनल हाउस,
Tullock Road, Bombay—1

नागपुर में सम्पदा के प्रतिनिधि

श्री रामकुमार भारतीय
गंजी पेट
नागपुर—1

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हमारी अर्थ व्यवस्था और समस्याएं

(श्री लक्ष्मी पत सिंहानिया)

कठिन परिस्थिति

प्रथम योजना के प्रारम्भ के समय की अपेक्षा लगभग दस महीने पूर्व आर्थिक स्थिति स्पष्टतया अच्छी थी। किंतु इन दस महीनों में, अर्थात् दूसरी योजना के प्रथम वर्ष में, कुछ चिन्ताजनक गति-विधि देखने में आई। थोक कीमतों की सामान्य अनुक्रमणिका जो मई १९५६ में तनिक उच्च स्तर पर ही रही, कुछ स्थिर हो चली थी, फिर ऊँची उठने लगी और वह दिसम्बर १९५६ में ४२८·८ अङ्क तक पहुँच गई, जब कि सन् १९५५ में उच्चतम अंक ३६८·२ और सन् १९५४ में ४०२·६ था। चालू वर्ष में यद्यपि उसकी गति तनिक नीचे की ओर रही, किन्तु फरवरी में सामान्य अनुक्रमणिका का अङ्क ४२४·८ था। मुख्यतः खाद्य पदार्थों की कीमतों में होने वाली वृद्धि के कारण ही यह ऊपर की ओर गति हुई। इसका मुख्य कारण सन् १९५३-५४ से खाद्यान्न के उत्पादन में होने वाली कमी है, जिसके कारण काफी बड़ी मात्रा में विदेशों से खाद्यान्न का आयात करना पड़ा है। इसके विपरीत, औद्योगिक उत्पादन में सतत् वृद्धि होती चली गई। इस उत्पादन-वृद्धि में अधिकतर उद्योगों का योग रहा है।

किन्तु व्यवसाय के लिए वित्त की कमी तीव्रता के साथ अनुभव की जा रही है। न केवल दीर्घकालीन विनियोजन के लिए रुपया सहज ही उपलब्ध नहीं हो रहा है, बल्कि काम चलाऊ पूंजी की भी न्यूनता है। हमारी स्टर्लिंग निधि में २५ करोड़ रुपया प्रति मास के हिसाब से कमी हो रही है और हमारी यह निधि उस स्तर तक कम हो चुकी है जो हमारी मुद्रा के संरक्षण के लिए आवश्यक न्यूनतम स्तर से कुछ ही अधिक है। योजना आयोग ने अनुमान लगाया है कि पांच वर्ष के समय में कुल घाटा १,१०० करोड़ से कुछ अधिक ही रहेगा। यह आशा की गयी थी कि स्टर्लिंग निधि में से औसतन ४० करोड़ रुपया वार्षिक निकाल कर, ८०० करोड़ रुपया पांच वर्षों में विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त कर और निजी क्षेत्र में १०० करोड़ रुपया विदेशी पूंजी के प्रत्याशित आगमन से इस घाटे की पूर्ति हो जाएगी। गत दस महीनों की अकल्पित घटनाओं के कारण विदेशी विनिमय के घाटे को पूरा कर लेने की यह सुचारु योजना गड़बड़ा गई है, हालांकि इन घटनाओं के बारे में सरकारी प्रवक्ताओं ने एक समय कहा था कि वे 'योजनानुसार' हैं। हम अपनी स्टर्लिंग निधि से २०० करोड़ रुपये से कुछ अधिक निकाल चुके हैं। हमारी विदेशी सुरक्षित निधि में इस शीघ्रगामी कमी का मुख्य कारण यह है कि हमने लोहा और इस्पात तथा मशीनरी और कारखानों की दूसरी सामग्री का अधिक मात्रा में आयात किया है।

मेरे विचार में ये कठिनाइयां विकास की छिपी हुई शक्तियों का ही एक पहलू हैं, जो मानो योजना के सावधानी के साथ निर्मित ढांचे को तोड़ कर मैदान में आने की कोशिश करती हैं। उनके कारण न तो हमको प्रथम योजना को कार्यान्वित करने में प्राप्त सफलता की ही दृष्टि से ओझल करना चाहिए और न हमको अपनी आर्थिक प्रणाली की क्षमता और स्थिरता की ओर ही उदासीन होना चाहिए। मैं अनुभव करता हूँ कि जिन समस्याओं का हमें आज सामना करना पड़ रहा है, वे उन मूलभूत प्रश्नों से उत्पन्न हुई हैं, जिनको कि हमें हल करना होगा। यह अत्यन्त महत्व की बात है कि सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों का लक्ष्य मूलभूत और तात्कालिक, दोनों प्रकार की जरूरतों को एक साथ पूर्ति करना होना चाहिए। आंशिक दृष्टिकोण अस्थायी रूप से सफल भी हो जाए तो भी समस्याओं को मुश्किल और पेचीदा बना देगा। अतः मैं अब हमारी तात्कालिक समस्याओं को प्रभावित करने वाले आर्थिक विकासके प्रधान अंगों की चर्चा करूँगा।

हमारी कोशिश यह है कि हमारी राष्ट्रीय आय जो इस समय ११,००० करोड़ रुपये से कुछ कम है, सन् १९७६ तक २७,००० करोड़ रुपये से कुछ अधिक हो जाए। यद्यपि इसका अर्थ यह होगा कि राष्ट्रीय आय दुगनी से कुछ अधिक हो जाएगी; किन्तु जनसंख्या में होने वाला निरन्तर वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति की आय दुगुनी ही हो सकेगी। इसलिए राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाने की कोशिश के साथ-साथ हमको जनसंख्या वृद्धि की इस समस्या पर भी काफी ध्यान

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

देना चाहिए। यह एक ऐसी समस्या है, जिसकी बार-बार चर्चा होती है, किन्तु जिसका सन्तोषजनक हल अभी मिल नहीं सका है।

बीस वर्ष में प्रति व्यक्ति की औसत आय को दुगुनी करने के लिए योजना आयोग के हिसाब के अनुसार कुल वास्तविक विनियोजन की मात्रा मोटे अर्थों में छः गुनी से अधिक होनी चाहिए। वास्तविक विनियोजन और राष्ट्रीय आय का अनुपात जो आज ७ प्रतिशत से कुछ अधिक है, १७ प्रतिशत हो जाना चाहिए। यूरोप के कतिपय देशों में जैसे कि जर्मनी, नीदरलैंड, नार्वे आदि में वास्तविक पूंजी निर्माण की मौजूदा औसत करीब २० प्रतिशत या इससे कुछ अधिक है। कनाडा में यह लगभग १९ प्रतिशत है। जापान में, जो उद्योगीकरण की दौड़ में गत शताब्दी के अन्त में ही शामिल हुआ, पूंजी विनियोजन की दर सन् १९१३ और सन् १९३९ के बीच १६ से २० प्रतिशत के बीच रही और हाल के वर्षों में २० और २५ प्रतिशत के बीच है। कुछ अधिक उन्नत अर्थ-व्यवस्था वाले देशों में, जैसे कि अमरीका, ब्रिटेन और फ्रांस में वास्तविक पूंजी निर्माण की दर लगभग १० प्रतिशत या इससे कुछ कम रही है। इन अंकों से पता चलता है कि सन् १९७६ तक २७ प्रतिशत वास्तविक पूंजी विनियोजन का हमारा लक्ष्य पूरा होना कठिन नहीं होना चाहिए।

सरकारी नीति

बचत की राशियों का विस्तार सरकार की वित्तीय और मुद्रा संबंधी योग्य नीतियों के अनुसरण पर निर्भर करता है। उद्योग और व्यापार के लिए पर्याप्त वित्त की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकारी करों का स्तर असाधारण रूप से ऊँचा नहीं होना चाहिए और रुपया उधार मिलने पर कठोर प्रतिबंध नहीं लगाए जाने चाहिए। यह सही है कि मुद्रास्फीति के दबावों को, जब कभी वे प्रकट हों, नियंत्रित करना होगा। किन्तु मूल्य वृद्धि एक लक्षण है और उसकी चिकित्सा यह है कि उत्पादन बढ़ाया जाए। साथ ही यह भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि राष्ट्रीय आय और व्यय में वृद्धि होने के साथ-साथ कीमतों के स्तर में कुछ वृद्धि होना अनिवार्य है। गत दो वर्षों का अनुभव यह बताता है कि उधार रुपये की तंगी और निरोधात्मक सरकारी नीतियों का लक्ष्य जितना कीमतों की वृद्धि को रोकता रहा है, उतना उद्योगों के विस्तार और उसके फलस्वरूप उत्पादन वृद्धि की ओर नहीं रहा। करों का वर्तमान भारी बोझ भी नवीन पूंजी विनियोजन में बाधक हो रहा है। वह अकेला ही, (और संकोचशील मुद्रानीति के साथ और भी अधिक) पूंजी बाजार के स्वस्थ विकास में बाधा डाल सकता है। आज यह स्थिति है कि हमारे यहां सुविकसित पूंजी बाजार नहीं है। उसका विस्तार विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है पर मौजूदा कर-प्रणाली उसके रास्ते में रुकावट डालती है। इस कर-प्रणाली के साथ कुछ और भी घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं—व्यक्तिगत आय पर कर की ऊँची दर, पूंजी लाभकर, कम्पनियों पर डिविडेंड (लाभांश) कर, बोनस शेयरों (हिस्सों) पर कर और वह योजना जिसके अनुसार कम्पनियों को अपने मुनाफों और संचित निधि का एक भाग सरकार के पास जमा कराना होता है। ऐसी एजेंसियां बहुत नहीं हैं जो लोगों की बचत को उत्पादक योजनाओं में लगाने का काम करती हैं। जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया है, जिसे निजी कम्पनियों ने सफलतापूर्वक चलाया था। लोगों की बचत को भली प्रकार संग्रह करने की कसौटी पर परखें तो इस निर्णय के औचित्य में शंका हुए बिना नहीं रह सकती, भले ही यह कदम किसी एक विचार-धारा से प्रभावित होकर उठाया गया हो। जो नई वित्तीय संस्थाएं हाल में स्थापित की गई हैं, उन्होंने अभी तक उद्योगों की बढ़ती हुई वित्तीय सावश्यकताओं के प्रति सक्रिय सतर्कता का परिचय नहीं दिया है। औद्योगिक वित्त निगम, औद्योगिक ऋण और विनियोग निगमों जैसी संस्थाओं को न केवल उनके साधनों को बढ़ा कर पुष्ट किया जाना चाहिए बल्कि उनमें उद्योग और व्यापार की सेवा करने की इच्छा और सामर्थ्य भी पैदा की जानी चाहिए।

खपत बढ़ाओ

हमारी जैसी कम विकसित अर्थ-व्यवस्था में जितनी समस्या बचत राशियों का विस्तार करने की है, उतनी ही खपत बढ़ाने की भी है। उद्योग और व्यापार का विस्तार तभी टिक सकता है, जब कि औद्योगिक उत्पादनों के लिए विस्तृत बाजार भी हो। विकास की विविध योजनाओं पर होने वाले सरकारी व्यय के परिणामस्वरूप काफी मात्रा में रुपया

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कृषि क्षेत्र में जा रहा है। कृषि उत्पादन में होने वाली वृद्धि से इस प्रवृत्ति को और भी बल मिलेगा। भारत में इस समय फसलों की उपज बहुत कम होती है। चावल (धान) की प्रति एकड़ औसत उपज सन् १९५५ में सिर्फ ११३५ पौण्ड थी, जबकि दक्षिण पूर्व एशिया के कम विकसित देशों में भी उसका औसत कहीं अधिक है। फारमोसा में प्रति एकड़ चावल की उपज २६०० पौण्ड, बर्मा में १४५० पौण्ड और थाईलैंड में १२२५ पौण्ड है। यूरोप के देशों में, जैसे इटली में उपज की औसत ४५०० पौण्ड प्रति एकड़ जितनी ऊँची है। जैसे-जैसे सिंचाई योजनाएं पूरी होंगी और खेती के सुधरे हुए तरीके काम में लाये जाएंगे तथा रासायनिक खादों का प्रयोग होगा, वैसे-वैसे भारत में भी फसलों की उपज बढ़ेगी। सरकार की यह कोशिश होनी चाहिए कि अच्छे किस्म के बीज काम में लाये जावें; उसे रासायनिक खादों के लाभों से किसानों को परिचित कराना चाहिए और उनको उचित मूल्य पर उन्हें उपलब्ध करना चाहिए। जब तक कृषि की पैदावार नहीं बढ़ती, औद्योगिक उत्पादनों के लिए बाजार भी संकुचित ही रहेगा और साथ ही किसानों की आय और उनका जीवन-स्तर वर्तमान के समान ही नीचा रहेगा। किन्तु कृषि की पैदावार बढ़ाना ही काफी नहीं होगा। ग्रामीण जनता को यह भी बताया जाना चाहिए कि उनके उपभोग के स्वरूप में परिवर्तन होने से उनको कितना लाभ और आराम मिलेगा। किसान अपनी परम्परागत भावना के अनुसार अपना रुपया सोना-चांदी में या इसी प्रकार अनुत्पादक संग्रह में फंसाना पसंद करता है। सरकार आय से अधिक खर्च कर रही है और उसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र में जो रुपया पहुंच रहा है, उसके कारण सोने की मांग बढ़ गई है। चांदी की कीमत सन् १९५४-५५ में औसतन् रु० १५९/३/९ थी; सन् १९५६-५७ के प्रथम नौ महीनों में उसका औसत रु० १७३/९/१ रहा। सोने की कीमतों का रुख भी गत तीन वर्षों में वृद्धि की ओर ही रहा है। सन् १९५४-५५ में उसका औसत रु० ८९/२/४ था तो १९५६-५७ के प्रथम नौ महीनों में रु० १०१/१५/३ रहा। सोने की कीमतों के रुख से पता चलता है कि लोगों की बढ़ी हुई आमदनी अनुत्पादक कामों में लग रही है। इस वृत्ति को रोका जाना चाहिए और रुपय का उत्पादक कामों में विनियोजन होना चाहिए या वह विविध प्रकार के उपभोग्य पदार्थों पर खर्च होना चाहिए।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में जहां तक संभव हो, बैंकों में खाते खोलने की आदत डालना जरूरी होगा। स्टेट बैंक आफ इण्डिया का मुफस्सिल में अपनी शाखाएं खोलने का कार्यक्रम है। मुझे खुशी होगी, यदि स्टेट बैंक शाखाएं खोलने का काम जोरों से प्रारम्भ कर दे। किन्तु मैं यह आश्वासन चाहूँगा कि इसके फलस्वरूप शहरी क्षेत्र में वित्त की उपलब्धि में कोई कमी

प्रकृति का अमूल्य वरदान

भारतीय अणुशक्ति विभाग ने, उत्तर पूर्वी भारत में किसी स्थान पर हाल में ही रेडियो धर्मी खनिजों के विशाल भंडार का पता लगाया है। ऐसा माना जा रहा है कि संभवतः यह भंडार विश्व का विशालतम भंडार हो।

अब तक की खोज के अनुसार, इन खानों में ३३ लाख टन से ऊपर कच्ची धातु का भंडार है। इसमें से ३ लाख टन थोरियम, और १० हजार टन यूरेनियम है। इसमें ८ करोड़ टन के लगभग लेगनाइट भी है। अभी आशा है कि अधिक खोज करने से वर्तमान अनुमान का दुगुना भंडार उपलब्ध हो सकेगा।

इन रेडियो धर्मी खनिजों की अणु-कार्य में बड़ी उपयोगिता है। इनकी प्राप्ति होना वरदान ही माना जाना चाहिए। पिछले ही वर्ष बम्बई में अणु शक्ति-विकास का कार्य आरम्भ किया गया है। अवश्य ही अब उसकी गति तीव्र हो जायेगी। इन खनिजों का संभवतः बम्बई के आस पास मिलना भी महत्वपूर्ण है।

अब तक त्रावणकोर-कोचीन के समुद्र तटीय प्रसिद्ध भंडार को विश्व का महत्त्वपूर्ण और सबसे अधिक समृद्ध भण्डार माना जाता रहा है लेकिन अब इन उपलब्ध खनिजों की मात्रा इससे भी अधिक होगी।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नहीं पड़ने दी जाएगी। निस्संदेह यह अच्छी बात होगी, यदि स्टेट बैंक देहाती क्षेत्रों की बचत को अपनी ओर आकर्षित करेगा और इस प्रकार जमा होने वाले रुपये को कृषि परिचालनों के लिए सुलभ करेगा। किन्तु हमें शहरी क्षेत्रों को हानि पहुंचाकर शहरों से रुपया ग्रामीण क्षेत्रों को नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि अब भी औद्योगिक और व्यावसायिक हल्कों में बड़ी भारी वित्तीय तंगी अनुभव की जा रही है। उद्देश्य यह होना चाहिए कि बचत का संग्रह किया जाए और उसका आर्थिक प्रणाली को गति देने में उपयोग किया जाए। लोगों के लिए अधिकाधिक उपभोग्य वस्तुएँ सुलभ की जानी चाहिएं। वास्तविकता यह है कि मूलभूत उपभोग्य वस्तुएं जैसे कपड़ा आदि जितना चाहिए उतने खुले रूप में उपलब्ध नहीं हो रही हैं। इसके दो कारण हैं। एक तो यह कि संभवतः उत्पादन की छोटी इकाइयों को संरक्षण देने के लिए संगठित औद्योगिक प्रयासों को अपने विस्तार और नवीनीकरण के कार्यक्रमों को धीमी गति से चलाने की नीति अपनाई गई है। दूसरा कारण उत्पादन-करों का लागू करना है, जिनकी दरें उपभोक्ताओं अथवा उद्योग की सामर्थ्य से ज्यादा ऊँची है।

आर्थिक विकास विभिन्न परिस्थितियों पर निर्भर करता है और उनमें सभी विशुद्ध रूप से आर्थिक नहीं होतीं। आर्थिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि भौतिक रहन-सहन को अच्छा बनाने की प्रेरणा होनी चाहिए। अधिक वस्तुओं और सेवाओंका उपभोग होना चाहिए और नई एवं विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। युगों पुराने रिवाजों का, खासकर भारत में जहाँ संयम और सादगी को बड़ा महत्व दिया जाता है, आधुनिक आर्थिक विकास से मेल नहीं बैठ सकता। इसी प्रकार, जब आमदनी थोड़ी हो, तो विलास व आराम की वस्तुओं को प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए। आर्थिक विकास की कोई योजना इन बुनियादी तथ्यों की उपेक्षा नहीं कर सकती है।

प्राणवान जन सहयोग

हमारे विकास की वर्तमान अवस्था में शायद सबसे अधिक जरूरी है उत्साह और उमंग, जो विशिष्ट वर्ग और आम जनता दोनों में ही पैदा किया जाना चाहिए; ताकि लोग बाढ़-नियंत्रण और पानी की निकासी की स्थानीय योजनाओं, सड़कों और नहरों के निर्माण और इसी प्रकार दूसरी अनेक प्रवृत्तियों में, जिनसे कि लोगों की रहन-सहन की परिस्थितियों में सुधार होगा, सक्रिय भाग ले सकें। यह नया वातावरण बनाने का काम करते हुए हमको सामाजिक पूंजी का निर्माण करना होगा। समाजवादी ढंग की समाज व्यवस्था का जो लक्ष्य देश ने स्वीकार किया है, उसके लिए अस्पतालों और मकानों, सड़कों और नहरों, स्कूलों और कालेजों आदि के रूप में सामाजिक पूंजी की आवश्यकता होगी। किन्तु गत शताब्दी का एक सबसे चिन्ताजनक रूप यह रहा है कि स्थानीय संस्थाओं और संगठनों को, जो कभी भी अधिक प्राणवान् नहीं रहे, आवश्यक मात्रा में परिपुष्ट नहीं किया गया। आज की यह तात्कालिक आवश्यकता है कि देश में स्वशासित संस्थाओं का, जो सक्रिय और प्राणवान् हों, जाल बिछा दिया जाय। सत्ता और दायित्व के व्यवस्थित विकेन्द्रीकरण के द्वारा ही वांछित प्रकार के परिवर्तन लाना संभव होगा। केन्द्रित अर्थव्यवस्था में निहित खतरों और कठिनाइयों को हम सब अच्छी तरह जानते हैं। अपने लोकतंत्री आदर्शों के अनुसार, हमको समाजवादी ढंग की समाज व्यवस्था की व्याख्या इस तरह करनी चाहिए कि वह एक प्रकार का म्युनिसिपल समाजवाद होगा, जो लोगों की नागरिक सुविधाओं में वृद्धि करेगा। यदि राजनीतिक समानता का आर्थिक स्वतन्त्रता के बिना कोई अर्थ नहीं है, तो आर्थिक समानता का भी उन सामाजिक सेवाओं और दूसरी सुविधाओं के अभाव में, जिन से जीवन जीने लायक बनता है, कोई अर्थ नहीं हो सकता।

अनुचित केन्द्रीयकरण

जब हमने व्यापक आर्थिक विकास का लक्ष्य स्वीकार किया है, तो सरकारी नीतियां ऐसी होनी चाहिएं कि व्यवसायों के व्यापक विकेन्द्रीकरण के रास्ते में रुकावट न पड़े, बल्कि उसे प्रोत्साहन मिले। आज हमारे देश में व्यवसाय के विस्तार की शक्ति और प्रेरणा थोड़े से परिवारों और लोक-समूहों के हाथों में सीमित रही है। आर्थिक

(शेष पृष्ठ २३३ पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारत में सहकारिता की प्रगति

प्रो० लक्ष्मीनारायण नाथूरामका, एम. ए., बी. काम

आज भारत में प्रजातान्त्रिक समाजवाद का प्रयोग चल रहा है। समाजवादी ढंग के समाज की रचना में सहकारिता का प्रमुख स्थान होता है। इसीलिए सर्वत्र सहकारिता ही चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत की दोनों पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता के आधार पर समस्त ग्रामीण जीवन को पुनर्गठित करने के कार्यक्रम रक्खे गये हैं। सरकार ने सहकारिता की सफलता के लिए एक प्रगतिशील नीति अपनाई है और आशा है भारत में आर्थिक नियोजन की सफलता में भी यह नीति बहुत सहायक होगी। भविष्य में सहकारिता ही भारत की अर्थ-व्यवस्था को घाटे की दशा से लाभ व बचत की दशा में बदलने में सफल हो सकेगी।

आन्दोलन की संख्यात्मक प्रगति प्रभावपूर्ण

सहकारिता आन्दोलन को प्रारम्भ हुए हमारे देश में पचास वर्ष से भी ऊपर हो चुके हैं। इस अवधि में सहकारी संस्थाओं की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है जिससे प्रशासन व संगठन का कार्य बढ़ गया है। लेकिन इन संस्थाओं ने अभी तक कोई संतोषप्रद व ठोस कार्य जनता के समक्ष नहीं रक्खा है। अतः गुणात्मक प्रगति सराहनीय नहीं कही जा सकती। इसका क्या कारण है? सहकारिता आन्दोलन की असफलता की वैज्ञानिक जांच अखिल-भारतीय ग्रामीण-साख-सर्वेक्षण-समिति ने अपनी रिपोर्ट में की है जिसमें आन्दोलन को सफल बनाने के सम्बन्ध में भी सुझाव दिये गये हैं। उन सुझावों पर भारत सरकार कार्य कर रही है। संख्यात्मक प्रगति के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:—

	कुल संख्या	
	३० जून, १९५४	३० जून १९५५
राज्य सहकारी बैंक या शीर्ष बैंक	२२	२४
केन्द्रीय सहकारी बैंक (बैंकिंग यूनियन सहित)	४९९	४८५
प्राथमिक सहकारी साख समितियाँ	१,२६,९५४	१,४३,३२०

१९५४-५५ में जम्मू-काश्मीर व भोपाल में दो राज्य सहकारी बैंक और खुल गये थे। इस प्रकार अब तक सब "क" व "ख" श्रेणी के राज्यों में राज्य सहकारी बैंक काम करने लग गये हैं और "ग" श्रेणी के ६ राज्यों में भी ये बैंक कार्य कर रहे हैं। पंजाब, हैदराबाद और मैसूर में स्थापित होने वाले नये राज्य सहकारी बैंकों में राज्य सरकारों ने हिस्सा पूंजी में विशेष भाग लिया है। केन्द्रीय सहकारी बैंक (बैंकिंग यूनियन सहित) पहले से १४ कम हो गये हैं क्योंकि कई राज्यों में केन्द्रीय बैंकों के अभिनवीकरण की नीति अपनाई गई है।* हैदराबाद में केन्द्रीय बैंकों की संख्या ४१ से २८ तक पहुँच गई और हिमाचल प्रदेश में ४ बैंकिंग यूनियन, राज्य सहकारी बैंक में मिला दिये गये हैं। प्राथमिक सहकारी साख समितियों के सदस्यों की संख्या जून, १९५३ में लगभग ५८.५० लाख थी जो एक साल बाद बढ़ कर लगभग ६५.६५ लाख हो गई है।

१९५४-५५ के अंत में केन्द्रीय भूमि बंधक बैंकों की संख्या ९ थी और प्राथमिक भूमि बंधक बैंकों की संख्या २९२ थी।

सहकारिता आन्दोलन के सम्बन्ध में सब से बड़ी उल्लेखनीय बात यह है कि अभी तक यह साख के क्षेत्र तक ही सीमित रहा है। इसलिए गैर-साख क्षेत्रों में इसकी प्रगति बहुत असंतोषप्रद रही है। गैर-साख सहकारी संस्थाओं की स्थिति ३० जून, १९५५ को इस प्रकार थी:—

राज्य	गैर-साख समितियां	६०
केन्द्रीय	,, ,, ,,	२,५९९
कृषि प्राथमिक	,, ,, ,,	३०,१९७
गैर-कृषि प्राथमिक	,, ,, ,,	२४,२६६

उपर्युक्त आँकड़ों से कोई यह समझ सकता है कि सहकारिता आन्दोलन तो बहुत व्यापक हो चुका है और बहुत काम कर रहा है। लेकिन वास्तविक स्थिति इसके विपरीत है। साख-सर्वेक्षण-समिति का तो यह निष्कर्ष रहा है कि सहकारिता आन्दोलन भारत में असफल हुआ है। अभी तक साख के क्षेत्र में भी इसकी सफलता नगण्य रही

* The Ninth Year of Freedom p. 99. (All India National Congress Publication)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

है। कुल ग्रामीण साख की पूर्ति में सिर्फ ३.९ प्रतिशत सहकारी समितियों से प्राप्त हुआ है और लगभग ७० प्रतिशत साख की पूर्ति के लिये कृषक महाजन पर आश्रित रहा है। बहुत कम ग्रामीण ही हो सहकारी समितियों के सदस्य पाये हैं। देहाती जनता पर अब भी महाजन का प्रभाव विद्यमान है।

सहकारी आन्दोलन की असफलता के कारण

इस आन्दोलन की सबसे कमजोर कड़ी प्राथमिक सहकारी साख समिति रही है। उसकी सदस्य संख्या सीमित रही है। इन्होंने किसानों की मध्य-कालीन की आवश्यकता की पूर्ति नहीं की है। इनको वित्त के लिए बाहरी संस्थाओं के सहारे रहना पड़ा है। इसलिये ये किसान की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण ढंग से पूर्ण नहीं कर सकी हैं। शुरू में ये एक उद्देश्यीय थी, इसलिए कृषक को आकर्षित करने में असफल रहीं। इसके अतिरिक्त अकुशल प्रबन्ध, ऋण देने में देरी, ब्याज की ऊँची दरें, ऋणी पर नियंत्रण का अभाव आदि कारणों से भी प्राथमिक साख समितियाँ असफल हुईं।

सहकारिता आन्दोलन की असफलता में महाजन की कट्टर प्रतिस्पर्द्धा व विरोध ने सब से बड़ा भाग लिया। सरकार का दृष्टिकोण भी पहले प्रगतिशील नहीं था क्योंकि वह नियंत्रण व निर्देशन में ही विश्वास रखती थी और सक्रिय साझेदारी व सहयोग से दूर रहती थी। प्राथमिक समितियों को कहीं से भी सहयोग, संरक्षण व सहानुभूति प्राप्त नहीं हुई। सरकार, व्यापारिक बैंक व बीमा कम्पनियों का व्यवहार हमेशा असहानुभूतिपूर्ण रहा क्योंकि इसकी मनोवृत्ति 'शहरी' बनी रही। ऐसी परिस्थिति में सहकारी आन्दोलन की सबसे कमजोर कड़ी प्राथमिक सहकारी साख समिति ही बनी रही।

भावी नीति की रूपरेखा

साख सर्वेक्षण समिति के सुझावों को भारत सरकार ने मान लिया है और उन्हीं के आधार पर नई सहकारी नीति प्रारम्भ की गई है। भावी नीति ज्यादा उदार और रचनात्मक हैं और भूतकाल की नीति से बहुत अच्छी और प्रगतिशील है। नई नीति की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:—

(१) सरकार का सहकारिता में साझेदार हो जाना,

(२) साख के अलावा बिक्री, परिनिर्माण (Processing) व गोदाम आदि के सहकारिता के प्रयोग,

(३) स्टेट बैंक की स्थापना,

(४) प्रशिक्षित कर्मचारियों की व्यवस्था।

इनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है:—

(१) पहले सहकारिता आन्दोलन सरकार द्वारा जनता पर ऊपर से लाद दिया गया था इसलिये सहकारिता जन आन्दोलन न हो कर सरकारी आन्दोलन हो गया था। सरकार सिर्फ ऊपरी देख-रेख करती थी। इससे यह आन्दोलन निस्तेज व निष्प्राण हो गया था। भविष्य में सरकार इस आन्दोलन को हर प्रकार से मदद करेगी। सहकारिता एक राज्यीय विषय है। भावी नीति में सहकारी संस्थाओं को राज्य सरकारों की तरफ से वित्तीय सहायता मिल सकेगी। इसके लिए रिजर्व बैंक ने निम्न दो कोष स्थापित किये हैं जिससे राज्य सरकारें अपना भावी उत्तरदायित्व निभा सकेंगी।

राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घ कालीन) कोष में रिजर्व बैंक ने शुरू में १० करोड़ रुपये की धन-राशि दी है और १९५९ से आगे प्रतिवर्ष ५ करोड़ रुपये इस में जुड़ते जायेंगे जिससे कि १९६० तक इसकी पूंजी ३५ करोड़ रुपये हो जाएगी। इस कोष में से राज्य सरकारों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान किये जायेंगे जिससे वे सहकारी संस्थाओं की पूँजी में हिस्सा ले सकें। इस कोष में से ही भूमि-बंधक बैंकों के ऋण-पत्र भी खरीदे जा सकेंगे।

राष्ट्रीय कृषि-साख (स्थायीकरण) कोष में रिजर्व बैंक ५ साल तक प्रति वर्ष १ करोड़ रुपये की धनराशि देगा। इस कोष से रिजर्व बैंक राज्य सहकारी बैंकों के अल्पकालीन ऋणों को मध्य-कालीन ऋणों में बदल सकेगा। लेकिन यह उसी स्थिति में होगा जब कि राज्य सहकारी बैंक अकाल, बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोपों के कारण ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं।

(२) साख के अलावा सहकारिता के अन्यत्र प्रयोग:—

अभी तक सहकारिता आन्दोलन एकाँगी विकास कर पाया था। साख के अलावा अन्य क्षेत्रों में इसकी प्रगति नहीं के बराबर थी। भविष्य में इस आन्दोलन को व्यापक बनाया जायगा और विविध आर्थिक क्रियाएँ इसके अन्तर्गत लाई जायेंगी। राष्ट्रीय सहकारिता विकास व भण्डार-गृह मण्डल (Natinal Co-operative Development & Warehousing Board) की स्थापना हुई

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उद्देश्य से की गई है। इसके अन्तर्गत अखिल भारतीय भण्डार-गृह निगम (All India Warehousiug Corporation) व स्टेट वेयर हउसिंग कम्पनियाँ काम करेंगी। उपर्युक्त मण्डल के दो काम होंगे, (क) सहकारी बिक्री, परिनिर्माण (Processing), कुटीर व्यवसाय आदि को प्रोत्साहन देना। (ख) गोदाम व भण्डार-गृह बनवाना जिनमें कृषि की उपज संग्रहीत हो सके। उपर्युक्त दोनों कार्यों के लिए दो अलग अलग कोषों की व्यवस्था की गई है, पहला राष्ट्रीय सहकारिता विकास कोष और दूसरा भण्डार-गृह विकास कोष। राष्ट्रीय भण्डार गृह विकास कोष में शुरू में ५ करोड़ रुपये दिये जायेंगे और सालाना अनुदान दोनों कोषों को ५ करोड़ रुपये के दिये जायेंगे। जिसका अलग अलग वितरण राष्ट्रीय सहकारिता विकास व भराडार-गृह बोर्ड पर निर्भर करेगा।

(३) स्टेट बैंक आफ इण्डियाः—दिसम्बर १९५४ में भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री देशमुख ने लोकसभा में इम्पीरियल बैंक पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण स्थापित करके स्टेट बैंक बनाने की घोषणा की। बाद में मई १९५५ में स्टेट बैंक आफ इन्डिया एक्ट पास हो गया। स्टेट बैंक ने १ जुलाई १९५५ से कार्यारम्भ कर दिया है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण वित्त में मदद देना है। लेकिन यह साधारण व्यापारिक बैंकों के कार्य भी कर सकेगा। यह सुदृढ़ बैंकिंग सिद्धान्तों पर चल कर अपने कार्य का सम्पादन करेगा। इसका देश के द्रव्य-बाजार पर पर्याप्त प्रभाव पड़ेगा।

स्टेट बैंक ने प्रथम ५ वर्षों में ४०० अतिरिक्त शाखाएँ खोलने का कार्यक्रम रक्खा है। 'एकीकरण व विकास कोष' में से इन पर होने वाली क्षति की पूर्ति की जायेगी। इस कोष में रिजर्व बैंक व सरकार द्वारा ऋण दिया जायगा। स्टेट बैंक की निर्गमित (Issued) पूँजी ५.६२५ करोड़ रुपये है। इसका बड़ा भाग सरकार व रिजर्व बैंक के पास होगा। बैंक छोटे पैमाने के उद्योगों को भी अल्पकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इसमें राज्यों से सम्बन्धित बड़े बैंकों का विलयन भी भविष्य में किया जायगा जिससे इसके साधन बहुत बढ़ जायेंगे। अभी यह प्रश्न विचाराधीन है।

भावी योजना में प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिये अनुमान लगाया गया है कि लगभग २५,००० व्यक्तियों को ग्रामीण साख, बिक्री, व परिनिर्माण एवं गोदामों के कार्यों के संचालन में आवश्यकता पड़ेगी। १९५३ में केन्द्रीय सहकारी प्रशिक्षण समिति ने सहकारिता कर्मचारियों के प्रशिक्षण का कार्य सम्हाला है। पूना में सहकारी कालेज अन्य कर्मचारियों को ६ महीने का कोर्स देने की व्यवस्था करता है। पूना, राँची, मेरठ, मद्रास व इन्दौर में पाँच प्रादेशिक सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इन केन्द्रों में मध्यम श्रेणी के कर्मचारियों को शिक्षा दी जायगी। ८ विशेष केन्द्र ४,००० खण्ड स्तर पर काम करने वाले सहकारी अफसरों को शिक्षा देने के लिये स्थापित किये गये हैं। इनकी आवश्यकता राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में होगी।

द्वितीय योजना में सहकारिता के लक्ष्य

उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि सहकारी आन्दोलन भविष्य में प्रगति करेगा और सहकारी संस्थाओं को वित्तीय कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। द्वितीय योजना काल में प्राथमिक सहकारी समितियों को सफल बनाने की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जायगा। नई

नयापथ

(प्रगतिशील मासिक पत्रिका)

सम्पादक—

यशपाल ❀ शिव वर्मा ❀ राजीव सक्सेना

स्तम्भ—

- चक्कर क्लब
- साहित्य समीक्षा
- संस्कृति प्रवाह
- सिनेमा
- लेख
- कहानियां
- कविताएं।

"नयापथ" का जनवरी अंक 'लोक साहित्य' विशेषांक है। इसका सम्पादन हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक श्री श्रीकृष्णदास कर रहे हैं। ग्राहकों को यह अङ्क साधारण मूल्य में ही दिया जाएगा।

वार्षिक ६) एक प्रति ।।)

पता :—

२२ कैसर बाग लखनऊ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

समितियाँ बड़े आकार की होंगी। प्रत्येक समिति के ५०० सदस्य होंगे और प्रत्येक सदस्य का दायित्व उसके द्वारा लगाई हुई पूंजी का ५ गुना होगा। प्रत्येक सदस्य की न्यूनतम हिस्सा-पूँजी १५,००० रुपये होगी और उसका सालाना व्यापार लगभग १॥ लाख रुपये का होगा।

सहकारिता के भावी विकास के निम्न लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं:—

१ साख

बड़े आकार की समितियाँ १०,४००

अल्पकालीन साख १५० करोड़ रुपये

मध्यकालीन ,, ५० ,, ,,

दीर्घकालीन ,, २५ ,, ,,

२ बिक्री व परिनिर्माण समितियाँ

प्राथमिक बिक्री समितियाँ १,८००

सहकारी चीनी फैक्टरियां ३५

,, काटन जिनिंग कारखाने ४८

अन्य उत्पादक समितियाँ ११८

३ भण्डार व माल गोदाम

केन्द्रीय राज्य निगमों के गोदाम ३५०

सहकारी बिक्री समितियों के गोदाम १,५००

बड़े आकार की समितियों के गोदाम ४,०००

उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति से सहकारी साख समितियों की सदस्य संख्या लगभग १॥ करोड़ हो जायगी।

सामुदायिक विकास व राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में सहकारी आन्दोलन के बढ़ाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। ग्राम-पंचायतों के समुचित विस्तार व विकास से भी इस आन्दोलन पर प्रभाव पड़ेगा। भूमि-सुधार व सहकारिता का भी निकट सम्बन्ध है। सहकारिता की सफलता ग्रामीण जनता के सहयोग पर निर्भर करती है। सहकारिता को हमें संकुचित व संकीर्ण अर्थ में नहीं लेना चाहिये। यह एक आर्थिक संगठन का तरीका ही नहीं है बल्कि जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण है। यही व्यापक दृष्टिकोण हमें अपनाना चाहिए।

—०—

DENA BANK
Services

CURRENT ACCOUNTS
SAVING BANK ACCOUNTS
SPECIAL SAVINGS SCHEMES
CASH CERTIFICATES
FIXED & CALL DEPOSITS
SAVINGS INSURANCE SCHEME
SAFE DEPOSIT VAULTS
SMALL SILVER BARS
INVESTMENT SERVICE
EXECUTOR & TRUSTEE SERVICE
FOREIGN EXCHANGE

A STRONG EDIFICE

Head Office:
Devkaran Nanjee Bldgs.
Horniman Circle, Bombay 1.

Pravinchandra V. Gandhi
Managing Director.

DEVKARAN NANJEE BANKING CO. LTD.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राष्ट्र का आर्थिक प्रवाह

श्री जी० एस० पथिक

नया निर्वाचन और कांग्रेस

भारत का आम निर्वाचन संसार में अपना महत्व रखता है। लोकतंत्र व्यवस्था के अन्तर्गत बालिग मताधिकार के आधार पर इतनी बड़ी जनसंख्या का निर्वाचन संसार के किसी दूसरे देश में नहीं होता है। इस बार भी कांग्रेस को केरल और उड़ीसा के अतिरिक्त सभी राज्यों और केन्द्र में विजय मिली। पर यह मानना पड़ेगा कि वाम पक्षी दलों के संयुक्त मोर्चे के कारण कांग्रेस को जबर्दस्त संघर्ष का सामना करना पड़ा। यह भी कहना पड़ेगा कि कांग्रेस को जो सफलता मिली, वह इसीलिए नहीं कि देशभर में कांग्रेस संगठन सक्रिय और जोरदार हैं और जनता से उनका निकटतम सम्पर्क है, बल्कि इसलिए कि जनता की कांग्रेस के प्रति आस्था बनी हुई है। इस निर्वाचन में कम्युनिस्ट पार्टी अधिक आगे आयी और यह दीखता है कि संयुक्त मोर्चे में वह कांग्रेस के बाद दूसरा स्थान ग्रहण कर लेगी। भारत में समस्या जनक प्रदेश दो हैं, एक केरल और दूसरा पश्चिमी बंगाल। केरल में कम्युनिस्टों को सफलता मिली, और वैधानिक धरातल पर उन्हें अपने लक्ष्यों में आगे बढ़ने का अवसर मिला। पश्चिम बंगाल में यद्यपि कांग्रेस की विजय हुई किंतु कांग्रेस के बाद दूसरा स्थान कम्युनिस्टों का है। मध्य वित्त के शिक्षित बंगाली युवक आर्थिक दुरवस्था के कारण कांग्रेस से भटक गए और यही कारण है कि कलकत्ते जैसे नगर में कांग्रेसी उम्मीदवारों की भारी पराजय हुई।

कांग्रेस विजय की आर्थिक प्रतिक्रियाएं

पर इस दूसरे निर्वाचन में कांग्रेस की विजय के आर्थिक परिणामों पर भी हमें विचार करना चाहिए। यदि अगले पांच वर्षों में कांग्रेस अपने आर्थिक कार्यक्रम को पूरा करने में आगे नहीं बढ़ती है, मध्य वित्त वर्ग के बेकारों को रोजी नहीं देती है तथा दूसरी पंचवर्षीय विकास योजना को पूरा नहीं करती है, तो इस देश में लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा और देश का आर्थिक ढांचा दूसरा मार्ग ग्रहण करेगा। इसलिए कांग्रेस का निकट भविष्य स्थिर रहना दूसरी विकास योजना की प्रगति पर निर्भर है। इसी कारण राजनीतिक सत्ता के अधिकार का प्रश्न उठता है। इसी आधार भूत तत्व के लिए संयुक्त वाम पक्ष के दलों ने निर्वाचन में संघर्ष किया। यह कहना देश के विचारशील मतदाताओं का अपमान करना होगा कि वे इस राजनीतिक समस्या की जानकारी नहीं रखते। दूसरी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि वह साधन और स्रोतों से बहुत आगे है, और वह कैसे पूरी होगी। कांग्रेस ने विश्वास दिलाया कि वह इस जोखम को उठाएगी। यह स्पष्ट है कि साधारण मतदाताओं ने यह सोचा कि थोड़ा करने और धीमे चलने की जोखम अधिक भारी है, बजाय इसके कि तेजी से बढ़ें। देश में उद्योगपति और अर्थविद यह नहीं सोचते हैं। दूसरे प्रश्न उठते हैं, क्या दूसरी योजना बिना मुद्रास्फीति—तेजी आए बिना आगे बढ़ सकती है? इस सम्बन्ध में ख्यातिनामा अनेक अन्तर्राष्ट्रीय अर्थविदों ने भारतीय मतदाताओं के निर्णय से सहमति प्रकट की है। इन अर्थविदों में प्रोफेसर कैल्डार, केम्ब्रिज के श्रीमती जान राबिनसन, हावर्ड के प्रो० गेलब्रेथ, पोलैण्ड के डा० ओस्कर लैंज, श्री जान स्ट्रेचे प्रभृति हैं। दूसरी योजना की पृष्ठभूमि में यह अधिकृत प्रभावशाली पक्ष है।

लोकतंत्री समाजवाद के समर्थक विचारकों का कहना है कि भारत के वामपक्ष ने जिन आर्थिक तत्वों को उठाया है, दूसरी विकास योजना से उन्हें पूरा करना चाहिए। लोकतंत्र व्यवस्था को कायम रखते हुए योजना के साधन जुटाने से भारत समर्थ हो सकता है। किंतु उनका यह भी मत है कि भारत में लोकतंत्र को कायम रखने के लिए दूसरी योजना की सफलता आवश्यक है। यह आशा की जा सकती है कि दूसरी योजना सफल होगी, जिससे कि भारत लोकतंत्र से हट कर साम्यवादी केम्प में न लुढ़क जाए। यदि दूसरी योजना फेल होती है, तो देश में अराजकता का काल आ सकता है। आर्थिक दुरवस्था के वातावरण में एकाधिकार-शासन का राज्य आ जायगा। दूसरी योजना की असफलता होने पर भारत चीन और रूस के क्षितिज में बढ़ जाएगा।

कांग्रेस पूंजीवादियों की संस्था है?

यह प्रश्न उठता है कि क्या कांग्रेस पूंजीवादियों की

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

संस्था है ? संयुक्त वामपक्षी मोर्चे का कांग्रेस पर यही आरोप है। इस दिशा में हमें कांग्रेस के संगठन पर विचार करना है। स्वतंत्रता के आन्दोलन के समय कांग्रेस सारे देश का प्रतिनिधित्व करती थी। यद्यपि कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी बन गयी है, किन्तु वह पार्टी से परे है और आज भी किसी अंश तक उसके दायरे में सभी वर्ग आते हैं। यदि भूतपूर्व नरेश और उद्योगपति और उनके प्रतिनिधि कांग्रेस में आते हैं, तो उससे कांग्रेस अपने सिद्धान्तों से पीछे नहीं हटती है। हमने लोकसभा में निजी उद्योगों के कांग्रेसी प्रतिनिधियों को कम्पनी कानून और सम्पत्ति कर और अन्य वित्तीय करों के समर्थन में पाया। इसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस ने निजी क्षेत्र को नये मोड़ में ला खड़ा किया। राष्ट्रीयकरण की दिशा में यह देश लोकतंत्र व्यवस्था में प्रायः सभी देशों से आगे है। रेलवे का उद्योग सबसे बड़ा है, जिसका राष्ट्रीयकरण हो चुका है, जमींदारी उन्मूलन भी राष्ट्रीयकरण है और किसानों को भूमि के मालिक की संज्ञा देते हुए भी वे शासन के निरे जोतदार हैं। विद्युत और मार्ग यातायात के राष्ट्रीयकरण करके भी कांग्रेसी शासन आगे बढ़ा है। नये भारी उद्योग सरकारी क्षेत्र में स्थान पा रहे हैं। केवल उपभोक्ता उद्योग निजी क्षेत्र के अधिकार में हैं। कम्युनिस्ट दल का मेनिफेस्टो है कि इन उद्योगों को निजी क्षेत्र में कायम रखा जाएगा, पर नियंत्रणों के अन्तर्गत। कांग्रेसी शासन ने क्या किया है ? उसने भी उन पर कठोर नियंत्रण लगाये हैं। कम्पनी कानून, में किये गये नए सुधार कठोरतम नियंत्रण हैं। पूंजीगत संस्था के रूप में निजी वित्तीय स्रोत बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। समस्त उद्योग और बैंकों के कामकाज पर आज नियंत्रण लगे हैं। व्यापार पर भी नियंत्रण हैं। उत्पादन-कर लगे हुए हैं, जिससे उद्योग भारी मुनाफा न खींच सकें। इसके अतिरिक्त कम्पनियों के मुनाफे पर डिवीडेण्ड-कर लगा, पूंजीगत लाभ कर लगा। और अब वार्षिक लाभ कर, वार्षिक व्यय कर, वार्षिक सम्पत्ति कर की ओर शासन अग्रसर है। कांग्रेस ने केवल वर्ग संघर्ष नहीं किया। वह इन करों के द्वारा समाज की खाई दूर करने में अग्रसर है। उसने केवल यह नहीं किया कि इस विकास काल में निजी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करे, उसने इन्हें नियंत्रण में काम करने का अवसर दिया और उनकी बचतों और अतिरिक्त मुनाफों को सरकार के पास जमा रखने के लिए कदम बढ़ाया। दूसरे बिना मुआवजा चुकाए राष्ट्रीयकरण की व्यवस्था स्वीकार नहीं की तथा व्यक्तिगत आय सीमित नहीं की है। व्यक्तिगत आय कम्युनिस्ट देशों में भी सीमित नहीं की गई है।

विनियोजन में १।।।) अरब का ह्रास

देश में उद्योगका विस्तार हो रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, कम्पनियों की रिपोर्ट अच्छी निकल रही हैं, ऊंचे स्तर पर डिवीडेण्ड भी दिये जा रहे हैं, किंतु इन सब अवस्थाओं में निजी क्षेत्र के पूंजी विनियोजकों में कोई उत्साह नहीं है। १९५६-५७ के बजट के बाद केन्द्रीय मंत्रियों के भाषणों ने उसकी प्रगति रोक दी। पूंजीगत लाभ कर और डिवीडेण्ड पर सर-चार्ज ने विनियोजन को क्षीण बना दिया। दो तीन विदेशी कम्पनियों की नयी पूंजी की मांग में जो भारी विनियोजन हुआ, उससे सरकार ने समझ लिया कि पूंजी निर्माण के लिए शेयर बाजारों की कोई अवस्था नहीं है। जो संगठन पूंजी निर्माण के स्रोत हैं, उन्हें जुगांडखाने करार दिया गया। यह कहा गया कि शेयर बाजारों में शेयरों के भाव गिरने से औद्योगिक विकास पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। यह भी बताया गया कि राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था में शेयर बाजार कोई स्थान नहीं रखते हैं। इधर यह प्रहार हुआ। विनियोजन के क्षेत्र में शीत युद्ध छेड़ दिया गया, तो दूसरी और पूंजीगत लाभ कर और डिवीडेण्ड पर सरचार्ज लगा तथा कपड़े पर उत्पादन कर में वृद्धि कर दी गयी। इन परिस्थितियों में नौ महीने से विनियोजन गिरता चला आ रहा था, किंतु ३० नवम्बर के अतिरिक्त बजट ने विनियोजकों पर अज्ञात हमला कर दिया। यद्यपि अतिरिक्त बजट में १७ करोड़ रुपए के कर लगे, किंतु यह दहशत पैदा हो गयी कि आगे न जाने कब कितने कर लगें कि वे उस जोखम को उठा न सकें। केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि अच्छी कम्पनियों की पूंजी भरने में कोई दिक्कत नहीं है, पर टाटा स्टील, इंडियन आयरन और एशोसिएटिड सीमेण्ट कम्पनियां देशकी पहली श्रेणी की कम्पनियां नहीं हैं, उनका संचालन उच्च ही है ? पर इन कम्पनियों के भी शेयर पूरे नहीं भरे जा सके, क्योंकि नए शेयर पर प्रिमियम लगाए

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गए और दूसरी ओर विनियोजक नयी पूंजी लगाने में साहसहीन हो गए। परिणाम क्या हुआ, शेयरों के भाव गिरते चले गए और एक वर्ष में विनियोजन को १॥। अरब रु० का घाटा हुआ। शेयरों में इतनी क्षति होने पर विनियोजकों में कैसे प्रोत्साहन पैदा हो सकता है?

अनिवार्य डिपाजिटों के अत्याचार

अनिवार्य डिपाजिट की सरकारी योजना उद्योगों पर अत्याचार है। उद्योगों के पास रिजर्व और घिसाई खाते की जो रकमें जमा हैं, सरकार सोचती है कि वह राशि बेकार पड़ी हैं। सरकार ने निश्चय किया कि पुराने डिपाजिट-रिजर्व और घिसाई मद की रकमों का २५ प्र० शत और नए मुनाफे और घिसायी के मद की रकम ७५ प्रतिशत जमा की जाएं। इस देश में यह व्यवस्था निजी क्षेत्र के उद्योगों के वित्तीय स्रोतों पर कठोर दमन की है। यह कानून लागू हो गया और जो कम्पनियां भविष्य में मुनाफे की बचत और घिसायी की रकमें जमा न करेंगी उन्हें आय कर और विकास की रिबेट न दी जाएगी। पर हकीकत यह है कि कम्पनियां इस धन का दिन प्रतिदिन के संचालन में उपयोग करती हैं और इस पर भी जब पूरा नहीं पड़ता है, तब वे बैंकों से ऋण लेती हैं। यह तो सरकार ने स्वीकार किया है कि कम्पनियों के वित्तीय स्रोत नए पूंजी निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि यह होता तो उन्हें बैंकों से भारी ऋण न लेने पड़ते। १०२ कम्पनियों के विवरण से इस स्थिति का सहज में निराकरण होता है:—

इस विवरण में रिजर्व और घिसायी मद की रकमें जो स्थायी सम्पत्ति से बाहर हैं, उनकी स्थिति इस प्रकार है:—

	१९५४	१९५५
	(करोड़ रुपए में)	
स्थायी सम्पत्ति	१२६.४१,	१३५.४३
पूंजी कम की	६८.४३	६८.६१
	५९.९८	६६.८२
घिसाई की रकम कमी की	५३.८९	२७.६१
	६.०९	९.२१
रिजर्व कम किया	३२.७६	३५.६१
अतिरिक्त	२६.६७	२६.४०

१९५४ और १९५५ में स्थायी सम्पत्ति से रिजर्व की रकमें २६.६७ करोड़ रुपए और २६.४० करोड़ रुपए थी, पर ये रकम सुस्त नहीं पड़ी रहीं। पहले वर्ष में इन रकमों से २७.३ प्र० श० और दूसरे वर्ष में ३३.५ प्र० श० चलतू सम्पत्ति में धन लगा। इतने पर भी कम्पनियों को ऋण लेने पड़े। देनदारियों की रकमें कर चुकाने के लिए रखी गयीं। चलतू सम्पत्ति में १९५४ में ४३ प्र० श० और १९५५ में ४१ प्र० श० धन चलतू सम्पत्ति से विनियोजन किया गया। दूसरे शब्दों में १९५४ में ५७ प्र० श० और १९५५ में ५९ प्र० श० धन ऋण और एडवांसों से प्राप्त किया गया। इस अवस्था में सरकार रिजर्व और घिसायी मद की रकमें खींच लेती है तो कम्पनियों की क्या [illegible]

पूंजी
रिजर्व
ऋण
देनदारी

स्थायी सम्
घिसायी म
असली स
चलतू सम्

[illegible] वस्तु के हिसाब [illegible] ५० वस्तुएं खरीदनी हों तो पहले कुल राशि रुपये आनों में निकालिये। आपको ९ रुपये ६ आने देने हैं।

(२) अगर आपके पास केवल नये पैसे हैं तो आप मालूम करते हैं कि ६ आने ३७ नये पैसों के बराबर हैं। इस प्रकार आप ९ रुपये और ३७ नये पैसे चुकाते हैं।

अगर आप ३ आनों का ठीक ठीक समान मूल्य यानी १८¾ नये पैसों को लेते और ५० से गुणा करते तो भी परिणाम यही निकलता, पर यदि आप ३ आने का निर्धारित समान मूल्य परिवर्तन तालिका से यानी १९ नये पैसे लेते और ५० से गुणा करके निकालते तो यह गलत होता।

इसी प्रकार यदि आप विभिन्न दरों की कई वस्तुएं एक साथ खरीदते हैं और वे दरें रुपये-आनों में हैं। पहले आप कुल राशि रुपये आने पाई में निकाल लीजिए। अगर आप नये सिक्कों में मूल्य चुकाना चाहते हैं तो कुल राशि के आने पाइयों को परिवर्तन तालिका के जरिये नये पैसों में बदल लीजिए।

आप परिवर्तन को यह याद रखकर सरल बना सकते हैं कि—

४ आने	बराबर	२५ नये पैसे
८ आने	बराबर	५० नये पैसे
१२ आने	बराबर	७५ नये पैसे
१ रुपया	बराबर	१०० नये पैसे

उदाहरण :

(१) मान लीजिए आपको १०½ आने चुकाने हैं। पहले आप ८ आने या ५० नये पैसे दीजिए। शेष ढाई आने जो कि १६ नये पैसों के बराबर हैं, दे दीजिए।

(२) ३६ नये पैसों का अपको भुगतान करना है। पहले आप ४ आने या २५ नये पैसे दीजिए। शेष ११ नये पैसों के लिए १ आना ९ पाई दे दीजिए।

DA 56/250

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नये सिक्के

प्रथम अप्रैल १९५७ से चालू

	वर्तमान सिक्कों में ठीक ठीक समान मूल्य
१० नये पैसे—(एक रुपये का १/१० वां भाग)—	१ आना ७.२ पाइयां
५ नये पैसे—(एक रुपये का १/२० वां भाग)—	९.६ पाइयां
२ नये पैसे—(एक रुपये का १/५० वां भाग)—	३.८४ पाइयां
१ नया पैसा—(एक रुपये का १/१०० वां भाग)—	१.९२ पाइयां

पुराने सिक्के जैसे कि एक पैसा या १/४ आना, २ पैसा या १/२ आना, इकन्नी, दुअन्नी, चवन्नी और अठन्नी भी नये सिक्कों के साथ साथ चालू रहेंगे। चवन्निया और अठन्नियां क्रमशः २५ नये पैसे और ५० नये पैसे के ठीक ठीक बराबर हैं और सभी प्रकार के उपयोग में लाई जा सकती हैं। नये और पुराने दोनों ही सिक्के भुगतान अथवा हिसाब किताब करते समय कानूनी रूप से मान्य होंगे।

परिवर्तन की सुविधाएं

परिवर्तन की सुविधायें रिजर्व बैंक कार्यालयों, स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखाओं और अन्य एजेंसी बैंकों, ट्रेजरियों और सब-ट्रेजरियों में प्रदान की जाएंगी।

नये सिक्के, वर्तमान सिक्के चार आने अथवा उसके गुणक संख्याओं जैसे कि आठ आने, बारह आने, एक रुपया आदि के बदले में दिये जाएंगे।

परिवर्तन तालिका

परिवर्तन तालिका आने पाई के सिक्कों का नये पैसे में विनिमय मूल्य बताती है (जैसा कि हाल में संशोधित भारतीय सिक्के एक्ट १९०६ के १४(२) वीं धारा के अनुसार पूर्णांकित किया गया है)। कुल राशि के मूल्य का ठीक सही नया पैसा निकालते ...जाएगा, ... नया पैसा या उससे कम को छोड़ देते हैं और १/२ नये पैसे से अधिक को एक

क्या किया है ? उसने भी उन पर क...

हैं। कम्पनी कानून, में किये गये नए सुधार कठोरतम नियंत्रण हैं। पूंजीगत संस्था के रूप में निजी वित्तीय स्रोत बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। समस्त उद्योग और बैंकों के कामकाज पर आज नियंत्रण लगे हैं। व्यापार पर भी नियंत्रण हैं। उत्पादन-कर लगे हुए हैं, जिससे उद्योग भारी मुनाफा न खींच सकें। इसके अतिरिक्त कम्पनियों के मुनाफे पर डिवीडेण्ड-कर लगा, पूंजीगत लाभ कर लगा। और अब वार्षिक लाभ कर, वार्षिक व्यय कर, वार्षिक सम्पत्ति कर की ओर शासन अग्रसर है। कांग्रेस ने केवल वर्ग संघर्ष नहीं किया। वह इन करों के द्वारा समाज की खाई दूर करने में अग्रसर है। उसने केवल यह नहीं किया कि इस विकास काल में निजी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करे, उसने इन्हें नियंत्रण में

और पूंजीगत लाभ कर और ...

लगा तथा कपड़े पर उत्पादन कर में वृद्धि क...

इन परिस्थितियों में नौ महीने से विनियोजन गि... रहा था, किंतु ३० नवम्बर के अतिरिक्त बजट ... जकों पर अज्ञात हमला कर दिया। यद्यपि अतिरि... १७ करोड़ रुपए फे कर लगे, किंतु यह दहशत ... गयी कि आगे न जाने कब कितने कर लगें। जोखम को उठा न सकें। केन्द्रीय वित्त मंत्री ने ... अच्छी कम्पनियों की पूंजी भरने में कोई दिक्कत ... पर टाटा स्टील, इंडियन आयरन और एशोसिएटिड ... कम्पनियां देशकी पहली श्रेणी की कम्पनियां ... उनका संचालन उच्च ही है ? पर इन कम्पनियों के ... पूरे नहीं भरे जा सके, क्योंकि नए शेयर पर प्रिमियम

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तालिका में दी हुई रीति के अनुसार नये पैसों में पूर्णांकन करना केवल तभी आवश्यक है जब कि लेन देन के अंत में आने पाइयों को नये पैसों में परिवर्तित करना हो।

आप सारे नये सिक्कों में या सारे पुराने सिक्कों या कुछ नये पैसे और कुछ पुराने सिक्कों दोनों को मिला कर, जैसे भी आप के पास सिक्के हों, भुगतान कर सकते हैं।

परिवर्तन तालिका का प्रयोग केवल लेन देन के अंत में भुगतान करते समय अथवा खेरीज देते-लेते समय करना चाहिए। जैसा कि निम्न उदाहरणों में समझाया गया है।

उदाहरण : (जहां राशि आने पाइयों में दी हुई है)

मान लीजिए आपको १२ वस्तुएं डेढ़ आने प्रत्येक के हिसाब से खरीदनी हैं। आपको कुल १ रुपया २ आने देना है। खरीदार चाहे तो १ रु० २ आ० पुराने सिक्कों में दे।

अथवा

१ रुपया और १२ नये पैसे दे (तालिका के अनुसार २ आने का समान मूल्य है १२ नये पैसे)

ऊपर के उदाहरण में खरीदार २ रुपये पुराने सिक्कों में दे सकता है और बाकी पैसे मांग सकता है। उसे १४ आने वापस मिलने चाहिएं। १४ आने पूरे उसे पुराने सिक्कों में दिये जा सकते हैं *अथवा* कुछ नये सिक्कों में *अथवा* कुछ पुराने सिक्कों और कुछ नये सिक्कों में। मान लीजिए आठ आने पुराने सिक्कों में दिये गये और ६ आने नये सिक्कों में। ६ आने का नये सिक्कों में समान मूल्य निकालने के लिए तालिका का प्रयोग कीजिए जो कि ३७ नये पैसे आता है।

उदाहरण : (जहां राशि नये पैसों में दी हुई है)

मान लीजिए एक वस्तु की कीमत ११ नये पैसे है। कोई भी व्यक्ति यह राशि नये पैसों में दे सकता है अथवा पुराने सिक्कों में १ आना ९ पाई दे सकता है। (तालिका के अनुसार १ आना ९ पाई का नये पैसों में समान मूल्य ११ नये पैसे है)

अगर एक व्यक्ति ११ नये पैसों के लिए २० नये पैसे देता है तो उसे ९ नये पैसे वापस देने चाहिएं अथवा समान मूल्य के पुराने सिक्के दिये जाएं जो कि १ आना ६ पाई होते हैं।

११ नये पैसों का भुगतान करने के लिए कोई व्यक्ति चवन्नी दे कर खेरीज वापस मांग सकता है। चार आने २५ नये पैसों के बराबर हैं, बाकी १४ नये पैसे लौटाने हैं। ये बाकी पैसे पूरे ही नये सिक्कों या पुराने सिक्कों में दिये जा सकते हैं। तालिका के अनुसार २ आने ३ पाई बराबर होते है १४ नये पैसों के। कोई भी व्यक्ति इकन्नी (यानी ६ नये पैसे) और ८ नये पैसे नये सिक्कों में लौटा दे।

दरों या लागत की इकाइयों को जो कि आने-पाई में हों, कुल मूल्य या राशि निकालने के पूर्व नये पैसों में बदलना आवश्यक नहीं है।

उदाहरण :

(१) अगर ३ आने प्रत्येक वस्तु के हिसाब से ५० वस्तुएं खरीदनी हों तो पहले कुल राशि रुपये आनों में निकालिये। आपको ९ रुपये ६ आने देने हैं।

(२) अगर आपके पास केवल नये पैसे हैं तो आप मालूम करते हैं कि ६ आने ३७ नये पैसों के बराबर हैं। इस प्रकार आप ९ रुपये और ३७ नये पैसे चुकाते हैं।

अगर आप ३ आनों का ठीक ठीक समान मूल्य यानी १८$\frac{3}{4}$ नये पैसों को लेते और ५० से गुणा करते तो भी परिणाम यही निकलता, पर यदि आप ३ आने का निर्धारित समान मूल्य परिवर्तन तालिका से यानी १९ नये पैसे लेते और ५० से गुणा करके निकालते तो यह गलत होता।

इसी प्रकार यदि आप विभिन्न दरों की कई वस्तुएं एक साथ खरीदते हैं और वे दरें रुपये-आनों में हैं। पहले आप कुल राशि रुपये आने पाई में निकाल लीजिए। अगर आप नये सिक्कों में मूल्य चुकाना चाहते हैं तो कुल राशि के आने पाइयों को परिवर्तन तालिका के जरिये नये पैसों में बदल लीजिए।

आप परिवर्तन को यह याद रखकर सरल बना सकते हैं कि—

४ आने	बराबर	२५ नये पैसे
८ आने	बराबर	५० नये पैसे
१२ आने	बराबर	७५ नये पैसे
१ रुपया	बराबर	१०० नये पैसे

उदाहरण :

(१) मान लीजिए आपको १०$\frac{1}{2}$ आने चुकाने हैं। पहले आप ८ आने या ५० नये पैसे दीजिए। शेष ढाई आने जो कि १६ नये पैसों के बराबर हैं, दे दीजिए।

(२) ३६ नये पैसों का अपको भुगतान करना है। पहले आप ४ आने या २५ नये पैसे दीजिए। शेष ११ नये पैसों के लिए १ आना ९ पाई दे दीजिए।

DA 56/250

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हमारा चाय-उद्योग

कृष्णचन्द्र विद्यालंकार

कुछ दिन हुए संसद में चायके उद्योग के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न उपस्थित हुआ था। यद्यपि सरकारने इस प्रस्ताव को मानने से इन्कार कर दिया, तथापि इस चर्चा से दो बातें स्पष्ट हुई हैं। एक तो यह कि चाय उद्योग का देश की अर्थ-व्यवस्था में बहुत महत्त्व है। दूसरी बात यह कि चाय का उद्योग अब तक भी अधिकांशतया विदेशी पूंजीपतियों के हाथों में है। हम इस लेख में चाय के असाधारण महत्वकी चर्चा करना चाहते हैं।

विश्वके कुल चाय उत्पादन में से ४० प्रतिशत भारत में उत्पन्न होता है। और निर्यात भी कुल निर्यात का ४० प्रतिशत होता है। इसके निर्यात से भारत को १ अरब रु० से अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। गत तीन वर्षों में भारत को ३५९ करोड़ रु० चाय के निर्यात से मिले, जबकि जूट और कपड़ेके निर्यात से क्रमशः ३५६ और २०२ करोड़ करोड़ रुपए मिले हैं। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि जूट और कपड़े के निर्माण में तो हमें जूट और रुई के रूप में कच्चा माल विदेशों से मंगाना पड़ता है, जबकि जूट के उत्पादन में हमें विदेशों पर बिलकुल आश्रित नहीं होना पड़ता।

भारत से चाय का निर्यात

देश	(मात्रा लाख पौंड)		(मूल्य लाख रुपये)	
	१९५४-५५	१९५५-५६	१९५४-५५	१९५५-५६
ब्रिटिश	३३००	२८९	१०१,८३	७३,९५
सं. रा. अमेरिका	३०३	२५४	१०,३८	६,७८
कैनेडा	२०३	१७३	७,३८	४,७२
ईराक गणतंत्र रा.	२३२	१९७	७,३४	५,६१
ईरान	८५	८३	४,२९	३,९७
मिश्र	९२	१४७	३,४१	४,१२
आस्ट्रेलिया	७८	६२	२,७४	१,५१
नैदरलैण्ड	४०	४१	१,५१	१,०४
सूडान	४८	३०	१,२९	६९
नवेट	३०	२८	१,१९	७३
पश्चिमी जर्मनी	२६	४२	१,०५	१,२९
वहीनी	२५	२६	९४	६२
टर्की	२१	५४	८३	१,७२
योग	१५६७	४००	१४९,२२७	१०८,६९

इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि ब्रिटेन हमारी चाय का सबसे बड़ा ग्राहक है। किन्तु हमें यह न भूलना चाहिए कि वह अन्य देशों से भी चाय मंगाता है, जैसा कि निम्नलिखित सूची से स्पष्ट है।

(मात्रा दस लाख पौंडोंमें और मूल्य दस लाख पौंडोंमें)

देश	१९५५	१९५६	१९५५	१९५६
भारत	२८३.३९	२९९.६७	७५.५०	६८.८१
लंका	१२१.९७	१२५.८१	३०.८८	३१.९१
रोडेशिया और न्यासालैंड	१७.११	१२.२९	३.८५	२.७१
पाकिस्तान	१७.०७	१३.९६७	४.२०	२.५१
केनिया	८.९६	१०.६७	१.७७	१.७२
पूर्वी अफ्रीका पुर्तगीज	६.९३	११.१७	१.२९	१.६३
इण्डोनेशिया	७.०३	८.१५	१.६५	१.४४
अन्य देश	३६.८४	२४.८९	६.६८	३.६८
योग	४९९.३०	५१२.६२	१२५.८२	११४.५४

ब्रिटेन के बाद भारतीय चाय के ग्राहक सं० रा० अमेरिका और आस्ट्रेलिया हैं। भारत सरकार का ध्यान अब अमेरिका में चाय का निर्यात बढ़ाने की ओर गया है, वहां अभी तक चाय अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम प्रचलित हुई है, जैसाकि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है:—

चाय की खपत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष

इंगलैंड	९.९ पौंड
नीदरलैंड	७.५ पौंड
आस्ट्रेलिया	६.८ पौंड
कैनाडा	३.० पौंड
सं० रा० अमेरिका	०.७ पौंड

आस्ट्रेलिया भारत की अपेक्षा श्रीलंका से अधिक चाय मंगवाता है। इस देश में चाय का निर्यात बढ़ाने के लिए विशेष प्रयत्न करना होगा। कैनेडा में भी १८० लाख पौंड चाय श्री लङ्का से आती है। मिस्र के साथ जैसे हमारे सम्बन्ध बढ़ रहे हैं, उससे यह आशा की जा सकती है कि

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गांव में कैसे सुख-शांति हो ?

सर्व प्रथम सारे गांव को एक करना होगा, जमीन की मालकियत मिटानी होगी, सारे गांवको प्रेम से जमीन देनी होगी और मानना होगा कि 'यह सारी जमीन गांव की है और उसमें मेरा भी हिस्सा है।' जैसे हवा-पानी का कोई मालिक नहीं हो सकता, वैसे जमीन का भी कोई मालिक नहीं हो सकता। पानी का अगर कोई मालिक हो जायगा, तो दुनिया की दुर्दशा हो जायगी। इसी तरह जमीन की मालकियत धर्म-विरुद्ध है, इसलिए प्रेम से सब एक हो जायं, मिलजुल कर काम करें, तो गाँव की ताकत बढ़ेगी।

दूसरी बात यह कि कोई भी रोजमर्रा की चीज बाहर से गाँव में नहीं आनी चाहिए। कच्चे माल का पक्का माल गाँव में ही बनना चाहिए। कपड़ा, गुड़, तेल, जूते, बटन आदि खुद तैयार कर लेंगे, तो बाजार भाव से हम बच जायेंगे।

तीसरी बात तो सहज ही हो जायगी। गाँव की सारी जमीन बंट गयी, गाँव के धंधे शुरू हो गये, तो झगड़े ही मिट जायेंगे।

चौथी बात यह कि व्यक्तिगत तौर पर न कर्जा लिया जाय, न दिया जाय। कर्जा लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अपने गाँव में धंधे खड़े होंगे, इसलिए व्यापारी के पंजे से छूट गये। झगड़े मिट गये, तो वकीलों के पंजे से छूटे! लोगों को खाना-पीना अच्छा मिलेगा, तो बीमारी कम होगी; फलस्वरूप डाक्टरों के पंजे से छूट जायेंगे। इस तरह प्रेम से, मिलजुल कर पुरुषार्थ करेंगे तभी गाँव सुखी होगा।

—विनोबा

भूदान आंदोलन की सफलताएं

भूदान-यज्ञ-आन्दोलन ने क्या कार्य किया, इसका संक्षेप में विवरण निम्नलिखित प्रकार है :—

राजनीति : १—लोकशाही का मूल आधार लोक-शक्ति है। जनता में उस भाव को जागृत किया। उसमें पुरुषार्थ की प्रेरणा जगायी।

२—लोकशाही सफल बनाने के लिए सरकार की सर्वकष सत्ता के बदले जनता का जीवनव्यापी सर्वस्पर्शी विधायक पुरुषार्थ अनिवार्य है, यह लोकनीति का सूत्र समझाया।

३—पक्षपाती लोकशाही का विचार देश के सामने आया।

अर्थनीति : १—उत्पादन के साधन सौदे की वस्तु नहीं हैं, संग्रह की चीज नहीं हैं, वे उत्पादन के साधनमात्र हैं, और इसी नाते उनका समाज में विनियोग होना चाहिए--यह क्रांतिकारी सूत्र अपढ़, अशिक्षित ग्रामीणों तक पहुँचाया।

२—उत्पादन के साधन अनुत्पादक के हाथ में रहना गलत है। इसलिए अनुत्पादक का स्वामित्व समाप्त करना एवं उत्पादक के हाथ में उन साधनों को सौंप देना हमारा धर्म है, यह मूलभूत क्रांतिकारी सिद्धान्त गाँव-गाँव तक पहुँचाया।

३—उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति का स्वामित्व होना गलत है। उससे संग्रह का लालच, शोषण का प्रलोभन इत्यादि संघर्ष के बीज समाज-रचना में अनायास पैदा होते हैं, इसलिए उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व रहे, यह गंभीर विचार ग्रामीणों के लिए सुलभ कर दिया।

४—तात्पर्य, स्वामित्व के आधार बदलने के लिए जनमानस अनुकूल बनाया। बदलने की पद्धति, साधन एवं प्रक्रिया का प्रात्यक्षिक देश के सामने रखा।

५—अपरिग्रह को सामाजिक मूल्य में परिणत किया।

सांस्कृतिक : १—क्रांति की प्रक्रिया में अहिंसा,

वह श्री लंका की अपेक्षा भारत से अधिक चाय मंगाने लगेगा।

चाय के व्यापारमें एक समस्या हमारे सामने यह है कि ब्रिटेन भारत से विपुल मात्रामें चाय मंगाकर बहुत अधिक कीमत पर अन्य देशों को बेचता है। यदि भारत स्वयं उन देशों को चाय का निर्यात करने लगे तो ब्रिटेन को होने वाले अतिरिक्त लाभ का एक बड़ा अंश भारत को ही मिलने लगे।

चाय की बिक्री के दो प्रबन्ध हैं। एक तो साधारण-तया बिक्री, दूसरे नीलामी। इस व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बंधुत्वभाव एवं सहयोग को दाखिल किया; अर्थात् इनको जनजीवन में सामाजिक मूल्यों की प्रतिष्ठा दिला दी।

२—मनुष्य की मूलभूत सत्प्रवृत्ति पर विश्वास ही आदर्श समाज-रचना की सच्ची नींव है, यह समझा कर आस्तिकता को समाज-परिवर्तन के साधन में परिणत किया।

३—सहअवस्थान पर्याप्त नहीं है, मनुष्यों के स्वयं प्रेरित सहजीवन के लिए परस्पर-विश्वास एवं स्नेह अनिवार्य हैं, यह दिखलाते हुए नया स्नेह-दर्शन संसार के सामने रखा। अन्तर्राष्ट्रीय मैत्री एवं शांति के लिए 'स्नेह' एकमात्र आलंबन है, इसका भान जगाया।

४—लोकशिक्षण द्वारा विचार-परिवर्तन एवं हृदय-परिवर्तन क्रांति का अमोघ साधन है, इसका भी प्रात्यक्षिक संसार के सामने रखा।

स्वावलम्बी गांव के लिए वस्त्र

५०० की जनसंख्या के स्वावलम्बी गांवमें नीचे लिखा कपड़ा हर व्यक्ति को साल भर में मिलना चाहिये।

ग्राम में जनसंख्या—पुरुष १८१, स्त्रियां १५१, बालक ९६८, कुल ५००।

	वस्त्र	संख्या	कुल कपड़ा—	
पुरुष	धोती	२	९। व० ग०	३१ व० ग०
	कुरते	३	६।।। व० ग०	
	चादर	१	४ व० ग०	
	गमछा	२	२। व० ग०	
	टोपी बड़ी, आदि		८।। व० ग०	
स्त्री	साड़ी	३	१८।।। व० ग०	३५ व० ग०
	लंहगा	३	६ व० ग०	
	कमीज	२	४ व० ग०	
	चादर	१	४ व० ग०	
	चोली	२	२। व० ग०	
बालक	पाजामे	२	२।।। व० ग०	१२ व० ग०
	कुरते	३	४।।। व० ग०	
	घुटन्ने	२	१।। व० ग०	
	बनियान	३	१।।। व० ग०	
	अन्य	२	१। व० ग०	

५०० ग्राम वासियों की कुल आवश्यकता

पुरुष	१८१×३१=५६११ व० ग०	कुल १२,९१२ व० ग०
स्त्रियां	१५१×३५=५२८५ व० ग०	
बालक	१६८×१२=२०१६ व० ग०	

—श्री प्रभुदासगांधी द्वारा लिखित खादी द्वारा ग्राम विकास

मूल्य बदलने की क्रान्ति

एक आदमी ने अदालत में नालिश की कि यह दूसरा आदमी हमारी औरत को भगाकर ले गया। अदालत ने कहा "तुम क्या चाहते हो?" उसने कहा—"हमको पन्द्रह हजार रुपये हरजाना मिल जाना चाहिये।"

अदालत में एक और दूसरा आदमी आया। कहने लगा—"मैं इसके कारखाने में काम करता हूं, मेरा हाथ टूट गया है।

अदालत पूछती है "तुमको क्या चाहिये?"

वह कहता है "मुझे हाथ के बदले में पन्द्रह हजार रुपये मिलने चाहिये।"

फिर तीसरा, दादा धर्माधिकारी वहां पहुँचा। कहने लगा—इसने हमको भरे बाजार में सबके सामने जूता मार दिया, हमारी इज्जत लुटादी।

अदालत पूछती है "तुमको क्या चाहिये?"

हमने कहा—"हमारी मानहानि के बदले पन्द्रह हजार रुपये मिलने चाहिये।"

अब देखिये क्या हाल हुआ। औरत के बदले में पैसा, हाथ के बदले में पैसा और इज्जत के बदले में भी पैसा। आगे चलकर वोट के बदले में और भगवान के बदले में भी पैसा होगा। आज 'भगवद्गीता' तीन आने में मिलती है, पर सिगरेट का डिब्बा सवा रुपये में मिलता है, तो सिगरेट का डिब्बा सम्पत्ति है और भगवद्गीता विपत्ति है।

इस मूल्य को बदल देने का नाम ही है—क्रांति!

—दादा धर्माधिकारी

श्रम और सम्पत्ति

बिनोवा कहता है कि मनुष्य के श्रम का कोई मूल्य नहीं, वह अनमोल है। पूंजीवाद कहता है कि 'मेहनत मजदूर की और दौलत मालिक की।" समाजवाद कहता है, "जिसकी मेहनत, उसकी दौलत।"

सर्वोदय कहता है, "मेहनत इन्सान की, दौलत भगवान की।"

पृष्ठसंख्या में भूल

आगे के १६ पृष्ठ २०७ से २२२ तक की बजाय भूल से १०७ से १२२ तक छप गये हैं। पाठक सुधार लें।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रतिदिन एक करोड़ रु० घाटे का बजट

आन्तरिक और बाह्य साधनों दोनों की दृष्टि से आलोच्य वर्ष में अर्थ-व्यवस्था पर कुछ दबाव रहा है। मुख्यतः विकास-कार्य की गति में तीव्रता आ जाने से देश में वस्तुओं के मूल्यों और शोधन-सन्तुलन पर दबाव रहा है। १९५५-५६ में कृषि-उत्पादन में कमी और स्वेज नहर बन्द हो जाने जैसे बाहरी कारणों से अर्थ-व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है। स्थिति को काबू में रखने के लिए हमने पिछले महीनों में अतिरिक्त कर, अन्त की पहले से अधिक पूंजी बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों पर नियंत्रण, आयात में भारी कटौती आदि कई तरह के उपाय किये; और मुझे पूरी आशा है कि ये यथासमय प्रभावकारी सिद्ध होंगे।

आन्तरिक मूल्यों की सम्भावना बहुत कुछ कृषि-उत्पादन के स्तर पर निर्भर होगी और सरकार इस बात को भली-भांति समझती है कि इस क्षेत्र में और भी अच्छे परिणाम प्राप्त करने की तत्काल आवश्यकता है। मूल्यों की स्थिरता के लिए भी यह आवश्यक है कि ऋण देने पर नियंत्रण रखा जाय और बजट सम्बन्धी ऐसी नीति निर्धारित की जाय, जिससे जनसाधारण की क्रयशक्ति नियंत्रित हो जाय। हाल ही में हमने छंटाई (सेलेक्टिव) के आधार पर नियंत्रण लगाने के लिए कार्रवाई की है, पर साथ ही इस बात की भी सावधानी रखी है कि गैरसरकारी क्षेत्र में विस्तार-कार्यक्रम के लिए ऋण में अनुचित रूप से कमी न हो जाय। बुनियादी तौर पर हमें निवेश में कमी नहीं, बल्कि बचत में वृद्धि की आवश्यकता है।

जहां तक बजट सम्बन्धी नीति का प्रश्न है, मैं स्वीकार करता हूं कि जितने बड़े घाटे का इसमें उल्लेख है। वह मुझे पसन्द नहीं है। इस प्रसंग में प्रतिरक्षा (डिफेंस) विषयक आवश्यकताओं के लिए धन की बढ़ती हुई मांगों को यों ही टाला नहीं जासकता। इस शीर्षक के अन्तर्गत वृद्धि होने से अगले वर्ष राजस्व खाते के घाटे में बहुत अधिक वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति को देखते हुए बजट का सम्पूर्ण घाटा, अर्थात् ३६५ करोड़ रुपया, मेरे विचार से कुछ अधिक है।

किन्तु इस समय सबसे विकट समस्या विदेशी मुद्रा

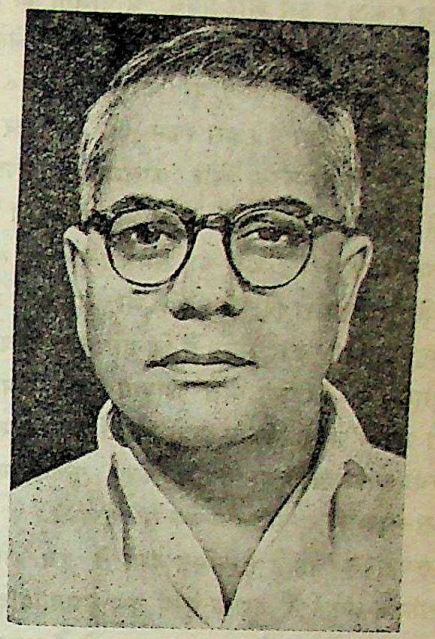

वित्तमंत्री श्री श्रीकृष्णमाचार्य

विदेशी मुद्रा

की है। दूसरी पंचवर्षीय आयोजना में उद्योग-धंधों, खानों और परिवहन के विकास पर जोर दिया गया है और इनके कारण बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी और अब ऐसा जान पड़ता है कि आयोजना की अवधि में, शोधन-संतुलन में मूल अनुमान की अपेक्षा अधिक कमी रहेगी। इसका कारण यह है कि विदेशों में मूल्य बढ़े हैं और आयोजना में सम्मिलित कुछ प्रायोजनाओं में विस्तार हुआ है। सच तो यह है कि हमारे विदेशी मुद्रा साधनों से अभी ही मूल अनुमान की अपेक्षा अधिक रकम निकाली जा चुकी है; अप्रैल, १९५६ से यह लगभग २६० करोड़ रुपये तक पहुँच गयी है। शोधन-सन्तुलन पर इस दबाव के कारण आयात नीति को, जिसकी घोषणा जनवरी में की गई थी, कठोर बनाने की आवश्यकता हुई है।

आयोजना की अवधि में विदेशी मुद्रा की स्थिति संक्षेप में इस प्रकार है। इस अवधि में शोधन-संतुलन में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कुल जितनी कमी की कल्पना की गई थी, उसकी अपेक्षा अब लगभग ४०० करोड़ रुपये की अधिक कमी रहेगी। हमारी विभिन्न प्रायोजनाओं के लिए विदेशों से जितना धन मिल सकता है उसे और प्रथम आयोजना की अवधि की प्राधिकृत रकम के बाकी हिस्से को हिसाब में लेते हुए हमारे पास अपनी आवश्यकताओं के लिए ४५० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा है। इस रकम को मिलाकर और यह मान कर कि अमरीका और कोलम्बो आयोजना के देशों से न्यूनाधिक उतनी ही रकम मिलती रहेगी जितनी इस समय मिल रही है और यह समझते हुए कि सामान्य मात्रा में गैर सरकारी विदेशी पूँजी भी लगायी जाएगी, हम यह अनुमान कर सकते हैं कि हमें कुल आवश्यकता का लगभग ५० प्रतिशत मिल जायगा। इस समय हम अपनी अपनी अनेक विकास प्रायोजनाओं की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पुनर्निर्माण और विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से ऋण लेने के सम्बन्ध में बातचीत कर रहे हैं। विभिन्न देशों से हम जो पूंजी-गत सामान मंगाते हैं, उसका मूल्य कुछ समय बाद चुकाने की सम्भावनाओं का भी हम पता लगा रहे हैं। सब मिला कर, आयोजना के लिए विदेशी मुद्रा जुटा सकने की संभावनाएं पूर्णतः निराशाजनक नहीं है। निस्सन्देह, मेरे इस कथन का यह अर्थ नहीं है कि यह काम सरल हो गया है।

जब तक नयी आयात नीति का प्रभाव नहीं पड़ता, तब तक के लिए हमने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से कुल मिलाकर २० करोड़ डालर का ऋण ले लिया है। समस्या यह नहीं है कि आयात में कटौती कर के हमारे विदेशी मुद्रा खाते में बचत दिखलायी जाय। यह काम दोहरा है। पहले तो यह कि आयोजना परिव्यय सावधानी के साथ इस ढंग से व्यवस्थित किया जाय कि शोधन-सन्तुलन पर बहुत अधिक दबाव न पड़े। इसके लिए आयोजना के सामान्य ढांचे में रहते हुए प्राथमिकताओं की कठोर प्रणाली का अवलम्बन करने की आवश्यकता है। दूसरे यह कि दूसरी आयोजना के लिए जो वस्तुएं अब भी आवश्यक हैं, उन्हें भारी मात्रा में विदेशों से मंगाने के लिए हमें धन का जुगाड़ करने की आवश्यकता पड़ेगी। पहली आवश्यक बात यह है कि निर्यात में वृद्धि की जाय, जिससे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में वृद्धि हो और आयात में यथासम्भव कमी की जाय। त्याग के बिना इनमें से कोई भी सम्भव नहीं, किन्तु आयोजित विकास की दृष्टि से त्याग करना ही पड़ेगा।

अब क्या करें ?

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के कारण अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ेगा, किन्तु मेरे विचार से इस समय आवश्यकता इस बात की है कि इस दबाव को सर्वोत्तम ढंग से संभालने के विषय में विचार किया जाये न कि आयोजना सम्बन्धी आधारभूत अनुमानों अथवा कल्पनाओं के सम्बन्ध में आपत्ति उठायी जाय। विकास का मार्ग सदा ही सुगम नहीं होता। निवेश और खपत, उपलब्ध विदेशी साधनों और तत्सम्बन्धी मांगों तथा वस्तुओं और सेवाओं की अन्तिम रूप से प्राप्ति और उनके उत्पादन के लिए आवश्यक सामग्री के मध्यवर्ती सन्तुलन का सही-सही अनुमान लगाना कठिन है और अप्रत्याशित बातें भी पैदा होती हैं, जो इस सन्तुलन को समय समय पर बिगाड़ देती हैं। इस तथ्य को ध्यान में रख कर ही दूसरी आयोजना की रिपोर्ट में, आवश्यक समायोजन के लिए वार्षिक आयोजनाओं की व्यवस्था और आयोजन के लचीलेपन पर काफी जोर दिया गया है।

तात्कालिक आवश्यकता यह है कि उन योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय, जिनसे निर्यात सम्बन्धी आमदनी बढ़ती है और निकट भविष्य में ही विदेशी मुद्रा साधनों को बहुत अधिक खर्च किये बिना आयात सम्बन्धी आवश्यकताएं घटती हैं। कृषि-उत्पादन में जल्दी ही वृद्धि करने में सहायता देने वाली योजनाओं को भी उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये; जो योजनाएं प्रारम्भ की जा चुकी हैं और जिन पर काफी खर्च किया जा चुका है, उन पर उपलब्ध साधनों का काफी अंश खर्च किया जाना चाहिए। आयोजना सम्बन्धी व्यय-क्रम को निर्धारित करते हुए जो काम सब से पहले करने के हैं उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। साथ ही हमें यथासम्भव इस बात की भी पक्की व्यवस्था करनी है कि जिन विकास कार्यक्रमों से देश की उत्पादन-शक्ति में सबसे अधिक वृद्धि होने की सम्भावना हो और जिनसे शोधन-सन्तुलन की स्थिति में आगे चल कर मजबूती आती है, उनमें अनुचित रूप से बाधा न पड़नी चाहिए। सीमित

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आम बजट एक दृष्टि में

राजस्व

(लाख रुपयों में)

	बजट १९५६-५७	संशोधित ५६-५७	बजट १९५७-५८
सीमा शुल्क	१५०००	१७१००	१६२००
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क	१७०३५	१८८७३	२०९४३
निगम कर	४८२४	४८२४	५०५०
आय कर (निगम कर को छोड़कर)	८६३५	८२६१	८५९६
सम्पत्ति शुल्क	१८	११	९
अफीम	२१०	२२४	२५०
ब्याज	५४९	५२४	४९०
असैनिक प्रशासन	११०६	१५४९	४३२१
मुद्रा और टकसाल	२३६७	२४४८	३६०२
असैनिक निर्माण कार्य	२३९	२७०	२९५
राजस्व के अन्य स्रोत	१९३९	१९३२	२७६५
डाक और तार—सामान्य राजस्व शुद्ध अंशदान	१६०	५३०	४३४
रेलें—सामान्य राजस्व में शुद्ध अंशदान	६५७	६०३	६६७
जोड़—राजस्व	५२७३९	५७१४९	६३६२२

व्यय

(लाख रुपयों में)

	बजट १९५६-५७	संशोधित १९५६-५७	बजट १९५७-५८
राजस्व संग्रह पर व्यय	३७१५	३७९२	४१८०
सिंचाई	५	८	१०
ऋण-व्यवस्था	३५५०	३८२१	३५००
असैनिक प्रबन्ध	१३५९१	१३३६४	१८७५०
मुद्रा और टकसाल	३७९	५०२	६३९
असैनिक निर्माण-कार्य और विविध सार्वजनिक सुधा कार्य	१५९०	१४५४	१५९३
पेंशने	८८४	८९८	९१७
विविध—			
विस्थापितों पर व्यय	२१४२	२१८६	२२५०
अन्य व्यय	३०२३	२८३२	४२९०
राज्यों आदि को अनुदान	३८००	२९६०	२५२३
असाधारण दर्दें	१४७०	२२४३	२३८६
रक्षा सेवाएं (शुद्ध)	२०३९७	२०२९५	२५२७१
जोड़—	५४५४३	५३३५५	६६३०९
अधिशेष (–) कमी (–)	–१८०४	+३७९४	–२६८७

साधनों को देखते हुए प्राथमिकताओं की समीक्षा और समायोजन तथा उनका कठोरता से परिपालन यद्यपि प्रयोजनीय है, फिर भी इस बात की पूरी सावधानी रखी जा रही है कि पिछले तीन-चार वर्षों में भारतीय अर्थ-व्यवस्था में जो प्रगति हुई है वह जारी रहे। हमारे बजट तैयार करने में—जो आवश्यक रूप से विकास की दृष्टि से तैयार किये जाते हैं—और नीति निर्धारित करने में चलने वाले कार्यों के अवश्यकरणीय पक्ष को बराबर ध्यान में रखा जाता है।

घाटे की बजाय बचत

चालू वर्ष (१९५६-५७) के बजट में, संसद द्वारा स्वीकृत वित्त विधेयक के संशोधनों को ध्यान में रखते हुए १८·०४ करोड़ रुपये की कमी का अनुमान किया गया था। अब मेरा अनुमान है कि वर्ष के अन्त में ३७·९४ करोड़ रुपये का अधिशेष रहेगा। इस सुधार का अधिकांश कारण सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क के संग्रह में वृद्धि है; केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क में वृद्धि का मुख्य कारण इस वर्ष लगाये गये अतिरिक्त शुल्क की प्राप्ति है। खर्च खाते में भी कुछ बचत हुई है। सम्पूर्ण रूप से, अब ५७१·४९ करोड़ रुपये के राजस्व, अर्थात् बजट अनुमानों से ४४·१० करोड़ रुपया अधिक और ५३३·५५ करोड़ रुपये के व्यय

(शेष पृष्ठ १२७ पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

१९५७-५८ का रेलवे बजट

१९५७-५८ में रेलवे यातायात से होने वाली कुल आमदनी का अनुमान ३६८.५० करोड़ रु० दिया गया है। यह राशि १९५६-५७ के संशोधित अनुमान से १८.-५० करोड़ रु० अधिक है।

१९५७-५८ में यात्री-यातायात से होने वाली आमदनी का अनुमान ११९ करोड़ रु० है। चालू वर्ष में इस मद में आमदनी का संशोधित अनुमान ११५.५ करोड़ रु० है। चालू वर्ष में पारसल आदि अन्य यातायात की आमदनी का संशोधित अनुमान २१.४ करोड़ रु० है, जिसके मुकाबले में अगले वर्ष का अनुमान २४ करोड़ रु० लगाया गया है।

माल यातायात

श्वेत-पत्र में यह आशा प्रकट की गई है कि १९५७-५८ में माल-यातायात चालू वर्ष की अपेक्षा ५ प्रतिशत अधिक रहेगा। चालू वर्ष में माल यातायात से आमदनी का संशोधित अनुमान २०६.५ करोड़ करोड़ रु० है, लेकिन अगले वर्ष के लिए इस मद में आमदनी का अनुमान २१८ करोड़ रु० रखा गया है। इस २१८ करोड़ रु० की राशि में ६। प्रतिशत की दर से लिए जाने वाले पूरक कर से होने वाली आमदनी भी शामिल है। अभी पूरक किराया लिया जाना तब तक जारी रहेगा, जब तक माल-भाड़ा जांच समिति की सिफारिशों पर विचार नहीं हो जाता।

इस समिति का प्रतिवेदन शीघ्र ही मिलने वाला है और आशा है कि इसी बजट वर्ष में समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया जायेगा और उन्हें लागू कर दिया जायेगा। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न वस्तुओं के रेल-भाड़े की दर में होने वाले परिवर्तनों के कारण उपर्युक्त अनुमान में भी हेरफेर करने पड़ेंगे।

फुटकर आमदनी का अनुमान चालू वर्ष के संशोधित अनुमान ७.३५ करोड़ रु० से ७५ लाख रु० अधिक रखा गया है। यह आशा व्यक्त की गई है कि भोजन-व्यवस्था विभाग से आमदनी बढ़ेगी।

रेलवे मंत्री श्री जगजीवन राम

संचालन-व्यय

१९५७-५८ में सामान्य संचालन-व्यय का अनुमान २८४.४२ करोड रु० है जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमान, २६८.९८ करोड़ रु० से १५.४४ करोड़ रु० अधिक है। यदि रेलवे के अपने माल के भाड़े आदि खर्च का भी हिसाब लगाया जाय तो यह वृद्धि केवल १४.८२ करोड़ रु० की रह जाती है।

अगले वर्ष माल और यात्री दोनों के यातायात में वृद्धि होने की आशा है। इसलिए रेलों को अधिक ट्रेनें तय करनी होंगी और अनुमान है कि इससे परिचालन का खर्च ४.६ करोड़ रु० बढ़ जायगा तथा डिब्बों की मरम्मत पर भी ३.३२ करोड़ रु० अधिक व्यय होगा। कर्मचारियों की वार्षिक तरक्की तथा बढ़े हुए काम को संभालने के लिये अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति के कारण कर्मचारी वर्ग पर भी इस वर्ष में ९.०३ करोड़ रु० अधिक खर्च होने का अनुमान है। इस वर्ष में फुटकर मदों में कुल १४.१२ करोड़ रु० खर्च होने का अनुमान है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सामान्य राजस्व को लाभांश

१९५७-५८ में सामान्य राजस्व को लाभांश के रूप में मिलने वाली राशि का अनुमान ४३.७९ करोड़ करोड़ रु० रखा गया है। चालू वर्ष के लिए संशोधित अनुमान ३७.६९ करोड़ रु० है। १९५७-५८ में पूंजी-गत लागत में जो १२४ करोड़ रु० की

भारत की सरकारी रेलों पर लगी हुई कुल पूंजी

(लाख रुपयों में)

रेलवे	१९५६-५७	१९५७-५८
१. मध्य रेलवे	२०१,७५	२०८,०२
२. पूर्व रेलवे	१४२,६०	१५०,५५
३. उत्तर रेलवे	१६५,००	१७१,९७
४. पूर्वोत्तर रेलवे	११७,४६	१२०,६७
५. दक्षिण रेलवे	१४४,१३	१५२,४३
६. दक्षिण-पूर्व रेलवे	११२,७३	१२८,४०
७. पश्चिम रेलवे	१४०,५७	१५०,५२
८. चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना	१९,४५	१८,३७
९. सरकारी डिब्बा कारखाना (पेरम्बूर)	९,१८	१२,९२
१०. सरकारी कोयले की खानें		
११. रेलवे बोर्ड और अन्य विविध मद	२,८७	५७,७०
१२. मोकामा-गंगा नदी पर (बड़ी लाइन का) रेल सड़क पुल	६,३३	८,००
१३. कलकत्ता बिजली योजना	४,९३	११,५२
१४. इंजन पुर्जा कारखाना बनारस	३	८
१५. मीटर लाइन सवारी डिब्बा कारखाना बरेली		५
जोड़	१०६७,०३	११९१,२०

वृद्धि हुई है, बजट के आंकड़ों में उसका भी समावेश है।

सामान्य राजस्व को लाभांश देने के बाद १९५७-५८ में शुद्ध लाभ का अनुमान २१.४३ करोड़ रु० लगाया गया है, जिसे विकास निधि में देनेका प्रस्ताव है।

निर्माण, मशीन और डिब्बों पर व्यय

दूसरी आयोजना में रेलों के लिए जो ११२५ करोड़

भारतीय रेलें

प्रति वैगन दिवस के विशुद्ध मील-टन

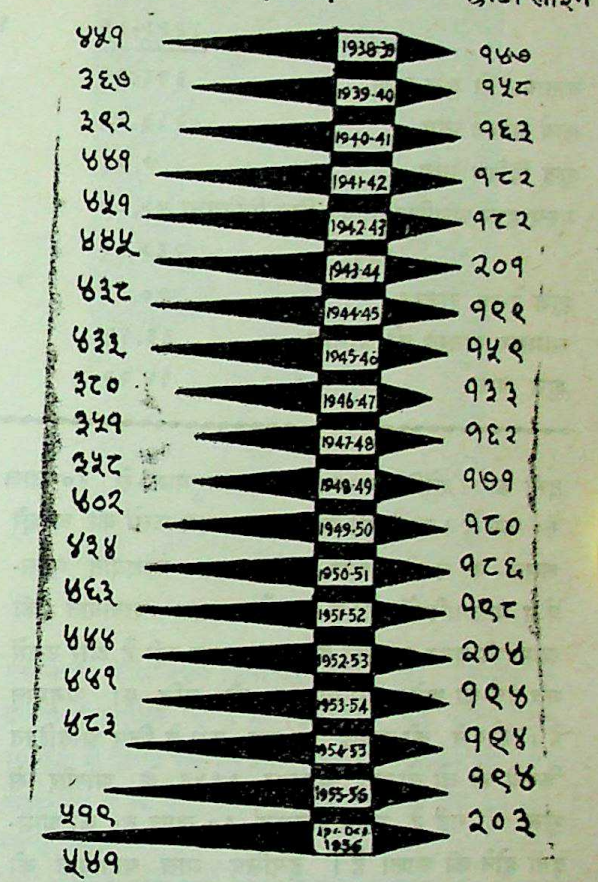

रु० की व्यवस्था है उसमें से १७८ करोड़ रु० पहले वर्ष में खर्च होनेका अनुमान है। योजना के दूसरे वर्ष १९५७-५८ में २१८ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। यह राशि डिब्बों, मशीनों और विभिन्न निर्माण कार्यों आदि पर व्यय की जायगी।

१९५६-५७ के संशोधित अनुमान

श्वेत-पत्र में कहा गया है कि चालू वर्ष में यात्री-यातायात बराबर बढ़ता रहा। यात्री यातायात की आमदनी का बजट अनुमान १११.४ करोड़ रु० था। उसको संशोधित अनुमान में बढ़ाकर ११५.५ करोड़ रु० कर दिया गया है। पारसल आदि अन्य यातायात की आम-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रेलवे बजट एक दृष्टि में

(करोड़ रुपये)

	वास्तविक १९५५-५६	बजट १९५६-५७	संशोधित अनुमान १९५६-५७	बजट १९५७-५८
यातायात से कुल प्राप्ति	३१६.२९	३४५.००	३५०.००	३६८.५०
कार्य चालन व्यय	२१३.२२	२२४.३०	२२९.३४	२४४.१६
शुद्ध विविध व्यय	७.७३	१३.०४	११.०२	१४.१२
मूल्य ह्रास आरक्षित निधिके लिए विनियोग	४५.००	४५.००	४५.००	४५.००
जोड़	२६५.९५	२८२,३४	२८५.३६	३०३.२८
शुद्ध रेलवे राजस्व	५०.३४	६२.६६	६४.६४	६५.२२
सामान्य राजस्व को लाभांश	३६.१२	३९.६७	३७.६९	४३.७९
शुद्ध बचत	१४.२२	२२.९९	२६.९५	२१.४३

दनी का संशोधित अनुमान बजट अनुमान से ४० लाख रु० कम है। इस कमी का प्रमुख कारण फलों की अच्छी फसल का न होना और कुछ पारसल यातायात एक्स-प्रेस मालगाड़ियों को दे देना है। माल यातायात की आमदनी बजट अनुमान के अनुसार चल रही है और उसमें गत वर्ष की अपेक्षा ८ प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। कोयले की ढुलाई पर कम दूरी के लिए अतिरिक्त किराये की जो योजना अक्टूबर १९५६ के आखीर से शुरू की गई है, उससे लगभग ९० लाख रु० की आमदनी होने की आशा है। इसलिए माल यातायात की आमदनी का संशोधित अनुमान २०६.५ करोड़ रु० है जो बजट अनुमान से लगभग १ करोड़ रू० अधिक है। फुटकर आमदनी का अनुमान ७.३५ करोड़ रु० है।

१९५६-५७ में यातायात से कुल आमदनी का संशोधित अनुमान ३५० करोड़ रु० है, जो बजट अनुमान से ५ करोड़ रु० अधिक है। प्रमुखतया यह वृद्धि यात्री यातायात में हुई है।

खर्च भी बढ़े

रेलवे के सामान्य संचालन व्यय का संशोधित अनुमान, बजट अनुमान २६२.०५ करोड़ रु. से बढ़कर २६८.९८ करोड़ रु० हो गया है। इस वृद्धि का कारण कोयले की कीमत में वृद्धि, फुटकर व्यय में वृद्धि, मजदूर कल्याण व्यय में वृद्धि, मजदूर कल्याण व्यय में वृद्धि है।

फुटकर व्यय का संशोधित अनुमान, बजट अनुमान १३.०४ करोड़ रु० से घटकर ११.०२ करोड़ रु० रह गया है। इस तरह १९५६-५७ में रेलों की शुद्ध आमदनी का अनुमान ६४.६४ करोड़ रु० है, जिसमें से ३७.६९ करोड़ रु० सामान्य राजस्व के लाभांश खाते का है और शेष २६.९५ करोड़ रु० शुद्ध लाभ है। यह सारा लाभ विकास निधि में दिया जायेगा।

पहली योजना की अवधि में किये गये विभिन्न उपायों के परिणाम-स्वरूप रेलवे की परिचालन दक्षता में बहुमुखी सुधार हुआ। पहली योजना की अवधि में यातायात से आमदनी ३९ करोड़ रु० बढ़ गयी। १९५०-५१ में इस मद में (रेल के अपने माल के भाड़े के अलावा) २४७ करोड़ रु० आमदनी थी, जो आयोजना के अन्तिम वर्ष में बढ़कर ३१६ करोड़ रु० हो गयी। यह वृद्धि १० करोड़ रु० यात्री-यातायात में ४ करोड़ रु० पारसल आदि अन्य यातायात में ५३ करोड़ रु० माल यातायात में और २ करोड़ रु० फुटकर आमदनी में हुई।

सामान्य संचालन व्यय आयोजन की अवधि में लगभग ४८ करोड़ रु० रहा। १९५०-५१ में १६५ करोड़

(शेष पृष्ठ १३० पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

१९५६ में भारत की अर्थ-व्यवस्था

श्री एन० एम० शाह

किसी देश की अर्थ-व्यवस्था का अनुमान नित्य बदलती हुई परिस्थितियों में एकाएक नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए आवश्यक है कि काफी लम्बे समय क भली प्रकार विद्यमान आर्थिक दशाओं का अध्ययन किया जाए। निस्संदेह इस कार्य के लिए आंकड़ों का अत्यन्त महत्त्व है, पर आंकड़े ऐसे हों जिनका संकलन निष्पक्ष दृष्टि से किया गया हो।

दुर्भाग्यवश हमारे देश में जो आंकड़े उपलब्ध हैं वे प्रायः दोषपूर्ण हैं। वे अद्यावधि नहीं हैं तथा उनकी तथ्यता भी संदेहास्पद है। पश्चिम के देशोंमें आंकड़ों के संकलन में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वे अद्यावधि हो और तथ्यपूर्ण हों। हमारे देश में विशेष ध्यान देने की बात यह है कि यहां आंकड़ों का संकलन और प्रकाशन सरकार या उसके तत्त्वावधान में गठित समितियों द्वारा किया जाता है। इसलिए तथ्यों में निष्पक्षता नहीं आ पाती, सब पर सरकारी विचारों की छाप लगी रहती है। इसके लिए एक उदाहरण यह है कि जिस समय सरकार ने अन्न पर नियंत्रण लगाया था उस समय प्रायः समस्त राज्यों ने अपनी पैदावार का अनुमान कम से कम लगाया और केन्द्रीय सरकार से गल्ले की लम्बी-लम्बी मांगें पेश कीं। सरकार ने यद्यपि उनकी ३।५ मांग पूरी कर दी, पर फिर भी नियंत्रण न हटाया जा सका। इसके अलावा, सरकार ने जब यह प्रकट करना चाहा कि उसकी सुन्दर अर्थ व्यवस्था का ही परिणाम है कि देश में इंगलैंड, अमेरिका आदि की अपेक्षा मूल्य में स्थिरता रही तो इसके लिए ऐसे सूचक अंकों का प्रमाण दिया गया, जिसका संकलन हाल के कुछ ही वर्षों के आधार पर किया था। ये आंकड़े अस्वाभाविक होने के कारण तथ्यहीन भी थे।

यही नहीं, इधर आर्थिक विकास के लिए जिन उपायों का आश्रय लिया जा रहा है उनसे भी विशेष संतोष व्यक्त नहीं किया जा सकता। केवल परिस्थितियोंका दास बन कर के हाथ पैर चलाना बन्द कर देना ठीक नहीं। आवश्यक है कि एक सुदृढ़ आर्थिक नीति का निर्माण करके उसका अनुसरण किया जाए तथा उसके परिणामों का

लेखक

सावधानी से अध्ययन किया जाए और इन्हीं परिणामों क प्रकाश में आर्थिक नीति का परिमार्जन भी होता रहे। समृद्धि के लक्ष्य तक सुरक्षित रूप में पहुँचने के लिए आवश्यक है कि ऐसी सुदृढ़ आर्थिक नीति के पथ का अनुसरण किया जाए।

आर्थिक समृद्धि के लिए पहले कंगाली का विनाश करना और आर्थिक आय एवं धन की असमानता को मिटाना आवश्यक है। १९५६ के वर्ष पर दृष्टि डालने पर यह नहीं कहा जा लकता कि हम इन दो बुराइयों को किसी भी प्रकार कम कर सके हैं। सच तो यह है कि घटनेके स्थान पर इनमें वृद्धि ही हुई।

आलोच्य वर्ष में थोक मूल्यों का स्तर ६० अंक याने १६ प्रतिशत ऊपर चढ़ा। विशेष उल्लेखनीय यह है कि खाद्य पदार्थों के मूल्य अपेक्षाकृत बहुत ज्यादे याने ९० अंक तक बढ़े। औद्योगिक कच्चे मालों के मूल्य में ८० अंक तक वृद्धि हुई। खाद्य पदार्थों के मूल्यों की इस अधिक वृद्धि का कारण यह है कि पिछले दो वर्षों में १९५३-५४ से १९५५-१९५६ तक खाद्य का उत्पादन ११९ (१९५३-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

५४) से घटकर १११ (१९५५-५६) ही रह गया।

१९५४-५५ में जितनी कुल कृषि उपज हुई वह १९५३-५४ की कुल कृषि उपज से कम थी। लेकिन १९५५-५६ में कृषि उत्पादन के सूचक अंकों में ११६ से लेकर ११४ तक कमी हुई। यही बात औद्योगिक कच्चे माल के उत्पादन के विषय में कही जा सकती है। अर्ध-निर्मित वस्तुओं का मूल्य भी ७१ अंक तक बढ़ा।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि सरकार की आयात के नियंत्रण की नीति के अनुसार, १९५१ के बाद हमारे औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होती रही। १९५१ के वर्ष के उत्पादन के सूचक अंक १०० मानते हुए १९५५ में औद्योगिक उत्पादन बढ़ कर १२२ हुआ और १९५६ के प्रथम ८ महीनों में १४८ तक बढ़ा। उत्पादन की वृद्धि और औद्योगिक लाभ के कारण कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि हो गई। निर्मित वस्तुओं का मूल्य विगत १२ महीनों में १४ अंक बढ़ा।

नियंत्रण के समय में मुद्रास्फीति का अधिक भार फुटकर वस्तुओं ही पर पड़ा; क्यों कि अन्न, कपड़ा और दूसरी दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के मूल्य पर सरकार ने नियंत्रण कर दिया था। लेकिन नियंत्रण के समाप्त हो जाने पर और इन वस्तुओं के स्वतन्त्र उत्पादन और संवहन पर किसी प्रकार की रोक न रहने के कारण अब फुटकर वस्तुओं पर मुद्रास्फीति का भार काफी कम हो गया है। फुटकर वस्तुओं के मूल्य स्तर पर ५६ अंक तक ही वृद्धि हुई, जो कि सामान्य मूल्य स्तर से कुछ कम है।

वर्षकी आरम्भिक अवधि में; जूट की वस्तुओं के लिए काफी मांग रही इससे इस उद्योग में अधिक उत्पादन के लिए उत्साह दिखाया गया। लेकिन शीघ्र ही मांग कम हो गई पर उत्पादन उसी के अनुसार बढ़ता ही गया। इधर जूट उद्योगों ने फिर ७॥ प्रतिशत तकुओं को बढ़ाने का निश्चय किया है।

औद्योगिक उत्पादनों के बढ़ने के साथ ही साथ विद्युत शक्ति का उद्योगों द्वारा प्रयोग भी बढ़ता गया। इस वर्ष में देश के उद्योगों ने १९४३ के वर्ष की अपेक्षा दुगुनी बिजली का उपयोग किया। १९५६ के वर्ष का औसत प्रति माह ४३० किलोवाट है।

जहां तक परिवहन की सुविधाओं का सम्बन्ध है विवेच्य वर्षमें कोई विशेष सुविधा नहीं मिली। स्थिति उसी प्रकार कष्टकारक है। इसलिए माल के इधर उधर भेजने में विशेष प्रगति नहीं हुई।

पूरे साल तक आयात लगातार बढ़ता रहा और घटते विदेशी व्यापार के कारण व्यापार संतुलन विपक्ष में रहा, जिससे १९५६ के ११ महीनों में २०० करोड़ रुपए की हानि हुई। इस कारण आयात में सख्ती बरती गई और इधर १९५७ की पहले छः महीनों में और भी अधिक सख्त नीति अपनाने का निश्चय किया गया है।

विवेच्य वर्ष में २०० करोड़ रुपए की मुद्रा चलन में बढ़ी। इसका कारण विदेशी व्यापार में असन्तुलन और देश के घाटे की अर्थ व्यवस्था है। विगत १८ महीनों में मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि २५ प्रतिशत तक पहुँची। इस मूल्य वृद्धि ने सरकार को घाटे की अर्थ व्यवस्था के परिणाम से उत्पन्न खतरों से सतर्क रहने को चेतावनी दे दी है। पहले विस्तृत आर्थिक विकास के हेतु, आगामी पांच सालों में जो १२०० करोड़ रुपए की घाटे की अर्थव्यवस्था का विचार था, यह देश के लिए अत्यधिक मानते हुए अब इस विचार का त्याग करके, वित्तमंत्री ने योजना के लिए देश के उपलब्ध सभी साधनों के उपयोग का निश्चय किया है। इसी लिए नये बड़े बड़े कर लगाए गए हैं।

वित्तमंत्री कई बार कह चुके हैं कि योजना को सफल बनाने के लिए हर संभव उपायों का सहारा लिया जाएगा और हर सूरत में योजना को सफल बनाना है, भले ही इसके लिए सर्वतंत्रवादी मार्ग का अनुसरण क्यों न करना पड़े। यह धमकी बेकार है क्योंकि यदि सरकार घाटे की अर्थव्यवस्था के खतरों का मुकाबला ठीक प्रकार से नहीं करेगी तो आर्थिक परिस्थितियों से मजबूर होकर सरकार को योजना के आकार में एक चौथाई से लेकर एक तिहाई तक कमी करनी ही पड़ेगी।

सम्पदा के बम्बई स्थित प्रतिनिधि
श्री टी० एन० वर्मा
चोगे बंगला, गोराई रोड,
बोरिवली, बम्बई।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारत व अमरीका में व्यापार

आज कल विभिन्न देशों से व्यापारियों के प्रतिनिधि मण्डल भारत में आ रहे हैं। इन सबका उद्देश्य भारत के विकासशील बाजार में अपना स्थान प्राप्त करना या बढ़ाना है। इसी दृष्टिसे अमेरिका का एक प्रतिनिधि मण्डल भारत में आया हुआ है। इसके नेता अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकास विभाग के संचालक श्री प्रेंस्टन फोर्ब्स हैं। संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका भारतीय सामग्री का बहुत बड़ा ग्राहक है। भारत से निर्यात होने वाले प्रत्येक रुपये के माल में २॥ आने का माल केवल अमेरिका को जाता है। १९५५-५६ में २७ करोड़ रुपये का माल अमेरिका में गया था, जबकि भारत के कुल निर्यात ५९१ करोड़ के हुए थे। इसका अर्थ यह है कि कुल निर्यात का १४.७ प्रतिशत व्यापार अमेरिका के साथ हुआ। निर्यात की मुख्य वस्तुयें निम्नलिखित हैं:—

१९५५-५६ में अमेरिका को निर्यात

	मात्रा	करोड़ रुपये
जूट का कपड़ा (टन)	१७३२५९	२८.८७
चाय (लाख पौंड)	२५४,४	६.७८
मैंगनीज ओर (टन)	३२१२५९	४.०५
अबरक (हण्डरवेट)	११४३४४	३.६१
कालीमिर्च (,)	१३२२६४	२.३१

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से भारत को भी कम सामान नहीं आता। १९५५-५६ में कुल ६५० करोड़ रुपये का सामान विदेशों से भारत में आया। इसमें से १३.७ प्रतिशत अर्थात् ८९ करोड़ रुपये का सामान अमेरिका से आया। इनमें से कुछ प्रमुख वस्तुएं निम्नलिखित मात्रा में हैं--

	करोड़ रुपये में	मात्रा में
मशीनरी और मिल का सामान	१६.५४	
स्टील शीट	६.९३	८८७१८ टन
गाड़ियां	५.८८	९४६१
तरह-तरह के मशीनरी के तेल	४.४९	२४८.६लाख गैलन
तांबा	२.२७	९७४०२ हण्डरवेट
दवाइयां	२.३०	
रासायनिक पदार्थ	१.५१	

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रतिनिधि-मण्डल यह सोचेगा कि दोनों देशों में व्यापार किस तरह बढ़ाया जा सकता है। भारत से उपर्युक्त वस्तुओं के अतिरिक्त रेशम, हाथ करघे का कपड़ा, अन्य कलापूर्ण वस्तुओंका निर्यात अमेरिका में बढ़ाया जा सकता है। यदि अमेरिकामें निर्यात-कर कम कर दिये जायें तो भारतीय सामग्री अधिक मात्रा में अमेरिका भेजी जा सकती हैं। इसी तरह यह भी प्रतिनिधि मण्डल को सोचना है कि अमेरिका किस तरह से भारतीय व्यापार उद्योग को सहायता दे सकता है। आज विदेशों को निर्यात बढ़ाये बिना भारत अपनी कठिनाइयों को हल नहीं कर सकता।

★

मिलों व तकुओं का संसार

कुछ दिन पहले मानचेस्टर के इन्टरनेशनल कौटन फेडररेशन ने सूती मिलों की जांच पड़ताल की थी। उससे कई मनोरंजक तथ्य सामने आये। यद्यपि इंगलैंड में तकुओं की संख्या बढ़कर १३ करोड़ १३ लाख ४० हजार हो गई (गतवर्ष की संख्या १२ करोड़ ९८ लाख ३८ हजार थी) तथापि योरोप की कुल संख्या पहले से घट गई है। १९५५ में वहां ७ करोड़ ४४ हजार तकुये थे। लेकिन १९५६ में ६ करोड़ ८८ लाख ९५ हजार रह गये इधर एशिया में नये नये उद्योगों के खुलने की वजह से तकुओं की संख्या, गतवर्ष की संख्या २॥। करोड़ से बढ़कर ३ करोड़ १६ लाख ६६ हजार हो गई है। उत्तरी अमेरिका में भी कुछ परिवर्तन हुआ है। दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका में बहुत कम उन्नति हुई है।

भारत में तकुए, कम तो हैं, किन्तु मिलों में २-३ पालियों की वजह से एक तकुए पर इंगलैंड की अपेक्षा बहुत अधिक, तिगुना काम होता है। यह हिसाब लगाया गया है कि अन्य ४५ देशों की अपेक्षा, जिनके अंक संग्रह किये गये हैं, ब्रिटेन में सबसे कम समय प्रति तकुए पर काम होता है। हांगकांग में ८,५२३ घन्टे एक वर्ष में काम होता है और भारत में ५,६०२ घन्टे, जबकि ब्रिटेन में कुल १५२६ घन्टे काम होता है। योरोप के फ्रान्स, जर्मनी, बेलेजियम, और नीदरलैंड में क्रमशः ३३२५, ३७२९, ३६८८ और ४३०८ घन्टे काम होता है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जहाजी उद्योग में इंगलैंड पिछड़ रहा है

किसी समय ब्रिटेन अपने प्रसिद्ध जहाजी व्यवसाय के कारण 'जहाजों की रानी' नाम से प्रसिद्ध था। लेकिन उसका साम्राज्य समाप्त होता जा रहा है—वह संसारका सबसे सम्पन्न देश, सबसे बड़ा औद्योगिक देश, संसार का बैंकर आदि अपनी प्रसिद्धियां भी छोड़ता जा रहा है इसी प्रकार जहाजी क्षेत्र में भी वह अपना प्रथम स्थान कायम नहीं रख पा रहा है। नये साल के अंकों से ज्ञात होता है कि जहाज-निर्माण में जापान उससे आगे है। लौयडस के वार्षिक प्रकाशन से मालूम होता है, कि १९५६ में जापान ने १७,४६,४२९ टन के व्यापारिक जहाज बनाये थे अर्थात् सारे संसार में बनने वाले कुल जहाजों के २६ प्रतिशत। ब्रिटेन ने कुल जहाज इस वर्ष में १३,८३,३८७ टन बनाये अर्थात गतवर्ष से ९०,५५० टन कम। यह संख्या संसार के जहाज निर्माण की दृष्टि से २०.१ प्रतिशत है।

संसार में जहाजों का कुल निर्माण-उत्पादन ६६,७३,७०१ टन हुआ है। जापान के बाद जर्मनी का स्थान है। जहां इस वर्ष १०,००,४९८ टन के जहाज बने। इटली ने भी जहाज निर्माण में बहुत उन्नति की है, जैसा कि नीचे अंकों से स्पष्ट है :—

१९५५	१९५६
१,९०,७४९ टन	३,५८००६

और आयल टैंकों के निर्माण में भी ब्रिटेन जापान से पीछे है। जापान में २४% बनाये गये, जबकि ब्रिटेन ने २३% बनाये।

जहाजों के निर्यात में भी जापान आगे है, जैसा कि नीचे लिखे अंकों से स्पष्ट है—

जापान	१२४१८२० टन
जर्मनी	६२०६३१ "
ब्रिटेन	३१४६७७ "

★

स्विटजरलैण्ड में औद्योगिक प्रदर्शनी

मार्च अप्रैल मई के महीने ऐसे हैं, जबकि यूरोप के भिन्न-भिन्न देशों में औद्योगिक प्रदर्शनियां हुआ करती हैं। स्वीटरजरलैंड की ४१ वीं औद्योगिक प्रदर्शनी २७ अप्रैल से ७ मई तक होगी। इसमें २३०० प्रदर्शक अपनी-अपनी चीजें दिखायेंगे। यह वस्तुयें १७ विभिन्न वर्गों में बटी हुई होंगी। कलापूर्ण वस्तुयें, दफ्तरों की आवश्यकताएं, कागज छपाई, जूते तथा चमड़े का सामान खिलौने, संगीत यंत्र, घड़ियां, वाहन, रासायनिक और शृंगार सामग्री आदि आदि। इस दृष्टि से यह प्रदर्शनी विदेशी व्यापारियों के लिये बहुत उपयोगी होगी। १९५६ की प्रदर्शनी में यूरोप के ३० और समुद्रपार के ५६ देशों के ३०००० यात्री आये थे। इस वर्ष की प्रदर्शनी और भी अधिक उपयोगी व आकर्षक होगी।

[शेष पृष्ठ १३२ पर]

नई दिल्ली व दिल्ली में सम्पदा

सम्पदा के फुटकर अंकों और विशेष कर विशेषांकों की मांग अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों में बनी रहती है। उनकी सुविधा के लिए आत्माराम एण्ड सन्स, काश्मीरी गेट, दिल्ली (हिन्दी विभाग) में सम्पदा की बिक्री की व्यवस्था कर दी गई है।

नई दिल्ली में सम्पदा के विक्रेता सेंट्रल न्यूज एजेंसी, कनाट सर्कस हैं।

इस प्रबन्ध से आशा है, दिल्ली के अर्थशास्त्र-प्रेमियों की असुविधा दूर हो जायगी।

— मैनेजर सम्पदा

अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नया सामयिक साहित्य

लेखक—श्री मोहनलाल मिश्र,

भारतीय परिवहन—प्रकाशक-जयप्रकाश नाथ एण्ड कम्पनी, मेरठ। मूल्य ३।)।

प्रसन्नता की बात है कि कालिजों में अर्थशास्त्र के हिन्दी में शिक्षण का निश्चय करने के बाद हिन्दी में अर्थशास्त्र के साहित्य का प्रकाशन काफी होने लगा है। और यह इस बात का प्रमाण है कि हिन्दी में पुस्तकों की कमी एक दम दूर हो सकती है, यदि शिक्षा विभाग किसी विषय को हिन्दी में पढ़ाने का निश्चय कर ले। मांग के साथ प्राप्ति का अर्थशास्त्रीय नियम शिक्षा-सम्बन्धी पुस्तकों पर भी लागू होता है। सम्पदा के सुपरिचित लेखक श्री शिवध्यानसिंह चौहान के बाद ही परिवहन पर यह दूसरी पुस्तक हमारे देखने में आयी है। लेखक अनेक वर्षों से अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। इसलिए यह स्वाभाविक है, कि वे विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को अनुभव करें।

प्रस्तुत पुस्तक में करीब १०० पृष्ठ रेलवे, ४५ पृष्ठ सड़क-परिवहन, और ४० पृष्ठ जल-परिवहन, और ३० पृष्ठ वायु-परिवहन पर दिये गये हैं। इन सब परिवहन-साधनों के इतिहास, प्रगति विकास के लक्ष्य तथा तत्संबंधी समस्याओं का परिचय देने का लेखक ने प्रयत्न किया है। रेल उद्योग व भाड़ा निर्धारण के दिए शास्त्रीय सिद्धांतों की चर्चा के साथ साथ यदि आजकल उद्योग व्यापार मंडल द्वारा दिये गये सुझावों का परिचय दे दिया जाता तो पुस्तक अधिक उपयोगी हो जाती। भारतवर्ष के परिवहन में जिस तरह बैलगाड़ियों व छोटी नावों का स्थान लुप्त होता जा रहा है, उसकी ओर लेखक बहुत ध्यान नहीं दे पाये हैं। राष्ट्रीयकरण के विरोधी पक्ष का भी लेखक सन्तोषजनक उत्तर नहीं दे पाये। फिर भी पुस्तक अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिये बहुत उपयोगी है।

खादी ग्राम विकास लेखक—श्री प्रभुदास गांधी, प्रकाशक—सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली। मूल्य ।।।)।

अभी तक पश्चिमी अर्थशास्त्र को ही अर्थशास्त्रीय रूप दिया गया है। यह स्वाभाविक भी था। १७७६ से एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र की जो परम्परा जारी की, वह आज प्रमुख अर्थशास्त्री कीन्स तक बहुत विकसित हो चुकी है। भारत के अर्थशास्त्रियों ने उसी अर्थशास्त्र का अनुसरण करके सैंकड़ों पुस्तकें लिखी हैं। भारत सरकार की ओर से चलने वाले बड़े-बड़े अनुसन्धान विभाग भी पश्चिमी अर्थशास्त्र के आधार पर गवेषणा कर रहे हैं। विश्व-विद्यालयों में भी इसी अर्थशास्त्र की शिक्षा दी जाती है। यही कारण है कि भारतीय अर्थशास्त्र, जिसका उद्गम वस्तुतः गांधी जी के चरखे के साथ हुआ है, अभी तक विकसित नहीं हो पाया। बहुत कम पुस्तकें इस दृष्टि से प्रकाशित हुई हैं। इस दिशा में अनुसन्धान तो बहुत ही कम हुआ है। प्रस्तुत पुस्तक इस दिशा में एक सुन्दर प्रयत्न है।

श्री प्रभुदास गांधी का जीवन ग्रामों में खादी द्वारा सेवा में बीता है। योजनाओं और शोध के अंकों के आज के युग में उन्होंने यह अनुभव किया है कि केवल भावुकता के आधार पर खादी का प्रचार नहीं हो सकता। इसके लिये परिश्रम पूर्वक व्यक्ति और ग्राम की आवश्यकताओं तथा उनकी पूर्ति के साधनों पर विचार करना आवश्यक है। इसी दृष्टि से लेखक ने वर्षों तक ग्राम-सेवा करते हुए जो अनुसंधान किया है, उसको इस पुस्तक में उन्होंने सरल शब्दों में लख दिया है।

प्रस्तुत पुस्तक में खादी के विरोध में उठने वाले प्रश्नों का उत्तर देते हुए एक स्वावलम्बी गांव की आवश्यकताओं का विस्तार से वर्णन करने के बाद यह बताया गया है कि वे आवश्यकताएं कैसे पूरी की जा सकती हैं। अपनी प्रत्येक स्थापना के लिए विस्तृत अंक दिये गये हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि खादी अर्थशास्त्र केवल कल्पना और भावुकता की चीज नहीं है। वह व्यावहारिक कठिनाइयों को हल करने का प्रमुख साधन है। हम विचारशील अर्थशास्त्रियों से अनुरोध करेंगे कि वह श्री गांधी के प्रयत्नों का अध्ययन करें और गम्भीरता से यह सोचें कि भारत के आर्थिक विकास में ग्रामोद्योगों का कितना उपयोग किया जा सकता है।

—कृष्ण

गांधी-मार्ग—त्रैमासिक, सम्पादक ऐस० के जार्ज प्रकाशक—गांधी स्मारक निधि, मणिभुवन, लेबरसम रोड बम्बई—७, पृष्ठ सं० ७२, मूल्य १२ आने।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इसी जनवरी से, गांधी स्मारक निधि के प्रकाशन विभाग ने, 'गांधी-मार्ग' नाम की त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ किया है। इस पत्रिका का उद्देश्य, जनसाधारण में सम्मुख गांधी जी के विचारों और कार्य प्रणालियों को रखना है। इसी हेतु समय समय पर देश-विदेश के लेखकों-विचारकों की रचनाओं का प्रकाशन किया जाता रहेगा कि 'गांधीवादी जीवन-प्रणाली को खुले तौर पर चारों ओर फैलाया जा सके और वर्तमान समस्याओं पर उसे चरितार्थ भी किया जा सके।' साथ ही गांधी स्मारक निधि की सहायता से चलने वाली समस्त रचनात्मक संस्थाओं का कार्य-विवरण भी इसमें छपता रहेगा।

हमारे सम्मुख इस पत्रिका का प्रथम अंक है। इसमें उद्देश्य के अनुसार ही गांधीवादी विचारधारा-सम्बन्धी देशी-विदेशी विद्वानों के लेख संग्रहीत हैं।

वैसे पत्रिका सभी के लिए उपयोगी है, पर गांधीवादी अर्थशास्त्र में रुचि रखने वालों को यह विशेष रुचेगी।

विश्व-ज्योति—मासिक। (नव वर्ष विशेषांक) सह सम्पादक-विश्वबंधु और संतराम, पृष्ठ १३२, मूल्य १॥)।

विश्वेश्वरनन्द वैदिक रिसर्च इन्स्टीट्यूट होशियारपुर (पंजाब) के तत्वावधान में विश्वज्योति नाम की उच्चकोटि की साहित्य-सांस्कृतिक मासिक पत्रिका पिछले ५ वर्षों से प्रकाशित हो रही है। मार्च में छठे वर्ष में प्रवेश कर लेने पर इस पत्रिका ने अपना नव वर्षांक प्रकाशित किया है। इस विशेषांक में उत्कृष्ट लेख कविता कहानी, एकांकी आदि का चयन किया गया है। श्री वासुदेव शरण का 'भारतीय धर्म तत्त्व' श्री राम चन्द्र तिवारी का भारतीय "संस्कृति का मूलमंत्र तथा श्री परमेश्वरीलाल का 'प्रागैतिहासिक भारत की खोज' लेख विवेचनीय हैं। पत्रिका की छपाई-सफाई उत्तम व आकर्षक है।

राष्ट्रधन—(विशाल उद्योग अंक)—गो. से. अर्थ-वाणिज्य महाविद्यालय नागपुर की पत्रिका। सम्मिलित पृष्ठ संख्या १३२।

नागपुर का सुप्रसिद्ध गो. से. अर्थ-वाणिज्य महाविद्यालय 'राष्ट्रधन' नाम की एक आर्थिक पत्रिका प्रकाशित करता करता है। पत्रिका का आठवां अंक विशाल उद्योग अंक के रूप में हमारे सम्मुख है। पत्रिका के ३ विभाग हैं—मराठी, हिन्दी और अंग्रेजी। तीनों विभागों में विशाल उद्योगों-सम्बन्धी विभिन्न दृष्टिकोणों से विभिन्न लेख दिये गये हैं। योजना के अन्तर्गत विशाल उद्योगों का क्या स्थान है, विशाल उद्योगों की स्थिति और समस्या क्या है, तथा लोहा, सीमेंट, वस्त्र, कोयला, जहाज निर्माण आदि अन्य समस्त उद्योग सम्बन्धी जानकारी इस पत्रिका में मिल जाती है।

खेती—(कृषि-यंत्र विशेषांक) मासिक, पृष्ठ संख्या ९६, सम्पादक—एम० जी० कामन। मूल्य ८ आने।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् नयी दिल्ली, खेती नामक कृषि की मासिक पत्रिका प्रकाशित करती है। इसमें कृषि सम्बन्धी अनुसंधानों की चर्चा भी रहती है। नवें वर्ष के नवें अंक को, कृषि यंत्र विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया गया है। इस अंक में कृषि अनुसंधान परिषद ने खेती के औजारों सम्बन्धी जो प्रगति की है, उसका परिचय और यंत्रों की जानकारी दी गयी है। परिषद की धारणा यह है कि ये यंत्र ऐसे हैं जो बनावट में आसान हैं, उनकी कीमत भी सस्ती है। पुर्जे आसानी से आस पास के बाजारों में मिल सकते हैं तथा गांव के बढ़ई-लोहार भी उनका मरम्मत कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि ये बैलों द्वारा चलाये जाते हैं तथा किसान, भूमि और फसल के बिल्कुल उपयुक्त हैं।

भारत के विभिन्न प्रदेशों में प्रयुक्त होने वाले कृषि यंत्रों के विवरण के साथ ही विदेशों में प्रयुक्त होने वाले यंत्रों का परिचय भी दे दिया गया है।

प्राप्ति स्वीकार

१. कब तक पुकारूं ?—(उपन्यास) लेखक—श्री रांगेय राघव पृष्ठ६६०। मूल्य ८रु०। प्रकाशक राजपाल एण्ड सन्ज दिल्ली।

२. धरती हमारी है, (नाटक) ले० विलियम काजलेकी पृष्ठ—८०। मूल्य २ रु० प्रकाशक वही।

३. वाल्मीकि रामायण—(सुगम हिन्दी रूपांतर) रूपांतरकार—आनन्दकुमार, पृष्ठ—३२४। मूल्य ३ रु० प्रकाशक वही।

४. बीरबल की कहानियां—लेखक—श्री आनन्दकुमार,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अर्थ वृत्त चयन

सम्पत्ति कर क्या है ?

डा० कैल्डर ने सम्पत्ति करके के बारे में जो सुझाव दिये हैं, उनके अनुसार सब प्रकार की सम्पत्ति पर चाहे वह खेती की जमीन हो, चाहे मकान हो, स्टौक शेयर हों, बैंकों में पड़ा रुपया हो, जेवर हों या कोई दूसरा कीमती सामान हो, बाजार दर से उसका अनुमान लगाकर के टैक्स लगाया जावेगा। घरेलू फर्निचर, कपड़े तथा बैंकों में जमा रुपये पर कुछ सीमा तक छूट दी जायेगी।

१,००,००० रुपये से नीचे	कुछ नहीं
१,००,००० रुपये से ४,००,००० रुपये तक	$\frac{1}{3}$ प्र० श०
४,००,००० रुपये से ६,००,००० रुपये तक	$\frac{1}{2}$ प्र० श०
७,००,००० रुपये से १०,००,०००० रुपये तक	$\frac{3}{4}$ प्र० श०
१०,००,००० रुपये से १५,००,००० रुपये तक	१ प्र० श०
१५,००,००० रुपये से ऊपर	$1\frac{1}{2}$ प्र० श०

सरकार ने इस सुझाव पर अभी कोई विचार नहीं किया है। सम्भवतः नई संसद में नया मंत्रिमण्डल बजट पेश करते हुए इस सम्बन्ध में कोई विचार करेगा। यदि यह कर लग गया तो कल्पना की जा सकती है कि सरकार को कितनी भारी आमदनी होगी। एक अनुमान के अनुसार सरकार को २० २५ करोड़ रुपया प्रतिवर्ष आमदनी होगी।

★

व्यय-कर

श्री कैल्डर ने लोगों के निजी खर्चे पर भी कर लगाने का सुझाव पेश किया है। प्रति व्यक्ति वार्षिक १० हजार रुपये तक के व्यय पर कर नहीं लगेगा। इससे ऊपर होने वाले व्यय पर २५ प्रतिशत या अधिक के हिसाब से कर लगेगा। इस खर्च में वे खर्च भी शामिल किये जायेंगे जो उसके नियम के द्वारा किये जाते हैं—जैसे शिक्षा, चिकित्सा, निवास, नौकर, सवारी आदि मित्रों और सम्बन्धियोंके द्वारा किये गये व्यय भी सम्मिलित किये जायेंगे।

गणना के लिये नाबालिग दो बच्चों का खर्च एक व्यक्ति के खर्च के बराबर समझा जायेगा। यदि एक परिवार का कुल व्यय ४५ हजार रुपया वार्षिक होता है जिसमें दो वयस्क और दो बालक हों तो प्रति व्यक्ति १५००० रुपये व्यय समझा जायेगा और १०००० रुपये की छूट देकर ५ हजार रुपया प्रति व्यक्ति के व्यय पर कर लिया जायेगा। यह कर क्रमशः बढ़ता जायेगा। १०००० से १२५०० तक व्यय पर २५ प्रतिशत कर लगेगा और बढ़ते-बढ़ते ५०००० से ऊपर के निजी खर्च पर ३०० प्रतिशत कर लगेगा।

★

विदेशों से तुलना

भारतीय उद्योग-व्यापार मण्डल ने एक पुस्तिका प्रकाशित कर सम्पत्ति कर के तुलनात्मक आंकड़े दिये हैं। अभी तक स्वीडन, नीदरलैण्ड और जापान में यह कर लगाया गया है। इन तीनों देशों के कर तथा भारत के प्रस्तावित करों के तुलनात्मक आंकड़े निम्नलिखित हैं:—

कुल सम्पत्ति रुपये	स्वीडन	जापान	नीदरलैण्ड	भारत
३०,०००	—	—	—	—
५०,०००	०.०४०	—	०.२३	—
१,००,०००	०.२९३	०.१७	०.४२	०.३३३
२,००,०००	०.६३२	०.५०	०.५२	०.३३३
५,००,०००	१.११२	१.२८	०.६०	०.३६६
१०,००,०००	१.३७१	१.९७	०.६५	०.५०८
५०,००,०००	१.७१४	२.८०	०.६९६	१.२५१
१,०० ००,०००	१.७५७	२.८०	०.६९८	१.३७५
१०,००,००,०००	१.७९६	२.८०	०.७००	१.४८८
५०,००,००,०००	१.७९२	३.००	०.७००	१.४९८

पृष्ठ—३२ मूल्य १२ आने प्रकाशक—वही।

५. हमारे पक्षी (पद्य मय) लेखक—श्री रुद्रदत्त। मूल्य १२ आने, प्रकाशक, वही।

इन पुस्तकों की समालोचना आगामी अंकों में की जायेगी।

सफ़ेद कोढ़ के दाग

हजारों के नष्ट हुए और सैकड़ों के प्रशंसापत्र मिल चुके

दवा का मूल्य ५) रु० डाक व्यय १) रु०

आर्थिक विवरण मुफ्त मँगाकर देखिये।

वैद्य के० आर० बोरकर

मु० पो० मंगरूलपीर, जिला अकोला (मध्य प्रदेश)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारत में ऊंटों की गणना

भारत में ऊंटों की गणना के अनुसार सबसे अधिक ऊंट राजस्थान और सबसे कम ऊंट सौराष्ट्र में मिलते हैं। उनकी तालिका इस प्रकार है: —

राजस्थान—	३,४५,३६५	पंजाब—	१,२१,४९५
पेप्सू—	७३,७९४	उत्तर प्रदेश—	३८,९४४,
बम्बई—	२५,८१२	मध्यभारत—	१०,९८२,
कच्छ	९,०५७ और	सौराष्ट्र—	३,१७४

ये आंकड़े सन् १९५५ की गणना के अनुसार हैं।

इसी प्रकार सन् १९२० से सन् १९५१ तक भारत में ऊंटों की संख्या इस प्रकार बताई जाती है—

सन् १९२०	—४,७६,०६०	ऊंट
सन् १९२५	—४,६०,९२५	,,
सन् १९३०	—९,११,२४७	,,
सन् १९३५	—८,४३,०९७	,,
सन् १९४०	—८,०९,३२४	,,
सन् १९४५	—६,५३,५८०	,,
सन् १९५१	—६,२९,०८७	,,

[इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं कि भारत में वर्ष-प्रतिवर्ष ऊंटों की संख्या कम होती जा रही है, जिसके कई कारण हैं। इस पशु को उचित संरक्षण नहीं होने से तथा इसके काम को नहीं सराहने से इसका ह्रास हो रहा है।]

★

नमक, सेंधा नमक भी

देश के विभाजन के बाद नमक की कमी पड़ गई। मुख्यकर पश्चिमी पंजाब की चट्टानों का उच्च कोटि का सेंधा नमक, जिसकी बाजार में खूब खपत थी, पाकिस्तान में चला गया। सरकार भी नमक की कमी दूर करने का प्रयत्न करती रही। अब तो देश नमक में आत्म निर्भर हो चुका है।

१९५५ में नमक का कुल उत्पादन ६५ लाख टन था। १९३७ के अन्त तक, नमक का उत्पादन बढ़कर ७० लाख हो जाने की आशा है। यह मात्रा देश की आवश्यकता को केवल पूरी ही न करेगी वरन् देश नमक का काफी निर्यात करने में भी समर्थ हो जाएगा।

अब हिमाचल प्रदेश में स्थित डारंग में नमक की चट्टानों का पता लग चुका है। इससे सेंधा नमक की भी स्थान पूर्ति हो सकेगी। सरकार ने इसी हेतु डारंग में ९० लाख की लागत का देश की सबसे बड़ी नमक निर्माणशाला की स्थापना करने का निश्चय किया है। निर्माणशाला के लिए बड़ी-बड़ी मशीनों को संगाने की प्रारम्भिक कार्यवाही हो चुकी है। देशी और स्वदेशी फर्मों को इसके आर्डर दिए जा चुके हैं। पूर्ण मशीनों के प्राप्त हो जाने पर वास्तविक कार्य आरम्भ हो जाएगा।

इस समय अविकसित रूप में इन खानों से १००० टन नमक प्रतिदिन के हिसाब से प्राप्त होता है, पर यह केवल जानवरों के उपयोग में ही आता है। कारखाने का पूर्ण विकास होने पर खानों का पूर्ण शोषण संभव हो जाएगा। नमक को साफ करने के उपकरणों की व्यवस्था हो जाने पर फिर ६६,००० टन का शुद्धतम नमक प्राप्त होने लगेगा।

★

सोने का विश्व में उत्पादन

लन्दन के सैम्बुअल मांटेगू बुलियन हाउस से प्रकाशित वार्षिक विवरण से प्रकट होता है कि (रूस सोवियत यूनियन) को छोड़कर कुल संसार में २८१ लाख औंस सोना १९५६ में निकाला गया है। इसमें से ८१.८ प्रतिशत सोना केवल ब्रिटिश कौमनवैल्थ में हुआ है। गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष १० लाख औंस ज्यादा सोना पैदा हुआ है। विभिन्न देशों का उत्पादन निम्नलिखित है :—

उद्योग विभाग, उत्तरप्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

सचित्र मासिक पत्र

उद्योग

पढ़िये, जिसमें भारत के आर्थिक विकास, विशेषकर उत्तरप्रदेश की औद्योगिक प्रगति के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण लेखों के साथ साथ अन्यान्य मनोरंजक साहित्यिक सामग्री कविताएं, कहानियां और लेख भी उपलब्ध होंगी।

विवरणार्थ लिखें :

प्रकाशनाधिकारी
उद्योग विभाग
उत्तरप्रदेश—कानपुर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(हजार औंसों में)

	१९५६	१९५५
दक्षिणी अफ्रीका	१५,८९१	१४,६०१
कैनाडा	४,३७९	४,५५२
अमेरिका	१,८५०	१,८७७
आस्ट्रेलिया	१,०४५	१,०४९
गोल्डकोस्ट (घाना)	६३८	६८७
दक्षिणी रोडेशिया	५३५	५२५
फिलिपाइन्स	४००	४१६
मैक्सिको	३५०	३७९
कोलम्बिया	४४०	३८१
कांगो	३५०	३७०
जापान	२९७	२८९
भारत	२००	२११
ब्राजील	१७०	१४५
चिली	८५	१२३
पेरु	१५०	१६३
न्यू गायना	७०	७४
फिजी	७०	७४
टांगानिका	६०	६९
स्वीडन	१००	१००
न्यूजीलैंड	२५	२७
अन्य देशों में	१,०१२	१,०२२
रूस को छोड़कर शेष संसार	२८,१००	२७,१२४
ब्रिटिश कामनवैल्थ	२८,९८०	२१,९२४
ब्रिटिश कामनवैल्थ प्र० श०	८१.८	८०.८
द० अफ्रीका यूनियन प्र० श०	५६.६	५३.८

★

रहन सहन और आय-व्यय के क्रम

गांवों में और शहरों में आमदनी के अन्तर से व्यय में भी विशेष अन्तर पड़ जाता है। जब आमदनी कम होती है तब उसका बड़ा भाग जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये व्यय होता है : आमदनी ज्यादा होने पर कुछ कम आवश्यक वस्तुओं पर व्यय बढ़ता जाता है। इस सम्बन्ध में गत कुछ वर्षों में सर्वे की गई है। हम नीचे तीन तालिकायें दे रहे हैं। इनसे यह स्पष्ट होगा कि भिन्न २ आय के कारण हमारे व्यय किस तरह घटते बढ़ते हैं :—

व्यय के विभिन्न मदों में विभाजन

	ग्राम	कस्बे	बड़े शहर
भोजन	६५.५६	५४.७४	४६.१२
कपड़े	६.१२	६.५०	६.९१
मकान	१.४०	२.९८	६.८६
ईन्धन व रोशनी	६.७३	६.१२	६.१८
विविध	२०.१९	२९.७६	३३.९६

ग्रामों और नगरों के आमदनी के अन्तर से आदतों और आवश्यकताओं में अन्तर पड़ जाता है। शहर में चाय, सिनेमा तथा तमाखू के खर्च बढ़ जाते हैं। निम्न लिखित तालिका से मालूम होगा कि गांव व शहर के मजदूरों के रहन-सहन में क्या अन्तर पड़ता है :—

एक परिवार के बजट का विश्लेषण (रुपयों में)

	मेरठ के एक गांव का कृषि मजदूर	कानपुर का मिल मजदूर
भोजन	३८.१	२६.३
कपड़ा	३.५	४.१
मकान	.३	४ ८
ईन्धन व प्रकाश	·५	३.३
फर्नीचर तथा मकान	—	१.०
विविध	२.६	१४.८

विभिन्न आय के अन्तर से व्यय में किस तरह अन्तर पड़ जाता है, यह निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट होगा। इसमें विभिन्न आय वालों के व्यय का प्रतिशत बनाया गया है।

आय	१-१०० रु०	१०१-२०० रु०	२०१-३५० रु०	३५१-७०० रु०	७०१ रु० से ऊपर
भोजन	६५.९०	६०.००	५५.३७	४७.१८	३८.९६
कपड़ा	६.४०	५.९४	५.२१	५.२८	४.७७
मकान किराया	३.९३	५.५९	५.४६	५.५६	५.७०
ईन्धन व प्रकाश	७.९३	५.७७	४.९८	४.०८	३.७३
विविध	१५.८४	२२.७०	२८.९८	३८.००	४९.८४

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रेलवे और हम

भारत में हर रोज करीब ३६ लाख मुसाफिर रेल-गाड़ियों में सफर करते हैं। यह तादाद अमृतसर की कुल आबादी के ११ गुने से भी ज्यादा या लखनऊ की कुल आबादी के सात गुने के बराबर है। करीब पांच हजार गाड़ियां रोजाना ६ हजार रेलवे स्टेशनों से सवारियां चढ़ाती-उतारती हैं। हर २४ घण्टे में भारत में सवारी और माल-गाड़ियां कुल मिलाकर ५,४२,००० मील से भी ज्यादा का सफर करती हैं। यह सफर दुनिया के करीब २२ चक्कर लगाने के बराबर है। आज, भारतीय रेलों में १० लाख से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि देश के हर ७२ लोगों में से १ आदमी या तो रेलों में काम करता है, या उसका कुटुम्बी है।

★

यह भी जानिए

दूसरी आयोजना की अवधि में जल और अग्नि विद्युत का उत्पादन ३५ लाख किलोवाट से बढ़कर ८० या ९० लाख किलोवाट, और तीसरी आयोजना में १ करोड़ ५० लाख किलोवाट हो जायगा।

भारत में प्रतिवर्ष लगभग २० करोड़ रु० के मूल्य का बिजली का सामान तैयार किया जाता है। दूसरी आयोजना की अवधि में ६० करोड़ रु० के मूल्य का सामान तैयार किया जायगा।

बिजली का सामान तैयार करने वाले उद्योग का कुल उत्पादन १९५१ में ७ करोड़ रु० के मूल्य से बढ़कर १९५६ में १७ करोड़ ९० लाख रु० मूल्य का हो गया।

१९५१ से १९५६ तक की अवधि में ट्रांसफार्मरों का उत्पादन १,९३,७०१ के. वी. ए. से बढ़कर लगभग ८,५४,००० के. वी. ए. और बिजली की मोटरों का १,४२,८०० अश्वशक्ति से बढ़कर ३,४०,००० अश्वशक्ति हो गया।

पहली आयोजना की अवधि के अंत में बिजली के तारों का उत्पादन प्रतिवर्ष ४ करोड़ रु० के मूल्य से बढ़कर ११ करोड़ रु० मूल्य का हो गया।

———

भारत सरकार के व्यापार और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित

'उद्योग व्यापार पत्रिका'

★ उद्योग और व्यापार सम्बन्धी प्रामाणिक जानकारी युक्त विशेष लेख, भारत सरकार की आवश्यक सूचनाएं, उपयोगी आंकड़े आदि प्रति मास दिये जाते हैं।

★ डिमाई चौपेजी आकार के ६० ७० पृष्ठ : मूल्य केवल ६ रुपया वार्षिक। एजेण्टों को अच्छा कमीशन दिया जायगा। पत्रिका विज्ञापन का सुन्दर साधन है।

★ लघु उद्योग विशेषांक मंगा कर छोटे उद्योगों के सम्बन्ध में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त कीजिये।

★ ग्राहक बनने, एजेन्सी लेने अथवा विज्ञापन छपाने के लिए नीचे लिखे पते पर पत्र भेजिये :—

सम्पादक

उद्योग व्यापार पत्रिका

उद्योग और व्यापार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दूसरी आयोजना और बैंक

श्री तुलसीदास किलाचन्द एम. पी.

इस वर्ष की महत्व पूर्ण आर्थिक घटना है—द्वितीय आयोजना का आरम्भ जो कि प्रथम आयोजना से आकार में दुगुनी से भी बड़ी है। इस आयोजना में ५३,०० करोड़ रु० सरकारी भाग पर और २४,०० निजी भाग पर खर्च होंगे। सरकार ने इस आयोजना की पूर्ति ५ वर्षों की नियत अवधि में ही करने का दृढ़ निश्चय प्रकट किया है, यद्यपि देश-विदेश के कुछ क्षेत्रों में इस आयोजना को बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा बताते हुए इसकी सफलता पर भी संदेह किया जा रहा है। प्रथम पंचवर्षीय आयोजना के लिए सरकारी खर्च में १५ प्रतिशत की कमी रही, यही बात द्वितीय योजना के प्रथम वर्ष के लिए भी सही है। लेकिन यह कहने से हमारा मतलब यह नहीं कि सरकार की ये योजनाएं उसके साधनों के वश से बाहर हैं। यह सत्य है कि आर्थिक दबाव, अस्थिरता की परिस्थितियां, मुद्रा प्रसार, वित्तीय साधनों की कमी, असंतुलित व्यापार और ढुलाई की असुविधा आदि के रूप में अनेक कठिनाइयाँ प्रकट हुई हैं। इन में से कुछ कठिनाइयां अंतर्राष्ट्रीय तनातनी के कारण थीं। उदाहरण के लिए स्वेज नहर के संकट के समय अत्यधिक आयात करने की ओर हमारा ध्यान बरबस चला गया, और हमें भविष्य के लिए एक चेतावनी मिल गई।

इस समय हमारी समस्या, असंतुलित व्यापार है। इसका मुख्य कारण आयात की वस्तुओं जैसे—इस्पात और दूसरी धातुओं, मशीनों और मोटरों का अधिक आयात बढ़ जाना है। साथ ही लाइसेंस बांटने में बहुत उदारता से काम लिया गया, जिससे अन्तराष्ट्रीय संकट के समय भी देश में वस्तुओं की सम्भावित कमी न रहे। अब आयात पर नियंत्रण किया जा रहा है और पूंजीगत सामान के आयात पर भी कठोर प्रतिबन्ध लगाये जा रहे हैं। इससे हमारी कठिनाइयां बहुत बढ़ जाएंगी।

बिलम्बित भुगतान से इस समस्या का उपचार हो सकता है। लेकिन इससे भविष्य में कठिनाई बढ़ जाएगी और वर्तमान दर से ४० से ५० प्रतिशत तक, अधिक मूल्य अदा करना होगा। दूसरी आयोजना के हेतु हमें १५,०० करोड़ रु० की मशीनों और पूंजीगत वस्तुओं का आयात करना है। यदि

लेखक

बिलम्बित भुगतान की व्यवस्था की गई तो परिणामस्वरूप योजना की लागत बढ़ जाएगी।

अतः बुद्धिमत्ता इसमें है कि बिना सोचे समझे बिलम्बित भुगतान को न किया जाय। अच्छा तो यह होगा कि आयात को कम करके निर्यात बढ़ाया जाय।

देश की आर्थिक परिस्थितियों के दबाव के कारण वित्तीय सुविधाएं काफी संकुचित हो गयी हैं। १९५७-५८ के बजट के श्वेत पत्र में कहा गया है कि स्वेच्छा से की गई बचत की मात्रा बहुत कम है, और संयुक्त सुरक्षित निधियां (कार्पोरेटेड रिजर्व) भी इतनी हैं कि उनसे उद्योगों को वित्तीय सहायता नहीं मिल सकती, उद्योगों को विवश होकर बैंकोंसे रुपया उधार लेना पड़ता है। वित्तीय स्रोतों में इस कमी का कारण व्यक्ति और संस्थाओं पर प्रत्यक्ष करों का लगना है। यदि सरकार इसी नीति पर चलती रहे तो होगा यह कि बैंक उद्योगों की मांग को पूर्ण करने में असमर्थ हो जाएंगे। सरकार ने बैंकों में उद्योगों के 'अनिवार्य जमा' करने की जो योजना चालू की हैं, इससे भी कोई लाभ होने की सम्भावना नहीं। इस योजना को समाप्त करके सुरक्षित राशि को कार्यकारी पूंजी में सम्मिलित किया जाए या अचल सम्पत्ति की खरीद की छूट दे दी जाए

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अन्यथा उद्योगों को संकट का सामना करना पड़ेगा।

देश में बैंक व्यवसाय पूर्णतः विकसित हो चुका है। बैंकों की जमा और उधार दी जाने वाली राशियों के बढ़ने की प्रवृत्ति से यह स्पष्ट है। पिछले वर्ष ६१ से बढ़कर यह अनुपात ७१ प्रतिशत तक पहुँच गया और अब भी बढ़ रहा है। इससे बैंकों की बचत में और उनके विनियोग के एक अंश की बिक्री में कमी हुई। व्यस्त मौकों पर, बैंकों को रिजर्व बैंक से काफी उधार लेना पड़ा। १९५६ में रिजर्व बैंक ने बिल बाजार में उदारता बरती, यद्यपि ब्याज की दर ३¼% से ३½% कर दी।

१ अप्रैल १९५६ से लागू होने वाले कम्पनी एक्ट से कम्पनियों के प्रबंधकों पर अनेक प्रभावकारी प्रतिबंध लग गये। कम्पनियों की तरह बैंकिंग कम्पनियों पर भी रोक लगी। कुछ दशाओं में तो बैंकों को सामान्य कार्य-संचालन में काफी कठिनाई मालूम हुई। कम्पनियों और बैंकों की तरफ से सरकार को कम्पनी कानून में यथोचित संशोधन के सुझाव दिये गये हैं। आशा करनी चाहिए कि सरकार उनकी ओर ध्यान देगी।

बैंकिंग कम्पनी कानून के संशोधन से बैंकों पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण और ज्यादा बढ़ गया है। यद्यपि अभी नहीं कहा जा सकता कि इससे बैंकों के कारोबार पर क्या असर होगा। रिजर्व बैंक अपने अधिकारों का प्रयोग कैसे करता है, इसी पर सारा दारोमदार है।

घाटे की अर्थ-व्यवस्था के कारण समुचित संगठित द्रव्य बाजार की स्थापना न हो सकी। सरकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों की नीति, राष्ट्रीयकृत बीमा निगम की असफलता से रुपया जमा करने की प्रवृत्ति में सहायता न मिल सकी। आय बढ़ने से मांग बढ़ती रही है। लेकिन यथोचित पूर्ति न होने से मूल्य चढ़ गये। इस समस्या का हल केवल कृषि और औद्योगिक उत्पादन के बढ़ाने में ही है।

विवेच्य वर्ष में बैंक दर स्थिर याने ३½% ही रही लेकिन पिछले महीने यह ४ प्रतिशत कर दी गई।

अब, इस बैंक की प्रगति का उल्लेख करते हुए मुझे खुशी होती है। पिछले वर्ष की अपेक्षा बैंक ने सब ले दे कर १०.२५ लाख का अधिक लाभ कमाया। बैंक के कार्य का विस्तार इतना हुआ कि इसका कार्यकारी पूंजी में ६.७९ करोड़ की वृद्धि हुई। याने इस वर्ष कुल कार्यकारी पूंजी ६३.०८ करोड़ रु० है, जब कि पिछले वर्ष ५६.२९ करोड़ रु० थी।

इस वर्ष बैंक की जमा राशि ४५.१३ करोड़ रु० रही जो पिछले वर्ष से ४.६२ करोड़ रु० अधिक है। हमारे बैंक की जमा राशि में केवल ८ प्रतिशत ही वृद्धि हुई।

हमारे विदेशी-कारोबार भी बढ़ा। विदेशी कारोबार की राशि ६.७९ करोड़ रु० तक पहुँची, गत वर्ष यह राशि ३.३१ करोड़ रु० थी।

इसी प्रकार सम्पत्ति के पक्ष में भी संतोषजनक प्रगति हुई। अग्रिम दी गई राशि इस वर्ष ३५.८६ करोड़ रु० है। गतवर्ष यह केवल ३०.४१ करोड़ रु० ही थी। यह सारी वृद्धि व्यापार के बढ़ने से हमारे ग्राहकों के ही पल्ले पड़ी है।

ऋणों और डिपाजिटों पर ब्याज के रूप में इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा २५.६६ लाख रु० अधिक दिये गये। बैंक आफ इंगलैंड की बैंक दर कम करके ५% कर देने पर भारतीय द्रव्य बाजार पर विशेष प्रभाव न पड़ा। इस समय रुपये की तंगी रही, इसीलिए ब्याज की दर बढ़ी। जमा-लागत, उधार और प्रबन्ध व्यय में वृद्धि हो जाने से (विशेषकर अवार्ड के कारण कर्मचारियों पर व्यय बढ़ने से) हो सकता है कि लाभ में कुछ कमी हो। लेकिन प्रयत्न हो रहा है कि बिना कार्यकुशलता में कमी किये खर्च कम किए जा सकें।

संचालकों ने दूसरी छमाही में प्रतिशेयर पर ४ प्रतिशत आय-कर-मुक्त लाभांश देने की सिफारिश की है। इस प्रकार इस वर्ष लाभांश १४ प्रतिशत हो जाएगा।

बैंक का लाभ और लाभांश पर कर के कारण विवेच्य वर्ष में कर की राशि बढ़ कर १५,७५,००० रु० हो गई है।

हमारा बैंक के कारोबार का विस्तार का कार्यक्रम जारी रहा। इस वर्ष, सिकन्दराबाद, राजपीपला, रीकजेमेरा (बम्बई) त्यागरायनगर (मद्रास) और दार-एस-सलाम (ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका) में शाखाएं खोली गईं। २१ जनवरी १९५७ को पोरबन्दर और २५ फरवरी को लन्दन में शाखाएं खोल दी गई हैं।❀

(शेष पृष्ठ २३८ पर)

❀बैंक आफ बड़ोदा की ४८ वीं वार्षिक बैठक में दिये गये अध्यक्षीय भाषण से।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

१० के १५
२० के ३०

यह कोई कठिन नहीं और न तो इस के लिए किसी जादूगर की जरूरत है। यदि आप आज नैशनल सेविंग्ज सर्टिफिकेट में १० रुपये लगाएंगे तो १२ साल के बाद आप को उसके १५ रुपये मिलेंगे। आप का पैसा सुरक्षित रहेगा और आप को सूद देने की जिम्मेदारी सरकार की है।

दुगना लाभ

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सम्पन्न किए जाने वाली भिन्नभिन्न योजनाओं के लिए आप के पैसों का उपयोग किया जाएगा और उसी के जरिये देश की तमाम जनता के रहन-सहन का स्तर ऊंचा किया जाएगा। आपको सूद मिलने के अलावा आप देश की खुशहाली में हिस्सा लेते है।

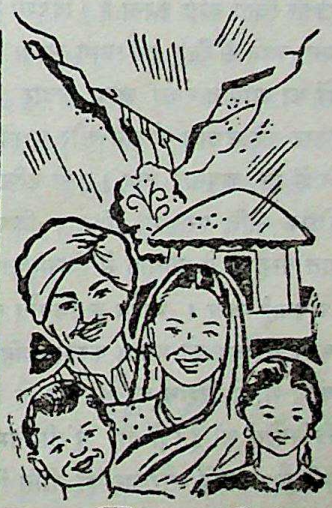

नव भारत के निर्माण में
आप सहायक होते हैं

अधिक विवरण और/या इस से सम्बन्धित नियमों की जानकारी के लिए नैशनल सेविंग्ज कमिश्नर, शिमला या अपने राज्य के रीजनल नैशनल सेविंग्ज आफिसर को लिखिए।

DA 56/151

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अ० भा० उद्योग व्यापार मंडल के कुछ महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव

२३-२४ मार्च को होने वाले अ० भा० उद्योग व्यापार मण्डल (फैडरेशन आफ चैम्बर्स आफ इण्डस्ट्रीज एण्ड कामर्स के अधिवेशन में) जो प्रस्ताव स्वीकार किये गये हैं, वे देश की आर्थिक समस्याओं पर उसके विचारों को प्रकट करते हैं। इसलिए उनका उनका सारांश नीचे दिया जाता है :—

फैडरेशन सरकार के कृषि और औद्योगिक, दोनों प्रकार के उत्पादन बढ़ाने व रोजगार दिलाने के प्रयत्नों की सराहना करता है। लेकिन पिछले दो एक सालों से जो आर्थिक तनाव उत्पन्न हो गया है, उसके प्रति चिन्ता व्यक्त करता है। उत्पादन में कमी होना भी चिन्ततीय है। इसकी सम्मति में अब कृषि उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाये, ऐसी नीति अपनाई जाये जो द्रव्य के अनावश्यक प्रसार सट्टा उपभोग पर नियंत्रण करते हुए उत्पादन बढ़ाया जा सके। कर-नीति ऐसी हो जिससे बचत को प्रोत्साहन मिले और योजना के लिए विनियोग-साधनों की प्राप्ति हो सके।

फैडरेशन भारत के गिरते विदेशी व्यापार पर और अत्यधिक आयात पर चिंता व्यक्त करता है। विदेशी मुद्रा की समस्या का सामना करने के लिए हमें त्याग करना चाहिए। उपभोग्य वस्तुओं का आयात रोका जाय, उदार लाइसेंस देने की नीति केवल नये उद्योग खोलने और पुराने उद्योगों का विस्तार करने में ही अपनाई जाए। इसी दृष्टि से हाल की आयात निरोधक नीति पर भी विचार किया जाना चाहिए। पूंजीगत वस्तुओं के आयात में विलम्बित भुगतान करने की नीति अपनाई जाए। भारत के निर्यात को बढ़ाने के हेतु उद्योगों और सरकार को प्रयत्न करना चाहिए।

कर के सम्बन्ध में, फैडरेशन का विचार है कि व्यक्ति की बचत और विनियोग की इच्छा ही पूंजी-निर्माण का आधार बन सकती है। यदि सरकार की नीति निगमों से अधिकाधिक कर वसूल करने की है तो व्यक्तिगत करों को कम करना चाहिए। सम्पत्ति और आय का अधिक समान बटवारा करके निजी बचत को बढ़ाया नहीं जा सकता।

फैडरेशन बिक्री करों की एकरूपता पर बल देता है। इसके लिए भारत सरकार को चाहिए कि वह राज्य सरकारों की सलाह से एक आदर्श कानून बनाये और उसे सब राज्यों पर लागू किया जाए। एक आयकर-सलाहकार समिति का भी गठन किया जाए।

सरकार को चाहिए कि यातायात के विकास पर विशेष ध्यान दे। रेलों के साथ ही साथ अन्य यातायात-साधनों का भी विकास भी किया जाए। ऐसी नीति अपनाई जाए, जिससे निजी व्यवसायियों को इनके विकास के लिए प्रोत्साहन मिले। विशेषकर सड़क और जहाजी यातायात के विकास में देश के अन्दर भी नदियों के यातायात का सर्वेक्षण किया जाए और उनको अधिक उपयोगी बनाया जाए।

उत्पादन बढ़ाना ही हमारे आर्थिक विकास का मूलमंत्र है। इसीसे मूल्य कम होंगे, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, और कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। मजदूरों का वेतन भी उत्पादन बढ़ने पर ही बढ़ाया जाना चाहिए, मजदूरों को इस बात का पूरा आश्वासन दिया जाए कि उत्पादन बढ़ने पर उनको न्यायोचित भाग मिलेगा। इन सब के लिए टेक्नीकल शिक्षा की सुविधाएं दी जाएं। कृषि और छोटे-बड़े सब उद्योगों में नवीन विकसित पद्धतियों को अपनाया जाए।

फैडरेशन सरकार और केन्द्रीय बैंक का ध्यान देश के द्रव्य बाजार की विकट स्थिति की ओर खींचता है जिससे व्यवसायियों और उद्योगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। योजना कार्य, तथा अन्य कारणों से द्रव्य की मांग बढ़ गयी है पर उसकी पूर्ति उसी प्रकार नहीं बढ़ी है। इसलिए यदि समय रहते रुपये की तंगी को दूर करने के लिए प्रभावशाली कदम न उठाया गया तो अर्थ व्यापार को ही हानि नहीं पहुँचेगी, वरन् देश का विकास कार्य भी मंद पड़ जायेगा। इसके लिए रिजर्व बैंक द्वारा बिलों के दुबारा बट्टा करने की नीति को उदार किया जाए, सरकारी सिक्यूरिटियों के लिए प्रभावशाली खुले बाजार की नीति अपनाई जाए। बीमा कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण का और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो द्वारा ली गई निजी सम्पत्तियों का शीघ्र ही मुआवजा दिया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बैंकों की शाखाएं खुलें और वहां भी बचत को प्रोत्साहन दिया जाए।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(पृष्ठ १०६ का शेष)

का अनुमान है, जबकि बजट में व्यय की रकम ५४५·४३ करोड़ रुपये रखी गयी थी।

राजस्व और पूंजी दोनों के बजटों को मिलाकर इस वर्ष २१६ करोड़ रुपये के सम्पूर्ण घाटे का अनुमान है, जब कि मूल बजट में ३५६ करोड़ रुपये का अनुमान था। यह राजस्व खाते में सुधार होने का, जिसका उल्लेख मैं पहले कर चुका हूँ, तथा राज्य सरकारों और दूसरों को ऋण और अग्रिम देने के लिए की गयी ३८६ करोड़ रुपये की व्यवस्था में लगभग ६४ करोड़ रुपये की बचत का परिणाम है।

मेरा १९५६-५७ में अनुमान है कि १९५७-५८ में वर्तमान कर-व्यवस्था के आधार पर ६३६·२२ करोड़ रुपये की राजस्व-प्राप्ति होगी और ६६३·०९ करोड़ रुपये का व्यय होगा, जिससे राजस्व खाते में २६·८७ करोड़ रुपये की कमी रह जायगी। इस प्रकार चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में राजस्व में २६·७३ करोड़ रुपये की और व्यय में ९२·५४ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी।

अगले वर्ष राजस्व में २६·७३ करोड़ रुपये की जो वृद्धि दिखलायी गयी है, उसमें ८ करोड रुपये पूंजी लाभ कर और कम्पनियों पर लगाये गये अतिरिक्त अधिकार की अनुमति प्राप्तियों के हैं, जो १ अप्रैल, १९५७ से प्रभावी होंगे; और १२·४ करोड रुपये सूती कपड़े की शुल्क-वृद्धि तथा रेयन, कृत्रिम देशों और धागे और मोटरकारों पर इस वर्ष लगाये गये नये शुल्कों से पूरे वर्ष में होने वाली प्राप्ति के हैं। आयात की जाने वाली वस्तुओं के निर्धारित अंशों (कोटा) में कटौती के कारण, जो विदेशी मुद्रा को सुरक्षित रखने के लिए की गयी है, सीमाशुल्कों से होने वाली प्राप्ति में ९ करोड़ रुपये की कमी होगी। किन्तु इसके मुकाबले रिजर्व बैंक के अधिलाभ में १० करोड़ की वृद्धि का अनुमान है।

अनुमान है कि आगामी वर्ष स्वतः सन्तुलित मदों को छोड़ कर ६२५·०९ करोड़ रुपये का व्यय होगा, जिसमें से २५२·७१ करोड़ रुपया प्रतिरक्षा (डिफेंस) सेवाओं पर और ४७२·३८ करोड़ रुपया असैनिक (सिविल) कार्यों पर खर्च होगा। प्रतिरक्षा सेवाओं के व्यय में ४९·७६ करोड़ रुपये की वृद्धि दिखलायी गयी है। अधिकांश वृद्धि का कारण स्थल सेना और वायुसेना के लिए आवश्यक नयी सामग्री की खरीद है। चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में आगामी वर्ष असैनिक व्यय में ४१·७८ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी जिसका मुख्य कारण राष्ट्रनिर्माणकारी विकास और समाज सेवाएं हैं।

आगामी वर्ष पूंजी-परिव्यय और राज्य सरकारों तथा दूसरों को ऋण देने के लिए ७७२·२१ करोड़ रुपये की व्यवस्था है, जबकि चालू वर्ष का संशोधित अनुमान ६३६·१५ करोड़ रुपये है। यह वृद्धि तीन इस्पात संयंत्रों और रेलों के लिए अपेक्षाकृत अधिक धन की व्यवस्था किये जाने के कारण है।

आगामी वर्ष के अनुमानों में १०० करोड़ रुपये बाजार ऋण के, ८० करोड़ रुपये छोटी बचतों के, १३५ करोड़ रुपये विदेशी सहायता के और ११९ करोड़ रुपये अन्य विविध ऋण, जमा तथा प्रेषण शीर्षक के अन्तर्गत होने वाले लेन-देन के जमा किये गये हैं। इन जमा रकमों को हिसाब में लेते हुए भी अगले वर्ष के सम्पूर्ण बजट में कुल मिलाकर ३६५ करोड़ रुपये का घाटा रहेगा।

इतने बड़े घाटे को भारत सरकार पसन्द नहीं करती। उद्देश्य यह होना चाहिए कि राजकोष में धन का आगम बढ़ा कर इसे यथासम्भव कम किया जाय। इसलिए अन्त में मैं इस बात पर फिर जोर देना चाहता हूँ कि तात्कालिक आवश्यकताओं और इस तथ्य को देखते हुए कि आयोजना-परिव्यय को वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ाना पड़ेगा, राजस्व को बराबर बढ़ाते रहने की आवश्यकता होगी और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए केन्द्र और राज्यों को यथाशक्ति प्रयत्न करना पड़ेगा।

—

ऐजेंट चाहिएं

विभिन्न नगरों में सम्पदा की बिक्री और गाहक बनाने के लिए ऐजेंट चाहिए। आकर्षक शर्तों के लिए लिखें—

मैनेजर-सम्पदा, रोशनारा रोड़, दिल्ली ६।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारत का विकासोन्मुख जूट उद्योग

श्री हेमचन्द जैन

भारतीय अर्थव्यवस्था में जूट उद्योग अपना एक विशेष और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भूतकाल में विदेशियों ने इस उद्योग के द्वारा बड़ी मात्रा में धन लाभ किया है और आज भी यह उद्योग, विशेषकर मुद्रा-अर्जन की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। विनियोजित पूंजी, मिलों की संख्या एवं कामगरों की संख्या की दृष्टि से, भारत में वस्त्रोद्योग और चीनी-उद्योग के बाद इसका ही स्थान है। परन्तु विदेशी मुद्रा-अर्जन की दृष्टि से इसका प्रथम स्थान है। जब हम अन्य उद्योगों के द्वारा विदेशी अर्जित मुद्रा की तुलना इस उद्योग से करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। अतः यह समीचीन ही है कि भारत सरकार इस उद्योग को विशेष प्रोत्साहन और संरक्षण दे। भारत का उत्तर पूर्वी अंचल जूट का आगार है। पश्चिमी बंगाल और इसकी राजधानी कलकत्ता शुरू से ही पटसन का एक प्रधान क्षेत्र और मिलों का केन्द्र रहा है और भविष्य में अपना स्थान सुरक्षित रखने में अग्रणी रहेगा।

आज विश्व के आर्थिक इतिहास में भारतीय जूट उद्योग को एक महत्वपूर्ण और प्रथम स्थान दिया जाता है। आज भारत में स्थापित जूट की ११३ मिलें, केवल भारतीय पटसन को ही पक्के जूट में परिणित नहीं करती वरन् पाकिस्तान से पटसन आयात कर उसे भी एक उपयोगी वस्तु का रूप देते हैं। ११३ जूट की मिलों में १०१ पश्चिम बंगाल, ४, मद्रास ३ बिहार, ३ उत्तरप्रदेश, और १-१ मध्यप्रदेश और असम में है। लगभग साढ़े तीन लाख व्यक्तियों की रोजी-रोटी प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से लगभग तिगुने व्यक्तियों की आजीविका इस उद्योग पर आश्रित है। इस उद्योग में ६० करोड़ रुपए की पूंजी लगी हुई है। भारत के कुल निर्यात का चौथाई भाग जूट का होता है। भारतीय जूट उद्योग में एशिया महाद्वीप की कुल उपज तीन चौथाई जूट उपयोग में लाता है।

जब जूट उद्योग के इतिहास पर दृष्टि डालते हैं तो ज्ञात होता है कि सर्व प्रथम बंगाल प्रान्त के सीरामपुर के समीप एक स्थान में, जूट की कताई करने की एक मिल स्थापित हुई थी, जो कुछ वर्षों के अनन्तर पूर्ण मिल के रूप में विकसित हो गई। १९ वीं सदी के पूर्व तक, यह उद्योग धीमी गति परन्तु सुदृढ़ आधार पर प्रगति की ओर बढ़ता रहा। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व ही, तीन शताब्दियों के समय में ही इस उद्योग ने भारतीय उद्योग में जगत में अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया। इस संदर्भ में इस उद्योग को न जाने कितनी कठिनाइयों, समस्याओं का सामना करना पड़ा। परन्तु यह उद्योग विकास की ओर अग्रसर होता ही गया। द्वितीय विश्व-युद्ध का प्रभाव भारत के अन्य उद्योगों की तरह इस उद्योग पर भी पड़ा। एकाएक जूट की मांग घट गई। द्वितीय विश्व युद्ध के कुप्रभाव से यह उद्योग संभल ही रहा था कि १९४७ में इसको विभाजन का सामना करना पड़ा। विभाजन का फल यह हुआ कि जूट की पैदावार का अधिकांश क्षेत्र अर्थात् ¾ भाग पाकिस्तान में चला गया और जूट की प्रायः सभी मिलें भारत में रह गईं। अतः पटसन जूट की समस्या उत्पन्न हो गई। पाकिस्तान सरकार की असहयोग और कुदृष्टि सदा इस उद्योग पर रही है। अतः पाकिस्तान के मुद्रा-अवमूल्य ने जूट-उद्योग में हलचल उत्पन्न कर दी। परन्तु 'संघर्ष ही जीवन' है और 'असफलता ही सफलता का सूचक है' को आदर्श मानकर यह उद्योग निरन्तर विकासोन्मुख रहा है। भारत सरकार की संरक्षण नीति एवं प्रोत्साहन के बावजूद भी आज के प्रतिद्विन्दिता के युग में हमारा जूट उद्योग विश्व पर से अपना एकाधिकार खो चुका है। परन्तु फिर भी उसका अपना एक विशेष और विशिष्ट स्थान है और आगे भी रहेगा।

प्रथम पंचवर्षीय योजना-काल में इस उद्योग ने अधिकतम विदेशी विनिमय का अर्जन कर योजना को सफल बनाने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किया है। सन १९४७-४८ में १४७ करोड़, १९४८-४९ में १२७ करोड़, १९४९-५० में ११४ करोड़ रुपये का जूट का सामान भारत से विदेशों को निर्यात किया गया। सन् १९५२-५३ में भारत के कुल निर्यात ५५५ करोड़ रुपये का २३.३ प्रतिशत अर्थात् १२९ करोड़ रुपये का, १९५३-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

५४ में कुल निर्यात ५१८ करोड़ के २२.० प्रतिशत अर्थात ११४ करोड़ रुपये का, १९५४-५५ में १२४ करोड़ रुपया और १९५५-५६ में अनुमानतः १२५ करोड़ रुपये की जूट की सामग्री का निर्यात भारत विशेषकर पश्चिमी और अपने समीपवर्ती देशों को करता है। अतः स्पष्ट है कि विदेशी मुद्रा अर्जन की दृष्टि से जूट उद्योग का भारत में एक विशिष्ट और विशेष स्थान है। परन्तु उत्पादन-शक्ति के अनुसार पटसन प्राप्त न होने के कारण, भारत सरकार ने पटसन की उत्पादन-क्षमता को ३३ लाख गांठ से बढ़ा कर आज ४१ लाख गांठ तक पहुँचा दिया है, जिससे पूर्ण उत्पादन शक्ति का उपयोग हो सके। प्रथम योजनाकाल के पूर्व ६५० हजार टन जूट की सामग्री का निर्यात किया जाता था, वह आज बढ़कर १००० हजार टन हो गया है। योजनाकाल में निर्यात किस गति से बढ़ा है, वह निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाता है।

सन्	(उत्पादन टनों में)
१९५०	८,७०,००० ,,
१९५१	९,०९,००० ,,
१९५२	९,०८,००० ,,
१९५३	९,२४,००० ,,
१९५४	१,०१०,००० ,,
१९५५	१,०९५,००० ,,

उत्पादन शक्ति का पूर्ण उपयोग करने एवम् विदेशी प्रतियोगिता का भली प्रकार सामना करने के लिए, भारत सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ऐसा प्रावधान रखा है कि गहन खेती की प्रणाली को अपनाकर जूट का उत्पादन ४१ लाख गांठ से बढ़ाकर ५० लाख गांठ कर लिया जाया। और निर्यात ९०० हजार टन पर स्थिर कर दिया है। परन्तु इतने पर भी कच्चे जूट की मांग की पूर्ति पाकिस्तान से निर्यात कर पूर्ण की जाएगी।

इस समय भारतीय जूट की मांग दिनोंदिन गिरती जा रही है। भारत सरकार और जूट उद्योग के सम्मुख एक विकट समस्या है कि किस प्रकार और किन उपायों और साधनों से जूट का निर्यात बढ़ाकर अधिकाधिक विदेशीमुद्रा प्राप्त की जा सके। यह युग प्रतिस्पर्द्धा का युग है। पाकिस्तान भी नवीन आधुनिक वैज्ञानिक मशीनों युक्त कारखानों की स्थापना कर स्वयं जूट को उपयोगी वस्तुओं में परिणत कर अधिकाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की ओर तीव्रगति से कदम बढ़ा रहा है। जापान वस्त्रोद्योग के समान ही जूटोद्योग के व्यापक प्रचार और प्रसार के लिए एक सुसंगठित योजना बनाकर कार्यान्वित करने की सोच रहा है। विश्व के औद्योगिक रूप में सम्पन्न राष्ट्र जो अणु का उपयोग करने लगे हैं, एक नये कृत्रिम रेशे का परीक्षण करने में सफल हो गए हैं, जिसका उपयोग जूट-सदृश वस्तुएँ बनाने में करेंगे। अतः कहने का तात्पर्य यह कि अगर भारत ने सस्ते दामों में उच्चकोटि का जूट के माल का निर्माण नहीं किया तो जल्दी ही पाकिस्तान और जापान भारत से जूट मंगाने वाले राष्ट्रों को स्वयं जूट की सामग्री का निर्यात करने लगेंगे। भारत का यों ही जूट उद्योग पर एकाधिकार नहीं रहा है, दूसरे पाश्चात्य राष्ट्रों ने जूट सदृश रेशे का उपयोग कर भी अपनी जूट के माल की मांग कम कर दी है। परन्तु भारत सरकार की संरक्षण नीति एवम् प्रोत्साहन के कारण यह उद्योग प्रतियोगिता का मुकाबला डटकर कर रहा है। भारत सरकार जूट के उत्पादन को प्रोत्साहन और बढ़ावा दे रही है जिससे जूट उद्योग कच्चे माल के बारे आत्मनिर्भर हो जाए। पाकिस्तानी रुपये के अवमूल्यन से उत्पन्न समस्या के निराकरण के लिए, भारत सरकार ने तुरन्त जूट पर से निर्यात कर हटा दिया जिससे जूट निर्यात पर प्रभाव न पड़े।

आज दूसरी महत्वपूर्ण समस्या जो जूट उद्योग के सम्मुख उपस्थित है, वह है मशीनों का आधुनिकीकरण। यदि भारत को पुनः जूट-उद्योग पर एकाधिकार स्थापित करना है तो उसे उच्चकोटि का माल अन्य प्रतियोगी राष्ट्रों से सस्ते दामों में निर्यात करना पड़ेगा। यह तभी सम्भव है। जब उत्पादन का लागत व्यय कम पड़े। इसके लिए भारत सरकार को मिलों के आधुनिकीकरण के लिए तीव्रगति से कदम उठाना होगा। परन्तु यदि मिलों के आधुनिकीकरण को भारत सरकार सहायता देती है तो उसके सम्मुख ४० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी तथा छटनीशुदा ४ हजार मजदूरों की बेरोजगारी की समस्या और उत्पन्न हो जाएगी। परन्तु इसके अनन्तर भी उसने उन जूट मिलों को जिनकी मशीनें उत्पादन के अयोग्य थी या जिन पर लागत व्यय अधिक पड़ता था, आधुनिकीकरण करने के आदेश दे दिए हैं और राष्ट्रीय औद्योगिक निगम के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करने की

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

व्यवस्था की है। सन् १९६० तक भारत की प्रायः अधिकांश मिलों का आधुनिकीकरण हो जाएगा। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने विदेशों में शिष्टमंडल भेजकर एवम् जूट मिल्स एसोसियेशन स्थापित कर इस उद्योग के प्रचार व प्रसार के व्यापक कार्य किये हैं।

अतः तीव्र प्रतिस्पर्धा और अनेकानेक समस्याओं के बावजूद भारत सरकार के संरक्षण और प्रोत्साहन के फलस्वरूप यह उद्योग विकास के पथ की ओर अग्रसर होता रहा है, परन्तु यह उद्योग तब तक अपना एकाधिकार स्थापित नहीं कर सकता, जब तक वह उत्तम उच्चकोटि की जूट की सामग्री अन्य देशों से सस्ते दामों में निर्यात न करें। पर यह निर्विवाद है कि पंचवर्षीय योजना में इस उद्योग का व्यापक प्रसार होगा और विदेशी मुद्रा की उपलब्धि की दृष्टि से यह पंचवर्षीय योजना में सहयोग देता रहेगा।

(पृष्ठ ११२ का शेष)

रु० था जो बढ़कर आयोजना के अन्तिम वर्ष में २१२.९५ करोड़ रु० हो गया। खर्च बढ़ने का मुख्य कारण कर्मचारियों पर होने वाले व्यय में ३४½ करोड़ रु० की वृद्धि और ईंधन के मूल्य में ३½ करोड़ रु० की वृद्धि है।

स्वावलम्बी बनने का प्रयत्न

१९५५-५६ में चितरंजन कारखाने में १२९ इंजन बने। आशा है कि चालू वर्ष में १५६ और अगले १६८ इंजन बनेंगे। ये १६८ बड़े इंजन साधारण आकार के २०० इंजनों के बराबर होंगे। इंजनों के अलावा यहां इंजनों के सब कल-पुर्जे बनाने का प्रयत्न किया जायगा ताकि बाहर से कम से कम कल पुर्जे मंगाने पड़े।

टाटा लोकोमोटिव एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी ने छोटी लाइन के ५० इंजन बनाकर पिछले साल का अपना लक्ष्य पूरा दिखाया। दूसरी पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में यह कम्पनी प्रतिवर्ष १०० इंजन बनाने का प्रयत्न करेगी। १९५५-५६ में रेल-डिब्बों के कारखाने में सवारी गाड़ी के १२ डिब्बे तैयार हुए। इस साल ८० डिब्बे और अगले साल १८१ डिब्बे बनने की आशा है। इनमें से क्रमशः १० और ८१ डिब्बे देश में बने हिस्सों से ही तैयार किये जाएंगे।

देश में इस समय प्रतिवर्ष २०,००० माल डिब्बे बनाने की व्यवस्था है। अब देश में ३६,००० डिब्बे बनाने लायक व्यवस्था करने का विचार है। इसके लिए भारत की १६ नयी फर्मों से बातचीत चल रही है।

आपका स्वास्थ्य

(हिन्दी की एक मात्र स्वास्थ्य सम्बन्धी मासिक पत्रिका)

"आपका स्वास्थ्य" आपके परिवार का साथी है।

"आपका स्वास्थ्य" अपने क्षेत्र के कुशल डाक्टरों द्वारा सम्पादित होता है।

"आपका स्वास्थ्य" में अध्यापकों, अभिभावकों, माताओं और देहातों के लिए विशेष लेख प्रकाशित होते हैं।

आज ही ६) रु० वार्षिक मूल्य भेजकर ग्राहक बनिए।

व्यवस्थापक,

आपका स्वास्थ्य—बनारस-१

सरकारी विज्ञापनों के लिए स्वीकृत
राजस्थान शिक्षा विभाग से मंजूरशुदा

सेनानी साप्ताहिक

सम्पादक :—

सुप्रसिद्ध साहित्य सेवी श्री शंभुदयाल सक्सेना

कुछ विशेषताएं—

★ ठोस विचारों और विश्वस्त समाचारों से युक्त

★ प्रान्त का सजग प्रहरी

★ सर्वाधिक लोकप्रिय पत्र

ग्राहक बनिए, विज्ञापन दीजिए, रचनाएं भेजिए

नमूने की प्रति के लिए लिखिए—

व्यवस्थापक, साप्ताहिक सेनानी, बीकानेर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राष्ट्र का आर्थिक प्रवाह

[२०१ पृष्ठ का शेष]

छोटे उद्योगों के लिए पूंजी

छोटे उद्योग और खेती के धंधे में राहत देने के लिए राज्य बैंक अग्रसर हुआ है। राज्य बैंक की शाखाओं का देश भर में विस्तार हो रहा है। सभी प्रमुख जिलों और कस्बों में उसकी ४०० से अधिक शाखाएं होंगी। छोटे उद्योगों में पूंजी लगाने के लिए बम्बई, कलकत्ता मद्रास आदि ९ स्थानों में केन्द्र स्थापित किए गए हैं, जिनके परामर्श से सहकारी संगठनों द्वारा छोटे उद्योगों को ऋण मिलेंगे। राज्य बैंक ने उद्योगों को ऋण देने का मार्ग ग्रहण किया है। पर उद्योगों की सम्पत्ति पर विचार किया जाए और उस की सिक्यूरिटी में ऋण दिया जाए, तो उन्हें पर्याप्त धन मिलना संभव नहीं है। इसलिए उद्योगों के उत्पादन और खपत के आधार पर ऋण दिए जाते हैं। यदि उनका उत्पादन प्रगतिशील है और उनके पास माल बिक्री के सरकारी तथा गैर सरकारी आर्डर हैं, तो बैंक उनके आधार पर ही बिना किसी सिक्यूरिटी के ऋण देता है। मध्य वित्त वर्ग के शिक्षित व्यक्ति, जो नौकरियों के लिए मारे मारे फिरते हैं, निराश अवस्था में जीवन बिताते हैं और सरकार को कोसते हैं। उन्हें इस योजना से लाभ उठाना चाहिए। इससे अधिक कोई शासन क्या सुविधाएं दे सकता है। छोटे उद्योगों की प्रगति पर देश में स्वस्थ आर्थिक निर्माण होना संभव है। इसी बैंक ने किसानों को भी ऋण देने की व्यवस्था की है। किसानों की जमीनें बिना बंधक रखे केवल फसल के अनुमान पर किसानों को ऋण देने की व्यवस्था की है। ब्याज की दरें भी साधारण हैं।

विदेशी मुद्रा का बजट

पहली पंचवर्षीय योजना के काल में विदेशी मुद्राओं की आमद के स्रोत इस प्रकार थे:—

	करोड़ रुपए में
पहली योजना में बिना उपयोग की हुयी विदेशी सहायता और ऋण की रकमें	१००
विदेशी मुद्रा की बचत अमेरिका से कृषि पदार्थों की आमद के इकरार नामे से	१३७
इस्पात उद्योग के प्राप्त ऋण	८३
रेलवे योजना के लिए विश्व बैंक के ऋण	४००
अमेरिकन सहायता	१५०
कोलम्बो राष्ट्रों की सहायता द्वारा	८०
रूसी ऋण	६०
निर्यात व्यापार की वृद्धि द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जन	८०
	१२००

भारत निर्यात व्यापार में केवल पदार्थों के निर्यात द्वारा ही नहीं, जहाजी किरायों से विदेशी मुद्राओं की केवल बचत ही नहीं करता है, उल्टे अर्जन करता है। भारतीय जहाजी कम्पनियां अपने वर्तमान स्रोतों से प्रति वर्ष ७ करोड़ से ८ करोड़ रुपए की विदेशी मुद्राएं अर्जन करने लगी हैं। यदि इस उद्योग में ४० करोड़ रुपए का नया पूंजीगत विनियोजन हो जाए, तो भारतीय जहाज प्रतिवर्ष १२ करोड़ रुपए की विदेशी मुद्राएं अर्जन कर सकते हैं।

——

विभिन्न देशों की राष्ट्रीय आय ❀

देश	साल	आबादी लाख में	राष्ट्रीय आय करोड़ रु० में	प्रति व्यक्ति आय रु०
भारत	५४-५५	३७८०·७	१०,१७०	२६९
पाकिस्तान	५३-५४	७९३·३	१,९३१	२४३
बर्मा	१९५४	१९२·४	३९०	२०४
श्रीलंका	१९५४	८३·८	४७०	५६०
जापान	१९५५	८८९·०	८,६९८	९७८
फिलिपाइन्स	१९५५	२१८·५	१,८५७	८५०
न्यूजिलैंड	१९५५	२१·३	१,१२८	५,२९६
आस्ट्रेलिया	१९५४	८९·९	४,२२०	४,६९४
इंग्लैंड	१९५५	५०९·७	२२,१७८	४,३५१
कैनेडा	१९५५	१५६·०	१०,१६६	६,५१६
अमेरिका	१९५५	१६५२ ७	१५५,५२०	९,४१०
फ्रांस	१९५५	४३२·७	१७,०१०	३९३१
प० जर्मनी	१९५५	४९९·९	१४,४६०	२,६९०
इटली	१९५४	४७८·०	७४८०	१५६०
नार्वे	१९५५	३४·३	१३२०	३०५०
स्वीडन	१९५४	७२·१	३५४४	४९१२
नेदरलैंडस	१९५५	१०७·५	२,८५०	२६५०
डेनमार्क	१९५४	४४·१	१,६१०	३६५४
स्वीटजरलैंड	१९५४	४९·२	२,४१०	४,८९५

❀संयुक्त राष्ट्र संघ के मासिक बुलेटिन सितम्बर ५६ के आधार पर।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(पृष्ठ २१६ का शेष)

पश्चिमी जर्मनी व जापान

पश्चिमी जर्मनी उद्योग व टैक्निकल जानकारी की दृष्टि से बहुत आगे बढ़ा हुआ है। रूरकेला के लोह उद्योग में उसका सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। यह प्रसन्नता की बात है कि भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिये पश्चिमी जर्मनी का प्रतिनिधि मण्डल भारत आया हुआ है। अप्रैल से नवम्बर १९५६ की ६ मई में भारत ने जर्मनी से ५८.३ करोड़ रुपये का माल मंगाया और केवल ९.५ करोड़ रुपये का माल भेजा। हमें आशा करनी चाहिये कि इस नये प्रतिनिधि मण्डल के साथ चर्चा करते हुए भारत का निर्यात व्यापार बढ़ाने पर निश्चित विचार किया जायेगा।

जापान और भारत का व्यापारिक संबंध बहुत पुराना है। युद्ध में जापान के विजित हो जाने से यह व्यापार समाप्त हो गया। किन्तु पिछले ५-६ वर्षों में वह फिर उठ खड़ा हुआ है और वस्त्र उद्योग में भारत व ब्रिटेन का मुकाबला करने लगा है। आज भारत को पूंजीगत सामान की भारी आवश्यकता है, किन्तु आर्थिक साधनों की कमी अनुभव की जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि जापान के साथ चलने वाली बातचीत सफल हो गई तो कुछ सुविधा हो जायेगी। जापान के आयात-निर्यात बैंक के उपाध्यक्ष श्री एच० कानों इस प्रश्न पर विचार करने के लिए भारत आये हुए है कि भारत को पूंजीगत सामान बिना नगद दाम लिये किस तरह और कितना दिया जा सकता है। यह बैंक जापानी उत्पादक मशीन-निर्माताओं को आवश्यक राशि की सहायता प्रदान करेगा।

●

आगामी विशेषांक की विस्तृत जानकारी मई मास के अङ्क में

हिन्दी और मराठी भाषा में प्रकाशित होता है।

उद्यम

सर्वोपयोगी हिन्दी उद्यम प्रतिमाह १५ तारीख को पढ़िये

धर्मपेठ, नागपुर

उद्यम के स्थायी स्तम्भ

उद्यम में निम्न विषयों पर लेख प्रकाशित होते हैं

★ लाभदायक उद्योगधन्धों की व्यावहारोपयोगी जानकारी, अनाज की खेती, साग-सब्जी की बागवानी और रोगों का निवारण। पशुपालन, दुग्ध-व्यवसाय और ग्रामोद्योग-सम्बन्धी लेख। आरोग्य, घरेलू औषधियों सम्बन्धी जानकारी।

★ महिलाओं तथा विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त विभिन्न रुचिकर खाद्य पदार्थ बनाने की विधियां। घरेलू मितव्ययता। जिज्ञासु जगत्। कृषि व औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों की मुलाकात और परिचय। नित्योपयोगी वस्तुएं घर पर ही तैयार कीजिये।

आज ही उद्यम का वार्षिक चन्दा ७ रु० भेजकर उद्यम मासिक मंगवाइये।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हमारी अर्थ-व्यवस्था और समस्याएं

(पृष्ठ १६४ का शेष)

प्रवृत्तियों के विस्तार से यही तथ्य प्रकट होता है और इसीलिए कुछ लोग इसे अनुचित केन्द्रीयकरण की संज्ञा देते हैं। किन्तु यह आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण का उतना प्रमाण नहीं है, जितना कि सामान्य रूप में हमारे आर्थिक पिछड़ेपन का। दुर्भाग्यवश सरकार ने व्यावसायिक प्रयास के रास्ते में बहुत अधिक रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं और व्यवसायों से संबंधित कानून अधिकाधिक पेचीदा होते जा रहे हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में किसी भी नवागन्तुक के लिए यह करीब-करीब असंभव हो गया है कि वह कम्पनी कानून उद्योग कानून और विभिन्न श्रम संबंधी कानूनों की व्याख्या करने वाले सलाहकारोंकी सहायता के बिना अपना काम शुरू कर सके।

आज की परिस्थितियोंमें सबसे अधिक अज्ञान शिल्पीय ज्ञान के क्षेत्र में है और सबसे अधिक कमी शिल्पी कर्मचारियों की है। यह दोनों अति महत्व के साधन हैं। इस कथनमें जरा भी अत्युक्ति नहीं कि शिल्पी कर्मचारियों की कमी ही देश के शीघ्रगामी औद्योगीकरण के रास्ते में मुख्य बाधा है। यह सन्तोष का विषय है कि सरकार ने शिल्पी कर्मचारियों की आवश्यकता और उपलब्धि का हिसाब लगाने की आवश्यकता स्वीकार कर ली है और योजना आयोग ने इंजीनियरिंग कर्मचारी समिति द्वारा इस दिशा में कुछ काम भी किया है।

निर्यात व्यापार

सन् १९५६-५७ के वित्तीय वर्ष की प्रथम छःमाही में चाय और काजू को छोड़कर करीब-करीब सभी निर्यात होने वाली मुख्य वस्तुओं के निर्यात-मूल्य की राशि में कमी हुई। जिन वस्तुओं की निर्यात मात्रा में कमी हुई, उनमें सूती कपड़ा, मेंगनीज खनिज, कपास और तेल शामिल हैं। सूती कपड़े के निर्यात में कमी का कारण यह है कि सरकार ने कपड़ा-मिलों के विस्तार और नवीनीकरण पर प्रतिबन्ध लगाने की नीति अपना रखी है। कपड़े की किस्मों की पसन्दगी और जापान जैसे प्रतिस्पर्धियों की निर्यात बढ़ाने की युक्तियों के कारण भी हमारे निर्यात में कमी आई है। कपास और बनस्पति तेलों के उत्पादन में कमी और इन वस्तुओं की आन्तरिक मांग में वृद्धि ने भी उनकी निर्यात मात्रा को घटाया है। यह स्पष्ट है कि महत्त्वपूर्ण औद्योगिक कच्चे पदार्थों क देश में मांग बढ़ती जाएगी और साथ ही यदि योजना में निर्धारित विकास की गति मंद नहीं पड़नी हो तो अनिवार्य पूंजीगत माल का आयात भी जारी रखना होगा। आज स्थिति यह है कि सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए जरूरी पूंजीगत माल और मशीनी औजारों के आयात पर भी प्रतिबंध लगाना आवश्यक समझा है। मेरी यह दृढ़ धारणा है कि सरकारी और गैर-सरकारी व्यक्तियों की एक छोटी समिति राजकीय और निजी दोनों क्षेत्रों की आयात आवश्यकताओं की जांच-पड़ताल करने के लिए नियुक्त की जाए। इस समिति को यह विचार करना चाहिए कि क्या देश के भीतर उपलब्धि बढ़ाई जा सकती है। वह कम महत्त्वपूर्ण आयात में कटौती की संभावनाओं पर भी विचार कर सकती है, ताकि आवश्यक सामग्री का आयात जारी रह सके। विदेशी विनिमय के मोर्चे पर उत्पन्न हमारी समस्याओं से यह भी प्रकट हो गया है कि हमको अपनी अर्थ व्यवस्था के ढांचे में कौन से बुनियादी और मूलभूत परिवर्तन करने होंगे। भूतकाल में, विशेषकर उन्नीसवीं सदी के मध्य में स्वेज नहर के खुलने के बाद हमारी अर्थ-व्यवस्था को इस सांचे में ढाला गया कि वह ब्रिटेन की कच्चे माल की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। धीरे-धीरे भारतीय उद्योगों की स्थापना होती गई, किन्तु उनको मुख्यतः घरेलू बाजार की जरूरतों को पूरा करना था। अब हम उस मंजिल पर पहुँच चुके हैं, जब हमको औद्योगिक उत्पादनों का निर्यात बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान देना होगा। हमको नये निर्यातक उद्योग स्थापित करना और ऐसे ही वर्तमान उद्योगों को सुदृढ़ करना होगा।

यह बहुत आवश्यक है कि निर्यात बढ़ाने का संयुक्त और राष्ट्रीय दायित्व समझा जाए। प्रतिस्पर्धी विश्व बाजार में हमारे माल की किस्म, उसकी कीमत और माल को बेचने की कुशलता का बड़ा महत्व है। अतः हमारी उत्पादन की विधियां एकदम आधुनिक होनी चाहिएं। इसी प्रकार हमारी वितरण व्यवस्था भी वैसी ही होनी चाहिए। मैं सरकार और मजदूरों से अपील करता हूं कि वे उद्योगों को ऐसे उपायों का अवलम्बन करने दें, जिससे उत्पादन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

द्वितीय योजना में मध्यप्रदेश का खनिज एवं उद्योग

[श्री दशरथ जैन उपमंत्री]

मध्यप्रदेश क्षेत्रफल में देश का द्वितीय और जनसंख्या में देश का पांचवां प्रदेश है। यह न केवल क्षेत्रफल में ही योरोप के सुविख्यात देशों—इंग्लैंड, जर्मनी आदि से बड़ा है, अपितु अपने आकार के अनुरूप खाद्यान्न, खनिज सम्पत्ति आदि में भी बहुत सम्पन्न है। प्रदेश की आवश्यकताओं को पूरा करने योग्य खाद्यान्न तो यहां प्रायः हो ही जाता है, इस राज्य का लगभग एक तिहाई भाग विपुल वन सम्पदा से आच्छादित है, जिसमें साज, धावड़ा, तेंदू, बांस, महुआ, बबूल, टीक, सागौन आदि बहुमूल्य लकड़ियां पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती हैं। यहां का टीक तो भारतवर्ष में सर्वोच्च कोटि का माना जाता है। यहां उत्पन्न होने वाली रूसा घास भी बहुत महत्वपूर्ण है। कत्था भी यहां बहुतायत से उत्पन्न होता है। यहां खनिज सम्पत्ति का अक्षय भंडार भी एक साथ जुट गया है, जिससे किसी भी पदार्थ के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। यहां की रत्नगर्भा भूमि में कोयले से लेकर हीरे जैसी निधि गड़ी है, लोहे के पहाड़ के पहाड़ फैले हुए हैं, बाक्साइट और मैंगनीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। राज्य में फैली लगभग २६० खदानों में से इस समय आर्थिक महत्व के २० खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं। सन् १९५१ में इन खदानों से निकाले गये माल का मूल्य लगभग ८.४ करोड़ रुपये था।

उद्योग की रीढ़ कोयला यहां प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। छिंदवाड़ा जिला कोयले का गढ़ है। सरगुजा, रामगढ़, बिलासपुर और शहडोल जिले में कोयले की चट्टानें फैली हुई हैं। इस समय प्रदेश में ५२ कोयले की खदानें चल रही हैं, जिनमें से अधिकांश प्राइवेट कम्पनियों द्वारा संचालित हैं। सन् १९५३ में लगभग ४१,५२,३६१ टन कोयला निकला था। केन्द्र की ओर से ७ करोड़ रुपये व्यय करके विकसित की जाने वाली कोरबा

बढ़ाने, कीमतें घटाने और क़िस्म को सुधारने में मदद मिले। उद्योग और व्यापार के सिर पर भी भारी उत्तरदायित्व है। केवल मशीनरी ही पुरानी नहीं पड़ती; हमको दिमागी दकियानूसीपन से सतर्क रहना चाहिए। यदि प्रबन्ध में नवीन साहस करने की नौजवानों जैसी शक्ति बनी रहती है और विचारों में वह जागृत रहता है, तो मुझे तनिक भी संदेह नहीं कि हम अपने प्रयास में सफल होंगे।

भारत के इतिहास के इस क्षण में राष्ट्र का सम्पूर्ण ध्यान अर्थ व्यवस्था की रचना के महान् और विशाल कार्य पर केन्द्रित होना चाहिए और राजकीय और निजी क्षेत्रों के महत्व और स्थान संबंधी वाद-विवाद में हमको अपनी शक्ति नहीं खोनी चाहिए। आर्थिक प्रगति औद्योगिक क्षेत्रों के कठोर और तंग विभाजन द्वारा संभव नहीं हो सकती; और कटुतापूर्ण वाद-विवाद द्वारा तो उसकी और भी कम संभावना है। यह तो ऐसी क्रिया है कि जिसमें विकास की हर मंजिल पर औद्योगिक क्षेत्रों का एक दूसरे के आंगन में प्रवेश होगा।

इसमें शक नहीं कि हमको अपनी आर्थिक समस्याओं पर ऐकान्तिक रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक विकास की रोशनी में विचार करना चाहिए। अर्थ-व्यवस्था हमारी व्यापक सामाजिक प्रणाली का केवल एक अंग मात्र है। उसका काम है व्यापक समाज को वांछित बल प्रदान करना, ताकि वह अपने दीर्घकालीन उद्देश्यों को हासिल कर सके। यद्यपि अर्थ व्यवस्थ में सारी समाज व्यवस्था पर अपने ही मूल्य और लक्ष्य नहीं थोप सकती, किन्तु उसकी नियमित कार्य-प्रणाली की उपेक्षा समाज की भलाई को आपदमें डालकर ही की जा सकती है। हमारी समस्या केवल इतनी ही नहीं है कि हम आर्थिक विकास की छोटी पगडण्डी पकड़ लें, बल्कि यह भी है कि हमको अधिक खतरनाक रास्ता टालना है। यह सन्तोष का विषय है कि हमारे देश की जनता ने औद्योगीकरण में निहित नई शक्तियों और विचारों को अपनाने की इच्छा और सामर्थ्य का परिचय दिया है। हमको देश के करोड़ों स्त्री-पुरुषों के सतत दैनिक किन्तु शक्तिशाली प्रयत्नों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये प्रयत्न ही राष्ट्र निर्माण की हमारी क्षमता की आधारशिला हैं।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

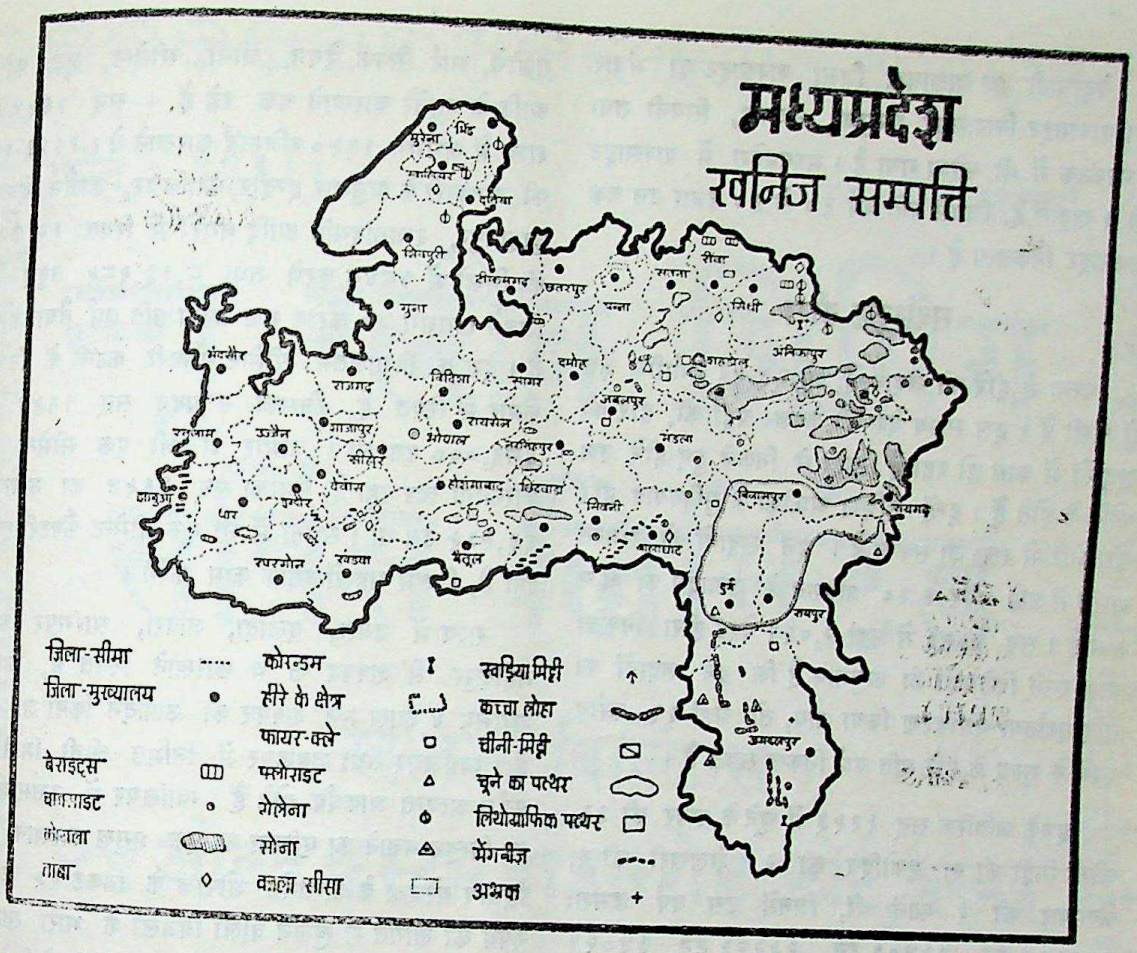

की कोयला की खदान बहुत ही बड़ी है। विशेषज्ञों का कथन है कि सन् १९६० तक प्रति वर्ष यहां से ४० लाख टन कोयला निकल सकेगा।

मैंगनीज़ और लोहा

दूसरा महत्वपूर्ण खनिज मैंगनीज है, जिसके लिये निमाड़, झाबुआ, बालाघाट, छतरपुर तथा छिंदवाड़ा जिले प्रसिद्ध हैं। मैंगनीज कच्चे लोहे से इस्पात तैयार करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। एक टन इस्पात तैयार करने के लिये लगभग १३ पौंड मैंगनीज की आवश्यकता पड़ती है। देश भर में जितना मैंगनीज निकलता है, उसका ६५ प्रतिशत मध्यप्रदेश में निकलता है। सोवियत रूस के बाद भारतवर्ष में सबसे अधिक मैंगनीज मध्यप्रदेश में उपलब्ध है। सन् १९५३ में लगभग ५,७६,४०८ टन मैंगनीज मध्यप्रदेश में निकला था। सन् १९५३ में इस प्रदेश में मैंगनीज की १६८ खदानें चालू थीं।

मध्यप्रदेश का तृतीय महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ कच्चा लोहा है। यह खनिज पदार्थ दुर्ग, बस्तर, जबलपुर तथा छतरपुर और होशंगाबाद जिलों में पाया जाता है। अनुमान है कि १५,३०० लाख टन कच्चा लोहा उक्त क्षेत्र में गर्भस्थ है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विन्ध्यप्रदेश की खदानों की खोज तथा सर्वेक्षण पर २ लाख रुपये व्यय होने वाले हैं। इन खनिज पदार्थों का उपयोग करने के लिये केन्द्रीय सरकार की ओर से लोहे और इस्पात तैयार करने का कारखाना इसी क्षेत्र में भिलाई में तैयार किया जा रहा है, जहां प्रतिवर्ष लगभग १० लाख टन इस्पात तैयार होगा और जिसका विस्तार अंततः २५ लाख टन तक किया जा सकेगा। उत्पादन सन् १९५८ से प्रारम्भ होने की आशा है। यह कारखाना प्रारम्भ ही में लगभग १ लाख व्यक्तियों को रोजगार दे सकेगा।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बेहरघाटी का बालाघाट जिला बाक्साइट का भंडार है। बाक्साइट बिलासपुर, सरगुजा, राजगढ, सिवनी तथा अमरकंटक में भी खोजा गया है। मध्यप्रदेश में बाक्साइट की ६ खदानें हैं, जिनसे प्रति वर्ष २० से ३० हजार टन तक बाक्साइट निकलता है।

सर्वोत्कृष्ट हीरा

पन्ना में हीरे की खदानें हैं, जो २३.५६ वर्गमील क्षेत्र में फैली हैं। इस समय देश की केवल यहीं की हीरे की खदानों में काम हो रहा है। यहां से निकले हुए हीरे उच्च कोटि के होते हैं। इन्हें दक्षिण अफ्रीका के सुविख्यात हीरे की कोटि में रखा जा सकता है। इन खदानों को समस्त भारत में प्राप्त हीरे के ६० प्रतिशत के उत्पादन का श्रेय प्राप्त है। सन् १९५३ में यहां २,०२२ केरट हीरा निकला था। रूसी विशेषज्ञों का अनुमान है कि इन खदानों का यदि पूर्णतया यंत्रीकरण किया जाय, तो यहां १२ करोड़ रुपये के मूल्य के हीरे प्रति वर्ष निकल सकते हैं।

इनके अतिरिक्त सन् १९५३ में चूने के पत्थर की ३३, चीनी मिट्टी की ९, एकोदिव की ६, शेलखरी की ६, फैल्सपार की ३ खानें थीं, जिनमें उस वर्ष क्रमशः ८७९११७ टन, २३४०१ टन, २५२२३ टन, ३४०२१ टन तथा १,५६६ टन उत्पादन हुआ। छतरपुर जिले में अभ्रक तथा साबुन बनाने के पत्थर पाये जाते हैं।

उद्योग के क्षेत्र में भी

उद्योग के क्षेत्र में भी मध्यप्रदेश बहुत अग्रसर है। जहां एक ओर भिलाई में १० लाख टन वाला इस्पात का कारखाना खड़ा किया जा रहा है, वहां दूसरी ओर ६ करोड़ रुपये व्यय करके निर्मित आधुनिकतम यन्त्रों से सज्जित अखबारी कागज की देश की पहली मिल नेपा भी खुली है, जिसका वार्षिक उत्पादन ३०,००० टन है और जो पूरे देश की एक तिहाई आवश्यकता पूरी करके विदेश-विनिमय में २२ करोड़ रुपये वार्षिक की बचत करायेगी। बांस और घास के सदुपयोग की दृष्टि से बुढ़ार में भी एक कागज की मिल स्थापित हो रही है, जिसमें हर प्रकार के कागज तैयार होंगे। उमरिया में हाथ से कागज बनाने का कारखाना चल रहा है। इनके अतिरिक्त यहां कपड़े, चीनी मिट्टी, बिस्कुट, गलीचे, आर्ट सिल्क, रेयन, चीनी, सीमेन्ट, जूट, कागज आदि के बहुतेरे कारखाने चल रहे हैं। सन् १९५४ में राज्य में लगभग १६५० रजिस्टर्ड कारखाने थे। १९५३-५४ की जानकारी के अनुसार इन्दौर, ग्वालियर, उज्जैन, देवास, बुरहानपुर, राजनांदगांव आदि नगरों में स्थित १८ कपड़े की मिलों में १८४८ करघे तथा ८,१३.२८५ तकुए हैं जिनमें लगभग ४० करोड़ गज कपड़ा प्रति वर्ष तैयार होता है। देश की विशालतम सीमेन्ट फैक्टरी कटनी के निकट कैमोर में स्थित है, जिसका उत्पादन सन् १९५४ में ३८३,००० टन था। बामोर में भी एक सीमेन्ट का कारखाना चल रहा है, जिसका सन् १९५४ का उत्पादन ६३,९३५ टन था। सतना में भी एक सीमेन्ट फैक्टरी खुल रही है, जिसमें सहस्रों व्यक्ति काम करेंगे।

राज्य में डबरा, दलोदा, जावरा, सारंगपुर और महीदपुर में शक्कर के ७ कारखाने स्थित हैं, जिनमें लगभग ४ लाख मन शक्कर का उत्पादन किया जा रहा है। ग्वालियर तथा जबलपुर में निर्मित चीनी मिट्टी के बर्तन अत्यन्त आकर्षक होते हैं। ग्वालियर में उत्तम कोटि का बिस्कुट बनाने का एशिया का एक प्रमुख कारखाना है। द्वितीय योजना के अन्तर्गत भोपाल के निकट २५ करोड़ रुपये की लागत से खुलने वाली बिजली के भारी सामान की फैक्टरी देश में अपने प्रकार की पहली ही होगी। यह सन् १९५८ तक तैयार हो जायेगी, ऐसा आशा है।

नई संभावनाएं

इनके अतिरिक्त कोरबा में ५५ करोड़ रुपये के व्यय से एक पेट्रोल कारखाना, बिलासपुर जिले में सुखेड़ा के निकट सीमेन्ट कारखाना, बडवाह के निकट कार्डबोर्ड फैक्टरी, डबरा में अलकोहल का कारखाना, शिवपुरी के पास एक कागज मिल स्थापित करने की दिशा में प्रारम्भिक कदम उठाये जा चुके हैं।

शक्कर, चीनी मिट्टी, गलीचे, रेयन सिल्क, कपड़ा, जूट, रेजर ब्लैड आदि उद्योग भी चल रहे हैं और योजनाओं में भी बहुत औद्योगिक विकास की गुंजायश की गई है। छोटे घरेलू उद्योगों की दृष्टि से मध्यप्रदेश बहुत प्रगति कर रहा है।

—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

फोन : ३३१११

तार : 'ग्लोबशिप'

न्यू ग्लोब शिपिंग सर्विस लिमिटेड

खताऊ बिल्डिंग्स

४४ ओल्ड कस्टम हाउस रोड, फोर्ट, बम्बई

सब प्रकार का क्लियरिंग, फारवर्डिंग, शिपिंग
का काम शीघ्र व सुविधापूर्वक
किया जाता है ।

सेक्रेटरी—
श्री बी० आर० अग्रवाल
बी. काम., एल. एल. बी.

मैनेजिंग डायरेक्टर—
श्री सी. डीडवानिया

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विभिन्न राज्यों के बजट

उत्तरप्रदेश

उत्तरप्रदेश के अंतरिम बजट में ९३ करोड़ ८८ लाख रु. की आय तथा १०३ करोड़ ५६ लाख रु. का व्यय दिखाया गया है। बजट में ९ करोड़ ७ लाख का कुल घाटा है।

१९५६-५७ के मूल बजट में ४२करोड़९८ लाख रु० के व्यय का अनुमान था लेकिन अब आशा है कि ३३ करोड़ ६१ लाख रु० का ही व्यय होगा।

विकास-कार्य के लिए ५२ करोड़ ८० लाख रु० निर्धारित किये गये हैं।

पश्चिमी बंगाल

पश्चिमी बंगाल के १९५७-५८ के पहले ५ महीनों के अंतरिम बजट में ६० करोड़ रु० की आय और ७१ करोड़ रु० का व्यय प्रदर्शित किया गया है। बजट १२ करोड़ रु० घाटे का है।

बम्बई

बम्बई के १९५७-५८ के बजट में, १०६.३२ करोड़ की आय और १०८.६९ करोड़ रु० के व्यय का अनुमान है। सम्पूर्ण खर्च मिला कर २५.१३ करोड़ के घाटे का अनुमान लगाया गया है।

दिल्ली

दिल्ली राज्य का, १९५७-५८ वर्ष में, ७ करोड़ १ लाख ६३ हजार रुपये व्यय का अनुमान है। यह अनुमान आय से १ करोड़ ३८ लाख रु० अधिक है। इस घाटे की पूर्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा होने वाले अनुदान से होगी।

पंजाब

पंजाब को १९५७-५८ के अंतरिम बजट में, ४० करोड़ ११ लाख रु० की आय और ४३ करोड़ ७३ लाख रु० का व्यय का अनुमान किया गया है। इस प्रकार बजट में ३३ करोड़ ६३ लाख रु० का घाटा होगा।

राजस्थान

राजस्थान के १९५७-५८ के अंतरिम बजट में २७.३७-३३ करोड़ रु० की आय और ३१.७९६२ करोड़ रु० के व्यय का अनुमान है। यह घाटा ४॥ करोड़ रु० का है।

(पृष्ठ २३२ का शेष)

गत वर्ष बैंकों की स्थिति में सुधार

इण्डियन बैंक ऐसोसियेशन के अध्यक्ष श्री सी. एच. भाभा ने १९ मार्च को १०वें वार्षिक अधिवेशन में भाषण में बताया है कि इस वर्ष भारत में अन्य देशों के देखते हुए डिपोजिट बहुत कम बढ़े हैं। एक ओर देश में नोटों का प्रचलन १०४ करोड़ रुपया बढ़ गया, दूसरी ओर अनुसूचित बैंकों में डिपोजिट केवल ७६ करोड़ रुपये बढ़े। १९५६ के अन्त में देश में १४४६ करोड़ के नोट चलन में थे, जब कि अनुसूचित बैंकों में डिपाजिट केवल ११०२ करोड़ रुपये के थे। इस वर्ष की एक विशेषता यह भी रही कि बैंकों ने डिपाजिटों की अपेक्षा बहुत अनुपात में रुपया उधार दिया। डिपोजिट जब केवल ७६ करोड़ रुपये बढ़े, उधार की रकम १०६ करोड़ से भी ज्यादा बढ़ी है। बैंकों की इस प्रशंसनीय सफलता का एक कारण बिल मार्केट की योजना है, जो रिजर्व बैंक ने ५ वर्ष पूर्व शुरु की। तब से बैंकों द्वारा बिलों की खरीद बढ़ी है। यह १९५३ में ४५.४३ करोड़ रुपये से बढ़कर १९५६ में १६५.५५ करोड़ हो गई।

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ३३। करोड़ डालर ऋण

पहली जुलाई १९५६ से आरम्भ होने वाले चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक विकास एवं पुन निर्माण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने ग्यारह देशों में चलने वाली योजनाओं के लिए चौदह ऋण स्वीकृत किए जिनका कुल योग ३३१,६५८,००० डालर है।

इन ऋणों से पांच देश—आस्ट्रिया, चिली, इटली, निकारगुए व उरगुए में विद्युत शक्ति सुविधाओं का प्रसार सम्भव हो सकेगा अन्य ऋण उत्पात-उत्पादन बन्दर विकास हवाई यातायात, कृषि व सामान्य विकास व लिए दिए गए।

चालू वित्तीय वर्ष में बैंक द्वारा प्रदान किए गए ऋणों की संख्या को जोड़ कर बैंक के शुरू होने से अब तक उसने १६४ ऋण दिए जिनका कुल योग ३,०५२,७६६,४६४ डालर बैठा। यह ऋण ४४ देशों व प्रदेशों में विभिन्न योजनाओं में सहयता पहुँचाने के लिए दिए गए।

गत जुलाई से एशिया व मध्यपूर्ण को दिए गए ऋण इस प्रकार है—

भारत स्पात उत्पादनार्थ बीस मिलियन डालर, ईरान, सामान्य विकास हेतु ७५ मिलियन डालर स्पात जापान—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

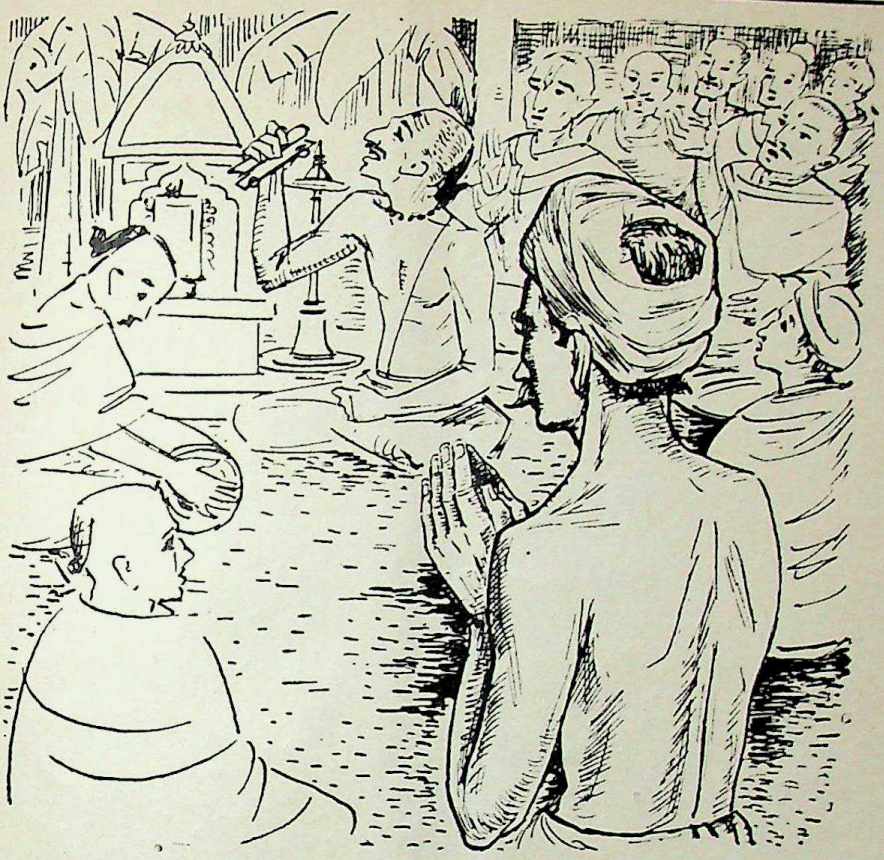

यह उनका अधिकार है . . .

"मंदिर में प्रवेश करना आध्यात्मिक क्रिया है जो अछूतों को स्वतंत्रता का सन्देश देगी और उन्हें विश्वास दिलाएगी कि वे परमात्मा के सम्मुख जातिभ्रष्ट नहीं हैं।"

—महात्मा गांधी,

भारतीय संविधान ने अस्पृश्यता का उन्मूलन कर सब व्यक्तियों को समान नागरिक और सामाजिक अधिकार दिए हैं।

छूतछात को छोड़ो
दिल को दिल से जोड़ो

DA 56/248

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दि बैंक ऑफ़ बड़ोदा लिमिटेड

(१९०८ में स्थापित)

प्राधिकृत पूंजी	...	...	२,४०,००,००० रु०
प्रार्थित पूंजी	...	...	२,००,००,००० रु०
परिदत्त पूंजी	...	...	१,००,००,००० रु०
सुरक्षित कोष	...	...	१,२८,००,००० रु०

मुख्य कार्यालय : बड़ोदा

शाखाएं

अहमदाबाद (भद्रा), अहमदाबाद (पंचकुवा), अमरेली, अमृतसर, बंगलौर, बड़ोदा (सयाजी), भावनगर, बिल्लिमोरा, बम्बई (फोर्ट), बम्बई (बुलियन हाल), बम्बई (मांडवी), बम्बई (ज़वेरी बाजार), (रिक्लेमेशन), बम्बई (घाटकोपर), कलकत्ता (नेताजी सुभाष रोड), कलकत्ता (बड़ा बाजार), कलकत्ता (क्रास स्ट्रीट), कैम्बे, कोयम्बटूर, दभोई, दिल्ली, धूलिया (पश्चिमी खानदेश), द्वारका, गण्टूर, हरिज (उ० गु०), हैदराबाद (दक्षिण), जलगांव (पूर्वी खानदेश), जामनगर, कादी, कलोल (उ० गु०), कानपुर, कापड़वंज, कारजन, लखनऊ, मद्रास (त्यागराय नगर), महसाना, मिठापुर, नवसारी, नवसारी (स्टेशन रोड), नई दिल्ली, पचोरा (पूर्वी खानदेश), पाटन, पेतलाड, पूना कैम्प, पूना शहर, पोरबन्दर, पोर्ट ओखा, राधानपुर (उ० गु०), राजकोट, राजपीपला, सांखेड़ा, सिकन्दराबाद, सिद्धपुर, सूरत, सुरेन्द्रनगर (बाढवान कैम्प), ऊंझा (उ० गु०), विरावल, विजापुर (उ० गु०), विसनगर (उ० गु०), व्यारा।

विदेशों में शाखाएं

लन्दन, नैरोबी, कम्पाला, मोम्बासा, दारे-इस-सलाम (ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका)।

देश और विदेश में सब प्रकार का बैंकिंग कारोबार होता है।

वसीयतों और समझौतों तथा विवाहित स्त्रियों के समझौते कानून के अंतर्गत बैंक प्रबन्धकर्ता और ट्रस्टी का काम करता है।

सेविंग बैंक खातों पर मुख्य कार्यालय तथा भारत स्थित सभी शाखाओं में २% ब्याज दिया जाता है। मामलों में चेक द्वारा रुपया निकाला जा सकता है।

३ वर्षीय कैश सार्टिफिकेट ३॥% चक्रवृद्धि ब्याज दर से दिये जाते हैं।

एम. जी. पारिख
बम्बई मैनेजर

एन. एम. चोकसी
जनरल मैनेजर

सम्पादक—कृष्णचन्द्र विद्यालङ्कार द्वारा, अशोक प्रकाशनमन्दिर के लिए अर्जुन प्रेस दिल्ली से मुद्रित व प्रकाशित

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्पदा

मई १९५७

संपादक

कृष्णदत्त विद्या

मूल्य

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

पहली व दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के अनुसार—

भारतवर्ष आज अपने आर्थिक विकास व पुनर्निर्माण के लिए प्रयत्नशील है। देश के हर एक भाग में पक्की सड़कें, नदियों के बाँध, विशाल पुल, सुन्दर भवन, हस्पताल, स्कूल व कालिज तथा बड़े-बड़े कारखाने बनाये जा रहे हैं।

इनको टिकाऊ, सुन्दर, एवं सबल बनानेके लिए सर्वोत्तम डालमिया सीमेंट का प्रयोग कीजिए।

डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटिड

डालमियापुरम् (त्रिचनापल्ली)

केवल ५० विद्यार्थियों के लिये

पंचवर्षीय योजनांक रियायत में

राजस्थान के एक सज्जन ने जो पंचवर्षीय योजना के प्रसार में विशेष रुचि लेते हैं, एक राशि इसलिये प्रदान की है कि हम अर्थ शास्त्र के विद्यार्थियों को अपने योजना अंक कम कीमत पर दें। इसलिये जो विद्यार्थी निम्नलिखित अंक मंगवाना चाहें, वे दो रुपया मनीआर्डर से भेज दें। इन अंकों की वी० पी० नहीं की जायेगी।

योजनांक—(प्रथम पंचवर्षीय योजना मूल्य १) रु०

राष्ट्रीय विकास अङ्क—(दूसरी योजना का विवरण १।)

जून १९५६ का अंक—(दूसरी योजना के संशोधित अंक इसमें दिये गये हैं) मूल्य ।।।)

यह रियायत केवल ५० विद्यार्थियों के लिये है। इसलिए शीघ्र करें, अन्यथा यह सुविधा नहीं मिल सकेगी।

—मैनेजर

भारत की औद्योगिक नीति

इसमें भारत की उद्योग नीति का अतीत, समय-समय पर होने वाले परिवर्तन और आज की नीति का संक्षेप में परिचय दिया गया है। इसके लेखक काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के श्री अश्विनीकुमार शाह और सेण्ट जेवियर्स कालेज रांची अर्थशास्त्र के अनुभवी अध्यापक श्री रामनरेश लाल हैं। दोनों अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों की कठिनता और आवश्यकताएं जानते हैं। इसलिए यह पुस्तक हायर सैकेण्डरी, इन्टर व बी० ए० के परीक्षार्थी विद्यार्थियों के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी। मूल्य ६२ नये पैसे ७५ नये पैसे के टिकट भेजकर अण्डर पोस्टल सर्टिफिकेट मंगाइये।

—मैनेजर, अशोक प्रकाशन मंदिर,

रोशनारा रोड, दिल्ली—६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्पदा का :—

आगामी विशेषांक

१० वें स्वाधीनता दिवस १५ अगस्त '५७ को प्रकाशित होगा

परन्तु वह कैसा होगा,
किस विषय पर प्रकाशित होगा,
उसकी विशेषताएं क्या होंगी,
आदि जानकारी के लिए

आपको अभी प्रतीक्षा करनी चाहिए

इतना ही समझ लीजिए कि अपने विषय का एक अद्भुत विश्वकोश होगा—हिन्दी पत्र जगत् में एक दम अनुपम और संग्रहणीय। विविध विद्वत्तापूर्ण लेखों, ज्ञानवर्धक तालिकाओं, ग्राफों और चित्रों से परिपूर्ण।

अभी से सम्पदा का ग्राहक बन जाने वालों को साधारण वार्षिक मूल्य में ही मिलेगा।

मूल्य होगा १॥) रु०।

—मैनेजर सम्पदा

अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिल्ली-६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विषय-सूची

क्रम	विषय	पृष्ठ संख्या
१.	केरल में साम्यवादी मंत्रिमंडल	२४५
२.	रेलवे व भारतीय उद्योग	२४७
३.	सम्पादकीय टिप्पणियां	२४८
४.	निजी या सरकारी नहीं, राष्ट्रीय क्षेत्र	२५१
५.	आर्थिक विकास में लघु कुटीर उद्योग	२५३
६.	अर्थ शास्त्र का आशावाद और निराशावाद	२५६
७.	अनिवार्य जमा : अर्थ व्यवस्था पर भारी बोझ	२६०
८.	सिंचाई का आयोजन	२६२
९.	बैंक व बीमा—बैंकों की समस्याएं—स्टेट बैंक द्वारा—प्रतिस्पर्धा—केन्द्र व राज्य—नये ऋण की तैयारी द्रव्य बाजार	२६४
१०.	द्वितीय योजना में छोटी बचतें	२६७
११.	आवश्यक भूमि सुधार	२७०
१२.	विश्व में चावल की खेती तथा अन्य टिप्पणियां	२७१
१३.	विश्व आर्थिक सम्मेलन	२७४
१४.	नया सामयिक साहित्य	२७५
१५.	श्रम-समस्या—कारखाना बन्द होने पर भी मुआवजा, बीमा कर्मचारी और अध्यादेश, मुकदमे के लिए अपील, केरल में इन्टक	२७६
१६.	भारतीय मसाले	२७८
१७.	सर्वोदय पृष्ठ	२८०
१८	मध्यपूर्व का तेल संघर्ष	२८३
१९.	वस्त्र-उद्योगके लिए नया सुझाव	२८५
२०.	मध्य रेलवे की सफलता	२८६
२१.	हमारे उद्योग	२८८
२२.	राष्ट्र का आर्थिक प्रवाह	२९१
२३.	अर्थ-वृत्त-चयन	२९३

● आगामी अङ्क में
● आप देखेंगे कि
● १५ अगस्त ५७ को
● कौन-सा विशेषाङ्क निकलेगा ?

अपूर्व प्रगति

३१ दिसम्बर १९५६

डिपोजिट १०६ करोड़ रुपये से अधिक
कार्यगत कोष १४१ करोड़ रुपये से अधिक

१९५६ में देश के सभी अनुसूचित बैंकों के अधिक-जमा का लगभग २० प्रतिशत पंजाब नैशनल बैंक ने प्राप्त किया है।

चेयरमैन

श्री एस. पी. जैन

दी पंजाब नैशनल बैंक लिमिटेड

प्रधान कार्यालय : दिल्ली

६२ वर्षों की विश्वसनीय सेवा का बृहत अनुभव

ए. एम. वाकर— जनरल मैनेजर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

76338

सम्पदा

वर्ष ६] मई १९५७ [अङ्क ५

केरल में साम्यवादी मन्त्रिमण्डल

हम सम्पदा के पृष्ठों को राजनीतिक आन्दोलन और मंत्रि मण्डलों के चुनाव तथा अन्य राजनीतिक हलचलों से अछूता रखते हैं। किन्तु केरल में नये मंत्रिमंडल की स्थापना राजनीतिक महत्व की अपेक्षा आर्थिक महत्व अधिक रखती है। इसलिए व्यक्तिगत या दल की चर्चा न करते हुए नये मंत्रिमंडल की स्थापना और तत्सम्बन्धी समस्याओं पर हम यहां कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं।

यह भारत के राजनीतिक इतिहास में असाधारण घटना है। समस्त देश में कांग्रेसी शासन होते हुए भी कम्युनिस्ट पार्टी ने लोकतंत्र की वैधानिक पद्धति से केरल में सरकार स्थापित करली है। कम्युनिस्ट पार्टीके इतिहासमें भी यह एक असाधारण घटना है। अब तक संभवतः किसी भी देश में कम्युनिस्ट पार्टी ने बिना हिंसा के अपनी पहली सरकार स्थापित करने में सफलता प्राप्त नहीं की। जब सारे देश में कांग्रेसी सरकारें स्थापित हुईं—तब एक राज्य में विरोधी दल द्वारा सरकार की स्थापना एक विचित्र परिस्थिति को जन्म देती हैं, किन्तु उसके राजनीतिक स्वरूप की चर्चा न करते हुए हम अपने पाठकों का ध्यान केवल आर्थिक महत्व की घटनाओं की ओर खींचना चाहते हैं।

अभी नये मंत्रिमंडल को स्थापित हुए एक मास भी कठिनता से बीता है। वह अपने चुनाव घोषणा-पत्र में की गई घोषणाओं को किस तरह पूरा करेगा, यह आज नहीं कहा जा सकता, किन्तु उसने प्रथम मास में ही जो कुछ किया है, उसमें से कुछ कार्य निम्नलिखित हैं: (१) मंत्रियों ने अपना वेतन ५००) रु० लेने का निश्चय किया है। मंहगाई भत्ते भी लेने बन्द कर दिये हैं। ऊपरी टीप-टाप में भी असाधारण कमी की गई है। (२) बड़े सरकारी अफसरों के वेतनों में ११०० से १६०० रुपये तक की प्रस्तावित वेतन वृद्धि को रोक दिया गया है। (३) अनेक विभागों में निम्न कर्मचारियों की वेतन वृद्धि करने का निश्चय किया गया है। (४) सरकारी कारखानों में काम करने वाले मजदूरों का मंहगाई भत्ता बढ़ा दिया है। ट्रेड यूनियनों की दरखास्तों पर दो रुपये की स्टाम्प ड्यूटी हटा दी है और एक नया वेतन कमीशन नियत करने का निश्चय किया है। (५) भूमि सुधार की दिशा में बेदखली बन्द करने के लिए आर्डिनैंस जारी कर दिया गया है। किसानों का सम्मेलन बुलाकर उससे भी सलाह मश्वरा करने का प्रयत्न किया जा रहा है। (६) लक्ष्मी कपड़ा मिल को खरीदने के लिये सरकार ने ३ लाख रुपये देने का जो निश्चय किया था, उसे स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि नये मंत्रिमंडल की दृष्टि में मिल की कीमत ५० हजार रु० से ज्यादा नहीं है। (७) बहुत से कैदी हिंसात्मक अपराधों में दण्डित थे। उनका मृत्यु या जेल दण्ड माफ कर दिया गया है, क्योंकि मंत्रिमंडल की सम्मति में वे राजनैतिक अपराधी थे और राज-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नैतिक उद्देश्य से ही उन्होंने कानून का भंग किया था। (८) राज्य की आर्थिक समस्या सुधारने के लिए उसने जो नीति घोषित की है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। अनेक निजी उद्योगों को सरकार अपने हाथ में ले लेगी, ताकि उनसे प्राप्त होने वाला लाभ सरकार को मिल सके। (९) केरल में चाय, काफी और रबड़ के बहुत से बागान है। इनपर विदेशी पूंजी पतियों का अधिकार है। इनके राष्ट्रीयकरण की नीति सरकार अपनाना चाहती है। (१०) अपनी क्रांतिकारी भावना का परिचय देने के लिए किसी कम्युनिस्ट मंत्री ने शपथ लेते हुए ईश्वर का नाम नहीं लिया।

उपर्युक्त कामों में कुछ ऐसे हैं जिनका जनता विशेष रूप से स्वागत करेगी। ५०० रु० वेतन लेने का निश्चय कम्युनिस्ट मंत्री मण्डल को अपने राज्य में ही नहीं, समस्त देश में लोक प्रिय बना देगा और कांग्रेसी मंत्रियों को भी इस दिशा में कोई कदम उठाने को विवश करेगा। मंत्रियों का तथा उच्चाधिकारियों का आडम्बरपूर्ण जीवन जनता की आंखों में सदा खटकता रहा है। निम्न कर्मचारियों तथा मजदूरों की वेतन वृद्धि, बेदखली बन्द करने तथा भ्रष्टाचार निरोध की कारवाइयों की सफलता भी उन्हें जनता में लोक प्रिय बनायेगी। किन्तु मुख्य प्रश्न यह है कि वह जनता में फैली बेकारी को दूर करने और उसका जीवन स्तर ऊँचा करने में कहां तक सफल होते हैं। दूसरा महत्व पूर्ण प्रश्न यह है कि केन्द्र की और संविधान में निर्दिष्ट सीमा के अन्तर्गत मंत्रीमण्डल कार्य करता है या नहीं। चलते हुए अनेक उद्योगों के राष्ट्रीयकरण से यह संभव है कि सरकार उनका नफा खुद कमाने लगेगी, किन्तु अपना रुपया चलाते हुए उद्योगों में लगाने की अपेक्षा यह कहीं अधिक लाभकारी होगा कि सरकार उससे नये उद्योग खोले और बेकार आदमियों को रोजगार दे। विदेशी बागान के राष्ट्रीयकरण की मांग साम्यवादी ही नहीं, समाजवादी भी करते रहे हैं और उनसे होने वाला नफा इतना आकर्षक है कि उसे कोई सरकार छोड़ना नहीं चाहती खासकर "केरल की सरकार वहां की अर्थ व्यवस्था में दिल्ली स्कूल आफ एकोनोमिक्स के प्रो० डा० के० एन० राज के अनुसार केरल में मुख्य रूप से तीन प्रकार के बागान हैं—काफी, चाय, और रबर। केवल त्रावनकोर कोचीन में २० लाख एकड़ भूमि पर बागान फैले हुए हैं। मलाबार में ४० या ५० एकड़ भूमि के ये बागान हैं। इस प्रकार नये केरल में कुल २५ लाख एकड़ भूमि पर बागान फैले हुए हैं। इसमें से २४ हजार एकड़ में केवल काफी की खेती होती है जो पूरे देश के काफी उद्योग का ५० प्रतिशत है। चाय की खेती १० लाख एकड़ में होती है जो कि पूरे देश के चाय उद्योग का १२ प्रतिशत है। बाकी में रबर पैदा किया जाता है। रबर का औसत ८० या ९० प्रतिशत तक पहुँच चुका है। इन तीनों तरह की उपजों की कुल कीमत १५-२० करोड़ रु० सालाना है।"

बागान कम्पनियों को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपया लाभ होता है। सरकार यह क्यों छोड़ना चाहेगी। किन्तु 'सम्पदा' के पाठक जानते हैं कि हाल ही में संसद ने विदेशी बागान के राष्ट्रीयकरण के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया था। अब केरल सरकार का यह प्रस्ताव अमल में आना संभव नहीं है, राज्य सरकार से भी यह छिपा नहीं है। आज पंचवर्षीय योजना की पूर्ति में जब एक ओर विदेशी पूंजी प्राप्त करने के लिये राष्ट्र अधिकाधिक प्रयत्न कर रहा है, तब विदेशी पूंजी को निकालने का प्रयत्न अखिल देशीय नीति से मेल नहीं खाता, इस प्रकार की मांग केन्द्र द्वारा अस्वीकृत होने का लाभ साम्यवादी शासन अपनी असमर्थता के छिपाने तथा कांग्रेसी सरकारों को बदनाम करने के लिए जरूर उठायेगा। जमींदारी उन्मूलन का भूमि सुधार

+ केरल में बागान : कृषि-भूमि का विभाजन

चाय	९७५००० एकड़
रबड़	१९८००० एकड़
काफी	४३००० एकड़
इलायची	४०००० एकड़
काली मिर्च	२००००० एकड़
संतरे	११००० एकड़
गोला	१२०००० एकड़
सुपारी	८७००० एकड़
लैमनग्रास	३०००० एकड़
काजू	२००००० एकड़

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

की समस्या केरल में महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वहां जमींदारी समस्या बहुत उग्र रूप में नहीं है। फिर केरल के मुख्य मंत्री श्री नम्बूदरीपाद ने इस सम्बन्ध में जो कार्यक्रम घोषित किया है, वह योजना आयोग के प्रस्तावित सुधारों से बहुत भिन्न नहीं है।

संविधान की सीमाओं में रहकर कार्य करने का आश्वासन केरल की कम्युनिस्ट पार्टी ने दिया है। उसके एक प्रस्ताव के अनुसार इसलिए मंत्रीमण्डल बनाया गया है कि "संविधान की सीमाओं के अन्दर रहते हुए जनता का अधिकाधिक भला किया जा सके। यद्यपि उसकी सम्मति में वर्तमान संविधान के अनेक दोष हैं और अनेक अलोकतंत्रीय धारायें हैं।"

मुख्य प्रश्न रह जाता है केरल की शिक्षित जनता की बेकारी दूर करने का। इसके लिए आज देश में नये से नये उद्योग खोलने, ग्रामोद्योगों के प्रचार करने तथा नयी योजनाएं प्रारम्भ करने के अलावा दूसरा मार्ग नहीं है। बेकारी की समस्या इतनी विकट है कि देश के वित्तमंत्री श्री कृष्णमाचारी ने कहा था कि केरल सरकार बेकारी की समस्या को दूर कर दे, तो वे कम्युनिस्ट हो जायेंगे। वस्तुतः केरल की शिक्षित जनता में बेकारी ने ही साम्यवाद की भावना को जन्म दिया है। यदि सरकार संविधान की वर्तमान सीमाओं में रहते हुए इस समस्या को हल कर लेती है तो उसका शासन सफल हो जायेगा और न केवल केरल में बल्कि अन्य राज्यों में भी साम्यवादी शासन की संभावनायें बढ़ जायेंगी। अपने आर्थिक व्यय बढ़ाने के लिये वह बिक्री कर तथा जनता पर अन्य करों में वृद्धि नहीं करना चाहेगी। तब वह अपनी आय कैसे बढ़ा सकेगी? केवल सम्पन्न वर्ग पर कर बढ़ा कर या केन्द्र पर निर्भर रहकर आर्थिक स्थिति नहीं सुधारी जा सकती। यही उसकी सफलता की परीक्षा है।

फिर भी हम केरल में साम्यवादी मंत्रिमण्डल का स्वागत करते हैं। आज देश में कोई प्रबल विरोधी दल नहीं है। केरल का साम्यवादी मंत्रिमण्डल उस अभाव की कुछ पूर्ति कर सकेगा। कांग्रेसी सरकारों को भी उसकी अपेक्षा अधिक लोकप्रिय होने का प्रयत्न करना पड़ेगा। इसके लिए मितव्यय, आडम्बर शून्यता, अधिक जन सम्पर्क, अधिक जनहित आदि को अपनाना पड़ेगा। यदि केरल में साम्यवादी मंत्रिमण्डल अन्य राज्यों के कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों को अपने कार्य से अधिक जागरूक रख सका तो समय समय पर उठने वाले अप्रिय संघर्ष के बावजूद यह मंत्रिमण्डल देश के लिये हितकर ही सिद्ध होगा।

*

रेलवे व भारतीय उद्योग

भारत के उद्योगों में रेलवे सबसे बड़ा उद्योग है इसलिए यह स्वाभाविक है कि देश के अन्दर उद्योगों के विकास में वह सबसे अधिक सहायक हो। एक छोटे से छोटे पिन से लेकर बड़े से बड़े इंजिन तक १५ हजार से अधिक वस्तुओं की उसे आवश्यकता होती है। जितना सामान रेलवे खरीदती है उतना सरकार के अन्य सभी विभाग मिला कर भी नहीं खरीदते। और यह मात्रा लगातार बढ़ती ही जा रही है। १९४४-४५ में रेलवे ने कुल ४५ करोड़ का सामान खरीदा था, १९५१-५२ में ९८ करोड़ का और ५ साल बाद अर्थात् प्रथम योजना के अन्तिम वर्ष १२६ करोड़ रु० का सामान खरीदा है। यदि इसमें विदेशी और देशी सामग्री का अनुपात देखना चाहें तो नीचे लिखे अङ्क सहायक होंगे।

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	भारतीय	विदेशी	कुल
१९५१-५२	६८.३३ (६०%)	२९.३२ (३०%)	९७.६५
१९५२-५३	६४.१५ (७०%)	२८.०० (३०%)	९२.१५
१९५३-५४	६४.४३ (७२%)	२५.६० (२७%)	९०.०३
१९५४-५५	८३.६४ (७८%)	२४.०३ (२२%)	१०७.६७
१९५५-५६	९३.६५ (७४%)	३२.६३ (२६%)	१२६.२८
योग	३७४.८० (७३%)	१३९.५८ (२७%)	५१३.७८

इन अंकों में वह सामान शामिल नहीं है, जो रेलवे के अपने कारखानोंमें बनाई जाती है। यह ख्याल किया जाता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक २०० करोड़ रु० से अधिक सामग्री रेल्वे प्रतिवर्ष लेने लगेगी। यह भी अनुमान किया गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में करीब १००० करोड़ रु० का माल रेल्वे लेगी जिसमें से करीब ४-५०० करोड़ रु० का सामान विदेश से मंगवाएगी।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ऐसा अनुमान किया जाता है कि बड़े सामान की (Rolling Stock)—२३६४ इंजन, १०४९० सवारी डिब्बे, १०७२४७ बैगन और ४८५ ई. एम. यू.—के लिए करीब ३८० करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी, जिनमें से करीब १५८ करोड़ रुपया विदेशों से मंगाना पड़ेगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल ९० करोड़ रुपये का माल भारत में खरीदा था, जब कि द्वितीय योजना में २२० करोड़ रुपये का माल भारत में ही खरीदा जायेगा। विदेश से लिये जाने वाले सामान में रेल पटरी, स्लीपर, फिश प्लेट आदि हैं। समस्त देश में रेलवे ही लोहा, स्पात, लकड़ी अलोह धातुयें लुब्रिकेटिंग आयल और ग्रीज आदि की सबसे बड़ी खरीदार है। इसलिये देश के अन्दर स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए उसी पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यह प्रसन्नता की बात है कि रेलवे विभाग इस दिशा में विशेष प्रगति कर रहा है। नीचे के अंकों से भी यह अधिक स्पष्ट हो जायेगा। देश के भिन्न २ स्थानों पर रेलवे सामग्री का उत्पादन नियमित रूप से बढ़ता जा रहा है। १९५१-५२ में बड़ी लाइन और छोटी लाइन के इंजनों का उत्पादन क्रमशः १७ और १० हुआ था, जबकि १९५५-५६ में यह दोनों संख्यायें १२५ और ५० हो गई हैं। इसी तरह सवारी और मालगाड़ी के डिब्बे क्रमशः ६७३ से १२६० और ३३०७ से १३५२६ तक पहुंच गये हैं। ये संख्यायें इस बात का प्रमाण हैं कि यदि हम यह निश्चय करलें कि हमें अपने देश के उद्योग व्यवसाय को बढ़ाना है तो देश के अन्दर उत्पादन भी बहुत बढ़ाया जा सकता है। अभी इ. एम. यू. स्टीम, बिजली और डीजल से चलने वाले इंजन देश में अभी नहीं बन रहे हैं। आशा करनी चाहिये कि देश आगामी पांच वर्षों में बहुत अधिक उन्नति कर लेगा और इसमें रेलवे का अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग होगा।

बन्द मिलें मजदूरों के हाथों में!

अहमदाबाद के मजदूर संघ ने एक नई मांग की है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि यदि कोई मिल अपना कारोबार बन्द करती है तो उसको अपने मजदूरों को छंटनी का मुआवजा देने के लिये विवश नहीं किया जा सकता। इसका लाभ उठाते हुए बम्बई और अहमदाबाद में अनेक छोटी मिलों ने जिन्हें नुकसान हो रहा है अपना कारोबार बन्द करने का निश्चय किया है। कलकत्ते की अनेक जूट मिलें भी बन्द हो रही हैं। इससे परिणामस्वरूप मजदूरों की बेकारी बढ़ रही है। अहमदाबाद के मिल मजदूर संघ ने सरकार से यह मांग की है कि बन्द होने वाली मिलें, मजदूरों की सहकारी समितियों को चलाने के लिये सौंप दी जायें और सरकार उन्हें चलाने के लिये आर्थिक सहायता दे। भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम-मंत्री श्री खण्डूभाई देसाई ने, जो अहमदाबाद मजदूर संघ के मंत्री चुन लिये गये हैं, इस मांग का समर्थन किया है। बहुत संभव है कि अहमदाबाद मजदूर संघ से दीर्घ काल तक संबद्ध श्री गुलजारी लाल नन्दा इस प्रस्ताव पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। हम मजदूर संघ की इस मांग का स्वागत करते हैं। जब मिलों के अधिकारी मिल चलाने में समर्थ नहीं हैं, तब यदि मजदूर संस्थायें मिल चलाने का प्रयत्न करें तो उसकी सुविधा उन्हें अवश्य दी जानी चाहिये। इसका एक लाभ जहां यह होगा कि बेकारी नहीं बढ़ेगी, वहां एक लाभ यह भी होगा कि मजदूरों को मिल चलाने का और मिल संचालन की सब कठिनाइयों का अनुभव हो जायेगा। आज वे जो मांगे पेश करते हैं, उन्हें वे व्यावहारिक रूप दे सकेंगे और उद्योग के सामने एक आदर्श उपस्थित कर सकेंगे कि मजदूरों की मांगों को स्वीकार करते हुए भी मिलों को घाटा नहीं हो सकता। यदि इस काल में उन्होंने यह अनुभव किया कि उनकी कुछ मांगें व्यावहारिक नहीं हैं तो वे ऐसी मांगें करना ही छोड़ देंगे। उत्साह के साथ अनुभव और विवेक के कारण मजदूर आन्दोलन देश के लिये ज्यादा उत्तरदायी और ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा।

प्रादेशिक समितियां : नवीन आशा

भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन का जो तूफान खड़ा हुआ था, उसने देश में अराष्ट्रीयता की भावना पैदा कर दी थी। उस तूफान में जो एक आशा की किरण दिखाई दी, वह प्रादेशिक समितियों के संगठन के रूप में थी। तूफान के शांत हो जाने तथा नये पुनर्गठित राज्यों में आम चुनाव हो जाने के बाद अब सरकार ने उन प्रादेशिक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

समितियों के निर्माण की ओर ध्यान दिया है। पिछले दिनों तीन प्रादेशिक समितियों की बैठकें हुईं। एक में पंजाब, दिल्ली, काश्मीर, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश सम्मिलित हैं। दूसरी में मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश सम्मिलित हैं और तीसरी में आसाम बिहार, बंगाल और उड़ीसा-पूर्वी भारत के राज्य सम्मिलित हैं। दक्षिण और पश्चिमी राज्यों की प्रादेशिक समितियां अपना कार्य शीघ्र आरम्भ कर देंगी, ऐसी आशा है। ये समितियां भाषा और राज्य की भौगोलिक सीमा के संकोच को छोड़ कर अधिक व्यापक और उदार दृष्टि से एक बड़े भौगोलिक एकक के हित का विचार करेंगी। और आज सबसे बड़ा हित आर्थिक हित है। उत्तरी क्षेत्र में पानी और बिजली की योजनाएं किसी राज्य तक सीमित नहीं हैं। भाकरा नांगल का पानी पंजाब दिल्ली और राजस्थान तीनों के लिये है और बिजली से दिल्ली और हिमाचल प्रदेश भी लाभ उठाएंगे। इसी तरह बिहार और बंगाल या उड़ीसा के हित आपस में गुथे हुए हैं। विभिन्न सीमावर्ती राज्यों में परस्पर यातायात, व्यापार तथा उद्योग अलग अलग नहीं किये जा सकते। प्रांतीयता की राष्ट्र-घातक भावना को तिलांजलि देकर ही हम एक समर्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। अन्न संकट के वर्षों में प्रत्येक राज्य की जनता और सरकार पड़ोसी राज्यों की कठिनाइयों से नफा कमाने की कोशिश करती रही। यह संकुचित दृष्टिकोण देश को निर्बल बना देता है। हमें आशा करनी चाहिए कि इन प्रादेशिक समितियों में विभिन्न राज्यों के अधिकारी मिल कर अधिक ऊँची दृष्टि से प्रत्येक प्रश्न पर विचार करेंगे।

स्वेज काण्ड और उसके बाद

स्वेज नहर आखिर खुल गई। महीनों के संघर्ष, आक्रमण के कारण भयंकर आर्थिक क्षति तथा यातायात बाधा के कारण करोड़ों रुपये की हानि के बाद मिस्र की जीत रही। और आज ब्रिटेन के जहाजों को भी अपने जहाजो के लिए इच्छा या अनिच्छा से उसी नहर का प्रयोग करना पड़ रहा है। हम इन पंक्तियों में इस विवाद में नहीं जाना चाहते कि इस संकट के लिये कौन उत्तरदायी था। मिस्र तो कुछ वर्षों में ही थोडा सा नहर-शुल्क बढ़ा कर अपनी जति पूर्ति कर लेगा। किन्तु ब्रिटेन को होने वाली क्षति शीघ्र पूरी नहीं हो सकती। बहुत संभव है कि वह स्वेज नहर की बजाय कोई दूसरा मार्ग तलाश करके कालान्तर में मिस्र को हानि पहुँचाने या बदला लेने का यत्न करे, किन्तु इसके लिये समय, श्रम और व्यय की भारी अपेक्षा होगी।

स्वेज नहर के इस काण्ड में मिस्र की सफलता ने अब नई संभावनाये पैदा करदी हैं। विश्व के अन्य भागों में भी स्वेज जैसे अनेक स्थलों पर, जो अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की नहरें या जल प्रणालियां हैं वे भी कठिन समस्यायें उत्पन्न कर सकती हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सरकार अब इस सुझाव पर विचार करने लगी है कि यदि पनामा नहर पर पनामा राज्य ने मिस्र की भांति अधिकार करना चाहा तो अभी से हमें उसका विकल्प सोचना चाहिये। स्पेन भी

राष्ट्रीय आय

१. प्रथम पंचवर्षीय आयोजना के आरम्भ में भारत की राष्ट्रीय आय ९,११० करोड़ रु० थी, जो १९५५-५६ में बढ़कर १०,८०० करोड़ रु० हो गई अर्थात् उसमें १८ प्रतिशत वृद्धि हुई।

२. यदि कीमतें स्थिर रहीं तो द्वितीय आयोजना के अन्त तक राष्ट्रीय आय बढ़कर १३,४८० करोड़ रु० हो जायेगी अर्थात् उसमें २५ प्रतिशत वृद्धि होगी।

३. १९५०-५१ में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय २५४ रु० थी, जो १९५५-५६ में बढ़कर २८१ रु० हो गई और १९६०-६१ में ३३० रु० हो जायेगी।

४. राष्ट्रीय आय में कृषि तथा सहायक धंधों का भाग १९५५-५६ में ४८ प्रतिशत था; १९६०-६१ में वह घट कर ४६ प्रतिशत रह जायगा और खानों तथा कारखानों का हिस्सा ९ प्रतिशत से बढ़कर ११ प्रतिशत हो जायगा।

५. दूसरी आयोजना की अवधि में ६,१०० करोड़ रु० व्यय होगा, जिसके लिए हमें कुछ अधिक बचत करनी होनी। हमें अपनी राष्ट्रीय आय की बचत की दर ७ प्रतिशत से बढ़ाकर १९६०-६१ तक १० प्रतिशत करनी होगी।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जिब्राल्टर पर कभी अधिकार का दावा कर सकता है। इस तरह स्वेज नहर की समस्या अनेक नई समस्याओं को जन्म दे सकती है।

प्रधान अन्तर

पिछले दिनों देश में दो मजदूर दिवस मनाये गये हैं। एक मई का दिवस और दूसरा ३ मई का दिवस। मई दिवस सदा की भांति उत्साह, विराट् जलूस, लाल झन्डों के प्रदर्शन तथा मजदूरों की मांगों एवं नारों के साथ मनाया तया। सभाओं में पूंजीवाद के विनाश के उत्तेजक नारे लगाये गये। सभाओं व प्रदर्शन में भारत की राष्ट्रीयता का प्रदर्शन नहीं हुआ और न मजदूरों का राष्ट्र के प्रति कोई कर्तव्य है, इसकी ओर कुछ संकेत मिला। किन्तु दूसरा मजदूर दिवस राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस की ओर से मनाया गया था। इसी दिन १० वर्ष पूर्व इस कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसमें भी मजदूरों के संगठन तथा अधिकारों की चर्चा हुई। किन्तु इसके साथ साथ मजदूरों को उनके कर्तव्य का निर्देश भी दिया गया। आखिर मजदूर भी मजदूर पीछे हैं, पहले भारतीय हैं और किसी भी नागरिक के समान उनके भी देश के प्रति उत्तरदायित्व हैं, इस चीज को भूल कर जो मजदूर आन्दोलन चलेगा, वह अराष्ट्रीय होगा। अधिकार के साथ साथ कर्तव्य की भावना सन्देश राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस देती है। यही कारण है कि वह जनता की अधिक सहानुभूति प्राप्त कर सकती है। इसीलिए हम उसके ११ वें जन्म दिवस पर उसका अभिनन्दन करते हैं।

अर्थतंत्र का नया मोड़

१९५७ और १९५८ - इन दो वर्षों में केन्द्रीय सरकार पूंजीगत—प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर—दोनों में वृद्धि करेगा। यह अंक प्रकाशित होने के पश्चात् दूसरे सप्ताह के अन्त तक नया बजट प्रकट होगा, जो अगले ५ वर्षों के लिए भारतीय अर्थतंत्र का रूप निर्धारित करेगा। यह कर भार व्यापार, उद्योग और निजी क्षेत्र के पूंजी निर्माण पर कितनी बाधा डालेगा, यह विचारणीय है। प्रश्न यह है कि क्या करों की वृद्धि से सरकार को इतनी आय हो जाएगी कि वह विकास व्यय की आवश्यकताएं पूरी करने में समर्थ हो सके। दूसरी ओर यदि कर-भार में वृद्धि न की जाए, और पूंजी-निर्माण को विस्तार का अवसर दिया जाए, तो क्या यह संभव नहीं कि इतनी बचत सुलभ होगी, जिससे न केवल निजी क्षेत्र, बल्कि सरकारी क्षेत्र की भी आवश्यकता पूरी हो जावे। इस नए बजट के बाद ही सरकार बाजार से करीब पौने दो अरब रुपए का ऋण लेगी। वह तो यह भी सोचती है कि यदि उसे अनुकूल वातावरण दिखायी दे, तो इससे भी अधिक ले। पर अनुकूल वातावरण कैसे पैदा हो? एक ओर रुपया बाजार की तंगी साठ सत्तर करोड़ रुपया लग जाने पर भी बनी हुई है। आज भी बाजार में रुपए की मांग है। बैंकों पर सरकार ने नया प्रतिबंध लगाया है कि वे शेयरों के धंधे में व्यापारियों को रकम एडवांस न करें। परिणाम यह होगा कि शेयरों के भाव गिर जाएंगे और गिरे बाजार में विनियोजकों को नई पूंजी लगाने का कोई प्रोत्साहन न रहेगा। भिन्न-भिन्न व्यापारों में रुपए के अभाव से माल नहीं निकल रहा है। इतने पर भी सरकार नये करों की ओर बढ़ रही है। इन नये करों की ओर सरा ध्यान लगा हुआ है। आय कर में उत्तरोत्तर आमद घटती जा रही है, और यह अधिक कम होगी, यदि उत्पादन कर बढ़ेंगे तथा बैंकों पर बाजार में रुपया लगाने पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। सरकारी क्षेत्र में रेलवे उद्योग में किराए और भाड़े की वृद्धि कर चाहे जितना मुनाफा बताया जाए, किन्तु सरकारी उद्योगों को अधिकाधिक सुविधाएं होने पर भी घाटा हुआ है, जबकि निजी क्षेत्र के उद्योग अनेक असुविधाओं वित्तीय प्रतिबंध और भारी कर भार के बावजूद मुनाफा करते आए हैं। उन्होंने अधिक से अधिक उत्पादन भी कर दिखाया है।

बम्बई में सम्पदा के प्रतिनिधि

श्री टी० एन० वर्मा
c/o उदय ट्रेडर्स
नेशनल हाउस,
Tullock Road, Bombay—1

नागपुर में सम्पदा के प्रतिनिधि

श्री रामकुमार भारतीय
गंजी पेठ
नागपुर—1

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

निजी या सरकारी नहीं, राष्ट्रीय क्षेत्र

श्री घनश्यामदास बिड़ला

"मेरे लिए सरकारी और निजी क्षेत्र जैसी कोई चीज नहीं है। देश की औद्योगिक उन्नति का क्षेत्र केवल राष्ट्रीय क्षेत्र है जिसमें हम सब को काम करना है। मैं तो इन दोनों नामों—सरकारी और निजी—से घृणा करता हूं।"

पुनर्निर्माणका दायित्व

हम सब इस दृष्टि से बहुत भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे उत्साह पूर्ण समय में रहे हैं, जब कि भारत ने अपने नेताओं के प्रयत्नों से स्वाधीनता प्राप्त की है। आज भी हम अत्यन्त उत्साह पूर्ण समय में रह रहे हैं जब कि समस्त देश के पुनर्निर्माण का उत्तरदायित्व हम पर आ गया है। मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि देश का व्यापारिक समाज उठेगा और देश के पुनर्निर्माण में सरकार को सहायता देकर इसे सचमुच स्वर्ग बना देगा। देश के व्यापारिक समाज को कोई निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है। वे कुछ भी कहते रहें, मैं जानता हूं कि उनमें उत्साह और उमंग की कमी नहीं है। वे कभी-कभी सरकारी नीति के विरुद्ध शिकायतें करते हैं। लेकिन यह तो हमारे देश का स्वभाव है कि हम अपनी बात को बहुत बढ़ाकर कहते हैं। मेरा ख्याल यह है कि भारत का व्यापारिक वर्ग उस हिन्दू पत्नी की तरह से है जो अपने पति के विरुद्ध शिकायत करने से थकती नहीं है, लेकिन उससे एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हो सकती। इसी तरह हम सब सरकार की आलोचना करते हैं। बहुत सम्भवतः इसका कारण यह है कि हम आज भी यह अनुभव करते हैं कि हम शासित हैं और दूसरे लोग शासन कर रहे हैं। हमने अतीत में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आन्दोलन किया है। और वह आदत आज भी नहीं छोड़ सके हैं। इसलिए आज व्यापारिक वर्ग को कोई निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि भारत का व्यापारिक वर्ग राष्ट्र के पुनर्निर्माण में सरकार को सहायता देकर अपना पूरा भाग अदा करेगा।

भारत के विचारशील उद्योगपति

श्री घनश्यामदास बिड़ला

'निजी' और 'सरकारी' उद्योग का भ्रम

वह बुरा दिन था जब कि सरकारी और निजी क्षेत्र शब्दों का निर्माण हुआ। इससे पहले भी सरकारी क्षेत्र रेलवे, तार आदि के रूप में विद्यमान था। और निजी क्षेत्र भी विद्यमान था। अमेरिका में आज भी दोनों विद्यमान हैं। लेकिन वहां ये दोनों शब्द प्रयोग नहीं किये जाते। मैं नहीं जानता कि भारत में ये दो नाम क्यों चलाये गये। मेरे लिए निजी और सरकारी नाम से कोई क्षेत्र नहीं है। यह तो राष्ट्रीय क्षेत्र है, जिसमें हम सब ने अपना भाग अदा करना है। व्यापारिक वर्ग में साहस और अध्यावसाय की भावना विद्यमान है। वे काम करते हैं यह उनका स्वभाव है। धनोपार्जन तो स्वयं हो ही जाता है। वे बिना काम के रह ही नहीं सकते। और इसलिए वे राष्ट्र निर्माण का काम जारी रखेंगे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम कठिन समय में से गुजर रहे हैं और सब प्रकार के परीक्षण कर रहे हैं। स्वभावतः हमें परीक्षण करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भूतकालीन अनुभव नहीं है। कभी-कभी हम बुरे परीक्षण भी करते हैं। किन्तु फिर हम अपने कदम वापिस लेते हैं। और फिर हम एक अच्छा परीक्षण करते हैं। इसके सिवाय दूसरा मार्ग भी नहीं है। व्यापारिक वर्ग को धैर्य से सरकारी परीक्षण की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हमें धैर्य पूर्वक यह देखना चाहिए कि देश में क्या हो रहा है, हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं या न। पीछे हटा रहे हैं। मैं व्यापारिक वर्ग से कहना चाहता हूं कि वे निराश न हों। वे निराश होना जानते ही नहीं। यह उनका स्वभाव ही नहीं है। लेकिन कभी-कभी सन्देह होता है कि वे निराश हो रहे हैं।

व्यवसायियों और सरकार में सम्पर्क आवश्यक

एक बड़ी कठिनता यह है कि व्यापारिक वर्ग तो कलकत्ता या बम्बई में रहते हैं और सरकारी शासक या राजनीतिज्ञ दिल्ली में। उनमें परस्पर सम्पर्क नहीं हो पाता। मुझे विश्वास है कि यदि हम मंत्रियों से सम्पर्क रखेंगे और अपनी कठिनाइयों को उनके सामने रखेंगे तो वे उस पर विचार अवश्य करेंगे, क्योंकि हम सबका उद्देश्य एक ही है राष्ट्र की उन्नति करना।

स्वतंत्र साहस या उद्योग की चर्चा समय-समय पर होती रहती है। मैं इसका समर्थन करता रहा हूँ। सरकारी क्षेत्र का आदमी नहीं हूँ किन्तु मैं आज यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब कभी मैं स्वतंत्र उद्योग की बात करता हूँ तब मेरे हृदय में कुछ प्रतिक्रियावादी तत्व उभर आते हैं। जब हमारे वस्त्र व्यवसाय में लाभ कुछ कम होने लगता है या विदेशी प्रतिस्पर्धा से हमें कुछ कठिनता होने लगती है तो हम व्यापार या उद्योग मंत्री के पास जाकर सहायता करने अथवा विदेशी माल पर प्रतिबन्ध लगाने की प्रार्थना करते हैं। जब हमें कुछ रुपये की जरूरत होती है तो हम उद्योग निगम या विश्वबैंक के पास जाकर रुपया मांगते हैं। तब सरकारी गारंटी की जरूरत होती है। यह स्वतंत्र साहस नहीं है। हम स्वतंत्र साहस नहीं चाहते, हम उन्नति चाहते हैं, चाहे इस विधि से चाहे उस विधि से।

सरकार का विशेष क्षेत्र

नई पंचवर्षीय योजना में तीन बड़े बड़े लोहे के कारखानों के लिये ३ अरब रुपया नियत किया गया है। सभी इस बात से सहमत होंगे कि इतनी बड़ी राशि हमारे लिये जुटाना सम्भव नहीं है। यह काम तो सरकार ही कर सकती है। भारी रासायनिक उद्योगों को भी हम प्रारम्भ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें लाभ की कोई गुंजाइश नहीं है। सरकार ने एक भी ऐसी योजना अपने हाथ में नहीं ली है, जिसे हम सफलतापूर्वक कर सकें।

और जब सरकार ६० लाख टन लोहा तैयार करती है तो उसका उपयोग कौन करता है। वस्तुतः मुझे निजी या सरकारी क्षेत्रों के नामों से घृणा है। मुझे इसमें रत्ती भर भी सन्देह नहीं है कि जिसे हम निजी उद्योग कहते हैं, उसे राष्ट्रनिर्माण करना है। प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि निजी उद्योग का देश में सम्मानपूर्ण अधिकार रहेगा।

कोई भय नहीं

परमात्मा के नाम पर मैं व्यापारिक वर्ग से कहना चाहता हूं कि यदि आप ब्रिटिश शासन काल में चमत्कार कर सकते थे तो अब आप इतना भयभीत क्यों होते हैं? आखिर यह तो अपनी सरकार है। हमें यह नहीं भूल जाना चाहिये कि आखिर सरकार वह सब नहीं कर सकती, जो हम सब उससे चाहते हैं। उसको अपने मतदाताओं को संतुष्ट करना है। आखिर लोकतन्त्र में आप वह चीज नहीं पायेंगे जो आप चाहते हैं। लोकतन्त्र की यह विशेषता है कि न इसमें हम बहुत अच्छा कर सकते हैं और न ही बहुत बुरा। इसलिये देश में लोकतन्त्र की प्रगति को हमें देखना चाहिये और सब बातें ठीक हो जायेंगी।❀

❀ बम्बई में दिये गये भाषण के प्रमुख अंश

ऐजेंट चाहिएं

विभिन्न नगरों में सम्पदा की बिक्री और गाहक बनाने के लिए ऐजेंट चाहिए। आकर्षक शर्तों के लिए लिखें—

मैनेजर सम्पदा, रोशनारा रोड, दिल्ली ६।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में—

आर्थिक विकास तथा लघु एवं कुटीर उद्योग (एक संक्षिप्त अध्ययन)

श्री रामनरेशलाल

किसी भी देश के प्राकृतिक एवं भौतिक साधनों को एक आदर्श की प्राप्ति के निमित्त सुन्दर से सुन्दर ढंग से उपयोग में लाने की प्रणाली को उस देश के आर्थिक विकास का नाम दिया जा सकता है।

इस छोटे से लेख में भारत के आर्थिक विकास को तीव्र करने की कला पर एक विचार रखते हुए इस बात को देखने का प्रयत्न किया गया है कि विकास के इस ढांचे में कुटीर एवं लघु उद्योगों का कहां और कितना महत्व है। इस प्रश्न को लेकर आर्थिक जगत में विवाद उठ खड़ा हुआ है।

भारत की आर्थिक व्यवस्था स्पष्टतः एक अर्ध-विकसित (Underdeveloped) अर्थ-व्यवस्था है। एक अर्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्था के विकास की गति मुख्यतः चार बातों पर निर्भर करती है—

(१) जन संख्या की वृद्धि-दर

(२) पूंजी निर्माण की गति

(३) पूंजी-उत्पादन अनुपात

(४) शैल्पिक ज्ञान (Technical know how) का स्तर।

एक अर्ध विकसित अर्थ-व्यवस्था में जन संख्या की वृद्धि के दर में कुछ खास कमी लाना एक लम्बी अवधि में ही सम्भव है। एक आर्थिक योजना काल के पांच वर्षों की अल्प अवधि में इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन लाना लगभग असंभव ही है। इसलिए इस दर को अल्प काल में यदि हम सम (Constant) ही मान लें तो ठीक होगा। दीर्घकाल में इस दर को कम किया जा सकता है।

तब विकास का भार आगे की तीन बातों पर और अधिक पड़ जाता है। जहां तक चौथी बात शैल्पिक ज्ञान का प्रश्न है, यह निर्विवाद सिद्ध है कि विश्व के उत्पादन एवं आय में वृद्धि लाने की दौड़ में अगर पीछे नहीं रह जाना है तो यह नितान्त आवश्यक है कि वह देश नवीनतम अनुसंधानों, खोजों, एवं प्रौद्योगिक एवं शैल्पिक ज्ञानों से भलीभांति परिचित हो और अपने श्रम-शक्ति को इन ज्ञानों से भली भांति परिचित एवं सुसज्जित करता रहे। अल्प अवधि में यह काम भी कठिन है; परन्तु एक दृढ़ इच्छा के साथ निश्चित कदम उठाकर, अनुसंधान-केन्द्रों, शैल्पिक प्रशिक्षण केन्द्रों एवं उचित शिक्षा पद्धति के द्वारा इस दृष्टि से राष्ट्र की कमी को लम्बी अवधि में भली भांति पूरा किया जा सकता है।

परन्तु विकास की सबसे बड़ी और कठिन समस्या एक अर्ध-विकसित देश में पूंजी के निर्माण तथा पूंजी के उत्पादन अनुपात को स्थिर करने की है। इसका कारण यह है कि इस प्रकार की एक पिछड़ी अर्थ-व्यवस्था, क्रमशः गिरते हुए उत्पादन और फलस्वरूप बढ़ती हुई गरीबी के दुःचक्र में इस प्रकार फंसी रहती है कि उसे इस चक्र से निकाल, उसमें पूंजी-निर्माण का साहस भर उत्तरोत्तर बढ़ते उत्पादन एवं उठते हुए जीवन स्तर की ओर मोड़ देना आसान नहीं है। इस मोड़ को लाने एवं विकास के चक्र को तीव्र गति से चलाने के लिए कम से कम समय में अधिक से अधिक पूंजी का निर्माण आवश्यक हो जाता है। क्योंकि अगर पूंजी के निर्माण और फलस्वरूप उत्पादन की मात्रा में वृद्धि मन्द गति से हुई तो आबादी की विभीषिका उसे निरन्तर निगलती जाएगी, और जीवन-स्तर में किसी भी सुधार की आशा नहीं की जा सकेगी। तीव्र गति से पूंजी का निर्माण, (यदि बहुत अधिक विदेशी ऋण पर निर्भर नहीं किया जा सकता) एक ऐसी अनिवार्य कठोर साधना है जिसका व्रत एक अर्ध विकसित राष्ट्र को लेना ही पड़ेगा, यदि उसके नेत्रों में विकास एवं प्रगति के स्वप्न खेलते हैं। इस युग में पूंजी उत्पादन की शक्ति का परिचायक है। जिस देश में पूंजी का आधार जितना ही विशाल एवं सुदृढ़ होगा, उसके उत्पादन का प्रवाह उतना ही अधिक वेगमय होगा, इसमें हो मत की आशंका नहीं है। बढ़ती हुई पूंजी, आय-स्रोत की क्षमता को निरंतर बढ़ाती रहती

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

है और इस प्रकार राष्ट्र के आर्थिक स्तर को अनुकूल परिस्थितियों में निरंतर ऊंचा उठाती चलती है।

फिर पूंजी का निर्माण कैसे हो ? अर्थशास्त्र का एक साधारण विद्यार्थी भी जानता है कि किसी राष्ट्र में पूंजी का निर्माण राष्ट्रीय बचत पर निर्भर करता है। बचत के आधार स्तम्भ दो हैं; बचत की क्षमता और बचत की इच्छा। बचत की क्षमता आय की मात्रा पर निर्भर करती है। आय जितनी ही अधिक होगी, बचत की गुंजाइश भी उतनी ही अधिक होगी। अब अगर यहां हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि राष्ट्र के बचत की इच्छा एवं आय के वितरण का ढांचा अल्पकाल में वही है; उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है तो फिर पूंजी का निर्माण मुख्यतः बचत पर ही अवलंबित है। जो देश अपने निर्माण काल में जितना ही कम उपभोग करेगा और अपनी बचत को पूंजी के निर्माण में लगा सकेगा, उसकी प्रगति का स्थान उतना ही सुरक्षित है। गरीब देश में, जहां अधिकांश लोग अपनी गरीबी से निरंतर संघर्ष करते हुए जी रहे हों, जीवन का निर्वाह भी जहां कठिन हो उनसे पूंजी निर्माण के निमित्त बचत की मांग खलती है, परन्तु आज भारत के राष्ट्रीय विकास की देवी अपने देश के कोटि-कोटि जनता से अपने उपभोग को और भी अधिक घटाने तथा बचत को बढ़ाकर पूंजी निर्माण में लगाने की पूजा मांगती है। गरीबी से कराहते आज के भारत को कल विहंसा सकने की मीठी लालसा को मन में पालते हुए हमें मिलकर इस पूजा, इस कठिन साधना की मांग को पूरा करना ही है। यह तो एक बात हुई जो आसानी से समझी जा सकती है।

एक दूसरी बात भी ध्यान देने की है कि पूंजी निर्माण में उत्तरोत्तर वृद्धि इस बात पर निर्भर करेगी कि बढ़ी पूंजी से एक अवधि में कितने प्रतिशत वृद्धि पुनः और लाई जा सकती है। यह बात एक उदाहरण से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। मान लीजिए कि किसी समय एक देश में पूंजी की मात्रा (कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों में मिलाकर) २००० क रु० के बराबर है। और मान लीजिए कि इस पूंजी से एक वर्ष में शुद्ध आय (Net income) की प्राप्ति २० प्रतिशत है। तो इस प्रकार वर्ष भर में इस पूंजी से वस्तुओं का शुद्ध उत्पादन या दूसरे शब्दों में राष्ट्र की शुद्ध आय २००० क $\times \frac{२०}{१००}$ = ४०० क रुपये के बराबर हुई। अब आगे चलिये। मान लीजिए कि आय और बचत का अनुपात १० : १ है; अर्थात् १०० रुपये की आय पर समाज १० रु० बचा पाता है और ९० रु० उपभोग में लाता है। अगर राष्ट्र की आय ४०० क रुपये के बराबर है तो उस वर्ष राष्ट्रीय बचत ४०० क $\times \frac{१०}{१००}$ = ४० क रुपये के बराबर हुई। एक कदम और आगे चलिए। मान लीजिये कि इस बचत का ८० % पूंजी निर्माण में लगता है। [सभी बचत पूंजी निर्माण में लग भी सकती है और नहीं भी लग सकता है; विशेषतः अर्ध विकसित देश में तो सारी बचत पूंजी निर्माण के निमित्त नहीं पहुँच पाती क्योंकि ऐसे देश में संचय (Hoarding) की प्रवृत्ति बड़ी घातक होती है] तो उपर्युक्त दर से अगर राष्ट्रीय बचत ४० करोड़ रुपए के बराबर है तो पूंजी निर्माण में ४०क $\times \frac{८०}{१००}$ = ३२क रुपये लगे। अब हम यह आसानी से समझ सकते हैं कि अगले वर्ष के लिए राष्ट्रकी पूंजी २०३२ क रुपए के बराबर की हुई। उपभोग की मात्रा में अगर वृद्धि न हो और अन्य सभी प्रवृत्तियां समान हों, तो इसी प्रकार पूंजी देश की बढ़ती जाएगी। तथा उत्पादन की मात्रा को बढ़ाकर एवं उपभोग को कम करके पूंजी निर्माण की गति को बढ़ाया भी जा सकता है। इस उदाहरण से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पूंजी के निर्माण की दर, यदि अन्य बातें समान हों तो निम्न लिखित तीन अनुपातों पर निर्भर है :

(१) पूंजी—उत्पादन का अनुपात

(२) आय (उत्पादन)—बचत का अनुपात

(३) बचत—विनियोग (पूंजी निर्माण) का अनुपात

इन अनुपातों को हैरड-डोमर (Harrod Domar) फारमूले को निम्नलिखित सरलतम रूप से भी समझा जा सकता है—

जब कि वृ का अर्थ है वृद्धि

$$\text{वृ} = \frac{\text{ब.स}}{\text{उ}} \times \frac{\text{उ}}{\text{प}}$$

: व स ,, ,, ,, स अवधि में बचत

: अ स ,, ,, ,, स ,, राष्ट्रीय आय

$\frac{\text{उ}}{\text{प}}$,, ,, ,, $\frac{\text{उत्पादन अर्थात्-}}{\text{पूंजी पूंजी जनित}}$ उत्पादन का अनुपात

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अब मान लीजिए कि एक अवधि में आप चाहते हैं कि आपकी अर्थ-व्यवस्था की आय में ४ प्रतिशत वृद्धि हो जाय और मान लीजिए कि पूंजी और उत्पादन का अनुपात ४:१ है तो उपर्युक्त फारमूले से हम निकाल सकते हैं कि इसके लिए राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत बचाकर पूंजी निर्माण में लगाना होगा। फारमूले के अनुसार :

$$\text{वृ} = \frac{\text{व स}}{\text{आ स}} \times \frac{\text{उ}}{\text{प}} \text{ अथवा } \frac{४}{१००} = \frac{\text{व स}}{\text{आ स}} \times \frac{१}{४}$$

आसानी के लिए $\frac{\text{व स}}{\text{आ स}}$ को यदि हम द मान लें, तो हम लिख सकते हैं कि—

$$\frac{४}{१००} = \text{द} \times \frac{१}{४} \text{ या } \frac{४}{१००} = \frac{\text{द}}{४}$$

$$\therefore १०० \text{ द} = १६$$

$$\therefore \text{ द} = \frac{१६}{१००}$$

$$\text{या दूसरे शब्दों में } \frac{\text{व स}}{\text{आ स}} = \frac{१६}{१००}$$

अर्थात् राष्ट्रीय आय का १६ प्रतिशत बचाकर पूंजी निर्माण के लिए लगाना होगा। उपर्युक्त मान्यताओं के अनुसार अगर किसी राष्ट्र की आय में ४ प्रतिशत वृद्धि करनी है, तो उसके लिये और सभी प्रवृत्तियों के समान रहने पर राष्ट्रीय आय का १६ प्रतिशत बचत करना अनिवार्य हो जाएगा।

उपर्युक्त अध्ययन में ध्यान दीजिए, एक बात बड़े मार्के की है। हमने पूंजी और उत्पादन का अनुपात ऊपर ४:१ का लिया है। अगर अनुपात २:१ हो जाय, यानी पूंजीजनित उत्पादन की मात्रा यदि दूनी हो जाती तो आप हिसाब लगाकर उसी प्रकार देखेंगे कि आय में ४ प्रतिशत वृद्धि लाने के लिए १६ की जगह ८ प्रतिशत बचत से ही काम चल जाएगा। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि पूंजी उत्पादन का अनुपात यदि ४ : १ के स्थान पर २ : १ हो जाय, तो हम अपने उसी बचत और पूंजी निर्माण दर से राष्ट्रीय आय को दूना कर सकते हैं। पूंजी-उत्पादन का दर जितना ही कम होता जाएगा, एक अवधि में राष्ट्रीय आय में उतनी ही अधिक वृद्धि होगी और पूंजी निर्माण के कार्य में भी फलस्वरूप तेजी आयेगी और फिर उत्तरोत्तर अधिक उत्पादन, बचत एवं पूंजी निर्माण का चक्र तेजी से चलता चला जाएगा।

लघु उद्योगों की विशेषता

अल्पकाल में वृहत् उद्योगों की अपेक्षा कुटीर उद्योगों में लगाई जाने वाली पूंजी का पूंजी-उत्पादक अनुपात बहुत कम होता है। वृहत् उद्योगों का, और विशेषकर आधारभूत या मूल उद्योगों का—जो सीधे उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन न कर, उपभोग की वस्तुओं को उत्पादित करने वाली मशीनों का उत्पादन करते हैं—अल्पकाल में उनका पूंजी उत्पादक अनुपात बहुत अधिक होता है; क्योंकि ऐसे उद्योगों में लगी पूंजी का फल शीघ्र अल्पकाल में पूरा नहीं मिल पाता। लम्बी अवधि में, इनके निर्माण के फलस्वरूप उत्पादन की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है और उत्तरोत्तर पूंजी-उत्पादन अनुपात कम होता जाता है, और जब ये अपने सामर्थ्य भर पूर्ण-रूपेण उपभोग के सामानों का उत्पादन करने का अवसर एक लम्बी अवधि के बाद पाते हैं तो इनके पूंजी-उत्पादन का अनुपात बहुत ही कम हो जाता है। अल्पकाल में कुटीर एवं लघु उद्योगों द्वारा थोड़ी पूंजी के बल पर, अधिक से अधिक श्रम का उपयोग करके, वृहत् उद्योगों की अपेक्षा बहुत शीघ्र एवं अधिक मात्रा में उपभोग के सामानों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, यह बात बिलकुल स्पष्ट है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बहुत अधिक ध्यान आधारभूत एवं मूल (Basic and key) उद्योगों को स्थापित करने की ओर दिया गया है; और लोक अंचल में लगभग २००० करोड़ रुपये के खर्च की व्यवस्था इन पर है। इनमें लोहे, इस्पात, भारी मशीनों, इमारतों, रासायनिक खादों के, तथा बिजली, रेलवे आदि आदि उद्योग आ जाते हैं। इनके द्वारा हम भविष्य में तीव्र औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिए एक विशाल ठोस आधार इस अवधि में बना सकेंगे। ये नितान्त आवश्यक हैं, क्योंकि इसके लिये विदेशों के ऊपर आश्रित रहने के लिए हम अपनी औद्योगिक प्रगति के स्वप्निल महल की नींव इस प्रकार बिछाने में जुटे हैं। परन्तु साथ-साथ यह भी हमें मालूम है कि उपर्युक्त विवेचन के अनुसार अल्पकाल में इस विनियोग से राष्ट्रीय उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन को यथा उचित बढ़ाया नहीं जा सकता। इनका फल हमें

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लम्बी अवधि में मिलेगा। परन्तु इस अवधि में उपभोग की वस्तुओं की मांग तो बहुत अधिक बढ़ जाएगी। इसके अनेक कारण हैं; प्रथम तो बढ़ती आबादी है; दूसरे उपर्युक्त उद्योगों, (आधार भूत एवं मूल) अनेक निर्माणकारी कामों, (जैसे, सामुदायिक विकास योजना एवं विस्तार सेवाओं) जन-कल्याण के कामों आदि के प्रसार से अनेक बेकार लोगों को रोजगार मिलेगा जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और बेकारी की अवस्था में आय के न होने से जिन जिन उपभोग की वस्तुओं का उपभोग वे मजबूरन नहीं कर पाते थे, उनकी मांग करने लगेंगे; तीसरे सामाजिक न्याय की दृष्टि से निरंतर होते हुए राष्ट्रीय आय के समान वितरण से असंख्य गरीबों की आय में वृद्धि होगी और उनके द्वारा उपभोग की वस्तुओं की मांग अवश्य बढ़ेगी आदि।

एक मात्र उपाय

इस प्रकार हम देखते हैं कि अल्पकाल में उपभोग की वस्तुओं की मांग तो बहुत अधिक बढ़ रही है, परन्तु इस अनुपात में हम वृहत् और आधारभूत एवं मूल उद्योगों की स्थापना में लगे रहने से (जिनका होना नितान्त आवश्यक है) उनकी पूर्ति को बढ़ा नहीं सकेंगे। तब अल्पकाल में कम से कम लागत पर अधिक से अधिक मात्रा में, जल्दी से जल्दी उपभोग की वस्तुओं को बढ़ाने का एक मात्र उपाय (यदि हम आयात पर निर्भर नहीं होना चाहते) कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास ही रह जाता है. जिसके पूंजी-उत्पादन का अनुपात कम भी है और साथ ही शीघ्र उत्पादन भी मिल सकेगा। इन कुटीर एवं लघु उद्योगों का महत्व इसलिये भी और अधिक हो जाता है क्यों कि हमारे देश के श्रमिकों में प्राद्योगिक एवं शैल्पिक ज्ञान की बहुत बड़ी कमी है और इस ज्ञान से इन्हें परिचित कराने में समय लगेगा। कुटीर उद्योगों की प्रणाली से अभिज्ञ कराने के लिए किसी विशेष प्रशिक्षण एवं ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। यही नहीं, अगर राष्ट्रीय उत्पादन या आय को इस अवधि में बढ़ाया नहीं जाता तो फिर हमारी बचत और परिणामस्वरूप पूंजी निर्माण पर बड़ाघातक प्रभाव पड़ेगा और हमारे विकास के चरण पंगु हो जायेंगे।

इनके साथ साथ कुटीर उद्योग के पक्ष में अन्य भी बहुत सी बातें याद आ जाती हैं, जिनका उल्लेख यहां करना उचित है। इनके द्वारा हम बेरोजगारी की भयानक समस्या का शीघ्र हल ढूंढ़ लेते हैं। इनके पनपने से उद्योगों का स्वतः विकेन्द्रीकरण (Decentralization) हो जाता है, जो सम सामाजिक विकास एवं राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्व रखता है; आय का असमान वितरण इससे स्वतः अपने आप कम होता जाता है। इनके द्वारा व्यक्तित्व का स्वस्थ विकास सम्भव है आदि आदि। शायद इन्हीं सब कारणों से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग ने कुटीर एवं लघु उद्योगों पर बहुत अधिक ध्यान दिया है। जब कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लोक अंचल के दायरे में लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए केवल २७ करोड़ रुपये की व्यवस्था थी; द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लोक आंचल के क्षेत्र में इन उद्योगों के लिये २०० करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

लम्बी अवधि के बाद ?

परन्तु एक लम्बी अवधि में आधारभूत और मूल उद्योगों के पूर्ण विकसित होने पर, जब कि उपभोग की वस्तुओं को उत्पादित करने वाली मशीनों एवं साधनों का उत्पादन तेजी से होने लगेगा और इनके द्वारा विस्तृत रूप में उपभोग सम्बन्धी उद्योगों की स्थापना की सुविधा मिलेगी; पूर्ण रोजगार देने की क्षमता इनमें आजाएगी और पूंजी-उत्पादन का अनुपात घटकर लघु एवं कुटीर उद्योगों की अपेक्षा भी कम होने लगेगा, तो इस दशा में राष्ट्रीय उत्पादन एवं पूंजी निर्माण के क्रम को अधिकाधिक शीघ्र से शीघ्र बढ़ाने एवं जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने आदि की दृष्टि से इन लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ाना या इस स्तर पर कायम रखना कहां तक उचित होगा—कम से कम आर्थिक दृष्टि से यह एक संदेहात्मक और विचारणीय बात हो जाती है। केवल आर्थिक दृष्टिकोण को सामने रखने पर लम्बी अवधि में कुटीर उद्योगों के लिये सुरक्षित जगह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मिल सकेगी, इसमें संदेह है और अगर इनके लिए जगह सुरक्षित रक्खी जाती है, तो इससे आर्थिक जीवन और शैल्पिक ज्ञान पर कुछ न कुछ चोट तो पहुँचेगी ही। पर आर्थिक अंग जीवन का एक अंग है। गांधीवादी आदर्शों एवं वांछित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक आदर्शों एवं

(शेष पृष्ट २८२ पर)

[सम्पादक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अर्थशास्त्र का आशावाद और निराशावाद

प्रो० विश्वम्भरनाथ पाण्डेय

मानव विचार और चिन्तन धारा के दो ही सम्भव पक्ष हो सकते हैं। एक तो वह जिसमें सुन्दर और शिवं संकेतों का दर्शन होता है तथा दूसरा वह जिसमें सब कुछ अशुभ एवं अन्धकारमय देखा जाता है। प्रथम पक्ष को हम मानव विचार के 'आशावाद' तथा द्वितीय पक्ष को 'निराशावाद' से अभिहित करते हैं। इस प्रकार 'आशावाद' हमारे सामाजिक वातावरण की तात्विक भव्यता तथा उस सिद्धान्त का प्रतीक है जिसके अनुसार माना जाता है कि संसार की वस्तुएं मानवीय हस्तक्षेप के बिना भी सुन्दर और शुभ स्वरूप ग्रहण कर लेंगी। इसके विपरीत 'निराशावाद' विवेकपूर्ण मानवीय प्रयत्नों के अभाव में सामाजिक वातावरण की अनुकूलता तथा उसकी स्वतः अपेक्षित रूप ग्रहण कर लेने की क्षमता को अस्वीकार करता है।

राजनीति और अर्थशास्त्र के विभिन्न युगीय सिद्धान्तों में मानव विचार एवं चिन्तन के इन दो पक्षों का विकास शायद समाजशास्त्र की अन्य सभी शाखाओं की अपेक्षा अधिक हुआ है। राजनीतिक विचारधारा की आशावादिता ने बेन्थम तथा प्रिंस क्रोपोटकिन के 'अराजकतावाद'(Anarchism) को जन्म दिया, जिसके अनुसार राज्य को मात्र एक 'आवश्यक बुराई' माना गया तथा निराशावादिता ने प्रोदों, राबर्ट ओवेन और कार्ल मार्क्स के 'समाजवाद' का विकास किया, जिसके अनुसार 'राज्य' की अनिवार्यता और सक्रियता को प्रतिष्ठा मिली।

आशावादी अर्थशास्त्री

'राज्य अर्थशास्त्र' (Political Economy) जिसके स्थान पर आजकल अर्थशास्त्र शब्द का व्यवहार होता है—१७वीं शताब्दी के एक 'अन्टवाइन दी मान्चरेशियन' नामक व्यक्ति की रचना है। प्लेटो और अरस्तू की पुस्तकों में भी हम आधुनिक अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों का बीज खोज सकते हैं; किन्तु व्यापक रूप से अर्थशास्त्र को शास्त्रीय रूप देने का प्रयत्न १८वीं शताब्दी के मध्य में, फ्रान्स के कतिपय राजनीतिज्ञों तथा दार्शनिकों द्वारा हुआ जिसका समवेत नाम 'फिजिओक्रैट' (Physiocrats) है। इनकी विचारधारा अर्थशास्त्र में 'फिजिओक्रेसी' के नाम से प्रसिद्ध है। 'राज्य अर्थशास्त्र' के आदि स्थापक ये 'फिजिओक्रेटिक' अर्थशास्त्री, जिनके नेता श्री क्वीस्ने थे, अटूट आशावादी थे। वे मानव समाज की एक ऐसी 'प्राकृतिक व्यवस्था' में विश्वास करते थे जो सर्वशक्तिमान थी और जो राज्य के कृत्रिम विधि विधानों से परिवर्तित वा तोड़ी नहीं जा सकती थी। उनके मत के अनुसार यह 'प्राकृतिक व्यवस्था' मानव जाति के सुख के लिए स्वयं ईश्वर ने स्थापित की थी। मर्सियर के शब्दों में 'प्राकृतिक व्यवस्था' के नियमों के मूल मानव जाति की आत्मा और प्राण में गड़े हैं—इसीलिए ये अपरिवर्तनीय हैं। ये स्वयं ईश्वर की महत् इच्छा के प्रकटीकरण हैं। 'हमारी सभी मनोकामनाएं और अभिलाषाएं मानव-जाति के मेल और व्यापक सुख पर केन्द्रित है, जिन्हें हमें एक 'परम दयालु नियति की कृपा का फल मानना चाहिए, जो सदा यह चाहती है कि इस पृथ्वी पर सर्व सुखी प्राणी बसें।' इस प्रकार ये फ्रांसीसी अर्थशास्त्री 'प्राकृतिक-व्यवस्था' (Natural order) को एक नैसर्गिक (Super natural) व्यवस्था मानने के कारण इसकी विश्व व्यापकता तथा शाश्वतता में अडिग विश्वास रखते थे। यह व्यवस्था सब के लिए तथा सब समय के लिये एक थी। उनके अनुसार यह व्यवस्था उत्पत्ति से दैविक होने के कारण प्रयोग में विश्वव्यापक थी। 'फिजिओक्रेटिक' पीठ की त्रिमूर्तियों में एक श्री तूर्गो ने इस प्राकृतिक व्यवस्था की सार्वभौमता पर कहा था कि ऊपर से भिन्न दिखने वाले राज्यों के मूलभूत सादृश्य को न स्वीकार करने वाला व्यक्ति कभी 'राज्य अर्थशास्त्र' के प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे सकता'। इसी प्रकार उसकी शाश्वतता की ओर संकेत करते हुए उसने कहा कि मानव समाज के नियम इतिहास से नहीं उत्पन्न होते, अपरंच वे मानव स्वभाव और प्रकृति से उत्पन्न होते हैं—जो मूलतः अपरिवर्तनीय हैं।

सरकारी हस्तक्षेप नहीं

इसी प्रकार फिजिओक्रैटों ने मानव समाज के एक ऐसे सुखमय रूप की कल्पना की, जो शाश्वत, सनातन, सर्वयुगीन और सर्वव्यापक था। इसका तर्क-सम्मत परि-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

णाम यह हुआ कि आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने राज्य के हस्त-क्षेप तथा आर्थिक विधानों की आवश्यकता को बिल्कुल नहीं माना और व्यापार तथा आर्थिक जगत के सभी क्षेत्रों में कृत्रिम बन्धनों को उठाने की मांग की। दूसरे शब्दों में उन्होंने अर्थतंत्र के प्रत्येक क्षेत्र में 'स्वच्छन्दतावाद' (Laissezfaire) का समर्थन किया। किन्तु उनके इस आर्थिक स्वच्छन्दतावाद को राजनीति-शास्त्र के 'अराजकता' का पर्याय नहीं मानना चाहिए; क्योंकि उन्होंने केवल राज्य के रचनात्मक विधि विधानों को अस्वीकार किया था, इसके अस्तित्व अथवा इसकी अपेक्षा को नहीं। राज्य के रक्षात्मक अस्तित्व को उन्होने स्वीकार किया तथा कहा कि राज्य तथा ऐसे ही बहिर्गत संघों की इसलिए आवश्यकता है कि वे देखें कि प्राकृतिक नियमों को कोई भंग नहीं करे। इस रक्षात्मक कार्य को छोड़ कर राज्य का कोई रचनात्मक स्वरूप नहीं हो सकता क्योंकि प्रकृति को छोड़कर नियमों की रचना करने की यथार्थ प्रतिभा न तो किसी व्यक्ति में है न किसी सरकार में। इसीलिये बोदी ने एक बार कहा था कि सबसे उत्तम कार्य जो एक विधान सभा कर सकती है, वह यह है कि वह सभी प्रकार के मानव कृत कृत्रिम नियमों को भंग कर दे। साम्राज्ञी कैथेराइन ने एक बार अपने देश के नये संविधान के निर्माण के अवसर पर जब प्रसिद्ध 'फिजिओक्रैट' मर्सियर को बुलाकर पूछा तो उसने परामर्श दिया कि 'किसी भी प्रकार का विधान न बनाना ही सर्वोत्तम विधान होगा।' कहते हैं साम्राज्ञी ने इस पर मर्सियर को अविलम्ब नमस्कार निवेदन करते हुए विदाई दे दी।

आदमस्मिथ का आविर्भाव

इसके बाद जैसा कि श्री एलफ्रेड मार्शल ने कहा है—अर्थशास्त्र का सैद्धान्तिक विकास अर्थशास्त्रियों के किसी एक वर्ग के द्वारा नहीं हुआ अपितु आदमस्मिथ (१७२३ से १७९० ई०) नामक एक व्यक्ति के द्वारा अकेले ही हुआ। आदमस्मिथ ने अपने पूर्व के फ्रांसीसी और अंग्रेजी दोनों ही अर्थशास्त्रियों की विचार-धारा से बहुत कुछ लिया फिर भी उनके "विचारों का विस्तार इतना अधिक था कि उनमें तत्कालीन सभी अर्थशास्त्रियों के विचार समा गये थे और जितना ही अधिक हम आदम-स्मिथ के साथ उनके पूर्व और पश्चात् के अर्थशास्त्रियों की तुलना करते हैं, उतना ही अधिक हमें उनकी प्रखरतर प्रतिभा, बृहत्तर ज्ञान और श्रेष्ठतर संतुलित चिन्तन धारा का स्पष्टीकरण हो जाता है।"। आदम स्मिथ ने विभिन्न अर्थशास्त्रियों के बिखरे और पृथक-पृथक विचार-कणों को समन्वित करके एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की और उन्हें क्रमबद्ध एवं मौलिक ढंग से उपस्थित किया। आदम स्मिथ इसी अर्थ में वर्तमान अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं और अर्थशास्त्र की पहली महत्वपूर्ण शास्त्रीय पुस्तक उनकी 'वैल्थ आफ नेशन्स' या 'राष्ट्रों की सम्पदा' मानी जाती है, अन्यथा उनसे पूर्व सर विलियम पेट्टी, लाक, सर डी० नार्थ, और रिचर्ड कैन्टिलान आदि अर्थशास्त्री इंगलैंड में ही हो चुके थे।

अदृश्य सत्ता में विश्वास

फिजिओक्रैटों की भांति आदम स्मिथ भी एक प्रकार की 'प्राकृतिक व्यवस्था' में विश्वास करते थे। उन्होंने एक ऐसी 'अदृष्ट सत्ता' (invisible hand) की कल्पना की थी जो प्रत्येक युग के प्रत्येक आर्थिक तथा राजनीतिक समाज का निर्माण करती है। उनके अनुसार आत्म प्रेम, सहानुभूति, स्वतंत्र रहने की इच्छा, आत्मगुणपरिज्ञान, परिश्रम रुचि तथा विनिमय प्रियता—ये छः मानव आचरणों की आधार भूत 'प्रेरक शक्तियां' हैं। आचरणों की इन प्राकृतिक प्रेरणाओं से संबलित होकर मनुष्य स्वयं ही अपने कार्यों का सर्वश्रेष्ठ निर्णायक है और इसलिए उसे स्वतंत्र छोड़ देने में ही उसका तथा समाज का हित है। आदम स्मिथ के अनुसार मानव समाज की रचना करने वाली 'नियति' (Providence) ने मानवीय आचरणों की प्रेरणाओं को बृहत्तर समाज के हित के साथ कुछ इस प्रकार संतुलित और अविरोधी बना रखा है कि अपने हित की दृष्टि से किये गये कार्य समाज के अन्य व्यक्तियों के हित के भी सहायक हो जाते हैं। व्यवसाय, वस्तुओं का विक्रय तथा उत्पादन अपने हित के लिए करते हैं, पर उनके हित के साथ समाज के उपभोक्ताओं का हित भी साथ-साथ हो जाता है। प्रतिस्पर्द्धा से प्रेरित होकर उत्पादक अपनी वस्तुओं का विक्रय बढ़ाने के लिए चीजें सस्ती और अच्छी बनाते हैं, पर उनके

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इस स्वार्थ कार्य से कौन कह सकता है कि समाज का भी स्वार्थ नहीं सध जाता ? अस्तु, आदम स्मिथ ने कहा कि स्वाभाविक प्रवृत्तियोंके कारण व्यष्टि और समष्टि के हित परस्पर अविरोधी ही नहीं, अपितु एक दूसरे के पूरक तथ स्थापक भी हैं। और उनकी इस उक्ति में तर्क था। मानव आचरणों की इस सहज हितकारिणी प्राकृतिक विशेषता के आधार पर आदमस्मिथ ने अपने प्रसिद्ध अदृष्ट सत्ता के सिद्धान्त की रचना की थी तथा कहा था कि यह 'अदृष्ट सत्ता' ही हम से ऐसे समान हित के कार्य करा डालती है, जो किसी प्रकार हमारी इच्छा के अंश नहीं कहे जा सकते।' अतः यदि मनुष्य अपने हित की दृष्टि से भी काम करे, तो भी समाज का हित होता ही जायेगा।

इस प्रकार आदमस्मिथ की 'अदृष्ट सत्ता' फिजिओक्रैट्स की 'प्राकृतिक व्यवस्था' की बहुत कुछ प्रतिलिपि थी। ऐसी आशावादी अदृष्ट सत्ता में विश्वास का परिणाम यह हुआ कि आदमस्मिथ ने भी सरकार के नकारात्मक रूप (Negative role) को ही अधिक महत्व दिया। उसने उसके आर्थिक हस्तक्षेपों का विरोध किया और सरकार के केवल तीन कार्य स्वीकार किये :—(१) बहिर्गत आक्रमणों से देश की सुरक्षा (२) देश के अन्तर्गत न्याय की प्रतिष्ठा और (३) जनहित के उन कार्यों को करना, जिनका व्यक्तिगत न होने के कारण व्यक्तियों द्वारा किया जाना सम्भव नहीं है, जैसे सड़कों और पार्कों का निर्माण।

आर्थिक अंचल में अपनी 'अदृष्ट सत्ता' के सिद्धान्त का प्रयोग कर आदमस्मिथ ने पूर्वगामी फिजिओक्रैटों से भी अधिक तीव्रता के साथ 'आर्थिक स्वच्छतावाद' का समर्थन किया। फिजिओक्रैटों और आदमस्मिथ के काल के बीचमें इंगलैंड में एक वाणिज्यवादियों (Mercantilists) तथा धनवादियों (Bullionist) का निराशावादी वर्ग तैयार हो गया था, जिसने फिजिओक्रैटों की प्राकृतिक व्यवस्था की स्वस्थता में अविश्वास करते हुए सरकार के क्रियात्मक रूप पर जोर दिया था तथा विदेशी व्यापार को बढाने के लिए राज्य से हर सम्भव प्रयत्न करने की सिफारिश की थी। आदमस्मिथ ने वाणिज्यवादियों के मत का विरोध किया और सरकारी विदेशी व्यापार नीति के साथ औद्योगिक नियमों (Industrial Regulations) सरकारी सहायताओं, व्यापारिक प्रतिबन्धों व संधियों तथा अन्य सभी प्रकार की विभेदात्मक सरकारी नीतियों की भर्त्सना, की क्यों कि वह अपनी 'अदृष्ट सत्ता' की कल्याणात्मक क्षमता में विश्वास रखता था तथा सोचता था कि समाज के हर युग में सर्वाधिक जनता का सर्वाधिक कल्याण करने के लिए 'नियति' का यह अगोचर उपकारी हाथ ही सक्षम है। समाज की रूपरेखा को मानव क्रियाओं की अप्राकृतिक 'टोक टाक' की कोई आवश्यकता नहीं; वह स्वयं ही अपना सर्वोत्तम और सर्व सुन्दर रूप ग्रहण कर लेगी।

ऐतिहासिक दृष्टि से यह स्मरणीय है कि इसी समय राजनीति शास्त्र में श्री बेन्थम अपने 'सुख-दुख' के सूत्र के आधार पर सर्वाधिक जनता का सर्वाधिक कल्याण का सिद्धान्त विकसित कर रहे थे। उनके अनुसार मानवीय क्रियाएं सुख और दुख की भावना से संचालित होती हैं। मनुष्य जिस कार्य से सुख की आशा रखता है, उसे करता है, किन्तु जिससे उसे कष्ट वा दुख की आशंका रहती है, उसे नहीं करता। यह मनुष्य का स्वभाव है। अतः यदि सभी मनुष्यों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाय तो वे केवल वे ही कार्य करेंगे, जिनसे उनका 'हित' और सुख सम्पादित होने वाला है। सुतरां, यदि किसी भी समय किसी भी समाज के सभी मनुष्यों के कार्यों का योग किया जाय, तो हम पायेंगे समाज को अधिकतम सम्भव संख्या का अधिकतम सम्भव हित कार्य (Greatest good of the greatest numbar) स्वयं ही हो चुका है। तब फिर राज्य की आवश्यकता ही कहां रह जाती है ? और यह कुछ कम आश्चर्य की बात नहीं है कि १७७६ ई० में आदमस्मिथ की 'वेल्थ आफ नेशन्स' तथा श्री बेन्थम की 'फ्रैगमेन्ट आव गवर्नमेंट' नामक पुस्तकें साथ साथ प्रकाशित हुईं।

आदमस्मिथ के बाद अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों का आशावादी धारा का प्रवाह हमें १९ वी शताब्दी के फ्रांस के 'उदारवादी' अर्थशास्त्रियों (French Liberal School) की ओर ले जाता है, जो अपने ही देश के प्राचीन फिजिओक्रैटों की तरह अत्यन्त आशावादी थे।

किंतु आदमस्मिथ और फ्रांस के इन उदारवादी अर्थशास्त्रियों के मध्यान्तर में अर्थ-शास्त्र का इतिहास

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आज की नई समस्या

अनिवार्य जमा : अर्थव्यवस्था पर अनिवार्य बोझ

आजकल औद्योगिक कम्पनियों की अनिवार्य जमा की योजना चर्चा का विषय बनी हुई है। दिसम्बर १९५६ में सरकार ने "वित्त अधिनियम सं० ३" पास किया था। इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक कम्पनी को अपने चालू लाभ का कुछ प्रति शत केन्द्रीय सरकार के पास जमा करना होगा। कम्पनियों को एकत्र घिसाई खाते और दूसरी सुरक्षित निधियों का २५ प्रति शत और वार्षिक लाभ का ७५ प्रति शत घिसाई खाते की रकम अलग करने से पहले, लेकिन कर और लाभांश को रख लेने पर—सरकार को सौंप देना होगा। कम्पनियां कानूनी तौर से १ लाख रु० की अतिरिक्त पूंजी अपने पास रख सकती हैं। इससे अधिक पूंजी जमा हो जाने पर कम्पनियों को इसका कितना भाग जमा कराना जरूरी है, यह केन्द्रीय सरकार ने निश्चित कर दिया है। कम्पनियों को पहली अप्रैल १९५७ से आरम्भ होने वाले वर्ष का आयकर तय करने में इस तरह की जमा करायी पूंजी का हिसाब लगाना होता है।

इस योजना का व्यवसायी वर्ग से सम्बन्ध है। देश की सभी औद्योगिक कम्पनियां तथा विदेशी कम्पनियां जो भारत में कार्य कर रही हैं, इससे प्रभावित होती हैं। केवल नीचे लिखी कम्पनियों के लिए पूंजी जमा कराना जरूरी नहीं है:—

(१) ऐसी कम्पनी जिसके ४० प्र० श० हिस्से केन्द्रीय सरकार या एक राज्य सरकार अथवा कई राज्य सरकारों या केन्द्र और राज्य या कई राज्यों की सरकारों के पास हैं;

(२) ऐसी कम्पनी को जो संसद के किसी अधिनियम के अधीन बनायी गयी है;

(३) ऐसी कम्पनी जो १९३८ (१९३८ का चौथा) के बीमा अधिनियम के अधीन बीमे के काम के लिए खड़ी की गई है;

बाकी सब कम्पनियों को उक्त अतिरिक्त धन का ५० प्र० श० जमा कराना जरूरी है।

औद्योगिक क्षेत्रों में इसकी प्रतिक्रिया अच्छी नहीं हुई। इस योजना को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है तथा इसको उद्योगों की प्रगति में बाधक माना जा रहा है। स्वयं योजना इतनी अस्पष्ट है कि अच्छे-अच्छे आर्थिक विशेषज्ञ भी कम्पनियों की इस अनिवार्य जमा की प्रक्रिया के सम्बन्ध में एकमत नहीं हैं।

एक अप्रैल १९५७ से यह एक्ट लागू हो गया। अप्रैल के दूसरे सप्ताह सरकार ने इनके नियम (प्रारूप) भी प्रकाशित कर दिये, यद्यपि ये नियम अंतिम नहीं। लोगों की राय जान लेने पर अन्तिम संशोधन करने के बाद इनको अंतिम रूप दिया जायेगा। वैसे ये नियम अपने आप में पूर्ण ज्ञात नहीं होते। इन नियमों में यह तो बताया गया है कि कम्पनियों को अपने चालू में से कितना जमा करना होगा, लेकिन उनकी जमा सुरक्षित निधि के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है। वास्तव में यह सुरक्षित निधि वाला अंश बड़ा विवादास्पद और मत वैभिन्नय का विषय है। मुख्य बात यह है कि सुरक्षित निधि का हिसाब करते हुए क्या इसमें कम्पनियों की परिदत्त पूंजी को छोड़ देना चाहिए या उसको स्थिर पूंजी से सम्बन्धित मानना चाहिए, यह स्पष्ट नहीं हुआ है। यहां तक कि चालू लाभ के जमा करने से सम्बन्धित नियम भी पूर्ण स्पष्ट नहीं हैं।

इस सम्बन्ध में विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि 'अनिवार्य जमा योजना' का औद्योगिक कम्पनियों पर कितना दबाव पड़ेगा, यह देखने के लिए एक शोधकार्य किया गया, जो काफी श्रम साध्य और भारत में अपने ढंग का पहला है। इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन के मुख पत्र 'इकनौमिक ट्रेंड्स' में इसका विवरण प्रकाशित हुआ, जो मूल विषय की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण है। अध्ययन के

इङ्गलैंड और फ्रांस के कुछ ऐसे लेखकों से प्रभावित हुआ जिन्हें हम 'निराशावादी' ही कहेंगे। इनमें डेविड रिकार्डो तथा राबर्ट माल्थस जैसे सैद्धांतिक तथा राबर्ट ओवेन और सिसमण्डी जैसे आदि समाजवादी अर्थशास्त्री प्रसिद्ध हैं।

(आगामी अंक में समाप्त)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लिए ५ उद्योगों से सम्बन्धित ४१० कम्पनियों को लिया गया। ये ५ उद्योग लोहा और इस्पात, सीमेंट, कागज, चीनी तथा सूती वस्त्र के हैं और अपने क्षेत्र से सम्बन्धित ७५ से १०० प्रतिशत कारखानोंका प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी कुल परिदत्त पूंजी १७५ करोड़ रु० है। उनका 'ग्रौस ब्लाक' ४२५ करोड़ रु० और उनकी उत्पादन क्षमता ६५० करोड़ रु० है। १९५४-५५ के वित्तीय वर्ष के आधार पर अध्ययन करने से परिणाम निकाला गया कि इन ४१० कम्पनियों की योजना के अनुसार कुल जमा करने की शक्ति एकत्र सुरक्षित निधि और चालू लाभ को देखते हुए ५३ करोड़ और ८ करोड़ रुपए के बीच रहेगी। जो सरकार के बनाये गये नियमों और उनकी कठोरता तथा उदारता पर निर्भर करती रहेगी।

देश की समस्त औद्योगिक कम्पनियों की जमा करने की शक्ति कितनी है, इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं है। तथापि ऊपर दिये गये परिणामों के आधार पर कहा जा सकता है कि औद्योगिक कम्पनियों पर भार सचमुच काफी बढ़ जायेगा। सरकार इस योजना से कितना जमा होने की आशा रखती है, यह स्पष्ट नहीं है। लेकिन इसका बाहरी अंदाजा १०० करोड़ के लगभग माना गया है। पर इसमें बड़ा भय यह माना जा रहा है कि अनिवार्य जमा के सम्बन्ध में सरकार के नियम चाहे कठोर हों या उदार, लेकिन औद्योगिक कम्पनियों की स्थिति जटिल हो जायेगी और द्रव्य बाजार में मुद्रा की कमी की वर्तमान स्थिति पर पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। वास्तव में बात है भी यही। देश में सब कम्पनियां इतनी समर्थ नहीं कि इस योजना के अनुसार सरकार के पास जमा कर सकें, क्योंकि उनकी तरल पूंजी पर्याप्त नहीं है। इसलिये उन्हें बहुत कुछ बैंकों का आश्रय लेना पड़ेगा। इससे बैंकों का भार और भी बढ़ जायेगा। बहुत सम्भव है कि यदि द्रव्य बाजार के भार को कम न किया गया तो आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाये।

(शेष पृष्ठ २६४ पर)

भारत सरकार के व्यापार और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित

'उद्योग व्यापार पत्रिका'

★ उद्योग और व्यापार सम्बन्धी प्रामाणिक जानकारी युक्त विशेष लेख, भारत सरकार की आवश्यक सूचनाएं, उपयोगी आंकड़े आदि प्रति मास दिये जाते हैं।

★ डिमाई चौपेजी आकार के ६० ७० पृष्ठ : मूल्य केवल ६ रुपया वार्षिक। एजेण्टों को अच्छा कमीशन दिया जायगा। पत्रिका विज्ञापन का सुन्दर साधन है।

★ लघु-उद्योग विशेषांक मंगा कर छोटे उद्योगों के सम्बन्ध में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त कीजिये।

★ ग्राहक बनने, एजेन्सी लेने अथवा विज्ञापन छपाने के लिए नीचे लिखे पते पर पत्र भेजिये :—

सम्पादक

उद्योग व्यापार पत्रिका

उद्योग और व्यापार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सिंचाई का आयोजन

[श्री एम० जी० हीरानंदानी]

हमारे देश में यदि एक ओर लम्बी चौड़ी नदियां हैं तो दूसरी ओर विस्तीर्ण मैदान भी हैं। इसका मतलब है कि देश में सिंचाई की बहुत गुंजइश है। भारत के ८० करोड़ ९० लाख एकड़ क्षेत्र में से ४५ करोड़ एकड़ भूमि खेती योग्य है। १९५४-५५ में कुल ३१ करोड़ ५० लाख एकड़ में काश्त हुई।

हमारी नदियों का वार्षिक प्रवाह १ अरब ३५ करोड़ एकड़ फुट होने का अनुमान है। इसमें से केवल ११ करोड़ ९० लाख एकड़ फुट का पहली आयोजना में उपयोग किया गया। मोटा अनुमान है कि ४५ करोड़ एकड़ में से सब राज्यों में कुल मिलाकर २ करोड़ ३६ लाख एकड़ में ही सिंचाई हो सकती है। और इतने क्षेत्र के लिए ६५ करोड़ एकड़ फुट पानी की जरूरत होगी।

पहली आयोजना के आरम्भ में देश भर में लगभग ५ करोड़ एकड़ क्षेत्र में सिंचाई हुई। अभी तक सिंचाई का सब जगह एक-सा विकास नहीं हुआ है। नीचे की तालिका से पता चलता है कि 'क' और 'ख' वर्ग के राज्यों में सिंचाई वाले क्षेत्र का प्रतिशत २.६ से लेकर ३०.८ तक है।

राज्यों का सिंचाई वाला क्षेत्र

राज्य	सिंचित क्षेत्र (लाख एकड़)	खेती योग्य भूमि (लाख एकड़ों में)	खेती योग्य और सिंचित भूमि का अनुपात
'क' भाग			
आंध्र	४५.८३	२४५.८	१८.७ प्र० श०
असम	१३.३९	२४१	५.५५ प्र० श०
बिहार	५५.९५	११३	१७ ८ प्र० श०
बम्बई	१९.७६	३४७	५.६५ प्र० श०
मध्यप्रदेश	२०.७०	४२४	४.९ प्र० श०
मद्रास	४४.१२	२६०.७	१७ प्र० श०
उड़ीसा	२५.१७	११०	२२.८ प्र० श०
पंजाब	४६.१७	१६१	२८.६ प्र० श०
उत्तर प्रदेश	११९.५९	५२६	२२.७ प्र० श०
प० बंगाल	२४.४६	१३६	१८.० प्र० श०
'ख' भाग			
हैदराबाद	१५.०१	३८५	३.९ प्र० श०
जम्मू और काश्मीर	६.४४	३४	१९.५ प्र० श०
मध्यभारत	५.१९	१२१	४.३ प्र० श०
मैसूर	१०.७८	१५२.६	७.०६ प्र० श०
पेप्सू	१७.८६	५८	३०.८ प्र० श०
राजस्थान	२८.३९	३६६	७.७५ प्र० श०
सौराष्ट्र	१.८९	७२	२.६ प्र० श०
तिरुवांकुर कोचीन	८.६७	३३	

सिंचित कृषि भूमि

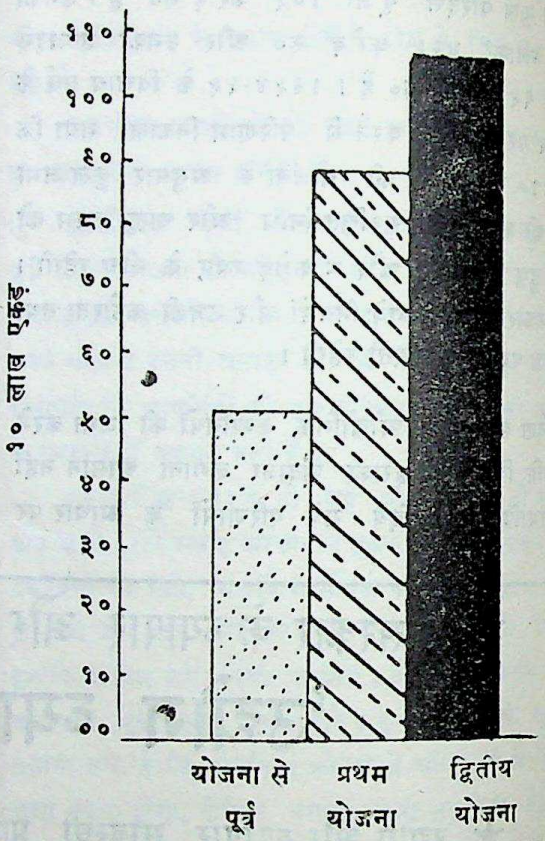

कुछ तो कई सिंचाई योजनाओं के पहले ही शुरू हो जाने से और कुछ आंकड़ों और साधनों आदि के अभाव

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

में, पहली पंचवर्षीय आयोजना में सिंचाई और बहु-उद्देशीय योजनाओं की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जा सका। भिन्न-भिन्न राज्यों में किस क्रम से और किन बातों का ख्याल रखकर सिंचाई और बहु-उद्देशीय योजनाओं को हाथ में लिया जाय, यह पहले से निश्चित करना होता है।

दूसरी पंचवर्षीय आयोजना की योजनाओं के चुनाव के ये आधार तय किए गए हैं—

(१) ऐसी योजनाएं जिनकी सब जांच पड़ताल हो चुकी है;
(२) योजना का खर्च और उससे होने वाला लाभ;
(३) राज्य काम पूरा कर सकता है या नहीं;
(४) योजना सूखे, कम वर्षा वाले या अधिक वर्षा वाले, किस क्षेत्र में हैं;
(५) सारे प्रदेश का एक सा विकास ताकि राज्यों की आर्थिक दशा में विशेष अन्तर न रहे;
(६) राज्य में कितने मजदूर मिल सकते हैं, कितने लोग बेकार हैं और योजना से कितनी आमदनी होगी, इसकी जानकारी।

दूसरी आयोजना में सिंचाई

देश की आबादी प्रति वर्ष ५० लाख बढ़ जाती है। इसी वृद्धि को ध्यान में रखकर दूसरी आयोजना की अवधि में १ करोड़ टन अनाज अधिक पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। सिंचाई की व्यवस्था भी इसी आवश्यकता को देखकर ही की जायगी।

लगभग २०० योजनाओं को पूरा करने का विचार है। इन पर लगभग ४ अरब १० करोड़ रु० खर्च होगा, जिसमें से ३ अरब ६० करोड़ रु० दूसरी आयोजना की अवधि में शुरू होकर दूसरी आयोजना में चलने वाली और नई योजनाओं पर कुल ३ अरब ८० करोड़ रु० खर्च होगा।

जब सिंचाई के सब नए काम पूरे हो जायेंगे, तो इनसे लगभग १ करोड़ ४५ लाख एकड़ में सिंचाई हो सकेगी। इसमें से ३० लाख एकड़ में सिंचाई दूसरी आयोजना की अवधि में होगी। दूसरी आयोजना की अवधि में नये और पुराने बड़े-बड़े साधनों से लगभग १ करोड़ २० लाख एकड़ में सिंचाई होगी, जिसमें से ९० लाख एकड़ में पुरानी योजनाओं से और ३० लाख एकड़ में इसी आयोजना की योजनाओं से। सिंचाई के छोटे-छोटे साधनों से लगभग ८० लाख एकड़ में और सिंचाई होगी। इस प्रकार १९६०-६१ तक कुल २ अरब १० लाख एकड़ में सिंचाई होने लगेगी और देश का सिंचाई वाला क्षेत्र बढ़कर ८ करोड़ ३० लाख एकड़ हो जायगा। बड़े साधनों से ६ करोड़ ९० लाख एकड़ क्षेत्र सींचा जायगा।

अनुमान है कि पहली और दूसरी आयोजनाओं की सब छोटी-बड़ी योजनाओं के पूरे हो जाने पर लगभग २६ करोड़ एकड़ फुट पानी से कुल १० करोड़ ६० लाख एकड़ में सिंचाई होने लगेगी।

भावी विकास

जिस २३ करोड़ ६० लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई हो सकती है, तीसरी और बाद की योजनाओं में उसमें से, १३ करोड़ एकड़ में सिंचाई और हो सकेगी। इसमें ३९ करोड़ एकड़ फुट पानी काम आ जायगा। प्रति एकड़ ३५० रु० के हिसाब से आगे की सिंचाई योजनाओं (१३ करोड़ एकड़ में) पर ४५ अरब रु० खर्च होने का अनुमान है। यदि आगे की हर पंचवर्षीय आयोजना में सिंचाई के लिए ५ अरब रु० मिलता रहा तो इस तरह की ९ आयोजनाओं के बाद २३ करोड़ ६० लाख एकड़ में सिंचाई हो सकेगी।

—

उद्योग विभाग, उत्तरप्रदेशीय सरकार
द्वारा प्रकाशित
सचित्र मासिक पत्र
उद्योग

पढ़िये, जिसमें भारत के आर्थिक विकास, विशेषतया उत्तरप्रदेश की औद्योगिक प्रगति के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण लेखों के साथ साथ अन्यान्य मनोरंजक साहित्यिक सामग्री—कविताएं, कहानियां और लेख भी उपलब्ध होंगी।

विवरणार्थ लिखें :
प्रकाशनाधिकारी
उद्योग विभाग
उत्तरप्रदेश—कानपुर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बैंक और उनकी समस्याएं

श्री शान्ति प्रसाद जैन

पंजाब नैशनल बैंक के अध्यक्ष श्री शान्तिप्रसाद जैन ने बैंक की वार्षिक सभा में भाषण देते हुए कहा :

गत वर्ष बैंकों के सामने उपस्थित समस्याओं में से एक प्रमुख समस्या यह थी कि रुपये के बाजार में आन्तरिक मांग व विदेशी सामग्री के लिए बहुत तंगी आ गई। यह तंगी इतनी निकट थी कि लोग सोचने लगे कि पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य बहुत बड़ा करके उचित नहीं किया गया है। रुपये की व्यवस्था में बैंकों का बहुत बड़ा भाग होता है। इसलिये व्यापारी बैंकों पर काफी ज्यादा दबाव पड़ा। देश की विकास की आवश्यकतायें बहुत थीं। भारी मात्रा में हमें पूंजीगत सामान लगाना पड़ा और इसके लिये बैंकों पर रुपये की व्यवस्था का बहुत बड़ा दबाव आ गया। नीचे की तालिका से यह स्पष्ट हो जायेगा।

बैंक और बीमा

विभिन्न उद्देश्यों से बैंकों द्वारा दिया गया धन (करोड़ रु०)

वर्ष	१९५३	१९५५	१९५६
उद्योग	१९२.८९	२४१.१९	३००.३०
व्यापार	२७५.०४	२९२.२८	३५६.३२
कृषि	१५.७२	१२.४५	१७.६९
निजीकार्य	४५.३२	५४.७९	५८.२२
अन्य	३५.५१	२४.९२	३१.२५
योग	५६४.४८	६२५.६३	७६३.८७

जब कि डिपोजिट में ७७ करोड़ की वृद्धि हुई, बैंकों द्वारा उधार दी गई राशि १५८ करोड़ बढ़ गई। बैंकों को रिजर्व बैंक से उधार लेना पड़ा। अपने दूसरे उद्योग कम करने पड़े, तथा शेष नकदी भी कम करनी पड़ी। श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने वित्त मन्त्री पद लेते ही स्थिति को आसान करने के लिए बिल मार्केट की शर्तें उदार कर दीं।

विकास के बढ़े हुए खर्चों के कारण देश में मुद्रा-प्रसार के लक्षण दीखने लगे, लेकिन कृषि पदार्थों के मूल्य वस्तुतः पैदावार कम होने से बढ़ गये। यदि कृषि उत्पादन के लक्ष्य हम पूरे कर लें तो महंगाई बहुत कम हो जायेगी। इसके दो परिणाम और भी होंगे—विदेशी मुद्रा पर बहुत बोझ नहीं पड़ेगा और लोग ज्यादा बचत कर सकेंगे।

विदेशी मुद्रा की दुर्लभता एक और कठिन समस्या है, जिसको हमें कुशलता से हल करना चाहिए। पूंजी गत सामग्री की मूल्य वृद्धि, तथा स्वेज नहर से यातायात की असुविधा ने भी विदेशी मुद्रा को अधिक कठिन बना दिया। मूल्य को देर में अदा करने की योजनाएं खर्चीली हैं, तथापि विचारणीय अवश्य हैं। इसके विस्तार में जाकर अधिक से अधिक सुविधाएं देने का प्रयत्न करना चाहिए।

रुपए की कमी, बढ़ते हुए मूल्य और विदेशी मुद्रा की दुर्लभता आदि समस्याओं का जितना समाधान किया जायेगा, उतना ही हम योजना पूर्ति के निकट पहुँचेंगे।

व्यापारिक बैंकों से आज यह आशा की जा रही है कि वे कम और बीच की अवधि के लिए ज्यादा से ज्यादा रुपए देंगे। इसलिए बैंकों को अधिक से अधिक रुपया बढ़ाने के साधन जुटाने चाहिएं। उन्हें उन क्षेत्रों से रुपया जमा करना चाहिए जिनका अभी तक संगठन नहीं हुआ है। शहरों में बहुत तीव्र और अनुचित स्पर्द्धा चल रही है, क्योंकि डिपाजिट तबदील करके जमा कराने वाले अधिक सूद ले लेते हैं, इससे अतिरिक्त रुपया महंगा मिल रहा है। इसलिए व्यापारिक बैंकों को अपना कार्य क्षेत्र ग्रामों तक व्यापक करना चाहिए और सहायक संस्था व छोटे बैंकों द्वारा रुपया जमा करना चाहिए। भारत सरकार व रिजर्व बैंक के सहयोग से इस काम में सफलता मिल सकती है।

को-ओपरेटिव बैंक केवल को-ओपरेटिव सोसायटी को पैसा देते हैं। उनसे साधारण ग्रामीण जनता को रुपया नहीं मिल सकता। इसलिए रिजर्व बैंक का कर्त्तव्य है कि वे व्यापारिक बैंकों को गांव में रुपया पहुँचाने की पूरी सुविधा दें।

भारत के प्रधान मन्त्री ने अपने भाषण में यह सुझाव दिया है कि लोग अपना सोना सरकार को दे दें, तथा

[सम्पूर्ण

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

संचित परन्तु निष्क्रिय सम्पत्ति देश के काम आये वित्त मंत्री को ऐसी युक्ति सोचनी चाहिए जिससे लोग अपना सोना सरकार को दे सकें। भारत सरकार भी संसार के मूल्य से अधिक कीमत देकर सोना खरीद लें तो भारत सरकार हमारी मुद्रा को मजबूत करेगी और विदेशों से हम ज्यादा सुविधा से रुपया प्राप्त कर सकेंगे। भारत सरकार को इसमें जो हानि होगी, देश की विकास योजना से उसकी पूर्ति होगी।

★

स्टेट बैंक द्वारा प्रतिस्पर्धा

श्री सी० एच० भाभा ने हाल में ही इण्डियन बैंकिंग एसोसियेशन की एक बैठक में भाषण देते हुए शिकायत की है कि स्टेट बैंक की दूसरे व्यापारिक बैंकों से अनुचित प्रतिस्पर्द्धा चल रही है। उन्होंने कहा कि १ जुलाई १९५५ से १९५६ के अन्त तक स्टेट बैंक ने ६६ नई शाखाएँ खोलीं और इनमें से केवल ८ स्थान ही ऐसे हैं, जहां पहले से ही किसी व्यावसायिक या सहकारी बैंक की शाखाएँ नहीं हैं।

श्री भाभा ने कहा 'इन ५८ स्थानों में प्रायः सब में बैंक सम्बन्धी अच्छी सेवाएं अन्य बैंकों की शाखाओं या पे आफिसों के द्वारा पहले से ही उपलब्ध थीं। इनमें जो कमी हुई वह स्पष्ट है। कोई भी आसानी से समझ सकता है कि इनमें से बहुत सी शाखाओं को ट्रैजरी सम्बन्धी कार्यों के लिये खोला गया था। यथार्थ में स्टेट बैंक की इन शाखाओं में कुछ अन्य बैंकों की शाखाओं के साथ अनुचित प्रतिस्पर्धा की भावना से काम कर रही हैं। मैं मानता हूँ कि स्टेट बैंक आफ इण्डिया की, जो अन्य बैंकों की अपेक्षा विशेष सुविधाओं से युक्त है, इस अनुचित प्रतिस्पर्द्धा का प्रतिरोध किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सरकारी हस्तक्षेप के द्वारा संस्थाओं और व्यक्तियों को विशेष रूप से स्टेट बैंक का समर्थन करने के लिये कहा जा रहा है, भले ही उनको इसमें असुविधाएँ हों।

★

केन्द्र व राज्य

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १,३०० करोड़ रु० के पूंजीगत व्यय के असंगत और अनुचित परिणामों में से एक परिणाम यह है कि यद्यपि भारत सरकार का सार्वजनिक ऋण १९५०-१९५१ में २,६५१ करोड़ रु० था, वह १९५५-५६ में अन्त तक बढ़ कर ३,३१२ करोड़ रु० हो गया। याने इसमें ७५१ करोड़ रु० की वृद्धि हुई। लेकिन केन्द्रीय ऋणों के बढ़ जाने के कारण सरकारी आय से मिलने वाले ब्याज में १९५५-५६ में १९५१-५२ की अपेक्षा कमी हो गयी। दूसरी ओर राज्य सरकारों का कुल ऋण १९५०-५१ में २४५ करोड़ रु० से बढ़ कर १९५५-५६ में ९६५ करोड़ रु० हो गया और उधार सम्बन्धी सेवाओं के मूल्य में ४३ करोड़ रु० की वृद्धि हुई। इस प्रकार राज्यों को अधिक त्याग करना पड़ा क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने उधार द्वारा प्राप्त की गयी राशि से ऋण न देकर ३५० करोड़ रु० की घाटे की अर्थव्यवस्था और २३० करोड़ रु० की विदेशी सहायता कर अपनी ऋण की सेवाओं सम्बन्धी देयता को राज्यों को हस्तांतरित कर दिया। केन्द्रीय सरकार की ऋण सम्बन्धी सेवाओं का मूल्य चुकाने में राज्य सरकारों के अतिरिक्त करों से होने वाली वार्षिक आय का $\frac{3}{4}$ भाग खर्च हो जाता है और इस उधार में और वृद्धि होने से द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्रायः अतिरिक्त करों की समस्त आय खर्च हो जायेगी।

★

नए ऋण की तैयारी

रिजर्व बैंक के विनियोग विभाग में २९ मार्च १९५७ को समाप्त सप्ताह में लगभग ४१ करोड़ रु० की वृद्धि हो गई है और उसके विनियोग खाते में १२१.२२ करोड़ रु० हो गए हैं जो २ मार्च को ०.२२ करोड़ रु० थे। इससे यह लगता है कि रिजर्व बैंक ऐसी स्थिति पैदा करने लगा है कि जिसमें चालू वित्तीय वर्ष की ऋण योजना को आगे बढ़ाया जा सके। यह भी उल्लेखनीय है कि अनुसूचित बैंकों का सरकारी सिक्यूरिटियों में विनियोग कम हो गया है और अधिक कारोबार के सीजन के शुरू होने से १५ मार्च तक उनके सिक्यूरिटियों के विनियोग में २२.५६ करोड़ रु० की कमी आ गई है। इसका एक कारण यह अवश्य है कि बैंक द्रव्य की आवश्यकता के लिए सिक्यूरिटियों में अपना विनियोग घटा रहे हैं। किन्तु इसका मुख्य कारण रिजर्व बैंक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

द्वारा सिक्यूरिटियों की खरीद शुरू कर देना है। इसका असर सिक्यूरिटियों पर अच्छा पड़ा है और उनके भाव सुधर गए हैं। किन्तु अभी यह कहना कि नए ऋण जारी करने के लिए बाजार में अनुकूल स्थिति पैदा हो गई है, गलत होगा १९५७-५८ के बजट में १०० करोड़ रु० के ऋण की व्यवस्था की गई है। इसी वर्ष १९५७ विक्ट्री ऋण का भुगतान होना है। यह ऋण ३० करोड़ रु० का है। इस तरह जो नया ऋण सरकार लेना चाहती है, वह ७० करोड़ रु० का है। गत तीन वर्षों से सरकारी ऋणों को जो सफलता मिली है, उन्हें देखते हुए ७० करोड़ रुपए की ऋण की सफलता की आशा आसानी से की जा सकती है। किन्तु अधिक करों के कारण द्रव्य बाजार में विनियोग के लिए राशि की जो कमी इस समय आ गई है, उसे देखते हुए ऋण लेने की योजना इतनी आसानी से शायद ही सफल हो सके।

★

द्रव्य बाजार की स्थिति

फिलहाल द्रव्य बाजार में राशि की कमी बराबर बढ़ रही है और इसकी मांग ऊँचे स्तर पर है। २९ मार्च को समाप्त सप्ताह के लिए रिजर्व बैंक ने जो आंकड़े प्रकाशित किए हैं, उनके अनुसार सक्रिय नोटों में आलोच्य सप्ताह में ८.३ करोड़ रु० की वृद्धि हुई और वे १५२६.०९ करोड़ रु० पर आ गए। इस सप्ताह बैंकिंग विभाग के पास जमा नोटों में ७.६५ करोड़ रु० की कमी होने के बावजूद जारी नोटों में ६६ लाख की वृद्धि हुई और वे १५३७.८३ करोड़ रु० पर आ गए।

★

निर्यात बीमा

केन्द्रीय व्यापार मंत्री श्री डी० पी० करमकर ने नई दिल्ली में यह घोषणा की है कि भारत सरकार ने माल निर्यात खतरा बीमा निगम स्थापित करने का फैसला किया है, जिसका कार्यालय बम्बई में होगा।

प्रस्तावित निगम अगले कुछ सप्ताहों में अपना काम चालू कर देगा। इस प्रकार के खतरों का बीमा होने से जो आम तौर से तिजारती बीमा कम्पनियां नहीं करतीं भारतीय निर्यातकों को विदेशी मंडियों में प्रतिस्पर्धा करने में काफी मदद मिलेगी।

गत वर्ष विदेशी व्यापार संतुलन हमारे खिलाफ रहा है। लेकिन इसका कारण यह है कि हमें अपने देश के आर्थिक विकास के लिए अधिक मात्रा में आयात करना पड़ा, न कि हमारे निर्यात में कोई कमी आ गई। हमारी मौजूदा कठिनाइयों का एकमात्र हल यह है कि हम अपने निर्यात व्यापार को ऊँचे पैमाने पर ले जाएं। नई-नई चीजें बाहर भेजें और नई-नई मंडियां तलाश करें। हाल में आयात पर जो कड़ा अंकुश लगाया गया है, वह एक अस्थायी कदम है जो विदेशी मुद्रा बचाने के लिए इस समय बहुत जरूरी हो गया था। लेकिन असल में विदेशी मुद्रा की कमाई बढ़ाने का तरीका यही है कि सरकार भारतीय उत्पादकों और निर्यातकों को निर्यात बढ़ाने में मदद दे और वह इस दिशा में सब सम्भव कदम उठा रही है।

एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कमेटी ने सिफारिश के अनुसार रिस्क इंश्योरेंस कार्पोरेशन आयात और निर्यात में विभिन्न प्रकार के जोखिमों—जैसे देर से माल पहुँचना या न पहुँचना, युद्ध या गृहयुद्ध का भय सम्बन्धी आदि इसी प्रकार के जोखिम, जिन पर आयात करने वाले या माल मंगाने वाले देशों का कोई वश नहीं है, का बीमा करेगी।

कार्पोरेशन की अधिकृत पूंजी ५ करोड़ रु० होगी। आर्थिक पूंजी २.५ करोड़ से आरम्भ की जायेगी। पर व्यवसाय बढ़ने के साथ ही समय-समय पर यह पूंजी भी बढ़ाई जाती रहेगी। योजना का आरम्भ यद्यपि ऐच्छिक आधार पर हो रहा है, लेकिन यदि कोई निर्यातकर्ता अपने निर्यात का बीमा करना चाहता है तो उसे १२ महीने की अवधि में अपने सब निर्यात का बीमा कर लेना चाहिए। सम्पदा के पाठक इस बीमे के सम्बन्ध में समय-समय पर पढ़ते रहे हैं।

★

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

द्वितीय योजना में छोटी बचतें

श्री एस० निवासाचार

बचत पूंजी-निर्माण का एक साधन है। लेकिन अर्थशास्त्र में बचत के विषय में बड़ी भ्रांति फैली है। विभिन्न व्यक्तियों ने विभिन्न समयों में इसका भिन्न-भिन्न अर्थ लगाया है। अलग-अलग परिस्थितियों में इसका स्वरूप भी विभिन्न रहा है।

वर्तमान समय में वैयक्तिक और सामूहिक—दोनों प्रकार की बचतों का बड़ा महत्व है। ये किसी भी राष्ट्र की आर्थिक उन्नति के मूलाधार हैं; भले ही उसके राजनैतिक विचार कुछ भी हों। रूस से साम्यवादी शासन के अंतर्गत औद्योगिक रूस से सम्पन्न राष्ट्र बना या अमेरिका और कनाडा जैसे स्वतंत्र-उद्योग-समर्थित राष्ट्रों ने इतनी आर्थिक उन्नति कर ली है। इसका कारण इन राष्ट्रों की भूतकाल की वह बड़ी बचत है, जिसका बाद में इन राष्ट्रों ने कुशलता से विनियोग किया।

दो साधन

इसके विपरीत, पिछड़ी अर्थव्यवस्था वाले एशियाई देशों में आर्थिक उन्नति के जो प्रयत्न किये जा रहे हैं, उनमें सबसे बड़ी बाधा इस बात की है कि यहां के लोगों की इतनी सामर्थ्य नहीं कि वे अच्छी मात्रा में बचत करके उसका कृषि और उद्योगों में विनियोग कर सकें। भारत जैसे देश में, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है और जिसने आर्थिक उन्नति के कार्यक्रम में कृषि और अन्य उद्योगों में सामंजस्य स्थापित करने का निश्चय किया है, बहुत बड़ी मात्रामें विभिन्न उद्योगों पर विनियोग करने की अत्यन्त आवश्यकता है। इस विनियोग के लिये धन प्राप्त करने के दो साधन हैं। पहला साधन यह कि आंतरिक बचत को सार्वजनिक ऋणों द्वारा प्राप्त करना और दूसरा साधन है विदेशों से ऋण लेना या आर्थिक सहायता प्राप्त करना। सरकार द्वारा प्रचलित अल्प बचत योजना, व्यापक रूप में आंतरिक बचत को प्राप्त करके पूंजी-निर्माण करने में सहायक होती है। इस योजना के द्वारा जो कुछ भी प्राप्त होता है, वह सार्वजनिक ऋण का ही एक भाग होता है।

जब एक व्यक्ति खर्च नहीं करता या खर्च करना टाल देता है तो वह इस प्रकार धन की बचत करता है। बचत की परिभाषा यह भी की जा सकती है कि चालू आय और व्यय (जिसमें दिये जाने वाले कर और उपभोग की वस्तुओं पर किया जाने वाला खर्च भी शामिल है) का अंतर ही बचत है।

वे बचतें जो आय और व्यय की अंतर हैं; कई प्रकार की होती हैं:— जैसे नकदी या सुरक्षित निधि, उधार में कमी, टिकाऊ सामानों और चल संपत्ति में विनियोग। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही कम है जिनकी आय उनके व्यय से अधिक हो जिससे वे बचत कर सकें। इसलिए वैयक्तिक रूप में प्रभावशाली बचत असम्भव सी है।

परिभाषा और गणना की दृष्टि से छोटी बचतों से तात्पर्य डाकखानों के सेविंग बैंकों में सरकार द्वारा एकत्र की जाने वाली राशि से होता है जिसको सेविंग सर्टिफिकेटों को बेचने और जमा को स्वीकृति करने के जरिये प्राप्त किया जाता है। ७ और १२ वर्षीय सेविंग सर्टिफिकेट, १० वर्षीय नेशनल प्लान सर्टिफिकेट तथा १५ वर्षीय एन्यूटी सर्टिफिकेटों के द्वारा सरकार लोगों की बचतों को योजना में विनियोग करने के लिये प्राप्त करने की कोशिश कर रही है।

छोटी बचत निम्नलिखित कई बातों पर निर्भर करती है। राष्ट्रीय आय और इसका वितरण, लोगों का आचार-विचार, मूल्य-स्तर, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का दबाव, राजनैतिक सुस्थिरता और काफी संख्या में लोगों को रोजगार मिलना।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ होने से इसमें विनियोग करने का मुख्य भाग सरकार का ही रहा है। निजी उद्योगों को गौण स्थान मिला है। समाजवादी समाज के उद्देश्य की पूर्ति के लिये, विनियोग कार्य में धन प्राप्त करने का भार भी प्रधानतः सरकार और सामान्य जनता को ही वहन करना पड़ेगा। सरकार अपना भाग कर लगा कर, उधार लेकर घाटे की अर्थ व्यवस्था के द्वारा अदा करेगी, लेकिन सर्वसाधारण—निम्न और मध्यम वर्ग की

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जनता तो छोटी बचत करके ही अपना कर्तव्य निभा सकेगी।

सरकार और जनता द्वारा बचत करने का यह प्रयत्न, राष्ट्रीय प्रयत्न का रूप धारण कर लेता है। यहां एक व्यक्ति केवल सामान्य गृहिणी की उस भावना के अनुसार कार्य नहीं करता कि बरबादी न करते हुए भविष्य के लिये भी कुछ न कुछ रख लेना चाहिए, वरन इससे भी ऊपर वह देशभक्ति से अनुप्राणित होकर राष्ट्र की दीर्घकालीन आपात स्थिति को भी विचार में रख कर बचत करता है।

साधारणतः राष्ट्रीय आय का बचत से घनिष्ट सम्बन्ध है। लेकिन जब छोटी बचत के विषय में कहते हैं तो हमारा तात्पर्य केवल राष्ट्रीय आय के वितरण से होता है न कि उसके परिमाण वृद्धि से। भारत में राष्ट्रीय आय के बढ़ने के साथ बचत के अनुपात में वृद्धि है या नहीं, यह इस तालिका में दिखाया गया है:—

वर्ष	राष्ट्रीय आय (करोड़ रु० में)	कुल	छोटी बचत विशुद्ध
१९५०-५१	९,५३०	३८·७०	३२·७१
(योजना से पूर्व)			
१९५१-५२	९,९७०	३९·७९	३८·७८
१९५२-५३	९,८२०	३९·६६	३९·७१
(मूल्यों में गिराबट)			
१९५३-५४	१०,४९०	५५·५१	३९·६१
१९५४-५५	९,९१०	६७·९१	५५·५१
(कृषि के उत्पादन और मूल्य में गिराबट)			
१९५५-५६	१०,८०० (अनुमा०)	७६·९३	६७·५१

इस तालिका से स्पष्ट है कि विभिन्न समयों में बचत की प्रवृत्ति बढ़ने की रही है। योजना के ३ साल पूर्व कुल राशि औसतन ३० करोड़ रु० प्रति वर्ष थी। लेकिन योजना काल के पांच वर्षों में पूर्ण प्राप्त राशि २१९ करोड़ रु० यानी औसतन ४४ करोड़ रु० प्रति वर्ष रही। कुल बचत का ३६ प्रतिशत अकेले सेविंग बैंक से मिला। १९५१ में सेविंग बैंक से प्राप्त बचत ६१ करोड़ रु० थी। शेष ४ वर्षों में यह १२० करोड़ रु० तक बढ़ी। इससे स्पष्ट है कि डाकखानों के सेविंग बैंक काफी लोकप्रिय हैं।

पिछड़े किन्तु विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश भारत में जहां पूंजी निर्माणका अल्प बचत योजना पर निर्भर रहना अत्यंत आवश्यक है, वहां उसी प्रकार साख-सुविधाओं के लिये घाटे की अर्थव्यवस्था का आश्रय लेना अवश्यम्भावी है।

इस प्रकार अतिरिक्त द्रव्य के निर्माण व नये उद्योगों में विनियोग-काल से लेकर इनके पूर्ण रूप से उपभोग की

पंचवर्षीय योजना पूरी होगी बशर्ते कि.....

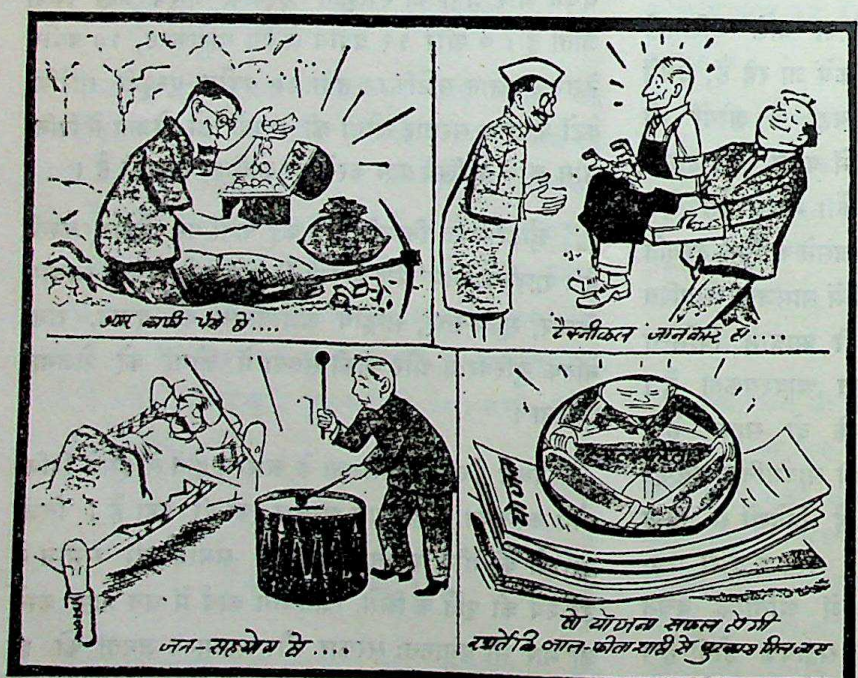

— ('योजना' से साभार)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वस्तुओं के उत्पादन कर सकने की अवधि तक मुद्रास्फीति की परिस्थिति अनिवार्य रूप से उत्पन्न होगी।

भारतमें एक साल से मूल्य तेजी से बढ़े भी हैं जिससे छोटी बचत करने वालों की सामर्थ्य कम हुई है, अनेक बचत करने वाले बचत नहीं कर सक रहे हैं। लेकिन इस समस्या का हल कंट्रोल लगाने से नहीं होगा, क्योंकि यह न तो उचित ही है और न व्यावहारिक ही। उल्टे इससे छोटी बचत के श्रमिकों को योजना के लिये धन प्राप्त करने में हानि होगी।

छोटी बचत पर राष्ट्रीय आय और उसके वितरण के ढंग का प्रभाव तो पड़ता ही है लेकिन रोजगार के स्वरूप से वह प्रभावित नहीं होती। शास्त्रीय दृष्टि से अनुन्नत देश में श्रमिक एक प्रकार से बेकार होते ही नहीं। या तो वे कम उत्पादन के कामों में लगे रहते हैं, या फिर रोजगार मिलने की दशाएं होती ही नहीं। इसलिए कम उत्पादन (Inefficiency) के काम से निकल कर मजदूर नये उद्योगों में काम करने लगें तो अनिवार्य रूपसे उपभोग की वस्तुओं की मांग बढ़ जायेगी और परिणामतः मूल्य भी बढ़ जायेंगे और एक सीमा तक वास्तविक आय का कुछ भाग पुराने मजदूरों से नये मजदूरों को मिलने लगेगा।

इस तथ्य से छोटी बचत योजना व आन्दोलन की कार्य-पद्धति में सामंजस्य करना अति आवश्यक हो जाता है। चूंकि भारत एक लोकतंत्रात्मक राष्ट्र है, अतः अनिवार्य बचत योजना को अपनाना ठीक नहीं। इस अल्प बचत आन्दोलन पर विशेष जोर नये खुले उद्योगों में देना चाहिए जहां अतिरिक्त मजदूरों को काम मिला है।

अल्प बचत योजना के प्रचार से किस सीमा तक मुद्रास्फीति का भार कम होने में सहायता मिलेगी, यह कोई गणित का साधारण प्रश्न नहीं। एक अल्प विकसित देश में जहां सारी शक्ति आर्थिक उन्नति में लगी हो, वहां मूल्य को निर्धारित करने वाले तत्व विभिन्न प्रकार के और कई होते हैं। स्थिर जनसंख्या, शांति और सुस्थिरता की सामान्य दशा में तथा नये उद्योगों में उपभोग्य वस्तुओं का उत्पादन बढ़ने पर मूल्यों को उचित स्तर पर लाया जा सकता है। लेकिन तेजी से बढ़ रही जनसंख्या के कारण जब उपभोग की वस्तुओं के मूल्य को वश में रखने के सभी प्रयत्न व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए परिणाम निकलता है कि अल्प बचत योजना की भावना यदि पूर्णतः नहीं तो अंशतः जीवन-लागत से निर्धारित होती है।

इन सब तथ्योंसे स्पष्ट है कि छोटी बचत योजना की प्रक्रिया बहुत जटिल है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में छोटी बचत को बड़ी आशा से देखा गया है। द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में सरकारी भाग पर ४८०० करोड़ रु० व्यय करने का निश्चय किया गया। ५०० करोड़ रु० छोटी बचत-योजना से प्राप्त होने की आशा व्यक्त की गई है। लेकिन कुछ ही समय पहले योजना-व्यय को ६०० करोड़ रु० और बढ़ा दिया गया है। इससे देश के तमाम साधनों पर—जिसमें अल्प-बचत भी हैं - भार अधिक बढ़ गया है। इस विषय में संतोष की बात यह है कि राष्ट्रीय आय के मुकाबले में छोटी बचत का अनुपात बढ़ता रहा है। इसका प्रतिशत १९५१ में ०.३५ और १९५५-५६ में ०.४५ थे।

यदि योजना में अल्प बचत से ५०० करोड़ रु० की प्राप्ति हो भी जाये, यही नहीं इसमें कुछ वृद्धि भी हो जाये तो भी देश की आवश्यकता को देखते हुए इसको अधिक नहीं मानना चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था पर जो अनेक प्रति-बंध लगे हुए हैं, उनको देखते हुए छोटी बचत योजना का स्वरूप लचकीला होना आवश्यक है। साथ ही उसमें जोर जबर्दस्ती की कोई गुंजाइश न हो, यह जोर जबर्दस्ती हमारे राजनैतिक विचारों के सर्वथा प्रतिकूल है।

निस्संदेह वर्तमान अल्प बचत योजना के संगठन में सरकार ने संशोधन करके इसको अच्छा बना लिया है। लेकिन यह निश्चित नहीं है कि इस आन्दोलन को व्यापक बनाने के लिए सरकार ने—मनोवैज्ञानिक और संगठनात्मक दोनों रूपों से सम्बन्धित समस्त उपलब्ध साधनों का उप-योग किया है। भारत में घरेलू बचत का एक बड़ा भाग सोना, चांदी और आभूषणों के रूप में संदूकों में बंद रहता है। यद्यपि इसका अंदाजा

[शेष पृष्ठ २९० पर]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आवश्यक भूमि-सुधार

श्री श्रीमन्नारायण

नये चुनावों के बाद बने हुए राज्यीय मंत्रिमण्डलों के सामने जो महत्वपूर्ण कार्य उपस्थित हैं, उनमें भूमि सुधार बहुत उल्लेखनीय है। गत वर्षों से इस दिशा में बहुत प्रगति हुई है, किन्तु बहुत सा क्षेत्र बाकी है। इस विषय पर कांग्रेस के महा मंत्री श्री श्रीमन्नारायण ने एक लेख आर्थिक समीक्षा में लिखा है। उसके कुछ आवश्यक अंश यहां दिये जा रहे हैं :—

बेदखलियां बन्द हों

यह जरूरी है कि सभी काश्तकारों को भूमि-व्यवस्था संबंधी पूरी सुरक्षा देने और मुख्तलिफ किस्म की बेदखलियां तुरन्त बन्द करने के लिए काश्तकारी-संबंधी सुधार लागू किये जायं। बहुत से राज्यों में सोचे गये भूमि-सुधारों की वजह से काश्तकारों और शिकमी काश्तकारों को काफी परेशानी उठानी पड़ी है। इस तरह के भूमि सुधारों को लागू करने में थोड़ी सी देर हो जाने की वजह से बहुत काश्तकारों को बेदखली का सामना करना पड़ा है। इस लिए यह जरूरी है कि तमाम बेदखलियों को तुरन्त बन्द करने के लिए आदेश जारी कर दिया जाय। जहां तक 'निजी खेती' के लिए फिर से जमीन हस्तगत करने का ताल्लुक है, यह जरूरी है कि बहुत साफ-साफ शब्दों में 'निजी खेती' की परिभाषा कर दी जाय। निजी तौर पर खेती करने के उद्देश्य से जमीन पर फिर कब्जा करने के लिए खेत पर एक निम्नतम मात्रा में स्वयं श्रम करना बुनियादी रूप में अनिवार्य हो जाना चाहिए। इसके लिए सिर्फ पूंजी लगाना और सामान्यतः खेती-बाड़ी की देख-रेख करना ही काफी नहीं माना जाना चाहिए। चूंकि भूतकाल में 'निजी खेती' की परिभाषा सामान्य तौर पर दोषपूर्ण रही है, इसलिए कुछ राज्यों में बटाई द्वारा खेती की व्यवस्था को, जिसमें काश्तकारी की सभी विशेषताएं पायी जाती हैं, 'निजी खेती' नहीं माना गया है और बटाई-दार उन हकों से वंचित रखे गये हैं, जो काश्तकारों को मिले हैं। इस दोष को भी, जहां तक मुमकिन हो, दूर कर देना चाहिए।

लगान की दर

पहली पंचवर्षीय योजना में यह कहा गया था कि अगर लगानदर उपज के एक चौथाई या पांचवें हिस्से से अधिक हो, तो उसके लिए विशेष औचित्य का आधार जरूरी होना चाहिए। लगान के नियमन की दिशा में हुई प्रगति असमान रही है और कई राज्यों में कानून काफी पीछे पड़ गये हैं। इसलिए यह वांछनीय है कि लगान की दर को उस स्तर पर ला दिया जाय, जिसका सुझाव पहली पंचवर्षीय योजना में दिया गया है। लगान-नियमन के सामान्य तरीकों के अलावा, अधिकतम लगान को भी मालगुजारी के कुछ गुने के रूप में निश्चित कर देना लाभदायक सिद्ध होगा।

अधिकतम सीमा

सबसे बढ़कर जरूरी बात यह है कि अब और ज्यादा देर किये बगैर सभी राज्यों में खेती की आराजियों की अधिकतम सीमा निश्चित कर दी जाय। पहली पंचवर्षीय योजना में इस सिद्धान्त का सुझाव दिया गया था कि कोई व्यक्ति अधिक से अधिक जितनी जमीन अपने कब्जे में रख सकता है, उसकी निरपेक्ष सीमा निश्चित कर दी जानी चाहिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजनामें आराजियों की अधिकतम सीमा निश्चित करने के सम्बन्ध में कुछ विशेष सुझाव दिये गये हैं। योजना में जो छूटें दी गयी हैं, वे भी काफी उदार हैं। इसलिए, यह डर नहीं होना चाहिए कि आराजियों की अधिकतम सीमा लागू कर देने से कुल खेती की उपज घट जायगी। बहुत से देशों में प्राप्त तजुरबों से साफ-साफ पता चलता है कि जमीन की औसत पैदावार आराजियों के आकार के अनुमान से नहीं बढ़ती। बड़े-बड़े

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

फार्मों पर मशीनी खेती से प्रति एकड़ उपज नहीं बढ़ती; उससे तो केवल श्रम की प्रति इकाई उत्पादन-क्षमता ही बढ़ती है। इसलिए यह सोचना गलत है कि योजना के सुझावों के अनुसार, आराजियों की अधिकतम सीमा निश्चित कर देने से जमीन की उत्पादकता घटने लगेगी। दरअसल, जमीन की आराजियों का फिर से बंटवारा कर देने और साथ साथ ही गहन-खेती के मुख्तलिफ तरीकों को अपनाने से भारत में खेती की कुल उपज निश्चित रूप से बढ़ेगी। इसलिए, राज्य सरकारों को चाहिए कि वे गंभीरता के साथ साथ आराजियों के सवाल को हाथ में लें और बिना हिचक या सन्देह के जरूरी कानून तैयार करें।

सहकारी खेती

भारत में सहकारी खेती के गुण-दोषों के संबंध में काफी विवाद रहा है। अब आम तौर पर यह विश्वास किया जाता है कि खेती की मुख्तलिफ प्रक्रियाओं में सहकारी आन्दोलन चालू कर देने से भारतीय किसानों को बहुत फायदा होगा। मिसाल के लिए, हमें जोताई, निराई, कटाई, सिंचाई, क्रय-विक्रय और खाद के इस्तेमाल में सहकारी तरीकों को लागू करना चाहिए। किन्तु यह जरूरी नहीं कि बड़े-बड़े सहकारी फार्मों के रूप में जमीन के बड़े-बड़े टुकड़ों को एकत्र किया जाय। जैसा कि हमने पहले कहा है, फार्म या आराजी के आकार के साथ-साथ जमीन की उत्पादकता भी अनिवार्य रूप से बढ़ती नहीं। इसके विपरीत, खेती की अपेक्षाकृत बड़ी इकाईयों पर प्रति एकड़ उपज घटने लगती है। इसलिए यह बहुत ही वांछनीय है कि सहकारिता के सिद्धान्तों का पूरा-पूरा उपयोग करते हुए हम अपने देश में खेती के गहन तरीके लागू करें। युगों से अत्यधिक व्यक्तिवाद भारतीय जीवन को विषाक्त करता रहा है। हमारे लिये यही उचित है कि हम एक दूसरे के फायदे के लिए एक दूसरे की मदद करने के सिद्धान्त को ग्रहण करें और व्यवहार में लायें।

विश्व में चावल की खेती

चावल भारत और संसार के अन्य अनेक देशों का मुख्य खाद्य पदार्थ है। युद्ध और उसके परवर्ती काल में खाद्य अन्न का संकट जिस भीषणता के साथ फैल गया था, उससे सम्पदा के पाठक कम परिचित नहीं हैं। किन्तु इसीलिए संसार के नेताओं का ध्यान इस ओर गया। सं० राष्ट्र संघ के नेतृत्व में फुड एण्ड एग्रीकल्चरल आर्गेनाइजेशन (एफ० ए० ओ०) की स्थापना की गई थी। इसकी ओर से कृषि-उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत प्रयत्न किए गये। यह संतोष की बात है कि कृषि-उत्पादन पहले की अपेक्षा बढ़ता जा रहा है। एफ० ए० ओ० की नई रिपोर्ट में चावल के उत्पादन पर बहुत अच्छा प्रकाश डाला गया है।

रूस को छोड़कर शेष संसार में चावल का उत्पादन १९५४ में १८८३ लाख टन था। परन्तु १९५५ में यह बढ़कर १९९२ लाख टन हो गया। आज भी एशिया विश्व का सबसे बढ़कर चावल का उत्पादन क्षेत्र है। १९५४ में एशिया में कुल ९९७ लाख टन चावल पैदा हुआ था, जबकि १९५५ में यह बढ़कर १०६२ लाख टन हो गया। चीन, उत्तरी कोरिया, वीतनाम में उत्पन्न चावल की इसमें गणना नहीं की गई। चीन में भी चावल की खेती लगातार बढ़ रही है। एक अनुमान से १९५४ और १९५५ में चावल क्रमशः ७०९ लाख टन और ७५२ लाख टन पैदा हुआ था, जबकि १९३४-३६ में ५०५ लाख टन पैदा हुआ था। एशिया के बाद दक्षिणी अमेरिका का उत्पादन में स्थान है। यहां १९५५ में ५२ लाख टन चावल पैदा हुआ था। अफ्रीका में उक्त दोनों वर्षों में क्रमशः ३८ लाख और ४२ लाख टन चावल पैदा हुआ। यूरोपियन देशों में कोई वृद्धि नहीं हुई और १९५४ व १९५५ में दोनों वर्षों में १७ लाख टन चावल उत्पन्न हुआ। उत्तरी अमेरिका में चावल का उत्पादन ३६ लाख टन से गिर कर ३२ लाख टन रह गया, क्योंकि वहां कृषि क्षेत्र में काफी कमी कर दी गई थी।

चावल के उत्पादन की एक मुख्य समस्या प्रति एकड़

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उपज बढ़ाने की है। इस दिशा में भी कुछ प्रगति की गई है। चावल की खेती के नये सुधारे हुए तरीके काम में लाये जाने लगे हैं। भारत में ही जापानी कृषि-पद्धति का उपयोग किया गया है। १९५२-५३ में कुल ४ लाख एकड़ भूमि में यह पद्धति अपनाई गई थी, जबकि १९५३-५४ में १३ लाख एकड़ और १९५५-५६ में २१ लाख एकड़ में इसे अपनाया गया। इस कृषि के परिणामस्वरूप प्रति एकड़ १७.३ मन धान या ११.५६ मन चावल प्रति एकड़ होने लगा है। ख्याल यह है कि इस योजना के अन्त तक ४० लाख एकड़ में इस पद्धति का प्रयोग होने लगेगा।

कृषि के नए तरीकों से विश्व में चावल की उपज बढ़ी है। १९५४ में प्रति हैक्टर (२.४७ एकड़) १४.९ क्विण्टल (१०० पौंड या १ मन ९ सेर के करीब) चावल पैदा हुआ था। १९५५ में औसत १५.६ क्विण्टल चावल पैदा हुआ। लेकिन अनेक देशों में चावल की पैदावार बहुत अच्छी होती है, जैसा कि तालिका से प्रकट होगा।

	प्रति हैक्टर पैदावार (क्विण्टल)	प्रति एकड़ पैदावार पौण्डों में
मिश्र	५१.९	२१०१.२
स्पेन	५९.५	२४०८.१
इटली	५१.०	२०६४.८
फ्रांस	४१.४	१६७६.१
सं० रा० अमेरिका	३२.९	१३३२.०
जापान	४८.१	१९४७.४
निम्नलिखित देशों में उपज बहुत कम होती है—		
भारत	१२.८	५१८.२
बरमा	१४.८	५९९.२
स्याम	१४.३	५७८.९
पाकिस्तान	१३.४	५४२.५
ब्राजिल	१६.४	७७३.१

बरमा में चावल की प्रति एकड़ उपज कम होने पर भी वह चावल के निर्यात द्वारा बहुत रुपया पैदा करता है। उसने १९५६ में अपनी कुल पैदावार का ४८ प्रतिशत निर्यात किया। अन्य देशों का उपज निर्यात अनुपात इस तरह है। आस्ट्रेलिया ७१ प्रतिशत, इटली ५५, मिश्र २७, सं० रा० अमेरिका ५९ और स्याम २३।

विश्व में चावल का निर्यात व्यापार भी बढ़ रहा है। १९५१ में ४६ लाख टन का कुल निर्यात हुआ था, जबकि १९५१ में यह बढ़कर ५१ लाख टन हो गया।

पाकिस्तान में चावल की खेती की उन्नति होने की बजाय अवनति ही हुई है। पाकिस्तान पहले चावल निर्यात करता था। १९५५ में निर्यातक देशों में उसका स्थान ४ था या ५ वां था, पर १९५६ में उसने निर्यात सर्वथा बन्द करके सं० रा० अमेरिका से ६१०००० टन चावल मंगाने की व्यवस्था की है।

भारत में चावल के मूल्य बहुत बढ़ गए हैं। इस लिए भारत सरकार विदेशों से प्रभूत मात्रा में चावल लेने की व्यवस्था कर रही है। बरमा से ५ वर्षों में २०

खेती और ट्रैक्टर

मैं नहीं चाहता कि ट्रैक्टरों से खेती करने के तरीके बतलाये जायें। मैं ट्रैक्टरों का विरोध नहीं करता; लेकिन ट्रैक्टरों से बहुत सी कठिनाइयाँ हो सकती हैं। ऐसे ही साधनों को काम में लेने से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है जिन्हें गरीब से गरीब किसान काम में ला सकें।

—जवाहरलाल नेहरू

लाख टन चावल मिलेगा। १९५७ में ही ५ लाख टन चावल मिलने की सम्भावना है। इस वर्ष सं० रा० अमेरिका से २ लाख और चीन से ६०००० टन चावल मिलने की संभावना है।

यद्यपि अमेरिका इटली व स्पेन अपनी चावल कृषि के क्षेत्र को कम कर रहे हैं, तथापि १९५७ में चावल की स्थिति खराब होने की संभावना नहीं है। आन्तरिक संकट से निवृत्त होकर कम्बोडिया, वीतनाम भी इस वर्ष चावल का निर्यात करेंगे। मिश्र अपनी पैदावार बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है। चीन भी, जो संसार में चावल सबसे अधिक पैदा करता है, अपनी पैदावार बढ़ाने में लगा हुआ है। लेकिन इसके साथ प्रति वर्ष खाने वाले मुख भी बढ़ते जा रहे हैं। भारत में प्रति वर्ष ५० लाख नागरिक बढ़ जाते हैं।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उत्पादन के नये लक्ष्य

विकास आयुक्तों का सम्मेलन

गत मास के अन्तिम सप्ताह में मसूरी में विकास आयुक्तों के सम्मेलन में कृषि उत्पादन पर विशेष रूप से विचार हुआ है। इसमें दो बातों पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। एक तो यह कि कृषि का उत्पादन इन पांच वर्षों में दुगुना कर दिया जाये और दूसरा यह कि कृषि की पद्धति में सहकारिता की संस्था को अपनाया जाय।

अगले तीन वर्षों में राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक विकास खण्डों में कृषि उत्पादन की वृद्धि, सिंचित इलाकों में ५० प्रतिशत तथा ३० इंच से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ३० प्रतिशत होनी चाहिए। यह वृद्धि केवल गेहूं और चावल में नहीं बल्कि अन्य सब कृषि उत्पादनों में भी की जानी चाहिए।

इस सम्मेलन में इस बात को भी सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया कि भूदान और ग्रामदान दोनों को यथा सम्भव पूरी सहायता और प्रोत्साहन दिया जाये।

नेहरू जी के विचार

सदा की भांति प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रश्न का निर्धारण करते हुए पं० जवाहरलाल नेहरू ने एक महत्व पूर्ण भाषण दिया। उन्होंने जो कुछ कहा, उसका आशय निम्नलिखित है :—

मुझे कोई कारण नहीं दीखता कि देश में कृषि-उत्पादन दुगुना क्यों नहीं हो सकता, जबकि अन्य देशों में उच्चतर उत्पादन हो रहा है।

वैज्ञानिक तरीकों का इतनी तेजी के साथ विकास हो रहा है कि यदि भारत ने सहकारी खेती के तरीके को नहीं अपनाया तो वह प्रगति की दौड़ में पीछे पड़ जायगा। सहकारी खेती निश्चित लक्ष्य है और योजना आयोग ने स्पष्ट शब्दों में एक राय से यह निर्धारित कर दिया है।

ग्रामदान में प्राप्त गांव सहकारी खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं, क्योंकि इन इलाकों में निजी स्वामित्व से उत्पन्न होने वाली समस्याएं सामने नहीं आएंगी। सहकारी खेती का विचार तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम में निहित है और वह देहाती इलाकों की नई आकांक्षाओं का आधार है।

केन्द्रीकरण का कुछ बुरा प्रभाव भी पड़ता है और निजी पहल में बाधा पड़ती है। सहकारिता ही इससे बचने का एकमात्र तरीका है।

ग्रामदान में प्राप्त गांवों की भूमि को पुनः ग्रामीणों में बांट देने तथा सहकारी प्रबन्ध के लिए सिर्फ १० प्रतिशत भूमि रखने के विचार के पक्ष में मैं नहीं हूं।

●

खाद्यान्नों का उत्पादन

अस्थायी अधिकृत आंकड़ों के अनुसार १९५६-५७ में चावल, गेहूं और अधिकांश व्यापारिक फसलों का उत्पादन नए उच्च स्तर का हुआ है।

चावल का उत्पादन १९५१-५२ में २ करोड़ १० लाख टन था, जो कि अब १९५६-५७ में २ करोड़ ८१ लाख टन हो गया है। इसी अवधि में गेहूं का उत्पादन २८ लाख टन बढ़ा है। मोटे अनाज में भी ४० लाख टन से अधिक वृद्धि हुई है।

व्यावसायिक फसलों में जूट का उत्पादन १९५२-५३ की तुलना में ४ लाख गाँठ कम हो गया है। कपास का उत्पादन १९५६-५७ में ४८ लाख गाँठ हो गया, जब कि पूर्व वर्ष में यह ४० लाख गांठ था। गन्ने के उत्पादन में भी १९५५-५६ की तुलना में ४० लाख टन की वृद्धि हुई। तिलहन का उत्पादन पहले की तरह १८ लाख टन रहा।

●

भूदान आन्दोलन और नेहरू

मैं भूदान आन्दोलन का स्वागत करता हूं और एक तरीके से उसे सहानुभूति द्वारा प्रोत्साहन देने की कोशिश करता हूँ, परन्तु प्रधानमंत्री की हैसियत से लोगों से जा कर यह कहना बेहूदा मालूम पड़ता है कि वे अपनी भूमि दान में दे। लेकिन मैं आचार्य विनोबा भावे की इस बात से सहमत हूं कि भूमि पर जनता का समान रूप से अधिकार हो।

★

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विदेशी अर्थ-चर्चा—

विश्व आर्थिक सम्मेलन

१३५५ की गर्मियों में संयुक्त राष्ट्र संघ के दसवें अधिवेशन में सोवियत संघ द्वारा विश्व आर्थिक सम्मेलन करने का सुझाव पेश किया गया था। सोवियत सरकार का विश्वास है कि विश्व आर्थिक सम्मेलन अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के लिए लाभप्रद होगा। इस प्रस्तावित सम्मेलन में निम्नलिखित जीवन्त समस्याओं पर विचार-विमर्श होगा :

(१) विश्व व्यापार का विकास करना तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे के अन्तर्गत विश्व व्यापार एजेंसी का निर्माण करना।

(२) अल्पविकसित देशों के अन्दर स्वतंत्र राष्ट्रीय अर्थतंत्रों के निर्माण में सहायता पहुंचाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग करना।

(३) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय और ऋण सम्बन्धी समस्याएं।

पश्चिम में कुछ ऐसे प्रभावशाली क्षेत्र हैं, जो यह अनुभव करते हैं कि राष्ट्रों के बीच आर्थिक सहयोग के ऊपर अभी विचार विमर्श करना 'असामयिक' है। बढ़ती हुई अन्तर्राष्ट्रीय तनातनी को दृष्टिगत रखते हुए शांतिपूर्ण व्यापार और ऋण सम्बन्धी सुविधाओं, तथा चीजों के निर्यात की समस्याओं पर विचार करना भी अव्यावहारिक और अलाभकारी होगा। उनका यह विचार है कि विभिन्न सामाजिक पद्धतियों वाले देशों के बीच व्यापार और ऋण-सम्बन्धी सौदा आर्थिक दृष्टि से लाभकर नहीं हो सकेगा। लेकिन तथ्य बताते हैं कि सोवियत संघ के साथ व्यापार करने में "सम्भावनाओं के अभाव' की आशंका निराधार है। हाल के वर्षों में सोवियत संघ में समाजवादी उत्पादन के विकास के साथ-साथ समानान्तर रूप में सोवियत वैदेशिक व्यापार का विकास हुआ है, जिसका परिमाण इस समय २५ अरब रूबल है। असाम्यवादी देशों के साथ सोवियत व्यापार का परिमाण पांच अरब पचास करोड़ रूबल के बराबर है। लेकिन निश्चय ही यह अंतिम सीमा नहीं है। पिछले वर्ष के दौरान में सोवियत संघ ने पश्चिमी शक्तियों से बारम्बार यह प्रस्ताव किया कि व्यापार की मात्रा वर्तमान स्तर की तुलना में चार पांच गुना बढ़ा दी जाए। ११ फरवरी १९५७ को पेरिस में हस्ताक्षरित फ्रांसीसी-सोवियत व्यापार समझौता इसका अच्छा उदाहरण है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार की मात्रा १९५९ तक १९५६ के स्तर की तुलना में तीन गुनी बढ़ जाएगी। यदि राजनीतिज्ञ शासक बाधाओं की प्रणाली न खड़ी करते और विभेदमूलक प्रतिबन्धों की तालिका न बनाते तो फ्रांसीसी-सोवियत व्यापार की सम्भावनाएं और भी अधिक अनुकूल होतीं। अब असाम्यवादी देश भी यह महसूस करने लगे हैं कि साम्यवादी देशों की मंडी में माल की बिक्री के लिए अपरिमित सम्भावनाएँ हैं और वह किसी प्रकार के आर्थिक चढ़ाव-उतार पर निर्भर नहीं करतीं। इसलिए उन्होंने उन देशों के साथ अपने आर्थिक सम्बन्धों का विस्तार करना आरम्भ कर दिया है। चीनी लोक जनतंत्र तथा ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मन प्रजातंत्र, हालैंड, नार्वे तथा अन्य देशों के बीच व्यापार बढ़ रहा है। अमेरिकी व्यापारी भी महसूस करने लगे हैं कि परम्परागत चीनी-अमरीकी व्यापारिक सम्बन्धों के भंग हो जाने से उन्हें बहुत असुविधाएं हो रही हैं।

अल्प विकसित देशों के लिए विश्व-आर्थिक सम्मेलन ही बहुत लाभकारी होगा। विश्व-आर्थिक सम्बन्धों के मौजूदा विघटन तथा प्रतिबन्धमूलक रुकावटों का असर इन देशों के अर्थतंत्रों के ऊपर पड़ रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय इजारेदारियां अल्प विकसित देशों से कच्चे माल कम कीमत पर खींच रही हैं और उनके हाथ अपने माल बेतरह चढ़ी हुई दरों पर बेच रही हैं।

[शेष पृष्ठ २८३ पर]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नया सामयिक साहित्य

कब तक पुकारूं (उपन्यास)—लेखक—श्री रांगेय राघव, पृष्ठ—६६०, मूल्य—८ रु०, प्रकाशक—राजपाल एण्ड संस, काश्मीरी गेट, दिल्ली।

श्री रांगेय राघव ने हिन्दी कथा (उपन्यास) साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान बना लिया है। अब तक उनके दर्जन से ऊपर छोटे-बड़े उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं पर उनके इस नवीनतम उपन्यास की अपनी एक विशेषता है। समाज के निम्न वर्गों—दलितों या उपेक्षितों—को लेकर कई उपन्यास लिखे जा चुके हैं, लेकिन निम्न वर्ग से भी निकृष्ट समझा जाने वाला एक और वर्ग जरायम पेशा वालों का वर्ग भी है। संभवतः इस पर सर्वप्रथम कलम चलाने का प्रयत्न इसी उपन्यास में हुआ है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के ८-१० साल पहले से लेकर और इसके १-२ वर्ष बाद के बीच की कालावधि में इस वर्ग का पूर्ण चित्र अपनी यथार्थता को लेकर अङ्कित हुआ है। यह चित्र हमें इस वर्ग के प्रति संवेदनशील बनाते हुए 'कुछ सोचने' को विवश करता है। इस सफलता का रहस्य यह भी है कि राजस्थान के इन करनटों के बीच में रह करके लेखक ने उनकी बारीकियों को समझा है। उपन्यास में इसी कारण ' 'राजस्थानी रंगत' भी आ गई है।

कथानक में गति है, प्रवाह है, वह रोचक और हृदय-स्पर्शी है। घटनाएं सुलझी हुई हैं। कथानक की सबसे बड़ी विशेषता, इस ६६० पृष्ठ के भीमकाय उपन्यास की घटनाओं की एकता का है। सुखराम की कथा ही मुख्य कथानक है। अन्य समस्त प्रासंगिक घटनाएं उसे तीव्रता प्रदान करने में सहायक हैं। नरेश की कथा अलग सी मालूम पड़ती है। परन्तु वह भी एक प्रकार से सुखराम की कथा का "अन्त" ही है। कथानक का नायक सुखराम है, जो अपने वर्ग का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है, उसकी दोनों पत्नियां, प्यारी और कजरी नायिकाएं हैं। प्रेम, त्याग, कष्ट-सहन, प्रत्युत्पन्नमति आदि उनके गुण हैं। दोनों उपन्यास की घटनाओं को 'रस' देती हैं और जब उपन्यास की घटनाओं से अलग होती हैं— संसार से ही विदा ले लेती हैं तो वातावरण करुण-वेदनामय हो जाता है। दोनों उस फूल की तरह हैं जो खिलते हास्य बखेरते हैं, लेकिन मुरझाते गंभीर अवसाद।

करनट जाति के अन्य प्रतिनिधि इसीला, मंगू, सोनी आदि हैं। इन्हीं के साथ शोषित और पददलित चमार स्त्री-पुरुष भी आते हैं। अत्याचारियों व शोषकों के रूप में दरोगा, रुस्तमखां आते हैं। उनके आसरे पर चलने वाले जुआरी, शराबी व पापी बांके का भी परिचय मिलता है। अंगरेज पौलिटिकल एजेण्ट और उसकी लड़की सूसन के भी दर्शन इसमें होते हैं। इन सबकी अपनी विशेषताएं हैं।

भाषा सरल है, पात्रानुकूल है। उपन्यास के पात्र जिस श्रेणी के हैं, उनका मानसिक और बौद्धिक धरातल जितना है, भाषा उस सीमा से आगे नहीं बढ़ी है। पात्रों की भाषा 'स्थानीय रंगत' देने में सहायक है। हां स्वतन्त्र स्थलों में जहां लेखक को स्वतन्त्रता मिली है, वहां मनोरम काव्यमयी भाषा लिखने का लोभ लेखक संवरण न कर सका।

उपन्यास में प्रेम और करुणा की गंगा-जमुना बही है। अद्भुतता के भी दर्शन होते हैं। 'पुराना किला' से तो देवकीनन्दन खत्री के तिलस्म की याद आती है।

लेकिन एक बात यह है कि लेखक ने अन्त में उपन्यास का नाम 'कब तक पुकारूं' पसन्द किया। क्यों? यह स्पष्ट नहीं होता। कथानक के घटना क्रम को देखते हुए इसका पहला नाम 'अधूरा किला' ही उपयुक्त जान पड़ता है, प्रत्येक अध्याय में घटनाएं उत्कर्ष को पहुंचती हुई हर समय इस 'अधूरा किला' को छूती जाती हैं।

—म० मो० चि०

—

गुरुकुल पत्रिका—(श्रद्धानन्द जन्मशताब्दि विशेषांक) प्रकाशक—गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार, मूल्य—७५ नये पैसे।

प्रस्तुत विशेषांक स्वामी जी की जन्मशताब्दि पर प्रकाशित किया गया है। इसमें स्वामी जी के सम्बन्ध में जहां अनेक सुन्दर लेख हैं, वहां उनके जीवन सम्पर्क में आने वाले महानुभावों के संस्मरण बहुत ही मनोरंजक तथा स्वामी जी के जीवन पर प्रकाश डालने वाले हैं।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कारखाना बन्द होने पर भी मुआवजा

श्रम समस्या

इस मास में श्रमिकों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समाचार यह है कि भारत सरकार ने एक अध्यादेश जारी करने का निश्चय किया है कि किसी कारखाने के बन्द होने या हस्तान्तरण करने की स्थिति में भी छंटनी किये जाने वाले कर्मचारियों को मुआवजा दिया जायगा। इस अध्यादेश से पश्चिम बंगाल, कानपुर और अहमदाबाद में छंटनी से आतंकित या छंटनीशुदा लगभग बीस हजार कर्मचारियों को लाभ होगा। यह दिसम्बर १९५६ से कार्यकारी माना जाएगा।

सम्पदा के पाठक जानते हैं कि इस अध्यादेश की इसलिए आवश्यकता पड़ी है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने गत नवम्बर में यह निर्णय दिया था कि औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ के २५ वें अनुच्छेद के अन्तर्गत उन कर्मचारियों को छंटनी का कोई मुआवजा नहीं दिया जा सकता जिनकी सेवा, किसी मालिक ने अपना कारखाना बन्द करके या कारखाने का स्वामित्व किसी अन्य व्यक्ति को सौंप कर, समाप्त कर दी है।

जब से सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय दिया है, तब से कई कारखाने, खास कर अहमदाबाद, कानपुर और पश्चिम बंगाल के कारखाने बन्द हो गए हैं, या उन्होंने बन्द होने का नोटिस दे दिया है, जिससे लगभग बीस हजार कर्मचारी बेकार हो गए हैं।

इस स्थिति से सरकार को गम्भीर चिन्ता हो गई क्योंकि सरकार का कहना था कि जब १९५३ के अक्तूबर में औद्योगिक विवाद अधिनियम में छंटनी के लिए मुआवजे की व्यवस्था की गई थी, तो उसका उद्देश्य यह था कि कारखाना-बन्दी को रोका जाए, और जहां यह सम्भव न हो, वहां छंटनीशुदा कर्मचारियों को मुआवजा दिलाया जाए, ताकि किसी और जगह काम तलाश करने तक कर्मचारी अपना गुजारा कर सकें।

प्रस्तावित अध्यादेश में यह बात स्पष्ट कर दी जाएगी कि जब किसी कारखाने को बन्द करना हो तो कर्मचारियों को छंटनी का मुआवजा मिलेगा और २५वें अनुच्छेद के अन्तर्गत छंटनी का नोटिस दिया जाएगा। तथापि यदि अनिवार्य कारणों से कारखाना बन्द करना ही पड़े तो मुआवजा तीन मास के औसत वेतन तक सीमित रहेगा।

इमारतें, पुल और बांध जैसे निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में अध्यादेश में संभवतः यह व्यवस्था होगी कि यदि काम दो वर्ष के अन्दर-अन्दर पूरा हो गया, तो कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में जो निर्णय दिया था, वह निम्नलिखित है :—

"छंटनी का सामान्य अर्थ यह है कि व्यापार तो जारी

स्वामी जी के ५०-६० साल पहले लिखे गए पत्र इस विशेषांक की एक विशेषता है, जो अन्यत्र नहीं पाई जाती। यदि इस अंक में स्वामी जी के चित्र (हाफटौन ब्लोक) ज्यादा दिए जाते, तो यह अधिक आकर्षित हो जाता।

—

श्री विश्वविजय पञ्चागम्—सम्पादक—श्री हरदेव शर्मा त्रिवेदी, प्रकाशक—गोयल ब्रादर्स, दरीबा कलां, दिल्ली, मूल्य १४ आने।

गत १२ वर्षों से उत्तर भारत में दृक् पक्षीय शुद्ध पंचांग और दैनिक स्पष्ट ग्रह की परम्परा जारी रखते हुए यह पंचांग प्रकाशित हो रहा है। विद्वान सम्पादक ने प्रस्तुत पंचांग में उसी सूक्ष्म गणित को स्वीकार किया है जिसे भारत सरकार द्वारा नियत समिति ने स्वीकार किया है, यद्यपि उक्त समिति के सब नये परिवर्तनों से वे सहमत नहीं हैं।

पंचांग की तिथि गणना के अतिरिक्त ज्योतिष से सम्बन्धित बीसियों ऐसी सूचनाएं इसमें दी गई हैं जो ज्योतिष पर विश्वास करने वालों के लिए उपयोगी हैं। दैवज्ञ की दृष्टि में संसार-चक्र इस पंचाङ्ग की एक विशेषता रही है। हमें आशा है कि इस पंचांग से जनता लाभ उठायेगी।

—

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

है किन्तु कुछ मजदूर और कर्मचारी अतिरिक्त माने जाकर निकाल दिये जायं। पर व्यापार बन्दी के फलस्वरूप समस्त मजदूरों की नौकरी की समाप्ति इस कारण उचित रूप से छंटनी नहीं मानी जा सकती। हालांकि छंटनी और व्यापार-बन्दी, दोनों में मजदूर नौकरी से निकाले जाते हैं, कानून के अनुसार मुआवजा केवल छंटनी के समय दिया जायगा और यदि यह मान लिया गया कि छंटनी का अर्थ है सामान्य अतिरिक्त मजदूरों को निकालना, तो उसमें व्यापार बन्दी के कारण निकाले गये मजदूर शामिल नहीं हो सकते।"

बीमा कर्मचारियों के विरुद्ध अध्यादेश

एक ओर सरकार अध्यादेश जारी करके मजदूरों को मिलों के बन्द होने की स्थिति में भी मुआवजा दिलाना चाहती है, दूसरी ओर स्वयं हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध कर्मचारियों के वेतन कम कर सकने का अधिकार प्राप्त कर रही है। बम्बई हाईकोर्ट ने एक निर्णय द्वारा बीमा कारपोरेशन को यह अधिकार देने से इन्कार कर दिया था कि वह बीमा कर्मचारियों के वेतन एकरूपता के नाम पर कम कर दे। कारपोरेशन में बीमा कर्मचारियों के वेतन संबंधी जो नियम प्रकाशित किये थे, उनसे बहुत से कर्मचारियों के वेतन कम हो जाते थे। उन्होंने इसके विरुद्ध अपील की थी। हाईकोर्ट ने उनकी मांग स्वीकार कर ली। इस निर्णय से सरकारी बीमा कारपोरेशन की स्थिति संकटपूर्ण बन गई थी। भारत सरकार ने एक आर्डिनैंस जारी करके कारपोरेशन को वेतन निर्धारित करने का अधिकार दे दिया है। इससे कर्मचारी अपने वेतन कम करने के विरोध में कोई कानूनी कार्यवाही न कर सकेंगे। इस अध्यादेश के कारण सरकार को न केवल जीवन बीमा कर्मचारियों के वेतनों में, बल्कि सर्विस की शर्तों में भी परिवर्तन का अधिकार मिल गया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगमों ने यह निश्चय कर लिया है कि बीमा शुदा व्यक्तियों के परिवारों को भी डाक्टरी सहायता दी जाए।

मुकदमे के लिए अपील

कोयले की खान मालिकों ने अपीलेट ट्रिब्यूनल के एक निर्णय के विरुद्ध अपने एक महत्वपूर्ण मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी है और श्री सीतलवाद को अपना वकील नियत किया है। सुप्रीम कोर्ट उस पर जो निर्णय देगा, वह बहुत महत्वपूर्ण होगा और उस पर कोयला-खनिकों का भविष्य निर्भर करेगा। इसलिए इन्टक ने उसके विरुद्ध मुकद्दमा लड़ने का निश्चय किया है। किन्तु इसके लिए बहुत रुपये की आवश्यकता है। ३-४ हजार रुपया प्रतिदिन व्यय होने की सम्भावना है। १०-१२ दिन भी मुकद्दमा चला, तो ५०,००० रु० व्यय हो जायगा। राष्ट्रीय खान मजदूर फैडरेशन ने इसके लिए मजदूरों से रुपये की अपील की है। यदि फैडरेशन जीत गया तो खान मजदूरों को पिछले बकाया के रूप में ही १॥-२ करोड़ रु० मिलेंगे और न्यूनतम वेतन ५० रु० हो जायगा।

केरल में 'इन्टक' की स्थिति

केरल में कम्युनिस्ट शासन स्थापित होने के साथ ही राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के लिए समस्या उत्पन्न हो गई है। कम्युनिस्टों का भारत सरकार पर यह आरोप रहा है कि वह रा० म० कां० के साथ पक्षपात करती है। अब उन्हें मौका मिला है कि एक राज्य की सरकार का वे भी पूर्ण समर्थन प्राप्त करें। केरल के श्रम मंत्री श्री टी० वी० थामस ने घोषणा की है कि सरकार ऐसा कानून बनायेगी कि एक उद्योग में एक ही संगठन हो। केरल में साम्यवादी शासन स्थापित होते ही रा० म० कांग्रेस से सम्बद्ध मध्य त्रावनकोर की ईस्टर्न स्टेट वर्कर्स यूनियन के कार्यालय पर साम्यवादियों की एक भीड़ ने सशस्त्र आक्रमण कर दिया। वहां के फर्नीचर को तोड़ डाला गया और अब वहां अधिकार कर लिया। किसी मजदूर को वहां जाने नहीं दिया जाता।

———

सफ़ेद कोढ़ के दाग

हजारों के नष्ट हुए और सैकड़ों के प्रशंसापत्र मिल चुके

दवा का मूल्य ५) रु० डाक व्यय १) रु०

अधिक विवरण मुफ्त मँगाकर देखिये।

वैद्य के० आर० बोरकर

मु० पो० मंगरूलपीर, जिला अकोला (मध्य प्रदेश)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारतीय मसाले

काली मिर्च

गत विश्व-युद्धके बाद भारत से कालीमिर्च के निर्यात से प्रति-वर्ष लगभग २३ करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा प्राप्त कर रहा है। जिन व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात से भारत को सबसे अधिक डालर प्राप्त होते हैं, उनमें एक काली मिर्च भी है। युद्ध से पहले देश में प्रति वर्ष १८,५०० टन काली मिर्च पैदा होती, पर १९५५-५६ में २६,००० टन पैदा हुई। इसके अलावा काली मिर्च के दाम भी युद्ध से पूर्व की अपेक्षा अब लगभग ३६ गुने हो गए हैं। यही कारण है कि अब काली मिर्च के निर्यात से अधिक विदेशी मुद्रा मिलने लगी है।

इण्डोनेशिया के बाद भारत में ही सबसे अधिक काली मिर्च पैदा होती है। ऐसे उपाय किये जा रहे हैं कि काली मिर्च का उत्पादन भी बढ़े और निर्यात भी, जिससे विदेशी मण्डियों में उसकी मौजूदा स्थिति बनी रहे।

दूसरी आयोजना में काली मिर्च के उत्पादन का लक्ष्य ३६,००० टन प्रतिवर्ष रखा गया है।

जो विकास-योजनायें बनायी गयी हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण कनानोर की योजना है, जो १९५५ में आरम्भ की जा चुकी है।

कनानोर-योजना के अन्तर्गत सारा पुनर्गठित केरल-राज्य आ जाएगा। देश में काली मिर्च के कुल उत्पादन का ९५ प्रतिशत इसी राज्य में होता है।

पश्चिम बंगाल, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, मैसूर आदि राज्यों में यह जांच की जा रही है कि उनमें काली मिर्च की खेती हो सकती है या नहीं। बम्बई में भी काली मिर्च के उद्योग का पुनर्गठन किया गया है।

राज्यों की आयोजनाओं में उक्त कामों के लिए १४ लाख ८० हजार रु० की व्यवस्था है।

काली मिर्च के अलावा इलायची, अदरक, हल्दी और लौंग, जायफल आदि वृक्षज मसालों का भारतीय अर्थ-व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है।

इलायची

भारत में इलायची की खेती का क्षेत्रफल लगभग १,२०,००० एकड़ है और उपज २,२५० टन है। इलायची उपजाने वाले राज्य हैं, मैसूर, केरल और मद्रास। १९५४-५५ में १,५३,७५,२२० रु० के मूल्य की ८९४ टन इलायची बाहर भेजी गयी थी। इलायची की मांग बढ़ती जा रही है और इसके उत्पादन और व्यापार के मामले में भारत को एकाधिकार प्राप्त है।

दक्षिण भारत की बढ़िया इलायची असम में भी उपजाने के सम्बन्ध में एक योजना शुरू की गई है।

अदरक

१९५५-५६ में अदरक की खेती का क्षेत्रफल ३५,४०० एकड़ और उत्पादन १४ हजार टन था। १९४८ में २ हजार टन अदरक का निर्यात किया गया था। १९५५ में २,८०० टन का निर्यात हुआ। इस प्रकार देश से बाहर भेजे जाने वाले अदरक का कुल मूल्य लगभग ६८,८५,५०६ रु० होता है।

अदरक की खेती के सम्बन्ध में पिछले ५ वर्षों से अम्बलवयल स्थित कृषि-गवेषणा केन्द्र में गवेषणा-कार्य किया जा रहा है। असम की खासी और जयन्तिया पहाड़ियों में नया बंगलो स्थान पर भी एक गवेषणा केन्द्र खोला गया है। अदरक सम्बन्धी तीसरा गवेषणा केन्द्र केरल में तोडुपुज्हा में खोला जायगा।

हल्दी

देश में हल्दी की खेती का क्षेत्रफल १,४२,४५५ एकड़ और उत्पादन १,२१,२१० टन है। आंध्र के गुन्टूर जिले में पेडुपलेम स्थान पर हल्दी की गवेषणा सम्बन्धी एक योजना चलायी जा रही है।

वृक्षज मसाले

वृक्षज मसालों में लौंग और जायफल का महत्वपूर्ण स्थान है। इनका उत्पादन अभी देश में बहुत कम होता है लेकिन उसे बढ़ाना जरूरी है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

फोन नं० : ३३१११

तार : माइनहोल्डर

मिनरल वैल्थ आफ इंडिया लिमिटेड

सब प्रकार के खनिज व धातुओं

के

व्यापारी तथा एक्सपोर्टर्स

खताऊ बिल्डिंग्स

४४ ओल्ड कस्टम हाउस रोड, फोर्ट, बम्बई

मैनेजिंग डायरेक्टर:—

श्री सी० डीडवानिया

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भुखमरी का रास्ता

प्रकृतिका यह नियम है कि भूमि के एक टुकड़े पर एक ही वस्तु, एक ही पदार्थ की खेती नहीं की जा सकती। ऐसा करने से भूमि की उत्पादन-क्षमता घट जाती है। इसी नियम की उपेक्षा करने के कारण दक्षिणी अमेरिका में भुखमरी की अवस्था उत्पन्न हो गई है। इसकी जिम्मेदारी व्यवसायियों की स्वार्थ वृत्ति पर है। सोने की खानों का पता लगाने, गन्ना उत्पादन करने, काफी उगाने और रबर प्राप्त करने के लिए भूमि को विनष्ट कर दिया गया है। इन सबका परिणाम यह हुआ कि जिस भूमि में एक समय सभी प्रकार के खाद्यों और फूल-फलों का उत्पादन विपुल मात्रा में होता था, आज वहां के निवासियों को भर पेट अन्न भी नहीं मिलता। फलदार वृक्षों को काट कर गन्ने की खेती की जा रही है, फूल-फल और साग सब्जी उगाने की सुविधा न होने, पशु-पालन के लिये संकट होने तथा गन्ने की खेती के कारण उर्वरा शक्ति क्षीण होने का दुष्परिणाम यह हुआ कि ऋतु-ऋतु में उत्पन्न होने वाले अनाज समय पर नहीं उगाये जा सकते हैं।

इतना होते हुए भी शोषक समुदाय ने बहुत बड़े-बड़े फार्म खड़े करके नकदी फसलें उगाने की योजना बना रखी है। जिसका निर्यात करके तुरन्त पैसा प्राप्त किया जाये। यदि यही ढंग जारी रहा, तो वहां न तो व्यवस्थित ढंग से खेती का विकास हो सकेगा और न लोगों के खाने के लिये अन्न ही प्राप्त होगा।

दक्षिणी अमेरिका के देशों की भूमि सम्बन्धित संग्रहित आंकड़े वस्तुस्थिति को स्पष्ट करते हैं—

अर्जेण्टाइना का ब्यूनर्स आयर्स प्रान्त में जिसकी जनसंख्या ३५ लाख है, केवल ३२० परिवारों के हाथ में प्रांत ४० प्रति शत भूमि है। दूसरे प्रांत सन्ताफे में १८९ बड़ी बड़ी जमींदारियां हैं और इनमें से प्रत्येक के पास औसतन ६२ हजार एकड़ भूमि है। देश का मध्य भाग सबसे अधिक उपजाऊ है और यहां धान की अच्छी खेती होती है। वह अधिकतर बड़े बड़े जमींदारों के हाथ में है क्योंकि प्रांत में ४३७ फार्मों में ही प्रांत की ८३ प्रति शत भूमि केन्द्रित हो चुकी है और शेष १७ प्रतिशत भूमि ५,९३७ छोटे-छोटे टुकड़े में बंटी है।

किसानों की हड़ताल नहीं होती!

एक दफा हमारी महाराजिन ने कह दिया कि हम आज रोटी बनाने नहीं आयेंगी! पचीस मेहमान आ गये थे। हमारा बेटा कहने लगा कि अगर तुम रोटी पकाने नहीं आओगी तो तुम्हारी तनख्वाह काट लेंगे। तब लड़के की माँ कहने लगी, उसकी तनख्वाह काटने से रोटी थोड़ी ही पकेगी। मैंने कहा, "तो अब क्या होगा?" वह कहने लगी, "मैं खुद आज रोटी बनाऊँगी।" तो जहाँ दूसरे का काम होता है, वहां हड़ताल हो सकती है। जहां अपना काम होता है, वहां हड़ताल नहीं हो सकती। आज तक दुनिया में किसानों की हड़ताल नहीं हुई, क्योंकि किसान अपना काम करता है। मजदूर की क्रांति की प्रक्रिया और किसान की क्रांति की प्रक्रिया एक नहीं हो सकती।

श्रीमानों को श्रमवान बनाना है

कम्युनिस्ट लोग हमें कहते हैं कि श्रीमानों से छीनना पड़ेगा। हम उनको कहते हैं कि अरे, उनके पास क्या लेने लायक है कि तुम उनसे छीनने की बात करते हो! उनके पास खाने-पीने की कोई चीज नहीं है! सिर्फ कागज के टुकड़े, लाल-पीले पत्थर और हीरे-मोती हैं। उसके सिवा "लक्ष्मी" तो उनके पास है ही नहीं, इसलिए उनका मत्सर करने की बात नहीं, उनका कुछ भी छीनने की बात नहीं है। उनके पास जो कुछ है, उनका मूल्य बदलने की बात है। जहां मूल्य बदल जायेंगे, वहां वे खत्म हो ही जायेंगे। फिर आज के बड़े-बड़े श्रीमान् बाबा के पास दरिद्री बन कर जमीन मांगने आयेंगे। बाबा उनको भी जमीन देगा। जब श्रीमान श्रमवान बनेगा, तब हम उसकी रक्षा करेंगे। हमारा धंधा श्रीमानों का मत्सर करना नहीं है, हम उनको श्रमिक बना कर श्रम की प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते हैं।

—विनोबा

(पापानायकनपट्टी, मदुरा)

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आदर्श ग्राम की मेरी कल्पना

एक आदर्श भारतीय गाँव इस ढंग से बनाया जायगा कि उसमें पूरी सफाई रखी जा सके। उसमें ऐसी कुटियां होंगी, जिनमें काफी हवा और रोशनी रहेगी और जो पांच मील के घेरे में प्राप्त होने वाली सामग्री से बनी होंगी। कुटिया में आंगन होंगे, जिनमें घर वाले घरू इस्तेमाल की सागभाजी उगा सकें और अपने मवेशी रख सकें। गांव की गलियों और रास्ते में यथासंभव धूल नहीं होगी। उसमें गांव की जरूरत के अनुसार कुएँ होंगे और उनसे सब पानी ले सकेंगे। वहां सबके लिए पूजा स्थान होंगे, एक आम सभा-स्थान होगा, पशु चराने के लिए एक सम्मिलित चरागाह होगा, एक सहकारी दुग्धालय होगा, प्राथमिक और माध्यमिक पाठशालाएं होंगी, जिनमें औद्योगिक शिक्षा मुख्य वस्तु होगी, और झगड़े निपटाने के लिए पंचायतें होंगी, वह अपना अनाज, अपनी सागभाजी, अपने फल और अपनी खादी आप तैयार कर लेगा। मोटे रूपमें आदर्श ग्राम की मेरी यह कल्पना है। —गाँधीजी

('हरिजन', ६-१-३७)

ग्रामवासी क्या करें ?

जहां पानी है, वहां कुछ ज्यादा काम होता होगा। नहीं तो खेती का काम छह महीने ही होता है और छह महीने बेकारी! दिन-ब-दिन जनसंख्या बढ़ रही है, तो हर आदमी के लिए जमीन का रकबा कम रहेगा। इस हालत में गांव तभी बढ़ेगा, जब कपड़ा हम तैयार करेंगे। इसके अलावा अनाज जमीन में से पैदा होता है। जमीन चंद लोगों के हाथ में रहे, यह नहीं होगा। तो आपको चार बातें करनी हैं:

(१) गांव की जमीन सबकी मानें।

(२) कपड़ा गांव में ही तैयार करना है।

(३) मक्खन, दूध, दही गांव के लोग, बच्चे खाएँ। उसे बेचना नहीं है।

(४) मनुष्य के मल-मूत्र का खाद तैयार करना है।

—आचार्य विनोबा

संचालक पंचायत राज विभाग उ० प्र०

की

विज्ञप्ति संख्या ४/५५८०/३३ : २७/५३, दिनांक १८

द्वारा

पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत

सुन्दर पुस्तकें

	लेखक	मूल्य रु०	मूल्य आ०
वेद सार	प्रो. विश्वबन्धु	१	८
प्रभु का प्यारा कौन ? (२ भाग)	,,		
सच्चा सन्त	,,		३
सिद्ध साधक कृष्ण	,,	०	३
जीते जी ही मोक्ष	,,	०	३
आदर्श कर्मयोग	,,	०	३
विश्व-शान्ति के पथ पर	,,	०	१
भारतीय संस्कृति	प्रो. चारुदेव	०	३
बच्चों की देखभाल	प्रिंसिपल बहादुरमल	१	१२
हमारे बच्चे	श्री सन्तराम बी. ए.	३	१२
हमारा समाज	,,	६	०
व्यावहारिक ज्ञान	,,	२	१२
फलाहार	,,	१	४
रस-धारा	,,	०	१४
देश-देशान्तर की कहानियां	,,	१	०
नये युग की कहानियां	,,	१	१२
गल्प मंजुल	डा० रघुवरदयाल	१	०
विशाल भारत का इतिहास	प्रो. वेदव्यास	३	८

१० प्रतिशत कमीशन और ५० रु० से ऊपर के आदेशों पर १५ प्रतिशत कमीशन।

विश्वेश्वरानन्द पुस्तक भंडार

—साधु आश्रम, होशियारपुर,

पंजाब

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

[पृष्ठ २५६ का शेष]

दीर्घकालीन आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर ही राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में हमें आगे चलकर कुटीर एवं लघु उद्योगों का स्थान रखना होगा। यह एक जटिल प्रश्न है जिसके समाधान के लिए समूचे राष्ट्र का मस्तिष्क लगा है। इस लेख की सीमा में यहां उनपर विचार करना सम्भव नहीं हो सकेगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आयोग ने कहीं यह स्पष्ट नहीं किया है कि लम्बी अवधि में इनका भाग्य क्या होगा।

अन्त में एक बात की ओर और ध्यान दिलाना है कि हैरड-डोमर (Harrod domar) पद्धति जिसका अध्ययन हमने ऊपर संक्षेप में किया है और जिसकी कसौटी पर हमारी, उद्योगों से सम्बन्धित नीति ठीक उतरती-सी जान पड़ती है वह एक परिपक्व (Matured) अर्थ-व्यवस्था के लिये अधिक उपयुक्त है जिसमें विकास का क्रम संतुलित ढंग से चलता है और उत्पादन आय बचत एवं विनियोग सम्बन्धी अनुपात बिल्कुल ठीक उतरते हुये लगभग सम (Constant) रहते हैं। इस पद्धति को या इस कला को भारत जैसे अर्ध विकसित क्षेत्र में लागू करते हुए हमें भूलना नहीं है कि हमारे यहां भोग एवं विनियोग सम्बन्धी उद्योगों का विकास असंतुलित ढंग से होता है (उपभोग की अपेक्षा विनियोग उद्योगों पर जोर अधिक है।) कुछ समय तक के लिये और इस बीच आय, बचत, विनियोग आदि के अनुपात में समय-समय पर पर्याप्त परिवर्तन होता रहेगा। इन परिवर्तनों के प्रति जागरूक होकर ही इस मंत्र का प्रयोग अपनी अर्थ-व्यवस्था को सँवारने के लिये कर सकते हैं।

References :

(1) First and Second Five Year Plan—Planning Commission, Government of India.
(2) New Horizons in Planning, by Alak Ghose, (Calcutta, Free World Press Private Ltd.)—1956.
(3) Planning for an Expanding Economy, by Vakil & Brahmanand—1956. (Vora & Co. Bombay, 2)
(4) Measures for the Economic Development of Underdeveloped Countries, by United Nations. Department of Economic Affairs —New York—1951.

हिन्दी और मराठी भाषा में प्रकाशित होता है।

उद्यम

सर्वोपयोगी हिन्दी उद्यम प्रतिमाह १५ तारीख को पहिले

धर्मपेठ, नागपुर

उद्यम के स्थायी स्तम्भ

उद्यम में निम्न विषयों पर लेख प्रकाशित होते हैं

★ लाभदायक उद्योगधन्धों की व्यावहारोपयोगी जानकारी, अनाज की खेती, साग-सब्जी की बागवानी और रोगों का निवारण। पशुपालन, दुग्ध-व्यवसाय और ग्रामोद्योग-सम्बन्धी लेख। आरोग्य, घरेलू औषधियों सम्बन्धी जानकारी।

★ महिलाओं तथा विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त विभिन्न रुचिकर खाद्य पदार्थ बनाने की विधियां। घरेलू मितव्ययता। जिज्ञासु जगत्। कृषि व औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों की मुलाकात और परिचय। नित्योपयोगी वस्तुएं घर पर ही तैयार कीजिये।

आज ही उद्यम का वार्षिक चन्दा ७ रु० भेजकर उद्यम मासिक मंगवाइये।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

[पृष्ठ २७४ का शेष]

विश्व-सम्मेलन में ऐसी महत्वपूर्ण ऋणीय एवं वित्तीय समस्याओं पर विचार-विमर्श छोटे और बड़े राज्यों के हित में होगा। अल्पविकसित क्षेत्रों के अर्थतंत्रों को सहायता पहुँचाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कोष का निर्माण विश्व आर्थिक सम्मेलन की बहुत बड़ी सफलता होगी। अन्ततः औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों के अनुभव, आर्थिक जानकारी का विनिमय, सभी देशों के समानाधिकार और प्रगतिशील प्रयास अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक संस्थान के ढांचे के अन्दर, जिसे विश्व आर्थिक सम्मेलन स्थापित कर सकता है, पूर्णतया प्राप्त किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संस्थान सम्बन्धी सीमित प्रस्तावों में बिना किसी अपवाद के सभी देशों के, चाहे वे संयुक्त राष्ट्र संघीय कार्यालयों में भाग लेते हों या नहीं, सम्मिलित होने की व्यवस्था है।

यदि आज शस्त्रास्त्र वृद्धि की बजाय हम परस्पर व्यापार अधिक बढ़ावें, तो उससे विश्वशान्ति का संभावना भी अधिक सुलभ और अधिक निकट हो जायगी।

मध्यपूर्व में तेल का संघर्ष

(श्री त्रियोगी नारायण वर्मा)

पश्चिमी एशिया में अशान्ति की जो आग स्वेज के पानी से भड़की थी, उसके बुझने के पहले ही अब तेल के कुओं से भयंकर विस्फोट होने के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। अप्रैल के तीसरे सप्ताह में जोर्डन में जो घटनाएं घटीं, उन्होंने इसका पूर्वाभास कर दिया है।

गत वर्ष अगस्त मास में ब्रिटेन और फ्रांस ने उत्साह से मिस्र पर हमला किया था। पर उनको एक सप्ताह में ही, रत्ती भर भी सफलता प्राप्त किये बिना ही, लड़ाई बंद कर देनी पड़ी। इसके अन्य कारण जो भी रहे हों, पर स्वयं उनकी आर्थिक परिस्थितियों ने उनको युद्ध बंद करने को मजबूर कर दिया। फ्रांस और इंग्लैंड में एक सप्ताह में ही पैट्रोल का बहुत बड़ा कमी हो गई थी। कहना न होगा, इन दोनों देशों को मुंह की खानी पड़ी। अब तक राजनैतिक और आर्थिक रूप में पश्चिमी एशिया पर जो कुछ भी इनका प्रभाव था, वह समाप्त हो गया। इसी प्रभाव के समाप्त होने को 'शक्ति-रिक्तता' कहा गया है। इसको सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय संयुक्त राज्य अमेरिका को है। "आइजन हौवर सिद्धांत" के रूप में अमेरिका ने पश्चिमी एशिया पर प्रभुत्व स्थापित करने की योजना बनाई। उसी में इसका प्रयोग किया गया है। अमेरिका, इसके अनुसार, पश्चिमी एशिया में अपना राजनैतिक, सैनिक और आर्थिक प्रभुत्व जमाना चाहता है। कौन नहीं कह सकता कि इस योजना में पश्चिमी एशिया के तेल पर भी अमेरिका की एकाधिकार स्थापित करने की भावना नहीं काम कर रही।

गत वर्ष से अमेरिका की तेल कम्पनियों की जो गतिविधियां हैं और वहाँ के समाचार पत्रों में जिस प्रकार के लेख प्रकाशित हुए हैं, उससे तो यहां तक ज्ञात होता है कि 'आइजन हौवर के सिद्धान्त" का मूलाधार ही 'तेल' है। पिछले अक्तूबर के महीने में केलीफोर्निया की स्टैंडर्ड आइल कम्पनी के अध्यक्ष श्री फौलिस ने राष्ट्रपति आइजनहौवर से पश्चिमी एशिया में इस तेल की कम्पनी को सुविधा की गारंटी देने की प्रार्थना की थी। इस कम्पनी के अरेबियन-अमेरिकन आइल कम्पनी में ३३ प्रतिशत शेयर हैं और सऊदी अरब में भी इसको बहुत सी सुविधाएं प्राप्त हैं। इसका वार्षिक विशुद्ध लाभ ३०,०० लाख डालर है। अमेरिका का प्रतिनिधि सभा के एक सदस्य श्री वानेच ने, श्री फौलिस के इस वक्तव्य को खतरनाक बताते हुए कहा कि इसका तात्पर्य तो यह है कि 'आइजन होवर सिद्धांत' के आधार पर जो अमेरिकी सेना पश्चिमी एशिया भेजी जाये उनका उपयोग अमेरिकी तेल कम्पनियों के हितों के रक्षा के लिये किया जायेगा।

अमेरिका के समाचार-पत्रों ने भी, "आइजन हौवर सिद्धान्त" और अमेरिकी तेल कम्पनियों के स्वार्थ को घनिष्ट रूप से सम्बन्धित माना है। प्रसिद्ध समीक्षक श्री ड्रिू पिअरसन ने तो स्पष्ट लिखा है कि पश्चिमी एशिया में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

समस्त अमेरिकी नीति का केन्द्र बिन्दु ही तेल है।

इसी प्रकार "फौरच्यून" पत्रिका के जनवरी के अंक में श्री थौर्न बर्ग का एक लेख प्रकाशित हुआ था। उसमें कहा गया था कि अरब जगत में मिस्र के बढ़ते हुए नेतृत्व को समाप्त करना अमेरिकी तेल कम्पनियों के हित के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

अमेरिका बहुत पहले से ही पश्चिमी एशिया के तेलों पर अपना एकाधिकार स्थापित करने का प्रयत्न करता आ रहा है। १९३७ में अमेरिका का यहां की तेल कम्पनियों में केवल १३ प्रतिशत भाग था तथा इंगलैंड का भाग ८० प्रतिशत से भी अधिक था, लेकिन वर्तमान परिस्थिति यह है कि १९५६ में अमेरिका पश्चिमी एशिया का ६० प्रतिशत तेल कम्पनियों का नियंत्रण करता है और ब्रिटेन का भाग एक तिहाई ही रह गया है।

एक मार्के की बात यह कि जिस समय मिस्र पर ब्रिटेन और फ्रांस ने हमला किया था, उस समय अमेरिका 'तटस्थ' रहा। इस तटस्थता का रहस्य क्या हो सकता है? सब यही मानते हैं कि अमेरिका को पश्चिमी एशिया में अपना प्रभुत्व जमाने का स्वर्ण अवसर मिल गया था। वह चाहता था कि इसे युद्ध के बाद ब्रिटेन और फ्रांस का रहा-सहा प्रभाव भी समाप्त हो जाने पर उसे अपना प्रभुत्व स्थापित करना आसान हो जायेगा। पर एक रहस्य और भी था; जैसा कि अमेरिकी विदेश विभाग के उप सचिव राबर्ट हूवर (जनियर) ने, जो डलेस के बीमार होने पर नीति-निर्धारण कर रहे थे, स्वीकार किया भी है कि—उस समय अमेरिका "तेल सम्बन्धी कूटनीति" से काम ले रहा था। मि० हूवर का अमेरिकन तेल कम्पनियों से घनिष्ठ सम्बन्ध है। उन्हीं के कारण ब्रिटेन व फ्रांस को तेल भेजने में बहुत देरी कर दी गई, ताकि इससे ज्यादा लाभ उठाया जा सके।

आज पश्चिमी एशिया में ब्रटेन और फ्रांस का प्रभाव समाप्त हो चुका है। अब अमेरिका पश्चिमी एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। उसकी टक्कर अनिवार्यतः अप्रत्यक्ष रूप से रूप से होनी ही है। अरब राष्ट्रीयता भी अब पनपने लगी है। अरब भी अपने तेल पर अपने हित को प्रमुखता देंगे ही। अमेरिकन हित अरब राष्ट्रीयता को भी खतरनाक मानते हैं। क्या कहा नहीं जा सकता कि 'आइजन हौवर सिद्धांत' ने इस क्षेत्र को यदि साम्यवाद से बचाने का संकल्प किया है तो साथ ही अमेरिकी तेल कम्पनियों को भी सुरक्षा का आश्वासन नहीं दे दिया है?

लिपजिग का औद्योगिक मेला

लिपजिग के औद्योगिक मेले में जो ३ मार्च से १४ मार्च तक हुआ, दर्शकों और व्यापार की दृष्टि से आशा से अधिक सफलता हुई। इस बार की विशेषता यह थी कि पश्चिमी यूरोप, एशिया व अफ्रीका के स्वतंत्र देशों ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया। १९४७ के बाद इन देशों ने प्रथम बार भाग लिया। इस मेले में करीब ४० देशों ने भाग लेकर इस मेले के अन्तर्राष्ट्रीय महत्व को कायम रखा है। ७८ देशों से ६,६२,०८३ दर्शकों ने भाग लिया जब कि गत वर्ष दर्शकों की संख्या ५ लाख थी।

रूस, पोलैण्ड, पूर्वी यूरोप के अन्य देश, मिस्र, फिनलैण्ड, सीरिया और भारत, कोलम्बिया, टर्की, फ्रांस, आस्ट्रिया, ब्रिटेन, ग्रीस आदि देशों के सरकारी व व्यापारी प्रतिनिधियों ने इसमें पूरा भाग लेकर यह सिद्ध कर दिया है कि यह मेला उत्तर व पूर्व में आर्थिक सम्बन्ध बनाने में बहुत सफल हो सकता है। इस मेले में करीब २,१७,६० लाख जर्मन मार्क का व्यापार (आयात-निर्यात) हुआ, साम्यवादी देशों के साथ १,३७,२० लाख मार्क का तथा अन्य देशों के साथ ४८,३० लाख मार्क के निर्यात व्यापार के सौदे किये गये। भारत से निर्यात और आयात व्यापारियों की एक टीम के अतिरिक्त स्टेट ट्रेनिंग कार्पोरेशन ने भी इस प्रदर्शनी में भाग लिया।

ब्रिटेन में कर कम हुए

जब भारत में वित्त मन्त्री लगातार कर बढ़ाने की धमकी दे रहे हैं, तब ब्रिटेन के वित्त मंत्री ने १ अप्रैल को पेश किये जाने वाले बजट में १० करोड़ पाउण्ड के कर कम करने की घोषणा की है। उन्होंने वर्तमान करों के आधार पर ५३८.७ करोड़ पाउण्ड आय और ४८२.० करोड़ पाउण्ड व्यय की कल्पना की है। खेलों तथा नाटक गृहों में मनोरंजन कर हटा दिया गया है। बहुत-सी पुस्तकों पर बिक्री कर ३० प्रतिशत से १५ प्रतिशत कर दिए गए हैं।

—

[सम्पूर्ण

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कपड़े और सूत की रद्दी : आय का महान स्रोत

श्री पद्मपत सिंहानिया

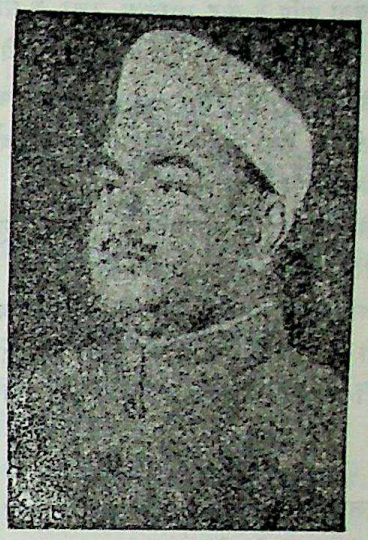

अखिल भारतीय वस्त्र सम्मेलन और औद्योगिक प्रदर्शनी के स्वागताध्यक्ष पद से भाषण देते हुए, श्री पद्मपत सिंहानियां ने एक बहुत उपयोगी प्रस्ताव में सुझाव दिया है कि यदि हम कपड़े की और सूत की रद्दी से किसी तरह फिर से सूत निकालने का तरीका निकाल सकें, तो यह न केवल भारतीय उद्योग के लिये, बल्कि सारे देश के लिये लाभकारी होगा। यदि इस तरह हम कुल वस्त्र का १५% भी अतिरिक्त उत्पादन कर सकें, तो हम ४३½ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष बचा सकते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में प्रति व्यक्ति २० गज कपड़े की खपत का अनुमान किया गया है। यदि नयी विधि से हम विदेशी रुई के आयात को कम कर सकें, तो हमें असाधारण लाभ हो सकता है और हम बहुत सी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं। नीचे की तालिका से यह स्पष्ट है कि भारतीय वस्त्र में विदेशी रुई का कितना महत्व है—

वर्ष	विदेशी रुई का कुल आयात लाख रुपये में	कुल आयात का प्रति शत	विदेशों को कपड़े का आयात लाख रुपये में	कुल का निर्यात प्रतिशत
१९४८-४९	६४,२८	१०	३६,५४	११
१९४९-५०	६३ ७९	१०	५९,६५	११.८
१९५०-५१	१,००,७७	१६	१ १२,१०	१८.५०
१९५१-५२	१,३७,१८	१४.५	४०,९५	५.८
१९५२-५३	७६,६७	११.६	५३.२८	९.३
१९५३-५४	५२,७५	९	५३,५८	१०.१
१९५४-५५	५८,४५	९	५५,०९	९.४
१९५५-५६	६९,३७	८	४८.१७	८.१

श्री सिंहनिया से इस बात पर बहुत बहुत जोर दिया कि रद्दी कपड़े का निर्माण कम करना चाहिए और विदेशी रुई आयात ५०% कम कर देना चाहिए। उत्पादन बढ़ाने का अर्थ मजदूरों पर काम का बोझ ज्यादा लाद कर या पूंजी ज्यादा लगा कर माल ज्यादा तैयार करना नहीं है, बल्कि इसका असली अर्थ औद्योगिक कार्य में कुछ सुधार करके उत्पादन बढ़ाना है।

——

सम्पदा के कुछ एजेण्ट

रांची में

क्राउन बुक डिपो।

जोधपुर में

मैसर्स द्वारकादास राठी, बुकसैलर्स।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मध्य रेलवे की सफलता

ले० श्री एम० एन० चक्रवर्ती,
जनरल मैनेजर, मध्य रेल

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय रेलों के सामने दुहरी समस्याएं आ खड़ी हुईं। एक ओर तो डिब्बे और रेल मार्ग पुराने होते जाते थे और उनकी मरम्मत की आवश्यकता बढ़ती जाती थी, तथा दूसरी ओर यातायात का बोझ निरंतर अधिक होता जा रहा था।

पहले दस वर्षों में यातायात में लगभग दुगुनी वृद्धि हुई है, परन्तु रेल ने इस स्थिति को सम्भाल लिया है। जहाँ अत्यधिक भीड़-भाड़ होती थी, वहां अब सामान्य स्थिति हो गयी है। माल की ढुलाई ठीक हो लगी है और कहीं भी अधिक समय तक माल पड़ा नहीं रहता।

कठिनाइयों से पार

उपलब्ध परिवहन का अधिकतम उपयोग करने के लिए जो कदम उठाये गये, उसी का यह फल है कि अब परिवहन में इतनी आसानी हो गयी है।

अनेक स्टेशनों पर रात में माल की ढुलाई का काम शुरू किया गया, काम के घण्टे बढ़ाये गए ताकि मालगाड़ी में माल उतारने-चढ़ाने के काम में एक दिन से अधिक न लगे और वह एक ही स्थान पर एक दिन से अधिक पड़ा न रहे। एक्सप्रेस मालगाड़ियां चलाई गयीं, जिन्हें गन्तव्य स्थान तक पहुँचने में पहले से आधा समय लगता है और इस प्रकार माल-डिब्बे जल्दी उपलब्ध हो जाते हैं। लगभग डेढ़ साल पहले मरम्मत के लिए रुके हुए माल-डिब्बों की संख्या कम से कम करने का आन्दोलन चलाया गया। नतीजा यह हुआ कि काम में आने वाले माल डिब्बों में १००० की और वृद्धि हो गयी। साथ ही कारखानों में इंजिनों और डिब्बों की मरम्मत जल्दी-जल्दी होने लगी।

माल की शीघ्र रवानगी

रेल मार्ग की क्षमता बढ़ाने के लिए काजीपेट माल गोदाम का सुधार किया गया, जिस पर ५ लाख ७५ हजार रु० खर्च हुआ। उत्तर-दक्षिण यातायात का यह मुख्य स्थान है और सिंगरेनी क्षेत्र का कोयला भी यहीं होकर जाता है। पहले यहां से प्रतिदिन ४५० माल डिब्बे भर कर

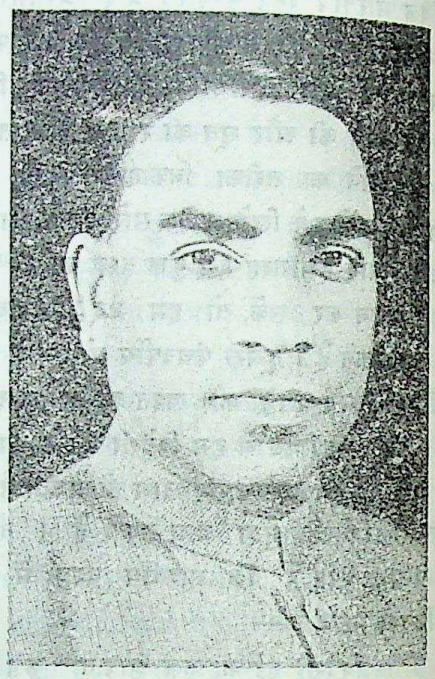

लेखक

भेजे जा सकते थे, सुधार के बाद ६०० डिब्बे प्रतिदिन भेजे जाने लगे।

बडनेरा माल गोदाम का भी सुधार किया गया, जिस पर २ लाख रु० खर्च हुआ। इसके अलावा इगतपुरी, सतना बीना, आमला आदि १० स्टेशनों के माल गोदामों का भी सुधार किया जा रहा है।

मथुरा-दिल्ली रेल-मार्ग को दुहरा करने का काम फरवरी १९५६ में शुरू हो चुका है। इस साल के अन्त तक इसके पूरे हो जाने से इस मुख्य मार्ग पर माल की ढुलाई की दिक्कत दूर हो जाएगी।

कुरला-चेम्बूर रेल मार्ग भारत में सबसे अधिक व्यस्त इकहरा मार्ग है। इस पर प्रतिदिन १०० से भी अधिक रेल-गाड़ियां आती-जाती हैं। यहां दुहरा करने का काम पिछले साल जुलाई से शुरू हो चुका है और अब आधे से अधिक पूरा हो गया है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आधुनिक सिगनलिंग

कुरला में आधुनिक इंटरलॉकिंग-प्रणाली की योजना पर ३० लाख रु० खर्च होने का अनुमान है। सिगनलिंग और इंटरलॉकिंग की नयी प्रणाली (पटरियां बदलने) का काम एक ही कार्यालय से संचालित होगा। इस समय यह ६ केबिनों से संचालित होता है। इनमें २७१ लीवर हैं, जो १ मील में फैले हुए हैं। सब काम हाथ से ही होता है। कुरला भारत का सबसे व्यस्त रेल-जंक्शन है। यहां पांच भिन्न-भिन्न दिशाओं से ५०० से भी अधिक रेल-गाड़ियां प्रतिदिन आती-जाती हैं। दो बड़े तेलशोधक कारखानों का माल भी अब यहां आने लगा है। इस साल के अन्त तक उक्त योजना पूरी हो जाने पर यह सारा यातायात बेवल बटन दबाने से ही संचालित होने लगेगा।

संकलन व अध्ययन

आपकी पत्रिका में अर्थशास्त्र विषय में वस्तु परिचय का अद्भुत संकलन और उसका विवेकपूर्ण अध्ययन। ये दोनों ही उत्तम होते हैं, मुझे यदा-कदा इसको देखने का अवसर मिला है। मैं पत्र के उत्तरोत्तर वृद्धि की शुभकामना करता हूं।

— पद्मपतसिंहानिया

बम्बई के उपनगरों में भी भायखला और कुरला के बीच सिगनलिंग की रंगीन बत्तियों और चौराहों के फाटक बन्द करने की स्वचालित प्रणाली आरम्भ हो गयी है।

पहले आठ महीनों में माल-डिब्बों की संख्या ३४,५६४ से बढ़कर ३५,१२६, इंजिनों की १,२६५ से बढ़कर १,४०५ और सवारी डिब्बों की २,०३६ से बढ़कर २,०६१ हो गयी है। पिछले चार महीनों में इनमें और भी वृद्धि हुई।

यात्रियों को सुविधाएं

इस वर्ष यात्रियों के लिए और अधिक सुविधाओं की व्यवस्था की गयी। इस पर लगभग ५३ लाख रु० खर्च हुआ। मुख्य मार्गों पर ६ अतिरिक्त रेलगाड़ियां और ६ अतिरिक्त उपनगरीय रेलगाड़ियां चलायी गयीं। अर्ध साप्ताहिक वातानुकूलित गाड़ी भी शुरू की गयी। तीसरे दर्जे के पुराने डिब्बों में १३० पंखे लगाए गए। ४२ स्टेशनों पर पीने के पानी तथा प्रतीक्षालयों का प्रबन्ध किया गया या उनमें सुधार किया गया। जबलपुर और कुरनूल के स्टेशन सुधारे गये।

खंडवा-हिंगोली रेल-मार्ग

खंडवा से पिपलोद को और हिंगोली से कन्हरगांव को जोड़ने वाले रेल-मार्ग लगभग पूरे हो गये हैं और कुछ ही सप्ताह बाद इस्तेमाल में आने लगेंगे। इनकी कुल लम्बाई ३५ मील है।

कर्मचारी-कल्याण

इस साल रेल-कर्मचारियों के लिए १,००० से भी अधिक क्वार्टर बनाए गए।

भायखला अस्पताल का विस्तार किया जा रहा है, जिससे वहां ४० और पलंगों की व्यवस्था की जा सके। ६४ स्टेशनों पर सभी क्वार्टरों में बिजली लगा दी गयी है। पिछले साल मई में छुट्टी पर गये हुए रेल कर्मचारियों के लिए माथेरान में एक विश्राम-घर की व्यवस्था की गयी थी। मध्य रेल पर अपने किस्म का यह पहला विश्राम-घर है।

नयापथ

(प्रगतिशील मासिक पत्रिका)

सम्पादक—

यशपाल ❀ शिव वर्मा ❀ राजीव सक्सेना

स्तम्भ—

- चक्कर क्लब
- साहित्य समीक्षा
- संस्कृति प्रवाह
- सिनेमा
- लेख
- कहानियां
- कविताएं।

"नयापथ" का जनवरी अंक 'लोक साहित्य' विशेषांक है। इसका सम्पादन हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक श्री श्रीकृष्णदास कर रहे हैं। ग्राहकों को यह अङ्क साधारण मूल्य में ही दिया जाएगा।

वार्षिक ६) एक प्रति ॥)

पता :—

२२ कैसर बाग लखनऊ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अखबारी कागज की एक और मिल

आंध्र राज्य के निजामाबाद जिले के शक्कर नगर में अखबारी काग़ज बनाने की एक और मिल शीघ्र ही खुलेगी। मिल की स्थापना में ५ करोड़ रु० खर्च होगा। इसकी उत्पादन क्षमता ३०,००० टन प्रति वर्ष होगी।

इस मिल की विशेषता यह है कि इसमें गन्ने के फोक (चीनी के मिलों के अनुपयोगी पदार्थ) से कागज तैयार किया जायेगा, जो अपनी किस्म की एक ही होगी। निजामाबाद जिले में चीनी की कई बड़ी-बड़ी मिलें हैं जिनमें प्रतिवर्ष ८५,००० टन फोक मिलता है।

पूर्वस्थापित मध्यप्रदेश की नेपा मिल से अखबारी कागज का उत्पादन आरंभ हो चुका है। यहां प्रति वर्ष ३० हजार टन अखबारी कागज तैयार होता है जो देश की एक तिहाई आवश्यकता की पूर्ति करता है। शक्करनगर से उत्पादन आरंभ होने पर ६० हजार टन अखबार कागज तैयार होने लगेगा। इस समय देश में अखबार कागज की कुल आवश्यकता १ लाख २० हजार टन प्रति वर्ष हैं। ये मिलें केवल देश की आवश्यकता के बड़े अंश की पूर्ति ही नहीं करेंगी, वरन २॥ करोड़ रुपये की बचत करने में भी सहायक होंगी। यह धन अब तक अखबारी कागज आयात करने में व्यय किया जाता है।

आयोजन आयोग ने दूसरी पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में १ लाख टन अखबारी कागज बनाने लक्ष्य रखा है। इसमें से लगभग ३० हजार टन कागज नेपा मिलों द्वारा बनाया जाएगा।

सीमेण्ट उद्योग

देश में चल रहे विकास कार्यों के लिए निर्माण सामग्री में इस्पात के बाद सीमेंट का स्थान है। देश में १९४९-५० में २६ लाख टन सीमेंट की खपत थी, परन्तु १९५६-५७ में यह बढ़कर १ करोड़ टन हो गयी है।

भारत-विभाजन के बाद १९४८ में देश में सीमेंट के १८ कारखाने थे और उनकी कुल वार्षिक उत्पादन-क्षमता ४३ लाख टन प्रतिवर्ष है। दूसरी आयोजना के अन्त में सीमेंट के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य वर्तमान क्षमता से दोगुना अर्थात् १ करोड़ २० लाख टन रखा गया है।

भारत में १९५०-५१ में २५ लाख टन, १९५२-५३ में ३५ लाख टन और १९५५-५६ में ४६ लाख टन सीमेंट तैयार हुआ।

१९५०-५१ तक सीमेंट उद्योग में कुल २९ करोड़ रु० की पूंजी लगी हुई थी। अप्रैल १९५५ तक नये कारखाने खोलने और कारखानों का विकास करने में १५ करोड़ रु० खर्च किए गए। १९६१ तक इस उद्योग की विकास योजनाओं पर ७५ करोड़ रु० से भी अधिक खर्च किया जायगा।

भारत में सीमेंट उद्योग अधिकांशतः निजी क्षेत्र में है, परन्तु अब सरकारने भी ३ कारखाने खोले हैं, एक उत्तर प्रदेश में, दूसरा बम्बई में और तीसरा मैसूर में।

पहली आयोजना के आरम्भ होने के समय सीमेंट उद्योग में ३३,००० कर्मचारी थे। अब इनकी संख्या ४०,००० है। अनुमान है कि १९६०-६१ तक इस उद्योग में ७५,००० कर्मचारी हो जाएंगे।

—

कोयला-उद्योग

३० अप्रैल, १९५६ के संशोधित औद्योगिक नीति प्रस्ताव में कोयले को अनुसूची 'क' में शामिल कर लिया गया। निजी क्षेत्र में जिन एककों को स्वीकृति दी जा चुकी है, उन्हें छोड़कर बाकी सभी एकक (यूनिट) अब सरकार खोलेगी। परन्तु वर्तमान निजी क्षेत्रों के एककों का विस्तार

सम्पदा का आगामी
विशेषांक
कौन सा निकलेगा ?
जून अङ्क में पढ़िये

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

करने अथवा नए एकक खोलने में सरकार द्वारा निजी क्षेत्र का सहयोग लेने पर कोई रोक नहीं रहेगी।

२. पहली पंचवर्षीय आयोजना के अंत में कोयले का वार्षिक उत्पादन ३ करोड़ ८० लाख टन हो गया था; इसमें से ३ करोड़ ५० लाख टन का उत्पादन निजी क्षेत्र द्वारा होता था।

३. दूसरी आयोजना में १९६०-६१ तक कोयले के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य ६ करोड़ टन रखा गया है।

४. यह लक्ष्य १९५५ के उत्पादन स २ करोड़ २० लाख टन अधिक है। इसमें से निजी क्षेत्र में १ करोड़ टन और सरकारी क्षेत्र में १ करोड़ २० लाख टन उत्पादन बढ़ाया जाएगा।

५. १९५६ में परिवहन की सुविधाएँ बढ़ जाने से खानों में कोयले का उत्पादन बढ़ा और कोयले की निकासी भी अधिक हुई। १९५५ के अंत में खानों के भंडारों में ३६ लाख टन कोयला था; १९५६ के अंत में केवल २७ लाख टन था।

६. गड्ढे के भरने के लिए रेत की आवश्यकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए मशीनों के आयात की समस्या पर सरकार विचार कर रही है।

७. जिन क्षेत्रों में कोयला है, पर अभी निकाला नहीं गया, उनके अधिग्रहण के लिए मई १९५७ में नयी संसद के पहले अधिवेशन में कानून बनाया जायगा।

———

लघु उद्योग निगम

भारत सरकार ने फरवरी, १९५५ में १० लाख रु० की पूंजी से राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना की थी। इस निगम के चार प्रमुख विभाग हैं—(१) सरकारी खरीद विभाग, (२) किश्तों द्वारा खरीद विभाग, (३) हाट-व्यवस्था विभाग, और (४) औद्योगिक बस्ती विभाग।

किश्तों द्वारा खरीद विभाग के पास पिछले वर्ष दिसम्बर के अंत तक १ करोड़ ९७ लाख रु० के मूल्य की तरह-तरह की ३,११० मशीनों के लिए ७२५ आवेदन-पत्र आये थे। हाट-व्यवस्था विभाग की ओर से दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में बिक्री-गाड़ियां चलायी जा रही हैं। ये गाड़ियां निश्चित मार्गों पर चलती हैं और इनमें लघु-उद्योगों द्वारा बनायी गयी ३०० से अधिक चीजें होती हैं।

भारत सरकार ने अब तक दिल्ली (ओखला), ग्विंडी, विरुदनगर, पलवाट, एरोड, राजकोट, क्विलोन, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, मैसूर, कल्याणी, गोहाटी, विशाखापट्टम, जयपुर आदि में १६ औद्योगिक बस्तियां खोलने की मंजूरी दी है।

राष्ट्रीय लघु-उद्योग निगम के बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में चार सहायक निगम खोले गये हैं।

★

सरकारी उद्योगों की प्रगति

नव स्थापित सरकारी उद्योगों ने १९५६ में जो उन्नति की है, उसका संक्षिप्त विवरण दिया जाता है:—

सिंदरी के खाद के कारखाने में १९५५ में उत्पादित ३,२१,००० टन की तुलना में इस वर्ष लगभग ३,३१,००० टन एमोनियम सल्फेट का उत्पादन हुआ, जो कि सिंदरी फर्टिलाईज़र्स फैक्टरी के लिए अब तक सबसे अधिक है। पैनिसिलीन फैक्टरी पिम्परी में, १९५५ में उत्पादित ६६ लाख मेगा यूनिट की तुलना में ४४१,२९ लाख मेगा यूनिट पैनिसिलीन तैयार हुई। हिन्दुस्तान शिपयार्ड विशाखपत्तनम में डीजिल एंजिन के दो आधुनिक जहाज 'जलविष्णु' तथा "स्टेट आफ कच्छ" बनाकर दिए। "स्टेट आफ कच्छ" शिपयार्ड में अभी तक बनाये गए जहाजों में सबसे बड़ा है। दिल्ली में स्थित डी० डी० टी० फैक्टरी में, जिसने १९५५ में उत्पादन आरम्भ किया था, १९५६ में लगभग ५०० टन डी० डी० टी० का उत्पादन हुआ। केबिल्स फैक्टरी, चितरंजन ने १९५५ के ३८६ मील केबिल की तुलना में इस वर्ष ६१० मील केबिल का निर्माण किया। इसी वर्ष के दौरान ही हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने अपनी पहली खराद बनाई। फरवरी १९५६ के अन्त तक, १३२ खराद बन चुकी थीं। गत वर्ष के ३८० लाख टन की तुलना में इस वर्ष कोयले का उत्पादन ३९० लाख टन रहा। नमक उत्पादन ने भी एक नवीन स्तर प्राप्त किया है जो कि १९५५ के ८१० लाख टन की अपेक्षा इस वर्ष ८८० लाख टन था।

६॥ हजार इंजीनियर प्रतिवर्ष

आज अमेरिका और रूस विश्व में औद्योगिक रूप से

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

[पृष्ठ २६८ का शेष]

लगाना आसान नहीं है, फिर भी ऐसा माना गया है कि इस प्रकार ५०,०० करोड़ रु० की राशि निष्क्रिय पड़ी है। इस राशि के बड़े भाग को विनियोग के लिए प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि इन लोगों को राष्ट्र के आर्थिक नव-निर्माण की गंभीर परिस्थितियों पर विचार करने को तैयार कर लिया जाये और वे इससे प्रभावित हो सकें।

इस समय जो बचत आन्दोलन चल रहे हैं, उनके सम्बन्ध में एक विचारणीय बात यह है कि छोटी छोटी बचत करने वालों को इनसे विनियोग सम्बन्धी सुविधा नहीं मिल सका है। एक व्यक्ति जो कि एक साल में १० रु० से अधिक नहीं बचा पाता, उसे तब बड़ी असुविधा होती है जब कि सर्टिफिकेट के रूप में उसे पेश्तर ही राशि को चुकता करने को विवश होना पड़ता है। जोर जबर्दस्ती का त्याग किया जाना अनुचित है। प्रयत्न तो यह होना चाहिए कि व्यक्ति के अन्दर ही बचत करने का उत्साह उत्पन्न हो। इसके लिए आवश्यक है कि इन व्यक्तियों की छोटी बचतों को लघु उद्योगों में आकर्षित किया जाये। इस प्रकार एक व्यक्ति ५ वर्ष में ५० रु (कम से कम) बचा लेगा, साथ ही वह वार्षिक या तिमाही प्रिमियम भी देता रहेगा। १० वर्ष के बाद उसे अपनी पूंजी वापिस लेने का अधिकार होगा और उस समय उसको अच्छा ब्याज भी मिलना चाहिए।

एक ऐसे समाज में, जहां सामाजिक सुरक्षा की पूर्ण सुविधाएं उपलब्ध हों, वहां बड़ी मात्रा में सरलता से पूंजी का विनियोग के लिए प्राप्त होना स्वाभाविक है। लेकिन एक अनुन्नत देश में, जहां 'व्यावसायिक अर्थव्यवस्था' (बिजनिस इकौनौमी) का विस्तार होने पर ही सामाजिक सुरक्षा की सुविधाएं बढ़ें, वहां पूंजी के संचय में काफी समय लग जाता है। इसके लिए लेटिन अमेरिका के राज्यों का जो भारत की तरह ही अनुन्नत हैं, उदाहरण महत्त्व का है। ऐसा कहा जाता है कि ब्राजिल, चिली और पैराग्वे में सामाजिक सुरक्षा की सुविधाओं की वृद्धि राष्ट्रीय आय के १ या २ प्रतिशत तक हुई।

यदि भारत सरकार विभिन्न बचत योजनाओं का निर्धारण मुख्यतः इस विचार से करे कि उनसे किसानों और छोटे कारीगरों को लाभ हो, तथा बीमारी, बुढ़ापा, शिशु दुर्घटना में प्राप्त होने वाली सामाजिक सुरक्षा व सुविधाओं को देश की सम्पूर्ण काम करने वाली जनता को प्रदान कर सके, तो वर्तमान बचत-योजनाओं के साथ ही छोटी बचतों को बढ़ाकर राष्ट्रीय आय के १.५ प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।

सर्वाधिक सम्पन्न हैं। १०० साल पहले अमेरिका और २५ साल पहले रूस हमारे देश की तरह ही पिछड़े थे। उन्होंने जो आर्थिक नव-निर्माण के कार्य आरम्भ किये उनकी सफलता में इंजीनियरों का महत्त्वपूर्ण भाग रहा है। इसी प्रकार नव-भारत के निर्माण में भी पर्याप्त संख्या में इंजीनियरों की उपलब्धि होना अति आवश्यक है, अतः ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंजीनियरी का पेशा अपनाना व प्राविधिक कार्यों में लगना आवश्यक है। १९५४ में, अमेरिका में ५ लाख ३५ हजार, रूस में ५ लाख ४० हजार, और ब्रिटेन मे ६० हजार इंजीनियर थे, जबकि भारत में सिर्फ २५ हजार इंजीनियर थे। १९५५ में, भारत में ३,१०० विद्यार्थियों ने इंजीनियरी की स्नातक परीक्षा पास की और करीब ६ हजार ने डिप्लोमे लिये। आयोजन-आयोग ने जो प्राविधिक जन-शक्ति समिति नियुक्त की है, उसने कहा है कि दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के अन्त तक कम से कम ६,५०० इंजीनियरिंग स्नातक प्रति-वर्ष तैयार होने चाहिएं। यदि हमें अन्य देशों पर निर्भरता से मुक्त होना है, तो हमें इस कमी को जल्दी से जल्दी पूरा करना होगा।

सम्पदा में विज्ञापन देकर लाभ उठाइए

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राष्ट्र का आर्थिक प्रवाह

श्री जी० एस० पथिक

निजी क्षेत्र की पूंजीगत संस्था

इंडस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इनवेस्टमैण्ट कार्पोरेशन निजी क्षेत्र के पूंजी निर्माण का एक नया संगठन है। निजी क्षेत्र के हाथ से जीवन बीमा कम्पनियों का व्यवसाय निकल जाने से उद्योगपति एक संस्थागत पूंजी विनियोजन के क्षेत्र से वंचित हो गए। यह क्षेत्र अत्यन्त महत्वपूर्ण था। अतएव उद्योगपतियों ने कम्पनी के रूप में भारतीय उद्योगों में पूंजी विनियोजन के लिए इस संगठन को खड़ा किया है। यह कम्पनी केवल ऋण देने वाली संस्था नहीं है, बल्कि मैनेजिंग एजण्ट तथा शेयर बाजार के दलालों की तरह नयी पूंजी को अंडर राइट करती है। इस रूप में उसने अनेक कम्पनियों के शेयरों में विनियोजन किया है। उसका क्षेत्र बढ़ता ही जाता है। वह सरकारी और निजी—दोनों औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए तत्पर है। कारपोरेशन के विनियोजन को धक्का लगता है, जब केन्द्रीय सरकार भारी पूंजीगत करों को लगाती है। १९५५ और १९५६ के बजटों ने तथा १९५६ के अतिरिक्त बजट ने विनियोजन के प्रोत्साहन को क्षीण कर दिया। आय कर, कारपोरेशन कर और सुपर टेक्स में वृद्धि की गयी - डिवीडेन्ड पर सर चार्ज बढ़ाया गया। पूंजीगत लाभ कर लगाया गया। पुराने और नये डिपाजिटों को हस्तगत करने की सरकार ने जो योजना तैयार की, उस सबसे सरकार को सरकारी उद्योग और सामाजिक सेवाओं में व्यय करने के लिए अधिक धन प्राप्त होगा, किन्तु निजी क्षेत्र के पूंजीगत क्षेत्र कुचल जाते हैं। भारतीय पूंजी और विदेशी मुद्रा की कमी के कारण सरकार ने विदेशी पूंजी के सहयोग की कामना की है। इस कारण से विश्व बैंक से १०० लाख डालर मिले हैं। इस धन से उन उद्योगों की सहायता की जाएगी, जो विदेशी मुद्रा चाहते हैं और पूंजीगत सामान खरीदना चाहते हैं। एक विशेषता यह भी है कि इस कारपोरेशन की जमानत पर विदेशी उद्योग दीर्घकालीन मुद्दत पर भारतीय उद्योगों को पूंजीगत सामान का आयात कर सकते हैं। १९५६ में इस कारपोरेशन ने ३६ लाख रुपए की आय की, जिसमें से ७ लाख रुपए आय कर में चुकाने पड़े। कम्पनी ने आय कर मुक्त ३॥ प्र० श० का डिवीडेण्ड शेयर होल्डरों को दिया। कम्पनी के संचालन में औद्योगिक विशेषज्ञ और पूंजी विनियोजक दोनों ही हैं। दोनों की जांच पड़ताल से विनियोजन किया जाता है।

कम्पनियों के डिपाजिट

भारत सरकार ने भारतीय कम्पनियों और भारत में व्यवसाय करने वाली विदेशी कम्पनियों के पुराने और नए डिपाजिट अनिवार्य रूप में जमा करने के नियम बना दिये हैं। गत दिसम्बर मास में फाइनेंस नम्बर (३) १९५३ के कानून के अन्तर्गत आय कर कानून में जो संशोधन स्वीकृत हुए थे, वे १ अप्रैल १९५७ से जारी हो गए। इस के साथ केन्द्रीय वित्तीय मंत्रालय ने डिपाजिट जमा करने के सम्बन्ध में नियम बनाये। १ लाख रुपए की रकम से डिपाजिट अधिक होने पर कानून के अन्तर्गत चलतू मुनाफे में से अमुक प्रतिशत जमा करना पड़ेगा। गत वर्ष कम्पनी की जो आय हुई हो, और उस पर आय कर तथा सुपर टेक्स लगने के बाद जो बचा हो, तथा उस पर जो डिवीडेंट घोषित किया गया हो तथा घिसाई के लिए जो रकम रखी गयी हो और विकास की जो छूट दी गयी हो, उसके उपरांत डिपाजिट के रूप में जो रकम बचती है, उसका निश्चित प्रतिशत कम्पनियों को सरकार के पास जमा करना पड़ेगा। जिस डिपाजिट धन से कम्पनियां अपना दैनिक कारबार चलाती थीं, उससे वे वंचित हो जाएंगी अर्थात अपनी बचत की रकम सरकार के पास जमाकर वे चलतू कामों के लिए बैंकों से ऋण लेंगी। कम्पनियों को गत वर्ष की बचत चलतू वर्ष में छः मास के अन्दर जमा कर देनी होगी। नकद रुपया बैंक में जमा कराया जा सकेगा और सिक्यूरिटियां रिजर्व बैंक में जमा होंगी, जिन पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।

डिपाजिट से छूट

मान लीजिए कि यदि कम्पनियां डिपाजिट की रकम सरकार के पास जमा न करें तो उन्हें विकास रिबेट की छूट तथा घिसाई की मद पर कर की छूट न मिलेगी। यदि कम्पनी यह सोचे कि वह बचत की रकम का उद्योग के

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विकास में व्यय करना चाहती है तो वह स्वीकृत कार्यों में ही लगा सकेगी, और सरकार ने उसकी सूची तैयार कर दी है। कारखाने की इमारत, मशीन और कल पुर्जे तथा अन्य स्थायी सम्पत्ति में पूंजीगत व्यय स्वीकार किया जाएगा। स्थायी सम्पत्ति पर जो कर्ज लिया हो, उसे भी इस धन से चुकाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आय कर कमिश्नर के मत में जो अन्य वित्तीय व्यय कम्पनी के लिए उचित प्रतीत हों, उन्हें भी मान लिया जाएगा। यदि आय कर कमिश्नर को यह संतोष हो जाए कि कम्पनी चलतू मुनाफे की पूरी रकम जमा नहीं कर सकती है, तो वह इस संबंध में अपने विविध निर्णय देगा।

२० औद्योगिक स्टेट

भारत सरकार ने योजना के अन्तर्गत छोटे उद्योगों के विकास के लिए विभिन्न राज्यों में २० औद्योगिक स्टेटों के निर्माण करने का निश्चय किया है। नए चुनाव के उपरान्त केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों का ध्यान छोटे उद्योगों के विस्तार की ओर गया है। जिन क्षेत्रों में विद्युत जल की आमद, यातायात की सुविधाएं और छोटे उद्योगों में दिलचस्पी रखने वाले व्यक्ति काफी तादाद में उपलब्ध होंगे, वहीं सामूहिक विकास योजना के अंतर्गत इन औद्योगिक उपनिवेशों को मूर्तिमन्त रूप दिया जाएगा। विदेशों में इस प्रकार की कालोनियां हर एक राज्य में हैं। ९ क्षेत्रों के लिए योजनाएं तैयार हो गई हैं। ग्राम और छोटे पैमाने के उद्योगों के विस्तार के लिए योजना आगे कदम उठा रही है। सरकार को शायद यह चेतना आई कि बड़े-बड़े उद्योगों के निर्माण में अरबों रुपए की पूंजी लगने पर देश की बेकारी दूर न होगी। किसानों और मध्यवर्ती युवकोंकी बेकारी ने गत निर्वाचन में कांग्रेस के सर दर्द पैदा किया था। पश्चिमी बंगाल ने मुख्यमंत्री डाक्टर विधानचन्द्र राय और उनके साथ के एक दल ने जापान में कुछ समय तक रह कर छोटे उद्योगों के संचालन का ज्ञान प्राप्त किया। पश्चिम बंगाल में डाक्टर राय जापानी व्यवस्था के आधार पर छोटे उद्योगों को जन्म देना चाहते हैं। इन उद्योगों के विस्तार पर ही निराश्रित और भटके हुए शिक्षित नवयुवक काम पाएंगे। अन्यथा, आज की स्थिति बड़ी भयंकर है। काम धंधा न पाने पर युवकों का दल कम्यूनिस्ट बन रहा है, जिससे राजनीतिक अशांति बढ़ती जा रही है।

विनियोजन का वातावरण

उद्योग और व्यापारिक क्षेत्र की यह मांग है कि यदि सरकार करों के द्वारा अधिक आय चाहती है तो वह करों का क्षेत्र बढ़ा दे, किंतु व्यक्तिगत करों में कमी करे। दूसरे कर वसूली की व्यवस्था में कड़ाई करे। आय कर न तो सब लोगों पर लग पाता है और न वास्तविक रूप में वसूल होता है। जितना अधिक व्यक्तिगत कर का स्तर ऊँचा होता है, व्यापारी वर्ग और भी नीचे स्तर पर कर चुकाते हैं। इधर विनियोजन बाजार की व्यवस्था गिरने के कारण दान या भेंट कर, व्यय कर या वार्षिक सम्पत्ति कर जैसे नये पूंजीगत कर पूंजी बाजार को नया धक्का पहुंचावेंगे। उससे विनियोजकों का विश्वास भंग हो जाएगा। सरकार को नये कर इस दृष्टि से लगाने चाहिएं और उन क्षेत्रों में लगाने चाहिएं, जिससे निजी क्षेत्र के विकास में पूंजी निर्माण को धक्का न लगे। औद्योगिक विकास के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि विनियोजन का वातावरण अनुकूल किया जाए।

१९५६ का विदेशी व्यापार

१९५६ में निर्यात ३ करोड़ रु० कम हुआ तथा आयात १५९ करोड़ रु० बढ़ा, क्योंकि बड़ी मात्रा में पूंजीगत सामानों का आयात करना पड़ा। पिछले साल घाटा ४० करोड़ रु० से बढ़ कर २०२ करोड़ रु० तक पहुँचा। जिन वस्तुओं का निर्यात घटा वे खली, कच्ची रुई तथा जूट का तैयार माल है। कुछ वस्तुओं, मुख्यतः चाय और तम्बाकू का निर्यात बढ़ा। इस प्रतिकूल व्यापार संतुलन की समस्या का सामना करने के लिए हर सम्भव उपाय काम में लाये जा रहे हैं। जैसे—निर्यात प्रतिबन्धों में ढील देकर निर्यात बढ़ाने के प्रयत्न करना निर्यात बढ़ाने वाली समितियों की स्थापना तथा दूसरे देशों के साथ व्यापारिक समझौतों में संशोधन किया जाना। १५ देशों के साथ व्यापारिक समझौतों के अनुसार कार्य चल रहा है तथा इस वर्ष (१९५६) और देशों के साथ व्यापारिक संधियां सम्पन्न हो चुकी हैं। विशेषज्ञों की एक समिति इस ध्येय से बनाई गई है कि वह निर्यात बढ़ाने सम्बन्धी कार्यों का समावलोकन करे और निर्यात बढ़ाने के इस विषय में ठोस सुझाव दे। एक संस्था एक्सपोर्ट क्रेडिट गारन्टी और इन्श्योरेंस भी स्थापित की जा रही है।

[सम्पन्न

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अर्थवृत्त चयन

विदेशों से आर्थिक सहायता और पंचवर्षीय योजना

पहली योजना के भीतर विदेशी सहायता का लक्ष्य १५६ करोड़ रुपये रखा गया था, जबकि हमें वस्तुतः २९५ करोड़ रुपये प्राप्त हुए। इसमें से भी सिर्फ २०४ करोड़ रुपये की सहायता का ही इस्तेमाल दरअसल हो सका। इसलिए हमें दूसरी योजना के भीतर खर्च करने के लिये ९४ करोड़ रुपये उपलब्ध हैं।

पिछले साल के भीतर विभिन्न विदेशी संस्थाओं द्वारा अनुदान और ऋण के रूप में निम्नलिखित रकमें भी देने का वादा हुआ है।

१. भिलाई इस्पात कारखाने के लिये रूसी ऋण ४३ करोड़ रुपये
२. दुर्गापुर इस्पात कारखाने के लिये ब्रिटिश सरकार तथा ब्रिटिश बैंकरों द्वारा संयुक्त ऋण ३३ करोड़ रुपये
३. सार्वजनिक कानून ४८० के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा सहायता १३७ करोड़ रुपये
४. कोलम्बो योजना के अंतर्गत कनाडा द्वारा अनुदान ६.५ करोड़ रुपये (लगभग)
५. दिल्ली दुग्ध याजना के लिये न्यूजीलैंड का अनुदान ८५ लाख रुपये (लगभग)
६. केरल राज्य का मत्स्य विकास योजना के लिये नार्वे सरकार द्वारा अनुदान १ करोड़ रुपये (लगभग)
७. विविध कार्यों के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए फोर्ड फाउन्डेशन द्वारा अनुदान ९० लाख रुपये (लगभग)

अगस्त २९,१९५६ को अतिरिक्त खेती की उपजों का आयात करने के लिये भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच एक समझौता हुआ। इसके अनुसार कुल ३६ करोड़ डालर की सहायता भारत को प्राप्त होगी जो १७२ करोड़ रुपये के बराबर है। इसमें आधा जहाजरानी का खर्च अदा करने की रकम भी शामिल है इसके अनुसार, अगले ३ वर्षों के भीतर भारत अमरीका से खेती में पैदा होने वाली वस्तुएं मंगा सकेगा।

कनाडा सरकार ने कोलम्बो योजना के अंतर्गत भारत की सहायता के लिये १.३ करोड़ डालर की रकम देना स्वीकार किया है। इसमें से ७० लाख डालर मद्रास राज्य में स्थित कुण्डा जल-विद्युत योजना पर खर्च होगा।

संयुक्त राष्ट्रसंघ की विभिन्न संस्थाओं से भी आर्थिक सहायता प्राप्त होने की उम्मीद है। यह भी आशा है कि अंतर्राष्ट्रीय बैंक रेलों के लिये ४२ करोड़ रुपये ऋण देगा।

रूस की सरकार ने भारी मशीनों का निर्माण करने वाले कारखाने खोलने के लिये ६० करोड़ रुपये देने का भी वादा किया है।

इस तरह हमें लगभग ४२० करोड़ रुपये के बराबर मूल्य का विदेशी विनिमय मिल गया है या देने का वायदा किया गया है। इसमें संयुक्त राज्य अमरीका से हुए समझौते की १३७ करोड़ रुपये की रकम भी शामिल है। और यह रकम कुछ खास उपभोक्ता वस्तुएँ मंगाने पर खर्च होगी। इस राशि को विदेशी विनिमय की अपनी जरूरत है उसमें जोड़ा नहीं जा सकता। हां, इससे उपभोक्ता वस्तुओं की बढ़ी हुई मांग पूरी की जा सकेगी और मूल्यों के मुद्रास्फीतिक बढ़ाव को रोका जा सकेगा।

अमरीका को चांदी की वापसी

भारत की ओर से अमरीकी सरकार को उधार-पट्टे की जो चांदी लौटाई जा रही है, उसमें छठे किंग जार्ज के शासनकाल में जारी किए गये चार धातुओं के मिश्रित के रुपये, अठन्नी और चवन्नी के सिक्के भी रहेंगे। प्रत्येक रुपए के सिक्के का वजन १८० ग्रेन, अठन्नी का ९० ग्रेन और चवन्नी का ४५ ग्रेन है। प्रत्येक सिक्के में ५० प्रतिशत चांदी, ४० प्रतिशत तांबा, ५ प्रतिशत जस्ता और ५ प्रतिशत शिल्प होता है। ये सिक्के देने से लगभग १२ करोड़ २० लाख औंस शुद्ध चांदी लौटाई जायगी। चांदी की छड़ों के रूप में लगभग ५ करोड़ औंस शुद्ध चांदी और लौटायी जायगी। भारत को कुल मिलाकर १७ करोड़ २० लाख औंस चांदी लौटानी है। इसमें से लगभग ३० लाख औंस की शुद्ध चांदी की पहली किश्त भेजी जा चुकी है।

——

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(पृष्ठ २६१ का शेष)

व्यावसायिक क्षेत्र से सुझाव दिये गये हैं कि इस योजना के अन्तर्गत परिदत्त पूंजी, ऋण, डिबेंचर और कार्यकारी पूंजी के रूप में प्रयुक्त सुरक्षित निधियों को सम्मिलित न किया जाये। साथ ही यह भी सुझाया गया है कि योजना के अनुसार जमा को थोड़ा-थोड़ा करके चुकाने की नीति अपनाई जानी चाहिए, जिससे कि बैंकों पर दबाव अधिक न पड़े और स्थिर तथा कार्यकारी पूंजी के निमित्त उन्हें रुपया निकालने की सुविधा मिलनी चाहिए।

विधेयक को पेश करते समय वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया था कि वार्षिक लाभ के ७५ प्रतिशत जमा के स्थान पर ५० प्रतिशत जमा करने की छूट दी जाएगी। साथ ही अन्य आश्वासन भी देते हुए उन्होंने विश्वास दिलाया कि योजना को सरल बनाने का प्रयत्न किया जायेगा और आवश्यकता होने पर न्यायोचित संशोधन भी किया जायेगा। अभी-अभी जो नियम प्रकाशित हुए हैं और व्यावसायिक वर्ग ने अपने जो न्यायोचित सुझाव और कठिनाइयां पेश की हैं—उन्हें साथ-साथ देखने से स्पष्ट है कि इन नियमों से उनको कोई राहत नहीं मिली, जैसा आश्वासन दिया गया था। जो कुछ थोड़ी बहुत छूट मिली भी है, उनको वित्त मंत्री संसद या बाहर पहले ही व्यक्त कर चुके थे। लाभ को कार्यकारी पूंजी के रूप में प्रयोग करने की ढाल का जिक्र वह दक्षिणी भारत में व्यावसायिकों की एक सभा में कर चुके थे और बैंकों को योजना से अलग रखने की घोषणा वे संसद में ही कर चुके थे।

इस योजना को प्रस्तुत करने का सरकार का उद्देश्य 'निष्क्रिय साधनों'' का उपयोग करना और सट्टा तथा दूसरी कम्पनियों के शेयर खरीदने में कम्पनियों के धन का दुरुपयोग रोकना कहा गया है। लेकिन फिर भी मूल प्रश्न तो रह ही जाता है कि क्या देश की औद्योगिक कम्पनियां इस भार का वहन करने में समर्थ हैं? जैसे कहा भी जा चुका है देश की अधिकांश कम्पनियां इस योग्य नहीं। इससे उनके लिए अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी। बहुतों का तो अस्तित्व ही खतरे में पड़ जायेगा। फिर सरकार ने इस योजना के सम्बन्ध में अपना जो उद्देश्य बताया है, उसमें भी पूर्ण सचाई नहीं। देश में आर्थिक परिस्थितियों का दबाव इतना है कि "निष्क्रिय साधनों" का प्रश्न उठता ही नहीं। फिर कम्पनियों के धन के दुरुपयोग को रोकने के लिये - कम्पनी एक्ट कैपिटल इश्यू में पूरी सहायता मिल सकती है।

सरकार ने योजना के नियमों का प्रारूप जनमत के लिये प्रकाशित किया तो है पर उनका सम्बन्ध अधिकतर व्यवसायिक वर्ग से है। साधारण जनता की उनसे रुचि होगी भी कितनी? इनके उद्देश्य की पूर्ति के लिए अच्छा तो यह है कि सरकार और व्यवसायी इकट्ठे होकर इन पर खुल कर विचार करें और इनमें आवश्यकतानुसार संशोधन-परिमार्जन किया जाये। अभी ३ मई को उद्योगपतियों का एक प्रतिनिधि मंडल सरकार से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने सरकार से अनिवार्य जमा योजना के सम्बन्ध में बातचीत की कि उनको अपने चालू लाभ का कितना प्रतिशत सरकार के पास (रिजर्व बैंक में) जमा करना होगा। इसके साथ ही प्रतिनिधि मंडल ने फेडरेशन आव इंडियन चेम्बर आफ कामर्स के अनिवार्य-जमा-योजना सम्बन्धी कुछ सुझावों और आलोचनाओं को स्पष्ट किया। इसके अलावा भी सरकार के पास १ दर्जन तक सुझाव, इस अनिवार्य जमा-योजना के विषय में आ चुके हैं।

यह सच है कि देश की आर्थिक उन्नति के लिये अवश्य ही पूंजी-साधनों की आवश्यकता है और उसके लिये यदि व्यवसायी वर्ग समर्थ है तो उसे त्याग करने में संकोच नहीं होना चाहिए पर यदि सरकार की 'किसी न किसी तरह धन लेने' की प्रवृत्ति से उद्योग-कम्पनियों के अस्तित्व पर ही आ बने, तब सरकार को सोच-समझ से काम लेना ही होगा।

सरकारी विज्ञापनों के लिए स्वीकृत
राजस्थान शिक्षा विभाग से मंजूरशुदा

सेनानी साप्ताहिक

सम्पादक :—
सुप्रसिद्ध साहित्य सेवी श्री शंभुदयाल सक्सेना

कुछ विशेषताएं—
★ ठोस विचारों और विश्वस्त समाचारों से युक्त
★ प्रान्त का सजग प्रहरी
★ सर्वाधिक लोकप्रिय पत्र

ग्राहक बनिए, विज्ञापन दीजिए, रचनाएं भेजिए
नमूने की प्रति के लिए लिखिए—
व्यवस्थापक, साप्ताहिक सेनानी, बीकानेर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

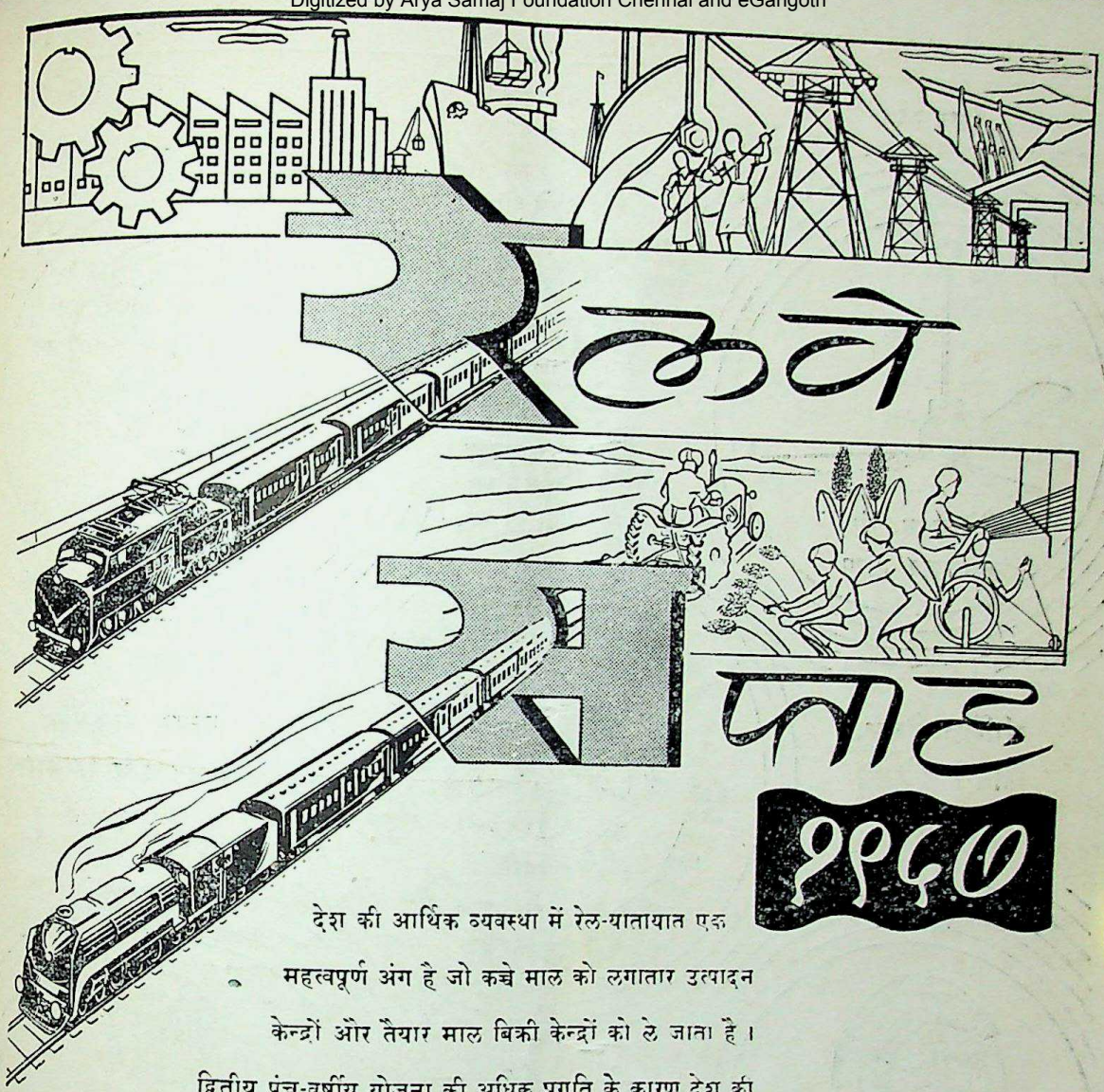

देश की आर्थिक व्यवस्था में रेल-यातायात एक महत्वपूर्ण अंग है जो कच्चे माल को लगातार उत्पादन केन्द्रों और तैयार माल बिक्री केन्द्रों को ले जाता है। द्वितीय पंच-वर्षीय योजना की अधिक प्रगति के कारण देश की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये रेलें एक बार फिर अग्रसर हो रही हैं। जो कार्य हमें सौंपा गया है उसे पूरा करने के लिये हम रेलवे सप्ताह के अवसर पर फिर से दृढ़ निश्चय करने जारहे हैं। मध्य और पश्चिम रेलों पर अनेक नई योजनायें चालू हैं और उनमें से कुछ लगभग पूरी होने जा रही हैं। इन सबका यह उद्देश्य है कि अधिक यातायात क्षमता, यात्रियों को अधिक आराम और सुविधायें प्राप्त हों ताकि द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के अंत में यात्री यातायात १५ प्रतिशत और माल यातायात ४० प्रतिशत योजना प्रारंभ होने के समय की अपेक्षा अधिक हो जाये।

INDIAN RAILWAYS

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कैसेल्स
आनन्द
लकी
आज़ाद

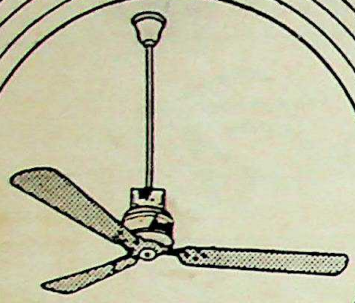

कैसेल्स ए. सी.
कैपैसिटर टाइप

कैसेल्स टिल्टिंग
केबिन फैन

एम. ई. आई. पंखे

मैचवैल इलैक्ट्रिकल इण्डिया लि०

आरामदेह होते हैं

सीलिंग, टेबुल,
केबिन व रेलवे
के पंखे

एअर सर्कुलेटर,
पेडेस्टल व सिनेमा
टाइप पंखे

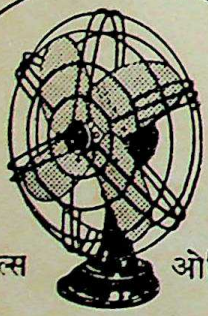

कैसेल्स ओसिलेटिंग
व फिक्सड़ टेबुल फैन

मैचवैल इलैक्ट्रिकल
(इण्डिया) लि०
४/११ आसफ अली रोड,
पोस्ट बाक्स नं० १५६
नई दिल्ली
टैलीफोन : २७८७१–२७८७२
तार : मैचवैल

कैसेल्स ए सी. एअर
सर्कुलेटर

सम्पादक कृष्णचन्द्र विद्यालङ्कार द्वारा, अशोक प्रकाशन मन्दिर के लिए अर्जुन प्रेस दिल्ली से मुद्रित व प्रकाशित।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्पदा

भारत-रूस-सहयोग
परिशिष्ट सहित

जून १९५७

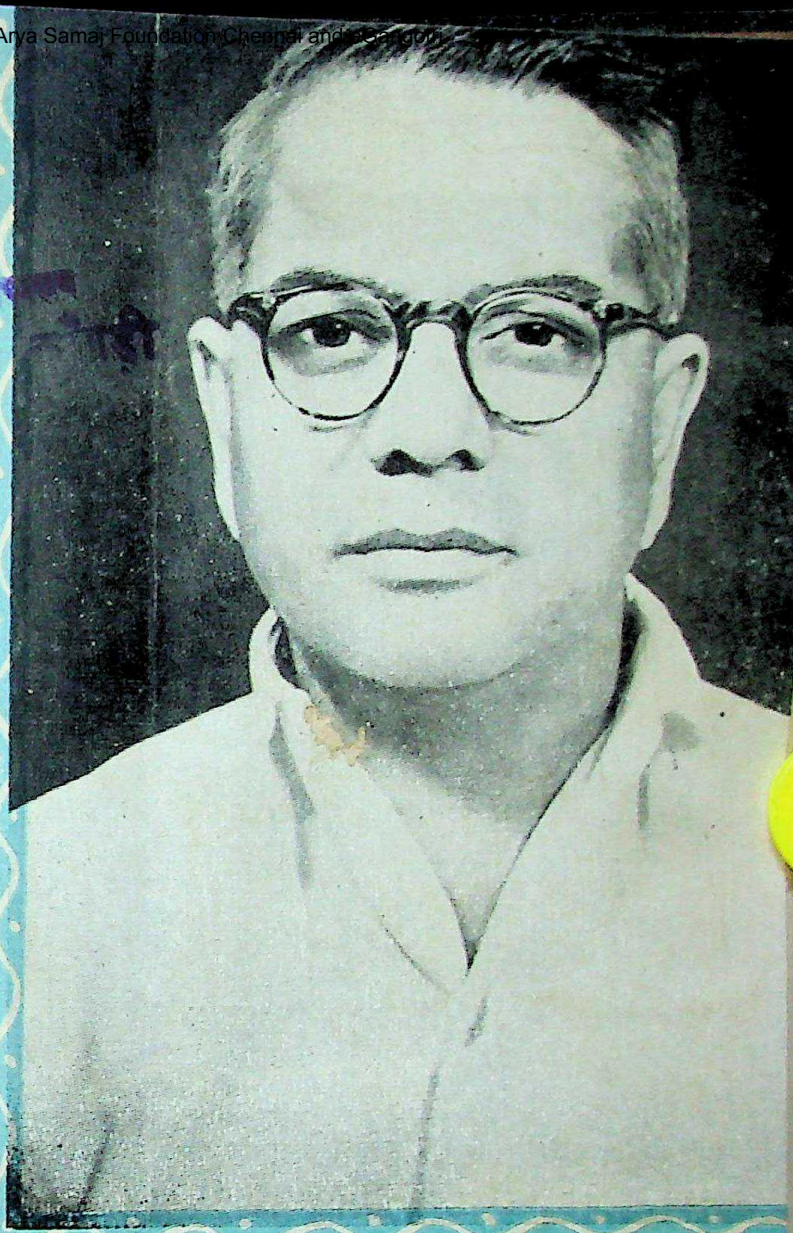

भारत के वित्तमंत्री श्री ति. त. कृष्णमाचार्य

पंचवर्षीय योजना की पूर्ति के लिए विशाल वित्तीय साधनों की व्यवस्था का कठिनतम गुरु भार वित्तमंत्री के कन्धों पर है। नये कर-प्रस्तावों के कारण सम्पन्न और सामान्य जन, उद्योगपति, व्यापारी, ग्राहक तथा सभी राजनीतिक दलों की कठोर आलोचना का लक्ष्य बनते हुए भी वित्तमंत्री ने राष्ट्र निर्माण के पुनीत यज्ञ में अपनी आहुति डालने के लिए सभी वर्गों का आवाहन किया है।

सम्पादक
कृष्णचन्द्र विद्यालंकार

मूल्य
७५ नये पैसे

अशोक प्रकाशन मन्दिर : रोशनारा रोड, दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

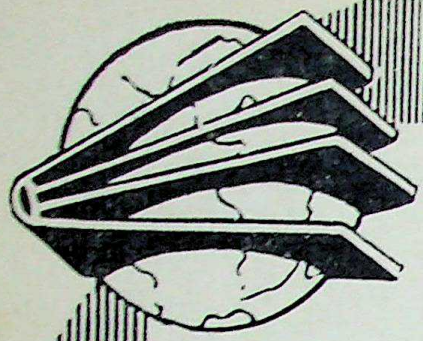

सोवियत जनता के बारे में अधिक जानकारी के लिए पढ़िये

सोवियत लैण्ड

सचित्र पाक्षिक पत्रिका निम्न लिखित भाषाओं में प्रकाशित होती है : अंग्रेजी, हिन्दी, बंगाली, उर्दू, तेलगू, तमिल, पंजाबी मराठी, उड़िया, मलयालम, गुजराती और कन्नड़

मूल्य की दरें

वार्षिक	रु० ४.००
अर्ध वार्षिक	रु० २.००
त्रैमासिक	रु० १.१०
एक अंक	रु० ०.२०

सोवियत संघ पर अन्य प्रकाशन

	रु० न० पै०
१. सोवियत संघ-१०० प्रश्न व उत्तर (अंग्रेजी)	०.५०
२. सोवियत संघ में योजना ,,	०.१२
३. सोवियत विद्यार्थी (अंग्रेजी व हिन्दी)	०.२५
४. सोवियत संघ में पेंशन सिस्टम (अंग्रेजी)	०.२५
५. सोवियत कज़ाकिस्तान ,,	०.२५
६. सोवियत ग्राम में एक औषधालय (गुजराती व अंग्रेजी)	०.१०
७. रूस में मुसलमान (अंग्रेजी उर्दू व मलयालम)	०.२०
८. घर और स्कूल (मराठी व हिन्दी)	०.१३
९. सोवियत रूस में विवाह और परिवार (उर्दू व अंग्रेजी)	०.२०

उपर्युक्त प्रकाशनों के लिए निम्नलिखित पते पर या सीधे हमें लिखें—

पीपल्स पब्लिकेशन्स हाउस प्राइवेट लि०

आसफ अली रोड, दिल्ली।

सोवियत रूस का सूचना विभाग (भारत स्थित सो० दूतावास)

२५ बारा खम्बा रोड, पोस्ट बक्स २४१, नई दिल्ली

फोन नं० ४०५८५

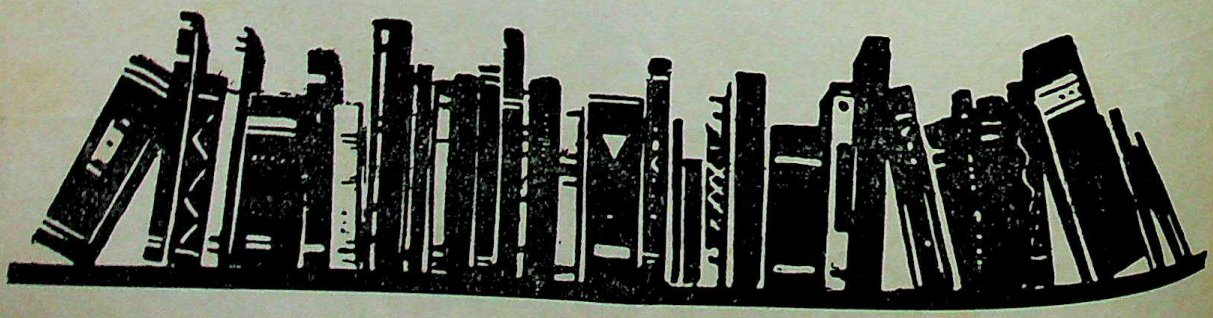

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

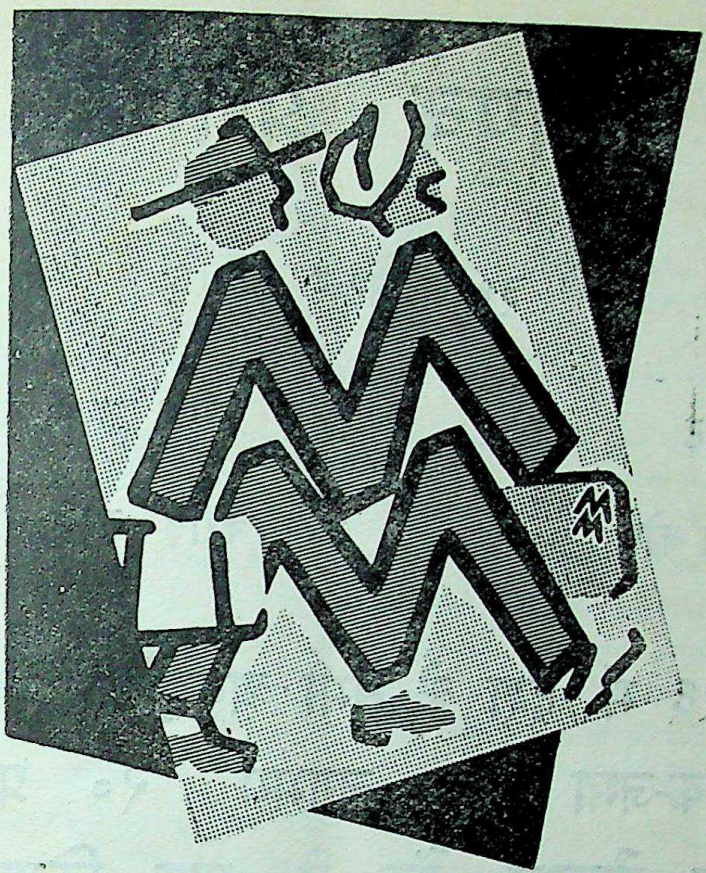

लीपजिग की अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी

प्राविधिक उपभोक्ता पदार्थों के प्रदर्शन के लिए

१ से ८ सितम्बर १९५७ तक

बढ़ा दी गई

विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क स्थापित कीजिये—

लीपजिग फेअर एजेंसी

पो० बा० सं० १९९३, बम्बई—११

अथवा

लीपजिग फेअर एजेंसी

मेहता मैंशन्स, ३ री मंजिल,

३ ए० डी० जी० स्कीम आसफ अली रोड, नई दिल्ली।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अपूर्व प्रगति

३१ दिसम्बर १९५६

डिपोजिट	१०६ करोड़ रुपये से अधिक
कार्यगत कोष	१४१ करोड़ रुपये से अधिक

१९५६ में देश के सभी अनुसूचित बैंकों के अधिक-जमा का लगभग २० प्रतिशत पंजाब नैशनल बैंक ने प्राप्त किया है।

चेयरमैन—

श्री एस० पी० जैन

दी पंजाब नैशनल बैंक लिमिटेड

प्रधान कार्यालय : दिल्ली

६२ वर्षों की विश्वासनीय सेवा का बृहत अनुभव

ए. एम. वाकर—जनरल मैनेजर

सम्पादक कृष्णचन्द्र विद्यालङ्कार द्वारा, अशोक प्रकाशन मन्दिर के लिए अर्जुन प्रेस दिल्ली से मुद्रित व प्रकाशित।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्पदा

वर्ष ६] जून १९५७ [अङ्क ६

हमारा नया बजट

भारत सरकार के वित्तमंत्री श्री कृष्णमाचारी ने अपना प्रतीक्षित बजट पेश कर दिया। मार्च में भी उन्होंने अन्तरिम बजट पेश किया था, किन्तु उस समय तक आम चुनाव नहीं हुए थे और नई सरकार का, जिसे इस वर्ष सारा शासनकार्य चलाना है और जिसके सिर पर योजना की पूर्ति का उत्तरदायित्व है, निर्माण नहीं हुआ था। तब न कोई नए कर लगाए गए थे। उस समय यह अवश्य स्पष्ट हो गया था कि देश की आर्थिक स्थिति बहुत गम्भीर है, समस्त अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ रहा है और निरन्तर आकार व लक्ष्य बढ़ते जाने के कारण नई पंचवर्षीय योजन की पूर्ति का भारी उत्तरदायित्व देश की जनता के कंधों पर है; इसके लिए सभी को—जनता के प्रत्येक अंग को अपनी ओर से अंशदान देने के लिए उद्यत रहना चाहिए। उसी समय यह सम्भावना की जाने लगी थी कि नया बजट देश के बजट-इतिहास में अभूतपूर्व होगा और उसमें भारी नये-नये कर लगाए जायंगे।

देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत भारी दबाव को कम करने के अनेक उपाय हैं। पहला तो यह कि हम अपनी नई योजनाओं के लक्ष्य काफी कम कर लें, किन्तु देश के नेताओं ने इसे अपनाना देश के गौरव के प्रतिकूल समझा। दूसरा उपाय यह है कि देश का उत्पादन खूब बढ़ाया जाय और निर्यात व्यापार का विशेष विकास किया जाय। उत्पादन बढ़ाने के लिए जो कारखाने बन रहे हैं या जो नई योजनाएं बन रही है, उनकी पूर्ति में कुछ समय लगेगा। लोहे के कारखाने १९५९-६० में उत्पादन प्रारम्भ कर सकेंगे। नई प्रस्तावित नहरें व बांध भी पूर्ण होने में कुछ समय लगेगा। तीसरा उपाय यह है कि समस्त देश अधिक से अधिक त्याग करे और राष्ट्रनिर्माण में अपना अंशदान दे। वित्तमंत्री ने इसी तीसरे मार्ग का अनुसरण किया है।

सम्पदा के पाठक अन्यत्र नये करों के सम्बन्ध में विस्तार से पढ़ेंगे। इन करों को हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में बांट सकते हैं। प्रत्यक्ष कर वे होते हैं, जो करदाता से सीधे ले लिए जाते हैं, जैसे आयकर या कारपोरेशन-टैक्स। इन करों का सीधा प्रभाव करदाता की जेब पर पड़ता है। अप्रत्यक्ष कर वे होते हैं, जिनका प्रभाव उस पर नहीं पड़ता, जिससे कर वसूल किये जाते हैं, वह भार उन पर पड़ता, है, जो उस चीज का उपयोग करते हैं। जैसे उत्पादन कर या सीमाशुल्क। इन अप्रत्यक्ष करोंका प्रभाव बहुत व्यापक होता है। चाय, कहवा, चीनी तम्बाखू, दियासलाई, तेल आदि पदार्थों पर उत्पादन करों में वृद्धि का बोझ देश की आम जनता को ही उठाना होगा। सीमेण्ट, लोहे तथा मोटर स्पिरिट व डीजल आयल आदि पर बढ़ाए गए नए करों का प्रभाव भी जनता पर पड़ेगा। किराया बढ़ेगा तो मध्यमश्रेणी के उत्पादकों, मकान निर्माताओं को यह भार उठाना पड़ेगा। विभिन्न ९४ वस्तुओं पर सीमा-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शुल्क (आयातकर) का प्रभाव भी मध्यम श्रेणी के करदाताओं को उठाना पड़ेगा। रेलवे मंत्री ने माल भाड़े को बढ़ा दिया है। इसका प्रभाव भी खरीददार पर पड़ेगा, क्योंकि व्यापारी बढ़ा हुआ भाड़ा मूल्य में वसूल कर लेगा।

अनेक अर्थशास्त्रियों ने और विशेषकर उद्योगपतियों ने यह सुझाव दिया है कि सरकारी कर नीति का क्षेत्र अधिकाधिक व्यापक व विस्तृत होना चाहिए और देश की सामान्य जनता को भी राष्ट्रनिर्माण में अंशदान करना चाहिए। प्रत्यक्ष करों से, जो प्रायः सम्पन्न वर्ग पर लगते हैं, पूंजीनिर्माण कठिन हो जाता है। इसका उत्तर देते हुए दो मास पूर्व पं० जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह सच है कि इस देश में करभार भारी है। लेकिन इस देश की उस ८० प्रतिशत जनता के भार के विषय में क्या कहा जाय? उस पर भार पहले ही काफी भारी है और इन वर्षों में यह बढ़ता ही गया है।" उन्होंने यह भी कहा था कि "देश के भाग्यनिर्माण में लोकतंत्रीय पद्धति के कारण ८० प्रतिशत की आवाज का बड़ा महत्व है इसलिए हमें ही (उच्च व मध्यवर्ग को ही) यह भार बरदाश्त करना है।"

लेकिन श्रीकृष्णमाचारी के अप्रत्यक्ष्य कर-प्रस्तावों को देखते हुए यह कहना कठिन है कि सरकार इस नीति का पालन कर रही है। जितने अप्रत्यक्ष कर लगाए गए हैं, उनसे कुल ६६.८८ करोड़ रु० की नई प्राप्तियां सरकार को होती हैं, अर्थात् इनका भार गरीब करदाता पर पड़ेगा। चीनी, चाय, तमाखू और दियासलाई से क्रमशः १८.५५, २.४५, ६.१५ और ६.२ करोड़ रु० की प्राप्तियां तो प्रायः सामान्य जनता की जेब से निकलेंगी। यह ठीक है कि राष्ट्र सबका है, अमीर का भी, गरीब का भी और इसलिए राष्ट्र-निर्माण यज्ञ में सभी को अपनी श्रद्धा व सामर्थ्य के अनुसार आहुति डालनी चाहिए। लेकिन जिस त्याग की आशा वित्तमंत्री ने की है, वह असाधारण है।

दूसरे प्रकार के वे कर लगाए गए हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं। इन्हें भी दो भागों में बांटा जा सकता है। रेलवे किराये में वृद्धि का भार तो आम जनता पर पड़ेगा। किराये में १० व १५ प्रतिशत वृद्धि जनता के लिए बहुत भारी पड़ेगी। डाकदर में वृद्धि, पोस्टकार्ड की मंहगाई का प्रभाव साधारण जनता पर कम नहीं पड़ेगा। दूसरे भाग में वे कर आते हैं, जो सम्पन्न या मध्यमवर्ग पर लगाये गये हैं। आयकर की न्यूनतम छूट की सीमा ४२०० से घटाकर ३००० रु० वार्षिक कर दी गई है। आज की मंहगाई व बढ़े हुए जीवनस्तर के युग में २५० रु० मासिक वेतन पाने वाले के लिए आयकर भारी पड़ेगा। आयकर, कारपोरेशन कर, सुपरटैक्स आदि में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, इनसे कर व्यवस्था कुछ आसान अवश्य हो जायगी, परन्तु करों का भार कुछ कम होकर पूंजी निर्माण की बाधा दूर होगी यह संभावना नहीं की जा सकती। शायद समाजवादी पद्धति के लिए उत्सुक वित्तमंत्री यह चाहते भी नहीं। पूंजीनिर्माण के स्वाभाविक उन्मुक्त मार्ग को छोड़ कर आज सरकार वित्तनिगम बनाकर पूंजीनिर्माण का क्षेत्र भी स्वयं लेने की कोशिश कर रही है।

नये करों में दो प्रस्ताव बिलकुल नये हैं। उत्तराधिकारकर तो पहले से लग चुका है। अब सम्पत्तिकर व

विषय सूची

क्रम	विषय	पृष्ठ संख्या
१	हमारा नया बजट	३०१
२	सम्पादकीय टिप्पणियां	३०३
३	प्लेनिंग का आधार ग्रामदान	३०६
४	अर्थशास्त्र का आशावाद और निराशावाद	३०९
५	दूसरी योजना में वित्तीय समस्या	३११
६	आज की हमारी अर्थ-व्यवस्था	३१३
७	सभी वर्गों से आहुति का आह्वान	३१६
८-१८	भारत-रूस परिशिष्ट (परिशिष्ट की विषय सूची ३२३ पर)	३२३-३४३
१९	ग्राम-दान और भारत की भूमि-समस्या	३४४
२०	अर्थवृत्तचयन	३४६
२१	राष्ट्र का आर्थिक प्रवाह	३४८
२२	बैंक व बीमा	३५२
२३	भारत कर नया रेल बजट (२६३)❀	३५५
२४	नया सामयिक साहित्य (२६७)	३५९
२५	कागज-उद्योग पर एक दृष्टि (२६९)	३६१

❀ पृष्ठ संख्या गलती से ३५५ आदि के बजाय २६३ आदि लगी है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

व्यय कर के प्रस्ताव पेश किए गए हैं। जिसके पास एक नियत परिणाम से अधिक की सम्पत्ति होगी उस पर यह वार्षिक कर लगेगा। व्यय कर तो करों के इतिहास में नई चीज है और प्रो० कैल्डार के नए प्रस्ताव की स्वीकृति है। जो परिवार एक नियतराशि (पति व पत्नी २४००० रु० तथा प्रत्येक आश्रित बालक ५००० रु०) से अधिक व्यय करेगा उस पर यह कर लगेगा। इन दोनों करों का उद्देश्य अमीर व गरीब के अन्तर को कम करके समाजवादी व्यवस्था लाने की दिशा में एक प्रयत्न करना है। अभी तो इन करों की दर बहुत कम है, परन्तु आगामी वर्षों में ये कर सुरसा के बदन की तरह उग्र रूप धारण कर सकते हैं।

इस तरह हमने एक दृष्टि डाल कर देखा कि वित्त मंत्री के नये कर प्रस्ताव बहुत भारी और जनता पर बहुत बोझ लादने वाले हैं। स्वयं वित्तमंत्री इसे स्वीकार करते हैं। लेकिन वह कहते हैं कि "वर्तमान परिस्थितियों में यह अनिवार्य है। एक ऐसे देश में, जहां अधिकतर व्यक्तियों की आय कम है, विकासकार्य को तब तक वित्तपोषित नहीं किया जा सकता, जब तक कि समाज के सभी वर्गों के लोग त्याग न करें।"

हमने ऊपर देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव कम करने के लिए तीन उपायों की चर्चा की है, जिसमें से कर-भार पर अधिक विस्तार से लिखा गया है। वित्तव्यवस्था पर दबाव कम करने के लिए एक चौथा उपाय है—मुद्राप्रसार या नोट छापने वाले मुद्रणालयों की सहायता। सरकार अनेक वर्षों से इसे अपना रही है और वित्तमंत्री श्री कृष्णमाचारी ने भी घाटे की वित्तव्यवस्था को स्वीकार किया है। २ अरब रु० से अधिक नोट जारी किए जावेंगे। लेकिन इस व्यवस्था का बहुत अधिक आश्रय लेने से महंगाई का संकट बहुत बड़ी नई समस्या पैदा कर देता है। वित्तमंत्री ने ठीक ही कहा है—"मैं मानता हूं कि इससे विकास में सहायता मिलती है। परन्तु यह औषध है, जो थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ही खाई जा सकती है। भोजन नहीं है, जिसे पर्याप्त मात्रा में लिया जावे।" इसलिए करों, ऋणों और बचतों का ही अधिक आश्रय लेना होगा।

वित्तीय व्यवस्था पर दबाव कम करने के लिए एक पांचवां उपाय है—शासन-व्यवस्था तथा कार्यमें मितव्यय। एक ओर वित्तमंत्री स्थिति का विकट चित्र खींचकर जनता को त्याग का उपदेश देते हैं। दूसरी ओर शासनतंत्र तथा विविध कार्यों में मितव्यय के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। यदि मितव्यय और सादगी को आदर्श बनाया जाय तो करोड़ों रु० की बचत की जा सकती है।

इतने भारी टैक्स लगाने का स्पष्ट अर्थ यही है कि भारत सरकार की सम्मति में गम्भीर आर्थिक परिस्थिति आ चुकी है और देश के प्रत्येक अंग को इस में आहुति देने के लिए तयार होना चाहिये। हम यह मानते हैं कि यदि देश को अपनी योजनाएं पूर्ण करनी है और इसमें सन्देह नहीं कि वे योजनाएं पूर्ण करनी हैं तो देश को भारी त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिये। लेकिन ऐसे असाधारण संकट के समय यह जरूरी है कि पहले अपने कम जरूरी खर्चों को काटा जाय। पार्लियामेंट में वोट गिनने की मशीन पर लाखों रुपया खर्च करना अनावश्यक था, केन्द्र और राज्यों के विभिन्न विभागों द्वारा प्रकाशित पत्रों में आर्ट पेपर और चित्रों की भरमार के बिना भी काम चल सकता है। हर एक विभाग में फोटो ग्राफरों की संख्या कम हो सकती है। जब देश में विदेशी मुद्रा की इतनी कमी है, तब नये ट्रान्समीटर स्टेशन दो तीन साल के लिए स्थगित किये जा सकते हैं। रेडियो के प्रोग्राम के घण्टे कम कर दिये जायं तो प्रतिवर्ष लाखों रुपये बचत हो सकती है। सरकारी कार्य के लिए भी (अपवाद छोड़ कर) बड़ी मोटरों के बजाय छोटी मोटरें ली जायं तो भी कीमत व पेट्रोल के खर्च में बचत हो सकती है। आलीशान इमारतों का मोह छोड़कर सादी लेकिन मजबूत इमारतें बनायी जा सकती हैं। और सबसे बढ़कर जब इतना संकट काल अनुभव किया जा रहा है, तब यह प्रस्ताव विचारणीय तो अवश्य है कि ८००) रु० या अधिक वेतन पाने वालों के वेतन व महंगाई भत्ते १५ से २५ प्रतिशत तक कम कर दिये जायें। संसद के सदस्यों के भत्ते कम हो सकते हैं। उनके जीवनस्तर में कुछ कमी खटकती नहीं। कम से कम देश को इससे कोई क्षति नहीं होगी। जिस भयंकर संकट की ओर संकेत करते हुये वित्त मंत्री भारी कर लगा रहे हैं, उसमें यह कदम उठाना असंगत नहीं है। इसका एक परिणाम यह होगा कि साधारण जनता

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

से त्याग की अपील की जा सकेगी। उसके सामने शासक और ऊंचे कर्मचारी आदर्श रख सकेंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष श्री ढेबर ने ठीक कहा है—"जहां राष्ट्र को त्याग के लिए कहा जा रहा है, वहां सरकार भी अपने खर्च में कमी करने का प्रयत्न करे।"❀

अ० भा० कां० कमेटी में

नये साल के बजट के अतिरिक्त गत मास अन्य अनेक दृष्टियों से भी महत्वपूर्ण रहा है। अ० भा० कां० कमेटी के अधिवेशन में अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों की विशेष चर्चा हुई। एक प्रस्ताव में आर्थिक नीति सम्बन्धी सरकारी दृष्टिकोण का समर्थन किया गया और प्रथम योजना की सफलता की प्रशंसा तथा समाजवादी उद्देश्य का समर्थन करते हुए तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कमी न करने पर बल देते हुए भारत सरकार के बजट करों का बिना किसी अपवाद के जिस तरह समर्थन किया गया, इससे स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस आजकल सरकार का मार्ग-दर्शन नहीं करती, किन्तु सरकारी नीति का अनुमोदन व प्रसार ही उसका कर्तव्य रह गया है। आर्थिक नीति-सम्बन्धी प्रस्ताव में कहा गया है कि योजना के लक्ष्यों और गति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिये, समाजवादी समाज की स्थापना का उद्देश्य सामने रहना चाहिये, इस्पात कोयला बिजली का उत्पादन निर्दिष्ट रूप में होना चाहिये, सब क्षेत्रों में अधिक उत्पादन का ध्येय सामने रखते हुए कोई ऐसा काम नहीं किया जाना चाहिए, जिससे उत्पादन की गति धीमी हो, शरणार्थियों के पुनर्वास, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा अपव्यय रोकने की चेष्टा करनी चाहिये और कांग्रेसियों को योजना की पूर्ति में सहायता तथा प्रचार में लग जाना चाहिये। प्रायः सब वक्ताओं ने कांग्रेस की नीति का समर्थन मात्र किया। कोई वक्ता ऐसे नहीं थे, जिनसे यह प्रतीत हो कि कांग्रेसी भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से, किसी प्रश्न पर विचार कर सकते हैं, बहुत सम्भवतः कांग्रेस में मुख्य प्रश्नों पर स्वतन्त्र विचार करने की भावना अथवा साहस समाप्त हो गया है। पंचवर्षीय योजना की विशालता के साथ-साथ देश की क्षमता को नहीं भूल जाना चाहिये था। उत्साह और भावुकता के साथ-साथ वास्तविक स्थिति पर भी विचार किया जाना आवश्यक है।

❀ ❀ ❀

पंचवर्षीय योजना की पूर्ति उत्पादन और विशेषतः अन्न के उत्पादन पर निर्भर करती है। खाद्यान्नों के मूल्य जिस तरह बढ़ रहे हैं, वह अत्यन्त चिन्ता जनक हैं। पंडित नेहरू जी ने ठीक ही कहा है कि हमारे सामने सबसे पहला सवाल अनाज की पैदावार बढ़ाना है चाहे इसके लिये सिर पटकना पड़े या फोड़ना पड़े। अन्न-उत्पादन सम्बन्धी विशालकाय प्रस्ताव में १८ सुझाव सरकार को दिये गये हैं, जिनमें भूमि-सुधारों को जल्दी से जल्दी लागू करना, सिंचाई के साधनों का विस्तार और उनका पूर्ण उपयोग, बंजर भूमि का सुधार, अन्न की बरबादी से रक्षा, भोजन के अपव्यय पर रोक, सहकारी समितियों पर अधिक बल, गहरी खेती, वैज्ञानिक खाद के साथ-साथ प्राकृतिक खाद का प्रचार, सामुदायिक विकास योजनाओं से सहयोग, अनाज के सट्टे और संग्रह पर रोक, खाद्यान्नों की न्यूनतम कीमत का निर्धारण मुख्य है। इसमें सन्देह नहीं कि अन्न उत्पादन की गम्भीर समस्या को देखते हुए हमें अपनी पूरी ताकत इस काम में लगा देनी चाहिये। इन प्रस्तावों पर अमल करने से निस्सन्देह अन्न के उत्पादन में सफलता मिलेगी, किन्तु जनता का सहयोग पाने के लिये यह आवश्यक है कि सभी राजनैतिक और सार्वजनिक संस्थाओं का सहयोग प्राप्त किया जाये, सामुदायिक योजना तथा भारत सेवक समाज आदि को केवल सरकारी या कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की संस्था बनाने से काम नहीं बनेगा।

❀ ❀ ❀

आयात व निर्यात

इस मास में आयात और निर्यात के सम्बन्ध में अनेक क्रांतिकारी कदम उठाये गए हैं। बहुत सी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध लगा है तथा निर्यात के प्रोत्साहन की नीति अपनाई गई है। सीमेण्ट की कमी को देखते हुए कुछ इमारतों का निर्माण भी रोक दिया गया है। वस्तुतः अन्न उत्पादन के बाद पंचवर्षीय योजना की पूर्ति में सबसे अधिक यदि कोई चीज सहायक हो सकती है, तो यह अनुकूल विदेशी व्यापार है। १९५६ में गत वर्ष की

[सम्पादक

❀ मालूम हुआ है कि सरकार इस दिशा में कुछ कदम उठाने पर विचार कर रही है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अपेक्षा निर्यात आय ४ करोड़ रुपए कम हुई। विभिन्न वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार अब जो योजनायें बना रही है उनसे यह आशा की जाती है कि यदि अन्न संकट के कारण विदेशी अन्न बहुत न मंगाना पड़ा तो व्यापार की व्यवस्था अच्छी हो जायगी, किन्तु इसके लिये आवश्यक है कि विदेशों से आयात पर प्रतिबन्ध लगाया जाय। केन्द्र के उद्योग-व्यापार मन्त्री अत्यन्त योग्य, कुशल तथा दृढ़ व्यक्ति हैं। उन्होंने विदेशी दवाइयों तथा सिनेमा की फिल्मों पर भी कुछ प्रतिबन्ध लगाये हैं, यह उनकी सूझ और दूरदर्शिता की सूचक है। चलचित्रों की लम्बाई यदि कुछ कम हो जाय तो कोई हानि होने वाली नहीं है। अखबारी कागज के उपयोग पर भी—अखबारों की पृष्ठ संख्या अन्धाधुन्ध बढ़ा देने पर भी कुछ प्रतिबन्ध लगना चाहिए। विदेशी शराब का आयात भी सर्वथा बन्द कर दिया जाना चाहिए। विदेशी कपड़े का आयात भी सर्वथा बन्द कर दिया जाय तो कोई हानि नहीं होगी। हमें विश्वास करना चाहिए कि भले ही भारत सरकार ने इस दिशा में कुछ देर से ध्यान दिया है परन्तु श्री मोरार जी देसाई की दृढ़ नीति इस सम्बन्ध में, अवश्य सफल होगी।

राज्यों के कर भी

विभिन्न राज्यों में नये वर्ष के बजट फिर से पेश किये जा रहे हैं। भारत सरकार की नीति के अनुसार ही सब राज्य सरकारें जनता पर तरह तरह के टैक्स लगा रही हैं। जब समस्त देश की नीति एक हो, तब किसी एक राज्य की कर-नीति की आलोचना का कोई लाभ नहीं है। हमारा अपना ख्याल है कि केन्द्रीय और राज्य-सरकारों द्वारा नये कर लगाये जाने के बाद स्थानीय संस्थायें भी नये कर लगाने पर पीछे नहीं रहेंगी और इनके सब के परिणामस्वरूप जनता भारी बोझ से दब जायेगी। अभी तक केन्द्रीय सरकार के नये कर प्रस्ताव ही हमारे सामने हैं और उनकी कठोरतम आलोचना की जाती है किन्तु वस्तु स्थिति को ठीक समझने के लिए हमें राज्य सरकारों के कर भी सम्मिलित कर लेने चाहिएं। पंजाब सरकार ने मोटर स्पिरिट का भाव एक आना प्रति गैलन बढ़ा दिया है। यात्री किराया भी आधा पाई प्रति आना बढ़ा दिया है। और कपास, गुड़ जैसी व्यापारिक वस्तुओं पर भी नया कर लगा दिया है। राजस्थान सरकार ने नये नये बिक्री करों से पचास लाख रु० की आशा की है और आबकारी मोटर टैक्स, मनोरंजन कर लगाये गये हैं। जो कर इन राज्यों में लगाये गये हैं, अन्य राज्य भी वे या उससे मिलते जुलते कर लगायेंगे। इस प्रकार संयुक्त रूप में देश की जनता पर कितना कर का भार बढ़ेगा, इसकी कल्पना करने में कुछ समय लगेगा।

राष्ट्रीय आय

भारत सरकार की एक प्रकाशित सूचना से ज्ञात होता है कि १९५५-५६ में भारत की राष्ट्रीय आय १०४२० करोड़ रु० थी अर्थात् प्रति व्यक्ति आय २७२.१ रु० थी। १९५३-५४ में यह आय २६८.७ रु० थी। इसी पत्रक में यह बताया गया है कि प्रथम पंच वर्षीय योजना की अवधि में राष्ट्रीय आय १७.७ प्रतिशत बढ़ी, जब कि योजना में ११ प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। यह अंक संतोषजनक है किन्तु जब हमें यह मालूम होता है कि पदार्थों के मूल्य पहले से बढ़ गये हैं तो यह आमदनी बहुत आशाजनक प्रतीत नहीं होती। वर्तमान मूल्यों के आधार पर यदि गणना की जाय तो प्रतिकूल परिस्थिति दृष्टिगोचर होती है। १९५३-५४ में प्रति व्यक्ति आय २८०.७ रु० थी जो १९५५-५६ में २५२ रु० रह गयी। यह ठीक है कि अधिकारियों ने राष्ट्रीय आय की इस कमी का कारण यह माना है कि १९५३-५४ में कृषि-पदार्थों के मूल्य बहुत अधिक थे। इस प्रकार के परिपत्रक बहुत अधिक स्थिति स्पष्ट नहीं करते, फिर भी यह निश्चित है कि भारत में प्रति-व्यक्ति आय बढ़ रही है। यह आय और भी बड़ी प्रतीत होती, यदि १९५६-५७ में पदार्थों के मूल्य बहुत न बढ़ जाते।

बढ़ती हुई मंहगाई

अप्रैल १९५६ के थोक मालों के सूचक अंकों से एक वर्ष बाद सूचक-अंक ७.९ प्रतिशत बढ़ कर ४२२.१ हो गया। मार्च १९५० से भी यह मूल्य ज्यादा हैं। चावल का भाव एक मास में १.५ प्रतिशत बढ़ा है। चीनी और गुड़ के भाव बढ़ जाने से अन्य खाद्य सामग्री का भाव भी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्लैनिंग का आधार ग्रामदान ही

आचार्य विनोबा

इस समय ग्रामदान और ग्रामदान के आधार पर ग्रामोद्योग प्रधान रचना की कई कारणों से हिन्दुस्तान को आवश्यकता है। उसमें सबसे बड़ा और एक नैमित्तिक कारण उपस्थित है, और नैमित्तिक कारण बलवान होता है। ग्रामदान के लिए ग्रामीण योजना, ग्रामोद्योग-प्रधान योजना के लिए भी एक बलदायी नैमित्तिक कारण उपस्थित है कि आज दुनिया की स्थिति अत्यन्त डांवाडोल है और कोई नहीं कह सकता कि कब महायुद्ध छिड़ जाय। यह काल्पनिक भय नहीं है, बल्कि दुनिया का जो चित्र आज हमारे सामने है, उसके अन्दर यह चीज पड़ी है।

अगर लड़ाई छिड़ जाय, तो कुल पंचवर्षीय योजना गिर जायगी, असम्भव होगी। इसलिए जो नेशनल प्लैनिंग करेंगे, उन पर यह जिम्मेवारी है कि अपना प्लैनिंग वे इस ढंग से करें कि दुनिया में लड़ाई शुरू हो, तो भी प्लैनिंग न सिर्फ टिका रहे, बल्कि जोर भी पाये। अगर प्लैनिंग ऐसा बनाया हो कि लड़ाई की सम्भावना ही नहीं है, शांति बनी रहेगी, तो कहना होगा कि हमने ठीक ढंग से और दुनिया की हालत सोच कर प्लैनिंग नहीं बनाया, बल्कि आंख मूंद कर बनाया। जाहिर है कि नेशनल प्लैनिंग आंख मूंद कर नहीं बनाया जा सकता। उस प्लैनिंग में कम-से-कम कुछ तो हिस्सा ऐसा हो, जो किसी भी हालत में मजबूत रहे और वह महत्त्व का भी हिस्सा हो। मैंने पंचवर्षीय प्लैनिंग का जो अध्ययन किया है, उससे मुझे यह भरोसा नहीं हुआ कि ऐसी दृष्टि रख कर प्लैनिंग किया हो। उसमें यह माना है कि दुनिया में शांति रहेगी। समूचे राष्ट्र के प्लैनिंग के लिए इस तरह मानना, आज की हालत में मैं नहीं मानता कि प्लैनिंग के शास्त्र में बैठेगा। यह वस्तु ही अशास्त्रीय प्लैनिंग है। मैं सिर्फ यह करना चाहता हूँ कि इस समय ग्रामदान और ग्रामीण योजना एक "डिफेन्स मेजर" है, यह सबको ध्यान में रखना चाहिए।

ग्रामदान की उत्कटता क्यों ?

वैसे ग्रामदान स्थायी वस्तु और स्थायी विचार है, इसलिए आहिस्ता-आहिस्ता ही वह विकसित हो सकता है और होगा, यह मानने में मुझे कोई उज्र नहीं था; बल्कि मैं यह भी मान सकता था कि सौ-दो सौ, पांच सौ ग्रामदान हासिल हुए, तो अब उन्हें अच्छे बनाओ, विकसित करो और फिर दूसरे ग्रामदान हासिल करो। इस तरह गो स्लो (Go Slow) की बात भी मैं कह सकता था, क्योंकि यह मूलभूत विचार है और मूलभूत विचार यदि आहिस्ता-आहिस्ता फैलता है, तो उसमें दोष नहीं है। परन्तु आज देखते हैं कि इस विचार के लिए इस समय मैं जरा उतावला हुआ हूँ। मन में इतनी अधीरता क्यों आयी है, इसका कारण यह है कि अगर यह काम हम जल्दी करते हैं, तो सब तरह से बच जाते हैं और यदि जल्दी नहीं करते हैं तो हम अपना काम कर ही नहीं पायेंगे। उसकी हमें उतनी चिंता नहीं है, परन्तु उससे देश का अपना काम कर ही नहीं पायेंगे। देश का ही कुल प्लैनिंग गिरेगा, तो सरकार की प्रतिष्ठा गिरेगी। यह कहने के पीछे एक बड़ी भूमिका है कि मेरे सामने लड़ाई का चित्र खड़ा है। मैं किसी को भयभीत नहीं करना चाहता, न खुद भयभीत होना चाहता हूँ, बल्कि लड़ाई छिड़ जाय, तो हमें अधिक धैर्य-सम्पन्न और सावधान

(शेष पृष्ठ ३५२ पर)

बढ़ गया है, कपास और जूट के भाव बढ़े हैं। यह स्थिति किसी तरह अच्छी नहीं कही जा सकती। जब तक मूल्य कम नहीं किये जायेंगे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होना कठिन है। सरकार ने मूल्य न बढ़ने देने के लिए कुछ कठोर आदेश जारी किये हैं कि वह निर्यात-मूल्य पर स्टाक खरीद सकती है, सट्टे पर भी प्रतिबन्ध लगाये हैं, कुछ क्षेत्रों के यातायात पर भी प्रतिबंध लगाये जा रहे हैं। इन उपायों की सफलता की कामना करते हुए भी आज यह कहना कठिन है कि कन्ट्रोल की दिशा में जाने से स्थिति में कहां तक सुधार होगा।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अर्थशास्त्र का आशावाद और निराशावाद

प्रो० विश्वम्भरनाथ पाण्डेय

२

डेविड रिकार्डो (१७७२-१८२३ ई०) तथा राबर्ट माल्थस इसलिये निराशावादी थे कि उन्होंने मानव समाज के आर्थिक भविष्य का एक विवादग्रस्त तथा अन्धकारपूर्ण चित्र खींचा था और आदि समाजवादी इसलिये निराशावादी थे कि उन्होंने फिजिओक्रेटों तथा आदमस्मिथ के 'आशावाद' का विरोध और प्रतिकार किया। संक्षेप के लिये रिकार्डो और माल्थस के जिन सिद्धान्तों ने फिजिओक्रेटों तथा आदमस्मिथ की 'प्राकृतिक व्यवस्था' की क्रान्ति को मलिन किया तथा मानव समाज के आर्थिक समाज के दुखी भविष्य की घोषणा की, उनमें से क्रमशः उनके 'लगान' और 'जनसंख्या' के सिद्धान्त की ही चर्चा यहां हम करेंगे।

लगान का सिद्धान्त

रिकार्डो के लगान की विशेषता यह थी कि उसने निरपेक्ष लगान (absolute rent) के अस्तित्व को अस्वीकार किया तथा भेदात्मक लगान (differential rent) के अस्तित्व की व्याख्या की। रिकार्डो ने कहा कि भूखण्डों की प्राकृतिक उर्वरता तथा बाजार आदि से सम्बन्धित उनकी स्थिति में भेद होने के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन व्यय एक समान नहीं हो सकते। अधिक उर्वर और बाजार से अधिक निकट खेतों की खेती सस्ती होगी अपेक्षाकृत उन खेतों की खेती के जो कम उर्वर तथा बाजार से दूर स्थित हैं। किंतु बाजार में चूंकि अन्न का भाव एक ही होगा, अतः वह कम से कम इतना ऊँचा तो होगा ही कि सबसे निम्नकोटि (सबसे कम ऊर्वर तथा सबसे दूरस्थ) के खेतों की खेती का व्यय निकल आए। परिभाषिक शब्दावली में इस प्रकार के खेतों को, जिनकी आय उनकी खेती के व्यय के बराबर होती है, सीमान्त भूमि कहते हैं। स्पष्ट है कि ऐसे खेतों से श्रेष्ठतर खेतों (अधिसीमान्त भूखण्डों) की खेती का व्यय भी उनसे कम होगा और उत्पादन की मात्रा भी अधिक होगी। इसलिये सीमान्त भूमि के उत्पादन व्यय के आधार पर निश्चित किये गये खाद्यान्नों के मूल्य के कारण इस अधिसीमान्त भूमि के कृषकों को सीमान्त भूमि के कृषकों की अपेक्षा अधिक लाभ होगा। सीमान्त भूमि और अधिसीमान्त भूमि के ऊपज के इसी अंतर तथा तज्जन्य अधिसीमान्त भूमि पर के अतिरिक्त लाभ को ही 'लगान' कहते हैं।

लगान की इस व्याख्या से यह स्पष्ट है कि आबादी की वृद्धि तथा अन्न के भाव में वृद्धि के कारण सीमान्त भूमि की जाति (Quality) जितनी ही गिरती जायेगी, अधि सीमान्त और सीमान्त भूमि के उपज का अन्तर उतना ही बढ़ता जायेगा और लगान भी उतना ही अधिक होगा। चूंकि मूल्य के बढ़ने से लगान बढ़ता है इसलिये रिकार्डो ने भूमि के ह्रासमान उपज की ओर संकेत तो किया ही साथ ही उसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भूमिपतियों तथा उपभोक्ताओं के हित परस्पर विरोधी हैं। उपभोक्ता का हित खाद्यान्नों के सस्ता होने में है जबकि भूमिपति का हित उनके मंहगा होने में। इस तरह रिकार्डो ने आदमस्मिथ की उस 'प्राकृतिक व्यवस्था' का प्रतिकार किया जिसके अनुसार समाज के प्रत्येक वर्ग के हित में समानता और अनुकूलता की कल्पना की गई थी।

> गतांक में विद्वान लेखक ने पश्चिमी अर्थ शास्त्र के इतिहास पर एक दृष्टि डालते हुए बताया था कि समय-समय पर आशा और निराशा के विचार उसे प्रभावित करते रहे हैं। इस लेख में उसी क्रम को जारी रखते हुए वर्तमान अर्थशास्त्र तक विवेचक दृष्टि डाली गई है।

माल्थस का सिद्धान्त

माल्थस का 'जनसंख्या का सिद्धांत' सरल और संक्षिप्त है। अपने सिद्धांत की प्रतिस्थापना के लिये उसने एक सूत्र की रचना की और कहा कि जब कि जनसंख्या ज्यामितिक गति (१,२,४,८,२६,३२,···आदि) से बढ़ती है, संसार की खाद्य पूर्ति मात्र अंकगणित की सहज गति (१,२,३,४,५,६,··· आदि) से बढ़ती है। अतः जनसंख्या की गति खाद्य सामग्री की वृद्धि से तीव्रतर है और यदि किसी प्रकार जनसंख्या को नहीं थामा गया तो निश्चय ही कालान्तर में खाद्य सामग्री

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

की अपेक्षा खाने वालों की संख्या अधिक हो जायेगी, जिसका परिणाम भुखमरी, दुर्भिक्ष, महामारी, आत्महत्या, शिशुहत्या और युद्ध जैसी नाना प्राकृतिक विभीषिकाओं के रूप में प्रकट होगा जिनके द्वारा प्रकृति अतिरिक्त जनसंख्या को नष्ट करने की कोशिश करती है। इस तरह माल्थस ने रिकार्डो से भी अधिक अंधकारपूर्ण एवं विवादग्रस्त मानव-भविष्य का चित्र उपस्थित किया।

दो श्रेणियों की उत्पत्ति

सिसमंडी आदि समाजवादियों के दूसरे निराशा-वादी वर्ग की चर्चा करने के लिए हमें तत्कालीन यूरोप और विशेषकर इङ्गलैंड के आर्थिक इतिहास का सिंहावलोकन करना होगा। यह १९ वीं शताब्दी का प्रारम्भ था। १८ वीं शताब्दी के मध्य से जिस औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ था, उसने अब तक एक ऐसे पूंजीवादी समाज की रचना कर डाली थी, जिसकी कोख से उस सर्वथा अकिंचन वर्ग का जन्म हुआ था जो मिलों में काम करके मजदूरी से अपना पेट भरता था। आर्थिक विषमता का चक्र तेजी से चल रहा था। धनी और भी धनी हो रहे थे और निरन्तर शोषण के कारण गरीब और भी गरीब। सामाजिक न्याय के विरुद्ध मिलों और फैक्टरियों में कम मजदूरी देने के प्रलोभन में पुरुष मजदूरों की अपेक्षा स्त्री व बच्चे मजदूरों को ही रक्खा जाता था। काम करने के घंटे मनमाने होते थे, वातावरण सर्वथा हीन और अस्वास्थ्यकर। गर्भिणी स्त्रियों तथा बीमार मजदूरों को भी छुट्टियां नहीं दी जाती थीं। थोड़े में, जैसा कि बाद में कार्लमार्क्स ने कहा, मजदूर वर्ग का हर तरह से शोषण हो रहा था। इसी परिस्थिति में मजदूर वर्ग का आंदोलन शुरू हुआ जो धीरे-धीरे समाजवाद में बदल गया।

सिसमंडी (१७७३-१८४२ ई०) उन अर्थशास्त्रियों में एक था जिन्होंने समाज में धनी और गरीब, पूंजीपति और मजदूर दल, इन दो परस्पर विरोधी और संघर्षशील वर्गों के अस्तित्व की घोषणा की थी। उसने पूंजीवादी समाज के उन आधारभूत कारणों की भी व्याख्या की जिनसे समाज का एक बहुत बड़ा भाग निरन्तर गरीब बनता जाता है। कार्लमार्क्स के यथार्थ अग्रवर्ती पुरखा के रूप में उसने यह जोर देकर कहा था कि पूंजीपतियों के हाथ में आर्थिक शक्तियों की जितनी ही वृद्धि होगी, वृहत्तर समाज की आर्थिक स्थिति का उतना ही ह्रास होगा तथा उत्पादन और उपभोग की क्रियायें इतनी अनमेल होती जाएंगी कि एक दिन पूंजीवादी राष्ट्र के सम्मुख महान आर्थिक संकट आ खड़ा होगा।

इस प्रकार सिसमंडी ने फिजिओक्रेसी तथा आदमस्मिथ के आशावाद तथा उनके स्वतः स्थापित होने वाले सामाजिक सांमजस्य की भावना को खोखला कर दिया।

इसी प्रकार ब्रे, ग्रे, थाम्पसन और हेजस्किन आदि समाजवादियों ने भी रिकार्डो के विचारों के आधार पर तत्कालीन पूंजीवाद की भर्त्सना की। उन्होंने अपने समाज में मजदूर संघों के आन्दोलन देखे थे, तथा पूर्ववर्ती समाजवादी विचारों का अध्ययन किया था। इन सबके बल पर उन्होंने इस विचारधारा पर जोर दिया कि अर्घ का स्रष्टा है मजदूर वर्ग। किंतु पूंजीपति इसका अधिकांश भाग हथिया लेता है। उनके सामने का शोषित दुखी और दीन समाज आदमस्मिथ और फिजिओक्रेट्स की 'प्राकृतिक व्यवस्था' का मूर्तिमान विरोध था।

फिर आशावाद की ओर

इस तरह हम देखते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से उत्पन्न तत्कालीन सामाजिक बुराइयों की प्रतिक्रिया के रूप में इंग्लैण्ड और फ्रान्स में सर्वत्र जिस समाजवाद और हस्तक्षेपवाद (interventionism) का विकास हो रहा था, उसके प्रभाव से अर्थशास्त्र की विचारधारा अपने आदि-काल की तुलना में विपरीत दिशा की ओर मुड़ चली थी और सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री जीड के शब्दों में अब समय आ गया था जब अर्थशास्त्र को अपने उस पुराने मार्ग पर लाना आवश्यक था जो फिजिओक्रैटों और आदम स्मिथ के जमाने से पीछे छूट गया था। यह काम प्रमुखतः फ्रांस के १९ वीं शताब्दी के उदारवादी पीठ (Liberal School) के अर्थ शास्त्रियों ने किया।

इस उदारवादी पीठ के प्रतिनिधि अर्थशास्त्री थे सर्वश्री बेस्टियट, ड्यूनोअर, लेवासर और अमेरिकन लेखक श्री हेनरी चार्ल्स केरे। सन् १८३० से १८५० ई० के २० वर्षों में अर्थशास्त्र की यह पुनरावर्तित (वापस आई हुई) आशा-वादी विचारधारा अपने उत्कर्ष पर थी। इस वर्ग के अर्थ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शास्त्रियों का विश्वास था कि निराशावाद ही अनेक आर्थिक कष्टों का कारण है जिसका निराकरण आशावाद की पूर्ण प्रतिष्ठा से ही हो सकता है। उनका विचार था कि सामाजिक और आर्थिक बुराइयों का कारण पूर्ण व्यक्तिगत स्वातंत्र्य नहीं, अपितु अपूर्ण व्यक्तिगत स्वातंत्र्य है। अतः इनका उपचार और भी पूर्ण और व्यापक व्यक्तिगत स्वतंत्रता से ही हो सकता है। अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक 'हारमोनिज' में बेस्टियट ने लिखा कि 'हम लोगों ने कितनी ही चीजों की परीक्षा की है किन्तु कितना आश्चर्य है कि पूर्ण मानवीय स्वतंत्रता के प्रभाव की परीक्षा कभी नहीं हुई।' उसने यह भी कहा कि ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य के मन में सत् की ओर एक स्वाभाविक और जबरदस्त प्रवृत्ति की रचना कर रखी है और इतनी बुद्धि दे रखी है कि वह कभी 'अच्छे' को देखने में चूक नहीं सकता। अस्तु यदि मनुष्य अपने पर छोड़ दिया जाय तो ईश्वर की प्राकृतिक इच्छा के अनुकूल सामाजिक कल्याण के अतिरिक्त और कुछ अन्य नहीं घट सकता।' इस प्रकार अर्थशास्त्रीय चिन्तन में आशावाद की एक बार फिर जीत हुई और उन सभी सामाजिक सुधार की विधियों की निन्दा की गई जिनकी रचना गरीबों और मजदूरों की रक्षा के लिये की गई थी तथा आर्थिक क्षेत्र में सर्वत्र पूर्ण प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहन एवं समर्थन दिया गया।

कार्लमार्क्स का आविर्भाव

किन्तु यह विवेचना अपूर्ण रह जाएगी यदि हम यहां कार्लमार्क्स और उनके आर्थिक विचारों की संक्षेप से चर्चा नहीं करते। फिजिओक्रैट्स, आदमस्मिथ तथा फ्रांस के १९ वीं शताब्दी के उदारवादी पीठ के अर्थशास्त्रियों के सैद्धान्तिक 'आशावाद' की कल्पना के बावजूद भी उस समय के पूंजीवाद के दुष्परिणाम से गरीब और अमीर के बीच की खाई निरन्तर बढ़ती जा रही थी और तत्कालीन समाज की दुखद आर्थिक विषमता तथा 'विपुलता के बीच विपन्नता' की स्थिति ने परमदयालु 'नियति' (a benevolent Providence) की कल्पना को निराधार और झूठा प्रमाणित कर दिया था। इसी समय कार्लमार्क्स का प्रादुर्भाव हुआ जो एक राजनीतिज्ञ से अधिक एक अर्थशास्त्री था। अर्थशास्त्र के इतिहास के लेखक श्री एरिकरोल के शब्दों में कार्लमार्क्स के आर्थिक सिद्धांतों से अधिक और किसी युग के किसी भी अर्थ-शास्त्री के विचारों का प्रभाव राजनीति के व्यावहारिक-पक्ष पर आज तक नहीं पड़ा। कार्लमार्क्स आदियुगीन अर्थशास्त्री रिकार्डो के परिवार का अन्तिम वंशज कहा जाता है। उसने अपने सिद्धांतों को रिकार्डो के विचारों की बुनियाद पर खड़ा किया किन्तु उनका विकास सिसमण्डी आदि आदिसमाजवादियों के विचारों के प्रकाश में किया। उसने कहा कि पूंजीवाद में कुछ ऐसे आधारभूत अन्तर्विरोध हैं जिनके कारण वह अपने विनाश का बीज स्वयं बोता है और कालान्तर में स्वयं ही टूट जायेगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अन्दर स्वयं ही एक दिन ऐसा संक्रमणकाल आयेगा जब कि चिरदलित, चिर-शोषित मजदूरवर्ग क्रान्ति कर उठेगा और पूंजीवाद के स्थान पर 'मजदूरों का अधिनायकतंत्र' (dictatorship of the proletariate) स्थापित होगा जिसके तत्वावधान में एक साम्यवादी समाज की स्थापना होगी जहां समाज 'सबसे क्षमता के अनुसार काम लेगा और सब को आवश्यकता के अनुसार सामग्रियां देगा'। इस साम्यवादी समाज की पूर्णावस्था में राज्य की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। स्पष्ट है कि कार्लमार्क्स का यह निष्कर्ष फिजिओक्रैट्स तथा आदमस्मिथ की क्रमशः 'प्राकृतिक व्यवस्था' और 'अदृष्ट सत्ता' की कल्पना से बहुत कुछ मिलता-जुलता है। इसीलिये हम कार्लमार्क्स को 'निराशावादी आशावादी' अथवा 'आशावादी निराशावादी' कह सकते हैं। कार्लमार्क्स ने कहा था कि किसी भी सिद्धान्त का विकास पक्ष, विपक्ष और समपक्ष इन तीन अवस्थाओं से होता है। पहले कोई पक्ष (वस्तुस्थिति) होता है, फिर उसका विरोध (विपक्ष) होता है और अन्त में न पक्ष रहता है न विपक्ष, अपितु दोनों ही का समन्वय रूप 'समपक्ष' (Synthesis) स्थापित होता है। अपने इस विचार की सत्यता का सबसे बड़ा उदाहरण कार्लमार्क्स स्वयं है। उसने रिकार्डो की निराशाप्रधान विचार प्रणाली का अनुसरण किया किन्तु स्वयं रिकार्डो के पूर्ववर्ती अर्थशास्त्री आदमस्मिथ के निष्कर्षों में मिल जाने से अपने को नहीं रोक सका। फिजिओक्रैट्स तथा आदमस्मिथ की 'प्राकृतिक व्यवस्था' से उत्पन्न सार्वजनिक आर्थिक वैषम्य और अन्याय (जिसका पारिभाषिक नाम 'पूंजीवाद' है) की प्रतिक्रिया के रूप में 'निर्यात'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

की नैसर्गिक दयालुता में अविश्वास रखने वाले यथार्थवादी सेन्टसाइमन, सिसमण्डी, प्रोदों, फरियर आदि समाजवादियों के 'हस्तक्षेपवाद' का जन्म हुवा जिसकी पूर्णाहुति कार्लमार्क्स के हाथों हुई। अब तक हमने अर्थशास्त्रियों के जिस वर्ग को 'आशावाद' से अभिहित किया है, उसके द्वारा राज्य की सक्रियता को अस्वीकार किया गया था। इसके विपरीत कार्लमार्क्स के पूर्वज समाजवादियों ने राज्य के अधिक से अधिक हस्तक्षेप और सक्रियता का समर्थन किया था। पर स्वयं कार्लमार्क्स ने समाजवादी विचारधारा का प्रबल समर्थक होते हुए भी, एक ऐसे समाजवादी समाज की कल्पना की जिसकी अन्तिम और पूर्णावस्था में राज्य का अस्तित्व खतम हो जायेगा। ('The State shall wither away') अब तक अर्थशास्त्रीय चिन्तन में जो आशावादी और निराशावादी धारा पृथक-पृथक चली आ रही थी, वह कार्लमार्क्स तक आकर रुक गई और शायद पहली बार उसके सिद्धान्तों में प्रच्छन्न रूप से मिल भी गई।

वर्तमान युग में

इसके बाद अर्थशास्त्र का वर्तमान युग प्रारम्भ होता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अर्थशास्त्रीय विधारधाओं का स्वरूप कभी आशावादी अथवा निराशावादी भले ही होता रहा हो, यह सत्य है कि आधुनिक सैद्धान्तिक अथवा व्यावहारिक अर्थशास्त्र न केवल निराशावादियों का अर्थशात्र है और न केवल आशावादियों का। ये दोनों ही धारायें आज एक रूप हो गई हैं। संसार में सर्वत्र कल्याण कार्य प्रधान सरकारें एक साथ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा संरक्षणवाद (Protectionism) की नीति अपनाती हैं। उनकी यह नीत नियंत्रित व्यापार स्वातंत्र्य (restrained Laissez faire) की हैं। संसार के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था (mixed economy) जहाँ लोकगत और व्यक्तिगत अंचलों के सहअस्तित्व के रूप में पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था के समन्वय की क्रिया परिणति हो रही है--चल रही है। इंगलैंड तथा यूरोप के अन्य पूंजीवादी देशों में भी कतिपय उद्योगों के राष्ट्रीयकरण तथा 'कारपोरेशनों' की स्थापना के रूप में आंशिक रूप से समाजवाद का व्यावहारिक पक्ष अंगीकृत हो रहा है।

इस प्रकार अर्थशास्त्रीय चिन्तन प्रणाली के 'आशावादी' और 'निराशावादी' पक्ष अब अलग-अलग दो धारायें न होकर मानव ज्ञान के एक ही बौधिक प्रवाह में संगठित हो गये हैं।

भारत सरकार के व्यापार और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित

'उद्योग व्यापार पत्रिका'

★ उद्योग और व्यापार सम्बन्धी प्रामाणिक जानकारी युक्त विशेष लेख, भारत सरकार की आवश्यक सूचनाएं, उपयोगी आंकड़े आदि प्रति मास दिये जाते हैं।

★ डिमाई चौपेजी आकार के ६०-७० पृष्ठ : मूल्य केवल ६ रुपया वार्षिक। एजेण्टों को अच्छा कमीशन दिया जायगा। पत्रिका विज्ञापन का सुन्दर साधन है।

★ लघु-उद्योग विशेषांक मंगा कर छोटे उद्योगों के सम्बन्ध में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त कीजिये।

★ ग्राहक बनने, एजेन्सी लेने अथवा विज्ञापन छपाने के लिए नीचे लिखे पते पर पत्र भेजिये :—

सम्पादक

उद्योग व्यापार पत्रिका

उद्योग और व्यापार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दूसरी योजना में वित्तीय समस्या

श्री बी० एल० अजमेरा

२३,५६ करोड़ रुपये की प्रथम पंचवर्षीय योजना से, राष्ट्रीय आय में १९५०-५१ में ८८५० करोड़ रुपये से, १९५५-५६ में १०,४४३ करोड़ रुपये की, अर्थात् १८ प्रतिशत की वृद्धि उल्लेखनीय सफलता की द्योतक है। खाद्य स्थिति में ६.५ करोड़ टन की प्रत्यक्ष वृद्धि हुई और औद्योगिक उत्पादन का सूचनांक भी १९५६ में १३४.७ रहा। इस अवधि में ४००-५०० करोड़ रुपये की घाटे की अर्थ व्यवस्था भी पूरी योग्यता के साथ संचालित की गई। मुद्रास्फीति फैलने के बजाय कीमतें नीचे ही रही। थोक कीमतों का सूचनांक, दिसम्बर १९५१ में ४३३.१ से गिरकर १९५२-५३ में ३८०.६, १९५४-५५ में ३७७.५ और १९५५-५६ में ३६०.३ हुआ। इस प्रकार प्रथम योजना काल मुद्रा स्फीति का विस्तार किए बिना सफलतापूर्वक समाप्त हुआ।

किन्तु ४८ अरब रुपयों की द्वितीय योजना, आर्थिक क्षेत्रों में भय और शंका का वातावरण फैलाए हुए हैं। ४८ अरब रुपयों में १२ अरब रुपये के घाटे की अर्थ व्यवस्था, अतिरिक्त नोट छाप कर की जायगी और ४ अरब रुपये की पूर्ति का अभी कोई हिसाब ही नहीं है। कुछ समय पूर्व में, उन्होंने घाटे को भोजन न मानकर औषधि माना था, जिसे स्वल्प मात्रा में लेना चाहिए। वित्तमंत्री श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने बताया थाकि सरकार घाटे की अर्थ व्यवस्था में कमी करने की समर्थक है। ख्याल था कि सरकार घाटे की अर्थ व्यवस्था घटा कर ८ अरब रुपये कर देगी। फिर भी सरकार को १२ अरब रुपयों (८ अरब की वित्त-व्यवस्था और ४ अरब अनिर्धारित) की व्यवस्था करनी पड़ेगी।

आर्थिक सिद्धांतों की कसौटी पर, इतने बड़े घाटे की व्यवस्था का प्रभाव, केवल १२ अरब रुपयों मे कहीं अधिक होता है। साधारणतः, यदि १०० करोड़ रुपये बाजार में डाले जायेंगे तो भारतीय दशाओं को देखते हुए, ८० करोड़ रुपये बाजार में, निजी क्षेत्रों में चलते रहेंगे और २० करोड़ रुपये बैंकों में जमा हो जायेंगे। बैंकों में २० करोड़ रुपयों की जमा रकम का विनियोग-प्रभाव, कम से कम पांच गुना होता है और इस तरह २० करोड़ का अर्थ १०० करोड़ रुपये के बराबर होगा। स्पष्ट है कि १०० करोड़ रुपये का प्रभाव १८० से २०० करोड़ रुपये तक बढ़ेगा और इसी अनुमान से कीमतों में वृद्धि होगी। इस गणित से, यह स्पष्ट है कि १२ अरब रुपये का प्रभाव वस्तुतः २५ से ३० अरब रुपये तक होगा। अतः घाटे की अर्थ-व्यवस्था का संचालन, साधारण और प्रत्यक्ष अनुमानों को बहुत पीछे छोड़ जाता है और मुद्रास्फीति और कीमतों की वृद्धि का कुचक्र प्रस्तुत करता है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आरम्भ होते ही मुद्रा-स्फीति का विचार प्रत्यक्ष सामने आने लगा। जुलाई १९५६ में थोक कीमतों का सूचनांक ४०९.२ और नवम्बर १९५६ में ४३३.२ तक बढ़ गया। इस कीमतवृद्धि में केवल मात्र मुद्रास्फीति का प्रभाव ही नहीं, बल्कि अन्य कारण भी हैं। द्वितीय योजना में अनेक बड़ी योजनाएं दीर्घकालीन है, जिन पर करोड़ों रुपया खर्च तो तुरन्त हो रहा है, किन्तु जिनका उत्पादन-फल कई वर्षों बाद मिलेगा। इसके अतिरिक्त, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए, सरकार ने बड़े कारखानों पर, अनेक उत्पादन वृद्धि सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगा दिए हैं, जिनका परिणाम सामग्री की कमी हो रही है। घरेलू उद्योग न तो शीघ्र उत्पादन बढ़ा सकते हैं और न ही उपभोक्ता तुरन्त घरेलू उद्योगों की वस्तुओं से अपनी मांग पूरी करने के आदी हैं। साथ ही विदेशों से भी उपभोक्ता सामग्री का आयात नहीं किया जा सकता है। सरकार इस समय लोहा और इस्पात के कारखानों तथा अन्य बड़े उद्योगों की भारी मशीनों का आयात कर रही है और हमारी स्टर्लिंग पूंजी का एक बड़ा भाग इसमें खर्च हो चुका है। जनवरी १९५६ में स्टर्लिंग पूंजी ७४२ करोड़ रुपयों से घट कर नवम्बर १९५६ में ५३९ करोड़ रुपयों तक आ गई। और अब तो ५०० करोड़ रुपये तक पहुँच गई है। इधर विदेशी व्यापारिक घाटा भी बढ़ता जा रहा है, १९५४ में ४६ करोड़ रुपये, १९५५ में ४० करोड़ और १९५६ के प्रथम ११ महीनों में १८९ करोड़ रुपये हो गया। भारतीय बाजार में मुद्रा का प्रसार

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भी बढ़ रहा है। अक्टूबर १९५५ में १९७८ करोड़ रुपये, जनवरी १९५६ में २०९४ करोड़ रुपये, और अक्टूबर १९५६ में २१२१ करोड़ रुपये की मुद्रा का चलन हो गया।

इस प्रकार मुद्रा प्रसार और कीमतों में वृद्धि का कुचक्र चल पड़ा है। वित्त मंत्री श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये दो उपाय स्पष्ट किए हैं:—१–घाटे की वित्त रकम में कमी करना और २-अतिरिक्त करों द्वारा रुपया वसूल करना।

वस्तुतः, अतिरिक्त करों की चर्चा के साथ, न केवल रुपया इकट्ठा करने का लक्ष्य ही सामने आता है, किन्तु योजना के मूलभूत उद्देश्य समाजवादी समाज की रचना का निर्माण करना भी है। कैल्डर के कर प्रस्तावों—जिनमें पूंजी, उपहारों और व्यक्तिगत खर्चों पर कर लगाना आदि सम्मिलित हैं—की अभी कोई सक्रिय प्रगति नहीं हुई है❀। हां, सरकार ने दिसम्बर १९५६ से पूंजी पर लाभ कर लगा दिया है, किन्तु विषमता दूर करने सम्बन्धी अनेक नये कर लगाना अभी बाकी है। पूंजीपति क्षेत्र में यह विचार व्यक्त किया जा रहा है कि अतिरिक्त करों का बोझ उद्योगपति उपभोक्ताओं पर लाद देते हैं, और इससे यद्यपि वस्तुओं की मांग में कमी हो जाती है, किन्तु कीमतों की वृद्धि में कोई रुकावट नहीं पड़ती। यह विचार उपयुक्त नहीं है। नवीन करों को उचित सावधानी और अंकुशों के साथ लगाया जाये तो निश्चय ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी और सम्पत्ति का केन्द्रीयकरण दूर होगा।

किन्तु वर्तमान परिस्थितियों के अध्ययन से ऐसा लगता था कि सरकार तुरन्त क्रान्तिकारी कर व्यवस्था लागू नहीं करेगी, बल्कि वित्त मंत्री के अनुसार वितरण और कीमतों पर नियंत्रण लगाये जायेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय का अनुभव हमारे पास है, और यह निश्चिन्तता पूर्वक समझा जा सकता है कि कंट्रोल का कुचक्र चोर बाजारी और जमाखोरी है। अतः एक व्याधि दूर करने के लिये दूसरा असाध्य रोग मोल लेना बुद्धिमत्त नहीं है। इन साधनों से चाहे मुद्रास्फीति में क्षणिक रोक लग जाये, किन्तु उनके चारित्रिक और मनोवैज्ञानिक असर भारत जैसे देश को पिछड़ी हुई जनता पर बहुत खराब पड़ते हैं। कंट्रोल एक अंतिम दुर्गुण है जिसे सब साधनों के असफल होने पर ही युद्धकालीन मनोवृत्ति बनाकर उपयोग में लाया जा सकता है। अतः सरकार को कंट्रोल के स्थान पर अधिक क्रान्तिकारी कर व्यवस्था की ओर ही तत्काल ध्यान देना चाहिए।

यह ठीक ही है १९६१ तक के ५ वर्षों में ४८ अरब (जो बढ़कर ५३ अरब तक हो जाये) की रकम बहुत बड़ी रकम है। सरकार द्वारा टुकड़ा देने के बावजूद यह सुझाव अवश्य ही ध्यान देने योग्य है कि पंचवर्षीय योजना को सप्त वर्षीय कर दिया जाये। इससे चाहे विकास की रफ्तार में कुछ कमी पड़ेगी किन्तु साथ ही मुद्रास्फीति में नियन्त्रण हो जायेगा और जो भी कुछ प्रगति होगी वह ठोस होगी। यदि यह संभव नहीं है तो सरकार को क्रान्तिकारी कर व्यवस्था को अपनाकर समाजवादी समाज की रचना करने में नहीं हिचकना चाहिए। सख्त कदम शीघ्र उठाने चाहिए, नहीं तो जनतांत्रिक असन्तोष बढ़ता जायेगा।

❀नये बजट प्रस्ताव में ये कर भी लगाने के प्रस्ताव भी कर दिये गये हैं।

सुभाषित रत्नमाला

(सम्पादक—श्री कृष्णचन्द्र विद्यालंकार)

प्रस्तुत पुस्तक में वैदिक एवं संस्कृत साहित्य के अगाध भण्डार में से कुछ सरल एवं सुन्दर मन्त्र और श्लोक संगृहीत किए गए हैं। अल्प आयु के बालक भी इन्हें सुगमता पूर्वक कण्ठस्थ कर सकते हैं। श्लोकों का अर्थ सरल हिन्दी में किया गया है। अन्त में कुछ संस्कृत सूक्तियां भी अर्थ सहित दी गई हैं, जिन्हें विद्यार्थी अपने निबन्धों में प्रयुक्त कर सकते हैं। उपहार तथा पुरस्कार के लिए पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है।

पुस्तक का मूल्य केवल चौदह आने

अशोक प्रकाशन मन्दिर रोशनारा रोड दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आज की हमारी अर्थ-व्यवस्था

वित्त मन्त्रीश्री कृष्णमाचार्य

महंगाई

२७ अप्रैल को समाप्त होने वाले सप्ताह का सूचक अंक ४२३.५ था, जिसका अर्थ है एक वर्ष पहले के स्तर में ८.५ प्रतिशत की वृद्धि। इस समय चावल के मूल्यों का सूचक अंक ६३३ और गेहूं का ५८१ है। इस प्रकार ये एक वर्ष पहले के मूल्यों से क्रमशः १४.१ प्रति शत और १६.४ प्रति शत ऊंचे हैं। इस वर्ष औद्योगिक कच्चे माल के मूल्यों में ९ प्रति शत, अर्धनिर्मित वस्तुओं के मूल्यों में ५.३ प्रति शत और निर्मित वस्तुओं के मूल्यों में २.४ प्रति शत की वृद्धि हुई है। मूल्यों के बढ़ने की प्रवृत्ति का एक कारण यह है कि जितनी मांग है, अनाज का उतना उत्पादन नहीं हो रहा।

इस वर्ष २ करोड़ ६८ लाख टन चावल पैदा होने का अनुमान लगाया गया है, जबकि पहले यह २ करोड़ ५५ लाख टन का था। अब अनुमान लगाया गया है कि इस वर्ष सभी अन्नों का सम्पूर्ण उत्पादन ६ करोड़ ४८ लाख टन होगा, जब कि पहले केवल ६ करोड़ ३४ लाख टन की उपज का अनुमान लगाया गया था। इतने पर भी, इस वर्ष, १९५३-५४ की तुलना में लगभग ४० लाख टन की और १९५४-५५ की तुलना में २० लाख टन की कमी रह जाती है।

१९५६-५७ के कृषि-उत्पादन के सामान्य स्तरों के अनुमानों से संकेत मिलता है कि कुल मिलाकर उत्पादन पिछले वर्ष से कुछ अधिक रहना चाहिए। अनुमान है कि चावल का उत्पादन २ करोड़ ८० लाख टन के आसपास रहेगा, जो १९५५-५६ के उत्पादन से १२ लाख टन अधिक है। गेहूँ का उत्पादन ८६ लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि १९५५-५६ में यह ८३ लाख टन था। मोटे अनाज और दालों का उत्पादन लगभग उतना ही रहने का अनुमान है जितना १९५५-५६ में था। जहां तक व्यापारिक फसलों का सम्बन्ध है, सबसे हाल की सूचनाओं से पता चलता है कि कपास के उत्पादन में २० प्रतिशत, मूंगफली के उत्पादन में ६ प्रतिशत और और गन्ने के उत्पादन में लगभग १७ प्रतिशत की वृद्धि हुई है, लेकिन कुछ राज्यों में स्थिति खराब है।

नये उद्योगों ने, क्या भारी सामान और क्या उपभोग्य वस्तुओं के क्षेत्र में, पुराने उद्योगों की अपेक्षा अधिक तेजी से प्रगति की। परन्तु इस क्रिया से भारी सामान (केपिटल गुड्स) और कच्चे माल के आयात के लिए हमें बहुत अधिक विदेशी मुद्रा व्यय करनी पड़ी।

मुद्रातत्व

यदि केवल मुद्रा उपलब्धि को ही देखा जाय तो पिछले लगभग बारह महीनों में मुद्रा उपलब्धि बहुत अधिक नहीं थी। १३ अप्रैल, १९५६ और इस वर्ष १२ अप्रैल के बीच इसमें लगभग १३२ करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। रिजर्व बैंक के पास की विदेशी मुद्रा में तीव्र गति से कमी हुई। पिछले बारह महीनों में रिजर्व बैंक के पास रुपया प्रतिभूतियों (सिक्योरिटी) में २७३ करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। स्पष्ट रूप से यह मुद्रा-बाहुल्य की द्योतक है, जो मुख्यतः सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से अधिक ऋण लिए जाने और अंशतः प्रतिभूतियां बेच कर अपने साधनों की पूर्ति करने के सम्बन्ध में व्यापारिक बैंकों पर पड़ने वाले दबाव को प्रकट करती है। इस वर्ष अनुसूचित बैंकों ने गैर-सरकारी क्षेत्र को पूर्वापेक्षया १४७ करोड़ रुपए का अधिक ऋण दिया। इस कार्य से बैंकों की भुगतान क्षमता पर दबाव पड़ा है, मुद्रा दरें बढ़ी हैं तथा मुद्रा बाजार में तंगी बनी रही।

विदेशी विनिमय

देश के सम्मुख बड़ी समस्या विदेशी विनिमय साधनों पर लगातार पड़ने वाला भारी दबाव है। १९५६-५७ के वित्त वर्ष के आरम्भ से शोधन सन्तुलन पर बराबर दबाव पड़ रहा है जिससे देश की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि से लगभग ३०० करोड़ रुपया निकाला जा चुका है। चूंकि, इस अवधि में, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ६०.७ करोड़ रु० का ऋण लिया गया, इसलिए रिजर्व बैंक के पास

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

की विदेशी मुद्रा में लगभग २४० करोड़ रुपए की कमी हो गयी।

स्थूल अनुमान के अनुसार १९५६-५७ में १००० करोड़ रु० से अधिक के माल का आयात हुआ और लगभग ६५० करोड़ रु० के माल का निर्यात हुआ। वर्ष भर में जो अधिक माल बाहर से मंगाया गया, वह विकास सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए मंगाया गया। इस बात की अब गुंजाइश नहीं रही कि हम अपनी विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि से कोई बड़ी रकम निकाल सकें। अब बाहर से माल मंगाते समय इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हम कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं; हम विदेशी मुद्रा के कितने साधन जुटा सकते हैं और आयोजना की किन प्रायोजनाओं को सबसे पहले पूरा करना है।

इसलिए यह आवश्यक है कि राजस्व-विषयक और मुद्रा सम्बन्धी नीति इस दृष्टि से निर्धारित की जाय कि देश में माल की खपत कम हो और देश में तैयार होने वाला कुछ माल निर्यात किया जा सके। १९५७ के पहले तीन महीनों में २६ करोड़ गज सूती कपड़ा बाहर भेजा गया है। इस हिसाब से वार्षिक औसत १०० करोड़ गज से अधिक बैठता है।

१९ मार्च १९५७ को जो अनु अनुमान पेश किए गए थे, उनमें राजस्व ६३६.२२ करोड़ रुपए और व्यय ६६३.०९ करोड़ रु० दिखाया गया था। इस तरह से राजस्व खाते में २६.८७ करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया था। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे परिवर्तन किए गए जिनसे वर्तमान कर स्तर के आधार पर, राजस्व खाते के घाटे में अब ६.२५ करोड़ रुपये की वृद्धि का अनुमान है।

व्यय में वृद्धि तीन मदों के कारण हुई है। एक तो यह कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग को अम्बर चर्खे के विकास के लिए ३.१२ करोड़ रुपया अनुदान के रूप में देने की व्यवस्था की गई है। इस विस्तृत कार्यक्रम के आधीन ९० हजार और अम्बर चर्खे चालू करने का विचार है। अनुमान है कि इस कार्यक्रम पर चालू वर्ष में कुल १०.०९ करोड़ रुपया खर्च होगा। इसमें से ३.१२ करोड़ रुपया अनुदानों के रूप में और शेष ऋण के रूप में आयोग को दिया जायगा।

असम सरकार को कुछ सीमावर्ती इलाकों में उपद्रव होने के कारण हाल ही में शांति और व्यवस्था बनाये रखने पर जो अधिक व्यय करना पड़ा है, उसकी पूर्ति के लिए राज्य सरकार को १.५५ करोड़ रुपये का अनुदान देने की व्यवस्था है।

तीसरी मद जिसके कारण व्यय में वृद्धि हुई है, यह है कि अमरीका सरकार को उधार पट्टे की चांदी लौटाने के सम्बन्ध में परिवहन आदि के प्रासंगिक व्यय के लिए ३३ लाख रुपए की व्यवस्था की गई है।

पुनर्वित्त निगम (रिफाइनैंस कारपोरेशन) को जो कि शीघ्र ही बनाने का विचार है, ऋण देने के लिए १५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है।

यह निगम समवाय अधिनियम (कम्पनी एक्ट) १९५६ के अधीन संयुक्त हिस्सा पूंजी कम्पनी के रूप में स्थापित करने का विचार है। शुरू में इसकी साधारण हिस्सा पूंजी १२.५ करोड़ रुपये होगी और रिजर्व बैंक भारत राज्य बैंक, जीवन बीमा निगम और भारत के १४ बड़े-बड़े अनुसूचित बैंक इसके हिस्से खरीदेंगे। अनुमान है निगम को चालू वित्तीय वर्ष में भारत सरकार से लगभग १५ करोड़ रुपए का ऋण लेना पड़ेगा।

इसके अलावा ५० लाख रुपए की व्यवस्था निर्यात बीमा निगम के हिस्से खरीदने के लिए की गई है। इसकी अधिकृत पूंजी २.५ करोड़ रुपए और चुकता पूंजी ५० लाख रुपए होगी। निगम एक समय में अपनी बिक्री हिस्सा पूंजी और प्रारक्षित निधि से दस गुने से अधिक का बीमा नहीं कर सकेगा। पूंजी खाते में इन तीन मदों पर २२.४७ करोड़ रुपया खर्च होगा।

पूंजी और राजस्व खातों को मिलाकर कुल कमी २.८९ करोड़ बढ़ जायगी। पहले ३६५ करोड़ रुपए की कमी का अनुमान लगाया गया था, लेकिन अब ३६७.८४ करोड़ रुपए की कमी रहने का अनुमान है।

संक्षिप्त विवेचन

बजट वर्ष की आर्थिक और वित्तीय स्थिति की समीक्षा से स्पष्ट हो जाता है कि जबकि सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में निवेश कार्यक्रम की बढ़ती हुई मांगों को

[सम्पन्न

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पूरा करने के लिए और अधिक साधनों की आवश्यकता है। अर्थ व्यवस्था से धन की उतनी बचत नहीं हो रही है। बजट सम्बन्धी घाटे, बैंक ऋणों में तेजी से वृद्धि, मूल्यों पर बराबर दबाव और शोधन सन्तुलन में भारी कमी, ये सब बातें इस बात का संकेत कर सकती हैं कि जितनी मात्रा में निवेश किया जा रहा है, उतनी मात्रा में स्वेच्छा से धन की बचत नहीं हो रही। इसके अतिरिक्त हमें आयोजना की समस्त योजना अवधि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इन दबावों पर विचार करना है। आयोजना व्यय को प्रतिवर्ष बढ़ाते रहना पड़ेगा और निवेश के फलीभूत होने तक जितना समय लगना अनिवार्य है, उसमें देश के साधनों पर दबाव बढ़ेगा। अर्थव्यवस्था द्वारा इन मांगों की सफल पूर्ति तभी सम्भव है, जब राष्ट्रव्यापी आधार पर उत्पादन में वृद्धि की जाय और धन की बचत के कार्य को बढ़ावा दिया जाय। साथ ही यह भी आवश्यक है कि सरकारी और गैर सरकारी, दोनों क्षेत्रों में प्रायः उसी अनुपात से पूंजी लगायी जाय जिस अनुपात से घरेलू बचतों को बढ़ाने में और चालू कार्यक्रम की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त मात्रा में बाह्य वित्त साधन प्राप्त करने में प्रगति होती है।

१९५६ में अनुसूचित बैंकों द्वारा किए गए ऋण में १५३ करोड़ रु० की वृद्धि हुई है और वह ७८८ करोड़ रुपये हो गया। अनुसूचित बैंकों ने इतना अधिक ऋण इससे पहले कभी नहीं दिया था। इस वर्ष के पहले चार महीनों में इसमें १११९ करोड़ रुपए की और वृद्धि नहीं हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि मुद्रा बाजार में धन की बड़ी तंगी रही और आह्वान द्रव्य (काल मनी) की दर और बैंकों से रुपया उधार लेने और बैंकों में उधार लेने और बैंकों में रुपया जमा कराने की दरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। अर्थव्यवस्था की सम्पूर्ण प्रवृत्तियों को देखते हुए आवश्यक यह है कि वास्तविक मांगों की पूर्ति के लिए उनमें सतर्कतापूर्वक और नियमित ढंग से विस्तार किया जाय और कम आवश्यक कार्यों के लिए अत्यधिक मात्रा में ऋण दिए जाने की रोकथाम हो सके।

विवेकपूर्ण नियंत्रण रखने की नीति के अनुसार बैंक की ब्याज की दर बढ़ा दी गई। हुंडी (बिल) बाजार योजना के अधीन अग्रिमों पर ब्याज की दर मार्च और नवम्बर १९५६ में दो बार करके ३ प्रतिशत से बढ़ाकर ३॥ प्रतिशत कर दी गई और इस वर्ष फरवरी में मियादी हुंडियों (बिलों) पर मुद्रांक शुल्क (स्टाम्प ड्यूटी) बढ़ा दिया गया जिनसे बैंकों द्वारा लिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज की दर बढ़ाकर ४ प्रतिशत कर दी। इसके अतिरिक्त जब यह मालूम हुआ कि बैंक से उधार ली हुई रकम सट्टे में और विशेषतः अनाज और अन्य ऐसी चीजों के सट्टे में लगायी जाती है जिनकी कमी है, तो रिजर्व बैंक ने ऐसी वस्तुओं पर ऋण देने के नियमन के सम्बन्ध में आदेश जारी किये।

अब छोटी बचतों के आंदोलन को जोरदार बनाना है, डाकखाने के सेविंग्स बैंक में जमा की जाने वाली रकमों के ब्याज की दर में १।२ प्रतिशत वृद्धि करने और वर्तमान राष्ट्रीय बचत पत्रों तथा राष्ट्रीय आयोजना पत्रों के स्थान पर १२ वर्षीय बचत पत्रों की एक नई श्रृंखला जारी करने का निश्चय किया गया है जिसे राष्ट्रीय बचत पत्र कहा जाएगा। अब सेविंग्स बैंक में जमा रकमों के ब्याज की दर, व्यक्तियों के लिए १०,००० रुपए तक की रकमों पर २-१।२ प्रतिशत और १०,००० रुपए से अधिक किन्तु १५,००० रुपए तक की रकमों पर २ प्रतिशत और संस्थाओं की रकमों के लिए २ प्रतिशत होगी। (आगे से केवल दो प्रकार के बचत-पत्र होंगे : (१) राष्ट्रीय आयोजना बचत पत्र, जो १२ साल में पकेंगे और (२) राजकोष बचत जमा पत्र जो १० साल में पकेंगे। दोनों की प्राप्तियों में वृद्धि हो जाएगी; पहले में १२ वर्ष समाप्त होने पर ४.२५ प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा और दूसरे में १० वर्ष समाप्त होने पर ४ प्रतिशत ब्याज मिलेगा।)

निर्यात व आयात

निर्यात द्वारा हम कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं, यह ऐसा विषय नहीं, जो सरासर हमारे हाथ की बात हो। यह दुनिया भर में मांग और मूल्यों पर निर्भर करता है। इसी प्रकार विदेशों से मंगाई जाने वाली वस्तुओं के लिए हमें जो मूल्य चुकाने पड़ते हैं, वे हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। हम केवल आयात की मात्रा को सीमित कर सकते हैं। यहां भी समस्याएं सामने आती हैं।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जो कटौती करते हैं, वे कुछ समय बाद ही प्रभावी होती हैं। विदेशी (मुद्रा) विनिमय नीति बड़े ही नाजुक सन्तुलन का मामला है और मेरे विचार में, यह ऐसा सन्तुलन है जिसमें अनुकूल वायु का एक झोंका बड़ा अन्तर पैदा कर सकता है।

कम उन्नत अर्थ-व्यवस्था वाले देश को, जो औद्योगीकरण का कार्यक्रम प्रारम्भ करता है, अनिवार्य रूप से विदेशों से ऐसा सारा या लगभग सारा साज-सामान और पूंजीगत माल मंगाना पड़ता है, जिसकी सही ढंग से कार्यारम्भ करने के लिए उसे जरूरत होती है। फिर भी काम शुरू करना पड़ता है और इसमें जोखिम उठानी पड़ती है। वस्तुस्थिति को देखते हुए विदेशी (मुद्रा) विनिमय के क्षेत्र में नीति और कार्यक्रम को उतना ठीक-ठीक या ब्योरेवार नहीं बनाया जा सकता, जितना कि घरेलू नीति के सम्बन्ध में। द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना पर बहुत अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा व्यय करनी होगी।

आयोजना

आयोजना बनाते समय इस पर जितना व्यय होने का अनुमान लगाया गया था, अब उससे अधिक व्यय होने का अनुमान है। आयोजना का निश्चित कार्यक्रम के अनुसार पूरा होना, अन्य बातों के अलावा, काफी बड़े पैमाने पर बाह्य-साधनों की उपलब्धि पर निर्भर है, और इन बाह्य-साधनों की सबसे अधिक आवश्यकता आयोजना के प्रारंभिक काल में है। यह नहीं बताया जा सकता कि विदेशी मुद्रा की कमी से आयोजना की प्रगति में कहां तक बाधा पड़ेगी। इस्पात, कोयला परिवहन व्यवस्था और इनके लिए आवश्यक बिजली, आयोजना के मूल आधार हैं। मेरा विचार है है कि हमें अब तक जितनी विदेशी सहायता का वचन मिल चुका है उससे, और इसके अलावा विश्व बैंक और अन्य साधनों से मिलने वाली सहायता से हम इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की प्रायोजनायें पूरी कर सकेंगे।

आयोजना में यह लक्ष्य रखा गया है कि १५ से २० वर्ष की अवधि में राष्ट्रीय आय धीरे-धीरे बढ़ाई जाए।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि रहन-सहन सुधारने में हमें अभी तक जो सफलता मिली है, उससे यह और भी आवश्यक हो गया है कि यह काम अधिक उत्साह और दृढ़ निश्चय के साथ जारी रखा जाय। भारत के करोड़ों लोग कई ऐसी नई इच्छाएं और आवश्यकताएं अनुभव करने लगे हैं, जो पिछली कई पीढ़ियों में देखने में नहीं आतीं। यह अनुभव होने से कि सभी का भविष्य उज्ज्वल हो सकता है, यह इच्छा भी पैदा हो गई है कि वांछित सुधार जल्दी से जल्दी हो जाएं। चाहे वह कारखानों के मजदूरों की अधिक मजदूरी और अच्छे मकानों के लिए मांग हो, और चाहे वह कम वेतन पाने वाले अध्यापकों और सरकारी कर्मचारियों की न्याय्य-व्यवहार और अधिक सुरक्षा के लिए मांग हो। ये सब नई जागृति और ऐसे आर्थिक भविष्य के लिए प्रयत्नशीलता की द्योतक है, जो एक स्वतंत्र समाज के नागरिकों के गौरव के अनुरूप हैं। ऐसी परिस्थिति में हम यह नहीं कह सकते कि यह सब तभी हो सकता है जब किसी न किसी तरीके से देश की वित्तीय स्थिति सुधर जाए। इस समय चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों हमें यह देखना होगा कि लोगों की विशेषतः कम आय वाले वर्गों की क्या जरूरतें हैं और जहां तक हो सकेगा, इन जरूरतों को पूरा भी करना होगा।

आजकल हमारे सब विचार आयोजना पर ही केन्द्रित हैं और हमारी सब नीतियां इसी को ध्यान में रख कर बनाई जा रही हैं। और जो देश विकास को सबसे अधिक महत्व देता हो उसमें और हो भी क्या सकता है? आयोजना को कार्य रूप देने में कठिनाइयां तो पेश आई हैं, लेकिन मुझे घबराहट का कोई कारण दिखाई नहीं देता। जरूरत इस बात की है कि हम आवश्यक त्याग के लिए तैयार रहें और आयोजन को क्रियान्वित करने में जो समस्याएं सामने आएं, उन्हें साहस और सूझ-बूझ से हल करें।

सफ़ेद कोढ़ के दाग

हजारों के नष्ट हुए और सैकड़ों के प्रशंसापत्र मिल चुके

दवा का मूल्य ५) रु० डाक व्यय १) रु०

अधिक विवरण मुफ्त मँगाकर देखिये।

वैद्य के० आर० बोरकर

मु० पो० मंगरूलपीर, जिला अकोला (मध्य प्रदेश)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नये कर प्रस्तावों पर वित्तमंत्री

देश के सभी वर्गों से आहुति का आह्वान

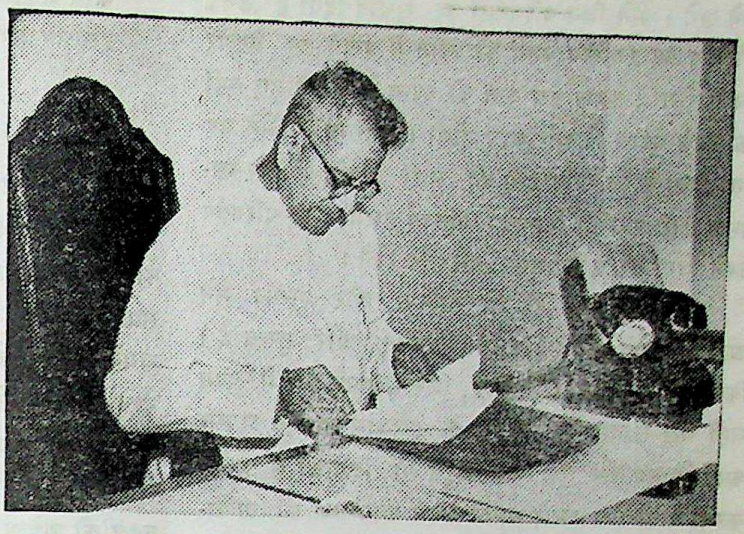

नये बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देते हुए वित्तमंत्री

नये कर-प्रस्तावों के परिणामस्वरूप केन्द्रीय राजस्व में ७७.८५ करोड़ रुपए की शुद्ध वृद्धि होगी और राजस्व बजट में अब ४४.७३ करोड़ रुपए का अधिशेष दिखायी देगा। साधारणतः इसके परिणामस्वरूप, सम्पूर्ण घाटा २६० करोड़ रुपए का रहेगा, यदि १५ करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व, जो इन प्रस्तावों के कारण राज्यों को दे दिया जाएगा, हिसाब में न लिया जाय।

मेरे प्रस्तावों से जन साधारण की ऐसी वस्तुओं पर करों का बोझ बढ़ता है, जो प्रायः आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में यह अनिवार्य है। इन बोझों का, जो कुल मिलाकर ज्यादा मालूम होते हैं, औसत भार कम है। एक ऐसे देश में, जहां अधिकतर व्यक्तियों की आय कम है, विकास कार्य को तब तक वित्तपोषित नहीं किया जा सकता, जब तक समाज के सभी वर्गों के लोग त्याग न करें, और मुद्रास्फीति के दबावों को कम करने और निर्यात को प्रोत्साहन देने के निमित्त उपभोग पर कुछ नियंत्रण रखने के लिये इस समय विशेष कारण है। साथ ही मैं यह अनुभव करता हूं कि समय-समय पर कुछ खास क्षेत्रों को, न्यूनतम पोषक खाद्य प्रतिमानों की दृष्टि से उपभोग को उचित स्तर पर बनाये रखने की दृष्टि से, सहायता देने की आवश्यकता हो सकती है और इसके लिये खाद्य के सम्बन्ध में राज-सहायता देने की आवश्यकता पड़ सकती है।

घाटे की अर्थव्यवस्था

मैंने जो सुझाव रखे हैं उनके बाद भी संपूर्ण घाटा उससे कुछ अधिक रहेगा जिसे मैं निरापद समझता हूँ। लेकिन मेरे विचार से किसी हद तक जोखिम उठाना गलत नहीं होगा, विशेषतः ऐसी स्थिति में जब कि इससे मुद्रा-बाहुल्य का स्तर समुचित रूप से ऊंचा बनाये रखा जा सके। बजट में घाटा होने से लोगों की क्रयशक्ति बढ़ती है। इसका अर्थ यह होता है कि सरकार जितना रुपया जनता के हाथ में दे देती है उतना उससे प्राप्त नहीं करती। अर्थ-व्यवस्था में जो दबाव पैदा हो गये हैं, वे इस बात की चेतावनी हैं कि घाटे की वित्त-व्यवस्था भी किसी हद तक ही की जा सकती है। मैं घाटे की वित्त-व्यवस्था के विरुद्ध नहीं हूं। मैं मानता हूं कि इससे विकास में सहायता मिल सकती है। लेकिन यह औषध है जो थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ही खायी जा सकती है, भोजन नहीं है जो शरीर के लिए आवश्यक है। सब बातों को देखते हुए मुझे इस बात में संदेह है कि हम आयोजना की अवधि में उस सीमा तक घाटे की वित्त-व्यवस्था कर सकेंगे जिसकी आयोजना में कल्पना की गयी है। इसका मतलब यह है कि हमें करों, ऋणों तथा छोटी बचतों से और अधिक धन प्राप्त करना होगा।

विश्वास और आशा

मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय आय की तुलना में सरकारी राजस्व में जो गतिहीनता आ गयी है उसे दूर करने में इन उपायों से सहायता मिलेगी। अपेक्षाकृत कम उन्नत देशों की तुलना में भी भारत में, करों की दृष्टि से राजस्व का अनुपात कम है। इसे बढ़ाने के लिए कर-व्यवस्था में परिवर्तन करने होंगे, ताकि आगे चलकर इससे अधिक आय

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

होने लगे। मैंने जिन परिवर्तनों का सुझाव दिया है उनके औचित्य पर इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए विचार करना होगा ! केवल इस बात को ध्यान में रखते हुए नहीं कि उनसे तुरन्त कितनी आय होगी। वास्तव में मैंने यह बता दिया है कि आयोजना की सारी अवधि में कर-व्यवस्था कैसी रहेगी। निस्संदेह प्रतिवर्ष इसमें कुछ परिवर्तन करने होंगे, पर वे मामूली परिवर्तन होंगे।

मुझे मालूम है कि जो नीतियां और प्रस्ताव मैंने आपके सामने रखे हैं। उनमें विविधता और गुरुत्व है। किन्तु परिस्थितियां ही ऐसी हैं, जिनमें, इससे कम में काम नहीं चल सकता। प्रत्येक राष्ट्र के इतिहास में ऐसे अवसर आते हैं जब उसे एक साथ बहुत सी दिशाओं में प्रगति करनी होती है। हमारे सामने केवल आयोजना की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन जुटाने का ही काम नहीं है। हमें साथ ही कर-व्यवस्था को भी ठीकठाक करना है, जिससे वह आने वाले वर्षों में बढ़ते हुए विशाल कार्य के भार को वहन कर सके। मैं उन लोगों में से हूँ जो यह भी विश्वास करते हैं कि आर्थिक समानता और ठोस सामाजिक सुधार की दिशा में, कठिन समय में ही महान प्रगति होती है, जबकि जनता में विवेक और एकता अत्यन्त उच्चकोटि की होती है।

कर-निर्धारण-नीति

वर्तमान परिस्थिति में कर-निर्धारण की नीति और प्रस्ताव इन सिद्धान्तों के आधार पर बनाने पड़ेंगे :

(क) इनसे सरकारी राजस्व में भारी वृद्धि होनी चाहिए ;

(ख) इनसे अधिक रुपया कमाने और अधिक बचाने की प्रेरणा मिलनी चाहिए ;

(ग) इनसे व्यापक रूप से खपत का नियंत्रण होना चाहिए, जिससे देश में मुद्रा-बाहुल्य के दबाव को काबू में रखा जा सके और पूंजी लगाने के साधनों को मुक्त किया जा सके ;

(घ) और इनसे करों के ढांचे में परिवर्तन होना चाहिए, जिनसे आमदनी बढ़ने पर करों से क्रमशः अधिक प्राप्ति होने लगे और सरकार तथा देश ने जिन उद्देश्यों को स्वीकार किया है, उनका समुचित ध्यान रखते हुए अर्थ-व्यवस्था का व्यवस्थित ढंग से विकास करने में सुविधा हो सके।

इसलिए सरकार नये कर लगाने के लिए विवश है।

अप्रत्यक्ष कर

विदेशी मुद्रा-व्यय को कम करने के लिए हमने वस्तुओं के आयात पर अनेक कठोर नियंत्रण लगा रखे हैं। इसके अलावा, तथाकथित विलास सम्बन्धी वस्तुओं में से अधिकांश पर काफी ऊंचे आयात-शुल्क लगे हुए हैं और भारी सामान (केपिटल गुडस) तथा औद्योगिक कच्चे माल पर लगने वाले शुल्कों को आवश्यकतावश अधिक से अधिक नीचे रखा है। जो प्रस्ताव मैंने रखे हैं, उनमें लगभग ८४ वस्तुओं पर शुल्क की दरों को थोड़ा सा बढ़ाने की कल्पना की गयी है। आयात-निर्यात-शुल्क-सूची में दी गयी दरों को पहले की अपेक्षा सरल रूप देने का प्रयत्न किया है और इस प्रक्रिया में अधिभारों (सरचार्जों) को बुनियादी दरों में मिला दिया गया है। निर्यात शुल्कों में और कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है सब मिलाकर, आयात-शुल्क सम्बन्धी मेरे प्रस्तावों से लगभग ६ करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी। यह प्राप्ति बहुसंख्यक मदों में से होगी, जिन्हें इस समय गिनना सम्भव नहीं है।

उत्पादन शुल्क के सम्बन्ध में

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्कों के सम्बन्ध में मेरे मस्तिष्क में दो बातें हैं : एक तो यह कि खपत को नियंत्रित किया जाय और दूसरी यह कि निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाय।

मैं इन वृद्धियों का प्रस्ताव रखता हूं :—

(१) मोटर-स्पिरिट: वर्तमान उत्पादन-शुल्क जो अधिभार (सरचार्ज) सहित अभी प्रति इम्पीरियल गैलन ९८ नये पैसे हैं, बढ़ाकर प्रति इम्पीरियल गैलन १२५ नये पैसे कर दिया जाय। इससे पूरे एक वर्ष में ६.६५ करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति होगी।

(२) रिफाइंड डीजल आयल (तेल) : प्रति इम्पीरियल गैलन २५ नये पैसे का वर्तमान शुल्क बढ़ाकर प्रति इम्परियल गैलन ४० नये पैसे कर दिया जाय। इससे एक वर्ष में १.९० करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी।

(३) डीजल आयल (तेल), जिसका अन्य प्रकार से उल्लेख नहीं हुआ : यह शुल्क प्रति टन ३० रुपये से

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बढ़ाकर ४० रुपये कर दिया जाय। इससे एक वर्ष में ३५ लाख रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति होगी।

(४) मिट्टी का तेल : प्रति इम्पीरियल गैलन १८.७५ नये पैसे का वर्तमान शुल्क बढ़ाकर, आंशिक रूप से प्रति इम्पीरिल गैलन २० नये पैसे कर दिया जाये। इससे पूरे एक वर्ष में २० लाख रुपये की प्राप्ति होगी।

(५) सीमेण्ट : प्रति टन ५ रुपये का वर्तमान शुल्क, बढ़ाकर प्रति टन २० रुपये कर दिया जाय। इससे ६.७ करोड़ रुपये की वार्षिक प्राप्ति का अनुमान है।

(६) इस्पात पिण्ड : वर्तमान शुल्क प्रति टन ४ रुपये से बढ़ाकर प्रति टन ४० रुपये कर दिया जाय। इससे ५.७ करोड़ रुपये की वार्षिक प्राप्त होगी।

(७) चीनी : वर्तमान शुल्क प्रति हण्डरवेट ५.६२ रुपये से बढ़ाकर प्रति हण्डरवेट ११.२५ रुपये कर दिया जाए। इससे पूरे एक वर्ष में १८.५५ करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी।

(८) असारीय निर्गन्ध वनस्पति तेल (वेजिटेबिल नान एसेंशल आयल) : प्रतिटन ७० रुपये का शुल्क बढ़ाकर प्रति टन ११२ रुपये कर दिया जाय। इसका अर्थ प्रति पौंड ३ नये पैसे से ५ नये पैसे की वृद्धि होगा। इस मद से एक वर्ष में ३.१५ करोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान है।

(९) तमाखू पर विभिन्न प्रकार से शुल्क में वृद्धि की जायगी। इन वृद्धियों से पूरे एक वर्ष में कुल ६.१५ करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति होगी।

(१०) दियासलाई : वर्तमान शुल्क बढ़ा दिये जायें, जिससे ६० और ४० तीलियों की डिबियां क्रमशः ६ नये पैसे और ४ नये पैसे में बेची जा सकें। इन वृद्धियों से पूरे एक वर्ष में ६.२ करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति का अनुमान है।

(११) कागज : विभिन्न प्रकार के कागजों का वर्तमान शुल्क बढ़ा दिया जाय। इससे प्रति वर्ष कुल २ करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति का अनुमान है।

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्कों से सम्बन्ध रखने वाले इन प्रस्तावों से पूरे एक वर्ष में ६०.८० करोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान है। चालू वर्ष के शेष भाग में इनसे ५३.२० करोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान है, जिस में से तम्बाकू और दियासलाइयों से सम्बन्ध रखने वाले राज्यों का हिस्सा लगभग ४.२ करोड़ रुपये होगा।

चीनी के शुल्क में वृद्धि करने का उद्देश्य वही है जो पिछले वर्ष कपड़े के उत्पादन-शुल्क में वृद्धि करने का था, अर्थात् निर्यात में वृद्धि करने के उद्देश्य से देश के अन्दर खपत को नियन्त्रित किया जाय। जहां तक दियसलाइयों का सम्बन्ध है, वर्तमान शुल्क इस दृष्टि से लगाये गये थे कि ६० तीलियों की डिबियां ३ पैसे में और ४० तीलियों की डिबियां २ पैसे में बेची जा सकें। दाशमिक सिक्का प्रणाली के अनुसार इन मूल्यों के बराबर का मूल्य क्रमशः ४.७ नये पैसे और ३.१ नये पैसे होता है, जिसका प्रभाव यह होता कि खुदरा मूल्य क्रमशः ६ नये पैसे और ४ नये पैसे हो जायगा।

प्रत्यक्ष कर

अब मैं प्रत्यक्ष करों को लेता हूँ। पहले मैं व्यक्तिगत आयकर और अधिक कर (सुपर टैक्स) की दरों में कुछ समायोजन करना चाहता हूँ। अब मैं इस प्रणाली को बिलकुल बदल देना चाहता हूँ और सभी अर्जित आयों पर दरों की एक निर्धारित तालिका का प्रयोग होना चाहिए तथा अनर्जित आयों पर पहले से अधिक (सरचार्ज) लगाना चाहता हूँ। आमदनी के ऊंचे स्तरों पर प्रत्यक्ष कर की हमारी वर्तमान दरें कर के ढांचे को सभी प्रकार के लचीलेपन से वंचित कर देती हैं। कहा जाता है कि इनसे काम करने की प्रेरणा घट जाती है, किन्तु मुझे पता है कि उनसे बहुत बड़े पैमाने पर कर-अपवंचन को प्रोत्साहन मिलता है। ऊंची दरें निर्दिष्ट कर-आधार के लिए प्रयुक्त की जाती है। दरों को एक संशोधित तालिका प्रस्तावित की गई है। (सरचार्ज) की एक नयी योजना का समावेश किया गया है।

मैं वर्तमान आयकर-आधार (इनकम-टक्स बेस) को भी विस्तृत करना चाहता हूं। इसके लिए कर लगाने योग्य कम से कम रकम को ४,२०० रुपये से घटाकर ३,००० रुपये देने का प्रस्ताव है। ४,२०० रुपये की आमदनी यद्यपि बहुत अधिक नहीं है, फिर भी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वह इस देशकी आमदनियों के औसत स्तर की कई गुना है। यह आशा करना उचित ही है कि जिन व्यक्तियों की आमदनी ३,००० रुपये से अधिक है, उन्हें भी राजकोष में अपना अंशदान देना ही चाहिए, भले ही वह बहुत थोड़ा हो, और इस प्रकार प्रत्यक्ष करों की परिधि में जाना चाहिए। मुझे आशा है कि ज्यों-ज्यों विकास-कार्यों में प्रगति होती जायगी, इस सीमा की आमदनियों में विशेष और क्रमिक वृद्धि होती जायगी और मेरे विचार से, यदि राजकोष को भी विकास-वृद्धि के परिणामस्वरूप आमदनियों के बढ़ने का अनुपातिक लाभ उठाना है, तो इन आमदनियों को आयकर की परिधि में लाना ही चाहिए। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि अब छूट की सीमा व्यक्तियों के लिए ३,००० रु० (२ बच्चों वाले विवाहित व्यक्ति को कुछ छूट दी जाएगी) और अविभक्त हिन्दू परिवारों के लिए ६,००० रुपए कर दी जाय। फिर भी मैं इसे विवाहित व्यक्तियों के लिए छूट की बढ़ी हुई दर से मिला देना चाहता हूं। १००० रुपए के अतिरिक्त कर कर मुक्त खंड जो इस समय विवाहित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, अब बढ़ाकर २००० रुपए कर दिया जायगा। इन प्रस्तावों के परिणामस्वरूप आयकर के विस्तार से लगभग इस वर्ष लगभग ५ करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी।

मेरा प्रस्ताव है कि कम्पनियों द्वारा दिया जाने वाला आयकर रुपए में ४ आने से बढ़ाकर ३० प्रतिशत कर दिया जाय और निगम कर (कारपोरेशन टैक्स) रुपए में २ आना ६ पाई से बढ़ाकर २० प्रतिशत कर दिया जाय।

(ख) सम्मिलित बचत की आज सबसे अधिक आवश्यकता है। फिर भी निगम कर (कारपोरेशन टैक्स) की दर में प्रस्तावित वृद्धि की दृष्टि से मैं अतिरिक्त लाभांश (डिविडेंड) कर में इस प्रकार कमी कर देना चाहता हूं—

कम्पनी करों के सम्बन्ध में जो परिवर्तन करने का मेरा विचार है, (ये परिवर्तन बजट भाषण में विस्तार से दिए गए हैं) उनसे सब मिलाकर, ७॥ करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्राप्ति होगी।

अब मैं दो नये कर-प्रस्तावों को लेता हूँ जिनका उद्देश्य इस ढंग से करों के ढांचे में परिवर्तन करना है कि कर-निर्धारण के लिए पहले से अधिक प्रभावशाली और साथ ही पहले की अपेक्षा अधिक न्यायपरक आधार सुनिश्चित हो जाय। मेरा पहला प्रस्ताव सम्पत्ति कर लगाने के सम्बन्ध में है। यह बात स्वीकार की जाती है कि आय-वर्तमान आयकर विधियों तथा रीतियों द्वारा जिसकी व्याख्या की गई है—कर देने की क्षमता का पर्याप्त आधार नहीं है और आमदनियों पर कर लगाने की प्रणाली द्वारा अनुपूरित करने की आवश्यकता है। यह अधिक न्यायपरक है और इससे यह आशा बंधती है कि इसके द्वारा बहुत कम समय तक कर-अपवंचन की सम्भावनाओं को कम किया जा सकता है। इससे पहले मैंने आमदनियों के ऊंचे स्तरों पर आयकर की उन छूटों का जिक्र किया है जिनका समावेश मैं इस साल कर रहा हूं। इन छूटों का उद्देश्य और अधिक उद्यम तथा और अधिक प्रयत्न को प्रोत्साहन देना है। एक मात्र जिनके आधार पर ही स्वस्थ तथा प्रगतिशील अर्थव्यवस्था का निर्माण हो सकता है। इसके साथ ही अन्य उपायों के अवलम्बन की भी आवश्यकता है जो उद्देश्य की दृष्टि से समभावपूरक तो हों पर जिनसे प्रेरणा कुण्ठित न होती हो। जिस सम्पत्ति कर का प्रस्ताव मैं कर रहा हूँ, वह इसी प्रकार का है। यह कर व्यक्तियों, अविभक्त हिन्दू परिवारों और कम्पनियों द्वारा देय होगा। व्यक्तियों के मामले में दो लाख रुपए तक के मूल्यों और अविभक्त हिन्दू परिवारों के मामले में ३ लाख रुपए तक के मूल्यों को मुक्त किया जायगा। जिस सम्पत्ति का मूल्य इससे अधिक होगा, उसके सम्बन्ध में पहले १० लाख पर कर की दर १।२ प्रतिशत, आगे १० लाख के लिए १ प्रतिशत और बाकी के लिए डेढ़ प्रतिशत होगी। इस प्रकार यह क्रमशः बढ़ने वाला कर होगा, जिससे अनर्जित आमदनियों के आयकर पर लगने वाले उन अधिकारों सहित, जिनकी मैंने सिफारिश की है, अपेक्षाकृत धनिक वर्गों पर अधिक प्रभावपूर्ण कर लगाये जा सकेंगे और साथ ही आमदनी बढ़ाने की प्रेरणा में भी कमी न आएगी।

जहां तक कम्पनियों का सम्बन्ध है, ५ लाख रुपए तक की परिसम्पद पर कर नहीं लगेगा, उससे ऊपर के

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के मूल्यों पर कर की दर १/२ प्रतिशत होगी। सम्पत्ति कर मुख्यतः व्यक्तिगत कर है किन्तु भारत के विशिष्ट आर्थिक ढांचे में में इस कर की परिधि से कम्पनियों को बाहर रखना नहीं चाहता। किन्तु कर की दर तो कम रखनी ही पड़ेगी। इसी से छूट के स्तर से ऊपर की परिसम्पद के लिए मैंने केवल १/२ प्रतिशत की समान दर की सिफारिश की है।

कुछ सम्पत्तियों को इस कर से छूट देनी पड़ेगी। इनमें से कुछ ये हैं :

कृषि सम्पत्ति;

धर्मस्य (चेरिटेबिल) अथवा धार्मिक न्यासों (ट्रस्टों) की सम्पत्ति;

कला कृतियां

पुरातत्वविषयक वस्तुएं, जिन्हें बेचना न हों;

मान्य भविष्य निधियों और बीमा पालिसियों की रकमें;

व्यक्तिगत वस्तुएं जिनमें फर्नीचर, मोटर गाड़ियां, आभूषण आदि सम्मिलित हैं, २५,००० रु० की अधिकतम सीमा तक; और पुस्तकें और प्रकाशित सामग्री जिसे बेचना न हो।

विभिन्न प्रकार की परिसम्पदों के जो किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान का अंग हों; मूल्य निर्धारण की प्रणाली को सरल बनाने के उद्देश्य से जहां तक सम्भव हो, व्यापारिक प्रतिष्ठान को मुल्य निर्धारण के उद्देश्य से एक इकाई मानने का प्रस्ताव है। दूसरी परिसम्पद का वही मूल्य लगाया जायगा जो बाजार में प्रचलित हो। अनुमान है कि इस कर से १५ करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी।

मेरा दूसरा प्रस्ताव व्यय पर कर लगाने के सम्बन्ध में है। यह इस ढंग का कर है जिसकी पुष्टि अभी तक इतिहास द्वारा नहीं हो पायी। फिर भी यह ऐसा कर है जिसके सम्बन्ध में प्रभावपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था होने से दिखाने के खर्चों को नियंत्रित करने और

"मैं राज्य की बढ़ती हुई ताकत को बहुत भय के साथ देखता हूँ। यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से यह मालूम होता है कि वह शोषण को कम कर रही है, तथापि वस्तुतः इससे मानव जाति की बड़ी भारी हानि होती है, क्योंकि इसे मानव का वह व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है, जो सब प्रकार की उन्नति का मूल कारण है।"

—महात्मा गांधी

स्वतन्त्र साहस और उद्योग के सम्बन्ध में जनता को शिक्षित करने वाली एक अ-राजनैतिक संस्था।

Forum of Free Enterprise

स्वतन्त्र साहस संघ

२३५, डा० दादाभाई नौरोजी रोड, बम्बई-१

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बचत को प्रोत्साहन देने में वास्तविक सहायता मिलेगी। मेरे विचार से वर्तमान परिस्थितियों में हम केवल स्वल्पारम्भ ही कर सकते हैं। मैं इस कर को केवल व्यक्तियों और उन अविभक्त हिन्दू परिवारों पर लगाना चाहता हूँ जिनकी आय, आय-कर की दृष्टि से ६०,००० रुपए से कम नहीं है। यह कर उन रकमों से अधिक की रकम पर, जो परिवार के आकार के अनुसार अलग अलग होंगी, किये गये सारे खर्च पर लगाया जायगा। बाद दी गई रकमें ये हैं :

करदाता और उसकी पत्नी के लिए २४,००० रु० की बुनियादी रकम और प्रत्येक आश्रित बच्चों के लिए ५,००० रुपए।

कर की दर एक खण्ड-प्रणाली पर आवृत होगी और प्रत्येक खण्ड की दर व्यय के स्तर में वृद्धि के साथ साथ क्रमशः बढ़ती जाएगी। इस प्रकार १०,००० रुपए के अतिरिक्त खर्च पर यह दर १० प्रतिशत होगी और ऊंचे खंडों के लिए क्रमशः बढ़ती जाएगी। सम्पत्ति-कर की भांति प्रशासनिक व्यवस्था और कर निर्धारण तथा अपील प्रणाली वही होगी जो आयकर के लिए है। मैं इस कर को १९५८-५९ के वित्त वर्ष से लागू करने का प्रस्ताव रखता हूं। इसलिए १९५७-५८ में इस मद में किसी भी प्राप्ति को सम्मिलित नहीं कर रहा हूं।

मैं रेल यात्रियों के किराये पर कर लगाने का प्रस्ताव करता हूं। रेल यात्रा के प्रथम १५ मील पर कोई कर नहीं लगेगा। १५ मील से ३० मील की दूरी तक के लिए ५ प्रतिशत, ३१ मील और ५०० मील की दूरी के लिए १५ प्रतिशत और इससे अधिक दूरी के लिए १० प्रतिशत होगी। सीजन टिकटों पर कर नहीं लगेगा। राज्यों को और अधिक धन की आवश्यकता है, इसलिए रेल-यात्रियों को दूसरी वस्तुओं के उपभोक्ताओं की तरह वर्तमान परिस्थितियों में अंशदान देना ही चाहिए।

डाक दरों में परिवर्तन

डाक और तार विभागकी शाखाएं घाटे पर चल रही हैं। बिना रजिस्ट्री के पत्रों और अन्तर्देशीय पत्र कार्डों को छोड़ कर, डाक से पहुँचायी जाने वाली प्रायः सभी मदों में घाटा हो रहा है। कई मदों, जैसे कि पोस्टकार्डों, मनी-आर्डरों, रजिस्टर्ड समाचार पत्रों आदि की दरें वर्षों से सेवा की व्यवस्था के लागत खर्च से भी काफी कम हैं। उदाहरण के लिए, अनुमान लगाया गया है कि एक पोस्टकार्ड को पहुँचाने का औसत खर्च ७.२४ नये पैसे है जबकि वर्तमान डाक महसूल सिर्फ ५ नये पैसे है। इससे साल भर में १५५ लाख रुपए से भी अधिक का घाटा रहता है। इन मदों से सम्बन्ध रखने वाले काम की हर वृद्धि से, और काम की वृद्धि तो हो ही रही है, घाटे में भी वृद्धि हो जाती है। कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण एवं क्रमशः बढ़ते हुए खर्च और कर्मचारियों के लिए अन्य सुख-सुविधाओं की व्यवस्था से वर्तमान डाक दरें और भी अलाभकारी सिद्ध होंगी। प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना के आधीन डाक-तार विभाग की विस्तार योजनाओं के एक अंग के रूप में अलाभकारी डाकखाने और तारघर खोले जाने से डाक और तार शाखाओं को हानि हुई है। इसलिए लिफाफे का दाम १ जुलाई १९५७ से १३ नये पैसे से बढ़ाकर १५ नए पैसे कर दिया जाएगा। किन्तु अब लिफाफे में १॥ तोले के वजन की वस्तु जा सकेगी, जबकि अभी तक एक ही तोले की वस्तु जा सकती थी। अतिरिक्त तोले का दाम ६ नये पैसे की बजाय १० नए पैसे होगा।

———

सरकारी विज्ञापनों के लिए स्वीकृत
राजस्थान शिक्षा विभाग से मंजूरशुदा

सेनानी साप्ताहिक

सम्पादक :—
सुप्रसिद्ध साहित्य सेवी श्री शंभुदयाल सक्सेना

कुछ विशेषताएं—
★ ठोस विचारों और विश्वस्त समाचारों से युक्त
★ प्रान्त का सजग प्रहरी
★ सर्वाधिक लोकप्रिय पत्र

ग्राहक बनिए, विज्ञापन दीजिए, रचनाएं भेजिए
नमूने की प्रति के लिए लिखिए—
व्यवस्थापक, साप्ताहिक सेनानी, बीकानेर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दोनों देशों के पारस्परिक सहयोग का प्रतीक दो महान नेताओं का मिलन

भारत-सोवियत रूस

सम्पदा

सहयोग परिशिष्ट

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भिन्न भिन्न देशों से भारत के आर्थिक और व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ रहे हैं। कुछ सहयोग की भावना और कुछ अपनी आवश्यकताओं के कारण अनेक देश भारत के आर्थिक उत्थान में महत्वपूर्ण सहयोग दे रहे हैं। सम्पदा के पाठकों को इसकी अधिक जानकारी मिल सके, इस लिए हमारा विचार है कि सम्पदा के परिशिष्ट रूप में समय समय पर विभिन्न देशों के भारत के साथ आर्थिक सम्बन्ध और सहयोग के बारे में आवश्यक सामग्री दी जाय। इसी उद्देश्य से हम यह परिशिष्ट प्रकाशित कर रहे हैं।

विषय सूची

१.	संसार का सबसे बड़ा देश—रूस	३२४
२.	भारत व रूस के ऐतिहासिक सम्बन्ध	३२५
३.	रूस की औद्योगिक उन्नति	३२७
४.	भिलाई का विराट् लोह उद्योग	३३१
५.	१९५६ में : १९५७ में	३३४
६.	जहाजरानी समझौता	३३६
७.	रूस व भारत का बढ़ता हुआ व्यापार	३३७
८.	परस्पर लाभकारी व्यापार	३३८
९.	औद्योगिक प्रशिक्षण	३४०
१०.	भारी बिजली घर	३४१
११.	रूस व भारत के तुलनात्मक आंकड़े	३४३

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

संसार का सबसे बड़ा देश-रूस

रूस संसार का सबसे बड़ा देश है। यह आधा यूरोप का तथा एक तिहाई एशिया का प्रदेश घेरे हुए है।

रूस का क्षेत्रफल २ करोड़ २० लाख वर्ग किलोमीटर (किलोमीटर = १,१०० गज) है। यह क्षेत्र भूमण्डल के निवासयोग्य क्षेत्र का छठा हिस्सा है। पश्चिम से पूर्व की ओर कम से कम दूरी ९,००० किलोमीटर से कुछ अधिक और उत्तर से दक्षिण की ओर ४,५०० किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा है।

रूस की सीमाएं ६०,००० किलोमीटर से भी अधिक फैली हुई हैं। यदि एक व्यक्ति ३० किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से चले तो रूस के चारों ओर एक चक्कर लगाने में उसे ५½ वर्ष लग जाएंगे। रूस के दो तिहाई हिस्से को १२ समुद्र स्पर्श करते हैं। जब रूस के पूर्वी सीमा प्रदेशों में सूर्योदय हो रहा होता है, तब उसके पश्चिमी सीमा प्रदेश में पहले दिन की शाम हो रही होती है। रूस के पूर्वी भाग में पश्चिमी हिस्से से ११ घण्टे पहले दिन निकल आता है।

रूस की सीमाओं से निम्न १२ देश लगते हैं—नार्वे, फिनलैण्ड, पोलैण्ड, चेकोस्लोवेकिया, हंगरी, रूमानिया, टर्की, इराक, अफगानिस्तान, मंगोलिया, चीन और कोरिया।

रूस की राजधानी मास्को है।

जनसंख्या

रूस की जनसंख्या २० करोड़ है। केवल चीन और भारत की आबादी रूस की आबादी से अधिक है।

सन् १९२६ में रूस की जनसंख्या १४.७ करोड़ थी। सन् १९३९ के प्रारम्भ में यह १७.०५ करोड़, और अप्रैल १९५६ में २० करोड़ हो गई। रूस का आबादी बढ़ाने में प्रथम आने वाले देशों में स्थान है। सन् १९५१ से १९५५ तक की अवधि में रूस की जनसंख्या १.६३ करोड़ बढ़ी थी।

औद्योगिक तथा दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या में तथा शहर आबादी में बहुत वृद्धि हुई है। सन् १९३२ में औद्योगिक तथा दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या २.२९ करोड़ थी, जो सन् १९३८ में २.७८ करोड़ और १९५५ के अन्त में ४.७९ करोड़ हो गई।

रूस की शहरी आबादी सन् १९१४ में २.४७ करोड़ थी, सन् १९२६ में २.६३ करोड़, सन् १९३९ में ५.५९ करोड़ तथा १९५३ में ८ करोड़ हो गई

रूस की शहरी आबादी संसार में दूसरे स्थान पर है।

रूस में १५३१ कस्बे (टाउन) तथा २४५४ शहर हैं।

विभिन्न जातियां

रूस में १०० से अधिक राष्ट्रीयताएं, जातीय समाज तथा जातियां निवास करती हैं। इनमें रशियन जाति सबसे बड़ी है। रशियन जाति के लोगों की संख्या कुल आबादी के ५० प्रतिशत से भी अधिक है। यूक्रेनियन लोगों का दूसरा स्थान है। वे कुल आबादी का लगभग २० प्रतिशत हैं।

सन् १९३९ के आंकड़ों के अनुसार विभिन्न जातियों की संख्या निम्न थी—रशियन ९.९ करोड़, यूक्रेनियन २.८ करोड़ (सन् १९४१ में ३,६५ करोड़) बाइलो रशियन .५३ करोड़, उज़बेक .४८ करोड़, तातार .४३ करोड़, कजाक .३१ करोड़, यहूदी .३ करोड़, अज़रेबजानी .२१ करोड़, ज्यौर्जियन .२२ करोड़, आर्मीनियन .२२ करोड़, मोल्दावियन .२२ करोड़। चूवश .१४ करोड़, ताजिक .१२ करोड़, किरीज .०९ करोड़ बाल्टिक गणतन्त्र की मुख्य जनसंख्या सन् १९४० में रूस में शामिल हो गई थी, वहां की मुख्य जातियों की संख्या इस प्रकार है—लेटों की .१५ करोड़, लिथुआनियन लोगों की .२४ करोड़ और इस्टोनियन लोगों की .१ करोड़।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इतिहास पर एक दृष्टि—

भारत व रूस के पारस्परिक सम्बन्ध

[श्री कृष्णचन्द्र विद्यालंकार]

भारत की स्वाधीनता प्राप्ति के बाद विदेशी सम्बन्ध की दृष्टि से यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई है तो वह है साम्यवादी रूस के साथ भारत के बढ़ते हुए सम्बन्ध। ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी और जापान आदि देशों के साथ भी भारत के सम्बन्ध बढ़ रहे हैं, यह ठीक है, किन्तु साम्यवादी रूस के साथ हमारा सम्बन्ध पिछली दो तीन सदियों में करीब करीब शून्य सा रहा है। ब्रिटिश शासन के काल में तो रूस और भारत के सम्बन्ध दोनों देशों के परस्पर निकट होते हुए भी विकसित नहीं हो पाये थे। इसके दो कारण थे। एक तो यह कि अंग्रेज रूस से सदा भयभीत और चौकन्ने रहते थे। पूर्व में प्रभाव वृद्धि के लिए रूसी तथा अंग्रेज परस्पर प्रतिस्पर्धी थे। इसलिए अंग्रेजों का सदा यह प्रयत्न रहा कि भारत और रूस में परस्पर सम्बन्ध न बढ़े। इसका दूसरा कारण यह था कि भारत और रूस की सीमायें जहां परस्पर बहुत निकट हो जाती हैं, वहां भी अफगानिस्तान और उसकी पूर्ववर्ती पर्वत-शृंखला तथा सीमा-प्रान्त की पठान जातियों का (जिरगों) का प्रदेश परस्पर सम्बन्धमें बाधक थे। काश्मीर की रूस से जहां सीमा मिलती है, वहां के पहाड़ी प्रदेश भी यातायात के मार्ग को कठिन बना देते हैं।

अतीत में

किन्तु आज से कई शताब्दियों पहले उक्त प्राकृतिक बाधायें रूस और भारत के सम्बन्ध स्थापित होने में असफल रही थीं। ऐतिहासिकों के कथनानुसार मध्य एशिया में मानव जाति का उद्गम हुआ था। आर्य जातियों की एक शाखा भारत की ओर मुड़ी तो दूसरी शाखायें मध्यपूर्व (जिसे हम भारतीय मध्य-पश्चिम कह सकते हैं) तथा योरुप को मुड़ गईं। इन जातियों या

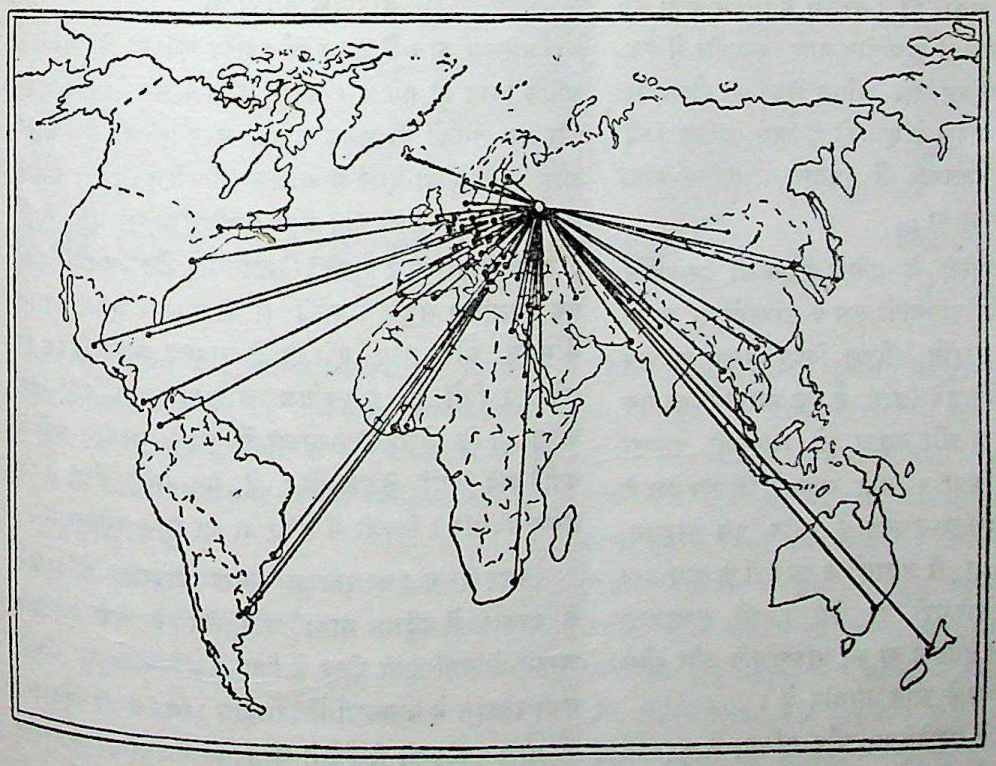

रूस का विश्व के अन्य देशों से सम्बन्ध

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शाखाओं का परस्पर सम्बन्ध कायम न रहा, किन्तु थोड़ी बहुत परम्पराओं की समानता किसी न किसी रूप में अवश्य कायम रही।

रामायण और महाभारत काल के समय की चर्चा हम यहां नहीं करना चाहते, किन्तु बौद्ध-काल में भारतीय संस्कृति के प्रचारक अवश्य मध्य एशिया और रूस जाते थे। उपरले हिन्द में जो भारतीय सभ्यता के व्यापक प्रसार के कारण 'उपरला हिन्द' कहा जा सकता है, भारतीय संस्कृति का बहुत प्रचार हो चुका था। सम्राट अशोक के समय से भारतीयों ने मध्य एशिया में उपनिवेश बसाने शुरू किये थे। पहली शताब्दी ईसवी में भारतीय संस्कृति चीन पहुँची और वहां से कोरिया और छठी शताब्दीमें कोरिया से जापान। उसके बाद उसने तिब्बत में प्रवेश किया और तिब्बती धर्मदूतों ने उसे मंगोलिया, मंचूरिया और सायबेरिया तक फैला दिया। अजरबाइजान का संगीत 'मोरइण्डी' मौर्यकालीन भारतीय संगीत की देन है। ताजिकिस्तान में जो आज सोवियत संघ का एक प्रदेश है, भारत की संस्कृति बहुत पहले फैल चुकी थी। कानिस में गांधार कला की कुछ मूर्तियां हैं। ताजिकों के प्राचीन नगर कुशानीर में एक चीनी कहानी के अनुसार एक प्रसिद्ध भवन की दीवार पर भारतीय और तुर्क जनता के शासकों के चित्र अंकित किये गये थे। सोलहवी शताब्दी में पंचतन्त्र का ताजिक भाषा में अनुवाद किया गया था।

'हिन्दु-पुपीरियोरिटी' के प्रसिद्ध लेखक श्री हरविलास शारदा ने भारत और एशियायी रूस के सम्बन्धों पर अच्छा प्रकाश डाला है। उन्होंने हरिवंश विष्णु पुराण अध्याय सत्रह का उद्धरण देते हुये लिखा है कि भारतीयों का एक समूह सायबेरिया गया और वज्रपुर को राजधानी बनाकर एक राज्य कायम किया। कहा जाता है कि उस देश के राजा की मृत्यु पर श्री कृष्णचन्द्र के तीन पुत्र परदमन, गद और साम्भ बहुत से ब्राह्मणों व क्षत्रियों के साथ वहां गये और ज्येष्ठ पुत्र राजगद्दी पर बैठा। श्री कृष्णचन्द्र की मृत्यु पर उन्होंने द्वारिका जा कर सहानुभूति और शोक प्रकट किया। बैंकट्रिया के लोग भारतीय थे।

भारत के प्रवासी साइबेरिया और एशिया के सुदूरतम उत्तर तक पहुँच गये थे। उनके वंशज आज भी वहां पाये जाते हैं। साइबेरिया के लमोयिदिज (Samoyedes) भारत के यदु ही हैं। लेख का कलेवर बढ़ने के भय से हम यहां अधिक उद्धरण देने में असमर्थ है। केवल प्रो. मैक्समूलर की सम्मति देकर आगे चलेंगें। "तुर्व और उनके वंशज भारतीय महाकाव्यों में अभिशप्त और भारतीय उत्तराधिकार से वंचित बताये गये हैं और इसीलिये उनको भारत छोड़ना पड़ा।...आज भी साइबेरिया और एशियायी रूस में भारतीय कला और मूर्तियों के दर्शन होते हैं।"

श्री लेव यूस्पैंस्की ने एक विद्वत्तापूर्ण लेख में बताया है कि अभी वास्कोडीगामा भारत-अन्वेषण के लिए इधर-उधर भटक रहा था कि रूसी त्वेर निकितन का व्यापारी भारत पहुँच गया था. इससे भी पहले नोवोगोरोद के शासनकाल में काश्मीर व बंगाली अतिथि रूस आ चुके थे। गंगा के तटवर्ती लोगों ने वोल्गा के दर्शन कर लिये थे। उस समय तक मास्को कुचिन गांव कहलाता था।

मुस्लिम काल में

मुस्लिम काल में भारत और मध्य एशिया के सम्बन्ध अधिक निकट हो गये थे। पारसी भाषा बोलने वाले कवियों और गद्य लेखकों की अनेक कृतियाँ मध्य एशिया में आईं और ताजि भाषी देशों में अधिक लोकप्रिय हुईं। अमीर खुसरो की रचनायें भी वहां बहुत प्रचलित हो गई थीं। तैमूर के उत्तराधिकारी शाह रोहने विजयनगर के सम्राट के पास एक शिष्टमंडल समुद्र के रास्ते से भेजा था। मुगल शासन में भारत और मध्य एशिया के सम्बन्ध काफी निकट हो गये थे। दोनों का सांस्कृतिक आदान प्रदान यहां तक चलता था कि सोलहवीं शताब्दी के पहले पच्चीस वर्षों में बनाये गये चित्रों के सम्बन्ध में यह सन्देह होता है कि उनका चित्रांकन दिल्ली में हुआ था या मध्य एशिया में।

पीटर दी ग्रेट का राजदूत मुगल बादशाह औरङ्गजेब के दरबार में पहुँचा था। औरङ्गजेब ने एक शानदार अम्बार के साथ हाथी पीटर के लिए भेंट में भेजा था। उसी रूसी राजदूत ने कलकत्ता में राष्ट्रीय रंगमंच की स्थापना की थी। एक रूसी लेखक ने यूरोपियन नाटकों का अनुवाद

(शेष पृष्ठ ३४२ पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

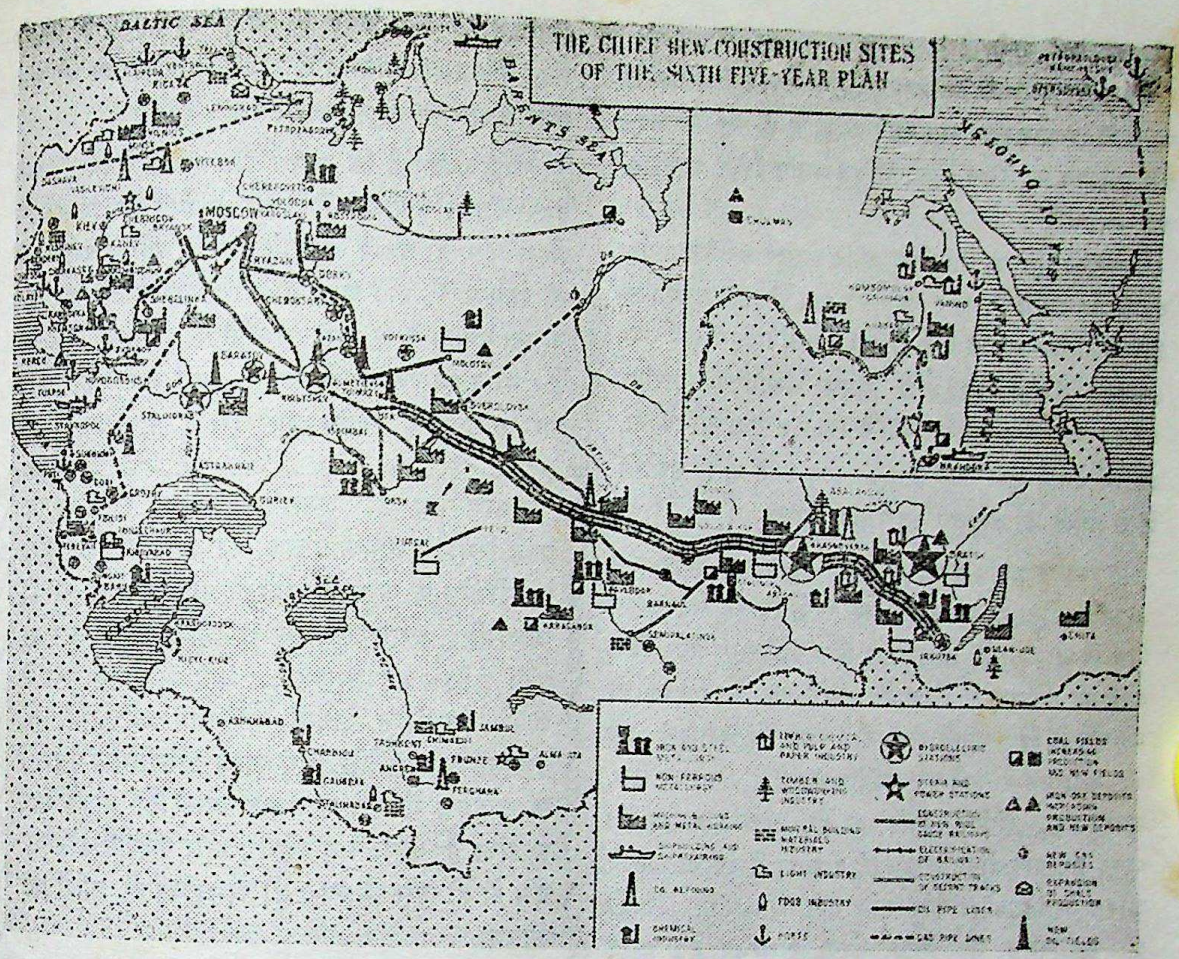

रूस की औद्योगिक उन्नति : छठी विकास योजना के महान लक्ष्य

रूस और भारत के औद्योगिक सम्बन्ध एवं पारस्परिक सहयोग की चर्चा करते हुए यह जान लेना अधिक लाभकारी होगा कि सोवियत रूस स्वयं औद्योगिक दृष्टि से कितना समृद्ध है या औद्योगिक समृद्धि की वहां क्या संभावनाएं हैं।

भारी उद्योग क्यों ?

रूस की अर्थ व्यवस्था की एक बड़ी विशेषता है और वह यह कि उसने अपने आर्थिक विकास के प्रारम्भ के साथ ही पूंजीगत भारी मशीनरी बनाने वाले उद्योगों की तरफ विशेष ध्यान दिया और छोटे उद्योगों अर्थात् उपभोग्य सामग्री के उत्पादन की ओर कम। विगत पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान में अर्थात् १९२८—१९५५ के बीच भारी उद्योगों का उत्पादन ३९ गुना बढ़ गया, जबकि छोटे उद्योगों का ९ गुणा। उपभोग्य वस्तुओं की इस उपेक्षा के कारण वहां साधारण उपभोग की चीजें भारत से बीसियों गुना महंगी हैं। रूस की इस अर्थ-पद्धति की आलोचना काफी हुई है, किन्तु रूसी अर्थशास्त्र के प्रोफेसर वी. स्मेखोव ने इस आलोचना का उत्तर देते हुए बताया है कि "भारी उद्योग राष्ट्रीय अर्थतंत्र की अनेक शाखाओं को अपने में समा लेता है। धातुओं और कोयले की खानें, धातु उद्योग और मशीन बनाना, तेल निकालना और उसे शुद्ध करना, भवन-निर्माण का सामान तैयार करना, बिजली तैयार करना, रसायन बनाना, लकड़ी की कटाई आदि

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

काम इसके अन्तर्गत हैं।

"भारी मशीनरी का उत्पादन मुख्यतया राष्ट्रीय अर्थतंत्र की सभी शाखाओं को सुसज्जित करता है। यह उत्पादन उस उत्पादन का, जिस पर प्राविधिक प्रगति निर्भर करती है, बड़ा साधन है।

"सीधे तौर पर प्राविधिक प्रगति मशीन बनाने के उद्योग पर निर्भर करती है, और सोवियत संघ में इस उद्योग का विकास विशेष रूप से तेजी से हो रहा है। इसलिए जब सोवियत संघ में १९५५ में समग्र औद्योगिक उत्पादन १९१३ के क्रान्ति-पूर्व रूस की अपेक्षा २५ गुना अधिक था, मशीनें बनाने वाले और धातु का काम करने वाले उद्योगों में से प्रत्येक का उत्पादन १३८ गुना अधिक था।

"मानव प्रगति केवल इस पर निर्भर नहीं है कि क्या उत्पादित होता है, बल्कि इस पर भी है कि वह कैसे उत्पादित किया जाता है, उत्पादन के किन यंत्रों द्वारा तथा किस शक्ति की सहायता से। अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य सीधे तौर पर न तो पिटी हुई धातु का, न मशीन के पुर्जों का उपयोग करता है, न वह तेल, सुपरफास्फेट, सीमेन्ट आदि का ही उपयोग करता है। परन्तु इन वस्तुओं के बिना वांछित मात्रा में रोटियां, कपड़े और जूते- रेफ्रिजरेटर और कपड़े धोने की मशीनें, किताबें और टेलीविजन सेट तैयार करना असम्भव है। इसके अलावा धातुओं, मशीन की शक्ति तथा भारी उद्योग के दूसरे मालों की जरूरत उन्हीं के उत्पादन के लिए होती है।

"इन पांच वर्षों के दौरान में, खेतों की उपज ७० प्रतिशत बढ़ी है। परन्तु यह कार्य पूरा करने के लिए खेती को (१५ अश्वशक्ति वाले) १६॥ लाख ट्रैक्टर, ५ लाख ६० हजार अन्न शस्य कम्बाइन, २॥ लाख मकई और चारे की फसलों के कम्बाइन तथा बहुत-सी दूसरी मशीनें देनी होंगी। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अकेली खेती की मशीनें तैयार करने में डेढ़ करोड़ टन पिटी धातु लगेगी। इतनी धातु तैयार करने के लिए ३ करोड़ टन खनिज लौह और ३ करोड़ टन कोयले की जरूरत पड़ेगी। इसलिए उपभोक्ता माल का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारी उद्योग के माल का उत्पादन बढ़ाना सबसे पहले जरूरी है। खेती, छोटे और खाद्य-उद्योग, भवन-निर्माण, म्युनिसिपल निर्माण आदि सर्वथा भारी उद्योग पर जो उनका आधार है, निर्भर करते हैं। उनकी वृद्धि और विकास भारी उद्योग की वृद्धि और विकास का अनुसरण करेगा।"

यही कारण है कि भारत की सरकार ने भी अपनी दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को असाधारण महत्व दिया है, यद्यपि उनके संचालन में आर्थिक कठिनाइयों की कमी नहीं। रूस आज भी औद्योगिक उन्नति की कोई योजना बनाता है तो भारी उद्योगों पर अधिक बल देता है। भारत की दृष्टि से तो रूस के भारी उद्योग ही लाभकारी हो सकते हैं क्योंकि हमारे देश में पूंजीगत सामग्री की ही कमी है। उपभोग्य वस्तुओं का उत्पादन छोटे-बड़े हजारों लाखों व्यवसायी कर रहे हैं।

> अमरीका की "युनाइटेड स्टेट्स न्यूज एण्ड वर्ल्ड रिपोर्ट" नामक पत्रिका का कथन है कि "रूस की योजना के अनुसार, अगले पाँच वर्षों में उसकी औद्योगिक प्रगति की गति अमरीका की रफ्तार से कहीं अधिक बढ़ जायगी...। यदि सोवियत रूस ने अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया, तो इस्पात, तेल, सीमेंट, एवं अन्य औद्योगिक पदार्थों के उत्पादन में जो अब तक अमरीका बाजी मार ले गया है, वह भी न रहेगी, और कोयले के उत्पादन में तो रूस निश्चय ही अमरीका से आगे बढ़ जायगा।"

नई योजना में

रूस की छठी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर विशेष बल दिया जा रहा है। १९३९ की अपेक्षा आज वहां ३॥ गुना औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है। छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य आर्थिक क्षेत्रों में उन्नति करते हुए रूसी नागरिक का जीवन स्तर ऊंचा करना है किन्तु औद्योगिक उत्पादन को—भारी मशीनों के उत्पादन को १९५५ की अपेक्षा १९६० तक ७० प्रतिशत बढ़ा देना है। अर्थात् युद्धपूर्व के स्तर की अपेक्षा ६। गुना। उपभोग्य पदार्थों का उत्पादन ६० प्रतिशत बढ़ा दिया जायगा।

१९५५ में रूस में लौहा-उत्पादन ४५० लाख टन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हुआ। पांच वर्षों में इसे बढ़ा कर ६८३ लाख टन कर दिया जायगा। यह संख्या कितनी बड़ी है, इसका अनुमान केवल इसी से हो सकता है, कि यह वृद्धि ही ब्रिटेन के कुल उत्पादन से अधिक है। मात्रा में वृद्धि के अतिरिक्त लोहे की किस्म तथा उत्पादनविधि में जो प्रगति की जायगी, वह इसके अतिरिक्त है। नीचे की तालिकाओं से मालूम होगा कि रूस लौह-उत्पादन में कितनी तेजी से प्रगति कर रहा है।

	कच्चा लोहा		फौलाद
	(लाख टनों में)		
१९१३	४२		४२
१९२८	३३		४३
१९४०	१५०		१८३
१९४५	९०		१२३
१९५०	१९३		२७३
१९५५	३३३		४४२
१९६०	५३०	(योजना)	६८२

तेल व ईंधन

ईंधन के उत्पादन में तथा तेल और गैस के उत्पादन में रूस तेजी से प्रगति करना चाहता है। १९५५ की अपेक्षा कोयले का उत्पादन १९६० में ५२ प्रतिशत और तेल का उत्पादन १०० प्रतिशत और गैस का उत्पादन ३०० प्रतिशत बढ़ा दिया जायगा। रूस में कोयला उद्योग बहुत उन्नत है। १९५५ में ३९११ लाख टन कोयला वहां निकाला गया था, लेकिन यह भी समय की आवश्यकताओं को देखते हुए पर्याप्त नहीं है। इसलिए इसका आगामी लक्ष्य १९६० में ५९३० लाख टन रखा गया है, जो सं० रा० अमेरिका के कोल-उत्पादन से भी अधिक हो जायगा। डानबस की कोयले की खानों को विकसित किया जा रहा है और यह आशा की जाती है कि १९६० में वहां से २१२० लाख टन कोयला निकलने लगेगा। यह कोयला पश्चिम जर्मनी तथा फ्रांस के संयुक्त कोल-उत्पादन से अधिक है। यूक्रेन, कुजनेस्क आदि की कोयला खानों का विकास किया जायगा। रूस में तैल-उद्योग बहुत उन्नत है, परन्तु अभी और भी नये तैल-क्षेत्रों की खोज हुई है।

तेल उद्योग के विकास में रूस ने कितनी उन्नति की है, इसका एक उदाहरण यह है कि अमेरिका की ड्रेसर इण्डस्ट्रीज नामक कम्पनी ने रूस को बहुत सी ड्रिल मशीनों का ऑर्डर दिया है। अमेरिकन विशेषज्ञों ने इन्हें अमेरिकन मशीनों से कई गुना अच्छा बताया है। १९६० में तेल का उत्पादन १३५० लाख अर्थात् १९४० से साढे चार गुना टन हो जायेगा। युराल और वोल्गा के क्षेत्र, जो बहुत सम्पन्न हैं, देश के उत्पादन का ७५ प्रतिशत भाग उत्पादन करने लगेंगे।

रूस की आर्थिक व्यवस्था को भी बहुत ऊंचे स्तर पर लगाया जा रहा है। मजदूरी की सख्त मेहनत बचाने के लिए तरह-तरह की मशीनरी लगायी जा रही है, बहुत सी स्वयं-चालित मशीनें और बिजली से चलने वाली मशीनें बन रही हैं। १९५५ में १५ हजार करोड किलोवाट बिजली पैदा हुई थी। १९६०में ३२ हजार करोड़ किलोवाट पैदा होने लगेगी। रूस में पानी से बिजली निकालने के बहुत से साधन हैं। बिजली का उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ बिजली पैदा करने वाली सारी मशीनरी भी काफी तैयार हो रही है।

१९१३ में रूस का स्थान बिजली उत्पादन में १५वां था और आज यूरोप के देशों में प्रथम और विश्व में द्वितीय है।

इंजीनियरिंग उद्योग

पंचवर्षीय योजना में इन्जीनियरिंग और धातु उद्योग को विकसित करने के लिए आधुनिकतम संयंत्रों का निर्माण किया जा रहा है। धातु उद्योग, खान, तेल उद्योग ,बिजली रोशनी व यन्त्रों के लिए इन्जीनियरिंग उद्योग प्रगति कर रहा है। यह प्रयत्न किया जा रहा है कि खानों को खोदने वाले एक्सकैवेटर और मिट्टी के खोदने वाले बुलदोजर ज्यादा समर्थ बनाये जावें। बड़े-बड़े स्टीम-टरबाइन तैयार किये जा रहे हैं, जिनकी क्षमता २।३ लाख किलोवाट की होगी और वे ९०० टन भाप निकाल सकेंगे। अणुशक्ति के प्रयोग की दिशा में रूस बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। यह आशा जाती है कि आगामी पांच वर्षों तक अणुशक्ति के द्वारा २० या २५ लाख टन किलोवाट की शक्ति पैदा होने लगेगी। युराल में अणुशक्ति के दो संयन्त्र लगाये जा रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक १० लाख किलोवाट शक्ति प्रदान करेगा। मास्को के निकट ४ लाख किलोवाट क्षमता वाला यन्त्र लगाया जा रहा है। अणुशक्ति के शांति कालीन प्रयोग के लिए रूस निरंतर आगे बढ़ रहा है। यातायात व परिवहन के साधनों के लिए अणु शक्ति का

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रयोग किया जाएगा। बर्फ को काटने वाले अणु-शक्ति से चालित इन्जन तैयार हो रहे हैं। रूस केवल भारी उद्योगों के निर्माण की ओर ही ध्यान नहीं दे रहा, किन्तु वस्त्र का उत्पादन आगामी पांच वर्षों में २० प्र० श०, ऊनी माल का उत्पादन ५० प्र० श० और रेशम का उत्पादन १०० प्र० श० बढ़ाने के लक्ष्य भी नियत किये गये हैं। जूतों का उत्पादन ५० प्र० श० बढ़ा दिया जायेगा। खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह प्रयत्न किया जा रहा है कि १९६० तक खाद्य पदार्थों का उत्पादन १८०० लाख टन तक बढ़ा दिया जाय। परन्तु रूस में तो साधारण

[शेष पृष्ठ ३४० पर]

रूस की औद्योगिक उन्नति

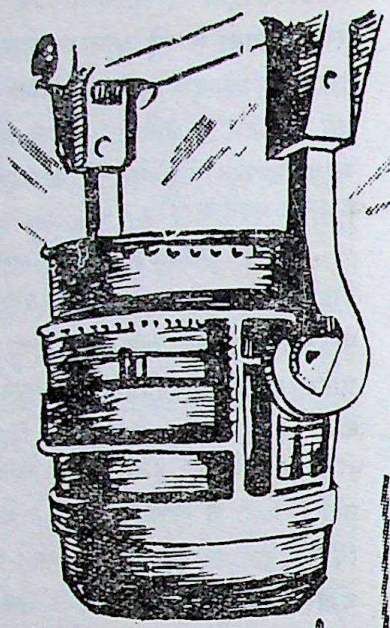

लौह-पिंड का उत्पादन (लाख टनों में)

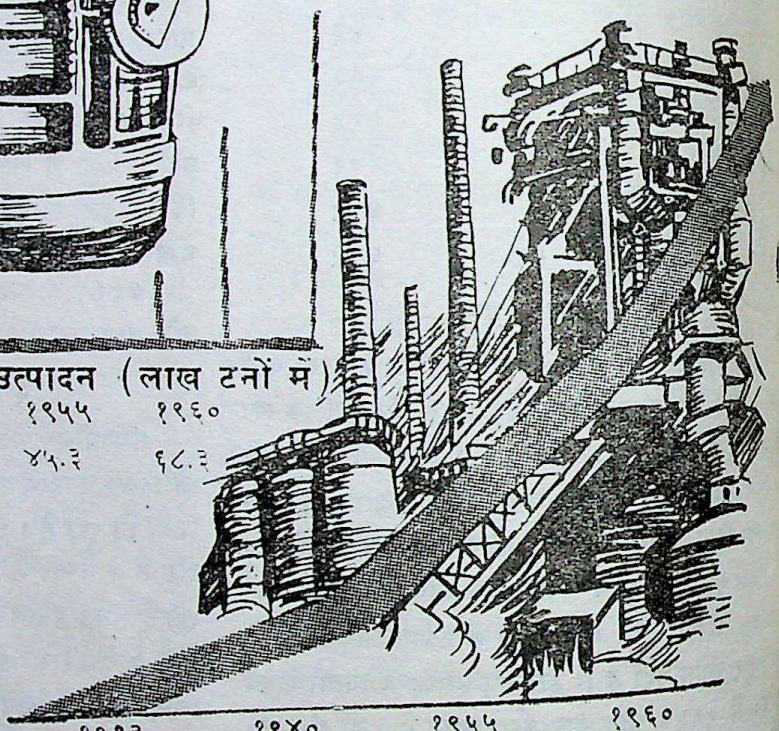

इस्पात का उत्पादन (लाख टनों में)

१९१३	१९५५	१९६०
४.३१	४५.३	६८.३

१९१३	१९४०	१९५५	१९६०
४.२	१४.९	३३.३	५३.०

तेल का उत्पादन (लाख टनों में)

१९१३	१९४०	१९५५	१९६०
१०.३	३१.१	७०.८	१३५.०

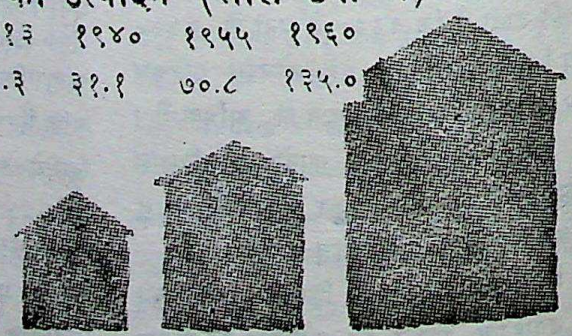

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

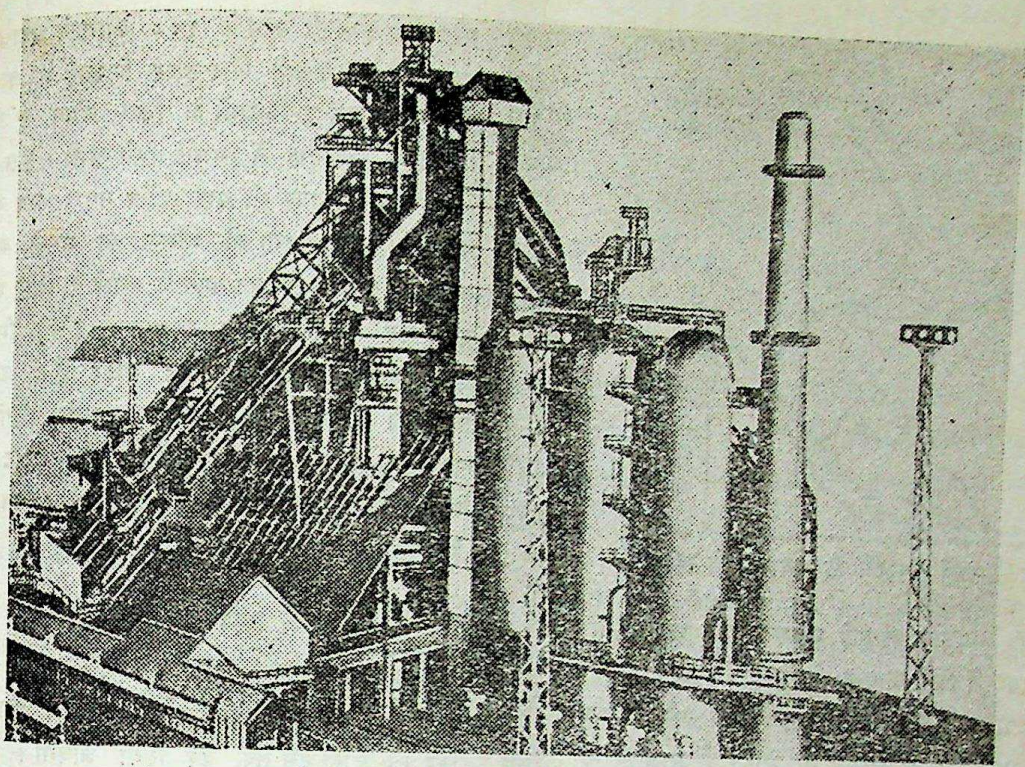

भिलाई के लोह-उद्योग की भट्टी का नमूना

रूस का महत्वपूर्ण योग—

भिलाई का विराट् लोह-उद्योग

भारत और रूस के पारस्परिक आर्थिक सहयोग के बीसियों रूप हैं, किन्तु इसका सबसे ज्वलन्त प्रमाण भिलाई का लोहे का कारखाना है। भारतवर्षने अपनी दूसरी पंचवर्षीय योजना को बनाते समय यह अनुभव किया कि लोहा उद्योग में बिना स्वावलम्बन प्राप्त किए हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इस दृष्टि से तीन नये बड़े उद्योग खोलने का निश्चय किया गया, परन्तु इन उद्योगों की स्थापना अत्यन्त कठिन थी, क्योंकि न हमारे पास इसके लिए रुपया था और न हमारे पास कुशल कारीगर। इस-लिए यह निश्चय किया गया कि विदेशों से इस सम्बन्ध में सहयोग प्राप्त किया जाए। भारत की पुनर्निर्माण की इस विशाल योजना में रूस ने भी सहयोग देने का निश्चय किया। मध्यप्रदेश के लिए यह सौभाग्य की बात है कि रूसी विशेषज्ञों ने भिलाई को लोहे के कारखाने के लिए उचित स्थान समझा। इससे पहले जर्मन विशेषज्ञ उड़ीसा के रूरकेला को प्राथमिनता दे चुके थे। भिलाई का प्रस्तावित इस्पात कारखाना मध्यप्रदेश के भाग्योदय का ही प्रतीक हो गया है।

समझौते की शर्तें

दो फरवरी १९५५ को भिलाई में निम्न शर्तों पर दस लाख टन का कारखाना खोलने का रूस से समझौता हो गया। इस की लागत ११० करोड़ रुपया आंकी गई है।

१-इसमें से इमारत, सामान और निर्माण में भारत ४७ करोड़ रुपए व्यय करेगा, शेष रुपए रूस लगायगा। कारखाने की मशीनें तथा अन्य सामान जो रूस भेजेगा, उसकी कीमत १२ वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी। प्रति वर्ष रूस जितनी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

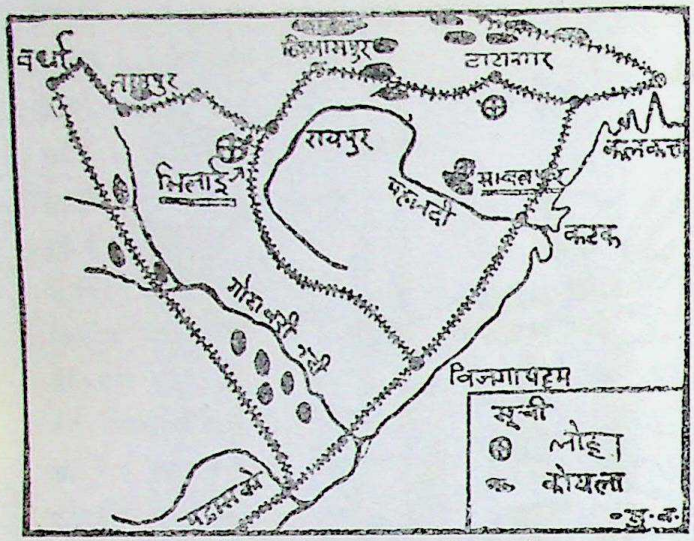

जहां कारखाने की स्थापना हो रही है

राशि देता रहेगा, उस पर ढाई प्रतिशत व्याज भारत देगा। भुगतान रुपए में किया जाएगा जो रिजर्व बैंक आफ इण्डिया में इसी काम के लिए खोले गए विशेष खाते में जमा किया जाएगा। इस धन से या तो भारत में माल खरीदा जा सकेगा या उसे पौंड स्टर्लिंग में बदला जा सकेगा।

२-रूसी इंजीनियरों की सेवाओं के बदले में भारत ढाई करोड़ रुपया देगा। योजना पूर्ति के भिन्न-भिन्न कार्य पूर्ण होने पर भी कुछ राशियां भारत रूस को देगा।

३-योजना बनाने और उसे अमल में लाने के प्रत्येक कदम में भारतीय विशेषज्ञों की सलाह ली जाएगी और भारतीयों को रूस तथा भारत में प्रशिक्षण देने की विशेष व्यवस्था की जाएगी।

४-भिलाई के कारखाने का उत्पादन लक्ष्य दस लाख टन वार्षिक रखा गया है। और रूसी इंजीनियरों ने यह विश्वास दिलाया है कि दिसम्बर १९५८ तक लोहे और दिसम्बर १९५९ तक इस्पात का उत्पादन अवश्य प्रारम्भ हो जावेगा। भिलाई के लिए रूस से आने वाली सब मशीनें विजगापट्टम बन्दरगाह में उतरने की व्यवस्था की गई है।

रूस से समझौते के सम्बन्ध में बाकायदा लिख पढ़ मार्च १९५६ में पूर्ण हो गई थी और भारत सरकार ने कारखानेकी अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार कर ली थी। यह समझौता पूर्ण होते ही रूस के ३०० कारखाने धड़ाधड़ माल तैयार करने लगे और इधर भिलाई में कारखाने के अलग २ विभागों के लिए योग्य इंजीनियरों के निरीक्षण में इमारतें बनने लगी। रूस के विशेषज्ञ इंजीनियर भी यहां पहुँच गए। जब यह कारखाना बन जाएगा तो एशिया का सबसे बड़ा कारखाना होगा। इस कारखाने के बनाने के लिए ४५ लाख घन मीटर (एक मीटर = ४० इंच) मिट्टी खोदनी पड़ेगी। एक लाख घन मीटर ईंटें काम आएंगी। ६५ मील रेलवे लाइन बनानी पड़ेगी। साढ़े पांच लाख घन मीटर सीमेंट की कंकरीट का निर्माण करना होगा। एक लाख टन फौलाद निर्माण में लगेगा।

प्रारम्भिक उत्पादन-क्षमता

भिलाई-इस्पात-कारखाना प्रारम्भ में १० लाख टन इंगाट इस्पात का उत्पादन प्रतिवर्ष करेगा, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर २५ लाख टन तक कर दिया जायगा। उक्त कारखाने में प्रमुख रूप-से प्रारम्भ में निम्नलिखित लगभग परिमाण में भारी वस्तुएँ निर्मित की जाएँगीः—

रेल पटरियां	...	१,००,००० टन
स्लीपर बार आदि	...	९०,००० टन
हैवी स्ट्रक्चरल	...	१,७५,००० टन
मर्चेन्ट बार	...	२,३५,९०० टन
बिलेट्स फार रिरोलिंग		१,५०,००० टन
कुल योग		७,५०,००० टन

प्रगति

कारखाने का निर्माण जिस तेजी और क्रम से हो रहा है, उसके सम्बन्ध में विस्तृत परिचय देने की जरूरत नहीं है। हम यहां भिन्न २ समाचार पत्रों से दो चार अवतरण देकर यह लेख समाप्त करेंगे। किन्तु उन समाचारों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि कितनी तेजी से रूस यह काम कर रहा है। वस्तुतः रूस के इंजीनियरों मजदूरों, अधिकारियों और जनता में इस कारखाने को शीघ्र से शीघ्र सम्पन्न और सफल देखने की उमंग और उत्सुकता पैदा हो चुकी है। रूस ने इस कारखाने की सफलता को अपनी प्रतिष्ठा

[सम्पादक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

का प्रश्न बनाया हुआ है। उसे यह सिद्ध करना है कि ब्रिटेन और जर्मनी की अपेक्षा, जो दुर्गापुर (बंगाल) तथा रूरकेला (उड़ीसा) में लोहे के कारखाने तय्यार कर रहे हैं वह अधिक फुर्ती और कुशलता के साथ काम कर रहा है। वे समाचार निम्नलिखित हैं:—

[१]

रायपुर, ४ जून। भिलाई इस्पात कारखाने के जनरल मैनेजर श्रीनाथ मेहता ने बताया है कि योजनाका कार्य पूर्णतः निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ रहा है और पहली भट्टी सम्भवतः अगले साल के अन्त तक काम करने लगेगी। भिलाई योजना में अभी तक १२ करोड़ रुपए व्यय हो चुके हैं। सम्पूर्ण योजना १५० करोड़ रुपए की है। अभी तक रूस से २०,००० टन मशीनें आ चुकी हैं। उनका आयात अभी भी जारी है।

१५ करोड़ की ३ भट्टियों में से पहली का शिलान्यास १० जून को हो रहा है तथा अन्य दो का इस वर्ष अक्तूबर तथा नवम्बर में होगा। ये भट्टियां ऐसे सीमेंट से बनाई जा रही हैं, जिस पर आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

दक्षिण-पूर्वी रेलवे ने भिलाई-हैरन-डुल्ली रास्ते पर २५ मील लम्बी रेलवे लाइन का निर्माण किया है और बाकी भी जल्दी पूरी हो जाएगी।

[२]

भिलाई ७ जून। इस कारखाने के मुख्य इंजीनियर बी० ई० दिमचित्स के कथनानुसार सोवियत संघ में ३०० कारखाने इस इस्पात कारखाने के लिये विभिन्न प्रकार की सामग्री, इस्पाती ढांचे, ऊष्मसह पदार्थ तथा अन्य विशेष प्रकार की वस्तुएं तैयार करने में न्यस्त हैं। सोवियत जनता में महान मित्र भारत और उसकी जनता के लिये बहुत अधिक हार्दिक और मित्रतापूर्ण भावनायें विद्यमान हैं, और वह भिलाई इस्पात कारखाने के लिये सब कुछ समय पर और उत्कृष्ट कोटि का बनाना चाहती है। पचास हजार टन से अधिक वज़न के इस्पाती ढांचे, सामग्री, पाइप और ऊष्मसह पदार्थ या तो भारत पहुँच चुके हैं, या रास्ते में हैं।

छः लाख घन मीटर से अधिक मिट्टी का काम खत्म हो चुका है, और पहला २५ हजार घन मीटर कंकरीट भी बिछ चुका है। जून १९५७ में पहली वायु भट्टी और गर्भक्लास्ट हीटरों की रिइनफोर्स्ड कंकीट की नींवें तथा पहली कोक ओवन बैटरी कंकरीट की नींव की प्लेट पूर्ण हो जाएगी, जिसके पश्चात् इस्पाती ढांचों को खड़ा करने का काम शुरू होगा। ६५ मीटर ऊंचे एक बुर्ज क्रेन को इस समय जोड़ा जा रहा है, जिससे वायु भट्ठी के पच्चीस-पच्चीस टन वजनी बड़े हिस्सों को जोड़ना सम्भव हो सकेगा। निकट भविष्य में इस जून से ही शुरू करके निर्माण कार्य में भाग लेने वाले ठेकेदार निर्माण में नियुक्त श्रमिकों की संख्या में काफी वृद्धि कर देंगे। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि काम घड़ी की सूई की तरह चालू रहे और बरसात में भी निर्माण चालू रखने की तैयारी कर लेंगे, तथा इस प्रकार के सब कदम उठायेंगे, ताकि कार्य का मासिक कार्यक्रम पूरा होता रहे। इससे काम की बड़े पैमाने पर प्रगति को सहायता मिलेगी ताकि कारखाने का नियत अवधि के भीतर कार्यारम्भ सुनिश्चित बन सके।

[३]

लेनिनग्राड, ८ जून ५७। बिजली के औजारों के कारखाने ने ऊंची वोल्टेज के तेल स्विच और सर्किट भंजक भिलाई भेजे हैं। लेनिनग्राड के बहुत से कारखाने इस संस्थान के आर्डर पूरे कर रहे हैं।

बिजली पल्प कारखाना, टेलीमिकेनिक एवं बहुत से स्वयंचालित यंत्रों तथा कण्ट्रोल पैनलों का निर्माण कर रहा है। इस समय एक बिजली की धोंकनी तथा स्टेप-डाउन सब स्टेशन के लिए कण्ट्रोल पैनलों को जोड़ने का काम खत्म कर रहा है। कोल्याकोव कारखाना भिलाई को एक धातु शोधन कारखाने के लिए सामग्री दे रहा है। पहली किश्त, जिसमें १२ मशीने शामिल हैं, तैयार है और भारत भेजे जाने वाली है। ये यंत्र ढुलाई और कच्ची धातु की छंटाई के लिए हैं। स्वदलोवस्क के एक समाचारके अनुसार यूराल का भारी मशीनों का कारखाना भारतीय गणतंत्र के लिए एक शक्तिशाली ब्लूमिंग मिल तैयार कर रहा है। यह उसके आधे पुर्जे तैयार कर चुका है, जिनमें से कुछ जहाज द्वारा भेजे जा चुके हैं।

——

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

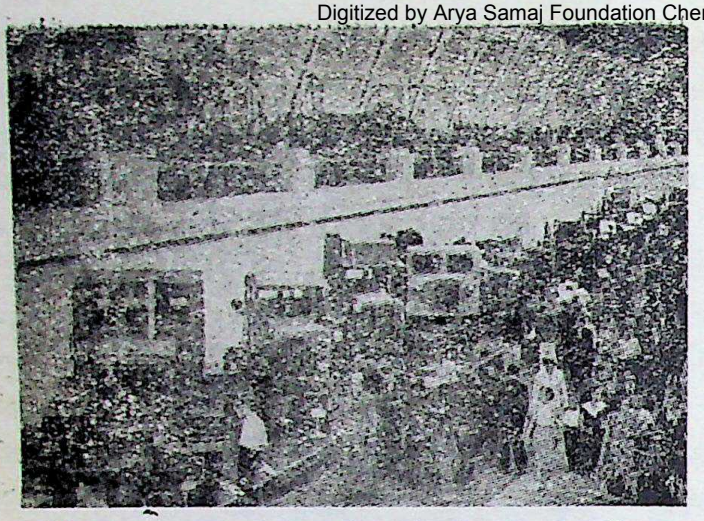

सोवियत जहाज स्तावरोपोल कृषि यंत्रों और मोटरों को लेकर बम्बई बन्दरगाह पर

१९५६ में

लेखक—

'सोवियत भूमि' ने १९५६ में भारत सोवियत सम्बन्ध को बढ़ाने वाली घटनाओं का एक सचित्र कलैन्डर प्रकाशित किया है। दोनों देशों के पारस्परिक सांस्कृतिक आदान-प्रदान व शिष्टमण्डलों के विवरणों के अतिरिक्त जो अर्थ-सम्बन्धी कार्य★ किये गये हैं, वे निम्नलिखित हैं—

फरवरी

❀ सोवियत मोटर-जहाज "स्तावरोपोल" कृषि सम्बन्धी मशीनों, मशीनी औजारों आदि का पहला बोझ लेकर बम्बई पहुँचा। ये सामान विभिन्न कारखानों के कर्मचारियों ने श्री नेहरू को सोवियत संघ के उनके भ्रमण के समय भेंट में दिये थे।

अप्रैल

❀ सोवियत संघ और भारत के बीच नियमित जहाजरानी सम्बन्ध की स्थापना के लिए नयी दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए।

मई

❀ सोवियत संघ के सहयोग से भारत में बन रहे इस्पात के कारखाने में काम करने के लिए ७०० भारतीय विशेषज्ञों और मजदूरों को सोवियत संघ में प्रशिक्षित करने के सम्बन्ध में एक समझौता हुआ।

जून

❀ सोवियत संघ की सहायता से बम्बई में एक प्रविधि-संस्थान की स्थापना के सम्बन्ध में सोवियत विशेषज्ञों का एक दल दिल्ली पहुँचा।

जुलाई

❀ लोक सभा के सदस्य श्री दास के नेतृत्व में भारत के कृषि विशेषज्ञों का एक दल सोवियत संघ आया।

❀ भारतीय जहाज "जल-मंजरी" ने नोवोरोसिस्क में लंगर डाला और भारत व सोवियत संघ के बीच जहाजरानी सम्बन्ध का उद्घाटन हुआ।

अक्तूबर

❀ T-U-१०४ नामक सोवियत जेट यात्री विमान मास्को से ६ घंटे १५ मिनट में दिल्ली पहुँचा।

नवम्बर

❀ भारत सरकार के उत्पादन मंत्री श्री देवरी के सोवियत संघ आगमन के समय एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अनुसार औद्योगिक निर्माण कार्य के लिए भारत को सोवियत संघ से ५० करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त होगा।

❀ भारत के तेल-साधनों की शोध करने में प्राविधिक सहयोग के सम्बन्ध में एक भारत-सोवियत समझौते पर हस्ताक्षर हुए।

★भिलाई लोहे के कारखाने के सम्बन्ध में जो प्रगति हुई, वह इसमें सम्मिलित नहीं की गई। इसी तरह भारत में तेल निकालने या शोधित करने के लिए जो मशीनरी दी गई अथवा शिक्षक भेजने के सम्बन्ध में जो समझौते हुए, उनका भी उल्लेख इसमें नहीं किया गया।

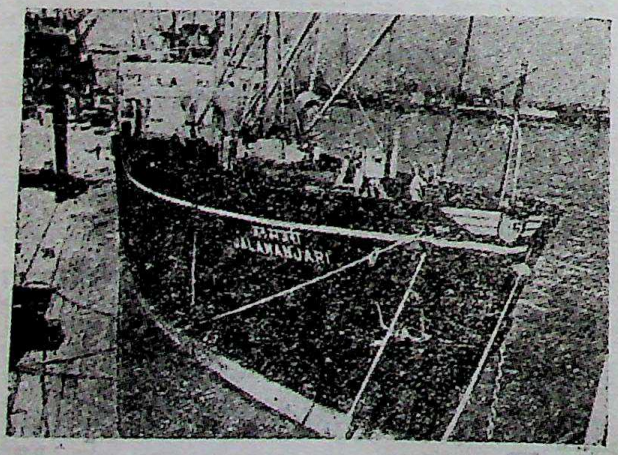

काला सागर के बन्दरगाह पर रूसी जहाज जो भारत आया

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

१९५७ में

—श्री टी० एन० वर्मा

सिलसिला जारी

१९५६ का यह सिलसिला १९५७ में भी इसी तरह जारी है। उदाहरणस्वरूप अखबारों के कुछ समाचार देखिये—

ब्लाडीवोस्टक फरवरी ५७। सोवियत रूस के जहाज भारत की ओर रवाना हो रहे हैं। कलकत्ते में वैलिरियन क्यूबीरोत नामक जहाज मिलाई के लोह कारखाने के लिए भारी मशीनें उतार रहा है। 'किम' जहाज ने मद्रास में ६ फरवरी को कई हजार टन भारी मशीनरी उतारी है।

दो और जहाज सेवजारल्स और पोलिना ओसिमैन भी भारत की ओर चल पड़े हैं। सुदूरपूर्व के जहाजी कर्मचारी भारत को सामग्री भेजने में बहुत उत्साहसे भाग ले रहे हैं।

अगस्त १९५६ की भांति इस वर्ष भी भारत के अनेक विशेषज्ञ सिंचाई के बारे में रूसी इंजिनीयरों से परामर्श प्राप्त करने के लिए रूस गये। वहां डेढ़ साल तक प्रशिक्षण केन्द्र चलता रहा।

तरुण भारतीय तैल इंजिनियरों का एक दल सोवियत संघ गया हुआ है। वे सोवियत संघ के तैल क्षेत्रों में प्रौद्योगिक प्रशिक्षा प्राप्त करेंगे।

तरुण तैलकर्मी आजरबाईजान सोवियत समाजवादी जनतंत्र के तैल उद्योग मंत्रालय के अतिथि हैं। वे अजरबाईजान औद्योगिक संस्था के ड्रिलिंग (तैलकूप-खनन) शिक्षण विभाग के प्रधान, प्रोफेसर एस० कुलियेव की देखरेख में बाकू में, जो सोवियत तैल उद्योग का एक केन्द्र है, प्रायोगिक शिक्षा प्राप्त करेंगे।

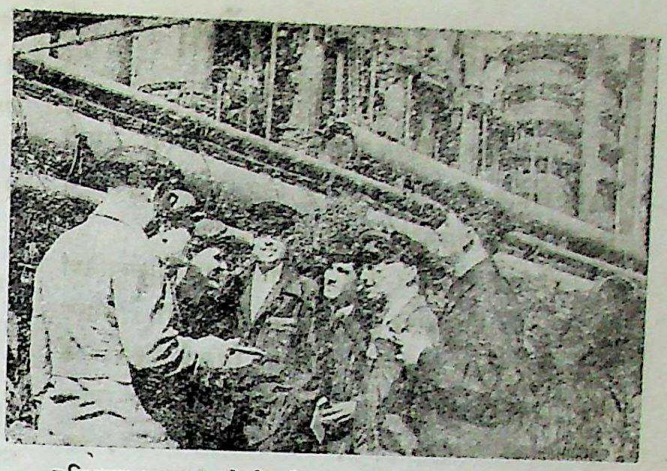

प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भारतीय विशेषज्ञ रूस में

नई दिल्ली २९ जनवरी। सोवियत संघ के भारी मशीन-निर्माण उपमंत्री एन० आई० बाबिच ने जो भारत सरकार के निमंत्रण पर इस समय भारत आये थे, भारत में भारी मशीनें और साज-सामान बनाने के पहले कारखाने के निर्माण के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू तथा भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय को पेश कर दी।

यह कारखाना बन जाने पर भारत लोहा और इस्पात तथा अन्य उद्योगों की मुख्य भारी मशीनें और साज-सामान स्वतंत्र रूप से तैयार कर सकेगा। कारखाना, पेरने और पीसने की मिलों, कोक तथा उपजात वस्तुओं के

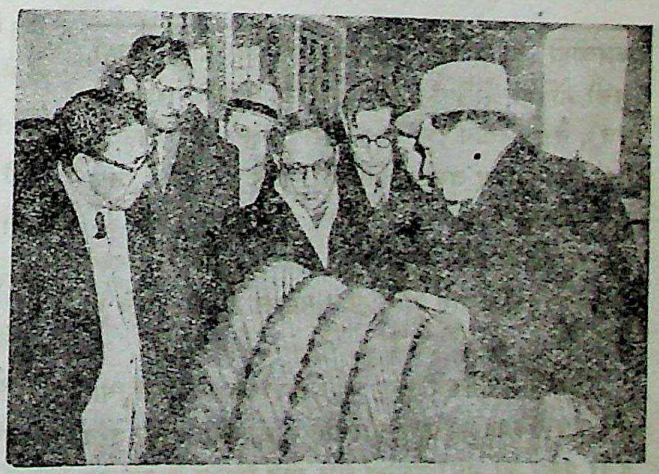

भारतीय विशेषज्ञों को जानकारी देते हुए रूसी इंजीनियर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जहाज राना समझौता

(श्री अ. सवेल्पेव)

भारत और सोवियत संघ के मध्य बाकायदा समुद्री जहाज चलाने की व्यवस्था करने के लिए दोनों सरकारों में दिल्ली में एक समझौता हो गया ।

इस वर्ष सोवियत और भारतीय जहाज कम्पनियाँ ७,००,००० टन माल इधर से उधर ले जायेंगी । भारत को ३,००,००० टन धातुओं के सामान भिलाई कारखाने के लिये, ३०,००० टन साज साज सामान जिसे बनाने में सोवियत सरकार मदद दे रही है, और लगभग २०,००० टन कृषि-औजार एवं अन्य पदार्थ भेजे जायेंगे ।

भारत सोवियत संघ को जूट का सामान, जूते, चाय, तम्बाकू, कृषिजन्य पदार्थ व मसाले वगैरा भेजेगा ।

समुद्री मार्ग से, भारत और सोवियत संघ के बीच ४,५०० मील का फासला है । दोनों देशों के मध्य ६ भारतीय पोत और ६ सोवियत पोत चला करेंगे । इन जहाजों की भार वहन क्षमता कुल १,१०,००० टन होगी ।

भारत में आये हुए जहाज ओदेस्सा, नोवोरोसिस्क तथा अन्य बंदरगाहों पर ठहरा करेंगे । दोनो देश एक दूसरे को विशेष सुविधाएं देंगे ।

सोवियत शिष्ट मंडल में समुद्र सचिवालय और विदेश व्यापार सचिवालय के प्रतिनिधि सम्मिलित थे । इस शिष्ट मंडल को भारत में ऐसा लगा जैसा मानों वे मित्रों के बीच थे । दोनों ओर से बहुत समझदारी और सद्भाव से काम लिया गया । हमारे प्रतिनिधि बड़ी मीठी याद भारत से लौटे हैं । भारतीय नाविकों और डाक कर्मचारियों ने जो विशेष स्वागत किया और जो सोवियत भारत में वृद्धि की कामना की थी, वह उन्हें भूली नहीं है ।

सोवियत विशेषज्ञों की रिपोर्ट ने ढले और गढ़े बनाने के एक विशेष कारखाने के निर्माण के सम्बन्ध भारत सरकार के निर्णय को दृष्टिगत रखा है । यह में रखना चाहिए कि भारी मशीनों के निर्माण के कारखाने को १००-१०० टन वजन के ढले और मढे टुकड़ों साल में कुल १ लाख टन वजन के बराबर जरूरत होगी ।

वह भारत में भारी मशीनों के निर्माण के उद्योग लिए उच्च दक्षता-प्राप्त मजदूर और नेतृस्थानीय कार्यकर्ता तैयार करने की एक बड़ी अच्छी पाठशाला होगी ।

कारखानों की मशीनें और साज-सामान, वायु-भट्टियां, खुली भट्टियां, रोलिंग मिलें, एस्कैवेटर (मिट्टी खोदने के यंत्र), तैल उद्योग के लिए भारी ड्रिलिंग रिंग, खानों के लिए वाइंडिंग इंजन, लोहसार और प्रेस की मशीनें तथा अन्य साज-सामान तैयार करेगा ।

कारखाने की अनुमानित उत्पादन-क्षमता प्रतिवर्ष ८०,००० टन मशीनें और साज-सामान तैयार करने की होगी ।

देश के आर्थिक विस्तार की आवश्यकताओं के अनुसार इस कारखाने की बहुधंधी और शक्तिशाली मशीनों को तुरंत दूसरे प्रकार की भारी मशीनों और साज-सामान के उत्पादन में लगाया जा सकता है ।

रूसी सहायता का उपयोग

नई दिल्ली ३० मई । उद्योग मंत्रालय ने एक प्रश्न उत्तर में बताया कि भारत सरकार, रूस से मिलने वाले करोड़ रूबल के ऋण से ये कार्य करने का विचार कर है । भारी मशीनें बनाने का एक कारखाना, खुदाई की बनाने का कारखाना, कोरबा कोयला क्षेत्रों का विकास नीवेली के भूरे कोयले के कारखाने के लिए एक बिजली घर; ऐनकों के शीशे बनाने का कारखाना और के मेथानोल कारखाने का सुधार । इन कार्यों पर इस खर्च होने का अनुमान है—

भारी मशीनें और खुदाई की मशीनें बनाने के कारखाने ...	२६.५० करोड़
फोरबा कोयला क्षेत्रों का विकास	८ करोड़
नीवेली के लिए बिजली-घर	१६ करोड़
ऐनकों के शीशे का कारखाना	८५ लाख
मेथानौल कारखाने का सुधार	१ करोड़
कुल	५२ करोड़ ३५ लाख

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारत व रूस में परस्पर व्यापार

ब्रिटिश शासन में रूस व भारत में परस्पर व्यापार ब्रिटिश फर्मों की मार्फत होता था, इस कारण पनप नहीं सका। भारत के स्वतंत्र होने के बाद से इस दिशा में एक नये अध्याय का प्रारम्भ हुआ। सबसे पहला बड़ा व्यापारिक समझौता अनाज के सम्बन्ध में हुआ। भारत गम्भीर अन्न संकट में से गुजर रहा था। रूस ने अनाज देने का और भारत ने चाय, जूट तथा अन्य सामग्री देने का वचन दिया। यह समझौते १९४८, १९४९ व १९५१ में हुए। इन्हीं वर्षों में मशीनरी, औजार, अखबारी कागज बेयरिंग और रंग भी रूस से आने लगे। रूसी व्यापार संस्थाओं ने भारतीय व्यापारियों से मसाले, लाख आदि लेने शुरू किये। १९५२ और १९५५ में क्रमशः बम्बई व दिल्ली में होने वाली अन्तर्राष्ट्रीय उद्योग-प्रदर्शनियों में रूस के सम्मिलित होने से दोनों देशों में व्यापार की संभावनाएं बहुत बढ़ गईं।

परस्पर व्यापारिक दिशा में बहुत बड़ा कदम तब उठाया गया, जब २ दिसम्बर ५३ को दोनों देशों में एक व्यापारिक समझौता हुआ। रूसी नेताओं की भारत यात्रा तथा भिलाईके कारखानेके संबन्ध में होने वाले समझौते ने व्यापार को भी प्रगति दी और १९५६ में पहले समझौते को अधिक पुष्ट रूप में दुहराया गया।

दिल्ली में एक समझौते पर दस्तखत हुए, जिसके अंतर्गत सोवियत संघ की सहायता से भिलाई में बन रहे लोहा और इस्पात कारखाने के लिए सोवियत रूस ने ५५,३०,००,००० रूबल के साज-समान उधार देने का जिम्मा लिया है।

यद्यपि भारत और सोवियत संघ के बीच व्यापार का परिमाण अभी तक कुछ बहुत बड़ा नहीं है, तथापि वह प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। १९५५ के वित्तीय वर्ष के पहले १० महीनों में, अर्थात् १ अप्रैल, १९५५ से ३१ जनवरी १९५६ तक, दोनों देशों के बीच व्यापार का परिणाम ६,५४,००,०००० रुपयों के बराबर हुआ, जब कि १९५४ के वित्तीय-वर्ष की उसी अवधि में वह ३,११,००,००० रुपयों के बराबर था। अर्थात् वह दुगुने से अधिक हुआ है। जैसा कि सोवियत के वैदेशिक व्यापार संगठनों के भारतीय फर्मों से इस साल बड़ी संख्या में हुए समझौतों से विदित है, यह परिमाण इस साल और भी बढ़ जायगा। पांच महीनों में (इनमें जनवरी और मई, १९५६ शामिल हैं) सोवियत मालों की बिक्री और भारतीय मालों की खरीद सम्बन्धी समझौतों में २४,५०,००,००० रुपयों का सौदा हुआ है।

भारत रूस व्यापार

(मूल्य लाख रुपयों में)

	आयात	निर्यात
१९५०-५१	२३	१,३७
१९५१-५२	१,३८	६,९२
१९५२-५३	२४	८५
१९५३-५४	६०	१,१५
१९५४-५५	१८१	२,१२
१९५५-५६	६,२१	३,२६
दिसम्बर १९५५-५६	३४	४८
दिसम्बर १९५६-५७	१४०	२,६१
अप्रैल-दिसम्बर १९५५-५६	२१०	१,८७
अप्रैल-दिसम्बर १९५६-५७	१०,८०	११,११

इन समझौतों के अन्तर्गत भारत को ३,१७,००० टन रोल्ड लौह धातु, ४०,००० टन गेहूं, ९०,००० टन सीमेन्ट, १०,००० टन कास्टिक सोडा, ६,००० टन अखबारी कागज, ३०० टन जस्ता, २०० टन अल्युमिनियम, ५० टन रंग तथा अन्य माल बेचे जायंगे। अन्य माल जो

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारत भेजे जायंगे, वे हैं बड़े परिमाण में मशीनें तथा अन्य साज-सामान, तार-रज्जु (केबल), तांबे का तार, रोल्ड अलोह धातुओं के तैयार सामान, सेल्युलोज, नीलिन तेल, बाइसिकिल, कैमरा, सिनेमा-फिल्म, पुस्तकें, आदि।

रुपयों में ही

इस परस्पर व्यापार की एक बड़ी विशेषता यह है कि सोवियत मालों की बिक्री से जो रुपए वसूल होते हैं, सोवियत संघ उनका इस्तेमाल उन कच्चे और तैयार मालों को खरीदने में करता है, जिनका भारत निर्यात करना चाहता है। फलस्वरूप, प्रत्येक नव वर्ष के साथ उन मालों की सूची लम्बी होती जाती है, जिनकी सोवियत के विदेशी व्यापार संगठन भारत में खरीद कर रहे हैं। भारतीय फर्म सोवियत संघ को वे माल निर्यात करते हैं, जिनका भारत सदा निर्यात करता रहा है, जैसे, चमड़ा, आधा कमाया बछड़े का चाम, आधा मोटा ऊन, जूट के रेशों के सामान, चमड़ा, मूंगफली, वनस्पति तेल, मसाले, चाय, काफी, औषधि और गन्धद्रव्य तैयार करने में व्यवहृत तेल, अबरक आदि।

वे तैयार माल भारतीय निर्यात में कम महत्व नहीं रखते, जिनसे उद्योग चालू रहते हैं। जैसे दस्तकारी के सामान, ऊन के कपड़े और चमड़े के जूते। इस वर्ष अभी तक सोवियत संघ के विदेशी व्यापार संगठनों ने ४०,००,००० चमड़ों, १,२८,००,००० मीटर जूट के रेशे के सामानों, २,००० टन मसालों, १००० टन चपड़ा, ५०० टन आधा मोटा ऊन, ५०० टन काजू, ५०० टन काफी तथा कई अन्य मालों की खरीद के समझौतों पर दस्तखत किये हैं। समझौते के अन्तर्गत आने वाले मालों का काफी बड़ा परिमाण एक देश से दूसरे को पहुँचाया जा चुका है। जूतों का भारी आर्डर भी रूस ने भारत को दिया है।

सोवियत संघ द्वारा भेजी मशीनों तथा अन्य साज-सामानों और मालों से भारत को अपने राष्ट्रीय अर्थतंत्र का विकास करने में मदद होती है और सोवियत संघ को भेजे भारतीय मालों से सोवियत उद्योग को कच्चा माल प्राप्त करने और जनता को अधिक सामान दे सकने में मदद होती है, जिससे कि छठी पंचवर्षीय योजना की पूर्ति में जिस पर सोवियत जनता अब अपने प्रयत्न केन्द्रित कर रही है, योगदान होता है।

रूस व भारत में परस्पर व्यापार को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों देशों में परस्पर जहाजरानी की अच्छी व्यवस्था हो। इस दृष्टि से दोनों देशों में जहाजी यातायात के लिए एक समझौता भी अप्रैल १९५६ में किया गया। यह समझौता पाठक अन्यत्र पढ़ेंगे। इसके अनुसार रूस व भारत के जहाजों को एक दूसरे देश के बन्दरगाहों पर सब तरह की सुविधा दी जायगी।

यह आशा करनी चाहिए कि आगामी कुछ वर्षों में भारत और रूस का पारस्परिक व्यापार शीघ्र ही अन्य देशों की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ जाएगा तथा दोनों देश एक दूसरे की आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सहायक होंगे।

पारस्परिक लाभकर व्यापार

— लेखक —
वी० स्पांदार्यान

सोवियत-भारत व्यापार सम्बन्धों का विकास, मेरी राय में, परस्पर लाभकर व्यापार का, मालों की दो-तरफा चलन का, जो दोनों के लिए बहुत आवश्यक है, एक नमूना है।

सोवियत संघ भारत को जो माल भेज रहा है, उसके बारे में लोगों को काफी जानकारी है। उदाहरण के लिए भिलाई में सोवियत संघ की मदद से बन रहे लोहे और इस्पात कारखाने के लिए भेजे जाने वाले सोवियत साज-सामान और सामग्रियों के बारे में, सोवियत संघ द्वारा भारतीय अर्थतंत्र के विकास के लिए आवश्यक रोल्ड स्टाक, साज-सामान, मशीनें तथा औद्योगिक साज-सामान भेजने के बारे में बहुत-से लोग जानते हैं।

सोवियत संघ भारत को उसके हितों के अनुरूप सोवियत माल खरीदने तथा सोवियत के प्राविधिक अनुभव का अध्ययन करने के व्यापक मैत्रीपूर्ण अवसर प्रदान करता

[सम्पादा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

है। इसके बावजूद वह भारत के ऊपर अपने माल या सेवाएं लादता नहीं।

ए० आई० मिकोयान ने मार्च १९५६ में दिल्ली में कहा था, "सोवियत संघ भारत को ऐसे माल नहीं बेचना चाहता, जिन्हें भारत पर्याप्त परिमाण में स्वयं तैयार करता है, क्योंकि हम उसके उद्योग और कृषि के साथ प्रतियोगिता नहीं करना चाहते। इसके विपरीत, हम भारत को ऐसे माल देते हैं जिनसे भारतीय अर्थतंत्र को विकसित करने में सहायता प्राप्त होगी।"

भारत को सोवियत के निर्यात की यही स्थिति है। अब देखना चाहिए कि भारत से सोवियत संघ को मालों का चालान किस प्रकार हो रहा है।

भारत से सोवियत संघ भेजे जाने वाले मालों की विविधता में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। जहां अभी बिल्कुल हाल तक—सोवियत-भारत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होने के पहले तक, सोवियत संघ भारत से केवल थोड़ी मादा में मसाले और लाख खरीदता था, वहां आज सोवियत के वैदेशिक व्यापार संगठन भारत, से परम्परागत रूप में बाहर भेजे जाने वाले कई सामानों का बड़े पैमाने पर आयात कर रहे हैं। १९५६ के दस महीनों में मसालों और लाख के अतिरिक्त, २,००,००,००० मीटर से अधिक टाट और १,५०,००,००० बोरे, लगभग ४,००० टन चाय तथा, ४० लाख से अधिक कच्चे चमड़े के छोटे-छोटे सामान खरीदे गये। सोवियत संगठनों ने इस साल भारत से बहुत-सा तम्बाकू, कहवा और काजू आदि भी खरीदा है।

सोवियत रूस संघ कच्चे मालों का आयात करने के अतिरिक्त कुछ औद्योगिक माल भी खास कर ऊनी कपड़े और जूते मंगा रहा है। सोवियत संघ में भारतीय हस्त-शिल्प प्रदर्शनी की बहुत बड़ी सफलता के बाद सोवियत वैदेशिक व्यापार संगठन भारत में चांदी और हाथी दांत आदि के बने भांति-भांति के हस्तशिल्प के सामान और सुन्दर काश्मीरी दुशाले खरीद रहे हैं।

एक-दूसरे के देशों की यात्रा करना, प्रदर्शनियों का आयोजन करना, मांगों का आद्यन्त अध्ययन करना—इन साधनों द्वारा सोवियत वैदेशिक संगठनों और भारतीय व्यावसायिक मंडलों के प्रतिनिधियों के सम्पर्क में और विस्तार होने से, निस्संदिग्ध रूप में, एक दूसरे के यहां भेजे जाने वाले मालों की मात्रा और विविधता में वृद्धि होगी।

सोवियत पक्ष की ओर से रुपयों में हिसाब का चुकता लेने की सहमति तथा एक नियमित सोवियत-भारतीय जहाज-लाइन हो जाने से सोवियत संघ और भारत के बीच के व्यापार के विकास में सहायता मिलेगी। एक महत्वपूर्ण परिस्थिति जिससे परस्पर लाभकर भारत-सोवियत व्यापार के विकास में सहायता होती है, दोनों देशों द्वारा, एक-दूसरे को बराबर-बराबर मूल्य के सामान भेजने के आधार पर, संतुलित व्यापार रखने का प्रयास है। ए० आई० मिकोयान की भारत यात्रा के समय इस आकांक्षा की एक बार फिर परिपुष्टि हुई, जब उन्होंने कहा :

"सोवियत संघ भारत के साथ अपने व्यापार में भारत की व्यापार और भुगतान की तुला पर भार नहीं डालना चाहता; इसलिए हम भारत में सोवियत मालों की बिक्री से प्राप्त रकमों को भारत के कच्चे और तैयार मालों की खरीद के लिए इस्तेमाल करने को तैयार हैं।"

प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार १९५६ में सोवियत संघ और भारत के बीच ३०,००,००,००० रुपए मूल्य से कम की क्रय-वस्तुएं नहीं आयीं या गयीं। यह कोई बड़ी रकम नहीं है। पर यहाँ यह उल्लेख कर देना चाहिए कि १९५३ में, व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होने से पहले, सोवियत-भारत व्यापार की कुल मात्रा केवल एक करोड़ रुपए के लगभग थी।

★

रूस के साथ व्यापार

१९५६-५७ के पहले नौ महीनों में भारत से कुल १० करोड़ ९५ लाख रु० का माल रूस को भेजा गया और इसी अवधि में १० करोड़ ८० लाख रु० का माल रूस से भारत आया।

—भारत, रूस से, तेल के कुए खोदने के ३७ लाख २४ हजार रु० के यन्त्र खरीदेगा। रूस सरकार ये यन्त्र ६ महीने के भीतर भेज देगी।

——

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शिल्पिक प्रशिक्षण

रूस ने विभिन्न देशों को शिल्पिक सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को १८१ लाख रूबल देने का निर्णय किया था। इस राशि का अधिकाँश भारत को शिल्पिक सहायता के रूप में मिल रहा है। १९५६ के अन्त तक इस राशि में भारत को २० लाख रूबल की मशीनरी तथा औजार मिल चुके हैं। यह मशीनरी लोहे को काटने वाली लेथ, आटोमोबाइल, हिल कम्यूटर, तथा छापने वाली मशीनों के रूप में है। इन्स्टीट्यूट आफ स्टैटिस्टिक्स के लिए बिजली से चलने और हिसाब करने वाली मशीनें भी दी जा रही हैं। जन्म निरोध केन्द्र के लिए भी एक हस्पताल का सारा सामान रूस दे रहा है। मातृ-शिशु कल्याण की दिशा में भी रूस की सहायता प्राप्त हो रही है। अनेक रूसी विशेषज्ञ भारत में आकर भारतीयों को शिल्पिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।

बम्बई में एक शिल्पिक संस्था स्थापित करने का काम भी इसी निधि के अन्तर्गत हो रहा है। इस संस्था के लिए १ करोड़ रूबल की प्रयोगशाला तथा अन्य आवश्यक सामग्री रूस भारत को देगा। १५ रूसी प्रोफैसर तथा पाठ्य पुस्तकों के अनुवाद के लिए तीन अनुवादक ५ सालों के लिए भारत भेजे जा रहे हैं, जो इस संस्था में प्रशिक्षण तथा शोध कार्य करेंगे। १२ भारतीय विशेषज्ञ रूस जाकर भी शिक्षा प्राप्त करेंगे। बम्बई की यह संस्था विशालतम योजना होगी, जो सं० राष्ट्र संघ इस दिशा में दे रहा है। १९५२ से १९५५ तक सं० रा० संघ ने जितनी शिल्पिक सहायता दी है, यह सहायता उन सबसे बड़ी है। ५५ भारतीय विद्यार्थियों को (११ प्रतिवर्ष) रूस में उच्च शिक्षा व प्रशिक्षण के लिए रूस छात्रवृत्ति दे रहा है।

भारत सरकार की इच्छा के अनुसार १६ भारतीय तैल शोधन कार्य की शिक्षा प्राप्त करने के लिए रूस के खर्च पर रूसी कारखानों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गये हैं। एक द्विदैशिक समझौते के अनुसार ५० भारतीय इंजीनियर रूस में लोहे के संयन्त्रों का अनुभव प्राप्त करने को गये हैं।

जुलाई १९५६ में ४ भारतीय इंजीनियर बिजली-कारखानों का अनुभव प्राप्त करने के लिए रूस गये।

(पृष्ठ ६३० का शेष)

हलों व बैलों से खेती नहीं होती। वहां कृषि भी आज के अर्थों में भारी उद्योग है। यांत्रिक कृषि के लिए वहां १५-१५ हार्स पावर के १६,५०,००० ट्रेक्टर इन पांच वर्षों में खेतों के लिए तैयार किये जावेंगे।

इतनी विशाल योजनाओं के लिए विपुल राशि की जरूरत है और ९,९०,००,००,००,००० रूबल राशि नियत की गई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना से यह राशि १८ गुना है। इतनी बड़ी योजना के उद्देश्य भी तो बहुत बड़े होने चाहिए। राष्ट्रीय आय ६० प्रतिशत तक बढ़नी चाहिए, मजदूरों व कारागरों के वेतन ३० प्रतिशत तक बढ़ाने का विचार है और सामूहिक खेतों की आय ४० प्रतिशत। मजदूरों के लिए काम के घण्टे भी ८ से ७ तक कर देने का उद्देश्य सामने रखा गया है।

औद्योगिक विकास की इन योजनाओं का परिणाम जहां रूस के नागरिकों के ऊंचे जीवन स्तर के रूप में प्रकट होगा, वहां विदेशी व्यापार की दृष्टि से भी बहुत लाभप्रद होगा। वह विभिन्न देशों और भारत को अधिकाधिक यंत्र व मशीनरी भेज सकेगा। १९५६ में उसका विदेशी व्यापार १९५५ की अपेक्षा दुगना था। अमेरिका के बाद संसार में उसी का स्थान है। लोह उद्योग की विशाल संभावनाएं विद्यमान हैं। पूर्वी रूस व साइबेरिया में नई खानें निकलती जा रही हैं और बड़े-बड़े लोहे के कारखाने खुल रहे हैं।

उत्पादन लाख टन

	लोहा	तेल
१९१३	२९	९१
१९४०	१६००	३१०
१९५०	२५००	३७८
१९५६	३९००	७००
१९६० (योजना)	५९३०	१३५०

छठी पंचवर्षीय योजना में रूस में बिजली का जाल फैल जायगा। साइबीरिया की शक्तिशाली नदियों का प्रयोग इस योजना में विद्युत उत्पादन के लिए किया जा रहा है। अंगारा नदी पर ३२ लाख किलोवाट का संसार में सबसे बड़ा बिजली घर बन रहा है। १९५४ में रूसने अणुशक्ति से चालित बिजली का पावर-स्टेशन बनाकर संसार में नया उदाहरण उपस्थित किया था।

[समाप्त

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वोल्गा पर भीमकाय विद्युत-शक्ति-गृह

(श्री एन. फिनिकोव)

रूसके विद्युतीकरण का विचार श्री वी०आई० लेनिन ने किया था। १९२० से इनके अनुसार कार्य आरम्भ हुआ। आगामी १०-१५ वर्षों में ३० शक्ति-गृह, जिनकी क्षमता १५ लाख किलोवाट थी, तैयार कर लिये गये। इस योजना में २०० प्रतिशत (लक्ष्य से भी अधिक) सफलता मिली।

एक वर्ष एक दिन

इस समय रूस, एक दिन में, १९२० के सारे वर्ष की अपेक्षा अधिक विद्युत-शक्ति का उत्पादन कर रहा है। याने अब एक वर्ष एक-दिन के बराबर हो गया है।

नये बिजली घरों में से, जिन्होंने युद्धोत्तर काल में कार्य करना आरम्भ किया है या भविष्य में करना है, सब से प्रथम स्थान क्विबिशिव (Kuibyshew) जल-विद्युत-गृह का है। यह दुनिया के बड़े बिजली घरों में से एक है। इस समय इसकी २० में से १२ इकाइयां ही कार्य-कर रही हैं, जिनकी कुल क्षमता १२,५०,००० किलोवाट है। क्विबिशिव विद्युत गृह की पूर्ण क्षमता २१ लाख किलोवाट होगी।

निर्माण चालू ही रहता है

क्विबिशिव जल-विद्युत-गृह का निर्माण कार्य, दिन और रात में, आंधी-तूफान में चलता ही रहता है। मजदूरों ने १८०० लाख क्यूबिक मीटर मिट्टी खोद निकाली है; ७० लाख क्यूबिक कंकरीट आदि बिछा ली है और ५० लाख टन इस्पात आदि निर्माण के लिये इकट्ठा कर लिया है।

इसी प्रकार १० हजार मशीनें और विभिन्न प्रकार की यंत्र सामग्रियां निर्माण-कार्य के लिये प्रयुक्त की जा रही हैं। इस क्षेत्र में रेल की पटरियों और सड़कों की लम्बाई क्रमशः ४०० और ३०० और किलोमीटर है।

इस विद्युत योजना में, इंजीनियर, फोरमैन और मजदूर सभी अपने कार्य में कुशल हैं। इसमें ५० हजार से

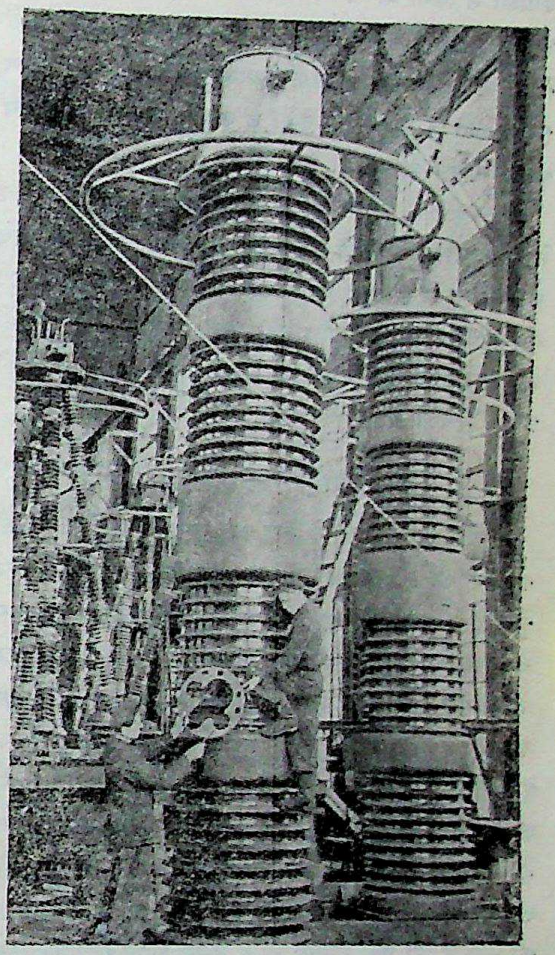

विद्युत-गृह का एक दृश्य

भी ऊपर निपुण व्यक्ति मोटर ड्राइवर, मशीन चालक, विद्युत शिल्पी, इंजिन चालक, कंकरीट बनाने वाले, ट्रेन पर काम करने वाले आदि के रूप में कार्य कर रहे हैं। क्विबिशिव औद्योगिक संस्थान ने, यहां पर ३ शाखाओं की स्थापना इस ध्येय से की है कि विद्यार्थी अपनी योग्यता बढ़ा सकें। यहां रात्रिकालीन ३ विशिष्ट माध्यमिक स्कूल भी चल रहे हैं।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारत व रूस के पारस्परिक संबंध

(पृष्ठ ६२६ का शेष)

बंगाली में किया था । करमजिर ने शकुन्तला नाटक का और जकोवस्की ने नल दमयन्ती का अनुवाद रूसी भाषा में किया था । अंग्रेजी शासन की स्थापना और मुस्लिम शासन समाप्त होने के बाद दोनों देशों में पारस्परिक सम्बन्ध करीब करीब समाप्त हो गये ।

१८५७ के स्वातन्त्र्य युद्ध के समीप ही नाना साहिब ने सेवेस्टोल के किले को देखा था । यह समय था, जब रूस भारत से सम्बन्ध बढ़ाने की योजनाएं बना रहा था । वोल्गा और दोन के बीच नहर निकालकर भारत जाने का जलमार्ग बनाने का विचार भी किया गया, किंतु ब्रिटेन की सतर्क दृष्टि से यह संभव न हो सका ।

ब्रिटिश काल में

अंग्रेजों ने भारत से रूस का सम्बन्ध प्रायः तोड़ने की कोशिश की । इसके कारण का हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं । यद्यपि महान बोलशोबिक क्रान्ति के बाद रूस ने साम्राज्यवादी वृत्ति के त्याग की घोषणा कर दी थी, फिर भी अंग्रेज राजनीतिज्ञ रूस से बहुत चौकन्ने रहे । रूसी जार की अपेक्षा भी साम्यवाद ज्यादा खतरनाक था । एक अंग्रेज ऐतिहासिक के शब्दों में "रूसी भालू जार की टोपी हो या लाल टोपी पीले सागर में स्नान करने के लिये सदा उत्सुक है । रूस और भारत के परस्पर सम्बन्ध न बढ़ने का एक और कारण भी था कि साम्यवादी रूस आर्थिक दृष्टि से संसार को कुछ दे भी नहीं सकता था । उसने अपने विभिन्न राजनीतिक कारणों से भी अपने दरवाजे बिल्कुल बन्द कर दिये थे और पश्चिमी देशों के कथनानुसार लोहे की दीवारों में अपने को बन्द कर दिया था ।

किंतु रूसी नेता अपने साम्राज्यवाद विरोधी आदर्श तथा संभवतः ब्रिटेन से विरोध के कारण भारतीय स्वाधीनता संग्राम का समर्थन कर रहे थे । महान् लेनिन ने भारत पर ब्रिटिश शासन को भारी लूट बताते हुए लोकमान्य तिलक को दी गई सजा की निन्दा की थी । १९२३ में लेनिन ने रूस-भारत-चीन मैत्री का वह महान् स्वप्न लिया था, जो आज पूर्ण हो गया है । श्री मानवेन्द्रनाथ राय का साम्यवादी क्रांति में सहयोग रहा है । इस सदी के तीसरे दशक में श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर, श्री मोतीलाल नेहरू व पं० जवाहरलाल नेहरू की रूस यात्रा का भी महत्व रहा है ।

और आज

भारत की स्वाधीनता प्राप्ति के बाद उक्त दोनों कारण नहीं रहे । भारत की विदेशी नीति अब स्वतंत्र थी, अंग्रेजों के हितों से बंधी हुई नहीं थी । भारत को जहां रूस की मित्रता अभीष्ट थी, वहां रूस को भी भारत का अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में सहयोग चाहिये था । अमेरिका और ब्रिटेन के साथ भारत अपने को न बांध ले, रूस के हित के लिये यह आवश्यक था। उधर अमेरिका और ब्रिटेन पाकिस्तान को हमेशा साथ दे रहे हैं, इससे भी भारत की जनता में उनके विरोधी रूस से सहानुभूति स्वभावतः बहुत बढ़ गई । इस राजनैतिक कारण के अलावा दोनों देशों की आर्थिक आवश्यकतायें भी एक दूसरे के निकट दोनों को ले आयीं । रूस अपने भारी मशीनरी के उद्योग को विकसित कर चुका है और अब वह उसे निर्यात करने की स्थिति में है । दूसरी ओर भारत को अपनी पंचवर्षीय योजना की पूर्ति के लिए भारी मशीनरी की आवश्यकता है । भारत रूस को उपभोक्ता सामग्री दे सकता है, जिसकी रूस को बहुत आवश्यकता है । इन पारस्परिक आवश्यकताओं के कारण रूस और भारत का सम्बन्ध इन कुछ वर्षों में निरन्तर बढ़ता जा रहा है । यह सम्बन्ध व्यापारिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों में बढ़ा है । आर्थिक दृष्टि से यह सम्बन्ध कितनी बहुमुखी और व्यापक हो रहा है, इसकी चर्चा सम्पदा के पाठक अन्य पृष्ठों में पढ़ेंगे । हमारा यह विश्वास है कि दोनों देशों की आवश्यकतायें और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियां इस सम्बन्ध को घनिष्ट से घनिष्टतर बनाती जायेंगी और यदि आकस्मिक घटनाओं ने कोई परिवर्तन नहीं कर दिया तो "हिन्दी रूसी भाई-भाई" का नारा विश्व इतिहास में स्मरणीय बन जायगा ।

—

—रूस में भारतीय दूतावास के सेकेण्ड सेक्रेटरी (व्यापारिक), नं० ६ और ८, क्लित्सा ओबूखा, मास्को । तार का पताः—इण्डेम्बेसी (INDEMBASSY) मास्को ।

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारत व रूस के तुलनात्मक अंक❀

खाद्य व व्यापारिक फसलों का प्रति व्यक्ति उत्पादन (किलोग्राम)

वर्ष	रूस	भारत
१९२९	४६९	
१९३३	५६५ (४६३)	
१९३७	७२५ (५९५)	१९१
१९३९	५९७ (४७८)	१८६
१९५०	६१७ (४९४)	१६७
१९५२	६२७ (५०२)	१४८
१९५५	८२५ (६६०)	

टैलिफोन (जनवरी १९५१)

	संख्या	प्रति १०० जनसंख्या
रूस	१५,०००००	०.७
भारत	१,६८,३९७	०.१ से भी कम
सं० रा० अमरीका	४,३०,०३,८३२	२८.१
ग्रेट ब्रिटेन	५४,३३,६१४	१०.७
पाकिस्तान	१८,७७१	०.१ से भी कम

प्रति व्यक्ति की पेट्रोलियम मांग

स्थानीय मांग (लाख बैंटल में) जनसंख्या (लाखों में)

देश	स्थानीय मांग	जनसंख्या	बैरल प्रति व्यक्ति मांग
भारत व पाकिस्तान	३९८	४४३०	.०९
रूस	३४७०	२०११	१.७
ब्रिटेन	१६०१	५०८	३.२
सं० राज्य अमेरिका	२६६५०१	५७०	१७.०

औद्योगिक उत्पादन

	रूस	भारत (१९५४)
कोयला और लिगनाइट (लाख टनों में)	१६६०	३७०
क्रूड आयल ,,	३१०	—
बिजली (किलोवाट बिलियन में)	४८	७.५
क्रूड स्टील (लाख टनों में)	१८०	१८
सीमैन्ट (दस लाख टन)	५८	४४
रूई (लाख टन मीटरों में)	३०८३६	६००००
कागज (हजार टनों में)	८१२	१५६
साईकल (हजारों में)	२७०	३७२
सिंचाई की मशीनें (हजारों में)	१७०	८०
कपड़े (लाख मीटर)	३८३६०	६०,०००

(१ मीटर = ३। फुट करीब)

तेल-उत्पादन

रूस	तेल तल क्षेत्र	उत्पादन
सारे संसार में	१ करोड़ वर्ग मील	७००,०००,००० टन
रूस में	३० लाख ,, ,,	६०,०००,००० ,,
सं० अमरीका	१० ,, ,, ,,	३५०,०००,००० ,,
शेष	६० ,, ,, ,,	२९०,०००,०००

रूस की राष्ट्रीय आय और विनियोजन

(गत वर्ष = १००)

१९५१	११२	११२
१९५२	१११	१११
१९५३	१०८	१०४
१९५४	१११	१०५

❀ ये अंक ईस्टर्न इकानामिस्ट के दिसम्बर ५५ विशेषांक से लिये गये हैं ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ग्रामदान और भारत की भूमि-समस्या

—श्री हर्षदेव मालवीय

समस्या का हल नहीं हुआ

इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारत की भूमि समस्या अभी तक हल नहीं हुई है। अभी तक जो कुछ हुआ है, उसके लिए हद से हद इतना ही कहा जा सकता है कि समस्या के हल की ओर दो-तीन कदम बढ़े हैं। भूख और नंगापन अब भी हमारे देश में व्यापक है। हमारे मानवों का जीवन-स्तर अभी भी अकथनीय निम्न कोटि का है। हमारे भूमि-सुधारों ने जमींदारी, मालगुजारी, जागीरदारी जैसी कुछ मध्यस्थ प्रथाओं को खत्म किया, पर यह काम भी अभी तक कई जगह पर नहीं हुआ है। निश्चय ही इन मध्यस्थों के उन्मूलन से हमारे कृषकों को अब हरी, बेगार, नजराना, मोटराना आदि तरह तरह की पैशाचिक वसूलयाबियों को नहीं देना पड़ता। यह कुल रकम क्या होती थी, इसकी तो कभी गणना भी नहीं हुई, पर यह निश्चय है कि यह रकम अरबों रु० के बराबर हुआ करती थी। यह छूट तो हमारे किसानों को मिली, पर उसके बाद बाकी सब ही बातें पुरानी ही हैं। निश्चय ही कभी किसी ने यह नहीं कहा कि जमींदारी उन्मूलन के साथ ही हमारी भूमि समस्या हल हो जायगी। इसके विपरीत, यह सदा कहा गया है कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन केवल हमारे भूमि सुधारों को पूरा करने के लिए दरवाजा ही खोलता है पर स्वयं हमारे पेचीदा भूमि प्रश्न का हल नहीं है।

वास्तव में, भारत की भमि समस्या का हल किसी और तरफ है। विनोबा जी यही तो कहते रहते हैं कि भारत की भूमि समस्या का हल भूमि का पुनर्वितरण है, और कुछ नहीं। सच में, भूमि प्रश्न पर विनोबा का दृष्टिकोण बहुत ही वामपक्षी है। वह तो भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व भी स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि हवा और जल के समान भूमि भी भगवान द्वारा दी गई चीज है और जिस प्रकार जल और वायु पर किसी का स्वामित्व नहीं हो सकता, उसी प्रकार भूमि पर भी किसी का स्वामित्व नहीं हो सकता।

उच्चतम सीमा निर्धारित करने की कहानी

भले ही हमारी सरकारें इतने उग्र दृष्टिकोण की हों, पर इसमें कोई सन्देह नहीं कि वे भूमि के पुनर्वितरण के विरुद्ध नहीं रही हैं और इस कार्य को आराजियों की उच्चतम सीमा निर्धारित कर पूरा करने का उनका विचार रहा है। पर फिर कहना पड़ेगा कि आराजियों की उच्चतम सीमा निर्धारित करने की यह कथा बड़ी लम्बी और दुखद हो गई है।

भूस्वामियों ने नातेदारों में जमीन बांट दी

इस बात को कहना पड़ेगा कि जो कुछ अब तक हुआ है, वह इन घोषणाओं से बहुत काफी पीछे है और आराजियों को उच्चतम सीमा निर्धारित करने में यह ६-७ साल की देर कर दी गई, उसका नतीजा यह हुआ कि भूस्वामियों ने इस काल में अनेकों कार्यवाहियां कर अपनी जायदाद को अपने नातेदारों, रिश्तेदारों में इस तरह से बांट दिया है कि अब यह अनुमान लगाया जाता है कि आराजियों की उच्चतम सीमा कल को लगा भी दी जाय, तो उसके बाद पुनर्वितरण के लिए जो भूमि प्राप्त होगी, वह लगभग नगण्य होगी।

हमने अपने से अनेक बार प्रश्न किया है कि आखिर यह देर क्यों होती है? सम्भवतः इस नीति को पूरा करने का निश्चित दायित्व जिन लोगों पर है, उनमें सब ही इसकी आवश्यकता को नहीं महसूस करते। लालफीतावादी सरकारी मशीनरी की ढील, कमेटियों के दौरान से गुजरने की आदत, लम्बी-लम्बी फाइलों और उन पर लम्बे लम्बे नोटों की परम्परा है। फिर यह भी सही है कि लम्बी चौड़ी संख्या की जांचों के चक्कर में काफी लम्बा वक्त गुजर जाता रहा है।

भूमि-पुनर्वितरण अनिवार्य

जो भी हो, असलियत तो यही है कि भारत में अब तक भूमि का पुनर्वितरण नहीं हुआ है और भारत

[सम्पू

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भूमि-प्रश्न अब तक हल नहीं हुआ है। हमारे आयोजन की सफलता में और तत्सम्बन्धी अन्य मामलों के लिए यह ही सबसे बड़ी रुकावट है। हमारा मनुष्य श्रम ही सबसे बड़ी सम्पदा है। पर जब तक यह मनुष्य-श्रम उत्साहित नहीं किया जाता और उसको उत्साहित कर जब तक राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के कार्यों में उसके कोटि-कोटि हाथों का बल नहीं लगता, तब तक हमारी सफलता कैसे संभव हो सकती है? देश में हम समाजवादी समाज की स्थापना तब तक नहीं कर सकते, जब तक कि हमारी कृषि का भी समाजीकरण न हो। पर जब तक भूमि के स्वामित्व में गहरी विषमताएं मौजूद हैं, तब तक कैसे कृषि-उत्पादक सहकारी समितियों का निर्माण हो सकता है?

ग्रामदान : भारत की भूमि-समस्याका हल

यहां पर विनोबा जी ने एक नई रोशनी डाली है। सच में, विनोबाजी के विचारों का, उनके व्यक्तित्व के समान ही गत वर्षों में उत्तरोत्तर विकास ही होता चला आया है। और कहा जा सकता है कि ग्रामदान की उनकी कल्पना है क्या? इसका अर्थ इसके अलावा और कुछ नहीं कि सारा ग्राम एक परिवार के तुल्य है और यह कि ग्राम का भूमि पर सम्पूर्ण ग्रामीण समुदाय का स्वामित्व है, व्यक्ति का नहीं। और इसी लिए उसी पर काम भी सम्पूर्ण ग्रामीण समुदाय को एक परिवार के समान करना चाहिए। यह बड़ा ही क्रांतिकारी विचार है और इस विचार का तात्पर्य सम्पूर्ण भारतीय समाज में मौलिक परिवर्तन लाना है। पर साथ ही इस महान् परिवर्तन को लाने के लिए जो तरीके अपनाये जा रहे हैं, वे मूलतः अपने भारतीय हैं, अपनी भारतीय परम्परा के अनुरूप हैं, और उनके अन्दर वैसी कोई बात नहीं है जो कम्युनिस्ट किस्म के समाजवादी-निर्माण को बहुत से विचारशील पुरुषों की दृष्टि में अवांछनीय बना देते हैं।

विनोबाजी आजकल केरल प्रदेश में हैं। आगामी कुछ मास केरल प्रदेश में घूमने का विचार रखते हैं। वहां यदि उनको राज्य से सहायता प्राप्त हुई और कम्युनिस्ट संगठन ने भी उनके साथ सहयोग किया कांग्रेस का उनमें सम्पूर्ण विश्वास तो है ही, तो क्या मालूम वे केरल में वह प्राप्त करके दिखला दें, जिसकी तलाश में वे इतने दिनों से सारे भारत का भ्रमण कर रहे हैं। और अगर विनोबा ने केरल में भूमि समस्या को भूमि पुनर्वितरण के कार्यक्रम द्वारा और ग्रामदान की कल्पना के द्वारा सफल बना दिया तो निश्चय मानिये, वैसा ही फिर सारे भारत में कल होना होगा।

सम्पदा के कुछ एजेण्ट

रांची में

क्राउन बुक डिपो।

जोधपुर में

मैसर्स द्वारकादास राठी, बुकसैलर्स।

नयापथ

(प्रगतिशील मासिक पत्रिका)

सम्पादक—

यशपाल ❀ शिव वर्मा ❀ राजीव सक्सेना

स्तम्भ—

- चक्कर क्लब
- साहित्य समीक्षा
- संस्कृति प्रवाह
- सिनेमा
- लेख
- कहानियां
- कविताएं।

"नयापथ" का जनवरी अंक 'लोक साहित्य' विशेषांक है। इसका सम्पादन हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक श्री श्रीकृष्णदास कर रहे हैं। ग्राहकों को यह अङ्क साधारण मूल्य में ही दिया जाएगा।

वार्षिक ६) एक प्रति ॥)

पता :—

२२ कैसर बाग लखनऊ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अर्थ वृत्त चयन

कम्युनिस्ट व नये कर

कुछ दिन पूर्व चौधरी श्री ब्रह्मप्रकाश ने एक भाषण देते हुये नये करों का समर्थन किया है। उनकी युक्तियों का हम यहां न विरोध करना चाहते हैं, न समर्थन, किन्तु उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा किये गये विरोध का अच्छा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि संसार के कई देशों में कम्युनिस्ट पार्टी सरकार चलाती है। इसलिये उस पार्टी से आशा करनी चाहिये कि कम से कम उन देशों के अनुकरण से लाभ उठाये। रूस ने अपनी विकासयोजना की पूर्ति के लिए जनता से असाधारण त्याग की अपेक्षा की है, यह कौन नहीं जानता। आज भी रूस में पदार्थ बहुत महंगे हैं। दो आने की एक पेन्सिल ढाई तीन रुपये में मिलती है। एक कमीज सौ रुपये से कम नहीं मिलती। एक जूता तीन चार सौ रुपये में मिलता है। एक चेस्टर ढाई हजार रुपये में मिलता है। जब रूस में आज भी जनता को भारी त्याग करना पड़ रहा है, उसके सिद्धान्तों पर चलने वाली कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय जनता पर लगाये गये करों का विरोध किस तरह कर सकती है? यदि देश का निर्माण करने में रूस की जनता ने अत्यधिक त्याग किया है, तो भारत की जनता से अधिक त्याग की आशा न करने के लिए कहना कैसे उचित है?

★

भारत के कपास का उत्पादन लक्ष्य

(जिन तक १९६०-६१ तक पहुंचना होगा)

	क्षेत्रफल (००० एकड़)	उपज (००० गठरियां)
बम्बई	४,५००	१,२५०
मध्यप्रदेश	३,७५०	७८०
मद्रास	१,१७४	५५७
आन्ध्र	९८६	३२५
पंजाब	९९०	५२६
हैदराबाद	३,५००	५५०
मध्यभारत	१,७०००	३८०
मैसूर	४७०	१२५
पेप्सू	४९६	३४४
राजस्थान	९००	३०१
सौराष्ट्र	२,३००	२६०
उत्तरप्रदेश	३४०	१०६
भोपाल	१००	१५
उड़ीसा	५०	१०
अन्य प्रान्त	१६०	४९
कुल	२०,४१६	५,५८६

ये लक्ष्य "प्लानिंग कमिशन" के विचार के अन्तर्गत हैं। ६० लाख रुपये इन लक्ष्यों को कार्य रूप में परिणत करने के लिये स्वीकृत किये गये हैं।

★

ब्रिटेन में जुए पर भारी खर्च

ब्रिटिश जनता ने गतवर्ष ५००० लाख पौण्ड अर्थात् ७५८ करोड़ रु० जुए पर खर्च कर दिये। इसमें ८९४० लाख पौण्ड की भारी रकम शामिल नहीं है, जो शराब पर खर्च हुई और न वह ९३५० लाख पौण्ड की रकम शामिल है, जो सिगरेट या तम्बाखू पर खर्च हुई। यह सब रकम मिलाकर ३२३४ करोड़ रु० के बराबर होती है। इन रकमों की गंभीरता इससे प्रकट होती है कि ब्रिटिश जनता ने भोजन पर जितना कुल व्यय किया, उसका ५५ प्रतिशत ये रकमें हैं।

जुए का बिल २०० रु० प्रति व्यक्ति (१७ वर्ष से ऊपर) औसतन पड़ता है। ब्रिटिश सरकारका समस्त देश में स्वास्थ्य-सेवाओं पर जितना व्यय एक वर्ष में पड़ता है, यह रकम उससे भी १० प्रतिशत अधिक है। एक अनुमान के अनुसार यह रकम समस्त ब्रिटिश परिवारों के ईंधन व रोशनी के कुल व्यय के बराबर है और समस्त देश के मकानों के निर्माण व व्यवस्था पर व्यय की जाने वाली विपुल राशि से केवल १० प्रतिशत कम है।

घुड़दौड़ के जुए पर, जिसमें सामान्य नागरिक से लेकर राज परिवार तक सम्मिलित है, ३५०० लाख पौण्ड व्यय किया जाता है। इसके बाद कुत्तों की दौड़ का नम्बर है, जिसके जुए पर १२१० लाख पौण्ड प्रतिवर्ष खर्च होता है।

[सम्पादक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

यहां तक कि फुटबाल की खेलों पर भी जुआ होता है लेकिन इसमें सम्पन्न वर्ग नहीं खेलता, फिर भी लोगों का इस जुए पर ७१० लाख पौण्ड खर्च हो जाता है। आयरिश स्वीपस्टेक की लाटरी पर १२० लाख पौण्ड से कम खर्च नहीं होता। छोटे मोटे खेल तमाशे भी जुए के अनेक रूप हैं, जिन पर लाखों रु० प्रतिवर्ष इंगलैंड में खर्च होता है।

यह जुआ चाहे हजारों लाखों आदमियों को बरबाद करता हो फिर भी ४६००० आदमियों को पूरे समय का और ३०००० आदमियों को आधे समय का रोजगार भी दिलाता है।

प्रति घंटा ५००० की जन-वृद्धि

संयुक्तराष्ट्र संघ के जनगणना सम्बन्धी १९५६ के वर्ष-बोध के अनुसार विश्व की जनसंख्या में, जो २७०,००,००,००० के लगभग है, हर घंटे औसतन ५००० की वृद्धि हो रही है। यह वृद्धि १,२०,००० प्रतिदिन अथवा ४ करोड़ ३० लाख प्रतिवर्ष के लगभग बैठती है। इतनी अधिक वृद्धि का मुख्य कारण यह है कि दुनिया भर में जन्म-गति तो प्राय: अपरिवर्तित रही, है किन्तु मृत्यु-गति में बहुत कमी हो गई है।

सं० रा० विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि १९५५ में विश्व की जन्म-गति ३४ जन्म प्रति १००० व्यक्ति प्रति-वर्ष के लगभग थी, जबकि मृत्यु-गति १८ के लगभग। इस प्रकार प्रतिवर्ष १.६ प्रतिशत वृद्धि का अन्तर रह जाता है और यह वृद्धि इस शताब्दी के अंत तक विश्व की जन-संख्या को दुगुनी कर देगी।

१४२ देशों और प्रदेशों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि विश्व-जनसंख्या के औसतन ३४ प्रतिशत व्यक्ति १५ वर्ष से कम की आयु के हैं, ५८ प्रतिशत १५ से ४९ तक की आयु के हैं तथा ८ प्रतिशत ६० वर्ष से ऊपर की आयु के। अफ्रीका, केन्द्रीय अमरीका और दक्षिण-पूर्वी एशिया की जनसंख्याओं में सबसे अधिक अनुपात बच्चों का है।

रूस का मार्ग आवश्यक नहीं

पोलैण्ड के कम्युनिस्ट नेता श्री गोमुल्को ने एक भाषण देते हुए कहा है।

अन्य देशों में समाजवाद का मार्ग उस मार्ग से भिन्न हो सकता है, जो रूस ने उक्त लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनाया है। रूस को प्रधान शक्ति बनने के लिए अनेक भयंकर कठिनाइयों में से गुजरना पड़ा है। किन्तु यह जरूरी नहीं कि अन्य देशों के सामने, जो समाजवाद का निर्माण करना चाहते हैं, वही कठिनताएं आएं। यह संभव है कि अन्य देश अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए इतनी तीव्र गति न अपनायें, जितनी रूस ने अपनाई है। प्रत्येक देश अपना इतिहास रखता है। प्रत्येक देश का अपना राष्ट्रीय चरित्र होता है। इस सत्य की उपेक्षा करने से हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

विविध राज्यों में वितरण

आयकर, उत्पादन-कर तथा सम्पत्तिकर से होने वाली आमदनी का नियत भाग विभिन्न राज्यों में इस तरह बांटा जायेगा:—

आंध्र प्रदेश	६.७९ करोड़	असम	२.४६ करोड़
बिहार	८.०१ करोड़	बम्बई	१४.१६० करोड़
मध्यप्रदेश	४.४२ करोड़	मद्रास	६.७० करोड़
मैसूर	४.७२ करोड़	उड़ीसा	३.७१ करोड़
पंजाब	४.१२ करोड़	राजस्थान	३.८५ करोड़
केरल	३.५४ करोड़	उत्तरप्रदेश	१३.३२ करोड़
प० बंगाल	११.२१ करोड़	जम्मू व काश्मीर	१.०८करोड़

विभिन्न राज्यों को दी जाने वाली सहायता पिछले वर्ष २९,५३ करोड़ रुपए दी गई थी। इस वर्ष वह २५ करोड़ १६ लाख कर दी गई है। संविधान की विभिन्न धाराओं के अनुसार कुल सहायता राशि निम्नलिखित है—

पश्चिमी बंगाल	२.४९ करोड़	बिहार	१.१७७ करोड़
असम	३.२२ ,,	उड़ीसा	१.५० ,,
पंजाब	२.४८ ,,	मध्यप्रदेश	२.९९ ,,
मैसूर	१.१३ ,,	राजस्थान	१.७५ ,,
मद्रास	१२.८ लाख	बम्बई	२.५७ ,,
आन्ध्र	४३ लाख	केरल	८९.५७ लाख
जम्मू व काश्मीर	१.७५ करोड़		

श्री सन्तानम की अध्यक्षता में भारत सरकार ने जो वित्त आयोग नियत किया था, उसकी सिफारिशों के अनुसार संभवतः करों से प्राप्त होने वाली आय का विभाजन किया गया है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारतीय राष्ट्र का आर्थिक प्रवाह

श्री जी० एस० पथिक

दूसरी योजना का पहला बजट

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरंभ काल से व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्रों में यह आशंका प्रसार पायी हुयी थी कि मई १९५७ का भारत सरकार का बजट पूंजीगत करों से भारी लदा हुआ होगा। उद्योगपति, व्यापारी वर्ग, पूंजी विनियोजक और सटोरिए सभी चिंतित थे। नए वित्तमंत्री श्री टी० कृष्णमाचारी ने स्वतः यह प्रकट किया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ के दो वर्ष भारी करों से लदे हुए होंगे। इसके उपरांत योजना के शेष वर्षों में नए करों का बोझ न पड़ेगा। श्री कृष्णमाचारी की यह नीति थी देशमुख की नीति से विपरीत है। श्री देशमुख ने प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारंभिक ३ वर्षों में घाटे की अर्थ व्यवस्था द्वारा नयी मुद्रा के प्रसार से काम लिया और बाद में नये करों द्वारा बाजार से रुपया खींचा। इससे लोगों को भारी करों का बोझ नहीं अखरा। पर नये वित्त मंत्री के सामने कई समस्याएं उपस्थित हुईं। अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों ने भारत को घाटे की अर्थ व्यवस्था को सीमित रूप में अपनाने के लिए कहा। नया मुद्राप्रसार भी विदेशी सिक्यूरिटियों और बिलों की अमानत पर ही संभव है। उनमें उत्तरोतर कमी हो रही है। इस व्यवस्था में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि और विदेशी आमद होने पर ही घाटे की अर्थ-व्यवस्था का आश्रय लिया जा सकता है।

पूंजीगत करों से लदा नहीं

पर नया बजट केवल नये पूंजीगत करों से लदा हुआ नहीं आया। उसमें उपभोक्ता पदार्थों पर भी भारी कर लगे। भारतीय व्यापारियों की मांग थी कि नए करों का क्षेत्र विस्तृत हो। पर भारतीय व्यापारियों के सुझावों की सरकार अवहेलना कर सकती थी, किन्तु विश्व बैंक ने करों की व्यापकता पर जोर दिया था। नये बजट में दो नये पूंजीगत करों के सुझाव दिए गए हैं, किन्तु ये इस वर्ष लगे नहीं। कर जांच आयोग की महत्वपूर्ण रिपोर्ट के लिए यह कहा गया था कि अगले बजटों में उसकी सिफारिशों का उपयोग होगा, पर प्रोफेसर कैलडर के सुझाव सरकार को इतने आकर्षक प्रतीत हुए कि यह रिपोर्ट ताक में रख दी गयी। प्रोफेसर कैलडर ने ३ नए करों के सुझाव दिये:—(१) कुल वार्षिक सम्पत्ति कर (२) व्यय कर और (३) भेंट या दान कर। भारतीय बजट में सम्पत्ति कर और व्यय कर को स्थान दिया गया। पर इसके साथ ही उक्त प्रोफेसरने आय कर और कार्पोरेशन कर की दरें गिराने के भी सुझाव दिये थे। उन्होंने कहा कि भारत में आय कर की दरें इंग्लैंड से भी ऊंची हैं। अतएव मई १९४७ का बजट प्रो० कैलडर के सुझावों का प्रतीक है। जहां दो नये करों को स्थान दिया गया, वहां आय कर में कमी की गयी। केवल निम्न आय पर ही नहीं, स्लेब सिस्टम के आधार पर कमी होने से उद्योगपति और पूंजीपति वर्ग को भी छूट मिली। बोनस शेयरों पर कर बढ़ने के सिवा व्यापारिक क्षेत्र के लिए नया बजट निराशाजनक न हुआ। पूंजीगत क्षेत्र से सरकार ने एक हाथ से लिया, तो दूसरे हाथ से दे दिया। इसी बजट के प्रकाशन के समय रिजर्व बैंक ने अपनी दर ४ प्रतिशत कर दी। अब तक बैंक ने जो संदिग्ध स्थिति पैदा कर रखी थी, अर्थात् बैंक दर की वृद्धि न कर व्यापारिक लेन देन की ब्याज की दर ४ प्रतिशत कर रखी थी, वह विवाद मिट गया। सरकार को बाजार से नया ऋण लेना है जिसका ३॥ प्रतिशत की दर में भरा जाना संभव नहीं था इसलिए रिजर्व बैंक को ४ प्रतिशत बैंक दर कायम करनी पड़ी। सारांश यह कि नये बजट से पूंजीगत क्षेत्र में कोई निराशाजनक प्रतिक्रिया न हुई। सुतरां, बजट का स्वागत किया गया। शेयरों के भाव जो नये पूंजीगत करों के लगने के भय से गिर रहे थे, वे मजबूत हुए।

पर नये बजट में जो अप्रत्यक्ष कर लगे, उससे आ

[सम्पूर्ण

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जनता में भारी बेचैनी पैदा हुई। करों का इतना विस्तार किया गया कि समाज का शायद ही कोई वर्ग उसकी चोट से बचा हो। अप्रत्यक्ष करों की बड़ी लम्बी सूची है, जिसमें सर्वसाधारण के दैनिक उपयोग की वस्तुएं दिया सलाई और लिफाफे चीनी, आदि हैं। चाय, काफी, चीनी, तम्बाकू, आदि का मध्य वित्त वर्ग और मजदूर वर्ग-सभी में उपयोग बढ़ गया है। फिर इन पदार्थों के पहले से दाम ऊंचे हैं। रेलवे यात्रियों पर नया कर भार लादने का तात्पर्य यह है कि लोग कम यात्रा करें। सरकार यह चाहती भी है। मोटर स्पिरिट व डेजिल तेल पर कर वृद्धि से ट्रकों और बसों का यातायात महंगा पड़ेगा। पेट्रोल और तेल केवल बड़े आदमियों की चीजें नहीं रह गयी हैं। इसका प्रभाव भी सर्वसाधारण जनता पर पड़ेगा। चीनी, सीमेंट और स्पात की दरें बढ़ने से सारे समाज में चिंता फैल गयी है। सीमेण्ट और स्पात की दरें बढ़ने से नए मकानों के निर्माण की वृद्धि रुकेगी और जो नये मकान लेंगे, उनकी लागत अधिक होने से किराये की दरें ऊंची होंगी।

उत्पादन करों का स्तर

विगत दस वर्षों में उत्पादन करों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुयी है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के काल में उत्पादन करों में ६७ करोड़ रुपए की वृद्धि होने से इस मद द्वारा कुल कर-भार करीब १७० करोड़ रुपए तक पहुँच गया। और अब यह फिर बढ़ा। नए बजट के प्रस्तावों के अनुसार एक वर्ष में ही उत्पादन करों की आय २०९ करोड़ रुपए के स्तर तक पहुँच जाएगी। यह भार सर्वसाधारण पर पड़ता है। जिस आधार पर प्रथम पंचवर्षीय योजनाके काल में उत्पादनों करों में वृद्धि हुयी, उसी आधार पर पूंजीगत करों में कोई वृद्धि नहीं हुयी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के काल में पूंजीगत करों का स्तर १७३ करोड़ रुपए पर स्थिर रहा।

१०० करोड़ के नए कर

विगत ७ वर्षों में या प्रथम पंचवर्षीय योजना के काल में जहां प्रत्यक्ष करों में केवल ४१ करोड़ रुपए की वृद्धि हुई, जिसमें सम्पत्ति कर और व्यय कर भी शामिल है, वहां अप्रत्यक्ष करों में १४२ करोड़ रुपए की वृद्धि हुयी। प्रथम योजना के काल में पदार्थों पर कर ५८.२९ करोड़ रुपए (१९५०-५१) से ९५.७० करोड़ रुपए (१९५५-५६) तक बढ़े। केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय उत्पादन करों से प्रथम योजना के काल में ५८० करोड़ रुपए वसूल किये। इसके अतिरिक्त राज्यों के उत्पादन कर वसूल करने पर कुल रकम १६०० करोड़ रुपए तक पहुँची। यह कर भार साधारण जनता पर पड़ा।

आयकर में कमी

आय कर में कुछ राहत दी गयी है। अब तक ४२०० रु० से अधिक आय पर कर लगता था, किन्तु अब ३००० रुपए की आय से ऊपर की रकम पर भी कर लगेगा। नयी रियायत से लाभ ऊंचे स्तर वालों को भी हुआ। आय कर स्लैब पद्धति पर वसूल होता है। सम्प्रति एक लाख रुपए की आय पर एक व्यक्ति को ५५,०२६ रुपए कर के चुकाने पड़ते है, अब नये प्रस्ताव से उसे ५१४०८ रुपए चुकाने पड़ेंगे। अर्थात् ३६१८ रुपए कम चुकाने पड़ेंगे। दो लाख रुपए की आय वाला व्यक्ति अभी १४४६०४ रुपए चुकाता है, वह भविष्य में १२८००० रुपए चुकाएगा अर्थात् १६६०४ रुपए कम चुकाएगा। जिनकी आय २५०,००० रुपए है और जो १९०५४१ रु० कर के चुकाते हैं, वे नयी योजना के अनुसार १६६९०८ रुपए चुकाएंगे। अर्थात् २३६३३ रुपए कम चुकाएंगे। इस प्रकार ऊंचे स्तरों की आय पर उत्तरोत्तर छूट दी गयी हैं। इन छूटों से सरकार की कितनी आमद घटी। वित्तमंत्री ने अपनी घोषणा के अनुसार आय कर, सुपर टैक्स, और सर चार्ज के ऊंचे स्तरों की दरें क्रमागत ९१.८ प्र० श० से ८४ प्र० श०, अनुपार्जित आय और ७७ प्र० श० उपार्जित आय पर गिरा दीं। सम्प्रति एक व्यक्ति जिसकी आय ५ लाख रुपए है, वह आय कर, सर चार्ज और सुपर टैक्स द्वारा ४७०००० रुपए चुकाता है, पर नये बजट के द्वारा ३८५००० रुपए चुकाएगा अर्थात् ८५००० रुपए की बचत करेगा। दस लाख रुपए की आय वाला व्यक्ति १७०००० रुपए कम चुकाएगा और पंद्रह लाख रुपए की आय वाला व्यक्ति २५५००० रुपए तक चुकाएगा। २० लाख रुपए वाले व्यक्ति की आय को ३४००० रुपए की छूट मिलेगी। इस प्रकार जितनी अधिक आय होगी, उतनी अधिक कर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

से राहत मिलेगी। इन रियायतों से सरकार को कितनी रकम खोनी पड़ेगी, इसका अनुमान करना कठिन है।

पूंजीगत करों में कमी

अन्य पूंजीगत करों पर लक्ष्य कीजिए। अतिरिक्त डिविडेण्ड कर १० प्र० श० घटा दिया गया, जो डिवीडेण्ड ६ प्र० श० और १० प्र० श० की जमा पूंजी पर वितरित होगा। १० प्र० श० और १८ प्र० श० की जमा पूंजी पर २० प्र० श० तक घटा दिया गया है। और शेष पूंजी पर ३० प्र० श० तक घटा दिया गया है। यहां भी ऊंचे स्तरों पर अधिक छूट मिली है। इंटर-कोर्पोरेट-सुपर टक्स १० प्र० श० तक घटा दिया गया है। देशी और विदेशी कम्पनियों को डिवीडेण्डों पर १७॥ प्र० श० की छूट दी गयी है। विदेशी कम्पनियों को रियायतें दी गयी हैं। जो विदेशी कम्पनियां अपनी शाखाओं द्वारा भारत में कारबार करती हैं, उन पर कर ३६ प्र० श० से ३० प्र० श० तक घटा दिया गया है। अर्थात् जो विदेशी कम्पनी आयकर और सुपर टैक्स आदि से ३६०००० चुकाती थी, वह अब ३०००० रुपए चुकाएगी। आयकर चुकाने में सभी किनारा करते हैं। प्रो० कैल्डर के अनुसार २०० करोड़ रुपए की रकम लोग चुकाने से बचाते हैं।

बोनस कर में वृद्धि

गये बजट में कम्पनियों की बचत का जो धन रिजर्व में जमा होता है, और जिसे वे अपने उद्योगों के विकास के लिए पूंजी में परिवर्तन करती हैं, और इस पूंजी के नए शेयर शेयर होल्डरों को बोनस शेयरों के रूप में देती हैं, इन बोनस शेयरों पर १२॥ प्रतिशत कर लगाया गया था। पर शिकायत की गयी थी कि चूंकि इस रकम पर एक बार कर लग चुका है, इसलिए उस पर दुबारा कर लगना उचित नहीं है। दूसरे बोनस शेयरों पर कर लगने से विनियोजकों पर विपरीत प्रतिक्रिया होती है : इतने पर भी विगत पांच छः मास में केन्द्रीय सरकार के पूंजी जारी करने के विभाग में नये बोनस शेयरों के जारी करने के अनेक प्रार्थना पत्र गए हैं, किन्तु उनमें से किसी को स्वीकृति नहीं मिली। वे शायद इस कर के लिए रोक लिए गए थे। नए बजट में बोनस शेयरों पर कर १२॥ प्र० श० से ३० प्र७ तक बढ़ा दिया गया। पर बोनस कर में इतनी भारी वृद्धि होने से अनेक कम्पनियां नये बोनस शेयर नहीं जारी करना चाहती हैं। ये अपने प्रार्थनापत्र वापस ले रही हैं। जो बचत कम्पनी पूंजी में परिवर्तित करना चाहती है, वह उसकी सम्पत्ति के रूप में बंद रहती है। इस बचत को पूंजी के रूप में परिवर्तित करने पर कर लगाने का अर्थ कम्पनी की सम्पत्ति को घटाना है। इस कर से लाखों रुपए कम्पनियों के पास से निकल जाते हैं।

सम्पत्ति-कर

नये बजट में सम्पत्ति कर को स्थान दिया गया है। १९५८ के बजट में कुल सम्पत्ति पर वार्षिक कर लगेगा। कर-जांच आयोग ने इस कर के लगाने का विचार रद्द कर दिया था। इस कर से भारतीय राजस्व को १५ करोड़ रु० की आय होने की संभावना है। दस लाख रुपए की अधिकतम सम्पत्ति पर १ प्र० श० कर और २० लाख की सम्पत्ति पर १.५ प्र० श० कर लगेगा। यह कर की दर न्यूनतम है। अन्यथा प्रो० कल्डार ने १ लाख रुपए या इस से भी नीची रकम की सम्पत्ति पर कर लगाने का प्रस्ताव दिया था। पर वित्त मंत्री ने सम्पत्ति के ऊंचे स्तर पर कर लगाने का निश्चय किया और सम्पत्ति कर की दर ८ आने प्रतिशत रखी। इस कर के अन्तर्गत २६००० व्यक्ति, ६००० कम्पनियां और ४००० हिन्दू संयुक्त परिवार आएंगे। पूंजीगत क्षेत्र में कम्पनियों पर सम्पत्ति कर लगाना अवांछनीय समझा गया। यह मांग की गई कि कम्पनियों को इस कर से मुक्त रखा जाय, क्योंकि उनकी सम्पत्ति उत्पादक होती है जिसका लक्ष्य योजना के अन्तर्गत उत्पादन में वृद्धि करना है। यह धन कम्पनियों के विनियोजन और नई कम्पनियों के निर्माण में लगता है। यदि सरकार कम्पनियों पर सम्पत्ति कर लगाना ही चाहती है, तो उसमें परिवर्तन किया जाए। १५ (ग) धारा के अंतर्गत आय कर के अनुसार कम्पनियों को छूट दी जाए। विदेशी पूंजी की आमद के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। कम्पनियों पर दोहरा कर न लगे, इस दृष्टि से शेयर होल्डरों को सम्पत्ति कर चुकाने के सर्टीफिकेट दिए जाएं। जिन शेयर होल्डरों पर सम्पत्ति कर न लगे, उन्हें रकम वापस मिले और जिन शेयर होल्डरों पर सम्पत्ति कर लगे, उनकी यह रकम जमा की जाए। कम्पनियों पर

[सम्पत्ति

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

५ लाख रुपए से ऊपर की सम्पत्ति पर १।२ प्र० श० कर लगेगा। इसी प्रकार ६० हजार रुपए से ऊपर के व्यय पर व्यय कर लगेगा। यदि भेंट या दान कर भी लगता तो उससे केन्द्रीय राजस्व को प्रतिवर्ष २० या ३० करोड़ रुपए की आय होती। उस अवस्था में उत्पादन करों में वर्तमान वृद्धि न करनी पड़ती।

सैनिक व्यय में वृद्धि

यदि दूसरी पंच वर्षीय योजना के लक्ष्य में कमी भी कर दी जाए, तो भी वर्तमान नए करों से योजना का व्यय पूरा नहीं पड़ता है। योजना के विकास व्यय के अतिरिक्त सैनिक व्यय में काफी वृद्धि हुयी है। सरकार ने चाहे जिस कारण से हो, सैनिक व्यय को नए बजट में स्पष्ट रूप से नहीं प्रकट किया। पर उसमें ५० करोड़ रुपए की नयी वृद्धि की गयी है। देश की सुरक्षा के लिए यह वृद्धि अनिवार्य है।

रुपया बाजार की तंगी

रुपया बाजार में रुपए की तंगी जारी है। करोड़ों रुपए की वृद्धि होने पर भी रुपए की कमी बनी हुई है। जिस प्रकार विनियोजन में वृद्धि होगी, उस प्रकार महंगाई भी बढ़ती जाएगी। दूसरी पंचवर्षीय योजना की सिद्धियां जब पूरी होंगी, तब होंगी, पर इस समय महंगाई बढ़ने से गरीबी बढ़ेगी। इस अवस्था में समाजवादी समाज रचना के नाम पर लोक-जीवन सुधारने और उच्च करने की बात केवल कागज या जबान पर रहेगी। प्रधान मंत्री की भावना अच्छी है। पर योजना की सफलता का सारा आधार जनता के सहयोग, सद्भावना और अमल पर निर्भर है। अभी तक लोगों को विपरीत अनुभव हुए, कर भार बढ़ता जाता है, उससे प्रजा हताश हो गयी है। उसमें योजना के लिए उत्साह और प्रेरणा नहीं रही है। बैंक दर ४ प्र० श० हो जाने से रुपया अधिक महंगा हो गया है। इससे रुपए की मांग कम पड़ जाएगी। इससे बैंकों का विनियोजन भी घट जाएगा और व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। परिणाम यह होगा कि अधिक आय सरकार के पास चली जाएगी।

———

संचालक पंचायत राज विभाग उ० प्र०

की

विज्ञप्ति संख्या ४/५५८०/३३ : २७/५३, दिनांक १५

द्वारा

पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत

सुन्दर पुस्तकें

	लेखक	मूल्य रु०	मूल्य आ०
वेद सार	प्रो. विश्वबन्धु	१	८
प्रभु का प्यारा कौन ? (२ भाग)	,,		
सच्चा सन्त	,,		३
सिद्ध साधक कृष्ण	,,	०	३
जीते जी ही मोक्ष	,,	०	३
आदर्श कर्मयोग	,,	०	३
विश्व-शान्ति के पथ पर	,,	०	१
भारतीय संस्कृति	प्रो. चारुदेव	०	३
बच्चों की देखभाल	प्रिंसिपल बहादुरमल	१	१२
हमारे बच्चे	श्री सन्तराम बी. ए.	३	१२
हमारा समाज	,,	६	०
व्यावहारिक ज्ञान	,,	२	१२
फलाहार	,,	१	४
रस-धारा	,,	०	१४
देश-देशान्तर की कहानियां	,,	१	०
नये युग की कहानियां	,,	१	१२
गल्प मंजुल	डा० रघुवरदयाल	१	०
विशाल भारत का इतिहास	प्रो. वेदव्यास	३	८

१० प्रतिशत कमीशन और ५० रु० से ऊपर के आदेशों पर १५ प्रतिशत कमीशन।

विश्वेश्वरानन्द पुस्तक भंडार

—साधु आश्रम, होशियारपुर,

पंजाब

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बैंक और बीमा

वेतन बढ़े

भारत सरकार ने कुछ समय पूर्व एक अध्यादेश जारी करके बम्बई हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यह घोषणा की थी कि बीमा कर्मचारियों के वेतनों में आवश्यकता के अनुसार कमी की जा सकती है। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने खुद अपनी दुर्बलता अनुभव की। संसद का अधिवेशन प्रारम्भ होते ही उसने बीमा कर्मचारियों के नये वेतन स्तरों की घोषणा कर दी। यह घोषित वृद्धि बीमा निगम पर क्या प्रभाव डालेगी, अभी यह हमें स्पष्ट नहीं है।

जनता पालिसी

बीमा निगम के आगे एक समस्या यह है कि वह अपना कारोबार कैसे बढ़ाये। पिछले दिनों में उसे कठोर आलोचना का शिकार होना पड़ा। क्योंकि पहले वर्ष में कारोबार गत वर्ष की अपेक्षा बहुत कम हुआ है। यदि बीमा के राष्ट्रीयकरण की उपयोगिता और सफलता सिद्ध करनी है, तो यह आवश्यक है कि वह अपना कारोबार ज्यादा बढ़ाये और यह सिद्ध कर दे कि राष्ट्रीयकरण के बाद भी बीमा कारोबार निजी क्षेत्र से काफी अच्छा चल सकता है। निगम ने बीमे का साधारण जनता में प्रचार करने के लिए जनता बीमा योजना चलाने का निश्चय किया है। इस योजना के अनुसार ५००-५०० रुपए की बीमा पालिसियां जारी की जायेंगी। इनके प्रीमियम प्राप्त करने के लिए बहुत सुविधाएं दी जायेंगी।

विनियोग नियम

बीमा निगम के सामने एक और समस्या है। अपने कोष के विनियोग की। इस समय उसके पास करीब ४ अरब रुपया विद्यमान है। पहले बीमा कम्पनियां अपनी अपनी समझ के अनुसार उद्योग व्यापार और सम्पत्ति में रुपए का उपयोग करती थी। अब यह सब काम सरकारी निगम को करना है। सरकार ने यह निश्चय किया है कि इस कार्य के लिए—बीमा निगम के कोष के प्रबन्ध के लिए एक ट्रस्टी मंडल बनाया जाय। इसमें रिजर्व बैंक का भी सहयोग प्राप्त किया जाये। हमारा ख्याल है कि सरकार इस बोर्ड को केवल सरकारी कर्मचारियों से नहीं भर देगी, वरन् अनुभवी व कुशल व्यापारियों का सहयोग भी प्राप्त करेगी। इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि निजी उद्योगों की उपेक्षा न हो। जिस प्रकार सरकार एक के बाद एक उद्योग पर अधिकार या नियंत्रण करती जाती है, टैक्स आदि के नियमों के द्वारा उनको जकड़ती जाती है उससे निजी उद्योग के लिए पूंजी दुर्लभ होती जाती है। और यह निश्चित है कि औद्योगिक क्षेत्र में जितनी जल्दी उन्नति निजी क्षेत्र कर सकते हैं उतनी सरकारी क्षेत्र नहीं। इसलिए निजी क्षेत्र की आवश्यकता बीमा उद्योग को पूरी करनी चाहिए।

आपका स्वास्थ्य

(हिन्दी की एक मात्र स्वास्थ्य सम्बन्धी मासिक पत्रिका)

"आपका स्वास्थ्य" आपके परिवार का साथी है।

"आपका स्वास्थ्य" अपने क्षेत्र के कुशल डाक्टरों द्वारा सम्पादित होता है।

"आपका स्वास्थ्य" में अध्यापकों, अभिभावकों, माताओं और देहातों के लिए विशेष लेख प्रकाशित होते हैं।

आज ही ६) रु० वार्षिक मूल्य भेजकर ग्राहक बनिए।

व्यवस्थापक,

आपका स्वास्थ्य—बनारस-१

सम्पदा में विज्ञापन देकर लाभ उठाइए

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

[पृष्ठ ३०६ का शेष]

धान होना चाहिए, इसी की बात मैं कह रहा हूँ।

नेशनल प्लैनिंग के लिए खतरे

नेशनल प्लैनिंग और देश को बचाने के खयाल से, याने युद्ध के समय उसका परिणाम अपने देश पर कम हो, देहात तो कम-से-कम बच जायँ, शहर भी कुछ बच जायँ, तो अच्छा ही है। इस खयाल से मैं कह रहा हूं कि गांव-गांव में दो साल का अनाज रहना चाहिए, नहीं तो गांव के लोगों पर अनाज खरीदने का मौका यदि आयेगा, तो लड़ाई के समय वे मारे जायेंगे। गांव में दो साल का अनाज तभी रहेगा, जब गांव के लोग एक होकर योजना करेंगे और इस तरह की ग्राम-योजना वे तभी कर सकेंगे, जब गांव के लोग एक होकर योजना करेंगे और इस तरह की ग्राम-योजना वे तभी कर सकेंगे, जब ग्रामदान होगा! जब तक गांव में आज की हालत रहेगी, याने जमीन की निजी मालकियत बनी रहेगी, कुछ लोग मालिक और कुछ लोग बेजमीन रहेंगे, तबतक गांव के लोगोंका एक दिल नहीं बनता और एक दिल न हो, तो ग्राम-योजना नहीं बनती। ग्राम-योजना के बिना ग्राम स्वाम्लम्बी नहीं हो सकते और ग्रामदान के बिना ग्राम-योजना नहीं हो सकती। इसलिए ग्रामदान आवश्यक है। गांधियन प्लैनिंग के विचार को हम अलग रखें, परन्तु अपने देश की आजादी, देश की आजादी, देश के ग्रामीणों की उन्नति और देश की सुरक्षा के लिए ग्रामदान बहुत जरूरी है।

सरकारी प्लैनिंग ग्रामदान के सिद्धान्त पर ही खड़ा होना चाहिए। इसमें थोड़ा-सा को-अर्शन (दबाव) का अंश आ जाय, तो भी हर्ज नहीं। अहिंसा के खयाल से बोलने वाला जब यह कहता है, तो वह बहुत खतरनाक माना जायगा, परन्तु देश के बचाव की बात जब आती है, तब कुछ न कुछ 'को-अर्शन' होता ही है। जहां डिफेन्स का सवाल आता है, वहां कुछ थोड़ा 'को-अर्शन' आता ही है। जहां लोगों के ध्यान में यह बात आ जायगी कि सरकार ग्रामदान को बहुत चाहती है और उसके बिना देश का रक्षण असम्भव समझती है और इसीलिए सरकारी तौर पर उसमें थोड़ा 'को-अर्शन' का अंश आ जाय, तो उसे मानने के लिए मेरा मन तैयार है।

समग्र ग्रामदान की क्रांति

भूदान-यज्ञके जरिए अहिंसा ने आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में प्रवेश पाया और भ्रातृत्व की मानवीय आकांक्षा एक नये पुरुषार्थ के साथ जुड़ गयी। जब पड़ौसी भूखा हो, तो हम कैसे खा सकते हैं, इस भावना से लोगों ने भूदान देना शुरू किया। एक वर्ष के बाद सर्व-सेवा संघ ने विनोबा जी के मार्गदर्शन में इस काम को देश भर में फैलानेकी जिम्मेदारी उठायी। देशके पांच लाख गांवों में कम से कम एक-एक भूमिहीन परिवार को जमीन मिले, इस दृष्टि से दो वर्ष में २५ लाख एकड़ भूमि इकट्ठी करने का संकल्प किया गया। इस संकल्प की कालावधि पूरी होने से पहले ही भारत की जनता ने उससे अधिक जमीन दे दी। साथ ही साथ भूदान यज्ञ का क्षितिज भी व्यापक हो गया। इस अहिंसात्मक प्रक्रिया के जरिए देश में भूमिहीनता मिटानेका लक्ष्य भूदान-कार्यकर्ताओं के सामने स्पष्ट हो गया और देश के एक करोड़ भूमिहीन परिवारों को खेती लायक जमीन मिले, इस दृष्टि से पांच करोड़ एकड़ भूमि प्राप्त करने का लक्ष्यांक स्थिर किया गया। इस संकल्प की पूर्ति होने से पहले ही भूदान आरोहण ऐसी मंजिल पर पहुँचा, जिसके कारण इस आंदोलन की क्रांतिकारी शक्यताएं स्पष्ट हो गयीं। देश के ढाई हजार

उद्योग विभाग, उत्तरप्रदेशीय सरकार

द्वारा प्रकाशित

सचित्र मासिक पत्र

उद्योग

पढ़िये, जिसमें भारत के आर्थिक विकास, विशेषतया उत्तरप्रदेश की औद्योगिक प्रगति के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण लेखों के साथ साथ अन्यान्य मनोरंजक साहित्यिक सामग्री—कविताएं, कहानियां और लेख भी उपलब्ध होंगी।

विवरणार्थ लिखें :

प्रकाशनाधिकारी
उद्योग विभाग
उत्तरप्रदेश—कानपुर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गांवों के लोगों ने प्रेमपूर्वक, स्वेच्छा से अपनी जमीन की व्यक्तिगत मालिकी मिटाकर ग्रामदान किया। स्पष्ट है कि ग्रामदान की फलश्रुतिके बाद पांच करोड़ एकड़ जमीन इकट्ठी करने का संकल्प अब देश की तमाम जमीन पर से व्यक्तिगत मालिकी के विसर्जन के लक्ष्य में स्वाभाविक ही समा जाता है।

अतः हमें अपनी सारी ताकत अब ग्रामदानके काम में लगानी है। सन्' ५७ का बर्ष भारत के इतिहास में एक अनोखा महत्त्व रखता है। इस वर्ष में भारत के जीवन को नया पल्टा देने वाला बड़ा परिवर्तन होगा। यह इच्छा गांधीजी की कल्पना के ग्राम राज की स्थापना से ही पूरी हो सकती है और ग्रामदान में ही ग्रामराज के इस आदर्श को मूर्त रूप देने की ताकत है। इसलिए हम सबको ग्रामदान आन्दोलन को अग्रसर करने में ही अपनी शक्ति लगा देनी चाहिए।

जब तक भारत में ग्रामराज की स्थापना न हो, तब तक अखंड घूमते रहने की श्री विनोबाजी ने प्रतिज्ञा की है। देश की तमाम ताकत यदि ग्रामदान के आंदोलन को सफल करने में लग जाती है, तो सन् '५७ के ऐतिहासिक वर्ष में ही इस महान् क्रांति का सन्पन्न होना सम्भव है।

—श्री सिद्धराज

दोनों एक साथ नहीं

भगवान् और माया की एक साथ आराधना नहीं की जा सकती, यह उच्चतम श्रेणी का एक आर्थिक सत्य है। हमें एक को चुनना होगा। पश्चिमी राष्ट्र आज भौतिकवाद के दैत्य के साये में बढ़ रहे हैं। उनका नैतिक विकास अवरुद्ध हो चुका है। ये अपनी प्रगति को पौण्ड तथा डालर के आधार पर आंकते हैं। अमरीकी धनाढ्यता आदर्श बन गयी है। मैंने अपने देश के बहुत से आदमियों को कहते सुना है कि हम अमरीकी क्रम से धनी होंगे, परन्तु उसकी बुराइयों से दूर रहेंगे। मेरा तो यह दृढ़ मत है कि यदि ऐसा प्रयत्न किया गया तो अवश्य असफल होगा।

—महात्मा गांधी

हिन्दी और मराठी भाषा में प्रकाशित होता है।

उद्यम

धर्मपेठ, नागपुर

सर्वोपयोगी हिन्दी उद्यम प्रतिमाह १५ तारीख को पढ़िये

उद्यम में निम्न विषयों पर लेख प्रकाशित होते हैं

★ लाभदायक उद्योगधन्धों की व्यावहारोपयोगी जानकारी, अनाज की खेती, साग-सब्जी की बागवानी और रोगों का निवारण। पशुपालन, दुग्ध-व्यवसाय और ग्रामोद्योग-सम्बन्धी लेख। आरोग्य, घरेलू औषधियों सम्बन्धी जानकारी।

उद्यम के स्थायी स्तम्भ

★ महिलाओं तथा विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त विभिन्न रुचिकर खाद्य पदार्थ बनाने की विधियां। घरेलू मितव्ययता। जिज्ञासु जगत्। कृषि व औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों की मुलाकात और परिचय। नित्योपगी वस्तुएं घर पर ही तैयार कीजिये।

आज ही उद्यम का वार्षिक चन्दा ७ रु० भेजकर उद्यम मासिक मंगवाइये।

[सम्पा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारत का नया रेल-बजट

श्री जगजीवनराम, रेलवे मंत्री

योजना में कमी

रेलवे मंत्रालय ने पहले-पहल अपनी दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए १४,८० करोड़ रुपये का अनुमान तैयार किया था, जो रेलवे के यात्री और माल परिवहन की अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने के लिए खर्च का सबसे कम अनुमान समझा गया था। यह जरूरी समझा गया कि पहली पंचवर्षीय योजना के अन्त में रेलवे की जो परिवहन क्षमता थी, उसे इतना बढ़ाया जाय ताकि रेलवे ३० प्रति शत अधिक यात्री और ६०८ लाख टन अधिक माल, अर्थात् कुल १८,०८ लाख टन माल ढो सके। रेलवे योजना में ३,००० मील नयी लाइन बनाने की भी व्यवस्था की गयी थी। लेकिन सरकार के वित्तीय साधन सीमित होने के कारण, रेलवे की दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए केवल ११,२५ करोड़ रुपये निर्धारित किये गये, जिनमें से योजना की अवधि में रेलवे को अपने निजी साधनों से ३७५ करोड़ रुपये की व्यवस्था करनी थी। रकम कम होने के कारण रेलवे योजना के कार्य-क्षेत्र को भी कम करना पड़ा। अधिकतर नयी लाइनों के बनाने का विचार छोड़ दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में अब केवल वे लाइनें रखी गयी हैं जो इस्पात और कोयले के उत्पादन के विकास लिए जरूरी हैं। निर्धारित रकम के आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि इस लागत से यात्री परिवहन की क्षमता केवल १५ प्रति शत बढ़ सकेगी और कुल १६,२० लाख टन माल ढोया जा सकेगा। यात्री यातायात की क्षमता के लक्ष्य में जो कमी की गयी, उसके फलस्वरूप योजना की अवधि में सवारी गाड़ियों में भीड़ हटाने की संभावना कम हो गयी। गाड़ियों में इस समय भीड़ की जो स्थिति है, उसका बना रहना कोई अच्छी बात नहीं है लेकिन माल परिवहन की क्षमता के लक्ष्य को १८,०८ लाख टन से घटा कर १६,२० लाख टन करना देश की विकासमान अर्थ-व्यवस्था के लिए कहीं अधिक चिन्ता की बात है। इस्पात के नये कारखानों के विकास के लिए जरूरी कोयला और दूसरे कच्चे सामान के लिए २५० लाख टन, दूसरे लोगों के लिए ६०

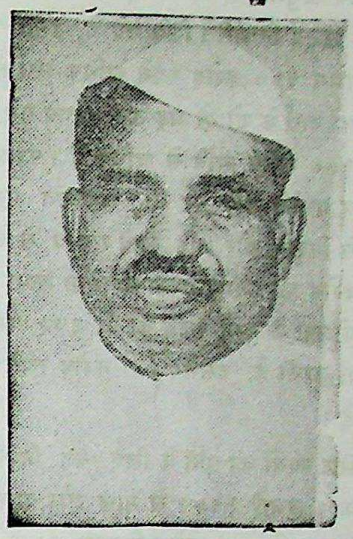

श्री जगजीवनराम

लाख टन अधिक कोयला और ४० लाख टन अधिक सीमेन्ट के परिवहन की क्षमता निकाल कर, बिसाता, व्यापार, और दूसरे सभी उद्योगों और खेती के बढ़े हुए उत्पादन के लिए परिवहन की क्षमता बहुत कम रह जाती है।

योजना की अवधि में रेल-परिवहन की मांग का जो १८,०८ लाख टन अनुमान पहले लगाया था, परिवहन की वास्तविक मांग उससे कहीं अधिक भी हो सकती है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में रेलवे के लिए निर्धारित ११,२५ करोड़ रुपये उसकी जरूरतों के लिए बिलकुल अपर्याप्त हैं, क्योंकि इसमें केवल ४२० लाख टन अधिक माल ढोने की व्यवस्था की गयी है। मोटे हिसाब के अनुसार यह अनुमान लगाया जाता है कि दामों के वर्तमान स्तर पर १८,०८ लाख टन माल ढोने के लिए रेलवे को १०० करोड़ रुपये से ऊपर अतिरिक्त रकम की जरूरत होगी। योजना की प्रगति के साथ रेल-परिवहन की मांग बढ़ेगी। इसके अलावा योजना तैयार होने के बाद श्रमिकों की लागत और इस्पात, सीमेन्ट आदि जरूरी सामान की कीमत बढ़ गयी, जिसकी वजह से

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

यात्री परिवहन में १५ प्रति शत बढ़ती और ४२० लाख टन अधिक माल ढोने के लिए ११,२५ करोड़ रुपये काफी नहीं हैं। अब अनुमान है कि ११,२५ करोड़ की योजना में पहले जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, उन्हें पूरा करने के लिए लगभग १०० करोड़ रुपये अधिक खर्च होंगे।

अतिरिक्त खर्च के जो दो मद ऊपर बताये गये हैं, वे कुल मिला कर १०० करोड़ रुपये से अधिक हैं। फरवरी १९५६ में माल और पार्सल भाड़े पर ६¼ प्रतिशत पूरक प्रभार के प्रस्ताव से किराये और भाड़े रेलवे राजस्व से केवल लगभग ३२५करोड़ की आमदनी का अनुमान किया गया था। इस तरह योजना के लिए रेलवे को जो ३७५ करोड़ रुपये की व्यवस्था करनी है, उसमें ५० करोड़ रुपये की कमी रह जाती है।

अतिरिक्त व्ययों की पूर्ति के लिए यह निश्चय किया गया है कि १ जुलाई १९५७ से माल और पारसल यातायात पर लिया जाने वाला पूरक किराया ६। प्र० श० से बढ़ाकर १२।। प्र० श० कर दिया जाय। जिन वस्तुओं को पूरक किराये (सरचार्ज) से छूट मिली हुई है, उन्हें यह छूट आगे भी मिलती रहेगी। अनाज, दालें, चारा, खाद, खादी, अखबार, अखबारी कागज और किताबें—इन पर पूरक किराया नहीं लगता।

रेल मंत्री ने कहा कि पूरक किराये में यह वृद्धि होने से रेलों को माल यातायात से ११ करोड़ ३० लाख रु० सालाना और पारसल यातायात से १ करोड़ २० लाख रु० सालाना आमदनी होने का अनुमान है। परन्तु चूंकि यह वृद्धि आगामी १ जुलाई से लागू की जायेगी इसलिए चालू वित्तीय वर्ष में इस वृद्धि से कुल लगभग ९।। करोड़ रु० मिलने की आशा है।

चालू वर्ष के अन्त तक माल-भाड़ा जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर माल-भाड़े की दर लागू करने की आशा है। ऐसा होने पर यह पूरक किराया समाप्त कर दिया जायगा।

पारसल और माल की बढ़ी हुई आमदनी को ध्यान में रख कर चालू वर्ष में अब ३०.८३ करोड़ की बचत का अनुमान है। यह रकम विकास निधि में डाली जायेगी।

संक्षेप में १९५६-५७ में निर्माण, स्थिर-यंत्र, मशीन और चलस्टाक पर १९३ करोड़ खर्च की व्यवस्था की गई थी। इस साल के आखिरी हफ्ते में रेलों का अनुमान १७८ करोड़ था। खर्च में जो कुछ कमी हुई, सब की सब प्रायः निर्माण के मद में हुई। सिविल इन्जीनियरिंग के कामों पर जो खर्च हुआ, उससे स्पष्ट है कि कम खर्च प्रायः सामान की कमी के कारण है खासतौर पर पटरी, स्लीपर, फिटिंग, सिगनल और अन्य पाश आदि रेल-पथ के सामानों की कमी रही। काम की प्रगति बढ़ाने के लिए निर्माण-संगठनों को तैयार करने में कुछ समय लगता है। योजना के पहले साल में पूरा करना सम्भव न था, फिर भी जिन कारणों से प्रगति धीमी रही, उन पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया है और काम किया जा रहा है, ताकि अगले वर्षों में काम तेजी से हो और योजना पर पूरी तरह अमल किया जाय।

रेल-पथ के लिए इस्पात, पुल के गर्डर, सीमेन्ट आदि जरूरी सामानों की बहुत कमी थी। फिर भी, निर्माण की प्रगति काफी सन्तोषजनक रही और योजना के विभिन्न कार्य प्रशंसनीय तत्परता के साथ किये गये। १९५६-५७ में कुल मिला कर ८७ मील लम्बी नयी रेलवे लाइनें यातायात के लिए खोली गयीं। कुल मिला कर ५२४ मील लम्बी दूसरी ८ लाइनों पर काम जारी है। ७०० मील लम्बी लाइन पर दोहरी पटरी बिछाने का काम हो रहा है। दक्षिण-पूर्व रेलवे में ३७० मील, पश्चिम रेलवे में ११० मील और दक्षिण रेलवे में ७८ मील लम्बी लाइनों पर दोहरी पटरी बिछायी जा रही है। पिछले वित्तीय वर्ष के अन्त में विभिन्न योजनाओं पर १,५०,००० से अधिक आदमी काम कर रहे थे।

कुल २,८०० मील लम्बी लाइनों के सर्वे की मंजूरी दी गई, जिसमें से लगभग २,००० मील में जांच-पड़ताल का काम अभी जारी है।

तुगलकाबाद और गाजियाबाद के बीच परिहार लाइन के अलावा दिल्ली में यमुना पर एक दूसरा रेल-सड़क पुल बनाने की योजना पर विस्तृत विचार किया जा रहा है।

आयोजना में कलकत्ता के उपनगरों और पूर्वी-रेल पर बर्दवान से गोमोह तक, मध्य-रेल पर इगतपुरी से मुम्बई तक तथा दक्षिण-रेल पर तम्बरम् से विल्लुपुरम तक ८०

[सम्पर्क

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रेलवे बजट एक दृष्टि में

(करोड़ रुपयों में)

	वास्तविक १९५५-५६	संशोधित अनुमान १९५६-५७	संशोधित अनुमान १९५७-५८ मार्च १९५७ में प्रस्तावित	संशोधित अनुमान १९५७-५८ वर्तमान प्रस्ताव
आय				
यात्री यातायात से आमदनी				
ऊंचे दर्जे	१२.८५	१३.००	१३.७५	१३.७५
तीसरा दर्जा	९४.८६	१०२.५०	१०५.२५	१०५.२५
पार्सल आदि यातायत से आमदनी	२०.८७	२१.४०	२४.००	२४.९०
माल यातायत से आमदनी	१८०.२८	२०६.५०	२१८.००	२२६.५०
फुटकर आमदनी	६.८१	७.३५	८.१०	८.१०
अवर्गित	०.६२	—०.७५	—०.६०	—०.६०
यातायात से कुल प्राप्ति	३१६.२९	३५०.००	३६८.५०	३७७.९०
व्यय				
कार्य चालन व्यय	२१३.२२	२२९.३४	२४४.१६	२४४.१६
शुद्ध विविध व्यय	७.७३	११.०२	१४.१२	१४.१२
मूल्य ह्रास आरक्षित निधि के लिये विनियोग	४५.००	४५.००	४५.००	४५.००
जोड़	२६५.९५	२८५.३६	३०३.२८	३०३.२८
बचत				
शुद्ध रेलवे राजस्व	५०.३४	६४.६४	६५.२२	७४.६२
सामान्य राजस्व को लाभांश	३६.१२	३७.६९	४३.७९	४३.७९
शुद्ध बचत	१४.२२	२६.९५	२१.४३	३०.८३

मील लम्बी रेल-लाइनों पर रेलों को बिजली से चलाने की व्यवस्था के लिये ८० करोड़ रु० रखे गये हैं। लेकिन अब गोमोह से मुगलसराय तक, आसनसोल से रूरकेला तक और राजखरस्वान से बरजमदा तक ५०० मील लम्बी रेल लाइनों पर भी बिजली लगाने की आवश्यकता महसूस की गयी है। फ्रांस की सरकार ने और फ्रांसीसी रेल-अधिकारियों गत वर्ष फ्रांसीसी बिजली इन्जीनियरिंग विशेषज्ञों की सेवाओं के रूप में प्रशंसनीय सहायता दी है।

यात्री-सुविधाएं

रेल-यात्रा को और अधिक सुखद और आरामदेह बनाने के लिए प्रयत्न जारी रहेंगे। इस काम के लिए २ करोड़ ९८ लाख रु० की व्यवस्था की गयी है। स्टेशनों पर आजकल जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनका पूरा सर्वे कराया गया है और स्टेशनों पर न्यूनतम स्तर की सुविधाओं में जो कमी है, उसको दूर करने के लिए क्या करना होगा, इसकी भी जांच की गयी है। मंत्री महोदय

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ने कहा कि मैंने यह कहने की जरूरत नहीं कि आवश्यक सामान मिलने पर ही यह काम किया जा सकेगा और इसमें समय लगेगा।

विश्व-बैंक ने भारतीय रेलों का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों का जो दल भेजा था, उसने विश्व-बैंक को अपना प्रतिवेदन दे दिया है। अब विश्व-बैंक से ऋण के लिए बातचीत करने के लिए एक दल तत्काल वाशिंगटन के लिए रवाना हो जायगा, जिसमें रेल-मण्डल के दो सदस्य होंगे।

रेल-कर्मचारी

गत मार्च में बजट पर हुई बहस का जबाब देते हुए मैंने बताया था कि रेल-कर्मचारियों के लिये वर्तमान भविष्य-निधि एवं ग्रेचुटी प्रणाली के स्थान पर पेंशन प्रणाली और अवकाश-प्राप्ति-सुविधाएं लागू करने के सम्बन्ध में दो या तीन वैकल्पिक प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। अब इस विषय में निश्चित प्रस्ताव बन चुके हैं और मैं शीघ्र ही कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ उन पर विचार-विमर्श करने वाला हूं।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की अपनी श्रेणी में तथा तृतीय श्रेणी में पद-वृद्धि के नियमों की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की जा चुकी है। इस समिति से अपना काम तुरन्त आरम्भ करने के लिए कहा गया है।

पहली आयोजना की अवधि में कर्मचारियों के लिए ४० हजार मकान बनाये गये। गत वर्ष १५ हजार मकान बनाये गये। चालू वर्ष में भी १५ हजार मकान बनाने का कार्यक्रम है। दूसरी आयोजना के अंत तक ६४,४०० और नये मकान बन चुकेंगे।

भारतीय रेलों के लिए इस्पात का सामान

रेलों के लिये इस्पात का विशेष सामान खरीदने का काम रेल मंत्रालय को सौंप देने का निश्चय किया गया है। रेल की पटरी, सलीपर इत्यादि उपलब्ध करने के लिये एक मिशन यूरोप और अन्य देशों को भेजा जा रहा है। इस सामान की कमी के कारण रेल आयोजना को लागू करने के काम में बहुत बाधा पैदा हो रही है।

लकड़ी के सलीपर उपलब्ध करने का काम काफी बढ़ा है। सलीपरों के प्रतिमान में ढील कर दी गयी है और अब नये और विभिन्न प्रकार के सलीपरों का प्रयोग किया जा रहा है। अंडमान से भी सलीपर अधिक मात्रा में आने लगे हैं। बर्मा, आस्ट्रेलिया, थाईलैंड, मलाया, इंडोनेशिया और ब्राजील से सलीपरों का आयात करने के लिए कार्यवाही की गयी है।

सब प्रयत्नों के बावजूद रेलों के लिए जितने सलीपरों की आवश्यकता है, उसका केवल तिहाई भाग प्राप्त हुआ है। विवश होकर रेलों को धातु के सलीपरों का प्रयोग करना पड़ा है और ये सलीपर भी काफी मात्रा में उपलब्ध नहीं है। अब यह विचार है कि कंकरीट के सलीपरों का भी प्रयोग किया जाय और शुरू में यह सलीपर बड़े पैमाने में प्रयोग में लाये जाएं।

नई दिल्ली व दिल्ली में सम्पदा

सम्पदा के फुटकर अंकों और विशेष कर विशेषांकों की मांग अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों में बनी रहती है। उनकी सुविधा के लिए आत्माराम एण्ड सन्स, काश्मीरी गेट, दिल्ली (हिन्दी विभाग) में सम्पदा की बिक्री की व्यवस्था कर दी गई है।

नई दिल्ली में सम्पदा के विक्रेता सेंट्रल न्यूज एजेंसी, कनाट सर्कस हैं।

इस प्रबन्ध से आशा है, दिल्ली के अर्थशास्त्र-प्रेमियों की असुविधा दूर हो जायगी।

— मैनेजर सम्पदा

अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नया सामयिक साहित्य

वाल्मीकि रामायण (संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर)—रूपान्तरकार—श्री आनन्दकुमार। प्रकाशक राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली; मूल्य ३)।

रामायण की कथा न जाने कितने सहस्रों वर्षों से भारत में सुनी और पढ़ी जाती है, फिर भी वह कभी पुरानी नहीं होती। हिन्दू जाति के लिए वह नित्य नूतन है। प्रस्तुत पुस्तक में वाल्मीकि रामायण के आधार पर वही राम कथा दी गई है। रूपान्तरकार ने वे प्रकरण निकाल दिए हैं, जिन्हें वह प्रक्षिप्त समझता है। उत्तरकाण्ड की सीता बनवास की प्रसिद्ध कथा को भी रूपान्तरकार प्रक्षिप्त मानते हैं। इसलिए वह कथा परिशिष्ट के रूप में दी गई है। आदि कवि वाल्मीकि की कथा भी जन-श्रुति के आधार पर दी गई है। अन्तिम परिशिष्ट में वाल्मीकि रामायण की सुन्दर सूक्तियों का संग्रह दिया गया है।

समस्त रामकथा सरल और सरस भाषा में लिखी गई है क्योंकि यह महान् कवि वाल्मीकि की रचना का संक्षिप्त रूपान्तर है। अनेक चित्र, बढ़िया छपाई और सुन्दर आवरण के कारण पुस्तक का बहिरंग भी बहुत अच्छा हो गया है।

सोमा—ले०—श्री सत्यकाम विद्यालंकार। प्रकाशक—वही। मूल्य ३ रु० ५० नये पैसे।

प्रस्तुत पुस्तक लेखक का नवीन उपन्यास है। इसका कथानक आज के समाज और विशेषकर सिनेमा के आकर्षक वातावरण पर आधारित है। एक महत्वाकांक्षिणी नारी—धन और प्रतिष्ठा की इच्छुक नारी—किस तरह अपने वर्तमान से असन्तुष्ट होकर अपने व अपने परिवार के जीवन को कष्टमय बना देती है, इसी का सुन्दर चित्रण लेखक ने इस उपन्यास में किया है। सोमा को उसकी गरीबी के कारण उसके प्रेमी युवक ने ठुकरा दिया है, यह क्षोभ उसे धन प्राप्त करने के लिए—अपने पति को भी वैसा सम्पन्न करने की उत्कट भावना से उन्मत्त कर देता है। वह अपने पति को सुख छोड़कर पैसा कमाने के लिए जुट पड़ने को प्रेरित करती है, मित्रों को तथा मां बाप को छोड़ने के लिए विवश करती है और स्वयं भी अर्थोपार्जन के निमित्त अभिनेत्री का जीवन स्वीकार करती है, भले ही वह उसे अप्रिय और पति के लिए अपमानकर था, परन्तु धन की पिपासा इतनी तीव्र थी कि वह एक ओर पति को अपमान के घूंट पीकर चुप रहने के लिए कहती है; दूसरी ओर स्वयं नारी की स्वाभाविक मातृत्व की इच्छा का भी दमन करती है, क्योंकि मातृत्व के बाद वह अभिनय और अर्थोपार्जन के लायक नहीं रहेगी। उसका साधु-स्वभाव, अत्यन्त धीर परन्तु विवश पति सब कुछ सहन करता जाता है, किन्तु अन्त में वह जब अपनी पत्नी को उसके पहले प्रेमी से मिलता-जुलता देखता है और पति पर किसी स्त्री से बात भी न करने के लिए दबाव डालते देखता है, वह उसे छोड़कर चला जाता है। सोमा को अपनी भूल मालूम पड़ती है। उसका पति अमर भी अपने अतीत पर दृष्टि डालता है। उसे मालूम होता है कि वह सदा सोमा के संकेत पर चलता रहा, अपने अधिकार—पतित्व के अधिकार और कर्त्तव्य का उपयोग नहीं किया। समस्त उपन्यास दो परस्पर विरोधी स्वभाव के पति-पत्नी के अस्वाभाविक जीवन का चित्रण कर आदर्श दाम्पत्य जीवन बिताने का संकेत करता है।

यौवन की आंधी—लेखक पीयरे लुई; अनुवादक—श्री महावीर अधिकारी। प्रकाशक—वही। मूल्य चार रुपये।

प्रस्तुत पुस्तक फ्रांस के प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री पीयरे लुई का एक प्रसिद्ध प्रेमाख्यान है। इस उपन्यास का कथानक, पृष्ठ-भूमि और वातावरण तथा लेखनशैली—सभी कुछ अद्भुत है, जिसका अधिकांश उपन्यासों से कोई मेल नहीं है। करीब २००० वर्ष पूर्व की मिश्री व यूनान की विलासमयी संस्कृति और तत्कालीन विलासिनी वारवनिताओं के जीवन का नग्न चित्रण लेखक की कुशल लेखनी तूलिका द्वारा हुआ है। तत्कालीन समाज का रहन-सहन विचारधारा तथा सामाजिक, धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं व अन्ध विश्वास, सबका एक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सजीव चित्र पाठक के सामने खिंच जाता है। क्राईसिस और डिमैट्रियस की प्रेम कथा, प्रेमिका की प्राप्ति के लिए किए गए दुःसाहस, उसका करुण अंत तथा प्रेमिका की मृत्यु का कारण बनकर भी उसकी कलापूर्ण मूर्ति की रचना कर उसके प्रति प्रेम प्रदर्शन की करुण अदम्य भावना सभी कुछ अद्भुत है। यौन आकर्षण, कामुकता, वासना तथा वेश्याओं के नग्न चित्रण से पूर्ण उपन्यास में भी लेखक डिमैट्रियस के शब्दों में विलासिनी नारी की भर्त्सना करता हुआ पाठक को वेश्या के हासविलास तथा सौन्दर्य से अभिभूत न रहने का यह सन्देश देना नहीं भूला है कि वासना का यथार्थ नाम गुलामी है। विलासिनी नारी प्यार नहीं करती; पुरुष को अपने आगे नतमस्तक करना, उसे मर्यादाहीन करना और उसके सिर पर अपने जूते रखना ही उसका उद्देश्य होता है। वह स्वयं झुकती है, उसके आगे, जो नारी को देखकर विचलित नहीं होता।

अनुवादक श्री महावीर अधिकारी की भाषा बहुत सरल, सजीव व सुन्दर है, इसमें सन्देह नहीं।

आर्थिक समीक्षा (सर्वोदय अंक)—सम्पादक श्री हर्षदेव मालवीय। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी। नई दिल्ली मूल्य ७५ नये पैसे।

कालड़ी (केरल) में होने वाले सर्वोदय सम्मेलन के अवसर पर यह अंक प्रकाशित किया गया है। प्रस्तुत बृहदाकार अंक में सर्वोदय, भूदान तथा आचार्य विनोबा आदि के सम्बन्ध में अनेक विचारपूर्ण लेख हैं। कुछ लेख भावुकता प्रधान हैं। परन्तु कालड़ी सम्मेलन और भारत की भूमि-समस्या ग्रामदान आन्दोलन का महत्व, अहिंसात्मक प्रजातंत्र की बुनियाद आदि विचारपूर्ण लेख भी हैं। आचार्य विनोबा के संस्मरण, अनेक सुन्दर कविताएं तथा कुछ चित्र अंक को अधिक उपयोगी व आकर्षक बना देते हैं। सर्वोदय की दृष्टि में आज की अर्थनीति तथा पंचवर्षीय योजनाओं पर एक विवेचनात्मक लेख इस अंक को और अधिक पूर्ण कर देता है।

Paddy Rice Production and Potash Fertilisers in Japan. लेखक डा० डब्ल्यू० रेमी।

भारतवर्ष में चावल की खेती का महत्व असाधारण है। आज चावल का उत्पादन आवश्यकता से बहुत कम हो रहा है। पाठकों को याद होगा कि भारत सरकार ने चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए जापानी कृषि पद्धति का अनुसरण किया था। प्रस्तुत पुस्तक में विद्वान लेखक ने यह बताने की चेष्टा की है कि किस तरह पोटाश के प्रयोग से जापान में चावल की खेती का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। लेखक ने बहुत अधिक चमत्कारपूर्ण परीक्षणों का हाल लिखकर यह सिद्ध किया है कि चावल की खेती के लिए पोटाश की खाद बहुत अधिक लाभकारी है। अभी तक भारत में खाद के कारखाने फास्फेट और नाइट्रेट पैदा करते हैं। लेखक का दावा है कि पोटाश का प्रयोग भारतवर्ष में भी सफल हो सकता है। यह पुस्तक जर्मनी में प्रकाशित की गई है और पोटाश फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ६, लोटस कोल्ड, जमशेद जी टाटा रोड, बम्बई—१ से प्राप्त हो सकती है।

पांचजन्य—(ऐतिहासिक कहानी विशेषांक)—राष्ट्र धर्म प्रकाशन लिमिटेड गौतम बुद्ध मार्ग, लखनऊ द्वारा प्रकाशित। मूल्य १)।

आज के साहित्यिक प्रगतिशीलता के नाम पर एक विशेष प्रकार का साहित्य दे रहे हैं, जिसमें समाजवाद का लक्ष्य सामने रखा जाता है अथवा अनैतिकता या उच्छृंखलता का आकर्षक चित्र। राष्ट्र निर्माण के लिए देश, प्रेम, त्याग, बलिदान व कर्त्तव्य भावना आदि जिन उदात्त गुणों की देश को आवश्यकता है, उनकी ओर बहुत कम साहित्यकारों का ध्यान जा रहा है। साहित्य का उद्देश्य आज मार्गदर्शन रहा ही नहीं है। पांचजन्य के सम्पादकों ने इसी अभाव को अनुभव करते हुए यह निश्चय किया कि नये साहित्यकारों को भारत के प्राचीन गौरवपूर्ण इतिहास से ऐसे कथानक लेने की ओर प्रेरित किया जाय, जिनसे राष्ट्रीय चरित्र का विकास हो सके। ऐसी २१ कहानियों का संग्रह इस अंक में है। इन सब लेखकों ने कला को केवल मनोरंजन मात्र न मानकर 'सत्य शिवं सुन्दरं' रूप में उपस्थित करने का प्रयत्न किया है। कुछ कहानियां तो वस्तुतः बहुत सुन्दर हैं। हमें आशा है कि हिन्दी के पाठक व साहित्यकार इस प्रयत्न को पसन्द करेंगे।

—

[सम्पादक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Printing and Polygraphic Equipment

★ **DEPENDABLE**
★ **STURDY**
★ **EFFICIENT**

Exported by: **V/O "MACHINOEXPORT"**
MOSCOW - U.S.S.R.

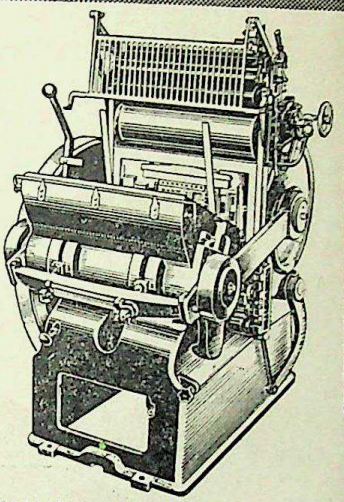

- Composing and slug casting machines
- Perforating typesetting machines
- Two revolution flat bed presses
- Rotary & Offset presses
- Photo offset equipment
- Paper cutting machines
- Book binding & stitching machines etc.

HEAVY DUTY PLATEN PRESS TT -1: 15" x 20"
4 Rollers (Ink), 1200 I.P.H.

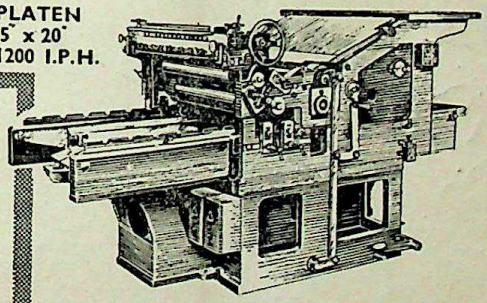

CYLINDER FLAT BED PRESS - Model M.P.
20" x 26" Automatic Cylinder Lifting Device, 2500 I.P.H. Manual Feed.

Please write for further details to our Agents:

MANUBHAI SONS & CO.
16, Custom House Road, Bombay -1

THE INRUPEXCO
16, Bentinck Street, Calcutta -1

TRADE REPRESENTATION OF THE U.S.S.R. IN INDIA

New Delhi ★ Bombay (Branch) ★ Calcutta (Branch)

NU - 56

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

AIR-CONDITIONED TRAIN

BETWEEN

BOMBAY & NEW DELHI

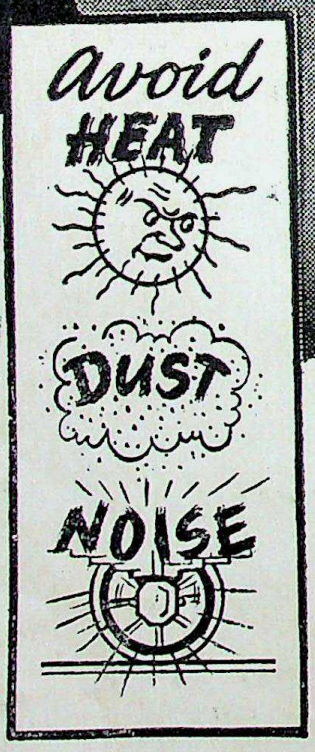

सप्ताह में दो बार

बम्बई सैण्ट्रल से—रविवार और बुधवार

बम्बई सैण्ट्रल रवानगी ... ... ११-३५ प्रातः

नई दिल्ली पहुँच ... ... १०-१५ प्रातः अगले दिन

नई दिल्ली से—सोमवार व शुक्रवार

नई दिल्ली रवानगी ... ... ५-०-० सायं

बम्बई सैन्ट्रल पहुँच ... ... ४-२० अगले दिन

केवल रु० ४२-२-० देकर बम्बई से नई दिल्ली तक

अनुकूलित तीसरे दर्जे में सैर कीजिये।

गरमी के महीनों में यह ठण्डा और आरामदेह है

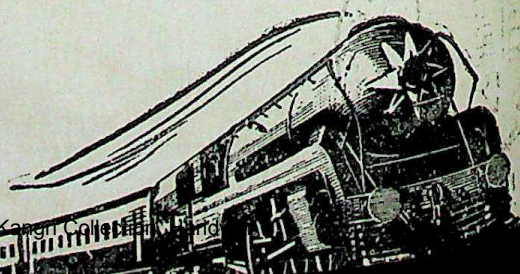

WESTERN RAILWAY

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

6333

गुरुकुल कांगड़ी

समदा

वर्ष ६ : अंक ७

जुलाई १९५७

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

स्वा ग त

लीपजिग के व्यापारिक मेले में

१सितम्बर से ८ सितम्बर १९५७ तक

- विविध वस्तुओं के नमूने
- यांत्रिक उपभोक्ता पदार्थों की प्रदर्शनी
- ३३ से अधिक देशों के ८००० से अधिक प्रदर्शक
- ११,८२,००० वर्ग फुट का विशाल क्षेत्र
- ७६ देशों से दर्शक आते हैं

जानकारी के लिए सम्पर्क स्थापित कीजिये –

लीपजिग फेअर एजेंसी

पो० बा० सं० १९९३, बम्बई—१

अथवा

लीपजिग फेअर एजेंसी

डी/१७ निजामुद्दीन ईस्ट, नई दिल्ली—३०

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्पदा का :—

आगामी विशेषांक

प्रकाशन की तैयारियां जोरों से प्रारम्भ हो गई हैं

परन्तु वह कैसा होगा,
किस विषय पर प्रकाशित होगा,
उसकी विशेषताएं क्या होंगी,
आदि जानकारी के लिए

आप तीसरा पृष्ठ देखिये

इतना ही समझ लीजिए कि अपने विषय का एक अद्भुत विश्वकोश होगा—हिन्दी पत्र जगत् में एक दम अनुपम और संग्रहणीय। विविध विद्वत्तापूर्ण लेखों, ज्ञानवर्धक तालिकाओं, ग्राफों और चित्रों से परिपूर्ण।

अभी से सम्पदा का ग्राहक बन जाने वालों को साधारण वार्षिक मूल्य में ही मिलेगा।

मूल्य होगा १॥) रु०।

पाठक अपनी प्रति डेढ़ रु० भेजकर सुरक्षित करा लें
विज्ञापनदाताओं के लिए भी यह अपूर्व अवसर है।

—मैनेजर सम्पदा

अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिल्ली-६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हिन्दी और मराठी भाषा में **उद्यम** सर्वोपयोगी हिन्दी उद्यम प्रकाशित होता है। प्रतिमाह १५ तारीख को पढ़िये

अब प्रतिमास 'उद्यम' में नावीन्यपूर्ण सुधार देखेंगे

— नई योजना के अन्तर्गत 'उद्यम' के कुछ विषय —

विद्यार्थियों का मार्गदर्शन—परीक्षा में विशेष सफलता प्राप्त करने के तथा स्वावलम्बी और आदर्श नागरिक बनने के मार्ग।

नौकरी की खोज में—यह नवीन स्तम्भ सबके लिए लाभदायक होगा।

खेती-बागवानी, कारखानेदार तथा व्यापारी वर्ग—खेती-बागवानी, कारखाना अथवा व्यापारी-धन्धा इन में से अधिकाधिक आय प्राप्त हो, इसकी विशेष जानकारी।

महिलाओं के लिए—विशेष उद्योग, घरेलू मितव्ययिता, घर की साजसज्जा, सिलाई-कढ़ाई काम, नए व्यंजन।

बाल-जगत्—छोटे बच्चोंकी जिज्ञासा तृप्ति हो तथा उन्हें वैज्ञानिक तौर पर विचार करनेकी दृष्टि प्राप्त हो इसलिए यह जानकारी सरल भाषा में और बड़े टाइप में दी जाएगी।

'उद्यम' का वार्षिक मूल्य रु० ७।- भेजकर परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को उपयोगी यह मासिक-पत्रिका अवश्य संग्रहीत करें।

उद्यम मासिक १, धर्मपेठ, नागपुर-१

भारत सरकार के व्यापार और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित

'उद्योग व्यापार पत्रिका'

★ उद्योग और व्यापार सम्बन्धी प्रामाणिक जानकारी-युक्त विशेष लेख, भारत सरकार की आवश्यक सूचनाएं, उपयोगी आंकड़े आदि प्रति मास दिये जाते हैं।

★ डिमाई चौपेजी आकार के ६०-७० पृष्ठ : मूल्य केवल ६ रुपया वार्षिक। एजेण्टों को अच्छा कमीशन दिया जायगा। पत्रिका विज्ञापन का सुन्दर साधन है।

★ लघु-उद्योग विशेषांक मंगा कर छोटे उद्योगों के सम्बन्ध में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त कीजिये।

★ ग्राहक बनने, एजेन्सी लेने अथवा विज्ञापन छपाने के लिए नीचे लिखे पते पर पत्र भेजिये :—

सम्पादक

उद्योग व्यापार पत्रिका

उद्योग और व्यापार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्पदा का समाजवाद-अंक

समाजवाद आज के युग का तकाजा है। कांग्रेस और भारतीय संसद ने समाजवादी समाज के आदर्श को स्वीकार कर लिया है। समस्त योजनायें इसी एक उद्देश्य को लेकर बनायी जा रही हैं। सार्वजनिक कार्यकर्ता समाजवाद के गीत गाते हैं, किन्तु आज भी समाजवाद क्या है, इस सम्बन्ध में जनता के सामने स्पष्ट और निश्चित विचार-धारा नहीं है। समाजवाद के मूल तत्वों, उसके विविध भेदों, उसकी प्रक्रियाओं और उसके मार्ग में आने वाली समस्याओं पर भी अभी तक बहुत कम विचार किया गया है। समाजवाद स्वयं एक उद्देश्य है अथवा उद्देश्य-प्राप्ति का साधन, यह भी निश्चित नहीं हो सका।

इन सब की जानकारी देने के लिए ही सम्पदा का यह समाजवाद अंक प्रकाशित किया जा रहा है। प्रस्तावित विषयसूची से इस अंक की उपयोगिता का अनुमान पाठक स्वयं कर सकेंगे।

— प्रस्तावित विषय-सूची —

विवेचनात्मक—

१. समाजवाद क्या है ?
२. समाजवाद के विविध भेद
३. वैदिक समाजवाद
४. साम्यवाद (विभिन्न धर्मों की दृष्टि से)
५. समाजवाद ध्येय है या साधन ?
६. साम्यवाद में व्यक्ति और राज्य का सम्बन्ध
७. सर्वोदय और साम्यवाद
८. राष्ट्रीयकरण क्या समाजवाद है ?
९. घोर केन्द्रीयकरण अथवा व्यक्ति-स्वातंत्र्य
१०. मिश्रित अर्थ-व्यवस्था।

इतिहास—

१. समाजवाद का जन्म तथा विकास (कार्ल मार्क्स औ अन्य समाजवादी विचारक)
२. रूस में महान साम्यवादी क्रांति
३. साम्यवादी शासन में रूस की असाधारण घटना
४. विभिन्न देशों में साम्यवादी पद्धति
५. यूगोस्लाविया में साम्यवाद का स्वरूप
६. चीन में साम्यवाद का स्वरूप
७. यूरोप में समाजवाद की लहर और उसका परिणाम
८. अमरीका के पूंजीवाद में नया मोड़
९. साम्यवाद में विविध प्रवृत्तियां
१०. साम्यवादी व्यवस्था में उद्योग और श्रम-संगठन
११. समाजवादी और श्रम समस्या

भारत में समाजवाद—

१. भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी
२. प्रजासमाजवादी और समाजवादी दल
३. कांग्रेस और समाजवाद
४. भारतीय संविधान और समाजवाद
५. सरकारी उद्योगों का विकास (दोनों पहलू)
६. उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की प्रवृत्ति
७. सरकारी नीति पर आलोचनात्मक दृष्टि
८. भारत में निजी उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान
९. समाजवादी आंदोलन और नयी समस्याएं
१०. भारत की संस्कृति, परम्पराएं और साम्यवाद

विविध—

१. संसार के महान नेता— कार्लमार्क्स, लेनिन और गांधी
२. विनोबा का भूदान-यज्ञ

आदि आदि।

बीसियों चित्र, चार्ट और ग्राफ देने की परम्परा भी कायम रखी जायगी।

इस महत्वपूर्ण सामग्री से युक्त विशेषांक का मूल्य केवल १॥) रु०

—मैनेजर सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारत की औद्योगिक नीति

इसमें भारत की उद्योग नीति का अतीत, समय-समय पर होने वाले परिवर्तन और आज की नीति का संक्षेप से परिचय दिया गया है। इसके लेखक काशी हिन्दू विश्व-विद्यालय के श्री अश्विनीकुमार शाह और सेण्ट जेवियर्स कालेज रांची के श्री रामनरेश लाल अर्थशास्त्र के अनुभवी अध्यापक हैं। दोनों अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों की कठिनता और आवश्यकताएं जानते हैं। इसलिए यह पुस्तक हायर सैकेण्डरी, इन्टर व बी० ए० के परीक्षार्थी विद्यार्थियों के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी। मूल्य ६२ नये पैसे। ७५ नये पैसे के टिकट भेजकर अण्डर पोस्टल सर्टिफ़िकेट मंगाइये।

—मैनेजर, अशोक प्रकाशन मंदिर,
रोशनारा रोड, दिल्ली—६,

केवल ५० विद्यार्थियों के लिए

पंचवर्षीय योजनांक रियायत में

राजस्थान के एक सज्जन ने जो पंचवर्षीय योजना के प्रसार में विशेष रुचि लेते हैं, एक राशि इसलिये प्रदान की है कि हम अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों को अपने योजना अंक कम कीमत पर दें। इसलिये जो विद्यार्थी निम्न-लिखित अंक मंगवाना चाहें, वे दो रुपया मनीआर्डर से भेजकर तीनों अंक मंगालें। इन अंकों की वी० पी नहीं की जायेगी।

योजनांक—(प्रथम पंचवर्षीय योजना मूल्य १) रु०

राष्ट्रीय विकास अंक—(दूसरी योजना का विवरण १।)

जून १९५६ का अङ्क—(दूसरी योजना के संशोधित अंक इसमें दिये गये हैं) मूल्य ।।।)

यह रियायत केवल ५० विद्यार्थियों के लिये है।

इसलिए शीघ्रता करें, अन्यथा यह सुविधा नहीं मिल सकेगी।

—मैनेजर

संचालक पंचायत राज विभाग उ० प्र०
की
विज्ञप्ति संख्या ४/५५८०/३३ : २७/५३, दिनांक १५
द्वारा
पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत

सुन्दर पुस्तकें

	लेखक	मूल्य रु०	आ०
वेद सार	प्रो. विश्वबन्धु	१	८
प्रभु का प्यारा कौन ? (२ भाग)	,,		
सच्चा सन्त	,,		३
सिद्ध साधक कृष्ण	,,	०	३
जीते जी ही मोक्ष	,,	०	३
आदर्श कर्मयोग	,,	०	३
विश्व-शान्ति के पथ पर	,,	०	१
भारतीय संस्कृति	प्रो. चारुदेव	०	३
बच्चों की देखभाल	प्रिंसिपल बहादुरमल	१	१२
हमारे बच्चे	श्री सन्तराम बी. ए.	३	१२
हमारा समाज	,,	६	०
व्यावहारिक ज्ञान	,,	२	१२
फलाहार	,,	१	४
रस-धारा	,,	०	१४
देश-देशान्तर की कहानियां	,,	१	०
नये युग की कहानियां	,,	१	११
गल्प मंजुल	डा० रघुवरदयाल	१	०
विशाल भारत का इतिहास	प्रो. वेदव्यास	३	८

१० प्रतिशत कमीशन और ५० रु० से ऊपर के आदेशों पर १५ प्रतिशत कमीशन।

विश्वेश्वरानन्द पुस्तक भंडार
—साधु आश्रम, होशियारपुर,
पंजाब

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विषय-सूची

सं०	विषय	पृष्ठ
१.	नई आयात नीति	३७५
२.	हमारी श्रम-समस्याएं	३७६
३.	सम्पादकीय टिप्पणियां	३७८
४.	वेतनों के निर्धारण का आधार क्या हो ?	३८१
५.	भारतीय कृषि के लिए धन	३८४
६.	बचत और हमारी पंचवर्षीय योजना	३८७
७.	रुपये की स्थिति सुदृढ़ है	३८९
८.	निरन्तर उन्नति के पथ पर जापान	३९०
९.	चीन द्वारा साम्यवाद को नई दृष्टि	३९२
१०.	दूसरी विकास योजना का प्रथम वर्ष	३९४
बैंक और बीमा		
११.	जीवन बीमा निगम और उसकी समस्याएं	३९८
१२.	भारत में विदेशी पूंजी, सं० रा० संघ से १८॥ लाख डालर, बैंकों द्वारा ऋण, सेविंग बैंकों की ब्याज दर	३९९
अर्थवृत्त-चयन		
१३.	संसद का पिछला अधिवेशन, तेल से असम में तूफान, कपास का भविष्य, अखबार व पूंजीपति, आलू में कैलोरी, रबड़ की खेती, आय के अन्य साधन	४०१
सर्वोदय पृष्ठ		
१४.	साम्यवाद और सर्वोदय	४०५
	सभ्य और धनी कब बनेंगे ?	४०५
	सर्वोदय समाज व बैंक	४०६
१५.	नया सामयिक साहित्य	४०७
१६.	भारत में प्लास्टिक उद्योग	४०९
विदेशी अर्थ-चर्चा		
१७.	रूस व अमेरिका में आणविक होड़	४११
१८.	विविध टिप्पणियां	४१४
१९.	मध्यप्रदेश—उज्ज्वल भविष्य का जून माप	४१५
२०.	उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती	४१६
२१.	आर्थिक समाचार	४१८

हमें विश्वास है कि

आप सम्पदा को पसन्द करते हैं

परन्तु क्या आपने अपने कर्त्तव्य का पालन भी किया है ?

सम्पदा के दो ग्राहक बनाकर

सिद्ध कर दीजिए कि राष्ट्र भाषा हिन्दी में गम्भीर साहित्य के पाठकों की कमी नहीं है !

—मैनेजर सम्पदा

सम्पदा

सम्पादकीय परामर्शमण्डल

१. श्री जी० एस० पथिक
२. श्री महेन्द्र स्वरूप भटनागर

वार्षिक मूल्य		८)
,, ,,	(शिक्षणालयों से)	७)
एक प्रति का मूल्य		७५ नये पैसे

बम्बई में हमारे प्रतिनिधि—श्री टी० एन० वर्मा, नेशनल हाउस, २री मंजिल, टुलक रोड, बम्बई-१

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार का पता—

कृष्णचन्द्र विद्यालंकार, अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिल्ली-६

प्रबन्ध सम्बन्धी पत्रव्यवहार का पता—

मैनेजर सम्पदा, अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिल्ली-६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्पदा व हिन्दी में आर्थिक साहित्य पर्यायवाची शब्द हैं

अपने पांच वर्षों के स्वल्प काल में सम्पदा ने आर्थिक प्रवृत्तियों तथा आर्थिक समस्याओं की जो जानकारी दी है, वह अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। यही कारण है कि:—

हा. सै. स्कूल, इण्टर व डिग्री कालेज और पुस्तकालय एवं वाणिज्य व अर्थशास्त्र के विद्यार्थी

सम्पदा की पुरानी फाइलें मंगा रहे हैं। थोड़ी सी फाइलें बची हैं। प्रत्येक विशेषांक स्वयं एक उपादेय पुस्तक है। कुछ समय बाद आपको हम फ़ाइल न दे सकेंगे। मूल्य प्रति फाइल ८) रु०

नमूने के एक अंक के लिए छः आने के टिकट भेजिये

यह स्मरण रखिये कि वी० पी० से मंगाने पर आपको ॥=) अधिक देना पड़ता है।

मनीआर्डर से मूल्य भेजना लाभकारी होगा।

राज्यों में सम्पदा स्वीकृत

सम्पदा को निम्नलिखित राज्यों के शिक्षा-विभागों ने अपने अपने राज्य के स्कूलों, कालेजों तथा सार्वजनिक वाचनालयों के लिए स्वीकृत किया है—

राज्य	परिपत्रक संख्या	दिनांक
(१) उत्तरप्रदेश	पुस्तक/५२५७	१२-१-५४
(२) बिहार	७३३/२पी/१/५३	२७-११-५३
(३) पंजाब	३२०६/५/२५/बी-५३-२६१४३	२३-७-५३
(४) मध्यप्रदेश		
(स्कूलों के लिए)	२ जी/बी	२-८-५२
(कालेजों के लिए)	३४२८ ३XVIII	२४-८-५२
(५) राजस्थान	३६८०/Edu II/५२	६-१२-५२
(६) मध्यभारत	३ : १५ : २ : ५२बी/२५६५	२४-३-५२

३३७ शाखाएं समस्त भारत में

तथा

संसार के सभी महत्त्वपूर्ण केन्द्रों में एजेंसियाँ

सर्व प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध। विदेशी विनिमय तथा व्यापार के लिए विशेष रूप से उपयुक्त

कार्यगत कोष १४१ करोड़ रु० से अधिक

चेयरमैन

श्री एस. पी. जैन

दी पंजाब नैशनल बैंक लिमिटेड

स्थापित : सन् १८९५ ई०

प्रधान कार्यालय : दिल्ली

श्री ए. एम. वाकर— जनरल मैनेजर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्पदा

वर्ष ६] जुलाई १९५७ [अङ्क ७

नई आयात नीति

यदि पिछले मास आर्थिक क्षेत्र में सबसे महत्त्वपूर्ण व्यक्ति वित्त-मंत्री श्री कृष्णमाचारी थे, तो इस मास के सबसे महत्त्वपूर्ण व्यक्ति उद्योग व्यापार मन्त्री श्री मुरारजी देसाई हैं। यदि वित्तमन्त्री ने असाधारण रूप से प्रायः सभी जीवन-उपयोगी वस्तुओं पर कर लगा दिये थे तो श्री देसाई ने आयात के खुले लाइसेन्स को समाप्त करके व्यापारिक जगत में एक क्रान्ति सी पैदा कर दी है।

वस्तुतः देश के आयात व निर्यात के व्यापार को देखते हुए विदेशी मुद्रा की स्थिति जिस तरह हीन से हीनतर होती जा रही थी, उसे देखते हुए आयात पर भारी प्रतिबन्ध लगाने आवश्यक भी थे। निम्नलिखित तालिकासे यह मालूम होगा कि हमारे देश में किस तीव्र गति से आयात व्यापार बढ़ रहा था।

आयात व्यापार (लाख रु० में)

	१९५४	१९५५	१९५६
कपास आदि	४३९३	३८९९	३५२६
पटसन	८४३	१२८६	७३६
रासायनिक पदार्थ व औषध	२४२४	२६८७	३१५७
कटलरी व हार्डवेयर	१२३८	१७४७	२०४१
बिजली का सामान	८०५	१०८०	१५[illegible]२
मशीनरी	६२८६	८५८७	११५७७
लोहा व इस्पात व निर्मित वस्तुएं	२११५	४२४५	९८४१
परिवहन के साधन	२५३५	४२७२	५१८२
कृत्रिम रेशम	१०१६	११७९	१३७४
योग	४८५,४०	५०२,००	६११,८२

हम पिछले डेढ़ वर्ष से भारत-सरकार से निरन्तर यह अनुरोध करते आ रहे थे कि वह आयात पर प्रतिबन्ध लगाये। अनिवार्य मशीनरी का आयात समझ में आ सकता था, किन्तु शराब, शृंगार सामग्री, बिस्कुट आदि खाद्य, विदेशी फिल्में, स्टेशनरी, विदेशी पत्रपत्रिकाएं और ब्लेड, पंखे, बिजली के चूल्हे आदि सैकड़ों पदार्थों को रोकने की अत्यन्त आवश्यकता थी। यह आश्चर्य की बात है कि आज वित्त मंत्री श्री कृष्णमाचार्य विदेशी मुद्रा की कठिनता अनुभव कर रहे हैं, किन्तु व्यापार मंत्री होते हुए वे ग्राहकों व उपभोक्ताओं के समर्थक बनकर आयात के लिए लगातार लाइसेंस देते रहे। परिणाम यह हुआ कि हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति निरन्तर हीन होती गई। उन्होंने अपने बजट भाषण में इसे स्वीकार करते हुए कहा कि—"आयात में वृद्धि के परिणामस्वरूप मुद्राबाहुल्य का प्रभाव तो कुछ कम हुआ, परन्तु देश की बाहरी प्रारक्षित निधियों में विशेष कमी हुई। रिजर्व बैंक के पास १९५५ के अन्त में जो विदेशी परिसम्पद ७३५ करोड़

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रु० की थी, वह एक वर्ष बाद १९५६ के अन्त में घटकर ५३० करोड़ रु० की हुई। जनवरी १९५७ से समाप्त होने वाले दस महीनों में रिजर्व बैंक की विदेशी परिसम्पद में लगभग २३६ करोड़ रु० की कमी हो गई, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह ५ करोड़ रु० बढ़ी थी। प्रारक्षित निधियों में इतनी अधिक निकासी निस्संदेह गम्भीर विषय है।"

जिस गम्भीर स्थिति की ओर वित्तमंत्री ने अपने भाषण में ध्यान खींचा है, वह इस वर्ष और भी अधिक गम्भीर हो गई है। भारतीय उद्योग-व्यापार-मंडल से प्रकाशित 'फोर्टनाइट रिव्यू' में दिए गये ये अंक स्थिति की विकटता को प्रकट करते हैं—

रिजर्व बैंक की विदेशी परिसम्पद्	(करोड़ रु० में)
दिसम्बर १९५६	५२९.९१
जनवरी १९५७	५१०.६१
फरवरी १९५७	५१८.८७
मार्च ,,	५२६.८३
अप्रैल ,,	५०४.९१
मई ,,	५५५.०७

इन अंकों से यह स्पष्ट है कि कितनी तेजी के साथ हमारी विदेशी मुद्रा कम होती जा रही है। फरवरी व मार्च के महीनों में संख्या में वृद्धि आयात में कमी या निर्यात में वृद्धि का परिणाम नहीं, परन्तु विदेशी मुद्रा कोष से प्राप्त ६०.७१ करोड़ रु० की भारी राशि का परिणाम है। यदि यह राशि प्राप्त न होती, तो ३९४ करोड़ रु० ही विदेशी परिसम्पद रह जाती अर्थात् पांच मास में १३५ करोड़ कम हो जाती। यह स्थिति थी, जब एक भारी कदम उठाने की जरूरत थी, छोटी-मोटी कतर ब्योंत से काम नहीं हो सकता था। इसलिए व्यापार मंत्री श्री मुरार जी देसाई ने १ जुलाई से तीन मास के लिए सभी प्रकार के खुले आयात के लाइसेंस समाप्त कर दिये हैं। इससे ४० करोड़ रु० की बचत की संभावना है। सभी प्रकार के उपभोक्ता पदार्थ बन्द कर दिये गये हैं। पहले छः मास के लिए आयात सम्बन्धी नीति की घोषणा की जाती थी, अब तीन मास के लिए ऐसा किया गया है। औषधियां, घड़ी, ब्लेड, रेडियो, फौण्टेनपैन फिल्म आदि ही नहीं, कास्टिक सोडा व तेजाब के आयात भी बन्द हो जावेंगे। जस्ता, सीसा, टिन, तांबा, तेजाब, पुस्तकों आदि को विशेष कमी अनुभव होने पर अधिकारी इनके लाइसेंस दे सकेंगे। पूंजीगत सामान का आयात रोका नहीं जा सकता, क्योंकि पंचवर्षीय योजना के आयात के लिए यह अनिवार्य होगा। इस का भी भारी बोझ आज हम पर न पड़े, यह व्यवस्था की जा रही है कि विदेशों से विलम्बित भुगतान के आधार पर पूंजीगत सामान मंगाया जाये। अर्थात् मूल्य आगामी कई वर्षों से चुकाया जाय। यह प्रसन्नता की बात है कि ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, रूस, फ्रांस, स्विटजरलैंड और स्वीडन ने इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है।

उपभोक्ता पदार्थों के आयात पर आकस्मिक प्रतिबन्ध से बहुत से व्यापारी सरकारी अनुरोध के बावजूद मूल्य बढ़ाकर अनुचित लाभ उठा रहे हैं। यह प्रवृत्ति देशद्रोह से पूर्ण है। ऐसे बड़े व्यापारियों को कठोर दण्ड देने की आवश्यकता है। उपभोक्ताओं को कुछ अधिक दाम देने पड़ेंगे या किन्हीं वस्तुओं से वंचित रहना पड़ेगा, परन्तु यह त्याग बहुत साधारण है और आशा करनी चाहिए कि उच्च मध्यम वर्ग इस त्याग को सहर्ष स्वीकार करेगा। विदेशी फिल्में, उपन्यास, और पत्रपत्रिकाएं, विशेषकर सिनेमा कहानी व सैक्स सम्बन्धी, शराब, विदेशी-स्टेशनरी- शृंगार-सामग्री व विदेशी वस्त्रों को भी छोड़ देने चाहिए।

इन प्रतिबन्धों का एक सुखद परिणाम यह होगा कि देश में बहुत से नये उद्योग धन्धे पनप उठेंगे। हमें विश्वास है कि उद्योग-व्यापार मन्त्री श्री मुरारजी देसाई एक कुशल शासक की भांति दृढ़ता के साथ आयात पर प्रतिबन्ध की नीति का पालन करेंगे।

—

हमारी श्रम-समस्याएं

इसी सप्ताह दिल्ली में भारत सरकार, मजदूर और मिल मालिकों के प्रतिनिधियों का भारतीय श्रम सम्मेलन का पन्द्रहवां अधिवेशन होने जा रहा है। इसमें अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार होगा। किसी देश के औद्योगिक विकास के लिए उद्योग और श्रम का सहयोग अनिवार्य है। भारत

[सम्पादक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सरकार उद्योगपतियों पर तरह-तरह के नियन्त्रण लगाकर अथवा अनेक उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करके उद्योग में पूंजी का सहयोग तो प्राप्त कर रही है, किन्तु श्रमिकों में उठता हुआ असंतोष वह हल कर पायी हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। यह असंतोष सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों में तीव्र गति से बढ़ता ही जा रहा है। जब तक उनका असंतोष दूर करके उन्हें राष्ट्रीय विकास में सहयोग देने के लिए तत्पर नहीं किया जायेगा, तब तक उद्योगों का पूर्ण विकास सम्भव नहीं है। भारत सरकार के नये श्रम-मंत्री श्री गुलजारीलाल नन्दा अत्यन्त अनुभवी और कुशल हैं। उन्होंने मजदूरों को यह सलाह देकर ठीक ही कहा है कि वे अपने वर्गहितों को इतनी प्रधानता न दें कि उससे राष्ट्र के विकास में ही बाधा पड़ जाय। यह भावना पैदा करने की समस्या ही आज सबसे बड़ी समस्या है।

उक्त सम्मेलन में जिन प्रश्नों पर विशेष रूप से विचार किया जायेगा, उनमें से एक मजदूरों का उद्योग के संचालन में सहयोग भी है। श्रम सम्मेलन ने एक अध्ययन-मण्डल नियुक्त किया था, जिसने ब्रिटेन, स्वीडन, फ्रांस, बेल्जियम, पश्चिमी जर्मनी और यूगोस्लेविया में जाकर प्रस्तुत प्रश्न का अध्ययन किया कि उद्योग के संचालन में मजदूरों का किस सीमा तक और किस रूप में सहयोग प्राप्त होता है। प्राय: सभी देशों में परामर्श-समितियां बनी हुई हैं। मजदूरों के मंगल और हितकार्यों में तथा प्रबन्ध-सम्बन्धी अन्य कार्यों में इनके परामर्श पर विशेष ध्यान दिया जाता है, किन्तु इन परामर्श समितियों को ऐसा कानूनी रूप नहीं दिया गया कि उनका निर्णय संचालकों को मानना अनिवार्य ही हो। यूगोस्लेविया में, जहां समाजवादी व्यवस्था है, मजदूर लोकतंत्रीय आधार पर मिल के प्रबन्ध में भाग लेते हैं। किन्तु यूगोस्लेविया के एक प्रमुख नेता ने यह राय दी है कि हमारे तीन चार साल के परीक्षण की हू-बहू नकल करना शायद खतरनाक होगा। अध्ययन मंडल की राय यह थी कि उद्योग संचालन में परस्पर परामर्श समितियों को प्रोत्साहन देना चाहिये। किन्तु प्रश्न यह रह जाता है कि क्या ये परामर्श समितियां और विशेषकर समितियों के मजदूर प्रतिनिधि मजदूर संघ (ट्रेड यूनियन) का स्थान ले लेंगे जो वेतन बोनस आदि का निर्णय करें? अध्ययन मण्डल ने यह राय दी है कि परामर्श समितियों को औद्योगिक संघर्ष का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिये। दोनों के कार्यक्षेत्र अलग होने चाहिये। इन परामर्श समितियों में एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा और वह यह है कि मजदूर प्रतिनिधियों के चुनाव कांग्रेस, कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट पार्टी के चुनाव के अखाड़े न बन जायें और मजदूरों को परस्पर लड़ने वाले गुटों में विभक्त न कर दें। उक्त मण्डल के सामने एक यह भी प्रश्न था कि इन परामर्श समितियों का संगठन कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया जाय या मिलों की इच्छा पर छोड़ दिया जाय। अध्ययन मंडल ने राय दी है कि कानून के द्वारा अनिवार्यता तो नहीं, परन्तु अनुमति दे देनी चाहिए। इन परामर्श समितियों का काम संक्षेप में पारस्परिक वार्तालाप के लिये अनुकूल वातावरण पैदा करना, मजदूरों के मंगल हित अथवा कार्य की दिशाओं में सुधार तथा उत्पादन वृद्धि के साधनों पर विचार आदि होंगे।

श्रम सम्मेलन में दूसरे जिस महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर विचार किया जायगा, वह है मजदूरों के प्रशिक्षण का। सरकार ने निम्नलिखित प्रश्नों पर अपनी सिफारिशें करने के लिये एक मण्डली नियत की थी: १-मजदूर संघों के संचालन संगठन और अर्थ व्यवस्था की शिक्षा देना। २-संघ के सदस्यों को संघ और देश के प्रति कर्तव्य की शिक्षा देना। ३-मजदूर प्रतिनिधियों को उद्योग के संचालन की शिक्षा देना। इस मण्डली ने शिक्षा के कार्य के लिये विविध संगठनों की सिफारिशें की हैं और अनेक आदर्श निर्देश के रूप में प्रस्तुत किये हैं। इन पर श्रम सम्मेलन में विचार होगा। इनके औचित्य और उपयोगिता में किसी को संदेह नहीं है, किन्तु हमें भय है कि इन संगठनों के जाल में ही हम कहीं उलझ कर न रह जायं।

श्रम सम्मेलन में तीसरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न वेतन नीति का है। वेतन निर्धारण की कसौटी क्या हो, यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न सदा झगड़े का कारण रहा है। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ने २५ प्रतिशत वेतन वृद्धि की मांग की है। आल इन्डिया ट्रेड यूनियन ने १०० रु० न्यूनतम वेतन की मांग की है। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने वेतन-निर्धारक-मण्डल (वेज-बोर्ड) नियत करने का निश्चय किया हुआ है। सूती मिलों के लिए एक बोर्ड

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नियत हो चुका है। इस प्रश्न पर भी सम्मति देने के लिये एक मण्डली नियत की गई थी। इस मण्डली ने यह सलाह दी है कि मजदूरों की अवस्था में सुधार तथा संचालकों को तर्कसंगत प्राप्ति का ध्यान रखकर वेतन नियत किये जायें। उद्योग की क्षमता को भी इस मण्डली ने कम महत्व नहीं दिया, परन्तु आज वही उद्योग अधिक क्षमताशाली हो सकता है, जो आधुनिकीकरण की मशीनरी से युक्त हो। उस अवस्था में मजदूरों की छटनी अनिवार्य हो जायेगी। यदि आज के मजदूरों को काम से न भी हटाया जाय तो भी वर्तमान मशीनरी के साथ सम्भावित नये मजदूरों की आजीविका समाप्त हो जायेगी। उक्त मण्डली ने मजदूरों को यह भी सलाह दी है कि आज जब देश में पूंजी-निर्माण की अत्यन्त आवश्यकता है, तब उत्पादन वृद्धि का सारा भाग केवल मजदूरों को ही नहीं मिल सकता। उन्हें कुछ भाग संचालकों के लिए भी छोड़ना पड़ेगा। फिर यह भी देखना होगा कि वेतन-वृद्धि के कारण उत्पादन व्यय बहुत न बढ़ जाय, ताकि देश व विदेश के ग्राहकों पर उसका बोझ पड़े। उत्पादन-व्यय बढ़ते ही विदेशी बाजारों में भारतीय माल की मांग बहुत कम हो जायेगी। अनेक अन्य पहलुओं पर भी इस मण्डली ने अपने परामर्श दिये हैं। सम्पदा के इस अंक में भी वेतन की कसौटी के सम्बन्ध में कुछ विचारणीय प्रश्न पाठक पढ़ेंगे। हम श्रम सम्मेलन में उपस्थित सब प्रतिनिधियों से आशा करते हैं कि जहां वे मजदूर वर्ग के हितों की विशेष चिन्ता करेंगे, वहां राष्ट्रीय विकास की आवश्यकताओं, उद्योग की क्षमता तथा ३६ करोड़ नागरिकों के हित का ध्यान भी रखेंगे। मजदूर प्रतिनिधियों की भावुकता और संचालकों के स्वार्थ दोनों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित ही हमारी सर्वोपरि कसौटी होनी चाहिये।

बचत आन्दोलन में कठिनाई

पाठक अन्यत्र श्री शिनाय का लेख पढ़ेंगे। उसमें यह सन्देह ठीक ही प्रकट किया गया है कि जब तक लोगों की वार्षिक आय नहीं बढ़ती, तब तक न बचत बढ़ सकेगी न उसका उपयोग विकास योजनाओं में हो सकेगा। सरकार बचत की योजनाओं पर विशेष बल दे रही है। इसके औचित्य व आवश्यकता पर सन्देह नहीं किया जा सकता, किन्तु प्रश्न यह है कि क्या हम मध्यम आय वाले लोग करों तथा अन्य कारणों से बढ़ते हुए जीवन व्यय को सहन करते हुए कुछ बचत भी कर सकेंगे? आज तो स्थिति यह है कि अधिकांश जनता की आमदनी कम और व्यय अधिक हैं। हमारी आर्थिक स्थिति कितनी हीन है, इसे इस तालिका से भली भांति जाना जा सकता है:—

आय के आधार पर आबादी का वर्गीकरण

परिवार का मासिक व्यय रु०	कुल आबादी (लाख)
१-२५	१४२.२६
२६-५०	४७५.११
५१-१००	१०९१.९८
१०१-१५०	७१२.०१
१५१-३००	७८३.७१
३०१-५००	२४२.०४
५०१-१०००	११४.३१
१००० से अधिक	७.७१
	३५६९.२२

इस तालिका से यह स्पष्ट है कि १४२.२६ लाख व्यक्ति ३ आना दैनिक से भी कम पर, ४७५.११ लाख व्यक्ति ६ आना दैनिक से कम पर और १०९१.९८ लाख १० आने से भी कम पर गुजर करते हैं। ७१२.०१ लाख व्यक्ति १) रु० से भी कम पर गुजर करते हैं। इस स्थिति में देश की जनता से बचत की आशा करना कहां तक आशाप्रद है, यह कल्पना की जा सकती है। तीन माह पहले स्टैटिस्टिकल इस्टीट्यूट ने बम्बई में मध्यम वर्ग के परिवारों का निरीक्षण किया था और वह इस निष्कर्ष पर पहुँची थी कि १५० रु० और ५०० रु० आय वाले वर्ग में एक भी परिवार ऐसा न था, जो अपनी आमदनी से ही सब खर्च पूरा कर लेता हो। सभी परिवारों में खर्च आय से ज्यादा थे। इन तीन वर्षों में खर्च बढ़े ही हैं, कम नहीं हुए। इसलिए यह आवश्यक है कि यदि बचतके आंदोलन में सफलता प्राप्त करनी है, तो ऐसे उपाय खोजने होंगे कि जिससे जीवन व्यय कम हो, वह रत्तीभर न बढ़े।

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

योजना में प्राथमिकता का सुझाव

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आलोचकों का मुख्य और वजनदार तर्क यह था कि योजना अति आकांक्षापूर्ण है। ५ वर्ष की अवधि में अति विस्तृत योजना के लक्ष्यों की पूर्ति असम्भव है। इसके लिए या तो योजना के लक्ष्यों में कमी करनी चाहिए या योजना की अवधि ५ साल से अधिक कर देनी चाहिए। पहले सरकार ने योजना के लक्ष्यों में कमी करना या योजनावधि बढ़ाना—इन दोनों बातों को देश के आत्मसम्मान के विपरीत माना था। लेकिन आयोजना आयोग की अर्थशास्त्रियोंकी समिति के इस सुझाव को सरकार स्वीकार कर लेगी कि योजनाओं को प्राथमिकता के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में बांटा जाये। ऐसा करते समय केवल उन्हीं मदों का ध्यान न रखा जायगा जिनमें विदेशी विनिमय बहुत चाहिए, वरन् उनका भी ध्यान रखा जायगा, जिन मदों में अधिक रुपयों की आवश्यकता होगी। एक तरफ पहले के अनुमानित व्यय से व्यय ८-१० अरब रु० बढ़ गया है, दूसरी ओर योजना निर्माताओं ने जिन संभावित साधनों की कल्पना की थी, उनमें भी ४ अरब रु० की कमी महसूस हो रही है। इसलिये अर्थशास्त्रियों ने यह भय प्रकट किया है कि कुछ और भी ज्यादा महत्त्वपूर्ण योजनाएं या तो छोड़ देनी पड़ेंगी या पर्याप्त व्यवस्था के बिना अधूरी ही रह जायेंगी।

शासन में मितव्यय

नये करों के असह्य होने की शिकायत जनता के सभी वर्गों ने की है। वित्तमंत्री श्री कृष्णमाचार्य ने यह कह कर सान्त्वना देनी चाही कि "द्वितीय योजना के महायज्ञ में प्रत्येक नागरिक को आहुति डालनी चाहिए।" लेकिन जब यह आवाज उठी कि जहां जनता को तप और त्याग का उपदेश दिया जा रहा है वहां समाजवाद के आदर्श से अनुप्रेरित सरकार को, मंत्रियों और बड़े-बड़े अफसरों के मोटे वेतनों में कमी करके, बढ़ते हुए प्रशासन-व्यय पर अंकुश लगाकर व्यर्थ के आडम्बर को दूर करते हुए स्वयं भी मनोवैज्ञानिक वातावरण बनाना चाहिए, तो इस शक्तिशाली तर्क की उपेक्षा न की जा सकी। भले ही अ० भा० कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में केवल ६ मतों से वेतन-कटौती का प्रस्ताव गिर गया, परन्तु पं० नेहरू ने लोकमत का आदर करने का निश्चय कर लिया। वे समझ गये कि उनके प्रति स्नेह और स्वयं मंत्रियों के मत देने से ही यह प्रस्ताव गिरा है, अन्यथा पास हो जाता। इसका परिणाम यह हुआ है कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने स्वेच्छा से अपने वेतनों में १० प्रतिशत कटौती की। राज्यों के मंत्री भी उसका अनुसरण कर रहे हैं। संसद और विधान मंडल भी इसके लिये यत्नशील हैं। प्रधानमंत्री ने स्वयं विदेश स्थित भारतीय दूतावासों को मितव्ययता से कार्य करने को कहा है। प्रत्येक मंत्रालय ने भी अपने विभाग में मितव्ययता के लिये समितियां नियुक्त की हैं। यह भी आशा की जाती है कि बड़े-बड़े अधिकारी भी अपने वेतनों में स्वेच्छा से कमी कर लेंगे। हमारी नम्र सम्मति में ५००) रु० से ऊपर १० प्रतिशत से क्रमशः २५ प्रतिशत तक वेतनों में कमी चाहिए। लेकिन मुख्य प्रश्न तो प्रशासन व्यय में कमी करना है। सरकार ने घोषित किया है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती बंद कर दी जायेगी, लेकिन उच्च श्रेणी के कर्मचारी जैसे सेक्रेटरी, डिपुटी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी आदि की लम्बी कतार में कमी करने की अधिक जरूरत है। शासकों द्वारा मोटर और पेट्रोल के खर्च पर भी अंकुश रखने की आवश्यकता है। इधर प्रत्येक विभाग द्वारा अपनी एक-एक पत्रिका प्रकाशित करने का फैशन चला है, जिनमें अधिकांश बहुत कम आवश्यक हैं। उनके कागज और छपाई पर अनावश्यक व्यय किया जा रहा है। पहाड़ों पर सरकारी कांफ्रेंसों का होना और कर्मचारियों के दलबल के साथ वहां जाना गरीब राष्ट्र के धन का अपव्यय ही किया जायेगा। विदेश-यात्राओं और देश में विभिन्न दौरों पर भारी व्यय काफी कम किया जा सकता है। कोठियों व फर्नीचर के खर्च भी कम हो सकते हैं। शान और आडम्बर का मोह करने वालों को म० गांधी का वह वाक्य स्मरण रखना चाहिए जो उन्होंने १९३१ में लंदन में ब्रिटिश सम्राट् से मिलने जाते समय कहा था कि मैं तो दरिद्रनारायण का प्रतिनिधि हूं, इसलिए उन्हीं के वेश में घुटने तक की धोती व चादर के वेश में सम्राट् से मिलूंगा। हमारे मंत्री व शासक भी जिस भारत के शासक हैं, उसमें प्रति व्यक्ति वार्षिक आय ३००) रु० भी नहीं है। यदि हम इस सत्य को ध्यान में रखेंगे, तो

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

स्वयं खर्च कम हो जायंगे। आज उच्च वर्ग को जीवनस्तर नीचा करने की ओर भारी कदम उठाने होंगे, तभी सफलता मिलेगी।

श्री विद्यलंकार के दो सुझाव

अंतर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन के जिनेवा में होने वाले अधिवेशन में भारत सरकार की ओर से जाने वाले प्रतिनिधि मंडल के नेता श्री अमरनाथ विद्यालंकारने दो बातों की ओर विभिन्न देशों की सरकारों, उद्योगपतियों तथा श्रमिक नेताओं का ध्यान खींचकर बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। वे कहते हैं—"अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की गतिविधियों का क्षेत्र चाहे कितना ही सीमित क्यों न हो, वह एक दर्शक की भांति संसार में होने वाली भीषण घटनाओं को देखकर चुप नहीं बैठा रह सकता। जब विश्व के विभिन्न हिस्सों में विषैली रेडियो-सक्रियता से वायु, जल और भोजन दूषित हो रहा है और समस्त मानवता के विनाश की घोषणा कर रहा है, हमारा यह प्रधान कर्तव्य हो जाता है कि हम विश्व के नेताओं को मानवता का चीत्कार व रुदन सुनावें।" दूसरी बात जिस पर उन्होंने जोर दिया, यह थी कि नयी वैज्ञानिक शक्ति के आविष्कारों के कारण एकाधिकारवाद की ओर उन्मुख प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने का एक सम्भावित तरीका औद्योगिक क्षेत्र में यथासम्भव अधिकतम मात्रामें जनतंत्री तथ्यों को समाविष्ट करने का है। श्रमिकों को उद्योग प्रबंध में भाग देकर उन्हें हम नये सामाजिक दायित्वों का भार वहन करने के लिए आमंत्रित करें। इससे सम्पदा और शक्ति एक स्थान पर केंद्रित न हो सकेगी।

बरमाका अनुभव

एक समाचार के अनुसार बरमा के प्रधान मंत्री श्री ऊ नू ने पिछले वर्षों में की गई भारी भूलों को स्वीकार करते हुए उच्च अधिकारियों को बरमा के लिए नई चतुर्वर्षीय योजना बनाने की सलाह दी है। उन्होंने अपने को भी अपराधी मानते हुए कहा कि अमन व कानून की स्थापना पर बल देने के बजाय बिना किसी अनुभव के हम उद्योगीकरण में लग गये। अब हमें फिर से नई योजना बनानी चाहिए और नफे के उद्देश्य से खनिज तथा अन्य उद्योग देश में प्रारम्भ करने चाहिएं। यह जरूरी नहीं है कि देश की अर्थव्यवस्था पर सरकार ही छा जावे। सरकार उद्योगों को चोरों व उचक्कों के हाथों में नहीं सौंपना है। बरमा सरकार की नई अर्थ नीति के अनुसार कुछ उद्योग सरकार ही चलायगी, कुछ उद्योग सरकार, नागरिकों और विदेशियों के सहयोग से चलेंगे, कुछ उद्योग सरकार विदेशियों के सहयोग से चलायगी और कुछ नागरिक विदेशियों के सहयोग से। लेकिन सरकार थोड़े से प्रधान उद्योग ही चलायेगी, शेष सब निजी व्यवसायियों के लिए खुले रहेंगे। बरमा सरकार अपने कुछ वर्षों के अनुभव के बाद नयी अर्थ नीति चलाने पर विवश हुई है। हमें भी अपनी उद्योगनीति निर्धारित करते हुए भावुकता की बजाय व्यावहारिकता का ध्यान अधिक रखना चाहिए।

उदारता की ओर

'सम्पदा' के पाठकों का ध्यान हम मास्को रेडियो के इस समाचार की ओर आकर्षित करना चाहते हैं—सोवियत सरकार ने एक आदेश जारी कर उस नियम को खत्म कर दिया है, जिसके अन्तर्गत सामूहिक कृषि कार्यों के सदस्यों को अपना माल अनिवार्य रूप से सरकार को देना पड़ता था। यह आदेश १ जनवरी १९५८ से अमल में आयेगा। निर्णय में कहा गया है कि सन् १९५३ में सामूहिक एवं सरकारी कार्यों का उत्पादन बढ़ जाने के कारण सामूहिक कृषकों, कर्मचारियों और नौकरों द्वारा सरकार को अनिवार्य रूप से दी जाने वाली पैदावार की निम्नतम मात्रा में कटौती कर दी गई थी। अब यह सम्भव है कि सरकार को दिया जाने वाले कृषि-उपज के अनिवार्य भाग को बिलकुल खत्म कर दिया जाय।" इस समाचार से ऐसा प्रतीत होता है कि रूस के नेता अब पहले की अनिवार्य कठोरताओं को शिथिल करना चाहते हैं और व्यक्ति को अधिकाधिक स्वाधीनता देने की दिशा में विचार कर रहे हैं।

विज्ञापन का महत्व

भारत के प्रमुख उद्योगपति श्री धर्मसी एम० खत्ताऊ ने अपने एक भाषण में कुछ महत्वपूर्ण अंक दिये हैं। इंग्लैंड के उद्योग विज्ञापनों पर प्रति वर्ष तीन हजार लाख पौंड व्यय करते हैं, अर्थात् प्रतिदिन दस लाख पौंड

(शेष पृष्ठ ४१९ पर)

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वेतनों के निर्धारण का आधार क्या हो ?

श्री कृष्णचन्द्र विद्यालंकार

हाल ही में डाक व तार कर्मचारी संघ ने वेतन वृद्धि के लिए हड़ताल करने की राय दी है। श्रमजीवी पत्रकारों के लिए वेतन नियत भी किये गये हैं, सूती मिलों के लिए एक वेतन बोर्ड नियत किया गया है। दूसरे उद्योगों में तथा सरकारी या गैर सरकारी दफ्तरों में भी वेतन-वृद्धि का प्रश्न विकट रूप से उपस्थित है। इसी सम्बन्ध में कुछ विचारणीय महत्त्वपूर्ण प्रश्न इस लेख में उपस्थित किये गये हैं।

अभी बहुत समय नहीं हुआ, भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक कमीशन ने यह निर्णय दिया था कि विभिन्न नगरों में काम करने वाले बैंक-कर्मचारियों के वेतन नगरों के महंगे जीवन स्तर तथा बैंकों के लाभ की दृष्टि से नियत किए जायें।

कुछ समय बाद बीमा कम्पनियों के कर्मचारियों ने यह आवाज उठाई कि बीमा कम्पनियाँ बहुत लाभ उठाती हैं, इसलिए उनके वेतन भी बढ़ाये जायें।

रेलवे-कर्मचारी भी रेलवे द्वारा होने वाली भारी सरकारी आय को लक्ष्य में रखकर वेतन वृद्धि की मांग वर्षों से करते रहे हैं और इसमें सन्देह नहीं कि उनकी यह मांग एक सीमा तक पूरी भी हुई है।

युद्ध के वर्षों में जब विभिन्न उद्योग खूब नफा कमा रहे थे और उधर मंहगाई बढ़ रही थी, तो एक तरफ बढ़ती हुई मंहगाई के नाम से कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ाया गया, दूसरी ओर प्रति वर्ष होने वाले भारी मुनाफे में हिस्सा बटाने के लिए मजदूरों ने बोनस की मांग की और यह बोनस इतना अधिक दिया गया कि वर्ष में तीन-तीन, चार-चार मास तक का वेतन कर्मचारियों को मिला।

हाल ही में भारत सरकार ने श्रमजीवी पत्रकारों के वेतन उद्योग की आमदनी के अखबारों की कुल आमदनी के—क्रम से बढ़ाने की घोषणा की है, जिसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा चुकी है।

यह कुछ उदाहरण हैं, जब वेतन वृद्धि की मांग इस आधार पर की गई कि उद्योग का नफा लगातार दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है।

\+ + + +

कुछ और उदाहरण लीजिए। कुछ वर्ष पहले उत्तर-प्रदेश में पटवारियों ने वेतन वृद्धि के लिए हड़ताल की थी और इसमें थोड़ी बहुत सफलता भी प्राप्त की थी।

देहली, उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा सम्भवतः कुछ अन्य राज्यों में भी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालयों के अध्यापकों ने वेतन-वृद्धि के लिए आन्दोलन, प्रदर्शन और हड़तालें की थीं। इसमें सन्देह नहीं कि प्रायः सभी राज्यों में अध्यापकों को शानदार सफलता प्राप्त हुई। समय-समय पर मंहगाई के कारण वेतन या मंहगाई भत्ता बढ़ाने के लिए आन्दोलन आम बात है। यह उदाहरण इस बात के हैं कि बढ़ते हुए जीवन व्यय के कारण कर्मचारियों के वेतन बढ़ाये गये। इनमें मांग का आधार यह नहीं है कि उनकी विनियोजक संस्थाएं बहुत नफा कमा रही हैं, इसलिए वेतन बढ़ाया जाय। वे अपना जीवनस्तर कायम रखते हुए अपना गुजारा कर सकें, उनकी मांग का यही आशय है। मिल मजदूरों के यूनियन भी मंहगाई के कारण वेतन-वृद्धि का आन्दोलन करते हैं।

\+ + + +

वेतनों के स्तर नियत करने का तीसरा आधार यह है कि योग्यता और कार्य की प्रकृति के आधार पर वेतन दिए जायें। एक दक्ष उच्च शिक्षित और कुशल कारीगर कर्मचारी या अध्यापक अथवा अधिकारी को अधिक वेतन दिए जाते हैं और कम दक्ष या कुशल कारीगर को कम। शिक्षणालयों में, दफ्तरों में, उद्योग और व्यापार की कम्पनियों में सर्वत्र इसी नियम का प्रचलन है। अदक्ष मजदूर बहुत ज्यादा मिलते हैं, इसलिए उनको वेतन भी कम मिलते हैं। बैलगाड़ी व मोटर ट्रक के ड्राइवर के वेतन क्रमशः बहुत कम व बहुत अधिक होते हैं।

उत्पादन की मात्रा के आधार पर भी वेतन देने की

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रथा बहुत प्रचलित है। छापाखानों व मिलों में पीस वर्क या ठेके की प्रथा में श्रमिक अधिक से अधिक काम करके सुस्त से सुस्त काहिल व अयोग्य कर्मचारियों की अपेक्षा अधिक कमाते हैं। विनियोजक इसी प्रथा के समर्थक हैं। 'जितना काम उतना दाम' का नियम मेहनत व ईमानदारी से काम करने की प्रेरणा देता है। ईमानदार या निकम्मे कारीगर को एक सा वेतन श्रमिक को कोई प्रेरणा व उत्साह प्रदान नहीं करता और फलतः उत्पादन गिर जाता है।

\+ + + +

वेतन-निर्धारण के इन आधारों के अतिरिक्त एक और आदर्श भी हमारे सामने रखा जाता है और वह है साम्यवाद के अनुसार समानता का। इसके अनुसार कर्मचारी की योग्यता नहीं, उद्योग का लाभ नहीं, कार्य की विशेषता नहीं, मांग और उपलब्धि का सामान्य सिद्धान्त भी नहीं, केवल कर्मचारी की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। इस आदर्श के अनुसार समस्त मानव समान हैं और उनकी आवश्यकताएं भी एक समान हैं। जहां भी कोई व्यक्ति कार्य करता है, उसकी आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिएं। वह कार्य छोटा हो या बड़ा हो, उसके लिए दक्षता जरूरी है या नहीं, उसकी चिन्ता किये बिना उस मानव की आवश्यकताएं देखनी चाहिएं। इसके अनुसार पांच बच्चों के बाप मेहतर को अधिक वेतन मिलेगा और दो बच्चों के बाप कालेज के प्रोफेसर को कम तथा एक बड़े अविवाहित इंजीनियर को और भी कम। मानवता के सिद्धान्त का यह चरम विकास है। इसमें यह मान लिया जाता है कि प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताएं एक समान हैं तथा प्रत्येक का जीवन-स्तर भी एक समान होना चाहिए।

यह कुछ आधार हैं, जिन पर किसी कर्मचारी या मजदूर का वेतन निर्धारित किया जाता है या करने की मांग की जाती है। भारत सरकार के सामने वेतन-निर्धारण की कसौटी का प्रश्न उपस्थित है। वह समय समय पर न्यूनतम वेतन निर्धारित करती रही है, जिसका आधार जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उद्योग या विनियोजक द्वारा देने की क्षमता माने गए हैं। उचित वेतन क्या है, यह आधारभूत विचार भी स्वयं विवादास्पद प्रश्न है। देश की कुल राष्ट्रीय आय निकाल कर प्रति व्यक्ति जो आय बैठती है, उससे मजदूरोंकी आमदनी आज बहुत ज्यादा निकलती है।

× × ×

विचारणीय प्रश्न यह है कि वेतनोंके उपयुक्त आधारों में से कौनसा स्वीकार होना चाहिए। इस प्रश्न पर विचार करते हुए जो दुविधायें उत्पन्न होती हैं, उन्हें कुछ अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता है। उद्योग की क्षमता को मुख्य आधार माना जाय तो इसका अर्थ यह होगा कि एक छोटे अपरिगणित (un-scheduled) बैंक के ज्यादा मेहनती कर्मचारी को कम पैसा मिलेगा और पंजाब या सेन्ट्रल बैंक के कर्मचारी को, जो उससे कम परिश्रमी और ईमानदार हो सकता है, अधिक वेतन मिलेगा। 'अर्जुन' या कानपुर के 'प्रताप' में काम करने वाले पत्रकार को, जिस पर कार्य का भार साधनों की कमी से बहुत ज्यादा आ जाता है, वेतन कम मिलेगा और नव भारत टाइम्स या हिन्दुस्तान टाइम्स के पत्रकार को, जहां साधनों की सुविधा तथा कर्मचारियों की अधिक संख्या के कारण काम का बोझ अपेक्षाकृत बहुत हल्का होता है, अधिक वेतन मिलेगा। इसका कारण पत्रकार की अपनी विशेषता नहीं, बैंक या पत्र के संचालक की अधिक धन सम्पन्नता तथा व्यापार-संगठन और व्यवहार कुशलता है। फिर पत्रकार को ही अधिक वेतन क्यों मिले, उसके सहकारी, प्रसार या विज्ञापन क्लर्क को क्यों नहीं, जिसका पत्र की आय बढ़ाने में विशेष भाग है। सरकारी पत्र पत्रिकाओं के सम्पादकीय विभाग को क्यों सब वेतनों से वंचित रखा गया? यदि उद्योग की आमदनी को ही वेतन निर्धारण का आधार माना जाय, तो रेलवे का एक मैट्रिक या इंटर क्लर्क ज्यादा वेतन पा सकता है और निरन्तर घाटा बर्दाश्त करने वाला शिक्षा विभाग अपने उच्च शिक्षा प्राप्त कर्मचारी को कम वेतन देगा। स्वास्थ्य-विभाग के योग्य डाक्टर को भी कम वेतन दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसका विभाग कमाने वाला नहीं है।

× × ×

इसमें सन्देह नहीं कि न्यूनतम जीवन व्यय के सिद्धान्त की उपेक्षा नहीं की जा सकती। प्रत्येक नागरिक को अपने

[समस्त

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जीवन यापन का अधिकार है और उसके लिए उसे आवश्यक वेतन मिलना ही चाहिए, लेकिन यहां फिर एक पेचीदा सवाल पैदा हो जाता है कि आवश्यक जीवन स्तर की कसौटी क्या है, १०० रु०, १५० रु० या अधिक ? एक सूती कपड़े की मिल में बुनकर को कताई विभाग के श्रमिक से अधिक वेतन मिलता है और कभी किसी ट्रेड यूनियन ने इस असमानता को दूर करने की आवाज उठाई हो, यह हमें मालूम नहीं। एक मिस्त्री मामूली मजदूर से ज्यादा मजदूरी पाता है, क्योंकि वह अधिक योग्य और उपयोगी माना जाता है। साम्यवादी आदर्श के देश रूस में भी यह असमानता पाई जाती है। वहां मजदूरी का स्तर उद्योग और श्रम की अवस्थाओं पर निर्भर करता है। भूगर्भ में काम करने वाले (कोयला तथा धातु की खानों में काम करने वाले) खनकों की मजदूरी सबसे ज्यादा है। उनकी औसत मासिक मजदूरी उनकी दक्षता के अनुसार, १५०० से ३००० रूबल प्रतिमास है। इंजिनियरिंग या धातुशोधक उद्योगों में गरम खातों में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी १००० से २५०० रूबल तक है। हलके और खाद्य-उद्योगों में जहां श्रम की अवस्थाएँ कहीं आसान हैं. प्रति व्यक्ति मासिक मजदूरी की दर ५०० से १३०० रूबल प्रतिमास है। इससे अधिक मजदूरी केवल वे ही मजदूर प्राप्त करते हैं, जो बहुत ही दक्ष हैं।

मांग और उपलब्धि के अनुसार ही श्रमिक का पारिश्रमिक नियत होता है, देने वाले की क्षमता पर नहीं। एक मजदूर मकान बनाने वाले अमीर से उतनी ही मजदूरी लेता है, जितनी गरीब मकान मालिक से। एक किसान ग्राहक की क्षमता देखकर मूल्य नहीं लगाता, वह अमीर गरीब सभी को एक ही भाद अनाज बेचता है। किसान के अनाज की तरह मानव का परिश्रम भी आज रुपए से नापा जाता है, इसलिए आज यह विचारणीय प्रश्न है कि मजदूरी या वेतन का निर्धारण किस आधार पर हो। दिल्ली में एक सा काम करने वाला पत्रकार, क्लर्क या मजदूर अलग अलग वेतन ले या एक समान ?

× × ×

कपड़े की मिलों में कुछ मिलें ऐसी होती हैं जिनके संचालक अयोग्य अथवा साधनहीन होते हैं और वे मिलें घाटा उठाती हैं। उन मिलों में काम करने वालों को बोनस नहीं मिलता या बहुत कम मिलता है। क्या यह न्याय है ? इस भेद को दूर करने का उपाय भी सोचा गया है कि एक नगर की सब मिलों का लाभ मिलाकर सब मिलों के कारीगरोंको बोनस बांटा जाय। यदि ऐसा किया गया, तो दिल्ली के सब बड़े छोटे अखबारों की आमदनी का अनुपात से एक भाग निकाल कर वह सभी अखबारों के कर्मचारियों को बांटा जायगा। इसे पूल सिस्टम कह सकते हैं। पर कोई संस्थान अपनी कमाई दूसरे संस्थान के कर्मचारियों को क्यों देना चाहेगा ?

× × ×

हमें ऐसा स्मरण आता है कि आज से कुछ वर्ष पूर्व एक सर्वोदयी नेता ने इन्दौर के मजदूरों को यह राय दी थी कि मिलों में होने वाले भारी लाभ में, जो वे कपड़े का ज्यादा मूल्य लेकर अनुचित रूपसे कमाती हैं, बोनस की मांग करके मजदूर ग्राहक के शोषण में स्वयं हिस्सेदार न बनें। अनुचित रूप से कमाये गये नफे में से बोनस या नके का भाग लेने का अर्थ यह है कि मजदूर भी जनता के शोषण में भागीदार होना चाहते हैं। उस नेता ने यह राय दी थी कि मिलों को इतना नफा ही नहीं कमाना चाहिए कि वे उचित से अधिक डिविडैण्ड शेयर-हौल्डरों में बांट सकें और मजदूर बोनसों की मांग कर सकें, क्योंकि यह दोनों ही—मालिक व मजदूर—गरीब ग्राहक की जेब पर बोझ डालते हैं। मिल मालिकों को कपड़े की कीमत कम करके सीमित लाभ ही लेना चाहिए। भारत सरकार ने कपड़े की मिलों में वेतनों के निर्धारण के लिए एक बोर्ड नियुक्त किया है और चीनी की मिलों के लिए भी एक बोर्ड नियुक्त किए जाने वाला है। आशा करनी चाहिए कि यह बोर्ड इस दृष्टि से भी विचार करेगा।

× × ×

हमारी नम्र सम्मति में अब वह समय आ गया है जब हम किसी पक्षपात अथवा अपनी दृढ़ धारणाओं पर आग्रह के बिना यह विचार करें कि वेतन निर्धारण की असली कसौटी क्या होनी चाहिए। विनियोजक की क्षमता हो, अथवा न्यूनतम या उचित जीवन स्तर हो ? पिछले दिनों मन्त्रियों के भारी वेतनों की बहुत चर्चा रही है और

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारतीय कृषि के लिए धन

श्री जी० एस० पथिक

कृषि के ऋण की श्रेणियां

व्यापार का संचालन पूंजी से होता है, और अधिकांश में पूंजी उधार मिली होती है। कृषि का धंधा भी इस दायरे से नहीं बचा है। सम्पूर्ण जगत की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का यह एक आम अनुभव है कि किसानों को ऋण लेना पड़ता है। यह सच है कि अमेरिका जैसे समृद्धिशाली देश के किसानों की अवस्था भारतीय किसानों की अवस्था से जुदी है।

किसान को धन की आवश्यकता बीज, खाद, औजार, पशु और जमीन खरीदने के लिए पड़ती है। इस देश में किसान को जीवन निर्वाह के लिए भी ऋण लेना पड़ता है। उसका पुराना ऋण भी नए ऋण से चुकता है। इस के लिए साहूकार के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। साहूकार उसे सदा ऋण देने को तत्पर रहता है। पर उसकी ब्याज की दरें और ऋण देने और रकम वापस लेने के तरीके किसान को चूसने वाले होते हैं। किसानों को ऋण तथा उधार में आवश्यक पदार्थों की आमद करने के लिए बहु-लक्षीय कृषि सहकार समितियों का निर्माण हुआ है, किंतु उनके ऋण का अंश ३.१ प्रतिशत से अधिक नहीं है। कृषि के लिए तीन प्रकार के ऋण होते हैं। किन्हीं अवस्थाओं में किसानों की असमर्थता के कारण ऋण लौटानेकी आशा नहीं की जा सकती है। दूसरी अवस्थाओं में ऋण चुकाने की दृष्टि से किसानों की अवस्था सुधारने पर आंशिक रूप में ऋण के लौटने की सम्भावना रहती है। इसके उपरांत अन्य परि-स्थितियों में मूलधन और ब्याज दोनों ही चुकाए जाते हैं।

तीसरी श्रेणी के ऋण पर अधिक जोर दिया गया है। केवल भारत में ही ये अवस्थाएं नहीं हैं, बल्कि सारे संसार में यही होता है। यह मानना पड़ेगा कि किसानों के पुनःस्थापन के लिए प्रथम दो श्रेणियों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। अच्छे बीजों के उपयोग के लिए किसानों का ऋण पहला स्थान रखता है। किसानों को बिना किसी अतिरिक्त व्यय के प्रथम श्रेणी के बीज देने चाहिए, यदि वे अपने खेतों में उपयोग करने के लिए रजामंद हों। बीज और उपज रखने के लिए गोदामों के निर्माण आवश्यक हैं। खाद रखने के लिए भी गोदाम चाहिए। ये ऋण दूसरे प्रकार के हैं। इनके निर्माण में जो रुपया लगे, उसके लौटने की आशा नहीं की जा सकती है। अलबत्ता लम्बी मुद्दत का ऋण होने पर थोड़ा-थोड़ा प्रति-वर्ष लौट सकता है। ग्रामीण क्षेत्र और मंडियों में अनाज रखने के लिए अनाज और कच्चा माल तथा अन्य कृषि उत्पादन रखने के लिए गोदामों का होना अनिवार्य है। इससे आमद और खपत की दृष्टि से किसानों को अच्छे

जनता के बड़े भाग की ओर से यह मांग की जा रही है कि उनके वेतन कम कर दिये जाने चाहियें, परन्तु केन्द्र, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश या बम्बई आदि किसी राज्य के मन्त्रियों पर समस्त राज्य की शिक्षा, उद्योग, वित्तीय व्यवस्था आदि का गुरु भार होते हुए भी जितना वेतन उसे मिलता है, क्या निजी या सरकारी उद्योग, एक बैंक या कम्पनी के बड़े कर्मचारी को उससे भी अधिक वेतन मिलना चाहिए? फिर यह भी सोचना है कि वेतनों का स्तर योग्यता हो या मांग और उपलब्धि का सामान्य अर्थशास्त्रीय नियम? यदि इस नियम को हम स्वीकार कर लें तो देश में बढ़ती हुई बेकारी का विनियोजक अनुचित लाभ अवश्य उठायेंगे। साम्यवाद का ऊँचा आदर्श सबको एक समान समझकर आवश्यकता के अनुसार वेतन देने का आदर्श अभी तक रूस में भी चालू नहीं हो सका। यहां भी उसकी कोई मांग अभी तक नहीं उठाई गई, इसलिए इसका प्रश्न ही नहीं उठता। हमें विश्वास है कि वेतन निर्धारण के महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करते समय यह भी अवश्य ध्यान में रखा जायगा कि वेतनों का स्तर इतना ऊँचा न हो कि अल्प साधन वाले नागरिक अपना नया कार्य प्रारम्भ ही न कर सकें। आज नये नियमों व निर्णयों से यही स्थिति आ रही है।

——

[सम्पादक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दामों में माल बेचने में सहायता मिलती है। ऊंचे दामों में उपज बिकने पर किसानों की आय बढ़ती है, और तब उनमें पूंजी लौटाने की क्षमता आती है।

पहले दो प्रकार के ऋण देना राज्य का कार्य है। ये काम प्रायः ऋण के अन्तर्गत नहीं आते हैं। यह आर्थिक सहायता है, जिसे किसान आमद बढ़ने पर लौटाते हैं।

ऋण के स्रोत

कृषि के लिए ऋण देने के निम्नलिखित स्रोत हैं—

(१) साहूकार, महाजन, जमींदार तथा किसान भी

(२) सहकारी समितियां, जिनमें ऋण देने वाली समितियां, जमीन बंधक रखने वाले सहकारी बैंक, विक्रय-समितियां भी।

(३) व्यापारिक बैंक, जिनमें रिजर्व बैंक तथा नया राज्य बैंक शामिल है।

(४) राज्य।

सहकारी समितियां और ऋण

इन सब स्रोतों में सहकारी ऋण समितियां महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, जो किसानों को साधारण ब्याज पर ऋण देती हैं। व्यापारी बैंक—अर्थात् रिजर्व बैंक और राज्य बैंक से भी साधारण ब्याज पर रुपया मिल सकता है। अन्य व्यापारी बैंक भी कृषि में विनियोजन कर सकते हैं। पर स्थिति यह है कि सहकारी समितियां और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें तो थोड़ी मदद करती हैं, किंतु व्यापारी बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में विनियोजन करने से दूर हैं। भारत में बैंकों ने २२०७ कार्यालय ऐसे कस्बों में हैं, जिनकी आबादी पचास हजार या इससे अधिक है। किंतु ५५८ ऐसे कार्यालय हैं, जहां की जनसंख्या दस हजार या इससे भी कम है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की गतिविधि नहीं है। व्यापारी बैंकों का कृषि में सीधा विनियोजन एक प्रतिशत से भी कम है। अतएव व्यापारी बैंकों का ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती दरों में विनियोजन एक पेचीदी समस्या है। अभी ऐसा वातावरण उत्पन्न नहीं हुआ कि व्यापारी बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में कारोबार कर सकें।

बैंक-स्रोतों का उपयोग

इस सम्बन्ध में ब्रिटिश बैंकिंग प्रथा का अध्ययन उपयोगी है। इंग्लैण्ड में 'पांच बड़े' व्यापारी बैंक हैं, जिनकी शाखाएं सारे देश में हैं। व्यापारी बैंक नगरों में व्यापार और उद्योगों के लाभजनक साधनों में आसानी से रुपया लगाते हैं। यहां उन्हें अधिक मुनाफा मिलता है। इसलिए उनकी सारी शक्तियां व्यापार और उद्योगों की आवश्यकताओं तक सीमित रहती हैं। इन क्षेत्रों में जोखिमों के संबंध में उन्हें अंधकार में नहीं रहना पड़ता है, ऋण के अमानत में सम्पत्ति बंधक होती है। पर ग्रामीण क्षेत्रों के विनियोजन में ये सुविधाएं कहां हैं? यही कारण है कि व्यापारी बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में आगे नहीं बढ़ते हैं। किसानों की ऋण चुकाने की क्षमता, उपयुक्त गारंटी देने की असमर्थता और मूलधन और ब्याज के लौटने की अनिश्चितता आदि कारण हैं, जिनसे व्यापारी बैंक ऋण देने का साहस नहीं करते हैं। उनकी चल और अचल जो भी सम्पत्ति होती है, उससे रुपया लौटना कठिन होता है।

अतः व्यापारी बैंकों के आगे न आने पर साहूकार और महाजनों का आश्रय लेना पड़ा। व्यापारी बैंकों की अपेक्षा वे उनके द्वार पर बसते हैं। महाजन या साहूकार किसानों को हर समय आसानी से रुपया देते हैं, और वे यह भी नहीं पूछते हैं कि ऋण किस काम के लिए हैं। किसानों की विपत्तियों के समय भी वे ऋण देते हैं। पर बैंकों से यह कब संभव है। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापारी बैंक प्रसार पा सकते हैं, यदि नयी अर्थ-व्यवस्था में किसान अपनी आय का रुपया बैंकों में जमा करने लगें। पर किसान नकद रुपया अपने पास जमा रखना अधिक पसंद करते हैं।

राज्य बैंक की ग्रामों में शाखाएं

इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण होने पर जिस राज्य बैंक की स्थापना हुई, उसका क्षेत्र अपनी शाखाओं सहित ग्रामों में विनियोजन का है। यह बैंक अपनी ४०० शाखायें ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित कर किसानों के लिए ऋण की उपलब्धि सुलभ करेगा। राज्य बैंक की शाखाएं, सहकारी ऋण समितियां तथा छोटे-बड़े व्यापारी बैंकों की शाखाओं के ग्रामों में विस्तार की अत्यंत आवश्यकता है। ग्रामों के क्षेत्र में बैंकिंग व्यवस्था का जितना विस्तार होगा, उतना ही कृषि का विकास संभव होगा। उस अवस्था में कृषि का

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

धंधा भारवत नहीं रहेगा। किसानों की आर्थिक अवस्था भी सुधरेगी। वे भी अपनी नकद आमद बैंकों में रखने के अभ्यस्त होंगे। आज देश की पूंजी का प्रवाह मुड़ गया है। नगरों की अपेक्षा ग्रामों में अधिक धन जाने लगा है। किसानों का रुपया यदि बैंकों में जमा होने लगे, तो बैंकों की आमद आज से कई गुना अधिक बढ़ जाए। घर में नकद रुपया रखने से किसान उसका दुरुपयोग करता है, और फिर आवश्यकता पड़ने पर उसे साहूकार के पास जाना पड़ता है। यही कारण है कि समष्टि रूप में उनकी आर्थिक अवस्था नहीं सुधरती है। सोना चांदी खरीदने, अन्य पदार्थ खरीदने तथा धार्मिक एवं सामाजिक रूढ़ियों के पालन में उनका रुपया लग जाता है। उन्हें यह भान नहीं रहता कि वे यह क्या करते हैं। फिर प्रथाओं के आदी होने पर वे इन कामों के लिए ऋण तक लेते हैं और साहूकार आसानी से देते हैं। एक तो साहूकार के ब्याज की दर ऊंचे-सी-ऊंची होती है, दूसरे वह अपना मूलधन पाने के लिए फसल पर अधिकार कर लेता है या जमीन बंधक में रख लेता है। सहकारी समितियां और व्यापारी बैंकों के लिए इस तरह ऋण देना कब संभव है। पर यदि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों और समितियों का व्यापक प्रसार हो, और किसान रुपया जमा करने के लिए आकर्षित हों, तो जहां वे धन बचा पाएंगे वहां सामाजिक कुप्रथाओं से भी मुक्ति पा लेंगे।

व्यापारी बैंकों की अड़चनें

पर व्यापारी बैंकों के लिए यह असुविधा है कि वे छोटे-छोटे स्थानों पर कैसे अपनी शाखाएँ खोलें। शाखाओं के संचालन-व्यय की पूर्ति के लिए उन्हें काफी काम मिलना चाहिए। पर ग्रामों में इसकी अनिश्चिता रहती है। इसके सिवाय आज बैंकों का व्यय बढ़ गया है। बैंक ट्रिब्यूनलों के एवार्डों के कारण शाखाओं के संचालन में भी व्यापारी बैंकों को भारी व्यय करना पड़ता है। यदि कृषक वर्ग अपना नकद रुपया बैंकों में जमा करने लगे और अपने सारे लेन-देन तथा कारबार बैंकों के द्वारा करे, तो शाखाएं ठहर सकती हैं। व्यापारी बैंकों ने शाखाएं खोलने के प्रयत्न भी किए, किन्तु उन्हें क्षति उठानी पड़ी, क्योंकि किसान अपना नकद रुपया बैंकों में जमा करने के लिए आगे नहीं आये। इससे अनेक बैंकों को घाटा उठाना पड़ा।

बैंकों की ग्रामीण शाखाएँ

यदि ग्रामों में बैंकों की शाखाएं खुलें, तो उन्हें विशेष सुविधाएं दी जाएँ। जब तक ग्रामीण क्षेत्रों के बैंकों की अर्थ-व्यवस्था संतुलित न हो, और वे साधारण बचत करने लगें, तब तक उन पर श्रम-ट्रिब्यूनल एवार्ड लागू न हों। ग्रामीण शाखाओं को मजदूरी या वेतन में छूट दी जाए और अमेरिका की तरह रकम जमा करने वालों से जमा करने के एवज में किसी प्रकार की गारंटी की जाए। यह गारंटी बीमे के रूप में हो। डिपाजिटरों के लिए यह बीमा गारन्टी के रूप में होगा कि बैंक के फेल होने पर उनका धन सुरक्षित रहेगा और वापस दिया जायगा। ये सभी विशेष प्रयत्न किए जाने चाहिए।

डिपाजिट बीमा कारपोरेशन

राज्य बैंक के निर्माण के साथ डिपाजिट बीमा कारपोरेशन के खुलने की भी आवश्यकता है, जिसमें रिजर्व बैंक और व्यापारी बैंकों की पूंजी लगे। यह कार्पोरेशन देश के सभी बैंकों से प्रीमियम की रकम संग्रह करे और उसे अमानत में ग्रामीण क्षेत्र की शाखाओं में रकम जमा करने वालों को किसी हद तक रकम की जोखम का बीमा दे। इस योजना से बैंकों की अर्थ-व्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, किन्तु इससे उन लोगों का भय दूर होगा, जिनके पास रुपया है। वे यह सुरक्षा पाकर अपना धन बैंकों में जमा करने के लिए प्रोत्साहन पाएंगे। जैसे-जैसे बैंकों की स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत होगी, उनमें अधिकाधिक रुपया जमा होगा। लम्बे समय में प्रीमियम के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति होना कठिन न होगा। हर जगह तो शाखाएं भी नहीं खोली जा सकती हैं, इसलिए चलती-फिरती बैंक शाखाएं भी होनी चाहिए। हफ्ते में एक बार ग्रामों में जाएं और डिपाजिटों की रकम जमा लें। ग्रामों में बचत करने के लिए प्रोत्साहन देने के लक्ष्य से चलते-फिरते बैंकों का प्रसार होना उपयोगी है।

(शेष पृष्ठ ३८८ पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बचत और दूसरी पंचवर्षीय योजना

प्रो० श्री बी० आर० शिनौय

इस लेख के लेखक योजना आयोग द्वारा नियत अर्थशास्त्री मण्डल के एक सदस्य थे। उनकी निश्चित सम्मति यह थी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की पांच वर्षों में पूर्ति व्यावहारिक व संभव नहीं है। उन्हीं के विचार पूर्ण लेख का एक अंश यहां दिया जा रहा है:—

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में सरकारी अनुमान के अनुसार १६०० करोड़ रु० योजना पूर्ति पर व्यय होगा। परन्तु योजना आयोग के अनुसार नियत राशि के ७५ प्रतिशत से यह अधिक नहीं है, पर दूसरी ओर यह बताया जा रहा है कि सरकार योजना के लक्ष्यों से इंच भर भी हटने वाली नहीं है, भले ही कितनी कठिनाइयां आवें। इसका अर्थ यह है कि भविष्य में बजट और भी बढ़े होंगे। पर बजट सिर्फ बड़े प्रभावशाली शब्दों से नहीं बन सकते। उसके लिए साधन जुटाने पड़ते हैं। अब जो कमी है, वह सरकारी क्षेत्र द्वारा पूर्ण की जाने वाली योजना में ही है। यदि आज सरकार निजी उद्योग के भी सभी स्रोत छीनकर अपने उपयोग में ले आवे, तो भी उसे २५०० करोड़ रु० की कमी रहेगी।

हमें यह महत्त्वपूर्ण सत्य नहीं भूलना चाहिए कि आर्थिक विकास विनियोजित बचत का ही एक परिणाम होता है। लोकतंत्र व निरंकुश साम्यवाद में एक अन्तर यह होता है कि साम्यवाद में तो जनता को सरकारी कानून के द्वारा जबर्दस्ती बचत करने के लिए, खाद्य वस्त्रादि का उपयोग कम करने के लिए लाचार किया जा सकता है, परन्तु लोकतंत्र में यह संभव नहीं है। यहां व्यक्ति को अपने जीवन स्तर को कम करने के लिए, अपनी जरूरतों की सरकारी आर्डर के अनुसार नियत करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। हमें तो यह अनुमान लगाना होगा कि जनता कुल कितनी बचत कर सकती है और तब अपने विनियोजन का हिसाब लगाना होगा। कठिनाई यही है कि हम साम्यवादी देशों की विचार धारा को लोकतंत्रीय देश में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं।

बचत ही आर्थिक विकास का कारण होती है, पर हमारे देश में बचत बहुत होती है। यहां प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति बचत दोनों ही कम होते हैं। अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय ७७५) रु० प्रतिमास है। इंगलैंड में ४१३ रु० है। जबकि प्रथम योजना के अन्त में भारत में २३.४२ रु० प्रति मास आय थी। हम जो कुछ चाहें—योजना, जीवनस्तर का ऊंचा करना, समाजवादी समाज का संगठन, सभी कुछ पूरा करना इसी प्रति व्यक्ति आय से ही होगा।

हमारी प्रति व्यक्ति बचत का दर क्या है? अमेरिका में १९५० में बचत की दर राष्ट्रीय आय का १५ प्रतिशत थी और वहां कुल १७,१३६ करोड़ रु० बचत हुई थी। यह बचत ही कुल भारत की राष्ट्रीय आय से करीब दुगुनी है। हमारी बचत ५७२ करोड़ रु० है। यही आधारभूत वस्तु है जिस पर हमें योजना का निर्माण करना है, क्योंकि बचत का आर्थिक विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। १९४८-१९५५ की अवधि में भारत की राष्ट्रीय आय २५ प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ी, जबकि अमेरिका में आर्थिक विस्तार की दर ४.९ प्रतिशत थी। इसका कारण यह है कि वहां बचत बहुत होती है और वे उसका उद्योगों में विनियोजन कर सकते हैं। यदि हमारी बचत कम होती है, तो हमारा विनियोजन भी कम होता है।

हमारे स्रोत क्या हैं? सरकारी अनुमान के अनुसार पांच वर्षों में ४५६० करोड़ रु० बचत से प्राप्त हो सकते हैं। यह अनुमान करते समय यह मान लिया गया है कि हम १९६०-६१ में ८ प्रतिशत बचाने लगेंगे और हमारी आय २० प्रतिशत बढ़ जायेगी। ९०० करोड़ रु० विदेशी सहायता और ३०० करोड़ मुद्रा संचित निधि से वापसी। इस तरह कुल ५७६० करोड़ रु० हम प्राप्त करेंगे, जबकि पिछली योजना की शेष राशि मिलाकर ८००० करोड़ रु० व्यय करना है। इसका अर्थ है २५०० करोड़ रु० का भारी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अन्तर, जिसे पूरा करने के लिए कोई उपाय नहीं बताया गया है।

हम घाटे की अर्थ-व्यवस्था द्वारा रुपया प्राप्त कर लेने पर गर्व करते थे, किन्तु २० महीनों में ही हमने देख लिया कि मूल्य २७ प्रतिशत बढ़ गये हैं। अब हम सोचने लगे हैं कि घाटे की अर्थव्यवस्था की भी एक सीमा होती है।

प्रश्न यह है कि क्या हम योजना की रक्षा कर सकते हैं? जनता पर कर लगा कर, उससे कर्ज लेकर, उसकी बचत का उपयोग करके तथा घाटे की अर्थव्यवस्था से कुल ५७६० करोड़ रु. प्राप्त कर सकते हैं। निजी उद्योग भी अतिरिक्त लाभ से तथा बैंकों से रुपया उधार लेकर अपना काम चलाते हैं। यदि सरकार कर लगाकर तथा स्वयं रुपया लेकर उसके स्रोत को बन्द कर देगी तो निजी उद्योग का क्षेत्र भी विकास नहीं कर सकेगा। इस तरह यह स्पष्ट है कि नये भारी कर योजनापूर्ति में सहायक नहीं हो सकते। बजट के भारी करों से ७३ करोड़ रु० की प्राप्ति हुई, पर इससे ४० करोड़ रु० से अधिक योजना पर व्यय नहीं होगा ३३ करोड़ रु० तो शासन की मशीनरी पर व्यय हो जायेगा कर लगा कर सरकार एक हाथ से कुछ प्राप्त कर लेगी, किन्तु दूसरी ओर जनता की होने वाली वह बचत भी कम हो जायेगी, जो शेयरों अथवा बैंक में जमा निधि के द्वारा उद्योग विकास के विनियोजन में लगता। देश की कुल बचत में इसलिए वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि सरकार ने कर के द्वारा वह राशि वसूल कर ली है। इसका एक ही परिणाम होगा कि निजी उद्योग के विनियोजन के साधन सरकार के हाथ में चले जावेंगे और इसका एक दुष्परिणाम यह होगा कि निजी उद्योग की आय कम होगी, सरकार को कर भी कम वसूल होंगे। कर भी तो आमदनी में से ही दिये जाते हैं, जब आमदनी ही नहीं रहेगी, तो कर कहां से दिये जायेंगे?

(पृष्ठ ३८६ का शेष)

ग्रामों के लिए बीमा योजना

व्यापारी बैंकों के लाभ के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के ऋण के बीमा की योजना भी जारी की जाए। डिपाजिट का बीमा और ऋण का बीमा दोनों व्यवस्थाएं क्रियान्वित हों। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापारी बैंक रुपया ऋण में दें, इसके लिए यह आवश्यकता है कि कृषक ऋण चुकाने के योग्य बनाया जाए। इसके लिए यह आवश्यक है कि सुरक्षित और क्षति-पूरक गोदाम बनाए जाएं और अन्य सुविधाएं उपलब्ध की जाएं। छोटे किसान अपनी उपज गोदामों में जमा कर व्यापारी बैंकों से रसीद लें। ये रसीदें आगे चल कर क्रय-विक्रय का साधन बन सकती हैं। बाजार में उन पर रुपया मिल सकता है। आवश्यक है कि इस समय इस व्यवस्था का सूत्रपात किया जाए।

व्यापारी बैंक ग्रामों के लिए पूंजी की समस्या आसानी से हल कर सकते हैं। भिन्न-भिन्न राज्यों में कृषि-वित्त निगमों का संगठन हुआ है। व्यापारी बैंक अपनी पूंजी इन निगमों में लगा सकते हैं। इन निगमों का मुख्य कार्य है कि किसानों को लम्बी मुद्दत के लिए ऋण मिले। पर जब तक किसान, जो देश की रीढ़ है, अपने पैरों पर नहीं खड़ा होता है, आर्थिक प्रश्न उसकी प्रगति के मार्ग में सदा क्षेत्र आएगा। इस अवस्था में उसके जीवन स्तर में कभी प्रगति नहीं हो सकती है।

ऋण देने वाली संस्था का निर्माण

अमेरिका में ऋण की सारी रकमें राज्य के खजाने से दी जाती है, पर इस देश में सरकार इस कोष को अकेले नहीं उठा सकती है। सरकार को अन्य योजनाओं के लिए धन की आवश्यकता है। पर यदि सरकार फ्रांस और इंगलैंड की पद्धति पर एक ऋण देने वाली संस्था खड़ी करे, जिसकी शाखाएं देश में सर्वत्र हों, तो यह प्रश्न हल हो सकता है। इस संस्था में बैंक अपनी पूंजी लगाने में आगे बढ़ेंगे। वे जो विनियोजन करेंगे, उसके बदले में उन्हें उचित मुनाफा मिलने की गारंटी रहेगी। इतना ही नहीं, वे इस संस्था की पूंजी के हिस्से खरीद कर सदस्य बन सकते हैं। इस संस्था के संगठन में विशेषज्ञों को भी लिया जाए, जो किसानों को अधिक उत्पादन करने के तरीके बताएं और समय समय उत्पन्न सूचनाएं दें।

बदनसीब किसान, जो पीढ़ियों से त्रस्त है, और पूंजी के साधनों के अभाव की तलवार जिस पर लटक रही है, उससे उसका छुटकारा तभी हो सकता है, जब सब उपायों से उसके लिए ऋण की व्यवस्था की जाए।

[समाप्त]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रुपये की स्थिति सुदृढ़ है

कुछ ही समय पूर्व विदेशों में और मुख्यतः इंगलैंड में यह अफवाह फैल रही थी कि भारतीय मुद्रा-पद्धति में अनेक त्रुटियां प्रतीत होने लगी हैं तथा विदेशों में भारतीय रुपये का मूल्य भी कम होता जा रहा है। इस विषय में लंदन के प्रमुख आर्थिक पत्र "फिनान्सियल टाइम्स" ने लिखा कि भारत सरकार विदेशी मुद्रा सम्बन्धी साधनों की कमी होने की प्रवृत्ति का नियंत्रण करने में असफल रही है, जिससे पौंड पावना मई के प्रथम सप्ताह में ३६८.४२ करोड़ रु० ही रह गया। पौंड पावने में इतनी कमी कभी नहीं हुई थी। साथ ही मुद्रा स्फीति के परिणामस्वरूप मूल्यों के बढ़ जाने से देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था चिन्तनीय हो गई है और विदेशों में भारत के माल की मांग में कमी होती जा रही है। लेकिन तथ्यों का भलीभांति अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि रुपये की सुदृढ़ता में कमी होने के कोई उल्लेखनीय लक्षण नहीं हैं और न ही इसकी चिन्ता करने की आवश्यकता है।

भारत में रुपये की स्थिरता में परिवर्तन होने की प्रवृत्ति का जो आभास सा होता है, वह इस कारण कि स्वर्ण में, रुपये का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश द्वारा ६२.५० रु० प्रति तोला निश्चित किया गया था; लेकिन विगत कई सालों से सोने का मूल्य उच्चतम स्तर तक रहा। निस्संदेह २२ मई को समाप्त होने वाले सप्ताह में, बम्बई में सोने का मूल्य १०७.१० रु० से १११.१ रु० प्रति तोला रहा। लेकिन यह मूल्य सट्टे के कारण बढ़े और इसके लिये आर्थिक परिस्थितियों को कोई दोष नहीं दिया जा सकता।

इसी प्रकार विदेशी बाजारों में रुपये की अस्थिरता के लिये कहा जाता है कि ज्यूरिच के स्वतंत्र बाजार में रुपये का मूल्य काफी अस्थिर रहा। भारतीय रुपये की बट्टे की दर १० से १५ प्रतिशत के लगभग रही, जबकि एक साल पहले यह ५ से १० प्रतिशत के बीच थी अर्थात् बट्टे की दर में ५ प्रतिशत वृद्धि हुई। लेकिन इसका कारण भारतीय पर्यटकों को विदेशी मुद्रा (पौंड) की सुविधाओं को प्रदान करने पर रोक लगा देना है। भारतीय पर्यटकों को केवल १० पौंड (७५० पौंड के बदले) और १३५ रु० की ही अनुमति दी गई। अतः उनके पास इसके अतिरिक्त और कोई चारा न रहा कि पर्यटन के लिये यथेष्ट राशि की पूर्ति के लिये रुपये को बट्टे की दर बढ़ा दें। लंदन के मुद्रा बाजार में रुपये और पौंड की विनिमय दर में शायद ही कोई बदलाव हुआ हो। न्यूयार्क में २ अप्रैल १९५६ को भारतीय रुपये की दर २१.०१ सेंट और यही मई १९५७ को २०.९० सेंट थी। याने सिर्फ ½ प्रतिशत कमी हुई। इसी अवधि में पौंड, २.८०¾ डालर से कम होकर २.७९½ डलर रह गया। इस प्रकार रुपया और पौंड की दर में घटती सामान्यतः बराबर ही रही। स्वेज नहर के संकट के कारण पौंड का मूल्य गिरा और पौंड से सम्बन्धित होने के कारण रुपये का मूल्य गिरना अनिवार्य है।

इसी प्रकार यह कहना भी सत्य नहीं है कि आंतरिक ऊंचे मूल्यों के कारण विदेशों में भारतीय माल की मांग में कमी हो रही है। यह इससे स्पष्ट है कि भारत के निर्यात के सूचक अंकों में पिछले साल की तुलना में कोई कमी नहीं हुई। वास्तव में विदेशी निर्यात के सूचक अंक (मूल्यों में) बढ़े ही हैं। हां, हमारी समस्या तो आयात का बढ़ना है, जो मात्रा और मूल्य दोनों रूप में ५ अंक तक बढ़ा है। इसी कारण हमें विदेशी माल के लिए अधिक मूल्य देना पड़ा, जिससे इधर के महीनों में मूल्य बढ़ रहे हैं।

यह सत्य है कि भारत में मुद्रा स्फीति है। पर भारत में ही नहीं, समस्त विश्व के देश मुद्रा-स्फीति से आक्रांत हैं। हां पश्चिमी जर्मनी और स्वीटजरलैंड दो भाग्यशाली देश हैं, जिनको ऐसी किसी परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ रहा है। खैर, मूल विषय तो यह है कि यदि संसार के समस्त देशों की मुद्रा स्थिति की तुलना की जाये तो भारत की स्थिति कई प्रमुख देशों से अच्छी सिद्ध होती है। उदाहरण के लिए विगत दशाब्दी में भारतीय मुद्रा के सूचक मूल्य में ३.२ प्रतिशत प्रति वर्ष की कमी हुई, जब कि अमेरिका, इंगलैंड, फ्रांस और आस्ट्रेलिया की मुद्रा में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

निरन्तर उन्नति के पथ पर जापान

जापान के प्रधान मंत्री श्री किशी की भारत यात्रा से भारत-जापान के सम्बन्ध मुख्यकर आर्थिक सम्बन्ध के और घनिष्ट होने में सहायता मिलेगी। श्री किशी समस्त एशियाई देशों के साथ मधुर राजनयिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है "मेरा विश्वास है कि एशिया एक हो रहा है।"

हमारे देश भारत की आर्थिक नीति भी हमारी विदेश नीति का ही प्रतिरूप है। अनेक देशों के साथ आर्थिक सहयोग स्थापित करना हमारा प्रयत्न रहा है। जापान से, जो एशिया का सर्वाधिक विकसित औद्योगिक राष्ट्र है, यद्यपि हमारा कोई 'प्रभावपूर्ण' आर्थिक समझौता नहीं हुआ था, लेकिन समय-समय पर जो व्यापारिक समझौते हुए, उनकी अवधि बढ़ाई जाती रही। हां पिछले अक्तूबर में जापान के साथ सांस्कृतिक समझौता हुआ था। इधर जापान की राजधानी टोकियो में भारत-जापान के प्रतिनिधियों की व्यापारिक वार्ता चल रही है और सितम्बर तक नया व्यापारिक समझौता होने की सम्भावना है। श्री किशी की भारत-यात्रा से आर्थिक सम्बन्धों को और घनिष्ट करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

जापान का सहयोग

श्री किशी ने भारत को दीर्घकालीन ऋण देने की घोषणा कर भी दी है। यद्यपि शर्तें, ऋण की दरें आदि क्या और किस प्रकार होंगी, यह अभी निश्चित होना बाकी है। खैर, इससे हमें कुछ राहत तो मिल ही जायेगी।

जापान वैसे पहले से ही भारत को छोटी-मोटी आर्थिक सहायता प्रदान करता आ रहा है। जापान की एक फर्म ने अति शक्तिशाली इन्सुलेटर बनाने में सहायता दी है। इसने अब अपना उत्पादन-कार्य आरम्भ कर दिया है। एक दूसरी फर्म सोदपुर के कांच के कारखाने के निर्माण में सहायता दे रही है। यह कारखाना शीघ्र ही अच्छे किस्म के कांच का उत्पादन आरम्भ कर देगा। लेकिन फिर भी जापान से और भी अधिक सहायता की आशा की जाती है।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि जापान के आयात-निर्यात बैंक के उपप्रधान श्री कानू, जो हाल ही में भारत आये थे और यहां के बड़ी-बड़ी मशीनों के आयातकों से मिले थे; टोकियो में जापानी निर्माताओं से विद्युत् उपकरणों और सूती कपड़ों की मशीनों के भारत को विलंबित भुगतान पर निर्यात करने के विषय में बातचीत कर रहे हैं। यह सच है कि अब भी जापान की अर्थ-व्यवस्था को अनेक कठिनाइयों और प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ता है। कच्चे माल के लिये—८० प्रतिशत तक—उसे विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। अनाज का उसे विदेशों से आयात करना पड़ता है।

युद्ध के बाद जापानी उद्योगों को कच्चे माल की पूर्ति के लिये दक्षिण पूर्वी अफ्रीका की अपेक्षा उत्तरी अमेरिका पर अधिक निर्भर हो जाना पड़ा। इसलिये जापान को अधिक ऊंचे मूल्यों पर आयात करना पड़ता है। आयात में कमी करने के लिये जापान के केन्द्रीय बैंक ने व्यापारिक बिलों की वट्टे की दर बढ़ा दी है। इससे जापान के अस्थगित विदेशी व्यापार को राहत मिलेगी।

उन्नतिशील जापान

बैंक आव जापान ने घोषणा की है कि अप्रैल १९५७ से

[सम्पन्न

क्रमशः ३.४, ४.६, ६.५ और ७.५ प्रतिशत की कमी हुई।

इस समय भारत में जिस प्रकार की मुद्रा स्फीति है, उसका प्रभाव हमारे बजट पर पड़ा है कि इसमें ८०० करोड़ रु० की घाटे की अर्थव्यवस्था का सहारा लिया गया है। हो सकता है कि यदि तत्काल आवश्यक उपायों का अवलम्बन न किया गया तो रुपये के मूल्य में कमी हो जावे। इस वर्ष वित्त मंत्री ने २७५ करोड़ रु० की नयी मुद्रा के चलन की संभावना व्यक्त की है पर साथ साथ ९३ करोड़ रु० के नये करों से उपभोग की वस्तुओं पर कुछ अकुंश लगने की आशा भी व्यक्त की है। इस प्रकार कर लगाने और उपभोग पर अंकुश रखने से मुद्रा स्फीति की प्रवृत्ति की रोक में सहायता मिलेगी, जिससे अवश्य ही रुपये के मूल्य में कोई गिरावट न होगी।

——

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

५७० लाख डालर का प्रतिकूल व्यापार हुआ। २६३० लाख डालर प्राप्त हुए और ३५५० डालर देने पड़े। मार्च १९५७ के मुकाबले में प्राप्ति १० लाख डालर कम हुई और १० लाख डालर अधिक देना पड़ा।

इन सबके होते हुए भी जापान की औद्योगिक उन्नति ईर्ष्या का कारण हो सकती है। जापान का व्यावसायिक कार्यकलाप निरन्तर बढ़ रहा है। १९५५ में औद्योगिक उन्नति के सूचक अंक १८०.७ तक पहुँच गये। इसकी तुलना में १९४९ में सूचक अंक ७१ थे। (इनके लिये १९३४-३६ को आधार वर्ष १०० माना गया है।) कुछ उद्योगों में तो जापान ने अद्भुत प्रगति की है। हाल के प्राप्त आंकड़ों से इसकी सत्यता सिद्ध होती है। इस्पात का उत्पादन जो १९५५ में ७० लाख टन था, वह आगामी १८ महीनों में बढ़कर ११४ लाख टन हो गया। १९५५ में जापान युद्ध पूर्व की स्थिति में ही २५ प्रतिशत के हिसाब से जलयानों का निर्माण कर रहा था। लेकिन दो ही वर्ष बाद जहाज-निर्माण के क्षेत्र में उसका स्थान दूसरा हो गया। मित्सुबिशि जहाज-निर्माण करने वाली कम्पनी के जहाजों का टनेज दुनिया की किसी भी जहाज निर्माण करने वाली कम्पनी से अधिक है। इसी प्रकार मोटरगाड़ियों आदि के निर्माण में जापान ने उल्लेखनीय प्रगति की है। १९५६ में ५० हजार कारें, बस और ट्रक, १ लाख ३ पहिये के ट्रक, तथा २ लाख मोटर साइकिल और स्कूटर बनाये गये।

युद्ध के समय जापान ने दक्षिणी पूर्वी एशिया और मध्य योरप के सब बाजार खो दिये थे। अब ऐसा प्रतीत होता है कि शीघ्र ही इन बाजारों को फिर प्राप्त कर लेगा। सूती कपड़े और सूत के निर्यात में उसने प्रधानता तो प्राप्त कर ही ली है। १९५०-५१ में भारत का सूती वस्त्र और सूत के निर्यात में विश्व में प्रथम स्थान था, लेकिन अब वह जापान से पिछड़ गया है। कोरिया के युद्ध ने भी जापान की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में काफी सहायता दी। अमेरिका और उसके मित्रराष्ट्रों की सेना जो कोरिया में बढ़ रही थी उनको सम्पूर्ण सप्लाई जापान से ही होती थी। १९५३-५४ में जापान का व्यापार १२०० लाख डालर था, दूसरे वर्ष यह १०० प्रतिशत के करीब बढ़ा। १९५५-५६ में सर्वप्रथम जापान के व्यापारिक लेनदेन में सर्वप्रथम समरूपता स्थापित हुई। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय तनातनी के समय से शुरू होनेवाले उसके व्यापारिक इतिहास में वह सर्वप्रथम व्यापारिक समानता प्राप्त कर सका।

वर्धमान राष्ट्रीय आय

राष्ट्रीय उत्पादन १९५६ में २४०० लाख डालर से अधिक रहा जो १९५५ की अपेक्षा ११ प्रतिशत और युद्धपूर्व की अपेक्षा ४७ प्रतिशत अधिक है। उत्पादन और व्यापार के बढ़ने के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ गये हैं। १९५१ को आधार वर्ष १०० मानकर कारखानों में रोजगार के सूचक अंक ११३ हो गये हैं। मजदूरी बढ़ी है लेकिन मूल्य मजदूरी की अपेक्षा और भी अधिक बढ़े। मजदूरी, युद्ध पूर्व के स्तर तक १५ प्रतिशत बढ़ी, जबकि टोक्यो में उपभोग के सूचक अंक १९५१ को १०० मानकर, १९५६ में ११६ तक बढ़ गये।

भारत को जापान से बहुत कुछ सीखना है; मुख्यकर उत्पादन के आधुनिक जितने भी शिल्प-विधान हैं, उनका पूर्ण परिचय प्राप्त करना है। जापान की कुछ विशेष प्रकार के उत्पादनों की अपनी तरकीबें हैं—उदाहरण के लिये जापानी किसान ९ करोड़ लोगों के लिये ८० प्रतिशत खाद्य सामग्री का उत्पादन करता है। हमारे देश में जापानी खेती की पद्धति प्रयोग रूप में चल रही है। इसी प्रकार छोटे और मध्यम उद्योगों के उत्पादन की जानकारी प्राप्त करना भी आवश्यक है। आशा है, भारत और जापान के बढ़ते सहयोग के साथ-साथ जापान के इन समस्त अनुभवों से हम लाभ उठाकर अपने आर्थिक नवनिर्माण में सफल हो सकेंगे।

—

बम्बई में सम्पदा के प्रतिनिधि

श्री टी० एन० वर्मा

नेशनल हाउस २ री मंजिल

Tullock Road, Bombay—१

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चीन द्वारा साम्यवाद की नई दृष्टि

श्री मदनमोहन मिश्र

"फूलों को खिलने दो ! विचारों को पनपने दो !!"

साम्यवादी शासन अपने एकदलीय अधिनायकत्व तथा कठोर अनुशासन के लिये प्रसिद्ध है । वहां विरोधी राजनैतिक दलों के लिये कोई स्थान नहीं है । रूस ही नहीं, अन्य साम्यवादी देशों में भी एक ही राजनैतिक दल कम्यूनिस्ट पार्टी का एकमात्र संगठन रहने दिया जाता है। चीन में भी यही स्थिति है । चीन की आबादी ६० करोड़ से भी अधिक है । वह विश्व का (जनसंख्या के लिहाज से) सबसे बड़ा देश है । स्वभावतः साम्यवादी जगत में उसका स्थान भी महत्त्वपूर्ण है । चीन के ही अध्यक्ष श्री माओ-त्से तुंग ने अभी अभी 'फूलों को खिलने दो, विचारों को पनपने दो, को व्यक्त करके साम्यवाद की अब तक की मान्यताओं या उसकी मौलिक धारणाओं पर गहरी चोट की है । उनके इन विचारों की सारे संसार में प्रतिक्रिया हुई है । ऐसा समझा जा रहा है कि चीन का साम्यवादी शासन उदार और सहिष्णु बन रहा है । इस प्रकार साम्यवाद के प्रवर्तक रूस की पद्धति से वह शायद कुछ दूर-सा हो रहा है ।

विचारों की स्वतन्त्रता

सबको विचारों की स्वतन्त्रता हो और इसमें सरकार की कोई जोर-जबरदस्ती न हो, श्री माओ ने इन विचारों को प्रकट करते हुए कहा कि, "मत-परिवर्तन के लिये लोकतंत्री और शांतिपूर्ण तरीकों का अवलम्बन किया जाना चाहिए । ये तरीके हैं—विचार-विनिमय, समझाना-बुझाना, तर्क करना और शिक्षा देना । प्रशासकीय आदेशों से दबाव डालकर आदर्श सम्बन्धी विचारों को बदलने में विफलता हाथ लगेगी । यहीं नहीं, उल्टे इनसे हानि भी हो सकती है ।"

साम्यवादी देशों में शिक्षा-दीक्षा ही इस उद्देश्य से होती है कि शिक्षार्थियों के विचारों को साम्यवाद के अनुरूप ढाला जाये । विज्ञान और कला के चरम आदर्श "साम्यवाद के प्रति आस्था" ही माने जाते हैं । सम्भवतः इन्हीं को चुनौती देते हुए श्री माओ ने कहा कि—"हमारे विचार से कला और विज्ञान की उन्नति के लिये यह हानिकारक है, यदि शासन विशेष प्रकार के कला और विज्ञान सम्बन्धी विचारों को थोपे और इसी तरह के दूसरे विचारों पर रोक लगाये ।"

वर्गसंघर्ष विद्यमान

साम्यवाद के सम्बन्ध में श्री माओ ने दो महत्त्वपूर्ण बातें कहीं, पहली यह कि साम्यवादी-व्यवस्था में पारस्परिक विरोध है तथा वर्ग-संघर्ष अभी विद्यमान है । चीन का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि वहां सामूहिक हित और व्यक्ति के हित में विरोध है । यह विरोध लोकतंत्र और केन्द्रीय सत्ता में, नेताओं और अनुयायियों में, राज्याधिकारियों के नौकरशाही तरीकों में और जनता में भी स्पष्ट है । १९५६ में कुछ मजदूरों और छात्रों ने अपनी मांगों की पूर्ति न होने के कारण हड़ताल की । यह भी महत्त्वपूर्ण है कि चीन ने अन्य साम्यवादी देशों की तरह हड़ताल को 'असाम्यवादी' नहीं माना है । चीन में हड़ताल का रूप यह है कि "इस प्रकार की घटनाओं से हमें फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि इनसे नौकरशाही से मुक्त होने में सहायता मिलती है ।" चीन का नौकरशाही से मुक्त होने का अभियान साम्यवाद के लिये बिल्कुल नई चीज है, क्योंकि साम्यवादी शासन-पद्धति में सरकारी मशीनरी का काफी आश्रय लिया जाता है, यह अनिवार्य भी है ।

चीन में वर्ग-संघर्ष मिटा नहीं । चीन ही में क्यों, श्री माओ का कथन तो यह है कि साम्यवादी व्यवस्था में वर्ग-संघर्ष है ही । पर इतना अवश्य है कि पूंजीवादी समाज और साम्यवादी समाज के वर्ग-संघर्ष में अन्तर है । पूंजीवाद में वर्ग-संघर्ष तीव्र है, लेकिन साम्यवाद में यह सौम्य है । इस विषय में उल्लेखनीय बात यह है कि चीन में पूंजीपतियों और जमींदारों को मताधिकार प्राप्त नहीं है

[सम्पा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

न ही उन्हें विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता है।

निजी व्यवसाय भी

चीन के आर्थिक-विचारों के विषय में श्री माओ के विचार भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। ज्ञात होता है कि चीन में निजी औद्योगिक और व्यापारिक प्रयासों को स्थान है। वहां के सरकारी और निजी उद्योगों में पूंजीपतियों को उनकी पूंजी पर निश्चित ब्याज मिलता है। अब भी पूंजीपतियों और मजदूरों में विचारों की भावनाओं और आदतों में बड़ा वैषम्य है। इसी कारण पूंजीवादको पूर्णतः समाप्त करके समाजवाद स्थापित करने में चीन ने कोई जल्दबाजी नहीं की। (यद्यपि शोषण समाप्त कर दिया गया है। इसका कारण यह है कि एक तो लोगों को 'नये ढांचे' से परिचित होने में काफी समय लगेगा और दूसरे सरकारी कर्मचारी अभी पूर्ण अनुभवी नहीं हैं।

श्री माओने व्यापारियों और उद्योगपतियों को स्मरण कराया है कि उनको नये विचारों के अध्ययन करने और उसके अनुसार बदलने का प्रयत्न करना चाहिए।

चीनकी सहकारी कृषि के सम्बन्ध में चीन में ही कुछ लोग इसकी श्रेष्ठता पर आशंका करते हैं। श्री माओ के कथन से ऐसी ध्वनि निकलती है। श्री माओ ने इसीलिये इनको उत्तर दिया है कि "हमारा सहकारिता का आन्दोलन सुदृढ़ आन्दोलन है। हां इसकी पूर्ण सफलता प्राप्त करने में ५ वर्ष या कुछ अधिक भी लग जायेंगे। अभी तो इसको आरम्भ किये एक ही साल हुआ है। अतः इतनी जल्दी फल-प्राप्ति की इच्छा करना ठीक नहीं।"

सह-अस्तित्व

श्री माओ ने चीन की तीव्र आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति का मूलमंत्र ही "दीर्घकालीन सहअस्तित्व" और पारस्परिक पर्यवेक्षण (Mutual Supervision) माना है। इसी में एक मार्के की बात श्री माओ ने यह कही कि "पारस्परिक सह-अस्तित्व" हमारी ऐतिहासिक परिस्थितियों की देन है। चूंकि प्रत्येक साम्यवादी देश की परिस्थितियां विभिन्न हैं, उनकी साम्यवादी पार्टियां भी अलग-अलग हैं। हम यह नहीं कहते कि दूसरे (साम्यवादी) देशों और साम्यवादी पार्टियों को चीन का ही तरीका अपनाना चाहिए।" साथ ही उन्होंने कहा कि चीन विश्व के समस्त देशों से 'सीखने' की इच्छा करता है, लेकिन अभी तो उसे रूस से बहुत कुछ सीखना है।" स्पष्ट है अवसर पड़ने पर चीन 'दूसरे देशों' के अनुभवों से भी लाभ उठा सकता है।

चीन आज हमारी तरह ही अपने आर्थिक नव-निर्माण में संलग्न है। इस दिशा में उनकी जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, वह बहुत कुछ भारत जैसी हैं। चीन को भी पूंजी की आवश्यकता है, और भारी मशीनों की आवश्यकता है। इसके लिए उसे आजकल केवल रूस ही सहायता प्रदान कर रहा है। पर श्री माओ के इन विचारों से ज्ञात होता है कि चीन भविष्य में इतनी कट्टरता न बरतेगा। 'सह-अस्तित्व' में उसका विश्वास दृढ़ है। अतः यदि रूस के अतिरिक्त अन्य गैर साम्यवादी देश उसको सहायता प्रदान करें तो वह स्वीकार करने में संकोच न करेगा। अभी-अभी इंगलैंड और चीन के बढ़ते हुए व्यापारिक सम्बन्धों से यही सिद्ध होता है। जापान और पश्चिमी जर्मनी भी चीन से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं। यह कहा जा सकता है कि चीन में देशी पूंजीपतियों का अस्तित्व तो है ही, लेकिन यदि विदेशी पूंजीपति भी चीन के आर्थिक नव-निर्माण में सहायता दें, तो चीन सहर्ष ग्रहण करेगा, यदि उसके हित के विपरीत न हो।

चीन के प्रधान श्री माओ त्से तुंग के इन नवीन विचारों से गैर साम्यवादी देश यह मानने लगे हैं कि चीन में रूस जैसी 'कट्टरता' नहीं और न ही उसका रास्ता बिलकुल रूस जैसा है। साम्यवादी देशों में इसकी प्रतिक्रिया भी उल्लेखनीय है कि अब तक वे बात-बात के लिए रूस का मार्ग-प्रदर्शन चाहते थे। अब वे स्वयं ही अपना रास्ता पकड़ सकेंगे।

—

सम्पदा के नये विशेषांक का परिचय पढ़िये और अपनी कापी १॥) भेजकर सुरक्षित करा लीजिए

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दूसरी विकास योजना का प्रथम वष

दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के पहले वर्ष (१९५६-५७) में कुछ क्षेत्रों में काफी सफलता मिली है। आयोजन-आयोग द्वारा की गई समीक्षा से पता चलता है कि परिस्थितियां आम तौर से बहुत अनुकूल नहीं रहीं, फिर भी इस वर्ष कुछ क्षेत्रों में काफी सफलता मिली और प्रगति भी हुई।

इस वर्ष स्वेज-संकट, देश में भावों की वृद्धि, इस्पात और सीमेंट की दुर्लभता और विदेशी मुद्रा की कमी जैसी अनेक कठिनाइयां सामने आयीं।

अन्न उत्पादन के कार्य-क्रमों के अनुसार १९५६-५७ में अन्न उत्पादन के २५ लाख टन बढ़ने की आशा थी, परन्तु इसमें वास्तविक वृद्धि केवल १४ लाख टन की हुई और १९५६-५७ का कुल उत्पादन ९ करोड़ ६२ लाख टन रहा। १९५५-५६ में ६ करोड़ ४८ लाख टन अन्न का उत्पादन हुआ था। १९५५-५६ की तुलना में चावल का उत्पादन १३ लाख टन और गेहूं का उत्पादन ३ लाख टन बढ़ा। मोटे अनाज के उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। दालों का उत्पादन २ लाख टन कम हो गया। व्यापारिक फसलों की स्थिति कुछ अच्छी रही। तिलहन का उत्पादन ५८ लाख ९० हजार टन रहा, जब कि १९५५-५६ में कुल उत्पादन ५६ लाख ६० हजार टन था। रुई का उत्पादन ४८ लाख गांठ होने का अनुमान है। अर्थात् पिछले वर्ष की अपेक्षा ८ लाख गांठ अधिक है। गन्ने का उत्पादन ६३ लाख टन रहा। यह मात्रा १९५५-५६ के उत्पादन से ४ लाख टन अधिक है। पटसन का उत्पादन थोड़ा बढ़कर ४२ लाख २१ हजार गांठ हो गई। पिछले साल पटसन का उत्पादन ४१ लाख ९७ हजार गांठ हुआ था।

१९५६-५७ में २५-२५ एकड़ के ४७५ बीज फार्म स्थापित करने की स्वीकृति दी गई। १९५६-५७ में २० लाख एकड़ भूमि पर जापानी ढंग से धान की खेती शुरू करने का लक्ष्य था। १९५६ के अंत तक १४॥ लाख एकड़ भूमि पर जापानी ढंग से धान की खेती शुरू की गई। १९५६ में ६ लाख ७५ हजार टन अमोनियम सल्फेट और एक लाख टन सुपरफास्फेट इस्तेमाल करने की आशा थी।

राष्ट्रीय योजनाएं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा

इस वर्ष ४९५ राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड स्थापित किये गए और ४९,६०० गांवों की ३ करोड़ २७ लाख जनता इन खंडों के अंतर्गत आ गई। इसके अलावा २५० को सामुदायिक विकास खंडों में बदला गया और ३५,७२० गांवों की १ करोड़ ७३ लाख जनता इनके अंतर्गत आ गई।

सिंचाई और बिजली

१९५६-५७ में सिंचाई की बड़ी और दरम्यानी योजनाओं से १५ लाख एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र और छोटी सिंचाई योजनाओं से १६ लाख एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र की सिंचाई हुई। इस वर्ष सिंचाई की ९० बड़ी और दरम्यानी योजनाएं पूरी होने की आशा है। हीराकुड बांध योजना का जनवरी १९५७ में औपचारिक रूप से उद्घाटन हुआ परन्तु सिंचाई के लिए सितम्बर १९५६ ही में नहरों में पानी छोड़ दिया गया। २४,००० किलोवाट बिजली तैयार करने वाले पहले इंजन ने दिसम्बर १९५६ में काम शुरू किया। हीराकुड से निकाली गई नहरें मार्च १९५७ के अंत तक १,५७,००० एकड़ क्षेत्र को सींचने लगी थीं। भारत-अमरीका प्राविधिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार ने जिन २६५० नलकूपों के निर्माण को स्वीकृति दी थी, वे सब सिंचाई कार्य के लिए तैयार हैं। 'अधिक अन्न उपजाओ' संगठन की सहायता से १९५४-५५ में १,१०० नलकूपों के निर्माण का काम शुरू हुआ था। ये नलकूप कुछ महीनों में बनकर तैयार हो जायेंगे।

१९५६-५७ में ३,०८,५०० किलोवाट बिजली तैयार करने योग्य बिजलीघर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था। २,६०,००० किलोवाट बिजली तैयार करने योग्य बिजलीघर स्थापित हो चुके हैं। इस प्रकार १९५६-५७ के अन्त में कुल क्षमता ३६ लाख ६० हजार किलोवाट हो गई है। छोटे नगरों और देहात में बिजली लगाने की

[सम्पादक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

योजनाओं के अन्तर्गत इस वर्ष २,००० छोटे नगरों और गांवों में बिजली लगाई गई। इस प्रकार बिजली वाले नगरों और गांवों की संख्या ९,४००० हो गई है।

उद्योग और खनिज

अलुमुनियम और वनस्पति के अलावा सभी प्रमुख उद्योगों में १९५५ की अपेक्षा १९५६ में उत्पादन बढ़ा है। औद्योगिक उत्पादन का सूचक अंक १९५५ के १२५.१ से बढ़कर १९५६ में १३२.७ हो गया। रेडियो के निर्माण में ८६ प्रतिशत की वृद्धि हुई। बाइसाइकिलों मोटर-गाड़ियों, बिजली की मोटरों, ट्रांसफारमरों और बिजली से चलने वाले पम्पों के निर्माण में ३३ से ६० प्रतिशत तक वृद्धि हुई। सीमेंट, चीनी, डीजल इंजन आदि ८ अन्य उद्योगों में १० से २५ प्रतिशत तक वृद्धि हुई। १९५६-५७ में सीमेंट का उत्पादन ४९ लाख टन और चीनी का उत्पादन १९ लाख ५० हजार टन हुआ। पिछले वर्ष ये संख्याएँ क्रमशः ४ लाख ५० हजार टन और १६ लाख १० हजार टन थीं। तैयार इस्पात के उत्पादन में भी ४ प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई। १९५६-५७ में १३ लाख १० हजार टन इस्पात तैयार बना। इस वर्ष मिलों में ५ अरब २८ करोड़ १० लाख गज सूती कपड़ा तैयार हुआ। यह संख्या पिछले वर्ष की संख्या से ४ प्रतिशत कम है। कमाए चमड़े और जूतों में भी ५ प्रतिशत वृद्धि हुई। चाय के उत्पादन में अधिक वृद्धि नहीं हुई।

पहली बार निर्माण

इस वर्ष देश में ये वस्तुएँ पहली बार बनाई गईं—पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ड्रिल, शाक एक्जारबर, क्लचडिश, ब्रेक लाइनिंग, हाइड्रोजन परआक्साइड, केप्सटेन लेथ्स १।२ कैपेसिटो, सेलिसिलिक एसिड, जेड ग्रीन बाट डाइज़, फेरो-मेंगनीज (इलेक्ट्रिक स्मेल्टिंग प्रोसेस द्वारा निर्मित) और ड्राई बैटरियों के लिए जिंक स्ट्राइप्स।

रेल-इंजन, सवारी डिब्बे, डी. डी. टी., पेनिसिलीन, अखबारी कागज, केबल और मशीन टूल जैसे सरकारी उद्योगों में भी १९५५ की अपेक्षा उत्पादन बढ़ा।

१९५६-५७ में कोयले के उत्पादन में १२ लाख टन की वृद्धि हुई। १९५५-५६ में ३ करोड़ ८२ लाख टन कोयले का उत्पादन हुआ और १९५६-५७ में ३ करोड़ ९४ लाख टन का। सरकारी कोयला-खानों में कोयले का उत्पादन २ लाख टन और निजी क्षेत्रों में १० लाख टन बढ़ा। सरकार ने नए क्षेत्रों में कोयला-खानों में खुदाई शुरू कर दी है। कोरबा में ८ करोड़ ६४ लाख टन, दक्षिण करणपुर में १० करोड़ टन और अन्य क्षेत्रों में ४ करोड़ टन कोयला प्राप्त होगा। कोरबा कोयला-खानों का विकास इस वर्ष आरम्भ कर दिया गया है।

इस वर्ष जैसमेर, पंजाब और काम्बे में तेल और प्राकृतिक गैस के लिए भू-गर्भ सर्वे जारी रहा।

ग्रामोद्योग तथा छोटे उद्योग

१९५६ में मिल के सूत से १ अरब ५४ करोड़ १० लाख गज हथकरघा कपड़ा तैयार हुआ, जबकि १९५५ में १ अरब ४७ करोड़ ३० लाख गज तैयार हुआ था। इस प्रकार हथकरघा कपड़े के उत्पादन में ६ करोड़ ८० लाख गज की वृद्धि हुई। ५ वर्षों में ७० करोड़ गज अधिक कपड़ा तैयार करने का लक्ष्य है। खादी (साधारण तथा अम्बर) में लगभग १ करोड़ वर्ग गज की वृद्धि हुई। १९५६-५७ में ३ करोड़ ४५ लाख वर्ग गज खादी तैयार हुई। जबकि १९५५-५६ में केवल २ करोड़ ५४ लाख वर्गगज खादी तैयार हुई। १९५६-५७ में ७५,००० अम्बर चर्खे बनाने और लगाने का कार्यक्रम था, जिसमें से साल के अन्त तक ६०,००० से अधिक अम्बर चर्खे लगाए गये। बड़े उद्योगों के सहायक के रूप में छोटे उद्योगों का विकास आरम्भ कर दिया गया है और १० नये औद्योगिक संस्थान खोले गये।

रेल, सड़क, जहाजरानी और नागरिक उड्डयन

१९५६-५७ में यातायात के लिए ८७ मील लम्बी नई रेल लाइनें खुलीं। साल के अन्त में ५२४ मील नई रेल-लाइनों में काम चालू रहा। ७०० मील रेल-लाइनों को दुहरा करने का काम भी जारी रहा। इनमें से ३७० मील दक्षिण-पूर्व रेल, ११६ मील पश्चिम रेल और ७८ मील दक्षिण रेल की लाइनों पर काम होता रहा। १९५६-५७ में २,८०० मील रेल लाइन का सर्वे करने की स्वीकृति मिली, जिसमें से २,००० मील पर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

काम चल रहा था। इस वर्ष ५५७ रेल-इंजन, १६३१ सवारी डिब्बे और २७१८४ माल डिब्बे मंगाने का आर्डर दिया गया। वर्तमान कारखानों को बढ़ाने और सुधारने तथा नए कारखाने खोलने का काम भी जारी रहा।

राष्ट्रीय राज-मार्गों के निर्माण का काम संतोषजनक रहा। इस वर्ष दो सड़कों को मिलाने वाली १५० मील लम्बी सड़कें बनाने, ७ बड़े पुल बनाने, ८०० मील सड़कों का सुधार करने और ३०० मील सड़कों को चौड़ा करने का जो लक्ष्य था वह पूरा हो गया। राष्ट्रीय राज-मार्ग संख्या १ ए के जम्मू-श्रीनगर खण्ड में नई बनिहाल सुरंग का बायां सुरंगी-मार्ग दिसम्बर १६५६ में खोल दिया गया। अभी यहां का यातायात सीमित रखा गया है। इसके फलस्वरूप अब पहली बार काश्मीर की घाटी और भारत के बीच बारह महीने यातायात जारी रखना सम्भव हो गया है। नवम्बर १६५६ के अन्त तक ६६ मील लम्बी अन्तरराज्यीय और आर्थिक महत्त्व की सड़कें बनाई गईं और ६४७ मील लम्बी सड़कों का सुधार किया गया।

अब जहाजों की लागत बढ़ गई है इसलिए नियत धनराशि से १,८०,००० जी० आर० टी० के जहाज ही बढ़ पाएंगे। आयोजना का लक्ष्य ३,६१,००० जी० आर० टी० (जिसमें वे जहाज भी शामिल हैं, जो बेकार हो जाएंगे) १६५६ में ४४,००० जी० आर० टी० के नये जहाज बढ़े और १६५६ के अंत में भारत के पास ५,१७,००० जी० आर० टी० के जहाज हो गये थे।

नागरिक वायु परिवहन का कार्यक्रम नियत गति से आगे बढ़ा। १६५६-५७ में एयर इण्डिया इंटरनेशनल कारपोरेशन में ३ सुपर कांस्टीलैशन विमान खरीदे और ३ बोइंग जेट विमानों का आर्डर दिया। इंडियन एयर लाइंस कारपोरेशन ने १६५६-५७ में मुख्य मार्गों पर चलाने के लिए ५ वाइकस वाइकाउंट विमानों का आर्डर दिया।

प्रशिक्षण और गवेषणा कार्यक्रम

शिल्पिक कर्मचारियों की तात्कालिक और भावी आवश्यकता की ओर इस वर्ष काफी ध्यान दिया गया और केन्द्र तथा राज्यों में शिल्पी तैयार करने के लिए आवश्यक कदम उठाये गये।

तीनों इस्पात कारखानों में काम करने के लिए कर्मचारियों की शिक्षा का इस साल विशेष प्रबन्ध किया गया। अन्य शिल्पियों जैसे दस्तकारों और कारीगरों की शिक्षा की योजना बनाने और उन पर अमल करने की ओर ध्यान दिया गया।

इस साल की सबसे उल्लेखनीय घटना है भारत में पहली अणु-भट्टी की स्थापना। यह अणु-भट्टी 'स्विमिंग पूल' किस्म की है। भारत और कनाडा के सहयोग से बनने वाली भट्टी लगाने के काम में संतोषजनक प्रगति हुई। १६५६-५७ में आयोजन आयोग को राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से वैज्ञानिक और प्राविधिक गवेषणा और अध्ययन के संयोजन के बारे में सलाह और सहायता देने के लिए वैज्ञानिकों की एक समिति नियुक्त की गई। समिति की पहली बैठक की सिफारिशों पर कार्रवाई की जा रही है।

अनुमित खर्च और साधन

१६५६-५७ में पुनर्गठित राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में आयोजना के अन्तर्गत खर्च के संशोधित अनुमान लगभग ३६१ करोड़ रु० के बैठते हैं और केन्द्रीय मंत्रालयों का खर्च ३७० करोड़ रु० होगा। इस प्रकार संशोधित अनुमानों के अनुसार आयोजना का खर्च ७६१ करोड़ रु० बैठता है, जिनमें से ३७० करोड़ रु० केन्द्र के और ३६१ करोड़ रु० राज्यों के हिस्से आता है। वास्तविक खर्च के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं। विकास की बड़ी-बड़ी मदों का खर्च इस प्रकार होगा :

विकास की मदें	बजट	करोड़ रु० में संशोधित
१. कृषि तथा सामुदायिक विकास	१०८	[illegible]
२. सिंचाई और बिजली	१८१	[illegible]
३. उद्योग तथा खनन	१२१	[illegible]
४. परिवहन और संचार	२४७	[illegible]
५. समाज सेवा	१४३	[illegible]
६. विविध	३०	[illegible]
कुल	८३०	७६१

संशोधित अनुमान के अनुसार ७६१ करोड़ के [illegible] की पूर्ति इस प्रकार की जाएगी —

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

	करोड़ रु० में
१. आयोजना का खर्च	७६१.०
२. बजट साधनों से	४२७.२
३. विदेशी सहायता	६३.१
४. कुल साधन (२-३)	४९०.३
५. कमी (१-४)	२७०.७

अर्थात् देश के साधनों (केन्द्र के ३२६.७ करोड़ रु० और राज्यों के १००.५ करोड़ रु०) और विदेशी सहायता के बाद भी २७०.७ करोड़ रु० की कसर रह जाती है।

चालू राजस्व में से केन्द्रीय सरकार १०२ करोड़ रु० आयोजना के लिए देगी। इसमें से लगभग ५३ करोड़ रु० १९५६-५७ के नये कर प्रस्तावों से प्राप्त होगा। रेलें अपनी चालू आय में से ४२ करोड़ रु० विकास कार्य के लिए देंगी। इस प्रकार चालू राजस्व में से केन्द्र कुल १४४ करोड़ रु० आयोजना के कामों के लिए देगा।

अनुमान है कि केन्द्रीय सरकार ७८.१ करोड़ रु० जनता से उधार लेगी। इस साल जो ऋण सरकार को प्राप्त हुआ था, वह कुल मिलाकर तो बजट अनुमान १००.६ करोड़ रु० से ५७ करोड़ रु० बढ़ गया, लेकिन १९५७-५८ में वापिस मिलने वाले कर्ज को दुबारा कर्ज देने की इजाजत होने के कारण नकद प्राप्ति बजट-अनुमान से काफी कम रही।

छोटी बचतों में केन्द्र के हिस्से ४५३ करोड़ रु० आया। इन बचतों से कुल ६४.६ करोड़ रु० इकट्ठा हुआ। यह राशि पिछले साल की वास्तविक बचत से १.०५ करोड़ रु० कम है। अन्य मदों से कुल ४२ करोड़ रु० प्राप्त होने का अनुमान है।

६३ करोड़ रु० की विदेशी सहायता को जोड़कर केन्द्र के पास ३९० करोड़ रु० खर्च करने के लिए होगा, जबकि केन्द्र की आयोजना पर ३७० करोड़ रु० खर्च करना है। साथ ही केन्द्र को राज्यों को २३५.५ करोड़ रु० देना होगा। इस प्रकार केन्द्र का घाटा लगभग २१६ करोड़ रु० बैठता है।

ऊपर जो अनुमान दिए गए हैं, उनके अनुसार राज्य सरकार अपने हिस्से के आयोजना के कुल ३९१ करोड़ रु० के अनुमित खर्च में से लगभग १०० करोड़ रु० अपनी तरफ से जुटायेंगी।

"मैं राज्य की बढ़ती हुई ताकत को बहुत भय के साथ देखता हूँ। यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से यह मालूम होता है कि वह शोषण को कम कर रही है, तथापि वस्तुतः इससे मानव जाति की बड़ी भारी हानि होती है, क्योंकि इसे मानव का वह व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है, जो सब प्रकार की उन्नति का मूल कारण है।"

—महात्मा गांधी

स्वतन्त्र साहस और उद्योग के सम्बन्ध में जनता को शिक्षित करने वाली एक अ-राजनैतिक संस्था।

Forum of Free Enterprise

स्वतन्त्र साहस संघ

२३५, डा० दादाभाई नौरोजी रोड, बम्बई-१

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जीवन-बीमा निगम और उसकी समस्यायें

बैंक और बीमा

जीवन-बीमा-उद्योग के राष्ट्रीयकरण हो जाने से इस उद्योग का विस्तृत व्यवसाय-क्षेत्र अब संकुचित हो गया है। सरकारी देख रेख में चलने के कारण इसके शक्ति-अधिकार बढ़े तो सही, लेकिन उसके साथ ही साथ कार्यकुशलता और प्रभाव में वृद्धि नहीं हुई। एक प्रकार से इनका ह्रास ही हुआ। पर इसका एक कारण था कि नये सिरे से एक देशव्यापी संगठन करना था और इसमें देर व भूल होना स्वाभाविक था।

१९५६ में जीवन-बीमा-निगम ने २०० करोड़ रु० का व्यवसाय किया। १ जनवरी १९५६ से ३१ अगस्त १९५६ तक १४५.५१ करोड़ रु० का और १ सितम्बर १९५६ से ३१ दिसम्बर १९५६ तक ५४.७६ करोड़ रु० का व्यवसाय हुआ। पहले आंकड़े बीमा-निगम की स्थापना के पूर्व के हैं, याने जब इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था। यह भी जान लेना रोचक होगा कि पिछले २-३ वर्षों में बीमा-उद्योग ने देश और विदेश में कितने रुपये का व्यवसाय किया। यह निम्न अंकों से स्पष्ट होगा :—

१९५३ में १६८ करोड़ रु०,
१९५४ में २४७ करोड़ रु०, और
१९५५ में २६८ करोड़ रु०।

व्यवसाय में कमी

ऊपर कहा गया है कि १९५६ में जनवरी से अगस्त के बीच बीमा-उद्योग ने १४५.५१ करोड़ रु० का व्यवसाय किया। यह राशि १९५६ के इसी अवधि के बीच की राशि से कुछ अधिक है। सितम्बर ५ से अक्तूबर १९५६ तक बीमा-व्यवसाय के कार्य में गिरावट आई। इसका कारण था बीमा कर्मचारियों की अदल-बदल, जिससे कार्य में अस्थिरता आ गई। यही नहीं, एक कठिनाई विभिन्न बीमा कम्पनियों की कार्य-पद्धति में विभिन्नता की भी थी। छोटी-छोटी बीमा कम्पनियों की तो यह एक विशेषता ही थी। इन कठिनाइयों को दूर कर दिया गया। इसी कारण नवम्बर दिसम्बर में, बीमा-कार्य में कुछ प्रगति दृष्टिगोचर हुई।

व्यवसाय में कमी के कारण

व्यवसाय में कमी होने का एक कारण यह है कि मोटे रूप में वैसी अनुकूल परिस्थितियां नहीं रही, जैसे विगत २-३ वर्षों में थी।

(१) १९५४ और १९५५ में बीमा-व्यवसायियों के स्टाफ एश्योरेंस स्कीम का प्रचलन करने से १० से १८ करोड़ रु० के एक नये व्यवसाय का जन्म हो गया। पर इसका विरोध किये जाने पर सरकार ने इसमें हस्तक्षेप किया तथा अक्टूबर १९५५ से यह व्यवसाय बंद कर दिया। अतः १९५६ में इसकी फिर से संभावना की ही नहीं जा सकती थी।

(२) १९५३ के सम्पत्ति कर कानून से १९५४-१९५५ में बड़ी संख्या में इस्टेट ड्यूटी और विवाहित महिला सम्पत्ति कानून पौलिसियों की खरीद को प्रोत्साहन मिला और इस प्रकार ७॥ करोड़ रु० का व्यवसाय केवल इन्हीं का किया गया। १९५५ की समाप्ति के बाद इस प्रकार का व्यवसाय हो ही न सका।

(३) १९५४ में प्रीमियम की दर में उपयुक्त कमी की गई। इससे ३६ करोड़ रु० का व्यवसाय और बढ़ा। लोगों की बड़ी भीड़ बीमा कम्पनियों में लगी रही कि वे अपनी पुरानी पौलिसी को परिदत्त में बदलते और फिर नयी पौलिसी लेकर प्रीमियम की दर कम कराते रहें। १९५६ में इस पर रोक लगी।

उन्नति के उपाय

जीवन-बीमा-निगम ने अपने व्यवसाय उन्नति के लिये प्रभावशाली कार्य आरम्भ कर दिया है। कुछ ये हैं— एजेण्टों की संख्या बढ़ाई जा रही है। १ सितम्बर १९५६ से १४ हजार से अधिक एजेण्ट नियुक्त किये गये हैं।

(१) क्षेत्रीय कार्यालयों को नये एजेण्टों के प्रशिक्षण की अनुमति दी गई है।

(२) स्त्रियों के जीवन के सम्बन्ध के आश्वासन [सम्बन्ध

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्बन्धी जो प्रतिबन्ध थे, उनमें ढिलाई कर दी गई है। अब केवल कुछ मामूली प्रतिबन्धोंके अतिरिक्त जीवन सम्बन्धी आश्वासन में पुरुष और स्त्री में कोई भेद न किया जायेगा।

(३) बीमा निगम ने बिना शर्त वाली पौलिसी जिन पर कुछ भी अतिरिक्त न देना होगा—और न कोई प्रतिबन्ध होगा, सेना के लिये प्रचलन करने का निश्चय किया है।

(४) बीमा-निगम ने सामूहिक बीमा योजना की रूप-रेखा तैयार की है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को उनके सेवा-काल में संरक्षण प्रदान करना है। इसमें प्रीमियम की दर में कमी होगी। कार्य का युक्तियुक्त संगठन होगा, जिससे व्यवस्था आदि व्यय कम हो जायेंगे। डाक्टरी जांच भी सरल कर दी गई है।

(५) बीमा-निगम ने एक योजना कर्मचारियों के हित के लिये चलाने का निश्चय किया है। प्रोविडेंट फंड से अधिक लाभ कर्मचारी को नहीं मिल पाता, जो कि कार्यनिवृत्त होने पर उसको शेष जीवन के लिये चिन्तामुक्त कर दे।

(६) अंतिम पर महत्वपूर्ण बात बीमा निगम की प्रगति के उपाय के सम्बन्ध में 'जनता पौलिसी' है। इसका परीक्षण के रूप में आरम्भ कर दिया गया है। आंशिक रूप से जनता पौलिसी की शुरुआत बम्बई, अहमदाबाद, शोलापुर, बंगलोर, कोयमुत्तूर, मद्रास, हैदराबाद, कलकत्ता, कानपुर, दिल्ली तथा कुछ चुने हुए ग्रामीण क्षेत्रों में की जायेगी। इस योजना की मुख्य विशेषताएं ये हैं—

(१) छोटी राशि—याने २५० से लेकर १००० तक का बीमा किया जा सकेगा।

(२) ३५ साल तक की आयु तक के लिये डाक्टरी जांच की आवश्यकता न होगी।

(३) एजेंट घरों में जाकर प्रीमियम ले आयेंगे या डाक टिकट द्वारा भी भेजा जा सकेगा।

इस योजना का उद्घाटन मई के अंतिम सप्ताह में दक्षिण क्षेत्र में श्री मोरारजी देसाई ने और जून के दूसरे सप्ताह उत्तरी क्षेत्र में श्री ढेबर ने किया। दोनों ने आशा व्यक्त की कि इस योजना से कम आय वाले—शहरी और ग्रामीण व्यक्ति लाभ उठा सकेंगे।

★

भारत में विदेशी पूंजी

प्राप्त विवरणों के अनुसार भारत में उद्योगों में लगाने के लिए ब्रिटेन, ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका तथा जर्मनी से ७३ लाख १६ हजार रुपए प्राप्त हुए। ब्रिटेन से ६५ लाख ९७ हजार रुपये विभिन्न निर्माण-उद्योगों के लिए, ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका से २५ हजार रुपये सीमेंट तथा रासायनिक उद्योगों के लिए और जर्मनी से ६ लाख ९४ हजार रुपये बांध-निर्माण आदि के लिए मिले। इस पूंजी से विदेशियों ने कितना लाभ उठाया और लाभ का कितना भाग फिर से भारतीय उद्योगों में लगाया, इस सम्बन्ध में सरकार को कोई जानकारी नहीं है। सरकार विदेशी पूंजी को उद्योगों में निमंत्रित करने के लिए एक विशेष सुविधा देने पर विचार कर रही है और वह यह है कि—

भारत सरकार का इरादा है कि विदेशी बैंकों द्वारा भारतीय उद्योगों को दिये गये ऐसे बड़े ऋणों के, जो सरकार द्वारा अनुमोदित हों और जिनकी वापस अदायगी ५ वर्ष या इससे अधिक की अवधि में की जाने वाली हो, ब्याज को आय कर से मुक्त कर दिया जाय।

वर्तमान आयकर अधिनियम के अन्तर्गत विदेशी ऋण-दाताओं को जो ब्याज दिया जाता है, उस पर भारतीय आय-कर लगता है। केवल उन बंधकों (बांड्स) के ब्याज पर आयकर नहीं लगता, जिन्हें भारतीय औद्योगिक संस्थाएं अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के साथ हुए ऋण-करार के अन्तर्गत जारी करती है और जिनकी गारंटी केंद्रीय सरकार करती है।

परन्तु, विदेशों में ऐसे दूसरे वित्तीय संस्थान भी हैं, जो अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की ही तरह ऋण देते हैं। अतः केन्द्र द्वारा स्वीकृत ऐसे वित्तीय संस्थान जो ऋण देंगे, उनके ब्याज पर भी आयकर नहीं लगेगा।

बाहर से कीमती यंत्र और मशीनें मंगाने के लायसेंस अभी इस शर्त पर दिये जाते हैं कि उनका भुगतान धीरे-धीरे कई वर्षों में दिया जाये या नया विदेशी ऋण मिलने पर उस ऋण की राशि से किया जाये। ऐसे कई मामलों में अभी विदेशी बैंकों या दूसरे ऋणदाताओं को ब्याज देना पड़ता है और इस ब्याज पर आयकर लगता है। अब यह तय किया गया है कि जिन बड़े-बड़े ऋणों का पांच वर्ष या

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उससे अधिक समय में भुगतान होना है, उनके ब्याज पर आयकर न लगाया जाये।

१९५८ में सं० रा० से १८॥ लाख डालर

संयुक्त राष्ट्र-संघ द्वारा सहायता के रूप में भारत को सन् १९५८ में, १८,५३,००० डालर दिये जायेंगे। संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेन्सियाँ इस सहायता का योगदान इस प्रकार है—

	डालर
(१) संयुक्त राष्ट्र टैक्नीकल सहायता प्रशासन	२,१७,०००
(२) अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन	१,८९,०००
(३) खाद्य और कृषि संगठन	३,७८,०००
(४) यूनेस्को	६,३३०००
(५) अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन	३३,०००
(६) विश्व स्वास्थ्य संगठन	४,०३,०००

यह सहायता केवल सरकार की ही प्रार्थना पर मिलती है और निम्नलिखित ३ रूपों में से किसी एक रूप में दी जाती है—

(१) देश में विशेष प्रयोजनाओं के लिये विशेषज्ञ प्रदान करना।

(२) देश के नागरिकों को विदेशों में व्यापक ट्रेनिंग के लिये सहायता देना, जिसका उपयोग वे अपने देश में कर सकें।

(३) विशेषज्ञों के कार्य से सम्बन्धित और मुख्य कर प्रदर्शन (डेमोस्ट्रेशन) के लिये सामग्रियों को देना।

ध्यान रहे, यह राशि संयुक्त राष्ट्र-संघ, विश्व स्वास्थ्य संघ और यूनेस्को की नियमित वार्षिक सहायता के अतिरिक्त हैं, जो इनके बजटों में से दी जाती हैं।

विश्वबैंक का निजी उद्योगों को दिया ऋण

अब तक विश्व बैंक ने भारत के निजी उद्योगों को जो ऋण दिया है, वह इस प्रकार है—

१. टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी लि०	७५० लाख डालर
२. टाटा हाइड्रो एजेन्सीज लि०	१६२ ,, ,,
३. इंडियन आइरन एंड स्टील कम्पनी लि.	५१५ ,, ,,
४. इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया	१०० ,, ,,

बैंकों द्वारा ऋण

देश के व्यापारिक बैंकों को उद्योग-व्यापार के विकास के लिये रुपया उधार देने का महत्त्वपूर्ण भार उठाने के कारण इसमें काफी कठिन स्थितियों में से गुजरना पड़ा। विकास कार्य के लिये लोहे व मशीन की आयात में वृद्धि करना अति आवश्यक था। उद्योग व व्यापार को सन् १९५५ में १९५६ के मुकाबले में बैंकों द्वारा दी जाने वाली पेशगी में वृद्धि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है :—

अनुसूचित बैंकों द्वारा विभिन्न कार्य के लिये दिया गया ऋण (करोड़ रु० में)

	१९५४	१९५५	१९५६
उद्योग	१९२.८९	२४०.९९	३००.३८
व्यापार	२७५.०४	२९२.२८	३५६.३२
कृषि	१५.७२	१२.४५	१७.६९
निजी और पेशे	४५.३२	५४.७९	५८.२२
विविध पेशे	३५.५१	५४.९२	३१.२५
जोड़	५६४.४८	६२५.६३	७६३.८७

सेविंग खातों की ब्याज-दर बढ़ी

भारत सरकार की एक घोषणा के अनुसार पहली जून से डाकखाने के सेविंग बैंक की ब्याज दर १/२ प्रतिशत बढ़ा दी गई है।

अब ब्याज-दर १० हजार रु० तक के वैयक्तिक खाते पर और २० हजार रु० तक के सामूहिक खाते पर ३॥ प्रतिशत प्रति वर्ष होगी। इससे अधिक रकम पर तथा सार्वजनिक खाते पर ब्याज दर प्रतिवर्ष २ प्रतिशत होगी। इससे पहले ये दरें २ प्रतिशत तथा १½ प्रतिशत थीं।

सेविंग बैंक के अन्य खातों में ब्याज-दर में भी इसी प्रकार १/२ प्रतिशत की वृद्धि होगी।

डाकखाने के उपहार पत्र

१ जुलाई से डाकखाने के उपहार-पत्रों का प्रचलन किया गया है। विवाह आदि शुभावसरों पर नकद रुपयों और सामग्रियों के उपहार देने की तरह ही इनको प्रयुक्त किया जा सकेगा। ये उपहार-पत्र ५, १०, ५०, १०० और १००० (शेष पृष्ठ ४०४ पर)

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अर्थ वृत्त चयन

संसद का पिछला अधिवेशन

नवनिर्वाचित संसद का प्रथम अधिवेशन यद्यपि २० दिन भी नहीं चला तथापि आर्थिक कानूनों की दृष्टि से वह महत्वपूर्ण माना जायेगा। रेलवे बजट और केन्द्रीय सरकार का बजट इस अधिवेशन की विशेषताएं हैं। रेलवे ने माल पर भाड़ा तथा यात्रियों का किराया बढ़ा दिया। केन्द्रीय वित्त मन्त्री ने जितने कर बढ़ाए थे, असाधारण रूप से अधिक हैं। उत्पादन कर तथा तटकरों में वृद्धि के अतिरिक्त सम्पत्ति कर तथा व्यय कर भारत की कर प्रणाली में एक नए अध्याय का सूत्रपात करते हैं। इनकी विस्तृत चर्चा पाठक सम्पदा के गतांक में पढ चुके हैं। इन दोनों बजटों के अतिरिक्त भी संसद का यह अधिवेशन अनेक अन्य आर्थिक विधेयकों के कारण भी महत्वपूर्ण रहा। वे विधेयक संक्षेप से निम्नलिखित हैं—

औद्योगिक विवाद संशोधन

सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ दिन पहले यह फैसला दिया था कि जो कारोबार बन्द हो रहे हैं, उनके कारीगरों की नौकरी से छूटने का कोई मुआवजा नहीं दिया जायगा। सुप्रीमकोर्ट के इस निर्णय को निष्क्रिय बनवाने के लिए राष्ट्रपति ने एक आर्डीनैन्स या अध्यादेश जारी कर दिया था।

उसी अध्यादेश को कानूनी रूप देने के लिए यह बिल संसद में उपस्थित किया गया। इसके अनुसार यदि कारोबार ऐसी परिस्थितियों में बन्द किया गया है, जिन पर विनियोजक का वश नहीं है तो मजदूरोंको ३ महीने का औसत वेतन मुआवजे के रूप में दिया जायेगा।

कोयला क्षेत्र अधिग्रहण

इस विधेयक के अनुसार सरकार कोयले के कुछ क्षेत्र उचित प्रतिफल देकर अपने हाथ में कर सकती है।

जीवन बीमा निगम

इस विधेयक के अनुसार केन्द्रीय सरकार को निगम के कर्मचारियों के वेतन कार्यदशा आदि में परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया है। एजेण्टों को भी वह लाइसेंस जारी कर सकती है।

रिजर्व बैंक संशोधन

इस विधेयक के अनुसार रिजर्व बैंक को यह अधिकार दिया गया है कि वह निजी उद्योगों को भी मध्यकालीन ऋण दे सकें। एक दूसरे विधेयक के अनुसार स्टेट बैंक आफ इण्डिया को भी यह अधिकार दिया गया है कि यह ६ महीने से अधिक समय के लिए अचल सम्पत्ति की जमानत पर उद्योगों को ऋण दे सकता है।

केन्द्रीय बिक्री कर

अन्तर-राज्यीय व्यापार के लिए घोषित वस्तुओं में सूत भी महत्वपूर्ण वस्तु के रूप में सम्मिलित कर लिया जाय। यह भी सिफारिश की गई है कि बिक्रीकर किसी चीज के आखिरी लेन-देन (Stage) पर लगाया जाय। अन्तरराज्यीय व्यापार में राज्य के कानून लागू न हों।

आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक

१९५५ के आवश्यक वस्तु कानून के अन्तर्गत अब सरकार गेहूँ का स्टाक रखने वाले व्यापारी को अपना थोड़ा या सारा स्टाक बेचने के लिए आदेश दे सकेंगे। यदि मूल्य नियंत्रण न हुआ, तो उन्हें पिछले तीन महीने की औसत से अनाज बेचना पड़ेगा।

—

तेल से असम में तूफान

पाठकों को ज्ञात होगा कि पिछले वर्ष से ही भारत सरकार और ब्रिटेन के पूंजीपतियों द्वारा संचालित 'असम आइल कम्पनी' में देश में एक तेल शोधक कारखाना खोलने के विषय में बातचीत चल रही थी। वैसे ही असम आइल कम्पनी की ढिलाई के कारण बातचीत में काफी देर लग गई और कठिनाइयां भी काफी सामने आईं। लेकिन अब जब किसी तरह समझौता तो हो गया पर असम में तूफान उठ खड़ा हुआ है कि वहां की कांग्रेसी सरकार तथा समस्त राजनैतिक दल केन्द्रीय सरकार से संघर्ष तक करने को तैयार हो गये हैं। इस तूफान का कारण यह है कि केन्द्रीय सरकार ने निर्णय किया है कि तेल शोधन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

का नया कारखाना बिहार के बरौनी नामक स्थान में खोला जाये। असम सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि यह कारखाना असम में ही स्थापित किया जाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार ने इसी प्रश्न पर विचार करने के लिये श्री वशिष्ठ की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की थी। उसने बरौनी को ही उपयुक्त स्थान बताया। कम्पनी की भी आम राय बरौनी के पक्ष में थी।

बरौनी को ही इसके लिये चुनने का कारण यह है कि यहां से कलकत्ता, बिहार और उत्तर प्रदेश को आसानी से तेल भेजा जा सकता है। विश्व में भी सभी तेल शोधक कारखाने ऐसे स्थानों पर स्थित हैं जहां उनका उत्पादन, उपभोग वौर वितरण की व्यवस्था आसानी से की जा सके। असम में न तो इतने अच्छे यातायात के साधन हैं और न ही पूरे तेल का उपयोग वहीं किया जा सकता है। असम के सीमावर्ती राज्य में इतना महत्वपूर्ण कारखाना युद्ध की स्थिति में कभी शत्रु की बमवर्षा का शिकार हो सकता है।

इस समय असम में दिगबोई का जो छोटा तेल शोधक कारखाना है, उसका भी असम केवल ३० प्रतिशत ही उपयोग करता है और बाकी अन्य राज्यों को भेजा जाता है। अतः नये तेल शोधक कारखाने का पूरा उत्पादन असम में होने पर बाहर भेजने को कार्य काफी जटिल हो जायेगा। करीब २५ लाख टन तेल के बाहर भेजने पर बहुत खर्च बैठेगा। सीमांत असम, पश्चिमी बंगाल और बिहार को तेल भेजने के लिये १ दर्जन तक विशेष रेलों की आवश्यकता होगी। इस समय न तो असम की रेलें इतना भार उठाने की स्थिति में है और न ही रेल विभाग नई रेल बिछाने की सामर्थ्य रखता है। असम में शोधित तेल कलकत्ता में ३ आना प्रति गैलन मंहगा बिकता। संयोग से बरौनी में पहले से ही बहुत बड़ा एक रेलवे यार्ड और शेड बन रहा है तथा जल यातायात के उपयोग की संभावना भी है।

असम सरकार का मुख्य दावा यह है कि राज्यों के संतुलित आर्थिक विकास के लिये इस तेल शोधक कारखाने की स्थापना असम में ही करनी चाहिए। केन्द्रीय सरकार ने आश्वासन दिया है कि वहां के आर्थिक और औद्योगिक विकास का पूरा ध्यान रखा जायेगा। इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि कोलम्बो योजना के अन्तर्गत कनाडा के विशेषज्ञ की सेवाएं उपलब्ध हो जो यह बता कि नहोरकातिया के तेल क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली पेट्रोल गैस का उपयोग उद्योग में किस तरह किया जाये। इसे प्रतिदिन ४ लाख टन पेट्रोल गैस प्राप्त की सकती है। इसके लिये तेल और गैस आयोग के तत्त्वावधान में गैस उपयोग मंडल की स्थापना करने का विचार किया जा रहा है।

बरौनी के तेलशोधक कारखाने की क्षमता २० लाख टन तेल शोधन करने की होगी। असम के नहोरकातिया से कलकत्ता तथा बरौनी के लिये पाइप लाइन अमेरिकन कम्पनी द्वारा बिछाई जायेगी इसकी लम्बाई असम से कलकत्ता ८०० और कलकत्ता से बरौनी १२५ मील होगी। दिसम्बर तक यह कार्य पूर्ण होने की आशा है। पाइप लाइन की क्षमता प्रतिवर्ष ४५ लाख टन तेल वहन करने की होगी। पाइप लाइन और कारखाने के पूर्ण हो जाने पर प्रतिवर्ष २५ करोड़ रु० की बचत होगी।

——

कपास का भविष्य

एक नई समस्या किसानों के सामने और विशेष कपास पैदा करने वाले किसानों के सामने आने वाली है। अभी तक किसान कपास के मुंह मांगे दाम पाते हैं। सरकारें भी यह कोशिश करती हैं कि किसानों को अच्छा मूल्य मिले। लेकिन जिस तरह नकली रेशम की पैदावार और खपत बढ़ रही है उसे देखते हुए यह भविष्यवाणी करना कठिन है कि किसान कब तक कपास के सम्बन्ध में अपनी आवाज ऊंची रख सकेगा। अमेरिकन कौटन स्पिनर्स के वें वार्षिक अधिवेशन में, जो २६ अप्रैल १९५७ को हुआ इस बात पर चिन्ता प्रकट की गई थी कि कपास का भविष्य ठीक तरह से उज्जवल नहीं है। इस अधिवेशन में अमेरिकन सरकार से यह मांग की गई कि ऐसे कानून बना दिये जांय, जिनसे कपास का बाजार स्वतन्त्र गति से चल पाता। एक बार उत्पादक और व्यापारी को यह समझ जाना चाहिये कि कपास का भविष्य क्या है।

अखबारों पर पूंजीपतियों का प्रभुत्व

अभी हाल ही में (१७ मई को) इंगलैंड की पार्लि-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मेंट में वहां के दैनिक अखबारों के बारे में चर्चा हुई थी। उस दौरान में जो बातें कहीं गयीं, वे आज के अखबारों की वास्तविक स्थिति पर अच्छा प्रकाश डालती हैं। पार्लियामेंट के एक सदस्य श्री फ्रैंक ऐलुअन ने, जो खुद एक पत्रकार हैं, बताया कि —

इंगलैंड का अखबारी उद्योग चार बड़ी कम्पनियों के हाथ में है, जिन्होंने गतवर्ष २ करोड़ ७० लाख पौंड व्यापारी मुनाफा कमाया। नतीजा यह हुआ है कि पिछले बारह महीनों में बहुत से पुराने दैनिक अखबार (आर्थिक दृष्टि से इन बड़े अखबारों के मुकाबले नहीं टिक सकने के कारण) बन्द हो गए! इन प्रभावशाली अखबारी कम्पनियों के पीछे चन्द व्यक्ति (याने उनके मालिक और संचालक) हैं, जो अत्यन्त अमीर, अत्यन्त प्रभावशाली और कुछ अपवादों को छोड़कर, अत्यन्त प्रतिगामी लोग हैं। इन लोगों के लिए अपने हितों को राष्ट्रीय हित का रूप देना बड़ा आसान है।

श्री फ्रैंक ऐलुअन ने चेतावनी देते हुए कहा कि "इस तरह अखबारों का चंद लोगों के हाथ में होना लोकतन्त्र को दूषित कर रहा है और आम जनता के हितों को इससे बड़ा खतरा है।" इस संदर्भ में अखबारों की स्वतन्त्रता का मतलब सिर्फ करोड़पतियों की स्वतन्त्रता से और जो उनके हित के अनुकूल खबरें हों, उन्हें छापने तथा प्रतिकूल खबरों को न छापने की आजादी से है।

आलू में अनाज से तिगुनी कलौरी

इधर कुछ महीनों में देश में अन्न की कमी प्रतीत हो रही है। अनाजों के उत्पादन बढ़ाने के साथ आलू के उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्न किए जाने चाहिए, क्योंकि आलू में किसी भी अनाज से तिगुनी मात्रा में कैलोरी होती है। देश में लगभग ३०० वर्ष से आलू का चलन है। परन्तु खाद्य के रूप में इसका भान कम था।

देश में लगभग ६ लाख एकड़ जमीन में अर्थात् कुल खेती के केवल ०.२ प्रतिशत भाग में आलू की खेती होती है। इसका वार्षिक उत्पादन ६ करोड़ मन है। देश में एक व्यक्ति के हिस्से में साल भर में केवल ४॥ सेर आलू आता है। जबकि पाश्चात्य देशों में एक व्यक्ति के हिस्से में २५० सेर पड़ता है।

रबड़ की खेती

भारत में रबड़ का उत्पादन, दक्षिण भारत में मुख्यतः केरल में होता है। राज्य में लगभग १ लाख मजदूरों को इससे प्रत्यक्ष रूप से मजदूरी मिलती है। बहुत से व्यापारी और बिचौलिया भी अप्रत्यक्ष रूप से इस धंधे में लगे हैं।

रबड़ की खेती सन् १९०२ में आरम्भ हुई थी। मांग बढ़ते रहने के साथ-साथ इसकी खेती का भी विस्तार होता रहा। १९१० में रबड़ के बगीचों का क्षेत्रफल २९,५०० एकड़ था। सन् १९२५ में यह ६७,२९७ एकड़ हो गया। द्वितीय महायुद्ध में रबड़ की असाधारण मांग हुई। १९४३-४६ के बीच खेती का क्षेत्रफल सबसे अधिक बढ़ा, सन् १९४२ में रबड़ की खेती का क्षेत्रफल जहां १,२४,९४३ एकड़ था, वहां १९४६ में १,६९, ९२३२ एकड़ हो गया। इस प्रकार ३६ प्रतिशत वृद्धि हुई।

सन् १९५५ के अन्त तक रबड़ की खेती का क्षेत्रफल २,०७,२३९ एकड़ और उत्पादन २२,४८१ टन हो गया। १९५३ में भारत में रबड़ की खेती का क्षेत्रफल २.३ प्रतिशत और भारतीय रबड़ का उत्पादन संसार भर के उत्पादन का १.२ प्रतिशत था।

१०० एकड़ से अधिक के बगीचों में लगी पूंजी अनुमानतः ९.९२ करोड़ रुपए है, जिसमें से ७.५६ करोड़ रु० या ७६ प्रतिशत भारतीय और २.३६ करोड़ रु० या २४ प्रतिशत अभारतीय पूंजी है। इन बगीचों का कुल क्षेत्रफल १,००,८०० एकड़ है जब कि रबड़ उत्पादक कुल भूमि २,०७,२३९ एकड़ है। १९३९ और १९५४ के बीच में पूंजी विनियोग में अभारतीयों के स्थान पर भारतीय पूंजी में वृद्धि हुई।

आय के अच्छे साधन

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्कों से आय बराबर बढ़ रही है। १९३८-३९ में केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों से केवल ९ करोड़ रुपये (कुल कर-राजस्व का १२ प्रतिशत) की आय थी जो बढ़ कर १९४४-४५ में ३८ करोड़ रु० (१५ प्रतिशत), १९५०-५१ में ६८ करोड़ रु० (१९ प्रतिशत) और १९५५-५६ में १४५ करोड़ रु० (३४ प्रतिशत) हो गयी।

आय-कर (निगम-कर सहित) से होने वाली आय

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सात-गुना बढ़ी। १९३८-३९ में इससे १६ करोड़ रु० की आय हुई। १९५५-५६ में यह आय बढ़ कर ११३ करोड़ रु० हो गयी। १९५७-५८ के बजट में आय-कर से १३७ करोड़ रुपये (कुल राजस्व का २७ प्रतिशत) आय होने का अनुमान है।

न भीगने वाला वस्त्र

एक नये करघे द्वारा अमेरिका में ऐसा सूती कपड़ा तैयार कर की तैयारियां हो रही हैं, जिसे यदि तेज से तेज वर्षा में भी पहना जाए तो पहनने वाला भीगेगा नहीं। इसके अतिरिक्त इस कपड़े की एक विशेषता यह भी है कि छिद्रदार होने के कारण यह हवादार होता है। इसलिए इसे पहन ने वाले को ठण्डी हवा लगती रहती है।

इस सूती कपड़े पर पानी का असर इसलिए नहीं होता, क्योंकि इस की बुनाई काफी घनी होती है। किसी प्रकार का लेप इस पर नहीं किया जाता, जिसके कारण यह कपड़ा नमीदार मौसम में भी पहना जा सकता है तथा इसमें किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती।

खास करघे द्वारा विशेष रूप से वस्त्र तैयार कर खेलों के मैदान ढक गए हैं और पांच वर्षों से इसके बारे में प्र[illegible] र्शन किए जा रहे हैं। न्यू औलियन्स के खेलने के मै[illegible] को जब तारपौलिन नामी इस वस्त्र से ढका गया, [illegible] मूसलधार वर्षा होने पर भी यह मैदान सूखा रहा। अमेरि[illegible] कृषि-विभाग के अधिकारियों का यह कथन है कि [illegible] तरह का सूती कपड़ा तैयार करने वाले यन्त्र को सूती क[illegible] के सामान्य करघों के साथ आसानी से व बहुत कम खर्च[illegible] जोड़ा जा सकता है।

—

(पृष्ठ ४०० का शेष)

रु० के मूल्य के हैं। इन उपहार पत्रों को सरलता से बच[illegible] सर्टिफिकेटों में बदला जा सकेगा। बचत सर्टिफिकेटों को उप[illegible] हार दिये जाने के पहले कई प्रकार की दफ्तरी कार्रवा[illegible] करनी पड़ती थी। लेकिन इन उपहार पत्रों को सरलता [illegible] बचत सर्टिफिकेटों में बदला जा सकेगा। साथ ही इनमें [illegible] की भी कोई पाबन्दी नहीं है।

किसानों के लिये ऋण-व्यवस्था

कृषि-कार्य में उन्नत साधनों को अपनाने तथा कृषि उत्प[illegible] को बढ़ाने के लिये श्री कृष्णप्पा की अध्यक्षता में एक समि[illegible] बनाई गयी थी। इस समिति ने चीन और दूसरे [illegible] देशों का पर्यवेक्षण करने पर सरकार को जो सुझाव दि[illegible] उनमें से एक किसानों को रुपये उधार मिलने की सुवि[illegible] प्रदान करना भी था।

केन्द्रीय सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार कर लि[illegible] है। रिजर्व बैंक और आयोजना आयोग से विचार विनि[illegible] के पश्चात् सरकार १९५७-५८ में किसानों को सहकारी समितियों के द्वारा ८० करोड़ रु० उधार देगी।

इस बात का ध्यान रखा गया है कि सहकारी समि[illegible] तियों द्वारा उधार देने की प्रक्रिया सरल हो। इसके लि[illegible] राज्य और कृषि तथा खाद्य मंत्रालय ने कार्रवाई आरम्भ कर दी है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सहकारी समितियों द्वारा २०० करोड़ रु० उधार देने का निश्चय कि[illegible] गया है।

—

सरकारी विज्ञापनों के लिए स्वीकृत
राजस्थान शिक्षा विभाग से मंजूरशुदा

सेनानी साप्ताहिक

सम्पादक :—
सुप्रसिद्ध साहित्य सेवी श्री शंभुदयाल सक्सेना

कुछ विशेषताएं—

★ ठोस विचारों और विश्वस्त समाचारों से युक्त
★ प्रान्त का सजग प्रहरी
★ सर्वाधिक लोकप्रिय पत्र

ग्राहक बनिए, विज्ञापन दीजिए, रचनाएं भेजिए
नमूने की प्रति के लिए लिखिए—
व्यवस्थापक, साप्ताहिक सेनानी, बीकानेर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

साम्यवाद और सर्वोदय

क्या कम्युनिज्म और सर्वोदय के बीच कोई कम्पोमाइज (समझौता) या 'कोआपरेशन' (सहयोग) हो सकेगा ? इस प्रश्न के उत्तर में श्री विनोबा कहते हैं—

दोनों के बीच समझौता कुछ भी नहीं हो सकेगा, लेकिन सहयोग बहुत हो सकेगा। सर्वोदय अपना विचार नहीं बदलेगा, क्योंकि वह किसी विचार की प्रतिक्रिया नहीं है, वह स्वयं एक जीवन-विचार है। कम्युनिज्म बदलता रहेगा, क्योंकि वह प्रतिक्रिया-रूप है।

योरप में जो कैपिटलिस्ट सोसायटी (पूंजीवादी समाजरचना) बनी थी, उसके प्रतिक्रियास्वरूप कम्युनिजम बना है। जो प्रतिक्रिया-रूप विचार है, वह स्वयमेव पूर्ण जीवन-सिद्धान्त नहीं बन सकता। वह तो हवा के झोंके के अनुसार बदलता जायेगा। आप देखते हैं कि यहाँ पर 'कान्स्टिट्यूशनल कम्युनिजम' (वैधानिक साम्यवाद) शुरू हुआ है, जो कम्युनिजम का एक 'डेवलपमेंट' (विकास) है। वे ही अपना समझौता करने को राजी होंगे, क्योंकि उनके पास सार्वभौम दृढ़ सिद्धान्त नहीं है।

वह प्रतिक्रिया-रूप है, इसलिए 'कैपिटलिजम' (पूंजीवाद) में जो दोष थे, उनकी प्रतिक्रया उन्होंने बनायी। हिंदुस्तान की परिस्थिति योरप से भिन्न है। यहाँ धर्मभेद, जातिभेद, भाषाभेद आदि बहुत हैं। समाज कृषि प्रधान है। बहुसंख्या कृषकों की है, मजदूरों की नहीं है। योरप में उन्होंने सारा दारोमदार मजदूरों पर रखा था, वैसा वे यहाँ नहीं रख सकते हैं। यहाँ पर मुख्य आधार किसानों पर रखना होगा और किसान-मजदूरों को एक मानना होगा। इसके अलावा हिंदुस्तान के जमीन का एक बड़ा मसला है। यहाँ और खासकर केरल में जमीन बहुत कम है और जनसंख्या ज्यादा। योरप के समान यहाँ पूंजवाद विकसित नहीं हुआ है।

> ऐसी हालत में कम्युनिज़्म ही अपना समझौता करता जायेगा। इसलिए सर्वोदय उसके साथ सहयोग (कोआपरेशन) करने को तैयार होगा। जितना वह अपना रूप बदलेगा और सर्वोदय के नजदीक आयेगा, उतना सर्वोदय उसके साथ सहयोग के लिए तैयार होगा।

समझौते का अर्थ यह है कि आप कुछ छोड़ें, हम कुछ छोड़ते हैं। इस तरह यहां नहीं होगा। बल्कि आप कुछ छोड़ें, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, तो फिर आपका और हमारा सहयोग होगा। इस तरह हमारी स्थिति कायम रहेगी और उनकी स्थिति बदलती रहेगी।

> इसीलिए हमने कहा था कि धीरे-धीरे कम्युनिज़्म की नदी सर्वोदय के समुद्र में मिल जायेगी। दूसरी भी नदियां यहां आकर मिल जायेंगी।

सोशलिज्म (समाजवाद) और 'वेलफेअर स्टेट' (कल्याण राज्य) भी आखिर अपने को समाप्त करके सर्वोदय में डूबेंगे, ऐसी व्यापक वस्तु सर्वोदय है। क्या समुद्र किसी नदी के साथ समझौता करता है ? पर वह सहयोग के लिए बिल्कुल खुला है। उसे उसमें करना भी क्या पड़ता है ? तुम आओ और हममें डूब जाओ ! इसलिए सर्वोदय को उसमें कुछ तकलीफ ही नहीं है !

मनुष्य सभ्य और धनी कब बनता है ?

जिस देश में गरीब के लिए रोजगार करने का उपाय कम है, रास्ता बंद है, वही गरीब ! जिस देश में गरीब धनी होने का भरोसा रखता है, उस देश में वह भरोसा ही सबसे बड़ा धन है। हमारे देश में रुपये का अभाव है, यह कहने से बात पूरी नहीं होती। असल बात यह है कि हमारे देश में भरोसे का अभाव है। इसीलिए हमारे देश में सबसे ज्यादा आवश्यकता हाथ में भिक्षा देने की नहीं है, बल्कि मन में भरोसा देने की है।

समाज की उपयोगिता

अच्छी तरह सोचकर देखें, तो मालूम होगा कि दारिद्रय का भय भूत का डर है। यह डर भाग जाता है, यदि हम समाज बनाकर खड़े हो सकें। विद्या कहो, रुपया कहो, प्रताप कहो, धर्म कहो, मनुष्य के लिए जो कुछ कीमती और महान् है, वह मनुष्य ने समाज बनाकर या मिल कर ही पाया है। बलुआ जमीन में फसल नहीं होती, क्योंकि

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वह बंधती नहीं; इसलिए उसमें रस जम नहीं पाता, अव-काश में से सब बह जाता है। इसीलिए उस जमीन का दारिद्र्य मिटाने के लिए उसमें चिकनी मिट्टी, सड़ी खाद, पत्ते आदि ऐसी चीजें मिलाते हैं, जिससे उसका अंतर कम हो, वह चिपक सके, उसका पिंड हो सके। मनुष्य के लिए भी ठीक यही बात है; उनमें अन्तर बहुत होते ही उनकी शक्ति काम की नहीं रहती, शक्ति होने पर भी नहीं के समान हो जाती है। इसी से मनुष्य अनेकों के साथ मिल कर सोच सकता है। उसकी भावनाएं बड़ी हो उठती हैं। इन्हीं बड़ी भावनाओं के ऐश्वर्य से मनुष्य के मन की गरीबी मिटती है। जितने ज्यादा मनुष्यों के मनों का योग होता है, उनकी भावनाएं भी उतनी ही बड़ी हो उठती हैं। तब प्रत्येक मनुष्य हजार-हजार मनुष्यों की भावना की सामग्री प्राप्त करता है। इसीसे उनका मन धनी होता है।

मनुष्य-योग ही सभ्यता

सभ्यता क्या है ? और कुछ नहीं, जिस अवस्था में मनुष्य के लिए इस प्रकार के एक योग का क्षेत्र तैयार होता है, जहां प्रत्येक मनुष्य की शक्ति सब मनुष्यों को शक्ति देती और सब मनुष्यों की शक्ति प्रत्येक मनुष्य को शक्तिमान करती है।

आज हमारा देश, जो इस प्रकार विषम गरीब है, उस का प्रधान कारण, हम लोग अलग-अलग होकर अपनी-अपनी विपदा आप वहन करते हैं। भार के बोझ के मारे जब कमर टूट जाती है, तब सिर उठा कर खड़े होने का भी उपाय नहीं रहता। जहां सभ्यता का जोर है, प्राण है वहाँ देश का मनुष्यों का कोई भी एक दल उपवास करके मरेगा या दुर्गति में डूब जायगा, यह बात मनुष्य सह्य नहीं कर सकता; क्योंकि मनुष्य के साथ मनुष्य के योग द्वारा सभी का भला होगा, यही सभ्यता का प्राण है। इसलिए यूरोप में जो लोग केवल गरीबों के लिए सोचने लगे, उनकी समझ में आया कि जो अकेले लोग अपना सुख अकेले ही वहन करते हैं, उनकी लक्ष्मी-श्री किसी उपाय से भी नहीं बढ़ सकती। अनेक गरीब अपनी सामर्थ्य को एक जगह मिला सकें, तो वह मिलन ही पूंजी है। अनेक लोगों की भावना के योग से सभ्य मनुष्य की भावना बड़ी हुई है। इसी तरह अनेक कामों का योग होने से काम अपने आप बड़ा हो सकता है। गरीब को सामर्थ्य देने का उपाय यह मिलन का रास्ता है। यूरोप में यही क्रम से चौड़ा होता जा रहा है। मेरा विश्वास है कि यह रास्ता ही पृथ्वी में सबसे बड़ा उपार्जन का रास्ता होगा।

—रवीन्द्रनाथ ठाकुर

——

सर्वोदय समाज और बैंक

सर्वोदय समाज में व्यक्तिगत व्यवसायिक बैंक नहीं होंगे और बैंकों का उपयोग मुनाफे के लिए नहीं किया जायेगा। सर्वोदय व्यवस्था में दो प्रकार के बैंक होंगे, सह-कारी बैंक और राज्य बैंक। सहकारी बैंक गांव की बचत को एकत्र कर उसका विभिन्न कार्यों में उपयोग करेंगे तथा खुद के रोजगारी व सहकारिता के आधार पर चलने वाले उद्योगों को जरूरी पूंजी प्रदान करेंगे। ये बैंक सहकारी खेती-बाड़ी, संयुक्त खेती तथा व्यक्तिगत किसानों को पूंजी की सहायता देंगे। जहां सहकारी बैंक उस क्षेत्र की जरूरतों को अपने साधनों से पूरा करने में असमर्थ होगा, वहां राज्य बैंक उसे अतिरिक्त पूंजी देगा। सहकारी बैंक जमा करने के लिए नकद रकम के साथ जिन्स भी ले सकते हैं।

राज्य बैंक केन्द्रीय बैंक का काम करेगा और वह देश की बैंक-पद्धति में सामञ्जस्य लाने में उसमें नवीनीकरण करने के लिए जिम्मेदार होगी। इसलिए बैंक व सहकारी बैंकों के उद्देश्यों और नीतियों में समन्वय लाने के लिये संस्थागत सहयोग की आवश्यकता होगी।

——

गांवों का भला भारत का भला

मैं तो कहूंगा कि यदि गांव नष्ट होता है तो भारत भी नष्ट होकर रहेगा। ऐसी हालत में भारत असली भारत नहीं रह जायेगा। दुनिया में वह अपना दायित्व नहीं निभा सकेगा। गांव का पुनरुद्धार उसी हालत में सम्भव है, जब उसका तनिक भी शोषण न हो। बड़े पैमाने के औद्योगीकरण के कारण जब प्रतिस्पर्द्धा और बाजार की समस्याएं उत्पन्न होंगी, उस हालतमें निश्चय ही ग्रामीणों का सक्रिय अथवा

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नया सामयिक साहित्य

वैदिक गृहस्थाश्रम—ले० प्रो० विश्वनाथ विद्यालंकार, प्रकाशक—वैदिक साहित्य मण्डल, ९ लक्ष्मण चौक, देहरादून, मूल्य ५)।

प्रस्तुत पुस्तक वेदों के प्रकाण्ड विद्वान श्री विश्वनाथ विद्यालंकार ने गृहस्थाश्रम के प्रति वेदों की आज्ञा, परामर्श और दृष्टिकोण का विस्तृत परिचय देने के लिए लिखी है। विवाह और गृहस्थाश्रम का मुख्य उद्देश्य विषय वासना नहीं, राष्ट्र-निर्माण में सहयोग है। पत्नी की स्थिति समाज में हीन न होकर पुरुष के समान है। योग्य पत्नी के लिए किन गुणों व स्वभाव का ग्रहण आवश्यक है, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए नागरिक के परिवार व समाज के प्रति मुख्य कर्त्तव्य क्या हैं, गृहस्थ-जीवन को कैसे सुखी बनाया जाये संतान-पालन कैसे करना चाहिए, गृहस्थ को सुखी कैसे बनाया जा सकता है आदि बातों पर वेद के मंत्रों से प्रकाश डाला गया है। यह आश्चर्य की बात है कि लेखक के मतानुसार वेद में पति को सलाह दी गई है कि वह पत्नी को अपना मकान स्त्री धन के रूप में दे दे, लड़कियों को दहेज दिया जाये, मातृहीना पुत्री पिता की ओर विधवा पत्नी की उत्तराधिकारिणी हो सकती है।

इतनी विद्वत्तापूर्ण लिखी गई पुस्तक की छपाई कागज व बाईंडिंग में अधिक ध्यान दिया जाता, तो बहुत अच्छा होता।

निष्क्रिय सहयोग होकर रहेगा। इसलिए हमारे सारे प्रयत्न ग्रामों को इस तरह आत्मनिर्भर बनाने पर केन्द्रित होने चाहिए, जिससे वे मुख्यतः उपयोग के लिये उत्पादन करें। अगर ग्रामोद्योग की यह विशेषता सुरक्षित रहे, तो ग्रामिणों द्वारा ऐसे आधुनिक यंत्रों और औजारों के प्रयोग पर कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए जिन्हें वे स्वयं बना सकते हों और जिनका प्रयोग करने में वे समर्थ हों। एतराज केवल यहीं है कि यंत्रों का प्रयोग दूसरों के शोषण के लिये न हो।''

[गांधीजी, हरिजन २९-८-३६]

ग्रामदान—विनोबा, पृष्ठ १७६, मूल्य '७५ रु०, प्रकाशक—अ० भा० सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन राजघाट काशी।

प्रस्तुत पुस्तक में पूज्य विनोबा के ग्रामदान सम्बन्धी भाषणों का संकलन किया गया है। वास्तव में ये पूरे भाषण नहीं, वे अंश निकाल लिये गये हैं जो विषय की दृष्टि से अनावश्यक समझे गये। ये भाषण एक प्रकार से ग्रामदान की व्याख्या करने वाले एक-एक अध्याय हैं।

श्री दादा भाई नाईक की भूमिका में ग्रामदान क्या है? इसका पूरा सार आ गया है। आज आनन्द की अनुभूति नहीं होती क्योंकि परिवार 'मैं' और 'मेरे' में संकुचित हो गया है। इसके लिये आवश्यक है 'वसुधैव कुटुम्बकम्' तक पहुँचना। ग्रामदान में आर्थिक उन्नति निहित है, धर्म तो उसकी आत्मा ही है और आधुनिक विज्ञान से भी इसका बैर नहीं, बशर्ते उसे शोषण का साधन न बनाया जाये। ग्रामदान आत्मनिर्भर होना आवश्यक मानता है। शासन और कांचन-निरपेक्षता उसका प्रयत्न होगा।

आज का धर्म—लेखक महात्मा भगवानदीन। पृष्ठ १०४, मूल्य ८ आना, प्रकाशक—वही।

प्रस्तुत पुस्तक में प्रसिद्ध विचारक और लेखक महात्मा भगवानदीन ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक युग का अपना धर्म होता है, पर सत्य शाश्वत धर्म के रूप में सर्वत्र रहता है। इस पुस्तक के ९ अध्यायों में से ४ अध्यायों में इसी सत्य की व्याख्या की गई है। पुस्तक विचारोत्तेजन का ही काम नहीं करती वरन् सोचने समझने को भी विवश करती है।

सफाई—(विज्ञान और कला)-लेखक श्री वल्लभ स्वामी, पृष्ठ १५०, मूल्य '७५ रु०, प्रकाशित—वही।

सन् १९४९ में लेखक की एक पुस्तक 'मल-मूत्र-सफाई' प्रकाशित हुई थी। प्रस्तुत पुस्तक में इस पुस्तक के अलावा श्री धीरेन्द्र मजूमदार की पुस्तक 'सफाई विज्ञान' का समावेश कर लिया गया है। सफाई के विस्तार में न जाते हुए केवल ग्राम-सफाई के विषय पर ही इसमें चर्चा की गई है। ऐसा स्वाभाविक ही था, क्योंकि वास्तविक भारत गांव में बसा है और वहीं सफाई के व्यापक प्रचार की आवश्यकता है भी।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विनोबा संवाद—लेखक—श्री ब्यौहार राजेन्द्रसिंह, पृष्ठ ७६, मूल्य '३८ रु०, प्रकाशक—वही।

१९४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह के दिनों में विनोबा जी नागपुर जेल में रखे गये थे। लेखक ने भी इस सत्याग्रह में भाग लिया। उन्हें भी नागपुर जेल ही भेजा गया। इस प्रकार लेखक को पूज्य विनोबा से संलाप-संवाद का अवसर प्राप्त हुआ। वे इन संवादों को नोट करते जाते। १९४२ में फिर लेखक को नागपुर और बेलौर जेल में बाबा का सानिध्य प्राप्त हुआ। संवादों का वही क्रम चलता रहा। परिणामस्वरूप वे इस पुस्तिका में प्रश्नोत्तर के रूप में प्रकाशित हुए हैं।

रात और प्रभात—लेखक श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी, मूल्य ३॥) प्रकाशक—राजपाल एंड संस कश्मीरी गेट, दिल्ली।

प्रस्तुत उपन्यास हिन्दी संसार के प्रसिद्ध लेखक श्री भगवतीप्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखा गया है। वे साहित्य को केवल मनोरंजन की वस्तु नहीं मानते। प्रस्तुत उपन्यास भी अशिव से शिव की ओर तथा असत् से सत् की ओर ले जाने के उद्देश्य से लिखा गया है। रामप्रसाद एक कुटिल, धोखे बाज और षड्यन्त्रकारी व्यापारी है परन्तु श्री ज्ञानचन्द्र की शालीनता और सज्जनता से अभिभूत हो जाता है और उसका सम्पूर्ण जीवन बदल जाता है। वह रात से प्रभात की ओर आ जाता है, किन्तु इस ऊंचे उद्देश्य को लेकर लेखक कला की बहुत रक्षा नहीं कर पाया। अनेक प्रसंग और विशेषकर घर की अत्यन्त सामान्य बातों का विस्तृत वर्णन अनावश्यक रूपसे आकर केवल उपन्यास के कलेवर को बढ़ा देते हैं। कथा का गठन जितना सम्पन्न व सुसंगठित होना चाहिये था, उतना नहीं हो पाया। अनेक पात्र मूल कथा को गति देने के लिए कुछ अन्यथासिद्ध हो गये हैं। यों रामप्रसाद और ज्ञानचन्द्र का चरित्र-चित्रण बहुत अच्छा हुआ है। भाषा पर वाजपेयी जी का पूरा अधिकार है।

उत्तरा पथ—लेखक श्री यादवचन्द्र जैन, मूल्य ३॥) प्रकाशक—वही।

प्रस्तुत उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यास है। इसका कथानक सिकन्दर और पोरस की ऐतिहासिक घटना पर लिखा गया है। इस घटना पर अनेक नाटक तो देखने में आये, किन्तु उपन्यास शायद इस घटना को लेकर पहला ही लिखा गया है। इसमें पश्चिमी उत्तरी भारतके तत्कालीन छोटे-छोटे राज्यों के आपसी संघर्ष, द्वेष और लड़ाई झगड़ों का दृश्य उपस्थित किया गया है और बताया गया है कि सिकन्दर को जो आंशिक सफलता मिली, उसका कारण यही पारस्परिक द्वेष था। इस उपन्यास के एक भाग में ग्रीस के तत्कालीन समाज तथा आन्तरिक संघर्ष का चित्र भी पाठकों के सामने उपस्थित किया गया है, परन्तु हमारी नम्र सम्मति में उत्तरापथ नाम के साथ-साथ ग्रीस के आन्तरिक संघर्ष का विस्तृत वर्णन अनिवार्य नहीं था।

प्राचीन काल का वातावरण उपस्थित करने के लिए भाषा को अधिक क्लिष्ट व संस्कृतमय बनाने की प्रथा कहां तक उचित है, यह भी विचारणीय प्रश्न है। पारस्परिक संभाषण, तत्कालीन रहन-सहन, या धार्मिक कृत्यों की सामग्री वेशभूषा शासकों के पद या नाम आदि में उस समय के प्रचलित शब्द आ जायें तो बात समझ में आती है किन्तु नदी-नाले और पहाड़ों के प्राकृतिक वर्णन में भी भाषा को बहुत क्लिष्ट बना देना और काव्य की छटा दिखाने के लिए बहुत स्थान ले लेना शायद पुरानी परिपाटी है। इस प्रकार की शैली कौतूहल और घटनाक्रम के उत्सुक पाठक के रस में बाधा ही डालती है। हमें आशा है कि उपन्यास के लेखक इस सुझाव पर विचार करेंगे।

दोनों उपन्यासों का बहिरंग, कागज, छपाई व जिल्द बहुत सुन्दर हैं।

——

सफ़ेद कोढ़ के दाग

हजारों के नष्ट हुए और सैकड़ों के प्रशंसापत्र मिल चुके

दवा का मूल्य ५) रु० डाक व्यय १) रु०

अधिक विवरण मुफ्त मँगाकर देखिये।

वैद्य के० आर० बोरकर

मु० पो० मंगरूलपीर, जिला अकोला (मध्य प्रदेश)

[सम्पादक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारत में प्लास्टिक उद्योग

ज० प्र० गठोरिया एम० काम०, विशारद

आज के इस नवीन युग में प्लास्टिक का महत्व दिनों-दिन बढ़ रहा है। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में प्लास्टिक का उपयोग करता है, चाहे वह बालों में कंघी कर रहा हो या फाउन्टेन पेन से लिख रहा हो या फिर सिगरेट पीकर उसको राख-दानी (एश-ट्रे) में डाल रहा हो। उसके उपयोग की ये सभी वस्तुएं जैसे कंघी, फाउन्टेनपेन और राखदानी (एश-ट्रे) प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। इतना ही नहीं साहब की टेबल पर और दरवाजे पर जो पर्दा लगा हुआ होता है वह भी तो प्लास्टिक का बना हुआ है। महज कहना यह है कि प्लास्टिक का उपयोग धीरे-धीरे हर एक क्षेत्र में होने लगा है।

हमारे उद्योग

प्लास्टिक का इतिहास

सन् १८६० और १८७० के मध्य में ब्रिटेन के वैज्ञानिक श्री अलेक्जेंडर पारीकिस ने सेल्यूलाइड का एक फार्मूला तैयार किया था। इस फार्मूले को सबने पसन्द किया और सेल्यूलाइड काफी प्रचलित भी हो गया। लेकिन प्लास्टिक नाम की चीज का जन्म अभी नहीं हुआ था। वर्षों के बाद फिरसियेटिक प्लास्टिक का जन्म हुआ और सिनेमेटोग्राफ फिल्म और खिलौने आदि भी उसके बनाये गये। लेकिन अब भी इस में कमी थी क्योंकि यह प्लास्टिक बहुत कड़ी और जल्दी टूटने वाली होती थी। काफी अनुसंधान के बाद सेलूलोस एशिटेट का उपयोग किया गया और बेकेलाइट का उस में उपयोग किया। बेकेलाइटकी खोज सन् १९०७ में की गयी थी। वैज्ञानिक दृष्टि से उत्पन्न प्लास्टिक बनाने का सौभाग्य बीसवीं शताब्दी को मिला है। अब प्लास्टिक एक महत्वपूर्ण वस्तु हो गयी है क्योंकि यह वजन में हलकी और शक्ति की दृष्टि से काफी मजबूत होती है। आजकल इसका उपयोग हवाई जहाजों, कपास की मशीनों, जलयानों, खिलौने बनाने रेडियो, दूरभाष, (टेलीफोन), टेलीवीजन और बिजली के कारखानों में होने लगा है।

भारत में प्लास्टिक का विकास द्वितीय महायुद्ध के समय में हुआ है। प्लास्टिक उद्योग का कच्चा माल विदेशों से आयात किया जाता है और उससे यहां पर वस्तुएं तैयार करके बेची जाती हैं। इस समय भारत में १०० बड़े-बड़े कारखाने और बहुत से कारखाने लघु उद्योग के रूप में विस्तृत हैं। भारत के इस उद्योग में लगभग ७ करोड़ रुपया लगा हुआ है और करीब १२,००० से अधिक लोग इस उद्योग में काम करते हैं। सन् १९५० में भारत के प्रमुख प्लास्टिक कारखानों के पास ४०३ औंस उत्पादन की शक्ति रखने वाली १८२ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें थीं और २,०७४ टन उत्पादन करने की शक्ति रखने वाले १५४ काम्प्रेसन मोल्डिंग प्रेसेस थे। इसके अतिरिक्त छोटी-छोटी मशीनें भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। भारत के इस उद्योग में निम्नलिखित पांच प्रकार का कार्य होता है—

(१) काम्पेसन मोल्डिंग (२) इजेक्शन मोल्डिंग (३) एक्स्ट्रूजन (४) फेब्रीकेसन और (५) फेब्रिक के ऊपर प्लास्टिक का पर्त चढ़ाया जाना। भारत में अब ये कारखाने बिजली के कारखानों के लिए, चश्मे के फ्रेम, कृत्रिम चमड़ा बनाने में, और जल-रक्षित (Waterproof) कपड़ा तैयार करने लगी हैं। निम्न लिखित तालिका सन् १९५१ से १९५५ तक का प्लास्टिक का उत्पादन दर्शाती है—

प्लास्टिक का उत्पादन

(००० ग्रास)

वर्ष	प्रति वर्ष की प्लास्टिक मोल्डिंग	मोल्डिंग का मासिक औसत
१९५१	१४४६·०	१२०·५
१९५२	१५४४.४	१२८·७
१९५३	१३५७·२	११२·३
१९५४	१३०२·०	१०८·५
१९५५ (मई माह तक)	९२५·२	१८५·०

सन् १९५५ में प्रति माह प्लास्टिक के उत्पादन की दर १,८५००० टन हो गयी थी जब कि यह दर सन्

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

१९५२ में केवल १,२८,७०० टन ग्रास ही थी।

इस उद्योग ने सन् १९५५ में ३० प्रतिशत रोज की खपत में होने वाली बस्तुएं जैसे कंघी, टूथब्रस आदि और ९० प्रतिशत उद्योगों के काम में आने वाली चीजों का उत्पादन किया। भारत में प्लास्टिक की १२ निर्माणियों २४ लाख टूथब्रश तैयार करती हैं। प्लास्टिक उत्पादन के कुछ आंकड़े नीचे दिये जा रहे हैं--

वस्तुएं	१९४९	१९५०	१९५१	१९५२
(१) टूथब्रश	—	—	४·३ लाख	२·८ लाख
(२) चश्मे के फ्रेम	—	०·३ लाख	०·५१ लाख	०·६४ लाख
(३) फाउन्टैनपैन	३ लाख	३·२३ लाख	४ लाख	३·८ लाख
(४) बटन	कुल ८.५७,००० ग्रास तैयार किये गये हैं।			

भारत में

भारत में इस समय चश्मे के फ्रेम तैयार करने वाले ९ कारखाने तथा फाउन्टेनपैन तैयार करने वाले ६ कारखाने कार्य कर रहे हैं। इन्शूलेटेड केबल वायर और फ्लेक्जिबल का उत्पादन सन् १९५० में प्रारम्भ हुआ था और इसकी उत्पादन शक्ति ८·६ लाख गज तैयार करने की है। इसका उत्पादन सन् १९५० में २·८१४ लाख गज, १९५१ में ३·४७५ लाख गज और सन् १९५२ में ४ लाख गज कैम्बल, वायर और फ्लैक्जिकल तैयार किये थे। ५·२८ लाख गज लैदर क्लाथ तैयार करनेकी क्षमता इन फैक्ट्रियोंमें हैं। इनका उत्पादन सन् १९४८ में ०·२०४, १९४९ में ०·७६, १९५० में ०·९३, १९५१ में २·०४ और सन् १९५२ में ०·९५ लाख गज था। सन् १९५२ में फेनौलिक रेसिन लेमिनेट का प्रथम कारखाना चालू हुआ और १९५२ में उसने ४० टन उत्पादन किया।

प्लास्टिक बनाने के लिये पोलिस्टिरीन (Polysterene), एथिलीन (Ethylene), एसिटेट (Aretate), फिनौल फारनाल्डीहाइड मोल्डिंग पाउडर उरिया फारमालिहाइड मोल्डिंग पाउडर, पोलिबेलीन क्लोराइड आदि की आवश्यकता पड़ती है। भारतीय फैक्टरियां ३००० टन थरमोसेटिंग मोल्डिंग पाउडर और ६००० टन थरमोप्लास्टिक मौल्डिंग पाउडर का उपयोग करने की क्षमता रखती है। अधिकांश कच्चा माल आयात किया जाता है। यह कच्चा माल स्टर्लिंग क्षेत्र और डालर क्षेत्र से आयात किया जाता है। पहले डालर क्षेत्र से आयात करने के लाइसेंस नहीं दिये जाते थे लेकिन भारत सरकार ने सन् १९५५ में आयात करने के लिये लाइसेन्स दिये और डालर क्षेत्र से भी आयात करने की आज्ञा दे दी। इससे कच्चे माल की पूर्ति हो गयी और माल प्रतिस्पर्धा के बाजार में खरीदा जा सका। कच्चे माल का आयात भी पहले से बढ़ गया। सन् १९४८-४९ में २०·५८ लाख रुपये और १९५१-५२ में २५६ लाख रुपये का कच्चा माल आयात किया गया इसमें १५८ लाख रुपये का सियेटिक रेसिन और मौल्डिंग पाउडर और ९८ लाख रु० का सेमीफेब्रिकेटेड प्लास्टिक का कच्चा माल था। फैनोल और फारमाल्डीहाइट और अल्काइड रेसिन आयात किये गये माल से भारत में ही तैयार किया गया था। निम्नलिखित तालिका १९५२ से १९५४ तक आयात किया गया कच्चा माल बतलाती है :—

	१९५२-५३	१९५३-५४	१९५४-५५
सियेटिक रेसिन और मोल्डिंग पाउडर (काउटमें)	७६,४०२	७६,०८७	९८,८२६
जिनका मूल्य रुपयों में—	१,४०,१०,७९६)	१,४८,१०,२९७)	१,८५,९१,४४५)
सेमी फेब्रीकेटेड वस्तुएं जिनका मू० रु० में–	८७,५३,४०१)	८८,४५,१८३)	८७,७२,५१७)

उद्योग को संरक्षण

भारत सरकार ने इस उद्योग को समय-समय में संरक्षण भी दिया है। सन् १९५० में टेरिफ कमीशन ने १९५३ मार्च तक इस उद्योग को संरक्षण देने की सिफारिश की थी बाद में टेरिफ कमीशन को विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिये इस उद्योग का यह संरक्षण दिसम्बर १९५३ तक बढ़ा दिया गया था।

भारत में ही प्लास्टिक की खपत सन् १९३८ से पांच गुना अधिक हो गयी है। अब तो प्लास्टिक वस्तुओं का निर्यात भी होने लगा है। भारत सरकार इस उद्योग के विदेशी व्यापार को देखकर प्रभावित हुई। उसने विदेशों में इसके बाजार खोजने के लिये 'प्लास्टिक के लिये

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

फोन : ३३१११

तार : 'ग्लोबशिप'

न्यू ग्लोब शिपिंग सर्विस लिमिटेड

खताऊ बिल्डिंग्स

४४ ओल्ड कस्टम हाउस रोड, फोर्ट, बम्बई

सब प्रकार का क्लियरिंग, फारवर्डिंग, शिपिंग
का काम शीघ्र व सुविधापूर्वक
किया जाता है ।

सेक्रेटरी—
श्री बी० आर० अग्रवाल
बी. काम., एल. एल. बी.

मैनेजिंग डायरेक्टर—
श्री सी. डीडवानिया

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

निर्यात बढ़ाने के लिये समिति (Export promotion council for plastic) का निर्माण किया। भारत से प्लास्टिक का माल ३० देशों को भेजा जाता है जिनमें बर्मा, अफ्रीका, ईरान और मिश्र का नाम उल्लेखनीय है। भारत से करीब १ लाख रुपये का प्लास्टिक का सामान, प्रतिमाह विदेशों को भेजा जाता है। निम्नलिखित तालिका विदेशों को भेजे गये माल का दिग्दर्शन कराती है :—

सन्	भेजे गये प्लास्टिक के माल की कीमत (रुपयों में)
१९५१-५२	६,४४,८३६)
१९५२-५३	१३,०२,७१४)
१९५३-५४	१५,९८,०५८)
१९५४-५५	१४,४१,०५२)

आशाप्रद भविष्य

एक्सपोर्ट कौंसिल के निर्माण से इसके निर्यात की मात्रा में बढ़ती होना स्वाभाविक ही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सिंथेटिक मौल्डिंग पाउडर के उत्पादन को बढ़ाने का प्रावधान है। सन् १९६०-६१ तक १०,६०० टन सिंथेटिक मौल्डिंग पाउडर का उत्पादन हुआ करेगा और इस समय तक भारत में ३४०० टन सिंथेटिक मोल्डिंग पाउडर-उत्पादन करने की क्षमता होगी, इस क्षेत्र में ४ करोड़ रु० खर्च होगा। ऐसा अनुमान किया जाता है कि इस पदार्थ की खपत तब तक ११,६०० टन हो जायेगी। भारत में अब पोलिस्टरीन का उत्पादन किया जा रहा है। डोव कैमिकल कंपनी लिमिटेड अमरीका के साथ एक भा[illegible] तीय कम्पनी इसका उत्पादन करेगी। इस वर्ष में यह कम्प[illegible] अपना उत्पादन प्रारम्भ कर देगी। यह कारखाना २[illegible] टन पोलिस्टिरीन सालाना तैयार करेगी। इस योज[illegible] कार्यान्वित हो जाने से भारतीय प्लास्टिक उद्योग कच्चे [illegible] में से एक प्रमुख माल के लिये स्वावलम्बी हो जायेगा।

भारतीय प्लास्टिक उद्योग के लिये एक सबसे [illegible] कमी उपयुक्त प्रशिक्षित प्रौद्योगिकों की है। इन प्रौद्योगि[illegible] (टैक्नीशियनों) की कमी के कारण विदेशों की तुलना [illegible] भारतीय उद्योग ठहर नहीं पाता। भारत में ऐसे प्रौद्योगि[illegible] की बहुत कमी है। विदेशों से ऐसे प्रौद्योगिकों को बु[illegible] जाना चाहिये और भारतीय विश्वविद्यालयों में प्लास्टि[illegible] टैक्नोलाजी का विषय का समावेश भी करना चाहिये, जि[illegible] कुछ दिनों में भारत में इस विषय के विशेषज्ञों की कमी [illegible] हो जावे। सं०रा० सहायता कार्यक्रम के तत्वावधान में [illegible] में इस विषय पर एक वैज्ञानिक कार्य कर रहा है। इ[illegible] एक और टैक्नीशियन बुलाने की योजना है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पूर्ण होने पर यह [illegible] भारतका एक प्रमुख उद्योग हो जायेगा जो कि विदेशों [illegible] पर्याप्त मात्रा में माल भेजा करेगा और इस प्रकार [illegible] व्यापार में संतुलन बनाये रखने के लिये यह उद्योग [illegible] प्रमुख साधन बन जाएगा।

——

नई दिल्ली व दिल्ली में सम्पदा

सम्पदा के फुटकर अंकों और विशेष कर विशेषांकों की मांग अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों में बनी रहती है। उनकी सुविधा के लिए आत्माराम एण्ड सन्स, काश्मीरी गेट, दिल्ली (हिन्दी विभाग) में सम्पदा की बिक्री की व्यवस्था कर दी गई है।

नई दिल्ली में सम्पदा के विक्रेता सेंट्रल न्यूज एजेंसी, कनाट सर्कस हैं।

इस प्रबन्ध से आशा है, दिल्ली के अर्थशास्त्र-प्रेमियों की असुविधा दूर हो जायगी।

— मैनेजर सम्पदा

अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दि[illegible]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इंगलैंड-अमेरिका में आणविक होड़

अमेरिका और इंग्लैण्ड ने, द्वितीय महायुद्ध के समय अणुबम का निर्माण पारस्परिक सहयोग से किया था। उनका उद्देश्य जर्मनी और जापान को युद्ध में हराना था। आज समय की बलिहारी ही समझिए कि (तब के दुश्मन) जर्मनी और जापान से अणु सम्बन्धी आर्डर प्राप्त करने में उनमें परस्पर तीव्र स्पर्धा आरम्भ हो गई है।

इंग्लैण्ड में अणु उत्पादन

इंग्लैण्ड में छोटी छोटी अणु भट्टियों का उत्पादन, बड़ी मात्रा में निर्यात करने के लिये किया जा रहा है। रेफिजरेटर और टेलीविजन की तरह ही प्रचुर मात्रा में इनका उत्पादन हो रहा है। इन अणुभट्टियों के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता नहीं होती; बस एक टेनिस कोर्ट का स्थान यथेष्ट है। अणु ईंधन भी १८ महीने से २ वर्ष तक चल जाता है। इस बीच ईंधन देने की आवश्यकता नहीं होती। इनकी लागत २० लाख पौंड या २.७ करोड़ रु० है। इनसे २५,००० लोगों के लिये यथेष्ट विद्युत प्राप्त हो जाती है। इनकी स्थापना का व्यय भी कोयले—ईंधन जनित बिजली से कुछ ही अधिक है तथा परम्परागत विद्युत-गृहों के मुकाबले में ही है।

ब्रिटेन के अग्रणी और विशाल अणु-शक्ति-गृह 'काल्डर हाल' पर इंग्लैण्ड के वैज्ञानिकों और प्राविधिज्ञों को विशेष गर्व है। अमेरिका इसको ईर्ष्या की दृष्टि से देखता है। इंग्लैण्ड की अणु सम्बन्धी २ विशेषताएं उसे अमेरिका की अपेक्षा व्यापारिक दृष्टि से अच्छी स्थिति प्रदान करती हैं—(१) ब्रिटेन में बनाई जाने वाली अणु भट्टियों की लागत अमेरिका की अपेक्षा कम है। स्वयं अमेरिकी अणु-शक्ति-आयोग ने इस बात को स्वीकार किया है कि इंग्लैण्ड में निर्माण की लागत और पूंजी पर दिया जाने वाला व्याज अमेरिका से कम है। इसी से अमरीकी अणु भट्टियों की लागत इंग्लैण्ड की अपेक्षा ५० प्रतिशत अधिक होती है। (२) अणु-भंजन-सामग्री जो इंग्लैण्ड में प्रयुक्त की जाती है वह सरलता से उपलब्ध हो जाती है। 'काल्डर हाल' की अणु भट्टियों में अणु ईंधन प्राकृतिक यूरेनियम के रूप में ही प्रयुक्त होता है। यह अब प्रायः सभी जगह मिल जाता है। अमेरिकी किस्म की अणु भट्टियों में परिष्कृत (Enriched) यूरेनियम की आवश्यकता होती है, जो एक दुर्लभ पदार्थ है। इसका प्रयोग अणु बम बनाने में किया जाता है। यह अमेरिका या रूस में ही उपलब्ध है। अतः इसकी प्राप्ति के लिये पहले रूस और अमेरिका की राजनैतिक शर्तों को पूरा करना होगा।

अमेरिका की स्पर्धा

इंग्लैण्ड अपनी इसी सुविधा का प्रचार अणु-व्यापार के लिये कर रहा है। दूसरी ओर अमेरिका भी ब्रिटेन की अणु शक्ति के खिलाफ प्रचार में संलग्न है। अभी अभी जापान-अमेरिकी अणु सम्मेलन में, अमेरिकी प्रतिनिधियों ने इंग्लैण्ड की अणु-शक्ति-गृह काल्दर हाल के प्रति 'कटु' शब्दों का प्रयोग किया। इंग्लैण्ड ने जापानी प्राविधिज्ञों को काल्दर हाल में प्रशिक्षण के लिये सुविधा दी है। अमेरिका कह रहा है कि उसी प्रकार के अणु-शक्ति-गृह जापान में बनाये जा सकते हैं। अमेरिका की वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कम्पनी और इंटरनेशनल जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी ने क्रमशः मित्सुबिसी इलेक्ट्रिक कम्पनी और शिबारुआ इलेक्ट्रिक कम्पनी नामक जापानी कम्पनियों से प्रविधिक समझौते किये हैं, जिनके अनुसार जापान में जापानियों द्वारा ही पूर्ण यंत्र उपकरणों से अणु शक्ति का उत्पादन किया जा सके। अमेरिका का आयात-निर्यात बैंक इस कार्य में उदारता पूर्वक सहायता दे रहा है।

फिर भी, अनुमान है कि ब्रिटेन ने वास्तविक और संभाव्य दोनों प्रकार के ५०० लाख पौंड के आर्डर प्राप्त कर लिये हैं, अमेरिका को नाम मात्र के ही आर्डर प्राप्त हुए हैं। लेकिन इंग्लैण्ड के इन छोटे छोटे अणु भट्टियों का जो प्रचार-प्रसार विदेशी बाजारों में हुआ है, इनकी प्रगति

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अमेरिका द्वारा अवरुद्ध हो सकती है। ब्रिटेन का अणु-उत्पादन कार्य अमरीकी उद्भव का है। इंगलैण्ड की अणु भट्टियों की खरीद वाशिंगटन की सरकारी स्वीकृति पर ही हो सकती है। साथ ही इन अणु भट्टियों के लिये जो ईंधन लिया जायेगा, विदेशी खरीददार इसको अमेरिका के अणु शक्ति-आयोग से लेने को विवश हैं।

—

यूगोस्लेविया का औद्योगिक उत्पादन

यूगोस्लेविया के एक सरकारी प्रकाशन के अनुसार, इस वर्ष के आरम्भिक ३ महीनों में जितना औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, वह पिछले वर्ष की इसी अवधि के उत्पादन से २१ प्रतिशत अधिक है। उत्पादन का क्षेत्र, इस अवधि में पिछले वर्ष की एक माह की औसत की अपेक्षा १५ प्रतिशत अधिक रहा।

सर्वाधिक उत्पादन-वृद्धि विद्युत-सामग्री में लक्षित हुई जो ४५ प्रतिशत है। इसी प्रकार क्रुड आइल में ४४ प्रतिशत, भारी इंजीनियरिंग के सामानों में ३३ प्रतिशत, विद्युत-शक्ति और रबड़ के सामानों में २८ प्रतिशन, रसायनों में २५ प्रतिशत, इमारती लकड़ी और मुद्रण सामग्री में २३ प्रतिशत, सूती कपड़ों और अलौह-धातुओं में २२ प्रतिशत वृद्धि रही।

मुख्य बात यह कि जिन वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हुई वे अच्छी संख्या में उपभोग्य सामग्री—जैसे सूती वस्त्र, विद्युत-सामग्री तथा धातु के समान—हैं। ये मांग और पूर्ति में सामंजस्य स्थापित करने के साथ ही साथ लोगों के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने में आवश्यक हैं।

यूगोस्लेविया की उत्पादन अर्थ-व्यवस्था न रूस जैसी अति केन्द्रित है और न पूंजीपति देशों की भांति निजी उद्योग पद्धति पर आश्रित है। मजदूरों की सहकारिता पद्धति आधारभूत पद्धति है।

—

१९५६ में जूट का उत्पादन

१९५६ में, विश्व में जूट के उत्पादन का ४६,५१० लाख पौंड का अंदाजा किया गया है, जब कि १९५५ में यह ४४,७७० लाख पौंड था।

—

प्रचुरता में भी अशान्ति

इस आधुनिक दुनिया याने अमेरिकामें एक नयी बात देखने में आती है और वह है अधिकता के बावजूद वहांके लोगों को कमी महसूस होना। इसमें कोई संदेह नहीं कि वहां उत्पादन और उपभोग्य वस्तुओंका बाहुल्य है। अमेरिकनों का जीवन-स्तर किसी भी देश के जीवन-स्तर से दुगुना ऊंचा है। भारत और पूर्वी देशों की अपेक्षा २० से ३० गुना अधिक ऊंचा है। वे अब भी अपने जीवन-स्तर को ऊंचा करने में लगे हुए हैं। सन् १९४६ के पश्चात १० वर्षों में कुल राष्ट्रीय आय, उत्पादन तथा सेवाएं दुगुनी हो गई हैं। नवीन लक्ष्य अभी उत्पादन को २० प्रतिशत और बढ़ाने का है। देश में जिस मात्रा में उत्पादन बढ़ता है, उत्पादित वस्तुओं का उपभोग भी उसी मात्रा में बढ़ना चाहिए अन्यथा राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था तहस-नहस हो जायेगी।

फिर भी इन तथ्यों के बावजूद प्रत्येक स्थान पर डालर की कमी हैं। वहां की जनता के किसी वर्ग के पास पर्याप्त डालर नहीं हैं। परिवारों पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। कितने ही व्यक्ति एक ही साथ दो जगह काम कर रहे हैं। अपने दिन के काम के अतिरिक्त वे शाम की नौकरी अलग से करते हैं। कितनी ही विवाहिता स्त्रियां अपने परिवार की आमदनी बढ़ाने के लिये बाहर काम करने जाती हैं।

आपका स्वास्थ्य

(हिन्दी की एक मात्र स्वास्थ्य सम्बन्धी मासिक पत्रिका)

"आपका स्वास्थ्य" आपके परिवार का साथी है।

"आपका स्वास्थ्य" अपने क्षेत्र के कुशल डाक्टरों द्वारा सम्पादित होता है।

"आपका स्वास्थ्य" में अध्यापकों, अभिभावकों, माताओं और देहातों के लिये विशेष लेख प्रकाशित होते हैं।

आज ही ६) रु० वार्षिक मूल्य भेजकर ग्राहक बनिए।

व्यवस्थापक,

आपका स्वास्थ्य—बनारस

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उज्ज्वल भविष्य का सन्देशवाही जून '५७

१९५७ का जून मास शायद मध्यप्रदेश के लिए बहुत भाग्यशाली और महत्वपूर्ण रहेगा। १० जून को भिलाई में इस्पात के कारखाने की प्रथम मट्टी का शिलान्यास वेदों के पुनीत मंत्रों और यज्ञ की आहुतियों के साथ हुआ। मध्यप्रदेश ही नहीं, समस्त देश के लिए यह महत्वपूर्ण घटना है। इसका परिचय पाठक सम्पदा के गत अंक-रूस-भारत परिशिष्ट अंक में पढ़ चुके हैं।

वृहत् प्रशिक्षण व कर्मशाला

केन्द्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री श्री मोरारजी देसाई द्वारा १८ जून को ४० करोड़ रु० की लागत की बिजली की भारी सामग्री के निर्माण की योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षणशाला तथा कर्मशाला के शिलान्यास के साथ मध्यप्रदेश के आर्थिक जीवन में एक नया अध्याय लिखा जाने लगा है।

ऐसा अनुमान है कि योजना के प्रथम भाग को सम्पन्न करने के लिए ही लगभग ९००० प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। प्रशिक्षित व्यक्तियों की इस विशाल आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही करखाना पूर्ण रूप से तैयार होने के दो वर्ष पूर्व इस प्रशिक्षणशाला तथा कर्मशाला की स्थापना की जा रही है।

प्रारम्भ के कुछ वर्षों में यह प्रशिक्षणशाला तथा कर्मशाला दो पाली : डबल शिफ्ट : प्रणाली पर कार्य करेंगी जिससे २००० शिक्षार्थी एक समय में ही प्रशिक्षण पा सकें।

बिजली के भारी सामानों को बनानेकी यह योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बड़ी उद्योग योजनाओं में से एक है और यह बिजली के भारी सामानोंके आयात में देशकी विदेशों पर निर्भरता काफी हद तक कम करने में सहायक होगी। यह कारखाना अनेक प्रकार के जल-विद्युत एवं अन्य विद्युत योजना सम्बन्धी प्लान्ट एवं ऊपकरण तथा रेलवे के लिए विद्युत् द्वारा संचालित अन्य उपकरण तैयार करेगा।

इस कारखाने में निर्मित होनेवाली सामग्री में पानी द्वारा चलने वाले ५०,००० के० वी० ए० शक्ति के बिजली के जेनरेटर, १५,००० के० वी० ए० शक्ति के सिन्क्रोनाइजर कन्डेन्सर, डीजल जेनरेटर, २०० अश्व शक्ति से अधिक के औद्योगिक मोटर, डी० सी० जेनरेटर तथा मोटर, क्रेन-मोटर, रेक्टिफायर ३३,००० वोल्ट से अधिक वोल्टेज के पावर ट्रांसफार्मर, हाई वोल्टेज स्विच गीयर, इंडस्ट्रियल कन्ट्रोल गीयर, विच डाईवर्टर तथा वाटर टरबाईन भी हैं। आशा है, १९६० ई० तक इस कारखाने में उत्पादन प्रारम्भ हो जायगा, और धीरे-धीरे १९६८ तक पूर्ण रूपेण उत्पादन होने लगेगा। इंगलैंड के मेसर्स एसोसियेटेड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, लि० इस योजना के लिए परामर्शदाता हैं।

कारखाने के स्थल पर काफी प्रारम्भिक कार्य हो चुके हैं। कारखाने के लिए आवश्यक भूमि मध्यप्रदेश सरकार बिना मूल्य दे रही है। प्रायः ४,००० एकड़ भूमि प्राप्त कर हस्तांतरित की जा चुकी है।

खडवा-टाकल रेल मार्ग

इस मास की तीसरी महत्वपूर्ण घटना यह है कि मुख्यमंत्री डाक्टर कैलाशनाथ काटजू ने १९ जून को खण्डवा हिंगोली मार्ग को जोड़ने वाले १८७ लम्बे खण्ड पर १८॥ मील लम्बे खण्डवा-टाकल रेलवे मार्ग का उद्घाटन किया। उत्तर एवं दक्षिण भारत को संलग्न करने वाली अत्यावश्यक एवं महत्वपूर्ण मीटर गेज रेलवे के प्रथम सोपान की सफलता पूर्वक पूर्ति से देश की मीटर गेज रेलवे पद्धति की सबसे बड़ी अड़चन दूर हो जायेगी और उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच माल एवं यात्रियों का आवागमन सरल हो जायेगा। इससे इस क्षेत्र के सर्वतोमुखी विकास में सहायता मिलेगी।

कोरबा विद्युत्-गृह

जून मास में मध्यप्रदेश के लिए महत्वपूर्ण चौथी घटना है कोरबा को विद्युत-गृह का शिलान्यास, जो मुख्य मंत्री डाक्टर कैलाशनाथ काटजू ने रायपुर से १५० मील दूर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उत्तरप्रदेश में चीनी, गुड़ व गन्ना

उत्तर प्रदेश में गत पांच वर्षों के बीच गन्ने का उत्पादन बढ़कर लगभग दुगुना हो गया है। इस साल राज्य में कुल १० लाख ४० हजार टन गन्ने का उत्पादन कूता गया है जबकि समूचे देश में इस वर्ष लगभग २० लाख टन गन्ना पैदा होने का अनुमान लगाया गया है। इस प्रकार देश के कुल उत्पादन का लगभग ५० प्रतिशत गन्ना इस राज्य में पैदा किया जाता है। साथ ही देश की कुल १३४ चीनी मिलों में से ६७ मिलें उत्तर प्रदेश में हैं जिनमें १९५०-५१ जहां में १६ करोड़ ४४ लाख मन गन्ने की पेराई हुई। १९५५-५६ में २७ करोड़ ७२ लाख मन गन्ना पेरा गया और ९ लाख ८९ टन चीनी का उत्पादन हुआ। इस वर्ष ३० करोड़ मन गन्ने की पेराई संभव होगी।

राज्य में इस समय २६ लाख एकड़ क्षेत्र में गन्ने की फसल उगाई जाती है जबकि २० लाख एकड़ क्षेत्र चीनी मिलों के लिए सुरक्षित रखा गया है। सुरक्षित क्षेत्र में से आठ लाख एकड़ क्षेत्र मिल के समीप है जिसका प्रगाढ़ विकास किया जाता है और शेष १२ लाख एकड़ क्षेत्र अन्य स्थानों पर है। द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना में मिलों से दूर स्थित क्षेत्रों में से तीन लाख एकड़ क्षेत्र में गन्ने की प्रगाढ़ खेती की जायगी। इस योजना का उद्देश्य है गन्ने की फसल के क्षेत्र में कमी करके खाद्योत्पादन के लिए अधिक भूमि उपलब्ध करना।

इस समय राज्य में गन्ने के कुल उत्पादन का ६६ प्रति शत गुड़ बनाने के उपयोग में लाया जाता है, २४ प्रति शत गन्ने से सफेद चीनी तैयार की जाती है और शेष गन्ना चूसने अथवा बीज के काम में लाया जाता है। देश के कुल उत्पादन का ४४ प्रति शत गुड़ उत्तर प्रदेश में तैयार किया जाता है और देश के ३३ प्रति शत गुड़ की खपत इस राज्य में होती है। उत्तर प्रदेश में १४ लाख टन गुड़ तैयार किया जाता है और १३ लाख टन गुड़ की खपत होती है।

फलस्वरूप राज्य के गन्ना-उत्पादक क्षेत्र पर इतना भारी भार पड़ गया है कि चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्र में ६०,००० कोल्हू गुड़ तैयार करते हैं और राज्य के अन्य क्षेत्रों में १,१०,००० कोल्हू गुड़ बनाने में लगे रहते हैं। ऐसी दशा में जबकि गुड़ के दाम बढ़ जाते हैं, चीनी मिलों को प्रायः गन्ना नहीं मिलता। अतएव चीनी और गुड़ के उत्पादन में सन्तुलन स्थापित करने और गन्ने का समुचित बंटवारा करने के लिए गुड़, खांडसारी और चीनी का उत्पादन करने वाली इकाइयां अलग-अलग करनी पड़ेंगी और साथ ही गुड़ के लिए गन्ने की व्यवस्था करने के निमित्त सुरक्षित गन्ना क्षेत्रों का प्रगाढ़ विकास करना पड़ेगा।

प्रथम पंचवर्षीय आयोजन में चीनी मिलों के निकटवर्ती गन्ना उत्पादन क्षेत्रों में प्रति एकड़ क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन बढ़कर ५६० मन हुआ। इस प्रयोजन के लिए २ करोड़ ४० लाख रुपये की धनराशि दी गयी। द्वितीय आयोजन में प्रति एकड़ क्षेत्र में गन्ने के उत्पादन को ६५०

कोरबा में किया।

यह १२॥ करोड़ रु० की लागत से बनेगा। मध्यप्रदेश में इतनी प्राकृतिक संपत्ति भरी पड़ी है कि उसका सारे देश के नव-निर्माण में महान योग रहेगा। कोरबा से ९०,००० किलोवाट बिजली उत्पन्न होगी। यह कार्य सितम्बर १९५८ में पूर्ण हो जायेगा। आगे चलकर इस विद्युत-गृह की शक्ति १,२०,००० किलोवाट हो जायेगी। यह राज्य का सबसे अधिक शक्तिशाली विद्युत-गृह होगा।

इस बिजलीघर के निर्माण से कोरबा की कोयला खदानों के विकास में बहुत सहायता मिलेगी। कोरबा कोयला खदानों में भारत सरकार मध्यप्रदेश राज्य सरकार को १।३ हिस्सा राटल्टी के रूप में देगी। यहां उत्पादित बिजली बहुत ही सस्ती होगी, क्योंकि इसमें जिस कोयले का उपयोग किया जायेगा, उसका अन्य किसी भी उद्योग में उपयोग नहीं किया जा सकता।

कोरबा से उत्पादित बिजली में से ६०,००० किलोवाट बिजली भिलाई इस्पात कारखाने को दी जायेगी।

—

[सम्पादा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मन तक बढ़ाने के लिए सरकार ने ७ करोड़ २८ लाख रुपये की व्यवस्था की है।

प्रति एकड़ क्षेत्र में गन्ने की पैदावार में वृद्धि करने के संबंध में जो आन्दोलन चलाया गया, उसके फलस्वरूप प्रथम पंचवर्षीय आयोजनावधि में २,०३ लाख टन गन्ने के निर्धारित लक्ष्य की अपेक्षा १,०० लाख टन गन्ना अधिक पैदा हुआ। द्वितीय आयोजन में, अपेक्षाकृत कम क्षेत्र में, ३,९३ लाख टन गन्ना पैदा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

परिणामस्वरूप प्रत्येक इकाई क्षेत्र की आय में वृद्धि होगी और लाखों गन्ना उत्पादक खुशहाल होंगे। अनुमान लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों के ९० लाख परिवार हैं या यों कहिए कि राज्य की कुल साढ़े छः करोड़ जन संख्या में से साढ़े चार करोड़ व्यक्ति गन्ने का उत्पादन करते हैं। उत्तर प्रदेश के ५१ जिलों में से २७ जिलों के किसानों का मुख्य पेशा गन्ना पैदा करना ही है। लगभग एक लाख परिवार गुड़ बनाने का काम करते हैं जिससे साल में छः महीने की अवधि तक लगभग १२ लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलता है। साथ ही दो लाख व्यक्ति चीनी मिलों में काम करते हैं। अतः स्पष्ट है कि राज्य की अर्थ-व्यवस्था बहुत कुछ गन्ने के उत्पादन पर आधारित है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि राज्य में कुल १५० करोड़ रुपये मूल्य की चीनी और गुड़ का उत्पादन होता है।

गन्ना विकास के निमित्त राज्य में १०,००० पक्के कुओं का निर्माण किया जायगा तथा १,१५० पम्पिंग प्लांट, ६,००० रहट और अनेक नलकूप लगाये जायेंगे। गोदामों का निर्माण करने के लिए गन्ना संघों को प्रोत्साहित किया जायगा। गन्ने के उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि करने के निमित्त १७२ लाख मन गन्ने का बीज गन्ना उत्पादकों को दिया जायगा और प्रतिवर्ष १० प्रति शत सुरक्षित क्षेत्र में नयी किस्म के बीज बोये जायेंगे। गन्ना उत्पादकों को आधुनिक उपकरण देने के लिए पांच लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर तथा गोरखपुर के अनुसन्धान केन्द्रों में गन्ना विभाग के लगभग १५ प्रति शत कर्मचारियों को विशेष प्रकार की ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की गयी है।

गुड़ विकास योजना के अन्तर्गत सुधरे कोल्हुओं, लकड़ी की कम खपत करने वाली भट्ठियों, रस छानने के उपकरणों और आधुनिक ड्रमों, जिनमें गुड़ का रंग आदि खराब नहीं होता, की व्यवस्था की जायगी। यदि इन कम खर्चीले उपायों को पूर्णतः व्यवहार में लाया गया, तो निश्चय ही ये राज्य के ग्राम्य क्षेत्रों में एक आर्थिक क्रांति लाने में सफल होंगे।

गुड़ विकास योजना इस समय राज्य के ४,००० से अधिक गांवों में चालू है। इनमें से १५० आदर्श गांव हैं।

नई समस्या व उसका हल

नवीनतम अंकों के अनुसार इस वर्ष उत्तर प्रदेश में गन्ने की पैदावार इतनी अधिक हो गयी और राज्य में ६७ चीनी मिलों में गन्ने से प्राप्त होने वाली चीनी का प्रतिशत आजकल इतना कम है कि गन्ना विभाग को वर्तमान सुरक्षित क्षेत्रों में गन्ने की पैदावार घटाने के लिए विवश होना पड़ रहा है। मौसम समाप्त होने के बाद भी गन्ने की पिराई होते रहने के कारण गन्ने से पर्याप्त मात्रा में चीनी नहीं मिल पाती, जिससे किसानों को गन्ने का मूल्य कम प्राप्त होता है। इसलिए गन्ना पहले की अपेक्षा इस वर्ष लगभग दो लाख एकड़ कम क्षेत्र में बोने का निश्चय किया गया है।

गन्ना अक्तूबर के अन्त में या नवम्बर के प्रथम सप्ताह में भलीभांति रसदार नहीं हो पाता, इसलिए नवम्बर में पिराई आरम्भ होने के कारण 'रिकवरी' ९.६ प्रतिशत की सामान्य 'रिकवरी' की अपेक्षा केवल सात से आठ प्रतिशत ही रह जाती है और अप्रैल में गन्नेमें सूखा आने के कारण यह 'रिकवरी' चार प्रतिशत ही रह जाती है।

किसानों को कम 'रिकवरी' वाला गन्ना बेचने से बचाने और सघन खेती को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य के गन्ना विभाग ने सन् १९५७-५८ के पिराई के मौसम में प्रत्येक किसान का कोटा निर्धारित करने का निर्णय किया है।

पिछले वर्षों में गन्ना सुरक्षित क्षेत्रों की अधिकाधिक भूमि में बोया गया था। सन् १९५३-५४ में जहां सुरक्षित गन्ना कृषि भूमि १२.६३ लाख एकड़ थी, वह १९५६-५७ में बढ़कर १९.७० लाख एकड़ हो गयी। इस वर्ष २०

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आर्थिक जगत् के समाचार

नयी आयात नीति

भारत सरकार की अगली तिमाही (जुलाई से सितम्बर) की आयात नीति के अनुसार कुछ चीजों को छोड़ कर केवल पूंजीगत सामानों तथा आवश्यक कच्ची सामग्री के आयात के लिये ही लाइसेंस दिये जायेंगे। खुले सामान्य लाइसेंस (ओ० जी० एल०) के अन्तर्गत केवल पाकिस्तान से मुर्गी, मछली, ताजी सब्जियां तथा अंडे मंगाने की छूट दी गई है।

इस अवधि में निर्धारित आयातकों को लाइसेंस जारी नहीं किये जायेंगे। केवल मशीनों और कच्चा माल मंगाने पर जोर दिया जायेगा। सरकारी घोषणा के अनुसार इस आयात नीति से किसी आवश्यक वस्तु की न तो कमी होगी और न मूल्य बढ़ेंगे। पर यदि जांच करने के बाद किसी आवश्यक वस्तु की कमी महसूस हुई तो इनके आयात लाइसेंस दिये जा सकेंगे। इस आयात का मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा की बचत करना है। इन तीन महीनों में ४० करोड़ रु० की बचत का अनुमान किया गया है। इस नीति का प्रभाव यह भी पड़ेगा कि देश के उत्पादकों को प्रोत्साहन मिलेगा।

पूंजीगत मालों के लिये उचित विलम्बित भुगतान के आधार पर आयात लाइसेंस जारी रहेंगे। आयात लाइसेंस ऐसे निर्माण कार्यों के लिये दिये जायेंगे जो या तो विदेशी मुद्रा कमायें या विदेशी मुद्रा की बचत करें। सरकारी घोषणा में यह भी कहा गया है

अप्रैल तक २६.६० करोड़ मन गन्ना पेरा जा सका, जबकि गतवर्ष २३.२० करोड़ मन ही पेरा गया था।

अनुमानतः इस वर्ष ३० करोड़ मन गन्ना पेरा जा सकेगा जिससे १०.७५ लाख टन चीनी तैयार होगी जब कि गत वर्ष २७.७२ मन गन्ने से ९.८९ लाख मन चीनी उत्पन्न की गयी थी।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री

श्री मोरारजी देसाई

कि ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी, रूस, फ्रांस, स्वीटजरलैंड और स्वीडन विलम्बित भुगतान के आधार पर भारत को पूंजीगत माल देंगे। रूस ने सबसे कम ब्याज २॥ प्रतिशत और प० जर्मनी ने सबसे अधिक ८॥ प्रतिशत विलम्बित भुगतान सरकारी आधार पर न होकर भारत और उन देशों की कम्पनियों के बीच होगा।

इस विषय में विशेष उल्लेखनीय यह है कि भारत सरकार ने विदेशों से पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं के मंगाने पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया है। साथ ही अब कोई भारतीय डरबी टिकट नहीं खरीद सकेगा, क्योंकि विदेशों को मनिआर्डर भेजने पर भी रोक लग गई है। अब तक २ रु० या ३० रु० विदेशों को मनिआर्डर द्वारा भेजा जा सकता था। १९५५-५६ में १ करोड़ रु० विदेशों को भेजा गया था।

गेहूं आवागमन-नियमन के ३ क्षेत्र

देश में गेहूं के आवागमन के नियमन हेतु भारत सरकार ने अन्तर्क्षेत्रीय गेहूं आवागमन नियन्त्रण आदेश, १९ जारी किया है तथा इसके अन्तर्गत निम्नलिखित गेहूं निर्मित किये गये हैं:—

क्षेत्र १—पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली,

[स

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

क्षेत्र २—उत्तर प्रदेश

क्षेत्र ३—राजस्थान, मध्य प्रदेश और बम्बई (बम्बई नगर को छोड़कर)

एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चोकर को छोड़कर गेहूं अथवा गेंहूं से बनी वस्तुओं का आयात निर्यात निषिद्ध है।

श्री अशोक मेहता खाद्य समिति के अध्यक्ष

पिछले ५-६ महीनों से देश में अन्न की बड़ी कमी महसूस की जा रही है। बिहार तथा देश के कुछ अन्य भागों में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सरकार ने देश की चिंतनीय खाद्य स्थिति पर विचार करने और तत्सम्बन्धी सुझाव देने के लिये प्रसिद्ध समाजवादी नेता श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में जून के मध्य में एक समिति बनाई है।

यह पहला अवसर है कि जब सरकार ने विरोधी दल के नेता को ऐसी किसी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। हो सकता है कि सरकार खाद्य-स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उसमें देश के प्रत्येक दल का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक समझती हो।

नये वर्ष में पर्याप्त चीनी

अनुमान है कि १९५६-५७ में बाजार में लगभग २५ लाख ८० हजार टन चीनी उपलब्ध होगी। इसमें से ५ लाख ३० हजार टन चीनी पिछले साल की बची हुई है। १९५६-५७ में २० लाख ५० हजार टन चीनी पैदा होने का अनुमान है। १९४७ से अब तक इतनी चीनी पहले कभी नहीं बनायी गयी। पिछले साल, १९५५-५६ में १८ लाख ६० हजार टन चीनी तैयार की गयी थी।

१७ जून, १९५७ तक निर्यात के लिए १ लाख ४२ हजार टन चीनी बेची गयी, जिसमें से ५० हजार टन बाहर भेजी जा चुकी है। अनुमान है कि साल के अंत में लगभग ४ लाख टन चीनी बच रहेगी। इस तरह देश में काफी मात्रा में चीनी उपलब्ध रहेगी।

योजना पूर्ति के लिए आवश्यक पूर्ति

भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री टाटा ने ८ जुलाई को बम्बई की व्यापारिक चेम्बर की पाक्षिक बैठक में एक महत्वपूर्ण बात कही है कि देश के औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है कि मजदूरी और लागत में कोई वृद्धि न होने दी जाये। उनके विचार से केवल औद्योगिक मजदूरों द्वारा ही समय-समय वेतन-वृद्धि की मांग की जाती है, क्योंकि वे संगठित हैं। दूसरी ओर कृषि उद्योग में संलग्न मजदूर अपनी मजदूरी बढ़ाने की मांग नहीं करते, क्योंकि वे असंगठित हैं। इसी प्रकार लागत न बढ़ने देने के सम्बन्ध में उन्होंने सरकार की कर-वृद्धि को त्रुटिपूर्ण कहा। द्वितीय योजनावधि में जो भारी कर लगाये गये हैं, उनसे उद्योगों को हानि तो होगी ही, साथ ही करदाताओं को गैर कानूनी ढंग से कर से छुटकारा पाने के लिये भी प्रोत्साहन मिलेगा

अन्तर्राष्ट्रीय बिक्री कर लागू

१ जुलाई से अन्तराज्यीय बिक्री-कर लागू हो गया है। एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापारिक माल के यातायात पर यह कर लगेगा।

देश के व्यापारी वर्ग ने सरकार की कर सम्बन्धी प्रस्तावों में जहाँ अन्य करों की आलोचना की थी, वहां अन्तर्राज्यीय बिक्री कर को लगाने की मांग की थी। दिल्ली आदि ऐसे स्थान, जहां से माल इधर-उधर भेजने के लिये खुश्क बन्दरगाह का सा कार्य करते हैं, इस कर के लगने से उनके व्यवसाय को बड़ी हानि पहुँच सकती है।

(पृष्ठ ३८० का शेष)

अमेरिका में १९५६ में विज्ञापनों पर नौ बिलियन डालर खर्च हुए। उक्त दोनों देशों की कुल राष्ट्रीय आय का क्रमशः २ और २॥ प्रतिशत भाग विज्ञापनों पर व्यय होता है। यद्यपि भारत में इस प्रकार के अंक सुलभ नहीं है, तथापि एक अनुमान के अनुसार भारत में कुल २ करोड़ रु० विज्ञापनों पर व्यय होता है जबकि हमारी राष्ट्रीय आय करीब दस अरब रुपया है। अधिकाधिक विज्ञापन ग्राहकों को अपनी ओर खींचते हैं। भारत में तो एक और भी विचारणीय बात है और वह यह कि अधिकांश विज्ञापन अंग्रेजी अखबारों में मिलते हैं। जन सामान्य तक पहुँचने वाले देशी भाषाओं के पत्रों को और उनमें भी क्षेत्रीय पत्रों को बहुत कम विज्ञापन मिलते हैं। देश के उद्योगपतियों तथा विज्ञापन दाताओं को इस सम्बन्ध में अधिक उत्साह शील होना चाहिये।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पिछले ५ वर्षों में सम्पदा ने क्या क्या दिया ?

प्रति वर्ष दो महत्त्वपूर्ण ज्ञानवर्धक विशेषांक

१. भारत सरकार का बजट—प्रति वर्ष विवेचनात्मक तथा परिचयात्मक लेख।

२. पंचवर्षीय आर्थिक योजना—पहली व दूसरी दोनों योजनाओं पर अलग अलग विशेषांक तथा प्रति वर्ष बीसियों लेख।

३. खाद्य समस्या—भूमि सुधार अङ्क तथा प्रायः प्रत्येक अंक में कृषि व खाद्य-स्तम्भ।

४. सामुदायिक विकास योजना—करीब २० लेख।

५. हमारे उद्योग—उद्योग अङ्क तथा वस्त्र उद्योग अङ्क; लोहा, चाय, सीमेंट, वस्त्र, चीनी तथा इंजीनियरिंग आदि उद्योगों पर समय-समय पर लेख।

६. सरल अर्थ चर्चा—ग्रामवासी ग्राहकों के लिए सरल भाषा में आर्थिक समस्याओं व देश की प्रगति का परिचयात्मक लेख।

७. बैंक और बीमा—बैंक अङ्क, रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, सहकारी अनुसूचित बैंक तथा बैंक और बीमा सम्बन्धी चर्चा प्रायः प्रत्येक अंक में।

८. हमारा व्यापार—प्रायः प्रतिमास व्यापार-सम्बन्धी सूचनाएं।

९. श्रम समस्या—मजदूर अङ्क—कर्मचारी बीमा योजना, प्राविडेण्ट फण्ड आदि सामयिक श्रम सम्बन्धी प्रश्न प्रायः प्रत्येक अंक में।

१०. अर्थवृत्त चयन—देश-विदेश की आर्थिक प्रवृत्तियों की जानकारी से यह स्तम्भ पूर्ण रहता है।

११. विविध राज्यों की आर्थिक समस्याएं—उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, मध्यप्रदेश और राजस्थान आदि राज्यों की आर्थिक समस्याओं पर लेख और उनकी आर्थिक प्रगतियों का संक्षिप्त परिचय।

१२. विविध विषयों पर लेख—

स्टर्लिंग-समस्या	बेकारी की विकट समस्या	समाजवाद व साम्यवाद
केन्द्र व राज्यों में परस्पर सम्बन्ध	ग्रामोद्योग और मिलें	उद्योग वित्त आयोग
मुद्रा कोष व विश्व बैंक	वित्त आयोग	भारत की आयात नीति
निजी उद्योग और राष्ट्रीयकरण	सामूहिक कृषि की मृग मरीचिका	नये कम्पनी कानून
हमारी राष्ट्रीय आय	घाटे की अर्थ-व्यवस्था	जमींदारी उन्मूलन
भारत की कर-व्यवस्था	रुपये का अवमूल्यन	भूमि समस्या के कुछ पहलू
कण्ट्रोल व विनियन्त्रण	भूदान का सर्वोदय अर्थशास्त्र	सम्पत्ति पर उत्तराधिकार कर
रेलवे बजट	भारत सेवक समाज आदि-आदि	

अर्थशास्त्र की यह अमूल्य सामग्री लेने के लिये पिछले अङ्क भी मंगाइये।

मैनेजर सम्पदा—अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिल्ली—६।

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

क्या आप जानते हैं ?

कि हाल में उत्पादन करों में हुई वृद्धि का आप पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

जब आप चीनी खरीदें तो ध्यान रखें कि केवल ५ नये पैसे प्रति पौंड या १० नये पैसे प्रति सेर कर वृद्धि हुई है।

वनस्पति तेलों में घानियों अथवा छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादित तेल पर कोई शुल्क नहीं बढ़ा है। अतएव कीमतें भी नहीं बढ़नी चाहिएं। बड़ी मिलों द्वारा तैयार होने वाले तेलों पर भी केवल २ नये पैसे प्रति पौंड शुल्क बढ़ेगा। गत वर्ष इस तेल में १० से २० नये पैसे प्रति पौंड वृद्धि हो चुकी है। अतएव यह तुच्छ वृद्धि व्यापार क्षेत्र द्वारा ही सहन की जा सकती है।

अगर आप धूम्रपान करते हैं तो कृपया ध्यान रखें कि केवल विशुद्ध भारतीय तम्बाकू से बनने वाली सिगरेटों जैसे कि 'चार मीनार' 'शाह दक्खन' को छोड़कर आप किसी भी छाप सिगरेटों का मूल्य अधिक नहीं देंगे। इन स्वदेशी सिगरेटों के एक पैकेट पर $\frac{1}{2}$ से लेकर १ नया पैसा कर बढ़ेगा। १०० बीड़ियों की कीमत केवल १ नया पैसा अधिक होगी। तम्बाकू का मूल्य किसी भी दशा में १३ नये पैसे प्रति पौंड से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए।

माचिसों में ४० तीलियों वाली माचिस का ४ नये पैसे और ६० तीलियों वाली माचिस का मूल्य ६ नये पैसे से अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें व्यापार का उचित लाभ और बढ़ा हुआ कर दोनों सम्मिलित हैं।

लिखने का साधारण कागज (८ पौंड) एक दस्ते का मूल्य किसी भी प्रकार $1\frac{1}{2}$ नये पैसे से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए।

उचित मूल्य ही दीजिए

इससे आपका और देश का लाभ है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

U. S. S. R. MAKE MODERN FLOUR MILL MACHINERY

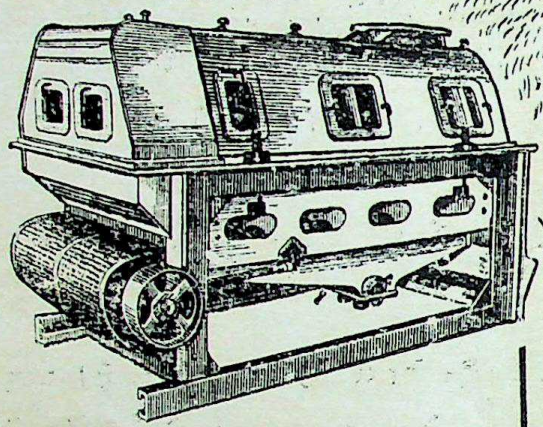

EXPORTED BY:

V/O Machinoexport

MOSCOW — U. S. S. R.

Golubev Groats Fanning Mill MODEL 3B-2-D.

Unique design for separation of groats and fine particles.

Cap: 750 to 1000 kgs per hour. Power 0.4 kw

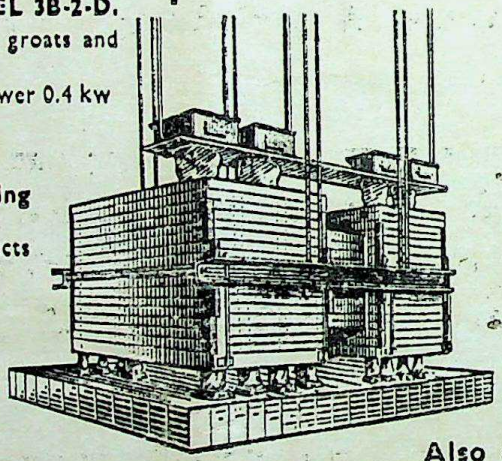

Circulating Grain Sizing Screen, MODEL 3P.

For grading of products after grain crushing.
Cap : 8 to 10 tons/hour
Power 1.0 kw

- ★ UNIQUE DESIGN
- ★ INCREASED OUTPUT
- ★ EASY OPERATION
- ★ DURABLE

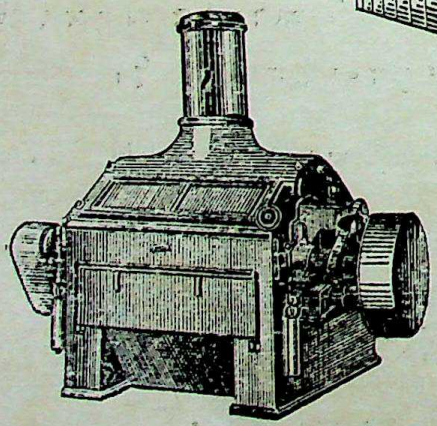

Roller Flour Mills MODEL-3M

For grinding grain and other friable cereals. Rollers plain or grooved automatic hydraulic control.
Cap: 6 to 12 tons/hour. Power 10 to 17.7 kw

Also available:

Grain Cleaning Separators, Disc Grading Separators, Hulling Mills, Exhausting Filters, Hammer Mills, Bucket Elevators, Belt Conveyers etc. for the Flour Mills. Food Canning Machinery, Cream Separators, Dough making Machines etc.

For further particulars please contact our Agents

BHANJI NANJI & CO.

67, Apollo Street, Bombay-1. 62, Bhawani Peth, Poona-2.

TRADE REPRESENTATION OF THE U.S.S.R. IN INDIA

BOMBAY (Branch) NEW DELHI CALCUTTA (Branch)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सप्तदल

अगस्त १९५७

सामुदायिक विकास योजना व ग्रामोत्थान में भाग लेती हुई राजस्थान की एक तरुणी। ऐसी हजारों बहिनें आज देश के कोने कोने में अपने अपने सीमित क्षेत्र में जन-जागृति और राष्ट्रनिर्माण के पवित्र व महत्वपूर्ण कार्य में मूक सेवा कर रही हैं।

सम्पादक
कृष्णचन्द्र विद्यालंकार

मूल्य : ७५ नये पैसे

अशोक प्रकाशन मन्दिर : रोशनारा रोड, दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार क्या कहते हैं?

भारतीय समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार की वार्षिक रिपोर्ट के कुछ अंक देखिये :—

- ३१ दिसम्बर ५६ को विभिन्न भाषाओं के कुल ६५७४ पत्र प्रकाशित हो रहे थे।
- सबसे अधिक दैनिक, साप्ताहिक और पाक्षिक हिन्दी में प्रकाशित होते हैं।
- अंग्रेजी पत्रों के बाद हिन्दी पत्रों के पाठकों का स्थान है। उनके १६ लाख पाठक हैं।
- हिन्दी मासिक पत्रों के पाठकों की संख्या सबसे अधिक ७ लाख ५० हजार है।

इसलिए आप भी हिन्दी के उत्कृष्ट मासिक पत्र सम्पदा में विज्ञापन देकर अधिकाधिक पाठकों से सम्पर्क कायम करें।

सम्पदा के पाठक वर्ष भर फाइल को पढ़कर उससे लाभ उठाते रहते हैं, इसलिए आपका विज्ञापन बारबार पाठक के सामने आता है।

विज्ञापन दरों की जानकारी के लिए लिखिये :—

—मैनेजर सम्पदा

अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिल्ली-६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्पदा का समाजवाद-अंक

समाजवाद आज के युग का तकाजा है। कांग्रेस और भारतीय संसद ने समाजवादी समाज के आदर्श को स्वीकार कर लिया है। समस्त योजनाएं इसी एक उद्देश्य को लेकर बनायी जा रही हैं। सार्वजनिक कार्यकर्ता समाजवाद के गीत गाते हैं, किन्तु आज भी समाजवाद क्या है, इस सम्बन्ध में जनता के सामने स्पष्ट और निश्चित विचार-धारा नहीं है। समाजवाद के मूल तत्वों, उसके विविध भेदों, उसकी प्रक्रियाओं और उसके मार्ग में आने वाली समस्याओं पर भी अभी तक बहुत कम विचार किया गया है। समाजवाद स्वयं एक उद्देश्य है अथवा उद्देश्य-प्राप्ति का साधन, यह भी निश्चित नहीं हो सका।

इन सब की जानकारी देने के लिए ही सम्पदा का यह समाजवाद अंक प्रकाशित किया जा रहा है। प्रस्तावित विषयसूची से इस अंक की उपयोगिता का अनुमान पाठक स्वयं कर सकेंगे।

— प्रस्तावित विषय-सूची —

विवेचनात्मक—

१. समाजवाद क्या है ?
२. समाजवाद के विविध भेद
३. वैदिक समाजवाद
४. साम्यवाद (विभिन्न धर्मों की दृष्टि से)
५. समाजवाद ध्येय है या साधन ?
६. साम्यवाद में व्यक्ति और राज्य का सम्बन्ध
७ सर्वोदय और साम्यवाद
८. राष्ट्रीयकरण क्या समाजवाद है ?
९ घोर केन्द्रीयकरण अथवा व्यक्ति-स्वातंत्र्य
१०. मिश्रित अर्थ-व्यवस्था।

इतिहास—

१. समाजवाद का जन्म तथा विकास (कार्लमार्क्स और अन्य समाजवादी विचारक)
२. रूस में महान साम्यवादी क्रांति
३. साम्यवादी शासन में रूस की असाधारण घटना
४. विभिन्न देशों में साम्यवादी पद्धति
५. यूगोस्लाविया में साम्यवाद का स्वरूप
६. चीन में साम्यवाद का स्वरूप
७. यूरोप में समाजवाद की लहर और उसका परिणाम
८. अमरीका के पूंजीवाद में नया मोड़
९. साम्यवाद में विविध प्रवृत्तियां
१०. साम्यवादी व्यवस्था में उद्योग और श्रम-संगठन
११. समाजवाद और श्रम समस्या

भारत में समाजवाद—

१. भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी
२. प्रजासमाजवादी और समाजवादी दल
३. कांग्रेस और समाजवाद
४. भारतीय संविधान और समाजवाद
५. सरकारी उद्योगों का विकास (दोनों पहलू)
६. उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की प्रवृत्ति
७. सरकारी नीति पर आलोचनात्मक दृष्टि
८. भारत में निजी उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान
९. समाजवादी आंदोलन और नयी समस्याएं
१०. भारत की संस्कृति, परम्पराएँ और साम्यवाद

विविध—

१. संसार के महान नेता—कार्लमार्क्स, लेनिन और गांधी
२. विनोबा का भूदान यज्ञ आदि आदि।

बीसियों चित्र, चार्ट और ग्राफ देने की परम्परा भी कायम रखी जायगी।

इस महत्वपूर्ण सामग्री से युक्त विशेषांक का मूल्य केवल १॥) रु०

—मैनेजर सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारत की औद्योगिक नीति

इसमें भारत की उद्योग नीति का अतीत, समय-समय पर होने वाले परिवर्तन और आज की नीति का संक्षेप से परिचय दिया गया है। इसके लेखक काशी हिन्दू विश्व-विद्यालय के श्री अश्विनीकुमार शाह और सेण्ट जेवियर्स कालेज रांची के श्री रामनरेश लाल अर्थशास्त्र के अनुभवी अध्यापक हैं। दोनों अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों की कठिनता और आवश्यकताएं जानते हैं। इसलिए यह पुस्तक हायर सैकेण्डरी, इन्टर व बी० ए० के परीक्षार्थी विद्यार्थियों के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी। मूल्य ६२ नये पैसे। ७५ नये पैसे के टिकट भेजकर अण्डर पोस्टल सर्टिफ़िकेट मंगाइये।

—मैनेजर, अशोक प्रकाशन मंदिर,
रोशनारा रोड, दिल्ली—६,

केवल ५० विद्यार्थियों के लिए

पंचवर्षीय योजनांक रियायत में

राजस्थान के एक सज्जन ने जो पंचवर्षीय योजना के प्रसार में विशेष रुचि लेते हैं, एक राशि इसलिये प्रदान की है कि हम अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों को अपने योजना अंक कम कीमत पर दें। इसलिये जो विद्यार्थी निम्न-लिखित अंक मंगवाना चाहें, वे दो रुपया मनीआर्डर से भेजकर तीनों अंक मंगालें। इन अंकों की वी० पी नहीं की जायेगी।

योजनांक—(प्रथम पंचवर्षीय योजना मूल्य १) रु०

राष्ट्रीय विकास अंक—(दूसरी योजना का विवरण १।)

जून १९५६ का अङ्क—(दूसरी योजना के संशोधित अंक इसमें दिये गये हैं) मूल्य ।।।)

यह रियायत केवल ५० विद्यार्थियों के लिये है।

इसलिए शीघ्रता करें, अन्यथा यह सुविधा नहीं मिल सकेगी।

—मैनेजर

संचालक पंचायत राज विभाग उ० प्र०

की

विज्ञप्ति संख्या ४/५५८०/३३ : २७/५३, दिनांक १५

द्वारा

पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत

सुन्दर पुस्तकें

	लेखक	मूल्य रु०	मूल्य आ०
वेद सार	प्रो. विश्वबन्धु	१	८
प्रभु का प्यारा कौन ? (२ भाग)	,,		
सच्चा सन्त	,,		१
सिद्ध साधक कृष्ण	,,	०	१
जीते जी ही मोक्ष	,,	०	१
आदर्श कर्मयोग	,,	०	१
विश्व-शान्ति के पथ पर	,,	०	१
भारतीय संस्कृति	प्रो. चारुदेव	०	१
बच्चों की देखभाल	प्रिंसिपल बहादुरमल	१	१२
हमारे बच्चे	श्री सन्तराम बी. ए.	३	१२
हमारा समाज	,,	६	०
व्यावहारिक ज्ञान	,,	२	१२
फलाहार	,,	१	४
रस-धारा	,,	०	१४
देश-देशान्तर की कहानियां	,,	१	०
नये युग की कहानियां	,,	१	१२
गल्प मंजुल	डा० रघुवरदयाल	१	०
विशाल भारत का इतिहास	प्रो. वेदव्यास	३	८

१० प्रतिशत कमीशन और ५० रु० से ऊपर के आदेशों पर १५ प्रतिशत कमीशन।

विश्वेश्वरानन्द पुस्तक भंडार
— साधु आश्रम, होशियारपुर,
पंजाब

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्पदा व हिन्दी में आर्थिक साहित्य पर्यायवाची शब्द हैं

अपने पांच वर्षों के स्वल्प काल में सम्पदा ने आर्थिक प्रवृत्तियों तथा आर्थिक समस्याओं की जो जानकारी दी है, वह अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। यही कारण है कि:—

हा. सै. स्कूल, इण्टर व डिग्री कालेज और पुस्तकालय एवं वाणिज्य व अर्थशास्त्र के विद्यार्थी

सम्पदा की पुरानी फाइलें मंगा रहे हैं। थोड़ी सी फाइलें बची हैं। प्रत्येक विशेषांक स्वयं एक उपादेय पुस्तक है। कुछ समय बाद आपको हम फाइल न दे सकेंगे। मूल्य प्रति फाइल ८) रु०

नमूने के एक अंक के लिए छः आने के टिकट भेजिये

यह स्मरण रखिये कि वी० पी० से मंगाने पर आपको ॥=) अधिक देना पड़ता है।

मनीआर्डर से मूल्य भेजना लाभकारी होगा।

राज्यों में सम्पदा स्वीकृत

सम्पदा को निम्नलिखित राज्यों के शिक्षा-विभागों ने अपने अपने राज्य के स्कूलों, कालेजों तथा सार्वजनिक वाचनालयों के लिए स्वीकृत किया है—

राज्य	परिपत्रक संख्या	दिनांक
(१) उत्तरप्रदेश	पुस्तक/५२५७	१२-१-५४
(२) बिहार	७३३/२पी/१/५३	२७-११-५३
(३) पंजाब	३२०६/५/२५/बी-५३-२६१४३	२३-७-५३
(४) मध्यप्रदेश		
(स्कूलों के लिए)	२ जी/वी	२-८-५२
(कालेजों के लिए)	३४२८ ३XVIII	२४-८-५२
(५) राजस्थान	३६८०/Edu II/५२	६-१२-५२
(६) मध्यभारत	३ : १५ : २ : ५२बी/२५६५	२४-३-५२
(७) दिल्ली		

३३७ शाखाएं समस्त भारत में

तथा

संसार के सभी महत्त्वपूर्ण केन्द्रों में एजेंसियाँ

सर्व प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध। विदेशी विनिमय तथा व्यापार के लिए विशेष रूप से उपयुक्त

कार्यगत कोष १४१ करोड़ रु० से अधिक

चेयरमैन

श्री एस. पी. जैन

दी पंजाब नैशनल बैंक लिमिटेड

स्थापित : सन् १८९५ ई०

प्रधान कार्यालय : दिल्ली

श्री ए. एम. वाकर— जनरल मैनेजर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विषय-सूची

सं०	विषय	पृष्ठ
१.	श्रमिक आन्दोलन अथवा अराजकता	४२९
२.	हमारी औद्योगिक उन्नति, अन्य टिप्पणियां	४३१
३.	कुछ ज्ञातव्य अंक	४३५
४.	हमारी पंचवर्षीय योजना में मौलिक दोष	४३७
५.	पंचवर्षीय योजना : कुछ विचार	४३९
६.	राजस्थान का आर्थिक विकास	४४१
७.	आज की आवश्यकता	४४३
८.	भारत सरकार की दो घोषणाएं	४४४
९.	हम कितना आगे बढ़े	४४८
१०.	भारत में भूमि व्यवस्था	४४९ व ४७६
११.	भारत में जलमार्ग का विकास	४५०
१२.	हमारा सीमेंट उद्योग	४५३
१३.	भारी मशीनें बनाने के उद्योग का विकास	४५५
१४.	सर्वोदय पृष्ठ सर्वोदय का कल्याण मार्ग—ट्रैक्टर बनाम बैल—योजना से मतभेद, सहकारी खेती में बल प्रयोग, असंग्रही समाज	४५७
१५.	नया सामयिक साहित्य	४६०
१६.	उत्पादकता क्या है ?	४६२
१७.	बैंक और बीमा सहकारी बैंकों का दायित्व—नये ऋण जारी, जीवन बीमा निगम—२ करोड़ रु० सम्पदा शुल्क—पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक	४६४
१८.	विविध राज्यों में आर्थिक प्रवृत्तियां दो बजट : मध्यप्रदेश व उत्तरप्रदेश—उत्तरप्रदेश की दूसरी पंचवर्षीय योजना	४६१
१९.	बाढ़ क्यों और उसका उपाय क्या ?	४७०
२०.	अर्थवृत्त-चयन नाप तोल भी दशमिक प्रणाली में—भारतका पशुधन—विश्व में अन्धाधुन्द चाय चम्बल योजनाकी प्रगति	४७१
२१.	विदेशी अर्थ-चर्चा रूस में परमाणु शक्ति—लीपजिग की औद्योगिक प्रदर्शनी	४७१

यदि डाक कर्मचारियों ने हड़ताल की ?

सम्पदा के प्रेमी पाठकों व ग्राहकों से अनुरोध है कि अगर डाक व तार कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी, तो संभव है कि स्वयंसेवक या नये कर्मचारी पता न जानने के कारण ठीक तरह से आपकी डाक हमें जल्दी न पहुँचा सकें। इसलिए आप निम्नलिखित पते पर पत्रव्यवहार करें।

—सम्पदा कार्यालय

१९. जैना बिल्डिंग्स (पैलेस सिनेमा के पास)
रोशनारा रोड, दिल्ली—६

★

सम्पदा

वार्षिक मूल्य ८)
,, ,, (शिक्षणालयों से) ७)
एक प्रति का मूल्य ७५ नये पैसे

सम्पादकीय परामर्शमण्डल
१. श्री जी० एस० पथिक
२. श्री महेन्द्र स्वरूप भटनागर

बम्बई में हमारे प्रतिनिधि—श्री टी० एन० वर्मा, नेशनल हाउस, २री मंजिल, दुलक रोड, बम्बई-१

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार का पता—
कृष्णचन्द्र विद्यालंकार, अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिल्ली-६

प्रबन्ध सम्बन्धी पत्रव्यवहार का पता—
मैनेजर सम्पदा, अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिल्ली-६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्पदा

वर्ष ६] अगस्त १९५७ [अङ्क ८

श्रमिक आन्दोलन या अराजकता

पिछले दिनों दिल्ली में श्रममन्त्री-सम्मेलन हुआ था। इसमें जिन प्रश्नों पर विचार हुआ, उनकी चर्चा हम पिछले अंक में कर चुके हैं। श्रम मन्त्री श्री गुलजारी लाल नन्दा ने इस सम्मेलन को आशातीत सफल बताते हुए कहा है कि इसमें वेतन नीति, अनुशासन, वैज्ञानिकन आदि अनेक विवादास्पद प्रश्नों को हल करने के तरीके निकाल लिए गए हैं। वे इस सम्मेलन की सफलता के सम्बन्ध में इतने अधिक आशावादी हैं कि उन्होंने कहा कि श्रमसम्मेलन उस निराशाजनक अंधकार में, जिसने हमें चारों ओर से घेर रखा है, एक प्रकाशमान स्थल है। मालिक और मजदूर के झगड़े ही अधिक उत्पादन के मार्ग में बाधा बनते हैं। हमने अब एक ऐसा उपाय निकाल लिया है, जिससे यह बाधा दूर हो जाएगी। इससे बड़ा सुखकर वातावरण पैदा हो गया है। हमने सुख-समृद्धि का बीज बोया है। हमने राष्ट्र में एक नई शक्ति पैदा की है।''

इसमें सन्देह नहीं कि उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की साझेदारी के सिद्धान्त को स्वीकार करके एक महत्वपूर्ण मांग मिल मालिकों ने स्वीकार कर ली है। औद्योगिक परिषदों का कार्यक्षेत्र भी अब बहुत विवादास्पद नहीं रहा। श्रमिक शिक्षा के सम्बन्ध में भी कुछ महत्वपूर्ण निश्चय कर लिये गये हैं, अभिनवीकरण के विवादग्रस्त प्रश्न पर मजदूर व मिल-संचालक अपने-अपने आग्रह को छोड़कर इस बात पर सहमत हो गये हैं कि अभिनवीकरण से होने वाला लाभ दोनों को समान रूप से मिले। अभिनवीकरण की प्रणाली भी तय कर ली गई है. परन्तु सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जिस पर सम्मेलन के सदस्य सहमत हुए हैं, मजदूरों में व्याप्त अनुशासनहीनता के लिए आचार संहिता का था। 'धीमे चलो' की नीति पर चलने, औद्योगिक यंत्रों व सम्पत्ति को जान बूझकर नष्ट करने, हिंसा, दबाव का प्रश्रय लेने, पूर्व सूचना दिए बिना हड़ताल करने आदि बातों का विरोध किया गया और हड़ताल से पूर्व समझौते के सब प्रयत्न अपनाने का सिद्धान्त सबने स्वीकार कर लिया। वेतनों का प्रश्न सदा से विवादग्रस्त रहा है, विभिन्न उद्योगों के लिए वेतन मण्डल नियुक्त करने का प्रस्ताव भी रखा गया। ये सब निर्णय इतने अच्छे हैं कि इन्हें देखते हुए यह कहना उचित ही प्रतीत होता है कि सम्मेलन सफल रहा है।

\+ + +

परन्तु प्रश्न यह है कि क्या इन समझौतों पर अमल भी होगा? राष्ट्र में औद्योगिक व आर्थिक शान्ति स्थापित रखने के लिए आवश्यक यह है कि हम देश की आर्थिक स्थिति तथा राष्ट्रीय हित को अपने सामने सदा रखें और

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अपने व्यवहार से कोई ऐसा कार्य न करें, जिससे जनता का अहित हो। क्या यह वातावरण आज देश में विद्यमान है? श्रम सम्मेलन ने देश में जिस शान्तिपूर्ण वातावरण की कल्पना की है, वह आज कहां है? आज तो मिलों के मजदूर इतने क्षुब्ध नहीं प्रतीत होते, जितने कि शिक्षित कर्मचारी। डाक व तार विभाग के हजारों कर्मचारी आज हड़ताल करने के लिए उद्यत हैं। उन्हें सब प्रकार के उचित आश्वासन दिये जाने पर भी—जनसामान्य से अधिक वेतन पाने पर भी—वे अपने निश्चय पर आग्रहशील हैं। जो स्थिति डाक-तार कर्मचारियों की है, केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों में भी वही स्थिति है। निम्न कर्मचारी व क्लर्क सरकार को हड़ताल का नोटिस दे चुके हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि समस्त देश में अराजकता की विकट एवं असन्तोषपूर्ण स्थिति छा गई है। दिल्ली के भंगियों ने समस्त नगर के स्वास्थ्य को नष्ट करने के लिए उस दिन जो कुछ किया, वह अत्यन्त निंदनीय था। उसे देखकर यह संदेह होता था कि राजधानी में कोई सरकार भी है? शिक्षित कर्मचारी पीछे कहां हैं? आज देश भर में केन्द्रीय कर्मचारियों के प्रदर्शन होने लगे हैं। कभी रेलवे के कर्मचारी हड़ताल का नोटिस देते हैं, तो कभी किसी दूसरे विभाग के। कहीं अध्यापक हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं गोदी कर्मचारी अपनी नई नई मांगें कर रहे हैं। किसी को यह चिन्ता नहीं कि उनकी इन मांगों को पूर्ण करने की क्षमता भी देश में है या नहीं। पिछले दिनों भारतीय सरकार के वित्तमंत्री ने अपने भाषण में बताया था कि भारत सरकार के केन्द्रीय कर्मचारियों की संख्या १७ लाख है और राज्य सरकारों के कर्मचारियों की संख्या ३५ लाख है, जिनमें स्थानीय संस्थाओं के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं। आज स्थिति यह है कि राज्य-कर्मचारियों के वेतन अपेक्षाकृत बहुत कम हैं। हैदराबाद में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी को १२५) रु० मिलते हैं, परन्तु राज्य-कर्मचारी को ७९ रुपये। उड़ीसा में तो राज्य कर्मचारी को केवल ६९) रु० मिलते हैं। इस पर भी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी वेतन-वृद्धि की मांग कर रहे हैं। भारत सरकार ने राज्यों को सूचना दी है कि यदि वे ६-६) रु० वेतन-वृद्धि कर दें तो केन्द्र दो तिहाई व एक तिहाई भार अपने ऊपर ले सकता है, किन्तु राज्यों के कोष बहुत कमजोर हैं, और सब राज्य इससे भी लाभ नहीं उठा सके। आज यदि केवल केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतन १५) रु० प्रतिमास बढ़ाये जावें, तो ३० करोड़ रु० अतिरिक्त भार हम पर पड़ जावेगा और 'सम्पदा' के पाठकों को यह जानना चाहिए कि यह सब देशवासियों को उठाना पड़ेगा, करों के रूप में। यदि राज्य सरकारों के ३५ लाख कर्मचारियों का भी वेतन-स्तर इसके बराबर करें, तो ६०-७० करोड़ रु० का अतिरिक्त बोझ जनता को उठाना पड़ेगा। क्या देश इस स्थिति में है?

मजदूर व शिक्षित कर्मचारियों के संघ आज अपनी-अपनी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए यह दूसरा पक्ष भूल जाते हैं। आज तो उन्हें यह भी चिन्ता नहीं कि उनके हड़ताल कर देने से राष्ट्र की कितनी भयंकर क्षति होगी। डाक तार का विभाग हो या भंगियों अथवा रेलवे या बन्दरगाहों के विभाग हों, किसी भी स्थान पर संकट का असर समस्त देशवासियों पर पड़ता है। परन्तु आज के संघ नेताओं को इससे कोई प्रयोजन नहीं, उनकी दृष्टि तो अपने हित तक सीमित है। बस यही एकमात्र दूषित दृष्टि है, जिसमें सुधार के बिना औद्योगिक व आर्थिक शान्ति असम्भव है और श्रम-सम्मेलन के निश्चय व्यवहार में आ जायंगे, इसमें पूरा संदेह होता है। आज प्रतिगामी आंदोलनकारी ताव देश भर में पनप रहे हैं, जो आर्थिक शांति कायम नहीं होने देंगे।

\+ + +

भारत सरकार एक नया कानून बनाने जा रही है जिसमें लोक सेवा के लिए आवश्यक कामों में हड़ताल गैर कानूनी करार दी जायगी। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने दृढ़ता से यह निश्चय कर लिया है कि वह हड़ताल की धमकियों से नहीं डरेगी और राष्ट्र को आवश्यक सुविधाओं से वंचित नहीं होने देगी। हम उसकी इस दृढ़ नीति का समर्थन करते हैं। कुछ विरोधी सदस्यों ने इसे डिक्टेटरशिप' कहा है। परन्तु हमें यह जानना चाहिए कि जब देश के सार्वजनिक कार्यकर्ता अपने उत्तदायित्व को भूल जाते तब सरकार देश में अराजकता की स्थिति आते देखकर चुपचाप नहीं बैठ सकती। इटली में मुसोलिनी ने शक्ति ही प्राप्त नहीं कर ली थी। वहां के साम्यवादियों ने देश में

[सम्पा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आर्थिक सुरक्षा व स्थिरता को नष्ट कर दिया था। मुसोलिनी की नीति वहां की तत्कालीन आवश्यकता थी। आज हमें यह देखना है कि हम दलगत राजनीति में आकर देश के सर्वांगीण हित को न भूलें, अन्यथा सरकार को अपने हाथ में अधिक अधिकार लेने के लिए विवश होना ही पड़ेगा। देश की व्यवस्था व शान्ति को तो नष्ट नहीं होने दिया जा सकता।

\+ + +

भारत सरकार ने एक ओर दृढ़ नीति अपनाने का निश्चय किया है, दूसरी ओर उसने कर्मचारियों के वेतन-स्तर आदि पर पुनर्विचार करने के लिए एक कमीशन भी नियत किया है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि वह कर्मचारियों के हितों की विरोधी नहीं है। क्या हम आशा करें कि डाक-तार व अन्य केन्द्रीय विभागों के कर्मचारी शान्ति व दूरदर्शिता से काम लेंगे? आज राष्ट्र की—राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक की शक्ति एक ओर लगनी चाहिए और वह है पंचवर्षीय योजना के विकास की पूर्ति। देश की अर्थ व्यवस्था पर नया भार डालने की रत्ती भर भी गुंजायश नहीं है। फिर भी नया कमिशन जो निर्णय करेगा, उस पर विश्वास न करके कर्मचारी आज नया संकट पैदा कर देंगे, तो जनता की सहानुभूति खो बैठेंगे।

हमारी औद्योगिक उन्नति

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की एक बड़ी विशेषता है कि उस में कृषि की अपेक्षा उद्योग पर अधिक बल दिया गया है। उसके पूर्ण होने पर भारत कितना समृद्ध और स्वावलम्बी हो जायगा, इसकी कल्पना की जा सकती है, पर अब भी उसकी औद्योगिक प्रगति कम सन्तोषजनक नहीं है। स्वातंत्र्यप्राप्ति के बाद उद्योगनीति ही बदल गई, क्यों कि ब्रिटिश उद्योगों का हित हमारा लक्ष नहीं रहा। इन १० वर्षों में देश का औद्योगिक उत्पादन ६० प्रतिशत बढ़ गया है। १९५७ में सूती कपड़े का उत्पादन बढ़ कर ५३० करोड़ गज हो गया, जब कि १९४७ में मिलों में ३७६ करोड़ गज सूती कपड़ा बना था। चीनी का उत्पादन १०.७५ लाख टन से बढ़कर २० लाख टन, वनस्पति का ९५,००० टन से बढ़कर २,५६,००० टन, साइकिलों का ४३,००० से बढ़कर ६,९५,००० और सिलाई की मशीनों का ६,००० से बढ़कर १.३३,००० हो गया है। नये इंजीनियरों और रासायनिक उद्योगों की स्थापना हमारी औद्योगिक प्रगति की उल्लेखनीय बात है। चित्तरंजन और टेलको के रेल-इंजन कारखाने, मोटर-कारखाने, सिंदरी का उर्वरक कारखाना, तेल-शोधक कारखाने, इस्पात का इमारती समान बनाने वाले कारखाने, पेरम्बू का सवारी डिब्बा कारखाना और माल-डिब्बे बनाने वाले अनेक निजी कारखाने, हिन्दुस्तान मशीन टूल कारखाना, औद्योगिक मशीनें, बिजली की मोटरें और डीजल इंजन के अनेक कारखाने और मूल-रसायन बनाने वाले कारखाने उल्लेखनीय हैं। १९५६ में ही २३ करोड़ रुपये मूल्य की मशीनें तैयार की गयीं। दस वर्ष पहले मशीनों का उत्पादन नगण्य था। १९४७ में केवल ७०० डीजल इंजन बनते थे, परन्तु १९५६ में १२,००० बनाये गये। बिजली के पम्पों का उत्पादन ६,००० से बढ़कर ४६,००० और बिजली की मोटरों का ३८,००० अश्व शक्ति से बढ़कर ३,५८,००० हो गया।

रासायनिक उद्योगों में भारत ने बहुत प्रगति की है गंधक के तेजाब का उत्पादन ६०,००० टन से बढ़कर २,६५,००० टन, कास्टिक सोडे का ३,००० टन से ३९,००० टन, सोडा ऐश का १२,००० टन से ८४,००० टन, अमोनियम सल्फेट का २१,००० टन से ३,३८,००० टन और सुपर फास्फेट का ५,००० टन से बढ़कर ८१,००० टन हो गया। कोयले और इस्पात का उत्पादन भी बढ़ा। सन १९४७ में ३ करोड़ टन कोयला खानों से निकाला गया था। १९५६ में ३ करोड़ ९० लाख टन निकाला गया। इसी अवधि में इस्पात का उत्पादन ८ लाख ९० हजार टन से बढ़कर १३ लाख २० हजार टन हो गया। सीमेंट के उत्पादन में तो आश्चर्यजनक वृद्धि हुई अर्थात् उत्पादन १४ लाख टन से बढ़कर ४९ लख टन हो गया। भारी मशीनों के निर्माण की ओर भारत किस तेजी से दौड़ रहा है, यह पाठक अन्यत्र पढ़ेंगे।

परन्तु यह निश्चित है कि भारत की औद्योगिक समृद्धि बिना ग्रामोद्योगों के नहीं हो सकती और न बेकारी दूर हो सकती है। इसलिए सरकार ने इच्छा से या विवशता से

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ग्रामोद्योगों की ओर ध्यान दिया है। गांवों की पुरानी शिल्प कला और दस्तकारी, हथकरघा और बिजली से चलने वाले करघे और छोटी मशीनों के कारखानों के विकास के लिए यत्न किया जा रहा है। पुराने उद्योगों के शिल्प में भी बड़ा भारी परिवर्तन हुआ है। कुछ साधारण पुर्जे और जोड़ देने से हथकरघे का उत्पादन लगभग ५० प्रतिशत बढ़ गया है। इसी तरह साधारण चर्खे के स्थान पर अम्बर चर्खे को चलाया जा रहा है। अम्बर चर्खा साधारण चर्खे से चार गुना सूत तैयार करेगा। इसी प्रकार गांव कुम्हार, तेली, मोची आदि के औजारों में भी सुधार किया जा रहा है, जिससे वे अधिक और बढ़िया चीजें तैयार कर सकें। परन्तु वस्तुत: इन दस वर्षों की औद्योगिक उन्नति में महत्वपूर्ण स्थान उन इंजिनीयरिंग उद्योगों का है, जिनमें टाइप राइटरों, सीने की मशीनों, साइकिलों, बिजली के बल्ब, रेजर ब्लेड तथा अन्य छोटी बड़ी मशीनें आती हैं। अब अनेक उद्योगों में भारत स्वतन्त्र हो गया है।

बन्दरगाहों पर बोझ

अभी केन्द्रीय मंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री ने बन्दरगाहों के अधिक सुधार व विकास के लिए एक बड़ी राशि की स्वीकृति संसद में लेने के लिए प्रस्ताव किया है। इसकी आवश्यकता समझने के लिए इसकी पृष्ठ भूमि जान लेना आवश्यक है। बन्दरगाहों पर माल ठीक समय जलदी नहीं उतरता और जहाजों को माल उतारने व चढ़ाने के लिए बहुत समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इस देर का दण्ड जहाजी कम्पनियों को अनावश्यक व्यय के रूप में मिलता है। एक दिन की देरी का अर्थ है कि एक सवारी व माल के जहाज को प्रतिदिन १०० पौण्ड की क्षति, क्यों कि वह जहाज नया कारोबार नहीं कर सकता और जहाजी कर्मचारियों पर होने वाला भारी खर्च बदस्तूर रहता है। विदेशी कम्पनियों ने काफी समय से किराया भाड़ा बढ़ाने की मांग की हुई है, यद्यपि उस मांग पर वे अमल नहीं कर पाये है, तथापि समस्या तो विकट है। माल उतारने में देरी के दो कारण हैं। एक तो यह कि बन्दरगाहों की क्षमता प्रतिदिन बढ़ते हुए व्यापार के अनुरूप नहीं है। कुछ मजदूरों में 'धीमे चलो' की खतरनाक लहर भी इसका कारण है। परिणामस्वरूप बम्बई में ही ४६ जहाजों को मझधार पानी में बहुत दिनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। एक अनुमान के अनुसार १३ करोड़ पौंड का माल लादे हुए जहाज भारतीय बन्दरगाहों पर यों ही माल उतरने की इन्तजार कर रहे हैं। यह ठीक है कि बन्दरगाहों के अधिकारी अपनी ओर से ज्यादा से ज्यादा माल उतारने की कोशिश करते हैं, परन्तु इसकी भी कोई सीमा होती है। आवश्यकता इस बात की है कि नये बन्दरगाहों की स्थापना की जाय, बम्बई कलकत्ता व मद्रास आदि में रेल वैगनों की संख्या बढ़ाई जाय और छोटे-छोटे जहाज दूसरे छोटे बन्दरगाहों पर लाये, जावें ताकि बड़े बन्दरगाहों पर माल भारी तादाद में जमा न होने पावे।

जहाजरानी का उद्योग

बन्दरगाहों के विकास के साथ-साथ एक बड़ी आवश्यकता भारतीय जहाजी व्यवसाय के विकास की है। तटवर्ती व्यापार के लिए हमें १९६१ तक ७ लाख टन (जी. आर. टी.) के जहाजों की आवश्यकता है, किन्तु जितने आर्डर इस समय तक दिये जा चुके हैं, उनके पूरा होने पर भी केवल २,९१,१८० टन के जहाज बन पायेंगे और दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंत में भी ४,५८,८२० टन की कमी रह जायगी। हमारे व्यापार में विदेशी जहाजों का कितना अधिक भाग है, यह इससे प्रकट है कि १९५५-५६ में १८० लाख टन का विदेशी व्यापार हुआ था, इसमें से केवल ११ लाख टन का व्यापार अर्थात् ६ प्रतिशत भारतीय जहाजों की मार्फत हुआ। कितनी रकम जहाजी भाड़े के रूप में विदेशों को देनी पड़ी होगी, यह कल्पना की जा सकती है। सम्पदा के पाठकों को यह शायद मालूम हो कि सं० रा० अमेरिका में एक कानून है कि विदेशी माल कम से कम ५० प्रतिशत अमेरिकन जहाजों पर आया करे। इस कानून के निर्माता श्री जोन बटलर इस मास नया बिल पेश कर रहे हैं कि अमेरिकन जहाजों का अनुपात ७५ प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाय। हम कुल ६ प्रतिशत व्यापार कर रहे हैं। जहाजरानी के व्यवसाय को सरकार द्वारा और अधिक प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इंगलैंड में विनियोजन पर ४० प्रतिशत की छूट दी जाती है, जब कि भारत में केवल विकास पर १२

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रतिशत छूट मिलती है। अब तो नये-नये टैक्स लग रहे हैं, जिनसे निजी कम्पनियों के लिए कुछ भी बचत करके नया पूंजी निर्माण करना कठिन हो जायगा। इन सब समस्याओं पर विचार करने के लिए अ० भा० उद्योग-व्यापार मण्डल के अध्यक्ष ने एक सम्मेलन अगस्त में बुलाया है। भारत सरकार को इस निजी उद्योग को अधिकतम सुविधाएं देनी चाहिए।

नये ऋण

भारत सरकार ने इन दिनों १०० करोड़ रु० का ऋण लिया है, किन्तु इससे सरकार को बहुत कुछ नयी प्राप्ति की आशा नही करनी चाहिए क्योंकि इसमें अधिकांश 'कन-वर्शन लोन' या परिवर्तनीय ऋण हैं। इसका अर्थ यह है कि सरकार ने आज जिन पिछले ऋणों की अदायगी करनी थी, उन्हें कुछ वर्ष बाद चुकावेगी। लेकिन इस ऋण के साथ एक नई समस्या भी पैदा हो गई है। भारत सरकार ने राज्यों को यह हिदायत दी है कि वे अपनी ओर से बाजार से ऋण न लें। कुछ राज्यों ने भारत सरकार के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है, कुछ ने इस पर अपनी सम्मति नहीं दी, किन्तु बम्बई राज्य ने ऐसा करने से इन्कार किया है। राज्यों की स्थिति बहुत विषम है। वे अपने व्यय पूर्ण करने के लिए अधिकतम टैक्स लगा चुकी हैं और उन्हें यह आशा नहीं कि जनता अधिक बोझ सहन कर सकेगी। बचत की प्रेरणा भी कहाँ तक की जा सकती है? जब लोगों के पास अपने-जीवन-यापन से कुछ बचे तो बचत संभव है। फिर इन केन्द्रीय ऋणों से बाजार का रुपया केन्द्र के पास चला जावेगा। इसका परिणाम निजी उद्योगों के लिए रुपये की कमी के रूप में प्रकट होगा। यह भी क्या हितकर है?

समाजवाद का उपाय

सम्पत्तिकर व व्ययकर पर कांग्रेस पार्टी की एक बैठक में भाषण देते हुए पं० नेहरू ने कहा है कि "हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि ये दोनों कर समाजवाद को ले आवेंगे। समाजवाद का सार समानीकरण के बजाय उत्पादन और वितरण में है। आज हमारा समस्त ध्यान उत्पादन वृद्धि की ओर केन्द्रित होना चाहिए।" परन्तु उत्पादन बढ़ाने की क्षमता निजी उद्योग में अधिक है, इस सत्य की उपेक्षा से काम नहीं बनेगा।

साध्य की उपेक्षा मत करो

प्रथम पंचवर्षीय आयोजना की समीक्षा सरकार की ओर से प्रकाशित की गई है। इससे प्रकट होता है कि योजना की अवधि में कुल मिला कर सरकारी और निजी कारखानों में २९३ करोड़ रु० की पूंजी लग गई। इसमें २३३ करोड़ रु० की निजी पूंजी थी और शेष ६० करोड़ रु० सरकारी पूंजी थी। दूसरी बात यह मालूम हुई कि निजी उद्योगों का उत्पादन जिस तेजी से बढ़ा, उस गति से सरकारी उद्योग नही बढ़े। इन दो बातों से एक सत्य स्पष्ट हो जाता है कि देश में निजी उद्योग की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यदि देश में उत्पादन बढ़ाना है, जो कि आज की स्थिति में अनिवार्य है, तो निजी उद्योगों के सामने राष्ट्रीयकरण या समाजवाद का भय नहीं रहना चाहिए। समाजवाद साधन है, साध्य है देश की सम्पन्नता और और उपभोग्य वस्तुओं का पर्याप्त उत्पादन। इसकी हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।

कठोर दण्ड की जरूरत

विशाल राशि से बनाये गए अशोक होटल की चर्चा अखबारों में काफी हुई है। उसमें प्रतिमास ३ लाख रु० की हानि सरकार को होती है। किन्तु इन दिनों दो तीन और भी समाचार प्रकाशित हुए हैं। एक समाचार के अनुसार बम्बई में शान्ताक्रुज के पास दस लाख रु० की श्रम संस्था के लिए जो इमारत बनाई गई थी, वह इसलिए गिरानी पड़ेगी कि हवाई अड्डे का विस्तार करना है। मद्रास के 'स्वराज्य' ने एक मंत्री के सम्बन्ध में यह समाचार दिया है कि एक बड़े कारोबार की तफसील में न जाने के कारण देश को बीस करोड़ रु० का नुकसान हो गया है। एक यह भी समाचार जिला है कि एक इमारत पर बीस लाख रु० खर्च हुआ, किन्तु उसकी मरम्मत के लिए २८ लाख रु० की जरूरत पड़ी।

आंध्र आडिट रिपोर्ट में भी कुछ मनोरंजक परन्तु दुःखप्रद रहस्योद्घाटन किये गये हैं। हथकरघा-प्रशिक्षण के नाम से एक योजना बुनकरों के बच्चों को सिखाने के लिए बनाई गई थी। ६ वर्षों के बाद मालूम हुआ कि ९,१२,२४१

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रु० (उस्मानिया) खर्च करके केवल ६१४ बच्चों को शिक्षा दी गई। उन बच्चों के शिक्षा समाप्त कर लेने के बाद व्यवहारतः शिक्षा का कार्य समाप्त हो गया, किन्तु शिक्षण अधिकारी दो वर्ष आगे भी बहाल रहे और उन्हें ४,४५००० रु० वेतन दिया गया। तीन वर्ष पहले समाप्त इस योजना के अन्तिम हिसाब अब तक नहीं दिये गये। एक छोटा कैण्टीन चलाने के लिए एक सरकारी विभाग ने विदेश से क्राकरी व कटलरी का सामान ८६८९ रु० का मंगा लिया। केन्द्रीय स्टोर विभाग की मार्फत यह नहीं मंगाया गया। विशेषज्ञों की प्रतिकूल सम्मति होते हुए भी एक अधिकारी ने ५ लाख रु० में दो टर्बोसेट एक कम्पनी से खरीद लिये। वे काम लायक नहीं थे, शायद इसलिए वे यथोचित स्थान पर नहीं भेजे गये और कम्पनी के गोदाम में चार वर्ष तक जंग खाते रहे। इसके बाद कम्पनी ने २००) रु० प्रति मास के हिसाब से गोदाम का किराया वसूल कर लिया। एक ठेकेदार को ठेका खतम होने पर पूरा पैसा दे दिया गया, फिर उसे ३५००० रु० अतिरिक्त रकम रेट बढ़ा कर दे दी गई।

हम नहीं जानते कि इन समाचारों में कहां तक सचाई है। यदि ये समाचार निराधार हैं तो इनका प्रतिवाद होना चाहिए और यदि इन समाचारों में कुछ भी सत्य है तो अपराधी अधिकारियों को ऐसा दण्ड मिलना चाहिए, जिससे इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। अपराधी को बिना कठोर दण्ड दिये इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रुक नहीं सकती।

आत्मनिर्भर होना है

पिछले दिनों भारत के प्रधानमंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू ब्रिटेन गये थे। राष्ट्र मंडल के प्रधान मन्त्रियों के सम्मेलन के अतिरिक्त उनकी यात्रा का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार से आर्थिक सहायता या ऋण लेना था। ऐसी सम्भावना भी प्रकट की गई थी कि ब्रिटेन की सरकार भारत को २०० लाख पौण्ड कर्ज देने की सम्भावना पर विचार कर रही है, किन्तु नये समाचारों से ज्ञात होता है कि ब्रिटेन अभी किसी तरह से आर्थिक सहायता नहीं कर सकता है। कुछ मास पहले पं० नेहरू अमेरिका गये थे। उस समय भी यह सम्भावना की गई थी कि अमेरिका से कुछ विशेष आर्थिक सहायता मिलेगी, किन्तु उसमें विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। एक ओर विश्व बैंक बहुत उदारता से पाकिस्तान को सहायता दे रहा है और दूसरी ओर भारत को एक ऋण देने पर भारी छान बीन और जांच पड़ताल करता है। इससे बैंक का पक्षपात स्पष्ट हो जाता है। आज उसी बैंक के हाथ में हमने अपना नहरी पानी का मामला छोड़ रखा है। हमें यह सन्देह है कि बैंक कोई भी न्यायपूर्ण निर्णय करेगा। वस्तुतः बैंक के अधिकारी अमेरिकन राजनीतिज्ञों के दृष्टिकोण और प्रभाव से मुक्त नहीं हैं। इसलिए हमें आज यह सोच कर चलना है कि विदेशों से हमें बहुत रकम नहीं मिलने वाली है। हमें अपने पैरों पर ही खड़ा होना है और इसी दृष्टि से अपनी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य पूरे करने हैं।

विदेशी कम्पनियों से पक्षपात

विदेशी मुद्रा की भीषण समस्या किस तरह सरकार को परेशान कर रही है, इसका एक उदाहरण सम्पत्ति व व्यय कर-सम्बन्धी विवाद में वित्तमंत्री का यह आश्वासन है कि भारत में कारोबार करने वाली विदेशी फर्मों से सम्पत्ति कर आधा लिया जायगा और व्यय कर में भी उन्हें सुविधाएं दी जावेंगी। यह भेद व पक्षपात विदेशी फर्मों को अपनी पूंजी अधिक लगाने के लिए आकृष्ट कर सकेगा, इसमें सन्देह है, क्योंकि भारत की सामान्य आर्थिक नीति सरकार द्वारा अधिकाधिक नियंत्रण व कर लगाने की होती जा रही है। समाजवादी समाज का नारा विदेशियों को भयभीत करने के लिए काफी है। यदि अन्य देशों में भारत से अधिक सुविधाएं हैं, तो वे अपनी पूंजी अन्यत्र लगाना ही पसंद करेंगे। इस तरह विशेष लाभ की संभावना नहीं है और अपने देशवासियों की अपेक्षा विदेशियों को अधिक सुविधाएं देने की नीति तो विदेशी शासन में भी थी, जिसका विरोध हम आधी शताब्दि से करते आये हैं। आज उसी नीति को अपनाना कहां तक तर्क संगत है?

——

सम्पदा के विचारशील पाठक क्या विकास योजना की पूर्ति में कुछ सहयोग न देंगे?

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

76333

भारत में सूती मिलें

विभिन्न राज्यों में १९५६ के अन्त तक पालियों के अनुसार कितनी सूती मिलें काम कर रही थीं, यह नीचे की तालिका से मालूम होगा।

	मिलों की कुल सं०	बन्द मिलें	१ पाली	२ पाली	३ पाली
बम्बई	१९६	४	९	६८	११५
मद्रास	९४	...	२	४६	४६
पश्चिमी बंगाल	२८	३	२	३	२०
उत्तर प्रदेश	२३	३	३	६	११
मध्यप्रदेश	१९	२	१	८	८
मैसूर	१४	१	...	७	६
केरल	१२	...	...	४	८
आंध्र	१२	१	३	४	४
राजस्थान	११	१	...	८	३
पंजाब	५	१	...	...	४
दिल्ली	४	...	...	...	४
बिहार	३	१	१	१	...
उड़ीसा	३	...	१	...	२
पांडिचेरी	३	...	...	२	१
योग	४२७	१७	२२	१५६	२३२

विविध राज्यों में कुल मजदूर

१९५६ के अन्त में विभिन्न राज्यों में कितने मजदूर काम कर रहे थे, यह नीचे की तालिका से पता लग जायेगा।

	रजिस्टर पर दर्ज मजदूरों की संख्या	औसत दैनिक उपस्थिति
बम्बई	५५०,७४३	४८४,६४५
मद्रास	११७,७०४	१०५,३३९
उत्तरप्रदेश	६२,८७४	५२,४८७
मध्यप्रदेश	५८,८४३	४९,६९६
पश्चिमी बंगाल	४३,७४५	४१,३३५
मैसूर	३२,९९२	२८,७११
दिल्ली	२१,३३३	१८,३४७
राजस्थान	१३,७१०	१३,१४६
आंध्र	११,८५०	९,७०१
केरल	१०,९५७	९,७५०
पंजाब	८,९३२	७,००७
पांडिचेरी	७,९०६	५,७४६
उड़ीसा	५,८६३	४,१५०
बिहार	१,५१६	९८९
योग	९४८,९६८	८३१,०४९

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

न्यूनतम वेतन व महंगाई भत्ता

गत दो वर्षों में न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ता प्रतिमास (२६ दिन का महीना) कितना मिला, यह नीचे की तालिका से मालूम होगा :—

	न्यूनतम वेतन	महंगाई भत्ता	
	१९५५-५६	१९५६	१९५५
	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०
बम्बई	३०— ०— ०	६८—१२— ४	६४—१२—११
अहमदाबाद	२८— ०— ०	६३—१५— ०	५४—११—१
शोलापुर	२६— ०— ०	५७—१०—१०	४०—१५—१
बड़ौदा	२६— ०— ०	५७— ६— ०	४९— ५—१
नागपुर	२६— ०— ०	४६—१३— ९	४०— २—१०
मद्रास	२६— ०— ०	४७—१२— ०	४१— ७—१
कानपुर	३०— ०— ०	५१—१२— ३	४३— ५—५
पश्चिमी बंगाल	२०— ०— ०	३०— ०— ०	३०— ०—०

भारत सरकार के व्यापार और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित

'उद्योग व्यापार पत्रिका'

★ उद्योग और व्यापार सम्बन्धी प्रामाणिक जानकारी-युक्त विशेष लेख, भारत सरकार की आवश्यक सूचनाएं, उपयोगी आंकड़े आदि प्रति मास दिये जाते हैं।

★ डिमाई चौपेजी आकार के ६०-७० पृष्ठ : मूल्य केवल ६ रुपया वार्षिक। एजेण्टों को अच्छा कमीशन दिया जायगा। पत्रिका विज्ञापन का सुन्दर साधन है।

★ लघु-उद्योग विशेषांक मंगा कर छोटे उद्योगों के सम्बन्ध में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त कीजिये।

★ ग्राहक बनने, एजेन्सी लेने अथवा विज्ञापन छपाने के लिए नीचे लिखे पते पर पत्र भेजिये :—

सम्पादक

उद्योग व्यापार पत्रिका

उद्योग और व्यापार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पंचवर्षीय योजना की मौलिक त्रुटियां

श्री मीनू मसानी, संसद् सदस्य

पिछले दिनों देश में जो अनेक विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, उन्हें देखते योजना की त्रुटियों पर भी अब ध्यान दिया जाने लगा है, जिनकी ओर योजना निर्माताओं ने ध्यान नहीं दिया था। देश के अर्थशास्त्रियों में इस लेख के लेखक अपना विशेष स्थान रखते हैं। उन्होंने बहुत योग्यता से योजना का दूसरा पक्ष उपस्थित किया है। लेखक की मान्यता है कि योजना का मूल आधार ही गलत है, साधनों का अनुसन्धान किये बिना काल्पनिक लक्ष्य बनाकर साधन तलाश करने के लिए असफल दौड़ धूप हो रही है; उपभोक्ता सामग्री की अपेक्षा भारी उद्योगों पर अनुचित बल दिया गया है; और हम साझी खेती का आकर्षक परन्तु अव्यावहारिक मार्ग अपनाने के प्रलोभन में पड़ गये हैं। लेखक का विश्वास है कि योजना साध्य है, साधन नहीं। योजना जनता के लिए है न कि जनता योजना के लिए।

अ-गांधीवादी दृष्टिकोण

पहली बात है योजना बनाने के प्रति हमारा दृष्टिकोण। महात्मा गांधी के इस देश में हमें सबसे पहला काम गांवों की जरूरतों का पता लगाने से शुरू करना चाहिए था, यानी गांव वालों को कितने कुओं, कितनी रासायनिक खादों, कौन-से औजारों और किस तरह के बीज की जरूरत है। इनमें और भी अनेक चीजें हैं। उसके बाद हमें कच्चे माल, जनशक्ति और पूंजी के अपने साधनों का पता लगाना चाहिए था, जिनको जुटा लेने के बाद जनता की जरूरतें पूरी हो सकती हैं। इसी खोज-बीन के आधार पर ही हमें यह देखना चाहिए था कि हम इन पांच वर्षों के दौरान में कितना उत्पादन करने की आशा करते हैं और कितना कर सकते हैं। अन्त में इन प्रयत्नों के फलस्वरूप हम कह सकते थे कि प्रति व्यक्ति आमदनी में कितनी प्रतिशत वृद्धि हो सकती है।

लेकिन, दूसरी योजना इसके बिल्कुल उलट बनाई गई है। कुछ लोग दिल्ली में मिलकर बैठे और उन्होंने फैसला कर दिया कि पांच वर्षों में राष्ट्रीय आय इतनी बढ़नी चाहिए। अपनी मरजी के मुताबिक उन्होंने आंकड़े निश्चित किये और फिर वे यह पता लगानेकी कोशिश करने लगे कि भिन्न-भिन्न उद्योगों में कितना उत्पादन करके इस लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार के उत्पादन के लक्ष्य निश्चित करके बाद में वे यह पता लगाने निकले कि हमारे पास आवश्यक साधन कितने हैं। यह जानकर कि हमारे साधन थोड़े हैं, उन्होंने फैसला किया कि कमी को घाटे की अर्थ-व्यवस्था से पूरा किया जाए, जिसका अर्थ यह है कि अधिक करेंसी नोट छापे जाएं। लेकिन उससे जनता की जेब में रुपए की कीमत घट जाती है। इसे ही मुद्रास्फीति कहते हैं। बाद में उन्होंने निश्चय किया कि इतने अधिक नोट तो न छापे जाएं, पर कुछ कमी को पूरा करने के लिए कर बढ़ा दिए जाएं। हमारी अर्थ-व्यवस्था में जो त्रुटियां हैं, उनका कारण योजना बनाने में जरूरत से ज्यादा यही केन्द्रीकरण और अ-गांधीवादी दृष्टिकोण है।

भारी उद्योगों पर अनुचित बल

योजना के जिस दूसरे पहलू से मुझे क्षोभ होता है, वह है भारी उद्योगों पर अनुचित जोर और उन्हें प्राथमिकता देना। दुनिया के सभी प्रगतिशील और बहुत अधिक उद्योगीकृत देशों ने उद्योगीकरण का सिलसिला पहले-पहल उपभोक्ताओं की जरूरतें पूरा करने के लिए कारखाने बनाकर आरम्भ किया, यानी उन्होंने कपड़े,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

साबुन, जूते, शृंगार-सम्बन्धी सामान और जीवन की सुख-सुविधा की अन्य चीजें बनाने के कारखाने बनाए। उन मशीनों का काम उन्होंने बाद में हाथ में लिया, जिनसे दैनिक जीवन की जरूरतों की चीजें बनाने के लिए मशीनें बनती हैं। हमारी दूसरी योजना में इस प्राकृतिक और ऐतिहासिक परिपाटी को उलट दिया गया है, और हमारी योजना के सिर के बल खड़ी है। "उत्पादक चीजों" (मशीनें आदि) को प्राथमिकता देकर, जिन्हें हम न पहन सकते हैं, न जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं और वे कारखाने आदि बनाने की बात को खटाई में डालकर, जिनसे जनता के लिए दैनिक जीवन की चीजें बनती हैं, यह योजना (जिसके द्वारा जनता का जीवन अधिक सुविधाजनक बनाने की आशा की जा रही है) जनता पर और भी बोझ लाद रही है। इस वर्ष के बजट में भी यही किया गया है। जनता से कहा गया है कि वह कुछ कुर्बानी करे, लेकिन जनता की तो आगे ही हालत अच्छी नहीं है। उद्योगीकरण का यह सिल-सिला अभी तक केवल रूस और अन्य साम्यवादी देशों में ही थोपा गया है, जहां हर पांच साल के बाद गरीब से यह कहा जाता है कि वह अपनी मेहनत का धन छोड दे, ताकि अगली पंचवर्षीय योजना को सफल बनाया जा सके। इन देशों में साधारण जनता का जीवन पहले की तरह कठोर और दयनीय है, पूर्वी यूरोपीय देशों और रूस में जनता यह आवाज उठा रही है कि हमें राहत देने के लिए इस सिलसिले में तबदीली करनी चाहिए।

आज अन्न की जो कमी है, उसका एक कारण यह है कि दूसरी योजना में पहली योजना के अनुसार कृषि पर पर्याप्त बल नहीं दिया जा रहा है। इस लिए यह योजना ऊपर से भारी और एकांगी है।

साझी खेती

दूसरी योजना में साझी खेती को जो तरजीह दी गई है, वह उन लोगों को पसन्द नहीं है, जिन्होंने इस विषय का गहरा अध्ययन किया है। जहां कहीं भी किसान से भूमि लेकर उसे सामूहिक अथवा साझे खेतों के रूप में रक्खा गया है, वहां पैदावार घटी है। सोवियत रूस और पूर्वी यूरोपीय देशों में भी यही हुआ है। इसी कारण यूगोस्लाविया और पोलैंड की साम्यवादी सर-कारों ने अपनी गलती महसूस की है और उन्होंने किसानों को साझी खेती छोड़कर अपनी जमीन खुद जोतने की छूट दे दी है। इस लिहाज से चीन की निस्बत हमें जापान को अपना पथ-प्रदर्शक मानना चाहिए। जापानी किसान ने उपयुक्त सहायता से जमीन के छोटे-छोटे टुकड़ों से भी इतनी अधिक पैदावार की है, जितनी कि साझे खेतों से नहीं की जा सकती। हम जितनी बहुमुखी सहकारी संस्थाएं बना सकते हैं, बनाएं। उन किसानों को जो खुशी से अपनी-अपनी भूमि इकट्ठी करके, मिलकर खेती करना चाहते हैं, हर तरीके से सुविधा भी दी जानी चाहिए। लेकिन फिर भी हमारी ज्यादा कोशिश यह होनी चाहिए कि किसान-मालिकों की मदद की जाए, जो कि हमारे राष्ट्र की रीढ़ हैं, ताकि जिस भूमि से उन्हें इतना लगाव है और जिसे एकाएक छोड़ने को वे तैयार नहीं हैं, उससे वे अधिक पैदा करें।

योजना बनाम जनता

योजना के बारे में विचार करते हुए हमारा ध्यान एक दार्शनिक प्रश्न की ओर जाता है। क्या योजना जनता के लाभ के लिए है या क्या जनता योजना को सफल बनाने के लिए है? किसी भी जनतन्त्र में किसान, उद्योगपति और मजदूर तथा उपभोक्ता को इच्छा के अनुसार काम करने की आजादी अक्षुण्ण रहनी चाहिए। यदि कोई योजना इस आजादी को कानून से और आर्थिक दबाव से दबाने की कोशिश करती है तो यह जनता की अन्तः प्रेरणा को कुचलती है और इससे ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है, जिसमें मुनाफाखोरी, चोर बाजारी और भ्रष्टाचार का बोलबाला हो।

इसके विपरीत यदि जनता को उसकी अन्तर्निहित शक्ति और उत्पादक क्षमता को उसकी मेहनत और उद्यम का पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया जाए तो प्रगति बहुत तेज होगी।

दृष्टिकोण व्यावहारिक हो

एक बात और है। यदि हम यह देखते हैं कि योजना

[सम्पूर्ण

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कुछ विचार—

हमारी विकास योजना

श्री रामनिवास रुइया

योजना के अनुसार आर्थिक उन्नति करना हर कोई स्वीकार करता है, इसमें कोई विवाद नहीं। यह तथ्य भी सर्वमान्य है कि हमारी राष्ट्रीय आय कम से कम दुगुनी हो जानी चाहिए याने वर्तमान आय स्तर से, जो ३०० रु० प्रति व्यक्ति से भी कम है, बढ़कर ६००) रु० प्रति व्यक्ति हो जाये। इस समय स्थिति यह है कि ग्रामों की ५० प्रतिशत जनता केवल ५० नये पैसे प्रतिदिन की आमदनी पर ही गुजारा करती है।

लेकिन यह बात ध्यान में रहनी चाहिए कि जब योजना इतनी महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है, तब कहीं जिस ढंग से उसका संचालन हो रहा है, इससे उसके मूलभूत उद्देश्यों को कोई हानि न पहुँच जावे। उदाहरण के लिए वर्तमान योजना के अन्त में लोगोंको यह प्रतीत न हो कि अब जब उनकी प्रति व्यक्ति आय तो ४०० रु० हो गई है, लेकिन इस राशि का क्रय-मूल्य ३०० रु० से भी कम रह गया है। याने मुद्रा-प्रसार के जोखिम और खतरों से लोगों की भली प्रकार रक्षा होनी चाहिए।

उत्पादन की वृद्धि एकमात्र उपाय

योजना की सफलता आवश्यक है। लेकिन यह कोरे सिद्धांतों की घोषणाओं से आगे नहीं बढ़ेगी, इसके लिये तो सीमेंट, इस्पात और कच्चे माल की आवश्यकता होती है। यही पदार्थ योजना को आगे बढ़ायेंगे। बहुत देर में हमें बताया गया है कि हम 'समाजवादी समाज के उद्देश्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं और यही हमारी आर्थिक नीतियों का आधार भी होगा। इस बात का दावा भी किया गया है कि समाजवादी रचना उस कल्याणकारी राज्य की ओर ले जायेगी, जहां जीवन-स्तर ऊँचा होगा। सबको अवसर की समानता होगी तथा धन और सम्पत्ति-सम्बन्धी कोई अन्तर न होगा। निस्संदेह ये विचार प्रशंसनीय हैं और कोई भी विचारवान व्यक्ति इस बात में विवाद न करेगा। लेकिन

> मुख्य प्रश्न तो यह है कि क्या समाजवादी साधनों को अपनाने से इन सत्-उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है? सैद्धांतिक और ऐतिहासिक दोनों प्रकार के अनुभवों से प्रकट होता है कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति समाजवादी सिद्धान्तों से सम्भव नहीं।

भ्रांत धारणा

समाजवाद का समर्थन करने के लिये इस भ्रांत धारणा का आश्रय लिया जाता है कि राज्य के स्वामित्व के स्थापित हो जाने पर आर्थिक ढांचे में ऐसा परिवर्तन कर दिया जाता है, जिससे अधिक से अधिक उत्पादन होता है और राष्ट्रीय आय का वितरण समान हो जाता है। यह भी कहा जाता है कि यह नयी अर्थ-व्यवस्था व्यक्ति के आचरण को प्रभावित करेगी, इस प्रकार एक नये समाज का जन्म होगा।

ये दावे बहुत ऊँचे और दिल पर असर करने वाले हैं। लेकिन अनुभवों से हमें ज्ञात होता है कि इनको कभी

की कुछ बातें व्यवहार और परीक्षा की कसौटी पर नहीं उतरतीं तो हमें उनमें हेर-फेर करने या उन्हें छोड़ देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। योजना में किसी धर्मान्धता से काम नहीं लेना चाहिए और न ही योजना कोई ऐसा तीर्थ स्थान है, जिसकी हमें पूजा ही करनी चाहिए। योजना तो किसी लक्ष्य की प्राप्ति का एक साधन है. और हमारा लक्ष्य है जनता की खुशहाली और आजादी। आर्थिक विकास के लिए किसी आसान रास्ते पर चलने से काम नहीं बनेगा। साम्यवादी देशों में जनता की इच्छाएं पूरी न करने से यह सिद्ध हो गया है। इस लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण ही सबसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। (योजना)

——

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

व्यावहारिक रूप नहीं दिया जा सका है। जब निजी स्वामित्व को समाप्त करके राज्य ने अपना स्वामित्व स्थापित किया, तो इन परिणामों की जिनकी इतनी आशा की गई थी, प्राप्ति हुई ही नहीं। यह मालूम रहना चाहिए कि सरकारी स्वामित्व के उद्योगों को किसी बाधा का सामना नहीं करना पड़ता, जब कि निजी क्षेत्र के उद्योगों की प्रगति पर पग-पग पर रोक लगाई जाती है। तथापि इन दोनों प्रकार के उद्योगों की तुलना करने पर कोई भी निष्पक्ष विचारक यह ज्ञात कर सकता है कि इतनी विघ्न-बाधाओं के होते हुए भी निजी उद्योग ने सरकारी उद्योग के मुकाबले में विलक्षण सफलता प्राप्त की।

जब हमने आयोजना को लक्ष्य रूप में स्वीकार कर लिया है, तो हमें इसकी प्राप्ति के लिये प्रयत्न करना चाहिए। निजी उद्योगों के प्रयत्न के बिना आयोजना के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसीलिए मैं यह मानता हूँ कि बड़े-बड़े कर लगाये जा सकते हैं, फिर भी एक उचित सीमा तो होनी चाहिए, जिससे कि व्यक्ति का उत्साह ठंडा न पड़ जाये। आखिर व्यक्ति के लिये भी न्यायोचित ढंग से कुछ न कुछ छोड़ना ही चाहिए, जिससे वह जीवित रह सके।

विदेशी मुद्रा

हमारी आयोजना के निर्माताओं को चाहिए कि वे आयोजना के सम्बन्ध में लैकरबाजी की अपेक्षा वे उसके विविध पहलुओं पर खूब विचार करें। वर्तमान समय में विदेशी मुद्रा की जो समस्याएं उपस्थित हैं; यह आयोजना का निर्माण करते समय दूरदर्शिता की कमी प्रकट करती हैं। विदेशी मुद्रा की कमी का आयोजना के भली प्रकार से संचालन करने पर प्रभाव पड़ रहा है। यदि हम आंशिक रूप से विदेशों में उधार की व्यवस्था करें, तो हमारी योजना पर व्यय ५० से ७५ प्रतिशत तक अधिक होने लगे। विगत वर्षों में अरबों रुपयों की मुद्रा अनावश्यक विलासितापूर्ण वस्तुओं की खरीद में खर्च कर दी गई। यदि यह मुद्रा खर्च न की गई होती तो हमें द्वितीय योजना के लिये काफी सुविधा होती। अवश्य ही उस समय भविष्य की स्थिति पर भी विचार कर लिया जा सकता था। इस भयंकर भूल के लिये कोई न कोई तो जिम्मेवार है ही।

प्रेरणा के तीन कारण

मेरा विश्वास है कि काम करने के तीन प्रेरक कारण हो सकते हैं। प्रेम, डर या लाभ की आशा। दुर्भाग्यवश इस श्रेणी के लोगों की संख्या बहुत ही कम एक प्रकार से नगण्य ही है, जो मानव मात्र के प्रति प्रेम की भावना से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। यदि समस्त विश्व में इसी प्रकार के मनुष्य होते तो फिर राज्य की आवश्यकता ही न थी। डर या डण्डे का शासन अवश्य ही उत्पादन करने के लिये प्रभावपूर्ण साधन है। लेकिन एक प्रजातंत्र शासन में, जिसमें हम रह रहे हैं, वहां सर्वाधिकारवादी रीतियों को नहीं अपनाया जाना चाहिए। यह स्मरण रखना भी आवश्यक है कि डंडे के बल से उत्पादन भले ही बढ़ जाये, लेकिन जीवन की अन्य अमूल्य वृत्तियां विनष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार उत्पादन बढ़ाने और समान वितरण का जो मूलभूत उद्देश्य मानव का विकास है, उसी का हनन हो जाता है।

अब कार्य करने का तीसरा उद्देश्य लाभ की भावना ही शेष रह जाती है। मैं यहीं पर लाभ और मुनाफाखोरी में अन्तर स्पष्ट कर देता हूं। यदि ठीक-ठीक कहा जाये तो लाभ मानवीय जोखिम का प्रतिफल है। लेकिन इस बात के कोई स्पष्ट नियम नहीं हैं, जिनसे यह निश्चित किया जा सके कि अमुक उपलब्धि लाभ है या मुनाफाखोरी। लेकिन न्याय और निष्पक्षता की भावना, जो कि प्रत्येक मनुष्य के अन्तःकरण में विद्यमान है, इनसे यह ज्ञात होने में सहायता मिलती है कि लाभ का स्वरूप क्या है। जनमत का बल, बाजार में उपभोक्ता की प्राथमिकताएं तथा इनसे भी अधिक राज्य द्वारा देश के हित में बनाये गये कानूनों से लाभ पर नियंत्रण किया जाता है और इसको मुनाफाखोरी का रूप धारण नहीं करने दिया जा सकता। संसार के इतिहास से स्पष्ट ज्ञात होता है कि लाभ की इच्छा ही उत्पादन बढ़ाने की सर्वश्रेष्ठ प्रवृत्ति है। (अनु०—श्री टी० एन० वर्मा)

एजेंट चाहिए

विभिन्न नगरों में 'सम्पदा' की बिक्री के लिए एजेंट चाहिएं। आकर्षक शर्तों के लिए व्यवहार करें।

—मैनेजर सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आश्वासन और दण्ड—

दो महत्त्वपूर्ण घोषणाएं

आज डाक तार व केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि की मांग के साथ हड़ताल की धमकी देकर देश भर में विषम समस्या उपस्थित करदी है। भारत सरकारने एक ओर उनकी मांग को स्वीकार करके कमीशन की नियुक्ति की है, दूसरी ओर आपातकालीन स्थितिका मुकाबला करने के लिए एक बिल संसद में उपस्थित करके बहुत से अधिकार लेने का निश्चय किया है।

आवश्यक सेवा कार्य

गृह मंत्री श्री गोविन्दवल्लभ पन्त ने लोकसभा में आवश्यक सेवाएं जारी रखने संबंधी विधेयक उपस्थित किया है। इसका उद्देश्य यह है कि आवश्यक सेवाओं के कर्मचारी हड़ताल न कर सकें। इसकी मियाद ३१ दिसम्बर १९५८ तक है।

इस विधेयक के अनुसार निम्न सेवाएं आवश्यक सेवाएं मानी जाएंगी :

१—डाक तार और टेलीफोन सेवा,

२—रेलवे तथा अन्य यातायात सेवाएं चाहे वे सेवाएं जल, थल और हवाई क्यों न हों।

३—हवाई अड्डे का संचालन,

४—किसी बंदरगाह में माल उतारना, चढ़ाना या गोदाम में रखना,

५—टकसाल अथवा नोट छापने का कारखाना।

६—रक्षा मंत्रालय के किसी भी कारखाने में जहां फौजी हथियार बनते हों,

७-किन्हीं भी अन्य सेवाओं को, जिसे केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझें।

जो भी व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करेगा, उसे एक वर्ष की सजा या १००० रु० जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। विधेयक का उद्देश्य यह बताया गया है कि डाक तथा तार कर्मचारियों और केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की कुछ अन्य संस्थाओं ने, जो ८ अगस्त की रात से हड़ताल करने का नोटिस दिए हैं, उसे खत्म करना है।

●

वेतन जांच आयोग

वित्त मंत्री श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने लोकसभा में घोषणा की है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे तथा सेवा स्थिति पर सरकार को रिपोर्ट देने के लिए जांच-आयोग नियुक्त किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्री जगन्नाथ दास इसके अध्यक्ष होंगे।

आयोग के सदस्यों की संख्या ५ होगी। ४ अन्य सदस्यों के नाम शीघ्र घोषित किये जाएंगे।

आयोग से कहा गया है कि वह देश की स्थिति तथा राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतन आदि को ध्यान में रख कर अपनी रिपोर्ट दे।

आयोग के विचारणीय विषय इस प्रकार हैं:—

१—केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं तथा वेतन भत्ता आदि निर्धारित करने की जांच करे।

२-केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों की सुविधाओं तथा वेतन में उचित वेतन परिवर्तन करने के लिए सुझाव दे। ऐसा सुझाव देते समय उसे देश की आर्थिक स्थिति तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना की आवश्यकताओं पर भी ध्यान रखना होगा। उसे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों, राज्य सरकार के कर्मचारियों, स्थानीय संस्थाओं तथा ऐसी अन्य संस्थाओं में असमानता न रहे, इस बात का ध्यान रखना होगा।

३—विशेष करके केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को वेतन तथा अन्य सुविधाओं के वर्तमान रूप में उचित परिवर्तन करने की सिफारिश करे।

स्मरण रहे कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की संख्या

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आज की आवश्यकता : औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि

जुलाई मास अनेक आर्थिक सम्मेलनों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। एक सम्मेलन औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में विचार करने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन के अध्यक्ष श्री मोरारजी देसाई थे। उन्होंने कहा कि—देश में दो आधारभूत समस्याएं हैं। एक तो महंगाई की बढ़ती हुई समस्या, जिससे मूल्यों की वृद्धि कम हो। दूसरी समस्या है विदेशी विनिमय का संतुलन रखने की, जिससे आयात निर्यात की अपेक्षा बहुत अधिक न बढ़ने पावें। आज की स्थिति में यह समस्या तो और भी विकट हो गई है। परन्तु वस्तुतः ये दोनों समस्याएं अलग-अलग नहीं, एक ही हैं। यदि देश का उत्पादन बढ़ जावे, तो उसका मूल्य देश में भी न बढ़ने पावेगा और विदेशी बाजार में भी हम अन्य देशों का मुकाबला कर सकेंगे तथा निर्यात बढ़ा सकेंगे। यदि हम देश में तिलहनों का, कपास का, जूट का, कपड़ों का, रासायनिक पदार्थों का, सिमेन्ट का, लोहे का, मशीनरी का उत्पादन बढ़ा सकें, तो न देश में पदार्थों के मूल्य बढ़ें, न मुद्रा-प्रसार की कठिन समस्या पैदा हो और न निर्यात बढ़ाने की चिन्ता उत्पन्न हो।

श्री मोरारजी देसाई के इन शब्दों में देश की उत्पादन-समस्या संक्षेप में आ गई है। परन्तु उत्पादन तो कैसे? दिल्ली के प्रमुख उद्योगपति ला० श्रीराम ने सुझाव रखा है कि इंजीनियरिंग मिलों में तीन-तीन पालियां चलाई जावें और ये मिलें सातों दिन चलें। उद्योग-व्यापार-मंडल के अध्यक्ष श्री बाबूभाई चिनाय ने यह प्रस्ताव किया कि सभी मिलों में तीन पाली चलाई जावें। वस्तुतः यदि भोजन तथा वस्त्र का उत्पादन प्रभूत मात्रा में होने लगे, तो महंगाई का खतरा देश में कम हो जाय। आज तो यह नारा लगाने की जरूरत है कि उत्पादन बढ़ाओ या नष्ट हो जाओ। किन्तु स्थिति इसके विपरीत है। १९५६ में देश में १५४ करोड़ रु० का पूंजीगत सामान आया था, किन्तु इस वर्ष की पहली छःमाही में केवल ५० करोड़ रु० के लाइसेंस दिये गये हैं।

देश का औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा है, इसमें संदेह नहीं। उत्पादन-वृद्धि को निम्नलिखित तालिका स्पष्ट करेगी।

औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि

(१९५१ = १००)

१९५५	१२२
१९५६	१३३
१९५७ (पहली तिमाही)	१४०

१९४७ में ३७६ करोड़ गज कपड़ा तैयार हुआ था, १९५७ में बढ़कर ५३० करोड़ गज हो गया। दस वर्षों में चीनी का उत्पादन १०० प्रतिशत तथा साइकिलों का १६ गुना बढ़ गया है। पर आज इस तरह अभिमान करने से काम न बनेगा। आज सचमुच औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रति दो वर्ष बाद देश की जनसंख्या एक करोड़ बढ़ जाती है, देश में भी जीवनस्तर बढ़ाने से मांग बढ़ रही है, और विदेशों को भी निर्यात बढ़ाते जाना है। इसलिए उत्पादन में जो वृद्धि हो रही है, उस पर संतोष प्रकट करके निश्चिन्त नहीं हो जाना चाहिए।

लगभग १७॥ लाख है और राज्य सरकारों के कर्मचारियों की संख्या लगभग ३७॥ लाख है। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों में सबसे अधिक रेलवे कर्मचारियों की संख्या है। इनकी संख्या लगभग १०॥ लाख है।

प्रथम वेतन आयोग सन् १९४६ में नियुक्त किया गया था और सन् १९४८ में उसकी सिफारिशों को मूर्त रूप दिया गया था। उसके पश्चात् देश में महंगाई बढ़ जाने के कारण सरकारी कर्मचारियों ने गत कुछ वर्षों से बारंबर मांग की थी कि उनके वेतन में वृद्धि की जाए। इस मांग के फलस्वरूप यह जांच आयोग नियुक्त किया गया है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राजस्थान का आर्थिक विकास

श्री वसन्त धर्मावत

वर्तमान वृहत्तर राजस्थान का उद्घाटन ३० मार्च सन् १९४९ को, प्रधान मंत्री पंडित नेहरू ने २० रियासतों का एकीकरण करके किया । १ नवम्बर सन् १९५६ को अजमेर राज्य भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। अब कुल २१ रियासतों का एकीकरण होकर इस वृहत् राजस्थान के स्थान पर न्यू स्टेट आफ राजस्थान का निर्माण हुआ। राज्य का कुल क्षेत्रफल १.३२,००० वर्ग मील है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्यप्रदेश व बम्बई को छोड़कर अन्य राज्यों में सबसे अधिक है।

राजस्थान की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं:

(१) १ करोड़ ६० लाख की आबादी का यह प्रान्त, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा होते हुए भी जन संख्या के घनत्व की दृष्टि से आसाम को छोड़कर सबसे कम है। जनसंख्या का औसत घनत्व ११७ व्यक्ति प्रति वर्ग मील है।

(२) राज्य के सम्पूर्ण विभागों का वितरण एक सा नहीं है। उदयपुर, जयपुर आदि में २०० से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग मील, बीकानेर में ६४ व जैसलमेर में ६ व्यक्ति प्रति वर्ग मील है।

(३) मानसून को रोकने के लिये ऊंचा पर्वत नहीं है, इसलिये वर्षा अधिक नहीं हो पाती।

(४) मरुस्थली भागों में कुंए १०० से २५० फीट तक गहरे हैं व तालाबों का अभाव है। नदियां पर्याप्त नहीं हैं। पूर्वी भाग में जहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं, भूमि पथरीली व पठारी है। राज्य में कृषि योग्य कुल भूमि (३ करोड़ एकड़) में से केवल २५.४२ लाख एकड़ भूमि में ही सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं।

(५) खेती व पशुपालन तथा कुटीर उद्योगों पर ही अधिक जनसंख्या निर्भर है। लगभग ८३ प्र० व्यक्ति गांवों में निवास करते हैं।

(६) वृहत स्तर के उद्योगों में ३४ हजार व्यक्ति व कुटीर उद्योगों में ७ लाख व्यक्ति लगे हुए हैं।

(७) राजस्थान का ६० प्र० शत भाग जागीरी इलाका था। एक विशेष अधिनियम के आधार पर इस प्रथा का उन्मूलन हो गया है।

(८) मिट्टी का तेल व पेट्रोल फिलहाल नहीं मिलता, परन्तु कुछ भागों में पेट्रोल निकलने की सम्भावनाएं हैं—जल विद्युत का अभाव है। कोयला भी अधिकांश बाहर से मंगाना पड़ता है।

(९) रेलों व सड़कों का अभाव है। राजस्थान में १०० वर्गमील भूमि में केवल ६–७ मील लम्बी सड़क है।

(१०) राजस्थान शिक्षा चिकित्सा व अन्य दृष्टि से पिछड़ा हुआ है।

खनिज

राजस्थान की भूमि में खनिज की बहुतायत है, परन्तु इनका पूर्ण उपयोग कभी नहीं हो पाया है। सरकार को रायल्टी के रूप में ५० लाख रु० की आय प्राप्त होती है। खनिज के दृष्टिकोण से राजस्थान का भारत भर में तृतीय स्थान है।

(१) अभ्रकः—उदयपुर डिवीजन में अधिकतया होता है।

(२) शीशा व जस्ताः—उदयपुर के पास जावर माइन्स में मिलता है।

(३) टंग्स्टनः—जोधपुर में डेगाना नामक स्थान पर उपलब्ध है।

(४) ताम्बाः—उदयपुर, डिवीजन में होता है।

(५) बेरिलः—उदयपुर, जयपुर डिवीजन में होता है।

(६) कोयलाः—बीकानेर में पालना नामक स्थान पर होता है।

(७) घीया पत्थरः—समूचे भारत का $\frac{3}{4}$ भाग राजस्थान में होता है।

(८) खड़ियाः—जोधपुर और बीकानेर डिवीजन में होती है।

(९) चूनाः—उदयपुर, जयपुर और बीकानेर डिवीजन में अधिक होता है।

(१०) इमारती पत्थरः—डूंगरपुर, जैसलमैर व कोटा डिवीजन में अधिक होना है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(११) नमक:—सांभर, पंचभद्रा व डीडवाना स्थानों पर होता है।

(१२) सोडियम सलफेट:—जोधपुर में डीडवाना स्थान पर पाया जाता है।

राजस्थान में २,५५० खाने हैं, जिनमें १½ लाख मजदूर कार्य करते हैं।

कृषि

राजस्थान की अधिकक्तर जन संख्या गांवों में निवास करती है और वह कृषि कार्य पर निर्भर करती है। राज्य की जन संख्या के ७१प्र० व्यक्ति कृषि कार्य करते हैं। इतनी बड़ी जन संख्या के कृषि पर निर्भर होने पर भी कृषि के लिए विशेष सुविधाएं नहीं हैं। पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल के कारण कहीं कहीं ज्वार बाजरा होता है। पूर्व भाग स्थित अलवर व भरतपुर के मैदानी प्रदेशों में नहरों के द्वारा सिंचित कई पैदावार प्राप्त होती हैं। उदयपुर में वर्षा अच्छी होने पर भी भूमि पथरीली होने से अधिक फसलें पैदा नहीं होती हैं। राजस्थान की कृषि की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं :

(१) कुल जनसंख्या का ७१% भाग भूमि पर निर्भर है।

(२) बहुत से व्यक्ति खेती के कार्य के साथ-साथ पशु भी पालते हैं।

(३) सिंचाई के साधनों का अभाव है।

(४) खाद का प्रयोग कम होता है, चूंकि वनों के अभाव के फलस्वरूप गोबर को जला देते हैं।

(५) वर्षा की न्यूनता एवं अनिश्चितता खेती के लिये बाधक है।

(६) खाद्यान्नों का कृषि में प्रमुख स्थान है। ज्वार, बाजरा उनमें प्रमुख है।

(७) राज्य की भूमि अधिक व जनसंख्या कम है, अतः प्रति व्यक्ति औसत जमीन अधिक आती है।

(८) ६६% भूमि में जागीरी रहने से उन्नति नहीं हो सकी है।

(९) सिंचाई के अभाव के कारण अधिकतर भूमि एक-फसली है। उत्पादित फसलों में खाद्यान्न ६०%, दालें १८.५%, तिलहन ७%, कपास १५%, और अन्य १३% हैं।

प्रमुख उपज :—ज्वार, बाजरा, मकई, गेहूं, उड़द, चना, मूंग, कपास, तिलहन, गन्ना, तम्बाकू, मसाले आदि हैं। शहरों के आसपास के भागों में शाक-सब्जी भी पैदा होती है।

उद्योग

राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया के शब्दों में "असली राजस्थान गांवों में ही है।" करीब ८३% व्यक्ति गांवों में निवास करते हैं, जिनमें से लगभग ६ लाख व्यक्ति छोटे उद्योग में लगे हुए हैं।

छोटे उद्योग

(१) सूती कपड़ा व्यवसाय :—कुल ५६,००० व्यक्ति लगे हुए हैं, हथकते सूत या मिलों के सूत से जुलाहे कपड़े बुनते हैं।

(२) ऊनी व्यवसाय :—राजस्थान के समस्त भागों में भारत की कुल ऊन का ⅓ भाग उत्पन्न होता है और इसका केवल १०% भाग ही उपयोग में लिया जाता है, बाकी बाहर निर्यात कर दिया जाता है। राजस्थान के पश्चिमी भागों में ही अधिक ऊन उत्पन्न होती है, चूंकि वहां अधिकतर भेड़ें पाली जाती हैं।

(३) कपड़े की रंगाई व छपाई :—यहां के रंगरेज इस कार्य के लिये निपुण हैं। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर डिवीजन में अच्छी रंगाई व छपाई होती है।

(४) पशुपालन सम्बन्धी :—दूध, घी, चमड़े का कार्य करना, ऊन का कार्य करना व अन्य सामान आदि में ३३ हजार से अधिक व्यक्ति लगे हुए हैं। जोधपुर के कसीदे के जूते बड़े प्रसिद्ध हैं। जयपुर में तलवारों की म्यानें, घोड़े की काठियां, हैंडबैग आदि बनते हैं।।

(५) वनों पर आधारित व्यवसाय :—वन्य प्रदेशों से प्राप्त उत्तम कोटि की लकड़ी फर्नीचर, मकान के दरवाजे आदि बनाने के उपयोग में ली जाती है। उदयपुर व सवाई माधोपुर में लकड़ी के खिलौने अच्छे बनते हैं।

(६) धातु का काम :—लोहे, पीतल व ताम्बे का काम व सोने चांदी के आभूषण बनाये जाते हैं। जयपुर इसके लिये प्रसिद्ध है।

(शेष पृष्ठ ४७५ पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हम कितना आगे बढ़े ?

प्रथम विकास योजना पर एक दृष्टि

सम्पदा के गतांक में पाठकों ने दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष की सफलताओं का संक्षिप्त परिचय पढ़ा था। इस अंक में हम प्रथम पंचवर्षीय योजना का, जो गत वर्ष पूर्ण हो चुकी है, कुछ परिचय देंगे।

देश की जरूरतों और साधनों की पूरी तसवीर पेश करना योजना का पहला लक्ष्य था। इसलिए चीजें "पहले करने" की स्कीम बनाई गई। कुछ ऐसी प्रायोजनाएं (प्राजेक्ट) थीं, जो पहले से ही शुरू हो चुकी थीं और उन्हें राष्ट्रीय कार्यक्रम में लेना ही था। देश की जनता इन सब बातों से नावकिफ्फ थी, इसलिए उसका ध्यान आयोजित विकास की आवश्यकता और उसकी समस्याओं की तरफ आकृष्ट किया जाना था। इसी प्रकार की अनेक महत्वपूर्ण बातों में पहली योजना को काफी सफलता मिली है।

खर्च—योजना पर जो हमने व्यय किया, वह काफी प्रभावपूर्ण है। कुल २,३८६ करोड़ रुपए व्यय करने का अनुमान था, पर कुल १,९६० करोड़ रु० खर्च हुए। व्यय में कमी का मुख्य कारण यह है कि उद्योग की मद में कम रुपया खर्च किया गया।

राष्ट्रीय आय—योजना के दौरान में राष्ट्रीय आय १७.५ प्रतिशत बढ़ी, पर उपभोग का स्तर मुश्किल से ८ प्रतिशत ही बढ़ा। राष्ट्रीय आय की इस वृद्धि में उद्योगों का योगदान अपेक्षाकृत कम रहा, फिर भी वृद्धि की सामान्य रफ्तार सन्तोषजनक ही है। पर इस बात से हम आश्वस्त नहीं हो सकते, क्योंकि यह वृद्धि काफी हद तक इसलिए सम्भव हुई कि बरसात ने हमारी मदद की, और बरसात पर हमेशा भरोसा नहीं किया जा सकता।

खेतीबाड़ी—योजना में सबसेज्यादा जोर खेती-बाड़ी, सिंचाई और बिजली पर दिया गया था। खेती-बाड़ी के लिए ३५४ करोड़ रुपए की व्यवस्था थी, पर वास्तव में कुल खर्च हुआ २९९ करोड़ रुपया। योजना के आरम्भ में ५४० लाख टन अनाज पैदा होता था, योजना का लक्ष्य था ६१९ लाख टन और कुल पैदावार हुई ६४९ लाख टन।

कृषि उत्पादन के साथ ही साथ औद्योगिक उत्पादन में भी वृद्धि हुई। आगे कृषि-उत्पादन सम्बन्धी ८ वस्तुओं और औद्योगिक उत्पादन सम्बन्धी २० वस्तुओं को इस दृष्टि से दिया जा रहा है कि उनके उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई। १९५०-५१ को आधार वर्ष मानकर पहले इस अवधि का उत्पादन दिया गया है, फिर योजना के अन्तिम वर्ष १९५५-५६ में जो वृद्धि हुई तथा अन्त में वृद्धि का प्रतिशत दिया गया है।

योजना आयोग ने व्यक्त किया है कि इस कृषि और औद्योगिक उत्पादन से अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में प्रगति की गति तीव्र हुई, जिसके आधार पर भावी विकास के कार्यक्रम आरम्भ किये जा सकेंगे।

कृषि उत्पादन

	१९५०-५१	१९५५-५६	वृद्धि
१. अन्न	५००·० लाख टन	६४९·० लाख टन	२९·८ प्रतिशत
२. कपास	२९·१ लाख गांठें	४०·० लाख गांठें	३७·५ "
३. जूट	३२·८ लाख गांठें	४२·० लाख गांठें	२८·० "
४. गन्ना (गुड़)	५६·२ लाख टन	५९ लाख टन	५·० "
५. तिलहन	५१·० लाख टन	५६·६ लाख टन	१३·२ "
६. तम्बाकू	२·५७ लाख टन	२·५९ लाख टन	८·० "
७. चाय	... ...	६०७६·८८ लाख पौंड	१०·५ "
८. आलू	१,६३४ हजार टन	१,८३९ हजार टन	१२·५ "

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

औद्योगिक उत्पादन

१. तैयार लोहा	९७६ हजार टन	१,२७४ हजार टन	३०·५ प्रतिशत
२. कच्चा लोहा	१,५७२ " "	१,७८७ " "	१३·७ "
३. सीमेंट	२,६९२ " "	४,५९२ " "	७१·३ "
४. उर्वरक			
(क) अमोनियम सल्फेट	... ...	४६,३९४ " "	७५६·५ "
(ख) सुपर फासफेट	... ...	५५,७१ " "	२९·१ "
५. इंजन	... ...	३१७९ (संख्या)	५,८६६·६ "
६. मशीनी पुर्जे	... ...	३,२७८ लाख रु०	१४३·७ "
७. डीज़ल इंजिन	५,५४० (संख्या)	१०,३६९ (संख्या)	८०·७ "
८. केबाइन्स और तार ACSR कंडक्टर्स	१,३४९ टन	८,७३० टन	५४७·१ "
९. मोटर गाड़ियां	१६,५१९ (संख्या)	२५,२७२ (संख्या)	५३ "
१०. अल्यूमीनियम	३,६७७ टन	७,३३३ टन	९९.४ "
११. सूत का सामान			
(क) कता सूत	११,७९० लाख पौंड	१६,३३० लाख पौंड	३९ "
(ख) मिल का कपड़ा	३७,१८० लाख गज	५१,०२० लाख गज	३७·२ "
(ग) हथकरघे का कपड़ा	८,१०० लाख गज	१४,४९० लाख गज	७९ "
१२. जूट का सामान	८२४ हजार टन	१,०५४ हजार टन	२८ "
१३. साइकिल	९८ हजार	५१३ हजार	४२९ "
१४. सिलाई की मशीनें	३३ हजार	१११ हजार	२३६·३ "
१५. बिजली के बल्ब	१५,००० हजार	२४,२२८ हजार	६१ "
१६. पावर एल्कोहोल	५० लाख गैलन	१०४ लाख गैलन	१०८ "
१७. चीनी	१,१०० हजार टन	१,८६० हजार टन	७० "
१८. वनस्पति	१५३ हजार टन	२७६ हजार टन	८०·४ "
१९. कागज और गत्ता	११४ हजार टन	१८७ हजार टन	६४ "
२०. चमड़े के जूते	५,१९५ हजार जोड़े	५,६७५ हजार जोड़े	९·२ "

(४) सिंचाई और बिजली—योजना में खेती-बाड़ी के बाद सिंचाई और बिजली कार्यक्रमों को महत्व दिया गया था। १९५१-५६ के दौरान में कुल ५६९ करोड़ रुपए व्यय किए गए, जबकि ५६१ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। १९५०-५१ में ५१० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हुई। योजना में ७०७ लाख एकड़ भूमि सींचने का लक्ष्य रखा गया था, पर कुल ६५० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकी।

योजनाके शुरू में २१ लाख किलोवाट बिजली पैदा हो जाती थी। योजना में ३६ लाख किलोवाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य था, पर ३४ लाख किलोवाट पैदा की जा सकी।

परिवहन और संचार—खेती-बाड़ी, सिंचाई और बिजली के बाद परिवहन और संचार का महत्व है। वास्तव में कुल व्यय का २९ प्रतिशत इन पर खर्च करने का विचार किया गया था। पर कुल खर्च २६ प्रतिशत हुआ, जो कि

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

१२५ करोड़ रुपए के बराबर बैठता है। सड़क परिवहन का काम लक्ष्य के अनुसार पूरा हुआ। रेलों के सम्बन्ध में हुई प्रगति भी सन्तोषजनक है।

रेलें

प्रथम योजना में रेलों की व्यवस्था सुदृढ़ हुई। योजना में व्यवस्था थी कि १०३८ इंजिन ५६७४ सवारी डिब्बे और ४९,११३ मालके डिब्बे उपलब्ध किये जायें। इन ५ वर्षों में १४०० इंजिन, ४८३८ सवारी डिब्बे और ६१,७१३ माल के डिब्बे प्राप्त किये गये।

साथ ही देश में १९५०-५१ से १९५५-५६ तक १७९ रेल के इंजिनों का निर्माण किया गया। माल के डिब्बे ३,०७७ से १३,५२६ तक तथा सवारी डिब्बे ५७३ से १२६० तक बनाये गये।

(६) सामुदायिक योजनाएं—सामुदायिक योजनाओं का कार्यक्रम बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण था। योजना की समाप्ति पर सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम लगभग १,४०,००० गांवों और ७८० लाख लोगों तक पहुँच चुका था। वास्तव में इन पर ९० करोड़ रु० व्यय करने का विचार था, पर कुल ४६ करोड़ रु० ही खर्च हुए।

सहकारिता—योजना में सहकारी संस्थाओं पर विशेष बल दिया गया था। सहकारी संस्थाओं की संख्या १,८०,००० के लगभग २,४०,००० और उनके सदस्यों की संख्या १४० लाख से लगभग १८० लाख हो गई। सहकारिता आन्दोलन में शुरू में जो कमजोरियां थीं, वे अब भी मौजूद हैं। योजना की आवश्यकताओं के अनुपात में सहकारिता आन्दोलन के लिए जनसाधारण का जोश-खरोश देखने में नहीं आया।

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा:— सरकार ने इनके लिए शुरू में १५२ करोड़ रुपए की व्यवस्था की थी। पर खर्च हुआ १५३ करोड़ रुपया। योजना की समाप्ति पर भी हम शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाओं और रोजगार के अवसरों में सन्तुलन नहीं कर सके। समाज-शिक्षा की प्रगति तो खासकर बहुत निराशाजनक है।

वैज्ञानिक गवेषणा के क्षेत्र में योजना का जो लक्ष्य मुख्यतः संस्थाएं संगठित करने का था, वह पूरा हो गया है। भारत में अब १४ राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें गवेषणा करने के लिए आधुनिकतम सुविधाएं हैं।

रोजगार—योजना काल में बेरोजगारी और अपर्याप्त रोजगारी में कोई कमी नहीं हुई। साथ ही ऐसा लग रहा है कि शिक्षा की प्रगति के साथ-साथ नगरों में बेरोजगारी की समस्या और भी भीषण हो गई है।

सीमित साधनों और बिभाजन से पैदा हुई आपत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए भारत की पहली पंचवर्षीय योजना को विवशतया संयत होना था। इसलिए योजना द्वारा निश्चित लक्ष्य देश की कम से कम जरूरतों को देखते हुए नहीं रखे जा सकते। वे तो केवल हमारी पिछड़ी हुई अर्थ-व्यवस्था की अधिक से अधिक क्षमता के अनुसार ही हो सकते हैं। जब हम योजना द्वारा निश्चित लक्ष्यों के प्रकाश में अपनी सफलता पर दृष्टि डालते हैं तो देखते हैं कि हमारी सफलता ८५ प्रतिशत से ९० प्रतिशत तक हुई है, और यह प्रगति कम उल्लेखनीय नहीं है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारत में भूमि-व्यवस्था

—कृष्णकुमारी शर्मा

भारत कृषि-प्रधान देश है। यहां की ७० प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर करती है। किन्तु भूमि समस्या के कारण हमारी कृषि पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पायी। देश के ८३ प्रतिशत ग्रामीणों के जीवन में सुधार तभी किया जा सकता है जब एक सकुशल भूमि व्यवस्था का निर्माण हो सके।

स्वतन्त्रता की प्राप्ति के पश्चात नयी सरकार ने देश के लिये जिन विभिन्न समस्याओं का विश्लेषण किया तथा सुधार का कदम उठाया, भूमि की समस्या भी उनमें से एक है। इसके कारण देश भर में एक हलचल उत्पन्न होगयी। 'टैन्योर' (Tanure) शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द Teno से हुई, जिसका अर्थ होता है 'अधिकार'। सो इसके अन्तर्गत भूमि को लेकर किसके क्या अधिकार हैं तथा कृषक व भूमि-मालिक का परस्पर क्या सम्बन्ध हैं, यह सब बातें आ जाती हैं। आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिकोण से देखने से हमें ज्ञात होता है कि देश का आर्थिक-जीवन कृषि द्वारा प्रभावित होता है तथा ग्राम के सामाजिक आधार के निर्माण में भी कृषि सहायक सिद्ध होती है। कृषि व भूमि व्यवस्था में उत्पादन व सामाजिक न्याय का भी समावेश हो जाता है।

हमारे देश में भूमि-सम्बन्धी तीन प्रणालियां रैयतवारी, महलवारी तथा जमींदारी प्रथा बहुत वर्षों से प्रचलित हैं। प्राचीन काल में लगान देने के नियम सरल थे तथा अनाज के रूप में लगान स्वीकार कर लिया जाता था। किन्तु समय के चक्र के साथ, भारत की राज्य सत्ता विदेशियों के हाथों में चली गयी। इन्होंने अपने अलग नियम बनाये। इसके कारण जमींदारी प्रथा का अभ्युदय हुआ और इस व्यवस्था के कारण अनेक कठिनाइयां आती गयीं।

देश की ५० प्रतिशत भूमि रैयतवारी प्रथा में आ जाती है। इस प्रथा में कृषक तथा सरकार में प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहता है। कृषक सरकार से भूमि लेकर उस पर खेती करता है। वह अपने खेत को दूसरे व्यक्ति को दे सकता है, बंधक रख सकता है परन्तु किसी भी स्थिति में उसे बेच नहीं सकता है। यदि वह खेती नहीं करना चाहता हो तो ऐसी अवस्था में सरकार उससे भूमि वापस ले लेती है तथा अन्य कृषक को सौंप देती है। कृषक अपनी इच्छानुसार भूमि को सभी तरह के प्रयोगों में ला सकता है। कृषक सरकार को लगान देता है तथा इसमें मध्यवर्तियों का नाम नहीं रहता। रैयतवारी प्रथा बम्बई, विदर्भ और मद्रास के कुछ भागों में पायी जाती है और इसकी अवधि बीस से चालीस वर्षों तक की होती है। इस प्रथा की विशेषता है कि सरकार और कृषक का सम्बन्ध प्रत्यक्ष होता है। भूमि के स्वामित्व को हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता है। कृषक बहुधा ऐसी प्रथा से प्रसन्न रहते हैं परन्तु इसकी सबसे बड़ी परेशानी है कि सरकारी कर्मचारियों को लगान एकत्रित करने में विशेष कठिनाई होती है।

भारत के कुछ ग्रामों में महलवारी-प्रथा पायी जाती है। देश की ८ प्रतिशत भूमि पर इस नियम के अनुसार खेती की जाती है। सरकार प्रत्येक कृषक को अलग-अलग भूमि देने के झगड़े में नहीं पड़ती है, परन्तु ग्राम के कुछ व्यक्तियों को सामूहिक रूप में देती है। उस दल का एक व्यक्ति मुखिया होता है और वह भूमि को कृषकों के मध्य विभक्त कर देता है। उसे सरकार को लगान देने का अधिकार रहता है। लगान से एक निश्चित मात्रा रख कर बाकी सरकार को दे देता है। महलवारी प्रथा में यदि एक कृषक लगान देने में असमर्थ रहा, तब भी सहभागियों को उसकी पूर्ति करनी पड़ती है। कृषक भूमि को हस्तान्तर कर सकता है, बंधक रख सकता है और सभी तरह से प्रयोग में ला सकता है ताकि अधिक उत्पादन सम्भव हो सके। यह प्रणाली पंजाब, मध्य प्रदेश तथा आगरा जिले में पायी जाती है।

खेती के अधिकार को लेकर कृषक दो भागों में बंट गए हैं—शिकमी और गैर-शिकमी। शिकमी भूमि-व्यवस्था की तीनों पद्धतियों में पाये जाते हैं। यदि शिकमी लगातार लगान देता चला आ रहा है तो उसका स्थायी रूप से भूमि पर अधिकार हो जाता है और वह उसे आगे के वंशों

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के लिए छोड़ कर मरता है। शिकमी स्वयं खेती करने को बाध्य नहीं होगा—वह अधिक लगान पर खेत अन्य को दे सकता है। कृषक १६ प्रतिशत शिकमी प्रथा में आ जाते हैं और बाकी गैर-शिकमी में।

गैर-शिकमी में भूमि मालिक और कृषक का सम्बन्ध अल्पकाल के लिए रहता है। प्रायः यह एक या दो वर्षों के लिए होता है। भूमि का मालिक अपनी इच्छानुसार किसी भी शर्त पर कृषक को भूमि दे सकता है। गैर-शिकमी (Tenancy at will) में लगान 'बटाई' अथवा 'ठेकेदार' के रूप में दिया जाता है। गांवों में बंटाई या अनाज के रूप में लगान देना अधिक प्रचलित है, परन्तु नगरों में रहने वाले भूमि मालिक ठेकेदार या नकद लगान लेना अधिक पसन्द करते हैं।

जमींदारी प्रथा

भूमि-व्यवस्था की अन्तिम प्रथा जमींदारी प्रथा कहलाती है। ४२ प्रतिशत भूमि पर यह नियम लागू होता है। ब्रिटिश शासन काल में यह प्रथा कार्यान्वित हुई। १७९३ लार्ड कार्नवालिस ने लगान देने के नियम को स्थापित कर दिया और देश में जमींदारी प्रथा का सूत्रपात हुआ। लगान लेने के अधिकार को स्थायी कर देने के पश्चात सरकार को $\frac{1}{10}$ भाग मिलने लगा तथा लगान वसूल करने वालों को $\frac{9}{10}$ मिलने लगा। लगान वसूल करने वाले कर्मचारी ही जमींदार कहलाये। शीघ्र ही काश्तकारों पर उनके अत्याचार प्रारम्भ हो गए। वे कृषकों से मनमाना लगान लेने लगे और सरकार को निश्चित रकम देकर बाकी स्वयं लेने लगे। कृषि विकास रुक गया तथा आर्थिक अवगुण दृष्टिगोचर होने लगे।

जमींदारी प्रथा के कारण सरकार की आय में घाटा होता है और साथ भूमि की उपज-शक्ति का भी ह्रास होता है। जमींदारों के शोषण के कारण कृषक खेतों की उन्नति या अधिक उत्पादन में चाव नहीं रखता है। कारिन्दों पर लगान वसूल करने के भार को सौंप देने से कृषकों का अधिकाधिक शोषण होता है। उनकी आय का एक बड़ा अंश जमींदारों के पास चला जाता है। खनिज पदार्थों और वन-सम्पत्ति का नाश होता है। सरकार और कृषक के बीच मध्यवर्तियों का जाल रहता है। सबसे बड़ा दोष है—कृषकों की सामाजिक स्थिति की दयनीय अवस्था और कृषि-उद्योग की दुरवस्था।

सरकार ने भूमि की बुराइयों का अन्त करने के लिए कई सुधार किये। सरकार के सामने तीन उद्देश्य थे—मध्यवर्तियों का अन्त करना ताकि सरकार और कृषक का प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहे। दूसरा उद्देश्य था वास्तविक खेतिहर को, स्थायी भूमि धर बना देना और अन्न के उत्पादन में वृद्धि। स्थायी भूमिधर होने से उसके शोषण की संभावना कम रहती है और वह नाना प्रकार से खेती की उन्नति करके राष्ट्र की पैदावार में वृद्धि करता है। देश के प्रायः सब प्रान्तों में भूमि सुधार नियम बनाये गए या बनाये जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार बिल १९५२ को स्वीकृत हुआ तथा जुलाई प्रथम १९५२ से इस प्रांत में जमींदारी प्रथा का अन्त कर दिया गया। मद्रास में भी इस प्रथा को उठा दिया गया है। बिहार राज्य में बिहार भूमि सुधार कानून १९५०में स्वीकृत हुआ। जमींदारी का अन्त करने के प्रयत्न जारी हैं। पंजाब, हैदराबाद, उड़ीसा, मध्यभारत, बम्बई, आसाम, जम्मू काश्मीर और पेप्सू राज्यों में भूमि सुधार कानून स्वीकृत किये गये हैं।

इन कानूनों के अनुसार उत्तरप्रदेश तथा पंजाब में एक कृषक परिवार ३० एकड़ भूमि का अधिकारी होगा। आसाम में ३३$\frac{1}{3}$ एकड़, मध्य प्रदेश में १२५ एकड़, पेप्सू में ३० एकड़, कच्छ में १५ एकड़ और उड़ीसा में ७.१४ एकड़ तक दिया जायेगा। सभी राज्यों में निश्चित की हुई भूमि की मात्रा समान नहीं है, क्योंकि यह भूमि की उर्वरा शक्ति पर निर्भर करता है।

हमारा जीवन राजनैतिक व आर्थिक क्रांति में से गुजर रहा है। संविधान में भी यह निश्चित कर दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विकास की दृष्टि से समान अधिकार प्राप्त हैं। एक ऐसी समाज की स्थापना हो जहां पर सब का समान रूप से विकास हो और समान अधिकार प्राप्त हों। देशवासियों के सम्मुख दो आदर्श हैं—सामाजिक न्याय तथा चतुर्दिक विकास। दीर्घकालीन भूमि सुधार की व्यवस्था ही राष्ट्र में

(शेष पृष्ठ ४६८ पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारत में जल-मार्ग का विकास

श्री एस० आर० वासुदेव,
निर्देशक, केन्द्रीय जल एवं विद्युत मंत्रालय

विकास की संभावना

देश में जल-मार्ग का काफी विकास किया जा सकता है। नर्मदा, सोन, चम्बल और केन नदियों को बहूद्देशीय योजनाओं से नर्मदा को गंगा से, और बेनगंगा तथा गोदावरी को बहुद्देशीय योजनाओं से नर्मदा को गोदावरी से मिलाया जा सकता है। इसी प्रकार ताप्ती नदी को भी गोदावरी से मिलाया जा सकता है। इन नदियों को नाव चलाने योग्य बनाने के लिए अनेक बांध, नहरें आदि बनाने की जरूरत पड़ेगी। यदि यह सब हो जाय तो देश के विभिन्न क्षेत्रों में जल-मार्ग का जाल बिछ जायेगा और पूर्वी तट को पश्चिमी तट से मिलाया जा सकेगा।

इस समय देश के अन्दर कुल ५,७६० मील में नावें चल सकती हैं। ३,००० मील में नदियों में और बाकी नहरों तथा मालाबार तटवर्ती समुद्री पानी में। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में १,५२२ मील तक स्टीमर चल सकते हैं। शेष में केवल नावें ही चलती हैं।

देश में मुख्यत: गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में ही नावें चलाई जाती हैं। दक्षिण में गोदावरी और कृष्णा, मध्य-भारत में नर्मदा और पश्चिम में ताप्ती में भी नावें चलाई तो जा सकती हैं, परन्तु अभी वहां केवल कुछ ही दूरी तक नावें चलाई जाती हैं और उनका पूरा-पूरा उपयोग नहीं हो पाता। यदि बरसात में पानी जमा करके गर्मियों में उसे छोड़ा जाय तो उन नदियों में नावें चलाई जा सकती हैं।

जिन २,७५० मील लम्बी नहरों और समुद्री पानी में नावें चलती हैं, वहां भी रेलों का जाल फैला देने के कारण नौकानयन की ओर ध्यान कम दिया जाता है।

सिंचाई तथा नाव चलाने योग्य नहरें

पूर्वी तथा पश्चिमी तट के निकट कुछ ऐसी तटवर्ती नहरें हैं, जिनमें समुद्र का पानी आता है और जिनके द्वारा काफी माल का यातायात होता है; जैसे—प० बंगाल में हिजिली ज्वारभाटा नहर, उड़ीसा तटवर्ती नहर, आंध्र प्रदेश और मद्रास में बंकिघम और वेदारण्यन नहरें, तथा पश्चिमी तटवर्ती नहरें और केरल तथा मैसूर में समुद्री जल के खात। ६० मील लम्बी उड़ीसा तटवर्ती नहर को छोड़कर बाकी सभी नहरों का प्रबन्ध राज्य सरकारें करती हैं। इसके अलावा, उड़ीसा में महानदी की नहरें और आंध्र प्रदेश में गोदावरी तथा कृष्णा डेल्टा नहरें आदि कुछ ऐसी नहरें हैं, जो संबंधित राज्यों की तटवर्ती नहरों से मिली हुई हैं। नयी नहरें बनाकर उक्त नहरों को जोड़कर और पुरानी नहरों को सुधार कर पूर्वी तट पर कलकत्ता से कटक होकर मद्रास तक नया जल-मार्ग बनाया जा सकता है। फिर ३०० मील लम्बी पश्चिम तटवर्ती नहरों से मिलाकर इस जल-मार्ग को कुमारी अन्तरीप तक बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह पश्चिम तटवर्ती नहरों और समुद्री खातों को भी नयी नहरें बनाकर मंगलौर तक बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान नहरों को भी सुधार कर जहाज चलाने योग्य बनाया जा सकता है। इस प्रकार यह तटवर्ती जल-मार्ग प० बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और मद्रास की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सभी नदियों को, पूर्वी तट के सभी बन्दरगाहों को और पश्चिमी तट पर मंगलौर तक के बन्दरगाहों को परस्पर मिला देगा। तब यह जल-मार्ग प० बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मद्रास, केरल और मैसूर के प्रमुख व्यापार-केन्द्रों में परस्पर यातायात का बहुत अच्छा साधन हो जाएगा।

बृहत् आयोजना

केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग ने देश में राष्ट्रीय जल-मार्गों के क्रमिक विकास की जांच और अध्ययन के लिए अन्तर्देशीय नौकानयन की एक बृहत् आयोजना तैयार की है।

कुछ मुख्य योजनाएं इस प्रकार हैं :—

१. पश्चिमी तट (अरब सागर) से पूर्वी तट (बंगाल की खाड़ी) तक सीधा जल-मार्ग बनाने के लिए गंगा को नर्मदा से मिलाना।

२. नर्मदा को गोदावरी से मिलाना।

३. ताप्ती को, गोदावरी की सहायक नदी वर्धा द्वारा, गोदावरी से मिलाना।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

४. गंगा को सोन (गंगा की सहायक नदी), रेंड (सोन की सहायक नदी) और हसदो (महानदी की सहायक नदी) द्वारा महानदी से मिलाना।

५. पूर्वी तट पर कलकत्ता से मद्रास तक (कटक होते हुए) अन्तर्राज्यीय जल-मार्ग बनाना और फिर उसे कुमारी अन्तरीप होकर पश्चिमी तट पर केरल के समुद्री खातों और नहरों से मिलाना।

आरम्भिक सर्वेक्षण

केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोगने पूर्व और पश्चिम को बहने वाली नदियों को मिलाने के कुछ प्रस्तावों के बारे में प्रारम्भिक सर्वेक्षण करनेके लिए ८,३०,९५० रु० के व्यय का अनुमान लगाया है। सर्वेक्षण होने के बाद ही अन्तिम योजना बनानेके लिए जांच की जायगी। अतः ये प्रस्ताव अभी अन्तिम नहीं माने जा सकते। सर्वे करने के बाद हो सकता है कि उनमें परिवर्तन करना पड़े। प्रमुख नदियों को जोड़ने और उन्हें नाव चलाने योग्य बनाने के प्रस्तावों का भी आगे अध्ययन किया जाएगा।

योजनायें बनाने के लिए काफी सर्वेक्षण और जांच-पड़ताल की जरूरत है। इन पर काफी रुपया खर्च होगा और व्यय को देखते हुए वे काफी लम्बे समय तक चलेंगी।

पोत व नौकानयन

दूसरी पंचवर्षीय आयोजना में भारत में जहाजरानी के विकास के लिए दो लक्ष्यों को पूरा करना है—पहला, तटीय व्यापार में वृद्धि, जिससे रेलों पर माल की ढुलाई का भार कम हो सके और दूसरा, भारतीय जहाजों के लिए भारत के विदेशी व्यापार में अधिक हिस्सा देना।

इस समय तटीय व्यापार भारतीय जहाजों में शत-प्रतिशत भारतीय कर्मचारियों द्वारा ही चलाया जाता है और संसार के प्रमुख जल-मार्गों पर भारतीय जहाजी कम्पनियों के मालवाही जहाज आते जाते हैं, जो भारत का संसार के सभी भागों में सम्बन्ध जोड़ते हैं।

भारत में वाणिज्य तथा उद्योग के विस्तार के साथ-साथ जहाजों की संख्या में भी वृद्धि हुई। पहली पंचवर्षीय आयोजना के शुरू में भारत के पास ३,९०,७०७ टन के जहाज थे। दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के लिए ९,०१,७०७

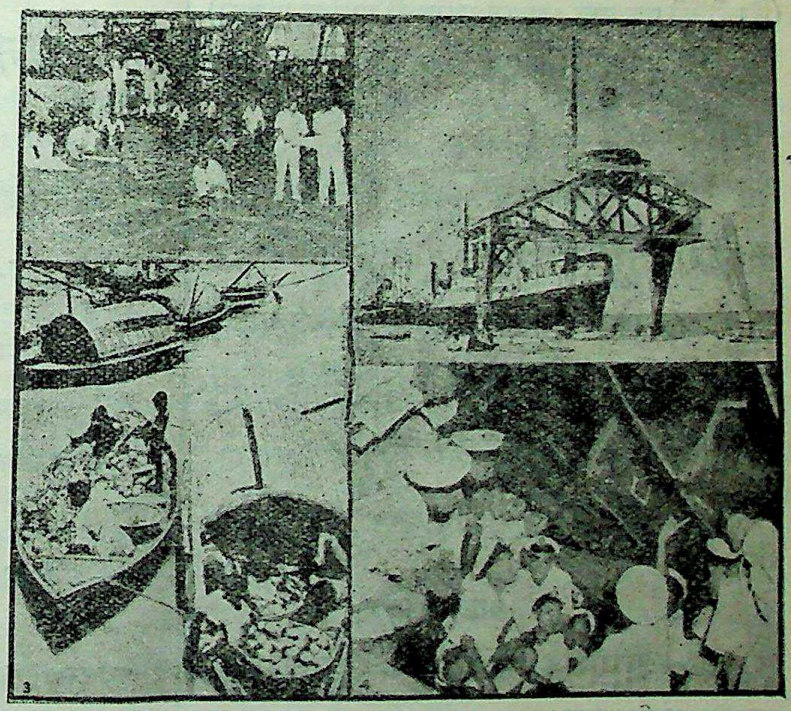

★

चित्र-संख्या १—विशाखापत्तनम के जहाज बनाने के कारखाने का आयोजन और सर्वेक्षण कक्ष। जहाजों के रेखा-चित्र फर्श पर बने हैं।

चित्र-संख्या २—हाल ही में बने कांडला बन्दरगाह के जहाज घाट का एक दृश्य।

चित्र-संख्या ३— मलाबार के एक जलमार्ग में नौकाएं चलती दिखाई दे रही हैं।

चित्र-संख्या ४—प्रशिक्षण पोत 'दफरिन' में नौसैनिक शिक्षार्थी दल एक शिक्षक के साथ।

★

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

टन के जहाजों का लक्ष्य निर्धारित किया गया। अनुमान है कि इस लक्ष्य के पूरा हो जाने पर देश के विदेशी व्यापार का १२ से १५ प्रतिशत तथा सीमावर्ती देशों के साथ ५० प्रतिशत व्यापार भारतीय जहाजों द्वारा होने लगेगा।

भारत में जहाजरानी के विकास के लिए जहाजी कम्पनियों को आर्थिक सहायता देने के अलावा दूसरी पंचवर्षीय आयोजना में बन्दरगाहों के विकास, प्राविधिक कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा विशाखापत्तनम में जहाज बनाने के कारखाने के विस्तार के लिए ४० करोड़ रु० की एक योजना भी शामिल की गयी है।

आयोजना में अन्तर्देशीय जल-परिवहन के विकास के लिए ३ करोड़ रु० की योजनाएं भी शामिल हैं। अनुमान है कि भारत में ५ हजार मील नदी-मार्ग में जहाज चलाये जा सकेंगे।

कुछ महत्वपूर्ण अंक

१. सरकार के विविध और निरन्तर प्रयत्नों के कारण इन सालों में भारतीय जहाजरानी की काफी प्रगति हुई है। महायुद्ध से पहले देश के पास कुल १,२५,००० टन के जहाज थे और अब ५,२०,००० टन के जहाज हैं।

२. महायुद्ध से पहले एक-तिहाई तटीय व्यापार भारतीय जहाजों से होता था अब यह सारा भारतीयों के हाथ में है।

३. लड़ाई से पहले भारत के जहाज जहां अपने देश के तट या बर्मा और लंका से आगे कभी नहीं गये, वहां अब यूरोप, आस्ट्रेलिया, मलाया, पूर्वी एशिया, जापान, ईरान की खाड़ी और पूर्वी अफ्रीका तक हमारे जहाज आते-जाते हैं।

४. देश में, कुल २० लाख टन के जहाज रखने का लक्ष्य है, ताकि सारा तटीय व्यापार और समुद्रपार का ५० प्रतिशत व्यापार अपने जहाजों से हो सके।

——

आपका स्वास्थ्य

(हिन्दी की एक मात्र स्वास्थ्य सम्बन्धी मासिक पत्रिका)

"आपका स्वास्थ्य" आपके परिवार का साथी है।

"आपका स्वास्थ्य" अपने क्षेत्र के कुशल डाक्टरों द्वारा सम्पादित होता है।

"आपका स्वास्थ्य" में अध्यापकों, अभिभावकों, माताओं और देहातों के लिए विशेष लेख प्रकाशित होते हैं।

आज ही ६) रु० वार्षिक मूल्य भेजकर ग्राहक बनिए।

व्यवस्थापक,

आपका स्वास्थ्य—बनारस-१

सरकारी विज्ञापनों के लिए स्वीकृत

राजस्थान शिक्षा विभाग से मंजूरशुदा

सेनानी साप्ताहिक

सम्पादक :—

सुप्रसिद्ध साहित्य सेवी श्री शंभुदयाल सक्सेना

कुछ विशेषताएं—

★ ठोस विचारों और विश्वस्त समाचारों से युक्त

★ प्रान्त का सजग प्रहरी

★ सर्वाधिक लोकप्रिय पत्र

ग्राहक बनिए, विज्ञापन दीजिए, रचनाएं भेजिए

नमूने की प्रति के लिए लिखिए—

व्यवस्थापक, साप्ताहिक सेनानी, बीकानेर

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हमारा सीमेंट उद्योग

श्रीमती शशिमदन माहेश्वरी

भारत का सीमेन्ट उद्योग उत्तरोत्तर उन्नति कर रहा है। प्रथम पंचवर्षीय आयोजना में सीमेन्ट-उत्पादन का लक्ष करीब करीब पूरा हो गया है और आगे भी उन्नति के पूरे पूरे साधन सुलभ हैं।

बड़े पैमाने पर सर्व प्रथम सीमेंट तैयार करने का श्रेय मद्रास को है। सन् १९०४ में सर्व प्रथम मद्रास में "पोर्ट-लैण्ड सीमेन्ट" का निर्माण प्रारम्भ हुआ, परन्तु यह नगण्य था। इसके पश्चात् १९१२-१३ में तीन नये कारखानों की स्थापना यहां पर हुई।

१. "इण्डियन सीमेंट कम्पनी" पोरबन्दर (गुजरात)

२. "कटनी सीमेंट एण्ड इण्डस्ट्रीयल कम्पनी" (मध्यप्रदेश)

३. "बूंदी पोर्ट लैण्ड सीमेंट कम्पनी" (राजस्थान)

सन् १९१४ ई० में भारत प्रतिवर्ष १.८ लाख टन आयात करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता था। महायुद्ध के प्रारम्भ से आयात में कमी आई और सीमेंट उद्योग को विकास के अवसर सुलभ हुए।

प्रथम महायुद्ध

यद्यपि प्रथम महायुद्ध से सीमेंट उद्योग पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, तथापि १९२२३ तक देश में उत्पादन क्षमता ८५००० टन वार्षिक से बढ़कर ५.८ लाख टन वार्षिक तक पहुँच गई। उत्पादन वृद्धि के साथ सीमेंट की मांग भी बढ़ी। फलस्वरूप सीमेंट के कारखानों की संख्या ७ तक पहुँच गई। परन्तु आवश्यक संगठन के अभाव में सीमेंट उद्योग के कदम डगमगाने लगे। महायुद्ध के उत्तरार्ध में सीमेंट का आयात प्रारम्भ हो गया। उक्त कारखानों में से तीन का विलीनीकरण हो गया, जिससे सरकार को २.३ करोड़ रु० की हानि उठानी पड़ी। १९२३-२४ के आस-पास इस उद्योग को भारी संकट का सामना करना पड़ा। विभिन्न प्रमण्डलों में गलाकाट प्रतिस्पर्धा होने लगी। फलतः सीमेंट का मूल्य लागत मूल्य से भी कम हो गया। अतः १९२४ में भारत के सीमेन्ट उद्योगपतियों ने टैरिफ बोर्ड से संरक्षण की प्रार्थना करते हुए मांग की कि सीमेन्ट आयात पर २५ रु० प्रति टन ड्यूटी लगा दी जाये। परन्तु बोर्ड ने इस प्रार्थना को अस्वीकार करते हुए बताया कि सीमेन्ट के मूल्य आन्तरिक प्रतिस्पर्धा के कारण गिरे हुए हैं, अतः आयात माल पर संरक्षण कर की कोई आवश्यकता नहीं है।

उद्योग को इस विषम परिस्थिति से बचाने के लिये स्वर्गीय श्री एफ० ई० दीनशा ने अपने सद् प्रयत्नों से "इण्डिया सीमेन्ट मेन्यूफेक्चरर्स एसोसियेशन" "कंक्रीट एसोसियेशन आफ इण्डिया", एवं "सीमेन्ट मार्केटिंग कम्पनी आफ इण्डिया लि०" की स्थापना क्रमशः सन् १९२६, २७ और ३० में की, फलस्वरूप सीमेंट उद्योग इस भयंकर परिस्थिति से निकल कर उन्नति के मार्ग की ओर अग्रसर हुआ। सन् १९३६ में ११ सीमेन्ट के कारखाने थे, जिनमें से १० प्रमण्डलों ने मिल कर एसोसियेटेड सीमेन्ट कम्पनी लि० का निर्माण किया। इसके प्राथमिक निम्न उद्देश्य थे:—

(अ) सीमेन्ट निर्माण के उत्पादन व्यय में कमी करना।

(ब) उद्योग में आयात किये जाने वाले माल की स्पर्धा की क्षमता हो।

(स) वितरण व विपणन व्यय में कमी करना तथा उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर सीमेन्ट उपलब्ध करना।

उपर्युक्त संगठन का परिणाम यह हुआ कि उत्पादन में वृद्धि होने लगी और १९३९ में एसोसियेटेड सीमेन्ट कम्पनी के अन्तर्गत रहने वालों कारखानों की उत्पादन क्षमता १४.९५ लाख टन तक हो गई।

सन् १९३८ ई० में डालमिया मंडल की स्थापना हुई जो कि एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनी से स्पर्धा करने लगी। उसके द्वारा मूल्यों में इतनी गिरावट लाई गई कि एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनी को उसकी स्पर्धा में कायम रहना दूभर हो गया। परन्तु १९४० में दोनों पक्षों में समझौता हो गया और तबसे निरन्तर सीमेंट उद्योग उन्नति करता आ रहा है। सन् १९४७ तक विभाजन से पूर्व भारतवर्ष में सीमेंट के २३ कारखाने थे और उत्पादन क्षमता २६ लाख टन तक पहुँच गई थी।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

द्वितीय महायुद्ध

इस काल में इस उद्योग को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। इस उद्योग को ऐसे समय में आंतरिक मांग की पूर्ति के अतिरिक्त मध्यपूर्व के देशों को भी सीमेंट उपलब्ध करना आवश्यक था। सरकार को युद्ध प्रयत्नों के लिये विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य के लिये भी सीमेंट की आवश्यकता हुई। अतः सरकार ने ९० प्रतिशत सीमेंट के उत्पादन का भाग अपने लिये सुरक्षित कर लिया। इससे सीमेन्ट का भीषण अभाव प्रतीत होने लगा। उक्त दशा के निवारण के हेतु सरकार ने वितरण व्यवस्था को स्वयं अपने हाथ में ले लिया तथा राशन प्रणाली कायम करदी, परन्तु जनता की मांग पूर्ति न हो सकी। चोर बाजारी व घूसखोरी को काफी प्रोत्साहन मिला। पर इतना अवश्य है कि द्वितीय महायुद्ध ने सीमेंट उद्योग के पैर भली भांति जमा दिये।

स्वतंत्रता से पूर्व १९४७ तक देश में २३ सीमेन्ट के कारखाने थे, जिनमें से ५ पाकिस्तान के हिस्से में चले गये, शेष भारत में ही रहे। आजादी हासिल होने के बाद एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनी व डालमिया मंडल अलग अलग हो गये। देश के विभाजन का इस उद्योग पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। हां, पुनर्वास की समस्या से सीमेन्ट की जरूरत और भी बढ़ी।

सीमेण्ट का मूल्य

पिछले चौदह वर्षों में एक-एक औंस सीमेंट भारत सरकार द्वारा मंजूर किये गये मूल्य पर ही बिका है। बिक्री की मौजूदा कीमत टैरिफ कमीशन की १९५३ की जांच पर आधारित है। एसोसिएटेड सीमेंट कम्पनीज ने दो बार अपनी मर्जी से मूल्य को ढ़ाई-ढ़ाई रुपये प्रति टन घटाने की खुद कार्रवाई की है। यह कार्रवाई संगठन की, जितने सस्ते भाव में हो सके, उतने सस्ते भाव में सीमेंट व उत्पादन और वितरण करने की नीति के मुताबिक ही हुई। निम्नलिखित थोक भावों की तालिका से पता चलता है कि दूसरी उपभोक्ता वस्तुओं की तुलना में सीमेंट की कीमत कितनी कम बढ़ी है :—

थोक भावों का इंडेक्स नम्बर (आधार १९३९ = १००), भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार द्वारा प्रकाशित

जूट उत्पादन	...	...	३८८.०
रुई उत्पादन	...	...	४१९.०
लोहा और इस्पात उत्पादन	...	...	३३०.०
मशीनरी	...	...	४०७.०
गाड़ियां (Vehicles)	...	...	४९५.०
कोयला	...	...	३६२.०
सीमेंट	...	...	२७९.०

इन तुलनाओं के देखते समय यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि "फ्रेट" (यातायात) के भाव या कोयले, जूट के पैकिंग और स्टोर की अनेक वस्तुओं की कीमत पर उद्योग का कोई नियंत्रण नहीं होता, जबकि जितना सीमेंट बिकता है, उसकी कीमत में इन सब चीजों का बहुत बड़ा हिस्सा रहता है। थोक भावों के इंडेक्स (आधार १९३९) से पता चलता है कि जूट की चीजों की कीमत में ३८८ प्रतिशत और कोयले की कीमत में ३६२ प्रतिशत बढ़ती हुई है, जबकि सीमेंट की कीमत में सिर्फ २७९ प्रतिशत। इससे यह बात साबित हो जाती है कि कितनी सावधानी और होशियारी के साथ उत्पादकों ने सीमेंट के वास्तविक उत्पादन मूल्य को दबा कर रखा है। यह सफलता भारत के किसी भी बड़े उद्योग की सफलता के मुकाबले की तो है ही, पूर्णतया विकसित अर्थ-व्यवस्था वाले उच्च कोटि के औद्योगिक देशों की सफलता के भी मुकाबले की है।)

—श्री दाण्डेकर

प्रथम पंचवर्षीय योजना

प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में १५.४ करोड़ रु० के व्यय की व्यवस्था इस उद्योग के विकास के लिये की गई थी। योजना के अन्त तक ४९.३ लाख टन उत्पादन का लक्ष्य था, जिसमें से ४५ लाख टन उत्पादन योजना के अन्त तक होने लगा और कारखानों की संख्या जो कि १९५१ में २२ थी, बढ़कर १९५५ में २७ हो गई। १९५६ तक भारत में २८ कारखाने हो गये। नये बांध निर्माण व

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गृह निर्माण के फलस्वरूप सीमेन्ट की मांग काफी बढ़ी, जिससे उद्योग के विस्तार में आश्चर्यजनक सफलता मिली।

द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना

द्वितीय आयोजना में सीमेंट उद्योग के विकास की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य १६० लाख टन तथा उत्पादन लक्ष्य १३० लाख टन रखा गया है। योजना आयोग ने औद्योगिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सीमेन्ट उद्योग का उत्पादन लक्ष्य इस प्रकार रखा है :—

वर्ष	लाख टन
१९५६-५७	७४.२०
१९५७-५८	८९.२०
१९५८-५९	९४.८०
१९५९-६०	११०.००
१९६०-६१	१३०.००

उक्त आंकड़ों को देखने से हमें सन्तोष अवश्य है परन्तु हम देखते हैं कि योजना आयोग ने जो लक्ष्य रखा है, उस तक पहुंचने में हमें कहां तक सफलता मिली है। १९५६-५७ के रखे गये लक्ष्य से भी हम आज बहुत पीछे हैं।

इस समय देश में जो २८ सीमेंट के कारखाने हैं, इनमें से २ उत्तरप्रदेश और मैसूर की सरकारों के स्वामित्व में हैं। शेष २६ कारखाने निजी उद्योगपतियों के हैं। इन कारखानों की संख्या बिहार में ७, बम्बई में ४, मद्रास में ३, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब प्रत्येक में २ तथा उड़ीसा और केरल प्रत्येक में १, है।

सीमेन्ट उद्योग के विस्तार के विभिन्न कार्यक्रम हमारे सामने हैं:—

वर्ष	कारखानों की संख्या
१९५७	२८
१९५८	२८
१९५९	५५
१९६०	६४

उक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि योजना के अन्त तक कारखानों की संख्या ६४ हो जायगी और देश की बढ़ती हुई मांग को यह उद्योग पूरा करने में सफल होगा।

वर्तमान कारखानों के अतिरिक्त भारत सरकार ने ३१ अन्य सीमेंट के कारखानों की स्थापना करने की योजना स्वीकार कर ली है। इन नये कारखानों की कुल उत्पादन-क्षमता ५६ लाख टन होगी। ये नये कारखाने, ७ आंध्र में, ७ बम्बई में, राजस्थान व मध्यप्रदेश प्रत्येक में ३, आसाम व पश्चिम बंगाल प्रत्येक में २, तथा उत्तरप्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पांडिचेरी और मैसूर प्रत्येक में १, स्थापित किये जायेंगे। विस्तार योजना के अनुसार इनकी क्षमता ४४ लाख टन बढ़ जाएगी।

सीमेंट उद्योग में इस समय सीधे ३०,००० व्यक्तियों को काम मिला हुआ है। इस उद्योग में लगभग ४० करोड़ रु० की पूंजी लगी हुई है। उद्योग के और विस्तार के कारण, इसमें ५० से ६० करोड़ रु० की और पूंजी लगेगी तथा ५० से ५५ हजार और मजदूरों को काम मिल सकेगा।

सीमेंट उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता से काम करते हुए उत्पादन बढ़ाये, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा चुके हैं। सीमेंट-निर्माण की योजनाओं की स्वीकृति के समय, प्रादेशिक वितरण व रेल के यातायात की सीमा का ध्यान रखा गया है।

भारी मशीनें बनानेके उद्योगका विकास

देश में भारी मशीनें बनाने के उद्योग के विकास के लिए भारत सरकार ने सिद्धांत रूप में पांच बड़े कारखाने खोलने का निश्चय किया है। प्रस्तावित ५ कारखाने ये हैं: भारी मशीनें बनाने का एक कारखाना; एक फाउन्डरी और फोर्जशाप; एक बड़ा मशीन टूल कारखाना; भारी ढांचे (गाटर आदि), पत्तर और विशाल पात्र (टंकियां आदि) बनाने का कारखाना; और कोयले की खुदाई की मशीनें आदि बनाने का कारखाना।

सरकार भारी मशीनें बनाने वाले उद्योग के विकास को कितना महत्व देती है। इस दृष्टि से निम्नलिखित आंकड़े उल्लेखनीय हैं —

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

	देश में मशीनों का उत्पादन	आयात	
१९५१	५ करोड़ से १० करोड़ रु० (अनुमानित)		
१९५४	१९ करोड़ रु०	१९५४-५५	८३ करोड़ रु.
१९५५	२३ करोड़ रु०	१९५५-५६	११८ करोड़ रु.
१९५६	३० करोड़ रु०	१९५६-५७ (अप्रैल-दिसम्बर)	११४ करोड़ रु.

अनुमान है कि १९६०-६१ तक देश को २५० से ३०० करोड़ रु० सालाना तक की मशीनों की आवश्यकता होगी, जबकि दूसरी तरफ १९६०-६१ में कुल ९० से १०० करोड़ रु० तक सालाना की मशीनों का उत्पादन होने का अनुमान है। इस प्रकार १५० से २०० करोड़ रु० तक की मशीनों की कमी रहेगी।

विभाजन के समय देश में बहुत कम मशीनें बनायी जाती थीं। १९५५-५६ में ३० करोड़ रु० की मशीनें बनायी गयीं। लेकिन, अब तक जो मशीनें बनायी गयी हैं या बनायी जा रही है, वे छोटी हैं और भारी मशीनें बनाने का काम अभी शुरू करना है। भारी मशीनें बनाने के सम्बन्ध में उन्नत और अनुभवी देशों की राय जानने के लिए भारत सरकार ने पिछले साल रूस और ब्रिटेन के दो विशेषज्ञ दलों को बुलाया था। इन दोनों दलों ने देश की वर्तमान उत्पादन-क्षमता और भावी आवश्यकताओं का अध्ययन करके सरकार को अपनी रिपोर्ट दी है। सरकार ने इन रिपोर्टों पर बड़े गौर से विचार करने के बाद उक्त कारखाने खोलने का निश्चय किया है।

भारी मशीनें बनाने का कारखाना

शुरू में इस कारखाने में करीब ४५ हजार टन मशीनें बनायी जाएंगी। बाद में इसका उत्पादन धीरे-धीरे ८०,००० टन सालाना तक बढ़ाया जायगा। शुरू में इस कारखाने में कोयला-भट्टियां, इस्पात पिघलाने वाली भट्टियां, खनिज धातुओं को कूटने-पीसने वाली मशीनें, क्रेन, रोलिंग मिलें आदि बनायी जाएंगी।

कार्यसंचालन-पूंजी और मजदूर-बस्ती आदि के खर्च के अलावा इस कारखाने पर शुरू में करीब २० करोड़ रु० खर्च होगा। धीरे-धीरे इस कारखाने का विस्तार किया जायगा। और उत्पादन १,६५,००० टन सालाना तक बढ़ा दिया गया।

फाउंडरी और फोर्ज शाप

कार्यसंचालन-पूंजी, मजदूर-बस्ती की लागत आदि को छोड़कर इस पर भी करीब २० करोड़ रु० खर्च होने का अनुमान है। ऐसी व्यवस्था की जायगी कि बाद में इस कारखाने का उत्पादन बढ़ाकर दुगना किया जा सके।

प्रस्तावित अन्य दो कारखानों की अनुमानित लागत और उत्पादन-शक्ति इस प्रकार होगी :—

	उत्पादन-शक्ति	अनुमित लागत
भारी मशीन टूल कारखाना	एक पारी में ३५० से ४५०० टन मशीन टूल सालाना।	५ करोड़ रु०
भारी ढांचे बनाने का कारखाना और पत्तर और विशाल पात्र बनाने का कारखाना	एक पारी में १० हजार से १२ हजार टन सालाना एक पारी में १० हजार से १२ हजार टन सालाना।	६ करोड़ ६० लाख रु०

इन अनुमानों में कार्यसंचालन-पूंजी, मजदूर-बस्तियों की लागत आदि शामिल नहीं है।

कोयले की खुदाई की मशीनें बनानेका कारखाना

यह कारखाना कोयले की खुदाई की प्रति वर्ष ३०,००० टन मशीनें आदि बनायेगा। इस पर करीब १३ करोड़ रु० खर्च आने का अनुमान है। इस खर्च में कार्यसंचालन-पूंजी, मजदूर-बस्ती की लागत आदि शामिल नहीं है। इस कारखाने की अपनी फाउन्डरी और फोर्ज शाप होगी।

भारी मशीनें बनाने वाले उपर्युक्त पांच कारखाने देश में भारी मशीन-उद्योग को मजबूती से जमा देंगे और तेज रफ्तार से उद्योगीकरण का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सर्वोदय का कल्याण-मार्ग

(श्री जयप्रकाश नारायण)

सर्वोदय एक प्रगतिशील, विकासशील विचार है। यह कोई रूढ़िवादी विचार नहीं है। इसका आधार सत्य है। अतः ज्यों-ज्यों सत्य का दर्शन होता जायेगा, त्यों-त्यों इस विचार में विकास होता जायगा। सर्वोदय का मूल तत्त्व है, "सर्व-कल्याण की भावना।" कुछ लोगों का हित और कुछ का अहित चाहने वाले विचार से संघर्ष पैदा होता है। सर्वोदय का लक्ष्य सर्व-हित-साधन ही है और वह सामाजिक विषमता को जड़-मूल से नष्ट भी करना चाहता है। सामाजिक विषमता से उत्पन्न दुःख-संक्रामक रोग की तरह कब किसको पकड़ लेगा, यह कहा नहीं जा सकता, इसलिए सर्वोदय का आदर्श ही श्रेयस्कर है। इस आदर्श की प्राप्ति हिंसा से संभव नहीं है, क्योंकि सर्वोदय का आधार है सत्य। और सत्य के साथ शिव जुड़ा हुआ है, जो एक मंगलवाचक शब्द है। अतएव सर्वोदय के आदर्श तक पहुँचने के लिए हिंसा से, जो एक अमंगलवाचक शब्द है, अलग ही रहना होगा; हिंसा की जगह अहिंसा का ही आश्रय लेना होगा और प्रेम की स्थापना करनी होगी।

आज हर देश में पूंजीवाद मिटाने का प्रयोग चल रहा है। कुछ देशों में यह प्रयोग वर्ग-संघर्ष के रूप में हुआ, पर वह असफल हुआ। उससे पूंजीवाद नहीं मिटा, सामाजिक विषमता कायम रही, यह सब जानते हैं। रूस में इस प्रयोग का नतीजा यह हुआ कि आज वहां ज़ार के जमाने से भी कम स्वतंत्रता है। ऐसा इसलिए हुआ कि वह प्रयोग हिंसा पर आधारित था। आर्थिक विषमता भी वहां आज कायम है। रूस के उपप्रधान मंत्री ने अपने दिल्ली-आगमन के अवसर पर खुद स्वीकार किया था कि वहां लोगों की आमदनी में १ से ४० तक का फर्क है और यह फर्क श्रमिक वर्ग में नहीं, अनुत्पादक वर्ग में ही है। रूस के क्रान्तिकारियों ने समाज-परिवर्तन के लिए हिंसात्मक साधन अपनाये, यही इसका कारण है। हिंसा से समाज में मूल्य-परिवर्तन हो नहीं सकता और बिना मूल्य-परिवर्तन के समाज-परिवर्तन भी नहीं हो सकता। इसलिए गांधीजी ने समाज-परिवर्तन के लिए वैचारिक क्रान्ति का मार्ग बताया।

पूंजीवादी समाज में व्यक्तिगत स्वार्थ और संग्रह के मूल्य प्रतिष्ठित होते हैं। गरीब और अमीर, दोनों इन सामाजिक मूल्यों को मान्यता देते हैं। अतः पूंजीवाद मिटाने के लिए इन मूल्यों को मिटाना जरूरी है। यह हिंसा या कानून से नहीं, प्रेमपूर्वक, विचार-परिवर्तन से ही संभव हो सकता है। विचार-परिवर्तन के द्वारा जीवन-परिवर्तन और जीवन-परिवर्तन के द्वारा समाज-परिवर्तन, यही सर्वोदय का मार्ग है। इस मार्ग पर अमल करने के लिए गांधीजी ने सत्याग्रह का विज्ञान हमारे समक्ष रखा है। आज विनोबा जी उन्हीं के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। सम्पत्ति समाज की है, यह विचार जनता को समझाने के लिए और इस पर उसके द्वारा आंशिक रूप से अमल कराने के लिए उन्होंने भूदान-आन्दोलन चलाया। अब ग्रामदान-आन्दोलन के मार्फत संपत्ति-विसर्जन का संपूर्ण विचार लोगों के सामने वे रख रहे हैं।

—

ट्रैक्टर से बैल हजार नियामत

भारतवर्ष में बैल का स्थान बड़े ही महत्व का है। खेत पर जो कोई काम जल्द या धीरे-धीरे किया जाता है, वह सारा काम, कच्ची या पक्की सड़कों पर गाड़ी खींचने का काम, और खाद देने का काम, ऐसे सभी काम बैलों द्वारा होते हैं। अर्थात् किसान के लिए किसानी के हर काम और स्थान में बैल से मदद लेना जरूरी है।

खेती की दृष्टि से खेत जोतना तथा खाद देना, ये दो महत्त्वपूर्ण कार्य हैं। कोई भी यंत्र ये दोनों काम नहीं कर सकते। कैसी ही पथरीली जमीन हो, बैल खेत जोत सकते हैं। कैसी ही पहाड़ी जमीन हो, बैल ऊपर नीचे आ जा सकते हैं। पेट्रोल से चलने वाले यन्त्र के लिए यह सम्भव नहीं। वही बैल हल चला सकता है, वही बोझ और गाड़ी खींच सकता है, लकड़ी आदि ढोकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचा सकता है; पर हम छोटे से छोटा इंजिन लें तो वह इतने अनेक प्रकार के काम नहीं कर सकता। एक विशेष बात यह है कि एक नियत-शक्ति के इंजन से आवश्यकता पड़ने पर उस नियत-शक्ति से अधिक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

काम नहीं लिया जा सकता, पर मौका पड़ने पर बैलों से उनकी सामान्य शक्ति से डेढ़ गुना काम लिया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त बैल से खाद भी मिलती है। भारतवर्ष में खेती का सारा दारोमदार खाद पर ही है, पर किसी यंत्र से खाद नहीं मिल सकती। भारतवर्ष उष्ण कटिबन्ध के समीप का देश है, अतः यहां का तापमान ११८ डिग्री तक बढ़ सकता है। उष्णता के कारण जमीन के बहुत से प्राणिजन्य तत्त्व नष्ट हो जाते हैं। अतः जिस अनुपात में बाहर से इन तत्वों को जमीन में पहुँचाया जायेगा, उसी अनुपात में फसल भी अच्छी या खराब होगी। कारण इस प्रकार से वनस्पतियों की वृद्धि के लिए आवश्यक नाइट्रोजन ग्रहण करने योग्य रूप में मिल जाता है। इन प्राणिजन्य तत्त्वों से जमीन की सच्छिद्रता बढ़ती है, जिससे वह उचित परिमाण में (नमी) एवं वायु भी ग्रहण कर सकती है। नाइट्रोजन (नमी) और हवा के योग्य परिमाण पर ही वनस्पतियों की वृद्धि निर्भर है। यदि ये तीन बातें न हों तो कितनी भी खाद डाली जाय, उससे कोई लाभ न होगा। भारतवर्ष की परीस्थिति में गोबर की खाद ही अत्यन्त महत्वपूर्ण है। खेती की पैदावार भी इसी पर पूर्णतया निर्भर है। कोई भी यन्त्र ऐसी खाद उपलब्ध नहीं करा सकता, यह बात सूर्य प्रकाश के समान स्पष्ट है।

कहा जा सकता है कि जब गाय या बैल बूढ़े हो जाते हैं, तब तो वे किसी काम के नहीं रहते। न तो बूढ़ी गाय ब्या सकती हैं, न बूढ़ा बैल हल जोत सकता है। ऐसी हालत में उनको पालने का खर्च तो व्यर्थ ही जाता है। बात यह भी ठीक नहीं है। बूढ़े गाय-बैल भी कुछ न कुछ काम करते ही हैं।

बूढ़े गाय-बैल न ब्याने और न हल जोतने के काम के हैं, यह सही है। पर वह खा-पी कर गोबर करते ही हैं, पेशाब करते ही हैं। उनका गोबर और पेशाब करना क्या कोई लाभ नहीं है? हमारे खेतों के लिए खाद की बहुत जरूरत है। बाजार से नमक जैसी नकली खाद बहुत ज्यादा दाम देकर लोग लाते हैं और अपने खेतों में देते हैं। फिर भी वह नकली खाद गोबर, गोमूत की असली खाद जैसी बढ़िया नहीं होती। ऐसी हालत में बूढ़े गाय-बैलों को खिलाने से उनकी खाद से दाम वसूल हो जाता है।

काम करने वाले बैल या दूध देने वाली गाय को जैसा पौष्टिक चारा देना चाहिए, बूढ़े पशु को वैसा देने की जरूरत नहीं। बूढ़े पशु को तो बस वही चारा दिया जा सकता है, जिससे उसका पेट अच्छी तरह से भर जाये और वह कमजोर होकर बेमौत मर न जाये।

★

योजना से मेरा मतभेद

जो प्लानिंग आज हुआ है, उससे बाबा के प्लानिंग का ढंग दूसरा ही है। उनका ढंग नैशनलाइज्ड प्लानिंग का है और दिल्ली में योजना बनती है, सारे हिन्दुस्तान की। बाबा चाहता है, गांव-गांव में योजना बने। गांव वाले ही योजना बनायेंगे और अपनी जमीन भी बांट लेंगे। दो साल का अनाज वे गांव में रखेंगे। क्या-क्या धंधे खड़े करने हैं, यह गांव वाले सोचेंगे। गांव वाले कहें कि गांव की योजना हम बनायेंगे। गांव वाले ही ग्रामसभा बनायेंगे। फिर ऐसे गांवों को जोड़ने वाली सैंट्रल गवर्नमेंट है। यह है बाबा का विचार। आज जैसा चल रहा है, उससे यह भिन्न है। इसलिए हमने ग्रामदान चलाया है। इसमें सारी जमीन गांव की होगी और ग्राम अपनी योजना करेगा। जो मदद देनी है, वह सरकार दे सकती है, परन्तु गांव वाले अपनी शक्ति से ही काम करेंगे।

—विनोबा

★

सहकारी खेती में बल प्रयोग

सहकारी खेती ही सर्वत्र हो, इस विचार से आज हम इतनी बुरी तरह भर गये हैं कि हमने अपनी तमाम पुरानी पद्धतियों तक से विश्वास खो दिया है। स्वभावतः इस दृष्टि से ग्रामदानी गांवों के प्रति कुछ आशाएं की जा रही हैं, सहानुभूति भी प्रकट हो रही है। लेकिन निजी स्वामित्व के विसर्जन के इस आंदोलन के प्रति जो पूर्वग्रह चला आ रहा है, उसने तो इस नयी सहानुभूति के बदले अधिक ही नुकसान पहुँचाया है। ऐसी हालत में अधिकारी-वर्ग सहकार के लिए गांव वालों को कैसे प्रेरित करेंगे? उड़ीसा की ही मिसाल लीजिये, जहां ग्रामदानी गांव आज करीब

[सम्पादक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

१७६२ हो गये हैं। पर जिले के कोआपरेटिव विभाग के द्वारा यहां के तमाम ग्रामदानी गांवों को ऋण देने से इस बिना पर इनकार कर दिया जाता है कि चूंकि इन गांवों में भूमि की निजी मालकियत समाप्त हो चुकी है, इसलिए ऐसी कोई सिक्युरिटी नहीं है, जिसके आधार पर ऋण दिया जा सके।

साहूकारों ने भी जब देखा कि अपनी सैंकड़ों सालों की शोषण-परम्परा खत्म हो रही है, तो वे भी इसी प्रकार बर्ताव कर रहे हैं। इस तरह समाज और शासन के संबंधित-स्वार्थ (वेस्टेड इन्टरेस्ट) वाले ग्रामदानी गांवों के लोगों को मानों एक तरह से उस अच्छी चीज की सजा ही दे रहे हैं, जो उन्होंने स्वेच्छा से की है। ग्रामदान संमत नहीं हुआ है, इसलिए सम्बन्धित स्वार्थ वाले (इंटरेस्टेड पार्टीज) रेवेन्यू आदि के बारे में भी लगातार बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। यहां तक कि ग्रामदानी गांवों के सैंकड़ों ग्रामीणों पर, साहूकारों और पुलिस के मेल के कारण, मुकदमे भी चलाये जा रहे हैं। इंडियन पीनल कोड के सेक्शन १०७ और १५७ का निर्लज्जतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है, जब कि मामला सौ प्रतिशत सिविल रहता है। दुर्भाग्य यह है कि अदालत में गरीब आदिवासियों के मुकाबले आदिवासियों के शोषक-साहूकारों का ही सरकार द्वारा बचाव होता है।

—ग्रामदान, उड़ीसा

विकेन्द्रीकरण

"केन्द्रीकरण का अवश्यम्भावी परिणाम समता और स्वाधीनता में बाधा तथा हिंसा ही है। इसलिए गांधी जी मानते थे कि सभी आर्थिक, राजनैतिक तथा दूसरे क्रिया-कलाप, जहां तक हो सके, विकेन्द्रित ही किये जायें। पर यदि किसी विशेष प्रकार के उत्पादन में केन्द्रीकरण अपरिहार्य मालूम हो, तो उसे आवश्यक बुराई समझ उचित नियंत्रण के साथ स्वीकार करना चाहिए, जिससे कि यह भरोसा रहे कि ऐसे उत्पादन से जहां तक सम्भव है, सर्व-सामान्य कल्याण और सार्वजनिक उद्देश्य पूरा होगा।

"गांधीजी ने यह भी सीख दी कि केन्द्रित उत्पादन का अनिवार्य परिणाम आवश्यकताओं की अमर्यादित वृद्धि है। फलस्वरूप उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निरन्तर व्यग्रता रहती है। उन्होंने दिखा दिया कि ऐसे समाज में शान्ति, परस्पर सद्भावना और सहयोग नहीं हो सकता। इसलिए उनका उपदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकता तो पूरी होनी ही चाहिए, पर सदा वर्धमान मौलिक आवश्यकताएं मानव-जीवन और सभ्यता का लक्ष्य नहीं मानी जाये। इसलिए मुख्य रूप से निजी या स्थानीय उपयोग के लिए चलाये जाने वाले छोटे-छोटे विकेन्द्रित उद्योगों को वे अपनी कल्पना के अहिंसक, स्वाधीन समाज के लिए सबसे उपयुक्त आर्थिक ढांचा मानते थे।"

—बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ के प्रस्ताव में से

पूंजीवाद से मुक्ति

रचनात्मक कार्यकर्त्ताओं में आज घोर निष्क्रियता आ गयी है, जिसे शीघ्र ही दूर किया जाना चाहिए। हमें आम जनता में जागृति लानी है; उनके दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन लाना है; सामाजिक मान्यताओं को हमें बदलना है, आम जनता के हृदय व दिमाग का परिवर्तन करना है। पूंजीवादी तत्त्वों के प्रभुत्व को समाप्त करने का सबसे आसान तरीका यह है कि उन पर बिल्कुल निर्भर न रहा जाये, उनका बिल्कुल बहिष्कार किया जाये और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपनी उत्पादित वस्तुओं से की जाय।

—प्यारेलाल नैयर

★

असंग्रही समाज का अर्थ !

लोग कहते हैं कि सारी दुनिया को ही यह शख्स 'बाबा' बनाने निकला है। लेकिन आक्षेप कर वाले लोग 'असंग्रही समाज' का अर्थ ही नहीं समझे हैं। बाबा के असंग्रही समाज के पांच लक्षण हैं :

(१) समाज में प्राचुर्य रहेगा, लक्ष्मी विपुल रहेगी।

(२) लक्ष्मी का समान विभाजन, वितरण होगा।

(३) शराब, सिगरेट आदि निरर्थक चीजों का संग्रह नहीं रहेगा।

(४) उपयुक्त संग्रह रहेगा और वह क्रम इस तरह है :—उत्तम अन्न, उत्तम कपड़ा, उत्तम घर, उत्तम खेती के औजार और मनोरंजन के उत्तम साधन।

(५) पैसों का संग्रह कम-से-कम रहेगा।

असंग्रही समाज का यह चित्र देख कर आप आशा महसूस करते हैं या निराशा, देख लीजिये।

—विनोबा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नया सामयिक साहित्य

भूदान गंगा—आचार्य विनोबा। प्रकाशक—अ० भा० सर्व सेवा संघ प्रकाशन, राजघाट, बाराणसी। मूल्य १.५० रु.

समय-समय पर भूदान-यात्रा के प्रसंग में दिये गये आचार्य विनोबा के भाषणों के संग्रह सर्व सेवा संघ की ओर से भूदान गंगा के नाम से प्रकाशित होते रहते हैं। इस दिशा में यह चौथा संग्रह है। ये सभी भाषण यद्यपि भूदान यात्रा के सम्बन्ध में दिये हैं, तथापि उनका क्षेत्र वस्तुतः सर्वोदय-अर्थशास्त्र के विविध पहलुओं तक व्यापक रहता है। आज इस विषय पर उन जैसा कोई आचार्य नहीं। देश के सामने आने वाले प्रायः सभी आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक प्रश्नों पर उनके विचार प्रामाणिक रूप से भूदान गंगा में मिल सकते हैं। विचार-दर्शन की दृष्टि से भी यह भाषण उत्कृष्ट कोटि के हैं।

✶

सर्वोदय संयोजन—प्रकाशक वही। मूल्य १)

सर्वोदय अर्थशास्त्र की अपनी एक विचारधारा है। वह आधुनिक अर्थशास्त्रको अनर्थ शास्त्र के नाम से देखती है, किन्तु सर्वोदय अर्थ शास्त्र के चिन्तकों को सिद्ध करना है कि वे केवल ऊंचे आदर्श की बात नहीं करते, वे अपने अपने विचारों को व्यावहारिक रूप देकर देश की वर्तमान समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। इस दिशा में किया गया सुन्दर प्रयत्न इस पुस्तक में पढ़ने को मिलेगा। सर्वोदय दृष्टि से आज देश का आर्थिक विकास कैसे किया जाय, इसकी क्रमबद्ध योजना का एक संक्षिप्त प्रारूप इसमें प्रस्तुत किया गया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का एक प्रकार से इसमें विकल्प प्रस्तुत किया गया है। सत्ता व उद्योग का विकेन्द्रीकरण इस योजना का आधारभूत सिद्धान्त है। आज बड़ी-बड़ी यंत्रमय योजनाएं जहां विराट् धनराशि की अपेक्षा रखती हैं, वहां वे निस्संदेह सत्ता और उद्योग के घोर केन्द्रीकरण की ओर ले जाती हैं। सर्वोदय योजना में ग्राम सबसे प्रमुख इकाई है, जिसका स्वावलम्बन की दृष्टि से विकास करना है। ग्राम को स्वावलम्बी इकाई मानकर बनाई नई योजना के लक्ष्य, भूमि-स्वामित्व, पशुपालन, उद्योग, यंत्रशक्ति, बैंक, सिक्का, व्यापार, यातायात, कर-पद्धति, योजना के साधन आदि सभी आवश्यक प्रश्नों पर विचार किया गया है। इस समस्त विचारधारा की दृष्टि क्रान्तिमूलक है, जिसमें आज के शिक्षित समाज की अधिकांश मान्यताओं को मानने से इन्कार कर दिया गया है। स्वावलम्बन का सिद्धान्त व्यापार की आवश्यकता को बहुत कम कर देगा। नगरों के बढ़ते हुए प्रभाव को समाप्त करना भी इस योजना का उद्देश्य है। परन्तु समस्त पुस्तक को ध्यान से पढ़ने के बाद भी यह शंका रह जाती है कि आज के युग में, जैसा भी मानव और समाज है, उसे देखते हुए क्या यह योजना सर्वांशतः व्यावहारिक हो सकती है? मानव, समाज, वर्तमान संस्कृति और जीवन के वर्तमान आदर्शों को बदल देने की कल्पना ही आदर्शमात्र प्रतीत होती है, फिर भी इस संयोजन का एक महत्व है। उसके अनेक अंशों का दूसरी पंचवर्षीय विकास योजना के साथ सुन्दर समन्वय किया जा सकता है और वह निस्संदेह लाभकारी भी होगा।

✶

मेरा धर्म—लेखक—श्री प्रियव्रत वेदवाचस्पति। प्रकाशक गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार। मूल्य ७)

गुरुकुल कांगड़ी विश्व विद्यालय के आचार्य श्री प्रियव्रत वेदवाचस्पति आर्यसमाज के उन विद्वानों में एक हैं, जिन्होंने वैदिक साहित्य का अच्छा अध्ययन किया है। वेदोद्यान के फूल और वेद का राष्ट्रीय गीत वे पहले लिख चुके हैं, जिनका संक्षिप्त परिचय इस स्तम्भ में पहले दिया जा चुका है। प्रस्तुत पुस्तक में उनके विविध समयों पर दिये गये इन नौ भाषणों का संग्रह किया गया है: स्त्रियों की स्थिति, गोपालन, समाज व्यवस्था, राष्ट्रोन्नति, उपासना, मांस-भक्षण, ब्रह्मचर्य, वेद और अन्य धर्म तथा इलहाम। इन सब विषयों पर वेद का संदेश और दर्शन क्या है, यह इन सब भाषणों में बताया गया है। प्रत्येक भाषण में पूर्वपक्ष या वैदिक धर्म पर किये जाने वाले आरोपों का उल्लेख कर उनका समाधान किया गया है। लेखक की शैली लेखों में विद्वत्तापूर्ण तुलनात्मक अध्ययन की है, जो विद्वत्समाज को विशेष रूप से आकृष्ट कर सकती है और उन्हें चिन्तन के लिए गंभीर विचार-

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सामग्री देती है। लेखक ने विविध प्रश्नों पर आधुनिक साहित्य और विचार-दर्शन की विद्वत्तापूर्ण आलोचना की है, जो उनके विस्तृत अध्ययन का सूचक है।

आज के युग में जब अपने धर्म ग्रन्थों का अध्ययन भी विदेशी विद्वानों के चश्मे से करते हैं, यह विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ बहुत से भ्रमों का निरसन करने में सहायक सिद्ध होगा, ऐसी आशा करनी चाहिए। आज स्वतन्त्र भारत को जिस संस्कृति का निर्माण करना है, उसका आधार पुष्ट भारतीय संस्कृति व धर्म की परम्परा होनी चाहिए, न कि विदेशी चिन्तनधारा। इस दृष्टि से भी इस पुस्तक का अध्ययन लाभकारी होगा।

★

मानस हंस—ले० श्री राजेन्द्र शर्मा। प्रकाशक—भारती साहित्य मंदिर, फव्वारा दिल्ली। मूल्य ३)

आज हमारे अधिकांश कहानी साहित्य में केवल प्रेम, शृंगार या आर्थिक विषमता की चर्चा ही रहती है, राष्ट्र निर्माण या चरित्र-निर्माण को हम भूल गये हैं। लेखक ने पुराणों, उपनिषदों आदि से धार्मिक आख्यानों का संग्रह कर और उन्हें नये रूप में प्रस्तुत कर बड़ी सेवा की है। सभी कथानक नैतिकता और आध्यात्मिकता का संदेश देते हैं। त्याग, सेवा, श्रद्धा, चरित्र की दृढ़ता आदि गुण राष्ट्र-निर्माण के लिए आर्थिक उन्नति और पंचवर्षीय योजना से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं, जिनकी राष्ट्र में घोर उपेक्षा हो रही है। इस तुच्छ दृष्टि से हम ऐसे साहित्य का विशेष स्वागत करना चाहते हैं।

★

सिगरेट के टुकड़े—ले० श्रीमती रजनी पनिकर। प्रकाशक—शारदा मन्दिर, नई सड़क, दिल्ली। मूल्य ३)

प्रस्तुत पुस्तक में लेखिका की सोलह कहानियों का संग्रह है। लेखिका कहानी लिखने में कुशल हैं। नई पीढ़ी, यह पत्र, आप ! तुम !!, सिगरेट के टुकड़े, सातवीं बहन, मूर्तियां सुन्दर हैं, रंजना और रमन बहुत सुन्दर लगीं, टैकनीक, भावना और विचार सभी दृष्टियों से उत्कृष्ट हैं। आज की शिक्षित तेजस्वी युवतियों का नई पीढ़ी में उज्ज्वल पक्ष है, तो आप तुम, में उसका कृष्ण पक्ष प्रकट हुवा है। भाषा में प्रवाह है और है सजीवता। यह पत्र नारी के भावुक हृदय को व्यक्त करता है। मूर्तियां में भी नारी के हृदय को छुआ गया है।

"आप तो मेरे नाम से सम्पदा भेजना शुरू करदें ?"

अर्थशास्त्र के एक विद्यार्थी का पत्र

माननीय महोदय,

यों कालेज के वाचनालय में सम्पदा आती है, पर उससे मुझे बहुत लाभ नहीं होता, क्योंकि मेरे कुछ सहपाठी सम्पदा के आते ही उस पर इतना झपटते हैं कि पढ़ने को ही नहीं मिलती। दो चार दिनों में ही कुछ चालाक लड़के उसके उपयोगी लेख फाड़ कर ले जाने लगते हैं और अन्त में तो टाइटिल व विज्ञापनों के ही पृष्ठ रह जाते हैं। इसलिए मेरे नाम से निम्न लिखित पते पर आप सम्पदा भेजना शुरू करदें।

आपका—
विजय ३रा वर्ष

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उत्पादकता क्या है?

जो सामान बने और जितना काम हो, उसके और उत्पादन में काम लाए गए आवश्यक साधनों के अनुपात को उत्पादकता कहते हैं। साधनों में श्रम-शक्ति, बिजली, माल आदि शामिल है।

उत्पादकता में वृद्धि का अर्थ है—उत्पादनके विभिन्न साधनों के उपयोग का अच्छा तरीका ढूंढना, ताकि कम से कम खर्च में अधिक से अधिक सामान तैयार किया जा सके। विभिन्न कार्यों में अच्छे तरीके तथा टैक्नीक का प्रयोग करने से ही उत्पादकता बढ़ेगी। इनमें से कुछ तरीके और टैक्नीक इस प्रकार हैं :—

१. प्रत्येक काम के बारे में यह पता चलाना कि उसको करने वाले व्यक्ति में कौन से गुण होने आवश्यक हैं ताकि प्रत्येक काम के लिए उपयुक्त व्यक्ति को चुना जा सके।

२. काम करनेके अच्छे, सरल, सुरक्षित और शीघ्रतर तरीके निकालने पर ध्यान देना।

३. कर्मचारियों को काम सिखाना।

४. यह स्मरण रखना कि हर काम हंसी-खुशी से स्वास्थ्यप्रद वातावरण में और अधिक से अधिक संतोष-जनक ढंग से किया जा सकता है।

५. काम को इस प्रकार संगठित करना, ताकि उसमें कम से कम अड़चनें आएं।

६. उत्पादन इस प्रकार करना कि उसमें कम से कम सामान की जरूरत पड़े।

७. ऐसे कच्चे माल की खोज करना जो कम खर्च हो और माल वैसा ही तैयार हो।

८. कच्चे माल की फजूल खर्ची के कारणों का पता लगाना और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना।

९. उपलब्ध मशीनों को प्रयोग करने का अच्छा तरीका निकालना और उसकी हिफाजत करना, ताकि उससे अधिक उत्पादन हो और वह काफी समय तक चल सके।

१०. उत्पादकता बढ़ाने के लिए मशीनें प्राप्त करना।

११. सभी श्रेणी के कर्मचारियों को अपना काम अधिक परिश्रम से करने के लिए उचित प्रोत्साहन देना और इसके लिए अच्छे और आसान तरीके ढूंढना।

आज जब समस्त राष्ट्र उत्पादन वृद्धि में लगा हुआ है, तब उत्पादकता (प्रोडक्टिविटी) शब्द बार बार प्रयुक्त होता है। औद्योगिकों व अर्थशास्त्रियों की सम्मति में इस शब्द का विवेचन अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा:—

उत्पादकता के बढ़ने से निम्नलिखित लाभ होते हैं—:

(१) राष्ट्रीय सम्पत्ति, प्रति व्यक्ति आय और रहन सहन के स्तर में वृद्धि।

(२) उत्पादन में कम खर्च।

(३) लाभ में वृद्धि होने से उद्योग में पूंजी लगाने की प्रेरणा।

उत्पादकता में वृद्धि अपने आप में साध्य नहीं है, बल्कि इससे रहन-सहन का स्तर बढ़ता है और सामाजिक उन्नति होती है। उत्पादकता में वृद्धि का एक तत्काल प्रभाव होता है उत्पादन के खर्च में कमी। इससे बाजार में चीजें सस्ती हो जाती हैं और उत्पादक को अधिक लाभ होता है।

कभी कभी यह कहा जाता है कि उत्पादकता के बढ़ने से बेरोजगारी बढ़ेगी। दूसरे देशों के अनुभवों ने इसे झूठ सिद्ध कर दिया है। उत्पादकता में वृद्धि से प्रायः रोजगार में भी वृद्धि होती है।

—

सफ़ेद कोढ़ के दाग

हजारों के नष्ट हुए और सैकड़ों के प्रशंसापत्र मिल चुके

दवा का मूल्य ५) रु० डाक व्यय १) रु०

अधिक विवरण मुफ्त मँगाकर देखिये।

वैद्य के० आर० बोरकर

मु० पो० मंगरूलपीर, जिला अकोला (मध्य प्रदेश)

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ग्राम-उद्योगों के लिए वित्त-व्यवस्था—

सहकारी बैंकों का नया दायित्व

द्वितीय पंच वर्षीय योजना में हाथ से चावल कूटने, वनस्पति तेल चमड़ा, गुड़, खांड आदि मुख्य ग्राम उद्योगों का विकास किया जायेगा। इन उद्योगों के विकास के लिए अन्य समस्याओं के अतिरिक्त वित्त की व्यवस्था करना भी प्रमुख समस्या है।

बैंक और बीमा

वित्त की व्यवस्था

ग्राम उद्योगों के लिए वित्त व्यवस्था करने में प्रायः वही समस्याएं उपस्थित होती हैं, जो कृषि के लिये वित्त-व्यवस्था करने में सामने आती हैं। इसका कारण यह है कि दोनों को एक सी विचित्र परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जैसे, पर्याप्त रूप से उधार न मिलना वैयक्तिक ऋणों का अति सीमित होना तथा उत्पादन की अनिश्चितता। इन परिस्थितियों से छुटकारा दिलाने के लिये एक ऐसी संस्था की आवश्यकता है, जो ग्रामोउद्योगों के लिये वित्त--व्यवस्था कर सके। पर इस संस्था का संगठन सहकारिता के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि ग्राम उद्योगों का भी सहकारिता के आधार पर संगठन होगा। सरकार ने भी सहकारिता के आधार पर संगठित उद्योगों की ही सहायता करने का निश्चय किया है।

इन बातों को दृष्टि में रखते हुए स्वाभावतः हमारा ध्यान केंद्रीय सहकारी बैंकों और शीर्ष बैंकों की ओर जाता है। ये बैंक कृषि के लिए आवश्यक ऋण देने का कार्य पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन अब इन्हें ग्रामोद्योगों के लिये भी ऋण-व्यवस्था का कार्य करने के लिये तैयार होना पड़ेगा।

सहकारी बैंकों का दायित्व

इस नये प्रकार के कार्य के कारण सहकारी बैंकों का दायित्व बढ़ जाता है। प्रश्न किया जा सकता है कि क्या सहकारी बैंक अच्छी प्रकार ग्रामोद्योगों के लिये वित्त--व्यवस्था कर सकते हैं और क्या इस समय उनकी कार्य प्रणाली इतनी सुदृढ़ है कि वे इस कार्य का पूरा उत्तर-दायित्व ले सकें। लेकिन हमें इस बात को स्मरण रखना चाहिए कि वित्त की आवश्यकता, ऋण की अवधि व सुरक्षा और उधार का चुकाना इन तीनों में विभिन्न उद्योगों में उनकी आवश्यकतानुसार विभिन्नता होती है। उदाहरण के लिये कुछ उद्योगों को वर्ष भर ऋण लेने की आवश्यकता होती है। वर्तमान अवस्था में ऐसे उद्योगों को ऋण देते समय यह आश्वासन देना होता है कि वे वर्ष के अंत में ऋण का १० प्रतिशत चुकता कर देंगे। फिर जब ऋण विशेष उद्देश्यों के लिये दिये जाते हैं, जैसे उत्पादन-पद्धति को उन्नत करना, तो इनकी अवधि निश्चित कर ली जाती है। बैंकों के उपनियमों के अनुसार कोई भी बैंक सहकारी उद्योगों को उनकी निधि से अधिक ऋण नहीं दे सकता है। सच तो यह है कि बैंक किस सीमा तक सहकारी उद्योगों के लिये वित-व्यवस्था कर सकते हैं, यह बहुत कुछ सहकारी उद्योगों के प्रबन्ध पर निर्भर करता है।

व्याज की दर

यह भी उल्लेखनीय है कि इस समय खादी--ग्रामोद्योग आयोग की व्यवस्था में ग्रामोद्योगों के लिये जो ऋण प्राप्त किये जाते हैं, उनकी व्याजदर ३ प्रतिशत होती है। कुछ में तो व्याज लिया ही नहीं जाता। प्रश्न यह है कि सहकारी बैंक अपनी व्याज दर को कम से कम ३ प्रतिशत तक रख सकेंगे या नहीं। वास्तव में सहकारी बैंकों पर जो नया दायित्व आ पड़ा है, उसको वे अच्छी प्रकार निभा सकेंगे या नहीं, तथा इसमें कहां तक सफल होंगे, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्यों कि देश के सभी भागों में सहकारी बैंकों का एक सा विकास नहीं हुआ है। इस

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

समय तो सहकारी बैंकों की स्थिति यह है कि वे नये जोखिम को उठाने में समर्थ नहीं हैं।

पिछले महीने के आरम्भ में बम्बई में सहकारी बैंकों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए रिजर्व बैंक के डिपुटी गवर्नर श्री बी० वेकटप्पा ने कहा था कि ग्रामोद्योगों के लिए ऋण की व्यवस्था करना बैंकों के लिए एक नई घटना है। इस सम्बन्ध में यथेष्ट अनुभव न होने के कारण, इसके आधार पर एक सी कार्य पद्धति नहीं अपनाई जा सकती। वास्तव में सहकारी-साख पद्धति स्वयं तीव्र रूप से विकासोन्मुख है और उसका स्वरूप शीघ्रता से पुनर्गठित हो रहा है। साथ ही साथ इसके उत्तरदायित्व भी इसी तेजी से बढ़ रहे हैं। इस लिये ग्रामोद्योगों के लिये ऋण-व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि आरम्भिक अवस्था में साख के ढांचे के सुदृढ़ होने में सहायता मिल सके, जिससे बाद में योजना के निश्चित कार्यक्रमों के लिये अच्छी मात्रा में वित्त की उपलब्धि हो सके।

नये ऋण जारी

भारत सरकार ने १०० करोड़ रुपए के दो नए ऋण जारी करने की घोषणा की है। ऋण--राष्ट्रीय योजना बोंड-में ३॥) प्रतिशत ब्याज मिलेगा और ९९.-५० रु. प्रतिशत पर वह जारी होगा तथा १ अगस्त १९६७ को वह वापस मिलेगा। दूसरा ऋण १०० रु. प्रतिशत जारी होगा, ४ प्रतिशत ब्याज मिलेगा तथा १ अगस्त १९७२ को वापस मिलेगा।

दीर्घकालीन विदेशी ऋण

श्री द्वारिकानाथ तिवारी तथा नौ अन्य सदस्यों के एक प्रश्न के उत्तर में श्री भगत ने बताया है कि फ्रांस से दीर्घ-कालीन ऋण पर बड़ी मशीनें आदि खरीदने की बातचीत चल रही है। उन्होंने यह भी बताया कि अन्य किसी देश से इस तरह की बातचीत नहीं चल रही।

जीवन बीमा निगम की प्रगति

भारतीय जीवन बीमा निगम ने १ सितम्बर १९५६ से २४ जून, १९५७ तक १ अरब १७ करोड़ २४ लाख रु० के बीमे किए। इसके बाद की जानकारी अभी ज्ञात नहीं है, यह सूचना केन्द्रीय उप-मंत्री श्री बलीराम भगत ने एक विवरण में दी। किस क्षेत्र में कितनी रकम के बीमे किये गये, इसके आंकड़े इस प्रकार हैं :—

क्षेत्र	बीमों की रकम
उत्तरी	१६ करोड़ ९८ लाख रु०
पूर्वी	२२ करोड़ ६८ लाख रु०
केन्द्रीय	१८ करोड़ २६ लाख रु०
दक्षिणी	३२ करोड़ ४१ लाख रु०
पश्चिमी	२६ करोड़ ९१ लाख रु०

२ करोड़ रु० सम्पदा शुल्क

१९५६-५७ में विभिन्न राज्यों से सम्पदा-शुल्क के रूप में २,१०,७५,१३५ रु० की वसूली की गयी। १९५७-५८ की पहली तिमाही में इस मद में २२,३१,५०५ रु० वसूल किये गये।

राज्यों के अनुसार सम्पदा-शुल्क की वसूली इस प्रकार हुई :—

राज्य	संग्रह १९५६-५७ (रुपयों में)	संग्रह १९५७-५८ (३० जून, १९५७ तक)
१. आंध्र प्रदेश	५,०१,४५९	२,८१,७६४
२. असम	१,२४,०००	१,०००
३. बिहार	१,५५,०००	४८,६९५
४. बम्बई	१,०७,९०,६५३	७,७६,८०५
५. केरल	८४,०००	८२,१४२
६. मध्यप्रदेश	१,२६,१९०	९,०००
७. मद्रास	३०,२१,१२१	४,८१,०००
८. मैसूर	११,९३,२७४	६८,२८०
९. उड़ीसा	८,०००	—

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

१०. पंजाब	१,१५,५३७	२३,३०६
११. राजस्थान	३,२६,२४५	१३,१०८
१२. उत्तरप्रदेश	५,७६,०००	३०,०००
१३. पश्चिम बंगाल	३२,२६,७५६	३,५३,०००
१४. जम्मू और कश्मीर	—	—
संघीय राज्य क्षेत्र		
१. दिल्ली	८,०८,६८२	६३,४०५
२. हिमाचलप्रदेश	१५,२१८	—
३. मणिपुर	—	—
४. त्रिपुरा	—	—
५. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—
६. लक्षद्वीप, मिनिकाय और अमीनद्वीप	—	—
जोड़—	२,१०,७५,१३५	२२,३१,५०५

१९५६-५७ में शुल्क लगने योग्य ४,३०३ और शुल्क न लगने योग्य ५,७७१ मामले तथा १९५७-५८ की पहली तिमाही में शुल्क लगने योग्य २,५०३ और शुल्क न लगने योग्य २१८९ मामले दर्ज किये गये।

पंजाब नेशनल बैंक

३० जून, ५७ को समाप्त होने वाली छमाही में पंजाब नेशनल बैंक ने जमाराशि, कार्य और लाभ की दृष्टि से अभूतपूर्व उन्नति की। बैंक की जमाराशि ३० जून १९५७ तक ११७ करोड़ तक बढ़ी, जो ११ करोड़ रु० की वृद्धि प्रदर्शित करती है। बैंक का सम्पूर्ण कारोबार १५२ करोड़ रु० तक बढ़ा जो ३१ दिसम्बर १९५६ को १४१ करोड़ रु० था।

इस अवधि में बैंक को आकस्मिक निधि रख लेने के बाद ६२ ९२ लाख रु० का लाभ हुआ। इस राशि में ६.२० लाख रु० पिछले वर्ष की आगे के लिये रखी राशि भी सम्मिलित है। जब कि विगत वर्षों को इसी छमाही में ४९.२३ लाख रु० का लाभ हुआ। इसमें २.३५ लाख रु० की उससे पिछले वर्ष की राशि भी सम्मिलित थी। बैंक के डाइरेक्टरों ने २.५० रु० प्रति शेयर के हिसाब से मध्य वर्षीय लाभांश देने का निश्चय किया है; जो आयकर से मुक्त है। पिछले वर्ष इसी अवधि में यह लाभांश प्रति शेयर २ रु० ही था।

बैंक के ३४१ कार्यालय भारत, बर्मा और पाकिस्तान में कार्य कर रहे हैं और ये सभी प्रकार की बैंकिंग और विदेशी विनिमय सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करते हैं।

स्टेट बैंक

स्टेट बैंक ने राष्ट्रीयकरण के बाद जनता का विश्वास फिर से प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। ३० जून १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में बैंक की जमा राशि २२६ करोड़ रु० बढ़कर ३१६ करोड़ रु० हो गई। देश में आर्थिक गतिविधियों की वृद्धि होने के साथ-साथ बैंक की अग्रिम राशि में भी वृद्धि हुई। ३० जून को यह १८३ करोड़ रु० थी कि एक वर्ष पहले १३४ करोड़ ही थी। याने एक वर्ष में ४९ करोड़ रु० की वृद्धि हुई।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक पद्धति के विस्तार पर जोर देने के लिये इस वर्ष सारे देश में १०० शाखाएं खोलने का निश्चय किया गया। जबकि १ जुलाई ५५ से जून १९६० तक ५०० तक ऐसी शाखाएं खोलने का कार्यक्रम है। जून ५७ के अंत तक कुल १०२ शाखाएं खोली जा चुकी हैं।

बैंक २.५ करोड़ रु० को सबस्क्राइब करने के लिये तैयार हो गया है। सहकारी संस्थाओं को विशेष शाख-सुविधा प्रदान की जाती रही। सहकारी बैंकों को स्टेट बैंक की स्वाभाविक दर से १/२ प्रतिशत कम पर अग्रिम ऋण दिये गये। सहकारी केन्द्रीय बैंक और शीर्ष बैंकों को, राशियों को मुख्य कार्यालय से ग्रामीण क्षेत्रों के शाखा कार्यालयों में भेजे जाने की सुविधा मुफ्त दी गयी।

भूमि बन्धक बैंकों के द्वारा स्टेट बैंक ने कृषि के लिए दीर्घकालीन साख की सुविधा भी प्रदान की।

देना बैंक

देवकरन नानजी बैंकिंग कम्पनी लि० को ३० जून ५७ को समाप्त होने वाली छमाही में ८.४५ लाख रु० का लाभ हुआ। जबकि इसी अवधि में पिछले वर्ष लाभ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विविध राज्यों—

आर्थिक प्रवृत्तियां

दो बजट

दो राज्यों के बजट : मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश : उत्तरप्रदेश की दूसरी विकास योजना : राजस्थान का आर्थिक विकास

मध्यप्रदेश

वित्तीय वर्ष की अनुमानित राजस्व प्राप्तियां ५०८८.५४ लाख रु० और राजस्व लेखे पर अनुमानित व्यय ५४३६.९४ लाख रु० है, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व घाटा ३४८.४० रु० का है। पूंजीगत व्यय रु० २११७.४३ लाख होने का अनुमान है। लोक ऋण खंड के अन्तर्गत लेन-देन के फलस्वरूप २१७१.४३ लाख रु० की शुद्ध बचत व राज्य सरकार के ऋण व अग्रिमों के अन्तर्गत रु० ६५९.९२ लाख रु० के व्यय की संभावना है तथा लोक लेखा के अन्तर्गत रु० १८१.९२ लाख की शुद्ध बचत दर्शाई गई है। वर्ष का प्रारम्भिक शेष ५४.८५ लाख रु० था और इस वर्ष के लेन-देनों के परिणामस्वरूप अन्तिम शेष ७१७.५५ लाख रु० घाटे का होगा।

नवीन मध्यप्रदेश में विलीन ४ इकाइयों में से प्रत्येक में टैक्स लगाने की अलग-अलग विधियां हैं, और उनमें टैक्स की विभिन्न दरें चालू हैं। टैक्स के ढांचे के नवीनीकरण का प्रस्ताव है, ताकि टैक्स के क्षेत्र में राज्य की सारी जनता के साथ समान व्यवहार हो सके। प्रस्तावित नवीनीकरण का सम्बन्ध स्टाम्प ड्यूटी, कोर्ट फी, पंजीयन शुल्क, बिजली-शुल्क, मनोरंजन कर, व्यावसायिक कर, मोटर टैक्स तथा बिक्री कर से है। आशा है, इससे चालू वर्ष में १.५० करोड़ रु० अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी। इस तरह बिना कर बढ़ाये भी कुशल वित्तमंत्री ने १.५० करोड़ रु० की आय बढ़ा ली।

सन् १९५७-५८ के आय व्ययक में प्रस्तावित विकास कार्यों के क्षेत्र में निम्नांकित कार्य उल्लेखनीय हैं:—

राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा सामुदायिक विकास

२० नये राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड खोले गये हैं तथा १२ ऐसे ही खंडों को सामुदायिक विकास खंडों में परिवर्तन किया गया है।

सिंचाई तथा विद्युत

ऐसे सिंचाई कार्यों के लिये जिनका कार्य जारी है, ३.७२ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। ६ तालाबों द्वारा जिनका निर्माणकार्य प्रायः समाप्ति पर है, ४३,००० एकड़ भूमि की सिंचाई के लिये जलपूर्ति होगी। तथा बहु-उद्देश्य परियोजना पर १९५७-५८ के वर्ष में ५० लाख रु० के व्यय का अनुमान है। केन्द्रीय जल तथा शक्ति आयोग द्वारा १४ नवीन योजनाओं के सर्वेक्षण के लिए ११ लाख रु० की व्यवस्था की गई है। चम्बल सिंचाई तथा विद्युत् योजना के निर्माण में संतोषजनक प्रगति की गई है, जिस पर १९५७-५८ के वर्ष में ३.३२ करोड़ रु० के व्यय का अनुमान किया गया है।

कृषि, पशु संवर्धन तथा सहकारिता

योजना में कृषि-उत्पादन, भूमि विकास तथा छोटे सिंचाई-कार्यों के लिये १९५७-५८ के वर्ष के लिये कुल व्यवस्था ४.९३ करोड़ रु० की है। कृषि उत्पादन के अन्तर्गत उन्नत बीजों तथा रासायनिक उर्वरक का वितरण प्रमुख अंग हैं।

[सम्पदा

६.२१ लाभ रु० ही हुआ था। डाइरेक्टरों ने प्रति ५० रु० के शेयर पर १ रु० ४ आ० का अन्तरिम लाभांश देना निश्चित किया। इसमें १.२५ लाख रु० लगे। बचत ९.३३ लाख रु० रही, जब कि एक वर्ष पूर्व ६.७३ लाख रु० थी।

——

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वर्ष १९५७-५८ में ३५० बृहदाकार बहु-उद्देश्यीय सहकारी समितियों को गठित करने तथा ग्राम्य क्षेत्रों में प्राप्य अल्पकालीन ऋण के आकार को ६ करोड़ रु० तक तथा दीर्घकालीन ऋण के आकार को २ करोड़ रु० तक बढ़ा देने का प्रस्ताव है।

उद्योग धन्धे

माध्यम तथा छोटे उद्योग-धन्धों के विकास तथा तीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु ११९ लाख रु० का प्रावधान रखा गया है।

भोपाल स्थित विद्युत का भारी सामान बनाने वाले कारखानें को जलपूर्ति का जो आश्वासन भारत सरकार को दिया गया है, उसके अनुसार उक्त कारखाने की जलपूर्ति की व्यवस्था करने का प्रावधान भी है। राष्ट्रीय जलपूर्ति और सफाई योजना के अन्तर्गत २०० गांवों में नलों द्वारा जलपूर्ति की व्यवस्था पूरी की जायेगी तथा ४०० और गांवों में कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

बजट में राजस्व खाते में ३.४८ करोड़ का घाटा दिखाया गया है, किन्तु राज्य पुनर्गठन के परिणामस्वरूप भोपाल में राजधानी की स्थापना करने तथा आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों को रखने पर होने वाले व्ययों को देखते हुये इसे अनुचित नहीं कहा जा सकता। विशेषतः इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि नये राज्य में विन्ध्य प्रदेश और भोपाल दो "ग" श्रेणी के घाटे वाले राज्य मिलाये गये हैं।

●

उत्तरप्रदेश

वित्त मंत्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम द्वारा राज्य-विधान सभा में प्रस्तुत १९५७-५८ के बजट में कुल ११ करोड़ ६७ रुपये का घाटा दिखाया गया है।

बजट में अनुमित राजस्व प्राप्तियां ९६ करोड़ ६६ लाख रु० और राजस्व व्यय १ अरब ८ करोड़ ३३ लाख रु० है।

बजट के ११ करोड़ ६७ लाख रु० का घाटा पूरा करने के उद्देश्य से सरकार ने अपने खर्चे को और अधिक कम करने का निर्णय किया है। सरकार ने इस दृष्टि से मितव्यता के अनेक प्रस्ताव स्वीकार किये हैं, जिनसे लगभग १ करोड़ रुपये की तात्कालिक बचत होगी।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम ने आय में वृद्धि के लिए जिन नये उपायों को प्रस्तावित किया, उनमें से एक है आवश्यक कानून तैयार होते ही मनोरंजन कर में पचास प्रतिशत की वृद्धि। मनोरंजन कर में इस वृद्धि से पूरे वर्ष में ४० लाख रु० की और चालू वित्तीय वर्ष में २० लाख रुपये की आय संभव होगी।

मोटर स्पिरिट पर बिक्री कर में प्रति गैलन ३ आने की वृद्धि की जायगी, रजिस्ट्रेशन फीस में १०० प्रतिशत वृद्धि कर दी जायेगी और कृषि आय कर में इस आशय का संशोधन किया जायेगा कि उससे तत्सम्बन्धी आय में ३० से लेकर ४० लाख रु० की वृद्धि संभव हो सके।

अल्प वेतन पाने वाले ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनका वेतन ९५ रु० प्रतिमास से अधिक नहीं है, उनके महंगाई भत्ते में पांच रुपये की वृद्धि की जायेगी।

छठी कक्षा तक की शिक्षा सभी के लिए निःशुल्क कर दी जायेगी। १०० रु० या उससे कम प्रतिमास वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की फीस नवीं कक्षा में आधी कर दी जायेगी।

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि १ अप्रैल १९५८ से खाद्यान्न पर केवल एक सूत्रीय बिक्री कर रह जायेगा।

●

उत्तरप्रदेश की दूसरी पंचवर्षीय योजना

द्वितीय आयोजना पर उत्तर प्रदेश में २५३ करोड़ रु० खर्च होगा, जिसमें से ४१ करोड़ ४ लाख रु० कृषि और उससे संबंधित कामों पर और ८० करोड़ ४३ लाख रु० आबपाशी और बिजली की योजनाओं पर, ६८ करोड़ ७२ लाख रु० सामाजिक सेवाओं पर और १६ करोड़ ९९ लाख सड़कों और रोड ट्रांसपोर्ट पर व्यय होगा। प्लानिंग कमीशन ने कृषि पैदावार की बढ़ोतरी को सबसे ऊंचा दर्जा दिया है। उत्तर प्रदेश के लिए कृषि पैदावार में योजना का लक्ष्य २२ लाख ५० हजार टन तक की वृद्धि करना है। इस प्रकार १९६१ तक खाद्यान्नों की कुल पैदावार १४७ लाख टन हो जायेगी। उद्योग धंधों के

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लिए इस आयोजना में १६ करोड़ ४३ लाख रुपये व्यय करना निश्चित हुआ है और इन्हीं धंधों की बढ़ोतरी पर इस आयोजना में जोर देना है। राष्ट्रीय प्रसार सेवा सम्बन्धी योजनाओं के लिए इस वर्ष तक जो रकम रखी गई है, वह २६ करोड़ ६० लाख रुपया है और यह तय पाया है कि इस पंचवर्षीय योजना की अवधि के अन्दर इस पूरे राज्य में राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड खुल जायें और उनमें से ४० प्रतिशत प्रगाढ़ विकास खंड हो जायें।

औद्योगिक विस्तार

चुर्क स्थित राजकीय सीमेंट फैक्टरी तथा लखनऊ की सूक्ष्म यंत्र निर्माण शाला अपनी क्षमता के अनुकूल उत्पादन कर रही हैं। इस समय यह भी तजबीज है कि सीमेंट फैक्टरी के उत्पादन को इस पंचवर्षीय आयोजना के अन्दर दुगुना कर दिया जाये, यानी वह ७०० टन सीमेंट रोजाना और ज्यादा बनाने लगे और सूक्ष्म यंत्र निर्माण शाला के जरिये यह इन्तजाम हो रहा है कि इसमें 'प्रेसर गाज' और चिकित्सा एवं शल्य-सम्बन्धी यंत्र भी बनवाये जायें। दूसरी पंचवर्षीय योजना के सिलसिले में यह भी तजबीज है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग धंधों में से एक "अलूमीनियम प्लांट" चुर्क के करीब, एक "सिन्थेटिक रबर प्लांट" बरेली के करीब और एक फैक्टरी लोकोमोटिव कम्पोनेंट बनाने के लिए वाराणसी के करीब मडुआडीह में स्थापित की जाय। इनके अलावा यह भी कोशिश की जा रही है कि वाराणसी के करीब एक सोडाएश-कम-एमोनियम क्लोराइड प्लांट लगेगा और नकली रेशम बनाने का प्लांट कानपुर में लगेगा। इन्हीं के साथ बिजली के एक ट्रांसफार्मर और स्वीच गेयर बनाने का कारखाना नैनी में और एक टार्चेज और बिजली के ड्राइसैल बनाने की फैक्टरी लखनऊ में स्थापित होगी। यह आशा की जाती है कि ये सब कारखाने जल्दी ही अपना काम चालू कर देंगे। किछा में एक शुगर फैक्टरी कायम हो रही है और उसके बनाने का काम शुरू हो गया है और इसके अतिरिक्त एक सहकारी चीनी मिल बाजपुर में लग रही है।

भूगर्भ एवं खनिज पदार्थ संचालन कार्यालय ने यह पता चलाया है कि उत्तरप्रदेश में चूने का पत्थर, खड़िया मिट्टी और 'क्ले' (विशेष प्रकार की मिट्टी) के ऐसे खजाने हैं, जिनसे बहुत कुछ काम लिया जा सकता है। इस आधार पर यह भी तजबीज हुआ है कि एक दूसरी सीमेंट फैक्टरी देहरादून में लगवाई जाये।

हाथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश में सबसे बढ़कर है, जिसमें यहां के रहने वाले ८ लाख आदमियों को रोजी मिलती है। सरकार ने भी अपनी स्कीमों से इसकी बहुत कुछ मदद की है। पिछले साल ३५९ बुनकरों की सहकारी उत्पादन समितियों ने ४ करोड़ ४२ लाख रुपये का कपड़ा बनाया। चालू साल में यह आशा की जा रही है कि ६ करोड़ रु० का कपड़ा बन जायगा। गांव की बनी हुई चीजों को बेचने के लिए गवर्नमेंट हैन्डीक्रैफ्ट एम्पोरियम के काम को बहुत बढ़ा दिया गया है और एक नया एक्सपोर्ट ट्रेड डिवीजन भी इसके साथ खोला गया है। यू० पी० गवर्नमेंट के हैन्डीक्रैफ्ट के शो रूम नई दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, कलकत्ता, नागपुर और हैदराबाद में खोल दिये गये हैं। इनकी बिक्री १९५२-५३ में सिर्फ ६ लाख थी जो अब बढ़कर १४ लाख हो गई है। पिछले साल एक्सपोर्ट डिवीजन ने दूसरे मुल्कों से ९ लाख के आर्डर हासिल किये और इनके अलावा निजी व्यवसायियों द्वारा ५ करोड़ रु० की उत्तर-प्रदेश की बनी हुई चीजें बाहर के मुल्कों को भेजी गईं।

छोटे उद्योग-धन्धों की और तरक्की करने के लिए कानपुर तथा आगरे में एक करोड़ के खर्च से दो औद्योगिक आस्थान स्थापित किये जा रहे हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण की ओर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

—

सम्पदा का विशेषांक
समाजवाद अंक

अभी से १॥) भेजकर अपनी प्रति रिजर्व करा लीजिये, अन्यथा पीछे पछतावेंगे।

—मैनेजर

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

फोन नं० : ३३१११ तार : माइनहोल्डर

मिनरल वैल्थ आफ इंडिया लिमिटेड

सब प्रकार के खनिज व धातुओं

के

व्यापारी तथा एक्सपोर्टर्स

खताऊ बिल्डिंग्स

४४ ओल्ड कस्टम हाउस रोड, फोर्ट, बम्बई

मैनेजिंग डायरेक्टर:—

श्री सी० डीडवानिया

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बाढ़ क्यों और उसका उपाय क्या ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी

बाढ़ का नियंत्रण करने, भूमि का कटाव रोकने तथा ऊसर, बंजर और रेगिस्तान की रोकथाम करने के लिए वनरोपण एकमात्र औषधि है। उत्तरप्रदेश, बिहार और पंजाब के कुछ हिस्सों में बाढ़ से हर साल तबाही और बरबादी होती रहती है। ऐसी हालत में अगर हम एक कृषि प्रधान देश के रूप में उन्नति करना चाहते हैं तो हमें इन बाढ़ों की रोकथाम के लिए कोई न कोई उपाय करना होगा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले भी जो अभी तक बाढ़ के प्रकोप से मुक्त रहते थे, पिछले वर्ष इसके शिकार हो गये थे। और इन जिलों में जान-माल की जो व्यापक क्षति हुई, उसने हमारी आशाओं को झकझोर डाला और हमें भविष्य के लिए चिन्तित कर दिया। बाढ़ों का यही रवैया रहा तो हमारे द्वितीय आयोजन को गहरा धक्का पहुँचेगा। पूर्वी ज़िलों के सिवा पश्चिम जिलों में बाढ़ का प्रकोपएक नयी मुसीबत है और आवश्यकता इस बात की है कि समय रहते ही हम इन जिलों में बाढ़ों का प्रतिरोध करें।

अतिवृष्टि-प्रधान कारण

इस तथ्य से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि वर्षा ऋतु में उत्तर भारत के समूचे हिमालयी क्षेत्र में अतिशय वर्षा होने के कारण ही उत्तर प्रदेश में बहमें वाली नदियां इतना विशाल रूप धारण कर लेती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में पानी इतनी अधिक मात्रा में बरस पड़ता है कि नदियां उस पानी को अपनी सीमा में बहा सकने में असमर्थ हो जाती हैं। पर विगत कुछ वर्षों से ही बरसात का पानी पहाड़ों से उतर कर क्यों इतना उधम मचाने लगा है ? वस्तुतः इस प्रश्न का उत्तर ही हमें वनों का महत्व स्वीकार करने के लिए बाध्य करता है और इस नतीजे पर पहुँचाता है कि बाढ़ों से बचे रहने या कम से कम उनके वेग को रोकने में वनों का विशेष स्थान है। पहाड़ों की ढाल पर से बहने वाले बरसाती पानी को रोकने के लिए वहां वनों के न होने के कारण पानी अवाध वेग मे बहने लगता है।

यह बात किसी से छिपी नहीं कि कुछ ही साल पहले विशेषकर द्वितीय महायुद्ध के दौरान में और जमींदारी उन्मूलन से आतंकित होकर तथा अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के फलस्वरूप वनों का निर्दयतापूर्वक विनाश किया गया। इसका यह परिणाम हुआ कि बरसात के पानी के लिए कोई अवरोध नहीं रह गया और नदियों में बाढ़ का प्रकोप बढ़ने लगा।

कहने की आवश्यकता नहीं कि वनों और वनस्पतियों के होने से वर्षा का पानी रुक रुक कर धरती पर आता है और उसे बहुत कुछ मात्रा में वन भूमि ही सोख लेती है। फलतः नदियों तक पहुँचते पहुँचते पानी का वेग मर जाता है और इस प्रकार बाढ़ की आशंका प्रायः कम ही रह जाती है। इसके अतिरिक्त प्रकृति की इस प्रक्रिया से भूमि क्षरण भी नहीं हो पाता तथा नदियों के तल में मिट्टी की तह नहीं जमने पाती। वनों और वनस्पतियों के अभाव में बरसात का पानी जमीन को काटता हुआ, बेलाग होकर नदियों में आकर गिरने लगता है, जो उनके बहाव की क्षमता से कहीं अधिक साबित होता है और नदी तल में दूर-दूर से पानी के साथ आयी हुई मिट्टी जम जाती है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि वनों और वनस्पतियों द्वारा धरती को पर्याप्त छाजन और आवरण न मिलने के ही कारण विनाशकारी बाढ़ों का आना अनिवार्य हो जाता है।

पिछले वर्ष राज्य के पश्चिमी जिलों में बाढ़ का मूल कारण कुमाऊं की नदियों में अचानक अतिशय पानी का आजाना ही था। कुमाऊं के पहाड़ों का पानी टिहरी गढ़वाल की टौंस, यमुना और भागीरथी तथा गढ़वाल जिले की मन्दाकिनी, अलकनन्दा, पिंडर और नयार तथा अलमोड़ा और नैनीताल जिले की रामगंगा, कोसी और काली या शारदा नदियों से होकर बहता है।

पूर्व की ओर रामगंगा और, कोसी और गौला नदियों से मुरादाबाद, बदायूं और फर्रुखाबाद जिलों में और शारदा तथा काली नदियों से पीलीभीत, खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, फैजाबाद, आजमगढ़ और बलिया जिलों में बाढ़ आने का भय बना रहता है। यमुना और चम्बल के किनारे

[सरफड़ा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भूक्षरण के भयानक दृश्य देखने को मिलते हैं। पहले जहां हरे भरे खेत थे, वहां अब खारें देखने को मिलती हैं और निश्चय ही इसका कारण है बनस्पति का पूर्णतः नष्ट होना।

बाढ़ों की रोकथाम के उपाय

बाढ़ों की रोकथाम के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपाय अपनाए जाने चाहिए:—

हमारे राज्य का अधिकांश वन क्षेत्र कुमाऊं में है। वहां तीन प्रकार के वन हैं यथा (१) सुरक्षित वन, (२) पंचायत वन और (३) प्रथम श्रेणी के वन। सुरक्षित वन, वन विभाग के अधीन हैं, अतः उनका कटाव अवैज्ञानिक ढंग से नहीं होता है। पंचायत वनों का प्रबन्ध भी संतोषजनक है। केवल प्रथम श्रेणी के वनों का प्रबन्ध सुचारुरूप से नहीं होता। ऐसे वन जिलाधीश के अधीन होते हैं, जिनके पास इन वनों का वैज्ञानिक ढंग से प्रबन्ध करने के लिए समुचित साधन नहीं हैं। अतएव आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे वनों का प्रबन्ध वन विभाग द्वारा किया जाये। कुमाऊं में इस समय ११ लाख ९१ हजार एकड़ क्षेत्र में प्रथम श्रेणी के वन हैं। सरकार व विभाग ने द्वितीय पंचवर्षीय आयोजन में इन वनों के पांच लाख एकड़ वर्गक्षेत्र को अपने प्रबन्ध में ले लेने का निश्चय किया है। इन वनों की देखभाल के लिए गत वर्ष में दो और वन डिवीजन खोले गये थे। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि लोगों में यह भावना पैदा की जाये कि इन वनों के नष्ट होने से उनका ही नहीं, अपितु समूचे राष्ट्र का अहित है।

नंगे पर्वतों में वनरोपण कार्य

पर्वतों की और विशेषरूप से उन क्षेत्रों की वनस्पति, जिनका पानी नदियों तथा नालों में आता है, गायब होने के कारण बाढ़ें आती हैं। अतः यह नितान्त आवश्यक है कि ऐसे क्षेत्रों में यथाशीघ्र पेड़ लगाए जायें। साथ ही खारों वाले क्षेत्रों में भी वृक्षारोपण कार्य करने की आवश्यकता है।

मैदानी क्षेत्रों में खारों तथा नदियों आदि के किनारे वृक्षारोपण

यमुना और चम्बल नदियों ने, उनके किनारे पेड़ों के न होने के कारण, गहरी खारों को बना डाला है और साथ ही कृषि योग्य एक बड़े भू-भाग को नष्ट कर दिया है। संभवतः अन्य नदियां भी ऐसा कर सकती हैं। अतः यह आवश्यक है कि इन नदियों तथा नालों के किनारे और खारों में वृक्षारोपण किया जाये, मैदानी क्षेत्रों में बेकार पड़ी समस्त भूमि में भी पेड़ लगाये जायं। हमारे राज्य के मैदानी क्षेत्रों में केवल दो प्रतिशत भूमि में वन हैं, जबकि अधिकांश वन क्षेत्र पहाड़ी इलाकों में है। अतः वन क्षेत्र की कमी दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि मैदानी क्षेत्रों के बड़े भू-भाग में यथाशीघ्र वन लगाये जायं।

पूर्वी जिलों में बाढ़

राज्य के पूर्वी जिलों में गोमती, बड़ी गंडक अथवा नारायणी, राप्ती, गंडक और घाघरा नदियों के कारण बाढ़ आती है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इन जिलों में बाढ़ों की रोकथाम के लिए जितने उपाय हम अपना सकते थे, नहीं अपना पा रहे हैं। इसमें मुख्य कठिनाई यह है कि इनमें से अधिकांश नदियों के उद्गम स्थान तथा वे क्षेत्र जिनका पानी इन नदियों में आता है नेपाल क्षेत्र में पड़ते हैं। अतः ऐसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कार्य नेपाल सरकार के सहयोग से ही सम्पन्न किया जा सकता है।

बाढ़ों की रोकथाम के लिए यद्यपि सभी संभव उपाय किये गये हैं तथापि वे पर्याप्त नहीं हैं। उन क्षेत्रों में, जिनका पानी नदियों में आता है, पेड़ों, झाड़ियों को लगाने और घास उगाने की आवश्यकता है जैसा कि राजस्थान के बढ़ते हुए रेगिस्तान को रोकने के लिए किया गया है। सभी नदियों के किनारे कम से कम चार फर्लांग चौड़ी वन-पेटी लगाने की आवश्यकता है। इन कार्यों को यथाशीघ्र सम्पन्न करने में भू-संरक्षण और बाढ़-नियंत्रण बोर्डों का सक्रिय सहयोग अपेक्षित है। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है गढ़वाल जिले के दक्षिणी भाग में बाढ़ों की रोकथाम के लिए सभी संभव उपाय अपनाकर राज्य के पश्चिमी जिलों को भयंकर तथा अनिश्चित बाढ़ों से सुरक्षित रखा जा सकता है। देहरादून के दक्षिण में शिवालिक पर्वत श्रेणियों की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि वहां पहाड़ों के खिसकने को रोका जा सके तो निश्चय ही देहरादून, मुजफ्फरनगर और मेरठ जिलों की उपजाऊ भूमि को होने वाले खतरे को दूर किया जा सकता है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अर्थ वृत्त चयन

नापतोल भी दशमिक प्रणाली में

रुपये, आने, पाई को दशमिक प्रणाली में बदल दिया गया है। अब रुपये के १०० पैसे होते हैं। इसके बाद सरकार आगामी अप्रैल से सेर, छटांक या मन की लोक-प्रचलित प्रणाली को बदलकर तोल नाप में भी दशमिक प्रणाली चलाना चाहती है। इसकी एक विशेषता या कमी यह है कि भारत के प्रतिभाशाली विद्वानों को हिन्दी का कोई शब्द ही नहीं मिला। अंग्रेजी का मीटर शब्द ही स्वीकार कर लिया गया है, और इस तरह अपनी मौलिकता का अभाव सिद्ध किया है।

मीटर शब्द का प्रयोग सबसे पहले १७९३ में फ्रांस की राष्ट्रीय अकादमी की समिति के प्रतिवेदन में किया गया। मीटर से आशय पृथ्वी की परिधि के चौथाई भाग के १,००,००,००० वें भाग से था। यह शब्द लेटिन की धातु "मी" से बना है, जिसका अर्थ है—नापना। इस प्रकार लम्बाई के "लौकिक" प्रतिमान, मीटर का जन्म हुआ। आज इस माप को अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है।

\+ + +

अंडमान की एक दुग्धशाला ने पंजाब से भैंसें खरीदीं। सौदे की शर्त यह थी कि भैंसों का मूल्य इस बात पर निर्भर होगा कि वह कितने सेर दूध देती हैं। कीमत चुकाये जाने के समय पंजाब की पशु-शाला ने कीमत मंजूर नहीं की, क्योंकि दूध सेरों में नापा नहीं गया था, बल्कि तोला गया था। इस बात को लेकर काफी समय तक झगड़ा चला।

\+ + +

चौदहवीं शताब्दी में इंग्लैंड के राजा हेनरी प्रथम ने गज की लम्बाई अपनी नाक के सिरे से अंगूठे की दूरी जितनी निश्चित कर दी। लगभग सौ वर्ष बाद रानी एलिजाबेथ ने घोषणा की कि एक खास रविवार को चर्च से निकलने पर १६ आदमी एक कतार में इस प्रकार खड़े होंगे कि उनका बायां पैर एक-दूसरे के पैर को छूता रहे। इस प्रकार जितनी दूरी नपी, वह लम्बाई का कानूनी माप बनी और इस दूरी का १६ वां भाग कानूनी "फुट" बना।

\+ + +

बंगाल को छोड़ बाकी सब राज्यों में माप और तोल-सम्बन्धी कानून हैं। केवल बम्बई, मैसूर, बिहार और पंजाब में ये कानून लागू किये गये हैं। बाकी राज्यों में इन कानूनों को लागू करने की व्यवस्था नहीं है।

\+ + +

माप-तोल विषयक कानून लागू करने से पहले बम्बई के विभिन्न जिलों में विभिन्न तरह के मन थे। स्वयं बम्बई नगर में ११ किस्म के मन और १२ किस्म की खंडियां थीं। इसके अलावा, कुछ जिलों में व्यापारी और महाजन दो तरह के तोल इस्तेमाल करते थे। अनाज आदि खरीदते समय वह भारी तोल इस्तेमाल करते थे और किसानों को अपना माल बेचते समय हलके तोल इस्तेमाल करते थे।

भारत का पशु-धन

पशु-धन की दृष्टि से भारत का संसार में पहला स्थान है। अमेरिका दूसरे नम्बर पर और रूस तीसरे नम्बर पर आता है। महायुद्ध के बाद संसार में पशुओं की संख्या अन्दाजन ७१ करोड़ ८० लाख थी, जिसका १९ प्रतिशत भारत में था।

अनुमान है कि पहली पंचवर्षीय आयोजना के प्रारम्भ में देश में १ करोड़ ८० लाख टन से ज्यादा दूध होता था, जिसमें से ३८ प्रतिशत दूध के रूप में, लगभग ४२ प्रतिशत घी के रूप में और बाकी मक्खन, दही आदि अन्य पदार्थों के रूप में खाया-पिया जाता था।

भारत में अच्छी नस्ल की गाय और भैंस एक बियात में औसतन १,५०० पौंड दूध देती हैं। पश्चिमी देशों में यह मात्रा ३,००० पौंड से ४,००० पौंड तक है, जिसकी तुलना में भारतीय उत्पादन बहुत कम है। इसका एक कारण यह है कि देश में पशुओं की संख्या चारे की पैदावार से कहीं अधिक है। खाद्यान्नों की आवश्यकता बढ़ने से चरागाहों की संख्या धीरे-धीरे घटने लगी है। परिणाम-

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

स्वरूप अधिकांश पशुओं को भरपेट चारा नहीं मिलता और वे दूध कम देते हैं।

राज्य सरकारें पशुओं की नस्लों के सुधार का कार्य मुख्यतः केन्द्र-ग्रामों में कर रही है। पहली आयोजना में विकास-कार्यों के लिए ६०० गांव चुने गये थे और १५० कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोले गये थे। दूसरी आयोजना में १,२५८ गांवों में विकास-योजनाएं चलाने, २४५ कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र और २५४ विस्तार केन्द्र खोलने की योजना है।

इस कार्यक्रम के अनुसार अच्छी नस्ल के २२,००० सांड, ९,५०,००० बैल और १० लाख गायें तैयार करने का इरादा है।

विश्व में अंधाधुंध चाय

आज प्रायः प्रत्येक देश में उत्पादन बढ़ाना आर्थिक उन्नति के लिए अत्यावश्यक माना जा रहा है। लेकिन विश्व के चाय उद्योग का भविष्य उत्पादनाधिक्य के खतरे से खाली नहीं हैं। गत वर्ष विश्व में चाय उत्पादन १२,५८० लाख पौंड था, जो १९५५ से ६३ लाख पौंड अधिक है। इस सम्बन्ध में एक बात उल्लेखनीय है। उत्तर भारत में उत्पादन २० नवम्बर से ही बंद कर दिया गया था। ऐसा न करने से उत्पादन ३०० लाख पौंड और बढ़ जाता। अफ्रीका का उत्पादन बढ़ रहा है और उत्तर भारत का उत्पादन प्राकृतिक प्रकोप पर नियंत्रण से ही बढ़ाया जा सकता है।

इस वर्ष के प्रथम तीन मासों में चाय का उत्पादन श्रीलंका में २१५ लाख पौंड, दक्षिण भारत में ४५ लाख पौंड और इंडोनेशिया में २२.५ लाख पौंड ज्यादा हुआ था। अतः भविष्य आशाप्रद प्रतीत नहीं होता।

सहकारिता और सामुदायिक विकास

तीन वर्षों में याने १९५३-५४, से १९५५-५६ तक कृषि सहकारी संस्थाओं की संख्या १,११,६२८ से बढ़ कर १,५९,९३९ हो गईं। यह बढ़ती ४३ प्रतिशत है। सदस्यों की संख्या ५१,३०,००० से ७७,९०,००० हुई। यह वृद्धि ५२ प्रतिशत है। कार्यकारी पूंजी ४९.१८ करोड़ रु० से बढ़कर ७९.१ करोड़ रु० हो गई। वृद्धि ६१ प्रतिशत हुई। परिदत्त शेयर पूंजी ९.९ करोड़ रु० से १६.८ करोड़ रु० हो गई। इसमें ९० प्रतिशत वृद्धि हुई। शेयर पूंजी, कार्यकारी पूंजी और विनियोग तथा सम्पति में जो वृद्धि हुई, इसका अनुपान सदस्यों की संख्या में हुई वृद्धि से अधिक है।

इस अवधि में सदस्यों की संख्या आदि में सर्वाधिक वृद्धि राष्ट्रीय विस्तार खंडों और सामुदायिक विकास योजना केन्द्रों के क्षेत्रों में हुई। लेकिन १९५५ तक राष्ट्रीय विस्तार सेवा के अन्तर्गत ८३,३०० गांव ही आये थे। उस समय इसने कृषि उत्पादन और सहकारिता के बढ़ाने पर आज की तरह अपना ध्यान केन्द्रित नहीं किया था।

हम बोझ उठावेंगे

हमने यह तय किया कि हम गरीबी को दूर करेंगे। इससे लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने में हमें भारी बोझा उठाना पड़ा। अंग्रेजों ने अपने मुल्क में जो काम डेढ़ सौ बरस में किया, हम चाह रहे है कि हम पन्द्रह बरस में करें। रूस ने जो काम तीस बरस में किया, याद रखिए रूस में इन्कलाब हुआ, उसको भी चालीस बरस हो गए, तो हम चाहते हैं कि उसे पन्द्रह, बीस बरस के अन्दर करें। इसके माने यह हैं कि हमें भारी बोझा उठाना है, जरा दिक्कतों का सामना करना है। किस लिए? इसलिए कि हम अपने को मजबूत करें, मुल्क को मजबूत करें ताकि कल कौम को आराम मिले, तरक्की हो। हम ता हिम्मत करके कूद पड़े दरिया में, और हमें उस पार जाना है। न हम वापस आ सकते हैं, न हम बीच में दरिया में टिके रह सकते हैं। तो इसके माने यह हैं कि हमें पूरी ताकत से अपने बड़े बड़े कामों को पूरा करना है।

—नेहरू

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विदेशी अर्थ चर्चा—

सोवियत संघमें पारमाणविक विद्युत

(श्री अलेकज़ान्द्रोव,)

यह समझना आसान है कि ब्रिटेन जहां ईंधन का अभाव है, जोरों से पारमाणविक विद्युत् उद्योग का विकास क्यों कर रहा है। लेकिन सोवियत संघ क्यों पारमाणविक विद्युत् कारखानोंमें इतनी बड़ी धनराशि लगा रहा है ?

सचमुच सोवियत संघमें कोयले और तेल के बहुत बड़े साधन-स्रोत हैं। फिर भी सोवियत वैज्ञानिकों और इंजीनियरोंका विचार है कि पारमाणविक विद्युत् उद्योग के विकास की भव्य सम्भवनाएं विद्यमान हैं। फिर कुछ औद्योगिक क्षेत्रों के उपयोग के लिए अब भी हजारों मीलों की दूरी से ईंधन लाना होता है। इस प्रकार यातायात व्यवस्था के ऊपर भारी बोझ पड़ता है और उन पर बहुत अधिक खर्च बैठता है। पारमाणविक विद्युत् स्टेशन ईंधन ढोने का बखेड़ा समाप्त कर देंगे। इसके अतिरिक्त उनसे शहरों के स्वास्थ्य और सफाई की परिस्थितियों में ठोस उन्नति होगी और वायु का दूषण कम होगा। दूसरा कारण यह कि सोवियत संघ के खनिज-द्रव्य-सम्पन्न बहुत से इलाके, जिनमें कोयला-क्षेत्र शामिल हैं, दूर उत्तर में तथा दक्षिण की मरुभूमि में हैं। विद्युत उत्पादन के लिए पारमाणविक शक्ति के उपयोग से इन क्षेत्रों के औद्योगिक विकास में ठोस रूप से तेजी आ सकती है, क्योंकि कीमती कोलवरियों और वृहत् श्रमिक-बस्तियों का निर्माण आवश्यक नहीं रह जाएगा। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि दुनियां में ईंधन के साधन-स्रोत सीमित हैं।

सोवियत संघ की सरकार ने बीस लाख किलोवाट से पचीस लाख किलोवाट की कुल क्षमतायुक्त पारमाणविक विद्युत्-स्टेशनों के निर्माण के लिए चालू पंचवर्षीय योजना (१९५६-६०) में व्यवस्था की है। भविष्य में विशाल कार्यक्रम का यह प्रथम चरण वृहत्तम पैमाने पर इंजीनियरिंग सम्बन्धी परीक्षण है।

रूसमें कैसे स्टेशनों का निर्माण हो रहा है ?

वहां २००,००० किलोवाट से लेकर ४००,००० किलोवाट क्षमतायुक्त तीन प्रकार के बड़े स्टेशनों का निर्माण हो रहा है। दो स्टेशन शोधित यूरेनियम के बल पर चापयुक्त सामान्य जल के सहारे चलेंगे, एक शोधित यूरेनियम बल पर ग्रैफाइट मौडरेटर और जलीय शीतलीकरण के सहारे तथा एक और स्टेशन कच्चे, यूरेनियम के बल पर भारी जल मौडरेटर और गैस शीतलीकरण के सहारे चलेगा। उदाहरणार्थ, मास्को के कुछ स्टेशन ताप की पूर्ति करने के लिए आंशिकरूप में सम्भवत: चल सकते हैं। उसके महत्व को समझना आसान है। इतने ही बड़े स्टेशन के लिए प्रतिवर्ष लगभग २,००० गाड़ी कोयले की जरूरत पड़ती।

लीपज़िग की शानदार प्रदर्शनी

लीपजिग (पूर्वी जर्मनी) की औद्योगिक प्रदर्शनी सबसे प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का स्थान प्राप्त कर चुकी है। बहुत वर्षों से यह नियमित रूप से हो रही है। यूरोपीय महायुद्ध के वर्षों में यह नहीं हो सकी। युद्ध के बाद ही बीसवीं प्रदर्शनी १ सितम्बर से ८ सितम्बर तक हो रही है। ११ लाख वर्गफुट में यह प्रदर्शनी होगी, जिसमें २० देशों के प्रदर्शक भाग लेंगे तथा ७० देशों के प्रतिनिधि आवेंगे। उत्पादक व उपभोक्ता सभी प्रकार की सामग्री इसमें दिखाई जायेगी। मोटर, रेडियो, टैलिविजन, सूक्ष्म यंत्र आदि वस्त्र, जूते, कांच का सामान, खिलौने, ग्रामोफोन, खेल के सामान आदि सभी श्रेणियों के उपयोग का सामान प्रदर्शनी में दिखाया जायेगा।

मंगोलिया, रूमानिया और अलबानिया इसमें पहली बार भाग ले रहे हैं। भारतीय उत्पादकों के भी सम्मिलित होने की संभावना है। आस्ट्रिया, चेकोस्लावेकिया, पोलैंड, हंगरी आदि साम्यवादी देश इसमें भाग लेकर अपने कला-कौशल की वस्तुएं दिखावेंगे। ब्रिटेन, फ्रांस, डैनमार्क, स्वीडन, नार्वे, जर्मनी आदि पश्चिमी यूरोप के देश भी बिना अपवाद के इसमें भाग लेंगे। स्विट्जरलैण्ड अपनी प्रसिद्ध घड़ियों का प्रदर्शन करेगा। ग्रीस, इटली व पुर्तगाल आदि फल व शराब लायेंगे।

लिपजिग आने जाने की पूरी सुविधाएं मिलेंगी। बर्लिन तक आने वाले विदेशी वायुयान लिपजिग भी आवेंगे। यहां आने के लिए दूतावास अनुमतिपत्र देने में दिक्कत नही करेंगे। विदेशी विनिमय की भी सुविधा सबको मिले, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है।

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(७) पत्थर :—लगभग ३० हजार व्यक्ति भवन-निर्माण में लगे हुए हैं। कई व्यक्ति पत्थर की मूर्तियां व अन्य उपयोगी व सुन्दर चीजें बनाते हैं। जयपुर की मूर्तियां इसके लिये प्रसिद्ध है।

(८) मिट्टी :—लाल, पीली व भूरी मिट्टियों से कई खिलौने, घड़े, ईंटें आदि बनाई जाती है।

(९) अन्य :—साबुन व सिर में डालने के लिये तेल, हाथी दांत की चूड़ियां, कागज, मधुमक्खी का पालन नमक आदि महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग विद्यमान हैं।

बड़े उद्योग

(१) सूती व्यवसाय :—राज्य में ७ मिलें थीं परन्तु १ नवम्बर सन् १९५६ में अजमेर राज्य के विलयन हो जाने से इनकी संख्या बढ़ कर ११ हो गई है। इनमें कुल ३ करोड़ की पूंजी लगी हुई है और वे प्रतिवर्ष ४ करोड़ गज कपड़ा और ९ करोड़ पौंड़ सूत तैयार करती हैं।

राज्य में २५ कारखाने मोजे बनियान आदि के हैं और ७१ कपास तोड़ने की मिलें हैं।

(२) चीनी उद्योग:—राज्य में दो चीनी के कारखाने हैं। (१) गंगानगर (२) भूपाल सागर जिसमें सन् १९५१-५२ में लगभग २४ लाख मन गन्ना, ७॥ हजार टन चीनी पैदा हुई है। इसके अतिरिक्त १० खंडसारी के कारखाने हैं, परन्तु अजमेर के विलयन के पश्चात् शक्कर की एक मिल और बढ़ गई है। वह विजयनगर में है।

(३) सीमेन्ट उद्योग :—राज्य में दो सीमेन्ट फैक्ट्रियां लाखेरी एवं सवाई माधोपुर में हैं, जिनमें प्रतिवर्ष करीब ६ लाख टन सीमेन्ट तैयार किया जाता है।

(४) कांच उद्योग :—राज्य में ७ कांच के कारखाने हैं, जो जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर, जयपुर व धौलपुर में है। इनमें अन्तिम धौलपुर व उदयपुर के कारखाने चालू है, बाकी बन्द हैं।

(५) रबर :—रबर के गेंद खिलौने तथा साइकिलों के पैडल आदि बनाने के कारखाना कोटा में है, जिसमें दो लाख के रुपये के मूल्य का वार्षिक उत्पादन होता है।

(६) दियासलाई उद्योग :—राज्य में तीन कारखाने हैं। (१) फतहनगर (२) कोटा (३) धौलपुर में स्थित है। इनमें से कोटा मैच फैक्ट्री चालू है।

(७) हड्डी पीसने का कारखाना :—राज्य में पांच हड्डी पिसने के कारखाने हैं, जिनमें २०० टन हड्डियां प्रतिदिन पीसी जाती है।

(८) वालवियरिंग उद्योग :—जयपुर में बिड़ला ब्रदर्स द्वारा स्थापित १ करोड़ की लागत का कारखाना भारत में सर्वप्रथम है। इसमें ४०० मजदूर प्रतिदिन काम करते हैं।

(९) सोडियम सल्फाइट :—जोधपुर में स्थित पांच टन सोडियम सल्फाइट प्रतिदिन तैयार करने वाला सबसे बड़ा कारखाना है।

(१०) पेन्ट व वारनिश :—एक कारखाना अलवर में है। इसमें प्रति पाली ५ टन पेन्ट, २ टन, वारनिश, २ टन सूखे रंग और २०० मन तेल प्रतिमास तैयार होता है।

(११) तेल उद्योग :—राज्य में ३८ मिलें है व २१० शक्ति संचालित कोल्हू है। तेल की ३५ मीलें हैं।

(१२) अन्य :—राज्य में ७ होजरी मिल्स, ६ शराब के कारखाने, १५ जनरल इंजीनियरिंग के कारखाने, २९ सरकारी व गैर-सरकारी बिजली घर, कई वर्क्स शौप, कई चक्कियां, चावल व दाल की मिलें, बिस्कुट व मिठाइयों के कारखाने, सोड़ा लेमन के कारखाने, गलीचा बनाने के, और चमड़े के सामान आदि बनाने के कारखाने हैं।

राज्य में विभिन्न प्रकार के उद्योग-धन्धे होते हुए भी अविकसित होने के निम्नलिखित कारण हैं :—

(१) शक्ति के साधनों का अभाव (२) यातायात परिवहन की कमी (३) बैंकिंग व वित्त व्यवस्था का अच्छा न होना (४) अशिक्षा (५) जल और कच्चे माल की कमी (६) यहां के निवासियों की उदासीनता और (७) सरकारी उदासीनता।

इस पृष्ठ भूमि को देखने से राजस्थान की आर्थिक समस्याओं का कुछ आभास हो जायेगा और यह भी प्रतीत होगा कि अनेक प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद राजस्थान आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हो सकता है। द्वितीय योजना में औद्योगिक व आर्थिक विकास की सम्भावनाएं वस्तुतः बहुत हैं, किन्तु उनकी चर्चा किसी आगामी अंक में।

—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(पृष्ठ ४४६ का शेष)

एक सुदृढ़, सुव्यवस्थित तथा प्रौढ़ स्थिति लायेगी और प्रगतिशील आर्थिक रुकावटों को दूर करेगी।

प्रथम तथा द्वितीय पंच वर्षीय योजनाओं के अनुसार जमींदारों और काश्तकारों का अन्त कर दिया जायेगा। वर्तमान कानून के अनुसार भूमि पर उसी का स्वामित्व रहेगा, जो उसे जोतेगा। जमींदारों का मुआवजा (Compensation) दीर्घकालीन बाण्ड में निश्चित कर दिया गया है।

भूमि व्यवस्था में प्रगतिशील सुधार लाने का श्रेय श्री विनोबा भावे को है। उन्होंने जमींदारों को प्रकाश का मार्ग दिखलाया और वे अपनी भूमि का 'दान' करने लगे। संत विनोबा अपने उद्देश्य में सफल हुए और 'भूदान आंदोलन' की नींव डाली। पैदल यात्रा कर उन्होंने ५ करोड़ एकड़ भूमि एकत्रित करने का निश्चय किया है, जो भूमि हीन कृषकों को दे दी जायेगी, 'भूदान यज्ञ' के द्वारा भी भूमि की समस्या एक सीमा तक सुलझायी जा सकती है।

अन्त में प्रश्न उठता है कि किस आधार पर भूमि-व्यवस्था का निर्माण हो। हमारे देश के लिए सहकारिता खेती सबसे उपयुक्त है। सहकारी कृषि की व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति के खेत उसी के स्वामित्व में रहते हैं, परन्तु उनकी जुताई सहकारी समिति की अध्यक्षता में की जाती है। उपज का वितरण प्रत्येक कृषक के खेती के भाग के अनुसार किया जाता है। इस प्रणाली में वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया जाता है। पूर्वी पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में सहकारिता खेती की जा रही है। पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिकता-कृषि को भारतीय भूमि की व्यवस्था का अंतिम लक्ष्य माना गया है। यह ठीक है कि इस दशा में सफलता बहुत कम मिल रही है, परन्तु यह आशा की जाती है कि भविष्य में भूमि सम्बन्धी सभी समस्याओं का पूर्ण रूप से समाधान हो जायेगा।

हिन्दी और मराठी भाषा में प्रकाशित होता है।

उद्यम

सर्वोपयोगी हिन्दी उद्यम प्रतिमाह १५ तारीख को पढ़िये

अब प्रतिमास 'उद्यम' में नावीन्यपूर्ण सुधार देखेंगे

— नई योजना के अन्तर्गत 'उद्यम' के कुछ विषय —

विद्यार्थियों का मार्गदर्शन—परीक्षा में विशेष सफलता प्राप्त करने के तथा स्वावलम्बी और आदर्श नागरिक बनने के मार्ग।

नौकरी की खोज में—यह नवीन स्तम्भ सबके लिए लाभदायक होगा।

खेती-बागवानी, कारखानेदार तथा व्यापारी वर्ग—खेती-बागवानी, कारखाना अथवा व्यापारी-धन्धा इन में से अधिकाधिक आय प्राप्त हो, इसकी विशेष जानकारी।

महिलाओं के लिए—विशेष उद्योग, घरेलू मितव्ययिता, घर की साजसज्जा, सिलाई-कढ़ाई काम, नए व्यंजन।

बाल-जगत्—छोटे बच्चोंकी जिज्ञासा तृप्ति हो तथा उन्हें वैज्ञानिक तौर पर विचार करनेकी दृष्टि प्राप्त हो इसलिए यह जानकारी सरल भाषा में और बड़े टाइप में दी जाएगी।

'उद्यम' का वार्षिक मूल्य रु० ७।- भेजकर परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को उपयोगी यह मासिक-पत्रिका अवश्य संग्रहीत करें।

उद्यम मासिक १, धर्मपेठ, नागपुर-१

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्र.४१ प्रतिशत आय-कर से मुक्त

नये १२-वर्षीय नेशनल प्लान सेविंग्ज़ सर्टीफिकेट खरीदिये

और ५.४१ प्रतिशत आय-कर से मुक्त ब्याज प्राप्त कीजिये।

प्रति १०० रु० जो आप इन सर्टीफिकेटों में लगाते हैं, १२ वर्ष की अवधि में १६५ रु० हो जाते हैं। ये सर्टिफिकेट डाकघरों से प्राप्य हैं।

आपकी बचतों से अब अधिक आय

१०-वर्षीय ट्रेजरी सेविंग डिपाजिट सर्टीफिकेट्स

समय पूर्ण होने पर आय-कर मुक्त ४% ब्याज मिलता है। आपको ब्याज प्रति वर्ष दिया जाता है

पोस्ट आफ़िस सेविंग्ज़ बैंक डिपाजिट्स

ब्याज की दर प्रति वर्ष २½% है।

नेशनल सेविंग्ज़ आर्गनाइज़ेशन

DA—57/82

सम्पादक—कृष्णचन्द्र विद्यालंकार द्वारा अशोक प्रकाशन मन्दिर के लिए अर्जुन प्रेस दिल्ली से मुद्रित व प्रकाशित।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'सम्पदा' का आगामी विशेषांक

समाजवाद अंक

- आपके पुस्तकालय में संग्रहणीय
- अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी
- समाजवाद के प्रेमियों के लिए विश्वकोष
- साधारण जनता के लिए ज्ञानवर्धक

इसकी कुछ विशेषताएं :

★ समाजवाद की पृष्ठभूमि, दार्शनिकता इतिहास, सफलता व असफलताओं पर विद्वत्तापूर्ण लेख
★ विविध देशों में समाजवाद के परीक्षण
★ भारत समाजवाद की ओर
★ समाजवादी नेताओं के मनोरम चित्र
★ समाजवाद-सम्बन्धी प्रगति के ग्राफ़, चार्ट व तालिका आदि, आदि

[प्रस्तावित विषय सूची पृष्ठ ४२५ पर पढ़िये ।]

यह अङ्क हाथों हाथ बिक जायगा, इसमें सन्देह नहीं।
इसलिए अभी से अपनी कापी
१॥) रु० भेज कर रिजर्व करा लीजिये ।

— मैनेजर सम्पदा
अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिल्ली ६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्पदा

समाजवाद अंक

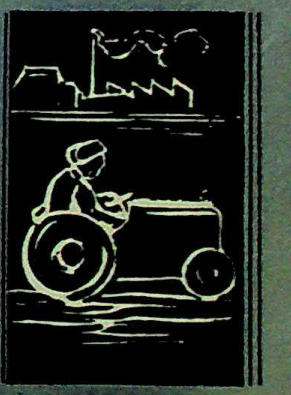

प्रकाशन मन्दिर रोशनारा रोड दिल्ली

मूल्य १.५०

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

एनडाउमेंट पालिसी

आप अपना भविष्य खुद बनाते हैं !

आयु बीमा आपके जीवनकी जरूरत है । आप अपने जीवन काल में ही आयु बीमा के सारे लाभ पा सकते हैं। इसलिए एनडाउमेन्ट पालिसी जीवन काल में सारे लाभ प्रदान करने के लिए एक आदर्श बीमा—योजना है।

एनडाउमेंट पालिसी में, **होल लाइफ पालिसी** से फर्क है। **होल लाइफ पालिसी** का भुगतान, मृत्यु के बाद ही हो सकता है, और **एनडाउमेंट पालिसी** में आपको गिने हुए वर्षों तक प्रीमियम जमा करने के बाद बीमा का पूरा रुपया अदा हो जाता है। (यदि दुर्भाग्य से इन गिने हुए वर्षों के अन्दर ही मृत्यु हो जाये, बीमा की पूरी रकम आप द्वारा नियुक्त किए हुए वारिस को ही मिलेगी।)

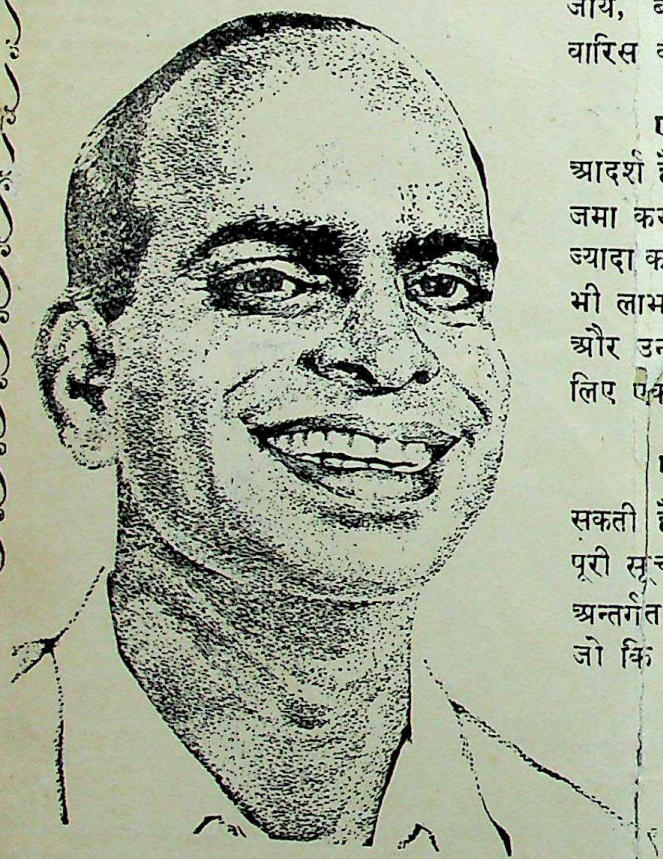

एनडाउमेंट पालिसी मध्यवर्गीय लोगों के लिए आदर्श है; जो अपनी वृद्धावस्था के दिनों के लिए रुपये जमा करना चाहते हैं; या अपने प्राविडेन्ट फण्ड को ज्यादा करना चाहते हैं। यह पालिसी उन लोगों के लिए भी लाभदायक है, जो भविष्य में अपने बच्चों की शिक्षा और उनके विवाह का या किसी और तरह के खर्च के लिए एक साथ थोक रकम चाहते हैं।

एनडाउमेंट पालिसी आपको भी फायदा पहुंचा सकती है। लाइफ इन्श्योरेन्स एजेन्ट से इसके लिए पूरी सूचना मांगिये, वह आपको एनडाउमेस्ट ग्रुप के अन्तर्गत और भी पालिसियों के विषय में बतायेगा, जो कि आपकी आवश्यकता के लिए उचित होंगी।

लाइफ़ इन्श्योरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इन्डिया

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

THE VISCOUNT IS HERE!

Already in service with 18 of the world's leading airlines, the Vickers VISCOUNT offers you unparalleled speed and comfort.

VICKERS VISCOUNT TURBO-PROP AIRLINER JOINS I.A.C. FLEET

THE FIRST OF TEN THAT WILL FLY IN YOUR SERVICE

THE FIRST of the ten Vickers Viscounts ordered by the I.A.C. to bring turbo-prop flying to India, is now here—to offer faster, finer air travel than ever before. The Viscount will operate on the Delhi/Calcutta, Calcutta/Rangoon routes from 10th October 1957. More Viscounts will soon be arriving and ultimately all I.A.C.'s major routes will operate with them.

NO VIBRATION Because it is powered by *turbo-props*, the Viscount is free from irritating vibration —gives you a really smooth flight

NO NOISE You get almost perfect quiet in the sound-proofed cabin of the Viscount. It's fully-pressurised too...and comfortable as in your own home!

ABOVE THE WEATHER Cruising at 20,000 feet, the Viscount seldom encounters bad weather...it actually flies *above* the clouds!

QUICKER Flying at over 300 miles per hour, the Viscount gets you there much faster, thanks to its four powerful Rolls-Royce engines

LUXURY Adjustable armchairs and large panoramic windows add to passenger comfort. You really enjoy your trip

INDIAN AIRLINES CORPORATION

VICKERS-ARMSTRONGS (AIRCRAFT) LIMITED

Represented in India by:

Vickers India Private Limited,
Killick House, Home Street, Bombay 1.

The new VISCOUNTS will fly on I.A.C.'s Delhi/Bombay/Karachi, Bombay/Calcutta, Delhi/Hyderabad/Madras/Calcutta, Bombay/Madras/Tiruchirapalli/Colombo and Calcutta/Delhi/Srinagar routes.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लोहे और इस्पात के निर्माण में उन्नति

मुकन्द

मुकन्द आयल एण्ड स्टील वर्क्स लिमिटेड

कुर्ला, बम्बई—३७

—मैनेजिंग एजेन्ट्स—

जीवन प्राइवेट लिमिटिड

५१, महात्मा गांधी रोड, बम्बई—१

दी बोम्बे स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि०

९, बेक हाउस लेन, फोर्ट, बोम्बे—१

(१९११ में स्थापित)

चैयरमैन : श्री रमणलालजी, सरैया ओ० बी० ई०

इस बैंक में जमा किये हुए रुपये से भारत के किसानों तथा सहकारी संस्थाओं को सहायता मिलती है ।

हिस्सेदारों की परिदत्त पूंजी :—			कुल डिपाजिट
हिस्सेदारों द्वारा खरीदी गई—		४०,११,५०० रु०	१०,७१,३३,२०० रु०
बम्बई सरकार द्वारा खरीदी गई	३१,००,००० रु०	७१,११,५०० रु०	सक्रिय पूंजी
			१७,६३,७३,००० रु०
रिजर्व तथा अन्य कोष	५९,२८,१०० रु०		

११ जिलों में ५६ शाखाएं

भारत के सब प्रमुख नगरों में रुपया एकत्र करने की व्यवस्था है । सभी प्रकार के डिपाजिट स्वीकार किये जाते हैं । प्रार्थना-पत्र भेजकर शर्तें मंगाइये ।

जी० एम० लाड

मैनेजिंग डायरैक्टर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

क्यों

लोग अधिक से अधिक सूटिंग के कपड़े

ग्वालियर रेयन

के ही बने हुए खरीदते हैं।

- **अरिस्टोक्रैट, डिप्लोमैट, डैमोक्रैट और इलाइट**
  सबसे अधिक प्रशंसित सूटिंग्स जो भारत में तैयार किये गये हैं।
- क्वालिटी, स्टाइल, खटाऊपन और बचत का पूरा-पूरा ध्यान रक्खा गया है।
- सारा दिन पहनने पर भी ये मुलायम सूटिंग्स कड़े व बिना सिलवट के रहते हैं।
- तरह-तरह के आकर्षक रंगों में प्राप्त। धूप और धुलाई में पक्के रंगों की गारंटी।
- शानदार सूटिंग्स उचित मूल्य पर।

और यह भी याद रखिये.....

- ड्राई क्लीनिंग की आवश्यकता नहीं। घर पर गुनगुने पानी और साबुन की झाग से सरलता से धोये जा सकते हैं। साफ़ पानी में अच्छी तरह खंगालने के पश्चात् बिना मरोड़े निचोड़ दीजिये। छाया में सुखा कर हल्की गर्म प्रेस से स्त्री कर लीजिये।

फ़ैशन में सब से आगे!

ग्वालियर रेयन सिल्क मैन्यू. (वी.) कं. लि०,
बिरला नगर—ग्वालियर
सभी मशहूर दुकानों पर प्राप्त

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

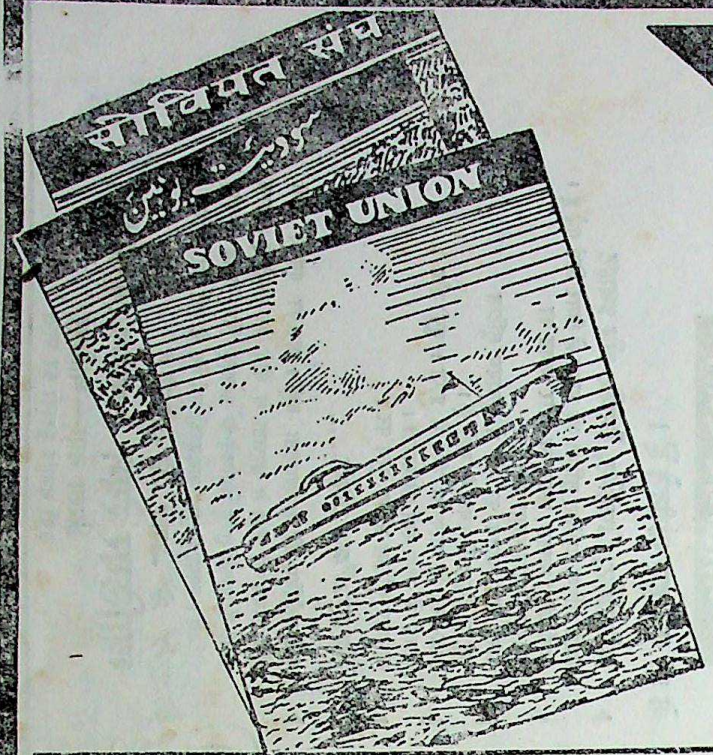

READ

SOVIET UNION NO 8

SEEK THE ANSWERS

What is a "winged ship"

What did American Tourist Farmers see in a Collective Farm

What are the Soviet Rocket builders doing to pave the way into the cosmos

What is the latest work of film producer Grigory Roshal

What agricultural machines work in the Soviet fields

Where do Soviet working people spend their leave

AND MUCH MORE...

Subscription :
Yearly
Rs. 6.75 n.P.
Half yearly
Rs. 3.37 n.P.
Single Copy
75 n.P.

Available with :
People's Publishing House
5, Jhandewalan, N. DELHI.
Jayana Book Depot
Chhappar wala kua, Karolbagh
N. DELHI.

V/O MEZDUNARODNAYA KNIGA, Moscow 200, U.S.S.R.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उत्तर प्रदेश सरकार के अभिनव प्रकाशन

हिन्दी पुस्तक-प्रकाशन योजना के ग्रन्थ

१. भारतीय ज्योतिष का इतिहास	डा० गोरखप्रसाद	४)
२. तत्व ज्ञान	डा० दीवानचन्द	४)
३. हिन्दू गणित शास्त्र का इतिहास (अनुवाद)	डा० विभूतिभूषण दत्त तथा डा० अवधेश नारायणसिंह	३)
४. अरिस्तू की राजनीति (अनुवाद)	श्री भोलानाथ शर्मा	८)
५. उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म का विकास	डा० नलिनाक्षदत्त तथा श्री कृष्णदत्त वाजपेयी	६)
६. डेवलपमेंट आफ बुद्धिज्म इन उत्तर प्रदेश	उक्त पुस्तक का अंग्रेजी संस्करण	८)
७. सामाजिक पोषण	डा० बूलचन्द	३)
८. संस्कृति का दार्शनिक विवेचन	डा० देवराज	६)
९. संस्कृत आलोचना	डा० बलदेव उपाध्याय	४)
१०. पश्चिमी दर्शन	डा० दीवानचन्द	४)
११. स्वतन्त्र दिल्ली	डा० सैयद अतहर अब्बास रिजवी	४)
१२. भारतीय ज्योतिष (अनुवाद)	श्री शिवनाथ झारखण्डी	८)
१३. भारतीय दर्शन	डा० उमेश मित्र	८)

सूचना-विभाग के कुछ ग्रन्थ

१. बुद्ध चित्रावली	६) रु०	न० पै०
२. चाचा नेहरू	१) रु०	
३. उत्तर प्रदेश में लोक नृत्य	१) रु०	
४. राष्ट्रीय कविताएं		५०
५. नग्मए आजादी		२५
६. नग्मए आजादी (उर्दू)		२५
७. आजादी के तराने		१२
८. भारतीय बुद्धिजीवी		७५
९. समाजवाद		७५
१०. ग्लोरीज आफ उत्तरप्रदेश	८ रु०	
११. स्पार्क्स फ्राम ए गवर्नर्स एन्विल (प्र० भा०)	५ रु०	
१२. स्पार्क्स फ्राम ए गवर्नर्स एन्विल (द्वि० भा०)	८ रु०	
१३. दि ट्रायल आफ अवर डेमोक्रेसी		७५
१४. इण्डियन इन्टेलेक्टुअल्स		७५
१५. एन एक्सपेरिमेन्ट इन साइल लेण्डस कल्टिवेशन		२५

कृपया व्यावसायिक नियमों और सीधे खरीददारी के लिए लिखें :

१—प्रकाशन ब्यूरो, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

२—सूचना साहित्य, फरीदी बिल्डिंग, हजरतगंज, लखनऊ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हम

पंजाब की सर्वश्रेष्ठ रुई

प्रयोग में लाते हैं

हमारे यहां ५००० व्यक्ति काम कर रहे हैं

हम सालाना ३४००००० व्यक्तियों की
आवश्यकता पूरी करते हैं

व्यापारी व उपभोक्ता

को
समान लाभप्रद है

दि

बिड़ला काटन स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि०

बिड़ला लाइन्स,
देहली—६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हिन्दी संसार को 'सम्पदा' के सात सुन्दर उपहार

सम्पदा के सभी विशेषांक पुस्तकालय में रेफरेंस-बुक की दृष्टि से रखने योग्य हैं।

योजना-अंक (भारत की पंचवर्षीय योजना पर प्रामाणिक व ज्ञानवर्धक सामग्री)

Hindi readers will benefit immensely from the publication. —Organiser

The best guide for digesting and understanding the economic situation of the country. —Commerce & Industry

भूमि-सुधार-अंक (भारत की भूमि-सम्बन्धी समस्याओं पर अद्भुत अङ्क)

...All this makes this number almost a reference number and deserves a place in all libraries and on every social worker's and patriot's table. —मरहट्टा (पूना)

वस्त्र उद्योग-अंक (भारत के प्रमुख उद्योग पर प्रामाणिक जानकारी)

इस अंक के पीछे काफी श्रम किया गया है। सम्पादक को बधाई! —घनश्यामदास बिड़ला

मजदूर-अंक (मजदूर समस्या का विशद एवं तथ्यपूर्ण विवेचन)

लेख बहुत रोचक व उपयोगी हैं। लेखों में केवल भौतिक व आर्थिक दृष्टिकोण ही नहीं है, मानव की नैतिकता पर भी जोर दिया गया है, जो देश की संस्कृति व परम्पराओं के अनुकूल है। —मान. खण्डूभाई देसाई, केन्द्रीय श्रममंत्री

उद्योग-अंक (भारत के प्रमुख उद्योगों के विकास पर तथ्यपूर्ण जानकारी)

सम्पदा ने विशेषांकों की स्वस्थ परम्परा स्थापित की है। इस अंक में भी अत्युपयोगी सामग्री का संकलन हुआ है। —विश्वज्योति

राष्ट्रीय विकास-अंक (द्वितीय पंचवर्षीय योजना का पूर्ण परिचय)

उत्कृष्ट और ज्ञानवर्धक उपयोगी अंक के लिए बधाई। —प्रो. रामनरेशलाल

बैंक-अंक (भारतीय बैंकों व उनकी समस्याओंका परिचय)

Here is one more Sampada special worth treasuring as a source of ready reference. —Organiser

सब अङ्कों का पृथक पृथक मूल्य १।) रु० है। सातों अङ्क रजिस्ट्री से केवल ७।) रु० में। १९५२, १९५३, १९५४ और १९५५ की कुछ फाइलें भी मिल सकती हैं।

मूल्य ८) प्रति वर्ष शिक्षणालयों से ७ रु०

मैनेजर—'सम्पदा' अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिल्ली।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विषय-सूची

संख्या	विषय	पृष्ठ
१.	समाजवाद : कुछ प्रश्न (सम्पादकीय)	५४७
२.	हम और समाजवाद —पं० जवाहरलाल नेहरू	५५०
३.	समाजवाद और सर्वोदय योजना —आचार्य विनोबा	५५१
४.	समाजवाद, साम्यवाद और गांधीवाद —श्री जयप्रकाश नारायण	५५३
५.	समाजवाद के सात सिद्धान्त—श्री श्रीमन्नारायण	५५४
६.	समाजवाद की विवेचना —प्रो० विश्वम्भरनाथ पांडेय	५५५
७.	मार्क्सवाद पर आक्षेप और उसका समाधान	५५६
८.	यूरोप में समाजवाद का जन्म —कृष्णचन्द्र विद्यालंकार	५६४
९.	साम्यवाद का विकास	५६५
१०.	रूस में समाजवादी क्रांति और उसके बाद	५६८
११.	समस्त संसार समाजवाद की ओर	५७०
१२.	हमारी चित्रावली	५७१-५७४
१३.	समाजवाद के विभिन्न रूप—श्री राजनारायण गुप्त	५७४
१४.	समाजवाद क्या है —श्री मदनमोहन बिष्ट	५८१
१५.	समाजवाद क्यों ? —श्री एम. एन. राय	५८३
१६.	मार्क्स और हिंसा —श्री नागेश्वरप्रसाद	५८४
१७.	समाजवाद की दिशा में भारत की तीव्र प्रगति	५८५
१८.	भारत की समाजवादी पद्धति —श्री एच. एम. पटेल	५८८
१९.	कांग्रेस व राष्ट्रीयकरण की नीति —श्री उ. न. ढेबर	५९१
२०.	समाजवाद कांग्रेस के प्रस्तावों में	५९४
२१.	प्रजा समाजवादी दल	५९६
२२.	भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी	५९८
२३.	मैं क्या मानता हूँ ? —श्री एन. आर. मलकानी	६००
	—श्री हरिभाऊ उपाध्याय	६०१
	—श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन	६०२
	—श्री जैनेन्द्र कुमार	६०३
२७.	समाजवाद तब तक स्थापित नहीं हो सकता	६०४
२८.	वैदिक समाजवाद—श्री प्रियव्रत वेदवाचस्पति	६०९
२९.	भारतीय समाजवाद में वैयक्तिक स्वातन्त्र्य —श्री रामनरेशलाल	६११
३०.	महान् क्रांति की महान् सफलताएं	६१७
३१.	साम्यवाद का व्यावहारिक स्वरूप	६२३
३२.	समाजवाद की ओर चीन के बढ़ते चरण	६२८
३३.	यूगोस्लेविया में समाजवाद का नया परीक्षण	६३२
३४.	अमेरिका में जनता का पूंजीवाद —श्री वेदप्रकाश	६३५
३५.	कम्यूनिज्म कम्यूनिज्म है, साम्यवाद नहीं	६३९
३६.	साम्यवाद के सैद्धांतिक आदर्श मिथ्या	६४०
३७.	समाजवाद—अधिनायक तंत्र का मार्ग —श्री सी. एल. धीवाला	६४१
३८.	मार्क्स की भविष्यवाणी मिथ्या	६४५
३९.	समाजवाद में भी मजदूर दास	६४७
४०.	राष्ट्रीयकरण और मजदूर	६४८
४१.	साम्यवाद व धर्म	६५०
४२.	सर्वोदय का द्वितीय चरण—सम्पत्तिदान —श्री ओमप्रकाश तोषनीवाल	६५१
४३.	ग्रामदान —श्री श्रीमन्नारायण	६५३
४४.	ग्रामदान से समाजवाद सम्भव	६५५
४५.	बनिया हाकिम गजब खुदा का —श्री सत्यप्रकाश मिलिन्द	६५८
४६.	यातायात उद्योग : नया कदम	६६०
४७.	पंचवर्षीय योजना व समाजवाद	६६२
४८.	यह समाजवाद अंक	६६३

सम्पदा

सम्पादकीय परामर्शमण्डल

१. श्री जी० एस० पथिक

२. श्री महेन्द्र स्वरूप भटनागर

वार्षिक मूल्य ८)

,, ,, (शिक्षणालयों से) ७)

एक प्रति का मूल्य ७५ नये पैसे

बम्बई में हमारे प्रतिनिधि—श्री टी० एन० वर्मा, नेशनल हाउस, २री मंजिल, टुलक रोड, बम्बई-१

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार का पता—कृष्णचन्द्र विद्यालंकार, अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिल्ली-६

प्रबन्ध सम्बन्धी पत्रव्यवहार का पता—मैनेजर सम्पदा, अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिल्ली-६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

समाजवाद विशेषांक

सम्पदा

वर्ष ६] अक्तूबर—नवम्बर १९५७ [अङ्क १०-११

समाजवाद : कुछ प्रश्न

समाजवाद, समाजवादी समाज अथवा सहकारिता की पद्धति से मुक्त समाजवाद आज के नेताओं, और विधायकों द्वारा स्वीकृत लक्ष्य के रूप में हमारे सामने हैं। शासन का प्रत्येक अधिकारी, और सार्वजनिक नेता यह मानकर चलने लगा है कि समाजवाद हमारा लक्ष्य है और उस दिशा में भारत को जल्दी से जल्दी प्रगति करनी है। जितनी नई योजनाएं बनती हैं, जितने नये कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाते हैं, जितने आर्थिक विधेयक पेश किये जाते हैं, उन सब का उद्देश्य देश को समाजवाद की दिशा में आगे ले जाना बताया जाता है। आज समाजवाद का ध्येय स्वयंसिद्ध सत्य का रूप धारण कर चुका प्रतीत होता है, विवाद की कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं दीखती।

× × ×

समाजवाद के ध्येय की प्रायः सर्वसम्मत स्वीकृति का अर्थ यह नहीं है कि इस प्रश्न पर अब कोई विवाद आवश्यक नहीं रह गया। सच तो यह है कि इस आदर्श की स्वीकृति के बाद ही इसका रूप अधिक विवादास्पद बन गया इसके अवान्तर अनेक प्रश्न अत्यन्त विवादास्पद रूप में विचारकों के सामने आ रहे हैं। समाजवाद का अर्थ क्या है? रूप क्या है? इस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए किस गति से हमें बढ़ना चाहिए? किस नीति और किन उपायों का अवलम्बन करना चाहिए? समाजवादी समाज में व्यक्ति और समाज का परस्पर सम्बन्ध क्या रहना चाहिए? विभिन्न देशों में समाजवादी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या किया गया और उन्हें इस लक्ष्य तक पहुँचने में कितनी सफलता प्राप्त हुई? कितनी कठिनाइयों को पार करना पड़ा? फिर क्या भारत की अपनी संस्कृति, परम्पराएं और आज के हमारे जातीय स्वभाव समाजवाद को किस रूप में और कहां तक स्वीकार करने को उद्यत है? इन सब प्रश्नों पर गंभीरता के साथ शांतिपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। हमें यह भी देखना है कि पिछले दो चार वर्षों में हमने समाजवाद के जिस लक्ष्य की घोषणा की है, उसके लिए हम स्वयं कितनी सामर्थ्य रखते हैं और जनता को कहां तक तैयार कर पाये हैं?

× × ×

इन सब प्रश्नों पर विचार करते हुए हमें दो बातें स्पष्ट

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कर लेनी चाहिए। एक तो यह कि केवल भावुकता या आकर्षक शब्दों के मोह में पड़कर किसी प्रश्न पर हम ठीक विचार नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात यह कि हमें यह न भूलना चाहिए कि समाजवाद स्वयं ध्येय या लक्ष्य नहीं है, यह एक साधन मात्र है देश के जन-जन की उन्नति व सुख समृद्धि का। हमारा उद्देश्य देश की सर्वांगीण उन्नति है, जिसमें सभी देशवासी खुशहाल व सुखी हों। इस मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति जिस उपाय या साधन से हो, वही साधन हमें स्वीकार्य होगा। इसे यदि हम स्वीकार कर लें तो फिर किसी रीति विशेष, वाद या 'इज्म' का हम आग्रह नहीं करेंगे। जब तक हम पक्षपात और दृढ़ आग्रह को छोड़ कर जनहित के मुख्य उद्देश्य पर विचार नहीं करेंगे, तब ठीक दिशा में विचार ही नहीं सकेंगे। समाजवाद पर हमें इसी व्यापक और उदार दृष्टि से विचार करना है। समाजवाद या साम्यवाद की सैकड़ों व्याख्याएं हो चुकी हैं, परन्तु इन सब में एक समान बात यह है कि केवल व्यक्ति की दृष्टि से हम अपनी नीति निर्धारित न करें, समस्त समाज के हित को सामने रखें। देश की समस्त अर्थ पद्धति व नीति की कसौटी केवल व्यक्ति का हित न हो, समाज का हित हो।

× × ×

जब हम समाज-हित का नाम लेते हैं, तभी एक नया गंभीर प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि व्यक्ति और समाज का परस्पर सम्बन्ध क्या है? समाज व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर हावी तो न हो जायगा? जिस तरह संसार की अनेक राजनैतिक, धार्मिक और आर्थिक संस्थाएं समय-समय पर रूढ़ि बनकर अपने-अपने स्वरूप की रक्षा करने के लिए व्यक्ति के हित की उपेक्षा करने लगीं और जिनके विरुद्ध समय-समय पर महान् जननायकों को क्रान्ति या विद्रोह का नारा बुलन्द करना पड़ा, हमारा समाजवाद वही रूप तो धारण न कर लेगा? समाज का हित ऊंचा आदर्श है, पर समाज जिन अवयवों से बना है, संघटित हुआ है, उन्हीं की उपेक्षा करने लगेगा, तो वह समाज भी बहुत वांछनीय न रहेगा और उसके विरुद्ध भी विद्रोह स्वाभाविक हो जायगा। व्यक्ति और समाज का समन्वय करके हम आगे चल सकेंगे। उन्नीसवीं सदी के महान् भारतीय विचारक ऋषि दयानन्द ने आर्य समाज के नियम बनाते हुए इस सिद्धान्त को सुन्दर शब्दों में व्यक्त किया है—

"प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, परन्तु सब की उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए।"

इस उदार व व्यापक दृष्टि से हमें समाजवाद के प्रश्न पर विचार करना होगा। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि एक ओर जहां हम यह देखें कि समस्त शक्ति कुछ व्यक्तियों में इतनी केन्द्रित न हो जाय कि जनसामान्य का शोषण होने लगे, वहां यह भी देखना होगा कि समस्त शक्ति समाज या राज्य की संस्था के पास भी इस रूप में केन्द्रित न हो जाय कि व्यक्ति राज्यरूपी मशीन का निर्जीव पुरजा बन कर रह जाय और वह सब कार्यों के लिए, अपनी रोटी, पानी और कपड़ों तक के लिए परमुखापेक्षी बन जाय।

× × ×

संसार के भिन्न-भिन्न देशों में दोनों प्रकार के परीक्षण हुए हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका आदि में पूंजीवाद की पद्धति खूब फूली फली। अन्य देशों ने भी इसका अनुसरण किया। भारत में भी इस प्रणाली का विकास हुआ और इसमें सन्देह नहीं कि विश्व की आर्थिक व भौतिक सभ्यता के विकास में इस संस्था का असाधारण महत्व रहा है। यदि व्यक्तिगत लाभ की प्रबल प्रेरणा न होती तो इसमें संदेह है कि आज संसार वैज्ञानिक और आर्थिक साधनों से इतना सम्पन्न होता। स्वयं भारत के उद्योगपति ब्रिटिश शक्ति व शासन की विपरीत स्थितियों में जिस तरह उद्योग को ऊंचे स्थान पर ले आये, वह अत्यन्त प्रशंसनीय है। दूसरी ओर रूस ने १९१७ में समाजवादी समाज की दिशा में जो महान् परीक्षण किया और पिछले दशक में पूर्वी यूरोप तथा चीन ने जिसे अपनाया, वह भी कम महत्व नहीं रखता। आज इन देशों ने आर्थिक क्षेत्र में असाधारण उन्नति कर ली है। हमें समाजवादी लक्ष्य पर पहुँचने का स्वप्न लेते समय इन दोनों परीक्षणों को सामने रखना होगा। दोनों पद्धतियों के गुण-दोषों की विवेचना किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह छोड़कर करनी होगी।

× × ×

यह एक सत्य है कि आज बदलते हुए समय व बद-

[समदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लती हुई परिस्थितियों में पूंजीवाद न उन्नीसवीं सदी का पूंजीवाद रहा है और न मार्क्सवाद या रूस में प्रथम घोषित समाजवाद रहा है। दोनों ने समय के अनुकूल अपने को बदला है और उसके परिणामस्वरूप दोनों एक-दूसरे के निकट आने को विवश हुए हैं। पूंजीवादी देशों में सामान्य जन के प्रति सहानुभूति की भावना पैदा हो चुकी है या विवश होकर उन्हें स्वीकार करनी पड़ी है। मजदूर व किसान सम्बन्धी नित नये कानून, अमीरों पर बढ़ते हुए कर और मंगलकारी राज्य की जिम्मेदारी इसी की सूचक हैं। समाजवादी देश भी व्यक्ति को स्वतंत्रता देने की दिशा में झुकाव रखते प्रतीत हो रहे हैं। स्वयं रूस अपने कठोर आग्रह को छोड़ रहा है, चीन व यूगोस्लेविया अपनी परिस्थितियों के कारण पद्धति में परिवर्तन कर रहे हैं, पोलैण्ड व हंगरी आदि देशों में मजदूर सरकार. मशीनरी के निर्जीव पुरजे बनने के विरुद्ध विद्रोह कर रहे दीखते हैं। अमेरिका में भी जनसामान्य का स्तर बहुत ऊंचा करने की दिशा में बड़ा भारी परिवर्तन हो रहा है। इन पर दृष्टि डालने के बाद किसी वाद या 'इज्म' पर कठोर आग्रह करना अनावश्यक व अनुचित हो जाता है। हम अपने दीर्घकालीन इतिहास, दीर्घकालीन परम्पराओं व जातीय चरित्र की उपेक्षा करके चलेंगे, तो भयंकर गलती करेंगे। हमारा समाजवाद इन सबका समन्वय करके स्थापित हो सकेगा। हम दूसरों से सीखें, पर उनका अन्धानुसरण न करें, यह हमें स्मरण रखना चाहिए।

× × ×

इस दृष्टि से सर्वोदय की भारतीय परम्परा पर हमें गम्भीरता से सोचना चाहिए। श्री जयप्रकाश नारायण के शब्दों में सर्वोदय समाजवाद के दर्शन में अन्तिम शब्द है। आचार्य विनोबा व्यक्ति और समाज का सुन्दर समन्वय जिस रूप में करने को हमें परामर्श दे रहे हैं, वह बहुत अधिक विचारणीय है। मूल प्रश्न यह है कि जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या हो? वह यूरोप का भौतिकवादी हो, प्राचीन भारत का आध्यात्मिक हो अथवा इन दोनों का समन्वय? इस प्रश्न का अन्तिम उत्तर पाकर ही हम अपनी अर्थव्यवस्था के स्वरूप का निर्धारण कर सकेंगे। सत्ता और उद्योग का विकेन्द्रीकरण पूंजीवाद व समाजवाद दोनों की अच्छाइयों को ले लेता है। समाजवाद की अधिनायकता या मैनेजरशाही को छोटे उद्योगों में स्थान ही नहीं मिलेगा और न कुछ व्यक्तियों में इससे देश का धन केन्द्रित हो सकेगा।

× × ×

किसी पद्धति को अपनाते समय अपने साधनों की सीमा का भी हमें अवश्य विचार करना होगा। आज उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की नीति पर जिस तेजी से अमल हो रहा है, (समाजवाद का यही स्पष्ट रूप सबसे सुबोध है) उसे बिना अपनी सामर्थ्य व परिस्थितियों का विचार किये करेंगे, तो धोखा खावेंगे। पहली बात यह कि अभी इतना धन ही नहीं है कि सब उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जासके, जो थोड़े बहुत साधन हैं भी. उनका उपयोग नये उद्योगों में करना प्रथम आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि आज हमें अपनी योजना की पूर्ति के लिए जिस तरह विदेशों की सहायता अपेक्षित है, उसे देखते हुए राष्ट्रीयकरण की तीव्र प्रगति हानिकर हो सकती है और इससे भी बड़ी बात यह है कि आज देश की जनता इसके लिए तैयार नहीं है। अभी इसमें 'स्व' की भावना छोड़कर 'राष्ट्रहित' की वह भावना उत्पन्न नहीं हो पाई है, जो उसे पूर्ण निष्ठा के साथ सरकारी उद्योगों के संचालन में प्रेरित करे। सरकारी उद्योगों में भ्रष्टाचार, शिथिलता और अपव्यय आज राष्ट्रीय चरित्र के दोष हैं। आज तो राष्ट्रहित की अपेक्षा वर्गहित की भावना बढ़ रही है। मजदूर या किसान भी राष्ट्रहित के प्रति अपने उत्तरदायित्व को अनुभव नहीं कर रहे। नेताओं व शासकों में भी श्रेणीहीन समाज की भावना आज उत्पन्न नहीं हो सकी है। हमें समाजवाद के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार करनी है, तभी हम समाजवाद के ऊंचे लक्ष्य की ओर प्रगति कर सकेंगे।

—कृष्णचन्द्र विद्यालंकार

इसी विशेषांक की भांति सम्पदा के दूसरे विशेषांक भी ज्ञानवर्धक निकले हैं।

पृष्ठ ५४५ पर देखिये

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

समाजवाद और हम

(पं० नेहरू द्वारा मार्ग प्रदर्शन)

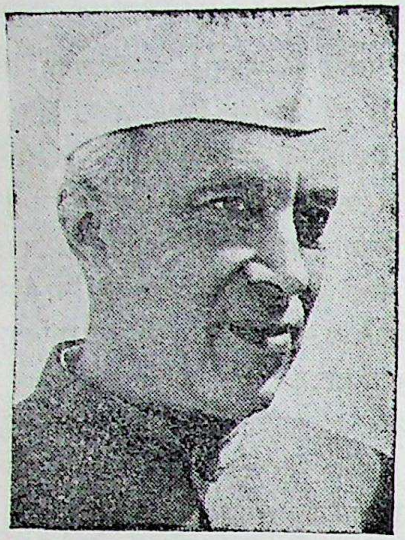

लोग साम्यवाद की बात कहते हैं। लेनिन की पुरानी परिभाषा के अलावा, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि प्राविधिक ज्ञान के हाथों में सत्ता आने पर साम्यवाद बिजली और सोवियतों का मिश्रण है, इसकी दूसरी परिभाषा है—बाहुल्य की सीमा तक उत्पादन करना। बेशक हर चीज की बहुलता ही कामयाबी लाती है। फिर उसे आप साम्यवाद कहिए, समाजवाद कहिए, या कोई भी वाद कहिए। वह क्रियाशील इसलिये होती है कि बहुलता क्रियाशील होती है। परेशानी तो अभाव से होती है। और साम्यवादी या समाजवादी सिद्धान्तों का औचित्य यही है कि आप उस सिद्धान्त या तरीके को अपनाकर बहुत जल्द बहुलता हासिल कर लेंगे न कि अभाव की हालत में रह कर उसे सिर्फ नियंत्रित करके। यह एक बहुत मामूली सा रास्ता है, जिस पर चलकर हम वहां पहुँच सकते हैं।

हमारा उद्देश्य है उत्पादन की व्यवस्था को सक्रिय कर देना, उसका निर्माण करना, ताकि हर तरह से वह ज्यादा दौलत पैदा कर सके। यह सबसे जरूरी बात है, क्योंकि हम भारत में गरीबी बांटना नहीं चाहते। गरीबी समाजवाद नहीं। इसलिए हमने सोचा कि मिश्रित अर्थ-व्यवस्था अपना लेने पर हम उत्पादन को सबसे ज्यादा बढ़ावा दे सकेंगे। हम उत्पादन के हर मुमकिन तरीके का इस्तेमाल करना चाहते हैं, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी उद्यम-हम कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहते जो हमारे उत्पादन बढ़ाने के रास्ते में रुकावट बने, क्योंकि हम चाहे चीजें पैदा करें या न करें, लेकिन हर साल ५० लाख के करीब मानव प्राणी तो पैदा करते ही हैं।

वास्तविक अर्थ

कुछ लोग सोचते हैं कि जो लोग लम्बे हैं, उनकी गर्दन उड़ा देना, और जिनके पास धन है, उनकी जेबें कतर लेना ही समाजवाद है। समाजवाद के बारे में इस प्रकार का सोचने का तरीका मूर्खतापूर्ण है। अगर धन की जरूरत है तो ज्यादा ऊंचे कर क्यों न लगायें, और इस तरह ज्यादा रकम हासिल करके अपने मसले क्यों न हल करें? हमारे देश में जो कुछ भी दौलत है—और मेरा ख्याल है, तो उसका होना ठीक ही है, लेकिन जिस खास बात की हमें फिक्र है, वह यढ़ा हुआ धन नहीं है, बल्कि धन का उत्पादन ही धन है। देश में एक ऐसी हालत पैदा करना जो कि सम्पत्ति पैदा करती है, और ऐसा वातावरण उत्पन्न करना जो कि उसे पानेमें हमारी मदद करता है—यही खास चीज है।

\+ + +

नकल करके कोई मुल्क गहीं बढ़ते हैं। चाहे आप अमरीका की नकल करें, चाहे आप रूस की नकल करें। हम अमरीका से सीखे, जो हमें सीखना है, पर हिन्दुस्तान की मिट्टी पर अपने पैर जमा कर। हम रूस से सीखे, चीन से सीखे, लेकिन हमारे पैर जमे हों अपने मुल्क में। अलग-अलग मुल्कों के सवाल अलग-अलग होते हैं। हमें अपने सवालों को अपने ढंग से सोचना है और मुल्कों से सीखकर। ये दोनों तरीके गलत हैं कि हम बाहर से सीखेंगे नहीं या कि हम आंखें बन्द करके बाहर की नकल करेंगे।

\+ + +

[शेष पृष्ठ ६५७ पर]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

समाजवाद की सर्वोदय योजना

आचार्य विनोबा

आज निजी और सार्वजनिक उद्योग में परस्पर विवाद विचित्र रूप धारण कर रहा है। शासन निजी उद्योग को तेजी से अपने अधिकार में कर लेने को उत्सुक है। निजी उद्योग अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। इस प्रश्न पर सर्वोदय की विचारधारा उसके आचार्य के शब्दों में पढ़िये।

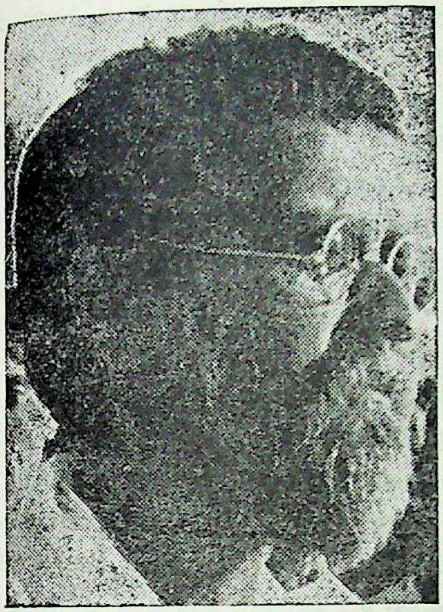

आचार्य विनोबा

आज हम समाजवाद की बात करते हैं। कांग्रेस भी कहती है कि हमको समाजवादी समाज रचना करनी चाहिए। यह बड़ी खुशी की बात है। वास्तव में समाजवाद तब बनता है, जब एक-एक व्यक्ति संयमशील होता है। जहां समाज का हर एक व्यक्ति अपने को समाज से अलग मानता है, वहां समाजवाद नहीं बन सकता। "समाजदेवो भव" ऐसा मानने वाले व्यक्ति ही समाजवादी बन सकते हैं। अपनी सारी शक्ति समाज को समर्पित करनी है, ऐसा जब हर व्यक्ति मानता है, तब समाजवाद बनता है। आजकल तो देश के लिए आर्थिक योजना बनाने की बड़ी बात चलती है। वहां झगड़ा चल रहा है कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र को कितना महत्व दिया जाय। कितने काम समाज के हाथ में और कितने काम व्यक्ति के हाथ में दिये जायं? यह तो ऐसा सवाल है कि जैसे कितना काम अंगुलियों से और कितना काम हाथ से लिया जाय। सर्वसाधारण के हाथ में ज्यादा काम दिया जाता है तो पूंजीपति घबड़ाते हैं और व्यक्तियों के हाथ में ज्यादा काम दिया जाता है तो समाजवादी घबराते हैं। फिर इन दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की बात चलती है। तब बात यह चलती है कि प्राइवेट सेक्टर में ५० प्रतिशत और पबलिक सेक्टर में ५० प्रतिशत अधिकार दिये जायं। बाद में शनैः-शनैः व्यक्ति के हाथ से अधिकार कम करते हुए समाज का हिस्सा बढ़ावें। आखिर में इस तरह व्यक्ति का हिस्सा शून्य बन कर समाज का हिस्सा ही १०० प्रतिशत हो जायगा।

लेकिन लोग पूछते हैं कि सर्वोदय की योजना क्या है? तो हम उत्तर देते हैं कि व्यक्ति के हाथ सौ फी सदी अधिकार और समाज के हाथों में सौ फी सदी अधिकार रहेगा। दोनों मिलकर १०० फी सदी! यह हमारा सर्वोदय का गणित है, जो किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता है। जैसे परिवार में हर एक व्यक्ति के हाथ १०० फी सदी शक्ति होती है, बाप, बेटा और मां की शक्ति में बंटवारा नहीं होता है। जिस तरह परिवार के व्यक्ति और परिवार में कोई भेद नहीं होता है, उसी तरह व्यक्ति और समाज के बीच में कोई भेदभाव नहीं होता है। यह भारतीयता का विचार है। व्यक्ति अपनी सारी सेवा समाज को देगा। समाज हरेक व्यक्ति को पूरी स्वतन्त्रता देगा। और उसके विकास की पूरी योजना समाज में होगी। यही है हमारी सर्वोदय-योजना! यहां 'प्रोटेस्ट गुड आफ प्रोटेस्ट नम्बर' नहीं चलता है। यहां तो 'सर्वभूतहिते रताः' चलता है। याने भिन्न-भिन्न व्यक्तियों में विरोध पैदा करके हम समाज-रचना नहीं करना चाहते हैं।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

साम्यवाद : एक प्रतिक्रिया

कम्युनिज्म योरप की परिस्थिति में से पैदा हुआ है। वहां पूँजीवाद का जोर था। बड़े-बड़े कारखाने, बड़े-बड़े शहर वहां बनाये गये। दुनिया भर की संपत्ति वे इकट्ठा करते थे। फिर मालिक और मजदूरों का झगड़ा हुआ। मजदूरों को मालिक ऊपर उठने नहीं देते थे। इसलिए उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप कम्युनिज्म पैदा हुआ। याने यह स्वयंपूर्ण विचार नहीं है। जो प्रतिक्रिया-रूप विचार होता है, वह बदलता ही रहता है। सोशलिज्म भी स्वतन्त्र विचार नहीं है। एक है पूंजीवाद की प्रतिक्रिया और दूसरी है, व्यक्तिवाद की। दोनों प्रतिक्रियारूप पैदा हुए, इस वास्ते उनमें पूर्ण दर्शन भी नहीं है। एक में है व्यक्ति विरुद्ध समाज और दूसरे में है पूँजी विरुद्ध श्रमशक्ति। वास्तव में दोनों में विरोध होने की जरूरत नहीं थी। वे विरोध मिट सकते थे। व्यक्ति समाज का ही अंश है। अगर समाज का हित व्यक्ति नहीं सोचेगा, तो व्यक्ति का भी उससे हित नहीं होगा और व्यक्ति का विकास नहीं हुआ, तो समाज का भी विकास नहीं होगा। इस तरह व्यक्ति और समाज, दोनों एक-दूसरे पर आधार रखते हैं। बुनाई में जैसे ताना और बाना ओत-प्रोत होते हैं, वैसे ही व्यक्ति और समाज का सम्बन्ध है। ताने और बाने का इंट्रेस्ट एक-दूसरे के विरोध में नहीं होता। उसी तरह व्यक्ति और समाज का इंट्रेस्ट वास्तव में भिन्न नहीं है। पूँजी और श्रम, दोनों का विरोध बताया जाता है। पर पूँजी माने क्या? जो श्रम भूतकाल में हो चुका, वही पूँजी बनी और जो श्रम आज करते हैं, वह श्रम है! कल के श्रम का आज के श्रम के साथ विरोध नहीं हो सकता। परन्तु हमने जो श्रम भूतकाल में कर रखा है, वह चंद लोगों के हाथ में पैसे के रूप में आया। इस प्रकार योरप में सेंट्रलाईजेशन होता गया, इससे झगड़ा करके वह पूँजी छीन लेंगे और श्रमशक्ति को ऊपर उठायेंगे, ऐसा "वाद" वहाँ आया। दुनिया में कहीं भी कोई वाद पैदा होता है, तो वह सारी दुनिया में चला जाता है। इसलिए वह भारत में भी आया, परन्तु वाद प्रतिक्रिया-रूप में होने के कारण बदलते रहते हैं।

बदल रहे हैं

समाजवाद के भी कितने प्रकार हुए हैं? हिंदुस्तान का एक अलग प्रकार है, क्योंकि पूँजी वाले भी उनसे नहीं डरते! उनको आश्वासन मिला है कि तुम्हारा प्राइवेट सेक्टर जैसा का वैसा रहेगा। इस तरह समाजवाद का कहाँ क्या रूप होगा, भगवान् ही जाने! हिटलर भी अपने को समाजवादी ही तो कहता था! आजकल समाजवाद 'वेलफेयर स्टेट' का भी रूप ले रहा है। याने समाज की उन्नति करना ही समाजवाद का रूप होता जा रहा है। इस प्रकार सोशलिज्म जगह-जगह बदल रहा है। यही हालत कम्युनिज्म की है। मार्क्स की पुस्तक में जो कम्युनिज्म है, वह आज रशिया में नहीं है। लेनिन और स्टालिन की पालिसी में फर्क था। अब तो वहां विश्व-शांति और को-एक्जिस्टन्स की बात चल रही है। इस पालिसी में बाधा डालने वाले कुछ साथियों को भी हटाया गया है। चीन में दूसरे ही प्रकार का कम्युनिज्म है। भारत में जो कम्युनिज्म है, वह तो संविधान के अन्दर रह कर काम करने जा रहा है। इस प्रकार कम्युनिज्म भी बदलता रहा है। कम्युनिज्म भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है, ऐसा कहा जा सकता है, फिर भी वह बदलता ही है, कभी हिंदुस्तान की संस्कृति में भी वह शामिल हो सकता है!

सर्वोदय स्थिर सिद्धांत है। स्वयं पूर्ण है। वह प्रतिक्रिया-रूप नहीं है। परन्तु कम्युनिज्म अस्थिर है, सो बदलता ही रहता है। अस्थिर सिद्धांत का परिणाम स्थिर सिद्धांत पर नहीं हो सकता। इस वास्ते सर्वोदय का ही प्रभाव धीरे-धीरे यहां के कम्युनिज्म पर होने वाला है। भारतीय संस्कृति का रंग आज ही उस पर चढ़ रहा है। परिणाम स्वरूप उनकी ओर से एक नेता ने कालड़ी में जाहिर किया कि जमीन की मालकियत मिटाने का काम, जो ग्रामदान-पद्धति से होता है, वह कानून से नहीं हो सकता। हम कम्युनिज्म से डरते नहीं, न हम उसको अपना शत्रु ही मानते हैं। उल्टे, हम उनको खाने बैठे हैं! हम उनको खाकर पचाने वाले हैं! आखिर ये लोग हैं कौन? भारत के बाहर के तो हैं नहीं!

सर्वोदय में हम अपनी चिंता नहीं करते, सबकी करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप नैतिक शक्ति बढ़ती है। यह

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

साम्यवाद, समाजवाद और गांधीवाद

श्री जयप्रकाश नारायण

साम्यवाद जहां विजयी हुआ है, उसकी परिणति राज्य-पूंजीवाद और तानाशाही में हुई है, जो साम्यवाद का प्रतिवाद ही है। समाजवाद पश्चिमी यूरोप में तो अपना पुराना आदर्शवाद खो ही चुका है। अब वह संसदीय और वैधानिक कार्यवाही पर निर्भर करने वाला मतवाद मात्र रह गया है। इस प्रकार समाजवाद और साम्यवाद दोनों को असफलता का सामना करना पड़ा है। गांधीवाद ही तीसरा मार्ग दिखाता है, वह पथ है अहिंसात्मक सामूहिक प्रयत्नों द्वारा क्रान्ति का मार्ग।

हमें इसका एक उत्तम उदाहरण विनोबा के भूदान आन्दोलन में मिलता है। एक ओर वह हिंसा का परित्याग करता है, तो दूसरी ओर कानून पर भी अपनी आस्था नहीं रखता है। वह जनता के प्रयत्नों द्वारा ही भूमि का बंटवारा करना चाहता है। जनता जो कुछ कर चुकेगी, कानून तो उस पर पीछे मुहर लगाने आयेगा। भूदान की प्रायः यह आलोचना की जाती है कि भीख मांगने से कठिन समस्या का समाधान नहीं हो सकता है और इसलिये कानून के द्वारा जमीन का बंटवारा होना चाहिये। मजा तो यह है कि इसे ही क्रांतिकारी दृष्टिकोण समझा जाता है। लोग इसे महसूस नहीं करते कि कानून के द्वारा क्रांति नहीं हो सकती है। सच्ची क्रांति तो जीवन के मूल्यों में क्रांति होना है। कोई भी कानून जीवन के मूल्यों में परिवर्तन नहीं कर सकता है। जनता के जीवन के मूल्यों में परिवर्तन पर ही उसकी प्रतिच्छाया कानून में प्रकट हो सकती है। इसी कारण विनोबा, जो सच्चा गांधीवादी है, कानून के फेर में नहीं पड़ता और इसीलिये वह और उसके सहयोगी लोगों के दिल और दिमाग बदलने के लिये चक्कर लगा रहे हैं।

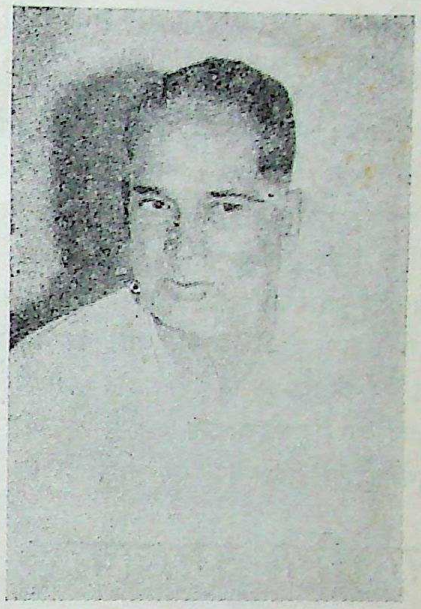

— लेखक —

कानून न तो दिमाग में परिवर्तन ला सकता है और न हृदय में। इस प्रकार की क्रांति कितना समय लेगी, यह प्रश्न उठाया जाता है। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिये गांधीवादी क्रांति ने अन्य राष्ट्रीय क्रांतियों की तुलना में अधिक समय नहीं लिया है। जो सफलता विनोबा को अब तक मिली है, वह भी इतिहास में अद्वितीय है।

मुझे भय है कि आज के अधिकांश लोगों का, कानून के द्वारा समाजवाद स्थापित करने की पाश्चात्य पद्धति की ओर झुकाव है। और यही कारण है कि सत्ता के लिए संघर्ष और राजनीतिक प्रयत्न की ओर लोगों की इतनी दिलचस्पी है। प्रायः सभी यही सोचते हैं कि सत्ता पर अधिकार करने के बाद ही कानून और राजकीय ताकत से समाजवाद की स्थापना की जा सकेगी। अगर हम सामाजिक क्रांति की वैधानिक परिकल्पना से ही चिपके रहेंगे, तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि हमारी भी स्थिति पश्चिम के समाजवादियों जैसी होगी। गांधीवाद सत्ता के अधिकार पर केन्द्रीभूत नहीं है और न

कार्य न समाजवाद कर सकता है; न साम्यवाद। उनका दारोमदार सेना पर है। दोनों एक ही देवता के भक्त हैं। इस वास्ते वे सब एक ही कैंप में रह कर आपस-आपस में लड़ते हैं, लेकिन सर्वोदय का कोई कैंप ही नहीं। किसी भी कैंप से वह अलग है।

—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वह राजसत्ता पर निर्भर करता है। वह सीधे जनता के बीच जाता है और उन्हें अपने जीवन में क्रांति लाकर सामाजिक जीवन में भी क्रांति लाने में सहयोग प्रदान करता है। जन शक्ति के निर्माण के बाद तो राज सत्ता का सहयोग निश्चित ही है।

यह स्पष्ट है कि इस प्रकार गांधीवाद की प्रक्रिया पार्टी और वर्ग के घेरे से आगे जाती है, क्योंकि वह तो, अगर आप चाहें, सभी पार्टियों और वर्गों के सदस्यों के जीवन में क्रांति लाना चाहता है। समाजवाद एक वर्ग के विरुद्ध दूसरे वर्ग को खड़ा कर आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन गांधीवाद वर्गों से आर पार होकर बढ़ता है। समाजवाद एक वर्ग को सब वर्गों के ऊपर विजयी बनाकर वर्गों का विनाश करना चाहता है। यह तर्क-सम्मत नहीं प्रतीत होता है। लेकिन गांधीवाद वर्ग भेद को मिटाना चाहता है और इसलिए वह वर्गों को इस प्रकार एक साथ लाता है कि वर्ग भेद रह ही नहीं जाता है।

समाजवाद का लक्ष्य है, वर्गहीन समाजकी रचना। लेकिन वह सामाजिक क्रांति को ही राज्य पर निर्भर बनाकर राज्य को सर्वशक्तिमान बना देता है। समाजवाद की तरह गांधीवाद का लक्ष्य भी है 'राज्य-विहीन' समाज। लेकिन सामाजिक प्रक्रिया को राज्य पर कम से कम निर्भर बनाकर वह अधिक तर्कसम्मत रास्ते से चलता है। राज्य-हीन समाज का प्रारम्भ 'अभी और यहां' से होता है, यह नहीं कि भविष्य में किसी दूरस्थ काल्पनिक समय के लिए उसे छोड़ता है। इसलिए यह अधिक सच्ची क्रांतिकारी पद्धति है, जिसे अपने लक्ष्य तक पहुँचने की अधिक संभावना है बनिस्बत और पद्धतियों के।

इन सब कारणों से गांधीवाद और गांधीवादी प्रक्रिया के अधिक अध्ययन की आवश्यकता है।

भारतीय समाजवाद के सात सिद्धान्त

श्री श्रीमन्नारायण

भारत ने समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने का निश्चय किया है। इस समाजवादी व्यवस्था में मूलतः सात सिद्धान्त निहित हैं :—

(१) पूरी रोजगार और काम पाने का अधिकार।

(२) राष्ट्रीय सम्पत्ति का अधिकतम उत्पादन।

गरीबी को बांटकर मंगलकारी राज्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। समाजवादी व्यवस्था के लिये राष्ट्रीय धन का अधिकतम उत्पापन और जीवन-स्तर ऊंचा करना आवश्यक है।

(३) अधिकतम राष्ट्रीय आत्म-निर्भरता। अपने पड़ोसी देशों के पिछड़ेपन का फायदा उठाकर अपने निर्यात की वृद्धि का प्रयत्न ठीक नहीं। वह समाज जो विदेशों में आर्थिक शोषण करके अपने बीच समाजवाद कायम करना चाहता है, सही मानों में समाजवाद पर आधारित समाज कभी भी नहीं कहा जा सकता।

(४) सामाजिक और आर्थिक न्याय। छुआछात, स्त्रियों की हीन स्थिति, वेश्यावृत्ति आदि के रहते समाजवादी व्यवस्था कायम नहीं हो सकती। कर जांच-कमीशन ने समाज में असमता का अनुपात १ : ३० से अधिक न रखने का परामर्श दिया है। यह अनुपात कम करके १ : २० लाना होगा।

(५) शांतिपूर्ण अहिंसात्मक और जनतान्त्रिक तरीकों का प्रयोग।

(६) ग्राम पंचायतों और औद्योगिक सहकारी समितियों के द्वारा आर्थिक और राजनैतिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण। अत्यधिक केन्द्रित और यंत्रीकृत उत्पादन के आधार पर अहिंसात्मक और जनतन्त्रात्मक समाज की योजना बनाना सम्भव नहीं है। अत्यधिक केन्द्रीकरण का अनिवार्य फल कुछ लोगों के हाथों में आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का केन्द्रीकरण होता है। हमें ऐसा समाजवादी संघटन चाहिए, जो सब प्रकार के शोषण से मुक्त हो और जिसमें व्यक्ति व समाज दोनों के न्यायोचित हितों का सफल समन्वय हो।

(७) अन्टू दि लास्ट (अन्तिम के लिए) का आदर्श है कि समाजवाद पर आधारित समाज कायम करने के लिए हमें अपनी जनता के दरिद्रतम और निम्नतम भागों की तात्कालिक आवश्यकताओं को उच्चतम प्राथमिकता देनी होगी। समाजवादी व्यवस्था कायम करने की हमारी योजना में अन्तिम को प्रथम और प्रथम को अन्तिम होना पड़ेगा।

[समाप्त

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

समाजवाद की विवेचना

प्रो० विश्वम्भरनाथ पाण्डेय एम० ए०

समाजवाद का जन्म पूँजीवाद के अन्तर्विरोधों अर्थात् पूँजीवादी समाज के वर्गभेद, वर्गसंघर्ष और शोषक स्थिति के प्रति भावात्मक विद्रोह व प्रतिक्रिया के कारण हुआ। वास्तव में पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था का सैद्धान्तिक आधार (Laissez faire theory and individualisim) तैयार करने वाले चिन्तकों जैसे फिजिओक्रैट्स, एडमस्मिथ जान स्टुअर्ट मिल और हर्बर्ट स्पेंसर आदि के विचार में कुछ आधारभूत हेत्वाभास थे। यथा—

(१) आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति स्वातंत्र्य का प्रचार करते समय उन्होंने यह मान लिया था कि स्वतंत्रता, दूरदर्शिता और क्षमता की दृष्टि से समाज के सभी व्यक्ति समान स्थिति के हैं; अतः कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता। किन्तु यह एक ऐसी मान्यता थी, जिसका वास्तविकता से मेल नहीं बैठता। (२) उनकी दूसरी भूल यह थी कि उन्होंने यह नहीं सोचा था कि अर्थतंत्र को व्यक्ति के ऊपर छोड़ देने से वैयक्तिक स्तर के सभी कार्य तो हो जायेंगे किन्तु सामाजिक स्तर के कार्य (जैसे-सड़क व पार्क निर्माण आदि के कार्य) जो किसी एक व्यक्ति के कार्य न होते हुए भी सभी के हित के कार्य हैं—नहीं हो सकेंगे। (३) तृतीय व्यक्तिवादियों का यह सोचना गलत था कि समाज के असंख्य व्यक्तियों के पृथक पृथक कार्यों का योग ही सामाजिक कार्य के बराबर हैं; क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्तियों के हित के कार्यों का योग समाज के भी हित का निर्माण कर सके। जैसे मान लीजिये यह अफवाह उड़ जाती है कि अमुक बैंक का दिवाला निकल रहा है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक बैंकर का हित इसी में होगा कि वह अपना कुल रुपया उक्त बैंक से निकाल ले। किन्तु सभी बैंकरों के अपने अपने रुपये निकाल लेने की वैयक्तिक चेष्टा का फल यह होगा कि बैंक दिवालिया हो जायेगा, जो किसी भी बैंकर या बैंकिंग समाज का हित नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः व्यक्तिवादियों की यह सब से बड़ी भूल थी कि उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को अलग इकाई माना और समाज को मात्र

— लेखक —

इन इकाइयों का योग। समाज का व्यक्ति से अलग भी कुछ अस्तित्व है। आपस में एक दूसरे से जुड़े होने के कारण एक के कार्य का प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर पड़ता ही है। अतः विभिन्न व्यक्तियों के कार्यों में सामंजस्य और मेल बैठाने के लिये व्यक्ति की स्वतंत्रता की विवेकपूर्ण मर्यादा होनी ही चाहिये। किन्तु इस तथ्य पर व्यक्तिवादियों का ध्यान नहीं गया।

समाजवाद का जन्म

इन सब का परिणाम यह हुआ कि शीघ्र ही औद्योगिक क्रान्ति के प्रभाव से यूरोप और विशेषकर इंगलैण्ड का समाज कुछ ऐसी विषमताओं से ग्रसित हो उठा, जिससे १९ वीं शताब्दी के व्यक्तिवाद की आदर्शवादिता का खोखलापन व्यावहारिक स्तर पर स्पष्ट रूप से प्रकाशित हो गया। तत्कालीन समाज दो वर्गों में बँट चुका था। एक तरफ थोड़े से पूँजीपतियों का समाज था, जो सम्पन्न और सुखी था; उद्योगों और मिलों पर जिसका स्वामित्व, नियंत्रण

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

और अधिकार था और दूसरी तरफ मजदूरों का वह वृहत समाज था, जो दरिद्र और सर्वथा अकिंचन था। इस द्वितीय वर्ग का प्रथम वर्ग के द्वारा निरन्तर शोषण हो रहा था। काम करने के घंटे अनिश्चित थे, मजदूरी कम दी जाती थी, गरीब मजदूर का आवास नितान्त अस्वस्थकर था। उनके बच्चों के लिये शिक्षा का प्रबन्ध न था, न रुग्णावस्था में औषधि का। बीमार और गर्भिणी स्त्रियों को भी अवकाश नहीं मिलता था। बाध्य होकर मजदूरी के लोभ से कम उनके बच्चों को भी मिलों में नौकरियां करनी पड़ती थीं। यह स्थिति सामाजिक अन्याय और विषमता की एक ऐसी प्रमाणपूर्ण घोषणा थी, जिसकी पुकार उस युग के आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र के प्रत्येक संवेदनशील लोक नायक ने सुनी और तत्कालीन समाज के ढांचे में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता समझी। फलतः उस विचार धारा का उद्गम हुआ, जिसके आदिकालीन पोषक सेन्टसाइमन, राबर्ट ओवेन, सिसमन्डी और प्राधों आदि थे तथा जिसके सैद्धान्तिक विचारों को पूर्णता कार्लमार्क्स के द्वारा मिली। इस प्रकार समाजवाद का जन्म हुआ।

समाजवाद के कितने ही रूप हैं। मार्क्सवादी समाजवादी मार्क्स के पूर्व के समाजवादियों को आदर्श (utpion) समाजवादी कहते हैं और अपने को वैज्ञानिक समाजवादी (Scientific Socialist)। उनके अनुसार सेन्ट साइमन, फरिअर, ओवेन आदि का समाजवाद अव्यावहारिक और कोरा आदर्श (utopia) है, क्योंकि उन्होंने समाजवाद के आदर्शों की चर्चा तो की, किन्तु यह नहीं बताया कि समाजवाद को किस प्रकार स्थापित कर समाजवादी आदर्शों को मूर्त रूप दिया जा सकता है। इसके विपरीत कार्लमार्क्स ने अपने सिद्धान्त की वैज्ञानिक व्याख्या तो प्रस्तुत की ही, साथ ही यह भी बताया कि किस प्रकार उसके समाजवाद की स्थापना की जा सकती है। उसके अनुसार समाजवाद समाज की एक स्थिति-विशेष का ही अपरिहार्य परिणाम है। समाज की वह स्थिति जब उत्पन्न हो जायेगी, समाजवाद के प्रादुर्भाव को कोई रोक नहीं सकता। इस तरह मार्क्स के लिये समाजवाद उसके पूर्ववर्ती 'आदर्श समाजवादियों' की तरह एक ऐसी आदर्शात्मक स्थिति मात्र नहीं थी, जिसकी स्थापना मनुष्य और मानव समाज के व्यक्तिगत और सामूहिक विवेक और सदिच्छा पर आश्रित हों। समाज प्रगतिशील है और जिन विकासशील नियमों के आधार पर समाज की अवस्थायें आज तक बदलती रही हैं, उन्हीं नियमों की क्रियाशीलता से यह पूंजीवादी समाज भी बदल जायगा और समाजवादी समाज की स्थापना होगी, चाहे हम और आप पसन्द करें या न करें।

समाजवाद की शाखाएं

यह स्पष्ट है कि समाजवाद पूंजीवादी समाज के दृष्टिगत अत्याचारों के प्रति भावात्मक विद्रोह और प्रतिक्रियाका परिणाम था। इसलिये विभिन्न समाजवादियों ने पूंजीवादी व्यवस्था के विपरीत या विकल्प (alternative) के रूपमें जिस व्यवस्था की कल्पना की उसके, आदर्शों में स्वभावतः एकता थी। किन्तु उनके समाजवाद की प्राप्ति के साधनों में बहुत भेद है। साम्यवाद, समष्टिवाद (Collectivism) मजदूर संघवाद (syndicalism), शिल्प संघवाद (guild socialism) और यहां तक कि अराजकतावाद (Anarchism)—ये सभी समाजवाद के नामसे ही अभिहित होते हैं और इनके आदर्शों में तात्त्विक एकता भी है, वह इस अर्थ में कि सबके अनुसार पूंजीवादी समाज के विरुद्ध एक ऐसे समाज की कल्पना की गई है, जिसमें अधिक सामाजिक न्याय हो, राष्ट्रीय आय का अधिक न्यायपूर्ण वितरण हो तथा जिसमें वर्गभेद न हो, किन्तु उनकी समाजवाद की स्थापना की पद्धति और कार्य में बहुत अन्तर है।

भारत की औद्योगिक नीति

इसमें भारत की उद्योग नीति का अतीत, समय-समय पर होने वाले परिवर्तन और आज की नीति का संक्षेप से परिचय दिया गना है। इसके लेखक अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों की कठिनता और आवश्यकताएं जानते हैं। इसलिए यह पुस्तक हायर सैकेण्डरी, इण्टर व बी० ए० के परीक्षार्थी विद्यार्थियों के लिए अन्यत उपयोगी सिद्ध होगी।

—मैनेजर, मूल्य ६२ नये पैसे

अशोक प्रकाशन मन्दिर रोशनारा रोड, दिल्ली-६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

स्थूल रूप से समाजवाद के विभिन्न पीठों को हम दो कोटियों में रख सकते हैं—(१) विकासवादी समाजवादी (Evolutionary socialists) और क्रान्तिकारी समाजवादी (revolutionary socialists) विकासवादी समाजवादी वे हैं, जो समाजके विकास (evolution) में विश्वास करते हैं, क्रान्ति में नहीं। उनके अनुसार समाजवाद की स्थापना शान्तिपूर्ण ढंग से धीरे-धीरे स्थिति-परिवर्तन (slow transformation) और समाज के स्वतः विकास के द्वारा होना चाहिये। समष्टिवादी (Collectivists या Fabians) इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त क्रान्तिकारी समाजवादी क्रान्ति, उथल-पुथल और आन्दोलन आदि में विश्वास करते हैं। इसके उदाहरण साम्यवादी तथा मजदूर संघवादी हैं। मार्क्स को सभी समाजवादियों से अधिक मान्यता मिलने का कारण यही था कि उसने मजदूर वर्ग को निश्चित आशा दी और उन्हें वह ढंग और कार्यपद्धति बतलाई, जिसके द्वारा वे अपने वर्तमान शोषण का अन्त कर सकते हैं तथा समाजवादी समाज की स्थापना में सफल हो सकते हैं। मार्क्सवाद समाजवाद का पूर्ण सिद्धान्त था क्योंकि उसने साधन और सिद्धि दोनों की व्याख्या की।

आदर्श समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद के इन विभिन्न रूपों के कारण एक जटिल समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके अतिरिक्त आजकल समाजवाद शब्द का प्रयोग एक 'सैद्धान्तिक समूह' तथा 'राजनीतिक घटना' दोनों ही अर्थों में होता है, जिसके कारण समाजवाद के दो पक्ष हो गये हैं—(१) राजनीतिक और (२) सैद्धान्तिक (अर्थ नीतिक)। श्री जोडके शब्दों में 'जिस सैद्धान्तिक समूह को हम समाजवाद से जानते हैं वह न तो पूर्णतः और न मुख्यतः राजनीति की वस्तु है—यह एक बहुत बड़े अंश में अर्थशास्त्रीय है। आर्थिक तथा राजनीतिक सिद्धान्त आपस में कुछ इस प्रकार जुड़े हुवे हैं कि समाजवाद के केवल राजनीतिक पक्ष की विवेचना न तो सम्भव है और न अपेक्षित।' समाजवाद के राजनीतिक पक्ष की विवेचना में इतनी विभिन्नता है कि इसकी कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं बनायी जा सकती। श्री जोड ने कहा है कि 'वास्तव में समाजवाद के प्रवक्ताओं तथा विभिन्न

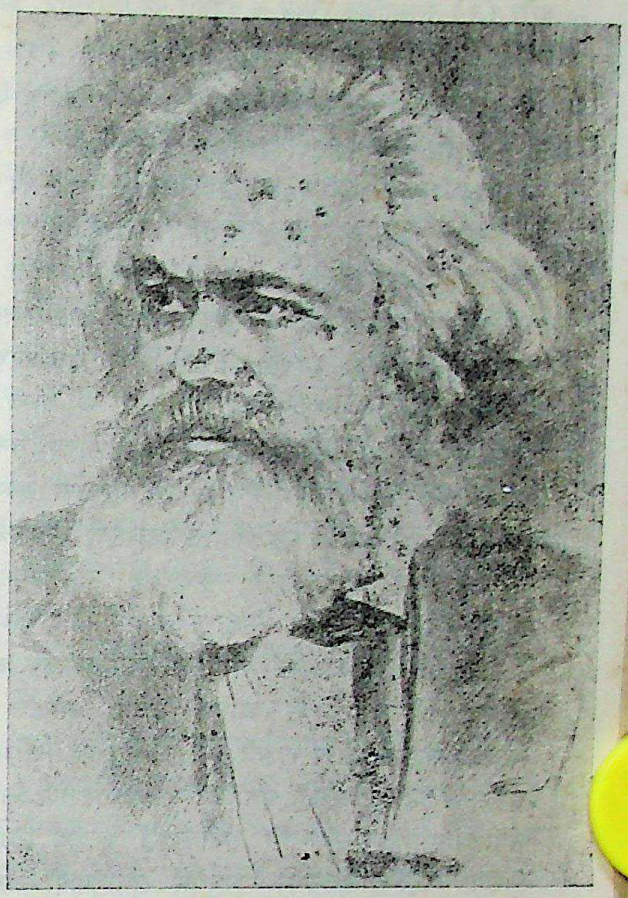

जन्म १८१८ (ट्रियर जर्मनी) मृत्यु १८८३ (लन्दन)

लेखकों की अनेकता के कारण इस विषय का साहित्य इतना विषद हो गया है कि ठीक ठीक यह बताना बड़ा कठिन है कि समाजवाद है क्या ?...तत्वतः समाजवाद का रूप उस हैट या टोपी के सदृश होगया है जो बुरी तरह विकृत हो गयी, है क्योंकि उसे जो चाहता है वही अपने सिर पर धर लेता है।' किन्तु जैसा कि मैंने ऊपर बताया है समाजवाद मुख्यतः व्यक्तिवाद की प्रतिक्रिया है। इसलिये समाजवाद के राजनीतिक अथवा सामाजिक व शासकीय संगठनों के सम्बन्ध में विभिन्न समाजवादियों में चाहे जो अन्तर हो, उनके आर्थिक उद्देश्यों (सैद्धान्तिक पक्ष) में पूर्ण एकता है। सब के अनुसार समाजवाद वह सामाजिक व्यवस्था है, जिसका आधार समता का सिद्धांत है। यह वह समाज है जहां—(१) सम्पत्ति का समान वितरण होता है

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

और (२) सामाजिक न्याय के आधार पर पर व्यष्टि और समष्टि का जीवन चलता है।

इसके अलावा निम्नलिखित तीन मुख्य सिद्धान्त ऐसे हैं, जो सभी समाजवादियों के आदर्श हैं:—

(क) उत्पादन के साधन पर व्यक्तिगत स्वामित्व का अन्त और उनके साथ प्रमुख उद्योगों और सेवाओं पर लोक (Public) स्वामित्व और नियंत्रण की स्थापना।

(ख) उत्पादन का कार्य व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से नहीं, अपितु सामाजिक आवश्यकता की दृष्टि से संचालित करना।

वास्तव में समाजशास्त्र को इसलिये अर्थशास्त्र के प्रति कृतज्ञता प्रगट करनी चाहिये कि उसने मानव चिन्तन के इतने बड़े सिद्धान्त की एक निश्चित परिभाषा सम्भव कर दी जो इस युग की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विचारधारा है। अंग्रेजी के विश्वकोष ने समाजवाद की परिभाषा की है—"समाजवाद वह सिद्धान्त तथा नीति (Policy) है जो एक केन्द्रीय प्रजातन्त्री संस्था के द्वारा उत्पादन और वितरण की आज से अधिक उत्तम सम्पत्ति के व्यवस्था स्थापित करना चाहती है।" किन्तु यह परिभाषा सर्वमान्य नहीं हो सकती, क्योंकि अराजवादी तथा शिल्प-संघी और मजदूर संघी जैसे समाजवादी केन्द्रीय सत्ता में विश्वास नहीं करते, उनके अनुसार समाजवादी समाज विभिन्न ऐच्छिक संघों का समुदाय होगा।

समाजवाद के दो पक्ष

सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री पीगू के अनुसार सामाजिक या राष्ट्रीय उद्योग वे उद्योग हैं, जिनके उत्पादन के भौतिक साधनों पर लोकगत अधिकार (Public ownership) होता है और जिनका संचालन उत्पादित वस्तुओं का विक्रय आय लाभ पाने की दृष्टि से नहीं होता, अपितु जनता की प्रत्यक्ष सेवा की दृष्टि से होता है। इस आधार पर समाजवाद वह व्यवस्था है, जिसमें उत्पादक साधनों का अधिक अंश सामाजिक व राष्ट्रीय उद्योगों में नियुक्त होता है।

दूसरे शब्दों में "समाजवाद की प्रमुख विशेषता यह है कि उत्पादन के आवश्यक यंत्रों के साथ उद्योगों और सेवाओं पर व्यक्तिगत स्वामित्व न रहे और न व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से औद्योगिक तथा सामाजिक व्यवस्था का ही संगठन हो।" (श्री वेन्स)। इस प्रकार सन् १९१७ के पहले तक समाजवाद का अर्थ—(१) व्यक्तिगत लाभ के उन्मूलन और (२) मनुष्य को छोड़कर उत्पादन के भौतिक साधनों पर लोक स्वामित्व की स्थापना की व्यवस्था से था। तब आर्थिक योजना का तत्व समाजवाद की परिभाषा में नहीं था। किन्तु रूस की समाजवादी क्रिया पद्धति के आलोक में समाजवाद की परिभाषा संशोधित हो चुकी है। अब समाजवाद की प्रमुख विशेषता यह है कि भूमि तथा सभी बड़े-बड़े उत्पादक साधन सार्वजनिक अथवा सामूहिक स्वामित्व के अन्दर हों तथा उनको एक राष्ट्रीय आर्थिक योजना के अनुसार इस प्रकार कार्यरत किया जाये कि उनसे व्यक्तिगत लाभ के स्थान पर सामूहिक कल्याण हो। इसका अर्थ यह न समझना चाहिये कि समाजवाद सर्व क्षेत्रीय राष्ट्रीयकरण का पर्याय है और न यही कि समाजवाद में व्यक्तिगत सम्पत्ति का कोई स्थान नहीं होगा। हमारा अभीष्ट है प्रमुख उद्योगों तथा उत्पादक साधनों पर लोक स्वामित्व, तथा उनका सामाजिक कल्याण की दृष्टि से संचालन। श्री राबर्टसन के शब्दों में समाजवादी व्यवस्था के महादेश में झील की तरह पूँजीवादी उद्योग कुछ अंश में उसी प्रकार रहेंगे जिस प्रकार समुद्र के छोटे छोटे द्वीपों की भांति पूँजीवादी व्यवस्था में राष्ट्रीय उद्योग रहते हैं।

> "अमीरी और गरीबी भगवान की बनाई हुई नहीं है। धर्म में उनका कोई स्थान नहीं है और यदि धर्म में विधान है, तो जिस धर्मने अमीरी-गरीबी को मंजूर कर लिया होगा, वह गरीब के लिए तो अफीम की गोली है।"
>
> —कार्ल मार्क्स

समाजवाद और साम्यवाद में अंतर

यहाँ समाजवाद और साम्यवाद का अन्तर जान लेना आवश्यक है। कभी कभी साम्यवाद का व्यवहार समाजवाद के पर्याय के रूप में होता है। किन्तु १८४७ में प्रकाशित मार्क्स और एंजिल्स के 'कम्यूनिस्ट मेनिफेस्टो' के अनुसार—

'साम्यवाद एक विधि का सिद्धान्त है (theory of

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

method) । यह उन आदर्शों की स्थापना करता है जिनके आधार पर समाज का परिवर्तन पूँजीवाद से समाजवाद में होगा ।' थोड़े शब्दों में साम्यवाद पूँजीवाद और समाजवाद के बीच की व्यवस्था है । समाजवाद में वितरण का आदर्श होता है—सब से क्षमता के अनुसार और सबको उनकी आवश्यकता के अनुपात में' । किन्तु साम्यवाद का सिद्धान्त ' सबसे क्षमता के अनुसार और सब को कार्य के अनुपात में है' । इस कारण यद्यपि रूस के संविधान की पहली धारा कहती है कि 'सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक संघ मजदूरों और किसानों का समाजवादी राज्य होगा, वास्तव में यह सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से शब्दों का गलत प्रयोग है, क्योंकि उसकी धारा १२ में सोवियत संघ का सिद्धान्त 'सब से क्षमता के अनुसार और सब को कार्य के अनुपात में' बताया गया है । रूसी संविधान में साम्यवाद के स्थान पर समाजवाद शब्द का प्रयोग क्यों हुआ, इसका सबसे बड़ा राजनीतिक कारण यह है कि मजदूरों और किसानों को समाजवाद जैसे परिचित शब्द के प्रयोग से सर्वाधिक मानसिक तुष्टि प्रदान की जा सकती थी, क्योंकि लेनिनवाद के अनुसार रूसी क्रान्ति के पश्चात् रूस में समाजवाद नहीं, अपितु सर्वहारा वर्ग अधिनायक तंत्र (Dictatarship of Proletariat) की स्थापना होनी थी । रूस आज भी इस साम्यवादी डिक्टेटरशिप आफ् दी प्रोलिटारियट, जिसे कम्यूनिस्ट पार्टी के किसी शक्तिशाली नेता का ही अधिनायक तंत्र कहेंगे, की स्थिति से आगे नहीं बढ़ा है । यह रूस की ऐतिहासिक आवश्यकता चाहे भले रही हो, किन्तु सत्य है; और सन्तोष की बात है कि पिछले कुछ वर्षों में स्तालिन की मृत्यु के बाद से वहाँ कुछ उदारता के लक्षण उभर रहे हैं ।

समाजवाद पर आक्षेप व उनका समाधान

व्यक्तिवादियों की आलोचना

समाजवाद के दर्शन के विरुद्ध व्यक्तिवादियों की आलोचना यह है कि समाजवाद व्यक्ति को पूर्णरूप से राज्य के अधीन कर के उसे प्राकृतिक अधिकारों से वंचित कर देना चाहता है, किन्तु सिद्धान्ततः समाजवाद सचमुच में व्यक्ति को भौतिक आवश्यकताओं और अभावों से मुक्त कर के एक ऐसे सामाजिक वातावरण में उपस्थित करना चाहता है, जहाँ व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम संभव विकास कर सके । किन्तु चूंकि समाजवादी समाज के अंगीय विकास (Organic development) में आस्था रखते हैं, उनका विश्वास है कि व्यक्ति समाज में और समाज के साथ ही विकास कर सकता है । इस तरह व्यक्तिवादी और समाजवादी अन्ततोगत्वा विरोधी विचार नहीं रखते, दोनों ही व्यक्ति को विकास का पूर्ण अवसर देना चाहते हैं किन्तु व्यक्तिवादी इसके लिये समाजवादियों से सर्वथा विपरित यह जरूर मानते हैं कि इसके लिये व्यक्ति को अबाधित स्वतंत्रता दे दी जाये । और किसी भी क्षेत्र में राज्य उसके ऊपर बहुत नियंत्रण या रुकावट न पैदा करे । पर इनके इस प्रकार के दर्शन (approach) में जो आधारभूत त्रुटियां थीं उनका आदि में ही उल्लेख हम कर चुके हैं ।

समाजवाद के प्रति दूसरी आलोचना प्रेरणा की है । व्यक्तिगत लाभ की आशा के अभाव में व्यक्ति के अन्दर कार्य की प्रेरणा (incentive) क्या रह जायेगी ? समाजवादी इसका उत्तर तीन प्रकार से देते हैं—

(१) इस आलोचना की यह मान्यता गलत है कि मनुष्य स्वभाव से आलसी है और वह लाभ की आशा की उकसान पर ही काम करता है; क्योंकि एडम स्मिथ जैसा व्यक्तिवादी भी यह मानता है कि श्रम करना मानव स्वभाव का अंग है । वास्तव में मनुष्य आनन्द चाहता है और कार्य करने से उसका आनन्द यदि न जाये तो वह वह कार्य करना कभी नहीं बन्द करेगा । प्रसिद्ध फेबियन समाजवदी बनार्ड शा ने कहा था कि नरक की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा अनवरत विश्राम है ।' अराजवादी क्रपोटकिन के शब्दों में—'मनुष्य को अतिशय कार्य अरुचिकर होता है न कि कार्य ।...कार्य तो एक मानवीय आवश्यकता है । जिसके द्वारा मनुष्य अपनी संचित शक्ति को खर्च करके जीवन और स्वास्थ्य प्राप्त करता है ।

(२) यह सत्य है कि मनुष्य गन्दे और अभद्र

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शोषण कैसे होता है ?

"किसान है, उसका बैल है। बैल किराये की गाड़ी में चलाता है। उसे तीन रुपए रोज किराया मिलता है। तीन रुपए रोज में से ढाई रुपये रोज की कम से कम मेहनत है। पर बैल को जिन्दा रखने के लिए जितना जरूरी है, उतना ही सिर्फ खिलाता है। निर्वाह के लिए जितना आवश्यक है, उतना ही बैल को देता है और बैल की मेहनत का बचा हुआ सारा फल किसान ले लेता है। यह "शोषण" (Exploitation) कहलाता है।"

— मार्क्स

कार्यों को स्वयं ही नहीं करेगा। किन्तु ऐसे कार्यों के लिये आज के वैज्ञानिक युग में यंत्रों की व्यवस्था करना कठिन नहीं है।

(३) मानवीय कार्यों की प्रेरणा में लाभ ही सब कुछ नहीं है। वास्तव में सामाजिक प्रतिष्ठा, और सम्मान, समाज सेवा की निःस्वार्थ भावना आदि भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। विश्व के महाकाव्यों की रचना लाभ की दृष्टि से नही हुई। सुकरात, अरस्तू, प्लेटो, बुद्ध, गांधी, लिंकन आदि ने जो कुछ किया, उसके पीछे व्यक्तिगत लाभ लेश मात्र भी नहीं था। इस तरह यह भी संदेहास्पद है कि विभिन्न युगों में वैज्ञानिकों ने अनेकानेक आविष्कार लाभ की दृष्टि से किये। अतः आवश्यकता व्यक्तिगत लाभ के स्थान पर सामाजिक सेवा की भावना की स्थापना की है, जिसे उचित व्यक्तियों पर सामाजिक यश और प्रतिष्ठा के समर्पण पद्धति से सरलतापूर्वक अक्षुण्ण रखा जा सकता है। थोड़े में इन सब के लिये जीवन के वर्तमान मूल्यों को बदलने की जरूरत है। स्पष्ट है, समाजवाद 'सर्वोदय-सिद्धान्त' के बहुत निकट है।

इतिहास साक्षी

जो हो, इतिहास व्यक्तिवाद (पूँजीवाद) की हार और समाजवाद की जीत का साक्षी है। पूँजीवाद की अन्तिम अवस्थायें—साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद—आखिरी दम तोड़ रही हैं। अफ्रीका और एशिया के देश एक एक कर स्वतंत्र हो रहे हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद साम्यवादी रूस का प्रभाव पूर्वी यूरोप के देशों पर बढ़ता गया है। पोलैण्ड, रूमानिया, हंगरी, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लावेकिया, अलबानिया, बलगेरिया आदि पूँजीवादी देशों के प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं। युगोस्लाविया यद्यपि रूसी प्रभाव में नहीं है, फिर भी उसे समाजवादी और अपूँजीवादी ही कहा जायेगा। इसके अतिरिक्त १९२९ के विश्वव्यापी मन्दी तथा द्वितीय महायुद्ध के बाद पूँजीवाद के जन्मदाता देश इंगलैंड और अमेरिका में भी राज्य का कार्यक्षेत्र आज जितना बढ़ गया है, उसे देखकर एडम स्मिथ, मिल और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे आदि व्यक्तिवादियों को शायद मूर्छा आ जाती। आज के राज्य 'पुलिस राज्य' न होकर निश्चित रूप से 'कल्याण राज्य' बनते जा रहे हैं। उनका कार्यक्षेत्र दिनों दिन बढ़ रहा है। समाजवाद की इस दुर्दमनीय प्रवृत्ति को कोई नहीं रोक सकता। किन्तु यह भी सत्य है कि भविष्य रूस के अधिनायकतंत्री साम्यवाद के हाथ में नहीं है, जिसकी आलोचना 'राज्य पूँजीवाद' (State Capitalisn) के रूप में होती है और जहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की बलि होती है। इसका सबसे बड़ा और ताजा संकेत हंगरी का आन्दोलन और उसकी प्रतिक्रिया है। मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन तीन रूपों में होते हैं—वस्तुस्थिति, वस्तुविरोध और वस्तु समन्वय। पूँजीवादी स्थिति का विरोध अधिनायकतंत्री साम्यवाद, है किन्तु इसका अन्त पूँजीवाद और समाज के समन्वय में होगा, जिसे आज की शब्दावली में 'क्रियात्मक प्रजातंत्र' (Functional democracy) कहते हैं। इसमें राजनीतिक और आर्थिक शक्तियां राज्य में केन्द्रित न होकर विभिन्न मानवीय संघों में विकेन्द्रित हो जायेंगी। स्पष्ट है कि इस प्रकार के क्रियात्मक प्रजातंत्र में न राज्य प्रधान होगा, न व्यक्ति, बल्कि व्यक्तियों का छोटा छोटा संघ। हमारे देश के प्रस्तावित 'समाजवादी ढांचे के समाज' की स्थापना के महत्वपूर्ण तत्वों में एक तत्व वह भी है कि देश का आर्थिक और राजनीतिक ढांचा इस प्रकार संगठित हो, जिसमें ग्राम पंचायतों, और लघु तथा कुटीर उद्योगों के आधार पर आर्थिक व राजनीतिक शक्तियों का विकेन्द्रीकरण हो। यह समाजवाद के शुद्ध रूप 'क्रियात्मक प्रजातंत्र' की ही कल्पना है।

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मार्क्सवाद क्या है ?

यद्यपि समाजवाद की दिशा में १७-१८ वीं सदी में ही यूरोप के अनेक विचारक विचार करने लगे थे, तथापि साम्यवाद का प्रथम आचार्य कार्ल मार्क्स माना जाता है। उसने और पेरिस के एंजल्स ने १८४८ ई० में साम्यवाद की विचार-धारा को अत्यन्त स्पष्ट और निश्चित रूप में कम्युनिस्ट मेनीफेस्टो का रूप देकर उपस्थित किया। आज करीब ११० वर्ष बीत जाने के बाद भी कार्ल मार्क्स साम्यवाद का प्रमुखतम आचार्य माना जाता है। सभी साम्यवादी और समाजवादी मार्क्स को देवता की तरह पूजते हैं।

मार्क्स के विचार

साम्यवाद को समझने के लिए यह आवश्यक है कि मार्क्स के विचारों को समझ लिया जाये। उसके विचार तीन रचनाओं में प्रकट हुए हैं—

१—कम्युनिस्ट मेनीफेस्टो

२—क्रिटिक आफ दि गोथा प्रोग्राम

३—दास कैपिटल

इन्हीं के आधार पर हम मार्क्सवाद को समझ सकते हैं। मार्क्सवाद स्वयं गम्भीर शास्त्रका रूप धारण कर चुका है, इसलिए उसे समझना बहुत सरल नहीं हैं। संक्षेप से हम कहना चाहें तो उसका दृष्टिकोण भौतिकवादी है। इहलोक के जीवन को ही वह सर्वोपरि लक्ष्य मानता है। उसकी सम्मति में धन या सम्पत्ति के साधनों के लिए संघर्ष ही मानव जाति की एक मात्र प्रेरणा रही है। मानव का समस्त इतिहास, मार्क्स की दृष्टि में आर्थिक या भौतिक उद्देश्यों से वर्ग-युद्ध का इतिहास है। धार्मिक या नैतिक आदर्शों को वह विश्व की प्रगति में कोई महत्व नहीं देता, साधन हीन वर्ग, मार्क्स की सम्मति में, साधनों की प्राप्ति के लिए अपने उच्च-वर्ग के साथ संघर्ष करता है और कुछ समय पाकर वह शक्तिशाली हो जाता है, परन्तु वह स्वयं शोषक बन जाता है और अपने से निम्न वर्ग का शोषण करने लगता है। इस तरह वर्ग-युद्ध तब तक जारी रहता है, जब तक भौतिक सम्पत्तियों में असमानता रहती है अर्थात् दो वर्ग संसार में रहते हैं। इसलिए मार्क्सने सम्पन्न और शक्तिशाली वर्ग के द्वारा होने वाले शोषण, अत्याचार और विरोध को समाप्त करने के उद्देश्य से एक नया क्रान्तिकारी विचार जनता को दिया कि विभिन्न वर्गों की समाप्ति कर दो। आज के संघर्ष और प्रतिस्पर्धा को सदा के लिए समाप्त करने के लिए विश्व में वर्ग-हीन समाज की स्थापना करनी चाहिये और इसके लिए आर्थिक समानता अत्यन्त आवश्यक है। यह आर्थिक समानता तब तक नहीं हो सकती, जब तक उत्पादन के सब साधनों तथा सम्पत्ति पर समाज या राष्ट्र का अधिकार नहीं हो जाता। उत्पादन और श्रम के साधनों पर से व्यक्ति का अधिकार हटाकर समाज का सामूहिक अधिकार स्थापित करने का नाम ही साम्यवाद है। आर्थिक समानता होने पर सामाजिक जीवन और सामाजिक सम्पर्कों में भावनाओं की असमानता भी समाप्त हो जायेगी। समाज में विद्यमान वर्ग-भेद समाप्त करने के लिए मार्क्स ने वर्गसंघर्ष आवश्यक बतलाया है। श्रमजीवी लोगों को पूंजी-पतियों के विरुद्ध उठ खड़ा होना होगा। ध्वंसात्मक एवं हर प्रकार के हिंसात्मक उपायों को अपनाकर किसी भी प्रकार राज्य सत्ता पर श्रमजीवी वर्ग को अधिकार करना होगा। इस वर्ग संघर्ष के उद्देश्य से मार्क्स ने विश्व भर के श्रमिकों का आह्वान किया। वह राष्ट्रीयता—देश-देश की अपनी भावना के विरुद्ध था। वर्ग संघर्ष की लड़ाई में देश के प्रति गद्दारी करके भी आन्दोलन में योग देने की उसने अपील की।

साम्यवाद तक क्रमिक रूप

मार्क्स ने 'क्रिटिक आफ दि गोथा प्रोग्राम' में अपने साम्यवादी समाज की कल्पना का स्पष्ट रूप चित्रित किया है। उसने साम्यवाद को दो भागों में विभक्त किया :—

१. साम्यवाद की प्रथम सीढ़ी 'समाजवादी व्यवस्था' होगी। वर्ग संघर्ष के परिणामस्वरूप पूंजीवाद का विध्वंस होने पर तुरन्त जिस नव समाज की रचना होगी, मार्क्स के अनुसार वह 'समाजवादी समाज' होगा न कि साम्यवादी। इसमें श्रमिक एक नये शासक वर्ग के रूप में अपने लिये

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

एक राज्य (the dictatorship of prolitariat) की आवश्यकता महसूस करेगा। इसमें श्रमिक शासन की तानाशाही होगी, साम्यवादी पार्टी की अखण्ड सत्ता होगी। केवल एक ही पार्टी—श्रमजीवी वर्ग की पार्टी ही तब रह जाएगी। उसके आदर्श और सिद्धान्त सम्पूर्ण समाज के आदर्श और सिद्धान्त माने जायेंगे। दूसरी भावना या पार्टी के उदय का सवाल ही नहीं उठेगा। इस स्तर पर पूंजीवादी भावनाओं का कुछ थोड़ा प्रभाव रह सकता है। इस समाज में व्यक्ति की आय जायदाद के स्वामित्व पर निर्भर न करके उसके काम पर निर्भर करेगी। कहना न होगा कि यह सामूहिकवादी (Collectivism) व्यवस्था होगी, जैसा कि रूस में है। इसमें सत्ता का पूर्ण केन्द्रीयकरण होगा।

इसके बाद समाज में अनेक प्रकार के क्रमिक विकास करके समाज साम्यवादी समाज के उच्चतर या अन्तिम स्तर पर पहुँचेगा। तब विश्वभर में श्रमिक वर्ग का आधिपत्य हो जाएगा, इसीलिये सभी श्रमजीवी रह जायेंगे और इस स्तर पर पहुँचकर राज्य की सत्ता भंग हो जाएगी। (The state will wither away)। श्रम के प्रति नई भावनाओंका उदय होगा। उस समय समाज के ध्वज पर यह संदेश फहरेगाः—सबसे काम तो योग्यता के अनुसार लिया जाएगा और आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक को दिया जाएगा। यह सुन्दरतम समाज होगा साम्यवादी समाज। साम्यवादी समाज, समाजवादी व्यवस्था का परिपक्व, सुधार, सुन्दरतम रूप है।

उत्पादन-क्रम

मार्क्स की दृष्टि में सामाजिक जीवन का आधार उत्पादन होता है। इसलिए किसी भी सामाजिक व्यवस्था के स्वभाव को जानने के लिए हमें उत्पादन-क्रम को जानना पड़ेगा। पूंजीवादी व्यवस्था के दो मुख्य वर्ग होते हैं। पूंजीपति एवं मजदूर। पूंजीपति मजदूर से कुछ उसकी सेवाएं मोल लेता है। दूसरी चीजों की तरह श्रमजीवी की मजदूरी भी बाजार की स्थिति (मांग और पूर्ति) पर निर्भर करती है।

पूंजीवादी व्यवस्था में जिसके पास द्रव्य है और यदि वह सचेत होकर उत्पादन का क्रम जारी रखता है, वह पूंजीपति हो जाता है। उसके पास पूंजी बढ़ती जाएगी। मार्क्स मूल्य के श्रम सिद्धान्त (Labour theory ofv alu e)पर विश्वास रखते हुए कहता है कि पूंजीपति जब एक श्रमिक को उत्पादन में लगाता है तो जितने घंटे मजदूर काम करता है, उसको दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम भाग में जितना उत्पादन होता है, उसका मूल्य श्रमिक के मजदूरी के ठीक बराबर हो जाता है। बाकी घण्टों में जितने मूल्य का वह उत्पादन कर पाता है, मार्क्स उसको अतिरिक्त मूल्य कहता है। और यही उसका लाभ है। अगर मजदूर आठ घण्टे काम करके एक दिन में चार ४) रु० के मूल्य के बराबर उत्पादन करता है और उसकी दिन की मजदूरी तीन रुपये है तो एक रुपया अतिरिक्त मूल्य हुआ, जो पूंजीपति की बचत होगी। आठ घंटे में ६ घंटा तो आवश्यक श्रम कहा जाएगा, जिससे वह अपनी मजदूरी भर पाता है और दो घंटा अतिरिक्त श्रम, जिसमें उत्पादक को वह अतिरिक्त मूल्य देता है। अतिरिक्त मूल्य का जो सम्बन्ध मजदूरी से होगा, उसे वह अतिरिक्त मूल्य की दर कहता है। पूंजीपति इस अतिरिक्त मूल्य की दर को अधिक से अधिक करना चाहता है। और सब बातें यदि समान हों तो प्रतिदिन काम के घंटों में वृद्धि करके, वास्तविक मजदूरी में कमी करके या श्रम के उत्पादन में वृद्धि करके पूंजीपति इसमें वृद्धि कर पाएगा और यही उसका ध्येय है।

दुष्परिणाम

पूंजी का संचय पूंजीपति का ध्येय हो जाता है। उसके बिना वह समाज में टिक नहीं सकता। वह उत्पादन बढ़ाता जाएगा और उसकी पूंजी बढ़ती जाएगी। परन्तु उत्तरोत्तर बढ़ते उत्पादन के लिए बाजार चाहिए। देश के बाजार में जब और गुंजाइश नहीं रहती, तो वह नए बाजारों की खोज करेगा। इस क्रम से वह विमुख नहीं हो सकता, क्योंकि इसी पर उसका अस्तित्व टिका रहता है, वह उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद का सहारा लेता है। मगर उसकी भी एक सीमा है। उसके आने पर अन्ततोगत्वा उसे पूंजीवाद को जारी रखने के लिए युद्ध और युद्ध की तैयारी का सहारा लेना पड़ता है, जिससे उसके मालों की खपत दुनिया के बाजारों में हो। तब वस्तुतः उत्पादन से आरम्भ करके विनाश की खाई में पहुँच जाता है। और

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इसलिए अगर खाई में गिरने के पूर्व ही—युद्ध की विभीषिका को हटाने के पूर्व ही यदि इस मूल लाभ प्राप्ति की भावना या पूंजीवाद को खतम नहीं कर दिया गया, तो युद्ध होगा।

बहुत संक्षेप में मार्क्सवाद की यही व्याख्या है।

मार्क्सवाद को समझने के लिये केवल ऊपर लिखी बातें ही काफी नहीं हैं। इसे समझने के लिये कुछ और बातें भी आवश्यक हैं। कार्ल मार्क्स की यह मान्यता थी कि समाजवाद की स्थापना के लिये क्रान्ति और हिंसात्मक संघर्ष आवश्यक है। मार्क्स के प्रमुख व्याख्याकार लेनिन ने 'दि स्टेट एण्ड रेव्वोलूशन' में लिखा है कि मध्यवर्गीय राज्य के स्थान में सर्वहारा राज्य हिंसात्मक क्रान्ति के द्वारा स्थापित हो सकता है। यह सर्वहारा राज्य वर्ग-भेद या वर्ग-संघर्ष को समाप्त करके उत्पादन के समस्त साधनों को समाजके हाथों सौंप देगा, तब राज्य की आवश्यकता ही न रहेगी। न कानून बनाने की आवश्यकता रहेगी न पुलिस की। राज्य का ढांचा व्यर्थ का भार होगा और आप ही आप टूट जायेगा। ऐंजैल्स के शब्दों में—"राज्य मुरझा कर झड़ जायेगा।"

लेनिन के विचार

लेनिन ने ऐंजल्स के इस सिद्धान्त पर टीका करते हुए कहा है कि दस हजार लोगों में से ९९९० राज के पतझड़ के सिद्धान्त को नहीं समझते और बाकी दस में से नौ यह नहीं जानते कि जनता के स्वतंत्र राज्य का क्या अर्थ है। सर्वहारा वर्ग की राजसत्ता ही स्वयं मुरझाती है, परन्तु यह सर्वहारा-वर्ग की सरकार १०-२० वर्ष में नहीं मुरझायेगी। यह स्थिति आने में समय लगेगा। समाजवादी को राज्य पर अधिकार करना ही होगा। समाजवादी क्रान्ति का अर्थ ही शोषित वर्गके हाथ में राजनीति के अधिकार पाना है। समाजवादियों की यह भी सम्मति है कि समाजवादी-व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि समाजवादी देश में एक नहीं, एक मात्र राजनैतिक दल हो। अपने कार्य में स्थायित्व लाने के लिए साधारण पार्लमेंट्री ढंग को अपनाने में वे रुचि नहीं लेते। वहाँ तो एक दलकी सत्ता चलेगी।

मार्क्सवाद की व्यवहार में परिणति का नेता

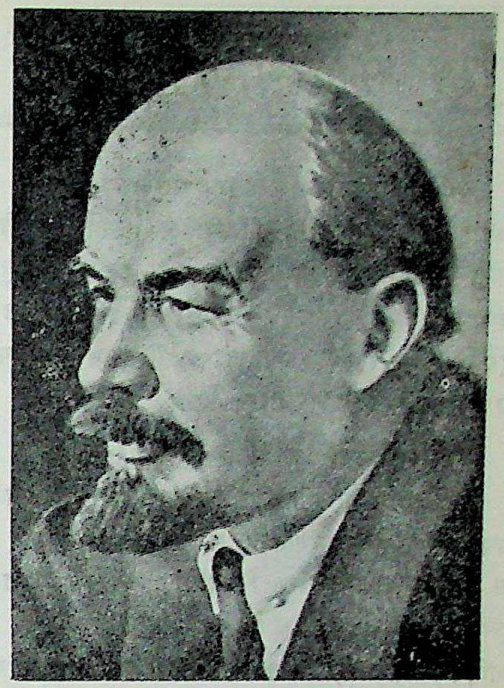

महान् लेनिन

आध्यात्मिकता को स्थान नहीं

मार्क्स के दार्शनिक विचारों में आस्तिकता अथवा ईश्वर की सत्ता आदि का कोई स्थान नहीं है। वह धर्म को जनता के बहकाने के लिए अफीम मानता था। मार्क्स प्रकृति या जड़-प्रकृति को ही संसार का मूल कारण मानता है। आध्यात्मिक चेतन शक्ति का उसकी दृष्टि में कोई स्थान नहीं है।

एक के बाद एक करके जब तक समस्त देशों में समाजवाद स्थापित नहीं हो जाता, तब तक समाजवादी दूसरे असमाजवादी देश को अपना शत्रु मानेगा। लेनिन कहता है "हम एक ही राज्य में नहीं रह रहे हैं, वरन् राज्यों की शृंखला के बीच में हैं। बहुत दिनों तक सोवियत प्रजातंत्र (रूस) साम्राज्यशाही राज्यों के साथ नहीं रह सकता। अन्त में दो में से एक की विजय होगी। इस अन्त के पहिले सोवियत और पूंजीशाही राजों में कई

[शेष पृष्ठ ५७८ पर]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

यूरोप में समाजवाद का जन्म

कृष्णचन्द्र विद्यालंकार

यद्यपि मार्क्स के नाम के साथ साम्यवाद का नाम जुड़ा हुआ है, तथापि समानता की भावना काफी पुरानी है। भारत और योरपके धर्म-नेताओंने बार-बार त्याग, दूसरोंके साथ दया, धर्म और लोभ के विरोध आदि के उपदेश दिये हैं। तथापि यह मानना चाहिए कि इन सब उपदेशों का उद्देश्य आर्थिक न रहकर धार्मिक ही रहा।

आर्थिक और सामाजिक समानता

आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से योरुप में प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'प्रजातन्त्र' में यह विचार प्रगट किया था कि धन आलस्य और बिलासिता को पूर्ण करता है, इसलिये सम्पत्ति पर एक व्यक्तिका अधिकार नहीं होना चाहिये। उसने पत्नियों तक को समाज की सम्पत्ति बनाने की राय दी थी। सैंट अगस्टाइन ने भी साम्यवाद का एक काल्पनिक चित्र हमारे सामने खींचा। जोन बिकालिफ ने वैयक्तिक सम्पत्तिका विरोध करते हुए राजतन्त्री साम्यवाद का समर्थन किया। सर थामस मोर (सन् १४७८ से १५८५) ने वैयक्तिक-सम्पत्ति का विरोध किया और प्रत्येक व्यक्ति से केवल ६ घंटे काम और ८ घंटे आराम की मांग की। इंग्लैंड और फ्रांस में समय-समय पर छोटे-मोटे किसान विद्रोह होते रहे। इंग्लैंडके गृहयुद्ध (१६४२ से १६५२) में समाजवाद की भावना अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट हुई। जेरार्ड वेन्सटैली ने अपने क्रान्तिकारी निबंधों में कहा कि निजी जायदाद के स्वामित्व ने समाज को गरीब और धनी दो वर्गों में ही नहीं विभाजित किया, वरन् इसने मनुष्य के बीच नफरत पैदा कर दी है। उसने यह भी कहा कि धरती सबकी है, जिसे भगवान ने हमें प्रदान किया है। पीटर चैम्बरलेन ने भी सम्पत्ति के राष्ट्रीयकरण की सलाह देते हुए कहा कि सम्पत्तिहीन श्रमजीवी ही राष्ट्र की सम्पत्ति और शक्ति हैं।

फ्रांस की राज्य-क्रान्ति ने साम्यवादी भावना को और भी प्रगति दी। अनेक क्रान्तिकारी इस समाजबादी विचार का प्रचार करते रहे कि सम्पत्ति की असमानता नष्ट हो जानी चाहिये। बैवफ आदि क्रान्तिकारियों ने राज्यसत्ता को उलट देने का एक असफल षडयंत्र भी रचा। उसका कहना था कि समाज का उद्देश्य सब का सुख है और यह समानता के बिना सम्भव नहीं। इन नेताओं को फांसी पर लटका दिया गया।

१९ वीं शताब्दि में इंग्लैंड और फ्रांस में समाजवादी विचारधाराओं का एक स्कूल बन गया था। इसमें प्रमुख व्यक्ति सेंट साइमन, फुरियर, प्राउढन और रौबर्ट ओवन थे। सेंट साइमन की भावना धार्मिक थी। फुरियर शान्ति का पक्षपाती और हिंसा का विरोधी था। लूई ब्लाक ने कहा कि हर एक से शक्ति के अनुसार काम लेना चाहिये और जरूरत के अनुसार देना चाहिये। पराउढन अधिक सम्पत्ति को चोरी समझता था। ये सब व्यक्ति मानवतावादी थे और इसलिए धनियों से सहयोग की आशा करते थे। इनके पास कोई व्यावहारिक योजना नहीं थी, जिससे समाजवाद को क्रिया में परिणत कर सकते।

> "बगैर मेहनत के जो कमाई है, उस पर मनुष्य का अधिकार नहीं। उस सम्पत्ति का निराकरण हम नहीं चाहते जो मनुष्य को अपने परिश्रम से प्राप्त हुई है।"
>
> —मार्क्स

समाजवादका सर्वप्रथम प्रयोग

रौबर्ट ओवन इंग्लैण्ड का पहला व्यक्ति था, जिसने मजदूरों के लिए कुछ व्यावहारिक उपाय बताये और मिलों के मजदूरों के लिए १८१९ में कारखानोंका कानून बनवाया। रौबर्ट ओवन ने ही, जो स्वयं मैनचेस्टर का ही मिल मालिक था, कहते हैं सबसे पहले समाजवाद शब्द का प्रयोग किया। वह मजदूरों की सहयोग समितियां

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

साम्यवाद का विकास

> जो लोग दलित हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, उनका पहला उद्धारकर्ता था—मार्क्स। उनके लिए वह पहला मसीहा बनकर आया। मैं तो यहां तक कहता हूं कि दस अवतारों के साथ एक तरह से वह ग्यारहवां अवतार लेकर ही आया है।
>
> मार्क्स को गरीबों का मसीहा कहने का मुख्य कारण यह है कि गरीबी और अमीरी का निराकरण हो सकता है, होना चाहिए और होकर ही रहेगा, यह बात किसी भी पैगम्बर ने, किसी भी धर्म प्रवर्तक ने, किसी भी ऋषि या अवतारी पुरुष ने कार्ल मार्क्स से पहले नहीं कही थी। यह एक ऐसी बात थी, जिसे मैं कार्ल मार्क्स की बहुत बड़ी विशेषता मानता हूं।
>
> —दादा धर्माधिकारी

यों अमीर गरीब का भेद अत्यन्त प्राचीन काल से चला आ रहा है, लेकिन वर्तमान औद्योगिक क्रान्ति और बड़ी बड़ी मशीनों के आने के बाद यह भेद बहुत अधिक तीव्र और स्पष्ट रूपसे हमारे सामने आया। पहले गाँवों में हर एक कारीगर अपने लिए अपनी चीज तैयार करता था और बेच देता था, लेकिन कल-कारखानों के प्रचार के बाद हर एक कारीगर मिल मालिक का नौकर हो गया और उसी के लिए माल तैयार करने लगा। उसका मुनाफा मालिक को मिला और थोड़ी सी नाकाफी मजदूरी कारीगर को। परिणाम यह हुआ कि मिल-मालिक ज्यादा अमीर बनता गया और कारीगर ज्यादा गरीब। उस समय के अनेक विचारकों का ध्यान इधर गया। उन्होंने साधारण जनता का ध्यान मजदूरों की दयनीय दशा की ओर खींचा। उन्नीसवीं सदी के एक महान अंग्रेज राजनीतिज्ञ और उपन्यासकार बेंजमिन डिसराइली ने इनका वर्णन इस तरह किया है—"ये दो (अमीर और गरीब) जातियाँ, जिनके बीच कोई सम्पर्क नहीं है, कोई पारस्परिक सहानुभूति नहीं है, जो एक दूसरे की आदतों, विचारों और भावनाओं से ऐसी अपरिचित हैं, मानो वे जुदा दायरों में रहती हों अथवा जुदे जुदे नक्षत्रों के रहने वाले हों, जो दूसरे तरह के शोषण से बनी हैं, जिनका पालन दूसरे तरह के भोजन से हुआ है, जिन पर जुदा जुदा रिवाजों का असर पड़ता है और जिनका शासन भी एक ही कानून से नहीं होता.....हाँ, ऐसी हैं ये दो जातियाँ—अमीर औरगरीब।"

मार्क्स का प्रादुर्भाव

इन दोनों श्रेणियों के पारस्परिक भेद-भाव को दूर करके समानता लाने के विचार अनेक विचारकों ने पेश किये। इनमें जर्मनी का कार्ल मार्क्स सबसे प्रसिद्ध था। उसने समानता

बनाने और मजदूरों के कारखानों में हिस्सा लेने का भी समर्थन करता था। अमरीका में दास-प्रथा की समाप्ति और इंग्लैण्ड में दास-व्यापार का विरोध समाजवाद की दिशा में बहुत बड़े कदम थे। १८६८ ई० में ब्रिटिश पार्लमेण्ट ने शहरी मजदूरों को भी मत देने का अधिकार दिया। अराजकतावादी विचारक भी कुछ लोगों के हाथ में शक्ति केन्द्रित करने का विरोध करते रहे। ये सब समाजवादी आदर्श और कल्पना की बातें अधिक करते थे, इसलिए आदर्शवादी या कल्पनावादी कहलाये। यद्यपि इनके आन्दोलन सफल नहीं हुए, तथापि इन्होंने वह पृष्ठभूमि और वातावरण तैयार कर दिया, जिसमें पेरिस के फ्रैडरिक ऐंजल्स और जर्मनी के कार्ल मार्क्स ने अपने विचारों को स्पष्ट निश्चित और वैज्ञानिक रूप देने का साहस किया। १८४८ ई० में इन्होंने वह प्रसिद्ध साम्यवादी घोषणा-पत्र निकाला, जो आज भी साम्यवादियों के लिए वेद-वाक्य की तरह से प्रमाण माना जाता है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के जिस सिद्धान्त का प्रचार किया, उसे ही हम मार्क्सवाद, सोशलिज़्म या समाजवाद का नाम देते हैं। यों कार्ल मार्क्स से बहुत पहले भी सर थामस मोर, फोरियर, राबर्ट ओवन, प्राउडन आदि ने ऐसे ही कुछ विचार पेश किये थे, लेकिन कार्ल मार्क्स ने इसे सबसे अधिक वैज्ञानिक रूप दिया और इसके प्रचार के लिए १८६४ में एक निश्चित संगठन भी स्थापित किया। यही मजदूरों का पहला व्यापक संगठन था। मार्क्स ने एक आवाज़ उठाई—"संसार के मजदूरो, एक हो जाओ और पूंजीवाद का जुआ उतार फेंको।" मार्क्स का स्थापित किया हुआ यह संघ 'प्रथम इण्टरनैशनल' के नाम से विख्यात है। इसके कई हजार सदस्य थे।

लेकिन यह संगठन बहुत समय तक स्थिर नहीं रह सका, क्योंकि इसमें सम्मिलित होने वाले भिन्न भिन्न विचारों के मानने वाले थे। योरुप के कई पराधीन देशों के अनेक प्रतिनिधियों में समाजवाद की भावना इतनी प्रबल नहीं थी, जितनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की। रूस के आन्दोलनकारी बैकुलिन के नेतृत्व में अराजकतावादी भी दक्षिणी योरुप के इटली, स्पेन आदि देशों से आये थे। इनकी इच्छा सरकारों से तुरन्त लड़ाई मोल लेने की थी। वस्तुतः बैकुलिन गरीब और असंगठित मजदूरों, शिक्षितों और असन्तुष्ट लोगों का प्रतिनिधि था। दूसरी ओर मार्क्स संगठित और खुशहाल मजदूरों का। मार्क्स एकदम संघर्ष मोल लेने के पक्ष में नहीं था। वह समय की प्रतीक्षा करने और तब तक मजदूरों को समाजवादी सिद्धान्तों के शिक्षण और उसी ढंग पर उनका समर्थन करता था। यद्यपि प्रारम्भ में मार्क्स की जीत हो गई तथापि 'प्रथम इण्टरनेशनल' बहुत समय तक स्थिर नहीं रह सका।

समाजवाद का वेद

१८६७ में कार्ल मार्क्स ने अपना प्रसिद्ध ग्रन्थ 'कैपिटल' पूंजी लिखा। यह वैज्ञानिक और दार्शनिक ग्रन्थ आज भी समाजवादियों के लिए वेद-वाक्य

अक्तूबर का गीत

[अक्तूबर की क्रान्ति में रूस की जनता में क्रान्ति का जो गीत बहुत प्रचलित हो गया था, उस गीत का हिन्दी अनुवाद नीचे दे रहे हैं।]

"हम रोटी और काम की भीख मांगते ही जाते थे। हमारे हृदय दुःख से पीड़ित और शिथिल थे। अंगूठा दिखाने की ताकत से हीन हाथों की तरह कारखानों की चिमनियां आकाश की तरफ इशारा कर रही थीं। हमारे दुख और दर्द के शब्दों से शांति, मामूली तरीके की बनिस्बत कहीं ज्यादा, भंग हो रही थी।

टूटे हुए हाथों की आकांक्षा सा ओ लेनिन! हमने समझ लिया है; लेनिन! हमने समझ लिया है कि हमें लड़ना, लड़ना और लड़ना है। तुमने अन्तिम लड़ाई तक हमें पहुंचाया। तुमने हमें श्रमिकों की विजय दी और कोई अज्ञान और अत्याचार पर उस विजय को हमसे छीन नहीं सकता। कोई नहीं! कोई नहीं! कभी नहीं! कभी नहीं!

लड़ाई में, संघर्ष में हरेक को युवा और बहादुर होने दो; क्योंकि हमारी विजय का नाम 'अक्तूबर' है। अक्तूबर! अक्तूबर! अक्तूबर सूर्य का सन्देशवाहक है। अक्तूबर विद्रोही शताब्दियों का संकल्प है। अक्तूबर! यह श्रम है, आनन्द है, गान है। अक्तूबर! यह खेतों और मशीनों का सौभाग्य है। यह युवा पीढ़ी और लेनिन के नाम का झण्डा है।"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

है, भले ही उनमें बहुत सी चीजें पुरानी पड़ गयी है। परन्तु, 'इण्टरनेशनल' के संचालन में मार्क्स के सम्मुख दो प्रमुख कठिनाइयां आईं, जिनके कारण उसने संस्था का प्रधान कार्यालय सात समुद्र पार अमरीका के न्यूयार्क शहर में भिजवा दिया। पहली कठिनाई यह थी कि १८७१ में पेरिस की पंचायत की स्थापना हुई। यह शायद पहली समाजवादी क्रान्ति थी। इससे योरुप की सरकारें डर गईं और मजदूर-आन्दोलन की तरफ से उनका रुख और भी कठोर हो गया। इस कारण यह भय हो गया कि योरुप की सरकारें इस संगठन को आसानी से चलने नहीं देंगी। बैकुनिन के अराजकतावादी अनुयायी भी उसे बहुत तंग कर रहे थे। उनसे पीछा छुड़ाना भी आवश्यक था। परन्तु दीर्घकाल तक संगठन-कार्यालय का योरुप के मुख्य केन्द्रों से अलग रहना सम्भव नहीं था। इसलिए पहला अन्तर्राष्ट्रीय संगठन धीरे-धीरे निष्प्राण होकर खत्म हो गया। लेकिन यह जाते-जाते भी योरुप पर महान् प्रभाव छोड़ गया। विभिन्न देशों के मजदूरों में संगठन और जागृति के भाव पैदा हुए। पूंजीपतियों के शोषण के विरुद्ध आवाजें उठने लगीं। मजदूरों के संगठन स्थान-स्थान पर बनने लगे। दमन के बावजूद जागृति और संगठन का आन्दोलन जोर पकड़ता गया। इनका प्रभाव बढ़ने के साथ साथ सरकारों को झुकना पड़ा और तरह तरह के मजदूर कानून बनने लगे। यह एक आश्चर्य की बात है कि इंगलैण्ड में जो पहला फैक्टरी का कानून बना था, वह एक दयालु मिलमालिक मि० ओवन के विचार और परिश्रम का परिणाम था। इस कानून के अनुसार ९ वर्ष के बच्चों से १२ घंटे से ज्यादा काम लेना गैरकानूनी करार दे दिया गया। मजदूरों की तब कैसी दर्दनाक हालत थी, वह इसी धारा से स्पष्ट है।

•

योरुप के भिन्न-भिन्न देशों में समाजवाद ने भिन्न-भिन्न रूप धारण किया। मार्क्स की विचारधारा जर्मनी और आस्ट्रिया में समाजवादी लोकतंत्र (Social Democracy) के नाम से प्रसिद्ध हुई। इंगलैण्ड में बहुत नरम नीति अपनाई गई जो शनैःगामी सेनापति फैबियन के नाम से फैबियनिज्म के रूप में प्रचलित हुई। ये लोग शनैः शनैः परिवर्तन के पक्ष में थे। फ्रांस में अराजकतावाद और समाजवाद का समन्वय किया गया और संघवाद या सिंडिकेलिज्म के रूप में यह आन्दोलन चला।

दूसरा इण्टरनेशनल

मार्क्स का देहान्त १८८३ में हुआ। उस समय तक योरप के अनेक देशों में मजदूर आन्दोलन संगठित हो चुका था। विभिन्न देशों के साम्यवादी नेताओं ने १८८९ में फिर एक अन्तर्राष्ट्रीय संघ की नींव डाली। यह 'द्वितीय इण्टरनेशनल' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। समाजवादियों का निश्चित विचार था कि विभिन्न राष्ट्रों के युद्ध पूंजीपतियों के स्वार्थों से प्रेरित होते हैं। इसलिए जनता को इन युद्धों में भाग नहीं लेना चाहिए। इसका प्रचार भी खूब जोरों से किया गया। लेकिन जब १९१४ में योरप का महायुद्ध शुरू हुआ, तो अधिकांश समाजवादी अपने-अपने देश की सीमा से बाहर न सोच सके और युद्ध में सहयोग देने के लिए तैयार हो गये। फलतः यह संगठन भी २५ वर्ष के जीवन के बाद टूट गया। मजदूरों के नेता अपने-अपने देश के स्वार्थ के लिए युद्ध में लिप्त हो गये। मजदूर-आन्दोलन के समय उन्होंने जो लोक-प्रियता प्राप्त की थी, उसके कारण सरकारों ने उन्हें बड़े बड़े पद दे दिये। युद्ध के बाद जर्मनी के समाजवादी लोकतंत्र के नेता प्रजातंत्र के अध्यक्ष या प्रधानमंत्री बने। फ्रांस में आम हड़ताल का पक्षपाती आग उगलने वाला संघवादी ब्रियाँद ११ बार प्रधान मंत्री बना और उसने पुराने साथियों की हड़ताल को कुचला। इंगलैण्ड के प्रसिद्ध मजदूर नेता रैमजे मैकडोनल्ड प्रधान मंत्री बने और उन्होंने अनुदार दल का सहयोग प्राप्त किया। इटली के कर्णधार मुसोलिनी और पौलैण्ड के सर्वेसर्वा पिलसूदस्की समाजवादी नेता थे। क्रोपाटकिन जैसे अराजकतावादी भी गिर कर राष्ट्रवादी बन गये। स्वीडन, डेन्मार्क, बेलिजयम और आस्ट्रिया आदि में भी पहले के समाजवादियों ने शनैः शनैः अपनी उग्रता छोड़ दी और अपने साथियों का साथ छोड़ कर देश के शासन-सूत्र सम्भाल लिये और समय-समय पर समाजवादी आन्दोलन को दबाने में लग गये।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रूस में समाजवादी क्रान्ति और उसके बाद

प्रथम महायुद्ध से पूर्व समाजवाद की विभिन्न शाखाएं अपने अपने देश में प्रस्फुटित और विकसित हो रही थीं। उधर रूस में लेनिन ने युद्ध के समाप्त होने के बाद 'तीसरे इण्टरनेशनल' की स्थापना कर दी थी। इसके परिणाम-स्वरूप समाज-वादियों में दो दल स्पष्ट हो गये। नरम दल के सोशलिस्ट जैसा कि हमने उपर कहा है, शासक दल में सम्मिलित हो गये। उन्होंने क्रान्ति का मार्ग छोड़कर सुधारवादी नीति को अपनाया। वे मजदूरों को सुविधाएं देने के कानून बनाने में लग गये। कुछ समाजवादी नेताओं ने दूसरे और तीसरे 'इण्टरनेशनल' में एक कड़ी जोड़ने का काम किया और २॥ वां 'इंटरनेशनल' (Two and a half International) स्थापित किया। किन्तु यह चल नहीं सका। समाजवादियों का संघर्ष योरप में तब तक चलता रहा, जब तक कि हिटलर ने जर्मनी में नाजी पार्टी का शासन स्थापित नहीं कर लिया।

रूस में नव-स्थापित "तीसरा इण्टरनेशनल" रूसी शासन का प्रबल समर्थन और अनन्त साधन पाकर पुष्ट होता गया। इसका मुख्य कार्य-क्षेत्र यद्यपि रूस रहा, तथापि विभिन्न देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों की स्थापना तथा साम्यवादी भावों का विचार भी इसका मुख्य कार्य रहा। प्रायः सभी देशों के साम्यवादी दल इसके प्रभाव में थे और इससे सहायता पाते रहे। इसके आदर्श और नीति समस्त संसार के साम्यवादी दलों की (जिनमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी है) नीति रही है। ये कम्युनिस्ट पार्टियाँ अपने अपने देशों की सरकारों के लिए सदा सिर-दर्द रहीं। भारत की ही कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा रूस की नीति के अनुसार अपनी आर्थिक और राजनीतिक नीति बदलती रही है। इसी तीसरे कम्युनिस्ट इण्टरनेशनल को 'कामिण्टर्न' कहते हैं।

स्टालिन और ट्राटस्की

लेनिन की मृत्यु के बाद स्टालिन और ट्राटस्की में गम्भीर मतभेद हो गया। ट्राटस्की यह समझता था कि समाजवादी क्रान्ति के लिए समस्त संसार में विश्व-क्रान्ति आवश्यक है। केवल एक देश तक समाजवादी प्रवृत्तियों को रखने से या सीमित करने से रूस की क्रान्ति खतरे में पड़ जायगी। स्टालिन फिलहाल विश्वक्रान्ति के फेर में पड़कर रूस के आर्थिक विकास को रोकना नहीं चाहता था और वह पंचवर्षीय योजना की पूर्ति में लग गया। ट्राटस्की क्रान्ति चाहता था, भले ही इसके लिए भीषण कठिनाई में से गुजरना पड़े। उसने कहा था कि "अगर हमारे समय का कोई आदमी और सब बातों से पहले सुख और शान्ति चाहता है तो उसने संसार में जन्म लेने के लिए बहुत बुरा समय चुना है।"

ट्राट्स्की की करुण मृत्यु कैसे हुई, इस दुखद प्रकरण की चर्चा न करते हुए भी यह कहना आवश्यक होगा कि उसने अपनी मृत्यु से पहले मैक्सिको में एक 'चौथा इण्टरनेशनल' की स्थापना की थी। उसकी सम्मति में स्टालिन साम्यवाद के लिए गद्दार था। 'एक देश में साम्यवाद की स्थापना लेनिन की अन्तर्राष्ट्रीय क्रान्ति से बिलकुल

[समाप्त

इण्टर नेशनल का गीत

उठ जाग भूखे बन्दी
अब खींच ला तलवार
कब तक सहोगे भाई
जालिम का अत्याचार—१

तुम्हारे रंग से रंग चितरंजन
अब दश दिश लाया रंग
यह सौ रक्त का बन्धन
एक करेंगे रंग—२

यह जंग अन्त न है जिसका
जीतेंगे हम एक साथ
कहो इन्टर नेशनल
यह स्वतन्त्रता का ३ान ।—३

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विरोधी चीज है। यह 'चौथा-इण्टरनेशनल' बहुत चल नहीं सका। इधर योरप में नाजियों व फासिष्टों के प्रभाव के कारण शिथिल होते हुए समाजवाद का पुनः प्रचार करने के लिए 'तीसरे-इण्टरनेशनल' ने 'पापुलर फ्रन्ट' पर जोर दिया। इसमें कम्युनिस्ट, सोशालिस्ट और अन्य उदार दल मिल कर शासन-चक्र पर अधिकार करने का प्रयत्न करने लगे। फ्रांस और स्पेन में अस्थायी सफलताओं के बाद यह फ्रन्ट प्रायः समाप्त हो गया।

किंतु नये विश्व व्यापी युद्ध का यह परिणाम हुआ कि रूस को अपनी 'तीसरीइण्टरनेशनल' समाप्त करनी पड़ी क्योंकि युद्ध में रूस के साथी ब्रिटेन, और अमेरिका ऐसी कोई संस्था सहन नहीं कर सकते थे, जो उनकी सरकारों के बरखिलाफ उन देशों में कम्युनिज्म या साम्यवाद का प्रचार करें, इसलिये जर्मनी से यह युद्ध छिड़ने के बाद रूस ने अपनी 'तीसरी इण्टरनेशनल' को भंग कर दिया, यद्यपि रूस ने ऊपरी तौर पर यह प्रकट किया कि अब विभिन्न देशों में साम्यवादी दल स्वयं अपनी नीति निर्धारित करने में समर्थ हो गये हैं, उन्हें हमारे नियंत्रण व निर्देश की आवश्यकता नहीं है।

युद्ध समाप्त होने के बाद जब पूर्वी योरप के देशों पर रूस का कठोर नियंत्रण हो गया तो फिर सब देशों को एक सूत्र में नियंत्रित करने के लिए १९४७ में एक नई संस्था बनायी गयी। इसका नाम 'कामिन फार्म' (कम्युनिस्ट इन्फार्मेशन) रखा गया। इसका काम विभिन्न देशों में होने वाली साम्यवादी प्रवृत्तियों की सूचना देना था। इसकी ओर से एक पत्र भी निकलता था, जिसका नाम 'फार दि लास्टिंग पीस फार दि पीपल डेमोक्रेसी था।' यद्यपि इस संस्था का उद्देश्य केवल सूचना प्रसार था, तथापि विविध देशों के साम्यवादी दलों को इसके द्वारा प्रायः आवश्यक निर्देश मिलते रहते थे। १९५५ में जब रूस ने भारत के साथ मित्रता करनी चाही, तब पंडित नेहरू के परामर्श देने पर इस संस्था को भी भंग कर दिया गया। इस तरह अब कम्युनिस्ट रूस की ओर से साम्यवाद के प्रसार के लिए कोई अन्तर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है। रूस की जर्मनी के साथ सन्धि और फिर युद्ध ने विभिन्न देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों को बहुत दुविधा में डाल दिया। एक समय ऐसा आया, जब चीन को छोड़ कर बाकी सब देशों में कम्युनिस्ट पार्टी प्रायः समाप्त हो गई। रूस और जर्मनी में युद्ध छिड़ते ही भारत के कम्युनिस्ट ब्रिटिश सरकार से सब सुविधाएँ पाकर फिर मैदान में आ गये।

गत महायुद्ध के अन्त तक कम्युनिष्ट पार्टी और साम्यवादी आन्दोलन की चर्चा हमने संक्षेप में की है। युद्ध के बाद की घटनाएँ बहुत ताजी हैं। पूर्वी योरप के अनेक देशों पर रूस का अधिकार या नियंत्रण रहा है। फलतः इन देशों में रूसी नीति के अनुकूल साम्यवादी दलों का शासन है। यूगोस्लोविया में रूसी नीति से मतभेद बहुत तीव्र हो गया। पोलेण्ड और हंगरी में भी रूस के प्रति असन्तोष प्रकट होने के लक्षण पिछले दिनों दिखायी दिये हैं। चीन में कम्युनिस्ट क्रान्ति के बाद संसार में कम्युनिस्ट प्रभाव बहुत बढ़ गया है। इण्डो-चायना में कम्युनिस्टों की शक्ति निरन्तर बढ़ती जा रही है। कुछ अन्य देशों में भी कम्युनिस्ट दल शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। भारत के केरल राज्य में कम्युनिस्ट दल का शासन है। मध्य-पश्चिम के मुस्लिम देशों में रूस और अमरीका जो शक्ति-संघर्ष कर रहे हैं, उसमें साम्यवादी दल निरन्तर शक्तिशाली हो रहे हैं।

ब्रिटेन के नेतृत्व में चलने वाली सोशलिस्ट इण्टर नेशनल संस्था का संबंध आज भी अनेक देशों से है। वस्तुतः यह दूसरे इण्टर नेशनल का अवशेष है।

साम्यवाद का भविष्य क्या है, इसका उत्तर भिन्न-भिन्न विचारक अलग-अलग देते हैं। 'सम्पदा' के पाठक भी स्वयं इसका उत्तर सोचेंगे।

——

क्रान्ति का आवाहन

"फिर भी हमें यह न भूलना चाहिए कि योरप में छठी सत्ता भी है, जो खास-खास मौकों पर पाँचों बड़ी कहलाने वाली सत्ताओं पर अपनी प्रभुता रखती है और उन सबको थरथरा देती है। यह सत्ता क्रान्ति की सत्ता है! इसे चुपचाप एकान्तवास करते हुए बहुत दिन हो गये। अब मुसीबतें और भूख इसे फिर लड़ाई के मैदान में बुला रही हैं। सिर्फ एक इशारे की जरूरत है। फिर तो योरप की छठी और सबसे बड़ी ताकत चमकता हुआ कवच पहने और हाथ में तलवार लिए निकल पड़ेगी। यह इशारा आने वाले योरप के युद्ध से मिल जायगा।"

—मार्क्स

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

समस्त संसार समाजवाद की ओर

जब १९१७ में रूस की महान् क्रान्ति हुई थी, तब यूरोप के अनेक देशों और जापान ने इस क्रान्ति को विफल करने के लिए उस पर चढ़ाई कर दी थी। इस प्रयत्न में असफल होने के बाद भी पूंजीवादी राष्ट्रों ने रूस का आर्थिक बहिष्कार कर दिया था। इस तरह रूस समस्त संसार से अकेला रह गया; उस समय पूंजीवादी राष्ट्रों ने यह समझ लिया कि न केवल साम्यवाद की प्रगति रुक गयी, बल्कि रूस में भी साम्यवादी शासन असफल हो जायगा; लेकिन गत चालीस वर्षों का इतिहास बताता है कि उनके दोनों स्वप्न पूर्ण नहीं हुए। रूस आज भी साम्यवादी शासन के नीचे निरन्तर उन्नति कर रहा है। रूस के अतिरिक्त संसार का एक बहुत बड़ा भाग आज साम्यवादी या समाजवादी पद्धति को अपनाये हुए है। आज तो स्थिति यह है कि साम्यवादी राज्यों की सीमा को पार कर साम्यवाद की विचारधारा उन देशों में भी भिन्न-भिन्न रूपों में प्रज्वलित हो रही है जो अपने को लोकतंत्री देश कहते हैं।

साम्यवादी और लोकतंत्री देश

साम्यवाद और लोकतंत्र इन दो नामों से आज संसार बंटा हुआ है। इन दोनों में प्रधान अन्तर यह है कि साम्यवादी देशों में सरकार का बल और अधिकार इतने अधिक हैं कि व्यक्ति के स्वतंत्र विकास की गुंजाइश बहुत कम रहती है। औद्योगिक, आर्थिक, व्यापारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में सरकारी, अधिकारी जो वहां के एकमात्र राजनैतिक दल के भी नेता होते हैं, नीति और कार्यक्रम का निर्धारण करते हैं। वे विकास की एक निश्चित योजना बनाते हैं, जिसके अनुसार समस्त राष्ट्र को चलने के लिए विवश होना पड़ता है। लोग अपनी-अपनी इच्छाओं से खेती, उद्योग, व्यापार आदि नहीं कर सकते। सरकार ही वहां निर्णय करती है कि कौन-सी फसल किस मात्रा में बोयी जाये और कौन से कारखाने कितनी उत्पादन-क्षमता के खोले जायें, यातायात की क्या नीति निर्धारित की जाये और पदार्थों के मूल्य या मजदूरों के वेतन कितने रखे जायें। मतलब यह है कि साम्यवादी शासन में स्वतंत्र उद्योग या स्वतंत्र अध्यवसाय का बहुत कम स्थान रहता है। सरकार प्रायः प्रत्येक क्षेत्र पर जनता को परामर्श ही नहीं, आदेश देती है।

इसके विपरीत पूंजीवादी देशों में व्यक्ति की स्वतंत्रता कायम रहती है। वहां प्रत्येक व्यक्ति किसी भी राजनैतिक दल में सम्मिलित हो सकता है, विचार प्रकट कर सकता है, अपने जीवन का क्षेत्र निर्धारित कर सकता है, अपनी आजीविका के लिये कोई भी उद्योग, व्यापार, पेशा आदि चुन सकता है। भिन्न-भिन्न व्यक्ति अकेले या एक कम्पनी स्थापित करके कोई नया उद्योग चला सकते हैं और व्यापारिक व्यापार कर सकता है। सरकार उद्योग के स्वतंत्र विकास में कम-से-कम हस्तक्षेप करती है। उद्योगपति या व्यापारी निजी लाभ की खातिर अपना रुपया खतरे में लगाते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि इस निजी लाभ की प्रेरणा से विश्व में औद्योगिक विकास चरम-सीमा पर पहुँचा गया है। संक्षेप में न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप और व्यक्ति का स्वतंत्र विकास, ये दो विशेषताएं लोकतंत्री देशों की हैं।

साम्यवाद का बढ़ता प्रभाव

बीसवीं शताब्दी के पिछले चार दशकों पर एक सरसरी दृष्टि डालने से यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि साम्यवादी विचारधारा समस्त संसार पर अपना प्रभाव बढ़ाती जा रही है। जब-जब देशों में असाधारण परिस्थिति उत्पन्न हुई, सरकार ने अपने अधिकार बढ़ा लिये और आर्थिक क्षेत्र में निर्देश और नियंत्रण देने प्रारम्भ कर दिये। जब रूस की पहली-पहली पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ हुई और सरकार ने एक विशेष दिशा में देश को ले जाना चाहा, तब पूंजीवादी राष्ट्रों ने उस योजना का मजाक उड़ाया था। वे यह कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि कोई देश इतनी बड़ी व्यवस्थित और नियंत्रित नीति से इतनी उन्नति कर सकता है। किन्तु जब रूस ने पांच वर्षों के लक्ष्यों को चार वर्षों में ही पूरा कर लिया, तो संसार इससे चकित रह गया, किन्तु इसी

[सत्यम्

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

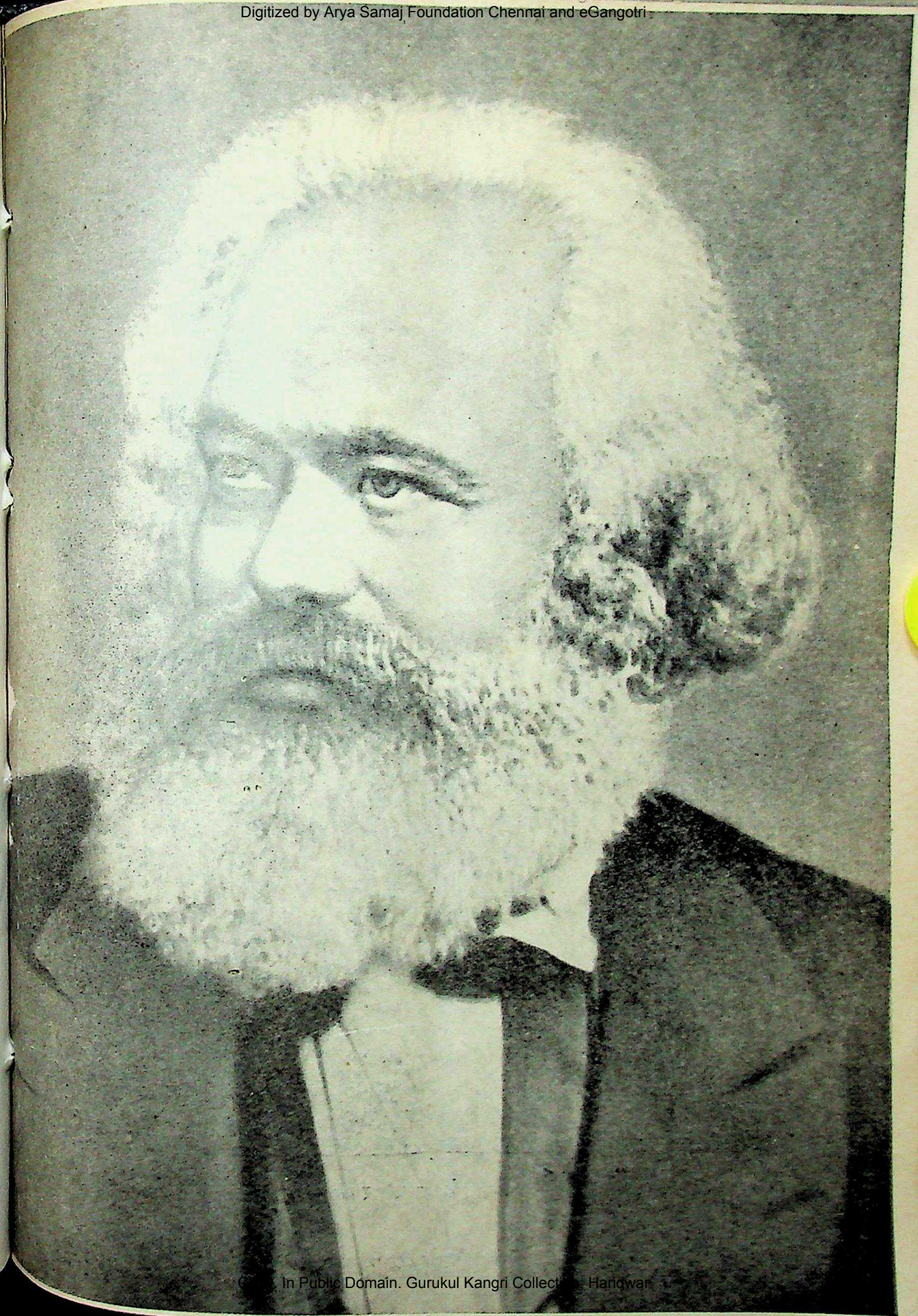

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मार्क्सवाद के व्याख्याकार श्री लेनिन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ने यह भी सिद्ध कर दिया कि सरकार द्वारा नियंत्रण, निर्देश और आदेश से भी देश की आर्थिक समस्या का समाधान किया जा सकता है।

रूस की इस सफलता ने विभिन्न देशों को समाजवाद की दिशा में विशेष प्रेरणा दी। जब अमेरिका में इस शताब्दी के तीसरे दशक के अन्त में आर्थिक संकट पैदा हुआ, तब प्रेसीडेण्ट रूजवेल्ट ने देश के लिये एक आर्थिक नीति निर्धारित की। एक कानून बनाकर सरकार ने आर्थिक नीति में हस्तक्षेप किया और औद्योगिक विकास का एक विशाल कार्यक्रम अपने हाथ में ले लिया। डालर की कीमत ४० प्रतिशत तक कम कर दी गई, मकान बनाने की एक विशालकाय योजना बनायी गयी, बेकारी को दूर करने की विशेष स्कीमें बनायी गयीं, बैंकिंग एक्ट और सिक्युरिटी-एक्सचेंज आदि के द्वारा सरकार ने व्यापारियों और बैंकों के अधिकारों पर नियंत्रण शुरू कर दिया। यह अमेरिका की साम्यवादी विचार-दिशा (सरकार द्वारा नियंत्रित आर्थिक नीति) में पहला कदम था। इटली और जर्मनी में भी देश की आर्थिक उन्नति के लिए अनेक निश्चित योजनाएं सरकारों द्वारा तैयार की गईं।

युद्ध काल में

विश्व-व्यापी महायुद्ध छिड़ने पर तो विभिन्न देशों की सरकारों ने कानून के द्वारा अपने हाथों में देश के आर्थिक, औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्रों में असीम अधिकार प्राप्त कर लिये। अन्न, वस्त्र, चीनी, तेल, सीमेंट आदि जीवन के लिए अनिवार्य पदार्थों की मांग और खपत बढ़ रही थी, किन्तु प्राप्ति उसके अनुसार नहीं हो रही थी। निरन्तर बढ़ती हुई महंगाई और दुर्लभता के कारण जनता के प्रति उत्तरदायित्व तथा युद्ध-सम्बन्धी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने के कारण सरकारों ने प्रायः सभी देशों में उत्पादन और वितरण पर नियंत्रण कर लिया। राशन और कन्ट्रोल की पद्धति प्रायः सभी देशों में अपनायी गयी। भारत में कन्ट्रोल और राशन किस सीमा तक बढ़ गये थे, यह 'सम्पदा' के पाठक भली-भांति जानते हैं। अनेक उद्योगों का उत्पादन भी सरकार ने अपने हाथ में कर लिया। पदार्थों की दुर्लभता के कारण ज्यों-ज्यों बाजार में नफाखोरी और चोर बाजार चलने लगे, त्यों-त्यों सरकार अपने नियंत्रण कठोरतर करती गयी। एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त और एक जिले से दूसरे जिले तक अनाज और कपड़ा लाना बन्द कर दिया गया। सम्पन्नतम व्यक्ति और एक गरीब भंगी दोनों के लिए छः-सात छटांक गेहूं का राशन नियत कर दिया गया। ये सब कदम एक दिशा की ओर इंगित कर रहे थे कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का बलिदान समाज के हित के लिए किया जा सकता है।

विभिन्न देशों में समाजवाद

विभिन्न देशों में आजकल समाजवाद की ओर बड़े कठोर कदम उठाये जा रहे हैं। ब्रिटेन तक में, जहां के मजदूर नेताओं के लिए कार्ल मार्क्स ने कभी कहा था कि इंग्लैण्ड में मजदूर नेता होना इज्जत की नहीं, बेइज्जती की बात है, मजदूर सरकार ने कोयला, लोहा और यातायात के धन्धे अपने हाथ में कर लिये, भले ही पीछे से ब्रिटिश सरकार ने इन कदमों को वापिस लेना शुरू कर दिया। ईरान की सरकार ने समाजवादी-भावना अथवा अपनी आवश्यकताओं के कारण तेल-कम्पनी को अंग्रेज-पूंजीपतियों के हाथों से छीनकर अपने हाथों में कर लिया। यह प्रवृत्ति भारत में भी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। मिश्र में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण इसी प्रवृत्ति का एक उज्ज्वल उदाहरण है।

युद्ध के बाद साम्यवाद की दिशा में जो कदम उठाये जा रहे हैं, उन सबके मूल में यह भावना विद्यमान है कि

अक्तूबर क्रान्ति नवम्बर में

रूस की महान क्रांति नवम्बर में हुई थी। किन्तु यह 'अक्टूबर क्रान्ति' के नाम से प्रसिद्ध है। इस असंगति का मुख्य कारण यह है कि इस जमाने में रूस का पञ्चांग असंशोधित और पश्चिमी पंचांग से १३ दिन पीछे था। इसके अनुसार मार्च सन् १९१७ की क्रान्ति फ़रवरी में हुई थी। इसलिए इसे "फरवरी क्रान्ति' कहते हैं। इसी तरह "बोलशेविक क्रान्ति' जो नवम्बर १९१७ के शुरूआत में हुई थी, "अक्टूबर-क्रान्ति' के नाम से प्रसिद्ध हुई। रूस ने अपना पंचांग अब बदल लिया है, लेकिन ये पुराने नाम अभी तक जारी हैं।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अमीर और गरीब में पारम्परिक भारी अन्तर को यथासंभव कम किया जाये। इसके लिए निम्नलिखित उपाय काम में लाये जा रहे हैं—

१—बहुत से उद्योग धन्धे सरकार स्वयं चलाने लगी है।

२—सार्वजनिक उपयोग के प्रायः सभी व्यवसाय—रेलवे, बिजली, पानी तथा यातायात के अन्य साधन सरकार स्वयं अपने हाथ में ले रही है।

३—उद्योगपतियों पर लाभ, उत्पादन आदि के संबंध में नियंत्रण।

४—मजदूरों के न्यूनतम वेतनों को नियत करना, ताकि मिल-मालिक उनका शोषण न कर सकें।

५—अप्रत्यक्ष करों को कम करके बड़ी आमदनी पर क्रमशः प्रत्यक्ष कर बढ़ाये जा रहे हैं।

६—जमींदारी प्रथा की समाप्ति।

७—उद्योग के लाभ से मजदूरों को एक भाग देना।

८—उत्तराधिकार के समय सम्पत्ति पर भारी कर।

इन सब साधनों से प्रत्येक देश की सरकार अमीर और गरीब के पारस्परिक अन्तर को यथासंभव कम करने की कोशिश कर रही है।

एशिया में समाजवाद

एशिया में जो देश स्वतंत्र हो रहे हैं अथवा अर्द्ध-विकसित हैं, उनमें अपने आर्थिक विकास के लिए समाजवाद के साधनों का, जिनमें राष्ट्रीयकरण की प्रवृत्ति विशेष है, प्रयोग बढ़ता जा रहा है। महायुद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के जो देश रूस के सैनिक नियंत्रण में आ गये, वहां तो साम्यवादी शासन बाकायदा स्थापित हो गया है और एकमात्र कम्युनिस्ट पार्टी अथवा कुछ कम्युनिस्ट नेता शासन करते हैं। स्वतंत्र उद्योग और कृषि का स्थान समाप्त हो गया है और सब काम सरकारी नियंत्रण में होता है। चीन, मंगोलिया, उत्तरी कोरिया आदि देश भी साम्यवादी हो गये हैं। चीन में तो कम्युनिस्ट शासन के लिए बड़ा भारी गृह-युद्ध करना पड़ा। इण्डोचायना में हो चि मिन के नेतृत्व में साम्यवादी दल ने एक बहुत बड़े प्रदेश पर अधिकार कर लिया है। इण्डोनेशिया, बर्मा आदि में भी साम्यवादी दल अच्छे संगठित हो गये हैं। मध्यपूर्व के देशों में रूस और अमेरिका का जो संघर्ष हो रहा है, उसके कारण साम्यवादी दलों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है।

इस तरह हमने देखा कि गत महायुद्ध के बाद समस्त संसार साम्यवाद की इस भावना को अपनाता जा रहा है कि अमीर और गरीब का अन्तर कम होना चाहिये। इसके लिए राष्ट्रीयकरण, नियंत्रण आदि की नीति अपनायी जा रही है, वहां वेतनों के न्यूनतम-स्तर बढ़ाये जा रहे हैं। इंग्लैण्ड के 'बीवरिज-पलैन' आदि की तरह समाज-कल्याण की योजनाओं की पूर्ति सरकारें अपना उत्तरदायित्व मानने लगी हैं।

सफलता के साथ दुष्प्रवृत्तियां भी

किन्तु अन्त में हम एक आवश्यक बात की ओर पाठकों का ध्यान खींचे बिना नहीं रह सकते। साम्यवाद की सफलताओं के साथ-साथ अनेक दुष्प्रवृत्तियों के भी लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे हैं और इस कारण जनता के बड़े भाग में साम्यवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया भी उत्पन्न होनी शुरू हो चुकी है। ब्रिटेन के 'मजदूर-दल' का पतन और अनुदार-सरकार के द्वारा राष्ट्रीयकृत अनेक उद्योगों का अराष्ट्रीयकरण अर्थात् उद्योगों को फिर निजी व्यक्तियों के हाथों में सौंपना इसका एक प्रमाण है। यूरोप के अनेक देशों में 'पापुलर-फ्रण्ट' का प्रभाव जल्दी ही समाप्त हो गया। आस्ट्रेलिया में उदारदलीय सरकार अब कई वर्ष पुरानी बात हो गयी है। हमारे अपने देश में मजदूरों और कर्मचारियों के यूनियन अपने जोशीले नेताओं के प्रभाव में आकर जिस तरह का अवांछनीय वातावरण पैदा कर रहे हैं, उसने आज के भारतीय विचारक को यह सोचने पर विवश कर दिया है कि क्या यह मजदूर-आन्दोलन देश की आर्थिक-व्यवस्था छिन्न-भिन्न तो नहीं कर देगा? आज सरकारी या गैर सरकारी उद्योगों, दफ्तरों व अन्य संस्थानों में पैदा किया जाता हुआ उग्र असन्तोष, जिस अनुशासन-हीनता और अनुत्तरदायित्व को उत्पन्न कर रहा है, वह देश के भविष्य के लिए कहां तक वांछनीय है? हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि देश और देश की जनता सर्वोपरि है। यदि कोई वर्ग उसके हित को भूलकर केवल स्वार्थ-साधन में लगेगा, तो जनता उसे सहन नहीं करेगी, भले ही वे मजदूर या किसान ही क्यों न हों।

[सम्पन्न

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

समाजवाद के विभिन्न रूप

श्री राजनारायण गुप्त

धर्म व ईश्वर के समान समाजवाद के भी बीसियों रूप हैं। कुछ रूप इस लेख में पाठक पढ़ेंगे।

परस्पर मतभेद

आधुनिक काल में समाजवाद तथा उसके विभिन्न स्वरूपों के सम्बन्ध में कोई भी चर्चा बड़ी निरर्थक सी लगती है। आज संसार का शायद ही कोई ऐसा देश हो, जो समाजवाद के प्रभाव से अछूता रह गया हो। प्रायः संसार के सभी देशों में समाजवादी या साम्यवादी दल हैं। जिन देशों में ऐसे दल नहीं हैं, वहां राजनैतिक दलों का संगठन विभिन्न आर्थिक विचारधाराओं के आधार पर किया जाता है और यह असम्भव है कि उन विचारधाराओं के पीछे समाजवादी विचारधारा काम न कर रही हो। संसार का एक-तिहाई भाग तथा उसकी जनता प्रत्यक्ष समाजवादी शासन के अन्तर्गत रह कर इस सिद्धांत के व्यावहारिक स्वरूप का आनन्द ले रही है। हमारे अपने देश में भी समाजवादी व्यवस्था का ध्येय स्वीकार कर लिया गया है। परन्तु समाजवाद की धारणा धर्म और ईश्वर के समान एक गौरव भावना है। ईश्वर के समान इनके अनेक रूप हैं और धर्म के समान इसके अनेक दृष्टिकोण। समाजवादी सिद्धांत के अपने पृथक देवी-देवता, पंडे और पुजारी तथा धर्म और स्मृति ग्रंथ हैं। अपनी अपनी भावना के अनुसार अलग-अलग भक्त समाजवाद के विभिन्न रूपों में अपने आराध्य देव, अपने मंतव्य तथा अपने सिद्धांतों का दर्शन करते हैं। प्रायः सभी समाजवादी मार्क्स को तो अपना आदि गुरु मानते हैं, परन्तु उसके प्रधान चेलों के प्रति एक सी ही भक्ति भावना नहीं रखते। कुछ लैनिन को मार्क्स का सही भाष्यकार मानते हैं, कुछ ट्राटस्की को, कुछ स्तालिन को, तो कुछ ख्रुश्चेव को, कुछ माओ त्से तुंग को कुछ मार्शल टीटो को। इसके अतिरिक्त मार्क्सवाद के अनेक छोटे छोटे देवी देवता हैं और अलग अलग देशों में उनकी पूजा तथा उपासना होती है। जिस प्रकार हिन्दू, इस्लाम या ईसाई एक धर्म हैं, परन्तु इन सब में अनेक मत मतान्तरों का जन्म हो गया है, उसी प्रकार मार्क्सवाद के अन्तर्गत अनेक दूसरे वादों का जन्म हुआ है। अपने आपको मार्क्सवाद का हामी मानते हुवे भी कोई अपने आपको साम्यवादी, कोई फेबियन समाजवादी, कोई श्रमी संघवादी, कोई गिल्ड समाजवादी कोई लेनिनवादी, कोई क्रान्तिकारी समाजवादी इत्यादि मानते हैं,

७७ किस्म व ६०० परिभाषाएं

समाजवाद के सम्बन्ध में इतना साहित्य लिखा गया है कि सबको इकट्ठा करने पर शायद कई वर्गमील का क्षेत्र भर जाये। विभिन्न लेखकों ने इस वाद की अपने अपने ढंग से व्याख्या की है। इसकी अनेक परिभाषाएं हैं। सन् १८९२ में ली फिगरो (Le Figaro) नामक एक फ्रांसीसी अखबार में समाजवाद की ६०० परिभाषाएं प्रकाशित हुई थीं। कहा जाता है कि इस वाद की कम से कम ७७ किस्में हैं। समाजवाद को समाजवाद के विरोधियों से इतना खतरा नहीं, जितना कि स्वयं इसके नेताओं से है, कारण इसके समर्थक समाजवाद के भिन्न भिन्न स्वरूपों के संबंध में आपस में इतना लड़ते झगड़ते हैं कि बस देखते ही बनता है। समाजवादियों का एक दल दूसरे को फासिस्ट तथा प्रतिक्रियावादी बताता है।

एक छोटे से लेख में समाजवादी सिद्धांत या उसकी पृष्ठभूमि का विस्तृत वर्णन संभव नहीं है। इसलिए प्रस्तुत लेख में हम केवल समाजवाद की मूल धारणाओं तथा उसके प्रमुख उपभेदों का ही वर्णन करेंगे।

समाजवाद क्या है ?

समाजवाद एक ऐसे नये समाज की कल्पना है, जिसका आधार न्याय, स्वाधीनता, समानता तथा मित्रता के सिद्धांतों पर अवलंबित है। यह समाज हित को व्यक्तिगत गुण के लक्ष्य बनाने का प्रयास है। यह ईसाई धर्म के आवश्यक गुणों का, अर्थात मनुष्य के बन्धुत्व का क्रियात्मक भाव है। यह सेवा के आधार पर समाज की व्यवस्था है। यह वह सिद्धान्त है, जिसका उद्देश्य समाज की उत्पादन-शक्ति पर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नियंत्रण रख कर, सारे समाज की भलाई के लिए धन का उचित वितरण करना है।

सभी समाजवादी चाहे वे किसी भी मत के अनुयायी हों, चार बातों में अवश्य विश्वास रखते हैं:—

(१) उत्पादन और वितरण के साधनों से व्यक्तिगत प्रभुत्व को हटा कर राज्य का नियंत्रण कायम करना।

(२) उत्पादन की सीमा का निर्णय लाभ के विचार से नहीं, सामाजिक आवश्यकता के आधार पर करना।

(३) व्यक्तिगत लाभ की भावना के स्थान पर सामाजिक सेवा के सिद्धांत को स्थापित करना।

(४) प्रतिस्पर्धा पर आधारित उत्पादन के स्थान पर योजनात्मक उत्पादन को मान्यता प्रदान करना।

मार्ग या साधनों पर मतभेद

उपर्युक्त सिद्धांत तो सब समाजवादी मानते हैं, परन्तु उनमें मतभेद इस बात पर है कि उत्पादन की शक्तियों पर सामाजिक नियंत्रण किस प्रकार रखा जाय तथा समाजवादी व्यवस्था कायम करने के लिए किस मार्ग का अवलंबन किया जाय? कुछ समाजवादियों का मत है कि समाजवाद की स्थापना धीरे धीरे वैधानिक तरीकों को अपना कर करनी चाहिए। इन समाजवादियों को विकासवादी, समष्टिवादी, फेबियन या संसदीय समाजवादी कहा जाता है। कुछ समाजवादी क्रान्तिकारी कार्यक्रम में विश्वास रखते हैं। वे वर्तमान सामाजिक संगठन को नष्ट कर देना चाहते हैं। ऐसे विचारकों को साम्यवादी, या क्रांतिकारी समाजवादी या लेनिनवादी इत्यादि नामों से पुकारा जाता है।

समाजवाद

समष्टिवाद या विकासवादी समाजवाद और प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली में किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं है। यह एक दूसरे के पूरक हैं। प्रजातंत्रवादियों का कहना है कि आर्थिक न्याय तथा धन के उचित वितरण के बिना वास्तविक प्रजातन्त्रीय शासन की स्थापना नहीं हो सकती। इसलिए प्रजातन्त्र शासन की सफलता के लिए समाजवाद की स्थापना अनिवार्य है। इस व्यवस्था तक पहुँचने के लिए प्रजातंत्रीय उपायों को ही काम में लाया जाता है। चुनावों में जनमत को अपने पक्ष में करके समाजवादी दल सत्ता प्राप्ति करता है तथा फिर सरकार का निर्माण कर देश की अर्थ-व्यवस्था पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है। धीरे धीरे प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है तथा जनता का जीवन स्तर उठाने के लिए योजनाबद्ध उत्पादन का कार्यक्रम अपनाया जाता है। हमारे देश में इन्हीं उपायों से समाजवाद की स्थापना का प्रयत्न किया जा रहा है। इंगलैंड का श्रमिक दल भी इसी प्रकार की शासन व्यवस्था में विश्वास रखता है। स्वीडन, नारवे, डेनमार्क इत्यादि देशों में भी इसी प्रकार की समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। "कमिएटर्न" की तरह समाजवादी दलों का भी एक संघ इण्टरनेशनल सोशलिस्ट के नाम से है। भारतीय समाजवादी दल की सहानुभूति इसी दल से है।

साम्यवाद

साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत पूंजीवादी प्रथा का एकदम अंत कर दिया जाता है। यह दल विकासवादी या संवैधानिक उपयों में विश्वास नहीं करता। उचित उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह हिंसा का मार्ग अपनाने में हानि नहीं समझता। (Ends Justify tne means) अर्थात् सही ध्येय पर पहुँचने के लिए कोई भी उपाय अपेक्षित हैं—यह वाद इस सिद्धान्त में विश्वास करता है। साम्यवाद के अंतर्गत सह-अस्तित्व का सिद्धान्त भी स्वीकार नहीं किया जाता, वहां पर पूंजीवादी प्रथा का एकदम अंत करके श्रमिक वर्ग का एकाधिपत्य (Dictatorship of the Proletariat) स्थापित किया जाता है।

श्रमी संघवाद व गिल्ड समाजवाद

साम्यवाद की दो प्रमुख उपजातियां जिनका यहां वर्णन करना हम आवश्यक समझते हैं श्रमी संघवाद (Syndicali) तथा गिल्ड समाजवाद (Guild Socialism) हैं।

श्रमी संघवाद क्रांतिकारी समाजवाद का रूप है। इसका जन्म १९ वीं शताब्दी के अंतिम दशक में फ्रांस में हुआ था। इस सिद्धान्त के मुख्य समर्थकों में सोरल तथा पैलोसियर हैं। आजकल इस वाद के अधिकतर अनुयायी केवल फ्रांस तथा इटली में ही पाये जाते हैं। वैसे तो श्रमी संघवादी साम्यवादियों की भांति ही समाज की वर्तमान

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चौथी इण्टरनेशनल के संस्थापक

श्री ट्राट्स्की

व्यवस्था को अन्यायपूर्ण तथा व्यक्तिगत संपत्ति को संघर्ष का मूल कारण मानते हैं, परन्तु साम्यवादियों की भांति वह श्रमिक वर्ग का एकाधिपत्य स्थापित करना नहीं चाहते; वह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें श्रमिकों के स्वतन्त्र समुदाय, बिना किसी केन्द्रीय सत्ता की उपस्थिति के, सहयोगपूर्वक कार्य कर सकेंगे। श्रमी संघवादियों के विचारानुसार प्रत्येक कारखाने में मजदूरों की एक संस्था अथवा यूनियन होगी, जो उस कारखाने का प्रबन्ध तथा संचालन करेगी। नगर के विभिन्न श्रमी संघों का एक केन्द्रीय संगठन होगा, जिसका मुख्य कार्य उत्पादन की नीति निर्धारित करना तथा उसे अमल में लाना होगा। यह संगठन सदस्य संघों के बीच सहयोग उत्पन्न करेगा तथा उत्पादन के उचित विनिमय का प्रबन्ध करेगा। एक व्यवसाय के विभिन्न श्रमी संघों को मिला कर एक राष्ट्रीय फेडरेशन बनाया जायगा, जिसके सदस्य विभिन्न संघों के निर्वाचित सदस्य होंगे। इस संस्था का मुख्य कार्य अपने व्यवसाय का राष्ट्रीय दृष्टिकोण से संचालन करना होगा। रेल, तार, डाक जैसी राष्ट्रीय महत्त्व की सेवाओं के लिए भी पृथक संघ होंगे। विदेशी आक्रमणसे रक्षा के लिए वेतन भोगी स्थायी सेनाएं नहीं होंगी; प्रत्येक यूनियन में एक दल होगा, जो ऐच्छिक आधार पर संगठित होगा और जिसका कार्य संकटकालीन अवस्था में राष्ट्र की रक्षा करना होगा।

श्रमी संघवादियों का विचार है कि पूंजीवादी प्रथा के नष्ट हो जाने पर दुःख, दारिद्रय और असानता का अंत हो जायगा। इसलिए समाज में अपराधों की संख्या बिलकुल कम हो जायगी। ऐसी अवस्था में न्यायालय और जेलों की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, फिर भी कोई मनुष्य अपराध करेगा तो उसे उसकी यूनियनों द्वारा बहिष्कार अथवा निर्वासन का दंड दिया जायगा।

श्रमी संघवादी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए शांतिपूर्ण उपायों में विश्वास नहीं करते। वह सार्वजनिक हड़ताल, बहिष्कार, 'सैबोटाज' तथा हिंसा के प्रयोग द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था का अंत कर मजदूरों की स्वायत्त शासन-संस्थाओं की स्थापना करना चाहते हैं।

गिल्ड समाजवाद समष्टिवाद और श्रमी संघवाद बीच का मार्ग प्रदर्शित करता है। श्रमी संघवाद की भांति यह प्रत्येक कारखाने म एक गिल्ड या श्रमी संघ की स्थापना

विचित्र, पर मनोरंक

भारतवर्ष में मजदूर आन्दोलन का प्रारम्भ मजदूरों के हित के लिए नहीं हुआ था। इंगलैण्ड के पूंजीपतियों ने भारतीय कल-कारखानों में सस्ता माल पैदा न हो, इसलिए मजदूरों के हित या मंगल की आवाज उठाई थी, जिससे भारतीय कल-कारखानों पर ज्यादा बोझ पड़े।

इसी तरह रूस की क्रान्ति में लेनिन का आकस्मिक प्रवेश रूस के शत्रु जर्मनी की स्वार्थ-साधना के कारण हो सका था। कैसर ने लेनिन को जो उन दिनों स्विटजरलैंड में रह रहा था, गुप्त रूप से बन्द गाड़ी में रूस में पहुँचाने की व्यवस्था की, ताकि रूस में जर्मनी से युद्ध बन्द करने का आन्दोलन जोर पकड़ सके। सचमुच जर्मनी को इससे लाभ हुआ और रूस की नई सरकार ने लेनिन की अध्यक्षता में जर्मनी से युद्ध बन्द करने की घोषणा की।

लेकिन इन स्वार्थप्रेरित भावनाओं ने भारत व रूस को कल्पनातीत लाभ पहुंचा दिया।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तो चाहता है तथा केन्द्रीय संघों की स्थापना में भी विश्वास रखता है; परन्तु श्रमी संघवादियों की भांति यह आर्थिक संघों में केवल उत्पादकों का ही आधिपत्य नहीं चाहता, यह आर्थिक जीवन के संचालन में उपभोक्ताओं को भी उचित स्थान देना चाहता है। इसके विचारानुसार यदि आर्थिक संघों में उपभोक्ताओं को किसी प्रकार का प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया जायगा तो उनका उत्पादकों द्वारा शोषण होगा, जो अत्यन्त अनुचित है। यह ठीक है कि प्रत्येक उत्पादक उपभोक्ता भी होता है, परन्तु उसके उत्पादक एवं उपभोक्ता हितों में विरोध हो सकता है। उदाहरणार्थ—एक कपड़े के कारखाने में कमाई करने वाला मजदूर यह मांग कर सकता है कि कपड़ा मंहगे से मंहगा बिके ताकि उसके कारखाने को अधिकतम लाभ हो और उसे अधिक से अधिक वेतन मिले। परन्तु इसके साथ ही यह उत्पादक यह भी चाहेगा कि उसे भोजन, मकान, ईंधन, बिजली, रोशनी इत्यादि सस्ते से सस्ते मूल्य पर उपलब्ध हों, जिससे उसका जीवन-स्तर ऊँचा हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के पारस्परिक हितों में घोर विरोध हो सकता है। गिल्ड समाजवादियों का कहना है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए 'उपभोक्ता परिषदें' (कन्जयूमर्स कौंसिल) होनी चाहिए। वस्तुओं की कीमतों का निश्चय उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की परिषदों को मिल कर करना चाहिए, जिससे दोनों वर्गों के हितों की रक्षा की जा सके।

गिल्ड समाजवादी नई आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए हिंसात्मक व उग्र उपायों के पक्ष में भी नहीं हैं। वह जनमत को अपने पक्ष में करके अपने उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं। वह हड़तालों को बहुत अनुचित नहीं मानते, परन्तु तोड़-फोड़ व सेबटाज की नीति के विरुद्ध हैं। इस प्रकार गिल्ड समाजवाद मध्यम मार्ग का हामी है। वह अंग्रेज विचारकों की नरम विचारधारा का परिचायक है। उसका व्यावसायिक लोकतन्त्र में विश्वास है।

आजकल साम्यवादी देशों में न श्रमी संघवादी विचारधारा पर अमल हो रहा है और न गिल्ड समाजवादी विचारधारा पर ही। पूर्णरूपेण साम्यवादी व्यवस्था भी अभी तक किसी राष्ट्र में स्थापित नहीं हो सकी है, कारण आदर्श साम्यवादी व्यवस्था के अन्तर्गत व्यक्तिगत सम्पत्ति का अंत कर, प्रत्येक व्यक्ति से उसकी बुद्धि एवं सामर्थ्य के अनुसार कार्य कराया जाता है तथा उसकी आवश्यकतानुसार उसे वेतन तथा जीवन की दूसरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। स्पष्ट है कि रूस में भी इस प्रकार की समाज-व्यवस्था कायम नहीं है। वहां पर व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार स्वीकार किया गया है तथा मजदूरों को उनकी आवश्यकतानुसार नहीं, वरन् उनकी योग्यतानुसार वेतन दिया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था को हम समाजवादी व्यवस्था ही कह सकते हैं, साम्यवादी व्यवस्था नहीं।

—

[पृष्ठ ५६३ का शेष]

भयंकर मुठभेंड होंगी। रूस इसी नीति पर चलता रहा है, यद्यपि आज पंडित जवाहरलाल नेहरू के पंचशील और सह-अस्तित्व के सिद्धान्त को रूस ने स्वीकार कर लिया है।

साम्यवाद-आदर्श स्थिति

मार्क्स समाजवाद को आदर्श स्थिति के रूप में स्वीकार नहीं करता। समाजवाद उसकी दृष्टि में पहली सीढ़ी है और साम्यवाद दूसरी एवं आदर्श स्थिति है। इस स्थिति में राज्य की आवश्यकता नहीं रहेगी और सबको केवल श्रम के अनुसार नहीं, आवश्यकता के अनुसार अपना पूर्ण श्रम करने पर वेतन मिलेगा। आज रूस में भी साम्यवाद की आदर्श स्थिति नहीं है। वहाँ आवश्यकताके अनुसार नहीं वरन् कार्य की किस्म और परिश्रम के अनुसार वेतन दिये जाते हैं। रूस के नेता यह स्वयं स्वीकार करते हैं कि रूस अभी साम्यवाद की ओर शनैः-शनैः प्रगति कर रहा है। यह नहीं कहा जा सकता कि यह स्थिति कब आयेगी। लेकिन जब तक अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना अन्तर्राष्ट्रीयता पर हावी रहती है, तब तक सच्चा साम्यवाद नहीं आ सकता। यह आदर्श स्थिति आज सम्भव नहीं दीखती, परन्तु साम्यवादी नेता अब भी इसका स्वप्न अवश्य लेते हैं।

—

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

समाजवाद क्या है ?

श्री मदन मोहन विष्ट

समाजवाद क्या है ? वास्तव में समाजवाद की कोई परिभाषा करने के स्थान पर समाजवाद के सिद्धान्तों को जान लेना आवश्यक है, क्योंकि समाजवाद 'अथाह' है, परिभाषा की परिधि में इसे समेटा नहीं जा सकता। जिन लोगों ने समाजवाद की परिभाषा की है—उन्होंने अपने दृष्टिकोण से रंग कर ही की है। फ्रांस ला फिगरेड ने १८९२ में समाजवाद की ६०० परिभाषाएं प्रकाशित कीं। इसी प्रकार १९२४ में डान ग्रिफिथ्स ने अपनी "समाजवाद क्या है ?" पुस्तक में समाजवाद की २६३ परिभाषाएं हीं। हां, प्रसिद्ध विचारकों ने समाजवाद के जो कुछ लक्षण किये या व्याख्याएं की हैं, उन्हीं में से कुछ का संकलन यहां किया गया है।

समाजवाद दरिद्रता और शोषण का विनाश करके समाज में समता स्थापित करना चाहता है। समाजवाद के

समाजवाद क्या है ? यह अत्यन्त विवादास्पद प्रश्न रहा है। उसकी आधारभूत विशेषताएं तथा विभिन्न विद्वानों द्वारा किये गये उसके कुछ लक्षण इन पंक्तियों में पढ़िए।

सम्पत्ति का अन्त करने पर समाजवाद बहुत जोर देता है। प्रोधों का विचार था "व्यक्तिगत सम्पत्ति चोरी है।"

(४) निजी जोखिम और स्पर्द्धा का अन्त—समाजवाद में कुछ अंशों तक निजी उद्योग रहेंगे, पर प्रधानतः सब उद्योगों पर राज्य का प्रभुत्व होगा। निजी जोखिम के अंत होने पर स्वतः आर्थिक स्पर्द्धा का भी अन्त हो जायेगा। स्पर्द्धा को नष्ट करना समाजवाद का प्रमुख लक्ष्य है।

समाजवाद पर विभिन्न विचारकों के मत ये हैं—

१. वर्तमान इतिहास में यह (समाजवाद) एक आंदोलन के रूप में प्रकट होता है, जिसका मूल विचार की अपेक्षा जीवन में तथा अध्ययन कक्ष की अपेक्षा कारखानों, दूकानों तथा गंदी गलियों में है। समाजवाद एक आर्थिक और राजनैतिक सिद्धांत अथवा बहुत से सिद्धांतों का सम्मिश्रण है, जिनका समाज के अस्तित्व और संगठन से सम्बन्ध है।

—स्टेनले मैलोर

२. समाजवाद—अंग्रेजी सोशसिलिज्म—लेटिन के Socius शब्द से निकला है जिसके अर्थ है साथी, सहायक अथवा भागाधिकारी। यह ऐसे व्यक्ति को सूचित करता है जो समान कोटि और अवस्था के हों। अतएव समाजवाद के अर्थ हैं भ्रातृभाव, मित्रता, जिसमें सब मनुष्य समान माने जायेंगे, जिसमें सब भागदारी के रूप में सम्मिलित होंगे और जिसमें सब मनुष्य साथ-साथ मिलकर काम

> "संसार के मजदूरो, एक हो जाओ। तुम्हें खोना कुछ नहीं है सिवाय अपनी गुलामी की जंजीरों के और पाने को संसार पड़ा है।"
>
> —(साम्यवादी घोषणा पत्र)

तात्विक सिद्धांत निम्नलिखित हैं—

(१) समाज को व्यक्ति से अधिक महत्त्व देना—दूसरे शब्दों में 'आत्म' का 'सर्वात्म' के हित में त्याग करना। यह भावना स्वार्थ की विरोधी है और व्यक्ति को समाज के लिये बलिदान करने को प्रेरित करती है।

(२) उन्नति के अवसरों में समानता—'समानता' समाजवाद की आत्मा है। प्रत्येक व्यक्ति को यह अपने विकास के लिए उन्नति का समान अवसर देना चाहता है, इसी बात को लक्ष्य करके प्रो० ग्रैहम ने लिखा है "समाजवाद का केन्द्रित लक्ष्य विषमता की कमी करना है। यही लक्ष्य उसके सभी स्वरूपों में समन्वित रहता है।"

(३) समाजवाद शोषण के साधनों जैसे पूंजीवाद, जमींदारी का अन्त करना चाहता है—व्यक्तिगत

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

करेंगे। राज्य के शासन के सम्बन्ध में यह प्रकट करता है कि प्रत्येक कार्य साधारण जनता की सेवा के लिए किया जायेगा। —वाइन्डहम अल्वरी

३. समाजवाद का लक्ष्य सार्वजनिक कुशलता है और यह व्यक्तिगत अधिकारों को इसी दृष्टिकोण से निर्धारित करता है। इसका ढंग सहयोग है, इस सहयोग में दूसरों के हित में अपना हित न समझने वाले व्यक्ति सम्मिलित नहीं किये जाते। वह संसार की वर्तमान सामाजिक अवस्था को अस्वीकार करता है। उसका निश्चय है कि हम संसार को अपने आदर्श के अनुसार बना सकते हैं।

—नार्मन एंजिल

४. समाजवाद एक प्रकार के विभिन्न सिद्धांतों का सामंजस्य है, जिसका मत है कि समाज को उत्पत्ति के साधनों के राष्ट्रीय आधिपत्य तथा मनुष्य के जातीय सम्बन्ध के आधार पर बनाना चाहिए।..... यदि लोकतंत्र का तात्पर्य है जनता के राजनैतिक विषयों का शासन जनता द्वारा व जनता के राजनैतिक हित के लिए हो, तो हम कह सकते हैं कि समाजवाद का उद्देश्य है: उपज के साधनों का आधिपत्य जनता द्वारा जनता के हित के लिये हो।

—मैक्स बियर

५. समाजवाद में सिद्धांतों की अपेक्षा विश्वास की भावना अधिक है।..... संक्षेप में, यह मजदूर वर्ग का तत्त्वज्ञान है, जो आर्थिक अनुभव द्वारा सीखा गया है और अपने को समय की परिस्थितियों के अनुसार एक रीति अथवा कार्य योजना में परिणत कर लेता है। इसके द्वारा शासन प्राबल्य का विनाश होता है और वर्गीय आधिपत्य के मिट जाने से मनुष्य स्वतंत्र हो जाते हैं।

—जी. डी. एच. कोल

६. समाजवाद उस विद्रोह की आत्मा है, जो पूंजीवादी, धनिक वर्ग, उसकी वेतन-प्रणाली तथा उसके द्वारा मनुष्यों के शोषण किये जाने के विरुद्ध खड़ा हुआ है। साथ ही साथ यह उन तीव्र भावनाओं का भी प्रेरक है जो समस्त औद्योगिक तथा व्यापारिक दिशाओं में न्याय तथा सहयोग चाहते हैं। —लुई डानल्डसन

७. समाजवादी चाहता है कि राष्ट्र के मूल्य उद्यम और जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति-सम्बन्धी धंधे, समाज के द्वारा सब के लाभ के लिए चलाये जायें।

—मारिस हिलक्विट

८. समाजवाद का आशय धन की उत्पत्ति तथा वितरण यह ऐसा आधिपत्य स्थापित कर लेना है, जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की उन समस्त भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं तक पहुँच हो सके, जिनके द्वारा वह अपने जीवन को सुखी बना सकता है। —हैराल्ड लास्की

९. इसका (समाजवाद का) लक्ष्य समाज की भौतिक तथा आर्थिक शक्तियों का संगठित करना और भावी शक्तियों द्वारा उन पर अधिकार स्थापित करता है।

—रैमजे मेक्डानल्ड

१०. समाजवाद का अर्थ मेरे विचार से भूमि तथा पूंजी पर सार्वजनिक अधिकार करना है, साथ ही साथ लोकतंत्र शासन भी स्थापित करना है। इसके अनुसार उत्पत्ति प्रयोग के लिये है, लाभ के लिये नहीं; और उत्पत्ति का वितरण या तो सबको समान रूप से हो अथवा केवल इतनी विषमता हो जो जनता के लिए अहितकर न हो। यह अनुपार्जित धन तथा मजदूरों की जीविका के साधनों पर व्यक्तिगत अधिकार के निराकरण का समर्थक है। पूर्ण रूप से सफल होने के लिये इसका अंतर्राष्ट्रीय होना आवश्यक है। —बरट्रेन्ड रसैल

समाजवाद मनुष्य जाति की सामूहिक चेतना की जागृति से अधिक अथवा कम और दूसरी वस्तु नहीं। यह एक सामूहिक संकल्प या निश्चय है जिससे नवीन प्रयोग, नवीन सफलता तथा मानव जाति को नवीन संदेश प्रदान करने के लिये महान तथा श्रेष्ठ व्यक्ति उत्पन्न हो सकते हैं।

—एच. जी. वेल्स

समाजवाद गिरगिट के समान रंग बदलने वाला विश्वास है। यह वातावरण के अनुसार बदलता है। सड़क के कोने तथा क्लब के कमरे के लिये यह वर्ग युद्ध का लोहित वस्त्र पहनता है; मानसिक पुरुषों के लिये इसका लाल रंग भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। भावनात्मक पुरुषों के लिये यह कोमल गुलाबी रंग हो जाता है तथा क्लर्कों के समाज में यह कुमारियों का श्वेत वर्ण ग्रहण कर लेता है, जिसको महत्त्वाकांक्षा की मंद मुस्कान का अभी अनुभव हुआ हो। —प्रो० रैमजे म्योर

——

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

समाजवाद क्यों ?

श्री एम० एन० राय

समाजवाद का दार्शनिक आधार भौतिकवाद है, जो धर्म और विधाता द्वारा ब्रह्माण्ड या जीवन के रचे जाने के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करता। समाजवाद तो द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है। मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार मानव किसी मानवोपरि शक्ति के हाथ का कठपुतला नहीं है और न किसी बड़ी भारी कल का पुरजा ही है, बल्कि मानव उस समाज का, जिसमें कि वह रहता है, स्रष्टा है।

मार्क्स के सिद्धान्तों के अनुसार आप या मैं अपनी इच्छा के अनुसार सामाजिक सम्बन्धों को निर्धारित नहीं कर सकते। आप आदर्श समाज-व्यवस्था की कल्पना कर सकते हैं। आप यह कल्पना कर सकते हैं कि समाज की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जिससे कोई किसी पर जुल्म न करता हो, जिसमें सब सुखी हों। कल्पना की स्वतन्त्रता आपको है; पर कल्पित व्यवस्था को स्थापित करने की, अपनी इच्छानुकूल समाज स्थापित करने की स्वतन्त्रता आपको उपलब्ध नहीं है। आप केवल उसी व्यवस्था को स्थापित कर सकते हैं जो चारों ओर के वातावरण में संभव है। संसार में जितनी क्रान्तियां हुई हैं, वे सब परिस्थितियों का परिणाम ही हैं। प्रत्येक नवीन सामाजिक व्यवस्था का अंकुर पुरानी व्यवस्था के गर्भ में ही जन्म ले चुका था। वास्तव में बिना इसके कोई व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती।

समाज का मूल आर्थिक सिद्धान्त उत्पादन, वितरण और विनिमय के साधनों पर से व्यक्तिगत स्वामित्व उठा देना है; परन्तु वास्तव में समाजवाद व्यक्तिगत सम्पत्ति को नष्ट नहीं करता है। पूंजीवाद ने जिस शोषित श्रेणी को जन्म दिया है, वही संगठित होकर अपने द्वारा उपार्जित किये गये सम्पत्ति को लेने के लिए संघर्ष करती है पूंजीवाद राज्य की सहायता से अपने अधिकार की रक्षा करता है। इस संघर्ष में बहुसंख्यक वर्ग सरकार को भी अपने अधिकार में करना चाहता है। मार्क्सवादी राजनीति का अर्थ है शोषित और पीड़ित जनता की शक्ति को हस्तगत करने के लिए चलाया जाने वाला युद्ध।

इस लेख के लेखक श्री मानवेन्द्रनाथ राय भारत के महान् क्रान्तिकारी नेता थे। रूस व चीन में साम्यवादी क्रान्ति में उन्होंने वर्षों तक काम किया।

अनेक भारतीय विचारक गांधीवाद को समाजवाद से श्रेष्ठ मानते हैं, पर मेरी सम्मति में समाजवाद का कहना है जन-साधारण का आर्थिक कल्याण प्राचुर्य में हो सकता है; गांधीवाद कहता है सार्वजनिक कल्याण सादगी के वातावरण ही में हो सकता है। समाजवाद प्रचुरता का दर्शन है; गांधीवाद दीनता का दर्शन है।

"सारे मानव-समाज का पिछला और मौजूदा इतिहास वर्ग-युद्ध का इतिहास है।"

—मार्क्स

सम्पदा व हिन्दी में आर्थिक साहित्य पर्यायवाची शब्द हैं

अपने पांच वर्षों के स्वल्प काल में सम्पदा ने आर्थिक प्रवृत्तियों तथा आर्थिक समस्याओं की जो जानकारी दी है, वह अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। यही कारण है कि:—

हा. सै. स्कूल, इण्टर व डिग्री कालेज और पुस्तकालय एवं वाणिज्य व अर्थशास्त्र के विद्यार्थी

सम्पदा की पुरानी फाइलें मंगा रहे हैं। थोड़ी सी फाइलें बची हैं। प्रत्येक विशेषांक स्वयं एक उपादेय पुस्तक है। कुछ समय बाद आपको हम फ़ाइल न दे सकेंगे। मूल्य प्रति फाइल ८) रु०

नमूने के एक अंक के लिए छः आने के टिकट भेजिये

यह स्मरण रखिये कि वी० पी० से मंगाने पर आपको ।।=) अधिक देना पड़ता है।

मनीआर्डर से मूल्य भेजना लाभकारी होगा।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मार्क्स और हिंसा

श्री नागेश्वर प्रसाद

साधारणतः कम्युनिस्ट मार्क्स के इस सिद्धान्त को निर्भ्रान्त और त्रैकालिक सत्य समझता है कि क्रांति के लिए हिंसा अनिवार्य है, परन्तु सचाई यह है, कि मार्क्स अपने जीवन के संध्याकाल में स्वयं अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन कर चुके थे और उनके साथी एंगेल्स भी अपनी भूल मान चुके थे।

विचारों में विकास

मार्क्स के जिन वचनों का हवाला प्रायः दिया जाता है, वे लगभग १८४८ के विचारों को प्रदर्शित करते हैं। उस विशेष ऐतिहासिक परिस्थिति में मार्क्स और एंगेल्स इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि सामाजिक परिवर्तन के लिए हिंसा अनिवार्य है। अतएव १८४८ में जब कम्यूनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ तो उसमें हिंसा को अनिवार्य रूप से अंगीकार किया। परन्तु औद्योगिक क्रान्ति की तीव्रता से इंगलैंड आदि देशों में नूतन आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन होते गये। फलस्वरूप इंगलैंड में आर्थिक क्षेत्रों में मजदूरों को कई मूलभूत अधिकार प्राप्त हुए। इसी प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में भी निर्वाचन की सीमा केवल कुछ लोगों में सीमित न रह कर उत्तरोत्तर विकसित होती गई। इनमें १८३२ से १८६७ तक के निर्वाचन सुधार का प्रत्यक्षीकरण मार्क्स और एंगेल्स के सामने हो चुका था। साथ ही पुराने तरीकों से लड़ने की जगह नए तरीकों का आविष्कार हुआ। गली और सड़क की लड़ाई की प्रणाली की जगह विज्ञान के उपयोग द्वारा, लड़ने की प्रणाली में ही परिवर्तन हो गया है। इस सतत विकासोन्मुख शक्तियों का साक्षात् करके मार्क्स और एंगेल्स के समान सप्राण विचारक पुरानी नीति एवं अव्यवहार्य निष्कर्षों से चिपके नहीं रह सकते थे। अतएव उन्हें भी अपने विचारों में परिवर्तन करना पड़ा। उदाहरण के लिए मार्क्स ने 'हेग कन्वेंशन' के अवसर पर जो भाषण दिया था, उसका यह उद्धरण देखिये—

"मजदूर नये श्रम संगठन की नींव डालने के लिए राजनीतिक सत्ता पर अधिकार अवश्य प्राप्त करे। अगर उसे ऐसी वस्तुओं की उपेक्षा और घृणा करने वाले प्राचीन ईसाइयों की तरह इस दुनिया की चीजों का परित्याग नहीं करना है तो पुरानी संस्थाओं द्वारा घोषित पुरानी नीति को वह अवश्य उलट दे। लेकिन हमारा यह कहना नहीं है कि इस लक्ष्य तक पहुँचने का एक ही रास्ता सर्वत्र है। हम जानते हैं कि भिन्न-भिन्न देशों की संस्थाओं, रीति रिवाजों का विचार अवश्य होना चाहिए और हम इस बात से इंकार नहीं करते कि इंगलैंड तथा अमेरिका जैसे देशों में और अगर मैं आपके तर्कों को बेहतर समझता हूँ, तो हालैंड में भी मजदूर अपने लक्ष्य की प्राप्ति शान्तिमय उपायों से कर सकता है।"

(एच० डब्ल्यू लैडलर द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक आन्दोलन' में काट्सस्की के "सर्वहारा की तानाशाही' से उद्धृत।)

एंगेल्स के विचार

एंगेल्स ने भी "फ्रांस में वर्ग-संघर्ष की भूमिका" लिखते हुए निम्नांकित विचार प्रदर्शित किया है। मार्क्स के देहावसान के बाद १८९५ में एंगेल्स ने अपनी और मार्क्स की गलतियों को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। वह कहते हैं—

"इतिहास ने हमें गलत साबित किया और हमारे तत्कालीन (१८४७-५०) विचारों को भ्रामक बताया। इतिहास और भी आगे गया; उसने न केवल हमारे भ्रम का निवारण किया, बल्कि उन परिस्थितियों को भी रूपान्तरित कर दिया, जिनमें संघर्ष करना पड़ता। सन् १८४८ के लड़ने के तरीके आज हर तरह से पुराने पड़ चुके हैं। अजागृत जनता के शीर्षस्थ छोटे-छोटे अल्पसंख्यक समूहों द्वारा क्रान्ति करने का समय चला गया। इतिहास का व्यंग हर चीज को उलट देता है। हम, क्रान्तिवादी और विप्लवी, विप्लव करने में अवैधानिक साधनों की अपेक्षा वैधानिक साधनों से अधिक सफल हो सकते हैं। व्यवस्थानिष्ठ पक्ष स्वनिर्मित वैधानिक परिस्थितियों के कारण ही

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारत की तीव्र प्रगति

भारत में वर्तमान औद्योगिक क्रान्ति यूरोप की देन है। इसलिए यह स्वाभाविक था कि यूरोप में उसकी जो प्रतिक्रिया हुई, वह भारत में भी प्रगट होती। भारत का मजदूर-आन्दोलन उसी दिशा में गया, जिसमें वह यूरोप में विकसित हुआ। वर्ग-युद्ध की भावना यूरोप की देन है। ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार भारत का पूंजीवाद यूरोप की देन है।

भारत में मजदूर आन्दोलन

यह ठीक है कि भारत में मजदूर-आन्दोलन का प्रारम्भ ब्रिटिश पूंजीपतियों के स्वार्थवश चलाये हुए आन्दोलन से हुआ, तथापि शीघ्र ही यह मानवता के उपासक कुछ भारतीय नेताओं ने अपने हाथों में ले लिया। राष्ट्रीय आन्दोलन के मूल में सामान्य-जन के हित की भावना थी, इसलिए यह भी स्वाभाविक था कि राष्ट्र के नेता मजदूर हित की आवाज उठाते। महात्मा गांधी ने मजदूर-आंदोलन का नेतृत्व बहुत उत्साह के साथ किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचन्द्र, लाला लाजपतराय, सरदार पटेल आदि भी समय-समय पर मजदूर-आन्दोलन में भाग लेते रहे, किन्तु ये नेता राष्ट्रीय-आन्दोलन में बहुत उलझे हुए थे। इसलिए अन्य अनेक नेताओं ने आकर मजदूर-आन्दोलन को अपने हाथ में लिया। शनैः-शनैः इस आन्दोलन में उन लोगों का प्रभाव बढ़ता गया, जो उग्र विचारों के थे अथवा कम्युनिस्ट थे।

कांग्रेस देश में बढ़ती हुई मजदूर-जागृति के सम्बन्ध में उदासीन नहीं रह सकती थी। इसलिए वह समय-समय पर उनकी समस्याओं पर विचार करती थी। केन्द्रीय असम्बली में भी कांग्रेसी-नेता मजदूरों के सम्बन्ध में विशेष रुचि लेते थे। मई १९२९ में कांग्रेस-कार्य-समिति ने एक प्रस्ताव द्वारा यह निश्चित किया कि वर्तमान आर्थिक और सामाजिक समाज-व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन करना और भारतीय जन-साधारण की अवस्था सुधारने और उनका दुःख-दरिद्र दूर करने के लिए प्रचलित घोर असमानताओं को मिटाना आवश्यक है। इसी बैठक में साम्यवादी प्रचार के अपराध में गिरफ्तार किये गये ३१ अभियुक्तों पर मेरठ में जो मुकदमा चलाया गया, उसमें अभियुक्तों की सहायता के लिए १५०० रुपये सहायता देने का निश्चय किया गया। कांग्रेस ने १९३१ में मौलिक अधिकार सम्बन्धी जो प्रस्ताव पास किया, वह समाजवाद की दिशा में बहुत महत्त्वपूर्ण है। उसमें अनेक ऐसे सुझाव दिये गये थे, जो आज भी देश में फैली हुई असमानता को दूर करने के लिए आदर्श रूप में उपस्थित किये जाते हैं। इसी महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव में यह विचार प्रगट किया गया था कि किसी भी सरकारी नौकर को ५००) से अधिक वेतन नहीं मिलना चाहिये, मजदूरों को पर्याप्त मजदूरी मिलनी चाहिये और किसानों की कष्टों से मुक्ति होनी चाहिये।

कांग्रेस समाजवाद की दिशा में

इसके बाद भी कांग्रेस समय-समय पर समाजवादी

नष्ट हो जाते हैं।"

(एंगेल्स की "फ्रांस में वर्ग संघर्ष" की भूमिका से उद्धृत)

हिंसा अनिवार्य नहीं

उपर्युक्त उद्धरणों से एक बात तो अवश्य स्पष्ट है कि दोनों विचारकों (मार्क्स और एंगेल्स) ने हिंसा की अनिवार्यता को अपने जीवन के संध्याकाल में स्वीकार नहीं किया। इससे यह साफ है कि मार्क्सवाद का हिंसा से कोई अटूट गठबन्धन नहीं है। काश! मार्क्स और एंगेल्स जीवित होते और महात्मा गांधी प्रणीत शान्तिमय प्रतिकार (सत्याग्रह) के चमत्कार को देख पाते। सम्भव है उनके विचारों में भी परिवर्तन होता। इतिहास की द्रुतगति की लय में अपने विचारों की लय मिलाना वे जानते थे। यद्यपि यह कहना मुश्किल है कि उनका दृष्टिकोण समाज परिवर्तन की इस नूतन प्रणाली के प्रति क्या होता।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिशा में विचार करती रही, यद्यपि उसका क्षेत्र राजनीति रहा, इन्हीं वर्षों में आचार्य नरेन्द्रदेव और श्री जयप्रकाश नारायण आदि कुछ कांग्रेसी नेता कांग्रेस में ही समाजवादी दल की स्थापना कर चुके थे। इस तरह कांग्रेस निरन्तर समाजवादी आन्दोलन की ओर बढ़ रही थी। यों समाजवादी दल शनैः-शनैः अपना बल बढ़ाता जाता था और कांग्रेस को शनैः-शनैः समाजवाद की ओर लाने में सहायक हो रहा था। १९३६ में चुनाव घोषणा-पत्र में गरीबी दूर करने का आश्वासन दिया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद सुभाषचन्द्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस में आर्थिक प्रश्नों पर अधिक विचार होने लगा। १९३७ में कांग्रेस ने अनेक प्रान्तों में जब शासन-सूत्र अपने हाथ में लिया, तब किसानों की उन्नति पर विशेष बल दिया गया। बारडोली का सत्याग्रह पहले ही हो चुका था। उसने किसानों में विशेष जागृति उत्पन्न कर दी थी।

१९३९ में विश्वव्यापी महायुद्ध शुरू हो गया और उसके साथ ही कांग्रेसी सरकारों का शासन भी समाप्त हो गया। अनेक वर्षों के युद्धकाल के बाद भारत स्वतन्त्र हुआ और कांग्रेस ने देश का शासन अपने हाथ में लिया। अब कांग्रेस केवल प्रस्ताव पास करने वाली संस्था नहीं रही थी। अब वह अपने विचारों को क्रिया में परिणत कर सकती थी। इसलिए कांग्रेस ने शासन-सूत्र हाथ में लेते ही समाजवाद की दिशा में दौड़ना शुरू कर दिया। उसने पिछले वर्षों में समाजवाद की दिशा में जो कार्य किये या महत्वपूर्ण कदम उठाये, उसके अतिरिक्त उनने समाजवाद की दिशा को अपना लक्ष्य ही मान लिया। इस सम्बन्ध में समय-समय पर जो प्रस्ताव पास किये गये, उन्हें पाठक अन्यत्र पढ़ेंगे। इस लेख में तो हम केवल समाजवाद की व्यावहारिक दिशा में जो कदम उठाये जा चुके हैं, उनका निर्देश मात्र करना चाहते हैं।

जमींदारी प्रथा का उन्मूलन

१—किसानों की दरिद्रता और उनका शोषण समाप्त किये बिना समाजवाद की स्थापना असंभव थी, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण कदम जमीदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए उठाया गया। आज प्रायः सभी राज्यों में जमींदारी की प्रथा समाप्त हो चुकी है या समाप्त होने वाली है और किसान स्वयं भूमि का स्वामी बनता चला जा रहा है। कृषकों की सुविधाओं के लिए अन्य भी बहुत-सी कानूनी कार्रवाइयां की गयी हैं। छोटे और बड़े जमींदार की असमानता को दूर करने के लिए अधिकतम जोत की सीमा निर्धारित की जा रही है।

उद्योगों का राष्ट्रीयकरण

२—भारत सरकार क्रमशः उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाती जा रही है। सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी को हाथ में लेने के बाद वायु-यातायात को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके उसे स्टेट बैंक के नाम से सरकार चला रही है। देश भर में फैले हुए जीवन-बीमा व्यवसाय को भी सरकार ने अपने हाथ में कर लिया है। जब केन्द्रीय सरकार निजी उद्योगों के पीछे हाथ धोकर पड़ गयी, तब राज्य सरकारें पीछे क्यों रहतीं। उन्होंने भी अपने-अपने राज्य में फैले हुए मोटर-यातायात को अपने हाथ में कर लिया। निजी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की प्रवृत्ति निरन्तर बढ़ती जा रही है, यहां तक कि शिक्षा विभाग निजी प्रकाशकों से छीनकर पाठ्य पुस्तकों का भी राष्ट्रीयकरण करने लग गयी है।

३—नयी औद्योगिक नीति की घोषणा द्वारा सरकार ने बहुत से उद्योग केवल अपने लिए सुरक्षित कर लिये हैं। जैसेः लोहा, जहाज-निर्माण, रासायनिक खाद, रासायनिक आधारभूत-पदार्थ, बिजली, मशीनों के कारखाने, खनिज तेल, वायुयान आदि।

४—केवल उद्योग के क्षेत्र में ही नहीं, व्यापार के क्षेत्र में भी सरकार निजी व्यापारियों से विदेशी व्यापार छीन कर अपने हाथ में करती जा रही है। स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के हाथ में लोहे और मेंगनीज का निर्यात व्यापार, सीमेंट का आयात और वितरण आदि काम सौंप दिये गये हैं। प्रति वर्ष इस कार्पोरेशन का कार्य-क्षेत्र अधिकाधिक विस्तृत किया जा रहा है। इसी मास जापान से सूती मिलों की मशीनरी मंगाने का काम भी इस संस्था को दिया गया है। इसके परिणाम-स्वरूप व्यापार से होने वाला लाभ निजी व्यापारियों को प्राप्त न होकर सरकार को ही प्राप्त होगा।

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अधिकाधिक कर

५—अमीर और गरीब की विषमता को कम करने के लिए योजना आयोग ने सम्पन्न व्यक्तियों पर अधिकाधिक कर लगाने की सलाह दी है। आय-कर, सुपर-टैक्स, उत्पादन-कर आदि में ही वृद्धि पर संतोष नहीं कर लिया गया, परन्तु नये-नये करों का आविष्कार करके सम्पन्न-वर्ग से उनकी सम्पत्ति का एक भाग ले लेने का भी प्रयत्न किया जा रहा है। १९५३ में संसद ने सम्पत्ति-कर लगाने का निश्चय किया। राज्यों को सहायता देने के अतिरिक्त इस कर का उद्देश्य सम्पत्ति के वितरण में असमानता को कम करना भी बताया गया था; जिससे कुछ इने-गिने आदमियों के हाथ में सारी सम्पत्ति न रहे। यह कर किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उसकी सम्पत्ति उसके उत्तराधिकारियों को हस्तान्तरित करते समय लगता है। कृषि-सम्पत्ति के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति पर यह कर लगता है और इसकी दर न्यूनतम ५ प्रतिशत और अधिकतम ४० प्रतिशत है। १९५७ के इसी वर्ष में दो नये कर लगाने का प्रस्ताव संसद् ने स्वीकार कर लिया है। एक है सम्पत्ति पर वार्षिक कर और दूसरा है व्यय-कर। इन पर आगामी वर्ष से अमल होगा। वर्ष में ५० हजार रुपये से अधिक व्यय करने पर 'व्यय-कर' लिया जाया करेगा। इन दोनों करों का प्रभाव सम्पन्न वर्ग पर विशेष रूप से पड़ेगा। उनकी सम्पत्ति पर शनैः-शनैः अधिकार करके सरकार अमीर और गरीब की चौड़ी खाई को कम करना चाहती है।

सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा

६—एक ओर जहां सरकार सम्पन्न वर्ग की सम्पत्ति पर अधिकार और नियंत्रण करना चाहती है, वहां दूसरी ओर गरीबों की आय बढ़ाने का उपाय कर रही है। राज्य के विविध कर्मचारियों, मिलों में काम करने वाले मजदूरों, बैंकों और अखबारों आदि के कर्मचारियों के वेतन-स्तर ऊँचे किये जा रहे हैं और उन्हें बीमारी या बुढ़ापे में सुविधाएं दी जा रही हैं। बोनस की व्यवस्था द्वारा भी व्यापारिक कम्पनियों के कर्मचारियों की आय बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है। ऊँचे वेतन पाने वालों के वेतनों में कटौती के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किया जा रहा है, जिससे दो कर्मचारियों के वेतनों में अंतर कम होता जाय।

७—व्यापारिक कम्पनियों के डिवीडेंड पर नियंत्रण किया जा रहा है।

८—सहकारी उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि उद्योग कुछ ही लोगों के हाथों में केन्द्रित न हो जायं। चीनी और सूत की कई बड़ी मिलें सहकारी उद्योग के आधार पर खोली जा रही हैं। इनमें छोटी-छोटी पूंजी सम्मिलित कर ही बड़े उद्योग खड़े किये जायंगे।

९—पंचवर्षीय योजना के विविध अंगों द्वारा किसानों और दस्तकारों की आमदनी बढ़ायी जा रही है। ग्रामोद्योगों को सुविधाएं देने के लिए बड़े उद्योगों पर कुछ प्रतिबन्ध भी लगाये जा रहे हैं।

भारतीय संविधान और समाजवाद

"राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक कार्य-साधक रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोककल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा। वह अपनी नीति का ऐसा संचालन करे कि समान रूप से नर और नारी सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो। और समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्थायित्व और नियंत्रण इस प्रकार बांटा जाय। कि वह सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधक हो। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी केन्द्रीकरण न हो।"

—भारतीय संविधान

इस तरह के उपायों से देश की सरकार भारत में समाजवादी समाज स्थापित करने का प्रयत्न कर रही है। इन प्रयत्नों में कहां तक सरकार को सफलता मिलेगी अथवा इन प्रयत्नों में कितनी त्रुटियां हैं, इसकी विवेचना करना इस लेख के विषय-क्षेत्र से बाहर की बात है। इस लेख का उद्देश्य तो केवल यह दिखाना है कि शासन किस तरह समाजवादी-समाज की स्थापना के लिए निरन्तर प्रयत्न कर रहा है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारत की समाजवादी पद्धति

श्री एच० एम० पटेल

भारतीय समाजवाद न रूस का समाजवाद है, न चीन और यूगोस्लाविया का, यह भारत का अपना समाजवाद है, इसी का सुन्दर विवेचन इस लेख में देखिये।

समाजवाद का अर्थ विभिन्न लोगों ने भिन्न भिन्न लगाया है। समय समय पर इसकी जितनी व्याख्याएं की गईं, वे कभी कभी तो परस्पर विरोधी तक प्रतीत होने लगती हैं। लेकिन एक सीधा प्रश्न किया जा सकता है कि भारत के लिए "समाजवादी समाज व्यवस्था" जैसी शब्दावली का महत्व क्या है? इस प्रश्न का ठीक उत्तर यही होगा कि यदि मैं कहूं कि इस शब्दावली का तात्पर्य भारत की कुछ प्रत्यक्ष आर्थिक समस्याओं का समाधान है। ये समस्याएं हैं—भूमि सुधार, उद्योगों व करों का नियंत्रण और विस्तार, साख की व्यवस्था करना आदि। मैं यहां पर स्पष्ट रूप से जोर देकर कहता हूं कि 'समाजवाद' को हम भारत में जिस रूप में ले रहे हैं, उससे इस बात का भ्रम न हो कि किसी निश्चित सिद्धांत या समाज व्यवस्था का अंधानुकरण करने का प्रयत्न किया जा रहा है। यह हमारी आर्थिक आवश्यकताओं और परम्पराओं के अनुकूल है। यहां इसके परीक्षण के लिये स्थान है और परिस्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जा सकता है।

हमारी परम्परा के अनुकूल

भारत की परम्परा की सुन्दर अभिव्यक्ति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की है, जिसके अनुसार प्रत्येक समस्या को शांतिपूर्वक और अहिंसक ढंग से निपटाया जाता है। इसी प्रकार "समाजवादी समाज" की शब्दावली भारत की परम्परा से ही ली गई है न कि किसी "वाद" विशेष से। अतः इसका आशय किसी प्रकार की कट्टर समाज व्यवस्था नहीं है। इस व्यवस्था में मानवीय मूल्य सदैव विद्यमान रहेंगे, पर इसका स्वरूप लचीला होगा। वे मानवीय मूल्य हैं:—सामाजिक और आर्थिक न्याय, समानता तथा क्रमिक उन्नति के अतिरिक्त व्यक्ति की स्वतन्त्रता सुरक्षित रहेगी और समस्याओं को प्रजातंत्रात्मक पद्धति से हल किया जायेगा।

भारत का संविधान

नवम्बर १९४९ में हमने अपने संविधान को स्वीकार किया, समाजवादी समाज इसी संविधान की भावना का मूर्त रूप है। संविधान की प्रस्तावना में भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय; विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता; अवसर की समानता; व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को प्रदान करने की प्रतिज्ञा की गई है। संविधान में "बंधुता" पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अतिरिक्त नागरिकों को जिन मूलभूत अधिकारों की गारंटी दी गई है, इनमें से एक अधिकार 'सम्पत्ति का अधिकार भी है।' इसी प्रकार नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है—

(क) नर और नारी सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन समान रूप से प्राप्त करने का अधिकार है।

(ख) समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और और नियंत्रण इस प्रकार हो कि सामूहिक हित सर्वोत्तम रूप से हों।

(ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन और और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकर केन्द्रीकरण न हो।

मौलिक प्रश्न

कुछ लोग सम्भवतः यह प्रश्न करें कि क्या यही भारतीय समाजवाद की व्याख्या है? यदि आर्थिक नीतियों का मूल उद्देश्य लोगों के रहन-सहन का स्तर ऊंचा उठाना और आय, धन और अवसर की समानता को व्यापक रूप में स्थापित करना है तो समाजवादी समाज का इससे क्या सम्बन्ध है? आखिरकार समाजवाद का मूलभूत आधार है उत्पादन के समस्त साधनों पर राज्य का अधिकार हो, जिससे पूर्ण रूप से नहीं तो अधिकांशतः आर्थिक क्रिया-

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कलायें राज्य के हाथों में केन्द्रित हो जाते हैं। क्या भारत में राज्य के कार्य क्षेत्र को धीरे धीरे बढ़ा कर निजी सम्पत्ति को समाप्त करने का प्रयत्न नहीं किया जा रहा है? ये मूलभूत प्रश्न हैं। जब हम किसी भी आर्थिक व्यवस्था समाजवादी, व्यक्तिवादी या पूंजीवाद के विषय में कुछ कहते हैं तो एक मुख्य प्रश्न राज्य के आर्थिक क्षेत्र में कार्य करने और भाग लेने के सम्बन्ध में उठता है। भारत ने समाजवाद को अपना लिया है। वर्तमान परिस्थितियों में यह उचित है कि राज्य आर्थिक उन्नति में सक्रिय भाग लेगा, पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि निजी उद्योगों को कोई हानि पहुँचाई जायेगी। यह भी नहीं समझना चाहिए कि इस प्रकार एक ऐसे निरंकुश शासन की स्थापना हो जायेगी, जिसके हाथ में सभी आर्थिक शक्तियां केन्द्रित होंगी। यथार्थ में भारत जैसे प्रजातंत्र राज्य में यह बात असंगत होगी। ऐसा कोई समाज ही नहीं, जिसका आधार या तो पूर्णतः राज्य पर आश्रित हो या 'निजी प्रयत्न' पर।

भारत का समाजवाद इस बात पर विश्वास नहीं करता कि केवल 'राष्ट्रीयकरण के लिए, राष्ट्रीयकरण' किया जाये। वास्तव में छीनने-झपटने की नीति में इसका विश्वास नहीं है। भारत में राज्य का आर्थिक क्रिया-कलाप में भाग लेना अनिवार्य है, लेकिन इसकी क्या सीमा हो, इसके लिए मैं आपका ध्यान तीन मूलभूत बातों की ओर आकर्षित करता हूं।

राज्य का कार्यक्षेत्र

पहली बात यह कि—भारत में आर्थिक क्रियाकलापों के क्षेत्र में राज्य, अन्य देशों की—जिनमें अमेरिका, फ्रांस और इंगलैंड भी हैं—अपेक्षा बहुत कम भाग लेता है। दूसरी बात यह है कि सरकारी उद्योग क्षेत्र के फैलने का तात्पर्य निजी प्रयत्नों का समाप्त हो जाना नहीं है। भारत के गांवों में करोड़ों लोग जिस कंगाली से दबे पड़े हैं, उनकी सहायता के लिये अनेक प्रकार के कार्य करना राज्य का कर्तव्य हो जाता है। इसके लिए ग्राम-उद्योग में विकास करना और जनता में यह उद्योग बुद्धि उत्पन्न करना जरूरी है कि सहकारी प्रयत्न के विस्तार से निजी उद्योग समाप्त नहीं हो जाते। सच तो यह है कि इस गलत धारणा के विपरीत राज्य के उद्योग क्षेत्र नये नये प्रयत्नों को उत्पन्न करते हैं।

तीसरी बात यह है कि भारत में समाजवाद से शीघ्र प्रगति हो जायेगी। भारत की जनसंख्या भी बढ़ रही है। अतः निजी और सरकारी दोनों प्रकार के उद्योगों को फलने फूलने का विस्तृत क्षेत्र है। मैं फिर इस बात को दोहराता हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था की मूलभूत आवश्यकता उत्पादन बढ़ाना है। जबकि आर्थिक-क्षेत्र दिन प्रतिदिन विस्तृत होता जा रहा है तो इस बात से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं कि सरकारी उद्योगों के प्रसार के लिए निजी उद्योगों का बलिदान किया जायेगा। भारतीय समाजवाद का सच्चा अर्थ तो यह है कि आर्थिक उन्नति इस ढंग से की जाये जो वैध, शांतिपूर्ण और जनतंत्रात्मक तो हो ही, पर साथ ही उससे सामाजिक-न्याय की भी स्थापना की जा सके।

ग्रामीण भारत में समाजवाद

ग्रामों का भारत जो हमारे राष्ट्र की रीढ है। इसमें ५ लाख गांव हैं, जिनमें ३० करोड़ से भी अधिक लोग निवास करते हैं। खेती और छोटे मोटे घरेलू उद्योग धंधों के विकास से ही इनकी उन्नति की जा सकती है। अक्टूबर १९५२ इस कारण चिरस्मरणीय रहेगा कि इस दिन सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। बाद में राष्ट्रीय विस्तार योजना का भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया। इनका उद्देश्य गांवों की सोई शक्ति को जगाना और लोगों का जीवन-स्तर ऊंचा उठाना है। १९६१ तक समस्त ग्राम्य भारत इन योजनाओं के अन्तर्गत आ जायेगा। मेरे विचार से ये योजनाएं भारत में जनतंत्रात्मक आयोजना और 'समाजवादी समाज व्यवस्था' की प्राप्ति के लिए प्रमुख साधन हैं।

इन योजनाओं के अतिरिक्त खेती की पैदावार बढ़ाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं इसके लिये सिंचाई की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। १९५६ तक भारत में कुल सिंचाई क्षेत्र ६७० लाख एकड़ तक पहुँच गया है और १९५१ तक ८८० लाख तक पहुँचाने का संकल्प है। खेती के लिए नई भूमि कृषि योग्य बनाई जा रही है। भूमि कटाव को रोकने और सूखी खेती के लिए कई कार्यक्रम पहले ही बनाये गये हैं। इसी प्रकार बाढ़ रोकने, अच्छे बीज प्रदान करने, खाद आदि की उपलब्धि के प्रयत्न

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चल रहे हैं। किसानों की सुरक्षा के लिए भूमि-सुधार किये जा चुके हैं। गांवों में सहकारिता का व्यापक प्रचार हो रहा है। ग्रामों की ऋण-व्यवस्था में सरकार गहरी दिलचस्पी ले रही है। गांवों के लोगों को रोजगार देने के लिए कुटीर और ग्रामोद्योगों का विकास किया जा रहा है। ग्रामों को बिजली देने के प्रयत्न भी किये जा रहे हैं। यह सारी रूप रेखा है समाजवादी समाज की, जिसे हम अपने गांवों में चला रहे हैं। यह रूप रेखा गांव के प्रत्येक पहलू को लेकर ग्रामवासियों के स्वयं अपने प्रयत्न के आधार पर बनाई गई है।

औद्योगिक उन्नति के प्रयत्न

भारत की औद्योगिक उन्नति में सरकार का भाग लेना अति आवश्यक माना गया है। आधारभूत उद्योगों के विकास के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, इसमें जोखिम भी बहुत होती है। अनुभव से ज्ञात हुआ है कि भारत में निजी उद्योग किसी भी रूप में इस स्थिति में नहीं है कि वह आधारभूत उद्योगों का विस्तार और विकास इतनी तेजी से कर सकें, जिसकी राष्ट्र को आवश्यकता है। इसलिये सरकार को ही इस कमी की पूर्ति करनी होगी, लेकिन यह भी स्मरण रखना चाहिए कि विकासशील अर्थ व्यवस्था में निजी और सरकारी दोनों उद्योगों के प्रसार के लिए विस्तृत क्षेत्र रहता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह व्यवस्था है कि कारखानों का उत्पादन २।३ बढ़ जाये। निजी उद्योग इस अवधि में ६ अरब से लेकर ७ अरब रु० तक का विनियोग करेंगे। इनमें उनकी आधुनिकीकरण की योजनाएं सम्मिलित नहीं हैं।

उपभोग वस्तुओं तथा दूसरी चीजों जैसे सीमेंट और रसायन के अतिरिक्त आधारभूत उद्योगों के विकास में भी निजी क्षेत्र का महत्त्वपूर्ण भाग रहेगा। इस सम्बन्ध में एक उदाहरण दिया जाता है कि इस्पात-उत्पादन को निजी उद्योग क्षेत्र ने आगामी ५ वर्षों में दुगुना कर देना है। सरकार भी निजी उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय बैंक से ऋण प्रदान करके सहायता पहुँचा रही है।

सरकार द्वारा नियंत्रण

अब यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या सरकार को उद्योगों के नियमन, निर्देशन और नियंत्रण के अधिकार मिलने चाहिएं? इसका उत्तर सरल है। भारत ने योजनाबद्ध विकास का रास्ता चुना है। आयोजना में यह आवश्यक हो जाता है कि निजी उद्योगों का विकास निर्धारित क्रम से हो। इससे राज्य को आयातकालीन स्थिति के लिए भी तैयार रहना चाहिए। राज्य का यह भी कर्तव्य है कि वह आर्थिक बुराइयों को उत्पन्न न होने दे। एक प्रकार से 'समाजवादी समाज' में नियमन और नियंत्रण कार्य अति महत्व का है।

विदेशी पूंजी भी

यहीं पर पर यह बात भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत की समाजवादी व्यवस्था में विदेशी निजी पूंजी के लिये भी पर्याप्त क्षेत्र है। भारत में विदेशी पूंजी के विनियोग के लिए वही सुविधाएं है जो स्वदेश की निजी पूंजी के लिये हैं। आयोजना में प्राथमिकता की जो व्यवस्था की गई है, उन्हीं के अनुसार इन पूंजियों का विनियोग किया जायेगा। हां एक शर्त पर विशेष जोर दिया गया है कि विदेशी उद्योगों को भारतीयों को प्रशिक्षित करने की सुविधाएं देनी होंगी और इस देश के लोगों को ही नौकरी पर नियुक्त करना होगा। हम विदेशी पूंजी को जो महत्व दे रहे हैं और जितनां महत्व का कार्य विदेशी पूंजी ने करना है, वह इस बात से स्पष्ट है कि आगामी ५ वर्षों में १ अरब रु० की नई पूंजी भारत में आने वाली है।

आप पूछ सकते हैं कि इस बात की क्या गारण्टी है कि समाजवाद को जिन बिभिन्न आशाओं और इच्छाओं का प्रतीक माना गया है, वे संभव हैं? क्या असमानता को कम करके तीव्र गति से उन्नति की जा सकती है? हम इस बात पर कैसे विश्वास करें कि सरकार के कार्यकलापों की व्याप्ति और मात्रा बढ़ जाने से निजी उद्योग पर कोई दुष्प्रभाव न पड़ेगा। क्या सरकार अपने कार्यक्रम बदलती परिस्थितियों के अनुसार ढालने को तत्पर रहेगी? इन प्रश्नों के उत्तर सरल नही हैं। भारत की परम्पराएं शक्तिशाली और गतिवान रही हैं। जो कुछ स्वीकार किये जाने योग्य है

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कांग्रेस व राष्ट्रीयकरण की नीति

श्री उ० न० ढेबर

शासक दल कांग्रेस ने देश में समाजवादी समाज व्यवस्था की स्थापना अपना लक्ष्य बना लिया है। इस समाजवाद के स्वरूप को समझने में कांग्रेस अध्यक्ष श्री ढेबर के इस लेख से पाठकों को काफी सहायता मिलेगी और अनेक भ्रम दूर हो जायेंगे।

समाजवाद से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण बात है—राष्ट्रीयकरण का प्रश्न।

साम्यवादी इस प्रश्न पर अपने दिमाग से सोचते हैं। वे पूर्व-निश्चित दृष्टिकोण से चलते हैं। वे इस बात पर दृढ़ हैं कि उत्पादन, वितरण और विनिमय के साधनों का स्वामित्व ही समाज का भाग्य तय करता है, और समाजवाद के ध्येय की पूर्ति के लिए राष्ट्रीयकरण के जरिए सामूहिक स्वामित्व राज्य का स्वामित्व परमावश्यक है। कांग्रेस कुछ विशेष क्षेत्रों में राष्ट्रीयकरण का तरीका अख्तयार करने के अलावा, उन अन्य क्षेत्रों पर सिर्फ नियंत्रण करने पर ही सन्तुष्ट रहती है, जिनमें वह सोचती है कि नियन्त्रण द्वारा उत्पादन तथा अर्थव्यवस्था के हितों की पर्याप्त रक्षा हो सकती है।

आधारभूत विचार

कांग्रेस कुछ पुराने निश्चित सिद्धान्तों के ही अनुसार नहीं चलेगी। वह प्रत्येक विभाग के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न उसके वास्तविक स्वरूप में, निम्नांकित प्राथमिक विचारणीय बातों को ध्यान में रखते हुए, देखना चाहेगी :—

(क) जब से मार्क्स ने अपना सिद्धान्त लिखा, समाज काफी आगे बढ़ चुका है। मानवीय विचारों के इस विकास ने उन लोगों पर एक हद तक असर किया है, जिनके हाथों में शक्ति और उत्पादन के साधन हैं।

(ख) गत ५० वर्षों के दौरान में हुई प्राविधिक प्रगतियों ने अर्थशास्त्र की सारी तस्वीर ही बदल डाली है। यदि विश्व-शान्ति तथा आदान-प्रदान की भावना कुछ शताब्दियों तक रहे, तो यह सम्भव हो सकता है कि सम्पूर्ण मानव-समाज को एक न्यायोचित जीवन-स्तर प्रदान करने के लिए न्यायोचित वैज्ञानिक और प्राविधिक प्रगति से फायदा उठाया जा सके, चाहे वह कुछ आराम-देह या महान न हो।

(ग) परिवहन में हुई स्पष्ट वृद्धि ने और विशेषतया एक शक्तिशाली विश्व मत ने, शोषण करने व शोषित होने दोनों का चालू रहना असम्भव सा कर दिया है। इसने सामाजिक तथा श्रम-सम्बन्धी कानून के विशाल स्वरूप में अपने को मूर्तरूप पाया है, जिसका न तो विचार मार्क्स के दिमाग में आया और न उसने उसकी कल्पना ही की। इतना ही नहीं, हम उस युग में प्रवेश भी कर चुके हैं,

अ० भा० कांग्रेस के अध्यक्ष

श्री उ० न० ढेबर

इसने उसको ग्रहण करने में संकोच नहीं किया। नवीन सत्यों और नवीन स्फूर्ति के लिये इसने अपने हृदय और मस्तिष्क को खुला रखा है। इसी विश्वास से हम 'समाजवादी समाज' के लिए प्रयत्नशील हैं।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जिसमें औद्योगिक संस्थाओं की व्यवस्था में श्रमिक हिस्सा लेने लगे हैं और सामूहिक सौदेबाजी होती है।

(घ) राज्य के प्रशासन-यन्त्र में भारी परिवर्तन आ गया है। आज राज्य कम्पनी कानूनों, प्रत्यक्ष कर, सामाजिक बीमा तथा इसी तरह के अन्य तरीकों द्वारा संगठित उद्योगों में क्रियाशील अनुचित लाभ उठाने तथा शोषण करने की प्रवृत्तियों पर काफी रोक-थाम कर सकता है।

एक सामाजिक उद्देश्य

महज राष्ट्रीयकरण के लिए किसी राज्य की दिलचस्पी किसी संस्था का राष्ट्रीयकरण करने में नहीं है। राज्य के इस कदम के पीछे एक सामाजिक उद्देश्य है—(१) यह अर्थ व्यवस्था के नाजुक हिस्सों की रक्षार्थ भारी अथवा प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने का निश्चय कर सकता है; (२) यह उत्पादन बढ़ाने, क्षमता में वृद्धि करने, तथा (३) श्रम और व्यवस्था में सम्बन्ध स्थापित करने के लिए एक ढांचा बनाने के हेतु भी राष्ट्रीयकरण कर सकता है।

समाजवाद की दृष्टि से दूसरी महत्वपूर्ण चीज राष्ट्रीय करण है। इस बारे में कम्युनिस्टों की दृष्टि है कि उत्पादन, वितरण और विनिमय के साधन किसी समाज के प्रकार को ध्वनित करते हैं। वे साम्यवाद के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीयकरण अनिवार्य समझते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस विशिष्ट क्षेत्रों में ही राष्ट्रीयकरण जरूरी समझती है, शेष क्षेत्रों में वह नियन्त्रण में ही विश्वास रखती है। कइयों का विचार है कि जब तक एक भी क्षेत्र में व्यक्तिगत शोषण के लिये स्थान रहेगा, तब तक श्रेणीविहीन समाज का निर्माण न हो सकेगा। राज्य को अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए राष्ट्र के सम्पूर्ण साधनों का पूरा सहयोग प्राप्त करना चाहिये।

विरोधियों का दूसरा पक्ष

दूसरी ओर राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में विरोधी पक्ष इन युक्तियों पर विश्वास करता है। उसका कथन है—

१. राष्ट्रीयकरण की नीति प्रजातन्त्र के सिद्धान्त के विपरीत है। इससे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का हनन होता है।

२. कानून निर्माण की तीव्र प्रगति से समाज का स्वाभाविक विकास अवरुद्ध होता है।

३. नौकरशाहों की बढ़ती हुई शक्ति से खतरा है कि सारा शासन पूरी नौकरशाही के हाथ में आ जायेगा।

४. राष्ट्रीयकरण की नीति से राज्य का पूंजीवाद स्थापित होगा।

कांग्रेस की नीति के आधार

राष्ट्रीयकरण के लक्ष्य की पूर्ति में हमें ख्याल करना चाहिए कि इसका प्रजातन्त्र से विरोध नहीं है। शासन किसी भी उद्योग का राष्ट्रीयकरण केवल राष्ट्रीयकरण की दृष्टि से नहीं करेगा। राज्य के कार्यों का मुख्य लक्ष्य, जैसा कि हम बता चुके हैं, सामाजिक होता है :—(१) वह आर्थिक स्थिति सुरक्षित रखने के लिए बड़े या बुनियादी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर सकता है।

(क) वह उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीयकरण कर सकता है। (ख) वह दक्षता बढ़ाने के लिए इस नीति को अमल में ला सकता है (ग) श्रमिक व प्रबन्धकों के संबंध में सुधार के लिए वह इस उपाय का सहारा ले सकता है।

नौकरशाही के खतरे को रोकने के लिये निजी क्षेत्र के उद्योगों में 'ट्रस्टीशिप' की नीति अपनानी होगी। राज्य तथा निजी क्षेत्र में औद्योगिक प्रजातन्त्र की प्रतिष्ठा के लिये श्रमिकों का सहयोग लिया जाना चाहिये।

कांग्रेस की निश्चित धारणा है कि इन क्षेत्रों का—चाहे वितरण के हों या विनिमय अथवा कृषि व लघु उद्योग हों, उनमें राष्ट्रीयकरण एक स्वेच्छाचारी शासन की प्रतिष्ठा करेगा। इस पर प्रश्न किया जायगा कि इन क्षेत्रों से मुनाफाखोरी का अन्त कैसे हो?

सबसे पहले हम वितरण को लेते हैं। वितरण की संस्थाएं और अवैध संचय, चोर बाजारी और अधिक लाभ करके देशी अर्थ-व्यवस्था को खराब कर सकती हैं या सम्पत्ति

सफ़ेद कोढ़ के दाग

हजारों के नष्ट हुए और सैंकड़ों के प्रशंसापत्र मिल चुके

दवा का मूल्य ५) रु० डाक व्यय १) रु०

अधिक विवरण मुफ्त मँगाकर देखिये।

वैद्य के० आर० बोरकर

मु० पो० मंगरूलपीर, जिला अकोला (मध्य प्रदेश)

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के खराब वितरण के लिए प्रयत्नशील हो सकती है। गत १५ वर्षों के दौरान में इनकी दो या तीन बार परीक्षा हुई, किन्तु ये असफल ही रहीं। यह देखना पड़ेगा कि एक किस्म की 'गड़बड़ी' से अपने को बचाने में हम अपने को दूसरे किस्म की 'गड़बड़ी' में तो नहीं फंसा रहे हैं। वितरण की प्रणाली के राष्ट्रीयकरण के क्या प्रभाव होंगे? इसका अर्थ होगा—देश के सम्पूर्ण वाणिज्य पर पूर्ण नियन्त्रण। एक ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि जब एक वितरण पद्धति वक्त के साथ चलने से इंकार कर दे, और तब हमें एक विशेष वस्तु या उसके एक हिस्से का वितरण कार्य अपने हाथ में लेना पड़े। लेकिन निजी व्यापारी को पूर्णतया या लगभग पूर्णतया अपने अधिकार में लेना सोचा भी नहीं जा सकेगा। इसके बजाय, व्यापार को प्रारम्भिक इकाई में संगठित करना ज्यादा आसान होगा, यानी जहां वस्तुएं फैक्टरी से निकलती हैं, वहां पर एक सुसंगठित व्यापार संघ स्थापित किया जाय, जोकि धीरे-धीरे सहकारिता के मार्ग द्वारा उपभोक्ताओं के हाथ में माल पहुँचा देगा। निजी व्यापार कायम रहेगा, लेकिन उसे सहकारी संघों की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, जो एक नियन्त्रण-शक्ति के रूप में कार्य करेंगे।

विनिमय एक सरलतम समस्या है। हमें इसे संगठित व्यापारिक संघों तथा सहकारी संघों के जरिए नियंत्रित करना चाहिए।

अन्त में, हम कृषि पर आते हैं। लाखों खेत, जिनमें हमारी कृषि बंटी हुई है, हमारे लिए सिवाय इसके कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं, कि हम इस क्षेत्र को उपर्युक्त अर्द्ध-सहकारी संस्थानों, सम्भवतः योजना सलाहकार बोर्डों या राष्ट्रीय-विस्तार सेवा परामर्शदात्री समितियों की देख-रेख में गांव-सभाओं, ग्राम-पंचायतों तथा सहकारी संघों द्वारा संगठित करें।

एक मात्र उपाय—उचित वितरण

हम प्रतिज्ञा तो गांधीजी के विचारों की करते हैं, लेकिन नकल करते हैं पश्चिमी देशों की। हम अनजाने ही पश्चिम के भौतिकवादी दर्शन की ओर देश को खिंचे जा रहे हैं। लेकिन, हम यह महसूस नहीं कर पाते कि गरीबी में डूबे हुए भारत के लाखों-करोड़ों अज्ञान और शोषित लोग ही भारत की असली सभ्यता के प्रतिनिधि हैं। जब हम अपने देश की मेहनतकश और शोषित आम जनता के दुःख-दर्दों और कष्टों को महसूस करने लगेंगे, तभी हमें आवाड़ी प्रस्ताव का असली मकसद स्पष्ट हो पायगा। यह प्रस्ताव इस शोषण का अन्त करने के लिए ही एक आह्वान है।

हमें इस बात का जवाब देना होगा कि हम गरीब मजदूरों के पसीने, नहीं नहीं, उनके खून को, कितनी अहमियत देते हैं क्योंकि उनके पसीने की एक-एक बूँद उनके खून की बूँद है। अगर दूसरे लोग उनके पसीने का मूल्य समझ जाये तो उन्हें रचंमात्र शोषण का परित्याग करना ही पड़ेगा। शोषण का मतलब है अपनी ज़रूरत से ज्यादा लेना। हम सबको समझना होगा कि कोई भी कमजोरों के शोषण या दूसरों की मेहनत पर फलफूल नहीं सकता। जनता के धैर्य की भी एक सीमा है। अगर हम एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों को उनके हिस्से से लगातार महरूम (वंचित) करते रहेंगे तो उनका असन्तोष फूट पड़ेगा और फिर उनकी प्रतिक्रिया का मुकाबिला करना कठिन होगा। बिहार राज्य में दर-रैयतों की संख्या ३० लाख है। आप उन्हें उनकी ज़मीन पर कब्जा पाने से रोक सकते हैं, लेकिन जब ये तीस लाख लोग अपने प्रति होने वाले अन्याय को समझ जायेंगे और उसे हटाने की मांग पर तुल जायेंगे, उस समय उन्हें रोकना मुश्किल होगा। आजादी एक दुधारी तलवार है। उसे बचाए रखने और खतरनाक नतीजों को रोकने का एक मात्र तरीका उचित वितरण है।

—डेबर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

समाजवाद—कांग्रेस के प्रस्तावों में

आबाडी अधिवेशन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने —'समाजवादी समाज' को अपना ध्येय घोषित किया। कुछ लोगों को यह अकस्मात निर्णय जान पड़ा। लेकिन सच तो यह है कि १९४७ से ही कांग्रेस के सभी अधिवेशनों में 'समाजवाद' को लक्ष्य माना जा चुका था। हाँ "समाजवादी उद्देश्य" की स्पष्ट घोषणा आबाडी में ही की गई। इस अधिवेशन के समय से कांग्रेस ने अपना ध्येय स्वीकार किया कि—

"भारत के प्रजाजनों की उन्नति और प्रगति तथा शांतिपूर्ण और वैधानिक साधनों के द्वारा सहकारी कामन-वैल्थ की स्थापना करना, जिसका आधार अवसर की समानता, और राजनैतिक, आर्थिक व सामाजिक अधिकारों की प्राप्ति है। इसके अतिरिक्त भारत के संविधान में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्त्वों के अनुसार आयोजना का आधार ऐसा हो, जिससे समाजवादी समाज की स्थापना की जा सके, जिसमें:—

(क) उत्पादन के प्रमुख साधन समाज के स्वामित्व और नियंत्रण में हों;

(ख) उत्पादन में तेजी से वृद्धि हो सके, तथा

(ग) राष्ट्रीय आय का समान वितरण हो सके, तथा

(घ) रोजगार मिलने की दशाओं में इतनी प्रगति हो जाये कि १० वर्ष के अंदर अंदर पूर्ण रोजगार मिल सके।

दिल्ली नवम्बर १९४७

इसके पहले भी स्वतंत्रता प्राप्ति के तत्काल बाद ही १९४७ में ही दिल्ली कांग्रेस में ऐसा ही प्रस्ताव पास किया गया था।

हमारा उद्देश्य एक ऐसे आर्थिक ढांचे का निर्माण और विकास करना होना चाहिए; जिसमें धन के एक ही दिशा में एकत्र होने की प्रवृत्ति के बिना अधिकतम उत्पादन किया जा सके, तथा जिसमें नगर और ग्रामों की अर्थ-व्यवस्था में सामंजस्य उत्पन्न किया जा सके। यही आर्थिक ढांचा, वैयक्तिक पूंजीवादी-विसम-अर्थ-व्यवस्था और सर्वाधिकारवादी शासन का एकमात्र विकल्प है।" आबाडी अधिवेशन में इसी बात को व्यापक रूप से स्पष्ट किया गया।

१९५४ में अजमेर में कांग्रेस महासमिति के अधिवेशन में आर्थिक नीति सम्बन्धी उद्देश्य का जो प्रस्ताव पास किया गया, उसका मूलाधार है—

(क) अधिकतम उत्पादन

(ख) पूर्ण रोजगारी तथा

(ग) सामाजिक और आर्थिक न्याय।

यह स्पष्ट किया गया है कि—जिन उद्योगों से अन्न, कपड़ा जैसे अन्य प्रारभिक आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन होता है, उनका संचालन विकेंद्रित रूप में होना चाहिए। जहां तक संभव हो इन उद्योगों का प्रबन्ध और संचालन सहकारिता के आधार पर मुख्यतः कुटीर और छोटे उद्योगों के स्तर पर जाना चाहिए।

उत्पादन के दोनों भागों—छोटे उद्योगों और बड़े उद्योगों में—स्पर्द्धा न हो, इसके लिए सरकार अपने नियंत्रण में ऐसे बड़े पैमाने के उद्योगों को ले सकती है जो छोटे पैमाने के उद्योगों के समान ही उत्पादन करें।

निजी और सरकारी उद्योग

आबाडी अधिवेशन में आर्थिक नीति का जो प्रस्ताव पास किया गया था, उसमें कहा गया है कि—देश में पहले से ही शक्तिशाली सरकार-नियंत्रित उद्योग हैं। जहां तक संभव हो दूसरे आधारभूत उद्योग और नये उद्योगों को सम्मिलित करके इसका विस्तार किया जाना चाहिए। जिन उद्योगों की निकट भविष्य में ही सरकारी उद्योग क्षेत्र के अन्दर लाने की संभावना न हो, उन पर प्रभावपूर्ण ढंग से सामाजिक नियंत्रण रखा जाये। देश के साधनों का उपयोग नये-नये सरकारी उद्योगों की स्थापना के लिए किया जाना चाहिए; निजी उद्योग या गैर सरकारी उद्योग और वैकल्पिक (Voluntary) उद्योग चलते रहेंगे। यदि 'निजी उद्योग' का कार्य 'राष्ट्रीय आयोजना' के आधार पर सरकारी नियंत्रण के अधीन किया जाये तो उत्पादन में तेजी आयेगी और लक्ष्य की पूर्ति पूर्ण रूप से हो जायेगी।

ग्रामोद्योग

ग्रामोद्योगों के सम्बन्ध में १९४८ में बम्बई कांग्रेस में

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया गया था—आयोजना का उद्देश्य छोटे उद्योग और ग्रामों के सम्बन्ध में यह होगा कि जनशक्ति, पशुओं तथा प्राकृतिक साधनों का अधिकतम उत्पादन के लिए पूर्ण उपयोग किया जा सके जिससे राष्ट्रीय न्यूनतम जीवन-मान की, जिस में संतुलित आहार, यथेष्ट वस्त्र तथा प्रत्येक परिवार को निवास स्थान—प्राप्ति हो सके।

इसी सम्बन्ध में अजमेर कांग्रेस (१९५४) के समय ग्रामोद्योगों के विषय में कहा गया है "इस प्रकार के उद्योगों के बड़े पैमाने के उद्योगों से भी अधिक रोजगार देने में समर्थ होने की संभावना है। विकसित शिल्प-तंत्रों का इनमें प्रयोग किया जाना चाहिए, जहां कहीं संभव हो विद्युत शक्ति का भी उपयोग किया जाये। नये शिल्पतंत्रों के कारण जो परिवर्तन हों उसके लिये यह ध्यान रखा जाये कि बेरोजगारों को काम मिल सके। जहां तक संभव हो, बड़े पैमाने के उद्योगों और छोटे उद्योगों के उत्पादन के क्षेत्र की सीमा स्पष्टतः अंकित कर देनी चाहिए।

पूर्ण रोजगार

मई १९५३ में कांग्रेस की कार्यसमिति ने एक प्रस्ताव पास किया था—किसी योजना की सफलता की कसौटी उन साधनों पर निर्भर है, जो बेरोजगारी को दूर करने के लिए अपनाये जाते हैं।... ... बेरोजगारी का कायम रहना केवल एक सामाजिक बुराई और राष्ट्र पर भार ही नहीं वरन् इससे पूर्ण उत्पादन में भी बाधा पहुँचती है क्योंकि इस रूप में श्रमिकों की यह अतिरिक्त उत्पादन-शक्ति व्यर्थ ही जाती है।"

अमृतसर अधिवेशन

१९५६ के अमृतसर अधिवेशन में स्पष्ट रूप से कहा गया कि आवाडी प्रस्ताव के अनुसार "समाजवादी ढंग की व्यवस्था कायम करने की दृष्टि से आर्थिक आयोजन किया जाना चाहिए। साथ ही मूल उद्योगों, छोटे धंधों और ग्रामोद्योगों के विकास पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इस अधिवेशन में इम्पीरियल बैंक और जीवन-बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण को समाजवादी व्यवस्था की ओर महत्वपूर्ण कदम मानते हुए उसका स्वागत किया गया।

आवाडी अधिवेशन के प्रस्ताव में—'सोशलिस्टिक' शब्द का प्रयोग किया गया था, जब कि आर्थिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव में 'सोशलिस्ट' शब्द ही काम में लाया गया।

इन्दौर अधिवेशन

द्वितीय आम चुनावों की पृष्ठ भूमि में १९५७ के आरम्भ में इन्दौर अधिवेशन समाजवाद की दिशा में 'स्पष्ट कदम' माना जायेगा। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने समाजवादी पर लोकतंत्रीय व्यवस्था की स्थापना को अपना उद्देश्य स्वीकार किया। जो भी भ्रांति कांग्रेस के 'समाजवाद' के सम्बन्ध में थी, वह दूर कर दी गई। कांग्रेस अध्यक्ष श्री ढेबर ने कहा भारत के समाजवाद का झुकाव "गांधी जी के सर्वोदय की ओर अधिक होना चाहिए।"

इन्दौर कांग्रेस के समाजवादी सिद्धांतों का लेखा चुनाव घोषणा पत्र से ही ज्ञात किया जा सकता है। घोषणा-पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि आर्थिक समानता स्थापित करना अत्यन्त आवश्यक है। इस समय जो आर्थिक असमानता मौजूद है उसे कम किये बिना भारत में समाजवादी समाज कायम करना नामुमकिन है। इसके लिए कहा गया है कि कर-व्यवस्था का पुनर्निर्धारण करना होगा; एक निम्नतम जीवन-स्तर नियत करना होगा; कुछ लोगों के ही हाथ में धन इकट्ठा न होता रहे इसके लिए उत्पादन के ढंग में क्रांतिकारी परिवर्तन करना आवश्यक है। निजी उद्योगों के अस्तित्व को भी देश के लिए आवश्यक बताया गया, पर विशेष उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का भी समर्थन किया गया।

चुनाव घोषणापत्र में विकेंद्रित आयोजन के महत्व को स्वीकार किया गया है और कहा गया है कि ग्राम पंचायतों को इसमें मुख्य भाग अदा करना होगा। सहकारिता पर बल दिया गया। ग्रामीण, कुटीर व बड़े उद्योगों का क्षेत्र स्पष्ट कर दिया गया तथा इस घोषणापत्र में कहा गया कि हम तब तक प्रयत्न करते रहेंगे, जब तक देश में पूर्ण सामाजिक व्यवस्था स्थापित न हो जाये, जिससे सब देशवासियों को स्वतंत्रता, मंगलहित और अवसरों व सुविधाओं की समानता मिलने लग जाये।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रजा समाजवादी दल

भारत में समाजवादी आन्दोलन और उसकी प्रगति को समझने के लिए केवल कांग्रेस के प्रस्तावों या कांग्रेस सरकार की प्रगति को जानना ही पर्याप्त न होगा। दो अन्य संस्थाएं भी देश में समाजवाद या साम्यवाद का प्रचार करती रही हैं और आज भी उनका देश के सार्वजनिक जीवन में स्थान है। ये दो संस्थाएं हैं—प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी।

दल का जन्म

१९३० के सत्याग्रह और १९३१ के कराची-कांग्रेस के बाद कांग्रेस में नयी विचारधारा जन्म लेने लगी थी। कुछ कांग्रेसी नेता यह अनुभव करने लगे थे कि अब अधिक स्पष्टता के साथ अपने विचार प्रकट करने चाहियें और किसानों व मजदूरों के हित की आवाज ज्यादा जोर से उठायी जानी चाहिये। मई १९३४ में कांग्रेस के अन्तर्गत ही एक कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गयी। १७ मई, सन् १९३४ को इसका पहिला अधिवेशन पटना में आचार्य नरेन्द्र देव के सभापतित्व में हुआ। श्री जयप्रकाश नारायण, श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय आदि प्रमुख नेता भी इसमें सम्मिलित थे। शनैः-शनैः इस दल का प्रभाव देश में बढ़ता गया। समय-समय पर कांग्रेस के दक्षिण पक्षी नेताओं से विरोध भी बढ़ता गया। इस दल के सम्मेलन काफी उत्साह के साथ होते थे। इस दल की विचारधारा एक ओर कम्युनिस्टों की रूस के प्रति अन्ध श्रद्धा तथा उनकी हिंसात्मक प्रवृत्तियों का विरोध करती थी, दूसरी ओर देश में किसान और मजदूर वर्ग का प्रबल समर्थन करती थी और उनके प्रश्नों को उग्रता के साथ प्रगट करने और कोई कदम उठाने का आग्रह करती रही। अनेक ऐसे अवसर भी आये, जब कांग्रेस के नेताओं का तीव्र विरोध किया गया। स्वयं गांधीजी ने इस दल के सिद्धान्तों के सम्बन्ध में कहा था—"यदि उसके सिद्धान्त कांग्रेस ने स्वीकार कर लिये तो मैं कांग्रेस में नहीं रहूंगा।" कांग्रेस के अन्दर रहते हुए भी समाजवादी दल कांग्रेस का विरोध उग्र करता जा रहा था। इसलिए नेताओं के द्वारा इसका विरोध भी उग्र होने लगा। आखिर कानपुर के अधिवेशन, १९३७ में समाजवादी दल ने अपने नाम के साथ कांग्रेस का शब्द हटा दिया और नासिक सम्मेलन १९४८ में तो कांग्रेस से बिलकुल सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया गया।

समाजवादी दल की नेत्री

श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय

कम्युनिस्ट नीति से मतभेद

एक लेखक के शब्दों में यह नासिक सम्मेलन समाजवाद के भारतीयकरण की भूमिका माना जा सकता है। दल के नेता श्री जयप्रकाश नारायण ने अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में कम्युनिस्ट पार्टी के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए साधनों में स्वच्छन्दता का विरोध किया और कहा कि "अगर समाजवाद के अर्थ ऐसे समाज के हैं, जहां प्रत्येक व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, जहां प्रत्येक व्यक्ति सभ्य, संस्कृत, वीर और उदार हो, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसे समाज तक पहुँचने के लिए हमें कुछ मानवीय गुणों, कुछ आचरण के मापदण्ड के नियमों का कड़ाई के साथ पालन करना होगा।..... खाते-पीते और अच्छी तरह से रहने वाले बर्बर समाज के नारे से 'समाजवादी

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

समाज' का नारा बहुत दूर की बात है।" स्पष्टतः यह विचार रूसी कम्युनिस्ट नीति का विरोध था।

कांग्रेस के शासनसूत्र संभालने के बाद समाजवादी दल एक विरोधी दल का रूप धारण करने लगा। पटना सम्मेलन में श्री जयप्रकाश नारायण ने पार्टी के संगठन के द्वार प्रजातांत्रिक आधार पर साधारण जनता के लिए खोल दिये और उसका संगठन व्यापक बनाया गया। हिंसात्मक प्रवृत्तियों व सशस्त्र क्रान्ति का स्पष्ट विरोध किया गया। समाजवाद सम्बन्धी एक कार्यक्रम की घोषणा भी की गयी।

आचार्य नरेन्द्रदेव, श्री जयप्रकाश नारायण, श्री राममनोहर लोहिया, श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय आदि देश के तपे हुए माननीय नेता इस दल में सम्मिलित थे। इसलिए यह दल निरन्तर उन्नति कर रहा था। लोकमत को जागृत करने का काम इन लोगों के हाथ में था। कांग्रेस शासन के प्रति जनता के असन्तोष को यही दल प्रगट कर रहा था। कम्युनिस्ट दल की रूस के प्रति अन्ध-श्रद्धा तथा हिंसात्मक नीति के कारण जनता में वह लोकप्रिय नहीं था। इसलिए वे सब लोग जो देश के प्रति पूर्ण आस्थावान थे, और कांग्रेस की नीति से असन्तुष्ट थे, इस दल के प्रति सहानुभूति रखने लगे। वस्तुतः इस दल की आदर्श संस्था ब्रिटिश लेबर पार्टी थी। किसी दूसरे राष्ट्र से प्रेरणा या आदेश स्वीकार न करके विशुद्ध राष्ट्र-प्रेम इसका लक्ष्य था। इस संस्था ने मजदूर आन्दोलन में विशेष रुचि ली और हिन्द मजदूर सभा के नाम से एक देशव्यापी संगठन किया।

प्रजासमाजवादी दल

१९५२ में इस दल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। आचार्य कृपलानी की कृषक प्रजा पार्टी इस दल में सम्मिलित हो गयी और दल का नाम "प्रजा समाजवादी दल" रखा गया। दोनों दलों के मिल जाने से ऐसा प्रतीत होता था कि इस दल का महत्व बहुत बढ़ जायगा। सोशलिस्टों का विचार-स्रोत यदि मार्क्स था तो कृषक मजदूर पार्टी का स्रोत गांधी था; परन्तु दोनों दलों के नेता एक-साथ राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य-संग्राम में विदेशी शासन से लड़े थे। दोनों सामाजिक न्याय और राजनीतिक या आर्थिक सत्ता के विकेन्द्रीकरण के पक्ष में थे। पूंजीवाद को दोनों बुराई के रूप में मानते थे और ग्रामोद्योगों के विकेन्द्रीकरण और बड़े उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में थे। दोनों इस बात में विश्वास करते थे कि नयी सामाजिक व्यवस्था केवल पार्लमेंटरी पद्धति से स्थापित नहीं होगी और न हिंसा या गृह-युद्ध हमें अपनाने हैं। हमें तो वर्तमान सामाजिक आर्थिक अन्याय का मुकाबला करना है।

प्रजा-समाजवादी दल ने देश की राजनीति में उत्साह से भाग लिया और कुछ समय ट्रावनकोर-कोचीन में राज्य सरकार का शासन-सूत्र भी अपने हाथ में लिया। भिन्न-भिन्न अवसरों पर जो आन्दोलन किये गये, उनका उल्लेख करके मैं पाठकों की स्मृति-शक्ति का अपमान नहीं करना चाहता। फिर भी, आन्ध्र के इनाम काश्तकारों की विजय, विभिन्न मजदूर आन्दोलन, भूदान यज्ञ का समर्थन, मध्यवर्ग की बेकारी के निवारण के लिए आन्दोलन, भूमि-सुधार के प्रयत्न, पारदी किसानों का सत्याग्रह, उत्तरप्रदेश में किसान आन्दोलन आदि इस दल की मुख्य प्रवृत्तियां हैं।

आजकल प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष श्री गंगाशरण सिंह हैं। इस समाजवादी दल की नीति घोषणा से मालूम होता है कि उसके आर्थिक और राजनीतिक विचार क्या हैं? वह जनता को पूर्णतम आर्थिक और राजनीतिक जनतंत्र प्रदान करना चाहता है। साधनों की पवित्रता, संघर्ष के अहिंसावादी तरीके, विकेन्द्रित जनतंत्र और अर्थ-प्रणाली आदि के कारण वह उस कम्युनिस्ट पार्टी से बिलकुल भिन्न है, जो रूस की कम्युनिस्ट पार्टी का अनुसरण करती है। नेताजी सुभाष बोस के द्वारा स्थापित फारवर्ड ब्लौक के अनुयायी भी पीछे से इस दल में मिल गये।

आज बिहार और उत्तरप्रदेश में इस दल का काफी प्रभाव है। उनकी विधान सभाओं में इस दल के सदस्यों की संख्या काफी है। दूसरे आम चुनाव के नीचे के अंकों से देश के सार्वजनिक जीवन में इस दल का स्थान स्पष्ट हो जायगा।

सफल प्रजा-समाजवादी उम्मीदवार

संसद—२२, १९ लोकसभा, ३ राज्यसभा।

राज्य—विधान सभाएं—१९५

उत्तरप्रदेश ४४, बिहार ३१, बम्बई ३६, बंगाल ११, मैसूर १९, उड़ीसा ११, शेष राज्य ३४।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (संक्षिप्त परिचय)

भारत में कम्यूनिस्ट पार्टी की स्थापना चीन में कम्यूनिस्ट पार्टी की स्थापना से ४ वर्ष पहले अर्थात् १९२४ में हुई। इन ३३ वर्षों में जितनी रहस्यमयता इस संस्था के इतिहास में रही है, वैसी किसी अन्य संस्था के जीवन में नहीं रही। यह कभी प्रत्यक्ष हुई, कभी विलुप्त हो गई। इसके कार्यकर्त्ता कभी मैदान में आये, कभी भूमिगर्भ में चले गये। ये नेता परस्पर मिलते भी, पर कोई निश्चित कार्यालय, निश्चित रजिस्टर, निश्चित सदस्य संख्या आदि सभी अज्ञात से रहे, फिर भी यह संस्था काम करती रही और शनैः शनैः ज्ञात या अज्ञात रूप से साम्यवादी विचारों का प्रचार करती रही। ब्रिटिश सरकार इसके कार्यों व प्रवृत्तियों को अत्यन्त शंका व संदेह की दृष्टि से देखती रही और जनता विस्मय व आदर के साथ। कम्यूनिस्ट कार्यकर्ता देश को अंग्रेजी शासन से भी मुक्त कराना चाहते थे। उनका प्रचार बढ़ रहा था। सारे देश में ये फैले हुए थे। आखिर २० मार्च, १९२९ के दिन बम्बई, पंजाब व यू० पी० में ताजीरात हिन्द की १२१ धारा के मातहत सैकड़ों घरों की तलाशी ली गई। ३१ कार्यकर्ताओं को, जिनमें से आठ अ० भा० कांग्रेस समिति के सदस्य भी थे, गिरफ्तार कर लिया गया। इन पर कम्यूनिज्म का प्रसार व षड्यंत्र करने का अभियोग चला, जो मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध है। इनके साथ देश की सहानुभूति थी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने मुकदमे की सहायता के लिए १५००) रु० दिये। इस मुकदमे के बाद बहुत समय तक कुछ प्रवृत्तियां शिथिल व अज्ञात रहीं, परन्तु रूसी समाजवाद का थोड़ा बहुत साहित्य भारत में प्रकाशित होता रहा। बम्बई आदि नगरों में मजदूर संगठन में इनकी रुचि बहुत बढ़ गई। हड़ताल इन का प्रधान साधन था। ट्रेड यूनियन कांग्रेस के मंच से, जिस पर इनका प्रभाव बढ़ गया था, जनता के सामने आते रहे।

फिर मैदान में

कम्युनिस्टों का संगठन गुप्त रूप से काम करता रहा, अधिकांश कार्यकर्ता जेलों में बन्द रहे। कम्यूनिस्ट पार्टी गैर कानूनी संस्था घोषित कर दी गई थी। इसलिए इसका कार्य प्रत्यक्ष रूपेण हो भी नहीं सकता था। श्री मानवेन्द्र नाथ राय तो रूस में जाकर बहुत समय तक कार्य कर चुके थे। वे भारत में आते ही गिरफ्तार कर लिये गये। १९३९ के यूरोपीय युद्ध के प्रारम्भ होने पर इन पर सरकार की और भी सशंक दृष्टि हो गई, क्योंकि इनकी सहानुभूति रूस के साथ थी और उस समय वह जर्मनी के साथ था। १९४१ में जब अचानक रूस पर जर्मनी ने आक्रमण कर दिया, तो कम्यूनिस्ट नेताओं की भी दृष्टि बदल गई और वे उस युद्ध में ब्रिटेन का साथ देने और स्वातंत्र्य युद्ध का विरोध करने लगे। सरकार से समझौता हो गया और सभी कम्युनिस्ट वर्षों के बाद जेलों से बाहर आ गये। युद्ध कालीन वर्षों में कम्यूनिस्ट पार्टी का केवल एक काम रह गया कि जनता को युद्ध-कार्यों में सरकार को सहयोग देने के लिए प्रेरणा दी जाय। इन वर्षों का कम्यूनिस्ट पार्टी का इतिहास राष्ट्रीय दृष्टि से गौरवपूर्ण न हो, किन्तु इससे भारत में पार्टी का संगठन निश्चित व सुदृढ़ हो गया। इनको साधनों की भी कमी न रही और वे अज्ञात भूमिगर्भ से निकलकर सामने आने लगे।

साम्यवादी नेताओं ने साम्यवादी साहित्य का प्रचार जोरों से शुरू किया। कार्ल मार्क्स द्वारा प्रकाशित साहित्य अपने सस्तेपन, अच्छी छपाई व बहिरंग के कारण देश भर में खूब लोकप्रिय हुआ। विभिन्न भाषाओं में साम्यवादी दल के अनेक पत्र चलने लगे। मजदूर आन्दोलन की प्रमुखतम संस्था आल इण्डियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस पर इसका अधिकार हो ही गया था। साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिशील लेखक संघ के नाम से कम्यूनिस्ट जनता के सामने आये और जोरों से आये। शांति-परिषद् विश्व शांति प्रसार के निमित्त स्थापित हुई, और कम्यूनिस्ट अधिकाधिक वह नारा लेकर भी जनता के सामने आये। पहले कुछ क्षेत्रों में यह संभावना की जा रही थी कि राष्ट्रीय स्वतन्त्र सरकार की स्थापना के बाद कम्यूनिस्ट उसे सहयोग देंगे, किन्तु दोनों की आर्थिक व राजनैतिक विचारधारा परस्पर विरोधी थी और यह विरोध बढ़ता गया। किसानों, मजदूरों, बन्दरगाहों, बैंकों व रेलवे कर्मचारियों आदि के विभिन्न

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आन्दोलनों का नेतृत्व करके कम्यूनिस्ट जनता के अधिकाधिक सम्पर्क में आने लगे। सरकार के प्रति इनका रुख अधिकाधिक कठोर व उग्र होता गया।

तैलंगाना के उपद्रव

तैलगांना के किसान-उपद्रव कम्यूनिस्ट पार्टी के इतिहास की प्रमुख घटना है। मारकाट, हत्यां, लूटमार, अग्निकाण्ड आदि सभी साधनों का प्रयोग इसमें किया गया और सरकार को इनका तीव्र दमन करना पड़ा। इन्हीं तैलंगाना उपद्रवों ने आचार्य विनोबा को वहां जाकर भूमि-समस्या का समाधान करने के लिए प्रेरणा दी और भूदान यज्ञ प्रारम्भ हुआ। विभिन्न आर्थिक व राजनैतिक प्रश्नों पर कम्यूनिस्ट दल अपनी स्पष्ट और निश्चित नीति के साथ आने लगा और समय पाकर वह अपनी शक्ति बढ़ाने लगा।

केरल में राज्य सूत्र

आज उसकी शक्ति कांग्रेस के बाद सबसे अधिक है। केरल में आज साम्यवादी दल शासन कर रहा है। मंत्रियों के वेतन ५००) रु० कर दिये गये हैं, पुलिस को निहित स्वार्थों की संरक्षक न बनाकर किसानों व मजदूर आन्दोलन की संरक्षक बना दिया गया है, भले ही यह प्रवृत्ति वहां चिन्ता का कारण बन गई है। कृषि आय पर भारी कर लगा दिये गये हैं। निजी व्यापार पर नियंत्रण किये जा रहे हैं। केरल का शासन सूत्र हाथ में आने के बाद इस दल का प्रभाव व शक्ति बहुत बढ़ गये हैं। लोकसभा में आज ३० साम्यवादी सदस्य हैं और विभिन्न राज्यों की असेम्बलियों में २०७। चुनावों में इस भारी सफलता का एक परिणाम यह भी हो रहा है कि कम्युनिस्ट नेता समझने लगे हैं कि केवल हिंसात्मक साधनों से ही नहीं, वैध उपायों द्वारा भी देश में शक्ति प्राप्त की जा सकती है। दृष्टि में यह परिवर्तन शुभ लक्षण है, यद्यपि दूसरे दल उनके इस दृष्टि-परिवर्तन में विश्वास नहीं करते। मार्क्स तथा दूसरे साम्यवादी नेता 'प्रोलितिरेयित डिक्टेटरशिप' की प्राप्ति के लिए हिंसा के साधनों को अनुचित नहीं मानते थे। भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के संविधान की प्रस्तावना में मार्क्स व लेनिन की शिक्षाओं के अनुसार साम्यवाद व वर्गहीन समाज और प्रोलितेरियत डिक्टेटरशिप की स्थापना के लिए संघर्ष का उल्लेख है। इसलिए भारतीय कम्यूनिस्टों का वैधानिक व जनतंत्री प्रणाली की ओर झुकाव इस दल के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना है।

भविष्य

साम्यवादी दल की व्यवहार नीति पर इस दल का भविष्य निर्भर है। इन वर्षों में प्राप्त सफलता के मुख्य कारण केवल इस दल के सिद्धान्त नहीं हैं। इस दल के आकर्षक व लुभावने नारों के अतिरिक्त अन्य कारण निम्नलिखित हैं—विश्व में कम्युनिस्ट आंदोलन की प्रगति, समाजवाद के विचारों की बढ़ती हुई लोकप्रियता, रूस व चीन में समाजवाद की प्रभावशाली सफलताएं और कांग्रेसी शासन की दुर्बलताओं से उत्पन्न असंतोष। प्रांतीय भाषा व सम्प्रदाय आदि स्थानीय प्रश्नों पर साम्यवादी दल ने विभिन्न दलों से जो समझौते किये, उनका भी प्रभाव कम्युनिस्टों के लिए बहुत अच्छा रहा है। दूसरी ओर आंध्र और तेलंगाना तथा तामिलनाड आदि राज्यों में साम्यवादी दल का पराजय इस बात का सूचक है कि कम्यूनिस्ट पार्टी का प्रभाव बुरी तरह गिर भी सकता है।

हमने इस लेख में कम्युनिस्ट पार्टी की राजनैतिक नीति व मन्तव्यों की जान-बूझ कर चर्चा नहीं की। सम्पदा के पाठक इसकी अनुमति भी शायद नहीं देंगे। आगामी १० वर्ष बतायेंगे कि देश में कम्यूनिस्ट पार्टी का भविष्य क्या है? तब तक जनता इसके सिद्धान्तों, व्यवहार तथा गुण-दोषादि से परिचित होकर अपनी सम्मति बना सकेगी।

———

सम्पदा के पिछले—

विशेषांक

भी समाजवाद अंक की तरह ज्ञान-वर्धक और उपयोगी हैं। उन्हें मंगाकर अपने पुस्तकालय को समृद्ध कीजिये।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मैं क्या मानता हूं ?

कुछ महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर विविध विचारकों के उत्तर

"समाजवाद क्या है और भारत सरकार के प्रयत्न इस दिशा में क्या सहायक होंगे, इस बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रश्न अनेक महानुभावों से किये गये थे—: समाजवाद क्या है, उद्योगों व कृषि का राष्ट्रीयकरण क्या समाजवाद है ? सरकार समाजवादी समाजवाद की स्थापना के लिए जो कुछ कर रही है, उससे आप क्या सन्तुष्ट हैं और आपकी सम्मत्ति में क्या कदम उठाने चाहिएं । जिन महानुभावों ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर उत्तर भेजें, उनमें से कुछ इन पृष्ठों में प्रकाशित किये जा रहे हैं :—

एन० आर० मलकानी

समाजवाद क्या है ? इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत कठिन है । परन्तु मेरा यह विश्वास है कि इस प्रश्न को समझने के लिये दो तरीके हैं । विध्यात्मक और निषेधात्मक । निषेधात्मक दृष्टि से देखें तो साम्यवाद या समाजवाद में गरीबी और भौतिक अभावों को दूर करना चाहिये, बेकारी को समाप्त करना चाहिये और पूंजीवाद की उन बुराइयों को भी खत्म कर देना चाहिये, जो आज संसार को संकट की ओर ले जा रही हैं । दूसरा विध्यात्मक उपाय यह है कि कमजोर, दरिद्र और भाग्यहीन या असमर्थ व्यक्तियों को पूर्ण सक्रिय सहायता देनी चाहिये और समाज की सेवा करनी चाहिये । जहां तक आर्थिक स्थिति का सम्बन्ध है, वहाँ तक समानता की ओर ले जाने का प्रयत्न करना चाहिये । विशेषकर स्त्रियों और पुरुषों को आजीविका और जीवन निर्वाह के लिए उचित वेतन प्राप्त करने का समान अवसर मिलना चाहिये । हमें यह समझ लेना चाहिये कि ऐसा समाजवाद एक ऐसे समाज की कल्पना करता है, जिसमें प्रतिस्पर्धा की अपेक्षा सहयोग और व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा समाज सेवा की दृष्टि मानव को प्रेरणा देने वाली बने ।

(२)

मेरा यह विश्वास है कि युद्ध-सम्बन्धी उद्योगों—कोयला, लोहा आदि प्रधान उद्योगों तथा रेलवे, पोस्ट आफिस आदि सार्वजनिक सेवा की प्रवृत्तियों का राष्ट्रीय करण अवश्य होना चाहिये । शेष उद्योगों के लिए मेरी नम्र सम्मति में छोटे किसानों, छोटे उत्पादकों और छोटे कारोबारियों के बड़े बड़े सहकारी संघ होने चाहिये । इन सहकारी संघों के सदस्य स्वयं अपने ऊपर नियंत्रण लगाकर उत्पादन की प्रेरणा पाएँगे ताकि समाज-विरोधी तत्व और प्रवृत्तियाँ प्रबल न हों । इसके बावजूद यह आवश्यक होगा कि निजी उद्योग पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहें। मैं उनके अस्तित्व को नष्ट नहीं करना चाहूंगा । परन्तु यह चाहूंगा कि उन पर सरकारी नियंत्रण और अनुशासन इतना अवश्य रहना चाहिये ताकि वे अनुचित रूप से बहुत अधिक मुनाफा न उठा सकें और कारीगरों का शोषण न कर सकें ।

खेती में मैं राष्ट्रीयकरण को पसन्द नहीं करता, परन्तु भूमि का पूर्ण उपयोग हो सके, इसके लिए सहकारी कृषि लाभकारी रहेगी । इससे समाज की रक्षा भी होगी और लोग जीवन धारण भी कर सकेंगे । मेरी सम्मति में कृषि क्षेत्र का आदर्श ग्राम-दान होना चाहिये ।

(३)

पिछले कुछ वर्षों से भारत सरकार समाजवाद की दिशा में कुछ निश्चित कदम उठा रही है । उदाहरण के लिए जमींदारी उन्मूलन किया जा रहा है, भूमि सुधार के लिए गम्भीर प्रयत्न हो रहे हैं, जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित की जा रही है, साजाजिक जीवन, जन सहयोग और समाज सेवा के लिए सामुदायिक योजनायें एक बहुत बड़े परीक्षण के रूप में अमल में लायी जा रही हैं । उत्तराधिकार-कर, व्यय-कर और सम्पत्ति कर जैसे नये कर लगाये जा रहे हैं तथा पुराने करों में वृद्धि की जा रही हैं । इनसे देश की न केवल आय बढ़ेगी, अपितु समाजवाद की दिशा में भी हम आगे कदम रखेंगे ।

यह दुःख की बात है कि अब तक सामुदायिक योजनाएँ,

[सम्पादा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विकास की प्रवृत्तियों तथा सम्पन्न वर्ग पर कर आदि जनता में उमंग और उत्साह पैदा करने में तथा नया नेतृत्व लाने में सफल नहीं हुए हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि भारतीय राज्य लोकतंत्री है। यहाँ रूस और चीन की भांति डिक्टेटरशिप की शक्ति का प्रयोग नहीं हो सकता। हमें तो एक मार्ग से ही सफलता मिल सकती है कि लोकतंत्री पद्धति से हम जनता में शक्ति को प्रबुद्ध करें। ग्राम, पंचायत, सहकारी समिति आदि का आधुनिकीकरण करें तथा लोकतंत्रीकरण करें, ताकि स्वयं जनता में उत्साह और स्फूर्ति उत्पन्न हो सकें।

मैं ऐसे समाजवाद में विश्वास नहीं करूंगा, जिसमें मजदूर और किसान क्रान्ति के नेता हों। मैं तो ऐसे सामान्य जन में विश्वास करता हूं जो बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप और आतंक के अपने हित के लिए स्वयं कार्य करे। यह ठीक है कि सरकार का निर्देश और सहयोग तो मिलता ही रहेगा। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं होना चाहिये कि सरकार एकदम बहुत से उद्योग अपने हाथ में ले ले। उसे भी शनैः शनैः उद्योग और व्यापार अपने हाथ में लेने चाहियें।

★

श्री हरिभाऊ उपाध्याय

समाजवाद क्या है? इस प्रश्न का उत्तर यदि साम्यवादी या समाजवादियों के शास्त्रीय रूप में न दे कर संक्षेप में देना चाहूं तो मेरी सम्मति यह है कि जब मनुष्य व्यक्ति से ऊपर उठकर प्रत्येक कार्य को समाज के हित की दृष्टि से देखने और करने लगता है, तब समाजवादी भावना का जन्म होता है, तभी समाजवाद की मूल प्रेरणा मिलती है। उक्त कसौटी देखते हुए भारत में समाजवाद की यदि सच्ची व्याख्या करनी हो तो 'सर्वोदय' शब्द से स्पष्ट हो जाती है, जिसमें व्यक्ति या वर्ग की अपेक्षा समस्त मानवता का हित चरम लक्ष्य होता है। समाजवाद, साम्यवाद या सर्वोदय के शब्दों में या उनके अर्थों में कोई विशेष अन्तर नहीं है। मुख्य अंतर लक्ष्य को प्राप्त करने के साधनों व प्रक्रिया में है। सर्वोदय उन साधनों को स्वीकार नहीं करता, जो साम्यवादी अपनी लक्ष्य-पूर्ति के लिए प्रयोग में लाना चाहते हैं। भारतीय समाजवाद या सर्वोदय में अहिंसा प्रधान तत्त्व है। हिंसा या दूसरे अपवित्र साधनों का उसमें किसी तरह का स्थान नहीं है। इसी एक भेद से भारतीय समाजवाद पश्चिमी साम्यवाद से बिलकुल पृथक हो जाता है। उसकी प्रक्रिया और स्वभाव, प्रवृत्ति आदि सर्वथा बदल जाते हैं।

यह कहा जा सकता है कि कानून भी एक प्रकार का दबाव है, इसलिए मैं उसे निर्दोष व स्वागत-योग्य नहीं मानता, परन्तु आज की परिस्थितियों में, जब मानव इतना उच्च नहीं है कि वह 'स्व' को छोड़कर 'पर, सर्व' अथवा समाज' के हित की दृष्टि से सोच सके, कानून का आश्रय सहन किया जा सकता है। शस्त्र तो प्रत्यक्ष दबाव है। कानून का दबाव अप्रत्यक्ष है। फिर आज तो उसका आश्रय लिए बिना कोई गति नहीं है। मानव के उच्च होने में—अपने संस्कार बदलने में जितना समय लगेगा, उतने समय तक प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। व्यक्ति को अपने 'स्व' के हित या स्वार्थ के भाव से ऐसा सब कुछ करने नहीं दिया जा सकता, जिससे समाज को हानि हो। इसलिए आज तो कानून का आश्रय अपरिहार्य है।

कांग्रेस और सर्वोदय

भारत में कांग्रेसी नेता आज भले ही अपने को सर्वोदयवादी न कहते हों, तथा 'सर्वोदय' शब्द को लक्ष्य न मानकर 'समाजवाद' को लक्ष्य मानते हों, तथापि वे प्रायः सभी सर्वोदय की भावना से अवश्य अनुप्राणित हैं। चिंतन की दृष्टि से अभी कांग्रेसी समाजवादियों से और समाजवादी सर्वोदयवादियों से पीछे हैं। जहां कांग्रेसी नेता हैं, समाजवादी उससे आगे की बात सोचते हैं और सर्वोदयवादी उससे भी आगे जाते हैं। मेरा ऐसा विचार है कि कांग्रेस पहले समाजवाद को ग्रहण करेगी और फिर सर्वोदय को अपना लक्ष्य स्वीकार करेगी, परन्तु इसके लिए आवश्यक यह है कि कांग्रेसी नेता आज देश में प्रचलित अर्थ व्यवस्था पर विशेष आग्रह न करें।

सर्वोदय में सब उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का स्थान नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीयकरण के लिए किसी केन्द्रीय प्रतिनिधि संस्था का होना एक अत्यन्त आवश्यक है, किन्तु सर्वोदय ऐसी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

किसी सत्ताशालिनी केन्द्रीय प्रतिनिधि संस्था को बहुत वांछनीय नहीं मानता। फिर भी आज राष्ट्रीयकरण का विरोध नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज हम मध्य मार्ग में हैं। स्वयं व्यक्ति अपना हित छोड़ने को तैयार नहीं है, परन्तु हमारा लक्ष्य व्यक्ति से समाज की ओर प्रयाण करना है, इसलिए अन्तर्वर्ती काल में राष्ट्रीयकरण को एक सीमा तक स्वीकार करना होगा। जब व्यक्ति 'स्व' के स्थान पर 'सर्व' को प्रमुखता देने लगेगा, तब राष्ट्रीयकरण भी अनावश्यक हो जायगा। तथापि हमें आज भी यह ध्यान तो रखना ही चाहिए कि यदि देश में राष्ट्रीयकरण से डिक्टेटरशिप या अधिनायकवाद कायम होने लगे, तो हमें राष्ट्रीयकरण की दिशा में बहुत तेजी छोड़ देनी होगी, और अपनी गति को धीमा करके चलना होगा।

श्री बालकृष्ण शर्मा 'नवीन'

हिन्दी की 'सम्पदा' नामक आर्थिक विषयों से सम्बद्ध मासिक पत्रिका के सम्पादक भाई कृष्णचन्द्र विद्यालंकार ने कुछ लेखकों से सुक्राती प्रश्न पूछे हैं। उन्होंने मुझे भी यह आदेश दिया है कि मैं उन प्रश्नों का उत्तर दूं। मैं अर्थशास्त्र, समाजवाद शास्त्र अथवा राजनीति शास्त्र का ज्ञाता नहीं हूं। अतः मेरे द्वारा दिये गये उत्तर शास्त्रीय दृष्टि से किसी काम के न होंगे, फिर भी उनके आदेश का पालन करना तो है ही।

उनका पहला प्रश्न है समाजवाद अथवा साम्यवाद क्या है? हिन्दी में समाजवाद अथवा साम्यवाद का शब्द सोशलिज्म अथवा कम्युनिज्म का अनुवाद प्रतीत होता है। मूल सैद्धान्तिक रूप में इन दोनों विचारधाराओं में विशेष अन्तर नहीं है। दोनों, ऋषि कार्लमार्क्स के सिद्धान्तों की शपथ खाते हैं और दोनों का सैद्धान्तिक भवन मार्क्स के पदार्थवादी सिद्धान्त पर खड़ा है। इधर इन दोनों में अन्तर यह हो गया है कि समाजवादी अर्थात् सोशलिस्ट यह मानने लगे हैं कि समाज में साम्य स्थापन करने के लिए कम्युनिस्ट उपायों का अवलम्बन अनावश्यक है। अर्थात् वे यह मानते हैं कि समाजवाद की स्थापना के लिए तथाकथित मजदूरों की तानाशाही (Dictatorship of the Proletariat) की आवश्यकता नहीं है। साम्यवाद जनसत्तात्मक शासन प्रणाली में भी स्थापित किया जा सकता है। कुछ साम्यवादी जैसे क्रिश्चियन सोशलिस्ट और कैथोलिक सोशलिस्ट मार्क्स के पदार्थवादी तत्त्वज्ञान को भी स्वीकार नहीं करते। वे जगत को अप्रतिष्ठ और अनीश्वर नहीं मानते। फिर भी वे अपने आपको समाजवादी इसलिए कहते हैं कि उन्होंने कार्लमार्क्स के आर्थिक सिद्धांतों और तत्त्वज्ञान को अपना लिया है।

अतः यह प्रश्न कि समाजवाद क्या है, विवादास्पद बन जाता है। मोटे रूप में समाज की ऐसी रचना करना, जिसमें आर्थिक शोषण का तिरोधान हो जाय और समाज के व्यक्तियों को अपनी उन्नति के लिए समान अवसर प्राप्त हो सकें, यह समाजवाद है। इस प्रकार के समाज की स्थापना करने के लिए उत्पादन के साधनों और वितरण के साधनों पर समाज का—दूसरे शब्दों में राज्य का नियंत्रण आवश्यक प्रतीत होता है। जब मैं इस धारणा को व्यक्त करता हूँ, तब कृष्णचन्द्र जी के दूसरे प्रश्न का उत्तर भी इसमें समाविष्ट हो जाता है।

उनका दूसरा प्रश्न है—क्या उद्योग और खेती का राष्ट्रीयकरण समाजवाद है? इस समय मैं खेती की बात पर बल नहीं देना चाहता। परन्तु यह स्पष्ट है कि समाजवादी-व्यवस्था में औद्योगिक राष्ट्रीयकरण निहित है। यह सम्भव है कि कुछ दिनों तक उद्योग-धन्धे राष्ट्रीय तत्वावधान में भी चलें और व्यक्तिगत तत्वावधान में भी। परन्तु अन्ततः उद्योगों का राष्ट्रीयकरण अवश्यम्भावी प्रतीत होता है। जहां तक खेती के राष्ट्रीयकरण का सम्बन्ध है, वहां तक मैं यह आवश्यक नहीं मानता कि समाजवादी व्यवस्था के लिए खेती राष्ट्र द्वारा ही संचालित हो। सहयोग समितियों के द्वारा खेतों पर व्यक्तिगत अधिकार बनाये रखते हुए भी खेती की उन्नति सम्भव हो सकती है।

समाजवाद शब्द को छोड़ दें

तीसरा प्रश्न है—भारतवर्ष के लिए किस प्रकार का समाजवाद ग्राह्य हो सकता है? यह प्रश्न बहुत टेढ़ा है। यूरोपीय साम्यवाद के अनेक रूप विकसित हुए हैं। सिंडी-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कैलिज्म, अनारकिज्म, कम्युनिज्म, क्रिश्चियन सोशलिज्म आदि समाज के अनेक रूप हैं। मेरा अनुमान है कि यूरोपीय समाजवाद का कोई भी स्वरूप भारतवर्ष के लिए उपयुक्त नहीं है। भारत को अपने लिए विशेष प्रकार के समाजवाद का निर्माण करना पड़ेगा। मेरा यह भी अनुमान है कि हमें समाजवाद शब्द को छोड़ना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि हम लोग विश्व की आर्थिक विचारधारा में ओतप्रोत हो जाने के लिए समाजवाद शब्द को पकड़े हुए हैं। हमारे देश को गांधी जी तथा सन्त विनोबा ने 'सर्वोदयवाद' का सन्देश दिया है। हमारे देश के विचारकों को यह सोचना है कि हमारी अर्थ-नीति में समाजवाद शब्द का व्यवहार करते जाना कहां तक उचित है। मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी-जल्दी हम समाजवाद के शब्द के मोह को छोड़ दें, उतना ही हमारे लिए वह कल्याणकर होगा। भारतवर्ष यूरोपीय समाजवाद के सिद्धान्तों के बल पर नहीं, किन्तु भारतीय सर्वोदयवाद के बल पर ही अपनी आत्मोपलब्धि कर सकता है।

चौथा प्रश्न यह है कि इस देश में समाजवादी ढांचे की स्थापना करने के लिए सरकार क्या करे? मेरा अनुमान है कि सरकार आजकल जिस दिशा में चरणक्षेप कर रही है, वह उचित है। आर्थिक शोषणहीन समाज की स्थापना के लिए सरकार के द्वारा अनेक कार्य हो रहे हैं। उनमें जहां-तहां परिवर्तन के लिए स्थान है। मोटे रूप में शोषण-विहीन समाज के लिए जो कार्य हो रहे हैं, वे ठीक दिशा के द्योतक हैं।

यह हमें नहीं भूलना चाहिए कि ऋषिवर सन्त विनोबा ने बिना 'समाजवाद' शब्द का प्रयोग किये, जो भूदान-आन्दोलन आरम्भ किया है और अब उन्होंने जिसे ग्रामदान आन्दोलन में परिणत कर दिया है, वह शोषणहीन समाज-व्यवस्था की स्थापना की ओर अत्यन्त क्रान्तिकारी चरण निक्षेप है। देश के युवक इस आन्दोलन में यदि योगदान दे सकें तो निश्चय ही हमारा देश ग्रामदान एवं सम्पत्तिदान के रूप में विश्व को समाजवाद से भी बढ़कर सर्वोदयवाद का संदेश देने में समर्थ हो सकेगा।

★

श्री जैनेन्द्रकुमार

१. समाजवाद में माना जाता है कि उत्पादन के साधनों पर स्वत्व व्यक्ति का न हो कर समाज का होगा।

मेरी सम्मति में स्वत्व समाज 'का' न होकर, समाज 'के लिये' होना चाहिए।

समाज अमूर्त है। यदि व्यक्ति में उसे मूर्त न मानें तो संस्था के रूप में उसे स्टेट (राज्य) में मानते हैं। स्वत्व राज्य का हो, तो यही समाज बन जाता है। उससे सामाजिक आशय पूरा नहीं होता।

२. राष्ट्रीयकरण अर्थात् राज्यी-करण। मेरी समझ में कृषि और उद्योग के राष्ट्रीयकरण से समाजवाद का अभिप्राय सिद्ध नहीं हो जाता।

३. सर्वोदय और समाजवाद में परस्पर समन्वय तब होना संभव है, जब समाज की वह इकाई मौलिक और आधार रूप मानी जाय, जिसको ग्राम-समाज कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में व्यक्तियों का वह समुदाय, जहां सबके हित प्रत्यक्षतः परस्पर अनुबद्ध हों और जो सहज रहन-सहन के माध्यम से एक दूसरे से सहज परिचित हों इकाई है। यह इकाई आसपास पांच हजार बालिग नागरिकों की होगी। इस ग्राम-समाज की निर्वाचित पंचायत में (उत्पादन के) साधनों का स्वत्व निहित माना जाय। अर्थात् राज्य-विकेन्द्रित हो और मूलतः वह ग्राम राज्य हो।

४. आज देश की सरकार जिस दिशा की ओर जा रही है, उससे बुनियादी तौर पर असहमत हूं। उसमें श्रम और श्रमिक की गणना गौण पड़ रही है। योजनाएं बड़ी हैं, जरूरी तौर पर उनके आंकड़े आर्थिक हैं और मशीन से वहां मनुष्य नीचे रह जाता है।

केन्द्री-करण की ओर वृत्ति है और इस कारण बाबूशाही बढ़ती है। मूल उत्पादक का मूल्य घट रहा है।

कुल मिलाकर जिस पद्धति पर सरकार चल रही है, उससे बताने और खाने वाला, करने और उपजाने वाले पर अधिकाधिक भारी होता जाता है। ऐसे विषमता फैलती है और सामाजिक स्तरों और वर्गों के बीच वैमनस्य और भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ती है। बेरोजगारी का जवाब वहां नहीं है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

समाजवाद तब तक स्थापित नहीं हो सकता

—स्पष्टवक्ता

देश के शासकों व नेताओं के सैकड़ों भाषण व सरकार के बीसियों कानून भी समाजवाद स्थापित नहीं कर सकते, जब तक स्पष्टवक्ता द्वारा बताये गये कुछ उपायों पर आप अमल नहीं करेंगे। इस दावे को आप पढ़िये और सोचिये कि क्या यह दावा ठीक नहीं है ?

एक समय था, जब हम स्वराज्य का नारा लगाते थे। स्वराज्य प्राप्ति के बाद वैलफेयर स्टेट या मंगलकारी राज्य का नारा लगाने लगे। फिर आया समाजवादी पद्धति के समाज का नारा और अब तो खालिस समाजवाद का नारा है। कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी तथा अन्य प्रायः सब राजनैतिक दल समाजवाद के नाम से वोट मांगते हैं। जो नया आन्दोलन आरम्भ किया जाता है, उस का उद्देश्य समाजवाद की स्थापना होती है। सरकार और उसके अधिकारी जब कोई बड़ा बांध, बड़ा बिजली घर, लोहे का बड़ा कारखाना या ग्रामोद्योग अथवा सहकारी समिति का प्रारम्भ या उद्घाटन करते हैं, तब भी उसका उद्देश्य समाजवाद के लक्ष्य तक पहुँचना बताया जाता है। समस्त पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य ही समाजवाद को देश में स्थापित करना हो गया दीखता है। परन्तु यह समाजवाद है, क्या इस बारे में अभी तक कोई सर्व-सम्मत निश्चय नहीं हुआ है।

समाजवाद क्या हो ?

कुछ लोगों की सम्मति है कि उत्पत्ति के सब साधनों पर सरकार का अधिकार ही समाजवाद है। यह विचार लोगों के हृदयों में इतना अधिक घर कर गया है कि हर एक राज्य यह प्रयत्न करता है कि अधिक से अधिक उद्योगों व संस्थाओं को सरकर अपने हाथ में कर लें। रोज पार्लमेंट में या विविध राज्यों की असेम्बलियों में किसी न किसी उद्योग के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव कर दिया जाता है। सरकारें एक के बाद एक उद्योग और विभिन्न व्यापारिक संस्थाओं को अपने हाथ में लेती जा रही हैं अथवा लेने का प्रस्ताव कर रही हैं।

परन्तु क्या उद्योगों का राष्ट्रीयकरण ही समाजवाद है ? हमारी निश्चित सम्मति है कि उद्योगों का राष्ट्रीयकरण समाजवाद की दिशा में एक बड़ा कदम अवश्य है, परन्तु स्वयं समाजवाद नहीं है। समाजवाद का मुख्य उद्देश्य श्रेणी-भेद और असमानता को कम करना है। यदि हमने सब उद्योगों को सरकारी उद्योग बना भी दिया परन्तु देश के अन्दर असमानता बढ़ती रही, दो वर्ग अधिकाधिक विकसित होते गये तो वह समाजवाद नहीं होगा। कार्ल मार्क्स ने जिस वर्ग-हीन समाज की स्थापना का संदेश दिया था, वह क्या उद्योगों के राष्ट्रीयकरण से पूरा हो जायेगा ? हमारी सम्मति है—नहीं। वर्ग-हीन समाज की स्थापना के लिए अथवा समाज में ऊंच-नीच का भाव समाप्त करने के लिए एक नयी दृष्टि की आवश्यकता है और उसी के सम्बन्ध में हम यहां कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं।

तीन श्रेणियां

आज हमारे देश में तीन श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी उन लोगों की है जो बहुत अमीर है, बड़े सरकारी नौकर हैं, सार्वजनिक नेता हैं। इन लोगों का रहन-सहन साधारण स्तर से बहुत ऊंचा है। खद्दर पहनने वाले बड़े कांग्रेसी नेता भी इसी दल में हैं। ये लोग विदेशी रहन-सहन के आदी हैं या बन रहे हैं। इनके बच्चे म्युनिसिपल स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे। ये स्वयं और इनके बच्चे मोटरों में घूमने जायेंगे, उनके घरों में नौकर काम करेंगे और साधारण जनता के सम्पर्क से दूर रहेंगे।

दूसरी श्रेणी निम्न मध्यवर्ग की है, जो थोड़ी-बहुत आमदनी से किसी तरह अपनी मान-प्रतिष्ठा की रक्षा करते हुए अपना गुजर करती है। यह श्रेणी अपने से उच्चतर वर्ग को ईर्ष्या की दृष्टि से देखती है, परन्तु अपने से निम्न-तर वर्ग के साथ यह भी मिलना नहीं चाहती। उसकी दृष्टि भी ऊपर की ओर रहती है और इसका प्रयत्न उच्च-

[सम्पादक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वर्ग की नकल करने की ओर रहता है।

तीसरी श्रेणी में देश की आम जनता आती है। जिसमें मजदूर, किसान तथा अधिकांश ग्रामीण जनता आती है।

प्रश्न यह है कि इन तीनों श्रेणियों को क्या हम निकट लाने का प्रयत्न कर रहे हैं? क्या देश की वर्तमान शासन-नीति और सार्वजनिक आन्दोलन की प्रवृत्तियां इस श्रेणी भेद को कम करने की ओर बढ़ रही हैं? हमारी सम्मति में ऐसा नहीं हो रहा। देश में समाजवाद स्थापित करने के लिए कुछ बातों का करना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। इस लेख में कुछ सुझाव देने का प्रयत्न करूंगा।

श्रेणी विहीनता के उपाय

१—ऊंच-नीच का भेद भाव समाप्त करने के लिए सब से अधिक आवश्यक बात यह है कि बच्चों के हृदय से असमानता और ऊंच-नीच का भाव दूर किया जाये। जो बच्चे बड़े खर्चीले स्कूलों में, जहां का जीवन-स्तर बहुत ऊंचा, रहन-सहन विदेशी और भाषा अंग्रेजी होती है, पढ़ते हैं, वे बड़े होकर किसी भी स्थिति में सामान्य जनता के सम्पर्क में आना पसन्द नहीं करेंगे। उनकी दृष्टि में निम्न वर्ग सदा हेय बना रहेगा। उसके साथ-खाने पीने, उठने-बैठने में वे एक प्रकार की हीनता अनुभव करेंगे। पंडित नेहरू ने इसी कोटि के अधिकारियों के लिए कहा था—"सरकारी कर्मचारी भारत के सामान्य-जन के साथ अपना सम्पर्क स्थापित नहीं करते। कोट कालर, व टाई आदि साहबी का पोशाक पहने हुए हम सामान्य-जन के साथ सम्पर्क स्थापित कर भी नहीं सकते। आज सरकारी अधिकारियों और जनता में एक बड़ी भारी खाई खुदी हुई है। जब तक हम अपनी मनोवृत्ति, भाषा और भूषा नहीं बदलते, तब तक सामान्य जनता का हित भी नहीं कर सकते। हमारा साहबी पोशाक हमें जनता से अलग कर देती है। हम बैठने के लिए कुर्सी चाहिये, हम किसानों की चारपाई पर नहीं बैठ सकते।" इस स्थिति के लिए आज के शानदार ऊंचे स्तर के पब्लिक स्कूल ही उत्तरदायी हैं। जब तक अमीर और गरीब के बच्चे एक साथ म्युनिसिपल या सरकारी स्कूलों में एकसा पोशाक पहनते हुए नहीं पढ़ेंगे, तब तक श्रेणी-भेद या ऊंच-नीच की भावना को समाप्त करना सम्भव नहीं है। प्राचीन-काल के गुरुकुलों में अमीर और गरीब के बच्चे एक साथ पढ़ते और गांवों में भीख मांगते थे।

२—आज यद्यपि धन का वितरण सब में समान रूप से नहीं किया जा सकता—उत्तरदायी अधिकारियों, इन्जीनियरों और विशेषज्ञों को अधिक वेतन देने ही पड़ेंगे—धन का महत्व तो कम किया जा सकता है। हमें प्रत्येक ऐसा प्रयत्न करना चाहिए, जिससे समाज में धन की प्रतिष्ठा कम हो, ज्ञान, चरित्र या गुण की प्रतिष्ठा बढ़े। आज जनता में असन्तोष केवल धन की असमानता पर नहीं है। अमीर जब धन का प्रदर्शन करता है, तब हृदय में क्षोभ और क्रोध पैदा होते हैं। एक आदमी अपने घर में बैठकर हलवा पूरी खाये, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, किन्तु जब वह शानदार मोटरों पर बैठकर मेरे कपड़ों पर कीचड़ उछालता हुआ जाता है, तो मैं झुंझला जाता हूं। जब कानून के द्वारा, जो अमीरों ने बनाया है, एक आदमी ५०—१०० रुपया देकर छूट जाता है और और मुझे वही अपराध करने पर जेल भोगनी पड़ती है, तब मुझे क्रोध आता है। जब एक अनपढ़ या मामूली पढ़ा-लिखा किसी विद्वत्-सभा का सभापति होता है तो मुझे क्षोभ होता है। जब मैं कांग्रेस के अधिवेशन में मुख्य पंडाल से बहुत दूर टांगे पर से उतरने के लिए विवश कर दिया जाता हूं और ५०—१०० रुपया देकर स्वागत समिति का सदस्य या सरकारी मिनिस्टर मोटरों पर पंडाल तक पहुंचने के लिए हम पर धूल उड़ाता हुआ चला जाता है, तो मुझे कांग्रेस के 'समाजवादी-प्रस्ताव' धोखे की टट्टी मालूम पड़ते हैं। हमारा प्रयत्न यह होना चाहिए कि कानून और व्यवहार के द्वारा कोई व्यक्ति अपने धन का विशेष प्रदर्शन न कर सके अथवा धन के कारण विशेष प्रतिष्ठा या सम्मान न प्राप्त कर सके। तभी सच्चा समाजवाद स्थापित करने की दिशा में प्रगति हो सकती है। तभी साधारण जनता को यह अनुभव हो सकता है कि समाज में से श्रेणी-भेद कम हो रहा है।

३—धन के ऐसे प्रदर्शन पर कानून के द्वारा रोक लगा देनी चाहिए, जो अमीर और गरीब की असमानता

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

को बहुत स्पष्ट घोषित करती है। एक अमीर विवाह के अवसर पर हजारों बत्तियों की जगमगाहट करता है। क्या यह नहीं हो सकता कि सरकार कानून बनाकर बिजली की जगमगाहट को सीमित कर दें? जाये अर्थात् ४०० या ५०० बत्तियों से अधिक कोई जला न सके, अथवा एक नियत संख्या से अधिक बराती, बाजे वालों या मोटरों का प्रयोग नहीं कर सके तो वैभव का प्रदर्शन कुछ कम हो जायेगा जो सामान्य जन के हृदय में घोर क्षोभ उत्पन्न करता है। यदि कोई दहेज देता है तो अपनी लड़की को जितना चाहे दे, परन्तु उसका प्रदर्शन जनता में न करे। किसी के बैंक में दस लाख रुपये पड़े हों तो मुझे नहीं खलते। लेकिन जब वह उनका प्रयोग अपने को ऊंचा दिखाने या अपने वैभव प्रदर्शित करने के लिए करता है, तो मेरे हृदय में विद्वेष की अग्नि जलने लगती है। इस दृष्टि से रेल गाड़ियों में पहले, दूसरे और तीसरे दर्जे का भेद भी समाप्त करना होगा। अमीर लोग हवाई जहाजों में जा सकते हैं, पर मेरे सामने 'एयर कन्डीशन्ड' फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठकर वे थर्डक्लास में बैठने की जगह तलाश करने वाले मुझे चिढ़ावें, यह अधिकार मैं उन्हें नहीं देना चाहूँगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप फिलहाल आमदनी की समानता पर जोर मत दीजिये।। वह सम्भव भी नहीं है। रूस जैसे देश में चालीस वर्ष के शासन के बाद भी आज एक और २०० गुण का अन्तर विद्यमान है। आखिर एक इंजीनियर को उसके विशेष गुणों के कारण आप अधिक वेतन देंगे ही, इसलिए आमदनी की समानता पर आग्रह न करते हुए भी हम वैभव के उस प्रदर्शन पर रोक लगा सकते हैं, जो हमारे हृदय में असन्तोष और विद्वेष, घृणा और क्रोध उत्पन्न करता है। सम्पत्ति रूपी सर्प को मत मारिए, परन्तु उसके विष को—अपनी उच्चता के प्रदर्शन को निकाल दीजिए। धन अपने आप में बुरी चीज नहीं है, लेकिन समाज में जब वह अनुचित प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है तो वह समाज के लिए घातक हो जाता है। उसके विष को नष्ट करने की जरूरत है। सच्चे समाजवाद की स्थापना के लिये ये उपाय रामबाण सिद्ध होंगे, इसमें मुझे सन्देह नहीं है।

"पाञ्चजन्य"
दीपावली विशेषांक में पढ़िए

★ विद्वानों के ज्ञानवर्धक लेख

★ रोचक तथा हृदयस्पर्शी कहानियां

★ ओजस्वी तथा भावपूर्ण कविताएं

★ व्यंग-चित्र, एकांकी और सूक्तियां

आर्ट पेपर पर बहुरंगा मुख-पृष्ठ अंक का विशेष आकर्षण रहेगा।

आकार २०"×२६"×$\frac{१}{८}$ पृष्ठ संख्या ७२ मूल्य : आठ आना

[पाञ्चजन्य के विशेषांक हाथों हाथ बिकते हैं, अतः अभिकर्ता तथा पाठक अपनी प्रतियां अभी मंगा लें जिससे ऐसा न हो कि बाद में अंक प्राप्त न हो सके]

व्यवस्थापक 'पांचजन्य,' गौतम बुद्ध मार्ग, लखनऊ

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विश्व के महान् साम्यवादी नेता

रूसी कम्यूनिस्ट पार्टी के प्रमुखतम नेता

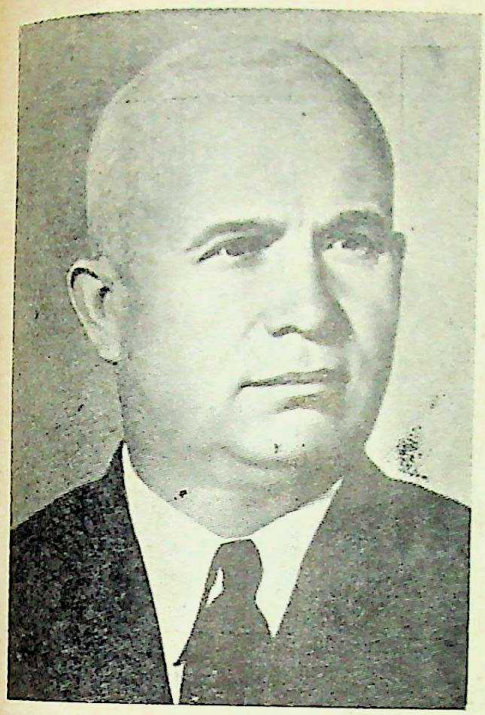

श्री ख्रुश्चेव

यूगोस्लेविया के राष्ट्रपति

मार्शल टीटो

चीन के राष्ट्रपति

श्री माओ त्से तुंग

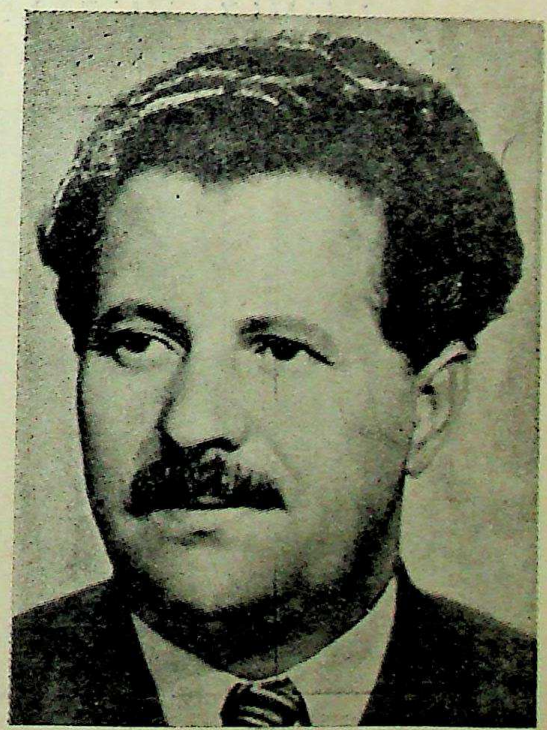

बल्गेरिया के प्रधानमंत्री श्री एण्टन यूगोव

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रजासमाजवादी दल के संस्थापक

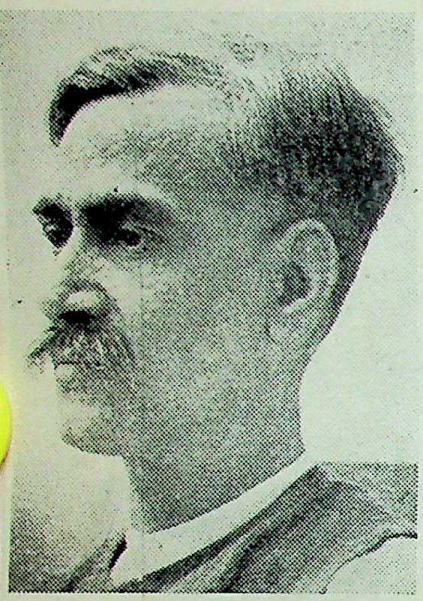

आचार्य नरेन्द्र देव

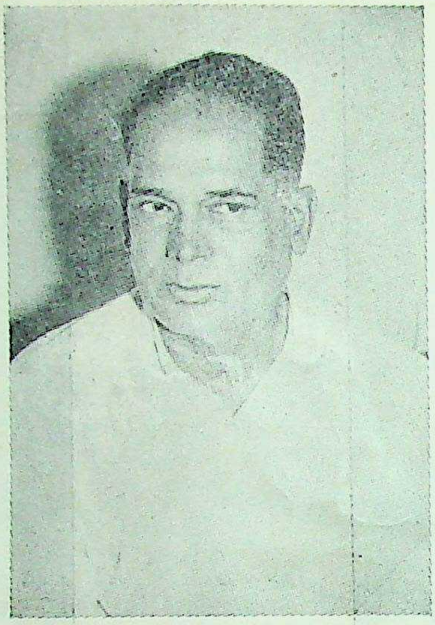

श्री जयप्रकाश नारायण

आचार्य कृपलानी

भारतीय साम्यवादी दल के नेता

साम्यवादी दल के अध्यक्ष

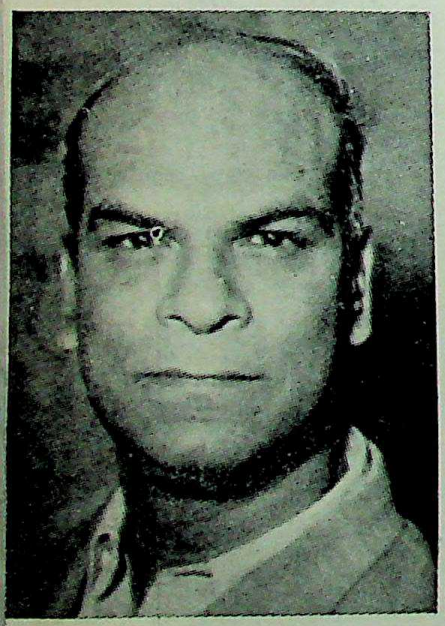

श्री अजय घोष

केरल-राज्य के मुख्य मंत्री

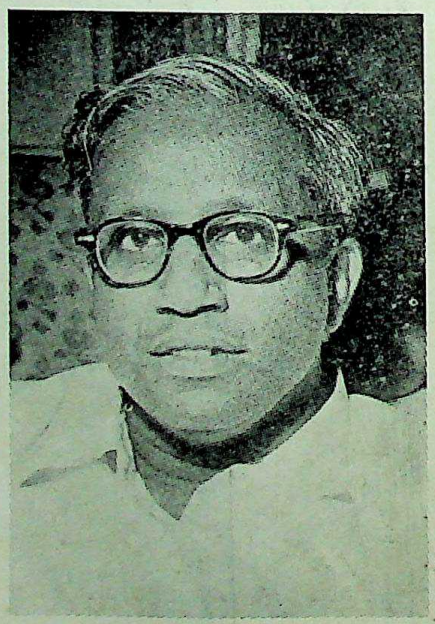

श्रीनम्बूद्रि पाद

साम्यवादी दल के मंत्री

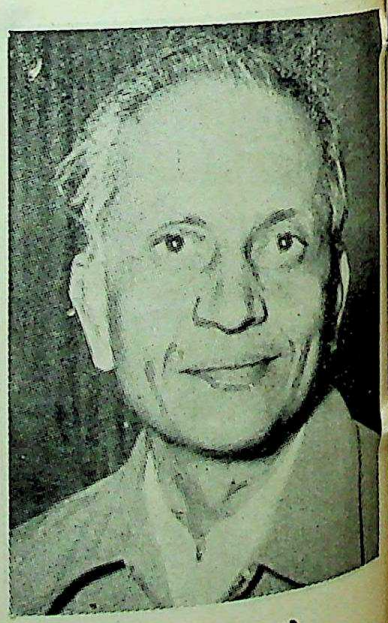

श्री ए. डांगे

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मध्यभारत और राजस्थान की

समृद्धि और सम्पन्नता के लिए चम्बल

१४,००,००० एकड़ भूमि को सिंचित करने के लिए ४७५००० टन अतिरिक्त अन्न के उत्पादन और २,१०,००० किलोवाट बिजली पैदा करके २०० वर्ग मील के विस्तृत क्षेत्र में बिजली को सुलभ करने के लिए चम्बल-योजना बनाई गई है। इस पर ७७.१५ करोड़ रु० व्यय होगा। इनसे मध्य-भारत व राजस्थान सम्पन्नताव समृद्धि प्राप्त करेंगे।

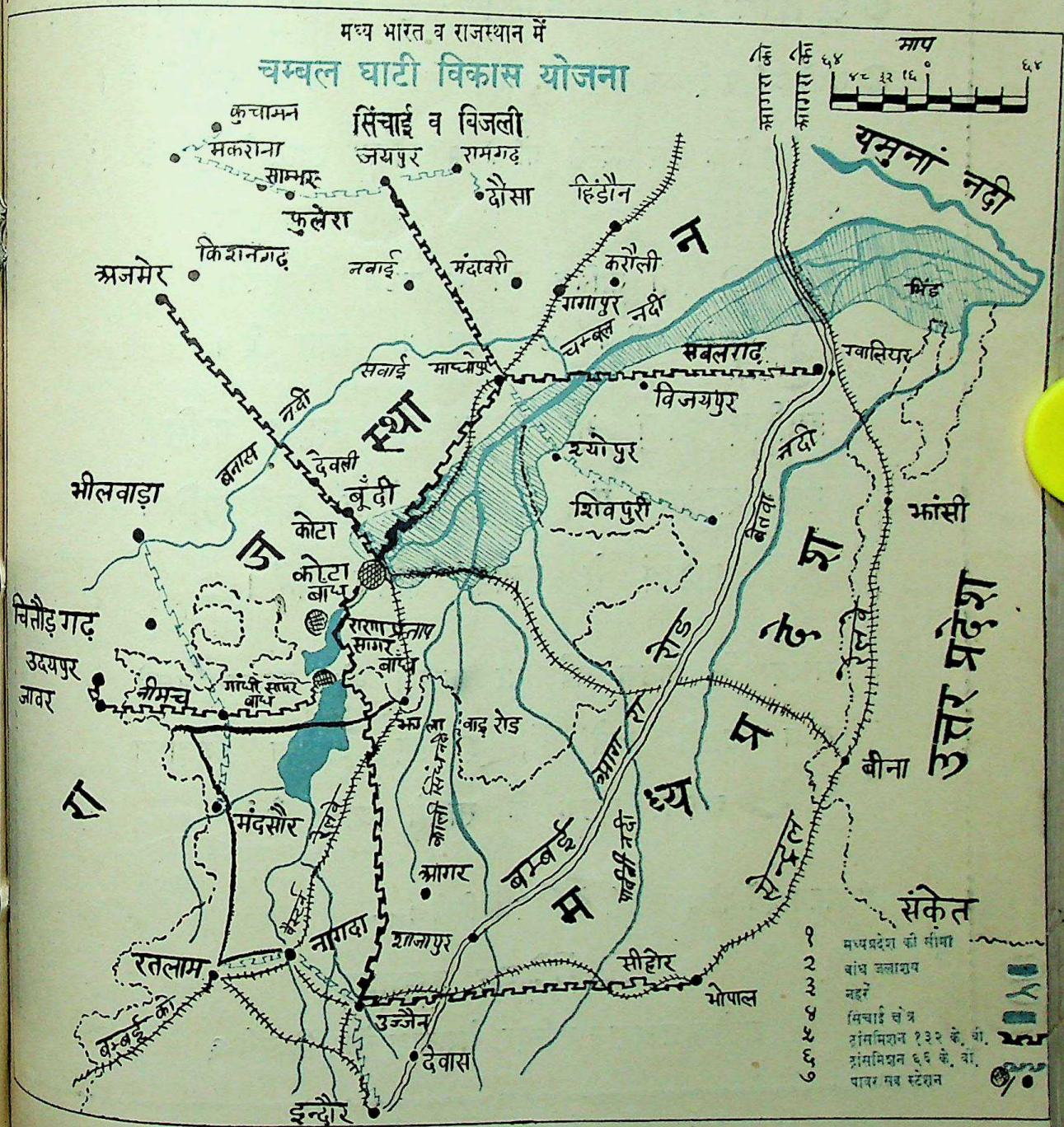

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार क्या कहते हैं ?

भारतीय समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार की वार्षिक रिपोर्ट के कुछ अंक देखिये :—

- ३१ दिसम्बर ५६ को विभिन्न भाषाओं के कुल ६५७४ पत्र प्रकाशित हो रहे थे।
- सबसे अधिक दैनिक, साप्ताहिक और पाक्षिक हिन्दी में प्रकाशित होते हैं।
- अंग्रेजी पत्रों के बाद हिन्दी पत्रों के पाठकों का स्थान है। उनके १६ लाख पाठक हैं।
- हिन्दी मासिक पत्रों के पाठक की संख्या सबसे अधिक ७ लाख ५० हजार है।

इसलिए आप भी हिन्दी के उत्कृष्ट मासिक पत्र सम्पदा में विज्ञापन देकर अधिकाधिक पाठकों से सम्पर्क कायम करें।

सम्पदा के पाठक वर्ष भर फाइल को पढ़कर उससे लाभ उठाते रहते हैं, इसलिए आपका विज्ञापन बारबार पाठक के सामने आता है।

विज्ञापन दरों की जानकारी के लिए लिखिये :—

—मैनेजर सम्पदा

अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिल्ली-६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

76398

वैदिक समाजवाद

श्री प्रियव्रत वेदवाचस्पति

आज की पूंजीवादी समाज-व्यवस्था के कारण सभी देशों की जनता के बहुत बड़े भाग को अभाव और गरीबी का जीवन बिताना होता है। यदि इससे मुक्त होना है तो समाज की इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, उसके स्थान पर समाज की कोई दूसरी व्यवस्था बनानी होगी और समाज का संगठन किसी दूसरे आधार पर करना होगा। जर्मनी के महान् विचारक कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद के विरुद्ध आवाज उठायी और साम्यवाद का विचार संसार को दिया। रूस ने इसी विचार को व्यवहार में परिणत कर दिया। साम्यवादी पूंजीवाद की बुराइयों का प्रतिकार एकमात्र समाजवादी व्यवस्था की स्थापना में मानते हैं।

वर्णाश्रम-वैदिक समाज-व्यवस्था

वैदिक धर्म भी समाज की एक व्यवस्था बताता है। उसमें पूंजीवाद और साम्यवाद के दोष तो नहीं आते, परन्तु दोनों के गुण आ जाते हैं। वेद की समाज-व्यवस्था का नाम 'वर्णाश्रम-व्यवस्था' है। साम्यवाद कहता है कि अभाव और गरीबी के कारण किसी को कष्ट नहीं मिलना चाहिये। वेद भी कहता है कि निश्चय ही परमात्मा ने भूख को मृत्यु का साधन नहीं बनाया है। (न वा उ देवाः क्षुधमिद्वधं ददुः। ऋग् १०.११७.१) वेद में राज्य के लिए यह आवश्यक बताया है कि जनता को अन्न, वस्त्र, मकान, चिकित्सा और शिक्षा की सुविधाएँ अवश्य मिलनी चाहियें। ये जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं।

पूंजीवाद का सबसे बड़ा दोष यह है कि उसमें धन का सर्वोपरि महत्त्व माना जाता है। वह व्यवस्था मनुष्य को लोभी और संचयशील बना देती है। 'वर्णाश्रम-व्यवस्था' में धन का स्थान बहुत कम महत्त्व का है। ज्ञानी, तपस्वी, ब्राह्मण का सम्मान राजा या धनी से अधिक होता है। वेद धन-सम्पत्ति में लिप्त न होकर त्यागमय-जीवनका उपदेश देता है। (तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। यजु. ४०.१)। वर्णाश्रम व्यवस्था में दान पर बहुत बल दिया गया है। वेद में दान के सम्बन्ध में सूक्त आते हैं, जिनमें बड़े कवितामय ढंग में उपदेश दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी धन-सम्पत्ति का दूसरे मनुष्यों के कल्याण के लिये दान करते रहना चाहिये। अथर्ववेद में एक जगह कहा गया है कि "हे मनुष्य! तुम सौ हाथों से धन कमाओ और हजारों हाथों से उसका दान करो।"

वेद हमें उपदेश देता है कि हम जो कुछ कमायें, स्वार्थी बन कर स्वयं न खा लें, किन्तु दूसरों के साथ मिलकर धन-सम्पत्ति का उपभोग करना चाहिये। वेद कहता है कि तुम्हारे पीने का स्थान समान हो, तुम्हारा अन्न का सेवन मिल कर हो। (समानी प्रपा सह वो अन्न भागः)। जो व्यक्ति अकेला खाता है, वह भोजन नहीं, पाप खाता है। (केवलाघो भवति केवलादी। ऋग् १०.११७.६)।

हमारे धार्मिक शास्त्रों में पांच यमों को मानव-जीवन के लिये आवश्यक बताया गया है। इन पांच यमों में एक यम 'अपरिग्रह' अर्थात् सम्पत्ति और सामग्री का कम से कम संग्रह है। वैदिक वर्ण आश्रम-व्यवस्था के अनुसार

हमारे यहां जीवन नाशक स्पर्धा की प्रणाली नहीं रही। हर एक अपना धंधा या व्यवसाय करता और नियमित मजदूरी लेता था। यह बात नहीं थी कि हमें यंत्रोंका आविष्कार करना नहीं आता था, परन्तु हमारे बाप दादा जानते थे कि अगर हमने इन चीजों में अपना दिल लगाया तो हम गुलाम बन जायेंगे और अपनी नैतिक शक्ति खो बैठेंगे। इसलिए उन्होंने काफी विचार करने के बाद निश्चय किया कि हमें केवल वही करना चाहिए जो हम अपने हाथ पैरों से कर सकते हैं। उन्होंने देखा कि हमारा सच्चा सुख और स्वास्थ्य अपने हाथ पैरों को ठीक तरह काम में लेने में है।.....साधारण लोग स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करके अपना खेती का धंधा करते थे। वे सच्चे राज्य का उपयोग करते थे।

—महात्मा गांधी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

केवल वैश्य को ही धन सम्पत्ति कमाने का काम सौंपा गया है, परन्तु वह भी गृहस्थाश्रम के केवल २५ वर्ष । इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम में धन-सम्पत्ति कमाने का काम छोड़ देना पड़ता है। शेष ब्राह्मणादि तीन वर्णों के लोग धन-सम्पत्ति कमाने के पीछे जाते ही नहीं। इन ब्राह्मणादि तीनों वर्णों के लोगों को गृहस्थाश्रम में जनता या राज्य की ओर दक्षिणा के रूप में जो थोड़ी-बहुत धन-सम्पत्ति मिलती थी, वानप्रस्थ-आश्रम में जाकर वे उसे कमाना भी बंद कर देते थे। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास आश्रमों में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को न्यूनतम बना लेता है और गृहस्थ जनता से मिलने वाली भिक्षा और दान पर अपना निर्वाह करता है। वर्णाश्रम-व्यवस्था की पद्धति में ढल कर अपना जीवन बिताने वाले लोगों की धन के सम्बन्ध में

"समाजवाद केवल पैसे की प्रधानता के खिलाफ बगावत है, किन्तु जिस व्यवस्था में पैसे को प्रधानता नहीं दी गई, वहां इस बगावत की क्या जरूरत रह जाती है ?"
—डा० पट्टाभिसीतारम्मैया

मनोवृत्ति पूंजीवादी पद्धति में मिलने वाले लोगों से सर्वथा भिन्न प्रकार की हो जाती है।

धन का महत्त्व अधिक नहीं

वस्तुतः धन का महत्त्व वर्ण व्यवस्था में बहुत कम कर दिया गया है। ब्राह्मण के लिए तो धन का संग्रह पाप माना गया है। वही मंत्री बन कर देश की शासन-नीति निर्धारित करेंगे और आर्य चाणक्य की तरह विस्तृत साम्राज्य के मंत्री होते हुए भी फूस की झोंपड़ी में रहा करेंगे। राजा या क्षत्रीय को भी धन-संग्रह की सलाह नहीं दी गयी। वैश्य रुपया कमाता है, परन्तु सारे राष्ट्र के पालन पोषण की जिम्मेदारी भी उसी पर है। देश में शक्ति-सन्तुलन का आधार धन नहीं रहेगा। त्यागी ब्राह्मण को सम्मान मिलेगा, क्षत्रिय को सत्ता मिलेगी और वैश्य को धन मिलेगा। आज के पूंजीवादी समाज की तरह केवल धन से कोई अधिकार और सत्ता नहीं पा सकेगा। इस प्रकार तीनों शक्तियों का सन्तुलन करके पूंजीवाद के उस भारी दोष से समाज की रक्षा कर ली जाती है, जिसमें धन के कारण सम्मान, सत्ता और सम्पत्ति एक व्यक्ति के हाथ में केन्द्रित हो जाती है। जो लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, उन्हें दण्डित करने की व्यवस्था भी वेद बताता है। (सम्राट् अदित्सन्तं दापयति। यजु ९.२४)

प्राचीन वर्ण-व्यवस्था की विशेषता यह है कि उसका आधार जन्म नहीं है। पौराणिक वर्ण-व्यवस्था की तरह से वेद जातिगत वर्ण-व्यवस्था को नहीं मानता। पूंजीवाद में पुत्र को पिता की सम्पत्ति मिलती है, चाहे वह योग्य हो या अयोग्य हो, उसकी सम्पत्ति छीनी नहीं जा सकती। वैदिक वर्ण-व्यवस्था इस सिद्धान्त को नहीं मानती। इस व्यवस्था में सम्पत्ति का अधिकार भी जन्म के आधार पर न मान कर सदुपयोग के आधार पर माना जाता है। ऋषि दयानन्द तो गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार सन्तानों के परिवर्तन की भी सलाह देते हैं। वैश्य का ऐसा पुत्र जिसमें उद्योग या व्यापार की बुद्धि नहीं है, दूसरे वर्ण के व्यक्ति को दे दिया जायगा। फलतः पैतृक-सम्पत्ति का अधिकारी भी नहीं रहेगा।

कम्युनिस्ट लोग केवल श्रम को सम्पत्ति के अधिकार का आधार मानते हैं, वह जमीन और कारखाने पर किसान और मजदूर का अधिकार मानते हैं, लेकिन वैदिक समाजवाद ऐसा सदुपयोग के आधार पर मानता है। एक किसान या मजदूर को भी अपनी सम्पत्ति का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता।

पूंजीवाद की तरह वैदिक-समाजवाद भी सम्पत्ति के व्यक्तिगत स्वामित्व को स्वीकार करता है किन्तु सम्पत्ति का यह व्यक्तिगत स्वामित्व निर्बाध और निष्प्रतिबन्ध नहीं है। पूंजीवाद में यह व्यक्तिगत स्वामित्व निर्बाध और निष्प्रतिबन्ध है; और इसके निर्बाध और निष्प्रतिबन्ध होने के कारण पूंजीवाद पर आधारित आज की समाज-व्यवस्था के सब बुरे परिणाम हो रहे हैं। वैदिक प्रतिबन्धों के कारण व्यक्ति अपनी सम्पत्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा, उसका राष्ट्र के हित के लिए सदुपयोग करेगा।

साम्यवादी सम्पत्ति का बलात् अपहरण करता है। किन्तु वैदिक व्यवस्था में त्याग का आध्यात्मिक उपदेश दिया गया है। त्याग से उसके आत्मा और चरित्र ऊंचे होते हैं। वह व्रत के कारण सम्पत्ति का सदुपयोग करता

(शेष पृष्ठ ६१६ पर)

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

एक गंभीर आक्षेप का समाधान

भारतीय समाजवाद में वैयक्तिक स्वातन्त्र्य

श्री रामनरेश लाल

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के साथ भारत भूमि पर भी समाजवाद को उतारने का क्रम प्रारम्भ हो गया है। संक्रामक युग आ पहुंचा है। एक व्यवस्था उखड़ रही है और दूसरी को रोपने का प्रयत्न किया जा रहा है। विगत के प्रति मोह और आगत के प्रति उल्लास का यह कठिन अवसर है; और इसलिये अभी समाजवाद रचना का जो स्वप्न हमने अपने सामने रचा है, उसने साथ साथ अनेक आलोचनाओं को भी आमंत्रित किया है। समाजवाद रोटी देता है, परन्तु इसके बदले में व्यक्ति की स्वतन्त्र आत्मा का दुःसह दासत्व चाहता है। इसलिये समाजवाद और पूंजीवाद का सौदा वस्तुतः अधिक रोटी और व्यक्ति की आत्मा की अत्यधिक स्वतन्त्रता का सौदा है।

नीचे की पंक्तियों में एक मामूली अर्थशास्त्र के विद्यार्थी की सरल जिज्ञासा लिये, प्रचलित विचारों के आधार पर मैंने यह जताने और खोजने का एक तुच्छ प्रयास भर किया है कि भारतीय समाजवाद में, जो प्रजातंत्रात्मक सिद्धान्तों पर आधारित अपने ढंग का एक अनुपम समाजवाद होने जा रहा है—उसमें व्यक्ति की स्वतन्त्र प्रवृत्तियों को कहां तक आदर मिल सकेगा और कहां तक इस दृष्टि से समाजवाद हमारे लिये उपयुक्त होगा। युग युग से स्वतन्त्र विचारों, चिन्तनों एवं प्रवृत्तियों के पोषक भारत देश के लिये यह कितना उत्सुक होगा? तथा क्या आवेश में समाजवाद को अपनाने के नाम पर सचमुच हम अपनी स्वतंत्र प्रवृत्तियों को दफनाने जा रहे हैं?

विरोधियों के तर्क

विरोधियों के तर्क संक्षेप में इस प्रकार रखे जा सकते हैं—समाजवाद व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का दुश्मन है और इसकी राह गुलामी की राह है, क्योंकि प्रथमतः समाजवाद में समाज की आर्थिक क्रियाएं एक केन्द्रीय योजना आयोग (Planning Commission) द्वारा निर्धारित की जाती हैं और इस प्रकार योजनाकार, एक निश्चित उद्देश्य के निमित्त राष्ट्र के आर्थिक क्रियाओं (उत्पादन, विनिमय,

लेखक

वितरण और उपभोग) सम्बन्धी अपनी नीतियों एवं अभिरुचियों को सामान्य जनता की कार्यरुचि पर हावी कर देते हैं। तब इन थोड़े से योजनाकारों की प्रवृत्तियों के इशारों पर समूचे राष्ट्र को चलना पड़ता है। परिणामतः व्यक्तिगत जीवन में लोगों की आर्थिक स्वतन्त्रता छिन जाती है। फिर योजनाकारों द्वारा ज्यों ही उत्पादन के विभिन्न लक्ष्य एवं प्रकार निश्चित किये जाएंगे, त्योंही यह भी निश्चित हो जाना आवश्यक हो जाता है कि समाज के श्रमिक (समाजवाद में सभी को श्रमिक बनना पड़ेगा; दूसरे के श्रम पर जीने का अधिकार इसमें नहीं मिल सकता) कब, कहां, कितना और किन शर्तों पर काम करेंगे। इस प्रकार श्रमिक की अपनी इच्छा कुचल दी जाएगी। अब चूंकि उत्पादन के लक्ष्य योजनाकार निश्चित करते हैं, इसलिये उपभोग की मात्रा और उसके प्रकारों का निर्धारण स्वतः आवश्यक हो जाता है, जिसे केन्द्रीय योजना समिति ही करती है। तब परिणामतः अपने उपभोग की मात्रा और प्रकार को निश्चित करने के लिये भी व्यक्ति स्वतन्त्र नहीं रहने पाता। इस प्रकार समाज का आर्थिक जीवन केन्द्रीय

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सरकार की सत्ता के कारागार में पूर्ण रूपेण बन्दी हो जाता है।

तर्क आगे चलता है कि समाजवाद के अन्तर्गत सामाजिक जीवन में व्यक्ति की नागरिक स्वतन्त्रता भी छिन जाती है। कारण कि समाजवाद में (जिसमें राष्ट्रीयकरण का जोर होता है) व्यक्तियों के जीवन पर सरकार इस प्रकार हावी हो जाती है कि मनमाने ढंग से आराम करने, बोलने, सोचने, सभा सोसायटी करने, व्याख्यान देने तथा लिखने आदि तक पर सरकार का नियंत्रण एवं अंकुश लग जाता है और इसलिए स्वतन्त्र विकास की प्रवृत्तियां दब जाती हैं। नौकरशाही के आतंक के नीचे, सरकारी आफिसरों एवं कर्मचारियों की गुलामी से पीड़ित नागरिक जीवन को पंगु बनाकर, सरकार अपनी यंत्रवत पद्धति के पीछे उसे घसीटती चलती है।

आगे चलकर सरकारी सत्ता का आतंक इतना बढ़ जाएगा (क्योंकि अंततोगत्वा जीवन के सभी कार्यों पर सरकारी नियंत्रण हो जाता है) कि फिर तानाशाही का जन्म होगा और परिणामस्वरूप व्यक्ति की राजनैतिक स्वतन्त्रता भी पिस जाएगी विशेषतः इसलिये कि व्यवस्थित सरकार अपने को उखड़ने देना पसन्द नहीं करेगी।

तर्क का उत्तर

देखने में उपर्युक्त तर्क बहुत गम्भीर प्रतीत होते हैं। यदि समाजवाद को अपनाने के लिये हम देश की जनता से मांग करते हैं तो हमें इन प्रश्नों का उत्तर देना होगा और यह सिद्ध करना आवश्यक होगा कि ये तर्क मिथ्या-एवं भ्रामक हैं।

सुविधा के लिये, इस प्रश्न से सम्बन्धित सभी पहलुओं पर विचार रख सकने के उद्देश्य से अपने अध्ययन को हम निम्नलिखित दो भागों में विभाजित कर लेते हैं:

१—आर्थिक स्वतन्त्रका का प्रश्न,

२—नागरिक स्वतन्त्रता का अपहरण,

आर्थिक स्वतन्त्रता

आर्थिक स्वतन्त्रता के अन्तर्गत हम मुख्यतः तीन बातों का समावेश कर लेते हैं:

क—उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण।

ख—बदलती रुचि, बदलते फैशन, आविष्कारों, नये खोजों के अनुसार उपभोग के वस्तुओं के स्वतन्त्र उत्पादन एवं उपभोग पर रोक।

ग—स्वतन्त्र व्यवसाय में हस्तक्षेप।

क—पूंजीवाद में मांग एवं पूर्ति का स्वतन्त्र खेल कीमत का निर्धारण करता है और इस प्रकार वस्तुओं की उतनी मात्रा का उत्पादन हो जाता है जितने की मांग होती है; क्योंकि जो भी कीमत बाजार में किसी वस्तु की होती है, उस पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर होते हैं, पूर्ति सदैव मांग को पूरा करने के निमित्त क्रियाशील रहती है तो इस व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह हुई कि उपभोक्ता एवं उत्पादक दोनों स्वतन्त्रतापूर्वक उपभोग एवं उत्पादन में संलग्न हैं। फिर भी कुछ अनिर्वचनीय संकेतों से सामान्य कीमत (Normal price) पर मांग और पूर्ति इस प्रकार बराबर हो जाती है कि इस कीमत पर उत्पादन लागत न्यूनतम होती है, उपभोक्ता सबसे सस्ती कीमत पर वस्तु का उपभोग कर पाता है; बिना किसी पूर्व योजना के यह सब स्वतः चलता है स्वतन्त्र ढंग से।

परन्तु समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन की मात्रा का निर्धारण केन्द्रीय योजना, समिति (Central Planning Commission) द्वारा समूचे आर्थिक व्यवस्था के लिये एक अवधि (प्रायः पांच वर्षों) के लिये किया जाता है; चूंकि पूर्ति का निर्धारण इस प्रकार स्थिर कर दिया जाता है और और उसे स्वतन्त्र रूप से बदलने, घटने-बढ़ने का अवसर नहीं मिलता तो मांग को भी मजबूरन पूर्ति के अनुसार चलना पड़ता है। मांग और पूर्ति का स्वतन्त्र खेल बिगड़ जाता है।

इस तर्क के विरुद्ध कही बातों का उल्लेख आवश्यक जान पड़ता है। प्रथम तो यह कि जिस सामान्य कीमत पर मांग और पूर्ति के बराबर होने की कल्पना की गई है वह बिन्दु काल्पनिक बिन्दु है। व्यवहार में कभी भी समाज सामान्य कीमत और उस कीमत पर बराबर हुये मांग और पूर्ति का लाभ नहीं उठा पाता। वास्तविक जीवन में बाजारू कीमत सामान्य कीमत से या तो ऊंची या नीची रहती है। यह इस बात का प्रमाण है कि पूंजीवादी समाज में भी वास्तविक जीवन में पूर्ति या तो वांछित मांग से कम होगी या अधिक, और इसलिये सामान्य कीमत केवल स्वप्न भर रह जाता है। सच पूछिये तो विश्व के पूंजीवादी देशों का अनुभव तो यह है कि कीमत को अपने अनुकूल रखने और लधिक से लधिक लाभ कमाने की लालसा में स्वतन्त्र उत्पादक लाखों करोड़ों रुपये के सामानों को

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

समुद्र में झोंक देते हैं, भले ही दूसरी ओर धरती के लाखों इन्सान उन वस्तुओं के अभाव में दम तोड़ते हों। समाज के इन करोड़ों अभावग्रस्त लोगों के प्राणों एवं समाज के दैवी साधनों के साथ थोड़े से पूंजीपतियों का यह स्वतन्त्र खेल कहां तक ठीक है और कब तक इसे सहन किया जा सकता है—यह सोचने का विषय है।

टिकाऊ सामानों का स्टाक संचित कर के विशेषतः जब उनकी कमी से समाज छटपटा रहा हो, भविष्य में ऊंची कीमत पर वस्तुओं को बेचना भी पूंजीवादी पद्धति की सर्व सम्मान्य घटना है। अवस्था तो यह हो चुकी है कि थोड़े से लोगों की इस घातक प्रवृत्ति का शमन यदि नहीं कर दिया जाता तो कल हमारी सारी योजना और हमारा सारा स्वप्न विनाश के गड्ढे में होगा। वास्तविक जीवन में पूर्ण स्पर्धा की स्थिति किसी पूंजीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत रह भी कहां पाती है कि जो समाज को सामान्य कीमत स्तर (Normal price) का सुख दे सके। पूंजीवादी स्वतन्त्र व्यवस्था अन्ततोगत्वा अपूर्ण स्पर्धा एवं एकाधिकार (Imperfect Competition and Monopoly) में बदल जाती है; और इस प्रकार उत्पादन या पूर्ति की मात्रा एकाधिकारी द्वारा उसके व्यक्तिगत अधिकतम लाभ की दृष्टि से निश्चित की जाती है, चाहे समाज के असंख्य उपभोक्ताओं को उससे कितना भी नुकसान क्यों न हो। तब समाजवाद और पूंजीवाद में अंतर इतना ही रह गया कि जहां समाजवाद में उत्पादन एवं पूर्ति का लक्ष्य चुने हुये अनुभवी कुशल शासकों या विशेषज्ञों द्वारा जन कल्याण की भावना से निर्धारित किया जाता है; वहां पूंजीवाद की तथाकथित स्वतन्त्र आर्थिक व्यवस्था में पूर्ति के लक्ष्य व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से निश्चित किये जाते हैं। आप किस व्यवस्था को अधिक पसंद करेंगे ?

मांग और पूर्ति प्रेरक

परन्तु यहीं पर रुक जाने से काम नहीं चलेगा। औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रगति के युग में, आर्थिक उल्लास के दिनों में जब कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं, प्रायः आवेश में उत्पादक भविष्य की बढ़ती मांग एवं ऊंची उठती कीमत की भ्रामक कल्पना में आवश्यकता से बहुत अधिक वस्तुओं का उत्पादन कर बैठते हैं। परन्तु बढ़ती जाती कीमत की एक सीमा होती है, जिसके पश्चात् और अधिक ऊंची कीमत देने का साहस सामान्य जनता में नहीं रह पाता। मांग घट जाती है या बढ़ नहीं पाती, उत्पादन आवश्यकता से अधिक हो चुका रहता है। उस अवस्था में फिर अवसाद (Deprission) के भयानक और दुःखद चक्कर में समाज को पड़ जाना पड़ता है। आर्थिक जगत् में त्राहि त्राहि मच जाती है, और तब ये पूंजीपति या स्वतन्त्र उपक्रमिक अधिकांश श्रमजीवियों को दूध में पड़े मक्खी की भांति मिलों और कारखानों के बाहर फेंक देते हैं, जिनके पास भूख की भट्टी में, रोजगार की तलाश में तड़प तड़प मर जाने के सिवाय कोई चारा शेष नहीं रह जाता। फिर सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि उन्हें रोजगार और रोटी दिलाने का प्रयत्न करे। व्यापारिक चक्र (Trade Cycle) पूंजीवादी व्यवस्था का ऐसा भयानक कोढ़ है, जिसके उपचार के लिये हमें सरकार की शरण लेनी ही पड़ेगी। पूंजीवादी व्यवस्था उपभोक्ताओं को किस प्रकार की आजादी देती है, जबकि खेतों या मिलों या व्यापार में काम करने वाले मजदूर घर पर एक बेला सूखी रोटी भी निश्चिन्त होकर नहीं खा पाते। पूंजीपतियों, व्यापारियों की सनक को सन्तुष्ट करने के निमित्त सारे समाज के बहुमूल्य उत्पादन के साधनों की, जो विलास सामग्री बनाने के लिए प्रयुक्त की जाती है, कब तक होली जलने दी जा सकती है। इसीलिये अगर समाजवाद के नाम पर हम एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण चाहते हैं, जिसमें उत्पादन के प्रकार एवं उसकी मात्रा थोड़े से लोगों के वैयक्तिक लाभ के आधार पर नहीं, वरन् समाज की आवश्यकता के अनुसार निश्चित की जाये, जिसमें जन जन को रोजगार और रोटी देने का उत्तरदायित्व थोड़े से सम्पन्न एकाधिकारियों के अधिकार से निकल कर जनता द्वारा चुनी हुई सरकार और सरकार द्वारा व्यवस्थित एक ऐसे योजना आयोग के हाथ में चला जाय, जिसके सदस्य दिन रात समाज और देश के आर्थिक भलाई के के लिये सोचते और उपाय रचते हों, तो कोई इसे बुरा क्यों माने ? विशेषतः भारतीय समाजवादी व्यवस्था के लिये तो यह और अधिक श्रेयस्कर प्रतीत होता है, जिसमें योजनाकारों द्वारा आर्थिक विकास को ऊपर से जनता के ऊपर लादा नहीं जायगा, वरन् प्रजातंत्रात्मक पद्धतियों पर टिक कर हमारा आर्थिक विकास एवं सुख धरती पर अंकु-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रित होकर आकाश को छूने का प्रयत्न करेगा। भविष्य को सुन्दर एवं भरापूरा बनाने के लिये वर्तमान उत्पादन की मात्रा पर आरोपित नियंत्रण को हमें हंसते हंसते कबूल करने से एतराज नहीं करना चाहिये।

एक प्रश्न यहां उठ जाता है कि योजनाकार उपभोग के लक्ष्यों के उचित निर्धारण में कहां तक ठीक होंगे? पूंजीवाद में पूर्ण स्पर्धा के अन्तर्गत व्यक्ति की मांग, बाजार की मांग बन कर पूर्ति को अपने आप प्रभावित कर देती है। सारे समाज के लिये एक निश्चित योजना की आवश्यकता नहीं पड़ती। समाजवाद में योजनाकारों के लिये यह असम्भव जान पड़ता है कि वे प्रत्येक व्यक्ति की मांग का विवरण अपने पास रक्खें। परन्तु सच तो यह है कि अर्थशास्त्र एक व्यक्ति की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता भी नहीं। समाज की औसत मांग या पूर्ति का अध्ययन ही वह करता है। इस दृष्टि से यदि मांग को प्रभावित करने वाले मूल कारणों में (जैसे, आय, रुचि, जनसंख्या, आविष्कार आदि) परिवर्तन नहीं होता तो योजनाकार आरम्भिक कुछ त्रुटियों और सुधारों को पार करते हुए अन्ततोगत्वा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की मांग का उचित निर्धारण जन-कल्याण की भावना को रखते हुये कर सकते हैं। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हमारे समाजवाद में पूंजीवादी व्यवस्था की अपेक्षा, थोड़े से धनिकों एवं पूंजीपतियों को छोड़कर उपभोग की मात्रा की दृष्टि से अधिकांश लोगों को अधिक संतोष होगा।

लक्ष्य का उपयोजन

ब—अब प्रश्न यह आता है कि यदि मांग और पूर्ति के मूल कारणों में परिवर्तन हो जाय तो योजना आयोग कितनी जल्दी कहां तक अपने लक्ष्यों में उपयोजन (Adjustment) एवं परिवर्तन कर सकता है।

जहां तक बदलती रुचियों, फैशनों एवं नये आविष्कारों का प्रश्न है, पूंजीवादी व्यवस्था के पक्ष में एक तर्क उठता है कि चूंकि इस व्यवस्था में स्पर्धा (Competition) का जोर होता है; उत्पादक अतिशीघ्र अपने उत्पादन को बदलती मांगों के अनुरूप ढालने को उतावले हो जाते हैं, जिससे कि उनके हाथ से बाजार चला न जाय, और इसलिये बदलती रुचियों, फैशनों एवं आविष्कारों को सन्तुष्ट करने के हेतु शीघ्रातिशीघ्र बाजार में नये-नये वस्तुओं की बाढ़ आ जाती है। जनता को अपनी पसन्द की नयी-नयी वस्तुएं मिलती हैं। समाजवाद में चूंकि उत्पादन की सारी जिम्मेदारी योजना आयोग के सुझावों पर अवलम्बित है और उसमें स्पर्धा की भावना नहीं है, इसलिये जनता को इस प्रकार नये-नये पदार्थों के उपयोग की वैसी स्वतन्त्रता कम से कम अल्प अवधि में तो मिल ही नहीं सकेगी। योजना आयोग जानबूझ कर भी इन परिवर्तनों के लिये उतावला शायद न हो क्योंकि इन वस्तुओं के उत्पादन के लिये नयी पूंजी एवं नये प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके लिये एकाएक प्रबन्ध करना सम्भव नहीं होगा।

इस प्रश्न पर दो पहलुओं से विचार करना है। प्रथम यह कि योजनाकार परिवर्तन जल्दी नहीं चाहते और द्वितीय वे परिवर्तन चाहते हैं। हम देखेंगे कि योजनाकार यदि परिवर्तन के पक्ष में नहीं हैं तो इसका एक ही कारण हो सकता है कि वे इन नयी वस्तुओं के उत्पादन की अपेक्षा अन्य दूसरी ऐसी वस्तुओं के उत्पादन पर अधिक जोर देते होंगे जिनका उत्पादन उनकी दृष्टि में अधिक श्रेयस्कर है। उदाहरण के लिये आज हमारे देश में योजना आयोग उपभोग की नयी वस्तुओं के उत्पादन पर बिल्कुल जोर न देकर आधारभूत उद्योगों के उत्पादन में जी जान से संलग्न है, जिनके बल पर भविष्य में मनमाने ढंग से मनचाही उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन हम कर सकेंगे। यदि देश को आर्थिक बल एवं प्रौढ़ता प्रदान करने के लिये योजना आयोग इस प्रकार उपभोक्ताओं की बदलती, पनपती चाहों एवं रुचियों पर अंकुश रखती है तो उसे हमारे क्रोध नहीं, वरन् प्रशंसा का पात्र बनना चाहिए। आयोग को उपयोग की वैयक्तिक स्वतन्त्रता पर अंकुश रखना पड़ता है, ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार कि एक परिवार में, परिवार की भलाई के निमित्त परिवार के स्वामी को परिवार के सदस्यों के फजूल खर्ची एवं व्यर्थ के उपभोगों पर नियंत्रण रखना प्रायः आवश्यक हो जाता है। अब दूसरे पहलू के अनुसार यदि आयोग परिवर्तन चाहता है और उसके लिये समर्थ है तो कोई कारण नहीं कि ये परिवर्तन न किये जायेंगे। हां अन्तर इतना अवश्य है कि पूंजीवादी व्यवस्था में जहां इन परिवर्तनों का प्रवेश बिना

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

किसी योजना के, वैयक्तिक उपक्रमिकों द्वारा इस प्रकार होता है कि उससे आर्थिक जगत में एक उथल-पुथल मच जाती है, वहां ये परिवर्तन समाजवादी व्यवस्था में सहूलियत के साथ एक योजना के अनुसार शांतिपूर्ण ढंग से होंगे।

इस सिलसिले में एक प्रश्न यह उठता है कि पूंजीवादी व्यवस्था स्पर्धा, खोजों एवं आविष्कारों को प्रोत्साहन देती है, जब कि समाजवाद में स्पर्धा एवं प्रतिस्पर्धा की कमी से नये आविष्कारों एवं खोजों की गति बहुत मन्द पड़ जाएगी। परन्तु यहां हमें समझ लेना है कि कोयलों, तेलों आदि की शक्तियों से बड़ी दूर अणुशक्ति के इस युग में नये-नये खोजों एवं अनुसन्धानों का पैमाना इतना विशाल हो गया है कि वह वैयक्तिक उपक्रमिक के पाकेट से बड़ी दूर की बात हो गई है। इसके लिये हर देश की सरकार को इतना दायित्व इस ओर आगे के युग में निभाना है और इसके लिये पूंजीवाद की अपेक्षा समाजवाद पर्याप्त सशक्त सिद्ध होगा।

स—स्वतन्त्र व्यवसाय

आर्थिक दासता के नाम पर समाजवादी व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा आरोप यह लगाया जाता है कि इसमें व्यक्ति अपने व्यवसाय का चुनाव स्वतन्त्र रूप से नहीं कर पाता। योजना द्वारा आयोजित व्यावसायिक क्षेत्रों में बाध्य होकर लोगों को काम करना पड़ता है और सरकारी नियंत्रण में मशीन के इस ऐसे पुर्जे की तरह खटना पड़ता है, जिसका अपना कोई मन, पसन्द नहीं होता।

यह आरोप भी भ्रमपूर्ण है। विशेषतः हमारे देश में तो यह बिल्कुल ही लागू नहीं होता, जहां हम प्रजातन्त्र की बुनियाद पर समाजवाद का भवन निर्मित करना चाहते हैं। इसमें दो मत नहीं हैं कि उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में, योजना आयोग एक व्यापक एवं मोटी दृष्टि से विभिन्न प्रकार के श्रमिकों, कर्मचारियों, एवं प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकताओं का निर्धारण करेगा, परन्तु यह सोचना शत प्रतिशत बेवकूफी होगी कि योजना आयोग या सरकार प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर व्यक्तिगत रूप से किसी विशेष व्यवसाय में जाने के लिये बाध्य करेगी। व्यवसायों के चुनाव के लिये इस समाजवाद में उसी प्रकार स्वतन्त्र रहेगा, जिस प्रकार वह किसी भी स्वतन्त्र आर्थिक व्यवस्था में रहने का स्वप्न देख सकता है। विभिन्न क्षेत्रों के लिये विभिन्न प्रकार की रुचियों एवं शिक्षाओं की आवश्यकता होगी। जो उन शर्तों को पूरा कर सकेगा और उधर उसकी रुचि होगी, उसी के लिये उस क्षेत्र के द्वार खुले होंगे।

जैसा चित्र हमारे सामने समाजवाद का आया है, उसके अनुसार यह स्पष्ट है कि भारतीय समाजवाद में वस्तुतः कृषि का समूचा विशाल क्षेत्र लोक-अंचल के बाहर होगा। अन्तर इतना अवश्य होगा कि इसके पूर्व जहां थोड़े से जमींदार या बहुत बड़े काश्तकार, बनिया, महाजन, देशी बैंकर तथा अन्य इसी प्रकार के लोगों के हाथ में जमीन का स्वामित्व रहता था, समाजवाद में धरती उसकी होगी, जो धरती को अपने लोहू और पसीने से तर कर सकने की क्षमता रखते हैं। यही नहीं, यथासम्भव जमीन का समान वितरण होगा। किसानों को उत्तरोत्तर भूमि को उपजाऊ बनाने की कृषि सम्बन्धी सारी सुविधाएं जैसे अच्छे यंत्र, खाद, सिंचाई, बीज, ऋण इत्यादि मिलती रहेंगी। इस प्रकार देश की ७० प्रतिशत जनता को वास्तव में कृषक होने का उनका खोया गौरव वापस मिलेगा। वे ही हमारे अन्नदाता कहे जायेंगे व धरती अन्नपूर्ण होगी।

निजी उद्योग में स्वतन्त्रता ?

निजी उद्योगों में ही व्यक्ति की स्वतन्त्रता कहां तक है ? उद्योगों के क्षेत्र में पूंजीपतियों द्वारा किये गये विकास में काम करने वाले लोगों में से कितने प्रतिशत लोगों को ठीक-ठीक स्वतन्त्रता प्राप्त है ? केवल थोड़े से मिल मालिक, पूंजीपति, डाइरेक्टर, मैनेजिंग डाइरेक्टर आदि को छोड़कर बाकी सभी कर्मचारी क्लर्क या श्रमिक होते हैं। ये श्रमजीवी निरन्तर संचालकों की व्यक्तिगत इच्छाओं के इशारे पर कठपुतली की तरह नाचने को बाध्य है।

व्यापार के क्षेत्र में वस्तुतः हमारा उद्देश्य केवल उन बड़े-बड़े व्यापारियों, मध्यवर्ती ((Middl-emen) लोगों को समाप्त करना है, जो उत्पादन और उपभोग के बीच अजगर की तरह बैठ कर कीमत का एक बड़ा भाग निगल जाते हैं। इस प्रकार इन मोटे व्यापारियों की अपनी स्वतन्त्रता तो जाती रहेगी, परन्तु यह जनता से मनमाना

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

खिलवाड़ नहीं कर सकेंगे। खुदरे व्यापारियों की स्थिति पूर्ववत् रहेगी।

नागरिक स्वतन्त्रता

एक बहुत गम्भीर और भीषण आरोप जो समाजवाद के ऊपर लगाया जाता है, वह नागरिक स्वतन्त्रता के अपहरण से सम्बन्धित है। आरोप यह है कि समाजवादी व्यवस्था में व्यक्तियों के स्वतन्त्र रूप से आराम करने, विचार करने, सभा समिति, लिखने और स्वतन्त्र भाषण इत्यादि करने के अधिकार छिन जाते हैं। इसका सबसे ज्वलन्त उदाहरण रूस की समाजवादी व्यवस्था है, जिसमें शासन एक डिक्टेटर के हाथ में वस्तुतः चला जाता है और उसके आदेश कानून बन जाते हैं। सरकार के विचारों के विरोध में उगने वाले सभी विचारों को रौंद दिया जाता है। विचार और विचारक दोनों की हत्या की जाती है।

भारतवर्ष सदैव से विचारों का भिखारी रहा है। विचारों को सुनने और समझने की आश्चर्यजनक सहिष्णुता हमारे देश के प्राणों में रही है और है। हम इस बात से पूर्ण रूप से अवगत हैं कि आज के नये और न जंचने वाले विचार कौन जानता है, कल मानव-कल्याण के पवित्रतम मंत्र बन जाय। जहां विचारों के संघर्षों ने, बर्बरता और मानवीय हिंसा एवं प्रतिहिंसा का आधुनिक इतिहास योरोपीय और इस्लामिक देशों में खून से लिखा है, वहां हमारे देश ने सदैव से नये विचारों के प्रति असीम श्रद्धा और भक्ति दिखलाई है। अनेक विचार, धर्म, जातियां आयीं और शान्तिपूर्वक भारत की मिट्टी की बीज बन गईं और हमने उनमें मानव कल्याण के गीत गाये। और इसलिये हमें यह समझने की भूल कदापि नहीं कर लेनी चाहिये कि समाजवाद के नाम पर हम विचारों की असहिष्णुता अपने में लाते जा रहे हैं। समाजवादी व्यवस्था का जन्म रूस में हुआ और इस असाधारण प्रयोग में रूस को भी अनेक त्रुटियों और बुराइयों को मोल लेना पड़ा। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं होता कि हम शत प्रतिशत उन्हीं रास्तों से गुजर कर समाजवाद के लक्ष्य तक पहुँचे जिनसे रूस गुजरा है। हम इन त्रुटियों को लिये बिना, अनुभव की सीख के आधार पर भलीभांति आगे बढ़ सकते हैं। पूंजीवाद के प्रारम्भिक दिनों में श्रमिक को नरक की दुःसह यातनाएं भुगतनी पड़ीं इसका अर्थ यह नहीं कि आज अगर कोई अर्ध विकसित देश पूंजी के निर्माण द्वारा औद्योगिक क्रान्ति लाना चाहता है तो उसमें मजदूरों को इन यातनाओं से गुजरना ही पड़ेगा। यह मूर्खता की बात होगी। इसीलिये हम प्रजातन्त्रात्मक ढंग पर अपने समाजवाद को ले चलना चाहतते हैं जिसमें व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर आंच न लग सके। समूहवादी (Collective) व्यवस्था का तिरस्कार कर इसीलिये हमने अपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना को सहयोग समितियों के बल पर खड़ा किया है।

पूंजीवाद का अपना एक समय था ठीक समय था। इसने अपना काम किया। उत्पादन के तरीकों में इसने गति भर दी और धीरे-धीरे यह व्यवस्था एक तीव्र उत्पादन कला की भूमिका बन गई। पर अच्छा हो कि यह भूमिका अब समाप्त हो जाय। विश्व के अध्याय में इस उत्पादन कला को अपना कर मानवीय जीवन को समुचित विकास एवं पूर्णता की ओर अग्रसर करने का ऐतिहासिक अभिनय समाजवाद को करना है—करना ही है; निःसन्देह आगे समाजवाद हर देश की मिट्टी के अनुसार वहां की जलवायु के अनुरूप पनपेगा, बढ़ेगा, खिलेगा।

समाजवाद! हमभारतवासी भी तुम्हारा स्वागत करते हैं, और पूंजीवाद! पुनः पुनः अलविदा!!

(पृष्ठ ६१० का शेष)

है। यह व्रत गांधी जी के शब्दों में ट्रस्टीशिप है।

हमारी समाज की व्यवस्था में असमानता को विद्यार्थी जीवन से ही समाप्त करने का प्रयत्न किया गया है। हर एक बालक समाज का बालक माना जाता था। राजा के बच्चे भी दूसरे बच्चों के समान एक गुरुकुल में रहते थे, कष्ट सहन करते थे और अपने भोजन के लिए गांव-गांव में भिक्षा मांगते थे। सारा समाज उन बच्चों को अपना बच्चा मानता था। इस तरह प्रारम्भ से ही ब्रह्मचारियों में ऊंच-नीच की भावना को पैदा ही नहीं होने दिया जाता था। शिक्षा निःशुल्क थी। वानप्रस्थ-आश्रम में जाकर बड़े-बड़े विद्वान शिक्षा-चिकित्सा आदि का काम बिना भारी वेतन लिए करते थे। गरीब को पैसे का अभाव अनुभव नहीं होता था।

साम्यवाद व्यक्ति की स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार नहीं करता। परिणाम वहां वैदिक व्यवस्था व्यक्ति के व्यक्तित्व का जहां विकास करने में सहायक होती है पूंजीवाद की बुराइयों को उत्पन्न नहीं होने देती।

[सम्पादक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

महान् क्रांति की महान् सफलताएं

अक्टूबर क्रांति से रूस में नव-युग

समाजवाद या साम्यवाद के गुणावगुणों पर दृष्टि डालते समय कुछ साम्यवादी देशों की पद्धति व प्रगति पर एक दृष्टि डाल लेना उपयुक्त होगा, इस विचार से इन पृष्ठों में तीन समाजवादी देशों—रूस, चीन और यूगोस्लाविया के सम्बन्ध में कुछ जानकारी दी जा रही है।

क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा देश, तथा जनसंख्या में (चीन और भारत के बाद) तीसरे नम्बर के देश रूस का अक्तूबर क्रान्ति के पहले औद्योगिक उन्नति की दृष्टि से विश्व में पांचवां और योरप में चौथा स्थान था। बड़े उद्योग पिछड़े हुए थे तथा छोटे-छोटे धंधे भी अल्प विकसित अवस्था में थे। मशीनों को बनाने वाले उद्योग इनसे भी अनुन्नत थे। इसके अतिरिक्त बड़े-बड़े उद्योगों के ऊपर विदेशी पूंजीपतियों का आधिपत्य था। रूस को बड़ी मात्रा में विदेशों से मशीनें और अन्य उपकरणों का आयात करना पड़ता था। इन सब कारणों से औद्योगिक उन्नति को बाधा पहुँचती रही।

अक्तूबर क्रांति से एक नये युग का श्रीगणेश हुआ और औद्योगिक उन्नति के लिए अभूतपूर्व सम्भावनाएं दृष्टिगोचर हुईं।

"सोवियत क्रांति के द्वारा मानव समाज प्रगति के पथ पर छलांग मार कर एकदम बहुत आगे बढ़ गया है। इस क्रांति ने एक ऐसी ज्योति जलाई जो कभी बुझेगी नहीं।" —जवाहरलाल नेहरू

विदेशी आक्रमणकारियों से लड़कर अपनी स्वतंत्रता और सामाजिक लाभों की रक्षा कर लेने के बाद सोवियत नागरिक अपनी अर्थव्यवस्था को समुन्नत बनाने का प्रयास करने लगे।

अनेक विघ्न बाधाएं

उस समय अनेक कठिन समस्याएं वर्तमान थीं। यथेष्ट मात्रा में कोयला और लोहा प्राप्त नहीं होता था तथा कच्चा माल नगण्य मात्रा में उत्पन्न होता था। कोयला और कच्ची धातु की खानें नष्ट-भ्रष्ट थीं। अधिकांश कारखाने और संयंत्र (Plants) निष्क्रिय पड़े थे। सारे देश में अन्न और वस्त्र की बहुत कमी थी। शत्रुओं ने भी देश की अर्थव्यवस्था को उखाड़ने में यथासंभव प्रयत्न किया। लेकिन जनता के ऐक्य के बल के सामने उनकी एक न चली। रूस के किसान और मजदूर अपने ही बल पर, बिना किसी बाहरी मदद के दृढ़ता से अपने देश के निर्माण कार्य में लग गये।

१९२६ में औद्योगिक उत्पादन युद्ध-पूर्व के काल तक पहुँच गया था। देश को आर्थिक दृष्टि से दृढ़ और विदेशी नियंत्रण से मुक्त रखने के लिए आवश्यक था कि रूस को कृषिप्रधान के स्थान पर उद्योग-प्रधान राष्ट्र बनाया जाये। इसके लिए देश की श्रमिक जनता को देश के औद्योगीकरण के लिए जुट जाना था और बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापना करना नितांत आवश्यक था। लेकिन ऐसा करना सहज कार्य न था, क्योंकि इसके लिए बड़ी मात्रा में पूंजी के विनियोग की आवश्यकता थी और यह उपलब्ध न थी।

समस्या सुलझी

नवजात सोवियत संघ को पूंजीवादी देशों ने ऋण देना अस्वीकार कर दिया। अतः औद्योगीकरण के लिए आंतरिक साधनों की ही ढूंढ करना आवश्यक हो गया। यह समस्या हल भी हो गई। रूस की जनता को परम्परागत कितनी ही ऐसी सुविधाएं प्राप्त हैं। सोवियत संघ में भूमि, कारखाने, संयंत्र, यातायात, बैंक तथा आन्तरिक और विदेशी व्यापार सब जनता के अधिकार में हैं। उद्योग, यातायात तथा व्यापार से जो लाभ मिलता था, उसका उपयोग राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को और उन्नत बनाने में किया जाने लगा। महान क्रान्ति के बाद समाजवादी रूस के किसान भी जो कि शोषण से सर्वथा मुक्त थे और जिन्हें जमींदारों को लाखों रूबल लगान रूप में नहीं देना पड़ता

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अतीत में मानव की समस्त बुद्धि, उसकी समस्त प्रतिभा एकमात्र इस उद्देश्य से सृजनकार्य में लगी थी कि प्रविधि एवं संस्कृति के समस्त लाभ कुछ ही लोगों को प्राप्त हों और दूसरे लोग शिक्षा और बिकास जैसी सर्वाधिक आवश्यक वस्तुओं से वंचित रहें। किन्तु अब प्रविधि की समस्त आश्चर्यजनक वस्तुएं, संस्कृति की समस्त उपलब्धियां जनता की सम्मिलित सम्पत्ति बन जाएंगी, और अब से मानव की बुद्धि और प्रतिभा हिंसा के साधन के रूप में, शोषण के साधन के रूप में कभी भी रूपान्तरित नहीं की जाएगी। —वी० आई० लेनिन

था, देश में बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापना करने में सहायता देने में पूर्ण समर्थ थे। सोवियत रूस की श्रमिक जनता ने भी सरकार को ऋण देकर और अपनी बचत को बैंकों में जमा करके देश के औद्योगीकरण में हिस्सा बटाया।

समाजबादी प्रकृति की अर्थ-व्यवस्था से बड़ी मात्रा में राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की आयोजना की पूर्ति संभव हुई। १९२८ में रूस ने राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की उन्नति के लिए पहली पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का मुख्य लक्ष्य सोवियत संघ के उद्योग और कृषि को आधुनिक साधनों से सम्पन्न करना था।

रूस के समाजवादी शासन पर सबसे बड़ा आक्षेप होता है कि वहां के आतंकवादी अधिनायकतंत्र में मनुष्य मशीन का एक पुरजा भर रह जाता है और उसकी स्वतन्त्र सत्ता एवं प्रतिभाशाली व्यक्तित्वका पूर्ण विकास नहीं हो पाता, पर रूस के वैज्ञानिकों ने बालचन्द्र के समान उपग्रह का आविष्कार करके यह सिद्ध कर दिया है कि समाजवादी पद्धति में भी आत्मा की स्वतन्त्र भावना व प्रतिभा का विकास पूर्णतः संभव है।

कार्य का श्रीगणेश

सारे देश में कारखानों, संयंत्रों और शक्ति-गृहों का निर्माण-कार्य बड़ी संख्या में आरम्भ किया जाने लगा। प्रयत्न यह था कि रूस को कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था से निकाल कर औद्योगिक अर्थव्यवस्था में लाया जाये। साम्यवादी दल के नेतृत्व में जनता ने इस प्रयत्न में पूर्ण सफलता प्राप्त की।

पूर्णतः अपनी शक्ति और साधनों पर निर्भर करके तथा विदेशी शक्तियों के प्रतिबंधों का सामना करते रहने पर भी सोवियत रूस ने कुछ ही वर्षों म इतनी आर्थिक उन्नति करली, जितनी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने पूरी एक शताब्दी में की थी। विकास के १३ सालों में ही रूस कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था से उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था, अनुन्नत अवस्था से उन्नत अवस्था को प्राप्त करते हुए निर्बलतम के स्थान पर एक बड़ी शक्ति बन गया।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (१९३३-१९३७) भी अपने निर्धारित समय के पूर्व पूर्ण कर ली गई। इस अवधि के बीच समस्त देश का प्राविधिक सम्बन्धी पुनर्निर्माण कार्य करना मुख्य लक्ष्य था। नयी समाज-व्यवस्था को दृढ़ आर्थिक आधार प्राप्त हुआ। समाजवादी व्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था का प्रधान अंग बनी।

१९४७ में, समग्रतः बड़े उद्योगों का उत्पादन १९१३ के मुकाबले में १३ गुना बढ़ गया तथा मशीनों के निर्माण की गति ५० गुना बढ़ गयी। सोवियत संघ ने केवल बाहनों, ट्रैक्टरों और कृषि-सम्बन्धी मशीनों का आयात करना ही बन्द नहीं कर दिया, वरन् स्वयं उनका निर्यात भी करना आरम्भ कर दिया। उस समय देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में मशीनों के निर्माण की मात्रा को देखते हुए सोवियत रूस का प्रथम स्थान था।

अग्नि परीक्षा की घड़ी

१९४१-४५ जब रूस की जनता जर्मनी के आक्रमण का वीरता से सामना करती रही तो देश के उद्योगों के लिए भी वह महान परीक्षा का काल था। अपनी सैनिक शक्ति का अल्पकालीन लाभ उठाते हुए, नाजी आक्रमणकारी देश के आंतरिक भाग तक पहुँच गये, इसके कारण दक्षिण के बड़े बड़े कारखाने अस्थायी रूप से छिन गये। विदेशों में ऐसे कई लोग थे, जो यह सोचने लगे थे कि रूस को यह ऐसी हानि है, जिसकी पूर्ति करना असंभव है।

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नाजी आक्रमणकारियों से रूसी उद्योग-धंधों को भारी हानि हुई। जिन जिलों पर उन्होंने अस्थायी अधिकार कर लिया था, वहां उन्होंने ३२,८५० कारखाने और संयंत्र नष्ट किये। युद्ध के पहले जिन खानों में सारे देश का ६० प्रतिशत कोयला निकलता था तथा जिन शक्ति गृहों में ५० लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न होती थी, सब नाजी आक्रमण के भेंट हो गये।

करीब दस वर्ष तक सोवियत रूस की अर्थ व्यवस्था की प्रगति को भारी धक्का लगा। इतिहास में किसी भी देश को यहां तक कि द्वितीय महायुद्ध में भी इतनी भारी क्षति नहीं हुई। सोवियत जनता समाजवादी अर्थव्यवस्था की महान आभारी है, जिसके कारण ५ वर्ष में ही नष्ट-भ्रष्ट अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित कर लिया गया।

पुनर्निर्माण पूर्ण हुआ

नाजी आक्रमणकारियों ने दक्षिणी क्षेत्र के जिन इस्पात के कारखानों को विनष्ट कर दिया था, उनका बिल्कुल नये प्राविधिक आधार पर पुनर्गठन किया गया और इनका उत्पादन युद्धपूर्व से भी अधिक हो गया। कोयले के खानों से २६ करोड़ टन कोयला निकला जो १९४० से १.५ गुना अधिक है। तेल के कुओं से युद्ध पूर्व के स्तर के बराबर ही तेल निकाला जाने लगा। सभी शक्ति-संयंत्रों को, जिनमें नीपर जलशक्ति गृह भी सम्मिलित है, पुर्नजीवित कर लिया गया तथा कई नये बड़े बड़े बिजली घर चालू कर लिये गये। उद्योगों में मशीन और मशीनों के उपकरणों के उपयोग की संख्या दुगुनी हो गयी। इन सब के कारण उद्योगों के क्षेत्रों में सफलता का नया आधार भी स्थापित कर लिया गया।

उन्नति की नयी गति

युद्ध के कारण क्षत-विक्षत अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित कर लेने पर, रूसी उद्योगों की उन्नति की गति तेज हो गई।

१९५५ में पांचवीं पंचवर्षीय योजना पूर्ण हुई, इससे रूस की अर्थव्यवस्था ने उन्नति का एक और कदम आगे बढ़ाया। इस अवधि में सोवियत रूस युद्धपूर्व के उत्पादन स्तर से ३.२ गुना उत्पादन करने में सफल हुआ। इस समय मशीनों, मशीनों के उपकरणों और मशीनी औजारों का उत्पादन ४.७ गुना बढ़ा। कच्चे लोहे और इस्पात को पिघलाने, कोयले की खदान, तथा विद्युत शक्ति के उत्पादन में रूस का योरप में प्रथम और विश्व में द्वितीय स्थान है।

बड़े उद्योगों को विकास में सफलता प्राप्त कर लेने और कृषि उपज के बढ़ने के कारण रूस उपभोग-पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने में, युद्ध पूर्व स्तर से भी अधिक सफल हुआ है।

औद्योगीकरण के इस उन्नत स्तर के कारण रूस व्यापक आर्थिक सम्बन्धों को स्थापित करने और विदेशों को प्राविधिक सहायता देने में समर्थ है। सोवियत संघ के कारखाने निर्यात करने की पूर्ण क्षमता रखते हैं। इस समय ६५ देशों के साथ रूस का व्यापार सम्बन्ध है।

रूस समाजवादी देशों के सैकड़ों औद्योगिक निर्माण कार्यों को पूर्ण करने में सहायता दे रहा है। अनुन्नत देशों को भी आर्थिक निर्माण में सहायता दी जाती है।

४० वर्ष बाद

१९५६ के आरम्भ में कुल आबादी २० करोड़ थी : कारखाने और दफ्तर के श्रमिकों तथा उनके परिवारों की आबादी ११ करोड़ ७० लाख, सामूहिक किसानों, सहकारी संस्थाओं में काम करने वाले कारीगरों और उनके परिवारों की आबादी ८ करोड़ २० लाख, वैयक्तिक किसानों और उनके परिवारों की आबादी १० लाख।

सोवियत शासनकाल में व्यवसाय और दक्षता की दृष्टि से श्रमिकवर्ग के गठन में महान् परिवर्तन हुए हैं। नये-नये व्यवसायों का उदय हुआ है, जैसे विभिन्न प्रकार की कम्बाईनों, विद्युत् रेलगाड़ियों, ट्रैक्टरों के चालक आदि। गोदियों के मजदूर, अश्वचालक, आदि के पुराने पेशे समाप्त हो रहे हैं। अब राष्ट्रीय अर्थतंत्र में विशेषज्ञों का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है।

१९५५ में कारखाने और दफ्तर के श्रमिकों की संख्या १९२९ के मुकाबिले चार गुनी थी। आशा की जाती है कि षष्ठ पंचवर्षीय योजनाकाल में १५ प्रतिशत से कम वृद्धि नहीं होगी, जिससे १९६० के अन्त तक उनकी कुल संख्या पांच करोड़ पच्चास लाख हो जाएगी जबकि १९१३ में एक करोड़ तीस लाख थी।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

FOR NEAT PRINTING

EASY OPERATION

INCREASED OUTPUT

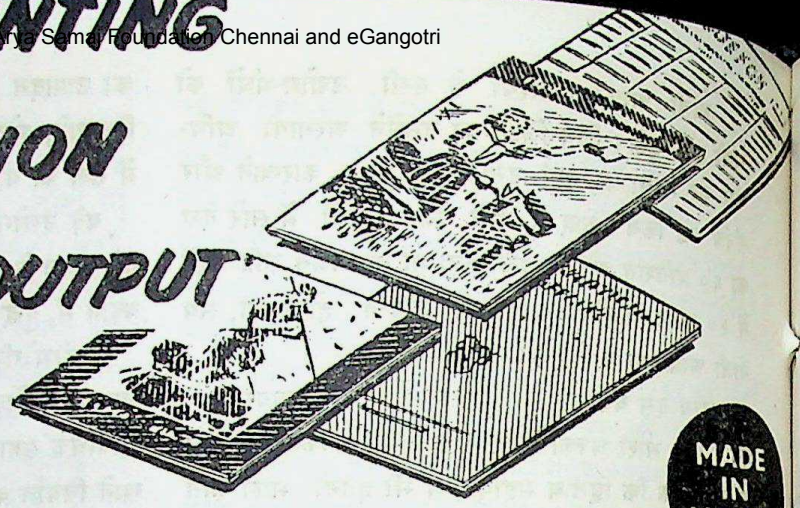

DEPEND ON...

MADE IN U.S.S.R.

TWO REVOLUTION
FLAT BED PRESS

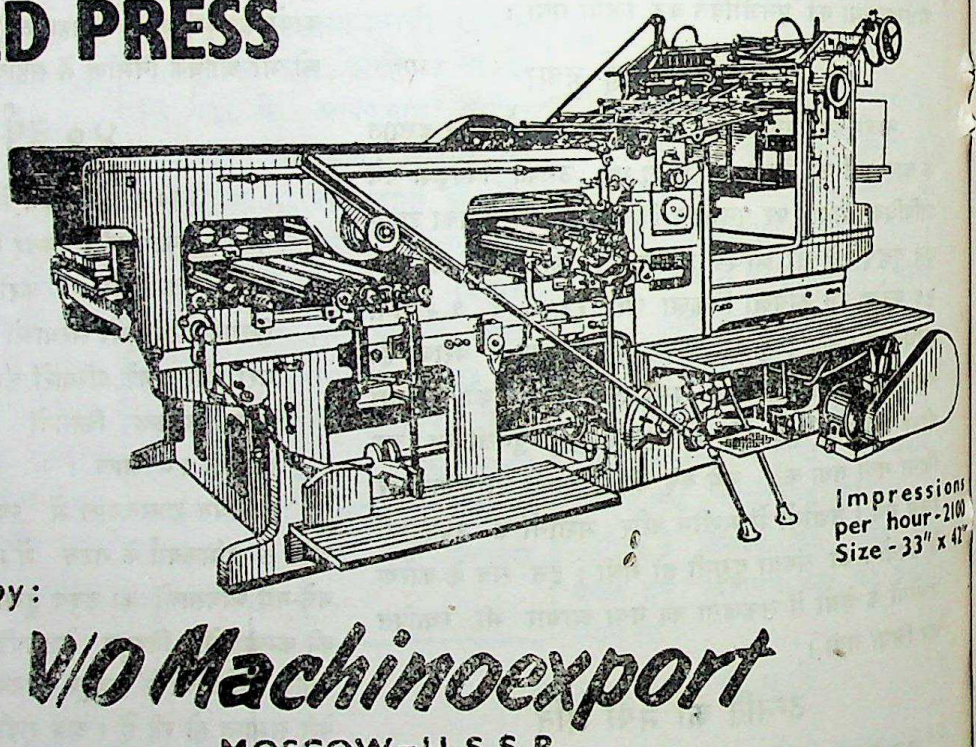

Impressions per hour-2100
Size - 33" x 42"

Exported by:

V/O Machinoexport

MOSCOW - U.S.S.R.

Also available

Platen presses, Offset, Rotary, Printing machines, Composing & casting machines, Book binding, Wire stitching and Paper cutting machines, Photo offset cameras and equipment etc.

Please write for further details to our Agents:

MANUBHAI SONS & CO.
16, Custom House Road, Bombay.

THE INRUPEXCO
16, Bentinck Street, Calcutta.

TRADE REPRESENTATION OF THE U.S.S.R. IN INDIA

BOMBAY (Branch) **NEW DELHI** **CALCUTTA** (Branch)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सोवियत शासनकाल (१९१७-५७) में सोवियत संघ की राष्ट्रीय आय में १२ गुनी, कुल औद्योगिक उत्पादन में जिसमें उत्पादन के साधनों का उत्पादन शामिल है। ४७ गुनी तथा उपभोक्ता माल के उत्पादन में ८.२ गुनी वृद्धि हुई है। बेकारी वहां है ही नहीं, राज्य का कर्तव्य है कि वह नागरिकों को काम दे, संविधान की ऐसी आज्ञा है।

श्रम की उत्पादनशीलता के विकास की दर १९१३ की तुलना में ९ गुनी अधिक है, जबकि दैनिक काम के घंटों में २५ प्रतिशत कमी कर दी गई है।

औद्योगिक उत्पादन में ६५ प्रतिशत वृद्धि करने की व्यवस्था छठी पंचवर्षीय योजना में है, जिसके आधे की उपलब्धि प्राविधिक प्रक्रियाओं में उन्नति तथा नये यंत्रों के प्रचलन के फलस्वरूप प्राप्त उच्चतर उत्पादन से होने की आशा की जाती है।

युद्ध से पहले के समय की तुलना में स्वतंत्र आय वाले मजदूर परिवारों के सदस्यों की संख्या ४३ प्रतिशत से बढ़कर ४९ प्रतिशत हो गयी है। और इसके साथ-साथ परिवारों में आश्रित लोगों की संख्या तदनुरूप घट गयी है। सामूहिक कृषिशालाओं के परिवारों में भी यही स्थिति है: उक्त अवधि में रोजगार पर लगे लोगों की संख्या ४६ प्रतिशत से बढ़कर ५४ प्रतिशत हो गयी और आश्रितों की संख्या कम हो गयी।

एक और उल्लेखनीय स्थिति यह है कि सन् १९४०-५६ की अवधि में कामकाज करने वाले परिवारों में काम न करने वाले पेन्शनयाफ्ता लोगों की संख्या प्रायः दुगुनी हो गयी और यह चार प्रतिशत से अधिक है। गत वर्ष पेंशनों के बारे में जो नया कानून पास किया गया, उसने वृद्धों और कार्य में अक्षम लोगों की पेंशन-दरों में दो से लेकर ढाई प्रतिशत तक की वृद्धि कर दी है। इससे मेहनतकश लोगों को बहुत बड़ी संख्या में पेंशन पर अवकाश लेने के लिए विशेष आधार मिला।

रोटी की प्रति व्यक्ति खपत में लड़ाई से पहले के जमाने की तुलना में रूसी नागरिक का जीवन स्तर बढ़ रहा है, इसका एक प्रमाण यह है कि खपत में २३ प्रतिशत कमी हुई है। अन्य अधिक पौष्टिक खाद्य-पदार्थों की प्रति व्यक्ति खपत में असाधारण वृद्धि हुई है। मांस तथा चर्बी की खपत में औसतन ८८ प्रतिशत मछली और मछली की बनी चीजों की खपत में दो-तिहाई से अधिक, दूध और दूध की चीजों की खपत में ढाई गुना, अंडों की खपत में तीन चौथाई, चीनी की खपत में ठीक दुगुनी और मिठाइयों की खपत में डेढ़ गुना से ज्यादा की वृद्धि हुई है, इत्यादि। सब्जियों और तरबूज की खपत में एक-चौथाई की वृद्धि हुई है। १९५५ के आंकड़ों के अनुसार यहां १९४० की तुलना में प्रतिव्यक्ति खपत में जो वृद्धि हुई है, वह इस प्रकार है:—मांस और मांस की वस्तुएं तीन-चौथाई, चर्बी दुगनी से ज्यादा, चीनी ४।५ से ज्यादा और फल और ताजी बेरियां कई गुना।

सामूहिक कृषिशालाओं के परिवारों को आम तौर पर अधिक पौष्टिक आहार मिलने के कारण स्वभावतः रोटी की खपत में कमी हुई है जो युद्धपूर्वके स्तर के ९९.८ प्रतिशत के बराबर है। १९५०-५६ की अवधि में चीनी की खपत में मोटे तौर पर साढ़े चार गुना और मिठाई की चीजों में ढाई गुना वृद्धि हुई है। श्रमिक परिवारों में १९४०-१९५६ के बीच (समूचे सोवियत संघ की औसत के अनुसार) कपड़ों की प्रति व्यक्ति खरीद में ७५ प्रतिशत वृद्धि हुई। ऊनी कपड़ों की खरीद में लगभग ३.५ गुनी, रेशमी कपड़ों की खरीद में १८ गुनी से अधिक और चमड़ों के जूतों की खरीद में ७८ प्रतिशत वृद्धि हुई।

सामूहिक किसान दीर्घकालीन उपयोग के वस्त्र और माल अत्यधिक परिमाण में खरीद रहे हैं। परिवार के प्रत्येक सदस्य पीछे १९५६ में १९४० के मुकाबिले २.२ गुना अधिक व्यय हुआ, बुनाई किये हुए माल पर लगभग २.७ गुना, फर्नीचर तथा घरेलू कामकाज की अन्य चीजों पर लगभग तिगुना तथा सांस्कृतिक उद्देश्य की वस्तुओं पर नौगुना अधिक व्यय हुआ।

कुछ ज्ञातव्य तथ्य

१. १९५६ में सोवियत रूस में विभिन्न वस्तुओं का प्रतिघंटा उत्पादन इस प्रकार था—

कच्चा लोहा	४,००० टन से भी अधिक
इस्पात	५,५०० टन से भी अधिक
कोयला	४८,००० टन से भी अधिक
सूत	६,२८,००० मीटर से भी अधिक

२. सोवियत रूस में प्रत्येक प्रकार की मशीनें, उनके

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पुर्जे और सम्बन्धित आवश्यक वस्तुएं देश की पूर्ण आवश्यकतानुसार सब वहीं बनाई जाती हैं ।

३. प्रतिवर्ष मशीनों और उपकरणों के ७०० से ९०० तक नये डिजायन सम्मुख आते हैं ।

४. १९६० तक रूस १ करोड़ ३५ लाख टन तेल और बिजली ३२० मिलियार्ड किलोवाट पैदा करने लगेगा ।

सांस्कृतिक उन्नति

१९१३ में उच्चतर तथा विशेष माध्यमिक शिक्षा प्राप्त लोगों की संख्या १९०,००० थी, १९२८ में उनकी संख्या ५२१,००० हो गई और पिछले वर्ष ६२५३००० हो गई ।

पुस्तकों का प्रकाशन जनता के सांस्कृतिक स्तर के ऊपर उठने का महत्वपूर्ण चिह्न हुआ करता है । रूस में प्रथम पुस्तक के प्रकट होने के बाद के लगभग चार सौ वर्षों में ५५०,००० पुस्तकें प्रकाशित हुईं । सोवियत सत्ता काल में १५,००,००० पुस्तकों की लगभग २०,०००,०००,००० प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं । सोवियत संघ के प्रति नागरिक को औसतन प्रतिवर्ष पांच नयी पुस्तकें मिलती हैं ।

× × ×

अक्तूबर क्रान्ति से पहले सम्पूर्ण रूसी साम्राज्य में १७२ थियेटर थे । अब सोवियत संघ में ३२ आपेरा और बैले थियेटरों समेत ५०० थियेटर हैं ।

क्रान्ति से पहले बालकों या युवकों के लिए एक भी थियेटर नहीं था । अब उनके लिए ऐसे १०१ थियेटर हैं ।

पुराने रूस में अधिकांश नाटक-थियेटरों के पास कोई स्थायी नाट्यदल नहीं थे । अब रूस के भूतपूर्व सीमा प्रांतों—किर्गिजिया, याकुतिया और मोल्दाविया समेत हर संघीय जनतंत्र में दर्जनों थियेटर हैं, जिनके अपने स्थायी नाट्य-संघ हैं ।

स्कूल और थियेटर, पुस्तकालय और अजायबघर, रेडियो और टेलिविजन—ये तमाम सांस्कृतिक सम्पदा जनता की है ।

सोवियत संघ में पेशेवर थियेटर मंडलियों के अलावा लगभग ढाई लाख शौकिया मंडलियां हैं, जिनमें तीन लाख व्यक्ति भाग लेते हैं ।

दी बैंक आफ बड़ोदा लिमिटिड

प्राधिकृत पूंजी	२,४०,००,००० रु०
प्रार्थित पूंजी	२,००,००,००० रु०
परिदत्त पूंजी	१,००,००,००० रु०
सुरक्षित कोश	१,२८,००,००० रु०

मुख्य कार्यालय : बड़ोदा

शाखाएं

अहमदाबाद, (भद्रा, पंचकुवा एम० जी० रोड), अमरेली, अमृतसर, बंगलौर, बड़ोदा (सयाजीगंज), भावनगर, बिल्लिमोरा, बम्बई (फोर्ट, बुलियन हाल, माण्डवी, जवेरी बाजार, रिक्लेमेशन, घाटकोपर), कलकत्ता (नेताजी सुभास रोड, बड़ा बाजार, क्रास स्ट्रीट), कैम्बे, कोचीन, कोयम्बटूर, दभोई, दिल्ली, धूलिया (पश्चिमी खानदेश), द्वारका, गण्टूर, हरिज (उ. गु.), हैदराबाद (दक्षिण), जलगांव (पूर्वी खानदेश), जामनगर, कादी, कलोल (उ. गु.), कारजन, कानपुर, कापड़ वंज, लखनऊ, मद्रास, (शहर व त्यागरायनगर), महसाना, मिठापुर, मिलापुर (मद्रास), नवसारी (शहर व स्टेशन रोड) नई दिल्ली, पाटन, पेतलाड, पूना (कैम्प व सिटी,) पोरबन्दर ओखा बन्दर, राधनपुर (उ. गु.) राजकोट, राजपीपला, सांखेड़ा, सिद्धपुर, सूरत, सुरेन्द्रनगर (बाढवान कैम्प), ऊंझा (उ०. गु.), विरावल, विजापुर (उ. गु.), विसनगर (उ. गु.), व्यारा, सिकन्दराबाद ।

विदेशों में शाखाएं

नैरोबी, मोम्बासा, कम्पाला, दारे-इस-सलाम (ब्रि० पूर्वी अफ्रीका)
लंदन (इंगलैंड)

देश और विदेशों में सब प्रकार का बैंकिंग कारोबार होता है । वसीयतों और समझौतों तथा विवाहित स्त्रियों के समझौते कानून के अन्तर्गत बैंक प्रबन्धकर्ता व ट्रस्टी का भी काम करता है । सेविंग बैंक खातों पर मुख्य कार्यालय तथा भारत की शाखाओं में २½ % ब्याज दिया जाता है । खास मामलों में चैक द्वारा रुपया निकाला जा सकता है ।

एम० जी० पारिख
बम्बई, मैनेजर

एन० एम० चोकशी
जनरल मैनेजर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

साम्यवाद का व्यावहारिक रूप

रूस की अर्थ-व्यवस्था पर एक दृष्टि

१९१७ की अक्तूबर क्रांति के बाद रूस में जिस साम्यवादी व्याख्या की स्थापना करने का प्रयत्न अब तक चल रहा है, उसका व्यावहारिक रूप क्या है, इसकी जानकारी प्राप्त करना 'समाजवाद' के अध्ययन में उपादेय तो है ही, मनोरंजक भी है। रूसी नेताओं के कथनानुसार "सोवियत लोगों ने समाजवाद की स्थापना करली है और अब वे साम्यवादी समाज का निर्माण कर रहे हैं"। उनका यह दावा कहां तक सफल हुआ है, इससे यह भी हम जान सकेंगे। साम्यवादी समाजवाद को 'विकास' का आरम्भिक और साम्जवाद को अंतिम रूप मानते हैं।

समाजवाद और साम्यवाद दोनों में 'आदर्श' का नहीं, 'क्रिया' का भेद है। मार्क्स और एंजेल्स के विचारों के आधार पर ही साम्यवादी समाज का स्वरूप स्थापित करने का प्रयत्न रूस में किया जा रहा है। तत्वतः समाजवाद (साम्यवाद भी) वर्ग भेद का अंत करने, असमानता को—चाहे वह आय की हो या सामाजिक या अन्य किसी भी प्रकार हो—दूर करके समानता स्थापित करने, उद्योग और उत्पादन के समस्त साधनों पर समाज (या व्यवहारतः सरकार) का नियंत्रण करने पर जोर देता है। शोषण का उन्मूलन करना समाजवाद का एक मुख्य ध्येय है। शोषितों के प्रति समाजवाद की विशेष सहानुभूति है। इन मोटे आधारों पर हम देखेंगे कि रूस की अर्थव्यवस्था क्या है। वहां वर्गभेद समाप्त हो गया है या नहीं। क्या वहां आर्थिक विषमता वर्तमान है? उद्योगों का नियंत्रण किस प्रकार किया जाता है? रूस में वैयक्तिक सम्पत्ति रखी जा सकती है अथवा नहीं? सरकार कर किस प्रकार लगाती है और कैसे उनका संग्रह किया जाता है? आदि आदि।

रूस में वर्ग भेद

धन के असमान वितरण या शोषण से वर्ग भेद की खाई खुदती है। सोवियत रूस में धन का समान वितरण होता है या नहीं, इसके लिये वहां के लोगों का सामान्य आय स्तर देखना होगा। १९५६ के आरम्भ में रूस में वेतन और मजदूरी प्राप्त करने वाले श्रमिकों और उनके परिवारों की संख्या १ करोड़ १७ लाख थी।

उत्पादकों के सहकारी संघों में सम्मिलित किसानों और दस्तकारों तथा इनके परिवारों की संख्या ८ करोड़ २ लाख थी। बाकी वैयक्तिक रूप से काम करने वाले किसानों और कारीगरों तथा उनके परिवारों की संख्या १० लाख के लगभग थी। इसके मुकाबले अप्रैल १९५६ में रूस की जनसंख्या २० करोड़ २ लाख है। वेतन और मजदूरी पाने वाले श्रमिकों का प्रतिशत ५८.३, सामूहिक फार्मों के कृषक और दस्तकारों का प्रतिशत ४१.२ और वैयक्तिक किसानों और कारीगरों का प्रतिशत ५.२ होता है। निस्संदेह यह आंकड़े सिद्ध करते हैं कि रूस में शोषण नहीं है, अतः वर्ग भेद का प्रश्न ही नहीं।

यह भी सत्य है कि रूस में दो वर्ग हैं पहला श्रमिक और किसानों का वर्ग और दूसरा बुद्धि जीवी। पर बुद्धि जीवी भी एक प्रकार से 'बुद्धि-श्रमिक' ही है। इनके पारस्परिक सम्बन्ध मधुर सौहार्द पूर्ण हैं।

समानता का अर्थ

सोवियत रूस में समानता का अर्थ यह लिया जाता है कि स्त्री और पुरुषों के बीच में किसी भी प्रकार का भेद-भाव नहीं होना चाहिए। सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है, सम्पत्ति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया जाता, हां कार्य और योग्यता के आधार पर समाज में व्यक्ति का स्थान निर्धारित होता है। सभी नागरिकों को काम करने, आराम, मनोरंजन, वृद्धावस्था में बीमारी और शारीरिक अयोग्यता

औद्योगिक उत्पादन के अंक सम्पदा के पाठक बार-बार पढ़ते रहे हैं, पर देश की समृद्धि नागरिकों के जीवन स्तर से मालूम होती है। समाजवादी क्रान्ति के बाद के चालीस वर्षों में वहां का जीवन स्तर कितना बढ़ा, यह जानना भी जरूरी है।

रूस की अर्थ व्यवस्था का ज्ञान समाजवाद के व्यावहारिक स्वरूप को जानने के लिए सहायक होगा, इस लेख में पाठक रुचि लेंगे।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के कारण सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है।

सोवियत रूस में सभी व्यक्तियों को काम करने का अधिकार संविधान में प्रदत्त है। संविधान की धारा ११८ में इसका उल्लेख है कि हर एक नागरिक को कार्य दिया जाये और मात्रा या गुण के आधार पर उसका प्रतिफल दिया जाये। विश्राम और मनोरंजन की भी पूर्ण सुविधाएं नागरिकों को दी गई हैं। यह बात इस तथ्य से भी सिद्ध होती है कि इस समय रूस में काम करने के साप्ताहिक ४६ घंटे हैं।

कार्यनिवृत्त होने पर सभी श्रमिकों के पेंशनों की व्यवस्था है। पेंशन, मासिक वेतन के ५० प्रतिशत से लेकर १० प्रतिशत तक होती है। कम वेतन पाने वालों की पेंशन वेतन का १०० प्रतिशत होती है और १,००० रूबल या इससे अधिक वेतन वालों की ५० प्रतिशत। पुरुषों की पेंशन ६० वर्ष की आयु अथवा २५ साल काम कर लेने पर और स्त्रियों की ५५ वर्ष की उम्र या २० साल काम करने पर। पर वृद्धावस्था में मिलने वाली कम से कम पेंशन ३०० रूबल प्रतिमास और अधिकतम १२०० रूबल होती है।

निजी सम्पत्ति और स्वामित्व

सोवियत रूस में नागरिक अपनी बचत का किसी भी प्रकार उपयोग करने के लिए स्वतन्त्र हैं। वह चाहे मकान बनाये, चाहे कार खरीदे या कोई काम करे। हां उसकी सामर्थ्य इसी बात में है कि वह कितना कमाता और बचाता है। कोई व्यक्ति यदि मकान बनाना चाहता है तो आवेदन करने पर उसे इसके लिए राज्य द्वारा मुफ्त जमीन और निर्माण सामग्री तथा टेक्नीकल सहायता भी मिल जायेगी। लेकिन सोवियत कानून इस बात की अनुमति नहीं देता कि बचत से या निजी सम्पत्ति से अनर्जित आय प्राप्त की जाये। सट्टा, सूदखोरी आदि रूस में गंभीर अपराध हैं और इनके लिए कठोर दण्ड व्यवस्था है। पर अपनी निजी सम्पत्ति—याने बचत, मकान, प्रकाशनाधिकार (कापी राइट) और व्यवसायाधिकार (पेटेंट)—को दान या वसीयत करने का अधिकार है। रूस में निजी स्वामित्व जैसी कोई चीज नहीं। उत्पादन के समस्त साधनों पर राज्य का एकमात्र अधिकार है। संविधान की धारा ४ में कहा गया है—

"रूस के सोवियत समाजवादी संघ में अर्थतंत्र का आधार समाजवादी व्यवस्था है और उत्पादन के साधन और तरीकों पर समाज का स्वामित्व होगा, जिसकी स्थापना पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था को पूर्णतः समाप्त करके, उत्पादनों के साधनों और तरीकों पर निजी अधिकार के उन्मूलन से और मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण का अन्त करके की जायगी।" अतः रूस में केवल सामूहिक सम्पत्ति ही है। यह दो प्रकार की है—पहली, राज्य की सम्पत्ति (जिन पर सोवियत जनता का अधिकार है। और दूसरी सामूहिक या सहकारी फार्म (जिन पर इनमें सम्मिलित किसानों व कारीगरों का सामूहिक अधिकार है)। भूमि और इसकी खनिज सम्पत्ति, नदियां, जंगल, मिल, कारखाने, खानें, रेल, समुद्र व हवाई यातायात, धक, संचार सुविधाएं, बड़े-बड़े संगठित फार्म (राज्य द्वारा नियंत्रित), नगर सभाओं द्वारा संचालित उद्योग, अवशिष्ट निवास स्थान सरकार की सम्पत्ति हैं।

आर्थिक क्रिया-कलाप

आयोजना—समाजवादी व्यवस्था में, अर्थतंत्र का नियोजन एक केंद्रीय आयोजना संस्था द्वारा होना अनिवार्य माना जाता है। अर्थतंत्र का संचालन पूर्णतः सरकार के द्वारा किया जाता है। समाजवादी सिद्धान्तों को व्यावहारिक रूप देने का सर्वप्रथम प्रयत्न रूस में ही किया गया। अतः योजनाबद्ध विकास करने के लिए पंचवर्षीय आदि की योजना बनाने का श्रेय रूस को ही है। आज प्रायः सभी देशों ने इस योजनाबद्ध प्रणाली को किसी न किसी प्रकार अपना लिया है। रूसमें पंचवर्षीय, त्रिवर्षीय जैसी दीर्घावधिकी योजनाओं के अतिरिक्त वार्षिक, त्रैमासिक या मासिक योजनाएं भी प्रचलित हैं। पहली प्रकार की योजनाएं सर्वोच्च सोवियत के द्वारा और दूसरी प्रकार की वार्षिक योजनाएं मंत्रिपरिषद के द्वारा बनाई जाती हैं।

आय का वितरण—रूस में राष्ट्रीय आय पर श्रमिक जनता का अधिकार माना जाता है। राष्ट्रीय आय का चौथाई के लगभग उत्पादन विस्तार और $\frac{1}{3}$ भत्ता श्रमिकों की भौतिक और आवश्यकताओं की पूर्ति में व्यय किया जाता है। इस तिहाई भाग में वेतन, मजदूरी और सामू-

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

REDUCE YOUR FARMING COSTS!
OBTAIN BETTER YIELDS!

USE

DT-14, 14 H.P.
DIESEL TRACTORS

Exported by

V/O AVTOEXPORT
MOSCOW - U. S. S. R.

Complete with Plough and Cultivator, Hydraulic Lift, Power take off, Belt Pulley, Hour Meter, Standard set of Tools and some spare parts.

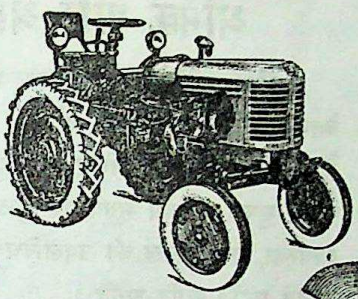

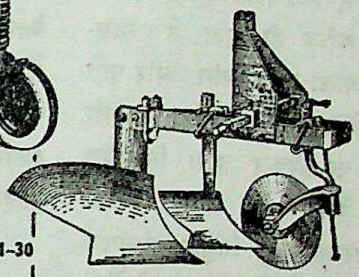

SINGLE-FURROW
TRACTOR PLOUGH nH-30

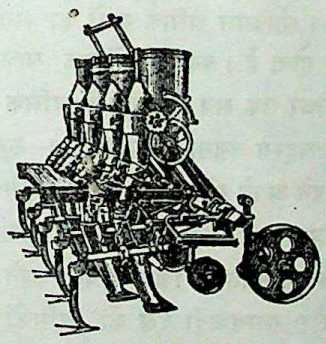

TRACTOR MOUNTED
CULTIVATOR-FERTILIZER
KPH-2.8

TRADE REPRESENTATION
OF THE U.S.S.R. IN INDIA

NEW DELHI
House No. 21,
Block 48
Panch Sheel Marg,
Chanakya Puri.

BOMBAY
(Branch)
44, Pedder Rd.

CALCUTTA
(Branch)
1, Bishop
Lefroy Road.

For further particulars, please contact our agents:

MOHANWI CORPORATION PRIVATE LTD.,
26-K, Connaught Circus, Opp. Plaza,
Post Box No. 555, NEW DELHI-1.
Areas: Punjab, Uttar Pradesh, Bihar, Himachal Pradesh, and Delhi, Jammu & Kashmir

BHARAT INDUSTRIES & COMMERICAL CORPORATION
Tower House, Chowringhee Square, Calcutta-1.
Areas: Assam, West Bengal, Tripura, Manipur, Bhutan, and Rajasthan.

THE INDIAN ENGINEERING & COMMERCIAL CORPN. (PRIVATE) LTD.
Bandi Vilas, Allenganj, Kanpur.
Mustafa Bldg., Sir P. M. Road, Bombay-1.
Areas: Bombay, Madhya Pradesh.

NU-D4

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हिक कृषकों की आय और सरकार द्वारा प्रदत्त सामाजिक सुरक्षा भी सम्मिलित है। १९५६ में इस पर १ अरब ६१ करोड़ २० लाख रूबल खर्च हुए थे।

मूल्यों का निर्धारण—पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मूल्य मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होते हैं, लेकिन समाजवादी व्यवस्था में इसके लिए बहुत कम गुंजाइश है। रूस में वस्तुओं के मूल्य सरकार की स्वीकृति से नियोजन अधिकारियों द्वारा नियत होते हैं। अन्न के अतिरिक्त, समस्त रूस में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य एक जैसे हैं। अनाज के मूल्यों में क्षेत्रों (Zones) के अनुसार कुछ अन्तर रहता है और कितनी ही बातों को ध्यान में रख कर इनका मूल्य निर्धारित होता है। सहकारी संस्थाएं अपने उत्पादन का मूल्य स्वयं तय करती हैं और इनके मूल्य का स्तर राज्य द्वारा निर्धारित मूल्य के करीब ही रहता है। सामूहिक फार्म के द्वारा लिया जाने वाला मूल्य मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है, लेकिन सरकारी और सहकारी दुकानों में इन मालों को बेचने पर सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य ही लिया जाता है।

उद्योगों का प्रबन्ध—सरकार द्वारा नियुक्त संचालक उद्योगों का प्रबन्ध करता है। यह संचालक उद्योगों के लिए भौतिक और आर्थिक साधनों को जुटाता है। यही योजनानुसार निर्धारित उत्पादन करने के लिए जिम्मेवार है। श्रम सम्बन्धी कानूनों की देखरेख भी इसी के द्वारा होती है। समय-समय उत्पादन सम्मेलन बुलाये जाते हैं, जिनमें मजदूर व श्रमिक संघ भाग लेते हैं और इस प्रकार उत्पादन की विधि और किस्म को बेहतर बनाने के लिए संचालक की सहायता करते हैं।

बैंक—रूस में सभी बैंक सरकार द्वारा नियंत्रित हैं। सोवियत रूस का राज्य बैंक मुख्य बैंक है। सभी सार्वजनिक संस्थाएं, कार्यालय, कारखाने सभी अपना चालू खाता इस बैंक में रखते हैं। इस बैंक की शाखाएं सारे सोवियत संघ में फैली हैं। सरकारी आय, कर राशि, इसी में जमा की जाती है। विदेशी व्यापार के सौदों को यही चुकाता है। लोग अपनी बचत को यहीं राज्य सेविंग बैंकों में जमा करते हैं। १९५६ में ५ करोड़ ८० लाख रूबल सेविंग बैंकों में जमा किये गये।

कर-व्यवस्था

रूस में कारखानों या दफ्तरों में काम करने वाले, कलाकार, कृषक और अन्य नागरिक जिनके पास आय के स्वतंत्र साधन हैं, कर देते हैं। ३७० से कम रूबल की मासिक आय वालों को कोई कर नहीं देना पड़ता। जिन श्रमिकों को ४ या अधिक व्यक्तियों का भरण-पोषण करना पड़ता है, उनको भी कर-मुक्त किया गया है। कर प्रतिमास देने पड़ते हैं। अधिकतम कर की सीमा मासिक आय का १३ प्रतिशत है। आयकर से १९५६ में ८·५ प्रतिशत आय हुई थी।

श्रमिक और श्रमिक संघ

श्रमिक सोवियत अर्थव्यवस्था धुरी है। श्रमिकों को वेतन के अलावा राज्य की ओर से अन्य उपलब्धियां प्राप्त हैं। जैसे सामाजिक बीमा की सुविधा, पेंशन, छुट्टी का वेतन, मुफ्त या कम मूल्य पर सुन्दर निवास और स्वास्थ्य-व्यवस्था, प्रसूतिकाल की उपलब्धियां (४ महीने की वेतन-सहित छुट्टी) आदि-आदि।

लेनिन ने श्रमिकों को "साम्यवाद की पाठशाला" कहा था। सोवियत श्रमिक संघों का संगठन उद्योगों के आधार पर होता है। कारखाने में एक साधारण मजदूर से लेकर मैनेजर तक सब कारखाने के श्रमिक संघ के सदस्य होते हैं। हां सदस्य बनना ऐच्छिक है। रूस में सभी श्रमिकों के अपने-अपने संघ हैं। इसमें इंजीनियर, टेक्नीशियन, क्लर्क, मजदूर आदि सभी सम्मिलित होकर वैज्ञानिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए प्रयत्न करते हैं। सोवियत सरकार और साम्यवादी दल को श्रमिकों की कार्यदशाओं और भौतिक सुविधाओं को बेहतर बनाने में परामर्श देने का काम भी ये संघ करते हैं। मजदूर-सम्बन्धित कानूनों के प्रारूप तैयार करने में भी इनसे सहायता ली जाती है।

श्रमिक संघों की एक केन्द्रीय परिषद् है, जिसका चुनाव सभी संघों के एक सम्मेलन में किया जाता है।

श्रमिकों की चर्चा करते समय एक प्रश्न संभवतः हो सकता है कि क्या मजदूरों और प्रबन्धकों में कोई विवाद भी होता है? यदि हां तो उसका प्रशमन किस तरह किया जाता है? यह ध्यान देने की बात है कि प्रबन्धक व मजदूर

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दोनों समाजवादी व्यवस्था में 'श्रमिक' ही हैं। दोनों में कोई विरोध नहीं; जैसा कि पूंजीवादी व्यवस्था में प्रबन्धक मालिक के हितों के लिये मजदूरों का तिरस्कार करते हैं। अतः सामान्यतः किसी विवाद का प्रश्न नहीं उठता। हां, दैनिक कार्य में एक मजदूर और प्रबन्धकों में कोई विवाद उठ सकता है। इसके लिये शिकायत समितियां बनी हुई हैं, जो निर्धारित नियमों के द्वारा ऐसे विवादों को तय करती हैं। इसके पहले यह समिति निष्पक्ष रूप से दोनों पक्षों से सम्बन्धित बातों की जांच करती है।

पारिश्रमिक का निर्धारण

सोवियत रूस में पारिश्रमिक के निर्धारण की सामान्य पद्धति "अंश दर पद्धति" (Peace rate System) है। इसके अनुसार मात्रा और गुण के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है। प्रायः सभी मजदूरों को इसी के अनुसार प्रतिफल मिलता है। अंश दरों के उत्पादन विधि (उत्पादन की एक इकाई पर समय) में श्रम पर व्यय और प्राविधिक स्तर के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं। इन सबका एक विशुद्ध लेख रखा जाता है। ये स्तर १ वर्ष के लिए नियत किये जाते हैं। बीच में इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हां, नयी मशीनों के प्रयोग, शिल्पविधि में सुधार आदि की हालत में इनमें संशोधन किया जाता है 'प्रत्येक उद्योग के लिए वेतन की दरें निर्धारित हैं। सरकार और श्रमिक संघ इनको नियत करते हैं। कुशलता और कार्य के लिहाज से विभिन्न उद्योगों के वेतन स्तर में अंतर होता है। जिस कार्य में अधिक मेहनत और कुशलता की आवश्यकता होती है, उसमें वेतन दर सबसे अधिक है।

कृषि, सहकारी और सामूहिक कृषि अलग लेख के विषय हैं।

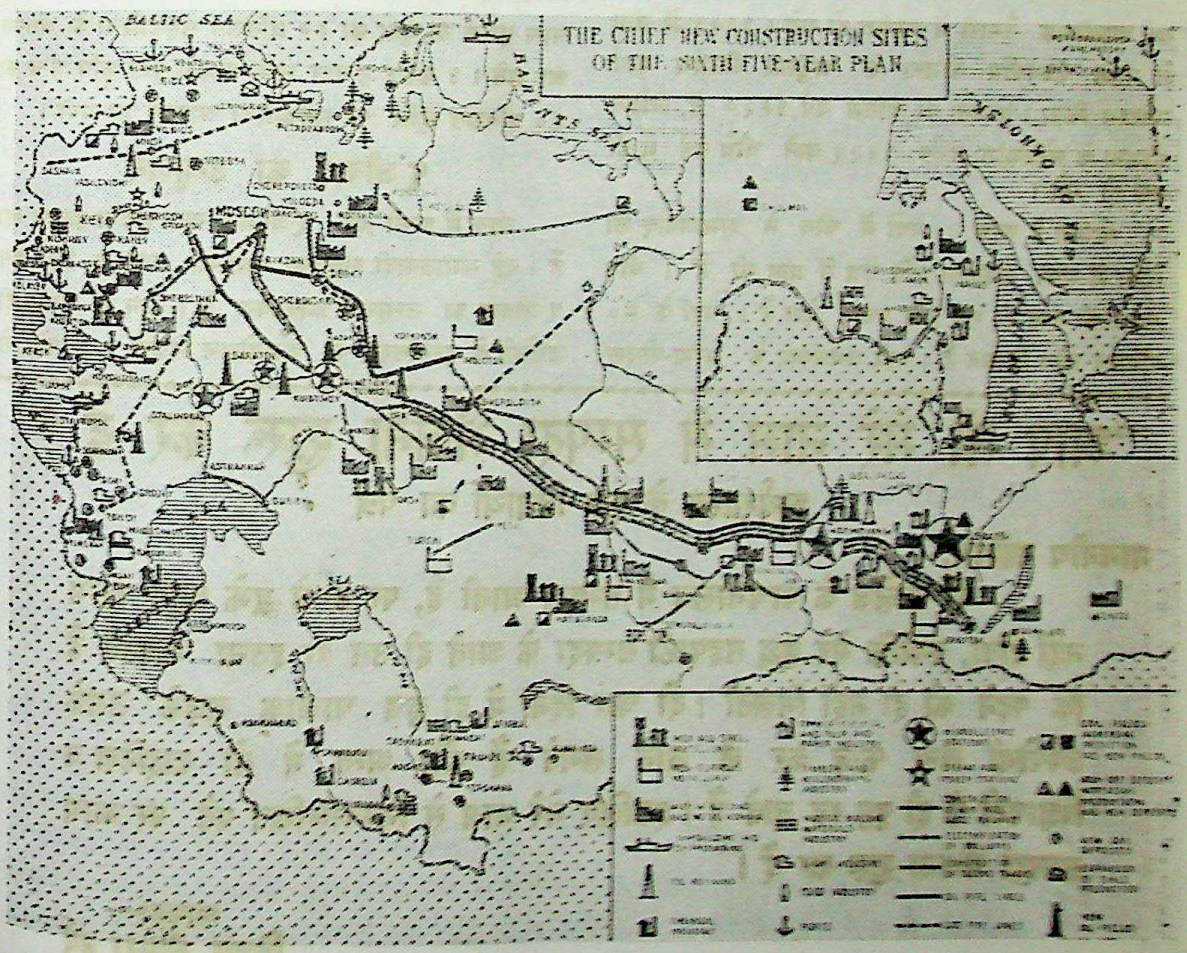

सोवियत रूस का औद्योगिक मानचित्र

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

समाजवाद की ओर चीन के बढ़ते चरण

साम्यवादी जगत में 'अक्तूबर क्रांति' का बड़ा महत्व है, पर वास्तव में 'अक्तूबर क्रांति' रूस में न होकर चीन में हुई है। (रूस की क्रान्ति अक्तूबर में नहीं हुई)। १ ली अक्तूबर १९४९ को चीन की मुख्य भूमि पर साम्यवाद की लाल पताका पहराने लगी। विश्व के इस सबसे बड़े देश (आबादी ६५ करोड़) में साम्यवाद क्या रूप लेता है और चीन अपनी समस्याओं को किस प्रकार हल करता है, इन बातों में पाठकों की रुचि का होना स्वाभाविक है।

पहली पंचवर्षीय योजना

समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के लिए शुरू के ४ वर्ष आरम्भिक तैयारी में व्यतीत हो गये। १९५३ में चीन ने प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार निर्माण कार्य आरम्भ किया। योजना का अंतिम वर्ष १९५७ है, लेकिन योजना के अधिकांश लक्ष्य १९५६ याने चौथे वर्ष में ही पूर्ण हो गये।

योजना के पहले ४ वर्षों में चीन ने समाजवाद की दिशा में भारी सफलता कृषि क्षेत्र में प्राप्त की है। चीन भारत की तरह ही एक कृषि प्रधान देश है। वहां के ८० प्रतिशत लोग किसान हैं। बड़ी जनसंख्या के भरण-पोषण के लिये कृषि-उपज बढ़ानी आवश्यक है। इसके लिए कृषि-पद्धति में अनेक आवश्यक परिवर्तन किये गये।

सहकारी कृषि

कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन था—निजी खेती का सहकारी खेती में बदलना। पहले इसकी गति बहुत मंद रही, इसका कारण शासक वर्ग की किसानों की प्रति अनुदारता-पूर्ण मनोवृति थी। लेकिन १९५६ में कम्यूनिस्ट पार्टी ने सरकार की इस मनोवृत्ति की आलोचना की, अतः सरकारी नीति में सुधार हुआ और तीव्र गति से सहकारी कृषि का विस्तार होने लगा। १९५६ के अन्त तक १ करोड़ १० लाख कृषक या कुल का ९२ प्रतिशत सहकारिता के अंतर्गत आ गये। १ करोड़ ट्रेक्टर भूमि अथवा कुल कृषि क्षेत्र का ९० प्रतिशत भूमि पर सहकारिता आरम्भ हो गयी।

पूंजीवाद का उन्मूलन

चीन में अभी तक पूंजीवाद खूब फलता-फूलता रहा है। नई समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने के लिये इस पूंजीवाद का उन्मूलन आवश्यक है। चीन में पूंजीवादी उद्योगों के हस्तांतरण का आन्दोलन पिछले १-२ वर्षों से

"आप तो मेरे नाम से सम्पदा भेजना शुरू कर दें?"

अर्थशास्त्र के एक विद्यार्थी का पत्र

माननीय महोदय,

यों कालेज के वाचनालय में सम्पदा आती है, पर उससे मुझे बहुत लाभ नहीं होता, क्योंकि मेरे कुछ सहपाठी सम्पदा के आते ही उस पर इतना झपटते हैं कि पढ़ने को ही नहीं मिलती। दो चार दिनों में ही कुछ चालाक लड़के उसके उपयोगी लेख फाड़ कर ले जाने लगते हैं और अन्त में तो टाइटिल व विज्ञापनों के ही पृष्ठ रह जाते हैं। इसलिए मेरे नाम से निम्नलिखित पते पर आप सम्पदा भेजना शुरू कर दें।

आपका—
विजय, तीसरा वर्ष

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चल रहा है। इसके अनुसार बिना मुआवजा दिये निजी उद्योगों पर कब्जा कर लेना है। पर यह कब्जा जोर जबरदस्ती से नहीं, 'शांतिपूर्वक' किया जायेगा। इसी प्रकार निजी व्यापार को भी सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है। इनकी पहली अवस्था निजी और सरकार का संयुक्त स्वामित्व है।

१९५६ में धीरे-धीरे शांतिपूर्ण उपायों से पूंजीवादी उद्योगोंके हस्तान्तरण की नीति का फो सफल रही। पूंजीवादी उद्योगों का ९९ प्रतिशत उत्पादन सरकार की देखरेख और आदेशों के अनुसार किया गया था। २००० उद्योगों को सरकारी और निजी दोनों के संयुक्त स्वामित्व में परिवर्तित किया गया। १९५६ में अधिकांश उद्योग संयुक्त स्वामित्व के अधीन आ चुके थे।

उद्योगों के हस्तांतरण की इस नीति का आधार 'राज्य का पूंजीवाद' का सिद्धान्त है। लेनिन का कहना था कि इस मार्ग (राज्य के पूंजीवाद) से श्रमिक वर्ग को समाजवादी स्वामित्व प्राप्त हो जायेगा। उसका यहां तक विचार था कि साम्यवाद के तीव्र प्रसार के लिये यह सर्वश्रेष्ठ साधन है। लेकिन उस समय की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण रूसी कम्युनिस्टों ने लेनिन के विचार को त्याग दिया और पूंजीवाद का जबरदस्ती उन्मूलन किया गया। लेकिन चीन की परिस्थितियां भिन्न हैं। अतः निजी उद्योगपतियों का राष्ट्र के विकास हित में सहयोग पाना आवश्यक हो गया है।

इन सब का परिणाम यह है कि मनुष्य के शोषण की आर्थिक प्रणाली चीन की धरती से बहुत हद तक लुप्त हो गई है और राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था का आधार बुनियादी तौर पर समाजवादी बन गया है।

उत्पादन में वृद्धि

समाजवाद की दिशा में इस महान प्रगति के साथ-साथ चीन में उत्पादन में भी आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। इस वर्ष ३० जून को प्रकाशित संयुक्त राज्य संघ की विश्व की आर्थिक रिपोर्ट में कहा गया है कि औद्योगिक वृद्धि जितनी तेजी से चीन में हुई, उतनी इसी समय में पृथ्वी के और किसी देश में नहीं हुई। वास्तविक आंकड़ों में औद्योगिक उत्पादन का कुल मूल्य ५८ अरब ६६ करोड़ युआन था अर्थात् १९५५ की तुलना में १३ अरब १० करोड़ युआन या ३१ प्रतिशत अधिक। यह वृद्धि १९४९ के कुल औद्योगिक उत्पादन से २८ प्रतिशत अधिक है।

नई दृष्टि

समाजवाद को दृष्टि में रखते हुए चीन का एक महत्वपूर्ण कार्य है 'साम्यवाद' को एक नई दिशा देना। बहुत समय नहीं हुआ चीन के राष्ट्रपति श्री माओ त्से तुंग के इन शब्दों 'सैकड़ों फूलों को खिलने दो और विचारों को पनपने दो !!'' पर सारे विश्व में गम्भीर प्रक्रिया हुई थी।

साम्यवादी शासन अपने एकदलीय अधिनायकत्व तथा कठोर अनुशासन के लिये प्रसिद्ध है। वहां विरोधी राजनैतिक दलों के लिये कोई स्थान नहीं है। रूस ही नहीं, अन्य साम्यवादी देशों में भी एक ही राजनैतिक दल—कम्युनिस्ट पार्टी का एकमात्र संगठन रहने दिया जाता है। चीन में भी यही स्थिति है। चीन के ही अध्यक्ष श्री माओ त्से तुंग ने फूलों को खिलने और विचारों को पनपने की दृष्टि व्यक्त करके साम्यवाद की अब तक की मान्यताओं या उसकी मौलिक धारणाओं पर गहरी चोट की है। ऐसा समझा जा रहा है कि चीन का साम्यवादी शासन उदार और सहिष्णु बनना चाहता है। इस प्रकार साम्यवाद के प्रवर्तक रूस की पद्धति से चीन शायद कुछ दूर सा हो रहा है।

विचारों की स्वतन्त्रता

सब को विचारों की स्वतन्त्रता हो और इसमें सरकार की कोई जोर-जबरदस्ती न हो, श्री माओ ने इन विचारों को प्रकट करते हुए कहा था कि, "मत-परिवर्तन के लिये लोकतन्त्री और शांतिपूर्ण तरीकों का अवलम्बन किया जाना चाहिए। ये तरीके हैं—विचार-विनिमय, समझाना, बुझाना, तर्क करना और शिक्षा देना। प्रशासकीय आदेशों से दबाव डालकर आदर्श सम्बन्धी विचारों को बदलने में विफलता हाथ लगेगी। यही नहीं, उल्टे इससे हानि भी हो सकती है।"

साम्यवादी देशों में शिक्षा-दीक्षा ही इस उद्देश्य से होती है कि शिक्षार्थियों के विचारों को साम्यवाद के अनुरूप ढाला जाये। विज्ञान और कला के क्षेत्र आदर्श

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"साम्यवाद के प्रति आस्था" ही माने जाते हैं। सम्भवतः इन्हीं को चुनौती देते हुए श्री माओ ने कहा कि—"हमारे विचार से कला और विज्ञान की उन्नति के लिये यह हानिकारक है, यदि शासन विशेष प्रकार के कला और विज्ञान सम्बन्धी विचारों पर रोक लगाये।"

वर्ग-संघर्ष विद्यमान

साम्यवाद के सम्बन्ध में श्री माओ ने दो महत्त्वपूर्ण बातें कहीं। पहली यह कि साम्यवादी-व्यवस्था में पारस्परिक विरोध है तथा वर्ग-संघर्ष अभी विद्यमान है। चीन का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि वहां सामूहिक हित और व्यक्ति के हित में विरोध है। यह विरोध लोकतन्त्र और केन्द्रीय सत्ता में, नेताओं और अनुयायियों में, राज्याधिकारियों के नौकरशाही तरीकों में और जनता में भी स्पष्ट है। १९५६ में कुछ मजदूरों और छात्रों ने अपनी मांगों की पूर्ति न होने के कारण हड़ताल की। यह भी महत्त्वपूर्ण है कि चीन ने अन्य साम्यवादी देशों की तरह हड़ताल को 'असाम्यवादी' नहीं माना है। चीन में हड़ताल का रूप यह है कि "इस प्रकार की घटनाओं से हमें फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि इनसे नौकरशाही से मुक्त होने में सहायता मिलती है।" चीन का नौकरशाही से मुक्त होने का अभियान साम्यवाद के लिये बिल्कुल नई चीज है, क्यों कि साम्यवादी शासन-पद्धति में सरकारी मशीनरी का काफी आश्रय लिया जाता है, यह अनिवार्य भी है।

चीन में वर्ग-संघर्ष मिटा नहीं। चीन ही में क्यों, श्री माओ का कथन तो यह है कि साम्यवादी व्यवस्था में वर्ग-संघर्ष है ही। पर इतना अवश्य है कि पूंजीवादी समाज और साम्यवादी समाज के वर्ग-संघर्ष में अंतर है। पूंजीवाद में वर्ग-संघर्ष तीव्र है, लेकिन साम्यवाद में यह संघर्ष सौम्य है। इस विषय में उल्लेखनीय बात यह है कि चीन में पूंजीपतियों और जमींदारों को मताधिकार प्राप्त नहीं है। न ही उन्हें विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है।

निजी व्यवसाय भी

चीन की आर्थिक नीति के विषय में श्री माओ के विचार भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। ज्ञात होता है कि चीन

चीन के प्रधान मंत्री

श्री चाऊ एन-लाई

में निजी औद्योगिक और व्यापारिक प्रयासों का स्थान है। वहां के सरकारी और निजी उद्योगों में पूंजीपतियों को उनकी पूंजी पर निश्चित ब्याज मिलता है। अब भी पूंजीपतियों और मजदूरों में विचारों की भावनाओं और आदतों में बड़ा वैषम्य है। इसी कारण पूंजीवाद को पूर्णतः समाप्त करके समाजवाद स्थापित करने में चीन ने कोई जल्दबाजी नहीं की, यद्यपि शोषण समाप्त कर दिया गया है। इसका कारण यह है कि एक तो लोगों को 'नये ढांचे' से परिचित होने में काफी समय लगेगा और दूसरे सरकारी कर्मचारी अभी पूर्ण अनुभवी नहीं हैं।

श्री माओ ने व्यापारियों और उद्योगपतियों को स्मरण कराया है कि उनको नये विचारों के अध्ययन करने और उसके अनुसार बदलने का प्रयत्न करना चाहिए।

चीन की सहकारी कृषि के संबंध में चीन में ही कुछ लोग इसकी श्रेष्ठता पर आशंका करते हैं। श्री माओ के कथन से ऐसी ध्वनि निकलती है। श्री माओ ने इसीलिये इनको उत्तर दिया है कि "हमारा सहकारिता का आन्दोलन सुदृढ़ आन्दोलन है। हां इसकी पूर्ण सफलता प्राप्त करने में ५ वर्ष या कुछ अधिक भी लग जायेंगे। अभी तो इसको

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आरम्भ किये एक ही साल हुआ है। अतः इतनी जल्दी फल-प्राप्ति की इच्छा करना ठीक नहीं।''

सह-अस्तित्व

श्री माओ ने चीन को तीव्र आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति का मूल तन्त्र ही ''दीर्घकालीन सह-अस्तित्व'' और और पारस्परिक पर्यवेक्षण (Mutual Supervision) माना है। इसी में एक मार्के की बात श्री माओ ने यह कही कि ''पारस्परिक सह-अस्तित्व'' हमारी ऐतिहासिक परिस्थितियों की देन है। चूंकि प्रत्येक साम्यवादी देश की परिस्थितियां विभिन्न हैं, उनकी साम्यवादी पार्टियां भी अलग-अलग हैं। हम यह नहीं कहते कि दूसरे (साम्यवादी) देशों और साम्यवादी पार्टियों को चीन का ही तरीका अपनाना चाहिए।'' साथ ही उन्होंने कहा कि चीन विश्व के समस्त देशों से 'सीखने' की इच्छा करता है, लेकिन अभी तो उसे रूस से बहुत कुछ सीखना है।'' स्पष्ट है कि अवसर पड़ने पर चीन 'दूसरे देशों' के अनुभवों से भी लाभ उठा सकता है।

चीन आज हमारी तरह ही अपने आर्थिक नव-निर्माण में संलग्न है। इस दिशा में उसको जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, वह बहुत कुछ भारत जैसी हैं। चीन को भी पूंजी की आवश्यकता है, और भारी मशीनों की आवश्यकता है। इसके लिए उसे आजकल केवल रूस ही सहायता प्रदान कर रहा है। पर श्री माओ के इन विचारों से ज्ञात होता है कि चीन भविष्य में इतनी कट्टरता न बरतेगा। 'सह-अस्तित्व' में उसका विश्वास दृढ़ है। अतः यदि रूस के अतिरिक्त अन्य गैर साम्यवादी देश उसको सहायता प्रदान करें तो वह स्वीकार करने में संकोच न करेगा। अभी-अभी इंगलैंड और चीन के बढ़ते हुए व्यापारिक सम्बन्धों से यही सिद्ध होता है। जापान और पश्चिमी जर्मनी भी चीन से व्यापरिक सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं। यह कहा जा सकता है कि चीन में देशी पूंजीपतियों का अस्तित्व तो है ही, लेकिन यदि विदेशी पूंजीपति भी चीन के आर्थिक नव-निर्माण में सहायता दें, तो चीन सहर्ष ग्रहण करेगा, यदि उसके हित के विपरीत न हो।

चीन के प्रधान श्री माओ त्से तुंग के इन नवीन विचारों से गैर साम्यवादी देश यह मानने लगे हैं कि चीन में रूस जैसी 'कट्टरता' नहीं और न ही उसका रास्ता बिलकुल रूस जैसा है। अपनी परिस्थितियों के अनुसार चीन का यह अपना समाजवाद है।

नई दिल्ली व दिल्ली में सम्पदा

सम्पदा के फुटकर अंकों और विशेष कर विशेषांकों की मांग अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों में बनी रहती है। उनकी सुविधा के लिए आत्माराम एण्ड सन्स, काश्मीरी गेट, दिल्ली (हिन्दी विभाग) में सम्पदा की बिक्री की व्यवस्था कर दी गई है।

नई दिल्ली में सम्पदा के विक्रेता सेंट्रल न्यूज एजेंसी, कनाट सर्कस हैं।

इस प्रबन्ध से आशा है, दिल्ली के अर्थशास्त्र-प्रेमियों की असुविधा दूर हो जायगी।

— मैनेजर सम्पदा

अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

यूगोस्लाविया में

समाजवाद का नया परीक्षण

श्री अवनीन्द्र कुमार

कार्ल मार्क्स का समाजवाद या साम्यवाद विभिन्न देशों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के भेद से, विभिन्न रूप धारण कर सकता है, इस सत्य को यूगोस्लेविया ने मार्शल टीटो के नेतृत्व में स्वीकार कर लिया है।

यूगोस्लेविया का अपना समाजवाद

यूगोस्लेविया में समाजवाद के जिस रूप का विकास हो रहा है, वह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थितियों का परिणाम है और बाहरी दवाब के कारण उन्होंने यह मार्ग पकड़ा है। इसको यूगोस्लोविया स्वीकार नहीं करता। उसका कहना है कि यूगोस्लेविया में समाजवाद का जो रूप विकसित हो रहा है वह वहां की आन्तरिक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का फल है। निस्सन्देह बाह्य प्रभाव भी उसको प्रभावित करते रहते हैं, किन्तु उनका प्रभाव वैसे ही होता है, जैसे कि बाग में लगे वृक्षों पर आकस्मिक आई आंधी और आये तूफान का असर होता है। यथार्थ स्थिति को दुर्लक्ष्य कर कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता।

यूगोस्लेविया दूसरे महायुद्ध से पूर्व एक पिछड़ा देश था। अविकसित और आयात पर जीने वाला एक देश था।

यूगोस्लेविया में जन-क्रान्ति के बाद उत्पादन के साधनों पर राज्य का अधिकार और नियंत्रण हो गय। इस समय यूगोस्लोविया के सामने समस्या आई कि वह किस मार्ग का अनुसरण करे। पीछे लौटने का अर्थ था क्रान्ति का अन्त और प्रतिगामी शक्तियों के प्रतीक राजतंत्र की पुनः स्थापना। पश्चिमी लोकतंत्र का मार्ग अपनाना सम्भव नहीं था, क्योंकि देश में मध्यम वर्ग का लगभग अभाव था। तीसरा मार्ग था स्तालिन मार्ग। इसमें राज्य के हाथ में सारी शक्ति केन्द्रित थी, राज्य और जनता की इच्छा यहां एक हो गए थे। वैयक्तिक पूंजीवाद की जगह राज्यकीय पूंजीवाद ने स्थान ले लिया था। नौकरशाही का राज्य था। मजदूर और किसान एक बड़ी मशीनरी के कल-पुर्जे थे। उनका कोई स्वतन्त्र व्यक्तित्व नहीं था। निर्णयों में, दिशा-निर्देशन में, प्रोग्राम बनाने और योजनाओं को विचारने में उनका कोई मान नहीं था। पूंजीवाद से समाजवाद के स्थापना की ओर संक्रमण काल में तो यह ठीक था, और यह स्थिति संक्रमण काल के लिए ठीक है, किन्तु समाज में समाजवादी भावना को सदा जगाए रखने, और सामाजिक चैतन्य द्वारा आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने का यह उपाय नौकरशाही के शासन तथा उसकी सर्वोच्च सत्ता को पुनः स्थापित करता है। अतः यूगोस्ललेविया ने एक नया मार्ग पकड़ाः—

"मुरारेस्तृतीयः पन्था"

एक नया मार्ग—मजदूर कौंसिल

राज्य को प्रबन्ध और संचालन का भार देना खतरे से खाली नहीं है। इसका अर्थ है "समाज के ऊपर सरकारी सत्ता"। अतः राजनीतिक लोकतंत्र के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र और समाजवादी आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए यूगोस्लेविया ने सोवियत रूस की केन्द्रीय समाजवादी प्रणाली का त्याग कर दिया और एक ऐसी समाजवादी प्रणाली का विकास करने का प्रयत्न किया है, जिससे धीरे-धीरे क्रमिक विकास के रूप में राज्य की सत्ता का सर्वथा नहीं तो बहुत कुछ सामाजिक और आर्थिक जीवन में लोप हो जायगा। इसकी पहली सीढ़ी है, मजदूर-कौंसिल की स्थापना।

यह मजदूरों को आर्थिक व्यवस्था का संचालन करने में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने का अवसर प्रदान करती है।

यह समाजबादी क्रान्ति द्वारा प्राप्त अधिकारों का विस्तार करने और सामाजिक जीवन में उपयुक्त पार्ट अदा करने का मौका देती है।

प्रशासकीय प्रबन्ध द्वारा आर्थिक व्यवस्था का संचालन करने से जिन खतरों के उत्पन्न होने की आशंका है, उनसे इसमें बचा जा सकता है।

मजदूर कौंसिल की स्थापना के पीछे एक भावना काम कर रही है। जीवन और समाज के प्रत्येक क्षेत्र में मजदूरों का—कर्म करों का स्वायत्त शासन स्थापित हो। दूसरा आदर्श यह काम कर रहा है कि राज्य के हस्तक्षेप से यह मुक्त रहे।

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प में स्थापित हो, इसके लिए यह जरूरी है कि व्यक्ति को उपक्रमण-शक्ति से वंचित न किया जाय। यह विकेन्द्रीकरण में ही संभव है। अतः मजदूर कौंसिल की स्थापना की गई है।

मजदूर एवं कर्मकर अधिक से अधिक उत्पादन करें, उत्पादन शक्ति बढ़े और प्रत्येक का और उद्योग का हित सुरक्षित रहे, इस पर विचार करने और [illegible] जदूर कौंसिल पर है। इस दृष्टि से प्रत्येक कल-कारखाना व उद्योग आत्म-पूरित है। निस्सन्देह इनका संचालन निर्धारित सामान्य सिद्धांतों और नियोजन के अनुसार होता है। विशुद्ध आय—उत्पादन-व्यय और मजदूरों का मूल वेतन घटाने के बाद बची राशि—समाज की होती है, समूह और व्यक्ति की दोनों की एक साथ। संघ कानून, और संघ के नियोजन, राज्य, कम्यून, (भारत की तहसील के समान), सम्बन्धित उद्योग, मजदूरों और कर्मचारियों द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार शेष समस्त आय का वितरण होता है। विशुद्ध आय का वितरण इस रीति से होता है। इसका एक अंश मजदूरों और कर्मचारियों में उनके वेतन और उनके द्वारा किये गये काम के अनुसार वितरित किया गया है, एक भाग उद्योग के फण्ड में जमा किया जाता है, जिससे उसका विस्तार हो, और उसकी तरक्की हो। एक अंश सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने में लगता है—जैसे गृहनिर्माण आदि और इसका निर्णय मजदूर कौंसिल स्वतः करती है। इस ढांचे के अन्दर उद्योग अपना कार्य करने को स्वतन्त्र है। कोई प्रशासकीय मशीनरी नीति का निश्चय न करेगी। यह उन्मुक्त बाजार में अपने माल की अच्छाई और सस्तेपन के आधार पर प्रतियोगिता करने को स्वतंत्र है। उद्योग का प्रबन्ध और संचालन प्रबन्ध समिति और मजदूर कौंसिल सामूहिक रूप से करती है। मजदूर सामूहिक रूपसे एक स्थान के वास्ते मजदूर कौंसिल के सदस्यों को चुनते हैं।

मजदूर कौंसिल कारखाने व उद्योग चलाने के लिए प्रबन्ध समिति को चुनती है। यह कार्यपालिका है, जो मजदूर कौंसिल के निर्णयों के अनुसार काम करती है और उद्योग का संचालन करती है। इसका कोई भी सदस्य एक साल से अधिक के लिए सदस्य नहीं हो सकता।

प्रबन्धक प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा चुना जाता है। उसका चुनाव मजदूर परिषद के प्रतिनिधियों और 'पीपल्स कमेटी' के प्रतिनिधियों का सम्मिलित बोर्ड करता है। 'पीपल्स कमेटी' साधारणतः पेशे व धंधों के संघों और अन्य लोगों में से अपने प्रतिनिधि चुनती है। जब उद्योग बड़ा होता है या विशेष प्रकार का होता है तो मैनेजर के चुनाव करने वाले बोर्ड में रिपब्लिकन या फेडरल सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। राज्य में कोई औद्योगिक बोर्ड नहीं, जिसके अधीन कल-कारखाने व मजदूर परिषद हों; लेकिन व्यापार मण्डल और आर्थिक परिषदें हैं और उसके ये कल-कारखाने और मजदूर कौंसिलें सदस्य हो सकती हैं। ये उनके सहयोग से अपना उत्पादन बढ़ा सकती हैं। ये विभिन्न सामान्य आर्थिक शिल्पिक सेवाएं और इसी उद्देश्य को पूरा करने वाली संस्थाएं भी बना सकती है।

नीति-निर्धारण का कार्य

मजदूर कौंसिल उद्योग की आर्थिक नीति का निर्धारण करती है। उसको क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी मैनेजर पर होती है। साधारणतः मजदूर कौंसिल योग्य मैनेजर और कार्यकारी विभाग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती। मजदूर कौंसिल निश्चय करती है कि इस चीज का उत्पादन किया जाय। मैनेजर और उसका शिल्पिक विभाग उत्पादन करने की योजना और प्रक्रिया तैयार करता है और मजदूरों तथा कर्मचारियों को काम बांट देता है। मजदूर कौंसिल मैनेजर के निर्णय में परिवर्तन नहीं करती। मैनेजर भी औद्योगिक आर्थिक नीति के विषय में मजदूर कौंसिल और प्रबन्धक समिति के सामने अपने विचार, प्रस्ताव और सुझाव पेश कर सकता है। मैनेजर का काम यदि असन्तोषजनक हो तो मजदूर कौंसिल उसको अलग कर सकती है और नए प्रार्थना पत्र मंगा सकती है। किन्तु अन्तिम निर्णय उस जगह की 'पीपल्स कमेटी करती है, जिस क्षेत्र में वह कारखाना और उद्योग होता है।

१९५५ से पहले वेतन का निर्णय केन्द्रीय अधिकारी करते थे। किन्तु अब इसका निर्णय 'कम्यून' और उद्योग परस्पर मिल कर करते हैं। वेतन और मजदूरी के नियमों का निर्माण कारखाना व उद्योग की प्रबन्धक समिति करती है। यह कार्य वह मजदूर कौंसिल के सदस्यों के निर्वाचकों

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

की सलाह से करती है। यह मशविरा फिर मजदूर कौंसिल के सामने रखा जाता है। यही नहीं यह ट्रेड यूनियनों और पीपल्स कमेटी के सामने भी पेश होता है। कम्यून यह देखता है कि वेतन इतना न बढ़ जायं कि उसका अपना फण्ड कम हो जाय। ट्रेड यूनियनें इस बात पर नजर रखती हैं कि मजदूर के वेतन का स्तर न गिरने पाय।

'कम्यून' अत्यधिक महत्वपूर्ण संस्था है। आर्थिक विकास के क्षेत्र में इसको पूर्ण स्वतन्त्रता है। फिर अपने क्षेत्र की सब मजदूर कौंसिलों और उत्पादकों की अन्य स्वायत्त संस्थाओं के साथ इसका सम्बन्ध है। कम्यून केवल एक राजनीतिक इकाई नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक अवयव है और धीरे-धीरे इसका राजनीतिक रूप गौण हो जायगा। कम्यून के द्वारा ही शेष लाभ का वितरण किया जाता है। 'पीपल्स कमेटी' कम्यून और जिले की राजनीतिक और आर्थिक सर्वोपरि संस्था है। जिले की पीपल्स कमेटी' के दो सदन होते हैं : (१) जिला कौंसिल और (२) उत्पादक कौंसिल।

बीच का मार्ग

संयुक्त राज्य अमेरिका ने ब्रिटिश शासन प्रणाली के दोषों और राजा के वर्चस एवं उसकी प्रभुता को ध्यान में रख कर अपना संविधान और अपनी सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार की रखी कि जिसमें पूर्ण वैयक्तिक स्वातन्त्र्य हो, और प्रशासन, न्याय और कानून बनाने का कार्य सर्वथा अलग रहे। ये तीनों अब तक स्वतन्त्र रहे। यूगोस्लेविया के सामने एक ओर पश्चिमी यूरोप के देश थे, जहां लोकतन्त्र तो था किन्तु उत्पादन के साधनों पर समाज का पूर्णतः स्वत्व नहीं था और मजदूर संस्थाएं उसके लिए यत्न कर रही थीं। दूसरी ओर सोवियत रूस था, जहां मूर्तिमान कम्युनिज्म था, किन्तु उत्पादन के साधनों पर राज्य का अधिकार था और एक पार्टी ने ही जनता की इच्छा का रूप धारण कर लिया था और वह पूर्णतः राज्य एवं प्रशासन का अंग बन गई थी। यहां नीति-निर्माण, कार्य संचालन और निर्देशन तथा निरीक्षण ये सब कार्य केन्द्रीय सत्ता के आधीन थे और मजदूर, किसान व अन्य उत्पादक किराये पर काम करने वाले मजदूर मात्र थे। यूगोस्लेविया ने इन दोनों के बीच का मार्ग अपनाया। उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वत्व स्थापित किया गया। किन्तु उपक्रमण, नियंत्रण निर्माण, योजना बनाने और निरीक्षण का अधिकार व्यक्तियों से छीना नहीं और उत्पादन के साधनों पर वास्तविक उत्पादकों का अधिकार स्थापित किया। मजदूर कौंसिलों और उत्पादक कौंसिलों का देशों और धंधों, आर्थिक कौंसिलों, व्यापार व्यवसाय वाणिज्य मण्डलों से सम्बन्ध है और ये इस प्रकार मिल कर एक सूत्री योजना-उत्पादन का निर्माण करते हैं और अपने-अपने कामों के मध्य एक-सूत्रता स्थापित रखते हैं। यह संघटन लम्ब रूप या शिखर नुमा है। व्यक्ति और समाज में हितों के बीच अंतर्द्वन्द्व को मिटाने का भार भी व्यक्तियों और समूहों को दिया गया है। राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता को शनैः शनैः हटाया जा रहा है और राज्य के प्रभाव से मुक्त किया जा रहा है।

समाजवाद का नया प्रयोग

यूगोस्लेविया मानव-समाज के' इतिहास में एक नया परीक्षण कर रहा है। वह एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहा है, जो अपना आर्थिक, एवं सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक विकास स्वतः करेगा और राज्य के निर्देशन की अपेक्षा न रखेगा। इसमें अभी समय लगेगा। किन्तु यूगोस्लेविया ने व्यक्ति और समाज के हितों को मध्य समरसता और सामंजस्य स्थापित करने का एक मार्ग ढूंढा है, जो कि वहां फल फूल रहा है और मानव समाज में एक नूतन आशा को उद्दीप्त कर रहा है। यह हमारे पंचायती राज्यों से बहुत कुछ मिलता है। इतिहास बताता है कि जहां शासन-सत्ता चोटी के कुछ व्यक्तियों में केन्द्रित थी, वे देश और उनकी सभ्यताओं का भी अंत हो गया, पर जिन देशों में सोचने, विचारने, कार्य करने का अधिकार अधिक से अधिक लोगों को दिया, वे जीवित रहे। एशिया के कवि इकबाल ने पूछा था, वह रहस्य क्या है जिसके कारण मिश्र यूनान, बैबीलोन, असीरिया के मिट जाने पर भी हिन्दुस्तान जिन्दा है, इसका उत्तर यही है कि सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन को सतत और निरन्तर रखने और शक्ति देने वाली पंचायतें बनी रहीं और इस कारण भारत जीवित रहा। यूगोस्लेविया ने इस सत्य को समझा है, और 'कम्यूनों' के रूप में उसने वैयक्तिक स्वतंत्रता

[सम्पादा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अमेरिका में जनता का पूंजीवाद

कुछ उल्लेखनीय प्रबल तथ्य

श्री वेदप्रकाश सिंह

'जनता के पूंजीवाद' और अमेरिका में उसके अद्भुत विकास के सम्बन्ध में लोग बहुधा जो प्रश्न पूछा करते हैं, वे इस प्रकार हैं—

१. हम जिन हालतों में किसी अर्थ-व्यवस्था को 'जनता का पूंजीवाद' कह सकते हैं, इस प्रकार की अर्थ-व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

२. अमेरिका के प्रचुर प्राकृतिक साधन-स्रोतों, तथा इसी प्रकार के अन्य कारणों ने अमेरिका के आर्थिक विकास में किस सीमा तक योग दिया है ?

३. अमेरिका की आर्थिक समृद्धि ने अमेरिका वासियों के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास में कहां तक योग प्रदान किया है ?

४. क्या अमेरिका के ढंग के 'जनता के पूंजीवाद' का विकास संसार के अन्य देशों में भी सम्भव है ?

प्रस्तुत लेख में इन्हीं प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर देने का प्रयत्न किया जायेगा।

जनता के पूंजीवाद का आशय

सामान्यतः पूंजीवाद से हमारा अभिप्राय एक ऐसी अर्थ-व्यवस्था से रहता है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार रोजगार में पूंजी लगाने और कारोबार करने की पूरी स्वतन्त्रता हो। यह भी आवश्यक है कि कारोबार की मण्डियों पर किसी भी प्रकार की पाबन्दी न हो और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के सिद्धान्त पर देश के व्यवसायियों को अपने कारोबार और उद्योगों का विकास करने के पूर्ण अवसर मिलें। संक्षेप में आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति को उतनी ही स्वतन्त्रता प्राप्त हो, जितनी स्वतन्त्रता का उपभोग वह

रूसी समाजवाद के अतिरिक्त अमेरिकन पूंजीवाद की नई दिशा भी एक महान परीक्षण है, जिसमें जनता का एक बहुत बड़ा भाग, जो निरंतर बढ़ रहा है, शेयर लेकर उद्योग का स्वामी बनता जाता है और इस तरह बड़े कल कारखानों या कम्पनियों का लाभ कुछ पूंजीपतियों में केन्द्रित न होकर जनता में वितरित होने लगता है और बिना सरकारी कानून, बाध्यता अथवा व्यक्ति-स्वातन्त्र्य का अपहरण हुए मजदूर उद्योग के स्वामी बनते जा रहे हैं, वे भी घरों में रेडियो रखने और अपनी मोटरों पर सैर सपाटे करने लगे हैं।

और सामाजिक प्रगति में केवल अविरोधी ही नहीं, अपितु दोनों में सामंजस्य भी स्थापित किया है। मानव-समाज का समान विकास हो, इसका अभिलाषी प्रत्येक व्यक्ति इस नूतन परीक्षण का अभिनन्दन करेगा, यह निःशंक होकर कहा जा सकता है।

मतदाता की हैसियत से राजनीतिक क्षेत्र में करता है। इस प्रकार की अर्थ-व्यवस्था में ऐसा लचीलापन आ सकता है कि समय और परिस्थितियों के अनुसार वह अपने स्वरूप में आवश्यक फेर बदल कर ले। उदाहरणार्थ युद्ध का संकट आने पर वह अधिकाधिक तेज गति से युद्धकालीन भार वहन करने में समर्थ हो जाये और युद्ध समाप्त होने पर बिना किसी कठिनाई के अपने शान्तिकालीन स्वरूप को पुनः ग्रहण कर ले।

इन सब बातों के अलावा यह भी आवश्यक है कि इस अर्थ-व्यवस्था का संचालन करने वाले सभी व्यक्ति पारस्परिक सहयोग और समझौते की भावना रख कर कार्य करें। ऐसा करने पर ही जनता के सभी वर्ग इससे प्राप्त लाभों का अधिकाधिक परिमाण में उपभोग कर सकेंगे। इस अर्थ-व्यवस्था की इन कुछेक अनूठी विशेषताओं के कारण ही हमें इसे जनता का 'पूंजीवाद' की संज्ञा देनी पड़ी है। संक्षेप में पूंजीवाद अब जनता का शोषक नहीं रहा। अब वह देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को दृष्टि में रख कर और समाज की उन्नति और समृद्धि के लक्ष्य को अपना कर ही अपनी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नीति और कार्यक्रम निर्धारित करता है। दूसरे शब्दों में यदि देश में सम्पत्ति का व्यापक और संतुलित वितरण है तो हम उसे 'जनता का पूंजीवाद' की संज्ञा दे सकते हैं।

साधनों का विकास में योग

अब दूसरा प्रश्न यह उठता है कि अमेरिका के विशाल साधन-स्रोतों ने तथा विशिष्ट भौगोलिक स्थिति ने उसके विकास में किस सीमा तक योग दिया है?

इस सम्बन्ध में सबसे पहली उल्लेखनीय बात यह है कि यूरोप के कुछ अत्यधिक साहसी लोग व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और प्रतिष्ठा के सिद्धान्तों को जीवित रखने के लिए अपार कठिनाइयों को झेलते हुए नई दुनिया में पहुँचे थे और इन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर उन्होंने अमेरिका

> जो मनुष्य कानून बनाने वाली संस्थाओं और म्युनिसपैलिटियों को घूंस देकर व शेयर होल्डरों और साधारण जनता को लूट कर कोष एकत्र करता है, वह सदाचार के पलड़े में उतना ही ओछा है, जितना कि वह घृणित व्यक्ति जो जुआ-घर, मदिरालय के रुधिर से मिश्रित रुपयों को खाकर पुष्ट और धनी होता है।
>
> —रूजवेल्ट

में एक नये समाज और राष्ट्र की नींव डाली। उस समय अमेरिका के साधनस्रोतों का तनिक भी विकास नहीं हुआ था और वहां जंगलों, पर्वतों और वनाच्छादित प्रदेश के अतिरिक्त कुछ नहीं था। इन अदम्य और साहसी व्यक्तियों ने अपने कठोर परिश्रम से नई दुनिया का स्वरूप बदल दिया। पहले लोग मुख्यतः कृषि पर ही आधारित थे और उन्हें खेती करने के लिए पर्याप्त भूमि सुलभ थी।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यूरोपवासी यहां शोषण करने की दृष्टि से नहीं, बल्कि इसे अपना घर बनाने की दृष्टि से आये थे। इसलिए यहां की स्थिति स्पेनिश अमेरिकी प्रदेशों से सर्वथा भिन्न थी, जहां स्पेनवासियों का मुख्य उद्देश्य उचित और अनुचित उपायों द्वारा सोना लूट कर स्वदेश वापस लौट जाना था।

इसके अतिरिक्त अमेरिका में आकर बसने वाले व्यक्ति नैतिकता और पुरुषार्थ में विश्वास करते थे और आलस्य के कट्टर शत्रु थे। यदि वे पुरुषार्थी और साहसी न होते तो इतने अल्प समय में इतने विशाल महाद्वीप पर विजय प्राप्त करना किसी प्रकार भी सम्भव न होता।

इसके अलावा यह बात भी उल्लेखनीय है कि, अमेरिका में उतरते ही प्रवासियों को खनिज पदार्थों के विशाल भण्डार नहीं मिल गये। प्रारम्भ में प्रवासियों को खेती और समुद्र द्वारा ही अपनी जीविका का उपार्जन करना पड़ा। महाद्वीप में दूर तक प्रवेश करना और खनिज-साधनों का विकास करना इन प्रवासियों के साहस, परिश्रम और पुरुषार्थ की अनूठी कहानी है।

सांस्कृतिक विकास

तीसरा और महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि अमेरिका की आर्थिक समृद्धि ने अमेरिका वासियों के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास में कहां तक योग दिया है।

अमेरिका में लोगों को अपने व्यक्तित्व का विकास करने के अनूठे अवसर प्राप्त हुए हैं। यद्यपि इन सभी अवसरों का अभी समुचित ढंग से उपयोग नहीं किया जा सका है, परन्तु जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने और लोगों को शिक्षा, मनोरंजन इत्यादि की सुविधाएं सुलभ करने में अमेरिका वासियों ने आशातीत प्रगति की है।

आज अमेरिका में कोई भी बालकों से श्रम नहीं करा सकता। सभी बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त सुविधाएं सुलभ की गई हैं, और उच्च-शिक्षा प्राप्त करने के मार्ग में भी अमेरिकी युवाओं को किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। जीवन-स्तर और रहन-सहन में सुधार करने के साथ-साथ अमेरिका-वासियों ने विशाल संग्रहालयों, पुस्तकालयों, संगीत कक्षों, नाटकगृहों, कला-केंद्रों और सांस्कृतिक समाजों की स्थापना की है और अमेरिकी परिवारों को आज सांस्कृतिक क्रिया-कलापों में भाग लेने के लिए अनेकों अवसर सुलभ हैं।

आजकल लगभग ९८ प्रतिशत अमेरिकियों के पास रेडियो सेट हैं और ८७ प्रतिशत परिवार टेलिविजन कार्यक्रमों का आनन्द उठाते हैं। अमेरिका में अधिकांश परि-

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वारों के पास आज अपनी मोटर गाडियां हैं, जिन पर वह देश के अन्दर दूर दूर तक यात्रा कर सकते हैं और अपने देश के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

इसके अलावा अमेरिकियों को इतना अधिक अवकाश मिल जाता है कि वह विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग ले सकें। यह सच है कि अमेरिकी अपने अवकाश का अधिकांश समय मनोरंजन पर खर्च करते हैं, परन्तु यदि वह चाहें तो यही समय आसानी से सांस्कृतिक कार्यक्रमों और आयोजनों में लगा सकते हैं।

यह भी कहना मिथ्या है कि अमेरिकावासी पहले की अपेक्षा अधिक भौतिकवादी हो गये हैं और धर्म में उनकी विशेष रुचि नहीं है। औपनिवेशिक काल में, अमेरिका की केवल ५ प्रतिशत जनसंख्या गिरजाघरों की सदस्य थी, जबकि इस समय ६१ प्रतिशत से अधिक अमेरिकी गिरजाघरों के नियमित सदस्य हैं और इनमें से अधिकांश रविवार की प्रार्थना-सभाओं में बड़ी श्रद्धा के साथ भाग लेते हैं। पिछले वर्ष १० करोड़ से अधिक अमेरिकी किसी न किसी गिरजाघर के सदस्य थे। पिछले १५ वर्षों में गिरजाघरों की सदस्यता में ५० प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई है और इन्हीं वर्षों में अमेरिका ने आश्चर्यजनक आर्थिक प्रगति की है। अतएव यह स्पष्ट है कि अमेरिका की आर्थिक समृद्धि ने देश के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास में महत्त्वपूर्ण योग प्रदान किया है।

अन्तिम प्रश्न यह है कि क्या अमेरिकी ढंग के जनता के पूंजीवाद की स्थापना या विकास संसार के अन्य देशों में भी सम्भव है?

इस सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं कि यदि अनुकूल

(शेष पृष्ठ ६४८ पर)

जनता का पूंजीवाद

अमेरिका की अर्थ-व्यवस्था तेजी से ऐसा रूप धारण करती जा रही है, जिसे "जनता का पूंजीवाद" की संज्ञा दी जा सकती है। इस पूंजीवाद के अन्तर्गत राष्ट्र के उत्पादन-साधन, मुख्यतः वस्तु-निर्माण-साधन, अधिकाधिक मध्यवित्त और कम आय वाले लोगों के स्वामित्व में आते जा रहे हैं अथवा वे परोक्ष रूप में ऐसी संस्थाओं के हाथ में हैं, जो इन लोगों की चत की रकमों का इन्तजाम करती हैं। प्रबन्ध-व्यवस्था का काम तेजी से मालिकों के हाथ से निकलता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में हिस्सेदारों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है और आज राष्ट्र के गैरसरकारी कारपोरेशनों में ८६ लाख व्यक्तियों के हिस्से हैं।

आर्थिक संगठन के रूप में अमेरिकी पूंजीवाद के निम्नलिखित मुख्य आधार हैं—उत्पादन के साधनों पर गैरसरकारी स्वामित्व; गैरसरकारी सूझ-बूझ; लाभ कमाने और (टैक्स अदा करने के बाद) अपनी मेहनत के फलों का आस्वादन करने का अधिकार। इन प्रणाली के अन्तर्गत प्रतिस्पर्द्धा का खूब जोर रहता है और इससे प्रबन्धकों को बेहतर और नई वस्तुएं तैयार करने की प्रेरणा मिलती है।

—प्रो० नेडलर

जनता उद्योगों की मालिक

फोर्ड मोटर कम्पनी के ३,१९,००० मालिक या शेयर होल्डर हैं। इस साल जनवरी में लगभग १ करोड़ १० लाख हिस्से ३,१९,००० लोगों ने खरीदे हैं। इन नये हिस्सेदारों में से ३,०९,००० तो व्यक्ति थे और शेष १०,००० संस्थाएं, प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय व कालेज थे। व्यक्तियों में से १८८,००० या ६० प्रतिशत हिस्सेदारों के पास १० या इससे कम हिस्से हैं और १८,००० या ६ प्रतिशत के पास १०० या इससे अधिक हिस्से हैं।

कुल हिस्सेदारों में से १,३७,००० पुरुष हैं। ८८,००० स्त्रियां और ८०,००० सम्मिलित नामों पर हैं।

इस कम्पनी के भागीदारों की पहली बैठक १९०३ में एक छोटे से दफ्तर में हुई थी और तब लगभग एक दर्जन मालिक ही उसमें शामिल हुए थे।

वाशिंगटन : जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी के ३ लाख ७० हजार अमेरिकी नागरिक कम्पनी के हिस्सेदार हैं। १ करोड़ पुरुष एवं स्त्रियां अमेरिकी कारपोरेशनों के हिस्सेदार हैं। इनके अतिरिक्त १० करोड़ अमेरिकियों का इन फर्मों में परोक्ष रूप में हिस्सा है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

फोन नं० : ३३१११ तार : माइनहोल्डर

मिनरल वैल्थ आफ इंडिया लिमिटेड

सब प्रकार के खनिज व धातुओं

के

व्यापारी तथा एक्सपोर्टर्स

खताऊ बिल्डिंग्स

४४ ओल्ड कस्टम हाउस रोड, फोर्ट, बम्बई

मैनेजिंग डायरेक्टर:—

श्री सी० डीडवानिया

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कम्यूनिज्म कम्यूनिज्म है; साम्यवाद नहीं

आचार्य अभयदेव

कम्यूनिज्म को साम्यवाद का नाम दे देने से ऐसा लगता है कि मानों कम्यूनिज्म कोई हमारे देश की बहुत अच्छी वस्तु हो। पर कहां 'साम्य' और कहां 'कम्यून'। संस्कृत पढ़े हुए लोग जानते हैं कि हमारे भगवद्गीता आदि सम्मान्य ग्रन्थों में तो 'साम्य' शब्द बहुत ऊंचे और पवित्र अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। जैसे 'येषां साम्ये स्थितं मनः' 'समत्वं योग उच्यते'। सो कम्यूनिज्म द्वारा जो एक मोटी और केवल आर्थिक और वह भी अधूरी समता (साम्य) अभिप्रेत है, उसे 'साम्य' नाम देना कितनी भारी विडम्बना है। यह तो ऐसा ही है, जैसे जमाये हुए तेल को 'वनस्पति घी' का नाम देकर आम जनता को धोखे में डाला जा रहा है। लोग ऐसी बातें सुनकर सचमुच बहुत धोखे में आ जाते हैं कि इस 'वाद' के द्वारा धनी-निर्धन (अमीर-गरीब) सब एक हो जायेंगे, साम्य हो जायेगा, वह कितना अच्छा होगा। पर वे यह नहीं जानते कि जिस सुन्दर साम्यावस्था को वे लाना चाहते हैं, जिस नये युग के लिए वे तरसते हैं, उसका कम्यूनिज्म से कोई सम्बन्ध नहीं। यदि सम्बन्ध है तो उलटा अर्थात् कम्यूनिज्म के आने से तो वह पुण्य युग और दूर चला जायेगा।

भारत-भूमि वस्तुतः कम्यूनिज्म के लिये तनिक भी उर्वरा भूमि नहीं है। भारत की अपनी संस्कृति, जो प्राचीनकाल से सतत परिपुष्ट होती चली आ रही है, अध्यात्म-प्रधान संस्कृति है। वह कम्यूनिज्म की सहज विरोधिनी है। इसलिये जब तक भारत अपने आपको ही खो दे; तब तक कम्यूनिज्म यहां पनप नहीं सकता। फिर भी, आज जो हमारे देश के बहुत से युवक प्रौढ़ तथा वृद्ध लोग भी कम्यूनिज्म के पक्ष में बोलते हुए दिखायी देते हैं या उससे सहानुभूति प्रकट करते हैं, उसका मुख्य कारण यह है कि वे उसकी झूंठी चमकसे या वाह्याडम्बरी रूप-रेखा से अभिभूत हो गये हैं। कम्यूनिज्म से जो पूंजीवाद के अभिशाप से मुक्ति होती दीखती है और निर्धन लोगों को राहत और सन्तोष की एक आशा दिखायी देती है, उससे वे भ्रान्त हो जाते हैं। पर इस ऊपरी चमक के पीछे जो श्रमिक वर्ग (मजदूरों) की अन्ध तानाशाही, वर्ग-विद्वेष का हाहाकार तथा अनीश्वरवाद का विष भरा हुआ है, वह हमें दिखायी नहीं देता है। वर्गहीन समाज की जो बात कही जाती है, वह केवल कल्पना ही कल्पना है वर्ग विद्वेष कभी भी स्थायी सत्य नहीं है। हमारे वर्ण धर्म में जो सामञ्जस्य है, वही स्थायी सुख-शान्ति का स्रोत हो सकता है। इसी प्रकार आर्थिक जड़-समता की जगह आर्थिक सहयोग तथा सामञ्जस्य ही समाज को विकसित और उन्नत कर सकता है और फिर अर्थ (धन) चाहे कितनी ही आवश्यक वस्तु हो, पर वह सब कुछ तो नहीं है। इसीलिये हम देखते हैं, कि धनगर्द्धा ('मा गृद्धः कस्य-स्विद् धनम्' का विरोधी भाव) या धन—लिप्सा पर आधारित कम्यूनिज्म मानव के अन्य सब ऊँचे भावों की उपेक्षा करता है। पर इसी में कम्यूनिज्म की सबसे बड़ी खराबी छिपी हुई है, कि वह मानव के आध्यात्मिकता आदि उच्च भावों का विरोधी है। यह जड़वाद तथा अनीश्वरवाद पर आश्रित है। यही इसका विष है, जिसके कारण यह जिस एक आंशिक, आर्थिक सत्य को प्रकट करता है, वह भी विषैला हो जाता है। सचाई यह है, कि कम्यूनिज्म के आदर्श में जो एक वैयक्तिक सम्पत्ति-रहित समाज की कल्पना है, वह यदि कहीं कुछ अंश में सफल हो सकती है या हुई है, तो वह धार्मिक भावों से प्रेरित किये संगठन में ही हुई है या हो सकती है। हमारे देश के ऋषि-आश्रम तथा गुरुकुल इसके उदाहरण के रूप में कहे जा सकते हैं, जहां कि राजकुमार तथा निर्धन बालक समभाव से एक होकर रहते थे और विकास को प्राप्त करते थे। पर उसी धर्म को कम्यूनिज्म मूर्खता बताता है और आध्यात्मिकता को भ्रम या वहम।

कम्यूनिज्म की बढ़ती चली आती हुई लहरें और चाहे कहीं बेशक पहुँचें और वहां स्वागत भी पा सकें; पर उन्हें मेरे भारत के तपःपूत तथा अध्यात्म प्रतिबद्ध तटसे टकराकर लौट ही जाना होगा। यहां वे अपना प्रपंच नहीं फैला सकेंगी।

———

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

साम्यवाद के सैद्धान्तिक आदर्श मिथ्या हैं

श्री बर्टरैण्ड रसल

साम्यवाद के सैद्धान्तिक आदर्श मिथ्या हैं और इसके व्यावहारिक नियम ऐसे हैं कि उन पर आचरण करने से मनुष्य के दुख कष्टों में बेतहाशा वृद्धि हो जाती है।

किसी भी राजनीतिक सिद्धान्त के मामले में उसके सैद्धान्तिक आदर्श सच्चे होने चाहिए और उसकी व्यावहारिक नीति ऐसी होनी चाहिए, जिससे लोगों की सुख-सम्पन्नता में वृद्धि हो। किन्तु साम्यवाद इन दोनों में से किसी भी बात में ठीक नहीं उतरता।

साम्यवाद के सैद्धान्तिक आदर्श मुख्यतः मार्क्स से लिये गये हैं, जो "जड़वादी-बुद्धि" बताया गया है। उसकी विचारधारा प्रायः पूर्णतया घृणा से प्रेरित हैं।

उसने यह कह कर कि सभी ऐतिहासिक घटनाएं वर्ग-संघर्ष का फल है, विश्व के इतिहास में उन कुछेक बातों को अविवेकपूर्ण और गलत तरीके से जोड़ा है, जो १०० साल पूर्व इंगलैण्ड और फ्रांस में पाई जाती थीं।

ये सैद्धान्तिक भूलें इतनी महत्त्वपूर्ण नहीं, जितनी कि यह बात कि उसकी यह मुख्य आकांक्षा थी कि उसके शत्रु नष्ट हो जाएं और उसने इस बात की चिन्ता नहीं की कि इस प्रक्रिया में उसके दोस्तों का क्या होगा।

मार्क्स के सिद्धान्तकी असत्यता को लेनिन और स्तालिन, दोनों ने बढ़ा दिया और सर्वहारा-वर्ग की तानाशाही एक छोटी सी समिति और अन्त में एक व्यक्ति—स्तालिन की तानाशाही बन गई।

मार्क्स के सिद्धान्तों से मैं कभी सहमत नहीं हुआ, परन्तु आज के साम्यवाद के बारे में तो मेरी आपत्तियां और भी अधिक हैं, क्योंकि यह एक ऐसी व्यवस्था है, जिसने लोकतन्त्र का परित्याग कर दिया है और यह बात खास तौर से दुर्भाग्यपूर्ण है। खुफिया पुलिस की कार्रवाई के सहारे सत्ता कायम रखने वाले अल्पसंख्यक दल का क्रूर, अत्याचारी और सुधार-विरोधी होना स्वाभाविक है। १८ वीं और १९ वीं सदी में अनुत्तरदायी सत्ता के खतरों को आम तौर पर अनुभव किया गया था, किन्तु सोवियत रूस

पंजाब के साहित्य, संस्कृति और जीवट जीवन का दर्पण

जागृति

सचित्र हिन्दी मासिक

मूल्य एक प्रति	वार्षिक चन्दा	छपाई
४ आना	केवल ३ रुपया	सम्पूर्ण आर्ट पेपर पर

पंजाब के इस अभिनव और गौरवपूर्ण प्रकाशन की कुछ विशेषताएं

- साहित्यिक सांस्कृतिक और सामाजिक विषयों पर अधिकारी और प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं,
- ख्याति प्राप्त चित्रकारों और कलाकारों के चित्र और कला कृतियां,
- बहुरंगे आकर्षक और मोहक छाया चित्र,
- जानकारी पूर्ण मनोरंजक लेख।

व्यवस्थापक 'जागृति' (हिन्दी)

लोक सम्पर्क विभाग, पंजाब, ६९ माडल टाउन, अम्बाला शहर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

समाजवाद अधिनायक तंत्र का मार्ग

श्री सी. एल. धीवाला

पिछले पृष्ठों में समाजवाद का पक्ष पाठकों ने पढ़ा है। लेकिन वह एकान्तिक सत्य है, या नहीं, इसकी जानकारी के लिए निजी उद्योग का पक्ष भी जान लेना चाहिए। इस लेख के विद्वान लेखक ने अपना पक्ष अत्यन्त योग्यतापूर्वक उपस्थित किया है। लेख अत्यन्त विचारणीय है।

वे सच्चे उद्देश्य जिनसे समाजवाद को प्रेरणा मिलनी चाहिए थी, भुला दिये गये हैं और साधन को ही साध्य मान लिया गया है। इससे अब समाजवाद, सरकारी उद्योगों का बढ़ाना, राष्ट्रीयकरण, केन्द्रीयकरण, केन्द्रीय आयोजना और इन सबका परिणाम नौकरशाही स्थापित करना मान लिया गया है। यह तथ्य भुला दिया गया है कि समाजवाद मूलतः जीवन के रहन-सहन का वह ढंग है, जिसमें कुछ नैतिक मूल्यों और व्यवहार-पद्धति की संयोजना है और जिसको सरकार द्वारा केवल उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करते हुए, निजी उद्योगों को समाप्त करके नहीं थोपा जा सकता। यह रास्ता तो सरकारी पूंजीवाद (State Capitalism) की ओर ले जायेगा और परिणामतः एकतंत्रात्मक राज्य की स्थापना हो जायेगी। समाजवाद का मूलमंत्र है—सामाजिक न्याय, अवसर की समानता, व्यक्ति की स्वतन्त्रता और बंधुता। पर ये आदर्श केवल 'सरकारी' या 'निजी' स्वामित्व में परिवर्तन मात्र से कदापि प्राप्त नहीं हो सकते। सच तो यह है कि ऐसे जो प्रयत्न किये भी जा रहे हैं, उनसे "बिल्कुल नये प्रकार के आदर्शों" की स्थापना की जा रही है। भले ही संस्थागत परिवर्तन आवश्यक और अपेक्षित हों, लेकिन फिर भी प्रमुखता हमेशा व्यक्ति के आंतरिक परिवर्तन और मानवीय मस्तिष्क की स्वाधीन प्रेरणा को दी जानी चाहिए।

यह उल्लेखनीय है कि मार्क्स ने पूंजीवाद से, जिस संघर्ष का उल्लेख किया था, वह असत्य सिद्ध हो चुका है। यह बात उसने उस समय लिखी थी, जबकि योरप में निरंकुश शासकों का बोलबाला था। विश्व के विभिन्न भागों में प्रजातंत्रीय आदर्शों और प्रतिनिधि संस्थाओं के स्थापित होने के माध्यम से फैलने वाले कल्याणकारी राज्य के विषय में वह तब कुछ सोच ही न सका। समाज में दरिद्रता बढ़ने के बजाय व्यक्ति का जीवन-स्तर निरन्तर बढ़ता जा रहा है तथा अब कंगाली और सामाजिक असुरक्षा भी समाप्त-प्रायः ही हैं। यह बात अधिक समय तक सही नहीं मानी जा सकती कि उत्पादन के साधनों के मालिक ही समाज की प्रवृत्ति को नियंत्रित करते हैं और राष्ट्रीयकरण के द्वारा स्थापित सामूहिक स्वामित्व ही समाजवाद की एकमात्र दशा है।

राज्य के बढ़ते अधिकार

कीन्स (Keynes) ने कहा है कि "राज्य के लिए उत्पादन के साधनों पर अपना स्वामित्व स्थापित करना आवश्यक नहीं है, यदि राज्य इस बात का निर्धारण कर सके कि साधनों का कुल योग कितना है और जो इन साधनों के मालिक हैं, उनको कितना प्रतिफल मिलना चाहिए तो अभीष्ट की सिद्धि हो जायेगी।" आधुनिक राज्यों में सामाजिक न्याय और समानता पर विशेष जोर दिया जाता है। निरंकुशता अब भूतकाल की वस्तु बन गई है। पर इसके बावजूद अ-हस्तक्षेप की नीति अब अव्यवहार्य और व्यर्थ मानी जाती है। आज राज्य को सामाजिक और आर्थिक कई प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। आर्थिक क्षेत्र में तो उसको व्यापक अधिकार प्राप्त हैं, जिनको हम राजनैतिक

की बाहरी सफलताओं से चौंधिया जाने वाले लोग निरंकुश राजाओं के जमाने में प्राप्त दुखद अनुभवों को भूल गये हैं और फिर से मध्य युग के निकृष्टतम काल में जा पहुँचे हैं। वे इस गलतफहमी के शिकार हो गये हैं कि वे प्रगति पथ पर अग्रसर होने वाले अग्रिम व्यक्तियों में हैं।

साम्यवाद एक ऐसा सिद्धान्त है जो गरीबी, घृणा और कलह पर पनपता है। इसका फैलाव गरीबी और घृणा को दूर करके ही रोका जा सकता है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नियंत्रण कह सकते हैं। विभिन्न प्रकार के कानून बनाने, मुद्रा, वित्त सम्बन्धी अधिकारों को प्राप्त करने के कारण राज्य रोजगारी की दशाओं को नियंत्रित करने, आय को वितरित करने, ब्याज और व्यापार-संतुलन की दर को निश्चित करने का कार्य भी स्वयं करता है। सरकार की नीतियों से ही उत्पादन का आकार-प्रकार तथा विनियोग की दशाएं निर्धारित होती हैं। श्रम-सम्बन्धी कानूनों से मजदूरों-मालिकों के सम्बन्ध निश्चित किये जाते हैं और मजदूरों के हितों की रक्षा होती है। इस प्रकार राज्य ने आर्थिक जीवन में 'अंतिम मध्यस्थ' का रूप ले लिया है।

राजनीतिज्ञ सर्वेसर्वा

इसी प्रकार ज्वाइंट स्टॉक कार्पोरेशन की स्थापना से जोखिम उठाने वाले पूंजीपतियों का नीति-निर्धारण का अधिकार मंत्रिपरिषद के उन सदस्यों को मिल गया है, जिनका उद्योगों पर कोई स्वामित्व नहीं। इससे यही प्रकट होता है कि जनसमुदाय में कंगाली का निरंतर बढ़ते रहना और फलस्वरूप वर्ग-संघर्ष का होना, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकतंत्र तथा उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व—जो मार्क्स के सिद्धांत की रीढ़ हैं, समाजवादी उद्देश्य की प्राप्ति के लिये असंगत ठहरते हैं। अब यह प्रतीत होने लगा है कि केवल स्वामित्व-परिवर्तन से आर्थिक समाजवाद की स्थापना की गारंटी नहीं दी जा सकती। इसके विपरीत कुछ देशों में समाजवाद के समर्थकों को राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में राज्य को पुनर्विचार के लिए तैयार करने के लिये संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि अनावश्यक केन्द्रीकरण, आर्थिक शक्तियों का राजनीतिज्ञों की मुट्ठियों में चले जाने और नौकरशाही द्वारा संचालित कार्पोरेशन के कारण कई नई समस्याएं उत्पन्न हो गईं। यहां तक कि श्रमिक संघ भी, जिन्होंने पहले राष्ट्रीयकरण का समर्थन किया था, लेकिन जब सरकारी उद्योग क्षेत्र के बढ़ने से उनके अधिकारों पर चोट लगने लगी, राष्ट्रीयकरण का विरोध तक करने लगे हैं। प्रधान मंत्री श्रीजवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारी योजना का आधार प्रजातंत्र है। "हम संसार की भौतिक वस्तुओं को उत्पन्न करना चाहते हैं, जिससे हमारे देशवासियों का जीवन-स्तर ऊंचा हो लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इनकी प्राप्ति के लिए मानवीय प्रवृत्तियों का हनन किया जाए या जीवन की उन सुन्दर मान्यताओं का बलिदान किया जाये, जिनका सदियों से मानव को ऊंचा उठाने में हाथ रहा है।"

आज समाजवाद को सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि विकसित अर्थ-व्यवस्था में लाभ की समस्या के प्रति अधिक संतुलित और सही दृष्टिकोण अपनाया जाये। चाहे निजी उद्योग हों या सरकारी, आर्थिक क्रियाओं का प्रधान उद्देश्य पूंजी का निर्माण होना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि बचत करने का स्तर ऊँचे से ऊँचा हो। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सरकारी उद्योगों में नौकरशाही के स्थापित हो जाने पर विनियोग की मात्रा बढ़ जायेगी, और साधनों का दुरुपयोग नहीं किया जायेगा, जैसा कि निजी क्षेत्र के सम्बन्ध में आशंका प्रकट की जाती है।

राष्ट्रीयकरण समाजवाद नहीं

विश्व के कुछ प्रजातन्त्री राष्ट्रों की सरकारों ने अ-हस्तक्षेप की नीति से हट कर विभिन्न प्रकार के कर-सम्बन्धी, आर्थिक और भौतिक अधिकारों को प्राप्त कर लिया है जिससे प्रत्येक प्रकार से नियमन और निर्देशन के द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। अनुभवों से ज्ञात हुआ कि सरकारी उद्योग-क्षेत्र पर समुचित नियंत्रण का रखा जाना तो दुष्कर कार्य है ही, लेकिन राष्ट्रीयकृत उद्योग-क्षेत्रों को जनता के सम्मुख यथार्थ रूप से जबाबदेह बनाना और भी दुष्कर है। इंगलैंड में जहां मजदूर दल की सरकार ने राष्ट्रीयकरण का प्रयोग किया, वहां यह एक कहावत सी बन गई कि सरकार को इम्पीरियल केमिकल इण्डस्ट्रीज की अपेक्षा लौर्ड सिट्राइन पर कम अधिकार है। इससे यही प्रकट होता है कि सरकारी क्षेत्र में विस्तार से संयोजन-कार्य कितना कठिन हो जाता है।

भारत में भी आरम्भ की अनेक कठिनाइयों को झेलने के बाद सरकारी क्षेत्र के उद्योगों जैसे—सिंद्री उर्वरक, चितरंजन लोकोमोटिव का कारखाना, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंडियन टेलीफोन फैक्ट्री ने अच्छी प्रगति तो की है, लेकिन अभी और भी अधिक कार्य करने को बाकी है। हम अभी तक सरकारी उद्योगों के संचालन के सम्बन्ध में

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उन्हीं गये बीते सिद्धान्तों को अपना रहे हैं, जिनका फल कई प्रकार की गम्भीर शिकायतों, अनियमितताओं और बिलम्ब के रूप में मिलता है। इसके लिए अनेक उद्धाहरणों के स्थान पर एक यही उदाहरण देना यथेष्ट है कि सरकार को एक कारखाने के लिए स्थान के अधिकृत करने में ३ वर्ष लग गये। जैसे कि सरकारी अर्थकोष के अधिकारी की रिपोर्ट में कहा गया है--कि जमीन की लागत में ४०० प्रतिशत वृद्धि हुई और यही लागत वृद्धि मशीन यंत्रों में ८० प्रतिशत, इस्पात में ४० प्रतिशत तथा निर्माण आदि में १०० प्रतिशत तक बढ़ गई।" संसद की आंकन समिति ने भी व्यक्त किया है "सरकारी उद्योग—क्षेत्र को नौकरशाही के अनुपयुक्त हाथों में सौंपा गया है। इनमें संयोजन और कार्यक्षमता की कमी है, तथा सार्वजनिक साधनों का अपव्यय होता है।"

अधिनायक-तन्त्र का मार्ग

एक व्यक्ति, जिसको इस बात का अनुभव है कि आर्थिक शक्तियां किस प्रकार कार्य करती हैं वह जान सकता है कि आयोजना के कारण देश की अर्थ व्यवस्था एक स्थान पर केन्द्रित हो जाती है। प्रजातन्त्रात्मक आदर्शों के अनुरूप योजनाबद्ध उन्नति करने के लिए आवश्यक है कि रूस और उसके जैसे पोलैंड, हंगरी और चीन के अधिनायकतन्त्रवादी देशों और यहां तक कि मजदूर दल के समय की ब्रिटेन, जैसी विचित्र व्यवस्था को अपने देश में पनपाने का घोर विरोध किया जाए। इस विचित्र व्यवस्था के कारण जोर जबरदस्ती और समस्त अर्थ व्यवस्था को 'युद्ध-स्तर' पर लाना अनिवार्य हो जाता है। इसे 'राष्ट्रीय आपातकाल' से सम्बोधित किया जाता है। ऐसी व्यवस्था अधिनायकतन्त्र में सम्भव हो सकती है, लेकिन प्रजातन्त्र में इसके लिए गुंजायश नहीं।

इस प्रकार राष्ट्रीयकरण के आधार पर चलने वाली आयोजना की प्रजातन्त्र से संगति नहीं बैठती। यह बात भुला दी जाती है कि एकाधिकार में—चाहे वह सरकारी ही क्यों न हो—गम्भीर खामियां होती हैं। इसका परिणाम यही नहीं होता कि व्यक्ति की स्वतन्त्रता प्रतिबंधित हो जाती है और व्यक्ति के उद्योगों की स्थापना और उत्पन्न करने के अधिकार छिन जाते हैं। इससे भी अधिक प्रतियोगिता की दशाओं को समाप्त होने के कारण सभी प्रकार के प्रयत्नों, जोखिमों व साहसिकता की भी समाप्ति हो जाती है जो कि अच्छी अर्थ व्यवस्था के लिए अत्यन्त आवश्यक है। इसी प्रतियोगिता के अभाव में राष्ट्रीय उद्योग उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, जो उनको इच्छानुकूल वस्तुओं की पूर्ति कर सकें। संक्षेप में, इंगलैंड जैसे प्रजातन्त्रात्मक देश में राष्ट्रीयकरण से ऐसे उद्योगों का विस्तार हुआ है, जिसमें नौकरशाही का बोलबाला है तथा अति केन्द्रीयकरण से प्रजातन्त्रात्मक समाज के अस्तित्व तक को भय हो गया है।

आर्थिक उन्नति राष्ट्रीयकरण से नहीं

यह स्वीकार कर लिया गया है कि राष्ट्रीयकरण आर्थिक उन्नति की समस्या का सही उत्तर नहीं है। श्री फ्रैंक बेसक्रिक ने ठीक ही कहा है "एक केंद्रीय सत्ता के अधिकार से आर्थिक उन्नति का स्तर कम हो सकता है। साथ ही यह आवश्यक नहीं कि राज्य का स्वामित्व स्थापित हो जाने से शिल्पविधान में कुशलता आ जायेगी।" ब्रिटेन के प्रसिद्ध समाजवादी क्रौसलैंड का कथन है कि "मजदूरों के उच्च जीवन-स्तर, मजदूरों-मालिकों के पारस्परिक परामर्श से अधिक कुशलता की प्राप्ति, मजदूरों और मालिकों के अच्छे सम्बन्ध, आर्थिक साधनों का भली प्रकार उपयोग, शांति का विकेन्द्रीकरण, अधिक से अधिक सहयोग और अधिक सामाजिक तथा आर्थिक समानता—इन सब की प्राप्ति के लिए मूलतः उद्योगों के स्वामित्व में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं।" सिवाय मार्क्स और लेनिन के सिद्धांतों के समर्थकों के अलावा कोई इस बात पर विश्वास नहीं करता कि उत्पादन के साधनों, वितरण और विनिमय पर सरकार का स्वामित्व समाजवादी समाज स्थापित करने के हेतु आवश्यक हो जाता है।

आर्थिक प्रवृत्तियों की उपेक्षा भयंकर

लेकिन ऐसा कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि सरकार को अविकसित देश में कुछ प्रकार के उद्योगों जैसे आधारभूत उद्योग, मशीन बनाने के उद्योग जिनसे किसी देश के औद्योगीकरण में सहायता मिलती है—अपने हाथ में लेने

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हीनहीं चाहिए। तथ्य यह है कि ऐसे बहुत ही कम उद्योग हैं, जिन पर सरकार का पहले से ही नियंत्रण या स्वामित्व नहीं है तथा ऐसे भी बहुत कम उद्योग हैं जो कि निजी उद्योग-क्षेत्र के सामर्थ्य के बाहर हैं, और जिनको सरकार देश की अर्थव्यवस्था के हित के लिए आसानी से अपने अधिकार में लेकर चला सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रीयकरण हमारी आर्थिक बुराइयों के लिए रामबाण नहीं। राष्ट्रीयकरण को असामान्य परिस्थितियों में ही अपवाद के रूप में अपनाना चाहिए, न कि किसी मत या सिद्धांत का अन्धानुसरण करके। राजनैतिक अंधविश्वास में आर्थिक प्रवृत्तियों की उपेक्षा करने का परिणाम भयंकर होगा।

केन्द्रीयकरण और नौकरशाही के खतरे

राष्ट्रीयकरण की नीति और सरकारी उद्योगों का परिणाम यह होता है कि एक अति अधिकार-सम्पन्न कार्पोरेशन की जिसमें नौकरशाही का बोलबाला होता है, स्थापना हो जाती है। इस प्रकार का कार्पोरेशन अप्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, पर इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता के अपहरण का भय रहता है। "बीसवीं सदी का समाजवाद" नामक पुस्तक में कहा गया है कि "इस प्रकार की पद्धति में बिना राज्य की अनुमति के किसी भी प्रकार से "विचारों का परीक्षण" संभव नहीं है। जो व्यक्ति इस प्रकार की जोखिम उठाना चाहता है, वह अयोग्य या बुरा माना जाता है। निजी पूंजी को छीन लेना सर्वाधिकारवादी राज्य का मार्ग है।" ऐसा करने से एक "स्वतंत्र और समतापूर्ण समाज" के जो समाजवादी समाज का मूलमंत्र है—स्थान पर इसके द्वारा समस्याएं ही उत्पन्न होंगी, क्योंकि आर्थिक शक्तियां अनुचित रूप से नौकरशाही के हाथों में केंद्रित हो गई हैं। ब्रिटेन की संसद के मजदूर दलीय सदस्य श्री क्रौसमैन का कथन है "नौकरशाही के हाथों में सत्ता का केंद्रित हो जाना हमारी स्वतंत्रता पर आघात ही है। यदि हम नौकरशाही के अधिकारों को और बढ़ाते जायें तो हम क्या उस स्वतंत्रता को खतरे में नहीं डाल रहे हैं, जिसकी सुरक्षा के लिए हम इतने आतुर हैं।"

दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के सम्बन्ध में जो भय प्रकट किया जाता है, वह काल्पनिक है। लेकिन सुविज्ञ व्यक्ति जान सकता है कि इस प्रकार का भय बहुत दूर नहीं। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि हमारे देश में ही सरकारी दल के एक प्रवक्ता ने कुछ समय पहले कहा है कि "प्रजातंत्र का मार्ग जो बहुत ढोल-ढाल का मार्ग है। इसी के कारण हमारे विकास की गति मंद है।" कुछ लोग तो इससे भी आगे बढ़कर जनता को उपदेश देने लगते हैं कि केंद्रीयकरण अनिवार्य है और जनता को इसके अनुकूल अपने को ढाल लेना चाहिए। लेकिन समाजवाद के ये समर्थक गांधीजी के इस कथन को भूल जाते हैं कि "मैं राज्य की बढ़ती ताकत को भयप्रद मानता हूँ क्योंकि प्रकटतः इससे शोषण कम तो हो तो जाता है, लेकिन व्यक्तित्व के—जो समस्त उन्नति का मूल है—विनाश हो जाने से मानव समाज को हानि ही होती है।"

आपका स्वास्थ्य

(हिन्दी की एक मात्र स्वास्थ्य सम्बन्धी मासिक पत्रिका)

"आपका स्वास्थ्य" आपके परिवार का साथी है।

"आपका स्वास्थ्य" अपने क्षेत्र के कुशल डाक्टरों द्वारा सम्पादित होता है।

"आपका स्वास्थ्य" में अध्यापकों, अभिभावकों, माताओं और देहातों के लिए विशेष लेख प्रकाशित होते हैं।

आज ही ६) रु० वार्षिक मूल्य भेजकर ग्राहक बनिए।

व्यवस्थापक,

आपका स्वास्थ्य—बनारस-१

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

एक विचारणीय लेख

मार्क्स की भविष्यवाणी मिथ्या

डब्ल्यू० एस० वोटिंस्की

लगभग १ शताब्दी पूर्व साम्यवाद के जन्मदाता श्री कार्ल मार्क्स ने यह भविष्यवाणी की थी कि पूंजीवाद का अन्त अत्यन्त निकट आ गया है। १८६० में उसे इस बात के स्पष्ट लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे थे कि ब्रिटेन में पूंजीवाद तेजी के साथ विनाश की ओर अग्रसर हो रहा है।

वास्तविकता तो यह है कि मार्क्स का 'अतिरिक्त मूल्य' (सरप्लस वेल्यू) नामक प्रसिद्ध सिद्धान्त, जिस पर उसकी विचारधारा का समस्त भवन आधारित था, गलत और भ्रमपूर्ण सिद्ध हुआ। इस सिद्धान्त के अनुसार पूंजीपति मजदूरों का शोषण करते हैं और उन्हें केवल उतनी मजदूरी देते हैं जो उन्हें जीवित रखने के लिए आवश्यक होती है। बिक्री से प्राप्त होने वाली अधिकांश धनराशि (लाभांश) जो वस्तुतः मजदूरों के श्रम का प्रत्यक्ष परिणाम है, इन पूंजीपतियों द्वारा हड़प कर ली जाती है।

गलत मूलाधार

वस्तुतः मार्क्स ने पूंजीपतियों और श्रमिकों के मध्य जिस प्रकार के संघर्ष की कल्पना की है, वह मूलतः गलत है। मार्क्स ने लिखा है कि पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था के फलस्वरूप गरीबी बढेगी और शोषित मजदूरों और दिवालियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी। यदि उसका यह निष्कर्ष सत्य मान लिया जाय तो इसका अर्थ यह होना चाहिए कि बाल्कन राज्यों की अपेक्षा इंगलैंड में गरीबों और बेकारों की संख्या कहीं अधिक होनी चाहिए।

लगभग १०० वर्ष पूर्व मार्क्स ने इस सिद्धान्त की कल्पना की थी। इस अवधि में संसार में न जाने कितनी क्रांतियां हुईं, न जाने कितने साम्राज्य बने और बिगड़े और न जाने कितने तानाशाहों का पतन हुआ। इन सभी परिवर्तनों में श्रमिकों ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा कीं। लेकिन इनमें से एक भी क्रान्ति मार्क्स द्वारा बताये ढंग पर नहीं हुई।

वर्तमान युग में रूस और चीन में दो महान् क्रांतियां हुईं, लेकिन ये मजदूरों द्वारा नहीं, बल्कि सेनाओं द्वारा संचालित थीं। और इसी अवधि में पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था के स्वरूप में ऐसे उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिनकी मार्क्स ने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। मार्क्स का यह सिद्धान्त गलत हो गया कि पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था में पूंजी कुछ चंद लोगों के हाथ में केन्द्रित हो जाएगी। अमेरिका में इसका बिल्कुल उल्टा हुआ है। १९२९ में कारखानों, फैक्टरियों और व्यवसायिक संगठनों की कुल संख्या ३०२९००० थी। १९५६ में इनकी संख्या बढ़कर ४२५२००० तक पहुँच गई थी। यह ठीक है कि इस अवधि में अमेरिका में बड़ी-बड़ी व्यावसायिक कम्पनियों जैसे कार्पोरेशनों का विकास हुआ है परन्तु इन कार्पोरेशनों का स्वामित्व कुछेक व्यक्तियों के हाथ में न होकर हजारों और लाखों छोटे-छोटे भागीदारों के हाथ में है। इसके अलावा व्यवसायों का संचालन पूंजीपति नहीं, बल्कि प्रशिक्षणप्राप्त एवं कुशल और अनुभवी प्रबन्धक करते हैं।

आधुनिक स्वतन्त्र-व्यवसाय व्यवस्था में श्रम-संगठनों ने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। मालिक-मजदूरों से सम्बन्धित सभी क्षेत्रों में आज उन्हें महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है तथा उनके मध्य उठने वाले सभी विवाद श्रम-संगठनों के माध्यम से ही तय किए जाते हैं। अमेरिका, इंगलैंड, कनाडा, स्वीडन, नार्वे, डेनमार्क इत्यादि देशों में प्रमुख उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए श्रम संगठन का सदस्य होना अनिवार्य है।

पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था पर प्रहार करते हुए मार्क्स ने पूंजीवाद पर चार मुख्य आरोप लगाये हैं। उनका कथन है कि मजदूरों के काम के घंटे बहुत अधिक हैं, उन्हें उचित मजदूरी नहीं प्राप्त होती, काम की परिस्थितियां बहुत अस्वास्थ्य प्रद हैं तथा महिलाओं और बालकों का शोषण किया जाता है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

त्रुटियां दूर कर दी गईं

आज इनमें से अधिकांश त्रुटियों का पूरी तरह निराकरण किया जा चुका है। इंगलैण्ड, अमेरिका आदि प्रमुख उद्योग प्रधान देशों के कोई भी मजदूर आज इन बातों की शिकायत नहीं कर सकते। उत्पादन में वृद्धि होने के साथ-मजदूरी-स्तर, काम की परिस्थितियों और स्वास्थ्य तथा कल्याण-सुविधाओं में विस्तार हुआ है। १८८९ में श्रम संगठन-आन्दोलन ने मजदूरों के लिए ४८ घंटे का काम सप्ताह निर्धारित करने की मांग की थी परन्तु आज के मजदूर को सप्ताह में केवल ४० घंके काम करना पड़ता है।

पिछले दस वर्षों में उद्योग-प्रधान देशों में बेकारी बहुत घटी है और अर्थ-व्यवस्था को स्थायी और स्थिर आधार प्रदान करने की दिशा में हमने बहुत अधिक प्रगति कर ली है। संकटकाल में मजदूरों की सहायता, बेकारी बीमा, वृद्धावस्था और आश्रित सहायता बीमा, सामूहिक सौदे बाजी, न्यूनतम वेतन दर इत्यादि अनेक सुविधाएं सुलभ हो रही हैं।

साम्यवादियों की दृष्टि में पूंजीवाद के गढ़ अमेरिका में लगभग प्रत्येक औसत श्रमिक के पास अपनी मोटर, रिफरिजरेटर, रेडियो या टेलिविजन तथा घरेलू उपयोग के विद्युत-चालित यंत्र और उपकरण हैं और पूंजीपतियों और श्रमिकों के भोजन, रहन-सहन तथा निवास में बहुत कम अन्तर दृष्टिगोचर होता है। आधुनिक पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था में श्रमिक पूंजीपतियों के गुलाम नहीं हैं। तथा इन देशों की विधान सभाओं में उन्हें प्रबल प्रतिनिधित्व प्राप्त है।

मार्क्स की भविष्यवाणी के सर्वथा विपरीत आधुनिक पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था में नई शक्ति, स्फूर्ति और चेतना दृष्टिगोचर होती है। उसमें स्थिति और वातावरण के अनुसार परिवर्तन करने की पर्याप्त गुंजाइश है और नैतिकता, समानता और न्याय के सिद्धान्तों को दृष्टि में रखते हुए जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में वह कहीं अधिक समर्थ है।

संचालक पंचायत राज विभाग उ० प्र०
की
विज्ञप्ति संख्या ४/५५८०/३३ : २७/५३, दिनांक १५
द्वारा
पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत

सुन्दर पुस्तकें

	लेखक	मूल्य रु०	आ०
वेद सा	प्रो. विश्वबन्धु	१	८
प्रभु का प्यारा कौन ? (२ भाग)	,,		
सच्चा सन्त	,,		३
सिद्ध साधक कृष्ण	,,	०	३
जोते जी ही मोक्ष	,,	०	३
आदर्श कर्मयोग	,,	०	३
विश्व-शान्ति के पथ पर	,,	०	१
भारतीय संस्कृति	प्रो. चारुदेव	०	३
बच्चों की देखभाल	प्रिंसिपल बहादुरमल	१	१२
हमारे बच्चे	श्री सन्तराम बी. ए.	३	१२
हमारा समाज	,,	६	०
व्यावहारिक ज्ञान	,,	२	१२
फलाहार	,,	१	४
रस-धारा	,,	०	१४
देश-देशान्तर की कहानियां	,,	१	०
नये युग की कहानियां	,,	१	१२
गल्प मंजुल	डा० रघुबरदयाल	१	०
विशाल भारत का इतिहास	प्रो. वेदव्यास	३	८

१० प्रतिशत कमीशन और ५० रु० से ऊपर के आदेशों पर १५ प्रतिशत कमीशन।

विश्वेश्वरानन्द पुस्तक भंडार
साधु आश्रम, होशियारपुर
पंजाब

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

साम्यवाद में भी मजदूर दास

श्री नागेश्वरप्रसाद

मार्क्स और एंजिल्स के सिद्धान्तों को अपनाकर रूस में सर्वहारा-वर्ग की क्रांति हुई। उत्पादनों के साधनों पर उसका प्रभुत्व स्थापित हुआ। लेकिन मार्क्स और एंजिल्स की कल्पना मूर्तिमान नहीं हो सकी—क्यों ?

वास्तवमें मार्क्स और एंजिल्स ने एक मूलभूत भूल की। उन्होंने जहां वैयक्तिक स्वामित्व की जगह सामाजिक स्वामित्व का विधान किया, वहां उत्पादन की प्रणाली को ज्यों का त्यों रखा। अर्थात् उनकी तीक्ष्ण दृष्टि बड़े पैमाने के उद्योगों को ओर नहीं जा सकी। फलतः उन्हीं के दर्शन के अनुसार केन्द्रित उत्पादन-प्रणाली पर केन्द्रित राजनीतिक शक्ति का भवन खड़ा हुआ। स्वभावतः उससे औपचारिक जनतन्त्र—जो वस्तुतः सर्वसत्तावादी है—और साम्यवादी अधिनायकत्व निःसृत हुए।

विज्ञान और यान्त्रिकता

वास्तव में बड़े पैमाने के उद्योगों का नियन्त्रण, परिचालन एवं निर्देशन बिना विशिष्टता के होना कठिन है। मार्क्स और एंगिल्स ने विज्ञान एवं यान्त्रिकता (Technology) की निरन्तर बढ़ती हुई प्रगति का स्वागत किया। परन्तु जिस यान्त्रिकता में उन्होंने मानवीय उद्धार के स्वप्न का दर्शन किया, वह विशाल एवं भयंकर दैत्य का रूप धारण कर आज मानव के व्यक्तित्व के टुकड़े कर रही है। मानव मशीन का महज पुर्जा होकर रह गया है। उसका व्यक्तित्व दैत्याकार मशीनों की विषाक्त छाया में प्रस्फुटित न होकर, निरन्तर दबता जा रहा है।

इन भैरवाकार उद्योगों के संचालन के लिए विशेषज्ञता (expert knowledge) की जरूरत है। स्पष्ट है कि सभी विशेषज्ञ नहीं हो सकते। नतीजा यह हुआ कि मजदूर अब पूंजीपति वर्ग का दास न होकर विशेषज्ञ तथा प्रबन्धक वर्ग का दास हो गया। नागनाथ की जगह सांपनाथ आये। अंतर नाममात्र का रह गया। इसीलिए श्री बर्नहम ने रूसी क्रांति को प्रबन्धक क्रांति या मैनेजरशाही (मैनेजेरियल रेवोल्यशन) का उपनाम दिया। ट्राटस्की के अनुसार इनकी अपनी एक विशेष जाति बन गई, जो मजदूरों पर उसी प्रकार जमी हुई है, जिस प्रकार पानी पर शैवाल। शासन और शोषण का चक्र अक्षुण्ण जारी है। केन्द्रित शासन में व्यक्ति की स्वतंत्रता का लोप एवं केन्द्रित उद्योग में उसका शोषण अनिवार्य हो गया है। राज्य पर कुछ मुट्ठी भर प्रबन्धकों एवं संचालकों (मैनेजर और डायरेक्टर) का अधिकार हो गया है। उस पर एक गिरोह सर्वशक्तिमान है। राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा हिस्सा इस गिरोह की जेब में जाता है, जैसा कि रूस के १ और ८० के अनुपात की मजदूरी में सिद्ध होता है। फलतः राज्य की शक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। राज्य के झर जाने के कोई आसार नजर नहीं आते।

विकेन्द्रीयकरण

शोषण, वैषम्य एवं व्यक्तित्व की पराधीनता का मूल कारण उत्पादन की वर्तमान प्रणाली में है। जब तक केन्द्रित पैमाने के उद्योगों की जगह एक नूतन उत्पादन प्रणाली का आविष्कार नहीं होता, तब तक मनुष्य की वास्तविक मुक्ति सम्भव नहीं। वह प्रणाली कैसी हो ? मार्क्स ने कहा था कि पूंजीवाद में उत्पादक का उसके औजारों से संबंध-विच्छेद हो गया है। वह स्वयं उसका स्वामी नहीं। गांधी जी ने कहा कि उत्पादक अपने यंत्रों का स्वामी उसी समय हो सकता है, जब उसके यंत्र छोटे-छोटे हों। यंत्रों में वह स्वयं खो जाता है। उसकी आत्म-चेतना लुप्त हो जाती है। अत एव उन्होंने बड़े उद्योग-धंधों की जगह विकेन्द्रित छोटे-छोटे उद्योग-धन्धों को प्राधान्य दिया, जिसमें मनुष्य के हस्तकौशल के लिए अधिक अवसर हो। इस विकेन्द्रित मानव-प्रधान अर्थ-प्रणाली का प्रतीक 'चर्खा' है।

———

होशंगाबाद मेंसम्पदा के प्रतिनिधि

श्री अमीरचन्द जैन

रोकड़िया का मकान दूसरी मंजिल

मेन बोर्ड स्कूल के पास, मंगलवारा, होशंगाबाद (M. P.)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राष्ट्रीयकरण और मजदूर समस्या

भारत के समाजवादी मजदूर नेता उद्योगों व कृषि के राष्ट्रीयकरण की मांग जोरों से करते हैं, परन्तु क्या इससे वे सन्तुष्ट हो जायंगे ? उनकी समस्याओंका समाधान हो जायगा ? यदि इस प्रश्न का उत्तर हां में हो, तो भी यह समाजवाद किसी तरह से समझ आ सकता है और उसे सहन करने की प्रेरणा की जा सकती है।

लेकिन पिछले वर्षों का अनुभव यह बताता है कि राष्ट्रीयकरण के समाजवादी सिद्धान्त से मजदूरों को संतोष नहीं होगा। आज निजी उद्योगों में हड़तालों की जितनी आवाज सुनाई देती है, उससे अधिक सरकारी उद्योगों में—कभी रेलवे कर्मचारी हड़ताल की धमकी देते हैं, तो कभी डाक कर्मचारी और सरकारी दफ्तरों के क्लर्क व निम्न कर्मचारी हड़ताल के लिए बैलट पेपर ले रहे होते हैं। कभी बन्दरगाहों में हड़ताल होती है, तो कभी दूसरे सरकारी कारखानों में। स्कूलों के अध्यापक और पटवारी भी समाजवाद के बढ़ते नारों के साथ-साथ हड़तालें करने लगे हैं। एक प्रकार की अराजकता सी पैदा हो रही है। इनकी हड़ताल किसी दिन भी देश के कारोबार को ठप कर सकती है। निजी उद्योग में जब हड़ताल या किसी संघर्ष का अवसर आता है, तो सरकार मध्यस्थ या पंच का रूप धारण कर सकती है और करती है, पर राष्ट्रीयकृत सरकारी उद्योगों में तो वह स्वयं एक पार्टी बन जाती है और मध्यस्थता या निर्णायक के गौरव पूर्ण पद पर नहीं रह सकती। जितनी राष्ट्रीयकृत क्षेत्र बढ़ता जायगा, वह उद्योगपति बनती जायगी और मजदूर समस्या का निष्पक्ष समाधान उसके लिए कठिन से कठिनतर होता जायगा। इसके समाधान का तब एक ही तरीका होगा कि वह मजदूर-असंतोष का कठोरता से दमन करे, जैसा कि पोलैण्ड व हंगरी में किया गया है। तब रूस की कम्युनिस्ट पार्टी की भांति ही शासन के पक्ष में मजदूर आन्दोलन का कठोर नियंत्रण करना होगा और तब मजदूर का आन्दोलन स्वतंत्र न होकर सरकारी मशीनरी का एक अंग मात्र हो जायगा ? क्या भारतीय समाजवादी मजदूर इस स्थिति को सहन करने को तैयार है ?

(पृष्ठ ६३७ का सेष)

और उपयुक्त परिस्थितियां और वातावरण उत्पन्न कर दिया जाए तो संसार के अन्य देशों में भी इस प्रकार की अर्थ-व्यवस्था का विकास किया जा सकता है। यह समझना भ्रमपूर्ण है कि अमेरिका ने यह आश्चर्यजनक आर्थिक प्रगति बिना किसी प्रयास के पलक झपते ही कर ली है। सत्य तो यह है कि इस प्रकार की प्रगतिशील और विकासोन्मुख आर्थिक व्यवस्था के विकास में १०० वर्षों से भी अधिक समय लग गया है, यह अवश्य कहा जा सकता है कि पिछले २५ वर्षों में आर्थिक विकास की गति बड़ी तेज रही है।

यह आवश्यक नहीं कि अमेरिकी ढंग की अर्थ-व्यवस्था ही अन्य देश आंख मूंदकर स्वीकार कर लें। हर देश की अपनी अलग अलग समस्यायें और आवश्यकताएं होती हैं और वह उन्हें दृष्टि में रख कर उसमें आवश्यक फेर-बदल और संशोधन कर सकते हैं। इसका विकास स्वाभाविक ढंग पर बिना किसी प्रकार की कठिनाई या अड़चन के सम्भव है। हर देश में जनता के पूंजीवाद का स्वरूप भिन्न होगा और उसका विकास भी भिन्न ढंग पर होगा। यह बात अवश्य है कि यूरोप के देश इसे आसानी से ग्रहण कर सकते हैं क्योंकि हमारे अधिकांश आदर्शों की जन्मभूमि यूरोप ही रहा है। 'जनता के पूंजीवाद' में इतना लचीलापन है कि वह प्रत्येक देश की परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप अपने को ढाल ले। अन्य देश हमारे सिद्धान्तों के आधार पर अपनी अर्थ-व्यवस्था का विकास कर सकते हैं। सरकार भी अर्थ-व्यवस्था के विकास में अधिक महत्त्वपूर्ण और प्रभावकारी योग दे सकती है, वशर्ते व्यवसाय और कारोबार के लिए मण्डियों पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न लगाया जाये।

——

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कार्ल मार्क्स के अनन्य सखा

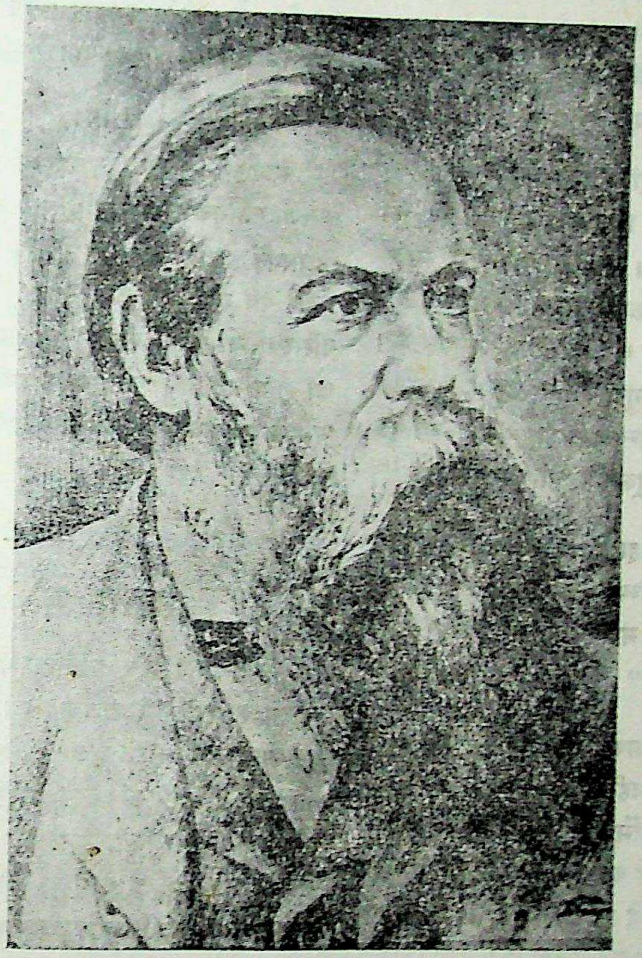

साम्यवाद के स्वप्न द्रष्टा श्री एंजेल्स

साम्यवाद के इतिहास में १८४८ ई० में प्रकाशित साम्यवाद का घोषणा-पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। इसे मार्क्स व एंजेल्स दोनों ने सम्मिलित रूप से तैयार किया था।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

साम्यवाद और धर्म

(एक विवादग्रस्त प्रश्न)

लेनिन से लेकर स्टालिन तक तथा स्टालिन से लेकर अद्यतन समय तक साम्यवाद ने कई मोड़ लिये। साम्यवाद उदार बनता जा रहा है, लेकिन धर्म के प्रति उसकी विचारधारा में परिवर्तन नहीं हुआ।

कार्ल मार्क्स ने अपने सिद्धांत द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद का प्रतिपादन किया था। इसी सिद्धान्त को मूर्त रूप देने का प्रयत्न रूस में किया गया। धर्म के सम्बन्ध में मार्क्स के विचार हैं— "धर्म मनुष्य का 'निर्माण' नहीं करता है। वरन् मनुष्य ही धर्म का निर्माण करता है। धर्म पददलित पशु की करुण गुहार है·····धर्म मनुष्य के लिए अफीम है। सच्ची प्रसन्नता के हेतु धर्म—जो एक 'छलनामय सुख' है—का उन्मूलन करना आवश्यक है।"

लेनिन ने इसी स्वर में कहा है—"धर्म मनुष्य के लिए अफीम है, एक प्रकार से आध्यात्मिक उन्माद है, जिसके कारण पूंजी के दास अपने मानवी स्वरूप और उच्च जीवन से वंचित हो जाते हैं।"

स्टालिन ने भी स्वर मिलाकर कहा है—"साम्यवादी दल धर्म के प्रति निरपेक्ष नहीं हो सकता। साम्यवादी दल को प्रत्येक प्रकार के धार्मिक विचार और धार्मिक पूर्वाग्रह के खिलाफ प्रचार कार्य करना चाहिए। धर्म के विरुद्ध प्रचार कार्य एक ऐसा साधन है जो प्रतिक्रियावादी पुरोहितों के वर्ग की हलचल को समाप्त कर सकता है।

ये दोनों कथन क्रमशः १९०५ और १९२७ के हैं। १९५३ में "सोविस्तक्या मोल द्विया" नामक बहुपठित समाचार पत्र में एक लेख धर्म के सम्बन्ध में छपा था। उसका एक अंश यह है "साम्यवादी-शिक्षा-प्रणाली में वैज्ञानिक नास्तिकवादी ज्ञान को प्रमुख स्थान मिलना चाहिए जिससे लोगों के मस्तिष्क के पूंजीवादी अवशेष, तथा पुराने समाज के दकियानूसी और खतरनाक विचारों को निकाल बाहर किया जा सके। सोवियत गणराज्य में यह कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण माना जाता है। बहुत से लोगों के विशेषकर ग्रामीण लोगों के मन में धर्म सम्बन्धी पुराने विचार अभी तक शेष है।·····धर्म की सच्चे रूप में ऐतिहासिक और वैज्ञानिक व्याख्या किये बिना लोगों का सांस्कृतिक विकास होना असम्भव है।

स्टालिन की मृत्यु के बाद रूस में कुछ ऐसे परिवर्तन हुए जो आर्थिक और राजनैतिक दृष्टि से काफी महत्व के हैं। विचारकों का मत है कि रूस का साम्यवाद उदार बन रहा है तथा विश्व की बदलती राजनैतिक परिस्थितियों और स्वयं "स्वतन्त्रता की भावना" जो आज का युग-धर्म है; को इसका कारण माना गया है। लेकिन धर्म के सम्बन्ध में अभी तक ऐसी कोई "उदारता" स्पष्ट नहीं हुई।

दोनों में तुलना

समाजवाद और सर्वोदय की तुलना करनी हो तो मैं यह कहूंगा कि समाजवाद का ध्येय है क्रान्ति, यानी सुसम्पन्नों पर दरिद्रों का शासनाधिकार और सर्वोदय का ध्येय है हृदय परिवर्तन यानी सुसम्पन्नों द्वारा दरिद्रों की सेवा। समाजवाद में क्रान्ति की सिद्धि के लिए दरिद्र सेवा (बल्कि दरिद्र सम्पर्क) एक साधन है। सर्वोदय में मानव-सेवा की सिद्धि के लिए क्रान्ति, याने शासनाधिकार की प्राप्ति, एक साधन हो सकता है। समाजवाद को परवा नहीं कि जिस क्रान्ति देवी की वह बड़ी दिव्य श्रद्धा से आराधना करता है, उसकी प्राप्त अहिंसा द्वारा ही या रक्तपात द्वारा। सर्वोदय में हिंसा के लिए गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उसमें परिवार-न्याय है। समाजवाद में इतनी ही प्रतिज्ञा है कि सब समान हैं। सर्वोदय में यह प्रतिज्ञा तो है ही, साथ ही यह भी है कि मनुष्य अहिंस्य है

—किशोरीलाल घ० मशरूवाला

[सम्पादा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

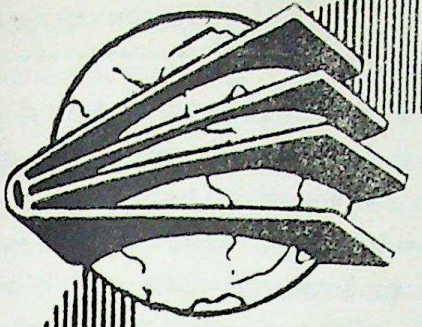

POLITICAL LITERATURE

Capital *by Karl Marx:* Vol.1	2.94 NP
Capital *by Karl Marx:* Vol.2	2.25 NP
Holy Family *by F. Engels :*	2.12 NP
Development of Capitalism in Russia *by V. I. Lenin*	2.62 NP
Peasant War in Germany *by F. Engels :*	1.25 NP
International Trade—Important Peace Factor *by M. Nesterov*	0.12 NP
International Situation & Foreign Policy of Soviet Union *by D. T. Shepilov*	0.12 NP
Selected Works *by Karl Marx & F. Engels* : Vol.1	2.25 NP
Vol.2	1.81 NP
Selected Correspondence *by Karl Marx & F. Engels*	1.87 NP
Dialectics of Nature *by F Engels*	1.25 NP
The Part Played by Labour in the Transition from Ape to Man	0.13 NP
Materialism and Empirio Criticism *by V. I. Lenin*	1.87 NP
Selected Works (in 2 Vols.) *by V. I. Lenin*	3.75 NP each
Socialism and War *by V. I. Lenin*	0.12 NP
Socialism and Religion *by V. I. Lenin*	0.12 NP
Marx, Engels, Marxism *by V. I. Lenin*	1.87 NP
The Development of the Monist View of History *by G. Plekhanov*	1.31 NP
Once More about the Historical Experience of the Dictatorship of the Proletariat:	0.12 NP

Available with:— Postage Extra

PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE
5, Jhandewalan, N DELHI.
JAYANA BOOK DEPOT
Chhappar wala kua, Karolbagh, N. DELHI.
V/o MEZDUNARODNAYA KNIGA, MOSCOW 200
U. S. S. R.

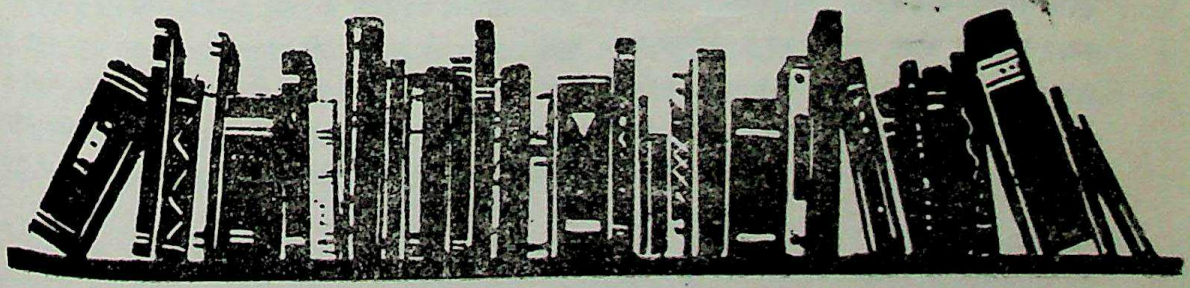

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भूदान-यज्ञ का द्वितीय चरण—सम्पत्तिदान यज्ञ

श्री ओमप्रकाश तोषनीवाल

भूदान यज्ञ आन्दोलन का अभिप्राय यदि एक वाक्य में हम समझना चाहें तो "उसका अभिप्राय है गरीब की मालकियत कायम करना," आज समाज में गरीब और अमीर का एक गहरा भेद-भाव दृष्टिगोचर होता है। संकट में दोनों ही हैं। भूदान यज्ञ का प्रादुर्भाव गरीब और अमीर दोनों के संकट को हरने हेतु हुआ है।

सम्पत्ति का स्वामी समाज

सम्पत्ति का स्वामी कौन ? उत्तर मिला है, जो उसे पैदा करे। लेकिन हमारा कहना है कि सम्पत्ति का स्वामी समाज है। फिर यदि जो पैदा करे वही सम्पत्ति का मालिक है तो भी आज इसके विपरीत समाज में चल रहा है। भूमि पर स्वामित्व उसका है, जो उसको जोतना—बोना तक नहीं जानते। कारखानों के मालिक वे लोग हैं जो श्रम के नाम पर अंगुली तक नहीं हिलाते। धनिक लोग गरीबों के सहयोग के बिना सम्पत्ति इकट्ठी नहीं कर सकते। अगर यह ज्ञान गरीबों में पहुँचकर फैले, तो वे बलशाली बनेंगे और विनाशकारी असमानताओं ने उन्हें आज भूख मरण के घाट तक ला पटका है। उनसे वे मुक्ति पाने का मार्ग अपनायेंगे। पर वे हिंसक बन जावें, हिंसा की इसी प्रवृत्ति को रोकने के हेतु और सम्पत्तिवान व मजदूर दोनों के हितों को समदृष्टि से रखकर ही संत विनोबा ने एक नये आंदोलन का श्रीगणेश किया था। अहिंसक क्रान्ति हो, इस दिशा में सर्वप्रथम विनोबा जी ने भूमि के समवितरण की बात उठाई थी। भूमि जीविका का मूल साधन है अतः पहले उसका ही सम विभाजन होना चाहिये। दूसरे हवा, जल और प्रकाश की भांति भूमि भी ईश्वरीय देन है, किसी की बनाई हुई नहीं, अतः उस पर भी समाज का आधिपत्य जिस सर्वोदय समाज की कल्पना को लेकर भूदान का कार्य चल रहा है, केवल उसी के द्वारा वह पूरा समाज नहीं बन सकेगा यह निश्चय है, क्योंकि केवल भूमि ही सम्पत्ति उत्पादन का एक मात्र माध्यम नहीं है। देश संतुलित व्यवस्था में कृषि के साथ उद्योग धंधों का भी उतना ही महत्त्व है। अतः भूदान यज्ञ के साथ—सम्पत्ति दान यज्ञ के प्रवर्तन की बात भी विनोबाजी ने सोची थी। उन्होंने कहा है, "मैंने सोचा कि पहले ही दो काम एक साथ शुरू करना ठीक नहीं हैं।" किन्तु जैसे जैसे भूदान यज्ञ का कार्य आगे बढ़ता गया, यह स्पष्टतः अनुभव किया जाने लगा कि भूमि के साथ साथ धन का अंश न मांगने से आन्दोलन में निहित उद्देश्य सिद्ध न होगा। अतः उन्होंने अपने बिहार—प्रवेश के समय २३ अक्तूबर १९५२ को वहां के प्रमुख नगर पाटलिपुत्र में सम्पत्ति दान यज्ञ की घोषणा की और लोगों से अपील की कि वे अपनी आमदनी का षष्ठांश सम्पत्ति दान में दें।

"अगर भारत को ऐसा आदर्श जीवन बिताना है, जिससे संसार को ईर्ष्या हो तो दिन भर तो ईमानदारी से काम करने का मेहनताना या मजदूरी तमाम भंगियों, डाक्टरों, वकीलों, शिक्षकों, व्यापारियों और दूसरे लोगों को एकसी मिलेगी। संभव है, भारतीय समाज इस ध्येय तक कभी न पहुँच सके, परन्तु हर भारतवासी का कर्त्तव्य है कि वह इस ध्येय के लिए प्रयत्न जारी रखे, अन्य किसी के लिए नहीं। तभी भारत सुखी हो सकता है।"

—गांधी जी

सम्पत्ति दान की पृष्ठभूमि में विचार

आज की विचार प्रणाली में जो सम्पत्ति का मालिक है, वह समझता है कि उसने मेहनत करके, चाहे वह शारीरिक हो या बौद्धिक, सम्पत्ति कमाई है, किसी की चोरी नहीं की है। कानून ने जो साधन उपलब्ध कर दिये हैं, उनके अनुसार ही उसने धन कमाया है। अतः उसे भोगने का उसका अधिकार है। यह उसका अधिकार कानून ने मान रक्खा है, समाज भी मानता है। फिर यह संत क्यों मेरा अधिकार छीनना चाहते हैं, यह बात जंचती नहीं है। साथ ही जिसको यह धान मिलेगा, उसने वह भूमि या सम्पत्ति कमाने के लिये प्रयत्न नहीं किया, उस दशा में उसका हक

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

है, यह बात कैसे मानी जाय ? बिना कमाये किसी का किसी चीज पर अधिकार कैसे हो सकता है, जबकि कानून उसका समर्थन नहीं करता। शंकाएं सभी तर्कयुक्त सी लगती हैं परन्तु इन पर विचारने की आवश्यकता है। प्रथम, क्या कानून और मान्यतायें सर्वोपरि हैं ? इस प्रश्न का हल ढूंढते समय यह ध्यान रखना होगा कि इन सबसे बढ़ कर सामाजिक न्याय भी कोई वस्तु है और वास्तव में वही सर्वोपरि है। श्री जाजूजी ने स्पष्ट कहा है "कानून तो बहुधा प्रचलित परम्परा को लेकर चलता है। समाज की मान्यता भी बहुत करके रूढ़ि को लेकर चलती है। जो बात कानून और समाज मानता है, वह सदा न्याय की ही होती है, ऐसा नहीं कह सकते।" इतिहास साक्षी है. विचार परिवर्तन के साथ साथ समाज की मान्यतायें बदली हैं और उन मान्यताओं के बदलने के साथ कानून भी बदले हैं। मनुष्य सोचने लगा कि सम्पत्ति का वास्तविक उत्पादक कौन है। यदि हम सम्पत्ति के स्वामित्व की वर्तमान विचार धारा को ही स्वीकार करलें तो भी, पूज्य विनोबा का कहना है कि "अपने परिश्रम से उपार्जित धन भी केवल अपने लिए नहीं है, बल्कि सबके उपभोग के लिए भगवान् ने वह दिया है। जिस बुद्धि, शक्ति और पुरुषार्थ की सहायता से इस धन का उपार्जन किया गया है, वह परमेश्वर का ही धन है।" सम्पत्तिदान यज्ञ की पृष्ठ भूमि में यही विचार-धारा है।

सम्पत्तिदान यज्ञ का अर्थशास्त्र

यों तो सम्पत्ति दान-यज्ञ का अर्थ धनदान, अर्थदान या आय दान होता है लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो इसके अंदर बुद्धि, शक्ति, पैसा सब कुछ आ जाता है। सम्पत्ति-दान-यज्ञ में आय का षष्ठांश मांगा गया है। गरीब, अमीर का भेद-भाव किये बिना विनोबा जी सभी से उनकी आमदन का एक छठा भाग मांग रहे हैं। उनका कहना है कि अगर किसी के पास कम है तो भी हम चाहते हैं कि वह अपनी अपर्याप्त रोटी में थोड़ी सी रोटी अपने से अधिक गरीब के लिए दे। यह तभी संभव हो सकेगा जब व्यक्ति समाज को एक परिवार के रूप में देखेगा। यह हिन्दू समाज का आदर्श और विशेषता है कि परिवार में सदस्य के पैदा होते ही उसका हिस्सा सम्पत्ति में हो जाता है। उसी आदर्श को लेकर विनोबा आज अपने को प्रत्येक परिवार के लिए उस नये सदस्य की भांति दर्शाते हैं और अपना षष्ठांश भाग असहाय और गरीब लोगों के लिए मांग रहे हैं। अगर आपके परिवार में सब लोगों के लिए पर्याप्त अन्न नहीं है और कल को उस भगवान का एक और स्वरूप आपके यहां जन्म ले लेता है तो क्या उसे भूखा रखेंगे ! सामाजिक दृष्टि से यही न्याय समाज के सब व्यक्तियों पर लागू होना चाहिए, क्यों कि राज्यकर्ता और समाज की दृष्टि में सारा देश एक परिवार है और यही सच्चा अर्थशास्त्र है।

व्यक्तिवाद का युग आज समाप्त हो रहा है और समाज-वाद की भावनायें बल पकड़ रही हैं। गांधी जी ने बहुत समय पूर्व ही इस भावना को परख लिया था और इसीलिए

पूंजीवाद कहता है कि मेहनत मजदूर की और दौलत मालिक की।

समाजवाद कहता है कि जिसकी मेहनत, उसकी दौलत।

सर्वोदय कहता है मेहनत इन्सान की, दौलत भगवान की। मनुष्य के श्रम का मूल्य नहीं, वह तो अनमोल है।

उन्होंने धनवानों और सम्पत्तिवानों के सम्मुख यह प्रस्ताव रक्खा था कि वे अपने को सम्पत्ति का ट्रस्टी समझें, क्यों कि जिस सम्पत्ति को वे अपना मानते आ रहे हैं, वास्तव में वह उनकी नहीं है, समाज की है। यही उनका ट्रस्टीशिप का सिद्धांत था। आज उसी का सफल प्रयोग विनोबा जी भूमि और संपत्ति के क्षेत्र में कर रहे हैं। और घर-घर घूमकर लोगों को इन बदलती हुई मान्यताओं का विचार समझा रहे हैं। 'अगर प्रेम का, अहिंसा का तरीका आजमाना चाहते हो तो भूमि और धन के इस महत्व को छोड़ो, नहीं तो हिंसा का एक ऐसा जमाना आने वाला है, जिसमें भूमि और धन ही नहीं, उनके मालिक भी समाप्त हो जायंगे।" इसीलिए भूमि संपत्ति के दान, के रूप में नहीं, बल्कि अधिकार के रूप में विनोबा जी मांग रहे हैं।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भूदान का तृतीय चरण : ग्रामदान

श्री श्रीमन्नारायण

ग्रामदान सब समस्याओं का हल

यह सोचना गलत है कि ग्रामदान आन्दोलन महज भारत की भूमि-समस्या हल करने का एक आन्दोलन है। यह सही है कि भूदान के बाद ग्रामदान आन्दोलन अहिंसक और शांतिपूर्ण तरीकों के जरिये हमारे देश की जमीन-संबंधी समस्या सुलझाने में ज्यादा सम्भाव्यताओं से पूर्ण है। जब समूचा गांव जमीन संबंधी निजी स्वामित्व का त्याग कर देता है और उसे ग्राम समाज को प्रदान कर देता है, तो उस हालत में अराजियों पर अधिकतम सीमा लागू करने और मुआवजा अदा करने के सवाल खुद-ब-खुद खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा, सहकारी तरीके, जिनमें एक या कई इकाइयों के रूप में जमीन इकट्ठी करना भी शामिल है, लागू करने की बहुत अधिक संभावनायें पैदा हो जाती हैं। सचमुच विनोबाजी ने यह बात साफ कर दी है कि ग्रामदान वाले गांवों में सहकारी खेती एकदम स्वेच्छा पर आधारित होगी। अगर ग्राम समाज की इच्छा होगी तो वह गांव की सारी जमीन को एक इकाई मान कर सहकारी खेती के रूप में उसे जोत-बो सकेगा। अन्यथा समाज या ग्रामसभा खेती के लिए गांव की जमीन को उचित ढंग पर मुख्तलिफ़ परिवारों में बांट देगी। इस मामले में भी, गांव के परिवार, जहां तक संभव होगा, अधिक से अधिक कार्यों में सहकारिता का तरीका लागू करेंगे। परिवारों को फिर से बंटबारे में जो जमीन मिलेंगी, उस पर निजी जायदाद के रूप में उनका स्वामित्व नहीं होगा। वे इस तरह मिली जमीन को खेती के लिए ग्रामसभा की ओर से मिली पवित्र धरोहर समझ कर उस पर काबिज रहेंगे। गांव की जमीन ग्राम समाज में निहित हो जायेगी और जमीन पर निजी मालकियत समाप्त हो जायेगी। आचार्य विनोबा जी ने इस बात पर जोर दिया है कि ग्रामदान का मतलब महज गांव की जमीन इकट्ठा कर देना नहीं। आखिर में चल कर इस का आशय ग्राम समाज के सभी आर्थिक साधनों का इकट्ठा कर देना होगा, जनमें जमीन के अलावा दूसरी संपत्तियां, श्रम और दूसरे किस्म के आर्थिक साधन, शामिल होंगे। लेकिन यह सभी सामाजिक और आर्थिक क्रांति मनुष्य की आत्मा की नैतिक और आध्यात्मिक क्रांति के जरिए ही संपन्न होगी। इस दृष्टि से, यह हिंसा, रक्तपात और वर्ग-संघर्ष पर जोर देने के जरिये लायी गई क्रांति से एकदम विपरीत है।

अहिंसक क्रांति—मिलन बिन्दु

इस समय दुनिया में दो बुनियादी विचारधारायें हैं, जिनकी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट होता है। एक तो मार्क्सवादी विचारधारा है, जो कि साम्यवाद हासिल करने के लिए हिंसा और वर्ग-संघर्ष की प्रक्रिया में विश्वास करती है। इस विचारधारा के अनुयायियों की मान्यता है कि लक्ष्य ही साधन के औचित्य को सिद्ध करता है। दूसरी ओर गांधीवादी या सर्वोदय विचारधारा है जो जरूरी तौर पर विश्वास करती है कि वास्तविक और स्थायी क्रांति केवल सच्चे और अहिंसक तरीकों से ही लायी जा सकती है। भारत ने साधनों की पवित्रता के गांधीवादी आदर्श का अनुसरण करने का निश्चय करके अपने लिए फैसला कर लिया है। इस बुनियादी सिद्धांत में किसी तरह के समझौते की गुन्जाइश नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने इस आन्दोलन का समर्थन करने का फैसला किया है, इसलिए हम आशा करते हैं कि वे बिना किसी आर्थिक दुराव के ऐसा करेंगे। अगर भारत का साम्यवाद गांधीवादी, अर्थात् शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीकों से सामाजिक और आर्थिक समानता लाने के सिद्धांतों को स्वीकार कर लेता है, तो कांग्रेस, कम्युनिस्टों तथा अन्य लोकतंत्रीय शक्तियों के बीच कटुता की कोई वजह नहीं रह जाती। अन्यथा, हमारा फर्ज होगा कि हम भारत के लोगों को लोकतंत्रीय और एकतंत्रीय विचारधाराओं के बीच बुनियादी फर्क समझा दें, ताकि आम जनता किसी खास विचारधारा के दूरगामी मन्तव्यों को साफ-साफ समझ कर ही उसे चुने।

—

[सम्पादक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

समाजवाद ग्रामदान के द्वारा ही संभव है !

श्री जयप्रकाश नारायण

ग्रामदान का महत्व समाजवाद की दृष्टि से बहुत अधिक है। देश में आज समाजवाद की ही चर्चा है। जवाहरलाल जी, पी. एस. पी. कम्युनिस्ट पार्टी आदि सब समाजवाद की बात करते हैं। जनसंघ वाले भी घुमा-फिरा कर वही बात कहते हैं। हिंदू सभा वाले भी 'हिंदू समाजवाद' चाहते हैं! पता नहीं 'हिंदू समाजवाद' क्या है? अगर वह कोई हो, तो वह भी ग्रामदान से ही सकेगा, क्योंकि ग्रामदान इसी देश की संस्कृति से निकली हुई चीज है और गांधी-विनोबा भी यहीं की उपज हैं! खैर! तो, इन मुख्य पार्टियों ने तो समाजवाद का ही ऐलान किया है। भारत कृषि-प्रधान देश है। बड़े उद्योग यहां कम हैं और उनमें काम करने वाले मजदूरों की संख्या भी यहां की जनसंख्या के मुकाबले नगण्य है। इसलिए अमरीका, इंग्लैंड आदि के समाजवाद से यहां का समाजवाद स्वभावतः भिन्न होगा। वहां पर सौ में आठ-दस-बीस लोग खेती करते हैं और यहां अस्सी प्रतिशत! यहां का समाजवाद वास्तव में कृषक-समाजवाद ही बनेगा। ग्रामदान में भी गांव का ही भूमि-स्वामित्व माना जाता है। इसका अर्थ है, समाज की ही वह संपत्ति है, जो लोगों के उपयोग के लिए सबको प्राप्त होगी; समाजवाद का भी यही मूल विचार है कि भूमि भी एक संपत्ति है और वह समाज की ही है। ऐसा हम सब जब मानते हैं, तब जितने भी समाजवादी हैं, वे इस आंदोलन का समर्थन क्यों न करें? अगर देश के सारे व्यवसायों का राष्ट्रीयकरण होता है, लेकिन कृषि-समस्या वैसी की वैसी रहती है, तो वह समाजवाद हरगिज नहीं हो सकता।

कानून से नहीं

ग्रामदान कानून से भी नहीं हो सकता, क्योंकि जमीन के मालिक लोग ही आज 'मेजारिटी' में हैं। जब उनमें विचार-परिवर्तन होगा कि भूमि का स्वामित्व-विसर्जन करना ही है, तभी ग्रामदान कानून से हो सकेगा! याने ग्रामीकरण का कानून तभी बनेगा। जब लोकमत तैयार कर लिया जायेगा, तब तक भूमि का निजी स्वामित्व कानून से कोई भी समाजवादी सरकार दूर नहीं कर सकती।

दरअसल कानून बनने पर भी प्रतिक्रिया-स्वरूप दसों समस्याएं पैदा होती हैं। फिर, राजनीतिक पार्टियों को बराबर यह खयाल रखना पड़ता है कि किन लोगों के पास शक्ति है और किन लोगों के पास वोट! इस प्रकार वे कुछ कर नहीं पाते। केरल में दोनों पक्षों की सरकारें बनीं और अब कम्युनिस्ट-सरकार है। लेकिन कोई भी १५-२० एकड़ से कम का 'सीलिंग' करने की बात नहीं करता या सीलिंग के आगे बढ़ ही नहीं पाता। जोतने वाले की जमीन हो और वह दूसरे के हाथ में कतई न रहे, इतना भी यदि उनसे हो जाय, तो काफी है! लेकिन 'पर्सनल कल्टिवेशन' (जोतने वाले को जमीन) के कानून में से भी घुमा-फिरा कर शोषकों को वापस कैसे उसी जगह पर लाकर बिठा दिया जाता है, यह हम जानते हैं! इसलिए एक ओर मामूली किसान, तो दूसरी ओर महाराजाधिराज दरभंगा भी आज 'पर्सनल कल्टिवेटर' हैं! मतलब यह कि गुत्थी को काट हो नहीं पा रहा है। बम्बई का कानून कुछ आगे बढ़ा, फिर भी समस्या का हल यह नहीं निकाल सका। परन्तु इधर ग्रामदान में हम देख रहे हैं कि भूमि-संबंधी निजी स्वामित्व-भावना कैसे सम्पूर्णतया समाप्त हो रही है! और ग्रामदान तथा ग्रामराज तो कानून के सपने में भी आज नहीं आ सकते।

भूमि राज्य की नहीं, जनता की

अभी तो लोग यह भी समझ नहीं पाये हैं कि वास्तव में जमीन है किसकी! वे कह देते हैं, वह राज्य की है। पर यह बिलकुल गलत बात है। जमीन तो जनता की है और राज्य व जनता में बहुत अन्तर है। लोग मालिक हैं, लोग ही जमीन की व्यवस्था करें। सरकार लगान भी क्यों लेती है? वह आमदनी पर कुछ टैक्स लेती है, सो तो ठीक है, क्योंकि उसको हमारा डाक-तार-रेल का कुछ प्रबंध करना पड़ता है, लेकिन वह लगान क्यों ले, जबकि मालिक वह नहीं, जनता ही है!

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तानाशाही भी नहीं

तो, कानून के और सरकार के फेर में ही यदि हम रहेंगे कि समस्या उनसे हल होगी, तो यह तय है कि कम-से-कम आज की डेमोक्रेसी में ऐसा कानून सफल नहीं हो सकता। और अगर तानाशाही बरती जाय, तो वह स्वयं अपने-आप में ऐसी समस्या बन जाती है कि जिसका कोई हल ही नहीं है! फिर, तानाशाही में क्या स्थिति है, यह भी हम रूस में देख ही रहे हैं। उन्होंने सारी जमीनें छीन कर राज्य को मालिक बना दिया। हजारों मारे गये, कैद में डाले गये, जख्मी हुए और किसानों को जबर्दस्ती सामूहिक खेती में लगाया गया। लेकिन जानकार लोगों ने लिखा है कि अधिकांश लोग आज भी व्यक्तिगत कृषि ही चाहते हैं, हालां कि आज वह वहां चल नहीं सकती, क्योंकि न तो उनके पास हल रहे हैं और न घोड़े! ट्रैक्टर भी स्टेट के हैं। वे लेकर एक-एक किसान अलग-अलग खेती नहीं कर सकता और न राज्य ही उसको इसके लिए मदद करेगा। ऐसी हालत में भी सामूहिक खेती के लिए उनका मन तैयार नहीं। बाद में स्टालिन ने परिवार के पीछे दो-तीन एकड़ जमीन दी, ताकि वे तरकारी पैदा करें, मुर्गी-सूअर पालें आदि। तो लोगों का उसी में ज्यादा मन लगता था। फिर सरकार को कड़े नियम बनाने पड़े, जैसे सामूहिक खेती का औजार कोई अपनी पारिवारिक खेती में नहीं ले जा सकता, आदि। इस तरह दिक्कतें खड़ी करते गये, फिर भी वे मन को नहीं बदल पाये। हृदय-परिवर्तन या मौलिक परिवर्तन की बात तो छोड़ दीजिये, एक मामूली परिवर्तन भी वहां डिक्टेटरी-कानून से नहीं हो सका।

चीन के बारे में लोगों की कुछ भिन्न राय है। वहां से आने वाले कुछ महानुभाव वहां की हालत से बहुत प्रसन्न हैं और प्रशंसा करते हैं। अगर उनकी बतायी हुई हालत सही है, तो उसका भी कारण है, रूस और चीन की क्रांतियों का अंतर। रूस की क्रांति अल्पसंख्यकों की थी, चीन की बहुसंख्यकों की। माओ त्से तुंग के पीछे अधिकांश किसान-मजदूर हैं, ऐसा हमें लगता है, तभी उनकी योजनाएं लोग उत्साहपूर्वक चलाते हैं। लाखों को-आपरेटिव फार्म दो साल में वहां बन गये! "डिक्टेटरशिप में सब कुछ हो सकता है, बहुमत की डिक्टेटरशिप अल्पमत पर वहां है! परन्तु ग्रामदान के तरीके में तो ऐसी कोई चीज ही नहीं है और वह सब तरह से सफल है।

राज्य शक्ति

आज ये तीन राज्य-व्यवस्थाएं हैं: मंगलकारी राज्य, समाजवादी व्यवस्था और साम्यवादी व्यवस्था। इन तीनों में राज्य-शक्ति बढ़ ही रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्न, वस्त्र, निवास आदि बुनियादी आवश्यकताओं में राज्य का दखल है। हम इसे ही मानवता के लिए घातक समझते हैं। जनता का पुरुषार्थ विकसित हो, परस्पर-विरोधी स्वार्थ न रहें, प्रेम स्वावलंबन बढ़े, इसकी ओर हमें जनता को ले जाना है और यह हर लोकतंत्र-प्रेमी, स्वातंत्र्य-प्रेमी का कर्तव्य है कि इस नयी किस्म की गुलामी का विरोध करे। जिस तरह रेलगाड़ी में खतरे में जंजीर काम करती है, उसी तरह राज्य काम करे। यह सब एकदम नहीं हो सकता। इसके लिए जनता का नैतिक विकास करना होगा, उसे कर्तव्य-परायण बनना होगा। दूसरों के अधिकार का ध्यान रखना होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि यह राजनीतिक या आर्थिक नहीं, बल्कि नैतिक प्रश्न है। स्वार्थों का संघर्ष रहेगा, तो नैतिकता नहीं बढ़ेगी। जहां दूसरों का शोषण और दमन होगा, वहां सर्वोदय में इतना नैतिक विकास होगा कि लोग यह समझेंगे कि अपने देश में इतने भूखे-नंगे लोग हैं, इसलिए हम ऐश-आराम नहीं लेंगे, आवश्यकता भर लेंगे। इसका निर्णय भी वे स्वयम् करेंगे। हमसे गरीब के समान होकर रहना तो संभव नहीं होगा, परन्तु आवश्यकताएँ कम-से-कम करेंगे। उस नैतिक विकास से सभी आर्थिक-राजनैतिक प्रश्न हल होंगे और उसी में से एक ऐसी राज्य-व्यवस्था प्रकट होगी, जो सच्चे अर्थ में लोकतांत्रिक कही जायगी।

गांधीजी ने सम्पत्ति के क्षेत्र में एक शब्द का प्रयोग किया था—"ट्रस्टीशिप।" विनोबाजी ने उसका विकास आज भूदान, संपत्ति दान के रूप में किया है।

—

समाजवाद के दर्शन और चिन्तन में सर्वोदय अन्तिम शब्द है। —जयप्रकाश नारायण

——

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

समाजवाद और हम

[पृष्ठ ५५० का शेष]

हम सभी इस बात पर सहमत है और वास्तव में यही हमारी दृढ़ नीति भी है कि हमें समाजवादी समाज बनाने की दिशा में प्रयत्न करना चाहिए। इस दिशा में बढ़े बिना इस युग की समस्याओं का सामना नहीं कर सकते।

हर एक उद्योग के अन्धाधुन्ध राष्ट्रीयकरण में मेरा विश्वास नहीं है, क्योंकि जब आप राष्ट्रीयकरण करेंगे, तो आपको क्षतिपूर्ति करनी होगी। मेरी समझ में नहीं आता कि हम हरजाना देने में आपना रुपया क्यों नष्ट करें। मैं उनके राष्ट्रीयकरण की अपेक्षा एक नया कारखाना खोलना व निजी कारखाने से प्रतियोगिता करना पसन्द करूंगा।

\+ + +

आजकल प्रायः वर्तमान उद्योगों को ही सरकार के अधिकार में लाने की बात पर ध्यान दिया जाता है न कि राज्य द्वारा या राज्य के अंकुश में नये उद्योगों के निर्माण पर। अच्छा यह रहेगा कि राज्य अपना अधिक ध्यान मौजूदा ढंग के नये उद्योगों पर दें और उनका पूरा नियंत्रण रखें, क्योंकि तब राज्यके कुल साधन देशकी उन्नति के लिए उपयोगमें आवेंगे, न कि केवल एक मौजूदा चीज पर अधिकार करनेके लिए।

\+ + +

वितरण बहुत आवश्यक है, लेकिन उससे भी अधिक आवश्यक है हमारा प्रगतिशील भविष्य। नई परिस्थितियों में नए साधनों को व्यक्तियोंके हाथोंमें पहुँचकर व्यक्तिगत एकाधिकार में पड़ने से बचाना चाहिए। वर्तमान साधनों का जहां तक मामला है, हमें एक-एक कदम बढ़ना चाहिए।

\+ + +

हमारे कम्युनिस्ट भाई हैं, जिनकी जड़ बुनियाद हमारे देश में नहीं है। न उनके दिमाग की जड़ हमारे देश में है और न काम की जड़ हमारे देश में है। वे हर चीज को ऐसे गज से नापते हैं, जो हमारे देश का गज नहीं है।

अपने लिये और राष्ट्रीय उन्नति के लिये बचाइये

पंजाब नैशनल बैंक आप लोगों की बचत को देश के साधनों का सदुपयोग करने में लगातार देश की सेवा कर रहा है

कार्यगत कोष १५२ करोड़ रुपये से अधिक

दि पंजाब नैशनल बैंक लिमिटेड

स्थापित : सन् १८९५ ई०

प्रधान कार्यालय—दिल्ली

चेयरमैन
श्री एस० पी० जैन

जनरल मैनेजर
श्री ए० एम० वाकर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"बनिया हाकिम गज़ब खुदा का"

श्री सत्यप्रकाश मिलिन्द

समय के डगमगाते पांवों को देखकर मनुष्य सशंकित अवश्य हुआ, पर उसने अपनी चेतना को नहीं गंवा दिया। अध्यवसाय, लगन और निष्ठापूर्ण त्याग ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित ही किया। नई चेतना ने उसके अन्तर को उद्वेलित कर दिया और संकल्प व विकल्प की आंधी ने उसको बहा ले जाने की चेष्टा की, लेकिन उसने अपनी आवश्यकताओं का लेखा जोखा तैयार किया, अपने अतीत पर एक दृष्टि डाली। वर्तमान के प्रति असंतोष व्यक्त किया और भावी को सुधारने की जुस्तजू में लग गया। गरीबी और असमानता ने उसको झकझोर डाला और उसने इतिहास के पन्नों को पलटा! उसका दृढ़ विश्वास हो गया कि कोई भी महज इसलिए बड़ा नहीं है कि वह बड़े घराने में पैदा हुआ है। सचेत होकर उठ खड़ा हुआ और समाज सेवा और आत्म-सेवा दोनों का उसने समन्वय किया। फिर लेनिनवाद, स्तालिनवाद और वर्तमान साम्यवाद का अध्ययन किया। उसे लगा कि कम्यूनिस्ट मार्क्सवादी सिद्धान्तों के आधार पर स्वार्थों का दमन और उन्मूलन सर्वहारा क्रान्ति द्वारा करना चाहते हैं। उसे यह पसंद नहीं आया। जिज्ञासु मानव ने मार्क्स की 'कैपिटल' में समझाये गये 'पूंजी और पदार्थ' के सम्बन्ध को समझना चाहा। 'सी—एम—सी' और एम—सी—एम के खरीदने और बेचने के फार्मूलों का उसने अध्ययन किया, लेकिन वह इसी निष्कर्ष पर पहुँचा कि समाज में फैले वर्ग, और पूंजीवाद की विनाशक प्रवृत्तियों के कारण ही यह सब ढोंग रचा जाता है। उसने एक स्थान पर पढ़ा था "अमेरिका में श्रमिक पूंजीपति भी हैं और पूंजीपति भी श्रम करते हैं।" यही तो बापू चाहते थे। वे कहते थे कि जो व्यक्ति शारीरिक श्रम की अवहेलना करता है, वह अनजाने में अपना ही अहित करता है।"

समाज को सामाजिक ढांचे में तोलने की बात तभी उसके मस्तिष्क में आई। वह कह उठा, "निस्संदेह बात तो बड़ी अच्छी लगती है। सुनने में तो कड़वी नहीं है। बरतने पर पता चले।" और तभी एक अन्तर्द्वन्द्व उठ खड़ा हुआ उसके मस्तिष्क में। उसने पढ़ा था—"To be democratic is to want to live co-operatively" वह सोचने लगा, समाज में समानता आजावे तो फिर असमानता के कारण फैला आज का वर्ग द्वेष, कलह, लिप्सा और मारकाट ही समाप्त हो जावे तो कितना सुन्दर हो। दूसरे ही क्षण उसे ध्यान हुआ कि यदि 'कम्पीटीशन, नहीं रहेगा तो इंसान की जिन्दगी ही गतिहीन हो जायेगी।

उसे याद हो आया कि अभी हाल ही में शायद दिसम्बर १९५४ में ही तो हमारे देश की पार्लियामैन्ट ने भारत की प्रगति के लिए, उसकी चंहुदिशि उन्नति के लिए "सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसायटी" समाज की समाजवादी व्यवस्थाओं का निर्णय किया है। सरकार तभी से निरंतर इस बात का प्रयत्न कर रही है कि देश में समाजवादी अर्थ-व्यवस्था की स्थापना हो, समाजवादी व्यवस्था हो, देश का हरेक व्यक्ति खुशहाल हो, दो वक्त हर आदमी और औरत खाना पा सके और आराम से तन ढकते को कपड़ा और सोने को छांह पा सके, यह तो नितान्त आवश्यक ही है। लेकिन इसकी प्राप्ति के लिए शोषक साधनों को अपनाकर गलत मार्ग का अनुसरण न हो जावे, हमें इस बात के लिए सतर्क रहना चाहिये। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार और सामाजिक संस्थाएं हर आदमी तक समाजवादी ढांचे की पहुँच के साधनों को समझावें और उन्हें ऐसे मार्ग का अनुकरण करने के लिए प्रेरित करें, जिससे कि हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो सके।

मानव घबड़ा सा गया—उसका विश्वास डगमगाने लगा। वह नहीं सोच सकता कि क्या करे। तस्वीर के दोनों पहलू उसके सामने हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था का नारा लगाने वाले बहुत से भाइयों और बहिनों को तो अभी तक समाजवादी समाज व्यवस्था के निर्दिष्ट लक्ष्य का भी पता नहीं है। आगे आने वाले चौराहों पर कई लाख बत्तियां खतरे का ऐलान करती हैं—राही! कहती हैं, देख कर चलो, टकरा गए तो साइकिल भी चकनाचूर हो जायेगी और तुम भी घायल। स्वर्ग के भीतर घुसना चाहते

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हो, मगर मार्ग मालूम है क्या ? अगर है तो पहले रास्ता मालूम करो। उसके लिए साधन जुटाने होंगे और साधना करनी होगी ! समझो और बूझो। समझ में नहीं आता तो अन्धानुकरण मत करो।

सरकार अपनी हो या पराई, उसका नियंत्रण रहे, लेकिन वह सीमित ही रहना चाहिए। अगर पूरा अधिकार ही सरकार का हो गया तो फिर तो व्यक्ति में आगे बढ़ने की भावना ही समाप्त हो जावेगी। मानव ने विचार किया, उसे बात युक्तिसंगत जंची और वह इस निर्णय पर पहुँचा कि बिना व्यक्तिगत प्रयास के, कम्पिटीशन की समाप्ति से जीवन की गति स्थिर सी हो जाती है।

"पार्टी और सरकार—सरकार और पार्टी"—शक्तिशाली पार्टी सरकार बनाती है। जनतन्त्र का यह आधारभूत सिद्धान्त है, पर बलवान दल के आगे कम्पीटीशन समाप्त होने पर केन्द्रीभूत सत्ता-प्राप्त सरकार एक 'डिक्टेटर' का रूप ग्रहण कर लेगी।

मानव फिर सहसा और विकलता के साथ छटपटाया। डिक्टेटर और इस शब्द के साथ ही 'हिटलर' व स्टालिन का भयावना रूप उसके सामने आ गया। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पुनीत और प्राचीन भारत में ऐसा कभी होगा ही नहीं—फिर इसकी कल्पना ही क्यों की जावे ?

जीवन-बीमा कम्पनी का राष्ट्रीयकरण किया गया, बसों पर बहुत सी जगहों पर सरकार का अधिकार है। होता यह है कि वहां आदमी सरकार के नौकर हैं, जनता से सम्पर्क कम होता जा रहा है।

यह सही है कि In the Socialist System Capital is deemed to be the savings of the nation which are pooled together for the good of the Society and is therefore not considered to be private Property. समाजवाद व्यक्तिगत पूंजी संचयन की आवश्यकता की भर्त्सना करता है, पर उद्योगों के सर्वांगीण राष्ट्रीयकरण से समस्या हल नहीं होने वाली है, गुत्थी उलझ भले ही जावे।

दिमाग को सोचने दीजिये, अपनी अकल को काम करने दीजिए। सोचना बंद मत कीजिए, फिर सरकार ही व्यवसाय करे, उद्योग चलाए और बन्दूक ताने—खुदा ही हाफिज है। अपने को गांव की एक कहावत याद है—

"बनिया हाकिम गजब खुदा का"। मैं भी बनिया हूँ मेरा बनिए से मतलब है—व्यवसायी से, उद्योग-धन्धे वाले और व्यापारी से।

मानव ने अपने को संभाला और बोला "नहीं, नहीं ! ऐसा नहीं होगा। समाजवादी ढांचे का मतलब सिर्फ उद्योग-धन्धों के राष्ट्रीयकरण से ही तो नहीं है। हमें अभी समाजवाद को समझना चाहिए, समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में इन्सान में यह माद्दा पैदा करना होगा कि वह यह अनुभव करे कि वह जो कुछ भी करता है, उसमें राष्ट्र का हित निहित है। एडवर्ड कारडेज ने Fouth Congress of the Peoples' front की रिपोर्ट में कहा था" By leaving the management of production to the state or the state apparatus the revolution in fact began to create its own grave-diggers."

अस्तु। इधर उधर घूमकर सोच विचार आज के मानव ने विचार बनाया है कि उद्योगों में सामुदायिक व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि मानव उन्मुक्त हो और उसका श्रम उन्मुक्त हो। मानव उन्मुक्त होकर ही उन्मुक्त रूप से अपनी उन्नति के लिए यत्न कर सकता है—सरकारी नौकरी से दिमाग शिथिल हो जाता है और आदमी मेहनत करना और पहल करना छोड़ देता है, ऐसा कई लोगों का ख्याल। है अस्तु। समाजवादी ढांचा बड़ा अच्छा है, पर समाजवाद का अर्थ यही नहीं होना चाहिए कि मानव आलसी या निकम्मा हो जावे अथवा उसमें आगे बढ़ने की प्रवृत्ति ही न रहे।

जबरदस्ती का परिणाम

एक लड़के ने गेहूं का दाना बोया। दो घंटे के बाद वह देखने को गया कि उगा या नहीं ? दो-दो घंटे बाद वह सतत तीन दिन तक देखता रहा, परन्तु वह उगता हुआ दीखा नहीं, तो आखिर वह ऊब गया और उसको बाहर खींच लिया। अब वह बढ़ेगा ? जबरदस्ती का परिणाम होता है कि खींचने से वह जल्दी हाथ में आता है, लेकिन उसका गेहूं खत्म हो जाता है। आप अगर कानून से समाजवादी परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो वह इसी ढंग का होगा।

—विनोबा भावे

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

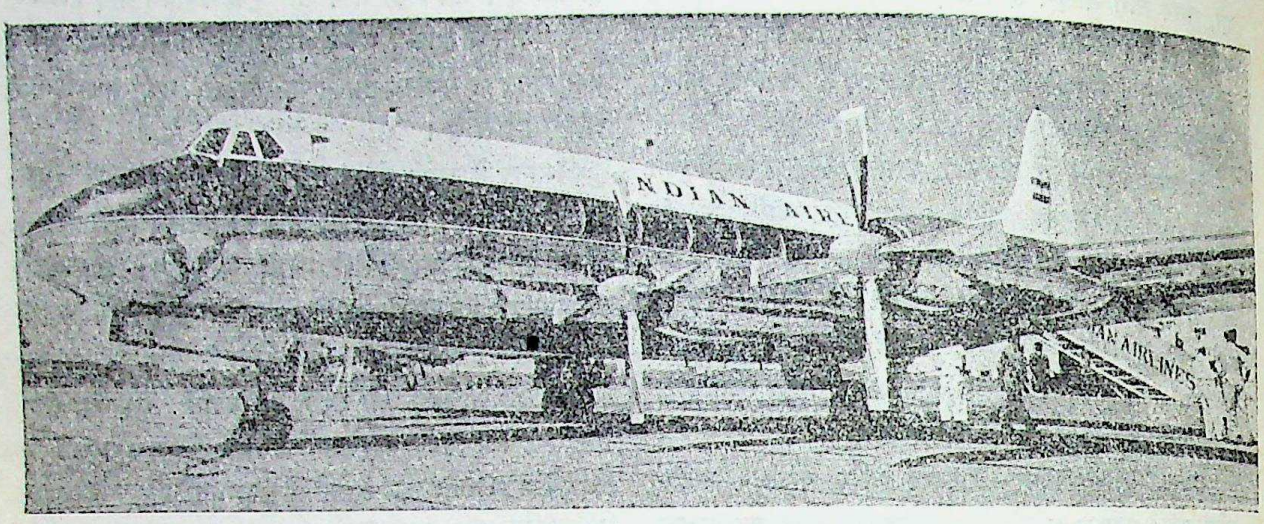

वाइकाउण्ट विमान कलकत्ता से उड़ने को तैयार (१० अक्टूबर ५७)

राष्ट्रीय वायु यातायात का नया प्रयत्न

भारत के समाजवाद की दिशा में भारत सरकार ने प्रारम्भ में जो कदम उठाये, उनमें मई १९५३ में हवाई यातायात का राष्ट्रीयकरण बहुत महत्वपूर्ण था। सरकारी स्वामित्व में आने के बाद एक के बाद एक ऐसे कदम उठाये गये, जिनसे यह उद्योग प्रगतिशील और व्यवस्थित होता गया। राष्ट्रीयकृत वायु-यातायात के क्षेत्र में सबसे नया महत्वपूर्ण कदम ७ अक्तूबर १९५७ को वाइकाउण्ट विमानों का प्रचलन है।

१० अक्तूबर को, एअर लाइन्स इन्टर नेशनल का यह नवीन नीले रंग का, चुस्त, तह में लाल और सुनहरे रंग से सुसज्जित विमान भारत के गौरववान राष्ट्रध्वज को लिये रंगून की ओर उड़ा। इस वर्ष के अन्त तक ऐसे विमानों का एक बेड़ा ही बन जायेगा। इस समय ये वाइकाउण्ट विमान केवल दिल्ली-कलकत्ता, कलकत्ता-दिल्ली और रंगून कलकत्ता मार्ग पर चलेंगे। अगले वर्ष इनका विस्तार हो जाने पर बम्बई दिल्ली, बम्बई कलकत्ता, बम्बई करांची, बम्बई मद्रास, त्रिची कोलम्बो, दिल्ली हैदराबाद, हैदराबाद मद्रास, मद्रास कलकत्ता और दिल्ली करांची के मार्गों पर भी चलने लगेंगे। श्रीनगर तक भी इस सर्विस को ले जाने का विचार है।

वाइकाउण्ट नवीनतम किस्म के वायुयान हैं। प्रोपेलर टर्बाइन शक्ति से चलने वाले ये सर्वप्रथम विमान हैं। इनसे अधिक तेज गति से अधिक माल तथा मुसाफिरों को इधर-उधर पहुँचाया जा सकता है। इसके रौल्स-राईस डार्ट इंजिन बहुत कम शोर करते हैं और सवारियों को बहुत आरामदेह रहते हैं। ३०,००० फीट की ऊंची उड़ान पर भी इन

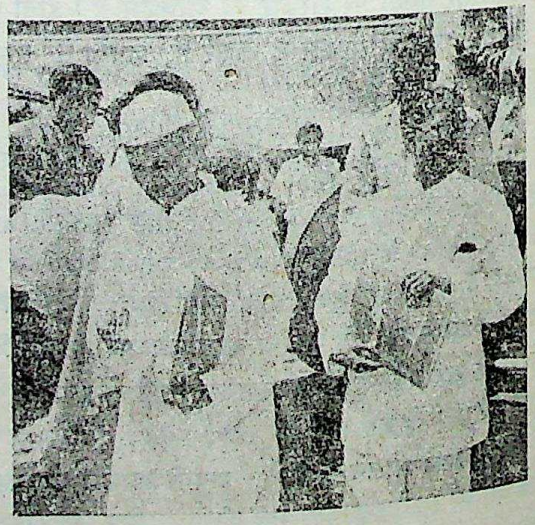

यातायात मंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री

[सम्पादा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वायुयानों में बैठे हुए यात्री साधारण वायुमंडल की स्थिति का ही अनुभव करेंगे। उनकी खिड़कियां इस प्रकार हैं कि आकाश, पृथ्वी और समुद्र के उत्कृष्ट दृश्यों का आनन्द लिया जा सकता है। खिड़कियों से अन्दर आने वाला प्रकाश यात्रियों को स्वस्थ और प्रसन्न रखेगा, चाहे कितनी लम्बी यात्रा क्यों न हो। इसमें एक गलियारा भी है, जिस में भोजन, चाय आदि 'सर्व' किये जा सकते हैं। हाथ मुंह व प्रसाधन के लिए भी दो कक्ष हैं। ३०० मील प्रति घंटे की इनकी उड़ान की सामर्थ्य से यात्रियों के समय की काफी बचत होगी। सामान्य वायुयानों से दिल्ली से कलकत्ते ४ घंटे ४० मिनट लगते हैं, जबकि इन नये वायुयानों से केवल ३ घंटे १५ मिनट लगेंगे। दिल्ली से बम्बई जाने में भी १ घंटा १० मिनट की बचत होगी।

इस नये वाइकाउण्ट विमान का संक्षिप्त परिचय यों दिया जा सकता है—४ रौल्स राइस डार्ट, १,७८० अश्व शक्ति वाले इंजिन, ६३,००० पौंड सामान और ४४ मुसाफिरों को ले जाने की सामर्थ्य और ३२५ मील प्रति घंटा की चाल। इन तीव्रगामी वायुयानों से यह भी संभव हो जायगा कि पाकिस्तान, बर्मा व लंका का भारत के प्रमुख नगरों से सम्बन्ध हो जाय। ये वाइकाउण्ट वायुयान बहुत दूर तक बिना रुके जा सकते हैं। निकट भविष्य में ही उत्तरी यूरोप से मध्यपूर्व व भारत होते हुए वायुयान मलय प्रायद्वीप तक एक उड़ान में जा सकेंगे। वस्तुतः विकर्स कम्पनी के विकर्स वायुयानों और रौल्स राइस के प्रसिद्ध इंजिनों के सम्बन्ध से नये तीव्रगामी, आरामदेह और ज्यादा मुसाफिर व माल ले जाने वाले इन वायुयानों का निर्माण हुआ।

इन नये वायुयानों से यह विश्वास किया जा सकता है कि भारत सरकार का यह राष्ट्रीयकृत उद्योग और भी अधिक सफलता प्राप्त करेगा और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण ठीक दिशा में किया जा रहा है, यह सिद्ध हो जायगा।

कबीर और आर्थिक समानता

"पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम।
दोनों हाथ उलीचिये, यही सयानो काम॥"

हिन्दी और मराठी भाषा में प्रकाशित होता है।

उद्यम

सर्वोपयोगी हिन्दी उद्यम प्रतिमाह १५ तारीख को पढ़िये

अब प्रतिमास 'उद्यम' में नावीन्यपूर्ण सुधार देखेंगे

— नई योजना के अन्तर्गत 'उद्यम' के कुछ विषय —

विद्यार्थियों का मार्गदर्शन—परीक्षा में विशेष सफलता प्राप्त करने के तथा स्वावलम्बी और आदर्श नागरिक बनने के मार्ग।

नौकरी की खोज —यह नवीन स्तम्भ सबके लिए लाभदायक होगा।

खेती-बागवानी, कारखानेदार तथा व्यापारी वर्ग—खेती-बागवानी, कारखाना अथवा व्यापारी-धन्धा इन में से अधिकाधिक आय प्राप्त हो, इसकी विशेष जानकारी।

महिलाओं के लिए—विशेष उद्योग, घरेलू मितव्ययिता, घर की साजसज्जा, सिलाई-कढ़ाई काम, नए व्यंजन।

बाल-जगत्—छोटे बच्चों की जिज्ञासा तृप्ति हो तथा उन्हें वैज्ञानिक तौर पर विचार करने की दृष्टि प्राप्त हो इसलिए यह जानकारी सरल भाषा में और बड़े टाइप में दी जाएगी।

'उद्यम' का वार्षिक मूल्य रु० ७।- भेजकर परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को उपयोगी यह मासिक-पत्रिका अवश्य संग्रहीत करें।

उद्यम मासिक १, धर्मपेठ, नागपुर-१

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पंचवर्षीय योजना व समाजवाद

द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मूलभूत उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना है। इस सम्बंध में योजना आयोग की रिपोर्ट के दो महत्त्वपूर्ण उद्धरण यहां दिये जा रहे हैं:—

"जीवन-स्तर में उत्थान एवं "भौतिक समृद्धि" (जैसा कि अक्सर कहा जाता है) की प्राप्ति ही अन्तिम लक्ष्य नहीं है। असल में यह तो एक तरीका है, जिसके जरिये बौद्धिक एवं सांस्कृतिक जीवन को समुन्नत बनाया जाय। आर्थिक विकास के जरिये हम समाज की उत्पादन शक्ति को बढ़ावा देना चाहते हैं, ताकि एक ऐसी फ़िजा तैयार, हो जिसमें विभिन्न प्रकार की आकांक्षाओं और आंतरिक शक्तियों का परीक्षण और उपयोग हो सके। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आरम्भ से ही विकास के ढांचे का और जिस प्रणाली या आर्थिक कार्यक्रम को निर्देशित किया जाय, उनका समाज के इन मूलभूत उद्देश्यों के साथ समन्वय होना आवश्यक है।"

"समाजवादी ढंग के समाज का, जिसे हम स्थापित करना चाहते हैं, अर्थ यह है कि हमें अब निजी मुनाफे को आधार-भूत निर्णायक रूप में नहीं रखना है, बल्कि सारे प्रयासों को सामाजिक लाभ की कसौटी पर देखना है। विकास की प्रणाली और आर्थिक—सामाजिक सम्बन्धों के ढांचे को इस प्रकार आयोजित किया जाना चाहिये कि उसके परिणामस्वरूप केवल राष्ट्रीय आय और रोजगार में ही वृद्धि न हो, बल्कि उससे आमदनी और पूंजी में भी अधिकाधिक समानता प्राप्त की जा सके। उत्पादन, वितरण, उपभोग तथा विनियोग के सम्बन्ध में मुख्य फैसले—और सच तो यह है सामाजिक आर्थिक सम्बन्धों की सारी रूप रेखा का निर्माण—सामाजिक उद्देश्य को दृष्टि में रखकर करने होंगे। आर्थिक विकास का लाभ अधिकाधिक रूप से समाज के कम अधिकार-प्राप्त वर्गों को पहुँचना चाहिये और इसी प्रकार आय, धन और आर्थिक सत्ता का केन्द्रीयकरण धीरे-धीरे घटता जाना चाहिये। समस्या यह है कि हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है, जिसमें उस साधारण व्यक्ति को, जिसे अब तक संगठित प्रयास के जरिये से उन्नति की विशाल संभावनाओं में भाग लेने तथा उसकी भलाई से परिचित होने के कम मौके मिले हैं, देश की बढ़ती हुई समृद्धि और अपने लिए एक उच्चतर जीवन स्तर स्थापित करने के लिए भरपूर प्रयत्न करने का अवसर मिल सके। इस प्रकार वह आर्थिक तथा सामाजिक रूप से उन्नति कर सकता है। इस तरह एक दिशा की बजाय सब दिशाओं में श्रम का संगठन करना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि यह भावना कि योग्य व्यक्ति को जन्म के संस्कार एवं प्रारम्भिक जीवन में उत्थान के उपकरणों के अभाव में अपने जीवन में आर्थिक एवं सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने का मौका नहीं मिल पाता'—न केवल उसकी आशाओं का नाश कर देती है, बल्कि उसके प्रयत्नों को भी जड़ बना देती है।"

जीवन साहित्य

हिन्दी के उन मासिक पत्रों में से है, जो

१. लोकरुचि को नीचे नहीं, ऊपर ले जाते हैं,
२. मानव को मानव से लड़ाते नहीं, मिलाते हैं,
३. आर्थिक लाभ के आगे झुकते नहीं, सेवा के कठोर पथ पर चलते हैं,

जीवन साहित्य की सात्विक सामग्री को छोटे-बड़े, स्त्री-बच्चे सब निःसंकोच पढ़ सकते हैं। उसके विशेषांक तो एक से एक बढ़कर होते हैं।

जीवन साहित्य विज्ञापन नहीं लेता। केवल ग्राहकों के भरोसे चलता है। ऐसे पत्र के ग्राहक बनने का अर्थ होता है राष्ट्र की सेवा में योग देना।

वार्षिक शुल्क के ४) भेजकर ग्राहक बन जाइए।
ग्राहक बनने पर मण्डल की पुस्तकों पर
आपको कमीशन पाने की भी सुविधा हो जायगी।

सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली।

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

यह समाजवाद अंक—

'सम्पदा' की यह परिपाटी रही है कि वह भिन्न-भिन्न विषयों पर कुछ लेखों का संग्रह मात्र न करके किसी एक महत्वपूर्ण विषय पर अनेक विचारपूर्ण लेख और सामग्री देकर पाठकों का ज्ञान-वर्द्धन करने के लिए विशेषांक प्रकाशित करती है। 'सम्पदा' का उद्देश्य पाठकों में आर्थिक चैतन्य उत्पन्न करना है, ताकि वे भिन्न-भिन्न प्रश्नों पर स्वयं विचार कर सकें। इसी उद्देश्य से 'सम्पदा' के विशेषांक प्रकाशित किये जाते हैं।

"समाजवाद-अंक" भी उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। आज जिस तरह समाजवाद की चर्चा देश में फैल रही है, उससे पाठक अपरिचित नहीं हैं। किन्तु समाजवाद क्या है, साम्यवाद क्या है; उसके परिणाम क्या हैं, भिन्न भिन्न वर्गों पर उसका क्या प्रभाव होगा, यह सब विचार करने के विषय हैं। हमारी यह इच्छा थी कि इन सब विषयों पर इस अंक में विस्तृत विचार किया जाय और भिन्न भिन्न दृष्टि-कोणों से लेख दिये जायें, किन्तु ज्यों-ज्यों हम इस अंक के लिए सामग्री जुटाने लगे, त्यों-त्यों इस विषय के व्यापक क्षेत्र और विभिन्न समस्याओं को देखकर हम यह अनुभव करने लगे कि सीमित कलेवर के एक अंक में सब प्रश्नों पर विस्तृत विचार संभव नहीं है, तथापि हमने यह प्रयत्न किया है कि यथासंभव विविध दृष्टिकोण इस अंक में पाठकों के सामने आ जायें।

'सम्पदा' किसी 'वाद' या 'इज्म' में विश्वास नहीं करती। उसकी प्रधान दृष्टि राष्ट्रीय हित है। सभी वाद या इज्म उसके लिए साधन हैं, साध्य नहीं। इसलिए किसी पक्ष विशेष से उसका आग्रह भी नहीं है। प्रस्तुत अंक में इसी दृष्टि से साम्यवाद, समाजवाद, सर्वोदय, मिश्रित अर्थ-व्यवस्था, भारत सरकार का समाजवाद और निजी उद्योग सभी पक्ष दिए गये हैं। जहाँ रूस, चीन और यूगोस्लेविया की अर्थ-पद्धति का परिचय दिया गया है, वहाँ अमेरिका की पूंजीवादी नयी व्यवस्था, का परिचय भी पाठकों को देने में संकोच नहीं किया। साम्यवाद और समाजवाद की आलोचना यत्र-तत्र हुई है। इसका उद्देश्य पाठक को निष्पक्ष होकर विचार के लिए अवसर प्रदान करना है।

आज अर्थ और राजनीति को पृथक् नहीं किया जा सकता। इसलिए साम्यवाद और लोकतंत्रवाद की पद्धतियों को राजनीति से पृथक् करके देखना कठिन है। रूस का साम्यवाद अपने साथ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को मिलाये हुए है। वह केवल अर्थ-व्यवस्था नहीं है। इसी तरह अमेरिका की अर्थ पद्धति के सब देश विश्व में एक राजनैतिक गुट बनाये हुए हैं। हमने यह प्रयत्न किया है कि 'सम्पदा' को राजनीति से बिलकुल अलग रखा जाये।

इस अंक का नाम 'समाजवाद-अंक' रखा गया है, यद्यपि इसमें समाजवाद तथा साम्यवाद आदि सब सम्बद्ध वादों की चर्चा की गयी है। इन सब वादों को एक 'समाजवाद' शब्द से ही व्यक्त किया जा सकता था।

हमारी यह इच्छा थी कि इस अंक में जहाँ समाजवाद के सैद्धान्तिक पक्ष की विशेष चर्चा की जाये, वहाँ उसकी ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि देकर भारत और उसके विविध राज्यों में समाजवाद की दिशा में किये गये प्रयत्नों का भी परिचय दिया जाये, किन्तु विविध राज्यों में समाजवाद की प्रगति का विवरण या परिचय नहीं दिया जा सका। कलेवर वृद्धि के भय के अतिरिक्त हमें यह कहते हुए खेद होता है कि विविध राज्यों के सूचना-विभाग अभी तक हिन्दी पत्रों को आवश्यक सामग्री नहीं देते या बहुत विलम्ब से भेजते हैं। उनके सहयोग के बिना यह काम सम्भव नहीं था। दो-एक राज्यों ने अपने विवरण अवश्य भेजे हैं, किन्तु हमारी इच्छा यह है कि यदि अधिकांश राज्यों और विशेषकर उत्तर भारत के हिन्दी भाषी राज्यों ने सहयोग दिया तो एक अतिरिक्त अंक में समाजवाद की दिशा में किये गये राज्य-प्रयत्नों का परिचय दे दिया जाये।

हमारा विचार था कि यह अंक २० अक्तूबर तक प्रकाशित हो जाये, किन्तु प्रेस की कठिनाइयों और मेरे अस्वास्थ्य के कारण कुछ विलम्ब हो गया। फिर भी ख्याल हुआ कि समाजवाद की दिशा में नेतृत्व करने वाले रूस की अक्तूबर क्रान्ति के ४० वें स्मृति दिवस के अवसर पर यह अंक प्रकाशित किया जाये। १९१७ की अक्तूबर क्रान्ति का ऐतिहासिक व आर्थिक महत्त्व समस्त संसार के लिए है, केवल रूस के लिए नहीं। इस अवसर पर समाजवाद-अंक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"मैं यह नहीं कहता कि खेती के लायक कुल ज़मीन का सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। मैं तो न्याय चाहता हूं। ये पाँचों उंगलियाँ आकार में बराबर नहीं है, मगर वे सब सहयोग के साथ काम करती हैं और मिलकर असंख्य कार्य सम्पादन करती हैं। साथ ही उनकी असमानता इतनी बे-हिसाब भी नहीं है कि एक तो एक इंच लम्बी हो और दूसरी एक फुट लम्बी हो। इससे यह शिक्षा मिलती है कि अगर पूरी समानता नहीं हो सकती, तो भयंकर असामनता भी नहीं होनी चाहिए। पाँचों उंगलियों की अलग-अलग क्षमता है। इसी तरह प्रत्येक मनुष्य में क्षमता अलग अलग होती है। हर एक आदमी की जन्मजात शक्तियों का विकास होना चाहिए। इसे ही पंचायत धर्म कहते हैं।"

—आचार्य विनोबा

का प्रकाशन उचित रहेगा।

हमारी पिछले वर्षों में यह परिपाटी रही है कि हम एक विशेषांक दो महीने के संयुक्त अंग के रूप में निकालते हैं, इसलिए यह अंक भी अक्तूबर-नवम्बर के संयुक्त अंक के रूप में निकाला जा रहा है। यदि सम्भव हुआ तो इसी महीने के अन्त तक पृथक् रूपेण एक नवम्बर अंक भी प्रकाशित कर देंगे।

'सम्पदा' पर अनेक लेखक प्रारम्भ से ही कृपालु रहे हैं। उनके सहयोग के बिना यह अंक भी प्रकाशित न हो सकता। उनके सहयोग के लिए हम उनके कृतज्ञ हैं। मेरे सहकारी श्री मदनमोहन बिष्ट ने जो सहयोग दिया, वह अत्यन्त प्रशंसनीय है।

अन्त में एक शब्द 'सम्पदा' के पाठकों से। एक पत्रकार के लिए अपने सीमित साधनों द्वारा 'सम्पदा' जैसी गम्भीर आर्थिक विषय की पत्रिका का इतने वर्षों तक चलाना सम्भव न होता, यदि पाठकों का सहयोग तथा प्रोत्साहन न मिलता। किन्तु आज बढ़ते हुए खर्चों को पूरा करने तथा पत्रिका को और अधिक उन्नत करने के लिए बहुत अधिक सहयोग की अपेक्षा है। मुझे आशा है कि 'सम्पदा' का प्रत्येक पाठक दो-दो नये ग्राहक बनाकर हमारी सहायता करेगा।

—कृष्णचन्द्र विद्यालंकार

भारत सरकार के व्यापार और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित

'उद्योग व्यापार पत्रिका'

★ उद्योग और व्यापार-सम्बन्धी प्रामाणिक जानकारी-युक्त विशेष लेख, भारत सरकार की आवश्यक सूचनाएं, उपयोगी आंकड़े आदि प्रति मास दिये जाते हैं।

★ डिमाई चौपेजी आकार के ६०-७० पृष्ठ : मूल्य केवल ६ रुपया वार्षिक। एजेण्टों को अच्छा कमीशन दिया जायगा। पत्रिका विज्ञापन का सुन्दर साधन है।

★ लघु-उद्योग विशेषांक मंगा कर छोटे उद्योगों के सम्बन्ध में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त कीजिये।

★ ग्राहक बनने, एजेन्सी लेने अथवा विज्ञापन छपाने के लिए नीचे लिखे पते पर पत्र भेजिये :—

सम्पादक

उद्योग व्यापार पत्रिका

उद्योग और व्यापार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

३,००,००० टन से अधिक

कोणार्क सिमेंट

का उपयोग हीराकुड बांध में हो चुका है।

भारत के विशालतम बांधों में से एक यह बांध उड़ीसा में महानदी के ऊपर बन रहा है। यह एक ऐसी बहुमुखी परियोजना है जिससे बाढ़ों का नियन्त्रण, १९ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई और २००,००० किलोवाट्स विद्युतशक्ति का उत्पादन हो सकेगा। मुख्य बांध १५८०० फीट लम्बा है और इसकी सर्वाधिक ऊंचाई १८३ फीट होगी। जिसमें से लगभग १२००० फीट बांध कच्चा है और लगभग ३००० फीट बांध का निर्माण सिमेंट कंकरीट का है जिसमें कोणार्क सिमेंट का ही व्यवहार हो रहा है।

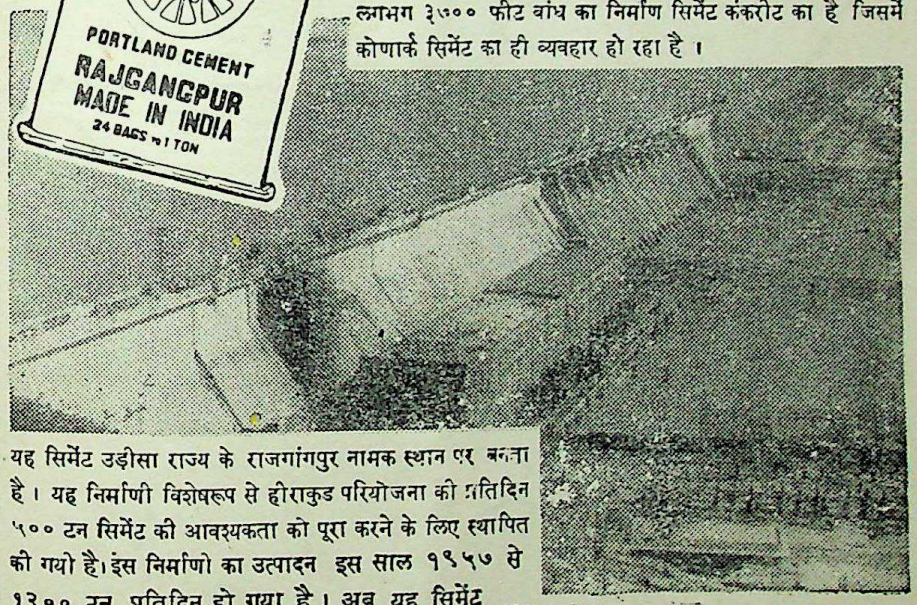

यह सिमेंट उड़ीसा राज्य के राजगांगपुर नामक स्थान पर बनता है। यह निर्माणी विशेषरूप से हीराकुड परियोजना की प्रतिदिन ५०० टन सिमेंट की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्थापित की गयी है। इस निर्माणी का उत्पादन इस साल १९५७ से १२०० टन प्रतिदिन हो गया है। अब यह सिमेंट जनोपयोग के लिए भी पर्याप्त मात्रा में मिल सकेगा।

उड़ीसा सिमेंट लिमिटेड

राजगांगपुर, उड़ीसा

प्रबंध-अभिकर्ता डालमिया एजेन्सीज प्राइवेट लिमिटेड

O.C.H 10. 57 A.I.A.8

सम्पादक—कृष्णचन्द्र विद्यालंकार द्वारा अशोक प्रकाशन मन्दिर के लिए अर्जुन प्रेस दिल्ली से मुद्रित व प्रकाशित।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मध्यभारत और राजस्थान की

समृद्धि और सम्पन्नता के लिए चम्बल

१४,००,००० एकड़ भूमि को सिंचित करने के लिए ४७५००० टन अतिरिक्त अन्न के उत्पादन और २,१०,००० किलोवाट बिजली पैदा करके २०० वर्ग मील के विस्तृत क्षेत्र में बिजली को सुलभ करने के लिए चम्बल-योजना बनाई गई है। इस पर ७७.१५ करोड़ रु० व्यय होगा। इनसे मध्य भारत व राजस्थान सम्पन्नताव समृद्धि प्राप्त करेंगे।

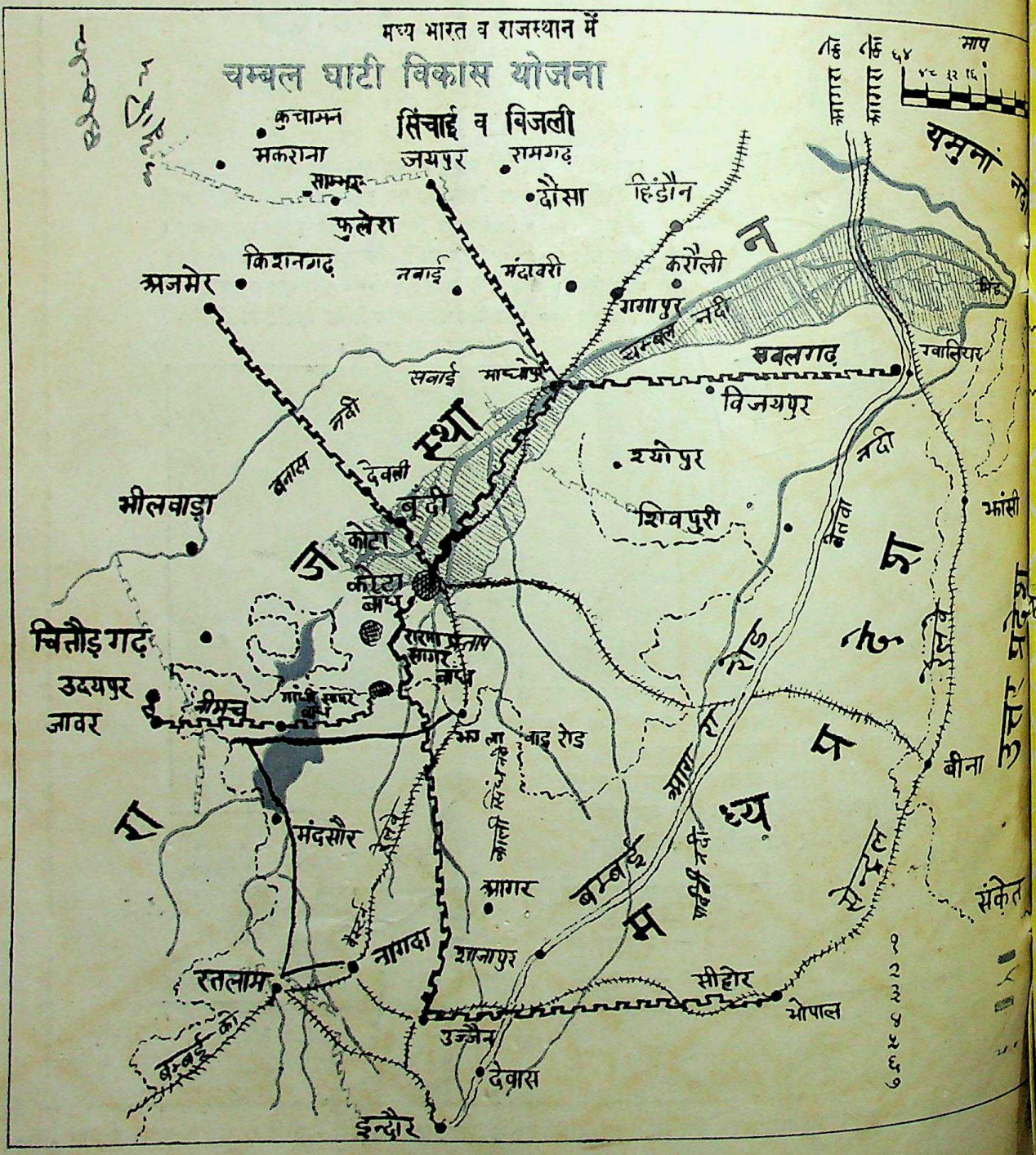

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्पदा

दिसम्बर १९५७

सम्पादक
[illegible]चन्द्र विद्यालंकार

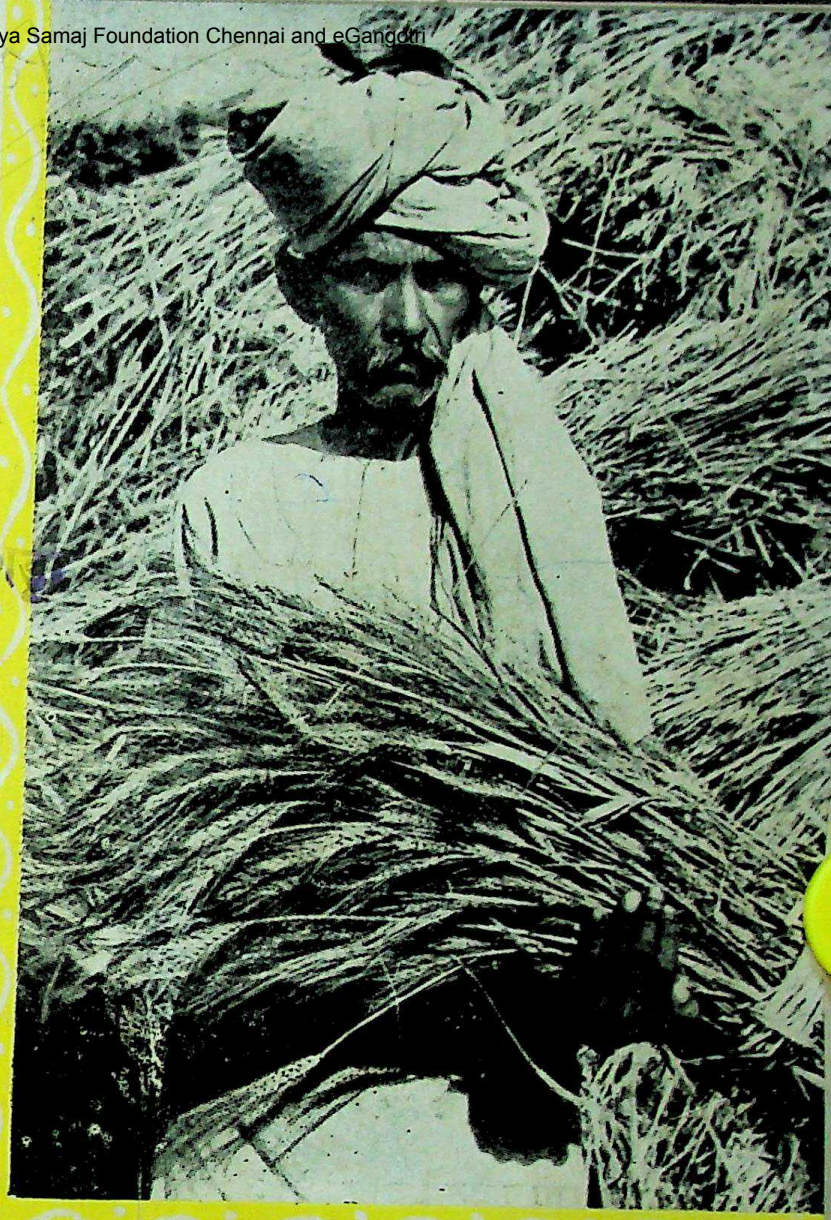

श्रम और निष्ठा का देवता अन्नदाता किसान

आज देश की विकट आर्थिक समस्या को अमरीका या रूस की सरकारें नहीं, भारत का अन्नदाता किसान हल कर सकता है। अन्न की बहुलता के साथ विदेशी विनिमय, महंगाई तथा दरिद्रता आदि अनेक समस्याओं का समाधान भी सरल हो जायगा।

मूल्य :
[illegible] पैसे

अशोक प्रकाशन मन्दिर : रोशनारा रोड, दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इन हाथों को आपकी सुरक्षा करने दीजिये

ये हाथ जीवन बीमा के प्रतीक हैं, जो सुरक्षा का सर्वोत्तम साधन हैं। आपके लिए इन हाथों का अर्थ बहुत अधिक है। आप के बुढ़ापे के लिए वे आमदनी का प्रबंध कर सकते हैं। यदि आप जीवित न रहें, तो ये आपके परिवार की परवरिश की व्यवस्था कर सकते हैं: ये आपकी संतान की शिक्षा के लिए कोश जमा कर सकते हैं और उनके विवाह के खर्च का प्रबन्ध कर सकते हैं।

पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हाथ सुरक्षा के प्रतीक हैं—ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो रकम आप जमा करते हैं, वह बिलकुल सुरक्षित हैं और जो लोग आपकी सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं, वे आपके हितों की रक्षा करते हैं।

लाइफ इन्श्योरेंस कार्पोरेशन आफ इण्डिया

मध्यवर्ती दफ्तर, जीवन केन्द्र जमशेदजी टाटा रोड, बम्बई-१.

Life Insurance Corporation of India

प्रादेशिक दफ्तर: बम्बई, नई दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, कानपुर

विभागीय और शाखा दफ्तर सारे भारत में हैं।

ASP/LIC-9

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

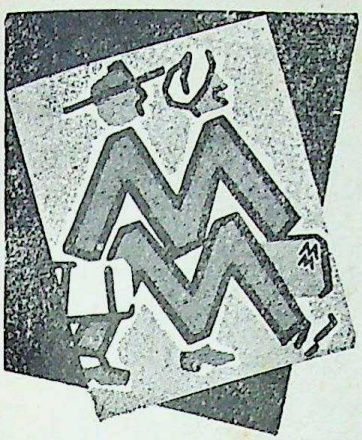

लिपज़ीग ट्रेड फेयर

टेकनीकल फेयर और सेम्पल फेयर

२ से ११ मार्च '५८ तक

यह टेकनीकल फेयर ३० भिन्न भिन्न व्यापारी विभागों वाला होगा जो २०,००० वर्ग मीटर के अन्दर फैला होगा। एक बृहद् अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शन सर्व प्रकार के पूंजीगत सामानों का होगा।

●

शहर के मध्य में स्थित मेले की १६ बिल्डिंगों में आप पूर्ण रूप से उपभोज्य वस्तुओं का प्रदर्शन पायेंगे।

●

४० देशों के ५५ व्यापारी समूहों के १०,००० प्रदर्शक होंगे और ८० देशों के खरीददार

पूर्ण विवरण और फेयर डाक के लिये संपर्क करें—

लिपज़ीग फेयर एजन्सी

पो० बा० नं० १९९३, बम्बई—१
डी/१७, निजामुद्दीन ईस्ट, नई दिल्ली—१३
३४/ए, ब्रेबोर्न रोड, कलकत्ता—१
"लोमोन्ड" ४६ हेरींग्टन रोड, मद्रास—३१

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विकास के पथ पर बढ़ते कदम

प्रथम पंचवर्षीय आयोजन के अन्तर्गत
उत्तर प्रदेश के निवासियों ने आपसी सहयोग के सहारे
प्रगति की राह पर द्रुत-गति से कदम बढ़ाये हैं
भावी समृद्धि के लिए किया गया यह प्रयास अन्य बातों के अतिरिक्त

३० लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में सिंचन सुविधाओं
१६ लाख टन अतिरिक्त खाद्योत्पादन
२४८ नयी प्राथमिक पाठशालाओं के शुभारम्भ

और

ग्रामांचल में १४१ अतिरिक्त औषधालयों की सुविधा के रूप में प्रकट हुआ

यह सफलताएं हमारे लिए
निरन्तर प्रेरणा की स्रोत बनी रहेगी ।

विषय सूची

सं०	विषय	पृष्ठ
१.	पंचवर्षीय योजना की समस्याएं	६७१
२.	सम्पादकीय टिप्पणियां	६७३
३.	पंचवर्षीय योजना : कुछ अनुभव	६७४
४.	औद्योगिक प्रतिभूतियों की बिक्री	६८०
५.	अनाज के मूल्यों का नियंत्रण	६८५
६.	लिपजिग का शरदकालीन मेला	६९२
७.	१९५७ में चीन का अर्थतंत्र	६९३
८.	नया सामयिक साहित्य	६९७
९.	१० वर्षों में भारत का श्रमिक	६९९
१०.	वित्तीय आयोग के नये प्रस्ताव	७०२
११.	मुद्रा चलन की सुरक्षित राशि में कमी	७०६
१२.	रूस से ५० करोड़ रूबल का ऋण	७०९
१३.	१९५७ के पूर्वार्ध में औद्योगिक प्रगति	७१०
१४.	अर्थवृत्तचयन—पृथ्वी की उष्णता से भी शक्ति	७१३
	२००० ई० में आबादी दुगनी—मकानों की समस्या	
	वर्षगांठ का उपहार—बाढ़ से हानि आदि	७१४
१५.	एशिया में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन	७१६
१६.	राजस्थान के वित्तीय साधन	७१८

—

सैंकड़ों में से एक पत्र

मैं अर्थशास्त्र का स्नातकोत्तर छात्र हूं । अभी मैं एम. काम (फाइनल) का अध्ययन कर रहा हूँ । मुझे 'सम्पदा' से काफी सहायता मिलती है व इसके प्रति हार्दिक प्रीति है। साथ ही इसके नये-नये ग्राहक बनाने के लिये भी कार्य कर रहा हूं, ताकि मेरे अन्य विद्यार्थीगण जो मेरे प्रीवियस व फाइनल के साथी हैं—बहुमूल्य पत्रिका का उपयोग कर लाभार्जन कर सकें । श्रम समस्याओं के विषय के लिये मैंने व मेरे दोस्तों ने आपके यहां से सम्पदा के मजदूर अंक मंगाये हैं, वे बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुए ।"

—श्रेणिक लाल जैन, एम० काम (फा०), इन्दौर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

१९५७ में चीन का अर्थतन्त्र

श्री चू ची-शिन

हर बड़ी लड़ाई के बाद हर फौज आराम करने के लिए रुकती है और दुबारा कूच करने से पहले अपना संगठन नये सिरे से करती है। १९५६ में चीन का आर्थिक निर्माण बड़ी तेजी से हुआ। अब यह साल, १९५७ जरूरी परिवर्तन करने और आगे की प्रगति के लिए सारी शक्ति को जुटाने का समय है।

महान सामाजिक परिवर्तन

परिस्थिति को ज्यादा अच्छी तरह समझने के लिए पिछले साल के महान सामाजिक परिवर्तनों पर विचार करना जरूरी है, क्योंकि ये परिवर्तन बहुत व्यापक थे और इतने गूढ़ परिवर्तन इससे पहले कभी नहीं हुए थे। ५० करोड़ किसानों और ५० लाख दस्तकारों ने समाजवादी सहकारिता का मार्ग अपनाया। ३० लाख औद्योगिक तथा वाणिज्य प्रतिष्ठानों के पूंजीपतियों ने शांति-पूर्वक समाजवादी रूपांतर को स्वीकार किया।

चीन में जो यह महान परिवर्तन हुआ है, वह इतिहास की किसी भी पूंजीवादी क्रांति से, जिसमें एक शोषक वर्ग दूसरे शोषक वर्ग को हटा कर उसका स्थान ले लेता था, ज्यादा गहरा परिवर्तन है। सत्रहवीं शतब्दी की इंगलैंड की क्रांति और अठारहवीं शताब्दी की फ्रांस की क्रांति दोनों ही के बाद, (जिन दोनों ही क्रांतियों में उस समय के उदीयमान पूंजीपति वर्ग ने सत्ता अपने हाथों में ले ली थी) बहुत समय तक आर्थिक अराजकता रही, उत्पादन की व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गयी और जनता के जीवन में एक उथल-पुथल मची रही। चीन की समाजवादी क्रांति जो मुख्यतः १९५६ में पूरी हो गयी, इनकी तुलना में शांतिमय थी। इसके फलस्वरूप कोई तबाही नहीं हुई और जिस समय यह क्रांति हो रही थी, उस समय आर्थिक निर्माण की गति में बहुत वृद्धि हुई।

महान सामाजिक परिवर्तनों के इस वर्ष के दौरान में प्रकृति ने साथ नहीं दिया। १९५६ में जैसी दैवी विपदाओं का प्रकोप हुआ, वैसा कई वर्षों से नहीं हुआ था। कई

चीन का आर्थिक विकास विश्व की महत्वपूर्ण क्रान्ति है, इसकी सफलताओं व कठिनाइयों का परिचय इस लेख में देखिये।

चीन के राष्ट्रपति श्री माओ-त्से-तुंग

जगह बाढ़ आयी और सूखा पड़ा। चीन के उत्तरी, मध्यवर्ती तथा दक्षिणी प्रदेशों में ३,७८,८०००० एकड़ भूमि और ७ करोड़ लोग इनके शिकार हुए। परन्तु इन विपदाओंके बावजूद, उस देश में कृषि-उत्पादन में वृद्धि हुई। देश भर में अनाज की जितनी फसल हुई, उतनी इससे पहले कभी नहीं हुई थी।

इस वर्ष ३० जून को प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र संघ की पूरे विश्व की आर्थिक रिपोर्ट में कहा गया है कि १९५६ में चीन की औद्योगिक वृद्धि जितनी तेज़ी से हुई, उतनी इसी समय में पृथ्वी के किसी और देश में नहीं हुई। वास्तविक आंकड़ों में औद्योगिक उत्पादन का कुल मूल्य ५८ अरब ६६ करोड़ युआन था, अर्थात् १९५५ की तुलना में १३

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अरब ६० करोड़ युआन, या ३१ प्रतिशत अधिक। यह वृद्धि ही १९४९ में, जिस वर्ष साम्यवादी शासन हुआ था, चीन के कुल औद्योगिक उत्पादन से २८ प्रतिशत अधिक थी।

१९५६ में पूंजीगत निर्माण भी जितने बड़े पैमाने पर हुआ, उतना इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इस मद में कुल मिलाकर १३ अरब ९९ करोड़ युआन की पूंजी लगायी गयी, अर्थात् १९५५ की तुलना में ६२ प्रतिशत अधिक। संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान तथा जन-स्वास्थ्य के क्षेत्रों में भी सराहनीय प्रगति हुई। मजदूरों तथा कर्मचारियों की संख्या तेजी से बढ़कर २,४१,७०,००० हो गयी। मजदूरी में औसत से १४ प्रतिशत वृद्धि हुई। समाज की क्रय-शक्ति १५.६ प्रतिशत बढ़ी। इससे अंदाज़ होता है कि जीवन की परिस्थितियों में कितना सुधार हुआ है।

वेग में कमी

भविष्य में चीन के आर्थिक विकास पर १९५६ के इस आम आर्थिक उत्थान का बहुत व्यापक रूप से असर पड़ेगा। तात्कालिक रूप से इसने पहली पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य से अधिक पूर्ति के लिए एक ठोस बुनियाद तैयार कर दी है। लेकिन इसकी वजह से कुछ कठिनाइयां भी पैदा हो गयी हैं। पूंजीगत निर्माण में इतनी अधिक पूंजी लगा देने की वजह से आवश्यक चीजों (इस्पात, लकड़ी, और इमारतें बनाने की कुछ मशीनों) की मांग और उनकी सप्लाई के बीच एक अन्तर पैदा हो गया है। आम खपत की चीजों के संबंध में भी क्रय-शक्ति की वृद्धि चीजों की सप्लाई से कुछ ज्यादा ही रही है। सरकार को अपने सुरक्षित भण्डारों का कुछ हिस्सा, जो उसने पिछले कुछ वर्षों में जमा किया था, बाजार में लाना पड़ा।

समाजवादी क्रांति की सफलता और योजना की लक्ष्य से अधिक पूर्ति को सुनिश्चित बनाने के लिए और दैवी विपदाओं का सामना करने के लिए सरकार के लिए इन संचित भण्डारों को इस्तेमाल करना ठीक था। फिर भी इन सुरक्षित भण्डारों के खर्च हो जाने की वजह से और १९५६ में उद्योगों के उत्पादन के मुकाबले में कृषि का उत्पादन कम होने की वजह से यह फैसला करना पड़ा कि आगे चलकर और प्रगति का रास्ता तैयार करने के लिए १९५७ में रफ्तार कुछ धीमी कर दी जाये।

१९५७ में उद्योगों की स्थिति

१९५७ के लिए औद्योगिक उत्पादन का लक्ष्य १९५६ की अपेक्षा ४.५ प्रतिशत अधिक, ६० अरब ३४ करोड़ युआन रखा गया। वेग को कम करने का मुख्य कारण यह था कि औद्योगिक फसलों की पर्याप्त पैदावार करने में कृषि असफल रही। १९५६ में प्राकृतिक कारणों से कपास की फसल निर्दिष्ट लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकी। इससे कपड़े के उत्पादन के १९५७ के कार्यक्रम पर असर पड़ा। चीन के लघु उद्योगों का काफी बड़ा हिस्सा कपड़े के उत्पादन का है। इसी प्रकार खाने-पीने की चीजें बनाने के उद्योग की प्रगति को भी धीमा करना पड़ा और उसमें बहुत थोड़ी ही वृद्धि होगी।

पूंजीगत सामग्री के क्षेत्र में खेतीबारी के औजार और मशीनें बनाने का काम इस वर्ष रुका रहेगा, क्योंकि पिछले वर्ष कृषि में जितनी मशीनों की खपत थी उससे ज्यादा मशीनें बना ली गयी थीं। कुछ अन्य प्रकार की मशीनों का उत्पादन भी धीमा रहेगा क्योंकि पूंजीगत निर्माण-स्थलों से इनकी मांग कम होने के कारण इन कामों में कम पूंजी लगायी जायेगी।

फिर भी सबसे महत्वपूर्ण पूंजीगत सामग्री का उत्पादन १९५७ में काफी तेजी से बढ़ेगा, यह बात निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट हो जायेगी।

१९५७ में उत्पादन के लक्ष्य

मदें	१९५७ के लक्ष्य	१९५६ की तुलना में (प्रतिशत)
बिजली	१८८,६०० लाख किलोवाट घंटे	११३.७
कोयला	१,१७२.७ लाख टन	११०.७
कच्चा तेल	१५ लाख टन	१२९.०
बीज लोह	५,५५४,००० टन	११६.३
इस्पात	४,९८७,००० टन	१११.७
इस्पात का-सामान	८,४७८,००० टन	११७.०
कास्टिक सोडा	१७८,००० टन	११३.८

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अमोनियम-सल्फेट	४९९,००० टन	१११.८
सीमेंट	६,८०७,००० टन	१०६.५
ब्वायलर	४,०१९.७ टन घंटे	१३३.०
भाप के टर्बाइन	१४३,५०० किलोवाट	११९.१
जैनरेटर	२८४,००० किलोवाट	९८.९
बिजली के मोटर	१,२५१,००० किलोवाट	११७.७
ट्रांसफार्मर	३,५९८,००० किलोवोल्ट ऐम्पीयर	१२६.४
धातु काटने के मशीनी औज़ार	२२,६४०	१०२.७
लारियां	७,०००	४२४.८
लकड़ी	८८४,६१८,००० घनफीट (हस्तशिल्प-उद्योग के उत्पादन सहित)	१२१.९

औद्योगिक उत्पादन के मामले में १९५७ के लक्ष्य—६० अरब ३४ करोड़ युआन—तक पहुँचनेका मतलब यह होगा कि उद्योगोंके मामलेमें पूरी पंचवर्षीय योजना लक्ष्य से १२.७ प्रतिशत अधिक पूरी कर ली जायेगी। अगर इस पूरे दौरानका औसत लगाया जाये तो औद्योगिक उत्पादनमें वार्षिक वृद्धि मूलतः आयोजित १४.७ प्रतिशत के बजाय १७.४ प्रतिशत बैठेगी।

चीन के राष्ट्रीय अर्थतंत्र में कृषि को अब भी जो महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, उसे देखते हुए औद्योगिक उन्नति की रफ्तार बहुत कुछ इसी की प्रगति पर निर्भर करती है। जैसी कि योजना बनायी गयी है, १९५७ में कृषि का उत्पादन, फसलों तथा अन्य सहायक उत्पादन के मूल्य की दृष्टि से, ६१ अरब १५ करोड़ युआन होना है—अर्थात् पिछले वर्ष की तुलना में ४.९ प्रतिशत अधिक। मुख्य मुख्य मदों के हिसाब से यह उत्पादन इस प्रकार होगा :

मद	१९५७ के लिए उत्पादन का आयोजित लक्ष्य	१९५६ की तुलना में वृद्धि
अनाज (सोयाबीन को छोड़ कर)	१९१,०००,००० टन	८,५००,००० टन
कपास	१,५००,००० टन	५५,००० टन
सुअर (१९५७ के अंत तक)	११०,०००,०००	१२,२००,०००

यदि हम १९५७ के लिए निर्धारित लक्ष्य तक पहुँच जायें तो इस संबंध में पूरी पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य से २.५ प्रतिशत अधिक उत्पादन होगा। औसत वार्षिक वृद्धि ४.८ प्रतिशत होगी। मूलतः ४.३ प्रतिशत औसत वार्षिक वृद्धि का हिसाब लगाया गया था।

पूंजीगत निर्माण

१९५७ में पूंजीगत निर्माण में ११ अरब १० करोड़ युआन पूंजी लगाने का आयोजन रखा गया है। अलग-अलग क्षेत्रों में इस रकम के बंटवारे में कुछ हेर-फेर किये गये हैं। उत्पादन-कार्य से संबंधित इमारतों व अतिरिक्त अन्य इमारतों पर (रिहायशी मकानों, सार्वजनिक सभा-भवनों आदि पर) १९५६ में कुल रकम का २२.४ प्रतिशत भाग खर्च किया गया था, इस वर्ष इसके बजाय लगभग २० प्रतिशत रकम इस काम पर खर्च की जायेगी। उत्पादन-कार्य से संबंधित इमारतों पर (फैक्टरियों, खानों, आदि पर) इसी हिसाब से ज्यादा रकम खर्च की जायेगी। कपड़ा, खाद्य तथा इंजीनियरिंग के उद्योगों की उत्पादन-क्षमता बढ़ाने के लिए जो पूंजी लगायी जाने वाली थी, उसमें कमी कर दी गयी है क्योंकि इन उद्योगों की उत्पादन क्षमता वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने से लिए इस समय भी पर्याप्त से अधिक है। उन उद्योगों के लिए जो आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं—जैसे कोयला, बिजली, धातु, रसायन तथा पेड़ों की कटाई—ज्यादा रकम मंजूर की जायेगी। कृषि, वन लगाने तथा जल-संरक्षण पर लगभग पहले जितनी ही पूंजी लगायी जाएगी।

वास्तव में शुरू-शुरू में जब पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया गया था, उस समय १९५७ में इस काम के लिए जितनी रकम रखी गयी थी, उससे यह रकम १ अरब ४० करोड़ युआन अधिक है। इन पांच वर्षों में कुल मिलाकर ४७ अरब ७२ करोड़ २० लाख युआन की पूंजी लगायी जायेगी—जो आयोजित राशि से ११.६ प्रतिशत अधिक होगी। राष्ट्रीय अर्थतंत्र में "पांच वर्षों में ७० करोड़ लिआंग+ सोने" के बराबर पूंजी लगाने के बजाय, जिस लक्ष्य पर चीन की जनता को न्यायोचित गर्व था, कुल जितनी पूंजी लगायी जायेगी, वह ७८ करोड़

+ १ लिआंग १.१०२३ औंस के बराबर होता है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

१२ लाख लिआंग सोने के बराबर होगी।

नयी चीजों का उत्पादन

चीन में अब अनेक ऐसे नये उद्योगों की स्थापना हो गयी है, जिनमें ऐसी चीजें तैयार होती हैं, जो चीन पहले कभी नहीं बना सकता था। १९५७ में आजमाइश के तौर पर ७२,५०० किलोवाट क्षमता वाले जल-विद्युत् संस्थानों की पूरी-पूरी कलें, ८० टन के बिजली से चलने वाले रेल के इंजन, ५,००० टन सामान ले जा सकने वाले तटीय जहाज, ४० हार्स-पावर के ट्रेक्टर, चार तकुओं वाली स्वचालित लेथ मशीनें, बहु-उपयोगी मशीनी औजार और इंडियम, सेलेनियम, तेलूरियम, जर्मेनियम, गैलियम, कोबाल्ट तथा अन्य दुर्लभ धातुओं की चीजें तैयार की जायेंगी।

परिवहन

१९५७ में परिवहन का विकास कृषि, उद्योगों तथा पूंजीगत निर्माण की वृद्धि के लिए आवश्यक पैमाने पर होगा। १९५३ से १९५६ के बीच जो रेलवे लाइनें बनायी गयी हैं, उन्होंने उत्तरी-पश्चिमी, दक्षिणी-पश्चिमी, मध्यवर्ती तथा तटवर्ती क्षेत्रों को एक-दूसरे से जोड़ने वाले नये मार्ग प्रदान किये हैं। वे राष्ट्रीय अर्थतंत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर रहे हैं। परंतु उत्पादन और निर्माण दोनों ही के निरंतर विकास के कारण रेलों की वर्तमान क्षमता पर बोझ बहुत बढ़ गया है। इस क्षमता को बढ़ाने के लिए और पूंजी लगाने की आवश्यकता है। इसलिए १९५७ की योजना में पेकिंग-हैंकाऊ, शिहचिया-चुआंग-ताइयुआन तथा ++लुंघाई रेलवे लाइनों पर दोहरी पटरियां बिछायी जा रही हैं।

चीन के प्रथम अणु-संस्थानों का निर्माण उल्लेखनीय है: एक तो हैवी-वाटर टाइप का आणविक रिऐक्टर है जो ७,००० किलोवाट बिजली पैदा कर सकता है और दूसरा ढाई करोड़ विद्युत-वोल्ट शक्ति वाला एक साइक्लोट्रोन है जो एल्फाकण उत्पन्न करता है। आशा की जाती है कि ये दोनों ही इस वर्ष बनकर तैयार हो जायेंगे।

१९५७ में राज्यीय योजना के अनुसार मजदूरों और वेतन भोगी कर्मचारियों की औसत संख्या+ २२,१६८,००० होगी, अर्थात् पिछले वर्ष की तुलना में ४.७ प्रतिशत अधिक रोजगार मिलने की रफ्तार इस समय ही पूरी योजना के लिए निर्धारित मूल लक्ष्य से आगे पहुँच चुकी है। १९५७ के अंत तक मजदूरों और कर्मचारियों का औसत पारिश्रमिक १९५२ की तुलना में ३७ प्रतिशत अधिक होगा (योजना ३३ प्रतिशत वृद्धि की बनायी गयी थी)। उत्पादन में वृद्धि के कारण अधिकांश किसानों की आमदनी भी बढ़ जायेगी।

सफलता का अर्थ

इस वर्ष की योजना की पूर्ति का अर्थ यह होगा कि निर्माण योजनाओं, नयी चीजों के उत्पादन और प्रतिष्ठानों के विकास के संबंध में जो पंचवर्षीय लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, उनमें से अधिकांश की लक्ष्य से अधिक पूर्ति हो जायेगी। चीन के उद्योगीकरण का प्राथमिक आधार तैयार हो जायेगा। मूलतः चीन अपने बिजली घरों, खानों, औसत आकार के धातु के तथा धातु की चीजें तैयार करने के कारखानों और रसायन तथा हल्के उद्योगों के लिए आवश्यक सामान तैयार करने लगा है। वह अपने परिवहन तथा अपनी कृषि के लिए भी अपनी ही बनायी हुई मशीनों का प्रयोग करने लगा है। अपने देश की बनी हुई मशीनों से उसकी राष्ट्रीय प्रतिरक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ होगी। चीन देश में ही उत्पन्न होने वाली धातु से अपने सतत विकासवान निर्माण-कार्य की अधिकांश आवश्यकताओंको भी पूरा करने लगा है। पिछले कुछ वर्षों में जो ये सफलताएं प्राप्त हुई हैं, इनका संबंध अभिन्न रूप से सोवियत संघ तथा अन्य समाजवादी देशों से प्राप्त सहायता के साथ है।

++ लुंघाई रेलवे लाइन किआंगसू प्रांत में लिएनयुनकांग नामक बंदरगाह से उत्तरी-पश्चिमी चीन के कांसू प्रांत में शैंचाऊ तक जाती है।

+ इसका हिसाब लगाने लिए साल में हर दिन काम करने वाले मजदूरों और वेतन भोगी कर्मचारियों की कुल संख्या को पहले जोड़ लिया जाता है। फिर उसे ३६५ से भाग दे दिया जाता है।

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नया सामयिक साहित्य

पथेर पांचाली (उपन्यास)—ले० श्री विभूतिशरण वंद्योपाध्याय। अनुवादक—श्री मन्मथनाथ गुप्त, पृष्ठ संख्या ३१५, प्रकाशक—राजपाल एंड संस, कश्मीरी गेट, दिल्ली। मूल्य ५ रु०

पथेर पांचाली बंगला के स्वनामधन्य उपन्यासकार श्री विभूतिभूषण वंद्योपाध्याय की अमर कृति है। बंगालके एक छोटे से मध्यम वर्ग के परिवार की कथा को इस उपन्यास का विषय बनाया गया है। पर इस कथा में सारे बंगाल के जीवन और उसकी आत्मा के सुन्दर दर्शन होते हैं। उपन्यास का मुख्य पात्र 'अप्पू' एक बालक है और उसका चरित्र चित्रण इतना स्वाभाविक और सजीव है कि हर समय उसमें दिलचस्पी बनी रहती है और उसका अमिट प्रभाव पड़ता है। 'दीदी' तो करुणा का श्रोत ही है। अवश्य ही इस उपन्यास को पढ़ते पढ़ते कई जगह पाठक को अपने आंसुओं का नियंत्रण करना मुश्किल हो जायेगा। निस्संदेह उपन्यास "बंगाल के निम्न मध्यम-वर्ग की महान गाथा है।"

इसके अनुवादक श्री मन्मथनाथ गुप्त बंगला भाषी हिन्दी साहित्यकार हैं, अतः वे अपनी निर्विवाद पात्रता के कारण विभूति बाबू की इस मूल बंगला कृति का हिन्दी में रूपान्तर करने में पूर्णतः सफल रहे हैं क्योंकि इसमें मूल का सा आनन्द और प्रवाह ज्यों का त्यों है।

लोकों का युद्ध (वैज्ञानिक उपन्यास)—लेखक एच० जी० वेल्स। पृष्ठ २३८, मूल्य ४ रु०, प्रकाशक—वही।

'लोकों का युद्ध' अंग्रेजी के प्रसिद्ध साहित्यकार एच० जी० वेल्स के वैज्ञानिक उपन्यास "War of the Worlds" का हिन्दी अनुवाद है। अनुवादक श्री रमेश विसारिया हैं। इस वैज्ञानिक उपन्यास में मंगल निवासियों द्वारा पृथ्वी पर किये गये आक्रमण की कहानी है, जो भयावह किन्तु रोमांचक है। यह कहानी १९ वीं शताब्दी की लिखी गई है जब न तो मनुष्य ने हवाई जहाज से उड़ना सीखा था और न अब की तरह चांद तक पहुँचने के लिए राकेट छोड़े जा रहे थे। कहानी नितांत काल्पनिक है पर उस महान साहित्यकार ने १९ वीं शती के अन्तिम चरण में अपने इस उपन्यास के द्वारा एक महान सत्य के दर्शन करा दिये कि "विज्ञान" में पारंगत मनुष्य केवल "मस्तिष्क प्रधान" हो जायेगा; और यही २० वीं सदी में हो भी रहा है।

हिन्दी में वैज्ञानिक उपन्यासों का स्थान अभी रिक्त ही है। इस दृष्टि से इस अनुवादित कृति का स्वागत है। लेकिन अनुवाद में प्रवाह की कमी खटकती है। कहीं कहीं बात अस्पष्ट सी रहती है, वाक्य रचना पर अंग्रेजी की छाया अधिक है। भाषा भी कहीं कहीं कुछ कठिन ही कही जायेगी। हो सकता है कि यह "वैज्ञानिक उपन्यास" की अनिवार्यता हो। —म. मो.

शेक्सपियर के नाटक—

जैसा तुम चाहो, जूलियस सीजर, मैकबेथ, आथेलो और वेनिस का सौदागर।

अनुवादक—श्री रांगेय राघव। प्रकाशक—वही। मूल्य—प्रत्येक पौने दो रुपये।

अंग्रेजी साहित्य ही नहीं, विश्व साहित्य में शेक्सपीयर का एक महत्वपूर्ण स्थान है। वह अंग्रेजी का जहां महान कवि था, वहां अत्यन्त कुशल नाटककार भी था। उसके नाटकों में जीवन के अत्यन्त विविध पहलुओं का सजीव चित्रण हुआ है। मानव जीवन की शाश्वत भावनाओं को चित्रित करने में वह बहुत कुशल था। उसके नाटक ऐतिहासिक, सामाजिक, काल्पनिक सभी प्रकार के हैं। इनमें मानव के सत् और असत् दोनों भावों का चित्रण हुआ है।

शेक्सपीयर के पांच प्रसिद्ध नाटकों का गद्यानुवाद हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक श्री रांगेय राघव ने किया है। उनकी भाषा सरल और सुबोध है। हिन्दी में पिछले दिनों में जिन प्रकाशकों ने एक साथ बहुत सा साहित्य प्रकाशित करके हिन्दी को समृद्ध करने का प्रयत्न किया है, उनमें 'राजपाल एण्ड सन्स' भी एक हैं। इसी संस्था की ओर से उक्त नाटकों के सुन्दर अनुवाद प्रकाशित हुए हैं।

छपाई कागज और बहिरंग सुन्दर हैं।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उत्तर रामचरित (हिन्दी अनुवाद) अनुवादक—प्रो० इन्द्र विद्यालंकार, एम० ए०। प्रकाशक—वही। मूल्य २.०० रुपये।

संस्कृत साहित्य में भवभूति का स्थान बहुत ऊँचा है। अनेक साहित्यकारों की सम्मति में उसका स्थान कालिदास से भी ऊंचा है। उन्होंने तो यहां तक कहा: "कवयः कालिदासाद्याः भवभूतिर्महाकविः।" कालिदास आदि तो साधारण कवि हैं, महाकवि तो भवभूति है। उत्तर रामचरित करुण रस के प्रकाशन में अपना समकक्ष नहीं रखता। भवभूति अत्यन्त भावुक था। राम जैसे मर्यादा-पुरुषोत्तम और धीरोदात्त नायक को भी उसने अधीरता की मूर्ति बना दिया। उसका प्रेम वासनात्मक या शारीरिक नहीं है। राम और सीता के प्रेम को जिस दिव्य रूप में भवभूति ने उपस्थित किया है, वह विश्व-साहित्य में अनुपम है।

इस उत्कृष्ट नाटक का अनुवाद हिन्दी और संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान् श्री इन्द्र ने किया है। उनका दोनों भाषाओं पर एक समान अधिकार है। इसलिए अनुवाद बहुत सुन्दर हुआ है। मूल नाटक के पद्यों का अनुवाद भी गद्य में किया गया है। संभवतः इसीलिए कि आजकल नाटकों में गीतों का प्रचलन नहीं है।

नाटक के प्रारम्भ में एक विद्वत्तापूर्ण भूमिका है, जिसमें भवभूति के जीवन तथा साहित्यिक उत्कर्ष की चर्चा है। संस्कृत साहित्य के विद्यार्थियों के लिए यह भूमिका बहुत उपयोगी होगी।

आपका स्वास्थ्य (परमाणु विशेषांक)—प्रकाशक—इण्डियन मेडिकल एसोसियेशन, बनारस—१। इस अंक का मूल्य ७५ नये पैसे।

स्वास्थ्य के सम्बन्ध में हिन्दी में जो पत्र प्रकाशित हो रहे हैं, उनमें सामग्री और बहिरंग की दृष्टि से 'आपका स्वास्थ्य' बहुत उत्कृष्ट है। भिन्न-भिन्न स्वास्थ्य-सम्बन्धी विषयों को लेकर इसमें सुन्दर लेख दिये जाते हैं। संसार में फैले हुए विभिन्न रोगों और महामारियों के अतिरिक्त आज एक नयी समस्या पैदा हो गयी है। वह है परमाणु-बम और उद्जन बमों के परीक्षणों से उत्पन्न रेडियो-सक्रियता के कारण उत्पन्न होने वाले रोग। प्रस्तुत अंक में जहां इन रोगों की चर्चा की गयी है, वहां अणुशक्ति से उठाये जाने वाले उन लाभों का भी उल्लेख है, जो चिकित्सा क्षेत्र में उठाये जा सकते हैं। इसके अध्ययन से यह भी मालूम होता है कि अणुशक्ति मानव को लाभ भी पहुँचा सकती है और भीषण हानि भी। वैज्ञानिक दृष्टि से परमाणु और अणुओं पर दो-तीन सुन्दर लेख भी हैं। आज के अणु युग में इन विषयों का ज्ञान नागरिकों के लिए आवश्यक है।

विकास (दीपावली विशेषांक) संचालक—सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय, जयपुर द्वारा संपादित और प्रकाशित। मूल्य ५० नये पैसे।

विकास पत्रिका, जैसा कि उसके नाम से स्पष्ट है, विकास योजनाओं के कार्यकर्त्ताओं तथा योजना क्षेत्र के रहने वालों के लाभ के लिए प्रकाशित होती है। प्रस्तुत अंक में रचनात्मक विकास कार्यक्रमों का अनेक लेखों में परिचय दिया गया है तथा अनेक उपयोगी सूचनाएँ दी गयी हैं। कुछ लेख दीपावली के सम्बन्ध में हैं, तो कुछ मनोरंजक कहानियां और कविताएं हैं। इस अंक की एक विशेषता यह है कि सम्पादकों ने साहित्यिक वाग् विलास नहीं किया। अपने पाठकों की शिक्षा स्तर का ध्यान रख कर सरल भाषा में सुबोध शैली के लेख दिये गये हैं। इस कारण ग्राम वासी इस अंक से सचमुच लाभ उठा सकते हैं। राजस्थानी भाषा में दी गयी कविताएँ तथा अन्य सामग्री, गाँव वालों की ज़बानी गाँवों की कहानी आदि के कारण यह अंक और भी अधिक उपयोगी हो गया है। हमें आशा है कि यह अंक उस क्षेत्र की सेवा करेगा, जिसके लिए प्रकाशित किया गया है।

आर्थिक जगत् (दीपावली विशेषांक)—सम्पादक—पं० प्रतापनारायण वाजपेयी। प्रकाशक—आर्थिक जगत प्रैस, १०, बेकरी रोड, हेस्टिंग्स, कलकत्ता। मूल्य १) रु.।

यह पत्र गत एक वर्ष से प्रकाशित हो रहा है। इस अंक में विविध उद्योगों का संक्षिप्त परिचय अनेक लेखों के द्वारा दिया गया है। सम्पत्ति-कर, व्यय-कर, बैंकिंग आदि पर भी कुछ लेख हैं। श्री 'पथिक' का विदेशी पूंजी का राष्ट्रीयकरण सुन्दर लेख है। खाद्यावस्था का लेख भी पठनीय है। अर्थशास्त्र और उद्योगों में रुचि रखने वालों के लिए यह

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

१० वर्षों में भारत के श्रमिक

हित व सुविधा सम्बंधी नये कानून

पहले आयोजन में औद्योगिक उत्पादन में जो ४० प्रतिशत वृद्धि हुई और दूसरे आयोजन में इसमें निरन्तर वृद्धि होती जा रही है, उसका बहुत कुछ श्रेय श्रमिकों को ही है। इन दस वर्षों में श्रमिकों का भी काफी लाभ हुआ हुआ है। उनके रहन-सहन और काम की शर्तों में सुधार हुआ, उनके कल्याण के लिए अनेक काम किए गए और पहली बार, उनकी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था की गयी। उनकी मजदूरी बढ़ी और जैसा कि आर्थिक विकास के समय होता है, देश में रहन-सहन का खर्च बढ़ा, परन्तु उनकी आय इस खर्च से अधिक बढ़ी है। परन्तु इसके यह तात्पर्य नहीं कि हम अपना काम पूरा कर चुके हैं, अभी तो हमारे सामने काफी काम करना बाकी है।

रास्ता बन चुका है

श्रमिकों की उन्नति के लिए रास्ता बनाया जा चुका है। पिछले दस वर्षों में जो श्रम कानून लागू किये गये और उनमें जो सफलता मिली, वह इसका प्रमाण है। श्रमिकों से सम्बन्धित जो बहुत जरूरी बातें हैं, वे सभी कानून के अन्तर्गत आ गयीं हैं और त्रिदलीय समितियों में उनमें से अधिकांश कानून मालिक, मजदूर तथा सरकार ने मान लिये हैं।

१९४८ के फैक्टरी अधिनियम, १९५१ के बागान अधिनियम और १९५२ के खान अधिनियम में श्रमिकों के लिए काम के घंटे और पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों के लिए साप्ताहिक छुट्टी निर्धारित की गयी तथा उनके लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण की भी व्यवस्था की गयी। खान अधिनियम में खानों में खतरों से बचने के लिए और दुर्घटना होने पर विशेष कार्रवाई करने की व्यवस्था की गयी है। कोयला खानों में सुरक्षा का और अधिक प्रबन्ध करने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में नियमों में संशोधन किया है। बागान श्रमिक अधिनियम में श्रमिकों को बीमारी के समय वेतन देने, स्त्री-श्रमिकों को प्रसवकालीन सुविधाएं देने और सवेतन छुट्टी देने की व्यवस्था है।

भारत सरकार ने दुकानों और व्यापारिक संस्थाओं में काम करने वालों के लिए भी आदर्श विधेयक तैयार किया। यह विधेयक राज्य सरकारों को भेजा गया, ताकि वे इसके आधार पर अपने राज्यों के नियमों में सुधार कर सकें। हाल ही में पत्रकारों के काम के घण्टे, छुट्टी आदि के बारे में भी कानून बनाया गया है। इन कानूनों से श्रमिकों को जो सुविधाएं मिली हैं, उनमें जलपान-गृह, भोजन-कक्ष, प्राथमिक चिकित्सा, सफ़ाई आदि की सुविधाएं शामिल हैं। खान-अधिनियम में खान से बाहर नहाने का प्रबन्ध करने की भी व्यवस्था है।

कल्याण कोष

श्रमिकों को और अधिक सुविधाएं देने के लिए

अंक उपयोगी होगा।

अणुव्रत (निर्माण अंक)— सम्पादक—श्री सत्यनारायण। प्रकाशक—अणुव्रत कार्यालय, ३, पोर्चुगीज चर्च स्ट्रीट, कलकत्ता-१। मूल्य १)।

आज अणुव्रत आन्दोलन का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। आज के आर्थिक युग में, जब कि प्रत्येक बात और काम का मूल्य हम रुपये-पैसों में लगाते हैं और स्वार्थ तथा लोभ की ही दृष्टि ही हमारे सामने रहती है, अणुव्रत आन्दोलन हमें सही दिशा का प्रदर्शन करता है। इस आन्दोलन के मुखपत्र 'अणुव्रत' का विशेषांक चरित्र-निर्माण के ऊंचे आदर्श की ओर ले जाता है। वस्तुतः देश के आर्थिक विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए आत्मजीवन का निर्माण अनिवार्य है। इसी दृष्टि से यह अंक प्रकाशित किया गया है। राष्ट्र निर्माण की विविध समस्याओं और प्रवृत्तियों पर इसमें अनेक सुन्दर लेख हैं। अनेक लेख विकास योजनाओं की दृष्टि से भी उपयोगी हैं। विविध लेखों में बताये गये वैयक्तिक और सामाजिक दोनों चरित्र आज हमारे लिए आवश्यक हैं। अनेक कहानियां और कविताएं भी अंक को उपयोगी बना देती हैं। हमें आशा है कि यह अंक उचित मार्गदर्शन करेगा।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कोयला तथा अभरक खान उद्योगों में विशेष कल्याण कोष भी खोले गये हैं। कोयला खान श्रमिक कल्याण कोष संगठन का मुख्य काम चिकित्सा का प्रबन्ध करना है। यह संगठन केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय अस्पताल खोलता है, आम अस्पतालों में श्रमिकों के लिए पलंगों की व्यवस्था करता है। जच्चा-बच्चा केन्द्र, दवाखाने आदि खोलता है। चलते-फिरते दवाखानों की व्यवस्था करता है और खान-मालिक दवाखानों की जो व्यवस्था करते हैं, उनके लिए आर्थिक सहायता देता है। यह संगठन तपेदिक तथा मलेरिया रोकने के काम में भी सहायता करता है।

औद्योगिक मकान

संगठन ने खान-मजदूरों के लिए २,१५० मकान बनाये हैं। इसके अलावा, खान-मालिकों को २,८०० मकान बनाने के लिए कल्याण कोष से सहायता दी गयी। कोष से इस काम के लिए खान-मालिकों को काफी सहायता दी जाती है।

स्वतन्त्रता मिलने से पहले, केवल कुछ इनेगिने मालिकों ने ही और कुछ सीमा तक सरकार तथा स्थाननीय संस्थाओं ने मजदूरों के लिए मकान बनाने का काम किया। १९५२ में सरकार ने सहायता-प्राप्त औद्योगिक मकान योजना शुरू की। इसके अंतर्गत राज्य सरकार, आवास-मण्डल और श्रमिकों की सहकारी मकान निर्माण संस्थाएं श्रमिकों के लिए मकान बनाती हैं। केन्द्रीय सरकार उन्हें सहायता तथा ऋण के रूप में आर्थिक सहायता देती है। अगस्त, १९५७ तक ६३,५०० मकान बन चुके थे और १५,८०० बन रहे थे। इसके अलावा मकान बनाने की और भी योजनाएं हैं। सरकार जब कोई उद्योग खोलना चाहती है, तो पहले श्रमिकों के लिए बस्ती बनाने पर विचार जाता है, ताकि वे आराम से रह सकें। पहले आयोजन में भारतीय रेलों ने श्रमिकों के लिए ४०,००० नये क्वार्टर बनाये।

सामाजिक सुधार

१९४८ में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम बनाया गया। इसमें श्रमिकों को उस समय सहायता दी जाती है, जब वे काम करते समय बीमार पड़ जाएं, या जख्मी हो जाएं। स्त्री-श्रमिकों को प्रसवकालीन सुविधाएं देने की व्यवस्था भी इस अधिनियम में है। उन्हें नकद और चिकित्सा सहायता के रूप में मदद दी जाती है। यह योजना देश के लगभग सभी प्रमुख औद्योगिक शहरों में लागू कर दी गयी है और इससे चलाने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम बनाया गया है। इस योजना से १२ लाख से भी अधिक श्रमिक लाभ उठा रहे हैं।

श्रमिकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि में भाग लेना भी अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि उन्हें अवकाश प्राप्त करने के बाद या बुढ़ापे में सहायता मिल सके और उनकी मृत्यु के बाद उनके बाल-बच्चोंकी मदद मिल सके। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम १९५२ में पारित हुआ था, जो इस समय २६ उद्योगों, ५ प्रकार के बागान (कहवा बागान सहित) उद्योगों, ४ प्रकार के खान उद्योगों और समाचार-पत्र संस्थाओं पर लागू है। इससे लगभग २४ लाख श्रमिकों को लाभ पहुँच रहा है। इसके अलावा कोयला खानों के ३ लाख ३३ हजार श्रमिक कोयला-खान भविष्य निधि के सदस्य हैं। अगस्त १९५७ के अन्त में कोष में १० करोड़ रु० जमा था।

श्रमिक की आय

स्वतन्त्रता के बाद श्रमिकों की आय काफी बढ़ी है। औद्योगिक झगड़ा अधिनियम के अन्तर्गत जो करार हुए तथा पंचाट बने, उन्हीं का यह परिणाम है। बैंक पंचाट और कोयला-पंचाट इनमें प्रमुख हैं! सरकार के प्रयत्न से ही बागान श्रमिकों को बोनस देने का समझौता हुआ, इससे इन उद्योगों में श्रमिकों की काफी आमदनी बढ़ी है।

बीड़ी बनाना, कालीन तैयार करना, पत्थर कूटना, मकान बनाना, बागान और खेती आदि जिन कामों में काफी शारीरिक परिश्रम करना पड़ता है, उनके लिए १९४८ में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित किया गया था। तबसे मजदूरी की न्यूनतम दरें, खेती को छोड़कर, बाकी सभी स्थानों में लागू की जा चुकी हैं। कुछ राज्यों में खेतिहर मजदूरों के लिए भी न्यूनतम दरें लागू कर दी गई हैं।

सूती कपड़ा उद्योग के लिए वेतन मंडल नियुक्त किया जा चुका है और चीनी तथा सीमेंट उद्योगों के लिए वेतन-मण्डल नियुक्त करने पर विचार किया जा रहा है।

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

झगड़े रोकने तथा उनका निपटारा करनेके लिए औद्योगिक झगड़ा अधिनियम १९४७ लागू किया गया। इसकी कार्यप्रणाली तथा इसे और अधिक स्थानों में लागू करने के लिए हाल ही में इसमें संशोधन किये गये हैं। फैक्टिरियों में द्विदलीय कार्यसमितियां बनायी गईं और उनके ऊपर संयुक्त सलाहकार मण्डल बनाया गया। इसके अलावा त्रिदलीय सलाहकार संगठन भी बनाये गये हैं।

देश के आर्थिक विकास के लिए उत्पादकता बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है। मोटे तौर पर उत्पादकता बढ़ाने के अर्थ होते हैं—जनशक्ति, पूंजी और प्राकृतिक साधनों का अच्छे से अच्छा उपयोग। अतः उत्पादकता बढ़ाने में श्रमिक का बहुत बड़ा हाथ होता है। भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के विशेषज्ञों की सहायता से बम्बई में राष्ट्रीय उत्पादकता केन्द्र खोला। बम्बई और बंगलौर में केन्द्र ने इन्जीनियरी उद्योग में उत्पादकता बढ़ाने की जो योजनाएं चलायीं, वे काफी सफल रहीं।

परन्तु जब तक श्रमिक स्वेच्छा तथा उत्साह से योग न दें, तब तक उत्पादकता बढ़ाने के या विकास के कार्यक्रम में अधिक सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए यह आवश्यक है कि मजदूर के अन्दर यह भावना रहे कि जो काम वह कर रहा है, उसमें उसका भी हिस्सा है और वह देश के विकास में अपनी ओर से काफी मदद दे रहा है। इसको ध्यान में रखकर सरकार ने कुछ उद्योगों के प्रबन्ध में श्रमिकों के भाग लेने की भी योजना बनायी है। योजना के अनुसार मालिकों और मजदूरों की प्रबन्ध परिषदें बनायी जाती हैं, जो कारखानों के बारे में सूचनाएं प्राप्त करती हैं और वहां विकास के लिए सिफारिशें करती है।

उद्योगों में शान्ति से काम होने से ही उत्पादकता बढ़ सकती है, विकास का काम तेजी से हो सकता है और श्रमिकों के कल्याण के लिए सुविधाएं बढ़ायी जा सकती हैं। मालिक-मजदूरों के बीच में अच्छे सम्बन्ध होना बहुत जरूरी है। हाल ही में सभी सम्बन्धित दलों ने उद्योगों में अनुशासन के लिए नियम बनाये हैं और उन्हें स्वीकार किया है। यह देश में औद्योगिक सम्बन्धों के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है।

संचालक पंचायत राज विभाग उ० प्र०

की

विज्ञप्ति संख्या ४/५५८० : २७/३३/५३, दिनांक १५

द्वारा

पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत

सुन्दर पुस्तकें

	लेखक	मूल्य रु०	मूल्य आ०
वेद सा	प्रो. विश्वबन्धु	१	८
प्रभु का प्यारा कौन ? (२ भाग)	,,		
सच्चा सन्त	,,		३
सिद्ध साधक कृष्ण	,,	०	३
जोते जी ही मोक्ष	,,	०	३
आदर्श कर्मयोग	,,	०	३
विश्व-शान्ति के पथ पर	,,	०	१
भारतीय संस्कृति	प्रो. चारुदेव	०	३
बच्चों की देखभाल	प्रिंसिपल बहादुरमल	१	१२
हमारे बच्चे	श्री सन्तराम बी. ए.	३	१२
हमारा समाज	,,	६	०
व्यावहारिक ज्ञान	,,	२	१२
फलाहार	,,	१	४
रस-धारा	,,	०	१४
देश-देशान्तर की कहानियां	,,	१	०
नये युग की कहानियां	,,	१	१२
गल्प मंजुल	डा० रघुबरदयाल	१	०
विशाल भारत का इतिहास	प्रो. वेदव्यास	३	८

१० प्रतिशत कमीशन और ५० रु० से ऊपर के आदेशों पर १५ प्रतिशत कमीशन।

विश्वेश्वरानन्द पुस्तक भंडार

साधु आश्रम, होशियारपुर

पंजाब

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वित्तीय आयोग : नये प्रस्ताव

केन्द्र व राज्यों के बीच आय का वितरण करने का विवाद ब्रिटिश शासन के प्रारंभ से और विशेषकर के १८३३ में गवर्नर जनरल तथा कौंसिल के अधिकारों में वृद्धि के समय से चला आ रहा है। ज्यों ज्यों इस प्रथा का निपटारा किया गया, विवाद और भी उग्र होता गया। भारत के स्वतंत्र होने के बाद १९४९ में श्री चिन्तामणि देशमुख ने इस संबंध में एक निर्णय दिया और १९५१ में श्री के० सी० नियोगी की अध्यक्षता में एक वित्त कमीशन नियत किया गया। इसकी सिफारिशों की अवधि (पांच वर्ष) १९५७ में समाप्त हो गई। इसलिए राष्ट्रपति ने गत वर्ष जुलाई में श्री के० सन्तानम की अध्यक्षता में वित्त आयोग की घोषणा की थी।

द्वितीय वित्त आयोग की हाल में ही स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा एकत्रित अनेक करों में से अब राज्य सरकारों को प्रतिवर्ष लगभग ४७ करोड़ रुपया अधिक मिलेगा। इस समय लगभग ९७ करोड़ मिलता है, परन्तु अब लगभग १४० करोड़ रु० मिलेगा।

भारत सरकार ने आयोग से कहा था कि वह केन्द्रीय सरकार को मिलने वाले आय कर और अन्य करों के सम्बन्ध में जांच कर बताए कि कितना अंश राज्य सरकारों को दिया जाए। अन्य करों में उत्पादन शुल्क, सम्पत्ति शुल्क तथा रेल के किराए पर कर शामिल हैं। इनके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद २७३ और अनुच्छेद २७५ के अन्तर्गत राज्य सरकारों की कितनी रकम दी जाए, इसके संबंध में भी आयोग से सिफारिश मांगी गई थी। आयोग ने सिफारिश की है कि आय कर का ६० प्रतिशत केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को दे, जब कि अब तक केन्द्रीय सरकार ५५ प्रतिशत राज्य सरकारों को देती थी।

आयोग को खेती की भूमि को छोड़ अन्य सम्पत्ति पर लगने वाले सम्पत्ति-शुल्क और रेल के किरायों पर हाल ही में लगाये गये कर के बंटवारे के बारे में भी सिफारिशें करनी थीं। आयोग को यह भी तय करना था कि राज्यों को मिल के बने कपड़े, चीनी और तम्बाकू पर बिक्री-कर से कितनी आय होती है और बिक्री-करों के स्थान पर लगाये जाने वाले अतिरिक्त उत्पादन शुल्कों के बंटवारे का उपाय भी सुझाना था। इसके अलावा, आयोग को केन्द्र द्वारा १५ अगस्त, १९४७ से ३१ मार्च, १९५६ तक राज्यों को दिये गये ऋणों की शर्तों की समीक्षा भी करनी थी और आवश्यक संशोधन का सुझाव रखना था।

इस समय निगम-कर से भिन्न आय-कर से, जिसमें संघीय उपलब्धियों पर लगने वाले कर और संघीय क्षेत्रों में लगने वाले कर (शुद्ध आय के १ प्रतिशत के हिसाब से निश्चित) शामिल नहीं है, होने वाली शुद्ध आय का ५५ प्रतिशत राज्यों में बांट दिया जाता है। राज्यों के अंश का ८० प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर और २० प्रतिशत कर-उपलब्धि के आधार पर निश्चित किया जाता है। वित्त आयोग ने यह सिफारिश की है कि राज्यों का अंश ५५ प्रतिशत से बढ़ाकर ६० प्रतिशत कर दिया जाय और इस अंश का ९० प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर और १० प्रतिशत कर-उपलब्धि के आधार पर बांटा जाय।

प्रथम वित्त आयोग को सिफारिशों के अनुसार एक अप्रैल, १९५२ से माचिसों, वनस्पति वस्तुओं और तम्बाकू पर केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क से होने वाली शुद्ध आय का ४० प्रतिशत राज्यों में जनसंख्या के आधार पर बांटा जाता है। द्वितीय आयोग ने सिफारिश की है कि कहवा, चाय, चीनी, कागज और असुगंधित वनस्पति तेलों पर लगा उत्पादन-शुल्क भी राज्यों में बांटा जाय। उपर्युक्त आठ वस्तुओं के उत्पादन-शुल्क से होने वाली शुद्ध आय में राज्यों का अंश अब २५ प्रतिशत निश्चित कर दिया गया है।

प्रथम वित्त आयोग ने पटसन और पटसन से बनी चीजों के निर्यात-शुल्क में हिस्सा देने के स्थान पर पश्चिम बंगाल को १५० लाख रुपये, उड़ीसा को १५ लाख रुपये और असम तथा बिहार को ७५-७५ लाख रुपये अनुदान देने की सिफारिश की थी। राज्यों के पुनर्गठन के परिणाम-स्वरूप बिहार के कुछ प्रदेश पश्चिम बंगाल में चले जाने के कारण, बिहार को दिये जाने वाले अनुदान में २.६६ लाख

[सम्पादा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रुपए कम कर दिये गये हैं और यह राशि पश्चिम बंगाल को दिये जाने वाले अनुदान में शामिल कर दी गयी है। आयोग ने सिफारिश की है कि इन राज्यों को ३१ मार्च, १९६० तक अनुदान की वर्तमान राशि ही दी जाए।

प्रथम आयोग ने प्राक्रमण की जो योजना सुझाई थी, और जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया था, उसके अंतर्गत असम को १०० लाख रुपए, उड़ीसा को ७५ लाख रु०, पंजाब को १२५ लाख रु०, सौराष्ट्र को ४० लाख रु०, तिरुवांकुर-कोचीन को ४५ लाख रु०, मैसूर को ४० लाख रु० और पश्चिम बंगाल को ८० लाख रु० की निश्चित राशि अनुदान के रूप में दी गयी। जम्मू एवं काश्मीर से हुए एक अलग समझौते के अधीन उसे प्रति वर्ष २५० लाख रु० अनुदान के रूप दिये जाते हैं। आयोग के सुझाव के अनुसार बिहार, हैदराबाद, मध्यभारत, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, पटियाला, पंजाब और राजस्थान राज्यों को प्रारम्भिक शिक्षा के विस्तार के लिये १९५६-५७ में समाप्त होने वाले चार वर्षों में कुल ९ करोड़ रु० के विशेष अनुदान दिये गए। द्वितीय वित्त आयोग ने ऐसे उद्देश्यों के लिए किसी अनुदान की सिफारिश नहीं की है, लेकिन १४ में से ११ राज्यों को पर्याप्त अनुदान देने की सिफारिश की है।

सम्पत्ति-शुल्क से होने वाली शुद्ध आय का वितरण संसद द्वारा स्वीकार कानूनों के अनुसार होना आवश्यक है। इस सम्पत्ति-शुल्क से होने वाली शुद्ध आय का वितरण आय कर से होने वाली शुद्ध आय के वितरण की भांति किया जाता है। अंतर केवल इतना ही है कि केन्द्रीय प्रदेशों से होने वाली शुद्ध आय के छोड़ बाकी सारी राशि बांट

विविध राज्यों में केन्द्र द्वारा वितरण

	आय कर का हिस्सा	उत्पादन कर का भाग	२७३ अनुबन्ध के अन्तर्गत सहायता	२७३ अनुबन्ध के अन्तर्गत	मृत्यु कर का भाग	रेल के किरायों पर टैक्स का भाग	उत्पादन कर में नई वृद्धि	
							संभावित आय	वितरण
राज्यों का भाग	६०%	२५%	...	...	९९%	९९.७५%	...	९७.७५%
विवरण	प्रतिशत	प्रतिशत	लाख रु०	लाख रु०	प्रतिशत	प्रतिशत	लाख रु०	प्रतिशत
आंध्र	८.१२	९.३८	..	४००	८.७६	८.८६	२३५	७.८१
असम	२.४४	३.४६	७५.००	३७५×	२.५३	२.७१	८५	२.७३
बिहार	९.९४	१०.५७	७२.३१	३५०×	१०.८६	९.३९	१३०	१०.०४
बम्बई	१५.९७	१२.१७	..	..	१३.५२	१६.२८	९६०	१७.५२
केरल	३.६४	३.८४	..	१७५	३.७९	१.८१	९५	३.१५
मध्यप्रदेश	६.७२	७.४६	..	३००	७.३०	८.३१	१५५	७.१९
मद्रास	८.४०	७.५६	..	..	८.४०	६.४६	२८५	७.७४
मैसूर	५.१४	६.५२	..	६००	५.४३	४.४५	१००	५.१३
उड़ीसा	३.७३	४.४६	१५.००	३२५×	४.१०	१.७८	८५	३.२०
पंजाब	४.२४	४.५९	..	२२५	४.५२	८.११	१७५	५.७१
राजस्थान	४.०९	४.७१	..	२५०	४.४७	६.७७	९०	४.३२
उत्तरप्रदेश	१६.३६	१५.९४	..	..	१७.७१	१८.७६	५७५	१७.१८
बंगाल	१०.०८	७.५९	१५२.६९	३२५×	७.३७	६.३१	२८०	८.३१
जम्मू-काश्मीर	१.१३	१.७५	..	३००	१.२४	..	..	×

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दी जाती है, जबकि आय-कर का केवल ५५ प्रतिशत भाग बांटा जाता है। आयोग ने सुझाव दिया है कि ३१ मार्च, १९५७ तक की अवधि के लिए इस अस्थायी वितरण को कानूनी स्वीकृति प्रदान की जाय। भविष्य के लिए आयोग ने यह सिफारिश की है कि केन्द्रीय प्रदेशों का एक प्रतिशत रख लेने के बाद बाकी शुद्ध आय को अचल सम्पत्ति और अन्य सम्पत्ति के हिसाब से बांटा जाय।

रेल के किरायों पर शुल्क के विषय में आयोग ने सिफारिश की है कि इस कर से होने वाली शुद्ध आय का एक-चौथाई प्रतिशत केन्द्रीय प्रदेशों के भाग के रूप में केन्द्र रखले और बाकी राज्यों में बांट दिया जाय। वह वितरण प्रत्येक राज्य में स्थित रेल की मार्च, १९५६ में समाप्त तीन वर्षों की औसत आय के आधार पर किया गया है। औसत आय के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय रेल और छोटी-बड़ी लाइनों की अलग-अलग आय निकाली गयी और उसे प्रत्येक राज्य की सीमा के अंतर्गत रेल-मार्ग की लम्बाई के आधार पर राज्यों में बांट दिया गया।

अतिरिक्त उत्पादन शुल्क

आयोग ने राज्यों को मिल के बने कपड़े, चीनी और तम्बाकू पर बिक्री-करों से प्रति वर्ष ३२.५० करोड़ रु० की आय होने का हिसाब लगाया है। आयोग ने सिफारिश की है कि इन वस्तुओं पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क से जो शुद्ध आय होगी, उसमें से पहले राज्यों को उनके अपने हिसाब से, मुआवजा दिया जाय और यदि कुछ बाकी बचे तो उसे राज्यों में बांट दिया जाय। यह वितरण अंशतः जनसंख्या के आधार पर और अंशतः खपत से किया गया है। आयोग ने सिफारिश की है कि राज्यों में वितरण से पहले शुद्ध आय का एक प्रतिशत केन्द्रीय प्रदेशों के भाग के रूप में केन्द्र रख ले और १। प्रतिशत जम्मू एवं काश्मीर राज्य को दिया जाय। इस समय जम्मू एवं काश्मीर में कोई बिक्रीकर नहीं है, परन्तु अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क का एक भाग उसे देना होगा, क्योंकि ये शुल्क वहां भी लगेंगे। राज्यों को जितनी आय की गारंटी दी गई है और बाकी में उनका जितना भाग है, वह साथ में संलग्न सारिणी में दिया गया है। उत्पादन के लाभ के बारे में भी कुछ सिफारिशें की गई हैं। आयोग ने यह अनुमान लगाया है कि प्राक्रमण की योजना के अनुसार राज्यों को केन्द्रीय राजस्व से प्रति वर्ष १४० करोड़ रु० मिलेंगे।

राजस्व के विभाग	राज्यों के कुल राजस्व का प्रतिशत		प्रति व्यक्ति आय रु० में	
	१९५१-५२	१९५५-५६	१९५१-५२	१९५५-५६
कृषि आय-कर	१.१	१.४	...	...
भूमि कर	१२.२	१३.९	१.४	२.२
राज्य उत्पादन कर	१२.२	७.८	१.४	१.२
टिकटें (स्टाम्प)	५.४	४.३	०.६	०.७
बिक्री कर (मोटर का तेल कर भी सम्मिलित है)	१४.४	१४.२	१.७	२.२
रजिस्ट्रेशन	१.०	०.७	...	...
अन्य कर	१०.०	७.५	...	...
आय-कर का भाग	१२.८	९.८	...	...
केन्द्रीय करों का भाग	...	२.९	१.५	२.०
राज्यों को केन्द्रीय सहायता	४.३	४.३	०.५	०.७
सहायता २८२ अनुच्छेद के अनुसार	१०९	९.३	०.२	१.५
राजस्व के अन्य कर	२४.७	२३.९	...	...
कुल कर	...	...	८.०	९.९
कुल राजस्व कर	१००.०	१००.०	१३.४	

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राजस्व खाते में व्यय

मदें	राज्यों के व्यय का प्रतिशत		विभिन्न सेवाओं में प्रति व्यक्ति व्यय (रु० में)	
	१९५१-५२	१९५५-५६	१९५१-५२	१९५५-५६
कर वसूली का व्यय	९.७	९.५	—	—
सिंचाई	४.४	३.८		
ऋण पर व्यय	०.१	१.०		
सामान्य शासन	८.६	७.४	०.९	१.२
पुलिस	१४.०	९.८	१.६	१.७
अन्य शासन कार्य	४.८	३.३	०.५	०.६
शिक्षा	१५.५	१७.७	०.७	२.९
चिकित्सा व सार्वजनिक स्वास्थ्य	७.४	७.७	०.८	१.३
अन्य समाज सेवाएं	६.९	६.७	०.८	१.०
उद्योग तथा विविध	३.६	३.६	—	—
सिविल कार्य	१०.६	१०.९	—	—
अन्य विविध	१५.४	१९.३	—	—
कुल व्यय ●	१००.०	१०००	१३.४ ●	

● १९५१-५२ में ४००.४ करोड़ रु० और १९५५-५६ में ५९७० करोड़ रु०

● १९५१-५२ से १९५५-५६ तक का औसत व्यय

१९५६,५७ में समाप्त होने वाले पांच वर्षों में राज्यों को औसत प्रति वर्ष ९३ करोड़ रुपया मिलता रहा।

वित्त आयोग की नयी सिफारिशों से राज्यों को १४० करोड़ रुपए मिलने लगेंगे, जबकि मार्च १९५२ की सिफारिश के अनुसार ९३ करोड़ रुपए केन्द्र से मिलते थे। रेलवे किरायों के टैक्स और बिक्रीकर के (कपड़ा, तम्बाकू और चीनी) उत्पादन कर में बदल जाने पर और ऋण के ब्याज पर बचत आदि के कारण यह आमदनी १७० करोड़ रुपये तक हो जायेगी। इससे राज्यों की सरकारों को कुछ प्रसन्न होना स्वाभाविक है, किन्तु राज्य सरकारों को पूर्ण सन्तोष होगा, इसमें सन्देह है। ऊपर की दी हुई दो तालिकाओं से यह प्रकट है कि राज्यों ने समाज सेवाओं तथा राष्ट्र निर्माण सम्बन्धी सेवाओं पर अपने खर्च बढ़ा दिये हैं, वहां आमदनी के भी नये जरिये निकाले हैं। शासन सम्बन्धी व्यय कम बढ़ा है।

१९५०-५१ की अपेक्षा १९५७-५८ के केन्द्रीय बजट में ७३ % राजस्व की वृद्धि हुई। राज्यों ने भी ६९% की वृद्धि की है। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने भी आय बढाने के प्रयत्न में केन्द्रीय सरकार के समान ही प्रयत्न किया है। किन्तु अब जब एक ओर पंचवर्षीय योजना के कारण उनके व्यय बहुत बढ़ जायेंगे, १९५१-५२ की अपेक्षा उनका शासन व्यय १९५५-५६ में २७.४% से गिर कर २०.५% रह गया है। दूसरी तरफ समाज सेवाओं में व्यय २९.८% की अपेक्षा बढ़कर ३१.४ ०/० हो गया है। यदि पहिले की अपेक्षा प्रति व्यक्ति शासन व्यय आठ आना बढ़ा तो समाज सेवाओं पर प्रति व्यक्ति दो रुपये व्यय बढ़ गया है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि वे केन्द्र से मिलने वाली नई सहायता से भी सन्तुष्ट न हों।

यों पंडित जवाहरलाल नेहरू के कथनानुसार आज देश में आत्मनिर्भरता का अभाव बढ़ता जा रहा है। नागरिक प्रत्येक कार्य के लिए राज्य सरकार के आगे हाथ पसारते

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रिजर्व बैंक की

मुद्रा-चलन की सुरक्षित राशि में कमी

भारत के राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश, (३१ अक्तूबर '५७ को) नोटों के चलन के लिए रखी जाने वाली न्यूनतम सुरक्षित राशि से सम्बन्धित रिजर्व बैंक के अधिनियम में संशोधन करने के लिए जारी किया है। इस अध्यादेश के द्वारा रिजर्व बैंक को विदेशी सिक्यूरिटियों के रूप में वर्तमान समय में ४०० करोड़ रु० की मुद्राचलन सम्बन्धी न्यूनतम सुरक्षित राशि में कमी करने का अधिकार मिल गया। यहाँ तक कि विदेशी सिक्यूरिटी और सोने के रूप में रखी जानी वाली न्यूनतम मात्रा को अलग से निर्धारित कर दिया गया है। इस अध्यादेश के अनुसार दोनों प्रकार की न्यूनतम सुरक्षित निधि मिलकर २०० करोड़ रु० नियत की गई है, जिनमें से सोने के सिक्के और बट्टियां ११५ करोड़ रु० से कम नहीं होनी चाहिए।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद मुद्रा चलन सम्बन्धी रिजर्व बैंक के कानून में संशोधन करने का यह दूसरा अवसर है। पहला संशोधन पिछले वर्ष संसद द्वारा बिल पास सरके किया गया था। पाठकों को ज्ञात होगा कि जुलाई १९५६ में भारत सरकार ने मूल कानून के खण्ड ३३ (२) और (४) और ३७ में संशोधन किया था। मूल कानून के खण्ड ३३ (२) में यह प्रावधान था—

"परिसम्पत की कुल मात्रा, जो $\frac{२}{५}$ से कम न होगी, सोने के सिक्के, सोने की बट्टियों और स्टर्लिंग सिक्यूरिटीके रूपमें रखी जायेगी।

"इस प्रावधान के होते हुए भी सोने के सिक्के और सौने की बट्टियां किसी भी समय ४०० करोड़ रु०के मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए।"

मुद्रा चलन के लिए ४० प्रतिशत के अनुपात पर जो सुरक्षित राशि थी, उसे समझा गया कि द्वितीय पँचवर्षीय योजना काल में आर्थिक विकास की आवश्यकता के अनुसार अधिक मुद्रा चलन में रिजर्व बैंक की शक्ति सीमित हो जायेगी। यह अनुमान लगाया गया था कि १,२०० करोड़ रु० की अवश्य ही मुद्रा के अधिक चलन (घाटे की अर्थ-व्यवस्था) से या प्राप्त की जानी चाहिए और स्टर्लिंग निधि को कम करके २०० करोड़ रु० कर देना चाहिए जिससे घाटे के विदेशी व्यापार का भुगतान किया जा सके। उस समय की स्थिति के अनुसार अधिक मुद्रा की राशि केवल १८९ करोड़ थी, जिसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के लिए, जब कि राष्ट्र की आय २५ प्रतिशत और बढ़ जायेगी, अपर्याप्त माना गया। यह भी खयाल किया गया था कि इस मुद्रा-चलन की राशि में वृद्धि करना प्रतिकूल विदेशी व्यापार में सम्भव नहीं है। इसी कारण खण्ड ३३ (२) का संशोधन इस प्रकार किया गया है:

"परिसम्पत की कुल मात्रा, सोने के सिक्कों या सोने बट्टियों की राशि और विदेशी सिक्यूरिटयों की राशि किसी भी समय क्रमशः ११५ करोड़ रु० और ४०० करोड़ के मूल्य से कम न होगी।"

आनुपातिक कठोरता हटी

इस संशोधन के अनुसार नियत अनुपात की कठोरता दूर कर दी गई और सोना तथा विदेशी विनिमय की एक न्यूननम राशि स्पष्टतः निर्धारित कर दी गई।

खण्ड ३२ (२) के साथ ही इसके उपखंड (४), में जिसमें सोना, रौप्य मुद्रा और सिक्यूरिटियों के मूल्य की दर नियत थी, भी संशोधन कर दिया गया था। इसका उद्देश्य यह है कि स्वर्ण राशि की दर ८.४७५१२ ग्रेन प्रति रुपया से २.८८ प्रति रुपया में पुनर्मूल्यित कर दी जाये, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की दर के बराबर है। दूसरे

[सम्पादा

हैं। राज्य केन्द्रीय सरकार के आगे और केन्द्रीय सरकार विदेशों से सहायता की प्रार्थना करती है। स्वावलम्बन का भाव नष्ट होता जा रहा है।❀

❀ वित्त आयोग की पृष्ठ भूमि जानने के लिए अगस्त १९५६ का 'सम्पदा' का अंक ७५ नये पैसे भेजकर मंगाइये।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शब्दों में सोने का मूल्य २१-३-१० प्रति तोला से ६२-८ प्रति तोला ऊपर बढ़ा, जिससे स्वर्ण राशि (७१ लाख औंस) का समग्र मूल्य ४०.२ करोड़ से बढ़ कर ११७.७६ करोड़ हो गया। इसी प्रकार सोने का पुनर्मूल्यन हो जाने से रिजर्व बैंक ने भी सोने की राशि की न्यूनतम मात्रा ४० करोड़ से बढ़ाकर ११५ करोड़ कर दी। इसमें विदेशी सिक्यूरिटियों की (केवल स्टर्लिंग सिक्यूरिटी ही नहीं) जैसे मूल एक्ट में कहा गया है, ४०० करोड़ की राशि सम्मिलित नहीं है।

मूल एक्ट के खण्ड ३७ के अनुसार रिजर्व बैंक को यह अधिकार है कि वह मुद्रा चलन की सुरक्षित राशि की मात्रा, खण्ड ३३ (२) में वर्णित प्रावधान से अस्थायी रूप में कम रखी जा सकती है यदि इसके लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति ले ली गई हो, लेकिन इसके द्वारा कम से कम ६ प्रतिशत कर की प्राप्ति होनी चाहिए जब कि सुरक्षित राशि में कमी हो जाये। विगत वर्ष इस खण्ड का भी संशोधन कर दिया गया ताकि विदेशी विनिमय के रूप में मुद्रा जलन की सुरक्षित राशि की आवश्यकता को अस्थायी रूप से बिना सरकार को कोई भी कर दिये स्थगित किया जा सके। खण्ड ३७ के संशोधन के अनुसार अब रिजर्व बैंक को यह अधिकार मिल गया कि विशेष परिस्थितियों में अपनी विदेशी सिक्यूरटियों को कम करके कम से कम ३०० करोड़ रु० पर ले आये, जब कि स्वर्ण राशि को ११५ करोड़ रु० से किसी भी परिस्थिति में कम नहीं किया जा सकता। इस प्रकार ४१५ करोड़ रु० की कुल न्यूनतम राशि रखनी होगी।

आपातकालीन प्रावधान

इसका तात्पर्य यह है कि रिजर्व बैंक सोने और विदेशी विनिमय की कुल न्यूनतम राशि में २०० करोड़ रु० की कमी कर सकता है जिसमें स्वर्ण बट्टियां अकेले ११५ करोड़ रु० से कम न होंगी। दूसरे शब्दों में विदेशी सिक्यूरिटियों में, वर्तमान न्यूनतम राशि ४०० करोड़ रु० से कम करके ८५ करोड़ रु० किया जा सकता है। चूंकि इस समय स्वर्ण मुद्रा और सोने की बट्टियां सम्मिलित रूप से ११८ करोड़ रु० की मूल्य की हैं अतः विदेशी सिक्यूरिटियों को कम करके ८२ करोड़ रु० तक लाया जा सकता है। यथार्थ में यदि मुद्रा चलन के लिए सुरक्षित राशि के रूप में सोने के सिक्कों और सोने की बट्टियों के अंश में वृद्धि की जा सकती है तो संशोधित खण्ड ३३ के अनुसार विदेशी सिक्यूरिटी में कमी भी की जा सकती है। सच तो यह है कि अस्थायी काल के लिए रिजर्व बैंक को किसी प्रकार की विदेशी विनिमय के रखने की आवश्यकता नहीं, बशर्ते कि सरकार आवश्यक अनुमति प्रदान कर दे। ऐसा केवल खण्ड ३७ (जिसमें पिछले वर्ष संशोधन किया गया) में ही यह आवश्यक है जिसमें इस समय कोई संशोधन नहीं किया गया। हां इसमें ऐसा अवश्य कहा गया है कि—"इस प्रकार विदेशी सिक्यूरिटी की जो राशि रखी जायेगी वह मूल्य में किसी भी समय ३०० करोड़ रु० से कम न होगी।" फिर भी यह माना गया है कि इस प्रावधान का उपयोग केवल घोर आपात काल में ही किया जायेगा।

मुद्रा चलन के लिये रखी जाने वाली सुरक्षित सीमा को कम करने का वर्तमान कदम आपेक्षित नहीं था, क्योंकि विगत समय जब इस राशि में सुधार करने का कार्य उठाया गया, तब से स्टर्लिंग निधि में तेजी से कमी होती गई, जैसे कि निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है—

अवधि	विदेशी परिसम्पत (करोड़ रु० में)
३० मार्च १९५६	७४६.१३
२७ अप्रेल १९५६	७२५.६५
१ जून १९५६	७०५.३३
२९ जून १९५६	६८१.५२
३ अगस्त १९५६	६५३.४६
३१ अगस्त १९५६	६३१.३१
२८ सितम्बर १९५६	६१५.०६
३० नवम्बर १९५६	५३५.५३
२८ दिसम्बर १९५६	५२९.९१
१ फरवरी १९५७	५१०.६०
१ मार्च १९५७	५१५.४०
२९ मार्च १९५७	५२६.८३
२६ अप्रेल १९५७	५०४.९१
३१ मई १९५७	४५५.०७
२८ जून १९५७	४५३.३४

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

२ अगस्त १९५७	४०१.८४
३० अगस्त १९५७	३७९.८६
२७ सितम्बर १९५७	३५२.९१
२५ अक्तूबर १९५७	३२७.१०

स्टर्लिंग निधि में भारी गिरावट

एक वर्ष के अन्दर विदेशी परिसम्पत में २४१.८३ करोड़ रु० की कमी हुई। इसमें ९५.५ करोड़ की अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से उधार ली जाने वाली वह राशि सम्मिलित नहीं है, जो इस अवधि में खर्च हो गई। यदि इस राशि को सम्मिलित कर लें तो इस वर्ष में विदेशी विनिमय ३३७.३३ करोड़ रु० की मात्रा में व्यय हुआ। ८२ करोड़ रु० की न्यूनतम मात्रा तक पहुँचने के लिए अभी २४५ करोड़ रु० और खर्च किये जा सकते हैं।

इस अध्यादेश को जारी करने का कारण यह है कि ऐसा भय होने लगा था कि ८ करोड़ रु० प्रति सप्ताह की दर से जो विदेशी विनिमय खर्च किया जा रहा है यह ३०० करोड़ रु० की न्यूनतम सुरक्षित राशि की सीमा तक कहीं संसद के दोनों सदनों की बैठक होने के पहले ही न पहुँच जाये। इस अध्यादेश के अनुसार वर्तमान दर से जो विनिमय-मुद्रा खर्च की जा रही, वह मई १९५८ तक के लिए पूरी होगी। इसके बाद रिजर्व बैंक को आपातकालीन प्रावधान द्वारा अपनी विदेशी सिक्यूरिटी को ८५ करोड़ से भी कम करना होगा। ऐसी आशा है कि यह आयातकाल उपस्थित नहीं होगा।

रुपये पर बुरा प्रभाव नहीं

वित्त मंत्रालय के प्रमुख सचिव श्री एच० एम० पटेल ने कहा है कि अध्यादेश से रुपये की शक्ति या विदेशी साख पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि रुपये की सुदृढ़ता रिजर्व बैंक द्वारा रखी जाने वाली सुरक्षित राशि के अतिरिक्त अन्य बातों में निहित है जो, अपरिवर्तनीय हैं। संसार के बहुत से देश तो किसी भी प्रकार की सुरक्षित निधि नहीं रखते। पूर्ण स्टर्लिंग क्षेत्र के लिए जो न्यूनतम राशि सुरक्षित थी, वह इस पूरे क्षेत्र के ६ या ८ सप्ताह तक के लिए आवश्यक चुकता की जाने वाली राशि के बराबर होती।

वर्तमान विदेशी विनिमय के साधनों, विदेशी सहायता की अनिश्चिता और आयात की भारी अदायगी के कारण भारत को अप्रैल १९५८ से मार्च १९५९ तक भारी विदेशी विनिमय की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और भारत को चालू वर्ष की आवश्यकता से दुगुनी याने ५७६ करोड़ रु० की विदेशी विनिमय की आवश्यकता होगी।

★

बम्बई राज्य कोआपरेटिव बैंक

३० जून को समाप्त होने वाले वर्ष में बम्बई राज्य को-आपरेटिव बैंक ने अग्रिम राशि पर लिये जाने वाले ब्याज के रूप में ४६.९१ लाख रु० का लाभ कमाया। इस प्रकार एक वर्ष में ५.२९ लाख रु० की अधिक प्राप्ति हुई। लाभ की राशि और भी बढ़ गई होती, यदि सहकारी चीनी की मिलों के संदेहास्पद ऋणों के लिए ४ लाख रु० की राशि नियत न कर दी जाती। जमाराशि में कमी होने के बावजूद भी, दिये गये ऋणों से ३.९२ लाख रु० की आय हुई। जमाराशि ४६.९१ लाख रु० रही और उसकी लागत बढ़ गई थी। लाभ ६.२९ लाख रु० से ७.१९ लाख रु० के बीच रहा। साथ ही ३० हजार रु० कर चुकता करने के लिए अलग रखने के बाद, (जबकि पिछले वर्ष यह राशि शून्य थी), २ लाख रु० की सुरक्षित और अन्य निधियों के लिये रख लेने पर और १.६५ लाख रु० का कर्मचारियों को बोनस दे देने के पश्चात् डाइरेक्टरों ने ५ प्रतिशत के हिसाब से लाभांश वितरित किया और इसमें ३.२५ लाख रु० लग गये।

★

इंडस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन

आजकल इंडस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन के कार्य की काफी आलोचना की जा रही है और काफी व्यक्ति यह कहने लगे हैं कि कार्पोरेशन आर्टिकल्स और मेमोरेंडम में दिए गए उद्योगों की मदद करने के बजाय अन्य दूसरे उद्योगों की ही मदद कर रहा है। निगम के खिलाफ मुख्य शिकायत यह है कि वह निजी क्षेत्र के दरम्याने दर्जे के उद्योगों को सहायता देने की बजाय अधिक सहायता बड़े उद्योगों की कर रहा है। इसके साथ ही कर्ज देने में वह पक्षपात से काम ले रहा है और उन

[सम्पादक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उत्तर प्रदेश में

द्वितीय पंचवर्षीय आयोजन का आशाप्रद प्रारम्भ

प्रथम वर्ष में ही

लगभग ५ लाख २१ हजार टन अतिरिक्त खाद्योत्पादन सम्भव हुआ, जब कि लक्ष्य केवल ३ लाख ९४ हजार टन ही था।

९ करोड़ ७० लाख ५१ हजार रु० सिंचन सुविधाओं के प्रसार पर व्यय किए गए।

विद्युत शक्ति उत्पादन की क्षमता ६६४० किलोवाट बढ़ गई।

वन-रोपण की आठ योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ हुआ, जबकि आयोजन की पूरी अवधि में ११ योजनाएं कार्यान्वित होनी हैं।

लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास की ५५ योजनाओं में से ४७ पर काम शुरू हो चुका है।

कुल २१७.८ मील लम्बी सड़कों के निर्माण के लक्ष्य की तुलना में ४४० मील लम्बी सड़कें बनीं

और

४७ एलोपैथिक एवं देशी औषधालयों की स्थापना हुई।

सन्तोषजनक प्रारम्भ

भविष्य की पूर्ण सफल आहुति का संकेत है !

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उद्योगों को प्राथमिकता दे रही है जिनकी आवश्यकता रु. २५ से ५० लाख की है, परन्तु जांच पड़ताल से पता चला है कि उपरोक्त शिकायतें निराधार हैं ।

यह ठीक है साख वाली पार्टियों को निगम २५ लाख रु० तक का कर्ज दे रहा है लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि वह उनकी उपेक्षा कर रहा है जिनकी आवश्यकता कम राशि की है । इसके अलावा अब वह परिभाषा भी बदल गई है जो पहले दरम्याने उद्योगों की थी । पहले उन उद्योगों को दरम्याना उद्योग माना जाता था, जिनकी आवश्यकता २० व २५ लाख रु० से अधिक नहीं होती थी, किन्तु अब उन्हीं श्रेणी के उद्योगों की आवश्यकता इससे तिगुनी से चौगुनी है । इस कारण ये सब उद्योग जिनकी १ करोड़ तक की आवश्यकता होती है, दरम्याने उद्योगों में शामिल हैं और निगम ऐसे उद्योगों को अपने ध्येयों के अनुसार सहायता देने से इन्कार नहीं कर सकता । पक्षपात का इलजाम आसानी से किसी पर लगाया जा सकता है किन्तु वह कहां तक ठीक है, इसे जान सकना बहुत मुश्किल है । निगम का कार्य बहुत सुदृढ़ है और इसकी प्रशंसा हाल ही में एक प्रमुख अमीरीको बैंकर ने भी की है, जो इस समय भारत का दौरा कर रहा है ।

रूस से ५० करोड़ रूबल का ऋण

९ नवम्बर १९५७ को नयी दिल्ली में सोवियत संघ की सरकार और भारत सरकार के बीच एक समझौता, भारत में कतिपय औद्योगिक कारखाने स्थापित करने और ५० करोड़ रूबल के ऋण की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में सम्पन्न हुआ है ।

इस ऋण का उपयोग भारत में भारी मशीनें बनाने का कारखाना, कोयला-निकासी की मशीनों का कारखाना, दृष्टि सहायक यंत्र बनाने का कारखाना, तापचालित बिजली-उत्पादक स्टेशन (२,५०,००० किलोवाट) तथा खानों से कोयला निकालने और उसके बाद की प्रक्रियाओं के लिये कारखाने बनाने में किया जायगा । सोवियत संगठन इन सब कार्यभारों के लिए विस्तृत आयोजन रिपोर्ट तैयार करेगा तथा साज-सामान, मशीनें और माल-मसाला देगा, प्राविधिक दक्षता सम्बन्धी सहायता प्रदान करेगा ।

इन आयोजनों के लिए वांछनीय भारतीय प्राविधिक कर्मचारियों के लिए सोवियत संघ में आवश्यक प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था समझौते में हैं ।

ऋण पर ढाई प्रतिशत वार्षिक सूद लगेगा और ऋण की अदायगी १२ समान वार्षिक किस्तों में की जायगी । सोवियत संघ जब प्रत्येक कारखाने से सम्बन्धित मशीनें और साज-सामान पूरे का पूरा दे देगा, उसके एक साल बाद से किस्तों का भुगतान आरम्भ होगा ।

ऋण का उपयोग उपर्युक्त कारखानों के लिए मशीनें, साज-सामान और माल-मसाला खरीदने के लिए जिनकी पूर्ति सोवियत संघ करेगा तथा सोवियत संगठनों द्वारा दी जाने वाली प्राविधिक सहायता के लिए वित्त रूप में होगा । ऋण में इन कारखानों के लिए जरूरी विदेशी मुद्रा की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है । उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए इस समय जिस धन-राशि के बारे में समझौता हुआ है, यदि वह अन्ततोगत्वा इन कारखानों की स्थापना के लिए पर्याप्त न जान पड़े, तो और ऋण देने की व्यवस्था रखी गयी है ।

श्री एन० ए० स्मेलोव ने सोवियत संघ की ओर से और मंत्रिमंडल के सचिव श्री एन० के० बेलाडी ने भारत की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं ।

इस समझौते पर हस्ताक्षर से भारत सरकार को निकट भविष्य में विदेशी मुद्रा के संचय में काफी सहायता मिलेगी तथा चालू पंचवर्षीय योजना की प्रगति को प्रोत्साहन मिलेगा ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

१९५७ के पूर्वार्ध में उत्पादन में वृद्धि

भारत सरकार द्वारा प्रकाशित विवरण से ज्ञात होता है कि १९५७ की पहली छमाही में भारत में औद्योगिक उत्पादन सन्तोषजनक रूप से बढ़ा। इस अवधि में औद्योगिक उत्पादन का सूचक अङ्क (१९५१ को आधार वर्ष १०० मानकर) १९५६ के पूरे साल तथा उसकी पहली छमाही के औसत सूचक अङ्कों से अधिक रहा। इस अवधि में सीमेंट, चीनी, मोटरगाड़ी डीजल इन्जन, मशीनी औजार, ब्लेड, कोयला, सिलाई मशीन और साइकिल का उत्पादन काफी बढ़ा है।

पहली छमाही में औद्योगिक योजनाओं के लिए ४२० लाइसेंस दिये गये। इनमें से १०९ नए कारखाने खोलने, २२६ वर्तमान कारखानों का विस्तार करने या उनमें नए सामान बनाने तथा शेष वर्तमान कारखानों में उत्पादन का काम जारी रखने या उनका स्थान परिवर्तन करने आदि के लिए थे।

इस अवधि में मोटर गाड़ी के पुर्जे, सल्फरिक एसिड, साइकिल के पुर्जे, मशीनी औजार, कागज, सुपरफास्फेट, नये औषध और रंगाई के सामान आदि तैयार करने के या तो नए कारखाने खोले गए या वर्तमान कारखानों का विस्तार किया गया। बुनाई के १० नए कारखानों में भी उत्पादन शुरू हुआ। इस अवधि में सीमेंट का उत्पादन बढ़कर २६ लाख ७६ हजार टन हो गया। १९५६ की पहली छमाही में २४ लाख ५४ हजार टन सीमेंट तैयार हुआ था। कोयले का उत्पादन २० लाख टन बढ़कर २१ करोड़ ६० लाख टन हो गया।

उपभोक्ता सामग्री

आलोच्य अवधि में सूती कपड़ा, नमक, साबुन, चीनी, सिगरेट, ब्लेड और साइकिल का उत्पादन भी काफी बढ़ा। सूती कपड़े के कारखाने में २ अरब ७० करोड़ ९० लाख गज कपड़ा तैयार हुआ। १९५६ की पहली छमाही में २ अरब ५८ करोड़ ३० लाख गज कपड़ा तैयार हुआ था। सूत का उत्पादन ८० करोड़ २० लाख पौण्ड से बढ़कर लगभग ८९ करोड़ १० लाख पौंड हो गया।

इस अवधि में चीनी का उत्पादन १४ लाख ८६ हजार टन से बढ़कर १५ लाख ६२ हजार टन और नमक का उत्पादन ७ करोड़ २७ लाख से बढ़कर ७ करोड़ ७५ लाख मन हो गया।

१९५६ की पहली छमाही से लगभग एक लाख अधिक साइकिलें तैयार हुईं। आलोच्य अवधि में कुल तीन लाख ८१ हजार ५०० साइकिलें तैयार की गयीं। ब्लेड का उत्पादन ९ करोड़ ९३ लाख से बढ़कर २० करोड़ ९० लाख रुपया हो गया। इस अवधि में सिगरेटोंका उत्पादन १२ अरब ५४ करोड़ से बढ़कर लगभग १४ अरब २१ करोड़ ४० लाख हो गया।

इस्पात के उत्पादन में भी कुछ वृद्धि हुई, जिससे इस अवधि में इसका उत्पादन बढ़कर ६ लाख ७० हजार ४०० टन हो गया। सीसा, तांबा और अलूमीनियम का उत्पादन भी बढ़ा।

१९५६ की पहली छमाही में १४८०० मोटर गाड़ियां तैयार हुई थीं। आलोच्य अवधि में विभिन्न प्रकार की १६,६०० मोटरगाड़ियां तैयार हुईं।

आलोच्य अवधि में ७,०७६ डीजल इंजन तैयार हुए। गत वर्ष की पहली छमाही में ५,६५६ डीजल इन्जन तैयार हुए थे। मशीनी औजारों का उत्पादन शत प्रतिशत बढ़ा। पिछले वर्ष की इसी अवधि में ४२ लाख ५० हजार रु० मूल्य मशीनी औजार बने थे, लेकिन आलोच्य अवधि में १ करोड़ रु० से भी अधिक मूल्य के मशीनी औजार बने।

रेडियो सेटों का उत्पादन ७१००० से बढ़कर ९१,८०० और बिजली के पंखों का उत्पादन १ लाख ६५ हजार ७०० से बढ़कर २ लाख ४७ हजार हो गया।

इस अवधि में कागज और कागज के गत्ते का उत्पादन बढ़कर १ लाख १ हजार टन हो गया। पिछले वर्ष

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

की पहली छमाही का उत्पादन ९४ हजार टन था। कास्टिक सोडा, सोडा एश, ब्लेचिंग पाउडर का उत्पादन बढ़ा और मध्यसार का उत्पादन कुछ घटा।

साइकिलों का ट्यूब उत्पादन ३० लाख से बढ़कर ३७ लाख हो गया। मोटरगाड़ियों के टायर का उत्पादन ४ लाख ५६ हजार से बढ़कर ५ लाख ७ हजार हुआ है और ट्यूब का उत्पादन ४ लाख २४ हजार से बढ़कर ५ लाख १ हजार हो गया।

बिजली के सामान में पांच गुनी वृद्धि

देश में इस बर्ष २५ करोड़ रु० के मूल्य का बिजली का सामान-लैम्प, पंखे, रेडियो, बैटरी आदि बना, जब कि १९४८ में केवल ५ करोड़ रु० का बिजली का सामान बना था।

१९४८ में केवल २५ हजार रेडियो सेट इस देश में बने थे, पर अब प्रतिवर्ष १ लाख ८५ हजार रेडियो सेट बन रहे हैं, परन्तु अभी देश में पुर्जे जोड़कर ही रेडियो बनाने का काम होता है, इसलिए उसके पुर्जे बनाने का विशेष ध्यान देना चाहिए। १९५७ में पहले छः महीनों में प्रायः २० लाख रुपए के बिजली के सामान का निर्यात हुआ। भारत में बने हुए बिजली के लैम्प, रेडियो और बैटरी आदि सामान बिदेशों में काफी बिक सकता है।

विविध समाचार

—हाल ही में आयात पर जो पाबन्दियां लगायी गई हैं, उनसे एक छमाही में ७० करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा की बचत होगी। यह अंक लोहा और इस्पात को छोड़कर अन्य व्यापारिक लाइसेंसों के बारे में है।

—१९५८-५९ के लिए विकास योजनाएं तैयार करने के सम्बन्ध में आयोजन आयोग ने सुझाव दिया है कि १९५८-५९ में कोई ऐसी नई योजना नहीं बनायी जानी चाहिए, जिस पर विदेशी मुद्रा खर्च हो। जो योजनाएं शुरू हो चुकी हैं, उनके लिए राज्य सरकारों को कहा गया है कि इस बात का प्रयत्न करें कि उनमें कम से कम विदेशी मुद्रा खर्च हो।

★

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक बस्तियां

पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास की दृष्टि से स्थान स्थान पर औद्योगिक बस्तियों की स्थापना का निश्चय किया गया है। तदनुसार विभिन्न राज्यों में ऐसी बस्तियां खोली गई हैं। इनमें लघु उद्योगों को एक साथ बनाकर पानी बिजली, परिवहन मकान, पुरजों की ढलाई आदि की सुविधाएं दी जाती हैं।

उत्तरप्रदेश में १ करोड़ रु० की लागत से, कानपुर और आगरा में औद्योगिक स्थानों की स्थापना राज्य के औद्योगीकरण की दिशा में विगत वित्तीय वर्ष की उल्लेखनीय घटनाएं हैं।

द्वितीय आयोजना के अन्तर्गत लाइट इन्जीनियरिंग मशीन शाप्स, डलाई, उद्योग, खाद्यसामग्रियों का निर्माण, बिजली का घरेलू सामान, साइकिल और सिलाई मशीनों के पुर्जों के निर्माण जैसे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए इन स्थानों की स्थापना की जा चुकी है। उद्योग संचालन कार्यालय ने आलोच्य अवधि में ग्राम्य क्षेत्रोंमें लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ४७ योजनाएं चालू कीं।

कानपुर के औद्योगिक आस्थान क्षेत्र में ६८ छोटे कारखाने खोलने की व्यवस्था की गई है। इसका क्षेत्रफल ३७.७ एकड़ है, जबकि आगरे के आस्थान का क्षेत्रफल ५० एकड़ है। आगरा का आस्थान इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को सौंप दिया गया है। तीसरा आस्थान भारत सरकार की ओर से इलाहाबाद के समीप नैनी में खोला जा रहा है। इसके अतिरिक्त गाजियाबाद, रुड़की, अलीगढ़, लखनऊ तथा वाराणसी में २५-२५ लाख रु० की लागत से पांच और औद्योगिक आस्थानों की स्थापना के सम्बन्ध में राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से लिखा पढ़ी कर रही है।

निजी उद्योगोंके क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किए गए। इलाहाबाद के निकट नैनी में २५,००० तकुओंकी एक कताई मिल खोली गयी। आगरे के जूते, पीतल के काम, साइकिल के पुर्जे आदि उद्योगों में भी काफी उत्पादन हुआ। रूस ने आगरे के जूते खरीदने के लिए बड़े बड़े आर्डर दिए।

———

[सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सिंदरी कारखाने को ४ करोड़ रु० लाभ

मार्च, १९५७ में समाप्त वर्ष में भारत सरकार के सिंदरी उर्वरक और रसायन कारखाने को ४,०९,५९,८७३ रु० का लाभ हुआ। यह रकम पिछले साल के लाभ से ३४,४२,०९५ रु० अधिक है।

इस वर्ष १७ करोड़ रु० की लागत पूंजी पर ५ प्रतिशत अर्थात् ८५ लाख रु० का लाभांश देना घोषित किया गया है। ६८ लाख रु० दिया गया था।

कारखाने की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है कि कारखाने में सभी क्षेत्र में विकास और सुधार हुआ। १९५६-५७ में कारखाने में ३,३३,७०५ टन अमोनियम सल्फेट तैयार किया गया, जबकि पिछले साल ३,२६,०६२ टन तैयार किया गया था। इस प्रकार इस साल ७,६४३ टन अधिक अमोनियम सल्फेट तैयार किया गया। अक्टूबर १९५६ में ३२,३९७ टन अमोनियम सल्फेट तैयार किया गया था और इस प्रकार एक दिन का औसत उत्पादन १,०४५ टन रहा, जो अब तक के दैनिक उत्पादन में सबसे अधिक है। १९५६-५७ में ३,६१,०८२ टन उर्वरक की निकासी हुई, जबकि इससे पहले साल ३,१७,५३४ टन की निकासी हुई थी।

सिंदरी के विस्तार की ११ करोड़ रु० की जो योजना है, उसमें काफी प्रगति हुई।

—

वस्त्र-निर्माण मशीनरी को संरक्षण

सरकार ने तटकर आयोग की यह मुख्य सिफारिश स्वीकार कर ली है कि पूरे बलय यंत्रों, तकुओं, कताई के छल्लों, नालीदार बेलनों और स्वचलित लूमों (करघों) के सम्बन्ध में सूती वस्त्र-निर्माण-यंत्र-उद्योग को दिया जाने वाला संरक्षण ३१ दिसम्बर १९५७ के बाद भी तीन साल की अवधि के लिए जो ३१ दिसम्बर, १९६० को समाप्त हो, जारी रहना चाहिए और संरक्षण-कर मूल्य पर १० प्रतिशत की दर से ही लिया जाना चाहिए। परन्तु सरकार ने यह भी सिफारिश स्वीकार कर ली है कि सादा लूमों (करघों) के सम्बन्ध में दिये जाने वाला संरक्षण १ जनवरी १९५८ से बन्द कर देना चाहिए।

—

"पाञ्चजन्य"
दीपावली विशेषांक में पढ़िए

★ विद्वानों के ज्ञानवर्धक लेख

★ रोचक तथा हृदयस्पर्शी कहानियां

★ ओजस्वी तथा भावपूर्ण कविताएं

★ व्यंग-चित्र, एकांकी और सूक्तियां

आर्ट पेपर पर बहुरंगा मुख-पृष्ठ अंक का विशेष आकर्षण रहेगा।

आकार २०"×२६"×$\frac{1}{8}$ पृष्ठ संख्या ७२ मूल्य : आठ आना

[पाञ्चजन्य के विशेषांक हाथों हाथ बिकते हैं, अतः अभिकर्ता तथा पाठक अपनी प्रतियां अभी मंगा लें जिससे ऐसा न हो कि बाद में अंक प्राप्त न हो सके]

व्यवस्थापक 'पांचजन्य,' गौतम बुद्ध मार्ग, लखनऊ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पृथ्वी की उष्णता से भी शक्ति

कोयला व तेल की शक्तियों के स्रोतों की समाप्ति के भय ने मानव को नये शक्ति स्रोतों की तलाश के लिए प्रेरणा दी है। बिजली और उसके बाद अणुशक्ति इसी दिशा में सफल प्रयत्न हैं, परन्तु इनसे भी संतुष्ट न होकर वह नये साधन की तलाश करने की चिन्ता में व्यस्त है।

अकादमीशियन दिमित्री श्चेर्बाकोव ने यह विश्वास प्रकट किया है कि इस शताब्दी के अन्त तक धरती के भीतरी भाग की तापशक्ति से बिजली तैयार करने के लिए पृथ्वी के अन्दर विद्युत यंत्र कायम करना सम्भव हो जाएगा। शक्ति के इस स्रोत की कोई सीमा नहीं है। ३० मार्च १९५६ में जब कमचत्का प्रायद्वीप का बेजीम्याइन्नी ज्वालामुखी फटा तो उसने चट्टानों के टुकड़े २८ मील की ऊंचाई तक फेंके, उस समय उसने इतनी तापशक्ति प्रसारित की, जितनी संसार का सबसे बड़ा बिजलीघर कुइबिशेव जल-विद्युत केन्द्र जो २१००,००० किलोवाट बिजली पैदा करता है, ३५०० वर्षों में पैदा करेगा। कुछ स्थानों पर गर्म चश्मे और सोते तो शक्ति-उत्पादन के लिए प्रयुक्त भी किये जा रहे हैं। कमचत्का प्रायद्वीप में एक कुंआ खोदा जा रहा रहा है, जिसमें से टर्बाईनों को चलाने के लिए ज्वालामुखी के स्रोतों से अति-उत्तम भाप निकाला जाएगा।

रूस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक श्चेर्बाकोव ने बताया कि जब ऐसा यंत्र जो भूमितल ताप को प्राप्त कर बिजली पैदा करे और उसे ऊपर धरती को भेजे, मीलों नीचे भेजना सम्भव हो जाएगा, तो इंजीनियरिंग का इतिहास एक नयी मंजिल में प्रवेश कर लेगा।

इन्जिनियर ज्भेल्तेन्कोव का विश्वास है कि इस शताब्दि के अन्त तक वायु की आणविक शक्ति से चालित राकेट तैयार हो जायंगे। उसके इन्जिन में अत्यधिक संचापित सामान्य वायु को अणुओं में विखंडित कर दिया जायेगा जो विशाल मात्रा में बिजली प्रसारित करेगी। पारमाणविक आक्सीजन को सामान्य आणविक आक्सीजन में परिणत करने के लिए अनुघटकों की खोज की जा चुकी है।

इन्जिनीयर ग्रिगोरेव ने ध्रुव प्रदेश के वीरान बर्फीले इलाकों के ऊपर कृत्रिम उपग्रह की कल्पना की है। यह सूर्य प्लास्पा (आयनीकृत गैस जिसमें इलेक्ट्रोनिक आवरण से मुक्त परमाणु होते हैं) से बनेगा और चुम्बकीय क्षेत्र द्वारा अटका रहेगा। उसका तापमान करोड़ों सेंटीग्रेड होगा। प्लास्मा के ताप पृथग्नयास (थर्मल इन्सुलेशन) के लिए चुम्बकीय क्षेत्र की सम्भावना १९५० में दो सोवियत अकादिमिशियनों आन्द्रेई सारादोव और इगोर ताम ने प्रकट की थी। अप्रैल १९५६ में अकादिमिशियन इगोर कुजोतोव ने प्रचण्ड तापमानयुक्त प्लास्मा को एक चुम्बकीय क्षेत्र में अटकाने की पहली कोशिशों को लन्दन में एक वार्ता के दौरान में वर्णित किया था। ध्रुव के ऊपर मनुष्य-निर्मित सूर्य के आकार, असली सूर्य के आकार जैसा ही लगेगा लेकिन वह दुगुना ताप प्रदान करेगा।

★

२००० ई० में आबादी दुगुनी

संयुक्तराष्ट्र संघ के अंकविज्ञों का कथन है कि वर्तमान शताब्दी की समाप्ति पर संसार की जनसंख्या अब से दुगुनी हो जायगी।

अगले १२ मास में ही संसार की आबादी ४ करोड़ ३० लाख की वृद्धि हो जाएगी। यदि विशेषज्ञों का कथन सही है तो २१ वीं सदी के शुरू में दुनिया की आबादी ५ अरब ४० करोड़ होगी।

इस वृद्धि का मुख्य कारण है स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। अनुन्नत देशों में अब एक और दो वर्ष के बच्चों की मृत्यु संख्या घट गई है किन्तु बच्चे पैदा होने का क्रम अब भी ज्यों का त्यों है। इस समय संसार की आबादी प्रतिवर्ष १.७ प्रतिशत के हिसाब से बढ़ रही है, जबकि चार साल पहले आबादी बढ़ने का अनुपात १.२ प्रतिशत था।

अन्य प्रदेशों की अपेक्षा दक्षिण अमरीका में आबादी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सबसे अधिक बढ़ रही है। वहां प्रतिवर्ष ४.४ प्रतिशत आबादी बढ़ जाती है। उसके बाद अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम एशिया की बारी आती है। वहां आबादी सामान्यतः ४ प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ती है। अमरीका और रूस दोनों में १.७ प्रतिशत आबादी बढ़ती है।

★

मकानों की समस्या

शहरों में

१. दूसरे आयोजन की अवधि में सरकारी और निजी क्षेत्रों में लगभग १९ लाख मकान बनाए जायंगे। पहले आयोजन में १३ लाख बनाए गए थे।

२. आयोजना में शहरों में सरकारी सहायता से मकान बनाने के लिए १ अरब ५ करोड़ रु० की व्यवस्था है, जिससे ३ लाख ६ हजार मकान बनाए जायंगे।

३. इसके अलावा केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए और कोयला खान, अभ्रक-खान और बागान मजदूरोंके लिए लगभग ७ लाख ६९ हजार मकान बनाएंगी।

४. निजी क्षेत्र शहरों में ८ लाख मकान बनाएंगे, जिन पर लगभग ८ अरब रु० खर्च होगा।

५. १९५१ में २५ लाख मकानों की कमी थी। नये मकानों की जरूरत, पुराने मकानों के गिरने और पुरानों की जगह नए मकान बनाने को ध्यान में रखते हुए १९६१ में लगभग ५७ लाख मकानों की कमी पड़ जायेगी।

६. १९५१-१९६१ के बीच शहरी जनसंख्या में २ करोड़ ६ लाख की वृद्धि होने की आशा है। उसी को देखते हुए उक्त अनुमान लगाया गया है।

गांवों में

१. भारत में कुल ५,५८,०८९ गांव हैं, जिनकी आबादी २९ करोड़ ५० लाख है और इनके रहने के लिए ५ करोड़ ४० लाख मकान हैं।

२. इनमें से लगभग ५ करोड़ मकान ऐसे हैं, जिनकी मरम्मत या सुधार की जरूरत है।

३. कई गांवों में चौड़ी सड़कें, सुधरी किस्म की दूसरे स्कूल की इमारतें और खेल के मैदान बनाने तथा सामुदायिक केन्द्र खोलने की आवश्यकता है।

४. अभी हाल में गांवों में मकान बनाने की एक योजना बनायी गयी है, जिसके अंतर्गत सरकार उन्हें मदद करेगी, जो स्वयं अपने लिए मकान बनायेंगे।

५. ये मकान बहुत छोटे पैमाने पर बनाये जायेंगे और इनको बनाने के लिए गांव की सहकारी संस्थाओं से मिलने वाली स्थानीय इमारती सामग्री काम में लायी जायेगी।

६. इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से कार्यान्वित, निर्देशित और नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकारें गांवों में मकान बनाने के विभाग खोलेंगी। ये विभाग गांवों के नक्शे तथा कम खर्च में मकान बनाने के डिजयन बनायेंगे तथा स्थानीय अधिकारियों को प्राविधिक मामलों में सलाह देंगे।

★

वर्षगांठ का उपहार

प्रधान मंत्री नेहरू की ६८ वीं वर्षगांठ के अवसर पर गाजीपुर जिले की जनता ने श्रमदान द्वारा ६८ मील कंकरीट की पक्की सड़क बनाने की प्रतिज्ञा की है और गत १४ नवम्बर से जिले के पन्द्रह राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा छाया खंडों में यह काम शुरू भी कर दिया गया है। मार्च १९५८, अर्थात् साढ़े चार महीने की ही सीमित अवधि में यह ६८ मील लम्बी पक्की सड़क बना डालने का निश्चय किया गया है। इस प्रकार के प्रशंसनीय प्रयत्न पहले भी हुए हैं परन्तु इन प्रयत्नों की संख्या को देश के कोने-कोने में बढ़ाना चाहिए। अब तक भी हमारी योजना जन-सामान्य का सहयोग प्राप्त नहीं कर सकी है। केवल सरकारी राशि और कर्मचारियों के प्रयत्न से देश का आर्थिक विकास संभव नहीं है। इसके लिए प्रत्येक नागरिक को अपनी आहुति देनी होगी।

★

मिल के कपड़े का उत्पादन

इस साल अक्टूबर के अंत तक कपड़ा-मिलों ने ४४,-४७० लाख गज कपड़ा तैयार किया। १९५६ में इस अवधि तक ४३,९७० लाख गज कपड़ा तैयार हुआ था।

१९५६ में कपड़ा-मिलों में ९,३२,८५५ मजदूर काम

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कर रहे थे, जबकि १९५३ में उनकी संख्या केवल ८,०२,००० थी। इस साल शुरू के आठ महीनों में मजदूरों की औसत संख्या प्रति मास ९,५०,२४६ रही।

—भारत में ३० जून, १९५७ को पूंजीकृत सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों की संख्या ९,५१८ थी और उनकी चुकता पूंजी ७२४ करोड़ रु० थी। रिजर्व बैंक ने १९५५ में जो विवरण तैयार किया था, उसके अनुसार इनमें से ७५० कम्पनियों की लेनदारी १,१९१ करोड़ रु० थी।

★

जनता बीमा पालिसी

२८ अक्टूबर १९५७ तक ६२,९५,९६१ रु० की जनता बीमा पालिसी करायी जा चुकी है। ३० सितम्बर १९५७ तक जनता बीमा पालिसी कराने के केन्द्र हैदराबाद, काकिनाडा (आन्ध्र प्रदेश), बम्बई शहर, शोलापुर और अहमदाबाद (बम्बई), मद्रास कुम्बकोणम और कोयम्बटूर (मद्रास राज्य), रोहतक और सोनीपत (पंजाब राज्य), कानपुर (उत्तरप्रदेश), कलकत्ता और सीलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल) और दिल्ली में खोले जा चुके हैं।

★

बिजली से रेलगाड़ियां

१४ दिसम्बर, १९५७ को पूर्वी रेलवे हावड़ा और श्योराफूली के बीच नयी उपनगरीय रेलगाड़ी चलाएगी, जिसका इंजन भाप के बजाय बिजली से चलेगा। बिजली से रेलगाड़ियां चलाने की दिशा में यह पहला कदम है। धीरे-धीरे कलकत्ता के सभी उपनगरों में तथा हावड़ा और मुगलसराय के बीच बिजली से रेलगाड़ियां चलने लगेंगी। उपनगरों की आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उससे यह स्पष्ट है कि अगले दस वर्षों में अब से दुगुनी रेलगाड़ियों की जरूरत होगी। भाप से चलने वाली रेलगाड़ियां इतनी भीड़ को नहीं ले जा सकतीं।

बिजली से रेलगाड़ियां चलाने से गाड़ियां तेज चल सकती हैं और अधिक भार खींच सकती हैं, न तो उनको कोयला पानी लेने के लिए ठहरने की आवश्यकता होगी और न उन्हें चलाने के लिए अधिक आदमियों पर निर्भर रहना पड़ेगा। इससे न केवल रेलों का खर्च बचेगा, बल्कि दूसरी आयोजना में भी सहायता मिलेगी।

★

बाढ़ से भारत को हानि

१. अनुमान है कि पिछले छः वर्षों में देश को बाढ़ों के कारण ३०० करोड़ रु० की हानि उठानी पड़ी है।

२. मनुष्य और पशु-हानि के अलावा, फसलों और जायदाद की लगभग २७० करोड़ रु० की हानि हुई और बाढ़ निवारणार्थ लगभग ५१ करोड़ रु० खर्च हुए। इस कार्य के लिए दूसरी पंचवर्षीय आयोजना में ६० करोड़ रु० की व्यवस्था है।

३. अनुमान है कि यदि बार-बार बाढ़ न आयी, तो देश की राष्ट्रीय आय में १०० करोड़रु० की वृद्धि होगी।

नई दिल्ली व दिल्ली में सम्पदा

सम्पदा के फुटकर अंकों और विशेष कर विशेषांकों की मांग अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों में बनी रहती है। उनकी सुविधा के लिए आत्माराम एण्ड सन्स, काश्मीरी गेट, दिल्ली (हिन्दी विभाग) में सम्पदा की बिक्री की व्यवस्था कर दी गई है।

नई दिल्ली में सम्पदा के विक्रेता सेंट्रल न्यूज एजेंसी, कनाट सर्कस हैं।

इस प्रबन्ध से आशा है, दिल्ली के अर्थशास्त्र-प्रेमियों की असुविधा दूर हो जायगी।

— मैनेजर सम्पदा

अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

एशिया में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठनके एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलनका चौथा अधिवेशन नयी दिल्ली में १३ नवम्बर से आरम्भ होकर समाप्त हुआ है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जो सिफारिशें और समझौते तैयार किये गये हैं, उनसे एशियाई देशों में श्रम-सम्बन्धी कानूनों को सुधारने और नये कानून बनाने में सहायता मिली है। परन्तु अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का एशियाई देशों में असल कार्य तभी आरम्भ हुआ, जब १९४४ के सम्मेलन में फिलाडेल्फिया की घोषणा को स्वीकार किया गया। इसके फलस्वरूप १९४७ में नयी दिल्ली में पहला एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ। १९५० में संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके विशेष अभिकरणों का प्राविधिक सहायता कार्यक्रम आरम्भ हुआ। इससे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कार्य आगे बढ़ा।

श्रम समस्या

नयी दिल्ली में होने वाले पहले एशियाई सम्मेलन में सामाजिक सुरक्षा (बुढ़ौती, बीमारी, बेकारी आदि स्थिति में सहायता) और औद्योगीकरण की समस्याओं पर विचार किया गया था। सम्मेलन ने यह भी स्वीकार किया कि मजदूरों की हालत सुधारने के लिये उन्हें अच्छा और पर्याप्त भोजन; आरोग्य और चिकित्सा की सुविधाएं; अच्छे मकान, प्राथमिक शिक्षा, और काम धंधे की सुविधाएं अवश्य मिलनी चाहियें। इन सब के लिये धन की आवश्यकता होती है जो उत्पादन बढ़ाकर ही जुटाया जा सकता है। इसलिये सम्मेलन में उत्पादन बढ़ाने वाले कार्यों पर जोर दिया गया। उद्योगों को प्रोत्साहन देने के साथ ही सम्मेलन ने कृषि के विकास पर भी जोर दिया और प्रति एकड़ उपज बढ़ाने तथा मजदूरोंके अधिक काम करने पर जोर दिया। सम्मेलनने सहकारिता प्रणाली के विकास की भी सिफारिश की थी।

दूसरा सम्मेलन

दूसरा एशिया-क्षेत्रीय-सम्मेलन न्युंवारा एलिया (श्रीलंका) में १९५० में हुआ। इसमें श्रम निरीक्षण, मजदूरों के हित के कार्य, सहकारिता का विकास, कृषि मजदूरों के वेतन, किसानों की आय और जन-शक्ति को ठीक काम में लगाने आदि पर विचार किया गया था। एशियाई देशों में १९४७ का श्रम-निरीक्षण-समझौता लागू कराने और जांच या निरीक्षण की व्यवस्था पर जोर दिया गया। सम्मेलन की मजदूर कल्याण समिति ने मत प्रकट किया कि मजदूरों को सुविधाएं देने की जिम्मेदारी सरकार तथा मालिक, दोनों पर है। समिति ने मजदूरों को क्या सुविधाएं मिलनी चाहिये, इसके कुछ सिद्धान्त भी स्थिर किये।

तीसरा सम्मेलन

तीसरा एशिया-क्षेत्रीय-सम्मेलन १९५३ में टोकियो में हुआ। इसमें एशियाई देशों में वेतन नियत करने की समस्याएं, मजदूरों के लिये मकान और कम उम्र के मजदूरों का संरक्षण, इन तीन विषयों पर विचार किया गया।

आवास समिति ने मजदूरों के लिए मकान बनवाने की कठिनाइयों पर विशेष रूप से विचार किया और समस्याओं को हल करने के उपाय सुझाये। ऊंचा वेतन देने की सलाह देते हुए वेतन निर्धारण का सबसे अच्छा तरीका मजदूरों और मालिकों में आपसी करार को बताया गया। जन-शक्ति को काम में लगाने, श्रम निरीक्षण, सहकारिता आदि विषयों पर विचार करने के लिए भी कई बैठकें हुई।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय एशियाई देशों को प्राविधिक सहायता भी देता रहा है। इस क्रम से वह एशियाई देशों को विशेषज्ञ भेजता है, और वहां के लोगों को विदेशों में काम सीखने आदि के लिए वृत्तियां आदि देता है।

एशियाई देशों को जन-शक्ति के संगठन, उत्पादकता वृद्धि, कारखानों में काम सिखाने की व्यवस्था, सहकारिता और दस्तकारी, सामाजिक सुरक्षा, श्रमिकों की भलाई की व्यवस्था और उसके संचालन आदि विषयों के विशेषज्ञ भेजे गये और एशियाई नागरिकों को दूसरे देश में जाकर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इन्हें सीखने के लिये वृत्तियां दी गयीं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन के प्राविधिक सहायता कार्यक्रम पर १९५६ में ९,७७,६६० डालर खर्च हुए और १९५७ में १०,६३,००० डालर का खर्च मंजूर किया गया।

एशियाई-क्षेत्र-कार्यालय

अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय ने १९४९ में बंगलौर में एशियाई क्षेत्र कार्यालय खोला। यह कार्यालय एशियाई देशों को प्राविधिक सहायता देने का आयोजन करता है, उसे कार्यान्वित करता और उसका मूल्यांकन आदि करता है। उद्योग धंधों में शागिर्दी, श्रम विभाग के प्रशासन, श्रम निरीक्षण और काम दिलाने की व्यवस्था आदि विषयों के लिये भी इसने व्यवस्था की है।

अभी तक एशियाई देशों में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के समझौतों को बहुत अधिक मान्यता नहीं मिल सकी है। इन समझौतों में से अफगानिस्तान ने ५, बर्मा ने २०, श्रीलंका ने १६, चीन ने १४, भारत ने २३, इंदोनेशिया ने ४, जापान ने २४, पाकिस्तान ने २३, फिलिपीन ने १०, थाईदेश ने १ और वियत्तनाम ने २ समझौते स्वीकार किये।

रेल कर्मचारियों के दोनों संगठनों की एकता

भारत के मजदूर आन्दोलन में इस मास महत्वपूर्ण घटना हुई है। नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेल्वेमेन और आल इन्डिया रेल्वे मेन्स फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने २० नवम्बर के दिन उस एकता समझौते को क्रियान्वित करने का निश्चय किया, जो मार्च १९५६ में श्री श्यामप्रसाद वसावड़ा व श्री एस. गुरुस्वामी के बीच हुआ था।

दोनों फेडरेशनों के प्रतिनिधि मार्च १९५६ के एकता समझौते को कार्यान्वित करने के निर्णय पर सहमत हो गये हैं। परस्पर सहमतियों से यह तय किया गया है कि १९५६ के समझौते में जिन चुनावों की कल्पना की गयी है, वे ३१ जुलाई १९५८ तक पूरा कर लिये जाय। परस्पर सहमति से यह भी तय पाया गया कि मार्च १९५६ के समझौते के क्रियान्वयन में किसी प्रकार का विवाद उपस्थित होने पर पहले तो उन विवादों पर एक पर्यवेक्षक की उपस्थिति में चर्चा की जायगी और बाद में आवश्यक होने पर उन्हें एक पंच को निर्णय करने के लिए कहा जायेगा।

पंजाब के साहित्य, संस्कृति और जीवट जीवन का दर्पण

जागृति

सचित्र हिन्दी मासिक

मूल्य एक प्रति	वार्षिक चन्दा	छपाई
४ आना	केवल ३ रुपया	सम्पूर्ण आर्ट पेपर पर

पंजाब के इस अभिनव अर गौरवपूर्ण प्रकाशन की कुछ विशेषताएं

- साहित्यिक सांस्कृतिक और सामाजिक विषयों पर अधिकारी और प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं,
- ख्याति प्राप्त चित्रकारों और कलाकारों के चित्र और कला कृतियां,
- बहुरंगे आकर्षक और मोहक छाया चित्र,
- जानकारी पूर्ण मनोरंजक लेख।

व्यवस्थापक 'जागृति' (हिन्दी)

लोक सम्पर्क विभाग, पंजाब, ६९ माडल टाउन, अम्बाला शहर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चतुर्थ सम्मेलन

अंतर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन का चतुर्थ एशियायी सम्मेलन १२ दिन तक नई दिल्ली में चला। सम्मेलन में १९ देशों के १९० प्रतिनिधियों, सलाहकारों तथा प्रेक्षकों ने भाग लिया।

कृषि मजदूरों के सम्बन्ध में पारित प्रस्ताव का मुख्य लक्ष्य समस्त एशियायी देशों में सामाजिक और आर्थिक नीति के अंतर्गत जमीन जोतने वालों और कृषि मजदूरों के पेशे तथा उनके जीवन-यापन के साधनों की सुरक्षा को कायम रखना है। प्रस्ताव में कहा गया है कि जहां तक सम्भव हो कृषकों को भूमि पर स्थायी अधिकार दिया जाय तथा पट्टे पर जमीन उठाने की अवधि कम से कम कर दी जाय। बेगार लेने की पद्धति का बहिष्कार तथा पट्टे की अवधि बढ़ाने के लिए भूमि-मालिकों को विशेष फीस या उपहार इत्यादि प्रथा को पूर्ण रूप से रोकने पर भी प्रस्ताव में जोर डाला गया है।

प्रस्ताव में अंत में सिफारिश की गई है कि पूरक रोजगार के लिए ग्रामीण-दस्तकारी और उद्योगों को बढ़ावा तथा अवकाश काल में मजदूरों को प्रशिक्षण दिया जाय।

सम्मेलन ने मजदूर-मालिक संबंधों पर उपसमिति के प्रतिवेदन को भी स्वीकार कर लिया। इसमें कहा गया है कि मजदूर और मालिक संबंध मालिकों और ट्रेड यूनियनों के आपसी संबंधों पर निर्भर करते हैं। यह उन तक ही सीमित है कि किस योग्यता और उत्तरदायित्व के साथ वे आपसी सम्बन्धों को कायम रखते हैं। मजदूर-मालिकों के झगड़ों को सरकार की मध्यस्थता से निपटाना अधिक वांछनीय है। प्रस्ताव में इस बात को माना गया है कि उद्योगों के उत्पादन-वृद्धि के लिए मजदूर-मालिकों के सम्बन्ध अच्छे होना अनिवार्य है। इसका प्रभाव एशिया निवासियों के रहन-सहन के स्तर पर पड़ता है।

—

भारत सरकार के व्यापार और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित

'उद्योग व्यापार पत्रिका'

★ उद्योग और व्यापार-सम्बन्धी प्रामाणिक जानकारी-युक्त विशेष लेख, भारत सरकार की आवश्यक सूचनाएं, उपयोगी आंकड़े आदि प्रति मास दिये जाते हैं।

★ डिमाई चौपेजी आकार के ६०-७० पृष्ठ : मूल्य केवल ६ रुपया वार्षिक। एजेण्टों को अच्छा कमीशन दिया जायगा। पत्रिका विज्ञापन का सुन्दर साधन है।

★ लघु-उद्योग विशेषांक मंगा कर छोटे उद्योगों के सम्बन्ध में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त कीजिये।

★ ग्राहक बनने, एजन्सी लेने अथवा विज्ञापन छपाने के लिए नीचे लिखे पते पर पत्र भेजिये :—

सम्पादक

उद्योग व्यापार पत्रिका

उद्योग और व्यापार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

113084

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्पदा व हिन्दी में आर्थिक साहित्य पर्यायवाची शब्द हैं

अपने पांच वर्षों के स्वल्प काल में सम्पदा ने आर्थिक प्रवृत्तियों तथा आर्थिक समस्याओं की जो जानकारी दी है, वह अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। यही कारण है कि:—

हा. सै. स्कूल, इण्टर व डिग्री कालेज और पुस्तकालय एवं वाणिज्य व अर्थशास्त्र के विद्यार्थी

सम्पदा की पुरानी फाइलें मंगा रहे हैं। थोड़ी सी फाइलें बची हैं। प्रत्येक विशेषांक स्वयं एक उपादेय पुस्तक है। कुछ समय बाद आपको हम फ़ाइल न दे सकेंगे। मूल्य प्रति फाइल ८) रु०

नमूने के एक अंक के लिए छः आने के टिकट भेजिये

यह स्मरण रखिये कि वी० पी० से मंगाने पर आपको ॥=) अधिक देना पड़ता है।

मनीआर्डर से मूल्य भेजना लाभकारी होगा।

आपका स्वास्थ्य

(हिन्दी की एक मात्र स्वास्थ्य सम्बन्धी मासिक पत्रिका)

"आपका स्वास्थ्य" आपके परिवार का साथी है।

"आपका स्वास्थ्य" अपने क्षेत्र के कुशल डाक्टरों द्वारा सम्पादित होता है।

"आपका स्वास्थ्य" में अध्यापकों, अभिभावकों, माताओं और देहातों के लिए विशेष लेख प्रकाशित होते हैं।

आज ही ६) रु० वार्षिक मूल्य भेजकर ग्राहक बनिए।

व्यवस्थापक,

आपका स्वास्थ्य—बनारस-१

जीवन साहित्य

हिन्दी के उन मासिक पत्रों में से है, जो

१. लोकरुचि को नीचे नहीं, ऊपर ले जाते हैं,
२. मानव को मानव से लड़ाते नहीं, मिलाते हैं,
३. आर्थिक लाभ के आगे झुकते नहीं, सेवा के कठोर पथ पर चलते हैं,

जीवन साहित्य की सात्विक सामग्री को छोटे-बड़े, स्त्री-बच्चे सब निःसंकोच पढ़ सकते हैं। उसके विशेषांक तो एक से एक बढ़कर होते हैं।

जीवन साहित्य विज्ञापन नहीं लेता। केवल ग्राहकों के भरोसे चलता है। ऐसे पत्र के ग्राहक बनने का अर्थ होता है राष्ट्र की सेवा में योग देना।

वार्षिक शुल्क के ४) भेजकर ग्राहक बन जाइए।

ग्राहक बनने पर मण्डल की पुस्तकों पर आपको कमीशन पाने की भी सुविधा हो जायगी।

सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली।

आर्थिक समीक्षा

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आर्थिक राजनीति अनुसंधान विभाग का पाक्षिक पत्र

प्रधान सम्पादक: आचार्य श्री श्रीमन्नारायण

सम्पादक: श्री हर्षदेव मालवीय

★ हिन्दी में अनूठा प्रयास
★ आर्थिक विषयों पर विचारपूर्ण लेख
★ आर्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत

भारत के विकास में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यावश्यक, पुस्तकालयों के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक।

वार्षिक चन्दा: ५ रु० एक प्रति: ३॥ आना

व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी,

७, जन्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

डालमिया उत्पादन

प्रयोग-सिद्ध एवं उच्च-कोटि के

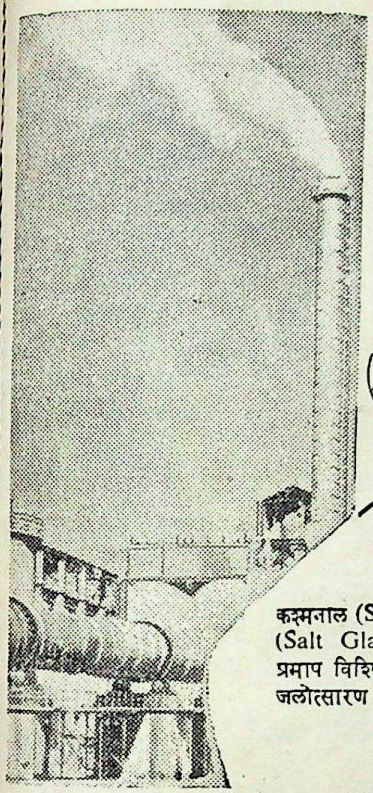

डालमियापुरम् मिल की सिमेंट भट्टी का एक दृश्य

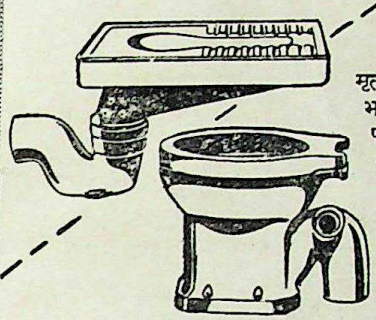

मृत्सा-आरोग्यपात्र (Porcelain sanitary ware) भारतीय और योरोपीय शौच कुंड (closets) धावन पात्री (Wash basins) मूत्रकुंड (Urinals), इत्यादि विसवाहक (Insulations) एवं क्षाररोधक खर्परी (Tiles) भी मिल सकती है।

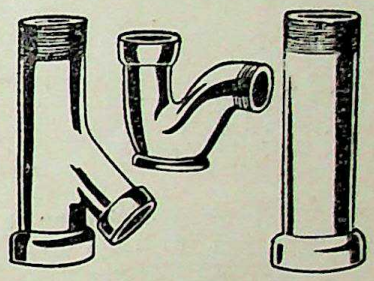

कश्मनाल (Stone ware Pipes) पूर्ण रूपेण लवण काचित (Salt Glazed) क्षार रोधक (Acid Resistant) एवं प्रमाप विशिष्ट (Tested of standard specification) जलोत्सारण (Drainage) के लिये

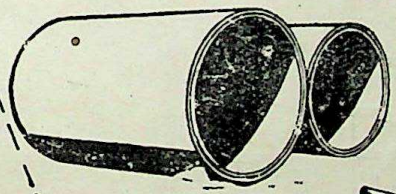

वज्रचूर्ण-आयरसंघा नाल (R. C. C. Spun pipes) सिंचाई, पुलियाओं (Culverst) जलप्रदाय और जलोत्सारण (Cupply and drainage) के लिये सभी श्रेणियों और मापों में प्राप्य।

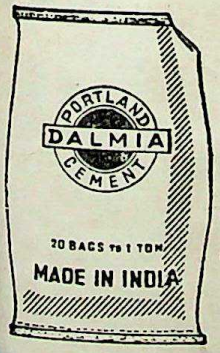

पोटलेण्ड सिमेंट सामान्य निर्माण के लिये

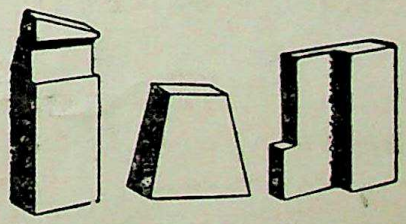

उष्मसह (Refractories) अग्नीष्ट कायें (Fire Bricks) संमृद (Mortors) तथा समस्त ताप-सीमाओं और आकृतियों में प्राप्य विसंवाहक ईस्ट कायें (Insulating Blocks) सभी औद्योगिक आवश्यकताओं के लिये

डालमिया सिमेंट [भारत] लिमिटेड

डाकघर – डालमियापुरम्
जिला – तिरुचिरापल्ली, दक्षिण भारत

A.I.A.B. D/C H2

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

समाजवाद-अंक पर लोकमत

पत्र क्या कहते हैं?

'सम्पदा' ने देश के सामने, जो आर्थिक क्रांति से गुजर रहा है, समाज के विभिन्न आर्थिक पहलुओं पर प्रकाश डालने वाली ऐसी सामग्री प्रस्तुत की है कि जो तथ्यों और आंकड़ों से युक्त होने के कारण उत्तम संदर्भ साहित्य का स्थान ले सकती है। वैदिक समाजवाद से लेकर कांग्रेस-समाजवाद तक की अवस्थाओं का इसमें सुन्दर ढंग से विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

—'नवभारत टाइम्स' बम्बई

इस अंक में समाजवाद, साम्यवाद, सर्वोदयवाद आदि के सम्बन्ध में प्रचुर सामग्री प्रस्तुत की गई है। उसमें जहां रूस, चीन और युगोस्लाविया की अर्थव्यवस्था का परिचय दिया गया है, वहां अमरीका की नवीन पूंजीवादी व्यवस्था पर भी प्रकाश डाला गया है। —हिन्दुस्तान (दैनिक)

प्रस्तुत अंक में सुयोग्य विद्वानों द्वारा लिखित लेखोंके द्वारा 'समाजवाद' के सभी पक्षों का यथेष्ट विवेचन प्रस्तुत किया गया है।

—पाञ्चजन्य (साप्ताहिक)

इसमें सन्देह नहीं कि 'सम्पदा' अपने विशेषांकों के द्वारा 'मील स्टोन' कायम करती जा रही है।

—'आपका स्वास्थ्य' (मासिक)

अर्थशास्त्र के अध्यापक क्या कहते हैं?

समाजवाद अंक मिला, देखकर जी खिल उठा। मिलने के बाद एक सांस सम्पदा ही पढ़ता रह गया। अंक बहुत सशक्त है। खूब बधाई! सचमुच मन भर गया।

—श्री रामनरेशलाल, रांची

"समाजवाद का बिशेषांक हिन्दी क्षेत्र में आपकी लगन का परिचायक है, इस तथ्य को स्वीकार करना पड़ेगा।"

—श्री ओमप्रकाश तोषनीवाल

आप में लगन बहुत है। ईश्वर आपके विचारपूर्ण और मौलिक सूझपूर्ण सम्पादकत्व को नित नया स्नेह और आलोक दें दीर्घकाल तक, यही कामना होती है।

—प्रो० बी० एन० पाण्डेय

अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों, सार्वजनिक कार्यकर्ताओं और शिक्षित वर्ग सबके लिए एक समान उपयोगी समाजवाद विकास को १॥।) (डाक खर्च समेत) मनी आर्डर भेज कर मंगा लीजिये।

योजना अंक, राष्ट्रीय विकास अंक, उद्योग अंक, भूमि सुधार अंक, वस्त्रोद्योग अंक, मजदूर अंक, बैंक अंक और समाजवाद अंक एक साथ मंगाने के लिए ६) रु० म० आ० से भेजिये। सब अंक रजिस्ट्री से भेजे जायेंगे।

76308

—मैनेजर सम्पदा
अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिल्ली।

सम्पादक—कृष्णचन्द्र विद्यालंकार द्वारा अशोक प्रकाशन मन्दिर के लिए अर्जुन प्रेस, दिल्ली से मुद्रित व प्रकाशित।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Compiled
1930-2050

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri